

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

Economy of Rajasthan

(महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रथम वर्ष कला के नवौनतम पाठ्यक्रम पर आधारित)

110661

W. G. C. BOOKS

नरेन्द्र कुमार बड़ाना
व्याख्याता,
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर

रतन लाल मेहरा
व्याख्याता,
राजकीय महाविद्यालय,
किशनगढ़

दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
सहायक निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
अजमेर

सशोधित संस्करण
1999-2000



नाकोड़ा पब्लिशिंग हाऊस

प्रकाशक

नाकोड़ा पब्लिशिंग हाऊस

बी-132, जनता कॉलोनी,

जयपुर फोन - 605266

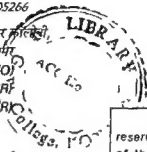
ए-103 मानमरोवर कॉलेजी,

वैशाली नगर, अजमेर

फोन - 641668 (O)

428512 (R)

641275 (R)



© प्रतिलिप्याधिकार लखकाधीन

प्रथम संस्करण 1998-1999

द्वितीय संस्करण 1999-2000

111111

मूल्य 140/- एक सौ चालीस रुपये

लेजर टाईप मेटिंग

कम्प्यूटर सेल्यूशन

30, जीवा विहार कॉलोनी

अजमेर

मुद्रक

नफीस ऑफसेट प्रेस,

जयपुर

Printing & Publishing rights reserved with the publisher. No part of this book may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise without the written permission of the Authors

Due care and diligence has been taken while writing editing and printing this book neither the Authors nor the Publisher of the book hold any responsibility for any mistakes whatsoever

In case of any dispute all cases will be subject to Jaipur jurisdiction

प्राक्कथन

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों हेतु "राजस्थान की अर्थव्यवस्था" की यह पुस्तक प्रस्तुत करते हुये हमे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक को विद्यार्थियों के लिये उपयोगी बनाने हेतु लेखकों ने हर सम्भव प्रयास किया है यथा

- ❶ छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुये यथासम्भव अत्यन्त सरल भाषा में पुस्तक की रचना की गई है।
- ❷ उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से विषय को बोधगम्य बनाने की चेष्टा की गई है।
- ❸ प्रामाणिक तथ्यों व आकड़ों का समावेश करने के लिये आर्थिक समीक्षा, स्टैटिस्टिकल एब्सट्रैक्ट नवीं पधवर्षीय योजना, भारत (संदर्भ ग्रंथ), आर्थिक सर्वेक्षण विश्व विकास प्रतिवेदन मानव विकास प्रतिवेदन, इकॉनोमिक टाईम्स, योजना तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी पत्र-पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है।
- ❹ यथासम्भव सभी आकड़ों व तथ्यों के स्रोतों को उद्धृत किया गया है।
- ❺ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु लगभग सभी बिन्दुओं के साथ उनके अंग्रेजी पर्याय भी दिए गए हैं।
- ❻ यथेष्ट सामग्री के समावेश के लिए, आधुनिक कम्प्यूटरीकृत तकनीक द्वारा ठोस मुद्रण का प्रयोग किया गया है।
- ❼ विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली के अनुरूप परीक्षोपयोगी प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास किया गया है।

पुस्तक की पांडुलिपि को वर्तमान स्वरूप देने, उसे समय पर प्रकाशित कराने में श्री महेश गुप्ता, प्राध्यापक, इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, श्री पी एम जैन, प्राचार्य आचार्य श्री तुलसी अमृत महाविद्यालय गंगापुर (भीलुवाड़ा), नाकोडा पब्लिशिंग हाऊस जयपुर-अजमेर एव कम्प्यूटर सोल्यूशन्स अजमेर का अपार सहयोग प्राप्त हुआ। उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। परिवार-जनों ईष्टमित्रों के सहयोग के बिना इस कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उन सभी के प्रति आभार।

हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी तथा कला के विद्यार्थियों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगी। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिये आपके रचनात्मक सुझावों का सदैव स्वागत है।

लेखकगण

अनुक्रमणिका

(INDEX)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति (POSITION OF RAJASTHAN IN INDIAN ECONOMY) 1 - 13
राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया - 1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूचक - 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति - 4, राजस्थान में आर्थिक विकास की भाषाएँ - 10
अभ्यासार्थ प्रश्न - 12
2. राजस्थान में मानवीय संसाधन (HUMAN RESOURCES IN RAJASTHAN) 14 - 31
जनसंख्या का महत्व - 14, राजस्थान में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि - 15, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर - 17 राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या - 19 राजस्थान में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण - 21, राजस्थान में स्त्री-पुरुष अनुपात - 22, राजस्थान में जनसंख्या का घातक व असमान वितरण - 23, राजस्थान में अनुसूचित जाति व जन जाति - 24 राजस्थान में मानव संसाधन विकास के तीन महत्वपूर्ण सूचक - 25, राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम - 27 अभ्यासार्थ प्रश्न - 30
3. राजस्थान में निर्धनता की समस्या (PROBLEM OF POVERTY IN RAJASTHAN) 32 - 38
गरीबी व अमीरी की रेखा - 33 निर्धनता की कैलेंसरी आधारित आधारणा के दावे - 34, राजस्थान में निर्धनता की स्थिति - 35 राजस्थान में निर्धनता निवारण के लिए आवश्यक सुझाव - 35, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए अपनाए गए कार्यक्रम - 37 जिला निर्धनता निवारण परियोजना - 37, अभ्यासार्थ प्रश्न - 39
4. राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या (PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN) 39 - 49
बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार - 39 बेरोजगारी की अवधारणाएँ - 40 राजस्थान में श्रम शक्ति - 40 राजस्थान में रोजगार - 41 राजस्थान में बेरोजगारी का आकार - 43 राजस्थान में रोजगार के अवसरों की सम्पन्नता - 44 राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति - 45 राजस्थान में बेरोजगारी के कारण - 46, राजस्थान में बेरोजगारी को हल करने के सुझाव - 47 नवी योजना में रोजगार सृजन की रणनीति - 48 राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार सृजन के कार्यक्रम - 49 अभ्यासार्थ प्रश्न - 49
5. राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन (NATURAL RESOURCES OF RAJASTHAN) 49 - 87
प्राकृतिक संसाधनों से अर्थ - 50 प्राकृतिक संसाधनों के महत्व - 51 राजस्थान की भूमि सम्पदा - 53, राजस्थान की जलवायु - 54, राजस्थान के प्राकृतिक भाग - 55 राजस्थान की मिट्टियाँ - 60, राजस्थान की वन सम्पदा - 62 राजस्थान की जल सम्पदा - 68, राजस्थान की पशु सम्पदा - 72 राजस्थान की खनिज सम्पदा - 74 अभ्यासार्थ प्रश्न - 86

6. राज्य का घरेलू उत्पाद (STATE DOMESTIC PRODUCT)

88-96

घरेलू उत्पाद का अर्थ - 89, राजस्थान के घरेलू उत्पाद की विशेषताएँ व प्रवृत्तियाँ - 89, राज्य के घरेलू उत्पाद का ढांचा एवं उसकी गणना - 91, राज्य के घरेलू उत्पाद को मापने की विधि - 93, राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में आने वाली कठिनाईयाँ - 94, राज्य के घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि के लिए सुझाव - 94, राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना का महत्व अथवा उपयोग - 95, अभ्यासार्थ प्रश्न - 96

7. पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थाई विकास की समस्याएँ (ENVIRONMENTAL POLLUTION & PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

97-128

पारिस्थितिकी सतुलन - 97, प्रदूषण 98 विश्व में प्रदूषण की स्थिति तथा पारिस्थितिकी सतुलन के प्रयास - 105, भारत में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी सतुलन के प्रयास - 107, राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी सतुलन के प्रयास - 110, सुस्थिर विकास की अवधारणा - 116, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याएँ - 116, अभ्यासार्थ प्रश्न - 127

8. कृषि, भू-उपयोग, फसल प्रारूप एवं प्रमुख फसलें (AGRICULTURE LAND UTILISATION, CROPPING PATTERN & MAJOR CROPS)

128-170

राजस्थान में कृषि का महत्व - 128, राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएँ - 131, राजस्थान में कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना/हरित क्रांति हेतु अपनाए गए कार्यक्रम - 133, राजस्थान में योजनाकाल के अन्तर्गत कृषि विकास - 143, राजस्थान की आठवीं योजना में कृषि विकास की व्यूह रचना - 146, राजस्थान की नवीं योजना में कृषि विकास की व्यूह रचना - 147, राजस्थान में भू-उपयोग - 147, राजस्थान में फसलों का प्रारूप - 151, राजस्थान में कृषि जलवायु छद्म - 153, राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि फसलें - 155, राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएँ एवं उनके समाधान - 166, अभ्यासार्थ प्रश्न - 169

9. राजस्थान में भूमि सुधार (LAND REFORMS IN RAJASTHAN)

170-181

भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य - 170, राजस्थान में भू सुधारों की पृष्ठभूमि - 172, राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय के पूर्व प्रचलित भू-धारण प्रणालियाँ - 172, राजस्थान में भूमि सुधार के प्रयास एवं क्रियाव्यवस्था - 173, भूमि सुधारों की प्रगति - 176, राजस्थान में भूमि सुधारों की समीक्षा, समस्याएँ व सुझाव 177, राजस्थान कारगरकारी अधिनियम, 1955 - 180, अभ्यासार्थ प्रश्न - 181

10. राजस्थान में पशु पालन (ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN)

182-201

राजस्थान में पशुओं की संख्या व पशु गणना, 1997 - 183, राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण - 184, राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु - 184, राजस्थान में पशु पालन के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएँ, कार्यक्रम व सुविधाएँ 186, योजनाकाल में पशु पालन का विकास - 193, राजस्थान में शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु समृद्धि का महत्व - 194, राजस्थान में पशु पालन की समस्याएँ तथा सुझाव - 195, राजस्थान में कुकुर पालन - 197, राजस्थान में मत्स्य पालन - 198, अभ्यासार्थ प्रश्न - 200

11. राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम (DAIRY DEVELOPMENT PROGRAMME IN RAJASTHAN)

202 - 209

राजस्थान में डेयरी विकास की पृष्ठभूमि - 203, राजस्थान के डेयरी सयत्र - 203, राजस्थान के पशु आहार सयत्र - 205, जिला दुग्ध सहकारी संघ एवं राजस्थान सहकारी परिषद लि - 205, डेयरी विकास में सहायक प्रमुख कार्यक्रम - 206, आठवीं व नवीं योजना में डेयरी विकास - 207, राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएँ व समाधान के उपाय - 208, अभ्यासार्थ प्रश्न - 209

12. राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन (SHEEP & GOAT HUSBANDRY IN RAJASTHAN)

210 - 216

राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की संख्या - 211, भेड़ों व बकरियों का जिलानुसार वितरण - 211, राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लें - 211, भेड़ व बकरी पालन से संबंधित विभिन्न योजनाएँ कार्यक्रम व सुविधाएँ - 212 भेड़ व बकरी पालन की विशिष्ट समस्याएँ व सुझाव - 215, अभ्यासार्थ प्रश्न - 216

13. राजस्थान का संरचनात्मक विकास (INFRA-STRUCTURAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)

217 - 254

राजस्थान में सिंचाई - 217, राजस्थान नहर अधिकाइदिग गांधी नहर परियोजना - 222, राजस्थान की अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ - 229 योजनाकाल में सिंचाई का विकास - 238 राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति - 239, राजस्थान में सिंचाई संबंधी समस्याएँ व सुझाव - 240, राजस्थान में शक्ति - 241, राजस्थान में ऊर्जा विकास के मंदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका - 246, ऊर्जा के साधनों की समस्याएँ और समाधान - 247 राजस्थान में सड़कों का विकास - 248, राजस्थान में रेल परिवहन - 250 अभ्यासार्थ प्रश्न - 253

14. राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं उद्योग (INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INDUSTRIES IN RAJASTHAN)

255 - 293

औद्योगीकरण का अर्थ - 255, राजस्थान में आय एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगीकरण का महत्व - 256 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएँ - 258 राजस्थान में औद्योगिक विकास - 261 राजस्थान में औद्योगिक विकास की समस्याएँ - 264, राजस्थान में उद्योगों का क्षेत्रीय वितरण/ फैलाव/असमानताएँ - 265, राजस्थान में औद्योगिक विकास की जिलावार क्षेत्रीय असमानताएँ - 266 राजस्थान के बृहद उद्योग - 271, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग - 289, अभ्यासार्थ प्रश्न - 292

15. राजस्थान में लघु व ग्रामीण उद्योग तथा हस्तकलाएँ (SMALL SCALE & VILLAGE INDUSTRIES AND HANDICRAFTS IN RAJASTHAN)

294 - 312

लघु व कुटीर उद्योग का अर्थ - 294, लघु व कुटीर उद्योगों में अंतर - 295, लघु व कुटीर उद्योगों का महत्व या भूमिका - 296, लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक समस्याएँ - 297, राजस्थान के प्रमुख लघु व कुटीर उद्योग - 299, राजस्थान में हस्तशिल्प - 306 राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याएँ व उनके सुझाव - 311 अभ्यासार्थ प्रश्न - 312

- 16. राजस्थान की औद्योगिक नीति, सुविधाएं व रियायतें (INDUSTRIAL POLICY, FACILITIES & CONCESSIONS IN RAJASTHAN)** **313-334**
- औद्योगिक नीति का अर्थ व महत्व - 313, राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1990 - 314, राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1994 - 325, नई औद्योगिक नीति, 1998 - 330, राजस्थान में आद्योगिक विकास की बाधाएं व इनके निराकरण हेतु सुझाव - 331, अभ्यासार्थ प्रश्न - 333
- 17. राजस्थान में औद्योगिक वित्त एवं विकास में संस्थागत योगदान (ROLE OF VARIOUS INSTITUTIONS IN INDUSTRIAL FINANCE AND DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)** **335-360**
- राजस्थान राज्य वित्त निगम - 336, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम - 340, राजसूको - 349, राजस्थान में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले अन्य विभाग/निगम - 356, भारत की औद्योगिक वित्त से सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्थाएं - 357, राजस्थान में औद्योगिक वित्त की समस्याएं व सुझाव - 359, अभ्यासार्थ प्रश्न - 359
- 18. राजस्थान में पर्यटन विकास (TOURISM DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)** **361-374**
- पर्यटन का महत्व - 361, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास - 362, राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं व समाधान - 366, आठवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास - 366, राजस्थान की पर्यटन नीति - 368, राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति - 370, राजस्थान पर्यटन विकास निगम - 370, आठवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास - 371, नवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास - 371, राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएं - 372, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल - 372, अभ्यासार्थ प्रश्न - 374
- 19. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम (SPECIAL AREA PROGRAMMES)** **375-412**
- सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (RDP - 376, जन-जाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम TAOP - 391, मरु विकास कार्यक्रम DDP - 397, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAAP - 399, खासगरी विकास कार्यक्रम ADP - 407, अभ्यासार्थ प्रश्न - 411
- 20. राजस्थान में आर्थिक नियोजन (ECONOMIC PLANNING IN RAJASTHAN)** **413-434**
- राजस्थान का नियोजन तंत्र - 413, विकेंद्रित नियोजन - 415, राजस्थान में आर्थिक नियोजन - 416, राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना - 431, अभ्यासार्थ प्रश्न - 434
- 21. राजस्थान का आर्थिक विकास : विशेषताएं एवं बाधाएं (ECONOMIC DEVELOPMENT IN RAJASTHAN CHARACTERISTICS & CONSTRAINTS)** **435-446**
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं - 435, राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान - 440, राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान - 442, राजस्थान के तौर विकास हेतु सुझाव - 444 अभ्यासार्थ प्रश्न - 445

22 राजस्थान में अकाल एवं सूखा (FAMINE & DRAUGHT IN RAJASTHAN) 447 - 456

राजस्थान में अकाल व सूखे के अध्ययन का महत्व - 448, राजस्थान में अकाल व सूखे का इतिहास - 449, अकाल व सूखा प्रबन्ध की अल्पकालीन व दीर्घकालीन व्यूह रचना - 451, राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के कारण व निवारण के उपाय - 452, अभ्यासार्थ प्रश्न - 455

23. राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ (STATE BUDGETARY TRENDS) 457 - 481

बजट का अर्थ - 456, राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ - 458, राजस्थान की वित्तीय स्थिति में सुधार के सुझाव - 464, केन्द्र राज्य वित्तीय संबंध - 465, राज्य योजना की वित्तीय व्यवस्था - 466, परिवर्तित आय - व्ययक, 1998-99 - 476, अभ्यासार्थ प्रश्न - 480

24 राजस्थान में पंचायती राज (PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN) 482 - 496

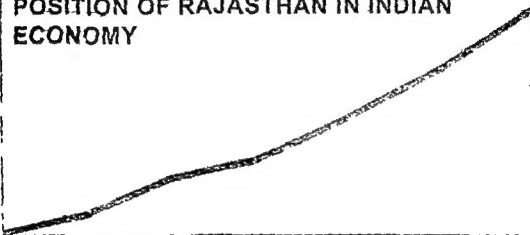
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की विशेषताएँ अथवा प्रावधान - 483, राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति - 488 राजस्थान में पंचायत समितियाँ 492 राजस्थान में पंचायती राज की कमियाँ व असफलताएँ - 495, राजस्थान में पंचायती राज की कमियों को दूर करने के उपाय 495 राजस्थान में पंचायती राज का मूल्यांकन - 496, अभ्यासार्थ प्रश्न 496

वस्तुनिष्ठ प्रश्न 497 - 504

अध्याय - 1

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति

POSITION OF RAJASTHAN IN INDIAN ECONOMY



“राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहाँ का संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसा था।”

“राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय में मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहाँ की संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसी थी।” ऐतिहासिक एवं मास्कुलिक दृष्टि में गौरवमयी परम्पराओं के लिए विख्यात राजस्थान इग्वेट का रचना-स्थल रहा है। वीणा त्याग और बलिदान की दृष्टि से इसका गौरवमय स्थान है। भारत में आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का एक बड़ा भू भाग रेगिस्तानों से घिरा हुआ है। दश में कृषि उद्योग व्यापार परिवहन खनिज वनसंसाधन व क्षेत्र की दृष्टि से राज्य का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रकृत शक्ति परिसंस्थितियों से युक्त राज्य में यह कृषि प्रधान राज्य अपना व संपूर्ण देश का आर्थिक परिदृश्य उदत्त करने हेतु कृतकल्प प्रयास होना है अतः व्यवस्थापन में राजस्थान की स्थिति व योगदान का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक व उपयोगी है।

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया
- राजस्थान का अर्थव्यवस्था का स्वरूप
- भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति
- राजस्थान में आर्थिक विकास की गति
- राजस्थान की समस्याएँ

राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया

PROCESS OF RAJASTHAN'S FORMATION

राजस्थान की वर्तमान स्वरूप देने की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 का अधिनियम और 1 नवम्बर 1956 का अधिनियम

हुई। इस प्रक्रिया के मध्य राजस्थान को 19 रियायतों 3 चापशिप्स व एक केन्द्रशासित सी श्रेणी का राज्य का विलीनीकरण किया गया सबसे पहले 18 मार्च 1948 को अन्वर भरतपुर भोलपुर व वगैरे रियायतों को मिलाकर मत्स्य मध बनाया गया इस मध की राजधानी अलवर थी। इसी माह 25 मार्च 1948 को ही वासना बूंदी डूंगरपुर टोक झालावाड विरानगढ कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा रियायतों को मिला लिया गया और इनके राजस्थान प्रथम या पूर्व राजस्थान का नाम दिया गया राजस्थान प्रथम की राजधानी कोटा को बनाया गया अगले माह 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान मध में उदयपुर रियायत को सम्मिलित करके इस मध का नाम मयूकत राजस्थान रख दिया गया और उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया 30 मार्च 1949 को बीकानेर जयपुर जोधपुर व जैसलमेर रियायतों को मयूकत राजस्थान के मध्य मिलाकर विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया

इस समय तक मत्स्य मध का अन्तग अस्तित्व बना हुआ था 15 मई 1949 को मत्स्य मध को विशाल राजस्थान में मिलाकर 'मयूकत विशाल राजस्थान' की स्थापना हुई और इसकी राजधानी जयपुर बनी रही। 26 जनवरी 1950 को विशाल राजस्थान में सिरोंही रियायत (आबू को छोड़कर) को सम्मिलित करके 'राजस्थान मध' का निर्माण हुआ। इसकी राजधानी भी जयपुर ही रही। अन्ततः 1 नवम्बर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के केन्द्रशासित 'सी श्रेणी के राज्य आबू रोड और तत्कालीन मध्य भारत में स्थित मदनमौर जिन के मानपुर तन्सीत के मुनेन टण्डा गांव को भी राजस्थान मध में मिला लिया गया तथा राजस्थान का आधुनिक स्वरूप अस्तित्व में आया जयपुर को ही पुनः इसकी राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान निर्माण प्रक्रिया को निम्नांकित तालिका से दर्शाया जा सकता है

राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया				
चरण	स्थापित मध	राजधानी	स्थापना दिनांक	सम्मिलित रियायतें
प्रथम	मत्स्य मध	अलवर	18 मार्च 1948	अलवर भरतपुर भोलपुर बरोली
द्वितीय	राजस्थान प्रथम	कोटा	25 मार्च 1948	वासना बूंदी डूंगरपुर टोक जालवाड विरानगढ़ राण प्रतापगढ़ शाहपुरा
तृतीय	मयूकत राजस्थान	उदयपुर	18 अप्रैल 1948	राजस्थान प्रथम + उदयपुर
चतुर्थ	विशाल राजस्थान	जयपुर	30 मार्च 1949	मयूकत राजस्थान + बीकानेर जयपुर जोधपुर जैसलमेर
पंचम	मयूकत विशाल राजस्थान	जयपुर	15 मई 1949	विशाल राजस्थान मध मध
षष्ठम्	राजस्थान मध	जयपुर	26 जनवरी 1950	समूचा विशाल राजस्थान पिपरी (आबू को छोड़कर)
सातम	राजस्थान	जयपुर	1 नवम्बर 1956	राजस्थान मध + अजमेर आबू मुनेन टण्डा

वर्तमान में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान को 8 मभागा (जयपुर अजमेर बीकानेर जोधपुर कोटा व उदयपुर) व 32 जिलों (अजमेर अलवर भरतपुर सवाई रामगढ़ा भोलवाडा बीकानेर बूंदी

चित्तौड़गढ़ चुरू धौलपुर डूंगरपुर गंगानगर हनुमानगढ़ जयपुर जैसलमेर जालोर झालावाड झुझु, जोधपुर कोटा नागौर पाली गवाईभाधोपुर सीकर सिरोंही टोक उदयपुर टोंका बांस बरोली व राजसमन्द) में बांटा गया है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूचक					
क्र.	विवरण	वर्ष	राजस्थान	भारत	टिप्पणी
1	देश में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन	1982	10.43	00.00	देश में दूसरा स्थान
2	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन	1982	342 रु.	3287 रु.	देश में 14वां स्थान
3	जनसंख्या	1991	4.40 करोड़	84.63 करोड़	देश में 14वां स्थान
4	कुल जनसंख्या का औद्योगिक उत्पादन	1991	5.2	100.00	देश में 14वां स्थान
5	जनसंख्या वृद्धि की दर	1991	2.50	2.14	राज्य में औद्योगिक विकास
6	जनसंख्या घनत्व	1991	129 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	274 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	देश में 15वां स्थान
7	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	1991	22.8%	25.7%	राज्य में औद्योगिक विकास

क्र	विवरण	वर्ष	राजस्थान	भारत	टिप्पणी
8	सड़कर का प्रतिशत	1991	38.55	52.21	15वां स्थान
9	जनसंख्या में अनुसूचित जाति का भाग	1991	17.29%	16.33%	राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या
10	जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का भाग	1991	12.44%	8.08%	राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक जनसंख्या
11	नक्का मूल्य पर औसत प्रति व्यक्ति राजस्व आय	1995-96 की	7523	10525	देश में 41वां स्थान
12	सिंचनीय क्षेत्रों पर प्रति व्यक्ति आय	1997-98	2306	9660	राष्ट्रीय औसत से कम आय
13	प्रतिशत मूल्य पर राजस्व आय	1995-96	33705 करोड़	967763 करोड़	देश में 35वां स्थान
14	आठवीं पंचवर्षीय योजना का व्यय	1992-97	1500 करोड़ रु	186235 करोड़ रु	देश में 5वां स्थान
15	प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की सखा	सितम्बर 1998	6.4	6.7	देश में 11वां स्थान
16	प्रतिशत दैनिक मिश्रण	सितम्बर 1998	3582	6597	देश में 13वां स्थान
17	प्रति व्यक्ति बैंक सखा	सितम्बर 1998	1595	3542	देश में 12वां स्थान
18	औद्योगिक क्षेत्र	1991	4.11 हेक्टेयर	1.57 हेक्टेयर	देश में प्रथम स्थान
19	सड़करों के अवशेष का	1995-96	119 लाख हेक्टेयर	1235 लाख हेक्टेयर	राष्ट्रीय क्षेत्र का सापेक्ष 10 प्रतिशत
20	सड़करों का उत्पादन	1995-96	95.66 लाख टन	1850 लाख टन	साधन उत्पादन का सापेक्ष 5 प्रतिशत
21	सड़करों के क्षेत्रों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन का औसत	1994-95	34.8 कि.ग्र	75.7 कि.ग्र	देश में 13वां स्थान
22	कुल पशु	1982	496 लाख	4195 लाख	देश के पशुओं के 10 प्रतिशत से अधिक
23	सड़कर	1991	9.3%	20%	राष्ट्रीय औसत से कम
24	पशुओं के क्षेत्रों का सापेक्ष	1990	10038	196068	देश के सापेक्ष 5 प्रतिशत पशुओं को
25	सड़करों के क्षेत्रों का सापेक्ष	1993-94	5116	996 रु	कम औद्योगिक प्रतिनिधि 13 वां स्थान
26	सड़करों के क्षेत्रों का सापेक्ष	1995	687	1059	देश में 12वां स्थान
27	सड़करों के क्षेत्रों का सापेक्ष	1988	204 करोड़ रु	11461 करोड़ रु	सड़करों का पर्याप्त विकास नहीं
28	सड़करों के क्षेत्रों का सापेक्ष	1994-95	269.53 करोड़ रु	320.10 करोड़ रु	देश में 40वां स्थान
29	कुल सड़करों का निर्यात	मार्च 1995	85.82	85.95	सारा राष्ट्रीय औसत के बराबर देश में 6 वां स्थान
30	प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर वाहनों की सख्या	31 मार्च 1995	3551	3587	देश में 8वां स्थान
31	प्रति हजार की किलोमीटर पर रेलमार्ग की सख्या	1991-92	17.02 कि.मी	19.00 कि.मी	देश में 12वां स्थान
32	सड़करों की सख्या	1994-95	1,30,085 कि.मी	22,00,163 कि.मी	देश में 7वां स्थान
33	सड़करों के क्षेत्रों का सापेक्ष	सितम्बर 1998	1060	14419	
34	सड़करों के क्षेत्रों का सापेक्ष	सितम्बर 1993	1969	45280	
35	अन्य अनुसूचित व्यापारिक बैंक	सितम्बर 1998	253	4918	
36	कुल क्षेत्रों की सख्या	सितम्बर 1998	3282	64647	
37	सड़करों की सख्या	1990-91	9870	1,48,719	

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति

POSITION OF RAJASTHAN IN INDIAN ECONOMY

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है।

स्थिति एवं क्षेत्रफल

Location and Area

भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित राजस्थान 23°3' उत्तरी अक्षांश से 30°11' उत्तरी अक्षांश व 69°29' पूर्वी देशान्तर से 78°17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

1 यह पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर लंबा है।

2 राजस्थान की सम्पूर्ण सीमा स्थलीय है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का 1070 किलोमीटर का भाग पाकिस्तान से जुड़कर अन्तर्गोलीय सीमा बनाता है।

3 राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब व हरियाणा और दक्षिण में गुजरात व मध्य प्रदेश हैं, जो राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं।

4 राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.43 प्रतिशत है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश (13.50%) के परान्वृत्त द्वितीय स्थान राजस्थान का ही है और तीसरा, चौथा व पांचवा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व आन्ध्र प्रदेश का है।

5 राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के अनेक राष्ट्रों की तुलना में बड़ा है। राजस्थान मॉरोको में लगभग 171 गुणा, चीन में लगभग पांच गुणा, जर्मनी में लगभग चार गुणा, फ्रांस व हंगरी में लगभग साठे से बीस गुणा, कुवैत से 19 गुणा, इराक में लगभग 16 गुणा, बेल्जियम में लगभग 11 गुणा, स्विट्जरलैंड में लगभग 8 गुणा, डेनमार्क का लगभग 3 गुणा, ऑस्ट्रिया का लगभग 4 गुणा, पुर्तगाल, नेपाल व बांग्लादेश का लगभग दस गुणा है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रों जैसे - ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, नार्वे, जर्मनी आदि के क्षेत्रफल से भी अधिक है।

क्षेत्रफल की स्थिति (हजार वर्ग किलोमीटर)

राजस्थान का क्षेत्रफल	342
भारत का क्षेत्रफल	3287

राजस्थान से बड़ा राज्य

मध्य प्रदेश	443
राजस्थान से भारत के छोटे प्रमुख राज्य	
महाराष्ट्र	308
उत्तर प्रदेश	294
अन्ध्र प्रदेश	275

राजस्थान से छोटे विश्व के प्रमुख विकसित राष्ट्र

जापान	378
इटली	301
स्विट्जरलैंड	271
ब्रिटेन	245
स्विजरलैंड	41

स्रोत: World Development Report 1987, Statistical Abstract

Rajasthan 1984

जनसंख्या

Population

जनसंख्या विकास का मापन व साध्य दोनों हैं। यह विकास के लिए आवश्यक प्रमत्त उदरभोग्य कच्ची है। साथ में यह उपभोक्ताओं के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए आवश्यक भाग भी उत्पन्न करती है।

1991 की जनगणना पर आधारित कुछ तथ्य

राजस्थान की जनसंख्या	4.40 करोड़
भारत की जनसंख्या	84.63 करोड़
राज्य का देश का जनसंख्या में प्रतिशत भाग	5.2 प्रतिशत
राजस्थान से अधिक जनसंख्या वाले भारत के प्रमुख राज्य	
उत्तर प्रदेश	13.91 करोड़
बिहार	8.63 करोड़
महाराष्ट्र	7.89 करोड़
राजस्थान से कम जनसंख्या वाले भारत के प्रमुख राज्य	
गुजरात	4.13 करोड़
उत्तराखण्ड	3.16 करोड़
केरल	2.90 करोड़

स्रोत: India 1988

1-4 Resource Atlas of Rajasthan Govt. of Rajasthan
5-6 Economic Review 1987-88 Govt. of Rajasthan
7 World Development Report, 1987

1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश व राजस्थान में भाग का तात्पा 40% जनसंख्या निवासकर्ता है। 1981-91 के दशक में भारी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई, उसमें 40% से अधिक भाग की वृद्धि भी इसी राज्य के कारण हुई। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4.40 करोड़ थी और यह भारत की कुल जनसंख्या (84.63) करोड़ का 5.2% है। जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान का नवा स्थान है। 1981-91 के दशक में भूमि में औसत वृद्धि दर 2.14% रही है। इसकी तुलना में राजस्थान में जनसंख्या 2.50% की दर से बढ़ी है। भारत में 1990-91 में जन व मृत्यु दर क्रमशः 29.2 व 10.1 प्रति हजार थी जबकि इसी वर्ष राजस्थान में ये दर क्रमशः 35 और 10.1 प्रति हजार थी। इस प्रकार राजस्थान में जन व मृत्यु दर अखिर भारतीय औसत से अधिक है। राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थलीय होने के कारण राज्य में जनसंख्या का घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत के घनत्व (267) के आधे से भी कम है। भारत की भांति राजस्थान में भी ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। राजस्थान में ग्रामण और शहरी जनसंख्या क्रमशः 3.39 करोड़ व 1.00 करोड़ है। जबकि भारत की जनसंख्या क्रमशः 62.9 करोड़ व 21.6 करोड़ है। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का भाग 5.20%, भारत की ग्रामीण जनसंख्या में राजस्थान का 5.39% एवं मरुस्थलीय देश की भांति राजस्थान में अशिक्षितों की एक बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है। भारत के छ राज्य, अन्ध प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भारत की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये साथ ही देश के निरक्षरों का तात्पा 60% भाग भी इन छ राज्यों में रहता है। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 38.55% है जो राष्ट्रीय औसत (52.21%) से कम है। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। राजस्थान में स्त्री पुनर्गण (910) राष्ट्रीय अनुपात (626) से कम है।

जनसंख्या की दृष्टि में भारत में राजस्थान का स्थान 1991		
क्र.सं.	विभाग	राज्यवार स्थान
1	कुल जनसंख्या	9
2	जनसंख्या घ घात	15
3	ग्रामीण जनसंख्या	15
4	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	12
5	महिला जनसंख्या	7

कृषि

Agriculture

कृषि राजस्थान के जन जीवन का आधार है। वर्ष-आगत 1990-91 के अनुसार राज्य में 51.07 लाख हेक्टेयर जोते थी। 1980-81 में जोतों का औसत अक्षर 4.44 हेक्टेयर था जो 1990-91 में घटकर 4.11 हेक्टेयर रह गया है। इस दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं आ सकती है जबकि समग्र भारत में जोतों का औसत अक्षर 1.68 हेक्टेयर है। औसत कृषि जोतों की दृष्टि में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान पंजाब का एवं तृतीय गुजरात का है। औसत जोत के बड़े होने के कारण राजस्थान में वैज्ञानिक कृषि की सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

प्रमुख फसलों का उत्पादकता (1994-95)	
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर	
राजस्थान की प्रमुख फसलें जिनकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है	
राजस्थान	भारत
1. चने	864
2. जलदी	364
3. कपास	919
260	
राजस्थान की प्रमुख फसलें जिनकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है	
राजस्थान	भारत
1. गन्ना	2417
2. बाजरा	1088
3. मूंगफली	790
4. जौ	227
5. मक्का	887
6. जन्म	45036
71095	

भारत के कुल फसल क्षेत्रफल का 10.45% राजस्थान में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र कुल फसल क्षेत्र प्रतिशत में राजस्थान से आगे है। इस प्रकार कुल फसल की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं आ सकती है। साथ ही, राजस्थान में कुल फसल क्षेत्र के विस्तार की भावी सम्भावनाएं भी विद्यमान हैं। राजस्थान नहर के निर्माण से कुल फसल क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। कुल फसल क्षेत्र का एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र कृषि विज्ञान हम एक सूचक बन गया है। इस दृष्टि से राजस्थान (6.94%) का स्थान

1. S. S. Economic Review 1991-92 Govt. of Rajasthan
2. S. S. Statistical Abstract, Rajasthan 1994
3. S. S. Draft Ninth Five Year Plan 1987-2002 Govt. of Rajasthan
10-11 A brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan
Dec. 1993

क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व पंजाब के पश्चात् आता है।¹ इससे हम बात का आभास मिलता है कि राजस्थान में अधिकांश कृषि भूमि पर केवल एक फसल ली जाती है। मिर्चाई साधनों की वृद्धि के साथ-साथ इस क्षेत्र में वृद्धि होगी। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 7.70% भाग राजस्थान में विद्यमान था, जबकि उत्तरप्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र संपूर्ण भारत में सर्वाधिक था।² सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान छठा था, द्वितीय स्थान आंध्रप्रदेश का व तृतीय स्थान पंजाब का, चतुर्थ मध्य प्रदेश व पांचवा बिहार का था।³ इस प्रकार से राजस्थान का छठा स्थान सतोषप्रद प्रतीत होता है, किन्तु राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल को देखते हुए इसे सतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राजस्थान नहर के कम खंड क्षेत्र का पूर्ण विकास होने पर सिंचित क्षेत्र सतोषजनक होने की आशा है। खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषजनक नहीं जा सकती है। राजस्थान का प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न का त्रिवार्षिक औसत उत्पादन 194 किलोग्राम था और इस दृष्टि से राजस्थान का देश में सातवा स्थान था। इस दृष्टि से प्रथम स्थान पंजाब, द्वितीय हरियाणा व तृतीय स्थान उत्तर प्रदेश का था।⁴ इस प्रकार राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में और वृद्धि की चेष्टा की जानी चाहिये। राजस्थान में कृषि उपजों के कम होने का एक बड़ा कारण मिर्चाई के अभाव में खाद का कम प्रयोग कर्त्ता भी रहा है। राजस्थान में बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर 34.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग हो रहा था, जो राष्ट्रीय औसत (75.7) किलोग्राम से कम था और वह देश में 13 वें स्थान पर था, जबकि 174.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग करके पंजाब प्रथम स्थान पर था।⁵ खाद का उपयोग बढ़ाने के लिए राजस्थान में मिर्चाई के साधनों में वृद्धि करनी होगी।

कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र.सं.	विवरण	राज्यवार स्थान
1	औसत कृषि जल (1990-91)	1
2	बोये गये क्षेत्रफल का प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग (1994-95)	13
3	कुल फसल क्षेत्र (1990-91)	4
4	एक में अधिक बार बोया गया क्षेत्र (1990-91)	7
5	खाद्यान्न का उत्पादन (1990-91)	8

स्रोत: Economic Review 1997-98 Rajasthan Statistical Abstract, Ra.asthan 1994

1992 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या 4.84 करोड़ थी जो राज्य की जनसंख्या

के लगभग 1:1 के अनुपात में थी। देश के कुल पशुओं का लगभग 7% राजस्थान में निवास करता है। राजस्थान देश के दूध उत्पादन का 10% में अधिक, मांस उत्पादन का 30% और ऊन उत्पादन का 42% उपलब्ध कराता है।

उद्योग एवं खनिज

INDUSTRY & MINERALS

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। संपूर्ण भारत के रजिस्टर्ड कारखानों का केवल 3.35% ही राजस्थान में कर्त्तव्य है। रजिस्टर्ड कारखानों की दृष्टि से राजस्थान 15वें स्थान पर है, जबकि प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु है।⁶ सयुक्त स्कन्ध कंपनियों (निजी व सार्वजनिक) की संख्या की दृष्टि से भी राजस्थान का 10वा स्थान है।⁷ राजस्थान में देश में विद्यमान इन कंपनियों की संख्या का मात्र 1.96% विद्यमान है।⁸ कंपनियों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल में है। इन कंपनियों में लगी दल पूंजी की दृष्टि से भी राजस्थान बहुत पीछे है। संपूर्ण देश में राजस्थान (1.44%) का स्थान इस दृष्टि से 11वा है। सर्वाधिक पूंजी क्रमशः पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में लगी हुई है।⁹ खनिज उद्योग की दृष्टि से यद्यपि राजस्थान खनिजों में धनी है और अनेक खनिजों के उत्पादन में उसका प्रभुत्व भी है, किन्तु खनिज उद्योग द्वारा उत्पादित खनिजों के मूल्य के अनुसार राजस्थान 10वें (1.85%) स्थान पर था।¹⁰ इस दृष्टि से प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात थे।¹¹ उद्योगों से प्रतिव्यक्ति आय-वृद्धि की दृष्टि से भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से प्रतीत होता है। इस दृष्टि से राजस्थान का 13 वा स्थान था और राजस्थान में उद्योगों की प्रतिव्यक्ति आय-वृद्धि राजस्थान में 511 रुपये थी जो राष्ट्रीय औसत (996 रुपये) से काफी कम थी। इस दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान गुजरात व तृतीय स्थान तमिलनाडु का था।¹²

उद्योग एवं खनिज की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र.सं.	विवरण	राज्यवार स्थान
1	पंजीकृत कारखाने (1988-89)	15
2	निजी व सार्वजनिक कंपनियों (1996-97)	10
3	दल पूंजी (1986-87)	11
4	उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि (1994-95)	10
5	उत्पादित खनिजों का मूल्य (1991-92)	10

स्रोत: Economic Review 1998-99 Rajasthan Statistical Abstract, Rajasthan 1994

1. 2. 3. 7. 8. 9. 11. Statistical Abstract, Rajasthan 1994
4. Economic Review 1996-97 Govt. of Rajasthan
5. 12. Economic Review 1997-98 Govt. of Rajasthan

संरचनात्मक ढांचा (Infra-Structure)

संरचनात्मक ढांचा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होता है। इसके अन्तर्गत प्रायः शक्ति, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति का आभास निम्नलिखित विवेचन से हो सकेगा -

1. शक्ति (Power) - राजस्थान में शक्ति का प्रमुख स्रोत, जल-विद्युत व तापीय विद्युत है। गणप्रताप सागर बाँध पर स्थित खेतभाटा का अनुशक्ति गृह भी राज्य का महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। राजस्थान के अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में कोयले का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का भण्डार मिलने के कारण प्राकृतिक गैस भी शक्ति का महत्वपूर्ण सम्भावित साधन बन गया है। राज्य में खनिज तेल भी मिला है, किन्तु उसके वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। शक्ति के गैर-परम्परागत साधनों में राजस्थान में सौर-ऊर्जा, वायु ऊर्जा व गोबर गैस की अच्छी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। विद्युत-उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषजनक नहीं है। राजस्थान में पर्याप्त जल भण्डार नहीं होने के कारण राज्य के बाहर से जल-विद्युत का आयात करना पड़ता है। विद्युत-उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में दसवें स्थान पर था और देश को केवल 2.5% विद्युत उत्पादित कर रहा था। इस दृष्टि से महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्य अच्छी स्थिति में थे। विद्युत का उपयोग भी आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। प्रतिव्यक्ति विद्युत-उपयोग की दृष्टि से राजस्थान दसवें स्थान (269.53 किलोवाट) पर था। इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर पंजाब तथा दूसरे स्थान पर गुजरात था। राजस्थान का प्रतिव्यक्ति विद्युत उपयोग, राष्ट्रीय औसत (320.10 किलोवाट) से कम होने के कारण राज्य के पिछड़ेपन को दर्शाता है। मार्च 1995 में देश के औसत 85.9% गाँव विद्युतीकृत थे, जब कि राजस्थान में केवल 85.8% गाँव ही विद्युतीकृत हो पाये थे। इस अवधि तक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब व तमिलनाडु शत-प्रतिशत

शक्ति की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र	विवरण	राजस्थान का स्थान
1	विद्युत उत्पादन (1989-90)	10
2	विद्युत उपयोग (1989-90)	10
3	प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग (1994-95)	10
4	कुल ग्रामों से विद्युत-इस ग्रामों का प्रतिशत (मार्च 1995)	5

स्रोत: Economic Review 1997-98, 1998-99 & other Statistical Abstracts, Rajasthan 1994

विद्युतीकृत हो चुके थे।

2 सिंचाई (Irrigation) - राजस्थान में महत्वपूर्ण के अनुसार कुएँ (नलकूप सहित) नहरें और तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन हैं।

राज्यों में नहरों का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सिंचाई की दृष्टि से राज्य के लिए इंदिरा गांधी नहर का विशेष महत्व है, जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को कार्यायुक्त कर देगी। सिंचाई के विभिन्न साधनों से राजस्थान में सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है, फिर भी भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 7.7% ही राजस्थान में है। इस प्रकार राजस्थान का इस दृष्टि से छठवाँ स्थान है। प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश व पंजाब हैं।

3 परिवहन (Transport) - राजस्थान की दृष्टि से सड़क व रेल परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वायु परिवहन का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है और राज्य के, सभी महत्वपूर्ण नगर इससे जुड़े नहीं पाये हैं। 12 महीने बहने वाली नदियों के अभाव के कारण आंतरिक जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया किन्तु राजस्थान नहर के निर्माण से आंतरिक जल-परिवहन की सम्भावनाएँ जन्म लेने लगी हैं। राज्य में खनिज तेल व गैस के भण्डार मिलने से पाईपलाइन यातायात का विकास होगा। राजस्थान की दृष्टि से सड़कें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे ही राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों को जोड़ती हैं। वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में निर्मित सड़कों की लंबाई 42.68 किलोमीटर थी जो कि राष्ट्रीय औसत 73 कि.मी. से बहुत कम है। राज्यानुसार उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में देश की 0.06% पक्की सड़कें थी और इस दृष्टि से क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे आगे थे। राजस्थान के प्रति लाख जनसंख्या पर मोटरगाड़ियों की संख्या 31 मार्च 1996 को 355.1 थी और राजस्थान का इस दृष्टि से आठवाँ स्थान था। राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर मोटरगाड़ियों की संख्या राष्ट्रीय औसत 358.7 से कम थी। इस दृष्टि से देश में क्रमशः पंजाब प्रथम स्थान पर, गुजरात द्वितीय स्थान पर और हरियाणा तृतीय स्थान पर थी। राजस्थान में रेल मार्गों का अधिक विकास नहीं हो पाया है। इसी कारण राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्गों की लंबाई (17.02 किलोमीटर) राष्ट्रीय औसत (19 किलोमीटर) से कम थी। 3 मार्च, 1992 के इन आंकड़ों के अनुसार प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक रेलमार्ग पश्चिम बंगाल में थे। द्वितीय स्थान पंजाब एवं तृतीय स्थान हरियाणा का था। राजस्थान रेलमार्गों की दृष्टि में 12 वें स्थान पर था।

परिवहन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र	विवरण	राजस्थान का स्थान
1	कुल पक्की सड़कें (1988-89)	8
2	प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च, 1996)	8
3	इतिहास किलोमीटर पर रेलमार्गों की लंबाई (1991-92)	12

स्रोत: Economic Review 1997-98, 1998-99 & other Statistical Abstracts, Rajasthan 1994

15879 Statistical Abstract, Rajasthan, 1994

2348 Economic Review 1997-98, 1998-99 Govt. of Rajasthan

राजस्थान के नियोजन कार्यालयों में 8.95 लाख व पूरे राष्ट्र में 3.74 करोड़ रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के नाम दर्ज थे।

3 सहकारिता (Co-operation) - राजस्थान में 20255 सहकारी समितियाँ थी। इनकी वार्षिकीत पूँजी 1390.47 करोड़ रुपये थी। इनमें 64.11 लाख व्यक्ति सदस्य थे। इन सहकारी समितियों की अंश-पूँजी 187.87 करोड़ रुपये थी। 1988-89 के उपलब्ध राज्यवार तुलनात्मक आँकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत की साख समितियाँ का 5.12% व गैर साख समितियों का 3.82% राजस्थान में विद्यमान था। भारत की सर्वाधिक साख और गैर साख समितियाँ महाराष्ट्र में थी।

4 योजनाओं की स्थिति (Planning in Rajasthan) - राज्य की योजनाओं से राज्य की वर्तमान एवं भवी कार्यक्रमाँ का आभास होता है तो साथ ही राज्य के भवी स्वरूप का अनुमान भी लगाया जा सकता है। राजस्थान में योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति बहुत अधिक सतोषजनक नहीं कहा जा सकता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना - व्यय 34 रुपये था जो सभी राज्यों के औसत (38 रुपये) से कम था। राष्ट्रीय औसत राजस्थान के प्रतिव्यक्ति योजना व्यय में आगामी योजनाओं के अंतर्गत अंतर बढ़ता गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जबस राजस्थान में प्रतिव्यक्ति योजना व्यय राष्ट्रीय औसत (51 रुपये) से अधिक रहा। तीसरी योजना में भी लगभग वही स्थिति रही जब राजस्थान का औसत प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (97 रुपये) राष्ट्रीय औसत (92 रुपये) अधिक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय औसत (142 रुपये) और राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (120 रुपये) रहा। पाचवी योजना में भी यह व्यय (332) रुपये राष्ट्रीय औसत (362 रुपये) से कम रहा। छठी योजना के अंतर्गत भी लगभग वही स्थिति बनी रही। इस योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (622 रुपये) राष्ट्रीय औसत (718 रुपये) से कम रहा। सातवी पंचवर्षीय योजना में यह अंतराल और बढ़ा। इस योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (875 रुपये) राष्ट्रीय औसत (1157 रुपये) से काफी कम था। इस प्रकार राष्ट्रीय औसत एवं राजस्थान के प्रतिव्यक्ति आय में अन्तर निम्नतर रह रहा है। मातृकी योजना के परिचय की दृष्टि में राजस्थान का 11वा स्थान रहा जबकि महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। आठवी योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय 2613 रुपये था। 1998-99 के दबट अनुमानों के आधार पर राजस्थान में प्रतिव्यक्ति विकास पर किया गया व्यय 1359.88 रुपये था और इस दृष्टि से राजस्थान 9वें स्थान पर था। इसी वर्ष

प्रतिव्यक्ति विकास पर व्यय की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे।

5 राजस्व (Public Finance) - पर्याप्त राजस्व उपलब्ध होने पर ही विकास कार्यों को गति दी जा सकती है। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति राजस्व व्यय, 1998-99 के अंतर्गत 2250.29 रुपये था और राजस्थान इस दृष्टि से दसवें स्थान पर रहा। प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः पंजाब, हिमाचल प्रदेश, व हरियाणा थे। प्रतिव्यक्ति राजस्व 1998-99 में राजस्थान में 1990.12 रुपये था और इस दृष्टि से राजस्थान का दसवा स्थान था। प्रतिव्यक्ति राजस्व की दृष्टि से जम्मू-कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे। प्रतिव्यक्ति राजस्व कम होने पर भविष्य में राजस्व को बढ़ाने की अच्छा भावनाएँ विद्यमान होती हैं। इस दृष्टि से 1998-99 में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति कर राजस्व 1408.74 रुपये था और देश में दसवें स्थान पर था। सर्वाधिक कर राजस्व केरल, में था। इसके पश्चात् गुजरात व तमिलनाडु थे। प्रतिव्यक्ति कर राजस्व कम होने का एक प्रमुख कारण आर्थिक दृष्टि में पिछड़ा होना है। राजस्थान में केंद्रीय करों का प्रतिव्यक्ति अंश 1998-99 में 541.39 रुपये था और 5वें स्थान पर था। प्रथम व द्वितीय स्थान क्रमशः जम्मू व कश्मीर व हिमाचल प्रदेश का था।

राजस्व की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र.सं.	विवरण	राज्यवार स्थान
1	प्रतिव्यक्ति राजस्व (1998-99)	10
2	प्रतिव्यक्ति कर राजस्व (1998-99)	10
3	केंद्रीय करों का प्रतिव्यक्ति अंश (1998-99)	5
4	प्रतिव्यक्ति राजस्व व्यय (1998-99)	10

Source: Economic Review 1998-99, Rajasthan.

6 कुल एवं प्रतिव्यक्ति राज्य आय (Total & Per capita GDP) - राज्य की कुल एवं प्रतिव्यक्ति आय में अर्थव्यवस्था की स्थिति का परिचय मिलता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण राज्य की आय पर मानसून की अनुकूलता व प्रतिकूलता का गहरा प्रभाव पड़ता रहा है। राजस्थान में कम आय का एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होना भी रहा है। राजस्थान का प्रतिव्यक्ति आय वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर लगभग राष्ट्रीय औसत से कम रहती आई है।

1974-75 से निम्नतर राजस्थान में प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत में कम रहती है। विभिन्न राज्यों की तुलना में भी राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। प्रचलित वित्तता पर वर्ष

जुटाना कठिन है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण राज्य में बेरोजगारी एवं निर्धनता आदि समस्याएँ भी विकसित रूप धारण कर चुकी हैं। निरक्षरता व नगरीकरण से परिसंस्थितियाँ प्रतिकूल हुई हैं।

4 कृषि की विशिष्ट समस्याएँ (Problems before agriculture) - राजस्थान में कृषि का प्रमुख स्थान है। लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। कृषि के विकास हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षाकृत कम धन का विनियोग किया गया है। राज्य में कृषि संबंधी कुछ विशिष्ट समस्याएँ भी विद्यमान हैं। मानसून की अनिश्चितता एवं वर्षा का अभाव, सिंचाई-सुविधाओं का अभाव, जल ससाधनों व अपेक्षाकृत कम कृषि-योग्य भूमि की उपलब्ध तथा पशुधन के समुचित विकास का अभाव आदि के कारण देश के अन्य राज्यों के समान कृषि का विकास नहीं हो पाया है। कृषि संबंधी उन्नत तकनीक का प्रयोग भी अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है। अतः राजस्थान कृषि विकास की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। भूमि सुधारों की धीमी प्रगति, उचित जल प्रबंध का अभाव, क्षारीय व लवणीय मिट्टियों की समस्या और सरकारी साख की अपर्याप्तता ने कृषि विकास में बाधा उत्पन्न कर राज्य के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है।

5 प्राकृतिक ससाधनों का अपेक्षाकृत कम उपयोग (Low utilization of natural resources) - देश के अन्य राज्यों की तुलना में भूमि, भूगर्भीय जल, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक ससाधनों का कम उपयोग किया गया है। भारत सरकार ने भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के विकास हेतु कम पूँजी विनियोजित की है। राज्य के उत्पादक कारकों जैसे - पूँजी, कुशल श्रम, उन्नत तकनीक एवं उद्यमियों की कमी के कारण भी राज्य के प्राकृतिक ससाधनों का अपेक्षाकृत कम उपयोग हो पाया है। अतः राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में बना हुआ है।

6 औद्योगिक पिछड़ापन (Industrial backwardness) - राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से भी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के औद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने देश के उन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया जहाँ पहले से ही औद्योगिक विकास की कुछ सुविधाएँ उपलब्ध थीं। ऐसी स्थिति में राजस्थान जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास न हो पाना स्वाभाविक था। यही कारण है कि

राजस्थान में औद्योगिक संरचना का निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया है। औद्योगिक रूपरत श्रम संबंधों व विवादों, शक्ति के साधनों के अभाव, परिवहन के अपर्याप्त साधन, कुशल श्रमिकों का अभाव, उन्नत तकनीक का अभाव तथा बीमा एवं बैंकिंग सुविधा की अपर्याप्त सुविधा के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमों भी राजस्थान में पूँजी विनियोग करने का साहस नहीं कर पाते हैं। अतः राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से औद्योगिक वातावरण बहुत रहा है।

7. शक्ति के लगभग सभी प्रमुख साधनों का अभाव (Lack of power resources) - राजस्थान में शक्ति के साधनों का अन्य राज्यों की तुलना में अभाव है। अतः राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। कोयले एवं विद्युत शक्ति के लिए राजस्थान को देश के अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान में शक्ति के अपरम्परागत स्रोत जैसे- सौर ऊर्जा, व पवन ऊर्जा की प्रबल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं लेकिन पूँजी के अभाव के कारण शक्ति के इन अपरम्परागत साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। शक्ति के साधनों के अभाव के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था देश के अन्य अनेक राज्यों के समान विकास नहीं हो पायी है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से स्थिति में परिवर्तन आने की संभावना है।

8 परिवहन के साधनों का अपेक्षाकृत कम विकास (Under development of transportation facilities) - राजस्थान का अधिकतर भू-भाग रेगिस्तानी, पहाड़ी व पथरीला है। अतः राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में सड़क परिवहन का धीमी गति में विकास हुआ है। राजस्थान में रेल परिवहन का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। आज भी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में ब्रॉड गेज की सुविधा नहीं है। इसी प्रकार वायु परिवहन सुविधाएँ भी अन्य अनेक राज्यों की तुलना में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं।

9 सामाजिक सुविधाओं का अभाव (Lack of social facilities) - राजस्थान में विभिन्न सामाजिक सुविधाओं जैसे - शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा व पोषाहार आदि का देश के अन्य अनेक राज्यों की तुलना में अभाव है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण-संस्थाओं का आज भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं चिकित्सा सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। इन सभी तथ्यों से ज्ञात होता है कि राजस्थान देश के अन्य अनेक राज्यों की तुलना में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है।

10 अधविश्वास, भाग्यवादिता एवं परम्परागत समाज (Traditional society) - राजस्थान में प्राचीनकाल से ही सामन्तवादी व्यवस्था विद्यमान है। स्वतंत्रता के पूर्व तक यह राज्य अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। सामन्तवादी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न रियासतों में अनेक प्रकार की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं, कु-प्रथाओं एवं परम्पराओं का प्रचलन हो गया। राज्य में बाल विवाह, मती प्रथा, पर्दा प्रथा, फिचूलखर्ची, अरिस्ता अधविश्वास, अज्ञानता, धार्मिक व सामाजिक मान्यताएँ तथा भाग्यवादिता आदि लंबे समय से चली आ रही है। ये प्रथाएँ एवं परम्पराएँ राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अत्यधिक बाधक रही हैं। अन्य अनेक राज्यों की तुलना में इन प्रथाओं और परम्पराओं का राजस्थान में प्रभुत्व रहा है और आज भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्पष्ट छलक देखी जा सकती है।

11 दोषपूर्ण नियोजन प्रक्रिया (Defective Planning) - भारत के अन्य राज्यों के समान राजस्थान में भी आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया 1950-51 में अपनायी गई। उस समय राजस्थान की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। राज्य की निर्माण प्रक्रिया ही 1956 में पूर्ण हुई। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू नहीं की जा सकी। राज्य में पंचायती राज मन्थाओं की स्थापना तो कर दी गई लेकिन नियोजन प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर अपनाया नहीं गया। अतः स्थानीय श्रमशक्ति एवं साधनों का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वय नहीं हो सका। जन सहभागिता के अभाव, परियोजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में देरी आदि से नियोजन प्रभावपूर्ण नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में दोषपूर्ण नियोजन के कारण राजस्थान का भारत के अन्य राज्यों के समान आर्थिक विकास नहीं हो पाया।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए।
Discuss the present position of the State of Rajasthan in Indian Economy
2. राजस्थान राज्य का संक्षेप में भौगोलिक परिचय दीजिए।
Give in brief a geographical introduction of the state of Rajasthan
3. स्वस्थ अर्थव्यवस्था के कौन से सूचक हैं?
What are the indicators of healthy economy?
4. राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए।
Explain the various stages of integration of the Princely States in Rajasthan

(B) विस्तारार्थक प्रश्न

(Essay Type Questions)

1. "राजस्थान के धीमे आर्थिक विकास का लिए सन्तु अन्ततः राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सूखता और रिमाव, दोषपूर्ण प्राथमिकताएँ, उपागम वन सहयोग का केन्द्रिय महत्त्व पर अत्यधिक निर्भरता ही उत्तरदायी है।" समीक्षा कीजिए।
"Slow Economic Development in Rajasthan is due to perennial famines, lack of political will, linkage and leakage, defective priorities, passive public sector and excessive dependence on central assistance." Discuss
2. राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारित कीजिए।
Determine the position of the State of Rajasthan in Indian Economy
3. राजस्थान प्रदेश का स्थिति का तुलना भारतीय स्थिति व मध्य पूर्व प्रदेशों के आधार पर जाँच।
(अ) जनसंख्या (क) क्षेत्रफल (ग) कृषि व (घ) उद्योग
Compare the positions of Rajasthan state with that of Indian position on the basis of the following points:
a. Population b. Area c. Agriculture and d. Industry
4. "राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है।" इस कथन का समर्थन या विरोध भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति की विवेचना कीजिए।
"Rajasthan is a backward region in a backward economy." Discuss the position of Rajasthan in Indian Economy with reference to this statement
5. राजस्थान प्रदेश का आर्थिक स्थिति का तुलना मध्य भारत की आर्थिक स्थिति से कीजिए और उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनसे राजस्थान प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रह गया।

Compare the economic position of Rajasthan state with that of India and throw light on those causes which have made it backward in comparison to other states

- राजस्थान राज्य की आर्थिक स्थिति की तुलना भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की आर्थिक स्थिति से कीजिए।

Compare the economic position of Rajasthan state with that of other important states of India

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Examinations Questions)

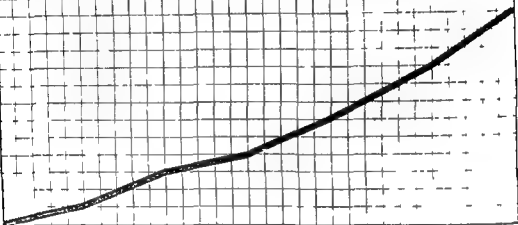
- 1 राजस्थान राज्य का अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारित कीजिए।
Determine the position of the State of Rajasthan in Indian Economy
- 2 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को समझाईए जिनसे ज्ञात होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में है।
Explain those factors which show that the state of economy of Rajasthan is backward
- 3 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जनसंख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में क्या स्थिति है?
What is the population of Rajasthan in Indian Economy with reference to population Area Agriculture Industry and Infrastructure?



अध्याय - 2

राजस्थान में मानवीय संसाधन

HUMAN RESOURCES IN RAJASTHAN



“किसी राष्ट्र की वास्तविक न सम्पत्ति उसकी भूमियों व नदियों में, न उसके वनों व खानों में, न उसके पशु व मीनिक सम्पत्ति में निहित हैं, बरन उसके स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न स्त्री, पुरुष व बच्चों में निहित है।”

अध्याय एक दृष्टि में

- जनसंख्या का महत्व
- राजस्थान में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि
- राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर
- राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या
- राजस्थान में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण
- राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात
- राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व व असमान वितरण
- राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति
- राजस्थान में मानव संसाधन विकास के तीन महत्वपूर्ण सूचक
- राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम
- अध्यासार्थ प्रश्न

मानवीय संसाधनों का महत्व

IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES

“किसी राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति न उसकी भूमियों व नदियों में, न उसके वनों व खानों में, न उसके पशु व मीनिक सम्पत्ति में निहित है, बरन उसके स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न स्त्री, पुरुष व बच्चों में निहित है।” श्री सी प्रिंसिपल के ये शब्द जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। जनसंख्या आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फ्रेडरिक हर्बिसन ने इस संदर्भ में कहा है, “राष्ट्र का विकास प्रथम एवं मुख्यतः उसके लोगों की प्रगति पर निर्भर करता है। यदि वह इनकी आत्मा और मानवीय सम्भाव्यताओं का विकास नहीं करता तो यह भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक रूप से अधिक विकसित भी नहीं हो सकता।” इस प्रकार जनसंख्या विकास का प्रमुख आधार है और विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय संसाधनों के माध्यम से उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जनसंख्या की कमी और वृद्धि उस देश एवं राज्य के समग्र जहाँ अनेक समस्याओं को जन्म देती है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति को भी प्रभावित करती है। राजस्थान की जनसंख्या, उसकी संरचना और उसकी अन्य विशेषताओं से परिचित

होना, राज्य के विकास के लिए अपरिहार्य है। मक्षेप में, जनसंख्या का सवर्ध और उसका महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है -

1 जनसंख्या व शक्ति (Population & Power) - जनसंख्या का आकार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। त्रिस प्रकार विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा (पूर्व) सोवियत संघ, दोनों ही जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम दस राष्ट्रों में आते थे, उसी प्रकार एक राष्ट्र में एक राज्य विशेष का महत्व उसकी जनसंख्या के कारण बढ़ जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार आदि अपनी जनसंख्या के आकार के कारण ही अधिक महत्व प्राप्त कर चुके हैं।

2 जनसंख्या व श्रम (Population & Labour) - जनसंख्या का सीधा संबंध देश एवं राज्य की कार्यशील जनसंख्या से है, फलस्वरूप राज्य को विकास के लिए आवश्यक श्रमशक्ति जनसंख्या से ही उत्पन्न होती है। कार्यशील जनसंख्या के निर्धारण के लिए उस राज्य में आयु के अनुसार जनसंख्या का विवरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3 जनसंख्या साधन एवं साध्य (Population as ends & Means) - उत्पादन के विभिन्न साधनों में श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। इसी कारण यह उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस साधन में विनियोग करके इसकी उत्पादकता व गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार तैयार किया जा सकता है। जनसंख्या साधन उपलब्ध कराने के साथ ही एक साध्य भी है, क्योंकि देश एवं राज्य में जो कुछ भी कार्य सम्पन्न होते हैं, उनका लक्ष्य जनसंख्या का अधिकतम कल्याण ही होता है।

4 मांग का निर्माण (Creation of Demand) - अधिक जनसंख्या के कारण अधिक प्रभावपूर्ण मांग का जन्म होता है, किसी राष्ट्र के विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण मांग का निर्माण होने से विकास की गति तेज होती है, क्योंकि मांग उत्पन्न होने पर ही अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा। कोन्स ने प्रभावपूर्ण मांग के महत्व पर अत्यधिक बल दिया है।

5 उत्पादन का पैमाना (Scale of Production) - यह आवश्यक तो नहीं है कि जनसंख्या अधिक होने पर कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मांग उत्पन्न होगी, किन्तु यह वास्तविकता है कि अधिक जनसंख्या होने पर, अन्य तत्वों के समान रहने पर, अधिक मांग उत्पन्न होगी। इस कारण जनसंख्या अधिक होने पर देश में उत्पादन का पैमाना भी बड़ा होने की अधिक संभावनाएँ रहती हैं। इस

कारण राष्ट्र व राज्य बड़े पैमाने की आंतरिक और बाह्य निर्यातों का प्राप्त कर सकते हैं।

6 शोध, अनुसंधान एवं आविष्कार (Research & Invention) - अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए अनेक प्रकार के शोधकार्य निरंतर जारी रहते हैं, जो कि अनेक आविष्कारों के कारण भी बनते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के क्रम में किसी राज्य विशेष पर बल दिया जाता है, फलस्वरूप उसके विकास की ओर भी ध्यान आकर्षित होता है।

7. समृद्धि का द्योतक (Indicator of Prosperity) - जनसंख्या के अध्ययन से राष्ट्र एवं राज्य की समृद्धि का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि-दर में निरंतर गिरावट आ रही हो तो यह उनकी अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख मापदंड के रूप में प्रयुक्त किए जाने योग्य है। जनसंख्या की सरचना को जानकर जनसंख्या की गुणवत्ता को जाना जा सकता है। यदि इस गुणवत्ता में वृद्धि (जैसे-साक्षरता, स्वास्थ्य आदि) हुई है तो यह एक शुभ संकेत माना जा सकता है।

राजस्थान में जनसंख्या का आकार एवं संवृद्धि

SIZE & GROWTH OF POPULATION IN RAJASTHAN

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4,40,05,990 थी। इस प्रकार 1981 से 1991 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 98 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई। 1981 की तुलना में दशक वृद्धि दर 28.44% है। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या 3,42,61,862 थी। संपूर्ण भारत की जनसंख्या 84,63,02,688 में राजस्थान का भाग 5.20% था। विभिन्न राज्यों की जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान का 9 वां स्थान है। 1981 की जनसंख्या के अनुसार भी यह स्थान 9 वां था। इस संदर्भ में राज्य के क्षेत्रफल को देखा जाए तो यह क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 10.41% है। इस प्रकार राजस्थान के 11.41% भाग में देश की 5.20% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की जनसंख्या के आकार को निम्न तालिका में स्पष्ट किया जा सकता है -

भारत एवं राजस्थान में जनसंख्या का आकार

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)		मनु दस्तावेज़ पर प्रतिशत वृद्धि/ह्रास (दशक वृद्धि दर)			
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	कोलप 4	व 5 का अंतर
1901	1.03	23.83	-	-	-	-
1911	1.10	25.21	+06.70	+05.75	0.95	
1921	1.03	25.13	-06.29	-00.31	-5.98	
1931	1.17	27.90	+14.14	+11.00	3.14	
1941	1.39	31.87	+18.01	+14.22	3.79	
1951	1.60	36.11	+15.20	+13.31	1.89	
1961	2.02	43.92	+26.20	+21.51	4.69	
1971	2.58	54.82	+27.83	+24.80	3.03	
1981	3.43	68.52	+32.97	+25.00	7.97	
1991	4.40	84.63	+28.44	+23.56	4.88	
2001 (समा)	5.60	-	-	-	-	-

* Statistical Abstract, Rajasthan 1994

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 1921 में गत शताब्दी की तुलना में राजस्थान की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक गिरावट आयी।

1931 ई. से 1991 ई. तक की अवधि में राजस्थान की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की तुलना में गिरावट हुई है।

1981 में राजस्थान एवं भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक अंतर किया गया है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तुलना में 1971 की अपेक्षा 7.97% तेजी से बढ़ी। 1991 की जनगणना के अनुसार यह अंतर कुछ कम हुआ है।

राजस्थान की जनसंख्या मनु 1997 में 5.1 करोड़ मनु 2000 में 5.47 करोड़ व मनु 2001 में 5.60 करोड़ होने का अनुमान है।

राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक भाग जयपुर जिले की जनसंख्या का है जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10.7% है। राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से इस जिले का भाग मात्र 0.78% है। उदयपुर जिला (6.5%) दूसरे स्थान पर है। गंगानगर व अलवर जिलों में क्रमशः 5.9% व 5.2% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान के विभिन्न जिलों की जनसंख्या को निम्नलिखित क्रम में दिया गया है।

राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या के आकार की स्थिति

राज्य की कुल जनसंख्या 4.4 करोड़

(A) सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले (1991)

1 जयपुर 47.2 लाख

2 उदयपुर 28.8 लाख

1 गंगानगर 26.2 लाख

(B) न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले (1991)

1 धौलपुर 7.4 लाख

2 सिंगेरी 6.5 लाख

3 जैसलमेर 3.4 लाख

स्रोत: Statistical Abstract Raj 1994

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि -

1 राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः जयपुर उदयपुर व गंगानगर जिले क्रमशः प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थानों पर है।

2 धौलपुर सिंगेरी और जैसलमेर जिले राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना (1991) के समय अंतिम तीन स्थानों पर थे।

3 1901 से 1991 के मध्य अर्थात् 90 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या में 3.38 करोड़ के लगभग वृद्धि हुई है।

4 राजस्थान की जनसंख्या में 1901 व 1951 के मध्य 50 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 57 लाख रहा थी, लेकिन दूसरी ओर 1981 में 1991 के मध्य ही राजस्थान की जनसंख्या 98 लाख से अधिक बढ़ गई थी।

5 गत 30 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या दुगुने से भी अधिक हो गई है। 1961 में यह जनसंख्या 2.01 करोड़ थी जो 1991 में बढ़कर 4.40 करोड़ हो गई।

राजस्थान में जन्म व मृत्यु दर -

राजस्थान में जन्म व मृत्यु दरों में निम्नतर कमी हुई है। लेकिन भारत की तुलना में ये दरें अधिक हैं। निम्न तालिका में राज्य की जन्म दर व मृत्यु दर को दर्शाया गया है।

* Statistical Abstract, Rajasthan 1994

राजस्थान में जन्म दर व मृत्यु दर (प्रति हजार)		
वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर
1980-81	37.1	14.3
1985-86	36.4	11.7
1990-91	35.8	10.1
1992-93	33.6	9.2

Source: Census of India, Rajasthan, 1997-2002

राजस्थान में ऊँची जन्म दर के कारण

राज्य में ऊँची जन्म दर के प्रमुख कारण निम्न हैं

1 विवाहित महिलाओं का अधिक भाग राजस्थान में विवाहित माहलओं का अनुपात बहुत ऊँच है। इसलिये राज्य में जन्म दर भी ऊँची है।

2 समाज का पिछड़ा होना राजस्थान की लगभग 30% जनसंख्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों में संगठित है। निर्धनता एवं अज्ञानता के कारण वे व्यक्ति परिवार नियोजन के सधनो का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः सामाजिक पिछड़ेपन के कारण राज्य में जन्म दर ऊँचा है।

3 विवाह की कम औसत आयु राज्य में विवाह की औसत आयु निर्धारित न्यूनतम स्तर (21 एवं 18 वर्ष) से बहुत कम है। राजस्थान में बाल विवाह आज भी भरा मात्रा में होते हैं अतः जन्म दर ऊँची होगी स्वाभाविक है।

4 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता की निम्न दर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 80% महिलायें निरक्षर हैं। निरक्षर महिलायें परिवार नियोजन के प्रति अपेक्षाकृत कम जागरूक होती हैं। अतः इन क्षेत्रों में जन्म दर ऊँची होती है।

5 दम्पति सुरक्षा दर कम राजस्थान में दम्पति सुरक्षा दर (कुल दम्पतियों में परिवार नियोजन अपनाते वलों का अनुपात) अन्य राज्यों का तुलना में कम है। अतः राज्य की जन्म दर ऊँची है।

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि - दर

GROWTH RATE OF POPULATION IN RAJASTHAN

जनसंख्या वृद्धि-दर से आशय प्रति हजार व्यक्तियों पर जनसंख्या का वृद्धि है। जन्म व मृत्यु दरों के अंतर से भा जनसंख्या वृद्धि-दर ज्ञात की जा सकती है। राजस्थान में 1921 तक संपूर्ण राज्य की प्रति

ही जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई। 1901 में राजस्थान की जनसंख्या 1.02 करोड़ थी जिसमें 1911 में मामूली वृद्धि होकर यह 1.10 करोड़ हो गई। 1921 में इस जनसंख्या में मामूली गिरावट आई और यह 1.04 करोड़ हो गई। 1921 के पश्चात् राजस्थान की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 1931 में यह जनसंख्या बढ़कर 1.18 हो गई और 1991 में यह 4.40 करोड़ तक पहुँच गई है। इस प्रकार विगत 90 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 326% बढ़ा है। जिलेवार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसी 90 वर्षों में राजस्थान के 14 जिलों में जनसंख्या का वृद्धि दर राज्य का जनसंख्या वृद्धि की तुलना में अधिक रहा है। इस अवधि में गंगानगर जिले में यह विकास दर सर्वाधिक 1725.77% रहा है। शीघ्र वृद्धि हुये 13 जिलों में जनसंख्या की वृद्धि-दर राज्य की औसत वृद्धि दर की तुलना में कम ही रही है। इनमें सबसे कम वृद्धि दर धौलपुर जिले में अंकित की गई जो कि 150.68% है।

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दशक की जनसंख्या वृद्धि-दर (Decade growth rate) 28.44% अंकित की गई जबकि 1981 में जनगणना के अनुसार यह वृद्धि-दर 32.97% थी। 1951 में वृद्धि-दर 15.20% थी। 1961 में इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई और यह 26.20% हो गई जो कि राष्ट्रीय औसत से 4.69% अधिक था। 1971 में इसमें अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई और यह 27.83% हो गई किन्तु 1981 में इसमें पुनः ताल वृद्धि हुई और यह 32.97% तक पहुँच गई जो कि राष्ट्रीय औसत से 7.97% अधिक था। 1991 की जनगणना से यह ज्ञात होता है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर में गिरावट आने लगी है क्योंकि यह 1991 में 28.44% रह गई जो कि 1981 की तुलना में 4.5% कम है। राजस्थान में जन्म व मृत्यु दर व उत्तरी पूर्वी राज्यों के छड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि-दर अंकित की गई है। यह राज्य राजस्थान के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसका आशय यह है कि राजस्थान सरकार का जनसंख्या वृद्धि-दर को नियंत्रित करने के विशेष प्रयत्न करते होंगे। यह हो सकता है कि 1991 में 1981 का अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि-दर में जो गिरावट आई है वह राजस्थान में निरंतर जनसंख्या वृद्धि दर में आने वाली गिरावट का प्रवृत्ति का एक संकेत है।

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर जिलेवार स्थिति

(A) राज्य की वृद्धि दर 28.44%

(B) राज्य की औसत वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर वाले प्रमुख जिले-

1 बिकानेर 42.70%

2 जैसलमेर 41.73%

3 जयपुर 37.44%

(C) राज्य की औसत वृद्धि दर से कम वृद्धि दर वाले प्रमुख जिले

1 पाली - 11.63%

2 अजमेर - 20.05%

3 चित्तौड़गढ़ 20.42%

स्रोत: Statistical Abstract of India 1994

1981 से 1991 के दशक में राजस्थान में 35 से अधिक की दशक जनसंख्या वृद्धि-दर बोकारो जैसलमेर और जयपुर में अंकित की गई। 30 से 35 के मध्य जनसंख्या वृद्धि-दर भीकर कोटा नागौर चूरू बांसवाड़ा और अलवर जिले में रही। 25 से 30 के मध्य जनसंख्या वृद्धि-दर (राजस्थान का औसत 28.44%) डुण्डु गंगानगर बाड़मेर डूंगरपुर धौलपुर जोधपुर सवाई माधोपुर भरतपुर जालोर और बूंदी में अंकित की गई। 20 से अधिक व 25 तक वृद्धि दर टोंक उदयपुर झालावाड़ भीलवाड़ा सिरोंही और चित्तौड़गढ़ जिलों में रही। 20% या इससे कम जनसंख्या वृद्धि दर अजमेर और पाली में पाई गई।

1991 की जनगणना के अनुसार औसत वार्षिक चक्र वृद्धि दर (Average annual exponential growth rate) राजस्थान व भारत में क्रमशः 2.50 व 2.14 प्रतिशत है।

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण

Factors Affecting Population Growth Rate in Rajasthan

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में दशक जनसंख्या वृद्धि-दर व औसत वार्षिक वृद्धि दर दोनों ही 1981-91 के दशक में राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही हैं। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर का स्थिति अलग-अलग है। मुख्य रूप से राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर राष्ट्रीय औसत से अधिक होने के निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं

1 आर्थिक पिछड़ापन (Economic Backwardness)- जनसंख्या वृद्धि दर और आर्थिक विकास का

गहरा संबंध है। आर्थिक विकास के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। यद्यपि पूरे देश और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर में 1981-91 के दशक में कमी आई थी फिर भी राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है क्योंकि राजस्थान अन्य राज्य की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है। यह पिछड़ापन औद्योगिक एवं सामाजिक पिछड़ापन है। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि-दर अपेक्षाकृत अधिक है।

अतिम जनगणना 1991

जनगणना की शुरुआत ब्र 1881 से माना जाता है लेकिन इसके पूर्व भी जनगणना की पर्याप्त महत्व दिया गया था। केटिल के अनुसार स्पष्ट होता है कि प्राचीन धर्म में सनातनी नामक अधिकारी को गावों का सौम्य या गावों में मतानों मंदिर धर्मशास्त्रों जानवरों की सखा कुक्का शिकारियों व्यापारियों भद्रदत्तों दातां पुरुषों खिल बल्लों बल्लों आदि के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करके उसका विवरण रखना पड़ता था। इसी प्रकार नगर के अधिकारी का वर्तन या कि वह जति गाँव के अनुसार सभी स्त्री पुरुषों की जनगणना करे, साथ ही उनका व्यवसाय आय व्यय का विवरण प्राप्त कर। बौद्धिक ने तो यह सुझा भी दिया था कि कई गावों की जनगणना प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस स तौर से व चौथी शताब्दी पूर्व मौर्यकाल में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। मौर्यकाल में भी राज्य व्यवस्था व राजस्व वसूली के लिए विस्तृत विवरण तैयार किया जाता था। अतः फलतः की आदिन अरबों में 16वीं शताब्दी में जनगणना का संकेत मिलता है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इस और विशेष प्रयास हुए लेकिन आधुनिक पद्धति पर जनगणना का आरम्भ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् ही हुआ। 1861 में जनगणना की योजना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बन गई थी। 1865 में परिवर्धन 1866 में मध्य शत 1867 में पञ्जाब तथा 1868 में अन्ध 1 की जनगणना हुई। इसी काल में क्रमशः मद्रास बम्बई और कलकत्ता की भी जनगणना हुई। भारत में 1991 की जनगणना वर्तमान जनगणना विधि के दृष्टिकोण से आधुनिक जनगणना होगी। आगामी जनगणना सम्पन्न सर्वेक्षण के अनुसार हुआ करेगा।

2 उष्ण जलवायु (Hot Climate) राजस्थान का लगभग समस्त प्रदेश कर्क रेखा से ऊपर स्थित है और इस प्रकार शीतोष्ण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राजस्थान का लगभग आधा भाग रेगिस्तानी होने के कारण राजस्थान की जलवायु अत्यधिक विषम है। प्रमुख रूप से उष्ण जलवायु के अन्तर्गत मनुष्य जल्दी परिपक्व होता है। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि-दर बढ़ने की अधिक सम्भावना रहती है। यह संपूर्ण भारत की भांति राजस्थान के सर्दार में भी जनसंख्या वृद्धि-दर अधिक होने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

3 बाल विवाह (Children's Marriage) राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत कम उम्र में विवाह होते हैं जिससे कम उम्र में ही सतान होना आरंभ हो जाता है। कनूत रूप से लड़के और लड़की की विवाह यात्रा आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष है किन्तु विशेषकर ग्रामीण

क्षेत्रों में इस नियम का पालन नहीं होता। स्वामी विवेकानन्द ने बाल विवाह के जो दुष्परिणाम बतलाये थे वे राजस्थान पर बिल्कुल सही उतरते हैं। उन्होंने कहा था कि "बाल विवाह से असाधारण सन्तानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में सन्तान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियाँ अल्पायु होती हैं, उनकी दुर्बल और रोगी सन्तान देश में मिसाखियों की संख्या बढ़ाये का कारण बनती है।" उन्होंने यह भी कहा था, "आज घर-घर इतनी विधवाएँ पाए जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है। यदि बाल विवाह की संख्या घट जाये तो विधवाओं की संख्या भी स्वयंसे घट जायेगी।"

4. संयुक्त परिवार प्रथा (Joint Family System) - राजस्थान में भारत के अधिकतर भागों की भाँति आज भी संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा में बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर होता है। इस कारण बाल विवाह और उसके परभाव कम उम्र में सन्तानोत्पत्ति, साथ ही बच्चों के पालन पोषण में अल्पायु में विवाहित दम्पति को कोई विशेष कठिनाई नहीं आती। इस कारण जनसंख्या वृद्धि की प्रोत्साहन मिलता है।

5. गरीबी एवं निम्न जीवन-स्तर (Poverty and Low standard of living) - राजस्थान की अगिकाश जनसंख्या की आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस कारण लोगों का जीवन स्तर भी नीचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर छोटे-छोटे बच्चों को भी अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से काम लगा दिया जाता है। इससे इस प्रवृत्ति का बल मिलता है कि अधिक सन्तान से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। यह मानसिकता जन्म दर को बढ़ाने में सहायक होती है।

6. शिक्षा का अभाव (Lack of Education) - राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। राजस्थान की केवल 38.55 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर है।¹ संपूर्ण भारत में साक्षरता का यह प्रतिशत 52.21 है।² यह तथ्य अनेक अध्ययनों में निरूपित हो चुका है कि साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि-दर में विपरीत संबंध है। इस कारण साक्षरता में कमी स्वाभाविक रूप से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर का एक महत्वपूर्ण कारण है। अशिक्षा के कारण गम्भीर व्यक्ति भविष्य के प्रति सचेत नहीं होता और उसका परिवार अकरण ही बढ़ा हो जाता है।

7. शिशु मृत्यु दर अधिक (Higher infant death rate) - शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण भी राजस्थान में अधिक सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यक्ति प्रायः यह सोचता है कि वर्तमान बच्चों में से भविष्य का पता नहीं किये बिना जेबित रहे, इस कारण वह

परिवार को बड़ा रखना चाहता है। इसके साथ ही पुत्र का होना आवश्यक माने जाने के कारण भी परिवार में वृद्धि होती है। शिशु मृत्यु दर के अधिक होने का प्रमुख कारण राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होना और स्वास्थ्य संबंधी जनकारी लोगों तक न पहुँचना है।

8. प्रकृति पर निर्भरता व भाग्यवादिता (Dependence on Nature) - देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सन्तानोत्पत्ति भाग्य भरोसे है। व्यक्तियों का साधारणतः यह विश्वास रहता है कि जो जन्म लेता है, वह अपना भाग्य भी साथ लाता है। रेगिस्तान व कम वर्षा तथा प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राज्य का निवासो विशेष रूप से भाग्यवादी बन गया है। भाग्यवादित्व के आधार पर सन्तानोत्पत्ति पर अकुश लगाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता है।

9. परिवार नियोजन को प्रति उदासीनता (Indifferent Attitude towards family planning) - राज्य में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के चलते हुए एक लंबी अवधि बीत चुकी है, किन्तु फिर भी राजस्थान में और विशेषतः इसके ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं हो पाया है। इसका कारण परिवार नियोजन के प्रति राजस्थान में अत्यधिक उत्साह नहीं देखा गया है। यह प्रवृत्ति जनसंख्या वृद्धि-दर को बढ़ाती है।

10. अन्य (Others) - देश के अन्य भागों की भाँति राजस्थान में भी विवाह की अनिवार्यता, आवास समस्या, मनोरंजन के साधनों का अभाव, सामाजिक सुखी की अपर्याप्तता आदि वे महत्वपूर्ण कारण हैं, जो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

ग्रामीण व शहरी जनसंख्या

RURAL & URBAN POPULATION

राजस्थान में गाँवों का आधिक्य है और राज्य की अगिकाश जनसंख्या गाँवों में रहती है। 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान को 3.42 करोड़ की जनसंख्या में से 2.70 करोड़ लोग गाँवों में और 0.70 करोड़ लोग शहरों में निवास कर रहे थे। इस प्रकार राजस्थान की जनसंख्या का 78.95% गाँवों में और 21.05% शहरों में निवास करता था। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 4.40 करोड़ की जनसंख्या में से 3.39 करोड़ लोग गाँवों में और 1.0 करोड़ लोग शहरों में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का 77.1%

की गाँवों में और 22.9% शहरों में निवास कर रहा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का वितरण निम्न तालिका में स्पष्ट है -

राजस्थान में जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसंख्या की स्थिति (1991)

- (A) राजस्थान का ग्रामीण जनसंख्या 3.39 करोड़
राजस्थान का शहरी जनसंख्या 1.00 करोड़
- (B) सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रमुख जिले
1 जयपुर 28.5 लाख
2 उदयपुर 23.9 लाख
3 गानगा 20.7 लाख
- (C) सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले प्रमुख जिले
1 जयपुर 18.8 लाख
2 जाधपुर 7.6 लाख
3 कोटा 7.3 लाख
4 अजमेर 7 लाख

स्रोत: Statistical Abstract Raj 1994

उपरोक्त तालिका में ज्ञात होता है कि राजस्थान की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या एवं इसी भाँति सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी जयपुर जिले में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से उदयपुर जिले का दूसरा और गानगा जिले का तीसरा स्थान है। राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर जिले में है। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर के पश्चात् जाधपुर का स्थान है। तीसरा स्थान कोटा व चौथा अजमेर जिले का है। राजस्थान में सबसे कम शहरी जनसंख्या जैसलमेर जिले में है। राजस्थान में नगरीकरण की प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। जनसंख्या के विभिन्न नगरे में कन्दित हो जाने का कोई अच्छा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। राजस्थान के साधन सम्पन्न होने व कारण इस प्रवृत्ति का दीर्घकाल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करके और मात्र ही छोटे नगरों कम्पों और शान्ति व औद्योगिक विकास करके इस प्रवृत्ति का बड़ा सामा तब रोक सकती है। राजस्थान में नगरी जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इस तथ्य का आशय राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपलब्ध आंकड़ों से होता है -

राजस्थान में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर				
शहर	जनसंख्या			
	1961	1971	1981	1991
जयपुर (U.S.)	403444	615258	977165	1518235
जोधपुर	224766	317612	576345	666279
कोटा	120345	212991	358241	537371
बीकानेर	150634	188518	253174	416289
अजमेर	281240	264591	375593	402700
उदयपुर	111139	161278	232588	308571
अलवर (U.S.)	72707	100378	145795	210146
भीलवाड़ा	43409	32155	122625	183965
गानगा	63854	90042	123692	161482
भरतपुर	49776	68036	105274	156880
सीकर	50636	70987	102970	148272
पाली	-	-	-	136842
ब्यावर (U.S.)	-	-	-	106721
टोंक (U.S.)	-	-	-	100235

उपरोक्त तालिका में ज्ञात होता है कि गत 30 वर्षों में जयपुर शहर की जनसंख्या 3 गुणा से भी अधिक हो गई है। इसी अवधि में जोधपुर शहर की जनसंख्या 2 गुणा से अधिक कोटा शहर की जनसंख्या 4 गुणा से अधिक बीकानेर शहर की जनसंख्या 2.5 गुणा से अधिक बढ़ी है। अजमेर शहर की जनसंख्या 1.5 गुणा से भी कम की वृद्धि हुई है। उदयपुर शहर की जनसंख्या 2.5 गुणा, अलवर शहर की जनसंख्या लगभग 3.0 गुणा तथा भीलवाड़ा शहर की जनसंख्या में 4.0 गुणा से भी अधिक की वृद्धि हुई है। गानगा शहर की जनसंख्या 2.5 गुणा से अधिक व भरतपुर शहर की जनसंख्या 3.0 गुणा से अधिक बढ़ी है। इस प्रकार सबसे कम वृद्धि अजमेर शहर में हुई है।

राजस्थान में नगरीकरण के कारण- FACTORS RESPONSIBLE FOR URBANISATION IN RAJASTHAN

राजस्थान में नगरीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -

1 कृषि क्षेत्रों में बेरोजगारी (Unemployment in Agricultural Sector) - मजदूर राजस्थान में कम से कम चरगागाह तो कृषक बेरोजगार ही रहते हैं। जिन स्थानों

पर केवल एक फसल ली जाती है, वहां पर वह लगभग छ माह बेरोजगार रहते हैं। प्राकृतिक विपदाओं के कारण अनाज आदि की स्थिति में कृषक एवं कृषि मजदूर दोनों ही बेरोजगार हो जाते हैं। इस कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए आना आरंभ हो जाते हैं।

2 ग्रामों में सुविधाओं का अभाव (Lack of facilities in villages) - भारत की भांति राजस्थान राज्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उन्नीसवीं के दशक तक ग्रामीणों इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहते, अतः शहरों में उपलब्ध इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वे शहरों में आकर बसना आरंभ कर देते हैं।

3 ग्रामों में सुरक्षा का अभाव (Lack of Security in Villages) - ग्रामीण क्षेत्रों में जान माल की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। अतः साहूकार, जमींदार तथा व्यापारी आदि धनी व्यक्ति शहरों में आकर बसने की प्रवृत्ति रखते हैं। आम व्यक्ति भी सुरक्षा की खोज में शहरों में आना चाहते हैं।

4 परिवहन साधनों का विकास (Transportation) - राजस्थान में पूरे देश की भांति परिवहन के माध्यम तेज़ गति में विकसित हो रहे हैं। इस कारण ग्रामीण लोग व व्यापारी शहरी मण्डियों एवं व्यापारिक केन्द्रों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। धीरे धीरे लाभ कमाने के उद्देश्य से ये शहरी क्षेत्रों में भी व्यापार करना आरंभ कर देते हैं।

5 कुटीर व लघु उद्योगों की कमी (Lack of Cottage and Small Scale Industries) - ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योग पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों और छोटे-छोटे कृषिपट्टों को पूरा कार्य नहीं मिल पाता। फलतः वे शहरों में आते हैं। शहरों में अधिक मजदूरी व स्थायी रोजगार मिल जान पर एम व व्यक्ति शहरों में ही बस जाते हैं।

स्लेट में राजस्थान में सार्वजनिक की भांति नगरपालिका की प्रवृत्ति को देखने के गर्भाग्र प्रयास किया जाना चाहिये। इन हेतु ताबो कम्बो और नाम का एवं दूसरे के पुत्र व रूप में विनाम हाना चरित्र्य ताकि सभी लोगों को लाभान्वित सुविधाएं व अवसर मिल सकें। तभी राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक वित्तीय के प्रयास सार्थक हो पाएंगे।

राजस्थान में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

OCCUPATIONAL DISTRIBUTION OF POPULATION IN RAJASTHAN

राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण यहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को प्रतिबिम्बित करता है। 1971 की जनगणना में श्रमिक की परिभाषा में श्रमिक वर्ग में केवल उनसे व्यक्तिओं का सम्मिलित किया गया था, जो मुख्य रूप से पूरे समय किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुये थे। शेष व्यक्ति गैर श्रमिक माने गये। राजस्थान में 1991 की जनगणना के आधार पर श्रमिकों का निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है -

श्रमिकों का वर्गीकरण (प्रतिशत में) ¹				
वर्गीकरण	प्रादेश	शहरी	कुल	
मुख्य श्रमिक	1991	31.53	26.54	30.48
	1991	32.94	27.18	31.62
सहायक श्रमिक	1981	7.54	0.83	6.13
	1991	9.10	0.99	7.25
गैर श्रमिक	1981	60.93	72.63	63.39
	1991	57.96	71.83	61.13

राजस्थान में 1991 की जनगणना के आधार पर मुख्य श्रमिकों को उनके व्यवसाय के अनुसार निम्न प्रकार विभक्त किया जा सकता है -

मुख्य श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण (लाखों में) ²			
व्यावसायिक वितरण	ग्रामीण	शहरी	कुल
कुल मुख्य श्रमिक	111.79	27.35	139.15
1 कृषक	79.38	2.42	81.81
2 कृषि श्रमिक	12.90	1.01	13.91
3 पशुपालन, वन, मत्स्य, आदि उपरोक्त उद्योग			
एव सहकार कृषि	2.10	0.40	2.51
4 खन एवं खनन	1.06	0.37	1.43
5 निर्माण, विपणन, उद्योग एवं पर्यटन			
घरेलू उद्योग	1.82	0.95	2.78
घरेलू उद्योग व			
अतिरिक्त	2.61	4.96	7.58
6 निर्माण कार्य	1.48	1.88	3.37
7 व्यापार एवं वणिज्य	3.02	5.90	8.92
8 परिवहन, संचालन एवं			
संचार	1.22	2.10	3.32
9 अन्य सेवाएं	6.16	7.32	13.48

तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में अधिकांश व्यक्ति कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। यह तथ्य राज्य में कृषि की प्रधानता को स्पष्ट करता है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम श्रमिक कार्यरत हैं। वस्तुतः राज्य में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अतः अन्य क्षेत्रों की तुलना में राज्य के उद्योग-क्षेत्र में कम श्रम शक्ति का होना स्वाभाविक है। राज्य का सेवा क्षेत्र अनेक व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी क्रियाओं में भी अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है।

जिलानुसार श्रमिकों के वर्गीकरण की स्थिति 1991

(A) मुख्य श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले

- 1 बीकानेर 41.45%
- 2 झालावाड़ 40.39%
- 3 झालावाड़ 38.25%

(B) सीमाना श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले-

- 1 झुणपुर 14.41%
- 2 बांसवाड़ा 13.89%
- 3 बाड़मेर 10.82%

(C) गैर श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले-

- 1 धौलपुर 70.42%
- 2 सीकर 68.35%
- 3 झुणपुर 66.58%

Source: Final Population Figures (1991)

राजस्थान में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण से ज्ञात होता है कि राजस्थान में प्राथमिक व्यवसायों में काफी बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। इस संदर्भ में आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रो. चार्ल्स स्टीवार्ट की उद्धृत किया जा सकता है। उनके अनुसार - "श्रम पथ के मद्देन में आर्थिक विकास का मूल तथ्य हमसे निहित है कि श्रमिकों का कृषि में वाणिज्यिक कार्यों में व्यवसायान्तरण किया जाए।" इस बात का समर्थन प्रो. ए.जी.डी. फिशर ने भी किया है। उनके अनुसार "प्रत्येक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में और विनियोग में एक निश्चित हस्तान्तरण प्राथमिक क्रियाओं व उससे अधिक सभी प्रकार की द्वितीयक क्रियाओं में और इसमें भी अधिक सीमा में तृतीयक उत्पादन में होता है।" इस प्रकार राजस्थान में कृषि पर अग्रिमता के कारण कार्दर्शन जनसंख्या की व्यावसायिक गतिविधियों में कमी दर्जित हो रही है। राजस्थान में दैर्घ्यविक्रय भी बहुत अधिक मात्रा में स्थित नहीं हो पाये हैं। इस कारण

भी यह स्थिति है। राजस्थान में तीव्र गति में विकास करने के लिए जनसंख्या को अन्य व्यवसायों में हस्तान्तरित करना होगा।

राजस्थान में स्त्री-पुरुष अनुपात SEX RATIO IN RAJASTHAN

स्त्री पुरुष अनुपात में आशय प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। यह एक महत्वपूर्ण सूचक है जिसका प्रभाव जन्म दर, मृत्यु दर और श्रम शक्ति पर पड़ता है। यदि इस अनुपात में काफी अधिक असमानता हो तो अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं के साथ जनसंख्या में संबंधित अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाएगी। आदर्श स्थिति में स्त्री-पुरुषों का अनुपात बराबर या लगभग बराबर होना चाहिये। राजस्थान में संपूर्ण भारत की भांति स्त्री पुरुष अनुपात कभी भी समान नहीं रहा। इस बात का ज्ञान निम्न तालिका से भी होता है -

राजस्थान में स्त्री - पुरुष अनुपात			
वर्ष	स्त्री पुरुष	वर्ष	स्त्री-पुरुष अनुपात
1901	905	1951	921
1911	908	1961	908
1921	896	1971	911
1931	907	1981	919
1941	906	1991	910

जिलेवार स्त्री-पुरुष अनुपात की स्थिति (1991)

(A) राज्य औसत (910) से अधिक अनुपात वाले प्रमुख जिले

- 1 झुणपुर 995
- 2 बंसवाड़ा 969
- 3 उदयपुर 965

(B) राज्य औसत से कम अनुपात वाले प्रमुख जिले

- 1 धौलपुर 795
- 2 बांसवाड़ा 807
- 3 बांसवाड़ा 832

Source: Statistical Abstract Raj 1994

ज्ञात होता है कि -

1 राजस्थान में गणानगर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमहोपुर, ब्रह्मपुर, जैमलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, डूंगरी व कोटा जिलों में स्त्री पुरुष अनुपात राज्य का औसत अनुपात से कम है।

■ राजस्थान में चुरू, झुणपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, नागौर

पाती, जालोर, सिरोंही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झुगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में स्त्री-पुरुष अनुपात राज्य के औसत स्त्री-पुरुष अनुपात से अधिक है।

3 राजस्थान में सर्वाधिक स्त्री-पुरुष अनुपात झुगरपुर जिले में है। तत्पश्चात् क्रमशः बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ आदि का स्थान है।

4 राजस्थान में सबसे कम स्त्री-पुरुष अनुपात धौलपुर जिले में है।

5 राजस्थान में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः स्त्री पुरुष अनुपात अधिक है। शहरी क्षेत्रों में यह राज्य के औसत से प्रायः कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः अधिक है।

6 राजस्थान में 1981 की तुलना में स्त्री-पुरुष अनुपात कम हुआ है। राज्य का स्त्री-पुरुष अनुपात सम्पूर्ण भारत के औसत अनुपात की तुलना में कम है।

7 1901 से 1991 तक राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं रहा, जिसमें लगभग नियो के मख्या पुरुषों में अधिक रही हो।

8 यह स्पष्ट करारा उपयुक्त प्रतीत होता है कि 1901 की जनगणना के समय झुगरपुर और बांसवाड़ा ऐसे जिले थे, जहां पर स्त्री-पुरुष अनुपात नियो के अनुकूल था। झुगरपुर में स्त्री-पुरुषों की मख्या बराबर थी और बांसवाड़ा में स्त्रियों की मख्या पुरुषों में अधिक थी। 1911 की जनगणना के अनुसार झुगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में स्त्रियों की मख्या अधिक थी। बांसवाड़ा में यह स्थिति केवल 1931 तक बना रही। झुगरपुर में 1931 की जनगणना में यह स्थिति नहीं बन रह सकी। 1931 की जनगणना में उसमें पुरुषों की मख्या अधिक हो गई। यह स्थिति 1941 की जनगणना में भी रही। 1951 में झुगरपुर में पुनः 1931 में पूर्व की स्थिति प्राप्त कर ली, जिसमें स्त्रियों की मख्या पुरुषों से अधिक थी। 1961 में यह स्थिति नहीं रही। इस जिले में 1971 और 1981 की जनगणना में स्त्रियों की मख्या बढ़ी अवश्य किन्तु वह पुरुषों की मख्या में कम रही। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का झुगरपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की मख्या पुरुषों से अधिक है।

राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व एवं असमान वितरण

DENSITY & UNEVEN DISTRIBUTION OF POPULATION IN RAJASTHAN

जनसंख्या के घनत्व और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण है। इसी कारण जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन

किया जाता है। जनसंख्या के घनत्व से आशय एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या से है। कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्र का भाग देकर जनसंख्या का घनत्व मासूम किया जा सकता है। घनत्व एक क्षेत्र विशेष में औसत जनसंख्या की स्थिति को बताता है। इससे यह ज्ञात होता है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या कम है और किसमें अधिक है। विभिन्न जनगणनाओं के अनुसार राजस्थान व भारत में घनत्व की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है-

राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व ¹		
वर्ष	राजस्थान	भारत
1901	30	77
1911	32	82
1921	30	81
1931	34	89
1941	41	103
1951	47	117
1961	59	142
1971	75	177
1981	100	216
1991	129	273
2001(अनु.)	164	-

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 10% से अधिक है, किन्तु इसमें भारत की लगभग 5% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के 27 जिलों के मध्य में 1991 की जनगणना के आकड़े उपलब्ध हैं जिनके अनुसार सभी जिलों में जनसंख्या का घनत्व अलग-अलग है।

राजस्थान में जिलेवार क्षेत्रफल एवं घनत्व की स्थिति (1991)

(A) राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रमुख जिले

1. जयपुर - 11.22%
2. बांसवाड़ा - 8.29%
3. बीकानेर - 7.95%

(B) राज्य के सर्वाधिक घनत्व वाले प्रमुख जिले-

1. जयपुर - 336
2. पाली - 326
3. अजमेर - 274

(C) राज्य के न्यूनतम घनत्व वाले प्रमुख जिले

1. बीकानेर - 8
2. बीकानेर - 27
3. बांसवाड़ा - 45

स्रोत: Statistical Abstract of India 1994

राजस्थान के घनत्व के संबंध में निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है

1 राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 1931 में निरंतर बढ़ रहा है। यह 1901 व 1921 में 30 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 1931 में यह 34 हो गया और उसके बाद निरंतर बढ़ता हुआ 1991 में 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया।

2 राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व सदैव भारत के जनसंख्या के घनत्व से कम रहा है।

3 जयपुर जिला राजस्थान का सबसे घना बसा जिला है। इसके प्रमुख कारण इसका गन्नाहारी होना तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त आवागमन सुविधाएँ उपलब्ध होना है। जयपुर का व्यापारिक केंद्र के रूप में उदित होना भी एक कारण है। जयपुर के पड़ोसी भरतपुर अलवर व झुझर का स्थान है।

4 जैसलमेर जिला घनत्व की दृष्टि से सबसे नीचे है। इस के मुख्य कारण इस क्षेत्र का रेगिस्तानी होना जनवास्य विषम होना प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होना कृषि एवं औद्योगिक विकास का दृष्टि से पिछड़ा होना तथा परिवहन के साधनों का विकसित न हो पाना आदि है।

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति

SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES IN RAJASTHAN

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 1981 में क्रमशः 58 38 लाख व 41 83 लाख था जो 1991 में बढ़कर क्रमशः 76 07 लाख व 54 47 लाख हो गई। राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति का जनसंख्या का प्रमाण व शहरी क्षेत्र में वितरण निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है।

राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति				
सं.	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	कुल संख्या	शहरी	कुल संख्या	शहरी
1961	58 38 47	90 10 48	41 83 40	271 56
1991	76 07 61	02 15 05	54 74 52	202 64

Source: Various Censuses & 1991 Census Population Figures 1991

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जिल्दवार स्थिति 1991

(A) अनुसूचित जाति के सर्वाधिक संवेदनशील वाले प्रमुख जिला	
1 जयपुर	29.50%
2 बिकानेर	21.87%
3 झुझर	21.84%
(B) अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक संवेदनशील वाले प्रमुख जिला -	
1 बीकानेर	73.47%
2 झुझर	65.64%
3 झुझर	36.79%

Source: District Abstracts 1991

राजस्थान में अनुसूचित जाति के व्यक्ति शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग बराबर स्थिति में है। अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। गानग जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का एवं बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है।

राजस्थान में धर्म के अनुसार जनसंख्या Religionwise Population in Rajasthan

धर्मानुसार जनसंख्या का वितरण 1991 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। 1981 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में 89.32% लोग हिन्दू 7.28% मुस्लिम 1.28% जैन 1.44% सिक्ख 0.12% ईसाई एवं 0.01% बौद्ध धर्मावलम्बी थे। ज्ञात होता है कि

- 1 राजस्थान में धर्मानुसार सर्वाधिक हिन्दू धर्मावलम्बी है।
- 2 कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर झुझर जिले में सर्वाधिक हिन्दू निवास करते हैं। राजस्थान में सबसे कम हिन्दू जनसंख्या का प्रतिशत जैसलमेर व गानग जिले में है।
- 3 जैसलमेर जिले का कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का भाग सर्वाधिक है। प्रतिशत जनसंख्या के अभाव पर सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या झुझर जिला व बांसवाड़ा व झुझर जिले में है।
- 4 गानग जिले में जनसंख्या में अन्य धर्मों का अंश सर्वाधिक जैन धर्मावलम्बी है। राजस्थान में सिक्खों का अभाव है।
- 5 सिक्खों की सर्वाधिक जनसंख्या गानग व झुझर जिले में है।
- 6 राजस्थान में ईसाई धर्म का अंश राजस्थान जिले में जनसंख्या में ईसाई धर्मावलम्बी का प्रतिशत सबसे

अधिक है, तत्पश्चात् अजमेर का स्थान है।

7 सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलम्बी अजमेर व बांसवाड़ा में निवास करते हैं।

राजस्थान में मानव संसाधन विकास के तीन महत्वपूर्ण सूचक

THREE IMPORTANT INDICATORS OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

(A) राजस्थान में साक्षरता (Literacy in Rajasthan) - व्यक्ति को द्वारा किसी भाषा को सामान्य रूप में लिखने पढ़ने तथा उसे समझने की क्षमता को प्रायः साक्षरता का नाम दिया जाता है। भारत में साक्षरता का प्रतिशत अन्य राष्टों की तुलना में कम है, जो राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में कम है। आधुनिक समय में साक्षरता उनकी ही महत्वपूर्ण माना जाती है जितना कि आवास तथा भोजन। सामान्य तौर पर दो प्रकार की साक्षरता दर्ज की जाती है। पहली, सामान्य साक्षरता दर जो कि कुल सभ्य और देश की कुल जनसंख्या का अनुपात होती है। दूसरी, प्रभावी साक्षरता दर जो कि 1981 की जनगणना तक भारत में पाँच वर्ष में कम उम्र के बच्चों को निरक्षर मानते हुये ज्ञान की जाती थी। 1991 की जनगणना से प्रभावी साक्षरता दर ज्ञान करने के लिए सात वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या को छोड़ दिया गया है। राजस्थान निम्नतम साक्षरता वाले राज्यों में से है। महिलाओं में साक्षरता बहुत ही कम है। इन सब तथ्यों का आधार निम्न तालिका से होता है।

राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत

वर्ष	पुरुष			स्त्री		
	संख्या	शत	योग	संख्या	शत	योग
1951	13 09	2 51	8 02	24 68	7 88	16 67
1961	23 71	5 84	15 21	34 45	12 95	24 02
1971	28 74	8 48	19 07	39 45	18 72	29 46
1981	38 30	11 42	24 38	46 89	24 82	36 17
1991	54 99	20 44	35 55	64 13	39 29	52 21

उपरोक्त तालिका में निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है-

1 राजस्थान में महिला एवं पुरुष साक्षरता, दोनों ही अखिल भारतीय साक्षरता दर से कम है। पुरुषों में साक्षरता दर भारतीय औसत में 9 12% कम है जबकि महिलाओं में साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत में 18 75% कम है।

राजस्थान में 1981 की तुलना में 1991 में पुरुष एवं महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है। 1981 में राजस्थान की कुल साक्षरता दर 30 09% (7 वर्ष व उससे ऊपर की जनसंख्या के आधार पर) थी जो 1991 में लगभग 8 5% बढ़कर 38 55% हो गई। पुरुषों में इसी अवधि में साक्षरता के अत्यंत 10% से भी अधिक वृद्धि हुई, किन्तु महिलाओं में यह वृद्धि मात्र 6 45% ही रही।

2 राजस्थान में विद्यालय जाने वाले बच्चों का प्रतिशत भी राष्ट्रीय औसत से कम है। 1989-90 में राजस्थान में 6-11 एवं 11-14 वर्ष आयु वर्ग में विद्यालय जाने वाले बच्चों का औसत क्रमशः 89 37 एवं 51 25% था। दूसरी ओर इसी आयु वर्ग में राष्ट्रीय औसत 1986-87 में क्रमशः 96 11 एवं 53 1% था। इसी संदर्भ में उपरोक्त आयु वर्ग में लड़कियों का विद्यालय जाने का प्रतिशत क्रमशः 57 60 एवं 24 93 प्रतिशत था। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं में निरक्षरता का एक प्रमुख कारण प्रारंभिक आयु में विद्यालय नहीं जाना भी है।

राजस्थान में जिलेवार साक्षरता दर की स्थिति 1991

(A) सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रमुख जिले

- 1 अजमेर - 52 34%
- 2 जयपुर - 47 88%
- 3 कोटा - 47 88%

(B) न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रमुख जिले

- 1 बाड़मेर - 22 98%
- 2 जालौर - 23 76%
- 3 बांसवाड़ा - 26 00%

(C) महिला साक्षरता में अग्रणी जिले

- 1 अजमेर - 34 50%
- 2 कोटा - 29 50%
- 3 जयपुर - 28 69%

Source: Statistical Abstract RAJ 1994

ज्ञान होता है कि -

1 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में राज्य की औसत साक्षरता दर की अपेक्षा गंगानगर, बीकानेर, झुझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, मेवार, अजमेर, जयपुर तथा कोटा जिलों में साक्षरता दर अधिक थी, जबकि अन्य जिलों में राज्य के औसत से कम साक्षरता विद्यमान है।

2 राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर अजमेर जिला में है, तत्पश्चात् जयपुर व कोटा जिले समुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर तथा झुझुनू जिला तृतीय स्थान पर आते हैं।

3 पुरुषों में साक्षरता दर की दृष्टि से अजमेर जिला प्रथम स्थान पर है। झुझुनू जिला द्वितीय स्थान पर तथा जयपुर

विस्तार की आवश्यकता है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर आठवी पंचवर्षीय योजना में 445.33 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। त्रन्म व मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। जीवन प्रत्याशा (1995-96) लगभग 61 वर्ष हो गई है जो कि 1961 में 46.8 वर्ष था।

(ii) पोषाहार (Nutrition) - राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को स्वस्थ रखने के लिए उपयुक्त पोषाहार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। नौ महिलाओं और बच्चों को यह पोषाहार विशेष रूप से जाना जाता है। ताकि गर्भवती महिलाएँ व बच्चे अनेक प्रकार के कुपोषण से सम्बन्धित रोगों में ग्रसित न हों। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्स्थाओं के सहयोग में भी ये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष रूप से निर्धन अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं व बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है। 1974 में पहली बार राष्ट्रीय नाति के अन्तर्गत बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया और उन्हें राष्ट्र की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सम्पदा के रूप में मान्यता दी गई। तत्पश्चात् इनके पोषाहार पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा। भारत में बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 42% में भी अधिक है। राजस्थान में 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 14% है। बच्चों के खराब स्वास्थ्य, अस्वास्थ्यकर आहार और चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण यहाँ की शिशु मृत्यु दर 8.4 प्रति हजार है जबकि राष्ट्रीय औसत 7.9 प्रति हजार है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान का आठवी योजना में विभिन्न मंदा के अन्तर्गत 34.90 करोड़ रुपये व्यय किये गये। नवी योजना में 125.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रवधान किया गया है।

राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास की दिशा में उठाये गये सरकारी कदम

1 शिक्षा एवं मशरफा - राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास हेतु शिक्षा के विस्तार एवं मशरफा अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में माध्यात्म अभियान राज्य के सभी जिलों में कार्यन्वित है। 1994-95 के बजट में शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। सीझा के सहयोग में त्वाञ्ज-जुमिशा योजना तथा टूनिमैफ के आर्थिक सहयोग से राज्य के पाँच जिलों में गुरु-मिश्र योजना चालू है।

2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ी हैं लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत कम हैं। 1995-96 के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया।

3 पेयजल एवं स्वच्छता - स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्य में अनेक पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया गया। राज्य के बड़े नगरों में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था है तथा राज्य के अधिकांश गावों में पूर्ण अथवा आंशिक व्यवस्था हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की व्यवस्था नगरपालिकाओं द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा का जाता है।

4 पोषण एवं पौष्टिक आहार - राज्य की जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राज्य सरकार अनेक पोषाहार कार्यक्रमों का संचालन करती रही है। सरकार समय-समय पर निर्धन जनता को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराती है। महिलाओं के स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए औषधियों का वितरण किया जाता है।

5 आर्थिक विकास - स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्य की जनता की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य का नियोजित ढंग से आर्थिक विकास किया जा रहा है। आठ पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है तथा नवी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जा रही है। अतः राज्य में आर्थिक विकास की गति तीव्र होने से जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि हुई है।

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम FAMILY WELFARE PROGRAMME IN RAJASTHAN

देश में तब्दी से बढ़ती हुई जनसंख्या व सम्बन्ध में कीन्ते माइड ने लिखा है कि "बन की तुलना में गर्भाशय अधिक मन्दाग्रामी है लेकिन उतना ही भयङ्कर मिद्ध हो सकता है। भस्मिकरण की बजाए श्वास घुनन मानव कथा का धन कर सकता है।" अतः परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य मोद-समग्रकर स्वेच्छा से, सन्तानोत्पत्ति करना एवं एकाएक होने वाले बच्चा का प्रतियन्धित करना है। कन्तुत "देशीय कल्याण कार्यक्रम मन्म रूप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तथा देश के विकास और खुशहाली की कुञ्जी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का अन्तर्गत प्रत्येक परिवार अपने का मोमिन्त रखते हुये अतिवैकपूर्ण मान्त्व पर गेक लगा सकता है व मन्तानों को उचित देखभाल कर

मालता है इस प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रम एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है।

परिवार नियोजन अनुसंधान एवं कार्यक्रम कमेटी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'परिवार नियोजन का कल्याण चक्र का प्राथमिकता करना वच्चों के चक्र में अंतर लाने के सर्वाधिक अर्थ में नयी की जानी चाहिये। परिवार नियोजन का उद्देश्य राजागभव परिवार का विकास समाज की एक इकाई के रूप में इस भाव निर्माण करने में जाता चर्चिय निम्न उन 'शाओ को पूरा करने में सुविधा है। ता उस 'शाओ के कल्याण के लिए सामाजिक सामर्थ्य और अधिक दृष्टि से आवश्यक है। इस प्रकार परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य अनियमित जनम दर को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम देश के अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य पौष्टिक आहार शिक्षा रक्षण और सामाजिक परिवर्तन के रूप में सफल बनाने में भी मदद है। ताकि परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में मदद हो सके।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम मई 1952 में अपनाया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम का विधिवत आरम्भ मई 1963 में हुआ जबकि परिवार नियोजन अनुसंधान कार्यक्रम समिति का गठन हुआ तथा सरकारों को पर इस अनुमति कार्यक्रम घोषित किया गया। राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम का विस्तार अपेक्षाानुरूप नहीं कहा जा सकता सरकार के अत्यधिक प्रचार एवं प्रयासों के बावजूद भी ग्रामीणों में यह अभी भी प्रभावी नहीं बन पाया है। राजस्थान में विभिन्न परिवार कल्याण विभागों के द्वारा जो व्यापक अभियान चला रहे हैं उनकी मूल्यांकन वर्षों में निम्न प्रकार रही है।

वर्ष	साप्ताहिक व्यक्तियों की संख्या
1983-84	3 29 438
1984-85	364355
1985-86	555050
1986-87	626803
1987-88	6767 7
1988-89	55 371
1989-90	8 26 78
1990-91	6 96 346
1991-92	7 67 706
1992-93	8 15 274
1993-94	9 75 66
1994-95	9 67 8
1995-96	980762

राजस्थान में व वैवाहिक जाड़ जा कि पुनर्जादन आयु के अन्तर्गत आता है उनका मूल्यांकन विगत वर्षों में निरंतर बढ़ती जा रहा है साथ ही उन परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी कुछ सफलता मिली है इससे आभास अब जाहिर हो रहा है।

वर्ष	पुनर्जादन आयु में वैवाहिक जाड़ (हजार)	प्रचारपूर्ण तरीके से परिवार कल्याण कार्यक्रम के संचालन करने वाले लोग की संख्या
1983-84	6603	17 9
1984-85	67 9	9 4
1985-86	6822	23 1
1986-87	7003	20 0
1987-88	7187	27 9
1988-89	8095	29 4
1989-90	8327	30 7
1990-91	8427	30 4

राजस्थान के जिन जिलों में साक्षरता का प्रसार अधिक हुआ है उनमें परिवार कल्याण कार्यक्रम अत्यधिक जाहिर की तुलना में अधिक प्रभाव रहा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों का अभाव राजस्थान के ग्रहण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम अधिक प्रभाव रहा है। राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रगति में निम्न आधार अनुभव की जाता रहा है।

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयास

राजस्थान सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का अपनाया है। राज्य का विभिन्न शाखाओं में व कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता रहा है इससे जनसंख्या नियंत्रण में कुछ कमी भी हुई है।

1 राजलक्ष्मी बान्ध स्कीम। साप्ताहिक परिवार का प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1992-93 में यह प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना के अन्तर्गत निम्न परिवार में माता या पिता की आयु 35 वर्ष में कम हो और उन्होंने एक या दो बच्चों के पश्चात् नमस्ते आभेक्षण करण में जो सरकार एस परिवार को एक बच्चा या दो बच्चों तक के लिए एक एक हजार रुपये की सहायता प्रदान करेगा। यह राशि 20 वर्ष पश्चात् की जायेगी बच्चा के जन्म के जमा राशि और अन्य पश्चात् व उम्र नाम में नमस्ते 20 वर्ष मासिक राशि के अन्तर्गत आता होगा बच्चा की 21 वर्ष की आयु अनुमति तारी और अनुमति बच्चा की 21 वर्ष की आयु बच्चा की 31500 रुपये प्राप्ति

लेगा। राजस्थान में बॉण्ड स्कीम का जून, 1996 में सरलिकरण किया गया है। इसके अनुसार अब प्रति-पत्नी का निर्धारित आयु की सीमा को समाप्त कर दिया गया है एवं बॉण्ड के लिये राशि भी 1500 रुपये निर्धारित कर दी गई है।

2 परिवार नियोजन की नवीन विकल्प योजना - राजस्थान में परिवार नियोजन के लिए एक नवीन योजना 'विकल्प' के रूप में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण जिला परिवार कल्याण व्यूरो व कर्मचारियों आमतौर पर विचार विमर्श के द्वारा निर्धारित करेंगे। नकद राशि एवं वस्तुओं के रूप में दिये जाने वाले पुरस्कारों को समाप्त कर दिया गया और उनके लिये निर्धारित राशि का उपयोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारन में लिया जाएगा। इस योजना में निम्न विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये योजना राज्य के टोक व दौसा जिलों में प्रारंभ किया गया है।

3 पंचायत चुनाव में परिवार कल्याण सदस्यों का नवीन प्रावधान - 15 जून 1992 को परिवार नियोजन की दिशा में एक कानूनी प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत दो बच्चों के बाद निर्वाचन के एक साल के आगे की अवधि में तीसरा बच्चा होने पर चयनित पंच अथवा सरपंच स्वन ही चुनाव के लिए अयोग्य हो जायेगा। इस प्रावधान में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति रुचि बढ़ी है।

4 जनमल योजना - जनमल योजना का प्रमुख उद्देश्य जन्म दर पर नियंत्रण करना है। इस योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में अपनाया गई परिवार कल्याण की नवीन प्रवृत्ति जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर की कमी में सहायक होगी। इस योजना में जन्म दर पर नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन के सहज प्रत्येक उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और आरक्षण व. विकसित क्षेत्रों में उपस्थित कराया गया है। इसी के साथ प्रत्येक गांव में गर्भ निरोधक वितरण केन्द्र भी खोले जा रहे हैं। गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन एवं सामुदायिक आधार पर गर्भ निरोध के वितरण की योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

5 शिक्षा एवं साक्षरता - परिवार कल्याण के उद्देश्यों की ध्यान में रखते हुये शिक्षण सम्मानों का तेजी से प्रसार किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में साक्षरता कार्यक्रम लागू कर दिया गया है। सूचिकीय की मददगार से राज्य के 5 जिलों में "गुरुमित्र योजना" कार्यक्रम की जा रही है। इसी कारण सोडा की विनय सहायता से "लोक बुद्धि योजना" कार्यक्रम की जा रही है।

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम की कमियां एवं सुझाव

SHORTCOMINGS & SUGGESTIONS

1 ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रचार-प्रसार (Less publicity in Rural Sector) - राजस्थान की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जनसंख्या अशिक्षित व निर्धन है। इस कारण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार अधिक प्रभावपूर्ण रूप में लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इस समस्या का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करके किया जा सकता है।

2 प्रशिक्षित चिकित्सकों का अभाव (Lack of Trained Doctors) - देश में चिकित्सकों का अभाव है। साथ ही उनका वितरण अत्यधिक असमान है। देश के अधिकांश चिकित्सक शहरों में काम करना चाहते हैं। जबकि अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। इस कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने के इच्छुक दम्पति भी इसमें वंचित रह जाते हैं। इस समस्या का समाधान सरकार द्वारा उचित नैतिकता का निर्माण करने में निहित है। जिसमें कुछ समय तक चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाये।

3 प्राणियों का समाधान न होना (Lack of Solution of Misconceptions) - राजस्थान के मध्य में विशेष रूप से जैन धर्म में अनेक प्रकार के सुझाव हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में वे सेवाएं दे रहे हैं। इस स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा धर्म के दूर करने के लिये उचित माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारियों को चाहिए। जो घर पर जाकर लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ उनका समस्याओं पर भी नज़र रख सकें।

4 उचित देखभाल का अभाव (Lack of proper after Care) - इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रदाताओं और लालचीयताओं का प्रभाव देखा जा सकता है। लोगों को अपेक्षाएं अधिक कर लिये जाते हैं कि जितना चाहिए। किन्तु अपेक्षाओं के पूर्ण होने और उसके पश्चात् उनकी देखभाल के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें न केवल लोगों को असुविधा होगी है, बल्कि अन्य लोगों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस हेतु किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

5 अपर्याप्त साधन (Lack of Resources) - परिवार नियोजन केन्द्रों में औषधियों व अन्य सधन का निर्यात करना देखा रहता है। इस कारण प्रचार प्रसार में प्रेरित लोग जिन लोग चिकित्सा केन्द्रों पर पहुंचते हैं तो उन्हें निराशा

माना पड़ता है। यह प्रक्रिया बार-बार होने पर लोग उस कार्यक्रम से दूर होने लगते हैं। इस स्थिति को पर्याय पूर्ति के माध्यम से सुधरा जा सकता है।

6 अन्य कारण (Other Reasons) - परिवार कल्याण
के साधन अभी भी महंगे कहे जा सकते हैं। राजस्थान में विभिन्न

मनोरं पर दो जा रही शिक्षा के पाठ्यक्रमों में परिवार कल्याण कार्यक्रम सतची जानकारी का अभाव है। साथ ही परिवार कल्याण कार्यक्रमों में ऑपरेशनो पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिससे यह कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त राजनैतिक प्रोत्साहन का भी अभाव बना हुआ है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- मानव संसाधन विकास में शिक्षा के महत्व को समझाईए।
Discuss the importance of education in human resource development
- राजस्थान राज्य के वर्तमान व्यावसायिक ढांचे का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
Discuss the nature of present occupational structure of the state of Rajasthan
- राजस्थान का भारत की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत भाग है?
What is the percentage share of Rajasthan in India's population and area?
- 1981 में राजस्थान में मुख्य श्रमिका का वितरण प्रतिशत विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के अनुसार बताईए।
Mention on the percentage of occupational distribution of main workers in Rajasthan in 1981
- राजस्थान का कुल क्षेत्रफल तथा आबादी कितनी है? आबादी का कितना प्रतिशत ग्रामीणों में रहता है व कितना प्रतिशत कृषि व पशुधन में?
What is the total area and population of Rajasthan? What is the proportion of Urban and Rural population in Rajasthan?
- राजस्थान में महिला साक्षरता की दर पूरे भारत में सबसे कम है क्यों? इस समस्या को समाधान हेतु क्या कदम तत्काल उठाए जाएं?
Why female literacy in Rajasthan is lowest in the country? What immediate steps should be taken to improve the situation?
- निम्नलिखित के बारे में बताएं
(अ) जनगणना
Explain the following
(a) Census

(B) निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के प्रमुख लक्षण बताईए।
Discuss the main features of Rajasthan's population according to 1991 census
- राजस्थान में जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि की विवेचना कीजिए। ये कौन से घटक हैं जो मानव संसाधन के विकास में सहायगी रह रहे हैं?
Discuss size and growth of population in Rajasthan. What factors have contributed to human resource development?
- राजस्थान में 1991 की जनगणना के प्रमुख तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
Give a brief description on the factors raised in the census of 1991 about Rajasthan
- राजस्थान राज्य की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख कीजिए। इसकी तेज वृद्धि के कारण बताईए।
Discuss the different aspects of population of the state of Rajasthan. Give reasons for its rapid growth
- राजस्थान में जनसंख्या वितरण का व्यवसाय आधारित शहरी एवं ग्रामीण पर उल्लेख करें। ये कौन से तत्व हैं जो मानव संसाधन के विकास में सहायगी रहे हैं?
Mention on the distribution of population in Rajasthan on the basis of occupation Rural Urban and district wise. What factors have contributed to human resource development?
- मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Discuss in brief the important components of human resource development
- राजस्थान राज्य में मानव संसाधन के विकास की समस्या की विवेचना कीजिए।
Discuss the problem of Human resource development in the state of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(University Examination's Questions)

- 1 राजस्थान में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि को विवेचना कीजिए। व कौन से घटक हैं जो मानव संसाधन के विकास में सहायता रहे हैं?
Discuss size and growth of population in Rajasthan. What factors have contributed to human resource development?
- 2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए
(अ) राजस्थान में साक्षरता (ब) राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या
Write short notes on the following -
(a) Literacy in Rajasthan (b) Working population in Rajasthan
- 3 राजस्थान में जनसंख्या के आकार, वृद्धि, व्यावसायिक संरचना तथा मानव संसाधनों के विकास के निर्देशांक पर विवेचना कीजिए।
Discuss the population indicators of size, growth occupational structure and human resources development in Rajasthan
- 4 राजस्थान राज्य की जनसंख्या का प्रमुख विशेषण बताइए।
Discuss the major characteristics of population of the state of Rajasthan
- 5 राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का वितरण का विश्लेषण कीजिए तथा उनकी वृद्धि दर का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
Analyse the districtwise distribution of Rural and Urban population in Rajasthan and discuss their growth rate comparatively
- 6 राजस्थान राज्य की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का प्रमुख जनसंख्या इनका तीव्र वृद्धि के कारण बताइए।
Discuss the different aspects of population of the state of Rajasthan. Give reasons for its rapid growth



राजस्थान में निर्धनता की समस्या

PROBLEM OF POVERTY IN RAJASTHAN

"निर्धनता, किसी भी राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- गरीबी व अमीरी की रेखा
- निर्धनता की केंद्री आधारित अवधारणा के दोष
- राजस्थान में निर्धनता की स्थिति
- राजस्थान में निर्धनता निवारण के लिए आवश्यक सुझाव
- राजस्थान सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए अपनाए गए कार्यक्रम
- जिला निर्धनता निवारण परियोजना
- अभ्यासार्थ प्रश्न

निर्धनता एक ज्वलन्त समस्या है। नियोजनकाल के आरंभ में यह सभावना व्यक्त की गई थी कि विकास के साथ-साथ निर्धनता की समस्या स्वतः हल हो जायेगी। किन्तु समय के साथ-साथ निर्धनों की मख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। ऐसा नहीं था कि विकास कार्य न हुये हो, वरन् जनमख्या की तीव्र वृद्धि ने इस समस्या की तीव्रता को निरन्तर बनाये रखा। इसी कारण नियोजकों को गरीबी के निवारण के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्धारण करना पड़ा। वर्तमान में विकास कार्यों के साथ-साथ निर्धनता-निवारण के जो प्रयास किये जा रहे हैं उनका प्रभाव दृष्टिगोचर भी होने लगा है। इसका आशय यह कदापि नहीं है कि गरीबी की समस्या की तीव्रता समाप्त हो गई है।

निर्धनता को जब न्यूनतम उपभाग या न्यूनतम आय से जोड़ दिया जाता है तो यह गरीबी की निरपेक्ष स्थिति को बताता है। दूसरी ओर एक आय वर्ग की तुलना दूसरे आय-वर्ग से की जाए या एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से की जाये या एक राष्ट्र की आय की तुलना दूसरे राष्ट्र की आय से की जाये तो इससे निर्धनता की सांश विचारधारा को बल मिलता है। भागत एव राजस्थान में सुनिधा की दृष्टि में निर्धनता की निरपेक्ष विचारधारा को अपनाया गया है।

गरीबी की रेखा व अमीरी की रेखा

POVERTY LINE & 'AMIRI KI REKHA'

“गरीबी में तात्पर्य मूल रूप से भोजन, वस्त्र व आवास जैसी आवश्यकताओं के अभाव से है। अतः गरीबी की रेखा निर्धारित करते समय भोजन, वस्त्र, आवास, जलापूर्ति तथा शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी उन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये, जिसमें आज गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले भी वंचित हैं।” गरीबी की रेखा के सर्तर्ष में विवेचन करते हुये यह बताना युक्तिमय प्रतीत होता है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह ने अपने कार्यकाल में ‘अमीरी की रेखा’ निर्धारित करने का विचार भी राष्ट्र के समक्ष रखा था, किन्तु इस मर्तर्ष में कुछ कार्यवाही नहीं हो सकी।

सर्वप्रथम 1960-61 में उन लोगों को निर्धन तथा गरीब की श्रेणी में रखा गया जो न्यूनतम कैलोरीज प्राप्त करने हेतु आवश्यक आय बुटाने में असमर्थ थे। 1960-61 में 20 रुपये से कम मासिक निर्वाह क्षमता वाले लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखा गया। 1968-69 में न्यूनतम मासिक जीवन निर्वाह व्यय की राशि को बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया। 1973-74 को प्रचलित कीमतों पर गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 49 1 रुपये व शहरी क्षेत्र के लिये 58 1 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। 1976-77 में प्रचलित कीमतों के आधार पर योजना आयोग ने न्यूनतम जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि करते हुये ग्रामीण के लिए इस 61 50 रुपये तथा शहरी लोगों के लिये 71 30 रुपये निर्धारित किया।

1979-80 की कीमतों पर न्यूनतम जीवन निर्वाह व्यय शहरी क्षेत्र के लिये 88 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 76 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया जो ग्रामीण व्यक्ति के लिए 2400 तथा शहरी व्यक्ति के लिये 2100 कैलोरी के बराबर भोजन व अन्य सामग्री बुटाने के लिये पर्याप्त हो।

1983-84 की कीमतों पर शहरी क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 117 50 रुपये से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 101 80 रुपये से कम थी तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना गया। 1991-92 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा क्रमशः 181 50 रुपये व 209 50 रुपये आजी गई।

‘गरीब कौन है?’ गरीबी रेखा क्या है? इस मर्तर्ष में समय-समय पर विचार व्यक्त किया जाने रहे हैं। भारत में नेशनल सेमिनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदत्त परेल्

उपभोग व्यय के पंचवर्षीय सर्वे आंकड़ों एवं 1979 में योजना आयोग द्वारा गठित “न्यूनतम आवश्यकता व प्रभावी उपभोग माग अनुमान टास्क फोर्स” के प्रतिवेदन में दी गई गरीबी की रेखा को दृष्टिगत रखते हुये भारत का योजना आयोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी की माप का अनुमान लगाता है। “केंद्रीय माध्यमिकीय माठन (CSO)” द्वारा कुल निम्ने उपभोग व्यय के हल में लगाये गये अनुमानों, “नेशनल सेमिनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन” के 50 वें चक्र (1993-94) के प्रारम्भिक परिणामों तथा जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के उपलब्ध हो जाने के कारण गरीबी के अनुमानों को संशोधित किया गया है।

गरीबी की रेखा (रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह)			
वर्ष	कीमतें	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1973-74	1973-74 की कीमतों पर	49 1	58 6
1987-88	1987-88 की कीमतों पर	132 0	152 3
1993-94	1993 94 की कीमतों पर	228 9	264 1

1987-88 के पूर्व निर्धनता सर्वेधी अनुमान “नेशनल सेमिनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन” के 43 वें चक्र (जुलाई, 1987 जून 1988) के आंकड़ों पर आधारित थे।

1993-94 के निर्धनता सर्वेधी अनुमान “नेशनल सेमिनल सर्वे” के 50 वें चक्र के प्रारम्भिक आंकड़ों पर आधारित है। इस चक्र के संपूर्ण आंकड़े प्राप्त होने पर इन आंकड़ों में संशोधन संभव है। इन अनुमानों में (1 अक्टूबर 1993) की जनसंख्या को लिया गया है।

मार्च 1997 में भारतीय योजना आयोग ने गरीबी की रेखा के निर्धारण के लिए नेशनल सेमिनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुमानों को त्याग कर “लकडवाला सूत्र” को अपनाया है। इस सूत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के उद्योक्त मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक को निर्धनता आंकड़ों के लिये आधार बनाया गया है। इस कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धनता रेखाएँ होंगी। राजस्थान में निर्धन लोगों की संख्या निम्न तालिका में स्पष्ट है -¹

(लाखों में)		
	1987-88	1993-94
राजन्य क्षेत्रों का विधि के अनुसार	84 3	41 7
निर्देशक नमूने के अनुसार	140 3	129 8
निर्देशक नमूने (घर-घर) के अनुसार	142 9	128 5

का दृष्टि से काफी विकसित हो चुके हैं तो अनेक जिले उद्योग रहित जिला की श्रेणी में आते हैं।

5 सामाजिक सुविधाओं का अभाव (Lack of social infrastructure) राजस्थान में सामाजिक सुविधाओं का स्तर अत्यन्त निम्न है। नियोजन काल में इस आशय का ध्यान देने के बावजूद भी ये सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। राजस्थान में व्यापक निरक्षरता है। विधवाएँ एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। राजस्थान के सभी गाँवों में पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है। कृषि के विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें सुविधाएँ, शिक्षा के माध्यमों, रेल व सड़क मार्गों की स्थापना अपर्याप्त रही है। सामाजिक सेवाक्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं पाषाण को स्थिति संतोषजनक नहीं है।

6 सामाजिक पिछड़ापन (Social backwardness) राजस्थान में विद्यमान परम्परागत सामाजिक ऋद्धिवादी व धार्मिक अंधविश्वासों ने राजस्थान के निवासियों को गरीबी का ओढ़ धकेला है। विवाह व मृत्युभाज जैसे अवसर पर आने भी अत्यधिक धन व्यय किया जाता है। बच्चों का भगवान की दान मानने के कारण जनमरणा में तत्पर गति में वृद्धि हो रहा है। समुचित परिवार तथा भाग्यवादिता ने लोगों की पराजित व अर्चमय बना दिया है। शिक्षा की आवश्यकता अनुभव न करने के कारण ये परम्पराएँ समाप्त नहीं हो पा रही हैं। समाज में व्याप्त खराब परम्पराओं को तुरन्त नष्ट बदला जा सकता है किन्तु शिक्षा के प्रसार के माध्यम से इन पर धीरे-धीरे चोट पहुँचाई जा सकती है।

7 मूल्य वृद्धि (Price rise) राजस्थान में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी के कारण गरीबी की समस्या बड़ी है। दालाँ एवं खाद्य तेलों व खाद्यान्नों जैसी वस्तुओं की मूल्य में अधिक वृद्धि के कारण लोगों का जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्थिर आयवर्ग के लोग भी गरीबी का ओढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी कानून भी प्रभावी नहीं है। इस कारण मूल्यवृद्धि का प्रभाव और व्यापक हो जाता है।

(8) सामूहिक सम्पत्ति का ह्रास (Depreciation of Community Assets) सामूहिक सम्पत्ति जैसे चारागाह, गन्नाखेत आदि के मध्यम में निर्धन लोगों का कुल-आय घटता जा रहा है। वे कुछ श्रम करके इनमें अपनी अर्जित कमान की रक्षा कर सकते हैं। धारणा इन सामूहिक सम्पत्तियों का या तो निगल-गला हो रहा है या तो विभिन्न बान्दों के मध्यम में उनका प्रयोग करने की संभावना कम हो गई है। इसका दुष्प्रभाव मुख्यतः निम्न वर्गों पर पड़ा है।

वे इसमें मिलने वाली आय में वृद्धि हो गयी और उनके समर्थ आजीविका कमाई की समस्या उत्पन्न हो गई। परिस्थिति की मनुष्य के व्यपन्न शरीर शरीर से जनजाति भी अपने पालन के बन्धों का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है।

(9) निर्धनता व आर्थिक असमानता (Poverty and Economic Inequality) राजस्थान में आर्थिक असमानता के कारण कुछ ही लोगों के पास धन व सम्पत्ति कनिष्ठ स्तर का ब्रह्म निरन्तर गरीबी में अर्जित है। वही अल्पविकाश जनमरणा निर्धन में निर्धनतर होता जा रहा है। राजस्थान में निम्न आय व उच्चभोग स्तर के कारण लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। अतः राजस्थान में गरीबी का कारण गरीबी स्वयं है। गरीबी के कारण राजस्थान निर्धनता के बुलन्द में फँसा हुआ है।

(10) बेरोजगारी (Unemployment) राजस्थान में व्याप्त बेरोजगारी गरीबी की समस्या की मूल कारण है। राजस्थान के आर्थिक विकास के साथ-साथ राजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है किन्तु जनमरणा में और भी तेजी से वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की संख्या तेजी में बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है।

राजस्थान में निर्धनता निवारण के लिए आवश्यक सुझाव

राजस्थान में निर्धनता की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुका है। अतः इस समस्या का निवारण हेतु प्रभावशाली प्रयासों का आवश्यकता है। राज्य के निर्धारण निवारण के निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं।

1 जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य का जनमरणा का नियन्त्रित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य का अन्तर्गत करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभाव डालने से लाभ किया जाना चाहिए तथा 'हम दो हमारे' के मिशन का अपना पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2 उद्योगों का विकास राज्य में औद्योगिक विकास का गतिमान होना चाहिए ताकि राज्य के अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए नए उद्योग उद्योग के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इन उद्योगों में निम्नलिखित उद्योगों में विशेष ध्यान दे दिया जाना चाहिए।

3 राजगार नीति राज्य में राजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए एक राजगार नीति बनानी चाहिए।

क्रिया जाना चाहिये। इस बात में राज्य की विशाल भूमि व उपभोग पर चल दिया जाना चाहिये तथा शिक्षा को उच्चतर उल्लेख, वगैरह के साथ राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योग वृषि व्यापार तथा परिवहन आदि का तात्पर्य में विस्तार किया जाना चाहिये।

4 मापान्तरिक स्तर में वृद्धि राज्य में निर्धनता का व्यपकता को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्तर में वृद्धि करना निम्न आवश्यक है। इसके लिये शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिये। निधनता को चिकित्सा सुविधा तथा आनन्द आवश्यकताओं का पूर्ण पथान मात्रा में का जाना चाहिये। प्रमाण मात्रा में एम। सुविधा का विस्तार पर निम्न वक्तव्य द्वारा किया जाये।

5 मन्त्रालय का उपयोग राज्य का एक बहुत बड़ा भूभाग सम्पन्न है। इस विशाल भूभाग का योजनाबद्ध रूप से उपयोग करके राज्य में निर्धनता को कम किया जा सकता है। इस क्षेत्र के उपयोग हेतु राज्य के वैज्ञानिकों का आग्रह किया जाना चाहिये और इससे अधिक नहर तथा शुद्ध जल नम कार्यक्रमों का खाज का जाना चाहिये।

6 भूमि सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं पुर्नगठन राज्य के भूमि सुधार कार्यक्रम का विशिष्टता द्वारा समझा जा सकता है। इसका कमियाँ एवं टप्पा का ध्यान रखते हुए इसका पुर्नगठन किया जाना चाहिये ताकि राज्य के अधिकारी भाग इसमें लाभान्वित हो सकें।

7 सहकारिता का विस्तार सहकारिता आन्दोलन राज्य में निर्धनता नकारण का मूल मंत्र हो सकता है। इस उद्देश्य का प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण आन्दोलन का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

8 प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग परंपरा पृथक के अन्तर्गत राज्य के विशाल प्राकृतिक सम्पत्ति विशेषतः खनिज संसाधनों का समुचित विवेचन करना हो पाया है अतः प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त उपयोग उसका राज्य में निर्धनता को भविष्य का कम किया जा सकता है।

9 अन्य मुद्दाएँ

(i) राज्य के कानून एवं नियमों का कठोरता एवं लागू किया जाना चाहिये।

(ii) प्रमाण क्षेत्र का निम्न स्तर का प्रमाण आवश्यकता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिये।

(iii) सार्वजनिक निर्माण कार्य का विस्तार करके राज्य सरकार के अवसरों में वृद्धि का प्रमाण होना चाहिये।

(iv) राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक प्रसारण के

समाप्त किया जाना चाहिये।

(v) पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

राजस्थान सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए अपनाये गये कार्यक्रम

RAJASTHAN GOVERNMENT'S PROGRAMMES FOR ERADICATION OF POVERTY

राजस्थान में निधनता एवं वरजगाता के उन्मूलन के लिए राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं।

- 1 समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2 ग्रामीण युवाओं का स्व-राजगार हेतु प्रशिक्षण
- 3 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम
- 4 जवाहर राजा योजना
- 5 जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम
- 6 मत्स्य विकास कार्यक्रम
- 7 सूखा सहायता क्षेत्र कार्यक्रम
- 8 अन्त्यादय योजना
- 9 20 सूत्री कार्यक्रम
- 10 बजट भूमि विकास कार्यक्रम
- 11 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
- 12 मवात क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम
- 13 अभावता विकास कार्यक्रम
- 14 माहिला विकास कार्यक्रम
- 15 अपना गांव-अपना काम योजना
- 16 कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम
- 17 सामाजिक विकास कार्यक्रम
- 18 कटारा सुधार कार्यक्रम

उपरोक्त सभी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण एक अलग अध्याय में किया गया है।

जिला निर्धनता निवारण परियोजना

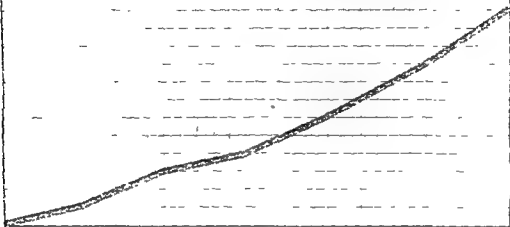
DISTRICT POVERTY INITIATIVE PROJECT (DPIP)

यह निधनता निवारण का नया योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम है। विश्व बैंक का सहयोग में राज्य के 7 जिलों गजमेन्द्र, दौसा, बाण, चुरू, जयपुर, जालंधर और जयपुर में इन कार्यक्रमों का प्रारंभ करना प्रस्तावित है। विश्व बैंक के नि

अध्याय - 4

राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या

PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN



“संसार में पाच आर्थिक राक्षस मानव जाति को ग्रसित करने के लिए तैयार हैं - निर्धनता, अज्ञानता, गंदगी, बीमारी और बेरोजगारी, परन्तु इन सबमें सबसे अधिक भयकर बीमारी है बेरोजगारी।”
- सर विलियम वेबरीज

अध्याय एक दृष्टि में

- बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार
- बेरोजगारी की अवधारणाएँ
- राजस्थान में श्रम शक्ति
- राजस्थान में रोजगार
- राजस्थान में बेरोजगारी का आकार
- राजस्थान में बेरोजगारी के कारण
- राजस्थान में बेरोजगारी को हल करने के सुझाव
- नवी योजना में रोजगार सृजन की रणनीति
- राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार सृजन के कार्यक्रम
- राजस्थान में रोजगार के अवसरों की सम्भावनाएँ
- राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति
- अप्रत्याशित घटनाएँ

बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार

MEANING & TYPES OF UNEMPLOYEMENT

सर विलियम वेबरीज ने बेरोजगारी के संवर्ध में लिखा है कि - “संसार में पाच आर्थिक राक्षस मानव जाति को ग्रसित करने के लिये तैयार हैं - निर्धनता, अज्ञानता, गंदगी, बीमारी और बेरोजगारी, परन्तु इन सबमें सबसे अधिक भयकर बेरोजगारी है। बेरोजगारी की स्थिति न केवल बेरोजगार व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है, बल्कि इससे समाज व राष्ट्र को भी हानि होती है।” बेरोजगारी का आशय उस स्थिति में होता है जिसमें काम चाहने वाले सफल व्यक्तियों की सेवाओं की पूर्ति उनकी मांग का तुलना में अधिक होती है। राजस्थान में मुख्यतः ग्रामीण बेरोजगारी एवं शिक्षित बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक व्यापक रूप धारण करती जा रही है, जो दूसरी ओर साक्षरता में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या भी विकसित रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या है तो शहरों में शिक्षित बेरोजगारी के रूप में खुली बेरोजगारी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित व अकुशल श्रम की बेरोजगारी की समस्या है तो शहरों में डॉक्टर, इंजीनियर व उच्च शिक्षित व्यक्ति भी बेरोजगारी के शिकार हैं। राजस्थान का जनमानस

उमसे अधिक के आयु वर्ग की श्रम-शक्ति में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार 1992-97 के मध्य अर्थात् आठवीं योजना के अंतर्गत राजस्थान में श्रम-शक्ति में 26.33 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होने का अनुमान था।¹ राजस्थान में श्रम-शक्ति का आयु एवं लिंग के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभाजन इस विश्लेषण से स्पष्ट है-

1 राज्य के शहरी क्षेत्रों में मार्च 1997 में महिला श्रम-शक्ति की अपेक्षा पुरुष श्रम-शक्ति अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी प्रायः ऐसी ही है। पुरुष व महिला श्रम शक्ति में इतना अधिक अंतर होने का प्रमुख कारण यह है कि राजस्थान में स्त्रियों की शिक्षा एवं पालन पोषण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना है और वे प्रायः घरों तक ही सीमित रहती हैं।

2 आयु वर्ग के अनुसार श्रम-शक्ति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि शहरी व ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में अधिकांश श्रम शक्ति 15-29 आयु-वर्ग में है।

3 नवी योजना व अतः के अनुदान का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पुरुष एवं महिला श्रम-शक्ति में दशोत्तरी के अतिरिक्त कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इस समय भी पुरुष श्रम का बाहुल्य बना रहेगा।

राजस्थान में रोजगार की स्थिति

EMPLOYMENT SITUATION IN RAJASTHAN

राजस्थान में लोगों की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार की स्थिति निम्नवत है -

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति (लाख व्यक्तियों में)			
वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1998	8.30	1.97	10.27
1988	9.12	2.00	11.12
1993	9.27	2.31	11.58
1992	9.73	2.31	12.04
1994	10.05	2.43	12.48
1995	10.09	2.55	12.64
1996	10.17	2.67	12.84
1997	10.13	2.63	12.76
1998	10.15	2.62	12.77
(जुल 98 तक)			

स्रोत: Budget 1997-98, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, Rajasthan.

उपरोक्त तालिका में निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1 राजस्थान में निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इसका प्रमुख कारण यह

है कि स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य व केन्द्र सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है।

2 राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा अन्य राज्य के निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

3 नवी पंचवर्षीय योजना के निजी क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अतः निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है।

राजस्थान में पञ्जीकृत निर्माणियों की मख्या और उनमें उपलब्ध रोजगार की स्थिति अग्निलिखित विवरण के अनुसार है -

पञ्जीकृत निर्माणियों की मख्या तथा रोजगार		
वर्ष	पञ्जीकृत निर्माणियों की मख्या	कुल रोजगार (लाख में)
1981	6608	1.66
1991	10797	2.60
1993	12580	

स्रोत: Budget Study 1992-93

पञ्जीकृत निर्माणियाँ एवं रोजगार की कमी का कारण भारतीय करखाना अधिनियम 1948 की धारा 85 में मुद्रणालयों को हटाया जाना है।

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1 1981 से 1993 के मध्य पञ्जीकृत निर्माणियों की मख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

2 1990 में निर्माणियों की मख्या में पुनः वृद्धि हो गई। अतः रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। 1981 की तुलना में पञ्जीकृत उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 1993 में रोजगार के अवसर लगभग दुगुने हो गये। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों में रोजगार की स्थिति निम्न प्रकार थी -

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार (31-12-1996)	
शाखा/उद्योग	कर्मचारियों की मख्या
राजस्थान	1017532
1 शाखाओं का वर्गीकरण	
a कृषि सम्पदा	172801
b राज्य सरकार	528353
c अर्द्ध-सरकारी	192001
d स्वतंत्र विभाग	124377
2 कृषि, वन्य-सम्पदा, प्रत्यक्ष अर्थ	23431
3 वित्त के सब वर्गीकरण	
a संचय और बचत	19540
b-ऊँचा स्तर	26443

स्रोत: Five Year Plan 1997-97, Govt. of Rajasthan

19	डिलिका सखु	908
20	घररकते	248
21	मैपेसइट	1
22	काल्मेटोरइट	1925
23	रॉक फाम्पट	3932
C धवन-निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिज		
1	धवन निर्माण में (कचरा बजरी व फलक)	107817
2	चूरा बनाने के लिए चूरा प्रदा	22571
3	मन्कल	73319
4	इन्टोनइट	105
5	एल्व्स अर्ब	104
6	विस्फ अर्ब व ऑक्सीडरी कल	12116

Source: Statistical Abstract 1996, Rajasthan.

उपरोक्त तालिका के विरलेषण से ज्ञात होता है कि -
1. खनन क्षेत्र में भवन-निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है।

2. मारबल, चूना बनाने, सोप स्टोन, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सोला-जस्ता व चाँदी तथा खनिज तांबा आदि से अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। लोहा, डोलोमाइट, गारेनेट, बेरिमकुलाइट तथा बेन्टोनाइट आदि से अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है।

राजस्थान में बेरोजगारी का आकार SIZE OF UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान में श्रम शक्ति के आकार की तुलना में रोजगार के अवसरो से तुलना करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना 2 04 लाख लोगों की बेरोजगारी के साथ आरम्भ होगी। सामान्य स्थिति के 2 04 लाख व्यक्ति ग्रामीण-शहरी, स्त्री-पुरुष एवं आयु-वर्ग के अनुसार इस प्रकार है।

राजस्थान में सामान्य स्थिति के बेरोजगारी का अनुमान (1 जन 1997) (हजारों)					
अयु	शहरी		ग्रामीण		
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	कुल
5-9	-	-	-	-	-
10-14	27	183	76	-	286
15-29	2174	468	1286	92	4020
30-44	516	541	65	50	1172
45-59	169	167	38	-	374
60+	05	-	-	-	05
कुल	2891	1359	1465	142	5857

13th Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2000, Govt. of Raj.

उपरोक्त तालिका के विरलेषण से ज्ञात होता है कि -

1. राजस्थान में मार्च, 1997 में शहरी क्षेत्रों के 15-29 आयु वर्ग के 284 2 स्त्री व पुरुष थे, जबकि इसी समय इसी आयु वर्ग के 137 8 हजार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार थे। अतः इस आयु-वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर थी।

2. तालिका के सामान्य विवेचन से ज्ञात होता है कि 1997 में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के पुरुष अधिक संख्या में बेरोजगार थे।

3. स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक संख्या में बेरोजगार थे। विभिन्न आयु वर्गों की तुलना में 15-29 आयु वर्ग के पुरुष एवं स्त्री अधिक मात्रा में बेरोजगार थे। यद्यपि शहरी महिलाएं 30-48 आयु वर्ग में अधिक बेरोजगार थीं।

रोजगार कार्यालयों में जिलेवार पंजीकृत व्यक्ति

DISTRICTWISE REGISTERED APPLICANTS IN EMPLOYMENT EXCHANGES

राजस्थान के विभिन्न जिलों में रोजगार के इच्छुक लोगों की रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत संख्या निम्नलिखित थी -

राजस्थान के रोजगार कार्यालयों की जिलेवार स्थिति		
प्र.सं.	वर्ष के जन्म में रोजगारकार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या	
दिनांक 1985	686341	
दिनांक 1990	915018	
दिनांक 1995	895213	

13th Statistical Abstract 1996 & 1998 some facts about Rajasthan & Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan.

विरलेषण से ज्ञात होता है कि

1. रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

2. रोजगार के इच्छुक आवेदकों के जिलेवार आकड़ों से स्पष्ट है कि जयपुर जिले में रोजगार चाहने वालों की संख्या सर्वाधिक थी।

3. अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर आदि राज्यों में भी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या पंजीकृत संख्या थी।

4. राज्य के जैसलमेर, जालोर, मिरां, झालावाड़, धौलपुर,

चाहती है तो उसे लघु व ग्रामीण उद्योग, सहकारिता, वृहद् एवं मध्यम उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जलापूर्ति, ग्राम एवं श्रम-कल्याण आदि पर अधिक धन व्यय करना चाहिए।

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन के अनुमान हेतु जो मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं -

कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु निर्धारित मानदण्ड		
क्र.सं.	फसलें	एक बीघे श्रम की आवश्यकता (मानव दिवस प्रति हेक्टेयर)
1	धान	81
2	ज्वार	48
3	बाजरा	35
4	गन्ना	
	(अ) सिंचित	59
	(ब) अमिचित	50
5	गहूँ	
	(अ) सिंचित	95
	(ब) अमिचित	40
6	जौ	89
7	दालें (चना, मूंग आदि)	32
8	तिन	35
9	मुगन्ना	52
10	गन्ना	150
11	कपास	147
12	मिर्च	120
13	खार	25

स्रोत: Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002 Govt. of Raj

उपराक्त तालिका में निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1 निर्धारित मानदण्ड के अध्ययन से ज्ञान होता है कि गन्ने की खेती के विस्तार के फलस्वरूप रोजगार के अधिक अवसर सृजित होने की संभावना है, लेकिन राज्य में गन्ने की खेती के लिए आवश्यक दृष्टांत सीमित क्षेत्र में ही उपलब्ध है। अतः वर्तमान में गन्ने की खेती का अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता है। इंटिग्रेटेड गन्ना नहर परियोजना क्षेत्र में गन्ने की खेती के लिए आवश्यक दृष्टांत उपलब्ध है। यदि नहर निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाये तो गन्ने की खेती का विस्तार करके अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

2 कपास एवं मिर्च की खेती के विस्तार से भी रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर सृजित होने की संभावना है। राज्य में सिचाई सुविधाएँ सीमित क्षेत्र में उपलब्ध हैं। यहाँ

कारण है कि इन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। सिचाई-सुविधाओं में वृद्धि करके ही इन फसलों के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

3 धान की खेती के विस्तार से भी रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होते हैं, लेकिन राज्य के वर्षा के अभाव एवं सिचाई के माध्यम की अपर्याप्तता के कारण धान की खेती का क्षेत्र सीमित है। अतः सिचाई सुविधाओं का विस्तार करके ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। ज्वार, बाजरा, दालें, मूंग व तिलहन की खेती में अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है लेकिन इन फसलों की खेती के लिए प्रायः सिचाई के साधनों की अधिक आवश्यकता नहीं होती। इनकी खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। अतः पर्याप्त वर्षा की स्थिति में इन फसलों की खेती का विस्तार करके रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर सृजित किये जा सकते हैं।

राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति VYAS COMMITTEE ON EMPLOYMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने 10 अक्टूबर, 1990 को विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक डॉ. बी.एम. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को मुख्यतः निम्नलिखित कार्य सौंपे गये थे -

1 रोजगार की स्थिति की समीक्षा करना - आगामी 10 वर्षों में श्रम-शक्ति की संभावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये आगामी 10 वर्षों में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए रोजगार की दर निर्धारित करने का सुझाव देना।

2 ऐसे क्षेत्रों, विभागों और क्रियाओं की जाँच करना, जिनमें बेरोजगारी की स्थिति अधिक गंभीर है और आने वाले 10 वर्षों में और अधिक गंभीर होने की संभावना है।

3 ऐसे गतिशील क्षेत्रों, जिनमें औद्योगिक विकास का पता लगाना, जिनमें प्रभावी रूप से उत्पादक रोजगार की संभावनाएँ विद्यमान हैं।

4 निम्नलिखित के मदर्भ में प्रवृत्त नीति एवं उपाय का सुझाव देना -

(अ) कानून एवं अनुदान

(ब) विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन

(घ) कच्चे माल की पूर्ति के लिए आधारभूत सुविधाएँ सृजित करना

(द) प्रशिक्षण एवं कुशलता का निर्माण

व्यास समिति के प्रथम दो बिन्दुओं के मदर्श में अपना सर्वप्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं -

1 राजस्थान को रोजगार सरचना में कृषि का अधिपत्य है और इसके अन्तर्गत रोजगार के स्वरूप के विविधीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सभावना नहीं है। गैर कृषि-क्षेत्र में राज्य सरकार सबसे बड़ी नियोजता है।

2 1980 के दशक में राजस्थान में रोजगार सृजन की दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है। दूसरी ओर, राजस्थान में श्रम-शक्ति राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक बढ़ी है। यही कारण है कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर से अधिक है।

3 क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से राजस्थान के दक्षिणी और उत्तरी-पूर्वी जिलों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर है।

4 राजस्थान में अल्परोजगार की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। अल्परोजगार की दर भी राजस्थान में राष्ट्रीय दर से अधिक है।

5 राजस्थान में उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जैसे-इंजीनियर, चिकित्सक आदि वर्गों में भी बेरोजगारी की दर अत्यधिक है।

■ समिति का मत है कि यदि सन् 2000 तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना है तो विकास दर को 1980 के दशक की विकास दर 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2.5% करना होगा।

व्यास समिति ने "राजस्थान में रोजगार समस्या की व्यापकता और भावी सभाबनाए" शीर्षक के अन्तर्गत अंतरिम रिपोर्ट जुलाई, 1993 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में 1980 के दशक में रोजगार सृजन की दर भारत की दर से कम रही है। राजस्थान में श्रमशक्ति में वृद्धि की गति भी भारत की तुलना में अधिक रही है। समिति के अनुसार ग्रामीण पुरुषों, दक्षिणी पूर्वी जिलों तथा शिक्षा के निम्न स्तर पर बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर है। इस समस्या से सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित हैं और वे इसकी गंभीरता को महसूस करती हैं। प्राणीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर 5-14 वर्ष तक के बच्चों में काम लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी बाल श्रमिक अधिक हैं। समिति के अनुसार राज्य में बेरोजगारी के अतिरिक्त सबसे अधिक समस्या अर्द्ध रोजगार की है। राज्य में अर्द्ध रोजगार की दरें संपूर्ण भाग की दरों से अधिक हैं। राज्य के जिलों में केवल गगनगर को छोड़कर शेष सभी जिले अर्द्ध रोजगार की समस्या से ग्रसित हैं। मध्यवर्ती व दक्षिणी जिलों की स्थिति अधिक खराब

है।

राजस्थान में रोजगार का ढाँचा मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इसे बहुआयामी बनाने के प्रयास नहीं किये गये हैं। राज्य का संगठित क्षेत्र बहुत कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र में आज भी सरकार ही सबसे बड़ी विनियोजक है। क़रखानों में जितने लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, उसमें कहीं अधिक रोजगार राज्य के शिक्षा व पुलिस विभाग ही दे देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी रोजगार के अधिक अवसर सृजित नहीं कर पाये हैं। राज्य के केवल दो सरकारी उपक्रमों-राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल और राजस्थान राज्य पशु परिवहन निगम को छोड़कर शेष सभी सार्वजनिक उपक्रमों में सबको मिलाकर भी नाममात्र का ही रोजगार मिल पाता है। राज्य के खनिज क्षेत्र के बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

1990-91 में राज्य में बेरोजगारी का "बैकलॉग" लगभग 3.5 लाख से 4.8 लाख रहा है अर्थात् इतनी मछली में लोगों को रोजगार नहीं मिला। समिति ने योजना निर्माण के लिए बैक लॉग के अधिकतम आकड़ों के प्रयोग का सुझाव दिया है। सन् 2000 तक सबको रोजगार देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने राज्य के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के लगभग 50 लाख नये अवसर सृजित करने की आवश्यकता बतायी। ऐसा करने पर ही सन् 2000 तक 4.8 लाख रोजगारों के बैक लॉग को पूरा किया जा सकेगा। इससे 15-59 वर्ष तक की आयु के बेरोजगारों को भी रोजगार दिया जा सकेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 2.5% की दर से रोजगार में वृद्धि करनी होगी। 1980 के दशक में राज्य में रोजगार की बढ़ोतरी की दर 2.1% रही है। समिति ने रोजगार के सख्तात्मक पहलुओं के अतिरिक्त गुणात्मक पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। इसके लिए शिक्षित एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिये और महिलाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उनके कार्य की स्थितियों को अच्छा बनाया जाना चाहिये। समिति के अनुसार राज्य के दक्षिणी जिलों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि वहां बेरोजगारी के अनुपात और अर्द्ध-बेरोजगारी की व्यापकता को कम किया जा सके।

राजस्थान में बेरोजगारी के कारण

FACTORS RESPONSIBLE FOR UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN

1 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि - राजस्थान में जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से भी अधिक गति से बढ़ रही है जबकि

इस दर में राजगार का अवसर का सुझाव नहीं हो पा रहा है। इस कारण बेरोजगारी का माध्यम निरंतर बढ़ रहा है। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिये।

2. रेगिस्तानी क्षेत्र व ग्रामीण जलवायु राजस्थान में अरावली पर्वतश्रृंखला के पश्चिम में थप का मरुस्थल विद्यमान है जो कि राजस्थान के समस्त क्षेत्रफल का एक बड़ा भाग है। इन क्षेत्र में जलवायु अत्यन्त विषम है एवं कृषि भा कम बरफ मिच्छाई मरगा के अभाव में मिच्छाई अवस्था में है। कृषि के मिच्छाई के कारण कृषि महत्वक उद्योग पर्याप्त मात्रा में नहीं उपज मंडिया एवं राजगार सृजित करने वाल अन्य कार्यों का अभाव है। इनस्वरूप बेरोजगार है।

3. कृषि क्षेत्र में राजस्थान का भूमिगत जल संचयन कृषि कार्य में लगा हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में छिपा हुआ बेरोजगारी की समस्या भी है। भूमि के प्रति प्रेम मानसून की अनिश्चितता कृषि पर अधिक जनसंख्या खेती का छोटा आकार उछा का बिखरा होना अवैज्ञानिक भूमि उत्तराधिकार के नियम कृषि में यंत्राकरण एवं सहयक क्रियाओं का अभाव आदि कारण से ग्रामीण बेरोजगार निरंतर बढ़ा है।

4. उद्योगों का अभाव राजस्थान अनेक राज्यों का तुलना में उद्योगों का दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक कि बड़े उद्योगों का अतिरिक्त प्रमाण व कुटीर उद्योग भी पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं हो पाये हैं। इन सबका एक प्रमुख कारण कृषि के लिए पर्याप्त मूलभूत सामानों का अभाव होना चाहिये।

5. बेरोजगारी नाति का अभाव राजस्थान में बेरोजगारी व समस्या का समाधान करने के लिए समय-समय पर कुछ राजगार कार्यक्रम प्रारंभ किये गये। ऐसे उपचार प्रणाली के फलस्वरूप राज्य में बेरोजगारी का संख्या में तबड़ा में वृद्धि हुई। वस्तुतः राज्य में बेरोजगारी का प्रमुख कारण राजगार नाति का अभाव रहा है। एक व्यपक एवं प्रभावशाली राजगार नाति के द्वारा राज्य का बेरोजगारी का समस्या का हल किया जा सकता है।

6. शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में भा लाठ मकाल का शिक्षा प्रणाली आरंभ हुई। जो आज भा जारी है। इससे राज्य में नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का भाड़ा बढ़ा हुआ है। व्यस्त-मय शिक्षा के अभाव के कारण बेरोजगारी निरंतर बढ़ रहा है।

7. लघु व कटोरा उद्योगों का समाप्त होना लघु व

कुटीर उद्योग बड़ा पैमाने के उद्योगों में प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है। अब राज्य के अनेक लघु व कुटीर उद्योग समाप्त हो चुके हैं। अब बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

8. बेरोजगारी की विचारधारा राज्य में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ शिक्षित लोगों की संख्या में निरंतर बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण उनका दह विनाशकारी कि व कवच सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य कई व्यवसाय नहीं कर पाते। इस कारण राज्य में राजगार के स्वरूप कादक्ष्य मरुत नहीं हो पाया है।

9. मानव शक्ति नियोजन में होना राजस्थान में मानव शक्ति नियोजन का प्रणाली का अभाव रहा है। अब राज्य में बेरोजगारी होना स्वभाविक है।

10. अन्य कारण उद्योगों का अतिरिक्त व्यपक निक्षेपता प्रणाली सामाजिक प्रणाली व अधाव्यवस्था प्रजातिवश का अभाव अति कारण से भा राजस्थान में बेरोजगारी का समस्या उत्पन्न हुई है।

राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के सुझाव

1. जनसंख्या नियंत्रण राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा न केवल राजगार का माध्यम करने वाला व्यक्तियों की भाड़ा का रखा जा सकता है वरन् विभिन्न राजगारों के लिए राजगार की व्यवस्था का जा सकता है।

2. कृषि विकास राज्य में अर्थव्यवस्था का एक व्यपक क्षेत्र है। अब कृषि क्षेत्र एवं मिच्छाई क्षेत्र में वृद्धि के कारण राजगार के अर्थव्यवस्था में सृजित करने में सक्षम है।

3. औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास का द्वारा भा बेरोजगारी की समस्या का निरंतर किया जा सकता है। बड़े उद्योगों के विकास के साथ-साथ कृषि अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। राजगार का समाधान को हल करने में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास भा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

4. इंदिरा गांधी नहर-क्षेत्र का विकास इंदिरा गांधी नहर पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने का मिच्छाई क्षेत्र एवं विषम जलवायु का मिच्छाई क्षेत्र का कुछ हद तक अनुकूल वातावरण का मकाल है। इंदिरा गांधी नहर के कमांड क्षेत्र में कृषि का विभिन्न हल के साथ-साथ राजगार के अवसर भा उत्पन्न होगा। अब इंदिरा गांधी नहर का मृग राजस्थान एवं विभिन्न राज्यों में क्षेत्र के लिए वरदान माना जा सकता है।

5. पर्यटन उद्योग का विकास पर्यटन उद्योग राजगार

वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकता है। राज्य में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त सभावनाएँ विद्यमान हैं। अतः इन सभावनाओं का वास्तविक रूप प्रदान किया जाना चाहिये।

6 रोजगार नीति - बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये ऐसी रोजगार नीति का निर्धारण किया जाना चाहिये जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था के सभी माघनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

7 आधारभूत संरचना का निर्माण - राज्य की आधारभूत संरचना कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रों का आधारभूत ढांचा नगण्य है। अतः संपूर्ण राज्य में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करके राजगार के नवीन अवसर सृजित किये जा सकते हैं।

8 अन्य सुझाव -

- (i) राज्य में मानव शक्ति नियोजन के प्रयास किये जाने चाहिये।
- (ii) पशुपालन का तीव्र गति से विकास करके रोजगार के अतिरिक्त अन्न सृजित किये जा सकते हैं।
- (iii) सामाजिक वानिकी का विकास भी रोजगार वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- (iv) आर्थिक उदारीकरण के द्वारा भी रोजगार में वृद्धि संभव है।
- (v) बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

नवी योजना में रोजगार सृजन की रणनीति

राजस्थान का नवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन की निम्न व्यूह रचना अपनाई गई

- (i) श्रम प्रधान कार्यक्रमों का प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ii) रोजगार प्रदान करने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों (जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि), के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जायेगा।
- (iii) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (अपना गांव अपना काम आदि) में जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जायेगा।
- (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निर्धारण एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- (v) ग्रामीण नवयुवकों को विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों (गोपाल सरस्वती, स्वस्थ कर्मी आदि) का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(vi) औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जायेगा।

(vii) स्वरोजगार योजनाओं के क्षेत्र में वृद्धि हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिये आर्थिक विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जायेगा तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का प्राथमिकता दी जायेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार-सृजन के कार्यक्रम

RAJASTHAN GOVERNMENT'S PROGRAMMES FOR EMPLOYMENT GENERATION

राजस्थान में बेरोजगारी एवं निर्धनता के उन्मूलन के उद्देश्य से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं

- 1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2 ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण
- 3 ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम
- 4 जवाहर रोजगार योजना
- 5 जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- 6 मरू विकास कार्यक्रम
- 7 सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम
- 8 अन्त्योदय योजना
- 9 बीस सूत्री कार्यक्रम
- 10 बजर भूमि विकास कार्यक्रम
- 11 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
- 12 मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना
- 13 अरावली विकास कार्यक्रम
- 14 महिला विकास कार्यक्रम
- 15 अपना गांव अपना काम योजना
- 16 कन्दार सुधार कार्यक्रम
- 17 कमाण्ड थार कार्यक्रम
- 18 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अध्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

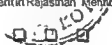
- 1 बेरोजगारी को परिभाषित करें।
Define Unemployment
- छिपे हुए बेरोजगारी क्या है?
What is disguised unemployment
- बेरोजगारी के निम्न अवधारणों को समझाइए
(i) सामान्य स्थिति (ii) सप्ताहिक स्थिति (iii) दैनिक स्थिति
Explain the following concepts of unemployment
(i) Usual Status (ii) Weekly Status (iii) Daily Status
- 4 राजस्थान में रोजगार की वर्तमान स्थिति बताइए।
Explain the present position of employment in Rajasthan
- 5 राजस्थान में बेरोजगारी का आकार बताइए।
Explain the size of unemployment in Rajasthan
- 6 राजस्थान में राज्य सरकार पर व्यास समिति पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Vyas committee on employment in Rajasthan
- 7 राजस्थान में रोजगार के अवसरों की संभावनाओं का उल्लेख करें।
Mention the employment opportunities in Rajasthan

110661

B. निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

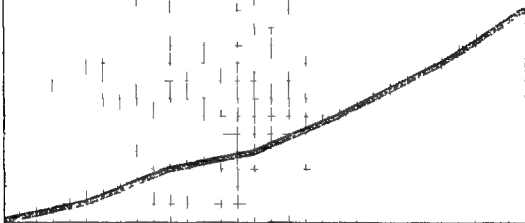
- 1 बेरोजगारी क्या है? राजस्थान में बेरोजगारी के क्या कारण हैं?
What is unemployment? What are the causes of unemployment in Rajasthan?
- 2 राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on unemployment in Rajasthan.
- 3 राजस्थान में बेरोजगारी के निम्न तथ्यों को स्पष्ट करें।
(i) बेरोजगारी का आकार (ii) बेरोजगारी के कारण
Mention the following factors of unemployment in Rajasthan -
(i) Size of Unemployment (ii) Causes of Unemployment
- 4 राजस्थान में बेरोजगारी के क्या कारण हैं? व्यास समिति का प्रमुख बालों का उल्लेख करें।
What are the causes of unemployment in Rajasthan? Mention the main features of Vyas Committee



अध्याय - 5

राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन

NATURAL RESOURCES OF RAJASTHAN



"प्राकृतिक संसाधन प्रगति की आधारशिला हैं।"

अध्याय एक दृष्टि में

- प्राकृतिक संसाधनों से आशय
- प्राकृतिक संसाधनों के महत्व
- राजस्थान की भूमि सम्पदा
- राजस्थान की जलवायु
- राजस्थान के प्राकृतिक भाग
- राजस्थान की मिट्टियाँ
- राजस्थान की वन सम्पदा
- राजस्थान की वन सम्पदा
- राजस्थान की पशु सम्पदा
- राजस्थान की खनिज सम्पदा
- अभ्यासार्थ प्रश्न

प्राकृतिक संसाधनों से आशय

MEANING OF NATURAL RESOURCES

प्राकृतिक संसाधनों से आशय प्रकृति द्वारा प्रदत्त उन उपहारों से है जो मानव के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होते हैं। इस दृष्टि से प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्व संसाधन है। भूमि जल वनस्पति खनिज जीव जन्तु जलवायु आदि मानव उपयोगी होने के कारण संसाधन हैं। कई तत्व परस्पर मिलकर या अलग-अलग भी संसाधन बनते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उपभोक्ता के रूप में मनुष्य स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला भी प्राकृतिक संसाधन ही है। इन पर ही राष्ट्र का विकास व भविष्य निर्भर करता है। संसाधनों में जितनी विविधता होगी उम्पति की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। मानवीय व प्राकृतिक तत्वों द्वारा उनका परस्पर संरक्षण मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिये मनुष्य को कृषि करने के लिए भूमि मिट्टी व जलवायु को दृष्टिगत रखना होगा। इसी प्रकार यह भी सत्य है कि मनुष्य को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी संसाधन एक ही स्थान पर मिल जाये जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस का एक स्थान पर मिलना। ऐसी दशा में इनकी सापेक्षिक महत्व के अनुसार मनुष्य यह निर्णय लेता है कि

किस समाधान का, कैसे और किनका उपयोग करेगा। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, मिट्टी, जलवायु, जल, खनिज वनस्पति पशु-सम्पदा आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन हैं।

प्राकृतिक संसाधनों में भूमि खनिज वन पशु वन संसाधनों आदि का समावेश किया जाता है। इनका विस्तृत विवेचन इस अध्याय में किया गया है।

प्राकृतिक संसाधनों का महत्व

IMPORTANCE OF NATURAL RESOURCES

1 कृषि (Agriculture) - कृषि फसलों की विविधता का कारण मुख्यतः जलवायु की भिन्नता है। मानसूरी, जलवायु वाले राष्टों में मानसून पर्याप्त व समय पर आने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही कृषि में मिर्चाई हेतु सतत बहने वाले नदियाँ प्राप्त होती हैं। कृषि में संचित विभिन्न आदान, जैसे रासायनिक खाद आदि, प्राकृतिक संसाधनों की ही देन हैं। उपजाऊ मिट्टी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2 उद्योग (Industry) - उद्योगों पर स्थिति का कवशाव प्रभाव पड़ता है। मानसूनी जलवायु और कृषि-प्रधान क्षेत्रों में कृषि-जन्य कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योग पाये जाते हैं। इनमें नदियों से प्राप्त जल विद्युत, शक्ति का प्रमुख स्रोत होती है। वन-सम्पदा अधिक होने पर उन पर आधारित उद्योग विकसित होने वाले जाते हैं। खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में खनिजों पर आधारित उद्योग बनने लगते हैं। शक्ति का जो साधन आसानी से उपलब्ध होता है वही शक्ति का प्रमुख साधन बन जाता है। कुछ कवशाव प्रकार के उद्योग जलवायु के अनुरूप स्थापित होते हैं, मुख्य रूप से फिल्टर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि।

3 व्यापार (Trade) - यदि राष्ट्र अविर्कसित पड़ोसी राष्ट्रों से घिरा हो तो उनके बाजारों में प्रवेश की अच्छी संभावनाएँ होती हैं। इसी प्रकार सामुद्रिक जल मार्ग उपलब्ध होने पर दूसरे राष्ट्रों से संपर्क कार्य सरल हो जाता है। भौगोलिक स्थिति के परिणामस्वरूप स्थल क्षेत्र से भी व्यापार संभव है। यदि राष्ट्र प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों के मध्य है तो प्रायः प्रत्येक राष्ट्र के व्यापारियों से संपर्क बढ़ता है। इससे व्यापार प्रोत्साहित होता है। जलवायु की विविधता के कारण विभिन्न कृषि फसलें लेना संभव हो जाता है। फलस्वरूप व्यापार बढ़ने की संभावना रहती है। राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा जनसंख्या को भी प्रभावित करती है। फलस्वरूप आंतरिक व्यापार भी प्रभावित होता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और अभाव में प्रायः देशी व विदेशी

व्यापारों में भी कमी व वृद्धि होती है।

4 परिवहन (Transport) - विशेष रूप से धरातल की अनुकूलता के कारण स्थल, वायु तथा आंतरिक जल यातायात विकसित होते हैं। समुद्र क्षेत्र पर सामुद्रिक यातायात प्रभावित बढ़ता है। आममान साफ होने पर वायु परिवहन में वृद्धि होती है। स्थिति के कारण कटे-फटे क्षेत्रों पर प्राकृतिक बदलाव उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अधिक होने पर भी देशी व विदेशी व्यापार अधिक होता है। फलस्वरूप परिवहन के साधनों के विकास की गति भी बढ़ जाती है। रैगस्तानी क्षेत्रों में स्थल यातायात काफी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार मुसलाधार वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थल परिवहन में अनेक बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं।

5 कार्यक्षमता (Efficiency) - गर्म जलवायु होने पर शीत-प्रधान राष्ट्रों की तुलना में कार्यक्षमता कम देखी गयी है क्योंकि गर्म प्रदेशों में जादी ही धान का अनुभव होने लगता है। एक राष्ट्र में अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों और ठंडे प्रदेशों में निवासियों की कार्यक्षमता का अंतर आ जाता है। कार्यक्षमता पर जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता का भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य काफी सीमा तक देश के प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है।

6 उपभोग (Consumption) - प्राकृतिक संसाधनों की विविधता के साथ-साथ उपभोग में भी प्रायः विविधता देखी गई है। खनिजों में विविधता विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास का कारण बनती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु से भिन्न-भिन्न कृषि फसलें प्राप्त होती हैं। वन-उत्पादों के कारण अनेक वस्तुएँ उपलब्ध होने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संसाधनों उत्पादों में विविधता का औः फलस्वरूप उपभोग में विविधता का एक महत्वपूर्ण कारण है।

7 पर्यावरण (Environment) - एक राष्ट्र का पर्यावरण किस प्रकार का होगा यह अनेक बातों पर निर्भर करता है। वह राष्ट्र विपुलत रेखा के किस ओर व कितनी दूर स्थित है, राष्ट्र समुद्र में घिरा है अथवा उसके किनारे दूर या पास है, उस राष्ट्र की प्राकृतिक संरचना किस प्रकार की है, वनस्पति, कृषि, उद्योग, परिवहन, जीवन-मर आदि किस प्रकार के हैं ये सब तत्व मिलकर उस राष्ट्र के प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की रचना करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर क्योंकि मानव का नियंत्रण नहीं होता इस कारण प्राकृतिक पर्यावरण की रचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

8. संचार (Communication) - अधिक वर्षा, पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र, राष्ट्र की अत्यधिक विस्तृत हुई स्थिति ये राष्ट्रों की संचार व्यवस्था को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित

करते हैं और इसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रतिकूल प्रकृति तत्वों के कारण संचार में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रायः मैदानी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था अधिक प्रभावपूर्ण होती है। संचार के विभिन्न उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल भी प्रकृति की ही देन है।

9 अन्तर्राष्ट्रीय साख (International credit) - विस्तार की दृष्टि से अधिक बड़ा राष्ट्र, प्रायः प्राकृतिक ससाधनों में भी सम्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में स्वयं उसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर देती है। इसके साथ ही यदि सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से वह अनुकूल स्थिति में हो तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में वह पर्याप्त सम्मान अर्जित कर लेता है। पिछड़े राष्ट्रों में घिरा एक विकसित राष्ट्र प्रायः उनके नेता के रूप में स्वीकार्य हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता, अन्य राष्ट्रों की ओर उस राष्ट्र की अग्रणी स्थिति में ला देती है।

10 सुरक्षा (Defence) - प्रायः बृहद् आकार के राष्ट्र बाह्य आक्रमणों व दुश्मनों के लिए प्रायः अजेय रहते हैं। समुद्र का लाभ मिलने पर नौसेना का गठन संभव हो पाता है। सीमाओं का विस्तार अधिक होने पर सुरक्षा व्यय बढ़ जाता है। भारत भी हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण विदेशी आक्रमणों से काफी सीमा तक सुरक्षित रहा है। भारत में द्वीपों की स्थिति ने भारत का सामरिक महत्व बढ़ा दिया है। प्राकृतिक ससाधनों ने माध्यम से सम्पन्नता प्राप्त करने वाले राष्ट्र को अपनी सम्पन्नता को बनाए रखने के लिए स्वयं ही सुरक्षा व्यवस्था की रचना करनी होती है। फलस्वरूप वह इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है।

11 आत्मनिर्भरता (Self-Sufficiency) - प्रत्येक राष्ट्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने से उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति करनी होती है। यह प्रगति प्राकृतिक ससाधनों के बाहुल्य और उनकी विविधता पर काफी सीमा तक निर्भर रहती है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधन राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12 जन-जीवन (Life Style) - किसी राष्ट्र में जन जीवन कैसा होगा इस पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जीवन प्रायः विषम होगा। वर्षाव नदियों में रहने वाले लोगों का जीवन और भी अधिक वर्धित होगा। मैदानी क्षेत्रों में लोग प्रायः अधिक सुविधापूर्ण स्थिति में देखे जाते हैं। इस प्रकार की विविधताएँ लोगों के

जन-जीवन पर तो प्रभाव डालती ही हैं, उनके जीने के तरीके और उनका जीवन-स्तर भी इससे प्रभावित होता है।

13 पर्यटन (Tourism) - विश्व में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। पर्यटन क्षेत्रों के विकास में प्रमुख भूमिका प्रकृति की ही कही जा सकती है। प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त राष्ट्र पर्यटक मयलों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अच्छा समुद्र तट, घने जंगल, नदियाँ व झीलें, अनुकूल जलवायु आदि मिलकर पर्यटन स्थलों की रचना करते हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैण्ड जैसे अच्छे पर्यटक स्थलों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। यह मान्यता उनकी आय को अत्यधिक बढ़ाने में सहायक होती है।

14 जनसंख्या (Population) - किसी भी राष्ट्र की जलवायु जनसंख्या की वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करती है। गर्म जलवायु वाले राष्ट्रों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है क्योंकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग शीघ्र परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। शीतल राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि दर प्रायः कम होती है। जनसंख्या के घनत्व पर भी प्राकृतिक ससाधन अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। उपजाऊ क्षेत्रों, शक्ति के पर्याप्त साधन वाले क्षेत्रों प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त क्षेत्रों में रहना लोग अधिक पसन्द करते हैं। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों का घनत्व बढ़ जाता है। प्राकृतिक ससाधनों के कारण रोजगार के साधन उपलब्ध होने से भी घनत्व प्रभावित होता है।

15 रोजगार (Employment) - विकास के लिए प्राकृतिक ससाधनों का विद्यमान किया जाता है। विदोहन की यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से पूरी होती है, जिनमें उद्योग प्रमुख है। ऐसी स्थिति में अधिक प्राकृतिक ससाधनों के होने पर रोजगार की अधिक सभावनाएँ उत्पन्न होती हैं। अनुकूल प्राकृतिक स्थिति होने पर व्यापार उन्नत अवस्था में होता है। जलवायु की अनुकूलता के कारण कृषि प्रधान राष्ट्र हो जाने से भी, अधिकांश जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधन अधिष्ठान होने पर अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है।

16 भण्डारण (Storage) - राष्ट्र में जो प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध हैं, उनकी भिन्नता विभिन्न वस्तुओं के भण्डारण को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इनमें से मुख्य रूप से जलवायु का भण्डारण पर प्रभाव देखा जा सकता है। शीत प्रदेशों में प्रकृति वस्तुओं को सुरक्षित अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता रखती है जबकि गर्म प्रदेशों में उनकी सुरक्षित रखने के लिए शीत भण्डारण की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी प्रकार अधिक गर्म वाले प्रदेशों में भी यह व्यवस्था अनिवार्य हो जा सकती है।

भण्डारण की व्यवस्था के कारण वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती हैं जिसका प्रभाव व्यापार व अन्य उत्पादन क्षेत्रों पर भी पड़ता है।

17 क्षेत्रीय विकास व विषमता (Regional development & disparities) - एक राष्ट्र में ही विभिन्न प्रदेशों अथवा क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुल्यता या कमी हो सकती है। इस प्रकार की कमी और बहुल्यता विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक विषमता व अनेक प्रकार की असमानताएँ उत्पन्न कर देती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के बहुल्य वाले क्षेत्रों में उद्योग परिवहन व्यापार, कृषि आदि उन्नत अवस्था में होते हैं। ऐसी स्थिति में इन उन्नत व पिछड़े क्षेत्रों के मध्य खाई निरंतर बढ़ती चली जाती है।

18 सभ्यता व संस्कृति (Civilizations & Culture) - किसी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन उसे अन्य राष्ट्रों से कितना निकट संपर्क में ला देता है अथवा उसे कितना अलग कर देता है, इस बात का प्रभाव उनकी सभ्यता व संस्कृति पर स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। भारत की प्राकृतिक सीमा व कवचभर हिमालय द्वारा शेष विश्व से अलग-अलग रहने के कारण भारत ने अपनी स्वयं की सभ्यता व संस्कृति को अपनाया रखा। यह तर्क कि जो आक्रमणकारी विदेशों में आकर बसे वे भी इसी देश की सभ्यता व संस्कृति के अभिन्न अंग बन गये। विभिन्न लोगों व राष्ट्रों के संपर्क में आने का प्रभाव कुछ हद तक भारतवासियों पर भी पड़ा। वर्तमान में इस सदर्भ में पश्चिमी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

19 राजनीति (Politics) - देश के आन्तरिक विस्तार प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता आदि के कारण उत्पन्न भिन्नताओं से गहराई निम्न के मध्य अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। विस्तृत राष्ट्र होने के कारण अनेक प्रदेशिक समस्याओं का मानना सरकार को करना पड़ता है। राष्ट्र की परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों का निर्धारण कर, संपूर्ण राष्ट्र को समुचित प्रदान करने की चेष्टा की जाती है। जब संपूर्ण राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों में समान हो तो विकास की समस्याएँ, शायद अभाव की समस्याओं की अपेक्षा कम दाय होती हैं। इन प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की कमी सरकार को समस्याओं में प्रायः बुद्धि ही करती है।

20 विकास (Development) - राष्ट्र की प्राकृतिक बनावट उसकी उर्जा-सम्पदा, वन-संपदा, जल-स्रोत उत्पत्ति तथा मछली उद्योगों का प्रयोग करने वाले मानवीय संसाधन विकास की गति को निर्धारित करते हैं। यदि यह तत्व अनुकूल हैं तो विकास की गति तीव्र होती है। कृषि, उद्योग, व्यापार परिवहन परिवहन आदि का तीव्र गति से

विस्तार व विकास होता है। फलस्वरूप वर्तमान विकास की दर बढ़ जाती है। लोगों का जीवन स्तर ऊँचा हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी से प्रायः वर्तमान के साथ-साथ भावी विकास की संभावनाएँ भी कम हो जाती हैं।

राजस्थान की भूमि-सम्पदा

LAND RESOURCES OF RAJASTHAN

भूमि सम्पदा में मुख्यतः भू-आकृति (Relief) भू-गर्भशास्त्र मिट्टी कन्दगाएँ व खाईयाँ, नदी-घाटियाँ, वनस्पति एवं वन, दृष्टीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और भू-उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। इनका विवेचन निम्न प्रकार है -

1 भू-आकृति (Relief) - अरब में विरव में गोंडवाना क्षेत्र व अरावली क्षेत्र नामक दो भू-खण्ड विद्यमान थे और इन दोनों भूखण्डों के मध्य टैपिस महासागर विद्यमान था। राजस्थान का कुछ भाग गोंडवाना क्षेत्र का व शेष टैपिस महासागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान में विद्यमान अरावली पर्वत-श्रृंखलाएँ तथा दक्षिण-पूर्वी पठार गोंडवाना प्रदेश के प्राचीनतम भू-क्षेत्रों में से हैं। अनुमान है कि शेष राजस्थान के स्थान पर टैपिस महासागर विद्यमान था जिससे गहराई को कालान्तर में अनेक नदियों ने पाट दिया। राजस्थान की दृष्टि में हमें सर्वाधिक योग्य सारस्वती नदी का रहा। यह नदी भी कालान्तर में लुप्त हो गई। राजस्थान को भूमि की दृष्टि में चार प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है (i) उत्तर-पश्चिमी रेगिस्तान (ii) पूर्वी मैदान (iii) मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र अथवा अरावली प्रदेश और (iv) दक्षिणी-पूर्वी पठार। इन प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तृत विवेचन राजस्थान के भौगोलिक परिचय के अन्तर्गत किया गया है।

2 भू-गर्भशास्त्र (Geology) - राजस्थान को प्राकृति ने अनेक प्राचीन चट्टानों की श्रेणियाँ उपहार स्वरूप प्रदान की हैं। इनमें से कुछ श्रेणियाँ लगभग 250 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। राज्य के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी भाग धार के मरुभूमि की मिट्टी से ढक दिये हैं। शेष भाग में अनेक प्रकार की कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतिम भाग में भूरे रंग की चट्टानों की श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक प्रकार की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य में मिट्टी और चूना पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन काल में राजस्थान के पश्चिमी भाग में चूना पत्थर के विशाल भण्डार थे।

3 वन एवं वनस्पति (Forests & Vegetation) - भारत में उपउष्ण आकृष्टों के अनुसार भारत में वनों का

से अधिक होता है।

(C) सर्दी - राज्य में सर्दी का मौसम प्रायः नवम्बर से मार्च के मध्य रहता है। राजस्थान में सर्दी के मौसम की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं -

- 1 राजस्थान में शीत ऋतु का सर्वाधिक प्रभाव जनवरी माह में होता है। इस माह में राज्य के कुछ जिलों (सीकर, अलवर, चुरू, गगानगर, बीकानेर आदि) का औसत दैनिक तापमान 12° से से 14° से तक रहता है।
- 2 इस मौसम में राज्य के जैसलमेर, चुरू, गगानगर, फरीदी व बीकानेर आदि राज्यों में कपड़ान पानी के जमाव बिन्दु से भी कम हो जाता है।
- 3 इस मौसम में राज्य के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में औसतन 5 सेमी से $1\frac{1}{2}$ सेमी तक वर्षा (महबूब) होती है। यह वर्षा राज्य की 'बी' की फसलों (गेहूँ, चना, जौ व सरसों आदि) के लिये अत्यधिक लाभदायक होती है। इस वर्षा में तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है।

राजस्थान के जलवायु आधारित प्रदेश

राज्य के जलवायु प्रदेश का निर्धारण लक्ष्मण वशा एव आर्द्रता के आधार पर निम्न रूप में किया जा सकता है -

(A) शुष्क प्रदेश (Dry Region) इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं-

- 1 जलवायु - इस प्रदेश की जलवायु गर्म एव शुष्क होती है।
- 2 तापमान - इस प्रदेश का औसत दैनिक तापमान गर्मी में 34° से एव सर्दी में 12° से रहता है।
- 3 वर्षा - शुष्क प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 10 सेमी से 25 सेमी तक रहता है।
- 4 वन - वन सीमित मात्रा में होते हैं।
- 5 विस्तार - शुष्क जलवायु प्रदेश में गगानगर जिले का दक्षिण भाग, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर का उत्तरी भाग तथा बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग सम्मिलित है।

(B) अर्द्ध-शुष्क प्रदेश (Semi-Dry Region) इस प्रदेश का विशेषताएँ निम्न हैं -

- 1 जलवायु - इस प्रदेश की जलवायु अर्द्ध-शुष्क है।
- 2 वर्षा - इस प्रदेश में 25 सेमी से 50 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है।
- 3 वन - इस प्रदेश में घास के मैदान व रेगिस्तानी पेड़-

फोंवे व झाड़ियाँ पाई जाती हैं।

4 विस्तार - यह प्रदेश बीकानेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, पाली, जालौर, गगानगर तथा बाड़मेर जिलों तक विस्तृत है।

(C) आर्द्र प्रदेश (Humid Region) इस प्रदेश की विशेषताएँ निम्न हैं -

- 1 जलवायु - इस प्रदेश की जलवायु आर्द्र होती है।
- 2 वर्षा - इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेमी से अधिक रहता है।
- 3 वन - वनों की स्थिति राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में घने वन हैं।
- 4 विस्तार - यह क्षेत्र राज्य के बांसवाड़ा, झुण्णपुर तथा झालावाड़ तक विस्तृत है।

(D) उप-आर्द्र प्रदेश (Sub-Humid Region) इस प्रदेश की विशेषताएँ निम्न हैं -

- 1 जलवायु - इस प्रदेश में उप-आर्द्र जलवायु पाई जाती है।
- 2 वर्षा - इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेमी से 80 सेमी तक बढ़ता है।
- 3 वन - इस प्रदेश में पर्याप्त वन पाये जाते हैं।
- 4 विस्तार - यह प्रदेश जयपुर, अजमेर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर तथा चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है।

राजस्थान के प्राकृतिक भाग

NATURAL DIVISIONS OF RAJASTHAN

आरभ में विश्व में ग्रेडवाना क्षेत्र व आगरे क्षेत्र नामक दो बू-खण्ड विद्यमान थे और इन दोनों भूखण्डों के मध्य टैक्स महासागर विद्यमान था। राजस्थान का कुछ भाग ग्रेडवाना क्षेत्र का व शेष टैक्स महासागर का अपरेश भाग जलता है। राजस्थान में विद्यमान अरावली पर्वत-श्रृंखलाएँ तथा दक्षिणी-पूर्वी पठार ग्रेडवाना प्रदेश के प्राचीनतम भू-क्षेत्रों में से हैं। अनुमान है कि शेष राजस्थान के स्थान पर टैक्स महासागर विद्यमान था जिसकी गहराई की कलान्तर में अनेक नदियों ने पाट दिया। राजस्थान की दृष्टि से इसमें सर्वाधिक योग्य सरस्वती नदी का रहा। यह नदी भी कलान्तर में लुप्त हो गई। राजस्थान की सुविधा की दृष्टि से चार प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है - (1) उत्तरी-पश्चिम रेगिस्तान (2) पूर्वी मैदान (3) मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र अथवा अरावली प्रदेश और (4) दक्षिणी-पूर्वी पठार। इन प्राकृतिक प्रदेशों का परस्पर निम्न विवेचन से स्पष्ट है

प्राकृतिक प्रदेश	भू भाग का प्रतिशत	जनसंख्या का प्रतिशत	प्रमुख विशेषताएँ
1 उर्वर पृथ्वी रेगिस्तान	57 ■ (61 11)*	30 (40%)**	बागमर बाडमेर जाधपुर हुमानगढ़ बीकानेर जालौर गगननगर चुरू नागौर पाली सीकर झुझुनू
2 शुष्क मैदान	23.9	40	अनवर भरतपुर टाक सवाई माधोपुर उदपुर दीसा धौलपुर
3 मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश	9.3	17	बंसवाड़ा झुझुनू उदपुर विरौड श्रीवांगडा अजमेर मिंगो राजनगर
4 दक्षिणी पृथ्वी पठार	9.3	13	कोटा बूंदी झालावाड़ बाण

** Economic Review 1995-96 Govt. of Rajasthan

(अ) उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तान

North West Desert

कहा जाता है कि इस भाग में टैक्सि महासागर विद्यमान था जो कालान्तर में लुप्त हो गया। सम्भर डाडवाना व पंचभद्रा की खास झीलें उसी सागर का अवशेष मानी जाती हैं। यह प्रदेश प्राचीनकाल में काफ़ी समृद्ध था और उस समय यहाँ सरस्वती नदी बहा करता थी। इस प्रदेश के हर भाग होने का आभास हाल में मिन वन-अवशेषों से भी होता है। तेनसाग के समय यह प्रदेश गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। विश्व में ऐसा कोई दूसरा मरुस्थल नहीं है जहाँ राजस्थान के थार मरुस्थल जितनी सख्त में मनुष्य व पशु रहते हैं। यह प्रदेश बीकानेर जैसलमेर पुरू पश्चिमा नागौर पाटणा जालौर और सिरोंहा तक विस्तृत है। जैसलमेर बाडमेर बीकानेर जाधपुर तथा चुरू जिले के कुछ हिस्से को मिला कर वन पश्चिमी मरुक्षेत्र के जोन प्रथम 'ए' कहा है। इसका क्षेत्रफल 1 244 करोड़ हेक्टर है। राज्य के अधिकांश मरुस्थलाय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। यहाँ रेत के 100 मीटर तक की ऊँचाई के टीले बने हुए हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का अभाव रहता है। अतः वनस्पति बहुत कम है। फसल तेज हवाओं के कारण बर्बाद से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसमें उपजाऊ भूमि ख़र भूमि में बदल जाती है और मड़क और मरुत रेत में ढब जाते हैं।

उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान का दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1 पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान यह प्रदेश बीकानेर जैसलमेर चुरू और पश्चिमी नागौर तक विस्तृत है। यहाँ आवासीय गैस गिरिफ मंत्रालय मनाइट तथा विंधन क्रम का गढ़ान है। जैसलमेर बाडमेर बीकानेर और पुरू गगननगर जिलों में पुरू के पत्थर की प्रधानता है। वन वन का स्तूपदुर्लभ प्रदेश बहनाता है।

2 अर्द्धशुष्क मैदान या राजस्थान बागड इसमें लूना नदी शालिका भू भाग नागौर उच्च भूमि तथा बागड नदी के मैदान का सम्मिलित किया जाता है। लूनी नदी

अजमेर के दक्षिणी पूर्वी भाग पाली जालौर व सिरौही तक विस्तृत है। यहाँ ताँबे खानवाली पहाड़ियाँ व विस्तृत जलवायु मैदान हैं। शोलावागे भू भाग राजस्थान बागड के अंतर्गत लूनी बसिन के उत्तर व राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। यह क्षेत्र ऊँच खण्ड और बालू मिट्टी के टीलों का है। यहाँ कान्तली नदी बहती है।

उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख विशेषताएँ निर्मात्रित हैं।

1 सीमा (Boundary) इस प्राकृतिक प्रदेश के उत्तर में पंजाब का मैदान व दक्षिण में कच्छ की खाड़ी है। पूर्व में अरावली पर्वत-श्रृंखला है तथा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है। यह प्रदेश अरावली पर्वत-श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है।

2 स्थल-आकृति (Topography) इस प्रदेश का ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर पूर्वी भाग की ऊँचाई लगभग 300 मीटर व दक्षिणी भाग 150 मीटर ऊँचा है। इस क्षेत्र में बालू रेत के टीले विद्यमान हैं और व अधिकांश कारण अपना स्थान बदलते रहते हैं।

3 जिले (Districts) लगभग 1 88 206 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस प्रदेश में राजस्थान के गगननगर बीकानेर चुरू नागौर जाधपुर जैसलमेर बाडमेर पाली हुमानगढ़ जालौर सीकर और झुझुनू जिले सम्मिलित हैं।

4 जलवायु (Climate) इस क्षेत्र की जलवायु विषम है। रात और दिन तथा सर्दी व गर्मी के तापक्रम में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। औसत तापमान ग्राम ऋतु में 34° से अधिक तथा शान ऋतु में 12° से कम रहता है। शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता 16% से भी कम हो जाती है। वर्षा की सामान्य औसत 12 से मा से 15 सेमी रहता है।

5 वनस्पति (Vegetation) उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में काटेदार झाड़ियाँ की रहता है। वनस्पति बहुत कम व खिखी हुई है। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश वृक्ष भा काटेदार व लंबा बड़ा पान होत है जैसे गहुन खैर अजि।

6 मिट्टी (Soils) इस क्षेत्र में मुख्यतः बालू मिट्टी विद्यमान है। मिट्टा में वनस्पति-अवशेष का कमी है तथा मिट्टा

के कण मोटे व असंगठित हैं। मिट्टी उपजाऊ होते हुए भी जल के अभाव में बेकार पड़ी है। गगानगर जिले की सम्पन्नता भी इस बात का स्रोतक है।

7 खनिज (Minerals) लिम्बाइन कोयला जिम्पम मुलवानी मिट्टी इमराती पत्थर व श्रुतिक गैस इस क्षेत्र में मिलते हैं। इस क्षेत्र में खनिज तेल का खोज की जा रहा है।

8 भू क्षेत्र व जनसंख्या (Area & Population) राजस्थान का 1.88 लाख वर्ग किलोमीटर भू भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यह 57.8% भाग है और राजस्थान का 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है।

9 नदियाँ व झीलें (Rivers & Lakes) सूनी सूकड़ा जराई व बाढा इस क्षेत्र का प्रमुख नदियाँ हैं तथा इस क्षेत्र में सांभर एचरदस व डांडवना का प्रसिद्ध खारी झीलें स्थित हैं।

11 कृषि (Agriculture) इस प्रदेश के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय खेती व पशुपालन है। यहाँ मुख्यतः मोटे अनाज उत्पन्न होते हैं। ज्वार बाजरा मूंग मटर आदि प्रमुख फसल हैं लेकिन गगानगर जिले में सिंचि के कारण गहू और कपास गन्ना आदि फसल भी उगाई जाती है।

(व) पूर्वी मैदान

Eastern Plain

राजस्थान के पूर्व में स्थित यह मैदान वास्तव में गंगा-सतलज के मैदान का ही भाग है। इस समूह प्रदेश का तीन भाग में विभक्त किया जा सकता है।

1 चम्बल का बेसिन (Chambal basin) यह वाटा बूटा टाक मवाइनाथपुर तथा धौलपुर जिले के लगभग 50 026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चम्बल नदी यमुना का प्रमुख सहायक नदी है जो विंध्य पठार के उत्तर-पश्चिम तथा अरावली पठार के मध्यवर्ती भाग में होकर बहता है। इस क्षेत्र में दंड के मैदान नदी काग व बागड है। काग बड़ा टाक सखड़ नाथपुर व धौलपुर आदि जिले में 4530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाहड़ फैला हुआ है। समुद्र तल से इस प्रदेश का ऊँचाई 350 मीटर से अधिक है यहाँ 60 से मा. से 100 से मा. के मध्य वर्षा होता है मिट्टी उपजाऊ व क्षारीय उपजाऊ है।

2 बानस बेसिन (Banas basin) बानस व उसका सतलज नदी का यह मैदान दक्षिण में सखड़ का मैदान तथा उत्तर में मन्सपुरा काली व मदान व नर्मदा में जना जाता है खाना मन्सपुरा एवं धौल नदियाँ बानस

का सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों के द्वारा एक विशाल मैदान का निर्माण किया गया है जो उदयपुर के पूर्वी भाग पश्चिमी चित्तौड़गढ़ भालवाडा टाक जयपुर पश्चिमा मवाइनाथपुर और अलवर के दक्षिण भागों तक फैला हुआ है। इस मैदान की औसत ऊँचाई 280 मीटर से 500 मीटर के मध्य है। यह 80 से मा. से 90 से मा. वर्षा होता है। उपजाऊ मिट्टी व पचास सिंचाई सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है।

3 मध्य माही बेसिन (Central Mahi basin) माही नदी द्वारा निर्मित यह मैदान दक्षिण पूर्वी बानसवाडा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिण भागों तक फैला हुआ है। यह मैदान 7056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान की औसत ऊँचाई 200 से 400 मीटर है एवं वर्षा का औसत 100 से मा. है। बांसवाडा व झुगपुर के पहाड़ भू भाग को स्थानांतरण भाग में बागड कहा जाता है।

पूर्वी मैदान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

1 सीमा (Boundary) पूर्वी मैदान के उत्तर व पूर्व में सतलज नदी का मैदान व दक्षिण में पठार प्रदेश विद्यमान हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत-श्रृंखला उत्तर पश्चिम में गिराना ने इस अंतरा करत है।

2 स्थल आकृति (Topography) यहाँ लगभग समतल मैदान है और भूमि का टल उत्तर पूर्व की ओर है। इस कारण अनेक नदियाँ इन ओर प्रवाहित होकर नालों या यमुना में मिलती हैं।

3 जिले (Districts) इस प्रदेश के जिले बानसवाडा प्रमुख जिले अलवर भरतपुर धौलपुर टाक दोसा सबड मन्सपुर तथा जयपुर हैं।

4 जलवायु (Climate) मैदानों में पूर्व में अधिक अक्षांश पश्चिम में अधिक शुष्क है। इस क्षेत्र का वर्षा का औसत 40 80 से मा. के मध्य है।

5 वनस्पति (Vegetation) अधिकांश भूमि नर्मदा व वनस्पति में लिपिता हुई है। जंगल जंगल घास व घासों का पाया जाता है वृक्ष में नर्मदा बरद आम आदि प्रमुख हैं।

6 मिट्टी (Soil) मिट्टी रोमट व उपजाऊ है। नदियों द्वारा निर्मित यह मिट्टी अधिकतर सांठित व बारोके टिकाव वाली है।

7 खनिज (Minerals) यह मैदान दक्षिण खनिजों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

8 भू-क्षेत्र व जनसंख्या (Area & Population) - पूर्वी मैदान का कुल क्षेत्रफल राजस्थान का 23.9% भाग है तथा जनसंख्या का 40% भाग इसमें निवास करता है।

9 नदियाँ (Rivers) - मावसी, मोरेन, वडेर बजाई व गोलवा नदियाँ बनावस की प्रमुख महायक नदियाँ हैं।

10 कृषि (Agriculture) - भूमि उपजाऊ होने के कारण खाद्यान्न व व्यावसायिक फसलें उत्पन्न करना संभव है। इस क्षेत्र में मुख्यतः गेहूँ और चना बाजरा निलहन कपास गन्ना आदि उत्पन्न की जाती हैं।

11 उद्योग (Industry) - इस प्रदेश में सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, चीनी व इञ्जीनियरिंग उद्योग विद्यमान हैं।

(स) मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश अथवा पर्वतीय प्रदेश

Middle Mountain Region

यह पहाड़ी क्षेत्र विश्व के प्राचीनतम भू-भागों में से एक है। अरावली पर्वत-श्रृंखला गुजरात में दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। दिल्ली की ओर इसकी ऊँचाई क्रमशः कम होती चली गई और दिल्ली के पास यह लगभग लुप्त हो गई है। कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर-पूर्व की फैली यह पर्वत-श्रृंखला समुद्र के अन्दर तक चली गई है और लक्षद्वीप समूह इसी का भू-भाग है।

यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत-श्रृंखलाओं में से एक है। भूगर्भीक इतिहास की दृष्टि से अरावली श्रृंखला धारवाड समय के समाप्त होने के समय में सञ्चित है। विध्यनकाल के अन्त तक यह पर्वत श्रृंखला अपने अस्तित्व में आई। इस प्रदेश को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है

1 उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी प्रदेश (North-East Mountain region) - यह प्रदेश जयपुर जिले के उत्तरी-पश्चिमी भाग में तथा अलवर जिले के अधिकांश भागों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र फाईलाइट एवं क्वार्ट्ज से निर्मित है। इनमें पर्वतों का निर्माण तेजी से होता है। क्वार्ट्ज के प्राण ऊँची चोटियों का निर्माण होता है। अलवर की पहाड़ियों का ऊँचाई 550 मीटर से 670 मीटर के मध्य है। इनकी शाखाएँ मोकर, नीम का थाना श्रीगोधपुर और खेनडी तहसीला तक फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों के मध्य चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं। अलवर में भैरव घाटी का ऊँचाई 792 मीटर व बैराठ घाटी की ऊँचाई 204 मीटर है। जयपुर में बाराई घाटी की ऊँचाई 792 मीटर व छोटी घाटी की ऊँचाई 920 मीटर है। मोकर जिले में गुनाय मठ घाटी की

ऊँचाई 1055 मीटर है।

2 मध्य अरावली श्रेणी (Middle Aravalli range) - इसमें अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों के दक्षिण-पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को सम्मिलित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत पश्चिम में विखरे कटक अलवर की पहाड़ियों, करौली उच्च भूमि और बनावस मैदान सम्मिलित हैं। इस प्रदेश को दो भागों में बाँटा जा सकता है - (अ) शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में बालू मेन की पहाड़ियों व गहरे गलों का बहुल्य है। पहाड़ी श्रृंखला साभर झील से प्रायः होकर झुझु झिले में मिहना तक चली गई है। यह इस क्षेत्र की सबसे लम्बी पर्वत-श्रेणी है। घाट गढ नामक गहाड़ी, आडा डगर तथा तोपवटी इस क्षेत्र की छोटी पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की पहाड़ियों की औसत ऊँचाई लगभग 400 मीटर है। साभर झील के पश्चिमी क्षेत्र की अरावली श्रेणी की पहाड़ियों की औसत ऊँचाई लगभग 500 मीटर है। (ब) मेरवाड़ा पहाड़ियाँ ये पहाड़ियाँ अजमेर शहर व उसके समीपवर्ती भागों में फैली हुई हैं। तारागढ इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणी है जिसकी समुद्रतल से ऊँचाई लगभग 914 मीटर है। तारागढ के पश्चिम में नाग पहाड़ हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ का यह क्षेत्र कुकरा में अजमेर जिले के अन्तिम सिरे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई लगभग 550 मीटर है।

3 मेवाड़ पहाड़ियाँ व भोराठ पठार (Mewar Hills & Bharat plateau) - यह क्षेत्र पूर्वी मिर्गोरी उदयपुर (कुछ पूर्वी भाग को छोड़कर) और डूंगरपुर जिलों में फैला हुआ है। उत्तर-पश्चिम में कुम्भलगढ व गोमुन्दा के मध्य में पठार का स्थानीय भाग में भोराठ पठार कहा जाता है। इस पठार की औसत ऊँचाई लगभग 1225 मीटर है। मिर्गोरी क्षेत्र की पहाड़ियों की स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है।

4 आबू-पर्वत-रूप (Abu Mountain range) - यह क्षेत्र अरावली पर्वत-श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है जो आबू के निकट प्रायः पृथक पहाड़ी के रूप में है। आबू पर्वत लगभग 19 किलोमीटर लम्बा व 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है। इसमें गुनशिखर (1728 मीटर) गमेर (1597 मीटर) और अन्तलगढ (1380 मीटर) प्रमुख शिखर हैं। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू मिर्गोरी पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊँचाई आबू पर्वत की तुलना में कम है।

विशेषताएँ (Characteristics)

1 सीमा (Boundary) - इस प्रदेश का उत्तर में गंगा का मैदान व दक्षिण में गुजरात का समुद्री तट है। पूर्व में पेटाना तथा पश्चिम में रणस्थानी भाग विद्यमान हैं।

2 स्थल आकृति (Topography) विश्व की प्रचलित पर्वत-श्रेणियाँ यहाँ इनका गुणगुनी होती हैं। यह पर्वत-शृंखला गुजरात में दिल्ली तक क्रमबद्ध नहीं है वरन् बीच-बीच में यह काफ़ी कटा पड़ी है। इसका ऊँचाई व गहरी भाँ सर्वत्र एक समान नहीं है। अरावली पर्वत का औसत ऊँचाई लगभग 3000 फीट है। इसका प्रमुख चट्टियाँ गुम्फाखर (1723 मीटर) जरागा (1310 मीटर) कुम्भलगढ (1244 मीटर) गेरम (936 मीटर) माडमता (930 मीटर) व नागाट (914 मीटर) हैं। अरावली पर्वत-शृंखला के दो प्रमुख दर्रे क्रमशः देसूरी दर्रा व हाथी दर्रा हैं।

3 जिले (Districts) अरावली पर्वत शृंखला राजस्थान के लगभग मध्य में है तथा इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले बनवाड़ा, डूंगरपुर, सिंगर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भरतवाड़ा तथा अजमेर हैं।

4 जलवायु (Climate) यह पर्वतीय प्रदेश पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क जलवायु के मध्य विद्यमान है। ऊँचाई वाले स्थानों में तापमान कम पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा 20 से 90 स.म. तक होता है।

5 वनस्पति (Vegetation) आधिकांश पहाड़ी-शृंखलाओं पर वनस्पति विलुप्त है वनस्पति में वृक्षों की कमी तथा कच्चा अनाज प्राप्त होता है।

6 मिट्टी (Soil) इस प्रदेश में पर्वत-शृंखलाओं के बीच-बीच में विद्यमान मैदानों व पहाड़ी क्षेत्र में जलोढ़ बालू, भूरा लाल तथा कंकरीला मिट्टी पाई जाती है।

7 खनिज (Minerals) राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश खनिजों का दृष्टि में काफी समृद्ध है। यहां लोहा, तांबा, जस्ता, अभ्रक आदि खनिज विद्यमान हैं।

8 भू-क्षेत्र व जनसंख्या (Area & Population) राजस्थान के कुल भू-भाग का 9.3 प्रतिशत भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आता है तथा सम्पूर्ण जनसंख्या का 17 प्रतिशत भाग इस क्षेत्र में निवास करता है।

9 नदियाँ (Rivers) अरावली पर्वत-शृंखला से अनेक नदियाँ निकलती हैं। लूनी, महासारा, सूरसूरा, घग्घा, बांस, गंगा, बठाना, उषा, जाखर व भांग क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं।

10 कृषि (Agriculture) पर्वत शृंखला के दो ओर तथा वाद-मध्य में स्थित मैदानों में प्रत्येक प्रकार के फसल उत्पादन का काम होता है।

11 उद्योग (Industry) इस पर्वत-शृंखला में प्रत्येक उद्योग के उत्पादन के लिए खनिज तथा पदार्थों का बड़ा स्त्रोत उदयपुर में स्थित किया गया है।

अरावली पर्वत शृंखला में लाभ (Advantages of Aravali Mountain Range)

- 1 अंतरी पश्चिम में ऐमिमान का प्रसार का एक म महत्वपूर्ण है।
- 2 अनेक नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण सिंचाई व पानी हेतु जल उपलब्ध करवाता है।
- 3 पर्वत का ऊँचा चट्टियाँ पर्वत केन्द्रों के रूप में विख्यात हैं जो सत-नियंत्रण को अपना आर आकर्षित करती हैं।
- 4 पर्वत श्रेणियों में विद्यमान वनों से अनेक प्रकार का वन-उपज प्राप्त होती है।
- 5 खनिजों की दृष्टि से यह एक समृद्ध क्षेत्र है इस कारण राजस्थान के भावी विकास का आधार बन गई है।
- 6 पर्वत शृंखलाओं से उपलब्ध वनस्पति के कारण पशु चरान का कार्य भी होता है।
- 7 मनुष्यों के साथ में कुछ अवरोध उत्पन्न कर अधिक वर्षा का प्रतिकार करता है।
- 8 इस प्रदेश के वनों में अनेक वन्य जीव जन्तु भी बहुतायत में मिलते हैं।

(द) दक्षिणी पूर्वी पठार

South East Plateau

यह भारत का दक्षिण में स्थित पठार का हिस्सा एक भाग है यह हाडाना या मनुष्यों के पठार के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है इस दो भाग में विभक्त किया जा सकता है।

1 विष्णु कागार भूमि इस प्रदेश का भूमि बलुआ पत्थरों से बना है। बलुआ व बलुआ नदी के मध्य कागार का निवास हुआ है जो बुन्देलखंड तक विस्तृत है एक कागार घाटपुर व कौला क्षेत्र में फैला हुआ है। इन कागार का ऊँचाई 350 मीटर से 550 मीटर के मध्य है।

2 दक्कन लावा पठार यह प्रदेश मध्य प्रदेश के विष्णु पठार व पश्चिम में फैला हुआ है। यह विष्णु कागार के अधोत्तर क्षेत्रों पर दक्कन टेप लावा के उपाव स्पष्ट दृष्टिगत हैं। यह बलुआ-भूदा का पठार इस भाग में विद्यमान है। इस प्रदेश में नदी-नदियों में कहा-कहा पर वास्तव में इनका मिलन है।

दक्षिणी पूर्वी पठार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- 1 सीमा (Boundary) इस पठार का पूर्व में दक्षिण पठार तथा पश्चिम में अरावली पर्वत है। उत्तर में राजस्थान का पूर्वी मैदान तथा दक्षिण में विन्ध्य-वन पर्वत है।

घग्घर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि राज्य में नहरों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर, गगननहर व घग्घर नदी की नहरों के कारण सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। फलतः कृषि पदार्थों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। राजस्थान की बनावट विषय है अतः यहां अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं।

राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार

Types of Soils in Rajasthan

1 रेतीली मिट्टी यह मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। अतः यह पानी को अधिक मात्रा में सोख लेती है लेकिन इसमें पानी रोकने की शक्ति नहीं होती है। रेतीली मिट्टी को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है -

(i) रेतीली बालू मिट्टी - यह मिट्टी 90 से 95% बालूय होती है। इसमें घुलनशील लवण अधिक मात्रा में होते हैं। रेतीली बालू मिट्टी मुख्यतः गगननगर, बुरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर तथा झुझुनू जिलों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तथा वायु का वेग तीव्र होता है अतः मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इन क्षेत्रों में धूल भी आसिया चलती है।

(ii) लाल रेतीली मिट्टी - इसका रंग लाल अथवा गहरा भूरा होता है। यह मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अतः जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उत्तम हैं। लाल रेतीली मिट्टी राज्य के नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर बुरू और झुझुनू जिलों के कुछ भाग में पाई जाती है।

(iii) पीली-भूरी रेतीली मिट्टी - यह मिट्टी पीली भूरी रेतीली से बालू दोमट व बालू मटियार दोमट के रूप में मिलती है। यह राज्य के मुख्यतः नागौर व पाली जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। पीली भूरी मिट्टी का लगभग 100 से 150 सेमी नीचे चूना मिश्रित मिट्टी मिलती है। यह उपजाऊ होती है अतः कृषि कार्यों के लिए ठीक रहती है।

(iv) खारी मिट्टी - इस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है अतः कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस मिट्टी में कुछ घस अवश्य उत्पन्न हो जाती है। यह मिट्टी राज्य के नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर की निम्न भूमि व गडों में मिलती है।

2 भूरी रेतीली मिट्टी - इसका रंग भूरा होता है अतः इसे भूरी रेतीली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी रेतीली मिट्टी की

अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। भूरी रेतीली मिट्टी राज्य के मुख्यतः पाली, सिरोंही, बीकानेर तथा झुझुनू जिलों में पाई जाती है। यह इन राज्यों के लगभग 36400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी में फॉस्फेट तत्व का बाहुल्य है। अतः इस क्षेत्र में मक्का, ज्वार, बाजरा तथा मोठ आदि की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में पानी का अभाव है। अतः श्रुंगियत जल के द्वारा सिंचाई की जाती है।

3 भूरी रेतीली कछारी मिट्टी - इसका रंग कुछ लाल व भूरा होता है। यह मिट्टी अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गगननगर जिले के मध्य भाग में मिलती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास व गेहूँ की खेती की जाती है। गगननगर जिले में कपास व गेहूँ की खेती इसी मिट्टी पर निर्भर है।

4 लाल मिट्टी - इस मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में होता है। अतः इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस, चूना व पोटाश आदि पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। यह मिट्टी मुख्यतः उदयपुर, झुझुनू, अजमेर, सिरोंही व बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, कपास, मूंगफली तथा मक्का आदि की खेती की जाती है।

5 लाल व पीली मिट्टी - यह लाल मिट्टी व पीली मिट्टी का मिश्रण होती है। इसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी मुख्यतः भीलवाड़ा, सिरोंही, अजमेर, सर्वाई माधोपुर व उदयपुर जिलों में पाई जाती है। इसमें मूंगफली व कपास आदि की खेती की जाती है। इस मिट्टी के अन्तर्गत रेतीली मिट्टी, छिल्ली या सतही यहूरी मध्यम भारी मिट्टी सम्मिलित है। जो अजमेर व सर्वाई माधोपुर जिलों के कुछ भाग तथा अरावली के पहाड़ी ढालों में पाई जाती है।

6 दुमट व कछारी मिट्टी - यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस, पोटाश तथा लोहा आदि अधिक मात्रा में पाये जाते हैं जबकि नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है। यह मिट्टी मुख्यतः अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक व बूंदी तथा गगननगर आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, चना, चन्ना तथा कपास आदि की खेती की जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है लेकिन टोंक, सर्वाई माधोपुर व भरतपुर की मिट्टी लाल-पीले रंग की है।

7 काली या रेपर मिट्टी - यह मिट्टी काले रंग की होती है। इसमें चूना व पोटाश की मात्रा अधिक होती है। अतः अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पानी सोखकर रखने की शक्ति अधिक होती है। यह मिट्टी मुख्यतः झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर प्रतापगढ़ तथा झुझुनू में पाई जाती है। इसमें विशेषतः कपास की खेती की जाती है। इस मिट्टी में

फास्फेट नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी होती है।

8 लाल व काली मिट्टी यह मिट्टी लाल व काली मिट्टी का मिश्रण होती है। इसमें उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः भीलवाड़ा उदयपुर त्रितोडगढ़ झारपुर तथा बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें प्रायः सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं।

राजस्थान में मिट्टी की समस्याएँ (Problems of Soils in Rajasthan)

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और मिट्टी यहाँ की कृषि का आधार है। राजस्थान में मिट्टी की प्रमुख समस्या मिट्टी के कटाव की समस्या है। मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का बर्णन कहलाता है। जो परिवर्तन का कारण कुछ भी क्यों न हो। राजस्थान में मिट्टी का धीमा या चादरदार कटाव हवा व पानी के माध्यम से लगभग सभी स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है। जहाँ मिट्टी का गहरा व नालोदार कटाव अत्यधिक वर्षा व तेज़ हवाओं वाले क्षेत्र में होता है। गन्धर्व के बोहड़ इसके अच्छे उदाहरण हैं। राजस्थान में गन्धर्व बनास व घग्घर राजगंगा आदि नदियाँ मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण हैं। इनसे राज्य की लगभग 4.5 लाख हैक्टर पर भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है। अरावली पर्वत-श्रृंखला के तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में भी प्लल द्वारा कटाव होता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु के द्वारा मिट्टी का बहुत अधिक कटाव होता है। राजस्थान में वन क्षेत्र कम होने के कारण मिट्टी के कटाव की गति तीव्र है। अनुमान है कि वन क्षेत्रों में मिट्टी का बटाव 9 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष हो सकता है। पशु पालने की दोषपूर्ण प्रथा में भी मिट्टी का कटाव बढ़ा है। मनुष्य स्वयं निर्माण कर्यों के लिए मिट्टी का कटाव बढ़ा है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की दूसरी प्रमुख समस्या जलाधिक्य की है। केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड की विशेष समिति के अनुसार 'एक क्षेत्र में जनधिक्य उस समय होगा जबकि जल का स्तर उस सीमा तक पहुँच जायेगा कि परत के जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी को भिगो दे तथा जिसके परिणाम स्वरूप वायु के सामान्य प्रवाह पर रोक लग जाने से आक्सीजन की वमी तथा कार्बनडाई आक्साईड की अभिप्राता हो जाये। गैर और गन्ना 0.11 मीटर मक्का बाजरा व कपास 1.2 मीटर तथा गन्ना और जौ 0.9 मीटर के भीतर जल स्तर होने पर प्रभावित होने लगता है। राजस्थान की 3.5 लाख हैक्टर भूमि जन प्रसार है। राजस्थान में मिट्टियों की तीसरी समस्या क्षारीयता लवणीयता की है। राजस्थान में मृत्तिका बनास गन्धर्व व माती आदि नदियाँ के क्षेत्र में यह समस्या प्रमुख है। भारतीय मिट्टी की एक और गंभीर समस्या क्षारीयता की समस्या है। यह रेगिस्तान राजस्थान के

उत्तर पश्चिम से अरावली पर्वत-श्रृंखला के कुछ भागों को पार करते हुए अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु जोधपुर में स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) मुख्य रूप से कार्य कर रहा है।

राजस्थान की वन सम्पदा FORESTS IN RAJASTHAN

मनुष्य के लिए वन प्रकृति का ऐसा वरदान है जिस पर उसका अस्तित्व उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। के एम मुशी के अनुसार 'यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमारे जीवन का दर्शन फिर से लिखा जाना चाहिए। वृक्षों का अर्थ है जल और जल का अर्थ है रोटी और रोटी से हम जीवित रहते हैं। विश्व में वन सम्पदा के हास से होने वाली गति और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले प्रयास इसका महत्व के परिचायक हैं। प्राचीनकाल से ही इसकी महत्ता को स्वीकार किया जाता रहा है। मत्स्य पुराण के अनुसार "10 कुएँ खोदना एक तालाब बनाने 10 तालाब बनाना एक झील बनाने 10 झील बनाना एक गुणवान पुत्र प्राप्त करने एवं 10 गुणवान पुत्र प्राप्त करना एक वृक्ष लगाने के बराबर पुण्य का भाग है। ब्रिटिश काल में 'वन शब्दकोष के अनुसार "पौधों की विशेष जाति को जिनमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे छत्ते की भाँति उगते हो वन कहते हैं।"

आर्थिक विकास एवं परिस्थितिक संतुलन के लिए वनों का महत्व सर्वविदित है। राजस्थान में रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए वृक्षारोपण का सारा सिया जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.33% भूमि में वन होने चाहिये किन्तु राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 9.32% वनों के अन्तर्गत आता है। इन 9.32% वनों में से केवल एक तिहाई वन ही तासद्व में वन कहे जा सकते हैं शेष में त्रिरे हुये वृक्ष एवं पेड़ पौधे पाये जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन काटेदार पेड़ों एवं झाड़ियों के रूप में हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ओषाकृत घने जंगल हैं और अन्य जीवों की दृष्टि में भी यह समृद्ध है। राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसमें बरकर भूमि का क्षेत्रफल 13 मिलियन हैक्टर है। राजस्थान की बरकर भूमि का यह क्षेत्र संपूर्ण भारत की बरकर भूमि का 1/6 भाग है। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो कि शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल 20 मिलियन हैक्टर है। इसमें से 50% क्षेत्र में क्रियाशील रेत व टीले हैं। इन परिस्थितियों का राजस्थान में जनजीवन एवं परिस्थितियों

पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है वे जल के कटाव से ग्रसित है। चम्बल व उसकी सहायक नदियों में यहाँ की गहरी खाईयाँ निर्मित कर दी है। इन खाईयों के कटाव से धीरे धीरे आमपाम के कृषि उपजाऊ क्षेत्र भी प्रभावित होत जा रहे है। इन कटराओं एवं खाईयों का क्षेत्रफल लगभग 4.5 हेक्टेयर है। अरावली और विन्ध्यचल पर्वत-श्रृंखलाओं में भी मानव की बढ़ता हुई आवश्यकताओं के कारण होने वाला वन विनाश स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किल्ला इम्टीटवूट आरू साइटिजिक रिमर्य द्वारा अरावली पर्वत-श्रृंखला से संबंधित 16 जिलों के 1972-75 से 1982-83 की अवधि के अंतर्गत किये गये अध्ययन से इस बात का ज्ञान होता है कि इस क्षेत्र में वन क्षेत्र के अंतर्गत 41.5% का कमी आई है। दूसरी ओर वन प्रतिवेदन 1989 के अनुसार राजस्थान के वन क्षेत्र में सुधार आया है। राजस्थान में ईंधन के लिए वन कानूनों से वनों का सर्वाधिक नुकसान पहुँचा है। मुख्यतः बड़े नगरे या कस्बों जैसे जयपुर अलवर बूंदो उदयपुर कोटा आदि के आस पास की पहाडियाँ लगभग वनविहान होती जा रहा है। राजस्थान में 1981-1991 व 2001 में ईंधन की आर्थिक औसत माग का अनुमान क्रमशः 51.21 लाख टन 56.03 लाख टन और 67.62 लाख टन लगाया गया है। राजस्थान में वना से दिना वन क्षेत्र का नुकसान पहुँचाये 6 लाख टन ईंधन का लकड़ी प्रण की जा सकती है किन्तु वनों से 7.25 लाख टन ईंधन प्रतिवर्ष काटा जाता है। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 1.25 लाख टन अतिरिक्त कानूनों के कारण वनों की भारी नुकसान पहुँचा रहा है। सन् 2001 में ईंधन की माग एवं पूर्ति में 62 लाख टन का अंतरान रहने की संभावना है। इन अंतराल का पाटने के लिए लगभग 1 लाख 40000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ 37 लाख पेड़ प्रतिवर्ष लगाने हग।

इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि वन व पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल से जो आँकड़ों अनुमान आधारित वन स्थिति प्रतिवेदन की जाता है उसके अनुसार 1991-1993 व 1995 के प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य के वन क्षेत्र में क्रमशः 5 वर्ष विलोमीटर 210 वर्ग किलोमीटर व 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होना दर्शाया गया है।

इस प्रकार क वर्षों में वन क्षेत्र में 396 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि अक्षित की गई है।

राजस्थान में वनों की स्थिति	
(A) राजस्थान का कुल वन क्षेत्र 31972 वर्ग वर्ग किलोमीटर	
(B) राजस्थान का वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394	
(1) चम्बल	4701.38 वर्ग किलोमीटर
(2) सरावली	2745.77
(3) विन्ध्यचल	2632.77
(C) नुकसान वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर (31 394)	
(1) उरु	20 17 वर्ग किलोमीटर
(2) बाँस	221.41
(3) बाँस	282.39
(4) बाँस	314.85

Source: Forest Survey of India, 1994

राजस्थान के वनस्पति प्रदेश

VEGETATION REGIONS OF RAJASTHAN

1997-98 में राजस्थान के 31 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन विद्यमान थे। राजस्थान की वनस्पति मुख्यतः मरुस्थलीय है। राजस्थान में उदयपुर जिले में सर्वाधिक और जोधपुर जिले में सबसे कम वन है। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति की आकृतिगत भागों में विवरण दिया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य	
(1) राजस्थान का वन क्षेत्र कुल 9% का है। इसमें से बाँस व अन्य वन क्षेत्र 3% है।	
(2) राजस्थान में वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	
(3) वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	
(4) वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	
(5) वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	
(6) वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	
(7) वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	
(8) वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	
(9) वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	
(10) वन क्षेत्र वर्ग वर्ग किलोमीटर 31 394 है।	

1.2 Eight Five Five Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan.
3. Economic Review 1996-97 Govt. of Rajasthan.
4. Economic Review 1997-98 Govt. of Rajasthan.
5. Forest Survey of India, 1994

1 शुष्क अथवा मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग में मगानगर, जोधपुर, चुरू बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 20-30 सेमी है। यहां के वृक्ष प्रायः काटेदार, मोटी व कड़ी छाल तथा छोटी-छोटी पत्तियों वाले होते हैं। छैर, वनूल, खेजड़ा, रुइया, काटेदार झाड़िया आदि इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं।

2 अर्द्ध-शुष्क अथवा अर्द्ध-मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र इस क्षेत्र में सिरोही, सीकर, पाली, झुझुनू व बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यहां वर्षा का औसत 30-35 सेमी है। इस क्षेत्र के वृक्ष भी प्रायः काटेदार हैं। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र की तुलना में ये अधिक सघन हैं। इनमें आड़ू, इमली, काटेदार झाड़िया आदि प्रमुख वृक्ष हैं।

3 शुष्क व आर्द्र वनस्पति क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान के अलवर, टोंक, भरतपुर, कोटा आदि जिलों में फैला हुआ है। यहां वर्षा का औसत 60-90 सेमी तक है। अतः वनस्पति सघन है और अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। आम, नीम, पीपल, शीशम, पलामू, धौव, बांस आदि यहां के प्रमुख वृक्ष हैं।

4 आर्द्र-वनस्पति क्षेत्र इस क्षेत्र में राज्य उदयपुर, वामवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, वृद्धी व झालावाड़ को सम्मिलित किया गया है। यहां वर्षा का औसत 90 सेमी से अधिक है। इस क्षेत्र में माल, तेन्दू, छैर, अकाला, सागवान, गुल्म व महुआ आदि वृक्ष पाये जाते हैं।

राजस्थान में वनों का प्रशासनिक विभाजन Administrative Division of Forests in Rajasthan

राजस्थान में वैधानिक दृष्टि से वना के लिए जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, वृद्धी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही व वामवाड़ा मण्डलों का निर्माण किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वनों को निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया गया है -

1 सुरक्षित वन (Reserved) ये वन 1997-98 में 12.30 लाख हैक्टेयर (38.6%) क्षेत्र में विद्यमान हैं। ये वन बाढ़ों पर नियंत्रण, भू-संरक्षण, मत्स्यत्व के प्रसार पर रोक तथा जलवायु की दृष्टि में महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इनमें लकड़ी काटने व पशु चराने पर प्रतिबंध होता है।

2 रक्षित वन (Protected) ये वन 1997-98 में राज्य के 18.06 लाख हैक्टेयर (50.3%) क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें पशु चराने व लकड़ी काटने पर सरकार प्रतिबंध

नहीं लगाती है।

3 अवर्गीकृत वन (Unclassified) ये वन 1997-98 में राज्य के 3.54 लाख हैक्टेयर (11.1%) में विद्यमान हैं। इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने की सुविधा दी जाती है। इसके लिए सरकार कुछ शुल्क प्राप्ति करती है।

राजस्थान में वनों का प्रशासनिक विभाजन

आवृत वन	12.30 लाख हैक्टेयर
रक्षित वन	18.06 लाख हैक्टेयर
अवर्गीकृत वन	3.54 लाख हैक्टेयर
राज्य का कुल वन क्षेत्रफल	31.90 लाख हैक्टेयर

स्रोत: Economic Review 1997-98, Raj

राजस्थान में वनों के प्रकार

Types of forests in Rajasthan

राजस्थान की जलवायु, स्थिति एवं मिट्टियों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। अतः राजस्थान में वनों की भिन्नता देना भी स्वाभाविक है। राज्य के वनों को अग्र भागों में विभक्त किया जा सकता है -

1 शुष्क सागवान वन सागवान के वन मुख्यतः वामवाड़ा वन क्षेत्र में पाये जाते हैं। चित्तौड़, उदयपुर व कोटा के वन क्षेत्रों में भी सागवान के वृक्ष पाये जाते हैं। मिट्टी की भिन्नता के कारण सागवान के वृक्षों की ऊँचाई में अंतर पाया जाता है। इनकी ऊँचाई 9 से 13 मीटर के मध्य है। सागवान का उपयोग मुख्यतः इमारती लकड़ी, फर्नीचर व मकान निर्माण में किया जाता है।

2 सालर वन सालर के वन राज्य के अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जयपुर व जोधपुर जिलों में पाये जाते हैं। सालर के वृक्ष मुख्यतः अगवली श्रेणियों के ऊपरी टीलों में मिलते हैं। यहां वर्षा का वार्षिक औसत 50-100 सेमी है। इन वृक्षों की ऊँचाई 12-15 मीटर होती है। इनकी लकड़ी का उपयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है।

3 ढाक अथवा प्लास वन ये वन मुख्यतः उन सभी नदी-घाटियों में पाये जाते हैं जहाँ सागवान के वृक्ष विद्यमान हैं। नदियों की घाटियों व नालों में काली भटिया, मिट्टी पाई जाती है जो गहरी व उपजाऊ होती है। उम मिट्टी के क्षेत्र में प्रायः महुआ, बेंडा, बरज, सफेद मिर्च, पारम, पीपल तथा गुल्म आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। ये वन सीमित मात्रा में विद्यमान हैं।

4 शुष्क पतझड़ वन ये वन अरावली श्रेणी के उदयपुर व वामवाड़ा क्षेत्र में 270 से 720 मीटर की ऊँचाई पर पाये जाते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः धौवड़ा, छैर, छिरनी, तेन्दू

1,2 Economic Review 1997-98 Govt. of Rajasthan
3 Economic Review 1995-97 Govt. of Rajasthan

आदि वृक्ष पाये जाते हैं। धौकड़ा की लकड़ी कृषि उपकरण व कोयला बनाने के काम आती है। खैर से कत्था एवं खिरनी से खिलौने बनाये जाते हैं। तेन्दू के पत्ते से बोझो बनाई जाती है। इस क्षेत्र में आम, बबूल, नीम, बहेड़ा, टिमरु, सेमल, ओक, आवला, बास आदि के वृक्ष भी पाये जाते हैं।

5 मिश्रित पतझड़ वन : ये वन मुख्यतः उदयपुर, सिरोंही, कोटा, बूंदी व चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाये जाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 35 से मी है। इस क्षेत्र में आम, जामुन, धौकड़ा, बरगद, गूलर, खैर, बबूल आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में कोयला बनाने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में उपयुक्त वर्षा व उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में सागवान के वृक्ष भी मिलते हैं।

6 उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन : ये वन बोक्नेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, झुझुनू जयपुर व अजमेर जिलों में मिलते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 25-50 से मी है। यहां की जलवायु शुष्क है और भूमि रेतीली है। अतः सूखे व झाड़ीदार वृक्ष पाये जाते हैं। यहां मुख्यतः खेजड़ा, बेर, पेड़िडा, जाल, खैर और बबूल आदि वृक्ष पाये जाते हैं। खेजड़ा इस क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। इस क्षेत्र में घास भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है।

7 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन : ये वन आबू पर्वत के लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विद्यमान हैं। यहां वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 150 से मी है। यह क्षेत्र राजस्थान में वनस्पति की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। यहां मुख्यतः आम, बांस, जामुन, पेड़िडा आदि वृक्ष पाये जाते हैं। यह वन पर्यटकों के लिए आकर्षण केन्द्र बन गया है।

राजस्थान की वन उपजे

FOREST PRODUCTS IN RAJASTHAN

1 इमारती लकड़ी - राजस्थान के वनों में सागवान, साल, बबूल, धौकड़ा आदि वृक्षों की प्रधानता है। इनसे प्राप्त लकड़ी का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। सागवान की लकड़ी मुलायम, चिकनी मजबूत व सुन्दर होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः रेल के डिब्बे, जहाज और फर्नीचर आदि में किया जाता है।

2 ईंधन व कोयला - राजस्थान के वनों की अधिकांश लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य के वनों में 50% से अधिक धौकड़ा पाया जाता है। जिसका प्रयोग ईंधन व कोयला बनाने में किया जाता है। बबूल,

वीकर, खैर, खेजड़ा आदि वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य से कोयले का निर्यात भी किया जाता है।

3 गोद - बबूल, खेजड़ा, नीम, पीपल, टाक आदि वृक्षों से गोद की प्राप्ति होती है। चौहटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण भू-भाग गोद के लिए प्रसिद्ध है। गोद का उपयोग अनेक बीमारियों में किया जाता है। राजस्थान से गोद प्रायः मुम्बई भेजा जाता है।

4 बास - राज्य के उदयपुर, बासवाड़ा, भरतपुर, सिरोंही व चित्तौड़गढ़ जिलों के वनों से बास प्राप्त होता है। इसका उपयोग मुख्यतः कागज, टोकरिया, चारपाई व झोपड़े बनाने में किया जाता है। राज्य के वनों से बहुत कम बास प्राप्त होता है।

5 घास - राजस्थान के वनों में अनेक प्रकार की घास उत्पन्न होती है। इसका उपयोग मुख्यतः पशुओं के चारे तथा झाड़ू व रस्सिया बनाने में किया जाता है। मूज की रस्सी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है।

6 कत्था - राज्य के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बूंदी व झालावाड़ जिलों में कत्थे का उत्पादन किया जाता है। कत्था टैर वृक्ष के तने से बनाया जाता है। राज्य में कत्था बनाने की प्राचीन विधि का श्रवण किया जाता है। अतः वैज्ञानिक विधि की तुलना में कम उत्पादन होता है।

7 तेन्दू पत्ता - तेन्दू के पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर, झालावाड़, बार व बासवाड़ा क्षेत्र में वनों में तेन्दू के वृक्ष पाये जाते हैं। तेन्दू पत्तों के उत्पादन के लगभग आधे भाग का उपयोग राज्य में ही कर लिया जाता है। राज्य के जयपुर, अजमेर, नसीरवाड़ा, भीलवाड़ा, व्यावर, पाली व कोटा आदि शहरों में बीड़ी बनाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता है।

8 आवल - आवल की झाड़ियों की छाल का उपयोग चमड़ा साफ करने में किया जाता है। राज्य के पाली, सिरोंही, जोधपुर, बासवाड़ा व उदयपुर जिलों में आवल की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आवल की छाल मुख्यतः कानपुर, मुम्बई, मद्रास, अहमदाबाद आदि शहरों में भेजी जाती है।

9 महुआ - महुआ के फलों का उपयोग मुख्यतः देशों शराब बनाने के किया जाता है। महुआ के वृक्ष मुख्यतः उदयपुर, झारपुर, सिरोंही, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाये जाते हैं।

10 शहद व मोम - मधुमक्खिया प्रायः वृक्षों पर छत्तों का निर्माण करती हैं। इनसे शहद व मोम की प्राप्ति होती है। राज्य के अजमेर, सिरोंही, भरतपुर, जोधपुर, बासवाड़ा

चिचोडगढ व उदयपुर जिला के वनों से शहद की प्राप्ति होती है।

11 खस खस एक विशेष प्रकार की घास होती है। इसकी जड़ों से तेल निकाला जाता है। यह घास मुख्यतः टोंक सवाईमाधोपुर व भरतपुर जिलों के वनों में उत्पन्न होती है। खस से मुख्यतः इत्र का निर्माण किया जाता है। इसका शर्दत भी बनता है। इसके तनों का उपयोग कर्मों को ठंडा करने में किया जाता है।

राजस्थान की वन-उपजा की मात्रा को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

राजस्थान में वन-उपज			
वन उपज	इकाई	1988-89	1989-90
जलान की लकड़ी	लाख बिग्स	6.05	2.20
इमारती लकड़ी	लाख क्यूबिक फीट	1.20	0.16
घास	लाखों में	13.00	19.00
कत्ता	क्विट्स	396.00	12.00
मृदु पत्ता	लाख क्वेरिन्स	2.09	3.94
शहद एंव मोम	क्विट्स	32.00	98.34
घास	क्विट्स	35285.00	50169.00

स्रोत Some Facts About Rajasthan

पंचवर्षीय योजनाएं व वन विकास

Forest Development Under Five Year Plans

पंचवर्षीय योजनाओं में वन विकास		
योजना	बजट आवंटन (लाख रुपये)	कुल विकास (हेक्टेयर)
प्रथम	1.76	960
द्वितीय	15.31	20708
तृतीय	22.30	68257
चतुर्थ	70.20	142953
पंचम	78	102268
छठी	381.45	139194
सातवीं	476.85	270000
आठवीं	3265.50	492000
नवीं	6750.00	—

स्रोत Draft of the Five Year Plan (1997-2002) Govt of Rajasthan
राजस्थान सुनार जनवरी 1998

राजस्थान में पाचवी योजना में पूर्व वनों का विवास माधनों की कमी के कारण गौमित रहा था। पाचवी योजना के अंतर्गत सामाजिक वादितों सहित अन्य कार्यक्रम कन्द्र की मताया से आरम्भ किय गया। छठी योजना के

अतर्गत ग्रामीण लोगो को ईंधन की आवश्यकता पूर्ति हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया साथ ही एन आर ई पी और आर एल ई जे पी कार्यक्रम आरम्भ किये गये। सातवी योजना में सामाजिक वानिकी को और गति प्राप्त हुई। इसके अतर्गत सामुदायिक सहयोग से फार्म वानिकी पचायत वानिकी भूमि में वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम आरम्भ किये गये। सातवी योजना के अतर्गत वन सन्धी कार्यक्रमों में 8 करोड मानव दिवसों का रोजगार सृजित हुआ। सातवी योजना में वन विकास और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में और अधिक धन की प्राप्ति के कारण वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गति आई। छठी योजना में 13 लाख हैक्टर भूमि में वृक्षारोपण किया गया और 7 लाख करोड पौधे वितरित किये गये थे। इसकी तुलना में सातवी योजना में 2.75 लाख हैक्टर लाख क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया और 31.70 करोड पौधे वितरित किये गये। 1990-91 एवं 1991-92 में क्रमशः 52 हजार 147 और 65 हजार 50 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। इसी अवधि में क्रमशः 3.99 करोड व 5.00 करोड पौधे फार्म वानिकी कार्यक्रम के अतर्गत वितरित किये गये। 1985-86 में विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की गई राष्ट्रीय सामायिक वानिकी परियोजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह परियोजना 16 गैर मन्सखलीय क्षेत्रों में चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बढ़ती हुई ईंधन व चारे आदि की मांग का पूरा करने की चेष्टा करना है। इस परियोजना के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण एवं भूमिहीन की आय व रोजगार को बढ़ाने का प्रयास किया जायगा। इनके माध्यम से भूमि के कटाव को रोकने की चेष्टा की जायेगी तथा बंजर भूमि का और क्षण होने से रक्षा जा सकेगा। इसी परियोजना के अतर्गत किसान एवं स्कूल नसरी वन चेतना केन्द्र बर ग्राफिटिंग पारिवारिक फार्म वानिकी आदि कार्य भी हाथ में लिये गये हैं।

राजस्थान की आठवी पंचवर्षीय योजना में ईंधन चार व लकड़ी की मांग को दृष्टिगत रखते हुये दीर्घकालीन उपाय किये जायेंगे एवं वातावरण संरक्षण का प्रयास किया जायेगा। राजस्थान में विद्यमान पौधा की किम्मी व वन्य जीवों की नस्लों का नष्ट होने से बचाया जायगा वन भेडा का पुन प्रिक्रम किया जायेगा। मुख्यतः अगवनी क्षेत्र के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण लोगो की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं स्थानाण निकार्ण का चयन किया जायगा। जल्दा बढन वाले एवं राजस्थान की जलवायु के लिए उपयुक्त वृक्ष लगाने जायेंगे इतिग माधी नहर एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीलों के स्थिरकरण के प्रयास किय जायेंगे। शहरों एवं कस्बों के अंदर तथा

उनके चारों ओर वृक्ष लगाये जायेंगे ताकि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वन क्षेत्र में वनिकी शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस काम को दृष्टिगत करते हुये कि राजस्थान में वनों से चारस प्रति वी दर 3 लाख टन प्रतिवर्ष है जबकि चारों की अनुमानित आवश्यकता 632.5 लाख टन है। इस अन्तराल को कम करने की चेष्टा की जायेगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारी वनों में राज्य के 47 लाख पशु चरते हैं। अतः योजनाबद्ध तरीके से वन विकास करना होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में वन विकास की विभिन्न कार्यक्रमों पर निम्नानुसार 326.55 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था।

राजस्थान में वन विकास की समस्याये

1 **वनो का अममान वितरण** - राज्य में वनों का वितरण अत्यधिक अममान है। राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम वन हैं। जबकि शेष राजस्थान में वनों का अधिकांश भाग केन्द्रित है।

2 **अपर्याप्त वन** - पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से राज्य का वन क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। कुल भू-क्षेत्र का लगभग 9 प्रतिशत वन है। राज्य का वन-क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है।

3 **वनो के व्यावसायिक उपयोग की सीमित सम्भावनाये** - राज्य में वनों का व्यावसायिक उपयोग नगण्य है क्योंकि वनों में वृक्षों के प्रकार अत्यधिक हैं। अतः एक प्रकार के वन सीमित व अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

4 **समन्वय का अभाव** - राज्य में वन विकास के अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। लेकिन उनमें समन्वय का अभाव है। अतः विकास की गति धीमी है।

5 **यातायात की समस्या** - वन क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं का अभाव है। अतः वन के वैज्ञानिक कार्यों की गति धीमी है। पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात मार्गों का नितान्त अभाव है।

■ **प्राकृतिक विपत्तियों एवं आग के कारण वन विनाश** - वनों में प्रायः लोगों की लापरवाही एवं आधी नूतन के कारण आग लग जाती है। अतः राज्य की मूल्यवान वन सम्पदा कुछ समय में ही नष्ट हो जाती है। जीडे-मकोडे एवं दीमक आदि कृमियों से भी वन नष्ट होते हैं।

7 **भ्रष्टाचार** - वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार भी वन विनाश का प्रमुख कारण है। भ्रष्टाचार के कारण मूल्यवान वृक्षों का तेजी से विनाश हो रहा है।

8 **वनो की अनियन्त्रित कटाई** - राज्य की जनसंख्या में

वृद्धि के साथ-साथ ईंधन एवं इमारती कार्यों के लिये लकड़ी की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। अतः वनों की तेजी से कटाई हो रही है। कृषि एवं आवास के उद्देश्यों से भी वनों का विनाश किया जा रहा है।

9 **अनियन्त्रित चराई** - राज्य के वनों का चरागाह के रूप में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। भेड़-बकरियों की चराई के कारण वन विनाश तीव्र गति में होता है।

वनो की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

1 वनों की अनियन्त्रित कटाई पर श्रमाव रोक लगाई जानी चाहिये।

2 वनों के विस्तार हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों व योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिये।

3 वन विज्ञान कार्यक्रमों में पर्याप्त समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

4 वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिये।

5 वनों में लगन वाला आग पर नियन्त्रण हेतु विशिष्ट प्रयास किये जाने चाहिये।

6 वनों में यातायात सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये।

7 वन अनुसन्धान कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

8 जनता को वनों के महत्व की जानकारी दी जानी चाहिये और विवास कार्यों में जनसहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

9 वन विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त व्यय का प्रावधान किया जाना चाहिये।

10 वन क्षेत्रों में पशुओं की चराई पर रोक लगाई जानी चाहिये।

11 मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनों के विस्तार हेतु विशिष्ट कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिये।

वन विकास के सरकारी कार्यक्रम

1 **साप्ताहिक टनिकी कार्यक्रम** के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों एवं पंचायती राज संस्थाओं को गेधे दिये जाते हैं जो दूध भूमि रेल सड़क-वन व नहरों के किनारे लगाए जाते हैं।

2 **फार्म वनिकी कार्यक्रम** के अन्तर्गत कृषकों का अपने खेतों में वृक्षादेयता हेतु सौध दिये जाते हैं।

3 अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत गज्य के दस जिलों - पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बासवाडा, नागौर, झुझुनू, सीकर अलवर एवं जयपुर में 1992-93 से वृक्षारोपण किया जा रहा है।

4 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान की सहायता से वृक्षारोपण और चरागाह विकास का कार्य किया जाता है।

5 वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास परियोजना के अन्तर्गत जापान सरकार के सहयोग से राज्य के 14 जिलों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।

6 वन विकास में जन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य के ग्राम स्तर पर वन संरक्षण एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है।

7 विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकी कार्यक्रम में सलान व्यक्तियों को खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है।

8 स्कूलों में प्रत्येक छात्र द्वारा एक वृक्ष लगाने की व्यवस्था की गई है।

9 पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु पर्यावरण विकास दलों का गठन किया गया है।

10 राज्य का वन विभाग वन-अनुसन्धान पर विशेष बल देता है।

11 महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा पर्यावरण विकास कैम्प कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण करते हैं।

राजस्थान सरकार की वन नीति

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का अनुसरण करते हुये 20% वन क्षेत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये निम्न रणनीति निर्धारित की है -

1 राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.32% क्षेत्र में वन है। इनमें से 1.32% वनों को प्रथम श्रेणी के वन कहा जा सकता है। शेष 8% वन निम्न श्रेणी के है। इन निम्न श्रेणी के वनों में परिस्थितिकी की पुर्नस्थापना विभिन्न उपायों से करने का निश्चय किया गया है।

2 वनस्पति के प्राकृतिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहित करने और इस सम्बन्ध में पूरक उपाय करने का निश्चय किया गया।

3 वस्त्र और अनुपजाऊ भूमि में गहन वनीकरण और वनों की पुन स्थापना का कार्य स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किया जायेगा।

4 ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी और चरागाह क्षेत्र विकसित करने का प्रथम विशेषतः पंचायत और राजस्व विभाग की बेकर पट्टी भूमि पर किया जायेगा।

5 सड़क, रेल और नहरों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा ताकि स्थानीय आवश्यकताएं भी पूर्ण हो सकें।

6 निजी भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जायेगा। राजस्थान में लगभग 61% भूमि इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

7 प्रमुख शहरी केन्द्रों में शहरी वानिकी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

राजस्थान की जल-सम्पदा

WATER RESOURCES OF RAJASTHAN

राजस्थान की जल-सम्पदा को राजस्थान की अर्थव्यवस्था रूपी शरीर में बहने वाला रक्त कहा जा सकता है। राज्य में जल के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजस्थान में 12 महीने बहने वाली कोई भी नदी नहीं है किन्तु राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से घबल नदी गुजरती है जिसने जल ससाधनों की दृष्टि से राजस्थान को कुछ राहत प्रदान की है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल देश का 10.4% है। इसी प्रकार देश का 10.6% भाग कृषि के अंतर्गत है किन्तु देश के जल ससाधनों का केवल 1.04% भाग ही राजस्थान में उपलब्ध है। इन आंकड़ों से राजस्थान में जल ससाधनों की कमी का ज्ञान होता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में भूमिगत जल के पर्याप्त स्रोत हैं क्योंकि यह भाग नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। इस क्षेत्र में प्रायः 15-20 मीटर की गहराई पर पानी मिल जाता है। यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र में भी भूमि के नीचे अथाह जल भण्डार होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में शतबीनवाल के सरस्वती और हाकरा नदियों का लुप्त हुआ जल भूमि के नीचे पाए जाने का अनुमान है। जैसलमेर व पोकरण नगरों के मध्य 112 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में मोटे जल के पर्याप्त होने का अनुमान है। मरुस्थल के अधिकांश भाग में भूमिगत जल प्रायः खारा है। जैसलमेर जिले के लाठी थैलिन में केंद्रीय भू जल बोर्ड द्वारा किए गए विनृत सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस क्षेत्र में भू जल स्रोत की वार्षिक खनन क्षमता 143 मिलियन क्यूबिक मीटर है। जल नियम के अनुसार राज्य के पूर्वी भाग (जयपुर, मवाई, माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर के अतिरिक्त गोंवर व झुझुनू जैसे मरुस्थलीय जिलों सहित) में बड़ी मात्रा में भू जल उपलब्ध है। राजस्थान में आज भी कुएँ ही गिनवाई व प्रमुख

साधन है। राजस्थान सरकार द्वारा जल संसाधनों पर गठित कमेटी के अनुसार राजस्थान में भूमिगत जल-स्रोत लगभग 10 18 मिलियन एकड़ फाट है, जिसमें से उपयोग योग्य भूमिगत जल का 50% विद्योहित किया जा चुका है। भूमिगत जल की सिंचाई, घरेलू एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बढ़ती हुई मांग और लगातार अत्यधिक दोहन के कारण जून, 1988 में राज्य के 237 खण्डों में से है। 81 खण्डों को डार्फ जोन तथा 31 खण्डों को ग्रे जोन खण्डों के अंतर्गत रखा गया है।

राजस्थान की नदियाँ

RIVERS OF RAJASTHAN

A चम्बल नदी - यह मध्यप्रदेश राज्य के मऊ नामक स्थान के पास "जनापाव पहाड़ी" से निकलती है। यह पहाड़ी 616 मीटर ऊंची है। यह नदी उत्तर-पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर आदि जिलों से लगभग 325 किलोमीटर बहने के पश्चात् चौरमोगढ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य की केवल यह नदी ही वर्षापर्यन्त बहती है। इसका प्राचीन नाम चर्मण्वती है और इसे कामधेनु के नाम से पुकारा जाता है। यह राजस्थान में कोटा सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में लगभग 210 कि.मी. बहती है। बामनी, बनाम, काली सिन्ध, पार्वती, कुण्ड, कुटाल व परवान नदियाँ इसके सहायक हैं। इस नदी पर गार्गी सागर, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाए गये हैं। धौलपुर के दक्षिण में इस नदी के किनारों पर गलीदार गतों का निर्माण हुआ है। अन्त में यह नदी उत्तरप्रदेश राज्य के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चम्बल की प्रमुख सहायक नदियाँ निम्नलिखित प्रकार हैं -

1 काली सिन्ध नदी - इस नदी का उद्गम-स्थल मध्य प्रदेश राज्य में देवास के पास बागला गांव है। मध्य प्रदेश में कुछ दूरी तक बहने के पश्चात् यह नदी राजस्थान के झालावाड़ व कोटा जिलों में बहती है। अन्त में यह नर्मेश नामक एक स्थान पर चम्बल नदी में मिल जाती है। आहु, परवान व निवाज इसकी सहायक नदियाँ हैं।

2 बनास नदी - यह नदी अरावली पर्वत श्रेणियों की छपनौर पहाड़ियों से, कुम्भलगढ के पास से निकलती है। यह प्रायः वर्षापर्यन्त बहती है लेकिन कभी-कभी वर्षा के मौसम में सूख जाती है। इस नदी को "वन का आशा" के नाम से पुकारा जाता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के बीच में से गुजरती है। यह लगभग 480 किलोमीटर बहने के पश्चात् मवाई माधोपुर व कोटा की सीमा के पास इस

नदी के ऊपरी क्षेत्र पहाड़ी है। अतः यहां वर्षा ठीक होती है नदी घाटी का क्षेत्र उपजाऊ है। कोठारी, वेडच, मारेल, धुम्य, मावस्य, मैनाल व खारी बनास की सहायक नदियाँ हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ निम्नलिखित हैं।

(i) वेडच नदी : यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम-स्थल उदयपुर के उत्तर में गोगुन्दा की पहाड़ियाँ हैं। गोगुन्दा की पहाड़ियों में उदयपुर झील तक इसे आयड नदी कहा जाता है। 190 किलोमीटर बहने के पश्चात् यह नदी बिणोद नाम स्थान के निकट बनास नदी में मिल जाती है। गर्मारी वेडच की एक सहायक नदी है।

गर्मारी नदी - यह वेडच नदी की सहायक नदी है। यह उदयपुर जिले में बहती है और अन्त में चित्तौड़गढ़ के चटियावली नामक स्थान के पास वेडच नदी में मिल जाती है। इस नदी पर निम्बाहोडा के निकट गर्मारी बांध का निर्माण किया गया है।

(ii) कोठारी नदी : यह नदी उदयपुर जिले के दिबरो नामक स्थान से निकलती है। 145 किलोमीटर बहने के पश्चात् यह भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है।

(iii) खारी नदी - यह उदयपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित बिपराग गांव के निकट की पहाड़ियों से निकलती है और टोंक जिले के देवली नामक स्थान के पास बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है।

(3) पार्वती नदी - यह नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मध्यप्रदेश में कुछ दूर बहने के पश्चात् कन्याहट नामक स्थान के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। यह कोटा व पाली जिलों में लगभग 85 किलोमीटर बहने के बाद चवल नदी में मिल जाती है।

■ लूनी नदी - यह नदी अजमेर के निकट नागपहाड़ से निकलकर जोधपुर मध्या में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और अन्त में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। यह मौसमी नदी है। बालोतरा तक इसका जल मोटा रहता है लेकिन उसके पश्चात् खारा हो जाता है। विलाडा के निकट इस पर एक बांध बनाया गया है। इस नदी की लंबाई 330 कि.मी. है। गृहिया, सुकडी, बाडी, मिर्छी, लीलडी, जोडडी, जवाई तथा मगाई इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।

C साही नदी - यह नदी मध्यप्रदेश की विंध्य पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में से होकर गुजरात में प्रवेश करती है, अतः यह खम्भात की खाड़ी में जा मिलती है। लगभग 583 कि.मी. लंबी यह नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व गुजरात में क्रमशः 167 कि.मी., 174 कि.मी. व 242 कि.मी. बहती है। यह नदी झारपुर व दासवाड़ा जिलों के मध्य सीमा का निर्माण भी करती है। दासवाड़ा में इस नदी का

माही वजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। सोम, बाप मोन व अनाम इसकी सहायक नदिया है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी सोम है।

(i) **सोम नदी** - यह नदी उदयपुर जिले के बीधामेडा नामक स्थान से निकलती है। प्रारंभ में दक्षिण-पूर्व दिशा में बहने के बाद यह इगारपुर की सीमा के साथ साथ पूर्व में बहती है और वेणरवर के निकट माही नदी में मिल जाती है। जालम गामती व सारनी इसकी सहायक नदिया है।

(ii) **जाखम नदी** - यह सोम नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल छोटी सादडी के निकट है। यह नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती हुई उदयपुर की धारियावट तहसील में प्रवेश करती है तथा सोम नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एक बांध बनाया जाता है और 45 मेगावाट क्षमता का एच विद्युतगृह भी निर्माणाधीन है।

साबरमती नदी - यह नदी उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में (अगवली पहाड़ियों से) निकलकर दक्षिण की ओर बहती है। कुछ दूरी तक उदयपुर जिले में बहती है और फिर गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। वनगव मेरवा हथमति माजम व बाकल इसकी प्रमुख सहायक नदिया है।

बाणगंगा नदी - यह नदी जयपुर जिले के बैराठ का पहाड़िया में निकलती है तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहाबाद के पास यमुना नदी में मिल जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 380 किमी है। इस नदी पर जमवा गमगढ़ के पास एक छोटा बांध बनाया गया है जिससे जयपुर शहर को पीने का पानी मिलता है।

घग्घर नदी - यह नदी कालिका के पास हिमालय में निकलती है और पंजाब और हरियाणा में बहती हुई गजस्थान के श्रीगंगानर जिले में प्रवेश करती है। उसके आगे यह नदी मरुस्थलीय भाग में लुप्त हो जाती है। इस नदी में प्रायः बाढ़ आती है अतः परसलों को नुकसान होता है और यातायात में रुकावट आ जाती है। इसकी तलहटी में चावल की खेती की जाती है।

काकनी या काकनेय नदी - यह नदी जैमलमेर में 27 किमी दूर काटनी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। यहां से उत्तर पश्चिम में लगभग 40 किमी बहने के पश्चात् यह भुज झील में गिर जाता है। यह मौसमी नदी है।

काटली या कातली नदी - यह नदी झुनझुन जिले की उत्तरी सीमा के मध्य से दक्षिण दिशा की ओर बहती है व झुनझुन जिले को लगभग दो भागों में विभक्त

करती है। लगभग 95 किमी बहने के पश्चात् यह लुप्त हो जाती है।

पश्चिमी बनास - यह नदी अगवली पर्वत के पश्चिमी ढालों से निकलती है। यह सिरोंही जिले में बहती है और अन्त में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है।

सावी या साहबी नदी - यह नदी जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से निकलती है। बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ मण्डावर तथा तिनारा तहसीलों में बहती है और हरियाणा के गुडगांव जिले में प्रवेश करती है। इस जिले में कुछ दूरी तक बहने के पश्चात् यह लुप्त हो जाती है।

मन्था नदी - यह नदी जयपुर जिले के मनोहर खाना नामक स्थान से निकलती है और अन्त में माभर झील में गिरती है।

राजस्थान की झीलें

LAKES OF RAJASTHAN

राजस्थान में खारे व मीठे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलों में नमक बनाया जाता है और मीठे पानी की झीलों के जल का उपयोग सिंचाई व पीने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ झीलें प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम हैं। इन झीलों में मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। कुछ झीलें पर्यटन स्थलों का रूप धारण कर चुकी हैं। राज्य की झीलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। (अ) मीठे पानी की झीलें (ब) खारे पानी की झीलें

A मीठे पानी की झीलें

(i) **जयसमन्द झील** - यह झील उदयपुर शहर से 51 किमी दक्षिण पूर्व में है। इसका निर्माण राजा जयसिंह ने मन् 1685 से 1691 के मध्य कववा था। इस झील का निर्माण गामती नदी पर 375 मीटर लंबा व 35 मीटर ऊंचा बांध बनवाकर किया गया। झील की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 किमी व 8 किमी है। इस झील में लगभग 8 टापू हैं। इन टापूओं में भोल व मोणा लाग रहते हैं। सम वड़े टापू का नाम बाबा का भागडा व छोटे टापू का नाम प्यारो है। झील का क्षेत्रफल लगभग 55 किमी है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और विरव की कृत्रिम झीलों में इसका दूसरा स्थान है। इस झील में 6 कलात्मक छतरियां व प्रामाद बनाये गये हैं। इस झील के चारों तरफ पहाड़ियां हैं। अब इसका प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यधिक मोहक है। यही कारण है कि यह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख

वेन्द्र बन गई है। इस झील से सिवाई के लिए दो नहरें निकाली गई हैं।

(ii) पिछोला झील - यह उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध व अत्यधिक सुन्दर झील है। इसका निर्माण राजा लाछा के शासनकाल में एक बजारे ने करवाया था। राजा उदयसिंह ने इस ठीक करवाया। यह झील उदयपुर के पिछोली गांव के पास स्थित है अतः इसे पिछोला झील कहा जाता है। झील की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 7 किलोमीटर व 2 किलोमीटर है। इसमें दो टापू हैं। एक टापू पर जगमदिर और दूसरे पर जगनियाम नामक महलों का निर्माण किया गया है। बादशाह बनने में पहले शाहजहां भी इस झील के महलों में आकर ठहरा था। अब इन महलों में पांच मिनारा हाउस स्थापित है।

(iii) राजसमन्द झील - यह झील उदयपुर में 64 किमी दूर बाकगोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसका निर्माण महाराजा राजसिंह ने 1662 में करवाया था। इस झील को जल की प्राप्ति गोमती नदी में होती है। इसके पानी का उपयोग सिवाई व पीने के लिए किया जाता है। झील की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 6.5 किमी व 3 किमी है। झील के उत्तरी भाग को 'नौ चौकी' कहा जाता है। जहा मगमगर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास मस्कृत भाषा में अंकित है।

(iv) आनासागर झील यह झील अजमेर शहर में दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज के दादा अनाजी ने 1137 में करवाया था। इसकी परिधि 8 मील है। शाहजहां ने इस पर एक बागटरी का निर्माण करवाया था तथा जहांगीर ने झील के पूर्व में एक उद्यान 'दौलत बाग' बनवाया, वर्तमान में इन उद्यान को सुभाष उद्यान कहा जाता है यह झील पूर्णमासी की रात्रि को चांदनी में अत्यधिक सुन्दर लगती है।

(v) फाई सागर यह झील अजमेर में स्थित है। इसमें प्रायः वर्षावर्ष पानी रहता है। इसका जल आनासागर में आता है। झील प्राकृतिक दृष्टि में सुन्दर है अतः शहर के लोग प्रायः पिकनिक व लिये यहाँ आते रहते हैं।

(vi) पुष्कर झील यह झील अजमेर में 11 किमी दूर पुष्कर में स्थित है। इसके तान और पहाड़िया हैं और झील के चारों तरफ स्नान घाट बने हुए हैं। इसके चारों तरफ मंदिर हैं। ब्रह्मा का मंदिर सर्वश्रेष्ठ प्राचीन है। बसुन्धरा यह एक पवित्र झील व नगरस्थल है जहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भी लगता है। यह देश के विभिन्न भागों में तीर्थयात्री आते हैं।

(vii) फतह सागर इस झील का राजा फतहसिंह ने बनवाया था। यह पिछोला झील से लगभग एक मील दूर

स्थित है। यह झील एक नहर द्वारा पिछोला झील में मिली हुई है। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कर्नॉट द्वारा रखी गई है।

(viii) सिलीसेढ झील - यह झील दिल्ली-जयपुर मार्ग पर, अलवर से लगभग 12 किमी दूर स्थित है। यह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ पर्यटक मुख्यतः मछली पकड़ने व नौका विहार के लिए आते हैं।

(ix) बालसमन्द झील यह झील जोधपुर के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके जल का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है।

110661

(x) उदय सागर इसे उदयसिंह ने बनवाया था। यह झील उदयपुर नगर से 13 किमी दूर स्थित है।

(xi) कोलायत झील यह झील बीकानेर से 48 किमी दूर स्थित है। यहाँ अनेक मंदिर हैं। इस झील में वर्षावर्ष पानी रहता है। यहाँ वर्ष में एक बार मेला भी लगता है।

(xii) नक्को झील - यह झील मिराही जिले में रघुनाथजी के मंदिर के पास स्थित है। यह कृत्रिम झील शान्त व स्थिर वातावरण में पवित्रता का आभास देती है। यहाँ पर्यटक नौका-चौकी विहार करते हैं। इस झील के एक ओर प्रसिद्ध टॉड रॉक (Tod Rock) है।

(xiii) गैव सागर - यह झील झुगरपुर जिले में स्थित है।

(xiv) कैलसा झील यह झील जोधपुर जिले में है। इसे महाराजा प्रताप ने बनवाया था।

(xv) नवलुआ झील यह झील बूंदी जिले में स्थित है। यह पहाड़ियों में घिरी हुई है।

8. खारे पानी की झीले

(i) सागर झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह जोधपुर-जयपुर मार्ग पर जयपुर जिले के कुनेरा बक्शान में 8 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह झील 26°9' उत्तरी अक्षांश से 27°2' उत्तरी अक्षांश पर तथा 74°3' पूर्वी देशान्तर से 75°3' पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 32 किमी और चौड़ाई 3.25 किमी से 11.25 किलोमीटर तक है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 360 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 145 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 5720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पानी आकर एकत्रित हो जाता है। एक अनुमान क अनुसार इस झील में लगभग 650 लाख टन नमक है। भारत का कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% इस झील से प्राप्त होता है। इस झील के छेद में 50 से भी अधिक वर्षा होती है। झील के उत्तरी तट पर सागर व नाग नामक शहर हैं, जहाँ

नमक का व्यापार व नमक बनाने का काम होता है। साभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से नमक का निर्यात भी होता है।

(ii) डीडवाना झील यह झील नागौर जिले में डीडवाना शहर के निकट स्थित है। यह झील 27°24 उत्तरी अक्षांश एवं 74°34 पूर्वी देशान्तरों पर स्थित है और 10 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस झील में लगभग वर्षभर नमक तैयार किया जाता है। इसके नमक का उपयोग बीकानेर व जोधपुर जिला में होता है तथा शेष नमक बाहर भेज दिया जाता है। डीडवाना नगर से 8 किमी दूरी पर सोडियम बनाने का एक संयंत्र लगाया गया है।

(iii) पचपदरा झील यह झील बाड़मेर जिले के पचपदरा नामक नगर में स्थित है। लगभग 25 किमी क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 1040 किमी क्षेत्र का पानी एकत्रित होता है। इस झील में तैयार किये गये नमक में 98% तक सोडियम फ्लोराइड होता है। यह नमक उत्तम श्रेणी का होता है।

(iv) लूनकरनसर झील यह झील बीकानेर से 80 किमी दूर लूनकरनसर में स्थित है। इससे बहुत कम मात्रा में नमक तैयार किया जाता है क्योंकि इसके पानी में लवणीयता की कमी है।

(v) अन्य झीलें फलीदी रेवासा व कछोर में भी खारे पानी की झीलें हैं।

राजस्थान की पशु-सम्पदा

ANIMAL WEALTH IN RAJASTHAN

पशुधन से तात्पर्य उन समस्त पशुओं से लगाया जाता है जिनसे प्रमुख प्रत्यक्ष रूप व अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह हेतु कुछ न कुछ वस्तुएं प्राप्त करता है। इस प्रकार इसमें प्रायः सभी प्रकार के पशुओं की सम्मिलित किया जाता है। पशुओं से न केवल विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं वरन् इन्हें विभिन्न उपयोगों में भी लाया जा सकता है। राजस्थान में पशु सम्पदा कृषि कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान में यह लोगों को पौष्टिक पदार्थों की पूर्ति का उचित पोषाहार उपलब्ध कराने में भी सहायता करती है। यह राजगार का भी महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त इसमें चमड़ा खाने-ऊन खाद आदि भी बहुतायत में प्राप्त किये जाते हैं। ये यन्त्रायत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

राजस्थान में पशुओं की संख्या

Live stock in Rajasthan

राजस्थान में पशुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1988 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में 4 करोड़ 9 लाख पशु थे जो 1992 की पशुगणना के अनुसार 4 करोड़ 77 लाख व 1997 में 5 करोड़ 43 लाख से अधिक हो गये हैं। 1988 व 1992 में राजस्थान में विभिन्न पशुओं की स्थिति निम्नलिखित थी -

पशु	पशुओं की संख्या (लाखों में)		
	1988	1992	1997
गाव	109.1	116.42	121.58
भैस	63.3	77.75	97.69
भेड़	99.1	124.91	143.12
बकरी	125.9	152.85	169.36
घेड़े एवं टर्क	0.2	0.2	0.2
गधे व खच्चर	1.8	1.9	1.86
ऊट	7.2	7.46	8.68
कुत्ता	2.0	2.4	3.03
खैर	408.0	477.73	543.48

स्रोत: Board of Revenue for Rajasthan Live stock Census 1997 & Statistical Abstract Raj 1998

राजस्थान में पशुधन की जिलेवार स्थिति (1997)

(लाखों में)

(A) राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाले प्रमुख जिले -

(i) बाड़मेर	41.77 लाख
(ii) जोधपुर	37.59 लाख
(iii) नागौर	32.27 लाख

(B) 1997 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में विभिन्न पशुओं की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान वाले जिले

गाव	जोधपुर	9.7 लाख
भैस	जोधपुर	7.7 लाख
भेड़	जोधपुर	15.6 लाख
बकरी	बाड़मेर	18 लाख
ऊट	बाड़मेर	1.1 लाख
कुत्ता	जोधपुर	14.9 लाख

स्रोत: Board of Revenue to Rajasthan Live stock Census 1997 & Statistical Abstract Raj 1998

राजस्थान में पशु-पालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु

राजस्थान में अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इनमें से कुछ विशाल महत्व के पशु निम्नलिखित हैं।

(1) भैंस (Buffalo) राजस्थान में दूध प्राप्ति के लिए भैंस बहुतायत में पाली जाती है। राजस्थान में जो भैंसे

पाली जाती है। उनकी मुख्यतः चार नस्लें हैं - मुरी, जाफरावादी, नागपुरी और बदावरी। इनमें से मुरी एक महत्वपूर्ण नस्ल है। यह नस्ल दूध की दृष्टि में उपयुक्त मानी जाती है और लगभग सारे उत्तरी भारत में बहुतायत में देखी जा सकती है। जाफरावादी नस्ल काठियावाड़ और जाफरावाद से संबंधित होने के कारण जाफरावादी कहलाती है। इसे भी दूध के लिए पाला जाता है। नागपुरी नस्ल और बदावरी नस्लें भी दूध के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

राजस्थान में सबसे अधिक भैंसे जयपुर में पाली जाती हैं। तत्पश्चात् क्रमशः अजमेर, सर्वाईमाधोपुर और उदयपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे कम भैंसे जैसलमेर जिले में है। राजस्थान के सभी जिलों में भैंस पालन का मुख्य उद्देश्य दुग्ध-उत्पादन है।

(2) गाय (Cattle) राजस्थान में गाय की मुख्य नस्लें साहीवाल, लालसिंधी, गिर, थारपरकर, मेवाती, नागौरी, मालवी आदि हैं। राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों में थारपरकर नस्ल बहुतायत में पाई जाती है। जोधपुर क्षेत्र की ओर नागौरी गाय अधिक मिलती है। मालवा के पठारी क्षेत्र में मालवी और राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर क्षेत्र में मेवाती नस्ल अधिक पाई जाती है। राजस्थान में गौ पालन का मुख्य उद्देश्य दूध-उत्पादन तो है ही, साथ में वृषिकर्षों के लिए बैलों का प्रयोग करना भी है। राजस्थान में घीर और दही नस्लों के साथ-साथ विदेशी नस्लें भी पनपने लगी हैं।

भैंसों की भांति सर्वाधिक गायें भी जयपुर जिले में पाई जाती हैं। गौ-पालन की दृष्टि से अन्य जिलों क्रमशः उदयपुर, गगानगर, चित्तौड़गढ़, बीटा नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर आदि हैं। राजस्थान में सबसे कम गायें धौलपुर जिले में हैं। विदेशी नस्ल की गायों की दृष्टि में भी जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है। महत्व के अनुसार अन्य जिले क्रमशः गगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा अजमेर हैं। विदेशी नस्लों में हॉलिस्टीन व बर्सी प्रमुख हैं।

(3) भेड़ (Sheep) राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण लोग कृषि की भांति पशुपालन पर भी निर्भर हैं और इसमें भेड़पालन का एक विशेष स्थान है। राजस्थान के पश्चिमी एवं उत्तर-पश्चिमी भागों में तो भेड़पालन आजीविका का प्रमुख आधार है। राजस्थान में उपलब्ध भेड़ों की आठ मुख्य नस्लें हैं। ये नस्लें हैं - चौकला, मणव, पूगल, नाली मारवाडी जैसलमेर, मालपुरी एवं मंठाडी। चौकला नस्ल मुख्य रूप से चूरू, झुझुनू व सीकर जिलों में तथा बीकानेर, जयपुर एवं नागौर जिलों की सीमाओं पर पाई जाती है। मणव नस्ल बीकानेर जिले में तथा नागौर एवं जैसलमेर जिलों की सीमाओं पर पाई जाती है। पूगल नस्ल बीकानेर

जिले के पश्चिमी भाग, पूगल क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र एवं जैसलमेर जिले के उत्तरी भाग में मिलती है। नाली नस्ल राजस्थान के उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी भागों में पाई जाती है। मारवाडी नस्ल बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर एवं नागौर जिलों में देखी जा सकती है। जैसलमेर नस्ल जैसलमेर जिला तथा जोधपुर एवं बाड़मेर की पश्चिमी सीमाओं पर बहुतायत में मिलती है। मालपुरी नस्ल जयपुर, टोंक, सर्वाई माधोपुर आदि जिलों में तथा इनके साथ लगी अजमेर भीलवाड़ा एवं बूंदी जिलों की सीमाओं पर मिलती है। मंठाडी नस्ल उदयपुर खण्ड में पाई जाती है।

राजस्थान में भेड़ मुख्यतः ऊन एवं मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाली जिले में हैं, तत्पश्चात् क्रमशः नागौर, बीकानेर और जोधपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे कम भेड़ें धौलपुर जिले में हैं।

4 बकरी (Goat) राजस्थान में बकरी पालन मुख्यतः गरीब वर्ग द्वारा दूध-उत्पादन के लिए किया जाता है। बकरी पालन के पीछे एक उद्देश्य मांस प्राप्त करना भी है। राजस्थान में बकरी की जो प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं उनमें जमुनापारी व बारवरी नस्लें प्रमुख हैं।

इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक बकरियाँ उदयपुर जिले में पाई जाती हैं तत्पश्चात् जयपुर एवं नागौर जिलों का स्थान है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे कम बकरियाँ धौलपुर जिले में हैं।

5 ऊँट (Camel) राजस्थान में ऊँट मुख्यतः आवागमन में सुविधा की दृष्टि से पाला जाता है, साथ ही इसका प्रयोग कृषि कर्षों के लिए भी बहुतायत में किया जाता है। राजस्थान में सम्पूर्ण देश में सख्खा की दृष्टि से सर्वाधिक ऊँट हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट गगानगर जिले में हैं। तत्पश्चात् क्रमशः बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे कम ऊँट धौलपुर जिले में हैं।

6 कुक्कुट (Poultry) राजस्थान में मुर्गीपालन का महत्व निम्नतर बढ़ता जा रहा है। कृषकों की खाली समय में रोजगार प्राप्त करने का यह एक प्रभावी माध्यम है। इस व्यवसाय में शहरी क्षेत्र के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। मुर्गीपालन का मुख्य उद्देश्य अण्डा व मांस उत्पादन है।

अजमेर जिला अपनी जलवायु की उपयुक्तता के कारण मुर्गीपालन में प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कामवाड़ा एवं तृतीय स्थान पर उदयपुर जिला है। तत्पश्चात् क्रमशः गगानगर, अलवर, झुझुनू व जयपुर जिलों का

स्थान है। मुर्गीपालन की दृष्टि से बीकानेर जिला सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। सकर नस्ल की मुर्गियों में भी अजमेर जिले का प्रमुख स्थान है जबकि इम दृष्टि से बीकानेर जिला सबसे पीछे है।

राजस्थान की खनिज-सम्पदा

MINERAL WEALTH IN RAJASTHAN

खनिज पदार्थ आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। ये अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। कृषि, परिवहन, संचार, उद्योग आदि के प्रत में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। शक्ति के साधन, आधुनिक युद्ध एवं अन्तर्गति विज्ञान का विकास खनिज ससाधनों के बिना सम्भव नहीं है इसलिए खनिज ससाधनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्ल बी शॉ के अनुसार, "खनिज प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अवैकिक तत्व हैं जिसकी निश्चित भौतिक विशेषताएँ होती हैं और जिसे रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है।" खनिज पदार्थों को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है (1) धात्विक खनिज धात्विक खनिजों के दो भाग हैं (अ) लौह धातु इसमें खनिज लोहा, टंगस्टन, मैंगनीज, क्रोमाइट आदि खनिजों को सम्मिलित किया जाता है। (ब) अलौह धातु इसमें जस्ता, तांबा, वाकसाइट, टिप, सीसा, स्वर्ण व चादी को सम्मिलित करने हैं। (2) अधात्विक खनिज इसमें अभ्रक, नमक, चूने का पत्थर आदि का समावेश किया जाता है। (3) शक्ति-उत्पादक खनिज इसमें खनिज तेल, थोरियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, बेरालियम आदि खनिजों को सम्मिलित किया जाता है।

राजस्थान के प्रमुख खनिज

Important Minerals of Rajasthan

"राज्य ज्ञात खनिज भण्डारों तथा उनकी सम्भाव्यताओं की दृष्टि में धनी नहीं है लेकिन बाद के सर्वेक्षणों में यह सिद्ध हो गया है कि राजस्थान निश्चित रूप से देश के मुख्य खनिज उत्पादकों में से एक है और खनिज ससाधनों की अधिकतम औद्योगिक सम्भाव्यताओं से परिपूर्ण व धनी है।" डा हेमन के इन विचारों से स्पष्ट है कि राजस्थान खनिज पदार्थों की दृष्टि में एक सम्पन्न राज्य है। यहाँ आक प्रगर के खनिज पाए जाते हैं, अतः राजस्थान को खनिज पदार्थों के अजायगराज की सज्ञा दी जाती है। राज्य के खनिजों से न केवल राज्य सरकार की

आय में वृद्धि होती है वरन् इनसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। कुछ खनिजों के उत्पादन में तो राज्य को पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है। राजस्थान में जिन महत्वपूर्ण खनिजों से राज्य का नाम बहुलता के साथ जुड़ा है, उनमें अलौह धातु (शीशा), जस्ता एवं तांबा तथा लौह धातु जैसे, टंगस्टन एवं उनके औद्योगिक खनिज सम्मिलित हैं। लघु खनिज विशेषतः सजावटी पत्थर जैसे, मार्बल, कोटा स्टोन, सैड स्टोन आदि के क्षेत्र में राजस्थान का विशेष स्थान है। खनिजों की दृष्टि में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है।

राजस्थान में विभिन्न खनिजों के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से प्रथम स्थान वाले जिले 1993-94		
A धात्विक खनिज		
तांबा		झुपारू
लोहा		झुपारू
जस्ता एवं सीसा		भीलवाड़ा
B अधात्विक खनिज		
ऐस्बेस्टोस		उदयपुर
कैल्साइट		सिरागा
फैल्सज		अजमेर
विषम		सगानगर
धुना पत्थर		विताइवाड़ा
अभ्रक		भीलवाड़ा
गंध राखेट		उदयपुर

स्रोत - Statistical Abstract Raj 1994

राजस्थान के प्रमुख खनिजों का वर्णन निम्नवत है

लोहा (Iron)

ऐतिहासिक खोज व प्राचीन खण्डों से यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीनकाल में भी राज्य में लोहे का विदोहन किया जाता था। वर्तमान में यहाँ लोहे का बहुत कम विदोहन किया जाता है यहाँ के लोहे की किस्म भी निम्न है। राज्य में लोहा सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

अ उपयोगिता अथवा महत्व (Utility or Importance) - खनिज लोहा कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार का प्रमुख आधार है वह अनेक दृष्टि से उपयोगी है (i) औद्योगिक क्षेत्र इस्पात व मशीनों का निर्माण, (ii) कृषि क्षेत्र - ट्रैक्टर, हल बैलगाड़ी एवं अन्य मशीनें तथा कृषि उपकरण, (iii) परिवहन क्षेत्र रेल जहाज व हवाई जहाज आदि, (iv) संचार टेलिफोन व वायरलेस आदि, (v) अन्तर्गति विज्ञान रॉकेट व राडार आदि, (vi) विद्युत

ट्रांसमिशन व जेट, (vii) सामरिक दृष्टि से तोप, टैंक मशीनगन आदि, (viii) विशाल वायु के निर्माण में उपयोग, (ix) कम्प्यूटर व नवीन खोजों में उपयोग, (x) दैनिक उपयोग के अनेक वस्तुओं का निर्माण।

(ब) लोहा-उत्पादन क्षेत्र (Production Areas)

(i) मेरीजा-बागेरा क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान में खनिज लोहा उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह जौभू-सामोद रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहां की खानों से प्रायः हेमेटाइट किस्म के लोहे का विदोहन किया जाता है। यहां की खानों में प्रायः उच्च किस्म का लोहा पाया जाता है। इस क्षेत्र के लोहे की शुद्धता 65 प्रतिशत तक है। इस क्षेत्र में लगभग 25 लाख टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है। (ii) नीमला क्षेत्र - इस क्षेत्र में उच्च किस्म का लोहा पाया जाता है। यह क्षेत्र जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहां के लोहे में 72 प्रतिशत शुद्धता होती है इस क्षेत्र में लगभग 105 लाख टन खनिज लोहे के भण्डारों का अनुमान है। (iii) डाबला क्षेत्र - यह क्षेत्र खेतड़ी के पूर्व में भावडा रेलवे स्टेशन से लगभग 1015 किलोमीटर दूर है इस क्षेत्र हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है इस क्षेत्र में लगभग 7 लाख टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है। (iv) नाथवा पोल क्षेत्र यह स्थान उदयपुर से लगभग 81 किलोमीटर दूर है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। इस लोहे में 52 प्रतिशत शुद्धता होती है। इस क्षेत्र में 110 करोड़ टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 20 लाख टन के भण्डार उत्तम किस्म के हैं। (v) अन्य क्षेत्र राजस्थान के झालावाड़, दुन्दी, बासवाडा, भीमवाडा आदि जिलों में भी लोहा पाया जाता है।

(स) उत्पादन (Production) राजस्थान में घटिया किस्म का लोहा मिलता है। परिवहन के साधनों का अभाव है और राजस्थान में लोहा-इस्पात के कारखाने भी नहीं हैं। अतः लोहे का उत्पादन बहुत कम होता है। 1984 में लोहे का कुल उत्पादन 128 हजार टन था जो 1988 में 35 हजार टन हो गया। उत्पादन का सर्वाधिक भाग जयपुर जिले से प्राप्त होता है। 1991 में कच्चे लोहे का उत्पादन 272 हजार टन था जो 1995-96 में बढ़कर 5903 हजार टन हो गया।¹

तांबा (Copper)

तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। जौधरी योजना में खेतड़ी जमक म्याप पर तांबा साफ करने का एक कारखाना स्थापित किया

गया। राज्य में 1311 करोड़ टन तांबे के भण्डार होने का अनुमान है। तांबे से सम्बंधित तथ्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(अ) उपयोगिता अथवा महत्व (Utility or Importance)

- इस्तर युग के पश्चात मानव ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का ही प्रयोग किया। तांबे के अनेक उपयोग हैं जैसे (i) तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर कुछ नवीन धातुएँ बनाई जाती हैं, उदाहरण के लिये, तांबा+जस्ता = पीतल, तांबा+मौना रोल्ट = गैल्ड, तांबा+तांग = वासा आदि। (ii) विद्युत तारों, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन बिजली के बल्बों, परिवहन इजनों, घड़ियों, सिक्कों (Coins), रासायनिक उद्योगों व वर्तन आदि में तांबे का उपयोग किया जाता है। 40 प्रतिशत तांबे का उपयोग विद्युत उपकरणों में, 45 प्रतिशत तांबे का उपयोग अन्य धातुओं का निर्माण करने में और शेष 15 प्रतिशत तांबे का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है।

(ब) तांबा उत्पादन क्षेत्र (Production Areas)

- खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र इस क्षेत्र में राज्य का सबसे अधिक तांबा मिलता है। इस क्षेत्र में आकशाली, कालिहान, माधव कूदन तथा सतकुई धरोहरों में तांबे की खानें हैं इन खानों में तांबे के भण्डारों व उनकी शुद्धता सम्बन्धी अनुमान निम्नवत हैं

क्षेत्र	खनिज तांबे के भण्डार	शुद्धता
माधव कूदन	3 करोड़ टन	8% व 1%
सतकुई धरोहर	9 टन	8% व 1%
आकशाली	10 लाख टन	1%
कालिहान	8 करोड़ टन	2.5%

(ii) अलवर क्षेत्र इस क्षेत्र में विशेष रूप से भगोली व दरिया क्षेत्र का खनिज तांबे का विदोहन किया जाता है। दरिया क्षेत्र में उत्तम किस्म का तांबा मिलता है जिसमें शुद्धता प्रायः 25% होती है। यहां तांबे के 50 लाख टन भण्डारों का अनुमान है। भगोली क्षेत्र में तांबे के 20 लाख टन भण्डार हैं और इसमें शुद्धता का अंश लगभग 1 से 8% तक है। (iii) भीलवाडा क्षेत्र भीलवाडा में लगभग 95 किलोमीटर दूरी पर पुरंदरिया क्षेत्र में 3 किलोमीटर लम्बी व 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से तांबे का विदोहन किया जाता है। इस क्षेत्र में तांबे के लगभग 20 लाख टन भण्डार हैं। (iv) अन्य क्षेत्र राजस्थान में देतवाडा-देबागे (उदयपुर), सेनपुरी (अलवर), दोधारा (झुंझार), झालवाड़, सतपुर, झुंझार, भीम (उदयपुर) आदि स्थानों पर तांबे का विदोहन किया जाता है।

(स) उत्पादन (Production)

- राज्य में खनिज तांबे के

¹ State and Abstract, Rajasthan, 1996
Statistical Abstract, Rajasthan, 1993
Statistical Abstract, Rajasthan, 1988

उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है निम्नांकित तालिका में खनिज ताबे के उत्पादन को दर्शाया गया है।

राजस्थान में खनिज ताबे का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	1502 00
1988	1790 30
1991	1730 80
1993-94	1686 90
1995-96	1577 80

स्रोत: Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

राजस्थान के कच्चे ताबे का सर्वाधिक भाग झुझरू जिले से प्राप्त हो रहा है।

मैंगनीज (Manganese)

मैंगनीज सामरिक एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज है। फलतः इसकी मांग निरन्तर बढ़ रही है। राजस्थान में मैंगनीज का अध्ययन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उपयोगिता अथवा महत्त्व (Utility or Importance) (i) मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः खनिज लोहे से इस्पात की निर्माण में किया जाता है। एक टन इस्पात का निर्माण करने के लिये लगभग 11 किलो मैंगनीज की आवश्यकता पड़ती है। मैंगनीज से बनाये गये इस्पात का उपयोग मुख्यतः मशीनों, रेल पटरियों व भड़क कूटने के हज्जों आदि के निर्माण में किया जाता है। (ii) इसका प्रयोग शुष्क बैटरी रंग रोगन, कोटाणु-नाशक औषधियों चीनी मिट्टी के बर्तन तथा मैंगनीज साल्ट के निर्माण आदि में किया जाता है।

(ब) मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) राज्य के बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है। उदयपुर व जयपुर जिलों में भी कुछ मैंगनीज निकाला जाता है। राजस्थान का मैंगनीज प्रायः घटिया किस्म का होता है।

(स) उत्पादन (Production) राजस्थान में 1989 में 0.3 हजार टन मैंगनीज का उत्पादन होता था जो 1991 में 0.17 हजार टन और 1992-94 में 0.20 हजार टन हो गया।

सीसा व जस्ता (Lead & Zinc)

सीसा व जस्ता मिश्रित रूप में मिलता है। इनके उत्पादन में राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। इसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उपयोगिता अथवा महत्त्व (Utility or Importance) इन धातुओं का उपयोग मुख्यतः सिगरेटों के ढक्कन में, मर्करी बर्फ बन्दूक की गांठियों तथा साइक्लि के पम्पर जाइने के मोल्यूशन का ट्यूब आदि वस्तुओं के निर्माण

में किया जाता है।

(ब) उत्पादन क्षेत्र (Production Areas)

(i) राजपुरा-देवारी इस क्षेत्र से प्राप्त खनिज में 5.5% जस्ता व 2.2% सीसा पाया जाता है। यहाँ के खनिज में सीसे व जस्ते के अलावा तांबा, चाँदी व एण्टीमनी आदि वस्तुएँ भी पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में खनिज के 1.26 करोड़ टन भण्डार होने का अनुमान है। (ii) जावर क्षेत्र यह क्षेत्र जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ लगभग 20 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में सीसा व जस्ता पाया जाता है। यहाँ के खनिज में 5 प्रतिशत सीसा व 7 प्रतिशत जस्ता होता है। (iii) सवाई माधोपुर क्षेत्र यह क्षेत्र का बरवाड़ा नामक क्षेत्र में सीसा व जस्ता पाया जाता है। यह क्षेत्र 100 मीटर लम्बा व 8 मीटर गहरा है। मोलवाड़ा जिले के आगुवा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जस्ते व सीसे के भण्डार हैं। अजमेर जिले में अजमेर शहर के पास ही इनके भण्डार मिले हैं। (iv) अन्य क्षेत्र राजस्थान में गुदा व किशोरदास (अलवर), लोहाखान सागर (अजमेर), बडालिडा (बांसवाड़ा) तथा सिरोही जिले में सीसा व जस्ता पाया जाता है।

(स) उत्पादन (Production) राजस्थान में सीसे व जस्ते के पर्याप्त भण्डार हैं अतः इनके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है।

राजस्थान में सीसा व जस्ता का उत्पादन (हजार टनों में)		
वर्ष	सीसा	जस्ता
1985	25.8	88.8
1988	29.8	117.2
1991	29.0	111.8
1992-93	32.0	98.2
1993-94	42.9	289.4
1995-96	45.6	276.8

Source: Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

सीसे व जस्ते का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र उदयपुर जिला है।

अभ्रक (Mica)

राजस्थान का अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। भारतीय ग्रन्थों में इस खनिज का उल्लेख 'अभ्र' नाम से मिलता है। प्राचीनकाल में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था। वर्तमान में भी अभ्रक भस्म नामक चूर्ण आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक प्रायः राफेड गुलाबी, काले व हरे रंगों में उपलब्ध होता है। यह गाढ़दर्शी, लज्जित, चिकना, ताप- अवरोधन एवं विद्युत कुचालक पदार्थ है। जल, अम्ल व तेजाब का

इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है और यह 500° से घरे ताप को भी आसानी से सहन कर सकता है। राजस्थान में अभ्रक सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन इन विन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उपयोगिता या महत्व (Utility or Importance) अभ्रक का प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक निर्माण, विद्युत संचालन, रेडियो विज्ञान, विद्युत भट्टियाँ, डायनेमो, तार व टेलीफोन, वायरलेस, वायुयान, कम्प्यूटर्स, परिवहन, मकान की छतों, चश्मों, मजबूत का सामान व रंग रोपन आदि में किया जाता है।

(ब) उत्पादक क्षेत्र (Production Area) राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर जयपुर, टोंक, सीकर, ब्यावर आदि जिलों में अभ्रक पाया जाता है, राज्य में जयपुर से उदयपुर तक के 320 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में अभ्रक मिलता है।

(स) उत्पादन (Production) राज्य में अभ्रक का उत्पादन कम होना जा रहा है। 1984 में अभ्रक का उत्पादन 0.8 हजार टन रह गया। 1988 में अभ्रक का उत्पादन 0.9 हजार टन हुआ था जिसमें भीलवाड़ा जिले का भाग 98.74% था। 1991 में अभ्रक का उत्पादन 0.55 हजार टन 1993-94 में 0.085 हजार टन व 1995-96 में 67.84 हजार टन था।

रॉक फॉस्फेट (Rock Phosphate)

यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। राज्य में रॉकफॉस्फेट सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन निम्नांकित विन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) राजस्थान में यह खनिज मुख्यतः बांसवाड़ा, जैमलमेर व उदयपुर जिलों में पाया जाता है। उदयपुर जिले में माटोन, कानपुर, डाकनकिश, सोसारमा नीमव, माटा बारागाव तथा झामर-कोटड़ा आदि स्थानों पर अभ्रक के भण्डार हैं। जैमलमेर जिले के विरमानिया व लाठी नामक स्थानों पर भी रॉक फॉस्फेट के भण्डार हैं। सीकर जिले में कपुड़ा नामक स्थान पर रॉकफॉस्फेट के भण्डार हैं।

(ब) उत्पादन (Production) निम्नांकित तालिका में राजस्थान के रॉकफॉस्फेट उत्पादन की बताया गया है।

राजस्थान में रॉकफॉस्फेट का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	718.90
1986	451.5
1988	459.4
1991	265.0
1993-94	977.98
1995-96	900.87

Source: Statistical Abstract, Raj. 1988-1993, 1994 & 1996

एस्बेस्टोज (Asbestos)

यह खनिज औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह एक रेशेदार धातु होती है जिसका निर्माण कैल्शियम मैग्नीशियम से होता है। राजस्थान में एम्फिबोलिक किण्वक का एस्बेस्टोज पाया जाता है जो घटिया श्रेणी का होता है। यह अधुनशील व ताप अवरोधक होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः सीमेंट की चादरे, सीमेंट पाइप, फिल्टर्स, गॉगलर्स, टाईले व अन्य ताप-निरोधक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। एम्बेस्टोज सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न हैं।

(अ) उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) (i) उदयपुर जिले के झणगदेव, खेरवाड़ा, नाथद्वारा, आसीन्द, कास्थल, सलुम्बर, डेकलिया व गुजान आदि स्थानों पर एस्बेस्टोज की खानें हैं। (ii) डूंगरपुर जिले के पोरपदा, देवल मलवा खेमाळ, जवेल, डूंगरगारभ आदि स्थानों पर भी यह खनिज पाया जाता है। (iii) अजमेर, जोधपुर व पाली जिलों में भी यह खनिज कुछ मात्रा में पाया जाता है।

(ब) उत्पादन (Production) स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में एस्बेस्टोज का उत्पादन में तीव्र गति में वृद्धि हुई है। भारत में सबसे अधिक एस्बेस्टोज राजस्थान में ही पाया जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% भाग राजस्थान में होता है। 1985 में एस्बेस्टोज का कुल उत्पादन 28.0 हजार टन था जो बढ़कर 1988 में 30.1 हजार टन हो गया। 1988 में कुल उत्पादन का 79% उदयपुर जिला 8.69% अजमेर जिला व 7.92% पाली उत्पादित कर रहा था। 1991 में उत्पादन बढ़कर 26.5 हजार टन व 1993-94 में 34.2 हजार टन तथा 1995-96 में 20.69 हजार हो गया।

जिप्सम (Gypsum)

इसे सनखड़ी ह्यूस्केट व खडिया भी कहा जाता है। यह एक औद्योगिक महत्व का खनिज है। भारत के कुल जिप्सम भण्डारों का लगभग 94% भाग राजस्थान में उपलब्ध है। इससे बनी मिट्टी के बर्तन, उर्वरक, चॉक स्टिक, रा रोपन आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में जिप्सम सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं।

(अ) उत्पादन के क्षेत्र (Production Areas)

(i) नागौर क्षेत्र भारत में सबसे अधिक जिप्सम इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ जिप्सम के लगभग 95.3 करोड़ टन के भण्डार उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में नागौर मण्डाना, मायलोड, यादवामी, खैरत व मालगू आदि स्थानों पर जिप्सम की खानें हैं। (ii) बीकानेर क्षेत्र इस क्षेत्र का जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से संयोजन में द्वितीय स्थान है। यह मुख्यतः जामसर, लूकरणगर, रामानगर आदि क्षेत्रों में जिप्सम की

खाने है। इस क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ टन जिप्सम का भण्डार होने का अनुमान है। (iii) अन्य क्षेत्र राज्य के पाली, जोधपुर, जैसलमेर व जडमेर आदि जिलों में भी जिप्सम की खानें हैं।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में जिप्सम के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	1132.2
1988	1313.0
1991	1618.9
1993-94	1626.78
1995-96	2042.09

स्रोत: Sahasrabhaskar Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

1988 में राजस्थान के जिप्सम का उत्पादन 69.79% गगानगर जिला 11.34% नागौर जिला व 11.29% जडमेर जिला उत्पादित कर रहा था।

घोंघा पत्थर (Soap Stone)

इस खनिज के उत्पादन में राजस्थान को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। यहां भारत के कुल उत्पादन का लगभग 9% घोंघा पत्थर निकाला जाता है। इससे पेन्सिल, टेल्कम पाउडर, खिलौने, विद्युत उपकरण, कागज, टाइली आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कौटुम्बिक औषधियां व रबड़ में निर्मित वस्तुओं में भी इसका उपयोग होता है।

राज्य में घोंघा पत्थर के उत्पादन से सम्बन्धित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production Areas) राजस्थान के उदयपुर, भालवाड़ा, डूंगरपुर, बरवाँधीपुर आदि जिला में घोंघा पत्थर की खानें हैं। उत्तम किस्म का घोंघा पत्थर भालवाड़ा जिले के वेवरिया, दिगाड़ा, धारवा, चादपुरा तथा उदयपुर जिले के भूगावन, दवली, देवपुरी आदि स्थानों में मिलता है। भालवाड़ा उदयपुर अलावर डूंगरपुर आदि जिला में घोंघा पत्थर का पौन्य की अनेक इकाइयां कार्यरत हैं लेकिन राज्य में इसका महीन वृण यंत्रों का कोई भी मयत्र नहीं है। राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 40% उदयपुर जिले से प्राप्त होता है। घोंघा पत्थर को टैल्क माफ स्टाइन तथा मिट्टास्टोन भी कहा जाता है।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य में घोंघा पत्थर के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है कुछ वर्षों के घोंघा

पत्थर के उत्पादन को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है -

राजस्थान में घोंघा पत्थर का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	386.30
1988	336.20
1991	395.60
1993-94	385.28
1995-96	794.72

स्रोत: Sahasrabhaskar Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

चूने का पत्थर (Lime Stone)

राजस्थान में चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह सीमेंट बनाने योग्य और रासायनिक पदार्थ व अन्य वस्तुओं का निर्माण करने योग्य पत्थर के भण्डार क्रमशः 300 करोड़ टन व 5 करोड़ टन हैं। राजस्थान में चूने के पत्थर सम्बन्धी विवरण निम्नवत हैं

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) राजस्थान के कोटा, जयपुर, बून्दी, सीकर, सर्वाईभाधोपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, बागवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि जिलों में चूने का पत्थर पाया जाता है। इस पत्थर का उपयोग मुख्यतः राज्य के सीमेंट कारखानों द्वारा किया जाता है। यह पत्थर भवन निर्माण उद्योग का प्रमुख आधार है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में चूने के पत्थर का पर्याप्त उत्पादन होता है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन का निम्न तालिका में दर्शाया गया है

राजस्थान में चूने के पत्थर का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टन में)
1985	4259.70
1988	6527.30
1991	7879.50
1993-94	7906.40
1995-96	11898.94

स्रोत: Sahasrabhaskar Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

1988 में चूना पत्थर के कुल उत्पादन का 43.20% चित्तौड़गढ़ जिला 13.50% अजमेर जिला 10.73% सिरोही जिला, 9.13% उदयपुर जिला, 8.87% कोटा जिला व 4.67% बून्दी जिला उत्पादित कर रहा था।

संगमरमर (Marble)

यह बहुमूल्य पत्थर है जिसका उपयोग मुख्यतः भवन व मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। संगमरमर के उत्पादन में राज्य को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। यहां का संगमरमर सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। संगमरमर के उत्पादन

सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) नागौर क्षेत्र इस क्षेत्र में मकरना नामक स्थान समरमर के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ उत्तम किस्म का गुलाबी सफेद व काले रंगों का समरमर पाया जाता है। यहाँ लगभग 20 किलोमीटर लम्बी पट्टी में समरमर के भण्डार हैं। भक्ताना व विशनगढ़ में समरमर की बारीक पट्टियाँ तैयार करने के अनेक कारखाने हैं। (ii) अन्य क्षेत्र राज्य के पाली, सोकर, जयपुर अजमेर, उदयपुर अलवर आदि जिलों में भी समरमर पाया जाता है लेकिन यह निम्न श्रेणी का होता है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में देश का सबसे अधिक समरमर उत्पन्न होता है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है

राजस्थान में समरमर (ब्लॉक) का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टन में)
1988	704.7
1991	1740.1
1993-94	1875.6
1995-96	2840.1

स्रोत: Statistical Abstract Raj 1988, 1993, 1994 & 1996

टंगस्टन (Tungston)

यह सामरिक महत्व का एक खनिज है जो मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 75% भाग राजस्थान से मिलता है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों व सुरक्षा सामग्री के निर्माण में किया जाता है। इससे कड़ी से कड़ी वस्तु को काटा जा सकता है। राज्य में टंगस्टन के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत-

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) राज्य में नागौर जिले के डैगाना नामक स्थान पर टंगस्टन की खानें हैं। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे किया गया है। यहाँ टंगस्टन के पर्याप्त भण्डारों का अनुमान है। टंगस्टन विकास निगम इन खानों के विकास हेतु अनेक कार्य कर रहा है। जयपुर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यहाँ टंगस्टन का विदोहन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में किया जाता है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में 1974 में टंगस्टन का उत्पादन 17000 किलोग्राम था जो बढ़कर 1988 में 24018 किलोग्राम हो गया। 1993-94 में 5.45 हजार टन टंगस्टन का उत्पादन हुआ। 1988 का समस्त उत्पादन नागौर जिले से प्राप्त हो रहा था। 1991

92 में सिरोही जिले में 1.7 हजार टन व 1995-96 में नागौर जिले से 6.45 हजार टन टंगस्टन का उत्पादन हुआ।

फ्लोराइट (Fluorite)

यह औद्योगिक महत्व का एक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः लौहा व इस्पात तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। भारत में फ्लोराइट का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है। यहाँ फ्लोराइट के पर्याप्त भण्डार का अनुमान है। राज्य में फ्लोराइट उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) यह खनिज राज्य के झुगपुर जिले में माण्डव की पान नामक पर्वत-श्रृंखलाओं में पाया जाता है। इस क्षेत्र की खान से फ्लोराइट का उत्पादन 1959 से हो रहा है। यहाँ लगभग 150 लाख टन फ्लोराइट के भण्डार हैं। ये खानें 24 किलोमीटर क्षेत्र में फैती हुई हैं। राज्य के अनेक क्षेत्रों में भी फ्लोराइट की खोज का कार्य जारी है।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य में फ्लोराइट का पर्याप्त उत्पादन होता है लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण फ्लोराइट के उत्पादन में कमी होती गई। अतः 1975 में फ्लोराइट की खानों का आधुनिकरण किया गया। राज्य के फ्लोराइट उत्पादन को अग्र तालिका में बताया गया है

राजस्थान में फ्लोराइट का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	3.8
1988	6.8
1991	3.7
1993-94	2.4
1995-96	1.69

स्रोत: Statistical Abstract, Raj. 1988, 1993, 1994 & 1996

वर्ष 1995-96 में उत्पादन का लगभग 14% भाग झुगपुर जिले व 49.1% भाग बालोर जिले से प्राप्त हो रहा था।

बेरिलियम (Beryllium)

यह एक अणु खनिज है जिसका निर्माण बेरिल धातु से किया जाता है। बेरिल धातु परमाण्वीय आवृत्ति में पाई जाती है और अनेक रंगों की होती है। बेरिल मुख्यतः राजस्थान व बिहार में ही पाई जाती है। राजस्थान में 11% तक शुद्धता बेरिल पाई जाती है। राज्य में बेरिलियम के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न हैं

1 Statistical Abstract, Raj. 1996

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) उदयपुर इस जिले के सिलेका गुदा, शिकारवाडी, रामआमेत आदि स्थानों पर बेरील की खाने है। (ii) भीलवाड़ा इस क्षेत्र में देवडा, तिलोली गुदा, मेजा, एकलिंगपुरा व शिवराती आदि स्थानों में बेरील की खाने है। (iii) अन्य डूंगरपुर जिले में पदेरी, सीकर जिले के बूकरा, चुरला, सावलपुरा व टोरेडा ताकि टोंक जिले के धोली, सकरवाडा व माथेराजपुरा में भी बेरील की खाने है।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य के मपूर्ण बेरील उत्पाद को अणु शक्ति आयोग को बेच दिया जाता है। राज्य में लगभग 5-7 टन बेरील का वार्षिक उत्पादन होता है।

बेराइटज (Barytes)

यह औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण खनिज है। इससे नाइट्रोजन, रासायनिक पदार्थ, पेंट बेरियम कारबोनेट, क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में बेराइटज के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में बेराइटज का खाने है उदयपुर जिले के जगतपुर नामक स्थान के पास बेराइटज के भण्डार मिले हैं जो अब तक खोजे गये भण्डारों में सबसे बड़े हैं।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में बेराइटज के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान में बेराइटज का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	11 00
1988	8 20
1991	6 10
1993-94	2 48
1995-96	3 25

स्रोत : Statistical Abstract, Ra. 1988 1991 1994 & 1996

1996 में कुल उत्पादन का लगभग 80% उदयपुर जिले एवं 20 25% अलवर जिले में उत्पादित किया जा रहा था।

कैल्साइट (Calcite)

यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग मुख्यतः कैल्साइट काच, बैलिशम कारवाइड, मिर्मिक का सामान, बरेचिंग फाउंडर कार्बन डाई ऑक्साइड, सिम्पेट

पदार्थ आदि वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। राज्य में कैल्साइट के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है -

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) सीकर जिला इस जिले के माडवा, रायपुर, बालपुरा झामस आदि स्थानों पर कैल्साइट की खाने है, (ii) सिराही जिला यह के सिआबा, सजपुरा, पिपटसाल, पिडवासी व जनकिया आदि स्थानों पर कैल्साइट पाया जाता है। (iii) पाली जिला इस जिले के बेरी, जनवेडा, दौरेरा व सिरामावरी में कैल्साइट की खाने है। (iv) झुझुनू जिला इस जिले के पापराना व माथेगढ नामक स्थानों पर कैल्साइट पाया जाता है। (v) जयपुर जिला इस जिले में बरना की चौकी, शाखून व तासकोला नामक स्थानों पर कैल्साइट की खाने है।

(ब) उत्पादन (Production) देश के कैल्साइट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राज्य का सबसे अधिक उत्पादन (लगभग 70%) सीकर जिले में होता है। कैल्साइट के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान में कैल्साइट का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	18 5
1988	25 6
1991	89 01
1993-94	75 73
1995 96	75 89

स्रोत : Statistical Abstract, Ra. 1988 1991 1994 & 1996

एमरॉल्ड अथवा पन्ना (Emerald)

यह एक बहुमूल्य जवाहरात है जिसके उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। यह एक हरे रंग का रत्न है। अतः इसे हरी अग्नि की सजा दी जाती है। इसका उपयोग गहनों के निर्माण में किया जाता है। राज्य में पन्ना उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) यह खनिज राज्य के उदयपुर व अजमेर जिलों में पाया जाता है। उदयपुर जिले में पन्ना के सर्वाधिक भण्डार हैं। इस जिले में पन्ना के तीन क्षेत्र हैं कालगुमान क्षेत्र यह यखाने कालगुमान नामक स्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टिछी क्षेत्र ये खाने देवगढ म्थेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर टिछी नामक स्थान के पास स्थित है। गोमुन्दा क्षेत्र - यह क्षेत्र नायद्वारा म्थेशन से लगभग 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

(ब) उत्पादन (Production) - वर्तमान में पन्ना का उत्पादन शायद बन्द है 1973 व 1980 में पन्ना का उत्पादन क्रमशः 0.7 व 2.9 हजार टन था। 1995-96 में 3.81 कि.ग्रा पन्ना का उत्पादन हुआ।

फेल्सपार (Felspar)

यह एक औद्योगिक महत्व का खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग मुख्यतः कँच, मीनाकारी व चीनी मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। राजस्थान देश के कुल फेल्सपार उत्पादन का लगभग 60% भाग उत्पन्न करता है। इसका उपयोग मुख्यतः पड़ोसी राज्यों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में फेल्सपार के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न है।

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : (i) अजमेर जिला इस जिले में राज्य के लगभग 95 प्रतिशत फेल्सपार का उत्पादन होता है। अजमेर व ब्यावर में इसे पीसने के अनेक सयंत्र हैं। (ii) जयपुर जिला इस जिले में दादिया, हूगरपुर, गुजरावाडा व बन्दरबनरी में फेल्सपार की खानें हैं। (iii) पाली जिला इस जिले के बाडा, डिगौर, चाकण्डिया, प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर फेल्सपार की छोटी खानें हैं। (iv) अन्य राज्य के सीकर, टोंक पासवाडा, उदयपुर आदि जिलों में भी फेल्सपार की खानें हैं।

(ब) उत्पादन (Production) - राज्य में फेल्सपार का पर्याप्त उत्पादन होता है। विगत कुछ वर्षों के फेल्सपार उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है।

राजस्थान में फेल्सपार का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों)
1985	42.70
1988	33.90
1991	72.50
1993-94	86.55
1995-96	71.06

स्रोत : Statistical Abstract, Raj. 1993 & 1996

1988 में फेल्सपार के कुल उत्पादन में अजमेर जिले का भाग 64.83% व भीलवाडा जिले का भाग 17.33% था।

काच बालुका अथवा सिलिका रेत (Silica Sand)

यह खन-उद्योग का कच्चा माल है। यह पर्याप्त मात्रा में काच बालुका प्राप्त होती है। काच बालुका के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है। राज्य में काच बालुका के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं।

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : (i) बूंदी जिला इस जिले के बागेदिया नामक स्थान पर काच बालुका प्राप्त होती है। (ii) जयपुर जिला यह के सागोट, कुण्डला, चित्तौड़ी, झर, बासखों, बर्याल, मनोला तथा घुलाधोपुर आदि स्थानों पर काच बालुका प्राप्त होती है। (iii) सर्वाईमाधोपुर जिला इस जिले के नागधूपपुर, ऐलानपुर, साधोरा, टट्टावा, नोली आदि स्थानों पर काच बालुका मिलती है। (iv) भरतपुर, बीकानेर व कोटा जिलों में भी काच बालुका मिलती है।

(ब) उत्पादन (Production) - राज्य के कोटा, बूंदी व जयपुर जिलों में काच बालुका के विशाल भण्डार हैं। कोटा जिले में श्रेष्ठ किस्म की काच बालुका प्राप्त होती है। राज्य के भीलपुर के काच कारखाने में इसका उपयोग किया जाता है तथा शेष बालुका अन्य राज्यों को भेज दी जाती है। 1985 व 1988 में काच बालुका का उत्पादन क्रमशः 215.7 व 172.0 हजार टन था। 1993-94 में सिलिकासैंड का उत्पादन 215.23 हजार टन तथा 1995-96 में 234.75 हजार टन था। अधिकांश उत्पादन अलवर, बूंदी, सर्वाई माधोपुर, जैसलमेर, टोंक तथा बाडमेर जिलों में प्राप्त होता है।

चीनी मिट्टी (China Clay)

यह अन्य सभी मिट्टियों से मूल्यवान होती है। यह शायद सफेद व पीले रंग की होती है। इसका उपयोग सिरेमिक सिलिकेट उद्योग द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग करने के पूर्व इसकी धुलाई की जाती है। राज्य के नीम का थाना नामक स्थान पर चीनी मिट्टी की धुलाई का एक कारखाना है इसने उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं।

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : सर्वाई माधोपुर जिला इस जिले के रायसीना व दसुव नामक स्थानों पर चीनी मिट्टी पाई जाती है। सीकर जिला यह के पुरणोतमपुर, म्हावाडा, टोरडा, बुधरा आदि स्थानों पर चीनी मिट्टी पाई जाती है। अन्य जालौर, अलवर तथा उदयपुर जिलों में भी चीनी मिट्टी के पर्याप्त भण्डार हैं।

(ब) उत्पादन (Production) - राजस्थान में चीनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 1990 1993-94 व 1995-96 में इसका उत्पादन क्रमशः 248.9, 334.1 व 433.0 हजार टन था।

अन्य खनिज (Other Minerals)

(i) डोलोमाइट (Dolomite) : इस खनिज का उपयोग मुख्यतः मकन निर्माण, कृषि कार्यो कागज निर्माण की सल्फाइट विधि में तथा अम्लीय द्रव बनाने में किया जाता है।

यह राज्य के सीकर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर तथा अलवर जिलों में पाया जाता है। जयपुर जिले में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 1985 व 1988 में इसका उत्पादन क्रमशः 8.5 व 2.3 हजार टन था। 1988 में उत्पादन का 46.07% जैसलमेर जिले व 44.6% सीकर जिले से प्राप्त हो रहा था। 1993-94 में इसका उत्पादन 7.3 हजार टन तथा 1995-96 में 17000 टन था।²

(ii) तामड़ा (Tamura) - इस खनिज के उत्पादन में राजस्थान को एकधिकार प्राप्त है। यह का तामड़ा (खजमहल व सरवाड) विश्व में प्रसिद्ध है। राज्य के अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा व सीकर जिलों में तामड़ा की खानें हैं। अजमेर जिले के सरवाड व टोंक जिले के खजमहल नामक स्थानों पर ग्रेन्थ किस्म का तामड़ा पाया जाता है। 1982 में तामड़ा का उत्पादन 780 टन तथा 1995-96 में 1700 टन था।³

(iii) बेन्टोनाइट (Bentonite) यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने तथा वनस्पति तेलों व खनिज तेल को साफ करने में किया जाता है। यह राज्य के बाड़मेर, बीकानेर तथा सवाईमाधोपुर जिलों में पाया जाता है। बाड़मेर जिले में बेन्टोनाइट के सर्वाधिक भण्डार हैं। 1986, 1988, 1993-94 व 1995-96 में इसका उत्पादन क्रमशः 36.8, 76.8, 31.8 व 54.5 हजार टन था।

(iv) मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी के विशाल भण्डार हैं। यह मुख्यतः बीकानेर व बाड़मेर जिले में पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः वनस्पति व खनिज तेलों को साफ करने तथा कागज, साबुन व प्रसाधन सामग्री बनाने में किया जाता है। 1991 में 12.7 तथा 1995-96 में 14.88 हजार टन उत्पादन हुआ।

(v) स्लेट पत्थर (Slate Stone) इस पत्थर का उपयोग मुख्यतः स्लेट बनाने में किया जाता है। यह राजस्थान के अलवर में बहरोड रासलाना, गीगलाना खुण्डरोड, भादणा तथा भोयसर आदि स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान स्लेट पत्थर विदेशों को निर्यात भी करता है। यह मुख्यतः हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी को भेजा जाता है। अतः यह खनिज विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में खनिज विकास की वर्तमान स्थिति एवं भावी सम्भावनाएँ

(PRESENT SITUATION AND FUTURE PROSPECTS OF MINERAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)

देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की सरकारी नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने देश की खनिज सम्पदा को खोज निकालने का कार्य है।

सरकारी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी सौंपने का निर्णय नई राष्ट्रीय खनिज नीति में लिया है। सरकार ने यह अनुभव किया है कि देश में कई खनिजों का पर्याप्त दोहन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए विदेशी तकनीक का अपनाया जाना आवश्यक है। सोना, हीरा, तांबा, जस्ता, निकल, टंगस्टन और रासायनिक खाद बनाने के काम आने वाले रॉक फॉस्फेट, पोटाश तथा सल्फर उन 13 खनिजों में से हैं जो गैर सरकारी उद्यमियों के लिए खोल दिये गये हैं। इस नीति में सामरिक महत्त्व के खनिजों के विकास पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव भी है। राजस्थान विभिन्न खनिज स्रोतों से भरपूर प्रदेश है और इन खनिज भण्डारों के लिए इसे देश में महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। यही कारण है कि राजस्थान को खनिजों का सचहालय भी कहा जाता है। राजस्थान में 42 प्रकार के प्रधान खनिजों का एवं 23 प्रकार के अप्रधान खनिजों का उत्पादन होता है।⁴ 1950 में केवल 15 प्रकार के प्रधान एवं 6 प्रकार के सघु खनिजों का ही विदोहन किया जाता था। देश के कुल सघु खनिज के उत्पादन मूल्य में राजस्थान का लगभग 30 प्रतिशत योगदान है। राजस्थान की अरावली पर्वत-शृंखला में शताब्दियों पुराने खनिज खनन के अवशेष विद्यमान हैं जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि इस प्रदेश में खनिजों के खनन का अति प्राचीन इतिहास है। विद्यमान खनिज सम्पदा में कुछ खनिजों के उत्पादन में तो राजस्थान का एकधिकार है जैसे, गार्नेट जेस्टार व बोलस्टोनाइट। इससे अतिरिक्त भी अन्य अनेक खनिजों में राजस्थान का प्रथम या द्वितीय स्थान है। इतनी विशाल खनिज सम्पदा होने के बावजूद भी इसका समुचित दोहन व उत्खनन नहीं हो पाया है। यह भी एक विरोधाभास प्रतीत होता है कि बिहार और राजस्थान जैसे खनिज सम्पदा में समृद्ध राज्य निर्धन व पिछड़े हुए हैं।

राजस्थान में 1950 में मुख्यतः अभ्रक, पीया पत्थर, बेराइट्स, कैलासाइट, एमराल्ड, सिलिका मैन्ड, फ्लुऑर, बेन्टोनाइट जिप्सम आदि खनिजों का कार्य किया गया। इस शताब्दी के मध्य से ही बीकानेर जिले के गीगलाना क्षेत्र पलाना में लिम्बाइट पर कार्य आरम्भ हो चुका था। डेगाना (नागौर जिला) के बोलासोमाइट भण्डारों से टंगस्टन अयस्क के दोहन का सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रश्नर जावर (उदयपुर) स्थित जम्मा शीशा क्रिस्टलों के दोहन से जुटे मैटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा पुनः कार्य आरम्भ किया गया। छोटड़ी के तांबा भण्डारों का सर्वेक्षण कार्य भी निजी फर्म द्वारा प्रारम्भ करवाया गया। वास्तव में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान व खनिज क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन आया है और खनिजों की खोज की

दिशा में किये जाने वाले विकास कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। राजस्थान की महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा लगभग 250 करोड़ वर्ग से भी अधिक पुरानी प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से लेकर मर्बलसेन्ट या सिसेन्ट चट्टानों में उपलब्ध है। यहाँ धात्विक व अधात्विक और रत्न श्रेणी के साथ ही इमारती और नक्काशी के पत्थरों तथा ग्रेनाइट व मार्बल आदि के विपुल खनिज भण्डार उपलब्ध हैं। धात्विक खनिजों जैसे तांबा, जस्ता, शीशा व टंगस्टन अयस्क तथा अधात्विक खनिजों जैसे, रॉक फॉस्फेट जिप्सम, सोप स्टोन, एम्बेस्मेंट फ्लस्पर, गार्नेट, बोलोस्टोनाइट आदि के उत्पादन में राजस्थान का देश में अग्रणी स्थान है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में चूना-पत्थर, वैडाल्ट्स, फ्लोराइट, चाइना क्ले फायरक्ले, बेन्टोनाइट फलसंकर्य, सिलिका सेन्ड, माइका आदि खनिजों का विस्तृत पैमाने पर खनन होता है। नागौर जिले के मेडता गेड, बाडमेर जिले के कूपरडी, बीकानेर जिले के गुडा क्षेत्रों में लिम्नाइट की खोज के साथ राजस्थान देश में तमिलनाडु के बाद लिम्नाइट भण्डारों के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान की ओर अग्रसर हो रहा है। अध्रान खनिजों में काना का मार्बल पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसके अतिरिक्त जालौर के ग्रेनाइट भण्डार तथा जोधपुर दूरी व धौलपुर के सैंडस्टोन के भण्डार भी सर्वविदित हैं। बामवाड़ा जिले में लगभग 20 लाख टन मैंगनीज अयस्क भण्डार होने का अनुमान है। बाडमेर जिले में लगभग 17 लाख टन सैलेनाइट के खनिज भण्डार का अनुमान लगाया गया है। झारपुर जिले की माण्डू की पत्त क्षेत्र में 15 लाख टन फ्लोराइट खनिज के भण्डार होने का अनुमान है। जयपुर जिले के चौमू क्षेत्र में 55 लाख टन लोह अयस्क के भण्डार सिद्ध हो चुके हैं। अजमेर जिले के मन्पाड़ा क्षेत्र के पास मैंगनीसाइट खनिज का पता लगाया गया है। सिरोही जिले के दसनगढ़ क्षेत्र में 35 लाख टन तांबा अयस्क के भण्डार सिद्ध हो चुके हैं। उदयपुर जिले में जगह - रेतपातलिया क्षेत्र में 10 लाख टन बैंगरूज के भण्डार विद्यमान हैं। अगुदा (जिला बीलवाड़ा) में 13.4 प्रतिशत जस्ता व 1.9 प्रतिशत शीशासुक्क 610 लाख टन भण्डारों के निष्पे सिद्ध किए गए हैं। मिरोही जिले के पिपला क्षेत्र में 12 लाख टन तांबे के भण्डारों का पता चला है। जैमलमेर जिले के हाबूर-खुडयाला क्षेत्र में 50-54% कैल्शियम ऑक्साइड युक्त 100 लाख टन उच्च श्रेणी का चुन-पत्थर मिला है। उदयपुर जिले के आशर, वेन की कुई कुण आदि स्थानों पर तांबा मिला है। उदयपुर जिले के ही जामर कोटड़ा क्षेत्र में 1968 में देश का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट भण्डार खोजा गया जो इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। रॉक

फॉस्फेट की 16 किलोमीटर लम्बी पट्टी में 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक फॉस्फेट तत्व के कुल 750 लाख टन भण्डार सिद्ध किए गए हैं। इस खनिज की खोज से कृषि उत्पादन के क्षेत्र को अत्यधिक लाभ पहुँचेगा। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील के कंसुपुत गांव के समीप हीरा मिलने के सकते हैं। इसी प्रकार झालावाड़ व सवाईमाधोपुर जिलों में भी हीरे की खोज जारी है। बामवाड़ा व मिरोही जिलों में सोना मिलने की संभावना है। राजस्थान में कई मूल्यवान व अर्द्धमूल्यवान तथा नक्काशी के काम के पत्थर उपलब्ध हैं। राजस्थान के पत्थरों की विभिन्न कोलंबिया के पत्थरों से अच्छी है। अजमेर जिले में मरवाड़ (किशनगढ़) का गार्नेट देश में सबसे अच्छा माना जाता है। राजस्थान में यूरेनियम भी उपलब्ध है।

राजस्थान में तांबा, जस्ता, टंगस्टन, रॉकफॉस्फेट, मोना व हिंग उपलब्ध हैं। ये वे खनिज हैं, जिन्हें नई राष्ट्रीय खनिज नीति के अन्तर्गत गैर सत्कारी उद्यमियों के लिए खोल दिया गया है। टंगस्टन सामरिक महत्व का खनिज है और ऐसे खनिजों के विकास पर इस नीति में विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। नई नीति के अन्तर्गत खनिजों के सर्वेक्षण और खोज पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। विशेष रूप से ऐसे खनिजों का विकास किया जायेगा जो अभी देश में बहुत कम मात्रा में या केवल आवश्यक पूर्ति भर के लिए ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी धातु और खनिजों की खोज पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा उच्च तकनीक में काम में आते हैं। इन खनिजों और धातुओं में राजस्थान में उपलब्ध टांगस्टन, यूरेनियम, जस्ता, शीशा, चूना, हीरा मांगक नीलम तांबा आदि की गणना की जा सकती है। अभी तक इन खनिजों और धातु को उपलब्धता के पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण, दोहन शोधन आदि कार्य भली प्रकार नहीं किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान व्यवस्था की समय-समय पर मरीफा की जाए ताकि सर्वेक्षण तथा खोज करने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और खनिजों का खोजखनन प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

1954 की राष्ट्रीय खनिज नीति को मूर्त रूप देने के लिए खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम 1957 में आवश्यक सरोधन करने का प्रस्ताव है। इस नई नीति के अन्तर्गत यूरेनियम, कोयला और खनिज तेल की छोड़कर सम्पूर्ण खनिज उद्योगों को गैर सत्कारी उद्यमियों के लिए खोल देने की योजना है। संशोधित नीति के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों के

साथ खनिज उद्योग में विदेशियों की भागीदारी की सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई। इस नीति के अन्तर्गत उन खनिज और धातु शोधन इकाइयों को अपनी स्वयं की खानें रखने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया ताकि कच्चा माल उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। विदेशी भागीदारी में चरने वाली खनिज परियोजनाओं में विदेशी पूजी निवेश सामान्यतः 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा किन्तु यह सीमा खनिज शोधन उद्योगों की खानों पर लागू होगी। यही हुई भागीदारी का निर्णय अलग-अलग मामलों में अलग-अलग किया जाएगा। नई खनिज नीति में विदेशी पूजी निवेश को इतनी सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने से विदेशी उद्योगी राजस्थान की खनिज सम्पदा के दोहन व शोधन की ओर आकर्षित होंगे। राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना से विकास की सम्भावनाएँ भी बढ़ गई हैं। विदेशी पूँजी के आगमन से वर्तमान खान मालिकों से प्रतिस्पर्धा की सम्भावना भी प्रतीत होती है जिससे कुशलता में वृद्धि होने की सम्भावना है। खनिज नीति सम्बन्धी दस्तावेज में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि खानों के पट्टे उस समय तक जारी नहीं किए जाने चाहिए जब तक पर्यावरण मरक्षण के पर्याप्त उपाय नहीं कर लिए जाएँ। इस नीति के लागू होने से अब सरकार एवम् खान मालिकों पर विरासत उत्तरदायित्व आ गया है। भारत की इस नई नीति के परभाव खनिज क्षेत्र में रूचि रखने वाले अनेक राष्ट्रों ने पूछताछ आरम्भ कर दी है जिसमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय खनिज कम्पनियों और भारत में विद्यमान कई गैर सरकारी कम्पनियों ने खनिज क्षेत्र में पूँजी निवेश करने में रूचि दिखाई है। संक्षेप में खनिज विकास की इस नई उदार नीति के कारण राजस्थान में खनिज विकास का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। यह आशा की जाती है कि राज्य में मूलभूत संरचना के विकास के साथ ही खनिज भण्डारों के समुचित दोहन में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना होगी एवम् औद्योगिक विकास के फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों के माध्यम से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे सरकार की अपेक्षा में वृद्धि होगी और राज्य में समृद्धि एवम् सम्पन्नता का नया अध्याय आरम्भ होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 1993 में जारी पर्यावरणीय अधिमूल्यान में राजस्थान के खनिज विभाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

नई खनिज नीति व अन्तर्गत द्वागुणित विकास में सम्पन्नित कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम

को सौंपे गये हैं और तदनुसार खनन क्षेत्र में मड़क, विद्युत आदि बुनियादी सुविधाएँ निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पट्टेधारी खनिज सम्पदा के आधारभूत विकास हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान निगम को करते हैं।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम संयुक्त क्षेत्र अथवा स्वयं के खनिज आधारित उद्योगों परियोजनाओं एवं उपक्रमों को प्रोत्साहित करने उनका विभाग बनने एवं संचालित करने में कार्यरत है। निगम खनिज कार्य पर अतिरिक्त खानों के विकास एवं खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु परामर्श का भी कार्य करता है। निगम राज्य के 13 जिलों में विभिन्न स्थानों पर राज्य की खानों का व्यावसायिक रूप से संचालन तथा लाइसेन्स, रॉयल्टी, फॉर्मेटेड डिप्लोमा, फेल्लोशिप एवं प्रेपराइट व उत्पादन व विपणन का कार्य कर रहा है। निगम ने 1995-96 तक 92.15 लाख रुपये का विनियोजन मनुष्य/सहायक क्षेत्र की कम्पनियों में किया है। निगम द्वारा वर्ष 1994-95 में राज्यकोष में 10.60 करोड़ रुपये का भुगतान गवर्लटी एवं भूमिकर के रूप में किया गया है।

राजस्थान में खनन क्षेत्र के सुधार

राज्य सरकार अगस्त 1994 में खनिज नीति की घोषणा कर चुकी है जिसमें आधुनिक खान तकनीक को अपनाते खनिज-आधारित उद्योगों पर प्रोत्साहन द्वारा मूल्य मूल्यनन वैज्ञानिक पद्धति में खनन करना तथा खनिजों के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने मार्बल एवं ग्रेनाइट व पट्टे-आवटन हेतु पृथक से नीतियाँ घोषित की हैं ताकि वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उत्खनन व खनिज गन्तव्य सम्पदा हो सके। खनिजों के अण्व्ययन को कम करने तथा वैज्ञानिक विधियों से खनन को बढ़ावा देने हेतु प्लांटों का आकार एक हैक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हैक्टेयर कर दिया गया है। बड़े सीमेंट प्लांटों की स्थापना की दृष्टि से राज्य में सीमेंट ग्रेड लाईमस्टोन क्षेत्रों की पहचान हो जा रही है। निकट भविष्य में 5000 करोड़ रुपये का निवेश में 13 बड़े सीमेंट प्लांटों की स्थापना होना सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर जिले में लिगा खोदगार क्षेत्र में तीन सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। राडमर जिले के गिराव क्षेत्र में मैसूर राजस्थान मिन्स डवलपमेंट

कॉरपोरेशन द्वारा लिमाइट का उत्पादन शुरू किया जा चुका है। यह सीमेंट सबसे एवं अन्य उद्योगों को ईंधन की आपूर्ति करेगा जिससे क्षेत्रों पर निर्भरता में कमी आएगी। दसिसगर, कपूरडी एवं जलिया के लिमाइट भण्डारों पर आधारित 1980 मेगावाट थर्मल के विद्युत गृह की स्थापना की कार्यवाही जारी है।

राजस्थान सरकार की नई खनिज नीति (1994)

राजस्थान सरकार ने अगस्त, 1994 में खनिज नीति की घोषणा की। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य आधुनिकतम खनन तकनीक को अपनाना, खनिज आधारित उद्योगों की प्रक्रिया और मूल्य वृद्धि को लक्ष्य बनाना, वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहित करना तथा खनिजों के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत नये खनिज भण्डारों की खोज करना, खनिज से आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना ही इस खनिज नीति का लक्ष्य है। इस नीति के अन्तर्गत खनिज उत्पादन से सम्बन्धित विद्यमान खनन नियमों और उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी किया जायेगा। उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार ने मार्बल एवं ग्रेनाइट के पट्टे आवंटन हेतु पृथक में नीतियां घोषित की हैं ताकि वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उत्खनन व खनिज संरक्षण संभव हो सके। खनिजों के अपव्यय को कम करने एवं वैज्ञानिक विधियों में खनन को बढ़ावा देने हेतु प्लांटों का आकार एक हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हेक्टेयर कर दिया गया है। बड़े सीमेंट सब्सिडी की स्थापना की दृष्टि से राज्य में सीमेंट के योग्य घूना-पत्थरों के क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। इस प्रकार राज्य की नई खनिज नीति मुख्यतः निम्न बिन्दुओं से संबंधित है।

1. खनिजों की खोज - खनन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं में समन्वय स्थापित करते हुये सर्वेक्षण की दो मंजूर नीति बनाई गयी है- पहला उन खनिजों के लिये जिनका निर्यात किया जा सकता है और उनसे सम्बन्धित उद्योग अति शीघ्रता से स्थापित किये जा सकते हैं। दूसरी नीति उन खनिजों के लिये है जिनका खोजने और उनका विदोहन आरम्भ करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। दूसरे वर्ष में आने वाले खनिजों हेतु सरकार विदेशी निवेशकों को अकर्षित करने का प्रयास करती है।

2. व्यवस्थित खनन - खनिज नीति के अन्तर्गत योग्यता और वैज्ञानिक ढंग से खनिज कार्य करना सम्मिलित है यहाँ कारण है कि समग्रतः और ग्रेनाइट के पट्टों की

सीमा बढ़ाई गई है। निर्गत आधुनिक तकनीक और खनन विद्यमान से सम्बन्धित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया है। कोटा स्टोन और स्लेट स्टोन के अन्तर्गत प्रोत्साहित नये पट्टे उन्हीं उद्यमियों को प्रदान किये जायेंगे जो आधुनिक यंत्रों द्वारा सम्पूर्ण ब्लाक का विदोहन करने को तैयार हैं। कोटा स्टोन के वेकर बचे हुए भाग को यदि कोई औद्योगिक इकाई कच्चे पदार्थ के रूप में वस्त्र में लेती है तो उन पर रायल्टी नहीं ली जायेगी। राज्य सरकार ने श्रमिक एवं कान्वा उद्योग की ऐसी इकाइयों हेतु वित्त में 5 करोड़ से 25 करोड़ के मध्य पूंजी लगने का अनुमान होता है उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिक्री कर आदि में लाभ की अवधि 7 वर्ष से 9 वर्ष कर दी गई है। यदि ऐसे उद्योगों में 25 से 100 करोड़ के मध्य पूंजी लगने की सम्भावना हो तो उन्हें बिक्री कर आदि में प्राप्त लाभ 9 वर्ष की बजाय 11 वर्ष तक प्राप्त होगा। सरकार जब भी पट्टों का नवीनीकरण करेगी तब विरोध रूप से यह देखा जायेगा कि खान का विकास व्यवस्थित रूप से किया गया है या नहीं। सरकार न अवधि ऋण प्राप्त करने के लिये पट्टाधारकों को खनन पट्टों को बंधक रखने की भी अनुमति दी है। छोटे खनिज और ऐसे खनिज जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं उनका परस्पर सटे हुए छोटे-छोटे पट्टों को आपस में मिलाया जा सकेगा लेकिन ऐसे मिले हुए पट्टे 5 हेक्टेयर से अधिक बड़े नहीं होंगे। सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों को स्थापित करने और खनिजों की खोज और खनन करने के लिये ऐसे उद्यमियों को सिंगल खिडकी सेवा और पथ प्रदर्शन सेवा प्रदान करेगी जिन्होंने उपरोक्त में 11 करोड़ से अधिक की राशि विनियोजित करने का निश्चय किया है।

3. प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ - निर्यात उद्योगों की स्थापना करने पर प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टा आवंटित किया जायेगा। सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से खानों को मड़कों से जोड़ा जायेगा। यदि खनिज पट्टाधारक अपने श्रमिकों के हित के लिये चिकित्सालय और विद्यालय आदि निर्मित करेंगे तो सरकार उस पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत वहन करेगी। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा जहाँ पर एक साथ पट्टे आवंटित किये जायेंगे। खनन करों के कारण होने वाले वन विनाश की क्षतिपूर्ति कम से कम 100 हेक्टेयर भूमि खान विभाग को दी जायेगी जिस पर खनिज पट्टाधारी प्रति हेक्टेयर कम से कम 400 पेड़ें लगायेगा। राज्य सरकार प्रदर्शनीय, मेलो और सेमीनारों के माध्यम से खनिज पदार्थों के निर्यात एवं आधुनिकतम यंत्रों के प्रोत्साहित करेगी।

4 सरलीकरण - खनन पट्टों की खाज उनकी स्वीकृति और नवीनीकरण प्रक्रिया का शास्य निपटारा जायेगा। चरगाघाट भूमि में खनन पट्टे के लिये आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। खनिज सम्पत्ती विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समय गारंटी भी निर्धारित की गई है ताकि सभी कार्य समय पर निपटारा जा सकें। गन्धर्व और वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता आदि में ढील दी गई है।

5 खनिज नियमों में संशोधन खनन पट्टे अब न्यूनतम 25 हेक्टेयर पट्टावर न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के जरूर दिए गए हैं। खनिज पट्टों की अवधि में 10 से 20 वर्ष कर दी गई। खनिज पट्टों का जब नवीनीकरण किया जायेगा तो वह भी 20 वर्ष के लिये होगा। खदान लाइसेंस की अवधि भी अब 1 वर्ष में बढ़कर 5 वर्ष की गई है। वार्षिक क्रियों को अधिक न्यायसुक्त बनाने के उद्देश्य से

संशोधित किया गया है। सरकारी अब खनिज पट्टों का आंशिक परित्याग का स्वीकार करेगा। आपत्ति हटाने में भी संशोधन किया गया है। ताम्र रसम से खाने बंद होने पर निरंतर खनने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। अवैध खनन का रोफने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

6 अन्य उद्यमियाँ और सरकार में सामन्तों के परम्परागत कार्यालय के उद्देश्य खनिज परामर्शदात्री परिषद का गठन का निर्णय लिया गया है। इस परिषद में किये गये निर्णय की क्रियान्वयन का कार्य मुख्य सचिव को अग्रभूमि में गठित समिति देखेगी। खान आवंटन में अब अनुदान जारी जनजाति और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसा अनुमान है कि इस नीति के कारण लगभग 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- राजस्थान में खनिज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Minerals in Rajasthan
- राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Present Position of Mineral Based Industries in Rajasthan
- राजस्थान राज्य खनिज विस्मय निगम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on the Rajasthan State Mineral Development Corporation (RSMDC)
- प्राकृतिक संसाधनों का महत्व बताइए।
Explain the importance of Natural Resources
- प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति बताइए।
Explain the Nature of Natural Resources
- राजस्थान में बहुतरास प्राकृतिक संसाधन हैं। समझाइए।
Rajasthan is endowed with abundant natural resources. Explain.
- राजस्थान राज्य के जल संसाधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Water Resources of Rajasthan
- राजस्थान में मिट्टी-अपक्रमण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Present a short account of soil-degradation in Rajasthan
- पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षा की मात्रा क्यों कम प्राप्त होती है।
Why does Western Rajasthan receive low amount of annual rainfall?
- राजस्थान का चार प्रमुख नदियों का नाम बताइए।
Name four important rivers of Rajasthan
- चम्बल नदी की दो मुख्य सहायक नदियों के नामों का उल्लेख कीजिए।
Mention the names of two major tributaries of Chambal river
- सफ़ेदाई काँची मिट्टी का महत्व बताइए।
Explain The Black Cotton Soil and its importance

B निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का विवरण दीजिए और बताइए कि वे राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं।
Describe the important Natural Resources of Rajasthan and discuss how they are important in

Economic Development of Rajasthan

2. प्राकृतिक संसाधनों में आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Natural Resources? Explain the importance of Natural Resources in Rajasthan
3. राजस्थान के प्राकृतिक विभागों पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on Natural regions of Rajasthan
4. जल संकल्प से आप क्या समझते हैं? राजस्थान में जल संकल्प के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान की जल संकल्प की वर्तमान स्थिति क्या है?
What do you understand by water resources? Explain its importance in Rajasthan. Discuss the present position of Water Resources in Rajasthan
5. राजस्थान के प्रमुख खनिज क्षेत्रों में से दो किन्हीं दो खनिजों के महत्व, उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
What are the principle minerals in Rajasthan? Describe the importance, production and area of production of any two minerals of Rajasthan
6. राजस्थान में खनिज उत्पादन की प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधानों पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on the problem of Mineral Production and suggest ways for their removal in Rajasthan
7. राजस्थान का वन सम्पदा का विभागगत विवरण कीजिए। साथ ही इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
Explain in detail the Forest Wealth of Rajasthan. Also discuss its importance
8. राजस्थान के वनों के प्रकार बताइए और इनके गुण अथवा लक्ष्यों का भी वर्णन कीजिए।
Explain the types of forest of Rajasthan and also discuss their merits or advantages
9. राजस्थान में औद्योगिक विस्तार के लिए आवश्यक आधारभूत खनिज उपलब्ध हैं। समझाइए।
Rajasthan is endowed with the basic minerals needed for industrial expansion. Discuss
10. राजस्थान में निम्नलिखित खनिज सम्पदा पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
(i) टंग्स्टन (ii) मैंगनीज (iii) जस्ता (iv) ताम्बा (v) फेल्स्पार
Write briefly about the following mineral wealth in Rajasthan -
(i) Tungsten (ii) Manganese (iii) Zinc (iv) Copper (v) Feldspar
11. भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर विभाजन कीजिए एवं दक्षिण पठार का भौगोलिक वर्णन कीजिए।
Divide India according to its physical features and give a geographical account of Deccan Plateau

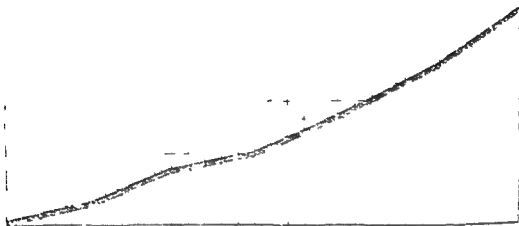
C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

1. राजस्थान का भौगोलिक स्थिति तथा क्षेत्रफल, इसके प्राकृतिक विभागों, विविध तथा भूमि उपयोग पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on the Geographical position, area, Natural regions, soil and land utilization in Rajasthan
2. राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का विवरण कीजिए और बताइए कि वे राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं।
Describe the important natural resources of Rajasthan and discuss how they are important in economic development of Rajasthan
3. राजस्थान में प्रचुर प्राकृतिक संपत्ति है। समझाइए।
Rajasthan is endowed with abundant natural resources. Explain
4. प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में राजस्थान किस संदर्भ में है?
To what extent Rajasthan is rich in Natural Resource endowments?
5. राजस्थान के आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व का भूमिका का विवरण कीजिए।
Discuss the importance (role) of the minerals in the economic development of Rajasthan
6. राजस्थान सरकार का खनिज नीति तथा प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों के विकास का संक्षेप विवरण कीजिए।
Describe in brief Mineral Policy and development of Mineral based industries in Rajasthan
7. राजस्थान के खनिज उत्पादों का वर्णन कीजिए और बताइए कि वे राज्य की औद्योगिक प्रगति में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं?
Explain the mineral products of Rajasthan and discuss how they are important in industrial advancement of the state
8. पिछले पाँच वर्षों में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में वनों के विकास के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं? बताइए।
What efforts have been made by the Government of Rajasthan during the Five Year Plans in the State? Discuss
9. राजस्थान में वन विकास का प्रमुख समस्याओं का विवरण कीजिए, साथ ही इनके समाधान के सुझाव दीजिए।
Explain the main problems of Forest Development in Rajasthan. Also give suggestions to solve them

राज्य का घरेलू उत्पाद

STATE DOMESTIC PRODUCT



"यह बिना अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- घरेलू उत्पाद का अर्थ
- रावस्थान के घरेलू उत्पाद की विशेषताएँ व प्रवृत्तियाँ
- राज्य के घरेलू उत्पाद के टाचा एण्ड उमरी गणना
- राज्य के घरेलू उत्पाद को मापने की विधियाँ
- राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में आने वाली कठिनाईयाँ
- राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना का महत्व और उपयोग
- राज्य के घरेलू उत्पाद में लक्ष्य वृद्धि के लिए सुझाव
- अन्तर्सर्प प्रश्न

देश की राष्ट्रीय आय, सभी राज्यों के घरेलू उत्पादों का योग होती है। राष्ट्रीय आय का विचार सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था लेकिन उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया था। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय आय की अवधारणा पर उचित ध्यान से विचार किया जाने लगा। वर्तमान में तो राष्ट्रीय आय का विचार अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी राष्ट्र या राज्य के आर्थिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना आर्थिक समस्याओं का समाधान करना, दो राष्ट्रों या राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने और देश की हलाकत की आर्थिक सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं का समाधान करने में राष्ट्रीय एवं राज्यीय घरेलू उत्पादों की जानकारी होना अत्यावश्यक होता है। यह विचार अर्थव्यवस्था के विस्तार में भी सहायक होता है क्योंकि इससे देश के उत्पादन स्तर को तो मापा ही जा सकता है आर्थिक विकास को समझा भी की जा सकती है और भावी अनुमान लगाने जा सकते हैं। विज्ञान की दिशा प्रवृत्ति और विकास दर ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार घरेलू उत्पाद के बढ़ते हुए महत्व के कारण इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय का अर्थ व परिभाषा

MEANING & DEFINITION OF DOMESTIC PRODUCT OR NATIONAL INCOME

घरेलू उत्पाद के विचार को ठीक प्रकार से समझने के लिए प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर फिशर द्वारा दो गई परिभाषाओं का अध्ययन बरत आवश्यक है। मार्शल ने अपनी परिभाषा में विस्तृत दृष्टिकोण को, प्रो पीगू ने मौद्रिक दृष्टिकोण को और प्रो फिशर ने उपभोग को अपनी परिभाषा का आधार बनाया है।

प्रो मार्शल के अनुसार "देश के प्राकृतिक माधनों पर श्रम एवं पूँजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष जो भौतिक व अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है इन सबका शुद्ध उत्पत्ति के योग को ही देश का आगम अथवा राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं।"

प्रो पीगू के अनुसार "राष्ट्रीय आय किसी देश के लोगों की आय का वह भाग है जिसमें निदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है और जिसे द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है।"

प्रो फिशर के अनुसार "राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय केवल उन सेवाओं द्वारा निरूपित होती है जो अन्तिम उपभोक्ताओं को भौतिक अथवा मानवीय वातावरण में शाय होती है। अतः एक पिपानो या एक ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है इस वर्ष की आय का भाग नहीं है अपितु पूँजी में वृद्धि है। केवल वे सेवाएँ जो कि इनके प्रयोग से इस वर्ष मिलेंगी राष्ट्रीय आय होंगी।"

उपरोक्त परिभाषाओं में घरेलू उत्पाद अथवा राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय का अर्थ समझने में सहायता मिलती है। उपरोक्त परिभाषा से ज्ञात होता है कि घरेलू उत्पादन की गणना अनेक प्रकार में की जा सकती है किन्तु व्यवहार में उत्पादन तथा आय के आधार पर यह गणना की जाती है।

राजस्थान के घरेलू उत्पाद की विशेषताएँ व प्रवृत्तियाँ

CHARACTERISTICS & TRENDS OF STATE'S DOMESTIC PRODUCT

राज्य का समस्त वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध व योग राज्य का घरेलू उत्पाद है। इस मूल्य और शुद्ध

घरेलू उत्पाद में विभक्त किया जा सकता है। एक निश्चित समय में, बिना इसका प्रावधान किए हुए, राज्य की समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राजस्थान के घरेलू उत्पाद को समझने में निम्नलिखित बिन्दु सहायक सिद्ध होंगे -

1 राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा लगाए जाते हैं। ऐसा सन् 1954-55 से किया जा रहा है।

2 राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद को राज्य आय के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की प्रगति को मापन का एक उचित मापदण्ड माना जाता है।

3 राज्य में घरेलू उत्पाद का की गणना और इससे सम्बन्धित विचार वही है जो कि केंद्रीय सांख्यिकी मण्डल (पी एस ओ) द्वारा अनुमानित किए जाते हैं।

4 राज्य के घरेलू उत्पादन की दृष्टि से राज्य की अर्थव्यवस्था की प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभक्त कर लिया जाता है।

5 राज्य में घरेलू उत्पाद के जा अनुमान लगाये जाते हैं, वे राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और केंद्रीय सांख्यिकी मण्डल द्वारा अलग-अलग एक साथ तैयार किए जाते हैं। इनको परस्पर मिलाया जाता है और आवश्यक होने पर सुधार भी किए जाते हैं। ऐसा इ कारण से किया जाता है ताकि अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार के आंकड़ों सामने आए त्रिजर्ना एक-दूसरे से तुलना भी की जा सके।

6 राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन, आय और व्यय से सम्बन्धित आंकड़ों का एक साथ प्रयोग किया जाता है।

7 राज्य का घरेलू उत्पाद का चालू एवं स्थिर कीमतों पर रिकार्ड जाता है। राज्य में इस प्रकार का पहला अनुमान 1954-55 को आधारवर्ष मानते हुए 1956 में जारी किया गया था। इस आधार वर्ष 1959-60 तक बना रहा। इसके पश्चात् आधारवर्ष 1960-61 हो गया और इसके आधार पर 1978-79 तक आंकड़े जाग किए जाते रहे। इसके पश्चात् 1970-71 को आधारवर्ष बनाया गया जो कि 1987-88 तक चलता रहा। इसके पश्चात् 1980-81 को आधारवर्ष के रूप में अपनाया गया और यह आधार वर्ष वर्तमान में भी ब्रिचालोत है।

8 राज्य की घरेलू आय की गणना के लिए राजस्थान की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का मानव भाग में विभक्त किया गया

है जो इस प्रकार है (i) वणि (ii) वन (iii) मत्स्य पालन (iv) खन (v) विनिर्माण (पजीकृत) (vi) विनिर्माण (गैर पजीकृत) (vii) निर्माण कार्य (viii) विद्युत गैस तथा जलापूर्ति (ix) शहरी विकास तथा स्पर्धन (x) संचार (xi) व्यापार (xii) पर्यटन तथा जलपात्र गृह (xiii) वैज्ञानिक व्यापार तथा बीमा अनुभाग (xiv) स्थावर सम्पदा आवासाय गृह। का स्थापित एवं व्यावसायिक सेवाये (xv) सार्वजनिक प्रशासन (xvi) अन्य सेवाये।

9 राज्य के घरेलू उत्पाद का अनुमान पचत्तिन मूल्यो एव स्थिर मूल्यो के आधार पर लगाया जाता है। जब लागू अर्थव्यवस्था पर राज्य के घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है तो यह अनुमान स्थिर मूल्यो पर आधारित होता है। इससे राज्य अर्थव्यवस्था में होने वाले सरचनात्मक परिवर्तनो का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस गणना के लिए राज्य अर्थव्यवस्था को मुख्यत तीन भागो में बांटा जाता है यथा (1) प्राथमिक क्षेत्र (2) द्वितीयक क्षेत्र व (3) तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र। इस गणना से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बदलती हुई स्थिति का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए राज्य की कुल आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा पहले की तुलना में कितना कम हुआ और अन्य बिसी क्षेत्र ने हिस्से। कितनी वृद्धि हुई? इससे किसी क्षेत्र विशेष के विभिन्न कारको की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनो की भी जानकारी मिल जाती है। राज्य के घरेलू उत्पाद सम्बन्धी आय दो के आधार पर ही आर्थिक नियोजन का निर्माण किया जाता है और इन्हीं आकड़ो के आधार पर आर्थिक योजना की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

10 विभिन्न क्षेत्रों का घरेलू उत्पाद में योगदान राजस्थान के घरेलू उत्पाद का विश्लेषण करने में सहायता होता है कि घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा किन्तु इसका योगदान निरन्तर गिर रहा है। सामान्यत आर्थिक विकास में तीव्रता आगे पर कृषि का भाग स्वत ही कम होता चला जाता है। इरावे 13 करोड़ उद्योग का घरेलू उत्पादन में योगदान निम्नलिखित के साथ बढ़ता है। राजस्थान में औद्योगिकरण की अपेक्षा के कारण उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर बना हुआ है। राजस्थान के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान निरन्तर बढ़ रहा है।

11 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (Net state Domestic Product) सकल राज्य घरेलू उत्पादन में से ह्रास के मूल्य का समायोजन करने के पश्चात शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस दृष्टि से राजस्थान की स्थिति इस प्रकार थी

राजस्थान में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (कोटि रूपयों में)		
वर्ष	प्रचलित मूल्यों पर	स्थिर कीमतों पर (1980 III)
1980 81	4125 71	4125 71
1989 90	15463 11	7492 27
1996 97	36442	9561
1996 97 (अनुमानित)	44107	11307
1998 99 (अनुमानित)	17155	11599
1998 99 (प्रतिष्ठित अनुमान)	50171	11649

तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान का घरेलू उत्पादन 1980 81 में 4125 71 रूपये था जो बढकर 1998-99 में 50271 रूपये हो गया। अतः घरेलू उत्पाद में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई। इसी अवधि में स्थिर कीमतों पर राज्य का घरेलू उत्पाद 4125 71 रूपये से बढकर 11648 रूपये हो गया। अतः स्थिर कीमतों की दृष्टि से राज्य के घरेलू उत्पाद में लगभग 2 5 गुना वृद्धि हुई।

12 प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income) - शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देकर प्रतिव्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। निम्न आकड़ों के आधार पर भारत व राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना की जा सकती है

राजस्थान एवं भारत में प्रतिव्यक्ति आय			
वर्ष	प्रचलित मूल्यों पर		स्थिर मूल्यों पर (1980 81)
	राजस्थान	भारत	राजस्थान भारत
1971 72	660	587	626 548
1980 81	1222	1627	1222 1627
1989 90	1595	4252	1742 2142
1996 97	8481		2247 -
(अनुमानित)			
1997 98	9215		2215
(अनुमानित)			

तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय जो 1971 72 में 660 रूपये थी 1996 97 में बढ़कर 8481 रूपये हो गई। इस अवधि में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय में लगभग 13 प्रतिशत गुना वृद्धि हुई।

स्थिर मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय 1971 72 में 626 रूपये थी जो बढकर 1996 97 में 2247 रूपये हो गई। अतः इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 3.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई।

14. विकास दर (Growth Rate) - राजस्थान में कुल राज्य आय व प्रतिव्यक्ति आय की विकास दरों का अनुमान निम्न तालिका से होता है-

राजस्थान की शुद्ध राज्य आय एवं प्रतिव्यक्ति आय की समग्र विकास दर		
अवधि	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	प्रतिव्यक्ति आय (1980-81 के मूल्यों पर)
तृतीय योजना (1961-66)	1.36	0.98
चौथी योजना (1966-69)	9.77	-3.02
पाँचवी योजना (1969-74)	7.08	3.81
छठी योजना (1974-79)	5.18	2.22
सातवी योजना (1980-85)	5.94	3.01
आठवी योजना (1985-90)	7.55	4.78
दशवर्षीय (1961-90)	3.99	1.22

स्रोत - Draft Eight Five Year Plan, 1992-97

इस तालिका से ज्ञात होता है कि

- राजस्थान में चतुर्थ योजना से सातवीं योजना तक शुद्ध राज्य आय में सतोषजनक वृद्धि हुई है।
- उपरोक्त अवधि में प्रतिव्यक्ति आय में सतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई क्योंकि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक रही है।
- दीर्घावधि दर की दृष्टि से भी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिव्यक्ति आय में कम वृद्धि होना, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने का परिचायक है।

15 अन्य राज्यों से तुलना (Comparison with other states) - निम्न तालिका से कुल आय एवं प्रतिव्यक्ति आय की राज्यवार स्थिति का ज्ञान होता है-

राजस्थान एवं अन्य राज्यों में वर्तमान एवं प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	
(1996-97)	
A. राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद - 41872 करोड़ रु	
B. भारत में सर्वाधिक शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाले प्रमुख राज्य-	
(1) महाराष्ट्र	152179 करोड़ रुपये
(2) उत्तर प्रदेश	133170 करोड़ रुपये
(3) आन्ध्र प्रदेश	72195 करोड़ रुपये
C. राजस्थान की प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद - 8481 रुपये	
D. भारत में सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाले प्रमुख राज्य	
(1) महाराष्ट्र	17296
(2) गुजरात	18719
(3) पंजाब	18213

Source: Economic Survey 1996-97

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि:

- 1980-81 में शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान था। इस समय सबसे कम शुद्ध उत्पाद सिक्किम का था। राजस्थान की घरेलू आय अरुणाचल प्रदेश, असम, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम व त्रिपुरा से अधिक थी।
- 1980-81 में राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद 4126 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1996-97 में 41872 करोड़ रुपये हो गया। 1996-97 में भी शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य का ही था। राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद अरुणाचल प्रदेश, असम, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर से अधिक था।

(iii) 1980-81 में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1022 रुपये था। इस समय प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से गोआ राज्य का प्रथम स्थान था। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश राज्यों से अधिक था।

(iv) 1980-81 में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 1222 रुपये था जो बढ़कर 1996-97 में 8481 रु हो गया। इस समय प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था। बिहार, केरल, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अधिक था।

राज्य के घरेलू उत्पाद का ढाँचा एवं उसकी गणना

STRUCTURE AND MEASUREMENT OF STATE'S DOMESTIC PRODUCT

राज्य की घरेलू आय को ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था को सोलह भागों में विभक्त किया गया है। अर्थव्यवस्था के ये समस्त भाग मिलकर राज्य के घरेलू उत्पाद के ढाँचे का निर्माण करते हैं। राज्य के घरेलू उत्पादन के ढाँचे को निम्नांकित बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है-

1. कृषि (Agriculture) - कृषि क्षेत्र को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बाँट दिया गया है। प्रथम- कृषि, द्वितीय-पशु सम्पदा एवं उसके उत्पादन और तृतीय

गिराई। कृषि के अन्तर्गत कृषि फसलों, घास, चरई, खेती या प्रबंध, कृषि से सम्बन्धित भग्नाओं तथा वृक्षों से सम्बन्धित विभिन्न मूल्यवत् क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पशु संपादन और उन्ने सम्बन्धित उत्पादन तथा, दूध उत्पादन चरवाए एवं झाले, अण्डे, शादर रेशम के लम्बे मुर्गापालन आदि को सम्मिलित किया जाता है। सिचाई से सम्बन्धित क्रियाओं में विभिन्न समकालीन चेतना से कृषकों को की गई उत्पादित सम्मिलित है। इसकी गणना के लिये उत्पादन विधि का अन्तर्गत हुए अनिश्चित मूल्य सूजन (Value added) ज्ञात किया जाता है।

2 वन (Forest) - वनों के अन्तर्गत इसकी क्रियाओं को पुन तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम वन, द्वितीय लकड़ी एकत्रित करना तथा तृतीय वनों से बाहर लकड़ी एकत्रित करना। वनों के अन्तर्गत वृक्षारोपण और उनका संरक्षण तथा वन उत्पादों को एकत्रित करना आदि सम्मिलित है। लकड़ी एकत्रित करने के अन्तर्गत सामान्य वनों से लकड़ी प्राप्त करना और वन उत्पादों को विक्रय केन्द्रों तक पहुँचाना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसी प्रकार सामान्य वनों के बाहर उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त औद्योगिक लकड़ों और जलाने योग्य लकड़ी आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना भी उत्पादन विधि से की जाती है।

3 मत्स्य पालन (Fisheries) - मत्स्य के क्षेत्र को धेरू उत्पादन की गणना करने के लिये पुन चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम - व्यापारिक मत्स्य पालन जो कि उपलब्ध स्थानीय जल में किया जाता है। उसमें नदियों, नहरों, तालाबों झीलों, खेतों आदि में फँड़े जाने वाली मछलियाँ सम्मिलित हैं। द्वितीय - जीवन निर्वाह हेतु मत्स्य पालन किया जाता है। जो कि छोटे-छोटे कृषि तालाब बनाकर या इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं से सम्पन्न हो पाता है। तृतीय - क्षेत्र के अन्तर्गत समुद्री क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को एकत्रित करना सम्मिलित है। इसकी गणना उत्पादन विधि द्वारा होती है।

4 खनन (Mining) - इस क्षेत्र के अन्तर्गत खनिज निष्कलना तथा निराले गए खनिजों को गन्नाहक क्रियाओं का मध्यम से ठीक करना आदि सम्मिलित है। ये सभी प्रवृत्त की क्रियाएँ खनन की शक्ति पर ही हानी चाहिए। ये क्रियाएँ खनिजों को तोड़ने, धोने, मलक करने, निष्कलन व श्रेणीकरण आदि से सम्बन्धित हैं। यहाँ खनिजों की स्थिति पर विभिन्न क्रियाओं पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है ता कि उसे क्षेत्र में सम्मिलित व वस्तु निर्माण कार्य में सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना उत्पादन विधि द्वारा होती है।

5 विनिर्माण - पंजीकृत (Manufacturing - Regd) - धारतु उत्पादन की गणना के लिए विनिर्माण की क्रियाओं को दो बड़े भागों में विभक्त किया गया है जो कमरा रजिस्टर्ड एवं अनरजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। रजिस्टर्ड विनिर्माण क्रियाओं में उन पैक्टोरियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें 10 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं और जो विद्युत का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी प्रकार वे फैक्टोरियाँ भी इगम सम्मिलित हैं जिनमें 20 या अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं लेकिन वे विद्युत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस कार्य हेतु विभाग 12 भागों का विवरण देखा जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया में वस्तुओं की बनाना, सुधारना, पैकिंग करना तोड़ना आदि अनेक क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। इन सब क्रियाओं का उद्देश्य उस वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाना होना है। इसी प्रकार प्रिंटिंग, शीतलन में वस्तुओं को रटना आदि भी इसी के अंतर्गत हैं। इनका गणना में उत्पादन विधि प्रयुक्त होती है।

6 विनिर्माण - (नैर पंजीकृत) (Manufacturing - Unregistered) - रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र मिलकर समग्र निर्माण क्षेत्र की रचना करते हैं। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के विनिर्माण, विधायन, मरम्मत और हर प्रकार के रखरखाव से सम्बन्धित सेवाएँ आ जाती हैं। जो क्षेत्र रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में नहीं आता, उन्हें अनरजिस्टर्ड क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना में उत्पादन विधि से अतिरिक्त मूल्य सूजन ज्ञात किया जाता है।

7 निर्माण कार्य (Construction) - निर्माण क्रियाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण, सिविल इंजीनियर और अन्य विशेष ठेकेदार द्वारा ठेके पर किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न मगटनों द्वारा अपने स्तर पर कराए जाने वाले कार्यों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत नये वृक्षारोपण फलों के बगीचे आदि के लिए किए गए निर्माण कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न निर्माण व मूल्यों व आधार पर इसे प्राप्त धेरू उत्पाद ज्ञात किया जाता है।

8 विद्युत, गैस और जलपूर्ति (Electricity, Gas and Water supply) - विद्युत के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और उमका चरण सम्मिलित किया जाता है। गैस व निर्माण के अन्तर्गत इमन मरम्मत कार्य, जिसमें गैस गैस व सम्मिलित है का वितरण सम्मिलित है। यह गैस धारतु कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इनके अन्तर्गत एल.पी.जी. गैस को भी सम्मिलित किया जाता है। उत्पादित के अन्तर्गत जल के समग्र उमको शुद्ध बनाने और उमक वितरण व कार्य को सम्मिलित किया जाता है।

विद्युत के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य विद्युत मंडल और एटॉमिक पावर प्लांट (आर ए पी पी) मुख्य सगठन है। गैस उत्पादन के संध में खादी प्रमोद्योग महत्वपूर्ण है। घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए विद्युत व जलापूर्ति के अंतर्गत सकल आय जोड़ी जाती है। गैस के लिये उत्पादन विधि का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त मूल्य सृजन ज्ञात किया जाता है।

■ **व्यापार, होटल एवं जलपानगृह (Trade, Hotels and Restaurants)** - इसके अंतर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं का फुटकर एवं थोक व्यापार सम्मिलित है। इसके अंतर्गत आयात निर्यात को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एजेंट, दलाल आदि की क्रियाएँ भी सम्मिलित हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर ठहरा जा सकता है और जहाँ खाने-पीने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, ऐसे होटल एवं रेस्टोरेंट भी इसके अंतर्गत आते हैं। गणना में उत्पादन विधि में मूल्य सृजन ज्ञात किया जाता है।

10 **रेल, अन्य परिवहन, संचरण और संचार (Railway, Other Transport, Storage & Communication)** - यातायात के अंतर्गत रेलवे, सड़क जल व वायु यातायात और उसमें सम्मिलित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भण्डारण में सम्बन्धित कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। डाक तार तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की संचार सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें आय विधि का प्रयोग कर घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात किया जाता है।

11 **बैंकिंग एवं बीमा (Banking & Insurance)** - बैंकिंग के अंतर्गत व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के बैंकिंग विभाग तथा अशा पत्रों, विभिन्न प्रकार के विनियोगों व ऋणों आदि से सम्बन्धित क्रियाओं में लगी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। इसकी गणना में आय विधि प्रयुक्त होती है।

12 **रियासत सम्पत्ति, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएँ (Real Estate, Ownership of Dwelling & Business Services)** - ज़रदाद से सम्बन्धित सेवाओं के अंतर्गत इसमें सम्मिलित एजेंटों और इसी भाँति कार्य करने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आवास के अंतर्गत आवासीय भवनों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक सेवाएँ भी इसके अंतर्गत आती हैं। ज़रदाद के लिये आय विधि और आवासीय भवनों के लिये वार्षिक किराया ज्ञात किया जाता है। वार्षिक किराये में मरम्मत आदि के व्यय कम कर दिये जाते हैं।

13. **सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration)** - इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों, नगर पंचायतों, मजिस्ट्रेट बोर्ड, जिला पंचायतों, पंचायत राज से सम्बन्धित संस्थाओं आदि द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा सेवाएँ सम्मिलित होती हैं। इन सेवाओं में बरों का मजहम, गुप्तचर, रेल, सामरिक एवं सैन्यव्यय सेवाएँ तथा कृषि, उद्योग आदि से सम्बन्धित आर्थिक सेवाएँ सम्मिलित होती हैं। इसकी गणना में आय विधि प्रयुक्त होती है।

14 **अन्य सेवाएँ (Other services)** - इस क्षेत्र में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य वैज्ञानिक सेवाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा दी जानेवाली अनेक प्रकार की सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। मनोरंजन के लिए प्रदर्शन की जाने वाली सेवाएँ जैसे, टी वी और रेडियो, भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसकी गणना आय विधि से होती है।

राज्य के घरेलू उत्पाद को मापने की विधियाँ

METHODS TO MEASURE G.D.P

राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना मुख्यतः उत्पादन विधि और आय विधि के द्वारा की जाती है। व्यय विधि का प्रयोग कम होता है। घरेलू उत्पाद के मापन की प्रमुख विधियाँ निम्नवत हैं -

1 **उत्पत्ति विधि (Product Method)** - राजस्थान में कृषि, वन, मूल्य उद्योग, पशुपालन, पञ्जीकृत निमाण कार्य व खनन आदि क्षेत्र में घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए 'उत्पत्ति विधि' का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र की अंतिम उत्पत्ति का बाजार मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसमें में उत्पत्ति के मापनों का कुल मूल्य (शक्ति, द्रव्य व कच्चे मूल्य आदि के व्यय) घटा दिया जाता है। इससे सकल आय ज्ञात हो जाती है। इसमें से मूल्य ह्रास पटारने पर शुद्ध अन्तः प्रजन हो जाती है।

2 **आय विधि (Income Method)** - इस विधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की आय को जोड़ लिया जाता है, यः उस क्षेत्र की आय होती है। आय विधि का प्रयोग निम्नांकित दो तरीकों से किया जाता है -

(अ) **प्रत्यक्ष आय विधि (Direct Income Method)** - इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों की आय की गणना हेतु किया जाता है जिनके अन्य संकेतों आकड़ों आलाचन में उपलब्ध

हो जाते हैं। रेल व सड़क परिवहन, बीमा बैंकिंग, जलापूर्ति तथा विद्युत आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विधि आसानी से अपनाई जा सकती है क्योंकि इन क्षेत्रों के आकड़े वार्षिक लेखों में उपलब्ध हो जाते हैं।

(व) **परोक्ष आय विधि (Indirect Income Method)** - इस विधि के अन्तर्गत (i) किसी क्षेत्र विशेष की श्रम शक्ति ज्ञात की जाती है (ii) प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिव्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाया जाता है और तत्पश्चात् (iii) श्रम शक्ति को प्रतिव्यक्ति औसत आय से गुणा करके उस क्षेत्र की आय ज्ञात कर ली जाती है। लघु कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, घरेलू सेवाएँ, होटल तथा असंगठित क्षेत्रों की आय की गणना हेतु परोक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है।

3 व्यय विधि (Expenditure Method) - इस विधि के अन्तर्गत किसी क्षेत्र विशेष के व्ययों को जोड़ कर उस क्षेत्र की आय ज्ञात की जाती है। यह विधि मुख्यतः निर्माण कार्यों की आय का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। निर्माण कार्यों के अन्तर्गत ईंट, पत्थर चूना, सीमेंट इमारती लकड़ी व इस्पात आदि का मूल्य सैम्पल सर्वे के आधार पर ज्ञात कर लिया जाता है।

राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में आने वाली कठिनाइयाँ

DIFFICULTIES IN THE MEASUREMENT OF GDP

राज्य की घरेलू आय की कुटिहीन तरीके से गणना अभी भी सम्भव नहीं हो पाई है, इसके अनेक कारण हैं प्रमुख कारण इस प्रकार हैं -

1 अशिक्षा एवं अज्ञानता (Illiteracy & Lack of Knowledge) - राजस्थान में देश के अन्य भागों की अपेक्षा अशिक्षा अधिक है। यही स्थिति अज्ञानता की है। अशिक्षा के कारण विभिन्न व्यवसायों व कार्यों में लगे लोग पूरा हिमाज किताब नहीं रखते। अनेक प्रकार की भ्रांतियों के कारण वे गणना करने वालों को पूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराते हैं।

2 मूल्य स्तर में परिवर्तन (Change in Price Level) - राज्य की आर्थिक क्रियाओं की गणना इस कारण भी कठिन हो जाती है कि मूल्यों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। इस कठिनाई से बचने के लिए किसी आधारवर्ष को लेकर चलना पड़ता है। राजस्थान तथा भारत में जो निर्देशांक बनाए जाते हैं और उनमें विभिन्न वस्तुओं को जो भार प्रदान किया

जाता है वह पूर्णतः कुटिहीन नहीं है।

3 दोहरी गणना की सम्भावना (Possibility of Double Counting) - राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में दोहरी गणना की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। ऐसा सम्भव है कि व्यक्ति की आय को कई स्थानों पर जोड़ लिया जाए। यही स्थिति उत्पादन के सर्धर्म में हो सकती है इस कारण राज्य का घरेलू उत्पादन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है किन्तु वास्तविकता वह नहीं होती।

4 विश्वसनीय आकड़ों का अभाव (Lack of Reliable Data) - राजस्थान में ही नहीं समस्त भारत में घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करने में अनेक दोष विद्यमान हैं। इस कारण इन्हें पूर्णतः विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर आकड़े सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं जो अधिक कार्यभार के कारण अथवा शिथिलता के कारण आकड़े एकत्रित करने में पूरा समय नहीं दे पाते। अतः कुटियों की सम्भावना बनी रहती है।

5 क्षेत्रों का वर्गीकरण (Classification) - राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्र बनाए गये हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों के लिए घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है किन्तु इन विभिन्न क्षेत्रों के मध्य स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता। ये क्षेत्र तथा इनकी क्रियाएँ परस्पर इस प्रकार से सम्बन्धित होती हैं कि उन्हें अलग करना दुष्कर हो जात है।

6 गणना की विधि (Methods of Measurement) - राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू उत्पाद निकालने के लिए अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक ही क्षेत्र में कुछ उपक्षेत्रों के लिए उत्पादन विधि तो कुछ उपक्षेत्रों के लिए आय विधि आदि का प्रयोग होता है। गणना की विधि बदलने से कुल उत्पाद की गणना में कुछ असंगति उत्पन्न हो जाती है।

राजस्थान के घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि के लिए सुझाव

1 कृषि क्षेत्र - राजस्थान में कृषि का विकास करके घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य में सिंचाई सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य में वर्षा के अभाव को देखते हुए फव्वारा सिंचाई, बूट-बूट सिंचाई व सूखी खेती की विधियों का व्यापक रूप में उपयोग किया जाना चाहिये। राज्य में पशुपालन, वन विकास, फल-विकास आदि कार्यक्रमों को

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राज्य घरेलू उत्पत्ति की प्रवृत्तियाँ व संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write ■ short note on Trends and Structure of S D P
- 2 राज्य आय या राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by State Income of State Domestic Product?
- 3 राजस्थान की राज्य आय में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है। समझाईए।
Contribution of Primary Sector is still more in the State Income of Rajasthan Discuss
- 4 राज्य घरेलू उत्पाद की आध्यात्मिकता को स्पष्ट कीजिए।
Explain the concept of State Domestic Product
- 5 राजस्थान के घरेलू उत्पाद की आधुनिक प्रवृत्तियाँ बताईए।
Mention the recent trends of Rajasthan s Domestic Product
- राज्य घरेलू उत्पाद की गणना का महत्व बताईए।
Mention the importance of measuring State Domestic Product

B. निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 'राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं?' राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति एवं संरचना का वर्णन कीजिए।
What do you understand by State Domestic Product? Discuss the trend and structure of State Domestic Product of Rajasthan
- 2 राजस्थान राज्य के घरेलू उत्पाद की संरचना या स्वरूप का स्पष्ट कीजिए। इस संरचना (स्वरूप) में पिछले 30 वर्षों में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं और उनका मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं?
Explain the structure of State Domestic Product (S D P) in Rajasthan State Discuss its changes which have been made in last thirty years and its salient trends
- 3 राजस्थान राज्य की घरेलू उत्पत्ति के अनुमानों की विवेचना कीजिए और उसके ढाँचे में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए।
Discuss the estimates of the Domestic Products of Rajasthan state and critically examine the changes occurring in its structure
- 4 राज्य घरेलू आय पर एक निबंध लिखिए।
Write an essay on State Domestic Product
- राज्य घरेलू उत्पाद की प्रमुख विशेषताओं एवं आधुनिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
Explain the main characteristics and recent trends of State Domestic Product

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

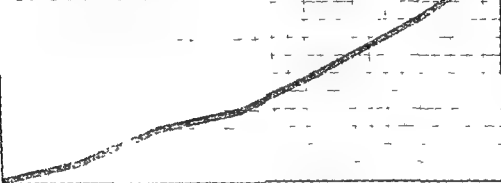
(Questions of University Examinations)

- 1 राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ एवं संरचना समझाईए।
What do you understand by State Domestic Product? Give the trends and structure of State Domestic Product in Rajasthan



पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थाई विकास की समस्याएं

ENVIRONMENTAL POLLUTION & PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT



अध्याय एक दृष्टि में

- पारिस्थितिकी का संतुलन
- प्रदूषण
- विश्व में प्रदूषण की स्थिति तथा पारिस्थितिकी संतुलन के प्रभाव
- भारत में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी संतुलन के प्रभाव
- राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी संतुलन के प्रभाव
- सुस्थिर विकास की अवधारणा
- पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याएं
- अभ्यासार्थ प्रश्न

पारिस्थितिकी संतुलन

ECOLOGICAL BALANCE

मानव पर्यावरण में सदैव से ही रूचि लेता रहा है। इस कारण उसके वातावरण सम्बन्धी ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है कि इसे व्यवस्थित रूप देने के लिए पर्यावरण विज्ञान या पारिस्थितिकी विज्ञान का विकास हुआ। यह विज्ञान इस तथ्य पर टिका हुआ है कि पौधे तथा प्राणी, दोनों ही एक-दूसरे या समन्वित समुदाय के अभिन्न अंग हैं। पारिस्थितिकी (Ecology) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में अर्नस्ट हैकेल (Ernst Haeckel) नामक एक प्रमुख जीव विज्ञानी ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओइकॉस (Oikos) से लिया गया है जिसका अर्थ है 'घर' या 'रहने का स्थान'। इस दृष्टि से पारिस्थितिकी या इकोलाजी में प्राणियों का उनके रहने के स्थान पर अध्ययन किया जाता है।

विश्व में सभी प्राणी एक साथ रहते और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। वे अपने आस-पास के वातावरण से भी सम्पर्क में होते हैं। इस प्रकार ये प्राणी और वातावरण एक-दूसरे के अंग बन जाते हैं। इस तरह की पारिस्थितिकी तरह कहा जाता है। प्राणी के अन्तर्गत जैव और अजैव वातावरण में प्राणियों का निर्माण एवं विनिमय चलता ही रहता है। यह हम

तब के अंतर्गत पदार्थों का चरमीकरण कहलाता है। पारिस्थितिकी तब स्वचालित होता है। यदि वातावरण में कोई भी बदलाव आता है तो जीवों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इससे पारिस्थितिकी सतुलन बिगड़ जाता है। यदि वातावरण में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है तो भी पारिस्थितिकी तब अपनी क्षमता के फलस्वरूप सतुलन को बनाये रखता है। इस भाँति पारिस्थितिकी तब द्वारा परिवर्तन का विरोध करते हुये, सतुलन में बने रहने की प्रवृत्ति को ही पारिस्थितिकी सतुलन कहा जाता है।

मौसम या दुर्भाग्य से मानव मस्तिष्क अत्यन्त विकसित हो चुका है। अपनी क्रियाओं के द्वारा वह पारिस्थितिकी सतुलन को नष्ट करने पर तुला हुआ है और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वह प्राकृतिक सतुलन के स्थान पर अपना कृत्रिम सतुलन स्थापित करने की चेष्टा, जाने या अनजाने में, निरन्तर कर रहा है। मनुष्य में अभी तक वह क्षमता विकसित नहीं हो पाई है जिससे वह पारिस्थितिकी सतुलन के स्थान पर कृत्रिम सतुलन स्थापित कर सके। न ही मनुष्य को इस बात का पूरा ज्ञान है कि वह पारिस्थितिकी सतुलन से जो छेड़छाड़ कर रहा है, भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। भविष्य को पूरा का पूरा जान पाना मनुष्य की क्षमता और योग्यता से बाहर की बात है। इस कारण पारिस्थितिकी सतुलन में बदलाव की कोई भी चेष्टा उसके लिए विनाशकारी मिट्टी हो सकती है, विशेषकर प्रदूषण के माध्यम से इस पारिस्थितिकी तब को तोड़ने का जो प्रयास मानव कर रहा है, वह प्रयास अंततः उसी के लिए घातक होगा।

प्रदूषण

POLLUTION

प्रकृति के पर्यावरण की रचना वायु, पानी, मिट्टी वास्ति, पशु पक्षी एवं समस्त प्राणी जगत् मिलकर करते हैं। ये सभी घटक पारस्परिक सतुलन बनाय रखने के लिए एक - दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जब मानव द्वारा प्रकृति का उपयोग किया जाता है और ऐसा करते समय यदि प्रकृति के सतुलन और विनाश की गति में सामंजस्य नहीं बनाये रखा जाता तो पर्यावरण में ऐसा भीषण असंतुलन उत्पन्न होने लगता है जिससे पृथ्वी पर विद्यमान प्राणियों पर संकट मड़ारने लगता है। इसी असंतुलन से वायु, जल आदि के माध्यम से पर्यावरण की प्राकृतिक जीवन शक्ति में एक विष या घुलन लगता है। प्राकृतिक असंतुलन से उत्पन्न इस घातक विष का नाम प्रदूषण है। ¹ "नैमति इंदिरा गांधी के अनुसार - "यह दु रा की बात है कि प्रगति प्रकृति

पर आक्रमण की पर्यायवाची बन जाए।" इस सदर्भ में ठीक ही कहा गया है, "यदि हम पियानो पर संगीत की भधुर धुन सुनना चाहे तो हमें हमारे दोनों हाथों की दमो अंगुनियों का एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम उन अंगुनियों को क्रमबद्ध न चलाए तो पियानो से निकलने वाली धुन बालाहल में बदल जायेगी। पर्यावरण में जीवन जीने का जो संगीत है, वह भी इसी प्रकार का है।"

स्वच्छ पर्यावरण प्रकृति का अनुशामित व सतुलित रूप है। वह अनुशासन भय होने अथवा सतुलन बिगड़ने से प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतः पर्यावरण या पारिस्थितिकी तब के किसी भी घटक में भौतिक अथवा रासायनिक तत्व जो अन्य घटक (जीव या निर्जीव) पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करें प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण एक ऐसी अवाछनीय स्थिति है जहाँ भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों के द्वारा हवा, जल और धरातल अपनी गुणवत्ता खो बैठते हैं। ये मानव के लिए हानिकारक होते हैं। प्रगति रुक जाती है और सांस्कृतिक जीवन को क्षति पहुँचती है। आजकल मनुष्य स्वयं ही अनेक प्रकार के जहरीले तत्व पर्यावरण में फैला कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वातावरण और वायुमण्डल को दोषपूर्ण बना रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण आधुनिकता की देन है। इसके प्रहार से वायु व जल जैसे जीवनदायी तत्व भी अपने गुण खोने जा रहे हैं। वनस्पतियाँ विनष्ट हो रही हैं और मौसम व स्वभाव बदल रहा है। वस्तुतः प्रदूषण आज की सर्वाधिक ज्वलन्त समस्या है और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है।

प्रदूषण के प्रकार

Forms of Pollution

प्रदूषण की विविधता और इनकी उपस्थिति की विविध परिस्थितियाँ पर्यावरणीय परिवर्तनों व व्यवस्थाओं तथा प्रकृति के तत्वों की सहन सीमा के आधार पर प्रदूषण को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है -

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 वायु प्रदूषण | 2 जल प्रदूषण |
| 3 ध्वनि प्रदूषण | 4 भू प्रदूषण |

(अ) वायु प्रदूषण

Air pollution

यह सभी प्रदूषणों में अधिक हानिकारक प्रदूषण है। पृथ्वी में एक मील ऊपर और एक मील नीचे तक मृष्टि के

लगभग 90% जीव सास लेते हैं। पृथ्वी के इस कटिबंध में उपयोगी गैसों जैसे-ऑक्सीजन, कार्बनडाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि का स्वतंत्र रूप से सतुलन चक्र निरंतर गतिशील रहता है। जनसंख्या के अधिक दबाव, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के कारण यह चक्र असंतुलित होता जा रहा है। डॉ. रघुवंशी के अनुसार- "वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों, जीवन परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक उपक्रमों तथा हमारी सांस्कृतिक संपत्ति का हानि पहुँचे या हमारे प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हो या उसकी हानि पहुँचे, वायु प्रदूषण कहलाता है।" एक सामान्य मनुष्य अपनी सास के माध्यम से 16 किलो हवा रोजाना ग्रहण करने के लिए 22000 बार सास लेता है। अतः मानव जीवन में वायु प्रदूषण का अर्थ मानव जीवन को नष्ट करना ही होता है। इसके एक सटीक उदाहरण का वर्णन करते हुये लिखा गया है "एक सुबह आयी, वह अपकारमय सुबह 3 दिसम्बर 1984 की थी। इस दिन एक भी विडिया नहीं चलती। ऐसा मनाया धिर आया कि घडकन बंद हो गई। अजोब सी तडपन से स्त्री-पुरुष ही नहीं, नहरे मुन्ने जो पल भर रहले मजे से खेल रहे थे, अचानक कराहकर दम तोड़ गये, सब कुछ वीरान हो चुका था। तमाम जानवर गाय, भैंस और बहरिया बुपवास बे-आवाज मौत की गोद में लुटक गये। नहीं यह किसी दैत्य का श्राप नहीं था, किसी जुड़ैल या जिन्न का कानामा नहीं था, न ही किसी दुश्मन से जग छेड़ी थी। यह हैतनाक कहर हमने खुद अपने उमर दावा था। यह हकीकत किसी और देश की नहीं, बल्कि हमारे ही शहर भोपाल की है।" वायु प्रदूषण से होने वाली क्षति की तो यह घटना एक सकेत मात्र है, वास्तविक क्षति का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता।

जब वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है। वायु प्रदूषकों का मिश्रण अनेक प्रकार के से होता है, जैसे - बड़े-बड़े कारखानों की विमिनियों से उठने वाला विषैला धुआँ स्मूटर, कार, ट्रक, बस रेल्वे इजिनो से निकलने वाली गैस व धुएँ भट्टियों व घर में जलने वाले कोयले से निकलता धुआँ, कार्बन डाइ-ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक-ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि से युक्त होता है। मानवोद्योग गतिविधियों से उठने वाली धूल आदि भी हमारे आस-पास की वायु को निरंतर दूषित कर रही है। इससे सास व दिल संबंधी अनेक बीमारियाँ होने का सम्भावना रहता है। मल्फर-डाइ-ऑक्साइड रेफ्रिजेंटों, आखों तथा त्वचा के लिए घातक है। जिन नगरीयों की वायु में केडमियम कणों की

सांद्रता अधिक है, वहाँ हृदय रोग से मरने वालों की संख्या भी अधिक है। जापान के टोकियो शहर में नद्यों से इतनी अधिक मात्रा में धुआँ निकलता है कि फ्यूजी पर्वत वर्ष में केवल 40 दिन ही दिखाई देता है।

वायु प्रदूषण के कारण Causes of Air Pollution

1 प्राकृतिक कारण (Natural Factors) - वनों में आग लगने के कारण उत्पन्न धुआँ तथा लूणत व आंधी के कारण उड़ती हुई धूल और ज्वालामुखियों में निकली राख आदि के कारण वायु प्रदूषित होती है। दलदल भी वायु को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक कारणों से हुये वायु प्रदूषण का मानव समाज पर प्रभाव बहुत कम होता है, क्योंकि यह प्रदूषण बहुत कम होता है और प्रकृति स्वयं ही कुछ समय में इसका उपचार कर लेती है।

2 उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण (By Industries)
औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। उद्योग वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। वस्त्र उद्योग, धातुकर्म, सब्जियों उद्योग, रासायनिक उद्योग, तेल-शोधन उद्योग, गन्ना उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग तथा शक्कर उद्योग आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इन उद्योगों द्वारा त्यागों गई गैस, धुआँ आदि वायुमंडल में पहुँचकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। उद्योगों के कारण अमेरिका का वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। वहाँ स्कूलों के खुले मैदानों पर लिखी यह चेतावनी, "सावधान! अत्यधिक धुएँ की स्थिति में कमरबंद न करें या गहरी सास न लें।" वायु प्रदूषण का स्पष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार जापान के टोकियो शहर के आस-पास की अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण जालीदार मुखाँटा पहनकर स्कूल जाता पड़ा है। भारत में मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर आदि शहरों में उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है।

23 दिसम्बर, 1984 की मध्याह्न में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड के कारखाने के एक मजदूर से दुर्घटना के कारण निकली गैसों से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस घटना को "भोपाल गैस त्रायदे" की मज्जा दी जाती है। सरकारों आकांक्षों के अनुसार इस घटना में लगभग 2000 व्यक्ति मारे गये। उस रात भोपाल ने माने एक गैस चैम्बर का रूप ले लिया था। लोग कोठे-मनोको की तरह मर रहे थे।

3 वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण (By Vehicles)
आधुनिक वाहनों जैसे - मटरकार, बस ट्रक स्मूटर आदि

में पेट्रोल व डीजल आदि ईंधनों का प्रयोग होता है जिनके जलन में निचला धुआँ वायु को प्रदूषित करता है। वाहनों के धुएँ में विभिन्न प्रकार का जहरीला गैस होती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। 1952 में लंदन शहर वायु प्रदूषण के कारण भूरा रा के रासायनिक धुएँ की हरी चादर में 5 दिनों तक घिरा रहा। इससे लगभग 4000 व्यक्ति का मृत्यु हो गई और अनेक लोग श्वसन व हृदय रोग में पीड़ित हो गए। जपान की राजधानी टोकियो में वाहनों से इतना अधिक वायु प्रदूषण होता है कि यातायात निषाह का थोड़ी-थोड़ी दूर में आक्रमेण ग्रहण करने के लिए आक्साजन मशीनों के पाम जाना पड़ता है। भारत के सभी बड़े शहरों में भी वायु प्रदूषण की समस्या निरंतर उभार हाता जा रही है।

4 घरेलू कार्यों से वायु प्रदूषण (By Domestic work) भाजन पकाने व पाना गरम करने जैसे घरेलू कार्यों में कायला मिट्टी का तल गैस आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके कारण उत्पन्न धुएँ में कार्बन डाई-आक्साइड, सल्फर डाई-आक्साइड और कार्बन-मोनो आक्साइड आदि गैस होती है जो वायु को प्रदूषित करता है। दहन प्रक्रिया में वायु को आक्साजन भी उपयोग में लाई जा रहा है। अतः इससे वातावरण में आक्साजन का मात्रा कम हो जाता है। घरेलू कार्यों में उत्पन्न धुएँ के कारण वायु प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण सम्मेलन (1972) में कहा गया था "ईंधन की लकड़ा गादर कड़ खेतों का कचरा और घास घूम आदि जलन में कार्बन मोनो-आक्साइड, सल्फर डाई-आक्साइड, नाइट्रोजन-आक्साइड, ओजोनिकम आदि तत्व निकलते हैं व (अन्य तत्त्वों की तुलना में) बहुत ज्यादा है।"

5 ताप विजलाघरो से वायु प्रदूषण (By Thermal Power Stations) ताप विद्युतगृह में अत्यधिक मात्रा में कायल का प्रयोग होता है। इसमें उत्पन्न धुएँ में सल्फर डाई-आक्साइड आदि गैस होता है। कोयले की राख का प्रायः दहल फेंक दिया जाता है जो वायु को प्रदूषित करती है। उदाहरण के लिए बक्सर जिल्ला में इन्द्रप्रस्थ स्थित ताप विद्युतगृह में प्रतिदिन 45 टन कार्बन 60 टन सल्फर डाई-आक्साइड और 85 टन फ्लाई एश आदि व्यर्थ उत्पन्न होता है। भाग में यह वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है क्योंकि देश के अधिकांश ताप विद्युतगृह कायल में ही चलते हैं। विद्युतगृह से निकल व्यर्थ पदार्थों का फैकन का सम्मान भी गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

■ कृषि कार्यों से वायु प्रदूषण (By Agricultural Works) आधुनिक युग में फसलों को कुकान पट्टान

वाले कीटों आदि को सम्पत्त करने के लिए कीटनाशक औषधियों का छिड़काव किया जाता है। ऐसा छिड़काव वायुयानों के द्वारा भी किया जाता है। अतः इस छिड़काव से विषैले रसायन वायुमण्डल में फैल कर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त खेतों का कचरा जलन व अनाज साफ करने आदि से भी कुछ मात्रा में प्रदूषण होता है।

7 दुर्घटना से वायु प्रदूषण (By Accident) दुर्घटना के कारण होने वाला वायु प्रदूषण प्रत्येक की ही स्थिति उत्पन्न कर सकता है क्योंकि रसायन कारखाना, आगविक स्टेशन व आयुध निर्माण करने वाले कारखानों में इतनी अधिक विषैली सामग्री होती है कि थोड़ी सी गलती के कारण हुई दुर्घटना से जल जीवन अस्तव्यस्त हो सकता है। भापाल गैस त्रासदी इसका उदाहरण है। इस गैस काण्ड में यहाँ की वायु इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इस सुधार में बहुत समय लगगा।

8 रेडियोधर्मी प्रदूषण (Radio Activity) परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण हेतु किया जा सकता है लेकिन अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में इस शक्ति का प्रयोग करके जर्मन व जापान की व हिरोशिमा को क्षमभर में टो बमोस नष्ट कर दिया। इसमें अनेक किलोमाटर तक समस्त वनस्पतियाँ व जीव जंतु समाप्त हो गए और लाखों व्यक्ति मृत्यु के शिकार हुए। इस विस्फोट का प्रभाव आज तक विद्यमान है। इस मरघट में आईन्स्टीन ने कहा था "मानव परमाणु शक्ति का दायर नहीं है। विस्फोटक व रेडियोधर्मी किरण निकलता है जो वायु तथा जल तरंगों द्वारा बहुत दूर-दूर तक फैल जाती है और रेडियोधर्मी प्रदूषण पैदा करता है। इस विकिरण के प्रभाव से जावधारियों का सताने विकृत पैदा होता है। यह विकिरण पौधों तथा जानवरों में होकर मानव शरीर में पहुँचकर स्थिर तौर पर क्षति पहुँचता है।

9 अन्य कारण (Others) वायु प्रदूषण के अन्य महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं।

- (1) महानगरों की स्थिति व विस्तार वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है।
- (2) कचरे का एकत्रित कर जलन में उत्पन्न धुएँ व कारण वायु प्रदूषण होता है।
- (3) त्यौहार व विवाह के अवसर पर पटाखे आदि जलाने से रासायनिक गैस व धुएँ के कारण वायु प्रदूषित होता है।
- (iv) सड़क पट्टियाँ व पतियाँ के कारण भी वायु प्रदूषित होती है।
- (v) परम्परागत ऊर्जा परियोजनाओं के कारण भी वायु

प्रदूषित होती है।

- (vi) कच्ची सड़कों पर आवागमन के कारण वायु प्रदूषित होती है।
- (vii) धूँधराय में भी वायु प्रदूषित होती है।
- (viii) मार्वाजनिक स्थानों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था न होने के कारण वायु प्रदूषित होती है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय Remedies

- 1 घरेलू कार्यों के लिए धुआररहित ईंधन जैसे- विद्युत हीटर, कुकिंग गैस आदि का उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- 2 उद्योगों में कम प्रदूषण वाले तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- 3 कोयला से चलने वाले रेल इंजनों के स्थान पर विद्युत इंजनों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- 4 कारखानों की धिमनियों की ऊँचाई पर्याप्त होनी चाहिये ताकि आम-जन के क्षेत्रों में कम से कम प्रदूषण हो।
- 5 वाहनों का उपयोग मितव्ययतापूर्वक किया जाना चाहिये तथा पुराने वाहनों को मुख्य मार्गों पर चलाने की पाबंदी लगा देनी चाहिये।
- 6 वाहनों के धुएँ का एक निश्चित स्तर तक सीमित रखने के लिए सरचिन्त कानून बनाया जाना चाहिये।
- 7 नवीन तकनीक के द्वारा ऐसे वाहनों का निर्माण किया जाना चाहिये जिनमें कम-से-कम प्रदूषण हो। भारत में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार ने 1981 में वायु प्रदूषण (निवारण व नियंत्रण) अधिनियम पारित किया। इसके अतिरिक्त अनेक अनुसंधान व शोध संस्थानों में वायु प्रदूषण से सम्बंधित शोध कार्य भी चल रहे हैं।

(व) जल प्रदूषण Water Pollution

यह ज्ञात होना आवश्यक है कि पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल है। स्थानीय भू-संरचना एवं स्थितियों के अनुसार जल में विभिन्न लवण घुले रहते हैं। कठोर-कागखानी द्वारा प्रयोग के बाद प्रवाहित जल में अनेक लवण क्षार एवं विभिन्न गैसें घुल जाती हैं जो जल को दूषित कर प्राणी मात्र की शारीरिक क्रिया पर दुष्प्रभाव डालने लगती हैं। पोषे के अनुसार- "प्रत्येक वस्तु जल में ही उत्पन्न हुई है तथा प्रत्येक वस्तु जल द्वारा ही प्रवेचित होती है।" संश्लेष में जल के बिना जीवन संभव भी नहीं है। मानव स्वतः का 80% भाग भी पानी ही है। यह मानव शरीर में परिपक्व करते हुये मानव का शरीर को स्वस्थ रखता है। जब जल में किसी

बाहरी अवाञ्छित पदार्थ का प्रवेश होने से उसके गुणों में कमी आ जाती है तो वह जल प्रदूषण की स्थिति में होता है। औद्योगिक एवं कृषि अवशिष्ट, तेल आदि पदार्थ जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। जल प्रदूषण से मानव तो प्रभावित होता ही है, पोषे व जलीय जीव भी नष्ट हो जाते हैं। डॉ. रघुवर्षा ने जल प्रदूषण का अनेक दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है

- (अ) "प्राकृतिक जल में किसी अवाञ्छित बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल को गुणवत्ता में अवनति आती हो जल प्रदूषण कहलाता है।"
- (ब) "विशिष्ट रूप में किसी जलाशय का प्रदूषण की परिभाषा उसमें ऐसे लक्षणों वाले पदार्थों के प्रवेश तथा इतनी मात्रा में प्रवेश से ये आ सकती है जो उसे दिखावट, गंध या स्वाद में आणविकरूपक बना दें।"
- (ग) "जल में किसी ऐसे बाहरी पदार्थ अथवा लक्षण की उपस्थिति को जल प्रदूषण कहते हैं जो उसके गुणों को इस प्रकार प्रभावित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाये अथवा उसकी उपयोगिता कम हो जाये।"
- (द) "मानवकृत परिवर्तनों से जल की वास्तविक अथवा सभावित उपयुक्तता में क्षतिग्रस्त हो जल प्रदूषण है।"
- (य) "जल में किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का योग जो जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को प्रभावित कर, उसे उपयोग विशेष के लिए अनुपयुक्त बना दे जल प्रदूषण कहलाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर जल प्रदूषण को चार भागों में बाँटा जा सकता है -

- 1 भौतिक प्रदूषण इससे जल की गंध, स्वाद व ऊष्मीय गुण में परिवर्तन हो जाता है।
- 2 रासायनिक प्रदूषण यह मुख्यतः जल में विभिन्न उद्योगों से मिलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण होता है।
- 3 जैव प्रदूषण यह जल में विभिन्न रोगजनक जीवों के प्रवेश के कारण होता है। इसमें जल मानव के लिए उपयोगी नहीं रहता है।
- 4 शरीर क्रियात्मक प्रदूषण इसका आशय जल के गुणों में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो मानव शरीर की क्रियाविधि को हानि पहुँचाते हैं।

जल प्रदूषण के कारण Causes of Water Pollution

- (1) घरेलू कार्यों में जल प्रदूषण (By Domestic works) - घरेलू कार्यों (खाना पकाना, नहाना, धोना, सफाई

आदि) से जल प्रदूषित होता है। फल व सब्जियों के छिलके, चूल्हे की राख, कूड़ा-करकट, कपड़ों के टुकड़े गढ़ा जल आदि नालियों में बहा दिये जाते हैं। ऐसे जल को मलिन जल कहा जाता है। यह जल जब नालियों द्वारा जलस्रोतों में मिल जाता है तो वहाँ के जल को भी दूषित कर देता है। घरों में मच्छरों आदि के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इससे जल में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। ऐसे पदार्थ यदि किसी जलस्रोत में पहुँच जाते हैं तो वहाँ काफी समय तक बने रहते हैं।

2 मलमूत्र से जल प्रदूषण (By Human waste) - घरेलू व सार्वजनिक शौचालयों से निकला हुआ मलमूत्र व जल नालियों के द्वारा किसी जल स्रोत में मिलता है तो गंभीर जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। ऐसे प्रदूषण को जैवीय प्रदूषण कहा जाता है। ऐसे जल से टाइफाइड बुखार, पोलियो, हैजा, पेचिश व आंत्रशोथ आदि रोग हो जाते हैं। यह जल तार्वार रोग को भी बढ़ावा देता है। उष्ण कटिबंधीय राष्ट्रीयों में इस रोग से लगभग 35 करोड़ व्यक्ति ग्रसित हैं। विश्व की अधिकांश नदियाँ व झील, महानगरों से निकले हुये गंदे जल व मल-मूत्र से कूड़ापात्र बन गयी हैं। अनेक नदियाँ व झीलें तो इतनी अधिक प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनमें मछलियों का जीवन दूभर हो गया है।

3 उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण (By Industries) - अधिकांश उद्योगों में जल का अत्यधिक उपयोग होता है। ऐसे उद्योग प्रायः नदियों या जलाशयों के किनारे स्थापित किये जाते हैं। इन उद्योगों का व्यर्थ जल को नदियों व जलाशयों में ही बहा दिया जाता है जिससे उनका जल प्रदूषित हो जाता है। यही कारण है कि भौगोलिक प्रगति के साथ-साथ जलस्रोत गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुके हैं। उद्योगों से निकले व्यर्थ जल में पारा व लवण जैसे पदार्थ अत्यधिक मात्रा में होते हैं, जो अनेक रोगों को ब्रम्ह देते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार टन पारे का उत्पादन होता है, लेकिन इसमें से लगभग 5 हजार किसी-न-किसी रूप में पर्यावरण में प्रविष्ट हो जाता है। मिनीमेटा खाड़ी की दुर्घटना पारा विषकरण की घटना का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह खाड़ी जापान के समुद्री तट की खाड़ी है। 1950 में इस क्षेत्र के मछुआरों मछलियों का उपयोग करने से, अचानक अनेक रोगों से ग्रसित हो गये थे।

4 कृषि कार्यों से जल प्रदूषण (By Agricultural work) - दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण मिट्टी के कटाव को बढ़ावा मिलता है, वर्षा होने पर ऋतु के साथ मिट्टी बहकर नदियों व जलाशयों में पहुँच जाती है जो न केवल

जल को प्रदूषित करती है, बल्कि जलमार्गों को भी अवरुद्ध कर देती है। उर्वरकों व कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से भी जल प्रदूषित हो जाता है। रैचल वारस ने अपनी पुस्तक 'साइलेन्ट स्प्रिंग' में लिखा है, 'हमारे द्वारा बिना विचार किये जाने वाले कीटनाशक औषधियों के अफ़ापुध लगातार उपयोग से एक वर्ष ऐसी बसंत ऋतु आ सकती है, जिसमें एक भयावह स्तब्धता व्याप्त हो। उदाहरण के लिए, सब चिड़िया कहा गई, लोग उनके बारे में चिन्तित होकर आपस में यह पश्न पूछेंगे।'

5 तापीय प्रदूषण (Thermal pollution) - अनेक रिफ़क्टोरे के अति-तापन के निवारण हेतु नदियों व जलाशयों के जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से गर्म हुआ जल पुनः नदियों व तालाबों में छोड़ दिया जाता है जिससे नदियों व तालाबों का जल प्रदूषित हो जाता है। इसे तापीय प्रदूषण कहा जाता है। इससे जलस्रोतों के जल का तापमान भी बढ़ जाता है। परमाणु शक्ति चलित विद्युत उत्पादक मयूत्रों में भी तापीय प्रदूषण होता है।

6 तैलीय प्रदूषण (Pollution by Oil) - विभिन्न उद्योगों से निकले तेल व तैलीय पदार्थों के जल स्रोतों में मिलने से तैलीय प्रदूषण होता है। अमेरिका की क्वारोगा नदी में इतना अधिक तैलीय प्रदूषण हो चुका है कि इसे ज्वलनशील नदी कहा जाता है। समुद्र में तेल प्रदूषण की संभावना अधिक रहती है। जलयानों द्वारा व्यर्थ पदार्थ का त्याग, तेलवाहक जहाजों में दुर्घटना तथा समुद्र में तेल की खोज आदि कारणों से तेल प्रदूषण बढ़ता है। इराक - अमेरिका युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में खनिज तेल के फैलाव के कारण वहाँ का जल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। इससे समुद्री जीवों का जीवन दूभर हो गया है।

जल प्रदूषण निर्वन्त्रण के उपाय

Remedies

- 1 गंदे जल को नदियों व जलाशयों में मिलने नहीं दिया जाना चाहिये।
- 2 पेयजल स्रोतों के चारों ओर दीवार बनानी चाहिये, ताकि गढ़ा जल प्रवेश न कर पाये।
- 3 नदियों व तालाबों में पशुओं को नहलाने पर रोक लगा देनी चाहिये।
- 4 जल स्रोतों में नहर व बंध धोने पर रोक लगा देनी चाहिये।

■ घरों में निकलने वाले गंदे जल को साफ़ करने के पश्चात् ही जल स्रोतों में छोड़ा जाये।

- 6 कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं किया जाना चाहिये।
- 7 जल स्रोतों के निकट उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिये तथा पहले से स्थापित उद्योगों के व्यर्थ जल को शोधन के पश्चात् ही जल स्रोत में छोड़ना चाहिये।
- 8 जनसाधारण को जल प्रदूषण के रोकथाम की विधियों की जानकारी दी जानी चाहिये।
- 9 समय समय पर जल स्रोतों की सफाई की जानी चाहिये।
- 10 ऐसे मछलियाँ जिन स्रोतों में छोड़ी जानी चाहिये जो विपरीत जीवों (सर्पों व मछुनों के अंडे आदि को) भक्षण करते हों।

भारत में जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1974 के अनुसार एक केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई है। अनेक राज्यों में भी ऐसे मंडलों की स्थापना की गई है। 1981-90 के दशक को भारत सरकार ने 'अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल व स्वच्छता दशक' के रूप में मनाया था।

(स) ध्वनि प्रदूषण

Noise Pollution

कल-कारखानों, वातायत आदि के कारण उत्पन्न शोर पर्यावरण की शान्ति को भंग करता है व मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। "ध्वनि प्रदूषण" शब्द ही मानव के कार्य आराम नींद व वार्तालाप में व्यवधान डालता है। यह मानव की श्रवण शक्ति को नुकसान पहुँचाता है तथा उसमें अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक व शारीरिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं। किन्तु ध्वनि प्रदूषण की जटिल प्रकृति विभिन्न प्रकार एवं इससे अन्य पर्यावरणीय तत्वों से अन्तर्सम्बन्ध व कारण स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव को आसानी से नहीं जाना जा सकता। यह तो मूल्य है कि यदि व्यक्ति बहुत देर तक गल में रहे तो कुछ शारीरिक व मानसिक दानियाँ पर कर लगे हैं। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार - शरणनक्षत्र में 35 डेसिबल, बाहरी वातावरण में 55 डेसिबल तथा सभागा कक्ष व कक्षाओं में 45 डेसिबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिये। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गये एक अध्ययन से डाढ़ हुआ कि शोर के कारण व्यक्ति में श्रवण शक्ति के घटने के अतिरिक्त पौष्टिक अल्पता व तनाव आदि भी विकसित हुये। इस प्रकार मनुष्य के लिए अवांछित ध्वनि है। नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक राबर्ट कॉंग का इस संदर्भ में यह कथन किताब सत्य है कि "एक दिन ऐसा आया जब मनुष्य के स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु

के रूप में निर्दयी शोर से सर्वप्रथम करना पड़ेगा।"

अवांछित तेज आवाज जो मानव की श्रवणशक्ति, स्वास्थ्य व आराम को घट्टाती बनाती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण नगरीकरण की देन है। मोटर-कारों, उद्योगों आदि के कारण उत्पन्न शोर मानव जीवन के लिए हानिकारक मिद्ध हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण का मानव की नाडियों पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उसमें हृदय रोग, रक्तचाप आदि कष्ट होने की प्रबल सम्भावना रहती है। विश्व के महानगर ध्वनि प्रदूषण से इतने आक्रांत हैं कि एक बड़ी जनसंख्या बहरी होती जा रही है। डॉ. समुअल रोजन ने ठीक ही कहा है, "आप चाहे शोर का क्षमा कर दें पर आपकी घमनिया नहीं करेगी।" शोर की अधिकता से वार्तालाप में विघ्न, कार्यक्षमता में कमी, सन्तानहीनता आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। डॉ. लेविस सोन्टेन के अनुसार - अजन्मे बच्चे पर भी ध्वनि प्रदूषण के घातक प्रभाव हो सकते हैं। प्रबल तीखे शोर द्वारा अजन्मे भ्रूण का समूचा आवरण तथा जीवन के भावी समायोजन का तरीका तक परिवर्तित किया जा सकता है। वस्तुतः शोर मनुष्य को समय से पूर्व खे बूढ़ा कर देता है।

ध्वनि प्रदूषण के कारण

Causes of Noise Pollution

1 **प्राकृतिक कारण (Natural Factors)** बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, भूकम्प व ज्वालामुखियों से उत्पन्न ध्वनियाँ, तूफानी हवाएँ तथा पहाड़ों से तीव्र गति से जल गिरने की ध्वनि आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है लेकिन यह शोर क्षणिक होता है, अतः बहुत अधिक हानिकारक नहीं होता है।

2 **उद्योगों व मशीनों से ध्वनि प्रदूषण (Industry & Machines)** - आधुनिक युग में कल-कारखानों में विशाल मशीनों व यंत्रों के प्रयोग के कारण शोर प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। इसमें मजदूर व सर्वोधिक प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण व सड़क निर्माण आदि कार्यों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

3 **परिवहन के साधनों से ध्वनि प्रदूषण (Means of transportation)** - सड़क परिवहन के अंतर्गत मोटर-कार, बस, ट्रक, रेल व स्कूटर आदि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। महानगरों में यातायात बढ़ने के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। सबसे अधिक शोर ट्रकों व भारी वाहनों से होता है। हवाई अड्डों के आस पास वायुयानों का शोर अत्यधिक तीव्र होता

है। जैट विमानों तथा सुपरसोनिक विमानों का शोर क्षेत्र में अधिक व्यापक होता है।

4 मनोरंजन के साधन व सामाजिक कार्यों से ध्वनि प्रदूषण (Entertainment & social work)

ध्वनि जो किसी मानव के लिए आनंददायक होती है, किसी दूसरे के लिए शोर सिद्ध हो सकती है। कुछ लोग नेत्र आवाज में गैडियों व टेप अदि सुनते हैं जो इसमें ध्वनि प्रदूषण होता है। सामाजिक उत्सवों में प्रायः तेज आवाज में संगीत व भजन प्रसारित करने का प्रचलन है। विभिन्न अवसरों पर पटाखे भी चलाये जाते हैं, जो भीषण व कर्कराशी शोर उत्पन्न करते हैं। चुनाव व हड़तानों के समय तेज आवाज में लाउडस्पीकर्स के द्वारा भाषण दिये जाते हैं। इन सबमें शोर बढ़ जाता है जो मानव के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

Remedies

- 1 पुराने वाहनों के मुख्य मार्गों से निकलने पर रोक लगा देने चाहिये।
- 2 कारखानों की स्थापना शहरों में पर्याप्त दूरी वाले स्थानों पर की जानी चाहिये।
- 3 वाहना में तेज ध्वनि एवं बहुरध्वनि वाले हॉर्न पर रोक लगाई जानी चाहिये।
- 4 उठावों से उत्पन्न शोर कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- 5 मशीनों के सगे गड़गड़ाव में शोर को कम किया जा सकता है।
- 6 जिन कारखानों में शोर में कमी करना अशभव हो, वहां के श्रमिकों के लिए पूर्ण श्रवण व कर्ण बन्दकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिये।
- 7 विमानों को विशेष दाय पर उतारना जाना चाहिये तथा हवाई अड्डों पर अधिकतम शोर सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।
- 8 कार्यालयों व आवासभूतों में उचित निर्माण सामग्री व उपायुक्त स्लाबट में शोर का कम किया जाना चाहिये।
- 9 ध्वनि प्रदूषण का गंभीरता से अनुसंधान कर शोर को कम किया जाने चाहिये।

(द) भू- प्रदूषण

Land Pollution

शब्द भूमि में मिट्टी व स्थलाकृतिक का सम्मिलित किया जाय है, लेकिन मिट्टी दृष्टिकोण से अनुसार इनमें किसी स्थान विशेष के सभी भौतिक लक्षणों का समावेश

किया जा सकता है। हेनरी प्रैडिक एमिल के अनुसार- "कोई भी दृश्य भूमि आत्मा की स्थिति की ही अभिव्यक्ति है।" जब भूमि में प्रदूषित जल रसायनयुक्त कीचड़, कूड़ा, कीटनाशक दवा और उर्वरक अत्यधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें भूमि की गुणवत्ता घट जाती है। इसे भू-प्रदूषण कहा जाता है। भू- प्रदूषण की घटना भी आयुनिकता की देन है। डॉ. खुबशी के शब्दों में "भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भू-प्रदूषण कहलाता है।" पृथ्वी के धरातल का लगभग चौथाई भाग ही भूमि है, लेकिन इसका केवल 280 लाख वर्ग मील क्षेत्र ही आबाद व उद्येती योग्य भूमि के रूप में है। अतः पृथ्वी पर उपयोग योग्य भूमि सीमित है। हर दृष्टि में मानव का भूमि के प्रति दृष्टिकोण समझदागी पूर्ण होना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं है। मानव अनेक प्रकार से भूमि को प्रदूषित कर रहा है अतः भू-प्रदूषण मानव का भूमि के प्रति अविवेकपूर्ण व्यवहार का ही एक उदाहरण है।

वायु में भू-प्रदूषण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। मेगिस्थान में टीनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु के वेग में स्थानान्तरण एक सामान्य गति है। अधिः आर्द्रता व वर्षा वाले क्षेत्रों में भू-भरण हो जाता है। वायु के वेग से भूमि की कई ऊपरी परतें अपने स्थान से मोलते दूर चली जाती हैं। अतः भू-प्रदूषण तीव्र गति से होता है।

भू-प्रदूषण के कारण

Causes of Land Pollution

1 **कीटनाशक व उर्वरक (Pesticides & fertilizers)** - कीटनाशक व उर्वरक भू-प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इनके प्रयोग से फसलों की प्रतिक्रिया हो जाती है, लेकिन जब ये तत्व भूमि में एकत्रित हो जाते हैं तो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं। इससे मिट्टी का तापमान प्रभावित होता है और उसके पोषक तत्वों में गुण कम हो जाते हैं। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या व क्षति के व्यापक प्रयोग व साथ-साथ कीटनाशकों व उर्वरकों के प्रयोग में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार कीटनाशक अपना रूप बदल कर फसलों में हानि द्यमान मानव के शरीर में पहुँच रहे हैं और स्वास्थ्य का भी प्रभाव रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष कीटनाशक से मरण पा जाते हैं।

2 **घरेलू अपशिष्ट (Domestic waste)** - कूड़ा-कचरा गन्ना कूड़ा-कचरा पनिया गन्ना अपशिष्ट लकड़ों, कागज व चोना मिट्टी के टूट हुए घर्तन, चुन्दी की

गल कगड क टुकड टान क डिब्ब मडें गल पन व मन्त्रिया अडा क छिलक आदि अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ मिट्टी म मिलकर भू-प्रदूषण का बढावा दते है। भारत के शहरी क्षेत्र म एस अनेक पदार्थों का मात्रा लाभम डढ कगड टन प्रतिवर्ष हाता है। मुस्तफा कमाल तोस्त्वा के अनुसार गंगव दश अर्न्तस्थाय कचरा टाकरिया बन गये है।

3 औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial waste) उद्योगों स निकले व्यर्थ पदार्थ किमी न किसा रूप म भू प्रदूषण का कारण बनते है। ये पदार्थ ज्वलनशाल विधैल व दुर्गन्धयुक्त हात है और स्थान घात है। उद्योग क प्रबन्धक इन पदार्थों वर यू ही भूमि पर फैंक दते है। अत औद्योगिक क्षेत्रों के आस पास व्यर्थ पदार्थों का ढेर लग जाता है। वर्षा जल के साथ बहकर आये ये पदार्थ दूर-दूर तक का भूमि का प्रदूषित कर दते है अत भूमि की गुणवत्ता म क्या हान लगता है। विकसित राष्ट्र के महानगरों का कृषि भूमि इतनी अधिक प्रदूषित हो गई है कि वहा विकास क प्रति आन्दोलन उभरने लगा है।

4 नगरपालिका अपशिष्ट (Municipal waste) इसके अतगत मुख्यत कूड़ा-करकट मानव मल सब्जा बाजार क मड गल पन व मन्त्रिया का कचरा बाग-बगीचा का कचरा उद्यान मडका नालिया व गन्ना का कचरा मांस व मछली बाजार का कचरा मर हुये जानवर व यमशाधन का कचरा आदि का सम्मिलित किया जाता है। इन मलमूत्र म प्रदूषण हाता है इन अपशिष्टों क समुपन व व्यवस्था क लिए नगरपालिकाओं का अत्यधिक धन भा व्यय करना पडता है।

5 अन्य कारण (Other Causes)

- कृषि अपशिष्ट (वर्षा घास घूस तथा उवरक और कम्पनागज औषधियों) क कारण भा भू प्रदूषण हाता है।
- नगा का कम व अधिकता से भी भूमि प्रदूषित होता है एस स्थिति म लवण का मात्रा बढ जात है अत भूमि म ऊसर क गुण आ जात है।
- भू प्रदूषण क लिए कुछ सूक्ष्म जीव भा उत्तरदायक हात है इनका वैक्यारिया प्रमुख है।

भू प्रदूषण नियंत्रण क उपाय

Remedies

- एक पदार्थ व अपशिष्ट क समुपन निम्न किया जात है।
- बाग बाग म डढा व बिडो एन्ड्रि तथा डालडन

(3) नागरिकों को चाहिये कि वे कूड़ा-करकट मडक पर न फेंके।

(4) अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना चाहिये।

(5) अपशिष्टों के निक्षेपण को प्रारम्भिकता दी जाना चाहिये।

(6) नागरिकों में सफाई क प्रति चेतना जागृत करना चाहिये।

(7) भू-सरण को रोकने के उपाय करने चाहिये।

विश्व में प्रदूषण की स्थिति तथा पारिस्थितिकी सतुलन के प्रयास

POLLUTION IN THE WORLD AND EFFORTS FOR ECOLOGICAL BALANCE

स्थिति

Position

विश्व बैंक के एक शोध पत्र आदामोदिव एयर पाल्यूशन इरयूब एण्ड अप्रसा फार डैवलपिंग कंट्रास क अनुसार तासरी दुनिया क देशों में तेजी म शहरीकरण और मोटरवाहनों का सख्या बढने से प्रदूषण खतरनाक मामा तक पहुच रहा है और सन् 2000 तक इन देशों क कुछ बड शहरों में प्रदूषण अब से दानु हा जाएगा।

शोध पत्र क अनुसार विश्व जनसंख्या 1985 ई का 4 अरब 800 लाख से बढकर 2000 ई तक 6 अरब हो जाने का अनुमान है जिसका अधिकतर वास्तविक विकासशाल देशों पर पडता। सन् 1985 में विश्व म एक कगड से अधिक जनसंख्या वाल 12 महानगर थे जिनमें से आठ महानगर विकासशाल देशों में थे सन् 2000 तक इनका सख्या दानु हो जाने क संभावना है मोटरवाहनों का सख्या भा इन्ना अनुपात म बढेगा। यदि समय रहत इनके कारण वयु प्रदूषण रोकने क लिए कदम नते उठाये गये तो इस शब्दा क अन्त तक तासरी दुनिया के 40 कगड से अधिक ला खतरनाक हो तक प्रदूषण से प्रभावित हा।

शोध पत्र क अनुसार अध्ययन से दह पन्ने चला है कि तासरी दुनिया क बढते म मोटरवाहन म मटोरोडिदा म निकलने वाल गैसोसिन हानिकारक पदार्थों का मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्देशित मुद्रित नाम म नहु अधिक है य शहर है मुम्बई मस्मका सिंग साओ पाउलो लास वैक क बर्मास मनला साल गंगरा बर्मास तहान बनारस दुहापूर और इम्फाल मस्मका

6 जनवरी 1993 को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार मालदीव का एक छोटा टापु समुद्र के गर्भ में विलीन हो गया। मालदीव में 1,196 टापु हैं और इनमें से कई सागर सतह से कुल 2 से 4 मीटर ऊपर हैं। ग्लोबल उष्ण प्रभाव से विश्व के औसत तापमान में बढ़ोतरी होने से ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ अधिक पिघलती है जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। पिछली एक शताब्दी के दौरान समुद्र के जल स्तर में केवल 15 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हुई थी पर वर्तमान दर के अनुसार सन् 2075 तक यह 30 से 219 सेंटीमीटर हो जायेगी। इससे बांग्लादेश, मालदीव, अमेरिका के तटवर्ती प्रदेश, नील डेल्टा, बंगाल, उड्डोसा के तटप्रदेश सभी जलमग्न हो सकते हैं। बांग्लादेश का आधा भाग मानर तट से केवल 4.5 मीटर ऊपर है और सन् 2100 तक इसका 34% भाग जलमग्न हो सकता है। विश्व के कुछ प्रमुख नगर जैसे- न्यूयार्क, लंदन, बंबई, कोचीन, मद्रास, गोआ के तट आदि अनीत के गर्भ में डूब जायेंगे।

जनवरी, 1993 में बंगाल की खाड़ी में निक्वेनर द्वीप समूह के पास डेनमार्क के एक तेलवाहक जहाज को दुर्घटनाग्रस्त होने से इस क्षेत्र के समुद्रीय जीवन के लिए गंभीर खतरा हो गया। जहाज में तीन लाख टन तेल लदा था। इसकी एक बड़ी मात्रा समुद्र के जल से रिम गयी और इस तेल की पतल को नष्ट करने के लिये विशेष अपमार्जकों (डिटरजेंट) का छिड़काव किया गया। इस क्षेत्र में अनेक दुर्लभ समुद्री जीव-जन्तु व पौधे पाये जाते हैं। इनको तेल की मोटी परत से नुकसान होता है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार- हाल के वर्षों में बंगाल की खाड़ी समुद्री जहाजों के लिए एक बड़े कूड़ा-बर्तन का काम दे रही है। जला हुआ स्नेहक, भट्टी का तेल और अन्य फलान सामान वहाँ फेंक दिया जाता है। इससे सुन्दर वन के तटों तथा समुद्री मछलियों के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है।

6 अप्रैल 1993 को साइबेरिया के टॉमस्क-7 नामक नगर में एक भूमिगत स्टोरेज टैंक में रखे रेडियोधर्मी उत्सृष्ट पदार्थ विशेषकर यूरेनियम के मलबे में विस्फोट होने से एक बार फिर परमाणु विकिरण में पर्यावरण के प्रति गंभीर खतरे की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। स्मरण रहे कि 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर में भयंकर दुर्घटना हुई थी। इससे न केवल आसपास के भू-भाग में भारी विनाश हुआ बल्कि दुर्घटना के कई दिन बाद तक आस-पास वातावरण यूरोप के बड़े हिस्से में छये रहे और पर्यावरण मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण पशुओं और पौधों की अनेक प्रजातियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। भारत में समय-समय पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में गड़बड़ों भारी फाँटों के रिस्के आदि के समाचार आदि आते रहते हैं। 31 मार्च 1993 को

नौग परमाणु रिएक्टर के यूनिट प्रथम के जेनरेटर में आग लगने से एक बड़ी दुर्घटना होती-होते टल गई, क्योंकि आग मुख्य संयंत्र से केवल 200 मीटर दूर लगी थी। इसके दो वर्ष पहले काकनापार रिएक्टर में भी आग लग चुकी थी। यद्यपि परमाणु ऊर्जा कमिशन के अध्यक्ष डॉ॰ पी के आयपर के अनुसार - भारतीय परमाणु संयंत्रों की रचना में चेर्नोबिल की तुलना में बहुत अधिक सवधानी बरती गई है पर साथ ही एक सरकारी आकलन में परमाणु कार्यक्रम से भूमिगत प्राकृतिक जल भण्डारों की खतरे की चेतावनी दी गई है। यदि भूमिगत जल में रेडियोएक्टिव पदार्थ बढ़ते हैं तो यह चिन्ता का विषय है, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या के लिए भूमिगत जल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है। 17 मई, 1993 को बंबई हाई तेल पाइपलाइन के फटने से समुद्र में 2 मील लंबे और 400 मीटर चौड़े क्षेत्र में तेल फैल गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) की हाल ही की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली बंबई और बलकता विश्व के उन प्रमुख नगरों में से है जहाँ का वायुमंडल अत्यन्त दूषित हो चुका है। नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के अनुसार- राजधानी दिल्ली ने वायु प्रदूषण में भारत में पहला व विश्व में चौथा स्थान ले लिया है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल से चलने वाले 19.67 लाख वाहन हैं, जो प्रतिदिन वायुमंडल में 250 टन कार्बन मोनो ऑक्साइड, 8 टन सल्फर डाई ऑक्साइड 400 टन हाइड्रोकार्बन व 600 किलो सोडा छोड़ते हैं। इन वाहनों के अन्वावा दिल्ली के थर्मल पावर स्टेशन मल्पर डाई ऑक्साइड तथा ससंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस पी एम) उगलते हैं। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कार्बन मोनो ऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ट्रैफिक पुलिस को गैस मास्क देने की योजना बनी है। इन गैसों के बढ़ने से छाती में दर्द, सास लेने में तकलीफ कर इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं।

भारत में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी संतुलन के प्रयास

POLLUTION IN INDIA & EFFORTS FOR ECOLOGICAL BALANCE

स्थिति :-

भारत सरकार व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पड़व का गविन्दगढ़ देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। राजस्थान का पल्लो नगर दशक दूसरे नगर का प्रदूषित शहर है। इन

अतिरिक्त दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) हावड़ा (पश्चिम बंगाल) तलचर अमूल (उड़ीसा) डिगबोई (असम) धनबाद (बिहार) नजफगढ़ (दिल्ली) वापी (गुजरात) आदि देश के अन्य प्रदूषित शहरों के अंतर्गत आते हैं। महानगरों में होने वाले कुल वायु प्रदूषण का 50 से 60% प्रदूषण वाहनों के माध्यम से होता है। वाहनों के धुएँ में कार्बन मोनो आक्साइड और सल्फर डाइआक्साइड जैसी जहरीली गैरें और सीसा होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 1987 के आकड़ों के अनुसार देश के 12 महानगरों में कुल मिलाकर लगभग 3000 टन प्रदूषणकारी तत्व वाहनों के धुएँ के रूप में वायुमंडल में छूटते हैं। 1976 की एक रिपोर्ट के अनुसार बर्क में कपड़ा मिलों के कारण वायु प्रदूषण की मात्रा काफी अधिक है। दिल्ली में अनेक छोटे बड़े 70 000 से अधिक उद्योग वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रकृति वनों के माध्यम से कार्बन डाइ आक्साइड के एक अंश को वृक्षों के भोजन के रूप में काम में लेकर उसके स्थान पर आक्सीजन छोड़ती है जिससे वायुमंडल में इन गैसों के मध्य संतुलन बना रहता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक इक्वेटोर वन क्षेत्र लगभग 3 टन कार्बन डाइ आक्साइड ग्रहण करके दो टन आक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है। दुर्भाग्य से भारत में पर्याप्त वन भी नहीं हैं। प्रदूषित भूमिगत जल के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख लोगों की अकाल मृत्यु होती है। इस प्रदूषित भूमिगत जल का कृषि पर भी बुरा असर पड़ता है। भारत में सही जल भी भारी मात्रा में प्रदूषित है। इसका प्रमुख कारण नदियों व तालाबों में उद्योगों नगरपालिकाओं आदि के दूषित अवशिष्ट को डाल देना है।

प्रयास -

1 भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारी अधिकरण Govt Agencies for Environmental Protection in India

पर्यावरण और वन मंत्रालय (Ministry of Environmental & Forest) पर्यावरण और वन सर्वद्वय ती आवश्यकता का ध्यान में रखते हुये जनवरी 1985 में केन्द्र सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय की अलग से स्थापना कर दी गई थी इसने अधीन पर्यावरण विभाग और वन तथा वन्य जीव विभाग कार्यरत है।

पर्यावरण विभाग (Department of Environment) पर्यावरण विभाग पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के नियोजन प्रोत्साहन एवं उनमें सम्मिलित करने के लिए एक राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में कार्य करता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (The Central Pollution Control Board) यह बोर्ड जल और वायु प्रदूषण

का पता लगाने और उस पर नियंत्रण करने के लिए सर्वोपरि राष्ट्रीय निकाय है। यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यक्षेत्रों को भी समन्वित करता है। बोर्ड के पास अपनी एक प्रयोगशाला है जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों तथा सामान्य पानी की कोटि पर निगरानी रखती है। बोर्ड द्वारा देश में पानी की कोटि की मासिक जाँच के लिए कन्द्र स्थापित किये गये हैं। जल और वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित अधिनियमों को लागू करने से संबंधित प्रशासनिक दायित्व भी केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली (National Natural Science Museum) इस संग्रहालय की स्थापना पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा उसमें जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई है।

केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण (Central Ganga Authority)

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य योजना के क्रियान्वयन तथा इस योजना में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर संबंधित एजेंसियों को सम्मिलित करने का दायित्व केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण पर है। इस प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 1985 में की गई थी।

पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (Ecological Development Board)

इस बोर्ड की स्थापना पर्यावरण की दृष्टि से गिरावट वाले क्षेत्रों का सम्प्रेषण करने की विधियों का प्रदर्शन करने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा छात्रों ग्रामीण युवाओं व महिलाओं में पर्यावरण के बारे में सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय मानव तथा जीवमंडल समिति और पर्यावरण अनुसंधान समिति (Indian National Human & Biosphere Committee & Environment Research Committee) यह समिति पर्यावरण संबंधी अनुसंधान करने अन्य समितियों में प्राण अनुसंधान प्रस्तावों की गणेश करने तथा परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिकता वाले प्रश्नों का परिशिष्ट करता है और अनुसंधान के परिणामों पर उचित क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त सुझाव भी देता है।

2 भारत में वन्य जीव संरक्षण Wild Life Protection in India

वन्य जीवों से तात्पर्य वन में रहने वाले प्राणिमालों का है वन्य जीवों का संरक्षण और उनके प्राणियों में है वन्य जीवों का संरक्षण और उनके प्राणियों में है वन्य जीवों का संरक्षण और उनके प्राणियों में है

कला सिध्दांत है। स्वावलम्बन उनका गुण है। सुमधुर वन्य-जीवन के परितोषक है। उनका कतारव गुजन हमारे जीवन में स्फुटि का नव संचार करता है। वन्य जीव हमें प्रकृति के सौन्दर्य और उसके माध जीवज क्रिया को आवह कर नैमार्गिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।

हमारे गौरवशाली सस्कृति में वनों के विकास के माध वन्य जीवों के मरक्षण को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है परन्तु पिछले कुछ दशकों में वन्य-जीवों के माध मानव जाति का क्रूर व्यवहार हुआ है और हो रहा है। अवैध शिकार, वना की कटाई आदि के परिणामस्वरूप कई वन्य-जीवों की प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं अथवा उनकी मज्जा में भारी गिरावट आई है। भारत में जिन वन्य-जीवों का सर्वाधिक हानि हुआ है, उनमें नीलगाव, कम्पूरी मृग सिंह गैहा मफट शर, जंगली भैंसा, गोडावण आदि के नाम प्रमुखता से लिये जा सकते हैं। वन्य जीवों का सरक्षण राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुका है। वन्य-जीव हमारी ही तरह ममान रूप में प्रकृति में विद्यमान और स्वतंत्रतापूर्वक जीने के अधिकारी हैं। गत वर्षों में राजकीय स्तर पर वन्य-जीव मरक्षण के लिए कई योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं।

राजकीय प्रावधान एवं अधिकारण

वन्य जीव मरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्र सरकार ने 'इण्डियन वाइल्ड लाइफ(प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972' पारित करके सर्वप्रथम प्रभावी कदम उठाया। इन अधिनियम में उन वन्य जीवों के सरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनकी जाति या उपजाति विलुप्त होने की है। साथ ही, राष्ट्रीय महत्व के अन्य पशु पक्षियों के सरक्षण का प्रावधान भी किया गया है तथा इसे एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

42 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण एवं वन्य जीव सारक्षण में मरक्षण कर्तव्य भी सम्मिलित किया गया है। "प्रत्येक नागरिक का यह भूल कर्तव्य है कि यह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसमें वन झील नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं रक्षा को और मरर्दन को तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।"

वर्ष 1983 में वन्य जीवन सारक्षण एवं सवर्दन हेतु एक राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना अपनाई गई। इस कार्य योजना के अंतर्गत यह कदम उठाये गये हैं (i) सभी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्यों एवं अन्य क्षेत्रों, जिनका मरक्षा अंतर्गत है का सर्वेक्षण किया गया है। (ii)

वन्य जीव भण्डारों की प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए पार्यदर्शी सिद्धान्त बनाये गए हैं और उन्हें राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू किया गया है। (iii) राष्ट्रीय वन नीति का पुनर्रक्षण करने तथा उसमें मरशोधन करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। (iv) वन्य जीव (मरक्षण) अधिनियम 1972 में किये गये संशोधनों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। और (v) सारक्षित प्रबन्धन और पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

उपर्युक्त कार्ययोजना में निर्दिष्ट कार्यक्रमा तथा परियोजनाओं को आरम्भ कर उन पर निगरानी रखने के लिए 'केन्द्रीय वन्य-जीव सारक्षण निदेशालय और भारतीय वन्य जीव सस्थान', देहपुर केन्द्रीय अधिकारणों के रूप में स्थापित हैं। वे यह कार्य राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों, जो देश में वन्य जीवों के सारक्षण और प्रबन्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, की सहायता से करते हैं।

3 केन्द्र सरकार की प्रदूषण निवारण नीति, 1992 Central Govt Policy of 1992'

केन्द्र सरकार ने प्रदूषण को रोकने हेतु फरवरी 1992 में एक नई प्रदूषण निवारण नीति की घोषणा की। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों द्वारा फैलाये जाने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु नए उपाय किये गये हैं। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाने में एकटने हेतु किये गये कुछ सुझाव इस प्रकार हैं

- (i) उद्योगों की निर्माण-क्रिया के सभी स्तरों पर पर्यावरणीय विषयों का शामिल किया गया है।
- (ii) इस नीति में प्रदूषण को मोत पर हो रखने पर बल दिया गया है। इस हेतु सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है।
- (iii) प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई में क्षतिपूर्ति वसूल करने की बात भी नई प्रदूषण निवारण नीति के अंतर्गत कही गई है।
- (iv) इन नीति में यह भी कहा गया है कि दुनो तरह में प्रदूषित क्षेत्रों की समुचित सुरक्षण की ज़रूरतें ताकि इन क्षेत्रों की जनता प्रदूषण से प्रभावित नही हो।
- (v) इस नीति में पर्यावरण प्रदूषण से संबन्धित मामलों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का बात कही गई है।
- (vi) पर्यावरण ऑडिट के बारे में कहा गया है कि औद्योगिक इकाइयों को अपने दार्षिक वित्तीय व्यौर की प्रति पर्यावरण का भी व्यौर देना अनिवार्य होगा।

(vii) प्रदूषण पर नियंत्रण रखने वाले तरीके अपनाने के लिए वितीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है।

प्रदूषण निवारण नीति में औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनका उद्देश्य उद्योगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में फैलने वाले प्रदूषण को रोकना है। ऐसी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं -

- (i) पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक किस्म के कीटनाशकों को क्रमबद्ध तरीके से प्रचलन से हटा लिया जायेगा।
- (ii) उर्वरकों के प्रयोग व उत्पादन हेतु एक नई उर्वरक नीति बनाने की व्यवस्था की गई है।
- (iii) जिन क्षेत्रों में खनन कार्य होता है यदि उनमें कोई क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील प्रतीत होता है तो वहाँ खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iv) वाहनों के धुएँ से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु कड़े उपाय किये जायेंगे।

इस प्रकार नई प्रदूषण निवारण नीति में उद्योगों तथा अन्य माध्यमों में फैलने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी उपाय सुझाए गये हैं। पर्यावरण प्रदूषण की विकराल स्थिति को देखते हुये इन उपायों को लागू करना एक आवश्यकता है। इन उपायों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये। स्वयं उद्योगों की भी चाहिये कि वे अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझते हुये पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली मशीनों व उपकरणों का प्रयोग रोके। उद्योगों में धूल धुआँ गढ़ा पानी व कचरा आदि हेतु ऐसी व्यवस्था को जिनसे कि इनके द्वारा फैला हुआ प्रदूषण आसपास के वातावरण को दूषित नहीं करे। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसी मशीनों के उपयोग की आवश्यकता है जिनमें आपाज कम से कम हो। जिन मशीनों की आवाज अधिक हो उनमें साइलेंसर जैसे उपकरणों को लगाया जाना चाहिये ताकि अनावश्यक ध्वनि को नियंत्रित किया जा सके।

इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है चाहे वह खतरनाक कीटनाशकों के माध्यम से फैलता हो अथवा उर्वरक उत्पादन से। हमारे हानके तथा भारी वाहनों के माध्यम से निकलने वाली ध्वनि तथा धुएँ के माध्यम से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयासों करने जरूरी हैं। यद्यपि प्रदूषण रोकने हेतु कानून भी है परन्तु पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु नव प्रयासों की नितात आवश्यकता है। कोई भी नीति या कानून तब तक पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि लोग उनमें बताई गई बातों को अपने जीवन के आत्मगत न कर लें। यही बात पर्यावरण प्रदूषण निवारण

नीति व कानूनों के साथ लागू होती है। इन नीति की सफलता व्यक्ति, समाज तथा सरकार के सामूहिक प्रयासों पर ही निर्भर है। इस दिशा में गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है, तभी हम पर्यावरण प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण स्वयं अपने लिए तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए कर सकेंगे।

राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रयास

POLLUTION IN RAJASTHAN & EFFORTS OF ECOLOGICAL BALANCE

राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति

Position of pollution in Rajasthan

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान का पाली शहर देश का दूसरे नंबर का प्रदूषित शहर है। प्रदूषण की दृष्टि से देश में जोधपुर का 22 वाँ स्थान है। इस प्रकार राजस्थान में रणारि-छपाई तथा वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात शहर पाली राजस्थान में प्रदूषण की दृष्टि से प्रथम एवं जोधपुर द्वितीय स्थान पर है।

रेगिस्तानी क्षेत्र के इन शहरों की इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित रासायनिक जल में बाड़ी नदी के प्रभाव क्षेत्र के किनारे बसे लगभग 20 गांव 10 लाख से अधिक आबादी एवं हजारों पशु प्रभावित हुये हैं। 45 किलोमीटर तक नदी के दोनों किनारों और 50 फीट तक के गहरे कुओं का पानी रसीन हो चुका है। 150 फीट तक भूमिगत जल प्रदूषित होकर पीने योग्य भी नहीं रहा है। राजस्थान का जलवायु चरम वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। जयपुर की शीतकालीन शाम व सुबह सीमा में अधिक प्रदूषित होती है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि झोटावाड़ा औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में त्रिप्रेतिलिख की हवा भारी बेहतर के लिए अधिक हानिकारक है। इसका प्रमुख कारण त्रिप्रेतिलिया में मोटर वाहनों का आवागमन और इनके इंजनों से निकलने वाला दूषित धुआँ है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियानिकी अनुसंधान संस्थान (सीरी) के तथ्यों के अनुसार वह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि जयपुर में वायु प्रदूषण की यही स्थिति रही तो आगामी 5 वर्षों में जयपुर शहर भी अहमदाबाद व कानपुर जैसा दूषित शहरों की श्रेणी में आ जायेगा और जयपुर वासी भी दिल्ली वालों की तरह फेफड़ों की बीमारियों व कैंसर जैसी खतरनाक बीमारों से ग्रसित हो जायेगा। 'सीरी' जयपुर में 1978 में वायु प्रदूषण जाच के कार्य में लगा हुआ है। वैज्ञानिक श्री मेद

का मानना है कि ग्राम में इस शहर का वायु अधिक प्रदूषित नहीं थी। आज भी महानगरी की दृष्टि से इसका नाम निंदित ब्रह्म के शहर में ही है। लेकिन प्रदूषण वृद्धि का गति को देखते हुए खतरा बहुत नजदीक है। राजस्थान के कोटा शहर में प्रदूषण का समस्या विकराल रूप धारण कर चुका है। यह एक औद्योगिक नगरी है। अतः यह शहर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का समस्या में प्रसिद्ध है। काबला कागजाला व कारन स्लेज और इट भट्टों का प्रदूषित वायु न शहर के पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। इस प्रदूषण के फलस्वरूप शहर के अनेक व्यक्ति सिंग दूध आदि में जलन, खाँसी, दमा और पच की बाधाओं में ग्रस्त हो रहे हैं। इस प्रकार उदयपुर शहर का भी पर्यावरण उत्पादक उद्योगों के कारण लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में सभा जलवायु विफल हो गये हैं एवं कुओं का पानी लाल व बैंगनी हो गया है। एक जाच रिपोर्ट के अनुसार इस पानी में नलकूप खराब हो गए हैं। भूमि का उर्वरण माना हो रहा है तथा एक लम्बे चौड़े इलाके में गन्ना बरबूदार पालो फलक धरता पर अपना परत बिछा गया है। इससे कुछ मशानों पर धना पुग तरह बाहर हो गई है। धानुमित्रित इस पानी में जमीन का गाव स्थित जल भंडार पर भी बुरा असर पड़ा है। पानी में सोडियम हाइड्रो आक्साइड भी मिला होगा है। जाच व अनुमान उद्योगों व व्यवहारों जल अवशिष्ट मामली नाला में बहकर पानी असर करता है। इस प्रकार प्लांटिक कमिशन और एनवयरमन्ट एण्ड डेवलपमन्ट के अनुसार राजस्थान व विभिन्न क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन का प्रदूषण व कारण गम्भीर खतरा का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान में पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के संतुलन हेतु संस्थाएँ

Agencies for Ecological Balance in Rajasthan

विश्व में पहला बार इस समस्या के बारे में 5 जून 1972 का म्यूकहम में मानव पर्यावरण पर अयोजित सम्मेलन में गायना प्रारंभ किया गया। 1975 में ब्रिज में विभिन्न देशों ने यह तय किया कि सभी राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यावरण नगरी निर्मित करना चाहिये। इस विचार के कारण पर्यावरण सुरक्षा विश्व में वर्तमान स्थिति तक पहुँचा है। भारत ने अपना राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तय की है तथा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र में पर्यावरण विभाग एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कार्यरत है। राजस्थान में भी अक्टूबर 1983 में राज्य स्तर पर पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। इस प्रकार राजस्थान में पर्यावरण विभाग के लिए दो प्रमुख संस्थाएँ हैं।

(अ) पर्यावरण विभाग राजस्थान

(ब) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल

(अ) राजस्थान का पर्यावरण विभाग (Department of Environment in Rajasthan) अक्टूबर 1983 में राज्य स्तर पर स्थापित पर्यावरण विभाग राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं उनके कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह वायु, जल, भूमि आदि के प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का प्रयास करता है तथा वन्य जीव वन संस्थाएँ उद्यान एवं अभयारण्यों का देखभाल करता है। यह विभाग पर्यावरणीय चेतना जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है और भारत सरकार व पर्यावरणीय विभाग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों को भी संचालित करता है। राजस्थान का पर्यावरण विभाग की सभी योजनाओं का प्रारूप राज्य पर्यावरणीय योजना एवं समन्वय मण्डल द्वारा निश्चित किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 4 जून 1984 को इस मण्डल का विधिवत् गठन हुआ। पर्यावरण विभाग के विशेषाधिकारी इस मंडल के पदेन सचिव होते हैं। इन कार्यक्रमों की क्रियाविधि के लिए पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर पर स्थायी समिति गठित की गई। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर का अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति बनाई गई है। राजस्थान के पर्यावरण विभाग ने 24 जुलाई 1983 से पारिस्थितिकी टास्क फॉर्म राजस्थान द्वारा राजस्थान नहर के बायें किनारे पर 150 किलोमीटर की लंबाई में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास का कार्य आरंभ किया गया। पारिस्थितिकीय स्टॉक फार्स ने इस योजना के अन्तर्गत नहर के बायें तट पर अर्धा किलोमीटर चौड़ाई में सघन वृक्षारोपण तथा उसके बाहर डेढ़ किलोमीटर चौड़ाई में चरागाह विकास का कार्य किया। इस कार्य से वन्य जीवों की वृद्धि हुई तथा अच्छे किस्म का चारा उपलब्ध हुआ एवं पर्यावरण में स्पष्ट सुधार दृष्टिगोचर हुआ। पर्यावरण विभाग ने पर्यावरणोंय जनचेतना जागृत करने के उद्देश्य से विचार्यों व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के माध्यम से पारिस्थितिकीय विकास शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में पर्यावरण के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों का समावेश होता है। शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए पर्यावरण विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि लोगों का पर्यावरण असंतुलन की जानकारी हो सके तथा उससे बचने के प्रयास प्रयास किये जा सकें। पर्यावरण से संबंधित विविध समस्याओं के निवारण हेतु सेमिनार एवं कार्य शिप्टिंग का आयोजन किया गया। पर्यावरण विभाग राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतिष्ठानों का आयोजन भी करता है जिसमें पर्यावरणीय चेतना जागृत हो सके। इन

प्रतियोगिताओं में प्राथमिक विद्यालयों के लिए बालनृत्तकला प्रतियोगिता माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निम्न प्रतियोगिता महविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं सभी लोगों के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता प्रमुख है। पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण के प्रमुख धटकों की जानकारी प्रदान करने के लिए साहित्य तैयार किया जाता है एवं वितरित किया गया है। विभाग के पुस्तकालय में भी पारिस्थितिकीय से संबंधित पुस्तकें एकत्रित की गई हैं। पर्यावरण विभाग फिल्मों वटपुतली प्रदर्शन स्टिकर आदि के माध्यम से प्रचार कार्य करता है। यह पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त कर रहा है। पर्यावरण विभाग द्वारा पारिस्थितिकीय समस्याओं का अध्ययन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ चुने हुये धार्मिक पर्यटन एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों के पर्यावरण विकास का राक्ष्य निर्धारित कर उस पर कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत गला (जयपुर) पुकर (अजमेर) गागा न दरगाह (झालावाड़) पूछरी गिरी गोवर्धन (भरतपुर) भाधला पगरा (उदयपुर) हनुमान जी की खेजडी (सुरतगढ़) राडी के हनुमानजी (झालावाड़) जैन मंदिर (झालावाड़) क्यसरा महादेवजी का मंदिर (झालावाड़) अरलगढ (माउण्ट आबू) ढाई दिन का झोपडा (अजमेर) ब्रह्माजी का मंदिर (पुकर अजमेर) रानीजी की बावडी (बूंदी) प्रमुख है पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय अनुसंधान प्रोजेक्ट निर्माण एवं उनकी क्रियाविति औद्योगिक इकाइयों के स्थल चयन में संबंधित अनापति प्रमाण पत्र पर्यावरण माह का आयोजन विश्व एवं राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों आदि का आयोजन भी करता है। यह भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के दिशा निर्देश का अनुरूप समन्वय तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित मणक कर उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश को पर्यावरण में सुधार लाने का कार्य भी करता है। मातवा याजना के अंतर्गत इस विभाग पर 112 57 करोड़ रुपये व्यय किय गये। 1990-91 में पर्यावरण से संबंधित एक कार्ट की स्थापना भी की गई ताकि इससे संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। आठवी योजना के अंतर्गत राजस्थान व पर्यावरण विभाग पर 546 00 लाख रुपये व्यय करन का प्रावधान है। आठवी योजना के अन्तर्गत 3394 हेक्टर पर भूमि पर भू सतलन का कार्य किया जायेगा। लगभग 460 पदावरणीय शिल्पा व चेतना कार्यक्रम आयोजित किय जायग तथा 52 समर एवं विस्तार कार्यक्रम आयोजित किय जायन वा योजना है। आठवा योजना में 30 नई पर्यावरणीय शाध राक्ष म ला जायेगी। केन्द्र सरकार की 1993 की पर्यावरणाय अधूना से राजस्थान के पर्यावरणीय विभाग का काय अत्यन्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण

हो गया है।

(ब) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल

राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल की समस्त गतिविधियों का समन्वय प्रशासनिक दृष्टि से पर्यावरण विभाग द्वारा किया जाता है। इस मंडल ने पाली झुझन कोटा जोधपुर उदयपुर अलवर व भोलवाडा जिले में पर्यावरणीय स्थिति का गहन अध्ययन किया है। राजस्थान में प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या से भी चिंतित है। प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है तो इससे विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष दुष्प्रति परिणाम जैसे भूमि की उत्पादकता में ह्रास आदि भी वहन करने होते हैं। वायु एवं जल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह मंडल कार्य करता है कुछ हा समय पूर्व इसे नुकसान देह पदार्थों एवं बेकार पदार्थों के प्रबंध का कार्य भी सौंपा गया है। यह अपने विभिन्न कार्यों का संपादन विभिन्न प्रदूषण अधिनियमों के अन्तर्गत करता है। इसकी प्रमुख क्रियाओं में प्रदूषण का न्यूनतम करना शहर के गंदे पानी को उचित प्रकार से नियंत्रित करना गंदे पानी का उचित क्रियाविधि में सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लाना नये उद्योगों का इस प्रकार स्थान निर्धारण करने की गलाह देना जिससे प्रदूषण न्यूनतम हो। यदि आवश्यक हो तो विद्यमान उद्योगों को भी नये स्थान पर स्थापित करने की सलाह दी जा सकती है। मंडल ऐसे उद्योगों का भी पता लगाता है जो नुकसान देह पदार्थों का उपयोग या उनका उत्पादन कर रहे हैं। उनमें निकलन वाल नुकसान देह पदार्थ कौन से हैं और उनका भली भांति डिम्बात्रल किया जा रहा है अथवा नहीं इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। इस मंडल द्वारा धरतु बेकार पानी उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी (1) ऐसे सभी शहर जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है। (2) ऐसे शहर जहां प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के कारण प्रदूषण है तथा (3) ऐसे शहर जो धार्मिक महत्व के हैं। मंडल यह प्रयास करेगा कि सभी गृह एवं मध्यम स्तर के उद्योग प्रदूषण को नियंत्रित करने के उचित प्रयास करें तथा लघु उद्योगों का भी प्रदूषण नियंत्रण के उचित उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। आठवी पर्यावरणीय योजना में राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल के लिए 750 लाख रुपये का प्राधान्य दिया गया है।

राजस्थान में पारिस्थितिकी सतुलन हेतु वन विकास (Forest Development for Ecological Balance in Rajasthan)

वैज्ञानिकों की मान्यता है कि जिन भूभाग में 6% में कम वन हात है उन क्षेत्रों में सम्यक्ताएँ नष्ट हो जाता है एवं

कागज शिल्प	भरतपुर जयपुर अजमेर मिराही बाडमेर और कोटा।
नील गाय	भरतपुर मवाईमाधोपुर अजमेर कोटा जोधपुर तथा झा नगड़।
वेष्टिया हरिया	सिराही और भातपुर।
खरगोश	भरतपुर नरीगा मवाईमाधोपुर कोटा सिराही भीलवाड़ा व अजमेर।
शेबरा	बीकानेर जैसलमेर नाडमेर जाधपुर और जालौर।
गोडावन	बाडमेर जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर।
कुत्तबुध	जानार बाडमेर जोधपुर जैसलमेर और श्रीगणेशगढ़।
तैयार	भरतपुर मिराही टोंक भीलवाड़ा बांसवाड़ा चणौर और अजमेर।
हटेर	जालौर, सिराही, झालपुर और जोधपुर।

संरक्षण

देश की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान वन्य जीवों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था। पछपि तत्कालीन देशी राज्य शिकारियों का स्वर्ग माने जाते थे तथापि रियासतों शासक वनों एवं वन्य जीवों के संवर्धन को भी प्रोत्साहित करते थे लेकिन स्वतंत्रता पश्चात् राज्य में वनों तथा वन्य जीवा पर मनुष्य के भयंकर अतिक्रमण के परिणामस्वरूप पशु पक्षियों का तेजी से विनाश होने लगा। वनों की अनियंत्रित कटाई और वन्य जीवों के निष्प्रयोजित शिकार की प्रवृत्ति से वनों में विरगण करने वाले पशु पक्षियों की संख्या में तीव्र हास होने लगा। चीता गोडावन लिक्स पिंग हेडड डक आदि वन्य जीव लुप्त हो गये। अतः इस शर्मनाक स्थिति में आगाह होकर राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण को समुचित महत्व दिया वन्य जीव संरक्षण को राज्य की योजना में अनिवार्य स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कड़ाई से पालन करते हुये वन्य जीव के शिकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया गया है। दुर्लभ पशु-पक्षियों के संरक्षण के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि के लिए भी याज्ञनायक प्रयास किये जा रहे हैं।

वन्य जीवों के मध्यस्थ विवरण तथा उनकी संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य का विभिन्न क्षेत्रों में 2 राष्ट्रीय उद्यान तथा 23 वन्य जीव अभयारण्य विवसित किए जा चुके हैं। जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर व बीकानेर में एक-एक जंतुशाला भी स्थापित की गई है। राज्य के 32 वन्य-क्षेत्रों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। मींग खाल तथा पुरों का निर्यात भी प्रतिबन्धित किया जा चुका है।

राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य-जीव अभयारण्य

NATIONAL PARKS & WILD LIFE SANCTUARIES IN RAJASTHAN

रणथम्बीर राष्ट्रीय उद्यान मवाईमाधोपुर जिला में प्रख्यात रणथम्बीर दुर्ग के चारों ओर विस्तृत इस प्राकृतिक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इस गण्टाय उद्यान में भारत के अन्य वन्य जीव अभयारण्य का तुलना में सर्वाधिक वन्य जीव विवरण करत है। वर्ष 1974 में इस प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत चर्चनित किया गया। भारत सरकार विश्व वन्य जीव तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन के सहयोग से यह बाघ संरक्षण की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रीय निदेशक प्रोजेक्ट टाइगर रणथम्बीर मवाईमाधोपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में है। प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत यहां बाघों के संरक्षण सर्वर्द्धन के साथ साथ अन्य वन्य जीवा तथा वन सम्पदा और पर्यावरण के संरक्षण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 20 बाघों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में घातल सांभर जंगली सूअर नीलगाय लकड़वाघा और सियार आदि भी विवरण करत है। उद्यान में विभिन्न किस्म के फली भी उपलब्ध है।

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान यह उद्यान घना पक्षी अभयारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह फली विहार भरतपुर से दो किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस पक्षी विहार में उधल पानी की झील का फैलाव है जिसमें जलीय वनस्पतिया उगा रहती है। झील के साथ साथ भूमि पर भी कदम्व और अकेशिया के पेड़ों के घने जंगल पक्षियों को आकर्षित करत है। फली अपना भोजन जलीय वनस्पति एवं जलजंग में आसानी से प्राप्त कर लेत है।

इस विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार में 332 प्रकार के पक्षी दृष्टि का मजबूत है। इस अभयारण्य में साइबेरिया ताशकन्द नेपाल चीन जापान मंगोलिया आदि स्थानों से हजारों मील की दूरी तय कर विदेशी पक्षी शरतःकालीन प्रवास कर लिए आत है। ये प्रवास स मार्ग तक यथा रहत है। इसी पक्षियों में साइबेरियन वन (साइबेरिया का सागरी) प्रमुख अवर्णन कर वन्द रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ आने वाले प्रमुख पक्षियों में वाइड स्टर्ज पिनटस मगई कूट पार्ड टायला गात्र बीकन मैडवैन शकलस लैंगवैन पीपेटस आदि प्रमुख है। इसी प्रकृति में बगुले हवा छील पन्ड स्टर्ज ओपन फ्लिग स्टर्ज फार्मिग काल्य कोकोरेंट कठपेडया घाँबिया पातो वृज्ज धारण्य शरस आदि प्रमुख है। इस उद्यान में पक्षियों के अतिरिक्त रणथम्बीर नीलगाय शिकार आदि वन्य जीव भी है।

राष्ट्रीय मरु उद्यान : मरुभूमि में प्राकृतिक वनस्पति को सुधित रखने, वन्य प्राणियों की संरक्षण प्रदान करने और करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में दबे हुये जीवावशेषों (Fossils) को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया। इसे जैसलमेर व बाडमेर जिलों के 3 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की योजना पर कुल 247 करोड़ रुपये का व्यय का प्रावधान है।

इस उद्यान में गोडावण (ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड), चिकरा, काला हिरण, चौंसिंघा आदि वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। गोडावण (राजस्थान का राज्य पक्षी) शर्मीले स्वभाव का और एकल में घूमना पसंद करने वाला पक्षी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आवश्यक वातावरण व सुविधाएँ उपलब्ध करके इस दुर्लभ पक्षी की वंशवृद्धि के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

पैगिस्तान के इस भू-भाग पर लाखों वर्ष पूर्व विविधतापूर्ण वृक्षों में सम्पन्न सघन वन थे, जिनके अवशेष यहाँ की भूमि के नीचे दबे हुये मिलते हैं। उद्यान में 'अकाल' नामक क्षेत्र में ऐसे विशाल जीवाश्म प्राप्त हुये हैं। इन जीवाश्मों का संरक्षण भी मरु उद्यान योजना का प्रमुख प्रयोजन है।

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य : अलवर जिले में, अलवर से 35 मील दूर स्थित सरिस्का अभयारण्य 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभयारण्य को भी बाघ संरक्षण के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट टाईगर' में सम्मिलित कर लिया गया है। इस अभयारण्य में शेरों व बाघों के अतिरिक्त साभर, चीतल, नीलगाय, चिकरा, चौंसिंघा, स्याहगोश, जंगली सूअर आदि वन्य पशु स्वच्छन्द विचरण करते हैं।

दर्रा वन्य-जीव अभयारण्य : कोटा से 48 किलोमीटर दूर विन्ध्य पर्वत शृङ्खला की सुगम घाटियों में 200 वर्ग किलोमीटर में दर्रा अभयारण्य विस्तृत है। इस अभयारण्य में साभर, नीलगाय, चीतल, हिरण और जंगली सूअर अच्छी संख्या में हैं। यहाँ कुछेक बाघ व शेर भी हैं। इसमें अनेक किम्ब के पक्षी भी हैं।

कुम्भलगढ़ वन्य-जीव अभयारण्य : उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुम्भलगढ़ के निकट 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस वन्य जीव अभयारण्य के निकट रणकपुर के मंदिर और कुम्भलगढ़ दुर्ग भी पर्वतखों के आकर्षण के केंद्र हैं। इस अभयारण्य में तमूर बहलगाय से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त साभर, चीतल, चौंसिंघा, जंगली मुअर,

तेंदुआ, गैह आदि वन्य जीव भी विचरण करते हैं।

जयसमन्द वन्य जीव अभयारण्य : उदयपुर से लगभग 53 किलोमीटर दूर स्थित इस अभयारण्य में चीतल, काला भालू, साभर, जंगली सूअर, तेंदुआ आदि वन्य जीव मिलते हैं। यह अभयारण्य जयसमन्द झील के निकट अरावली की घाटी में लगभग 52 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।

तालछापर मृग अभयारण्य : चुरू जिले में सुवानगढ़ में लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित इस अभयारण्य में मुख्यतः काले हिरणों के संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ काले हिरणों की संख्या 500 में भी अधिक है।

आयू पर्वत वन्य जीव अभयारण्य : मिरोही जिले में माउण्ट आबू के समीप लगभग 115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस पर्वतीय अभयारण्य में जंगली सूअर, रीछ साभर, नीलगाय, तीतर, जंगली मुर्गा एवं विविध जानियों के पक्षी मिलने हैं।

धौलपुर वन विहार अभयारण्य : धौलपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर लगभग 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस पर्वतीय अभयारण्य में साभर, चीतल, नीलगाय, चिकरा, मार आदि मिलते हैं। समीप स्थित झील के किनारे विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं।

सीता माता अभयारण्य : यह अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ साभर हिरण, भेड़िया, चौंसिंघा, तमूर, जंगली भालू नीलगाय जंगली सूअर और बाघ आदि वन्य जीव देखे जा सकते हैं।

नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य : जयपुर जिले में स्थित इस अभयारण्य में मुख्यतः चिकरा ही विचरण करते हैं।

जमवा रामगढ़ वन्य-जीव अभयारण्य : जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ के समीप लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस अभयारण्य में चिकरा नीलगाय, तमूर चीतल, मोर आदि वन्य जीव देखे जा सकते हैं।

रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य : बूंदी जिले में लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस अभयारण्य में कई माधुरण वन्य जीवों के अतिरिक्त कुछ बाघ भी उपस्थित हैं।

चम्बल राष्ट्रीय अभयारण्य : कोटा में चम्बल नदी पर स्थित इस अभयारण्य में मारमच्छ और जलबोंब का संरक्षण दिया जा रहा है।

अमृतादेवी कृष्णमृग पार्क . जोधपुर जिले के खेजडली में लुप्त हो रही हिरण प्रजाति के लगभग 500 काले हिरण हैं, जिनके संरक्षण के लिए यह भूगर्भ वन लगभग 50 हैक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित किया जा रहा है। इस पार्क का नामकरण आज में लगभग 250 वर्ष पूर्व वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण देने वाली अमर शहीद अमृतादेवी के नाम पर किया गया है।

सुस्थिर या स्थायी विकास की अवधारणा

CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

सुस्थिर विकास से अभिप्राय उस विकास से होता है जिसे भविष्य में भी जारी रखा जा सका। दूसरे शब्दों में आज का मानव वर्तमान विकास का लाभ उठाते समय यह ध्यान रखे कि वर्तमान विकास के फलस्वरूप भावी पीढ़ी को पर्यावरण के पतन की हानियाँ बहन न करनी पड़े। अतः वर्तमान पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएँ इस प्रकार पूर्ण करना चाहिये कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इसलिये सुस्थिर विकास का अवधारणा के अनुसार वर्तमान एवं भावी मानव के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक साधनों का विदोहन विकास एवं संरक्षण किया जाता है। इससे न केवल भावी मानव के हितों की रक्षा होगी बल्कि मानव कल्याण भी अधिकतम हो जायगा।

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याएं

Environmental Pollution & Problems of Sustainable Development

- | |
|--|
| (अ) विश्वव्यापी समस्याएँ (Global Problems) |
| (ब) राष्ट्रीय समस्याएँ (National Problems) |
| (ग) राज्य की विशिष्ट समस्याएँ (State Problems) |

(अ) विश्वव्यापी समस्याएं Global Problems

1. सल्फर में प्रदूषण (Pollution by sulphur emissions) विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व की सदस्यों पर 60 करोड़ टॉन सल्फर चल रहा है और आगामी 22-23 वर्षों में इसकी मात्रा दुम्भी होने की संभावना है। वाहनों की संख्या में अधिकांश वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है। चिनी देशों में इन वाहनों के कारण होने वाले

प्रदूषण की गंभीरता का ज्ञान उस शहर विशेष की समस्याओं, भौगोलिक स्थितियों, जलवायु और वातावरण के प्रयोग किए जाने वाले वाहनों पर निर्भर करता है। अधिकांश विकासशील देशों में मोटरवाहनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं होता है। विश्व बैंक के प्रतिवेदन में यह चेतावनी दी गई है कि इन वाहनों को कि नियंत्रण ही विकास के साथ-साथ बढ़ते चले जायेंगे के कारण वायु में सल्फर और नाइट्रोजन आक्साइड जैसे रसायनों की मात्रा वातावरण में घुलती चली जायेंगी। वाहनों से निकला हुआ सल्फर डाई ऑक्साइड आँखों व श्वास नलिका पर बुरा प्रभाव डालेगा। इससे मनुष्य की संवेदनशीलता कम हो जायेगी। इस गैस के कारण लोगों में कैंसर और हृदयरोग जैसी घातक बीमारियाँ हो जाती हैं। औद्योगिकीकरण के कारण शहर में रहने वाले औद्योगिक अवशिष्टों में भी सल्फर डाई ऑक्साइड जैसी घातक गैस निकलती है। यदि वायुमंडल में कोहल व आर्द्रता होती है तो इस गैस का घातक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मोटरगाड़ियों की बढ़ती संख्या से विशेष रूप से महानगरों में, प्रदूषण गंभीर रूप धारण कर रहा है। मोटरगाड़ियों के चलने से कई प्रकार के प्रदूषित तत्व धुएँ के रूप में वातावरण में मिलते रहते हैं। 1980 से 1987 के मध्य विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों के नाम न्यूयॉर्क (अमेरिका), मिडनी (ऑस्ट्रेलिया), ब्रिटेन (ब्रिटेन), फ्रैंकफर्ट (जर्मनी), हेलसिंकी (फिनलैंड), ब्रुसेल्स (बेल्जियम), मिलान (इटली) तथा रोड्स (स्पेन) में सल्फर का उत्सर्जन निर्धारित स्तर में अधिक रहा।

औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र जहाँ पर अधिकांश लोग प्रदूषण के प्रति अत्यन्त जागरूक हैं वहाँ भी प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। विकासशील देशों में तो अधिकांश लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक ही नहीं हैं। उनमें प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। ऐसी स्थिति में विकास के कारण परिवहन साधनों में तीव्र गति में वृद्धि होना स्वाभाविक है। फलस्वरूप दुम्भी, कारण होने वाले प्रदूषण भी भविष्य में मानव के लिए चुनौती सिद्ध होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि समुद्र के किनारे बसे शहरों और अत्यधिक हस्तियाँ वाले क्षेत्रों में प्रदूषण का प्रभाव कम दृष्टिगोचर होता है क्योंकि वहाँ जल एवं वृक्ष प्रदूषणकारी गैसों का काफी बड़ी मात्रा में मोख लेते हैं। इसलिये लोगों पर निपेली गैसों का घातक प्रभाव कुछ कम हो जाता है। जिन क्षेत्रों में हस्तियाँ हैं और न ही गैसों के फैलने के लिए खुली जगह है वहाँ प्रदूषण का प्रभाव घातक होता चला जाता है। गर्मियों की अपवाहनीयों में वायु प्रदूषण का असर और बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी के कारण गैसों का वातावरण में फैलना आसान और तीव्र हो रहा है। ये निचे रहने वाले गैसों अधिकांश

क्षतिक प्रभाव डालता है। अतः इस समस्या का हल इस बात में निहित है कि मोटर परिवहन प्रदूषण से मुक्त हो। आरम्भ में प्रदूषण का एक न्यूनतम स्तर स्वीकार किया जा सकता है किन्तु अन्ततः वे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त हों, ऐसी अवस्था आवश्यक है। इसके लिए आरम्भ में मशीन वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। बाद में भार धीरे-धीरे घालित व सौर चालित आदि प्रदूषणमुक्त शक्ति के माधमों में चलने वाले वाहनों का विकास किया जा सकता है।

2 पारम्परिक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन (Emissions of Traditional Pollutants) - पारम्परिक प्रदूषकों में धुल, धुएँ व गैसों का प्रमुख स्थान है। विकास के सापेक्ष-मात्र इनमें तीव्र गति में वृद्धि हुई है। इस प्रकार के प्रदूषण से धीरे-धीरे हमारे और स्मारकों को भी नुकसान पहुँचा है।

औद्योगिक राष्ट्रों के अतर्गत कनाडा में परम्परागत वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन सर्वाधिक है। तत्पश्चात् क्रमशः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। परम्परागत वायु प्रदूषकों की गिरावट विकासशील राष्ट्रों में और भी गंभीर है। चित्र स्थान पर छोटे-बड़े उद्योग केन्द्रित हो गये हैं, उन स्थानों पर ता धुएँ, धुल, गैस और बजड़ से संपूर्ण वातावरण प्रदूषित रहता है। इन स्थानों पर सदैव शोर-मचा रहता है। इस ध्वनि प्रदूषण व कारण हृदयरोग और श्वासमयिया तेज हो जाता है। अन्य गन्नाप और अल्सर की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुमान - यदि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो सन् 2000 तक महानगरों में रहने वाले अधिकांश नागरिक या तो ऊँचा सुनने लगेंगे या पूर्णतया बहरपन के शिकार हो जायेंगे।

पर्वतों की मध्य हवा और जीवनदायी जल टूट-टूट कर तापों को मध्यस्थ लाभ के लिए रहता है। लेकिन अब तो पर्वतों पर भी प्रदूषण का आक्रमण हुआ है। पर्वतों के नदियों के उद्गम-स्थलों और पहाड़ों की चोटियों पर बड़े के ढेर जमा कर दिये हैं। बड़ी संख्या में पशुओं के आगमन नदियों के तट मल में दूषित हो रहे हैं। भूमिगत और भूतल से जल की शुद्धता ममान हो जाती है। उनमें जल प्रदूषण को दबावा देता है। कृषि खाना तथा मत्तियों के अवशेष पानी के साथ बहकर आते हैं। इनमें जल एवं और चूना पत्थर निकालने से परता व वनस्पति क्षय का हानि हुआ है जो पानी का मलिन व शुद्धिकरण करने का गं दुसरी ओर झूलकण हवा में मिल गया है। पानी को कटाई निर्माण कार्यों और खनिज कार्यों में वातावरण में धुल की मात्रा बढ़ा है। भोजन पकाने अर्थात् विद्युत का उपयोग करने और यहाँ तक कि

श्वास किया से भी पर्यावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। इस कारण पारम्परिक प्रदूषकों की स्थिति की दृष्टि में, विकसित एवं विकासशील, दोनों ही राष्ट्रों के समक्ष लगभग एक जैसी समस्या विद्यमान है।

परम्परागत वायु प्रदूषकों पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। इसके साथ ही उद्योगों के केंद्रीयकरण शहरीकरण की प्रवृत्ति और कम बिनाश को गंभीर होगा, शक्ति के माधमों के रूप में कोयला व लकड़ी आदि का उपयोग धीरे-धीरे बंद करना होगा। वृक्षारोपण का गति बढ़ाना होगा और विद्यमान वनों को बचाना होगा।

3 बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण (Growing Population & Urbanisation) - विकास की धुरा शहरीकरण के लोह में प्रारंभ होती है। बढ़ती जनसंख्या शहरी विस्तार, कृषि भूमि, याचों के निर्माण आदि के कारण वनों की अथावश्यक कटाई से आक्रामक-असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रकृति ने मानव को पाला-पोसा एवं संभाला है, परन्तु आज विज्ञान का युग है जिसमें मनुष्य प्रकृति की गोद छोड़कर सरोवरों-गंगा व अपनों बढ़ती आक्रामकों की प्रकृति के लिए शहर की आरंभ बसा जा रहा है। बड़ती हुई जनसंख्या में विविध होकर मानव ने बहुत तावता से वन और पर्वत काटकर वास्तव्ययोगी तथा आवासीय भूखण्डों का निर्माण किया है। इसमें पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण का सकल गहरा होता जा रहा है। इसी के अनुरूप गाँव व शहरीकरण से भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मानव द्वारा विमर्षित मल-मूत्र तथा असंयमित व्यवहार व फलस्वरूप जल, वायु एवं ध्वनि, सभी प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि हुई है।

आज शहरी वातावरण विषाक्त व तनावग्रस्त रहने लगा बन गया है। इससे अधिक और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जीवनपर्योपी और मुक्त में प्राण वायु की अवशुद्ध व मध्य नहीं मिल पा रही है। वाहनों व मशीनों का दमक संख्या से वातावरण में अवैद्यनीय शोर भर गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार - विश्व के 630 बड़े-छोटे प्रदूषित वातावरण में सास ले रहे हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण नई तकनीक का विकास एवं उसका उपयोगवाद है। जलवायु वृद्धि से शहरीकरण, मशीनीकरण भूमि की कमी, वैज्ञानिक आविष्कारों का पर्यवेक्षण एवं वन का अथावश्यक विनाश ही प्रदूषण के कारण हैं। प्राकृतिक माधमों के अत्यधिक उपयोग के फलस्वरूप से पर्यावरण मनुष्य के नष्टनाश से प्रदूषण बढ़ने लगा है। धूम्र जल, वायु ध्वनि और वृक्ष सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अतः आज दृढ़ता

जनमर्यादा व शांतोकरण नि सदह मानवीय जन जीवन के लिए एक चुनौती बन गया है। इस प्रकार जनसंख्या व शांतोकरण बढ़ते हुए प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन गया है।

नगर निगम अवशिष्ट का शहर की जनमर्यादा से गुंथना संभव है। इन अवशिष्टों का किम् प्रकार से प्रयोग किया जाता है इसी पर प्रदूषण की मात्रा निर्भर करती है। यदि यह अवशिष्ट अधिकांश विकासशील राष्ट्रों की तरह शहरों में गंदे नालों के रूप में खुला रहता है तो इससे गार्गस डाइ आम्माइड और कार्बन मोनो आक्साइड जैसे गैस निकलती रहती है जो कि मनुष्य के लिए घातक है। मनुष्य के असंयमित व्यवहार के कारण शहरों में जल की शुद्धता का स्तर भी कम होता जा रहा है। इन प्रदूषण के प्रभाव के कारण मनुष्य व पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। उनमें हंजा टाइफाइड पेरिश मन्त्रिया आदि गैर प्रमुख हैं। इन प्रदूषण से बचने के लिए सरकार व नगर निगमों का प्रयास करना होगा। स्वयं मनुष्य का भी संयमित व्यवहार करना होगा। उसका अपन अम पास व सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। सार्वजनिक जल प्राप्ति के स्थानों पर गंदगी फैलाने से बचना होगा। इन स्थानों पर कुछ स्मूथ फैक्ट्री, धुंके आदि की प्रवृत्ति से बचना होगा। इससे शहर की सभी गलियों का उचित चरमस्थान नीति का पालन करना होगा।

4 औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial Waste) विरग में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण औद्योगीकरण की प्रवृत्ति है। औद्योगिक कारखाना एवं फैक्ट्रियाँ जो विभिन्न सामानों का निर्माण करने के लिए एक गंदे पानी में बांध व इन प्रदूषण में निरन्तर निरन्तर रहती हैं। यहाँ तक कि औद्योगीकरण क्षेत्रों के आसपास का भूमिगत जल भी अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। औद्योगिक नगरों के आसपास से निकलनेवाली नदियाँ भी प्रदूषित होती जा रही हैं। औद्योगिक उद्योगों के कारण नदियाँ भी प्रदूषित होती जा रही हैं। विभिन्न उद्योगों द्वारा वैज्ञानिक तरीकों का उचित उपयोग नहीं किए जाने से भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर हुई है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण विरग में जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों की कुल 17 लाख प्रजातियों में से जीवों का 1 हजार तथा वनस्पतियों की 20 हजार प्रजातियाँ विलुप्त होने की स्थिति में हैं। इस प्रदूषण में एक दिन में लगभग 25 हजार व्यक्ति मौत से शिकार हो रहे हैं।

औद्योगीकरण के कारण ठोस अवशेषों की मात्रा निरन्तर बढ़ रही है और शुद्ध जल एवं वायु की कमी होती जा रहा है।

5 अणु ईंधन (Spont Nuclear Fuel) अणुशक्ति को आने वाले वर्षों का प्रमुख शक्ति स्रोत माना जाता रहा है। अणुशक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके अन्तर्गत बहुत कम ईंधन प्रयुक्त करके भी बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। शक्ति के अनेक साधनों की तुलना में यह सस्ता भी है। विश्व की अणुशक्ति का पूर्ण विद्योत्पन्न भी अब तक नहीं हो पाया है। इस कारण भविष्य में अणुशक्ति के विकास का सम्भावनाएँ व्यवस्था की जा रही हैं। अणुशक्ति का एक दुष्परीतलवार माना जा सकता है जो मनुष्य का भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। अणुशक्ति के उपयोग के पश्चात् बचे अपशिष्टों को फैकल में अत्यधिक मात्रा में संग्रहीत किया जाता है। किन्तु अपशिष्ट पदार्थों को जिस प्रकार से फैका जाता है वह प्रतिक्रिया निर्विकार नहीं है। इन अपशिष्टों अपशिष्टों का गहरा को पेटियाँ में बंद करके समुद्र में फेंका जाता रहा है। कुछ समय पूर्व रूस ने भी इस तथ्य का स्वाकार किया है। ज्ञातव्य है कि 1945 से जो एक हजार से अधिक अणु विस्फोट हुए हैं। उनमें से 638 अमेरिका व 398 रूस द्वारा किए गए अणुशक्ति का प्रयोग अधिकांशतः विस्फोटित गन्ना द्वारा किया जा रहा है। किन्तु इनसे दुष्प्रभाव के कारण इन्हीं गन्ना एक माध्यम नहीं रहने वाले सम्पूर्ण विश्व का भविष्य उत्तम पड़ सकती है। इस तथ्य का समाधान ज्ञान है कि 28 अप्रैल 1986 का तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु गिबरेटर में भयंकर दुर्घटना घटित हुई थी। इससे आसपास के क्षेत्र में भारी विनाश हो हुआ। इस दुर्घटना के बाद कई दिनों तक आसपास रातों रात वृषाव के एक बहुत बड़े हिस्से में गए हैं जिससे पर्यावरण समुद्रों पर दुष्प्रभाव पड़ा। पशुओं और पौधों की प्रजातियों का अस्तित्व हो खत में पड़ गया। इस प्रकार 6 अप्रैल 1993 का म्हाडगिया के तामस्क 7 नामक एक भूमिगत स्टारज टैंक में गन्ना रेडियोधर्मी विरग पर नियंत्रण के मल में विस्फोट होने से एक बार फिर परमाणु पदार्थ विविध गति पर्यावरण का खतम उत्पन्न हुआ। 131 मार्च 1993 का भारत के नौगा परमाणु रिप्रेटर के युनिट प्रथम व द्वितीय में आग लगने से एक बड़ा दुर्घटना होने-होने का घण्टी। वैज्ञानिकों का कहना है कि परमाणु कार्यन्वा से भूमिगत प्राकृतिक जल भण्डार दूषित हो सकते हैं और अनेक गलियों में तो भूमिगत जल को पदार्थों का मुख्य स्रोत है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि विकास की प्रक्रिया शक्ति व मात्रा व विनाशकारी बल की आवश्यकता इस ज्ञान की है कि शक्ति व सम्पन्नता साधना का विकास

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थाई विकास की समस्याएँ

क्रिया जाए विशेष रूप से सौर ऊर्जा व वायु ऊर्जा के वाणिज्यिक उत्पादन पर बल दिया जाए विश्वव्यापी समझौते व माध्यम से विनाशक औद्योगिकियों के हस्तान्तरण पर रोक लगा देनी चाहिए तथा परमाणु परीक्षणों को तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए।

■ ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ओजोन की परत में छेद (Green House Effect & Hole in Ozone Layer) - ग्रीन हाउस से आशय एक ऐसे हाउस अथवा घर से होता है, जिनकी दीवारों और छतें कच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक जैसे मूल्य लागू होती पदार्थों से बनायी जाती है। यदि हम गृह में कोई पौधा लगाया जाता है तो वह हल-भरा रहता है। ऐसे गृहों का प्रयोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फल व सब्जियों के पौधे लगाने में किया जाता है। शीत ऋतु में इन गृहों में शीत ऋतु में उत्पन्न होने वाली सब्जियों व फलों को उगाई जा सकती है। इन गृहों में सूर्य की किरणें ऊष्मा विद्युत् दीवारों को भेदकर तापमान बढ़ा देती हैं। इस प्रकार शीत ऋतु में भी ऐसे गृहों का तापक्रम बाहरी वातावरण की अपेक्षा अधिक रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और मीथेन आदि गैसों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः वायुमण्डल में ऑक्सीजन की कमी हुई है। विस्तृत औद्योगिक राष्ट्रों ने इस तथ्य को मान लिया है कि ये गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर हो बंद कर रही हैं। फलतः धरातल के तापमान में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या विश्व के सम्पूर्ण एक गम्भीर चुनौती है। इस प्रभाव से आर्कटिक सागर और अण्टार्क्टिका महाद्वीप के विस्तृत बर्फीले भूखण्डों के पिघल जाने में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसके फलस्वरूप पृथ्वी के अनेक भूभाग उलटपुलट हो जाएंगे। सूर्य की किरणों में गर्म होने के परमाणु जल पृथ्वी ठण्डी होने लगती है तो ऊष्मा पृथ्वी में बाहर की ओर विकिरित होना प्रारम्भ हो जाती है। तबान् वातावरण में विद्यमान विभिन्न गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग मोख लेती हैं और इसे पुनः वायुमण्डल में छोड़ देती हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वायुमण्डल में अतिरिक्त ऊष्मा जमा होने लगती है। विगत वर्षों में इन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण पृथ्वी के तापक्रम में तेजी से वृद्धि हुई है। 1998 में नेशनल ऐरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) अमेरिका ने विगत 100 वर्षों के तापक्रम का अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निम्नान्वयित गया कि विगत 100 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.6-1.2 सेन्टीग्रेड की वृद्धि हुई। इसी प्रकार नई दिल्ली में आयोजित 'अन्तर्राष्ट्रीय योजना सम्मेलन,

1990' में वैज्ञानिकों ने कहा था कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे-वैसे वह सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर वातावरण का तापक्रम बढ़ायेगी। इससे जलवायु में परिवर्तनों के फलस्वरूप बाढ़ व सूखा जैसे प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि होगी और उत्तरी ध्रुव की बर्फीले पिघलने से भारत के तटवर्ती क्षेत्र, मालदीव और मंगलादेश जैसे अनेक राष्ट्रों के काफी भूभाग जल में समाहित हो जायेंगे।

वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं प्रथम, औद्योगिकरण और द्वितीय वनों की तेजी से कटाई। आधुनिक युग में उद्योगों के अन्तर्गत मुख्यतः कोयला व पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अतः वायुमण्डल में अनेक प्रकार की गैसें पहुँच रही हैं। इन गैसों में से कार्बन डाई ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी मात्रा में औद्योगिकरण के फलस्वरूप तेजी से वृद्धि हो रही है। मीथेन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड के परमाणु ग्रीन हाउस गैसों में एक ऐसी गैस है, जो पृथ्वी के वातावरण को बढ़ाती है और जो ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। औद्योगिकरण के कारण वातावरण में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों के सनीप वर्षों का जल धरातल पर पहुँचने में पूर्व वायुमण्डल में फैली गैसों में संशोधन करके तेजाब में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी वर्षा में अनेक पर्यावरणीय एवं जैविकीय समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इससे जल एवं मिट्टी में तेजाब की मात्रा बढ़ने में वनस्पति एवं जीवों के मृत अवशेष से दुर्गन्ध फैल जाती है। इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। फलतः अनेक पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त हो जायेंगी। इन सबके फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों में तेजी से वृद्धि होगी। आधुनिक युग में औद्योगिकरण के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से कमी हो रही है। सम्पूर्ण विश्व में वनविनाश एवं मिट्टी के कटाव के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई होगी। पेड़-पौधे वायुमण्डल में कार्बन-चक्र को सन्तुलित करने का काम करते हैं। हरे पौधे प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड को ग्रहण करके अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। अतः वृक्षों के अभाव में मरलेपन क्रिया में कमी हो जाती है और कार्बन डाई ऑक्साइड में वृद्धि। इसके अतिरिक्त, वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से भी कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती

है ज़र वृक्ष का काटा जाता है तो पृथ्वी के अन्दर क़ कुछ कार्बन आक्सीकृत होकर वायुमण्डल में प्रवेश क़ जाता है। अतः वायुमण्डल में कार्बन डाई-ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। यह कार्बन डाई-ऑक्साइड पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है।

वायुमण्डल विभिन्न हल्की एवं भारी गैसों के मगयाजन से बना है। इसे छ भागों में बांटा जा सकता है। इनमें अतर्गत आजान मण्डल पृथ्वीवासियों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यह सूर्य से आने वाली परावर्तनी किरणों का अवशोषण कर लेता है। यदि यह परब नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवधारियों का रहना वदित हो जाता इस परत का ऊँचाई 32 म 80 किलोमीटर है। इस प्रकार आजान परत जाव चनुआ के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है और पृथ्वी का तापवायु एवं मौसम प्रणाली को नियंत्रित करती है किन्तु औद्योगिकरण व फलस्वरूप रहित प्रदूषण व कारण इस परत का शरण क्षार शण्म हो गया है। प्रदूषण के फलस्वरूप बनारसप्लोरा वर्गन की मात्रा में तेजी से वृद्धि व कारण आजान परत में छेद हो गया है अणुकीटिक मगद्वीप में आजान परत में पाया गया छेद एक महाद्वीप चिन्ता रखा हो गया है अतः सूर्य की परावर्तनी किरण गीध पृथ्वी पर गतने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है इसका बुधभाव मानव की आवा एवं त्वचा पर भी दुर्गिणोग हो रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार इस छेद में प्रत्यक्ष 1 सन्तामीटर को वृद्धि से लगभग 40 हजार व्यक्ति परावर्तनी किरण से उत्पन्न रणों व शिवार हो सकते हैं यदि हम छेद में वृद्धि होती गयी तो पृथ्वी का ग्रीन हाउस रतन में अधिक गमन नहीं होगा इसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापवायु और इसकी मौसम प्रणाली में अनेक परिवर्तन हो पाएंगे

राष्ट्रीय समस्याएँ

NATIONAL PROBLEMS

1 **कृषि विकास एवं प्रदूषण (Agricultural Development & Pollution)** कृषि एक कृषावरण की गहरी मध्यस्थ है तथा भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषक विभिन्न प्रकार से फसल उत्पन्न करता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि गांधी मिशन की कृषि उन्नी अक्षरों में है। अक्षर नई प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो कृषि जलमय रूप में अक्षर मय या परिस्थितिगत तब है गुण में विभिन्न पौधे उद्भूत निवास करने वाले जीव जन्तु, जलवायु आदि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य जब इन घटकों में कृषि रूप में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है तो परिस्थितिगत तब

टूट जाता है अथवा अमृतुलित हो जाता है। मनुष्य न विभाग के साथ साथ कृषि विकास के लिए अनक प्रकार व खाद व बीजों की व्यवस्था की है। प्राकृतिक खादा का उपयोग निरन्तर कम होता जा रहा है। खेता में विद्यमान फसलों का रांगो से बगने के लिए व्यापक स्तर पर बीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। एरपरतवारों को नष्ट करने व लिए भी बीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। भूमि का क्षमता का अधिक-स-अधिक उपयोग करने के लिए उसमें तान तान बार बार फसले लिए जान की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रहा है। इन सभी कारणों से भूमि का मूल स्वरूप ही परिश्रित हो रहा है। कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग भी रहा है। मनुष्य न क्षेत्रों की हरियाली को नष्ट करके भयन रूपों में स्थानित कर दिए हैं जो पूना सीमेट ककर पत्थर में तातावरण का असंतुलित हो करत है जल और वायु में भूमि का बड़ पैमाने पर बटाव भा हान लगा है और यह प्रवृत्ति बढ़ता जा रही है। भूमि को कटाव में भी भूमि का मूल स्वरूप बदल रहा है। भूमि को कटाव के कारण नदियों में गाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है जो विभिन्न प्रकार से प्रदूषण का जन्म देता है। हरित क्रांति के पश्चात् भारत में कृषि के अन्तर्गत मानव का हस्तक्षेप बढ़ा है। सामाजिक उर्वरकों में भूमिगत जल के प्रदूषण के बार में इंडियन सामागटी आफ एग्राफूरल इकारिकम् द्वारा बरई में आयोजित सम्मेलन में महत्वापूर्ण तथ्या की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया था। इंग्लै पञ्जाब एग्रीकल्चरल यूनियनमिटी के वीन वैज्ञानिक एन एम चन् इतरवाल मिह और विजय मिह न रहस्याद्यानन किया कि रासायनिक उर्गता व अत्यधिक इन्तमान में पञ्जाब में भूमिगत जल के प्रदूषण में अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है। इनक अनुसार पञ्जाब में कृषि वायु भूमि में नाइट्रेट नाईटाजन की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय का गड़ और सुरक्षित माना जान वाला मात्रा में अधिक पाई गई है। यंग क्ललखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मर्तारिक नाइट्रेट व रण में 10 पार्ट्स प्रति मिलियन (पाएएम) नाईटाजन मात्रा माना जाता है जिससे नुकसान नहीं होता है। जिससे तम घुटन जैसी घातक स्थिति पैदा हो जाती है। इन 'अवशेस' के अनुसार अधिक कृषि पैदावार देने के लिए खिमान ब्रह्मण से ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्गता व इन्तमान कर रहे हैं। जिससे भूमिगत जल का प्रदूषण रार होता रहेगा।

यं ध्यान देने योग्य है कि गमनागर्भित उत्तरि क
50 प्रतिशत भाग हा फसल का पाषाण है। इसका 25
पाषाण भाग धियाट म मित्रक नाइग्रेस तन म लान
जाता है और शेषी 25 प्रतिशत भाग भूपात जन म
धियाट उस प्ररिण वर डानता विना म्माय्य माग

का एक प्रतिशत के अनुसार रासायनिक तत्वों को मिलाने से भूमिगत जल का अम्लीकरण हो जाता है। इस अम्लीकरण को वृद्धि में भूमिगत जल मनुष्य द्वारा पीए जाने पर शरीर में विषाक्त पैदा कर सकता है। ऐसे प्रदूषित जल में कैडमियम, अल्यूमीनियम, जस्ता और सोडा आदि होते हैं जो शरीर में डायरिया मगले रोग पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस जल में मौजूद नाइट्रेट पैदा के कैंसर जैसे घातक रोगों को भी पैदा कर सकता है।

यह मान्य है कि भारत में कृषि विकास के बिना अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव प्रतात नहीं होता। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि फसलों में रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग विना जाए। रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक व प्राकृतिक खाद का उपयोग बढ़ाया जाए तथा भूमि का क्षण रोका जाए।

2 औद्योगिक विकास एवं प्रदूषण (Industrial Development & Pollution) - भारत के औद्योगिक विकास ने ब्रह्म वायु में विद्यमान जल को सल्फर डाई आक्साइड व जरिए तेजाबी बनाया है, वहीं पृथ्वी पर विद्यमान पानी को विभिन्न किस्मों के कचरे तथा अपशिष्ट से और भी प्रदूषित किया है। अपने देश में भूमिगत जल-संपदा एक मोटे अनुमान के अनुसार वहाँ हर साल होने वाली वर्षा से कम गुना ज्यादा है। भूमिगत जल संपदा के पूरे आकड़े यहां उपलब्ध नहीं हैं फिर भी अनुमान है कि भारत में 300 मीटर की गहराई में करीब 3 अरब 70 करोड़ हेक्टेयर भीतर जल भंडार मौजूद है। इस जल भंडार पर रासायनिक उर्वरकों के अलावा उद्योगों कारखानों में भी प्रदूषण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

वर्ष 1993 में रेशा उद्घाटन और तमिलनाडु में चण्डा शोधन केन्द्र रडी मात्र में भूमिगत जल का प्रदूषित कर रहे हैं। केरल व कानकोने में नारियल के रेशों को साफ करने के लिए पानी में डुबा कर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में हाईड्रोजन सल्फाइड और ऑर्गेनिक तेजाबों से भूमिगत जल जहरीला हो जाता है। मैटर वॉर अर्थ साइमैज स्टडीज, त्रिवंद्रम के निदेशक डॉ. सी. कल्याणकर के अनुसार, उपलब्ध भूजल भंडार बारिश के पानी से घुलकर साफ हो जाते हैं मगर गहरे भूजल भंडार की समस्या गंभीर है। भविष्य में पानी का यही स्त्रोत काम आएगा। नगरों में हिन्दू विश्वविद्यालय व भूगर्भ वैज्ञानिक डॉ. गिरिश चन्द्र चौधरी ने भी एक अध्ययन में पाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में भूमिगत जल में फेडिफर्म तत्व मौजूद हैं। नगरों में हिन्दू व एक कुएँ में यूरेनियम के प्रति बिलियन

1/6 अंश मिले और दूसरे कुएँ में 15 अंश प्रति बिलियन थे। ज्ञातव्य है कि यूरेनियम का मान्य स्तर प्रति बिलियन 15 अंश है। गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और मिर्जापुर जिलों में डॉ. चौधरी ने भूमिगत जल में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फस्फेट, सोडा, जस्ता, मैग्नेज आदि जहरीले धातुओं को अधिक मात्रा में पाया। देश में इस समय कीटनाशक, उर्वरक, कृमिनाशक, पेस्ट, चमड़ा, सोडियम, पोटेशियम, रेयन, कुछ दवाइयों, फाउड्रीज, बैटरिया, एसिड, एल्कली, प्लास्टिक, रबड़, सीमेंट, एसबेस्टर आदि मग्न ऐसे उद्योग हैं, जिन्हें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में घोषित किया गया है। इनमें सर्वाधिक खतरनाक सिद्ध हो रहा है, कीटनाशक औषधि-उद्योग जिसमें हर दो मिनट में प्रभावित होने वाला एक व्यक्ति भारतीय है। 1974 में कीटनाशक के उपयोग ने तमिलनाडु में न्यूब वीन हज़ार तथा महाराष्ट्र में 400 लोग मारे गये। भारत जैसे उष्ण देश में कीटनाशक का प्रभाव ज्यादा प्रबल है। आई टी आर सी, लखनऊ की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती भारतीय महिलाओं में क्लोरोनयुक्त हाईड्रोकार्बन का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है। भारत के छिड़काव-कर्मचारियों में और लोगों के मुकाबले इसके अवशेष ग्यारह गुणा अधिक होते हैं। कीटनाशकयुक्त चारा खाने वाली मुर्गियों द्वारा दिए गए 10 अंडों में में 11 में डीडीटी के अवशेष पाये जाते हैं। दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों में जापान को छोड़कर भारत पेस्टिसाइड्स का सबसे बड़ा निर्यात है। जाहिर है प्रदूषण भी यहाँ सर्वाधिक है।

1993 में सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आयोजित सगोष्ठी के प्रस्तावों में कहा गया कि औद्योगिक अपशिष्टों के निष्कासन एवं रासायनिक अपशिष्ट को निष्क्रिय करने के लिए नवीनतम तकनीकी का विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किया जाए वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोतों का प्रयोग बढ़ाया जाए नये उद्योगों की स्थापना में पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि दुर्घटना की अवस्था में क्या प्रतिक्रियायुक्त सुविधाएँ उपलब्ध हों। अन्य प्रस्तावों में कहा गया है कि वानिकी को उद्योग घोषित किया जाए तथा प्रत्येक उद्योग को आवंटित भूमि का एक तिहाई भाग वानिकी के लिए सुरक्षित रहे। जनता को उद्योगों के बारे में जानकारी व अधिकार दिया जाए तथा उद्योगों द्वारा स्वयं की ओर से प्रदूषण सबसे सही उपलब्ध जानकारी हर तीसरे माह अखबारों में प्रकाशित करना आवश्यक किया जाए। इसके साथ ही पर्यावरण ऑडिट में स्वैच्छिक संगठन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, विधिवेत्ता एवं पर्यावरण वैज्ञानिकों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार करवाई जाए।

3 परिवहन विकास एवं प्रदूषण (Development of Transport & Pollution) औद्योगिक क्रांति क फलस्वरूप मनुष्य ने अपना मुख सुविधा के लिए अनेक माधन एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगिक विकास की दर तीव्र होना प्रारंभ हो गई। औद्योगिक विकास के साथ देश में मोटरगाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ने लग्य। मोटरगाड़िया एक ऐसा माधन है जो शहरी क्षेत्रों में समाज को गति प्रदान करता है। ये औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत भी है। प्रयोग की दृष्टि से इन्ने दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम पेट्रोल से चलने वाले वाहन जैसे स्कूटर मोटर साइकिल कार व मोपेड और द्वितीय डीजल से चलने वाले वाहन जैसे बस टक व मैट्रिडार आदि। भारत के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है अतः सार्वजनिक परिवहन प्रणाली दृढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती है। फलतः व्यक्तिगत वाहन की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उद्योगों का तेजी से विस्तार तथा महानगरों का सुनियोजित विस्तार नहीं होने के कारण भी व्यक्तिगत वाहनों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि स्कूटर मोटर साइकिल व कारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है सम्पूर्ण भारत में कुल मोटर साइकिलों का 60% भाग स्कूटर मोटर साइकिलों और मोपेड आदि वाहन का है इनका लगभग 40% महानगरों में है। मोटरगाड़ियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ महानगरों में प्रदूषण का समस्या तेजी से बढ़ रहा है। सम्पूर्ण भारत में पंजीकृत कुल मोटरगाड़िया का लगभग 35% महानगरों की सड़कों पर गतिमान रहता है। इनमें अनेक प्रकार के प्रदूषक धुएँ के रूप में उत्पन्न होते हैं। पेट्रोल से चलने वाले गाड़िया में मुख्यतः कार्बन मोनो आक्साइड हाइड्रोकार्बन तथा सीसा आदि निकलते हैं। इस प्रकार डीजल से चलने वाली गाड़ियों में मुख्यतः नाइट्रोजन के आक्साइड और आक्साइड हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। इसके अतिरिक्त मोटरगाड़िया के धुएँ में मल्पर डाई आक्साइड कार्बन मोनो आक्साइड व हाइड्रोकार्बन आदि तत्व निकलते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा 1980 में किए गए अध्ययन के अनुसार दिल्ली में उत्पन्न होने वाले 1172 729 टन वायु में से 670 605 टन वायु प्रदूषक प्रतिदिन दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली 13 लाख गाड़िया से उत्पन्न होता था। 1981 82 में पेट्रोल के उपयोग से 24 5 टन शीशा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ 1991 92 में यह मात्रा बढ़कर 52 2 लाख टन होन का अनुमान था। दिल्ली में मोटरगाड़ियों से उत्पन्न वायु प्रदूषण में लगभग 90 ग्राम प्रदूषक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सामान्य

जाने के लिए पर्यावरण में उपलब्ध रहते हैं। वायु प्रदूषण की यह मात्रा अत्यधिक यातायात वाले क्षेत्रों में और भी अधिक हो सकती है।

1987 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र का राजधानी मुम्बई में पंजीकृत कुल मोटरगाड़ियों की संख्या 520838 थी जिसमें आधी से अधिक कारें आर जीपी थी। इन गाड़ियों से मुम्बई में प्रतिदिन 548 81 टन वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। मुम्बई में पेट्रोल के उपयोग से 1981 82 में 25 ॥ टन शीशा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ जिसका मात्रा 1991 92 में बढ़कर 52 5 टन होन की संभावना थी। मुम्बई में लगभग 53 ग्राम वायु प्रदूषक प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मोटरगाड़िया से उत्सर्जित होकर पर्यावरण में फैलते हैं। इस महानगर में निजनों में चलने वाली तीव्र गति की लोकन गाड़िया की सुगंध होने के बावजूद भी यहाँ का भागों पर मोटरगाड़ियों का दबाव बहुत अधिक है।

भारत में कलकत्ता सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगरों में से एक है। यहाँ भी बहुत अधिक संख्या में मोटरगाड़िया के यातायात से निकलने वाले वायु प्रदूषक घातक रूप धारण कर चुके हैं। इनके उपयोग से 1981 82 में 14 टन शीशा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ। 1991 92 में यह मात्रा बढ़कर 28 7 टन होन का अनुमान था। कलकत्ता में मोटरगाड़ियों से उत्सर्जित 23 31 ग्राम प्रतिव्यक्ति वायु प्रदूषक पर्यावरण में मिलते हैं।

मद्रास देश का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है। भयानक दो तिहाई में अधिक संख्या में मोटरगाड़िया की हैं। इनसे 188 54 टन वायु प्रदूषक प्रतिदिन उत्सर्जित होते हैं यहाँ प्रतिव्यक्ति 48 58 ग्राम वायु प्रदूषक मोटरगाड़ियों से उत्सर्जित होकर हवा में मौजूद रहते हैं। पेट्रोल की मोटरगाड़ियों के उपयोग में मद्रास में 1981 82 में 5 6 टन शीशा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ।

लखनऊ में मोटरगाड़ियों में 69 50 टन वायु प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इस नगर में प्रतिव्यक्ति 65 88 ग्राम वायु प्रदूषक मोटरगाड़िया से उत्सर्जित होकर वायु मायामें घुलते हैं। वाराणसी में भी मोटरगाड़ियों से निकलने वाली गैस गंधीय रूपधारण कर रही है वाराणसी में मोटरगाड़ियों से 71 80 टन वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है।

सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ से उत्सर्जित गैसों का मनुष्य, जानवरों और पक्षियों पर प्रत्यक्ष या पराग रूप में प्रभाव पड़ता है। मोटरगाड़ियों द्वारा उत्सर्जित कार्बन मोनो आक्साइड एक जहरीली गैस है। इस गैस की उपस्थिति में रक्त में आक्साजन का बंधा हो जाती है। रक्त के द्वारा ले

शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। शरीर में ऑक्साइजन की कमी का सबसे बुरा प्रभाव केन्द्रीय स्नायुतंत्र पर पड़ता है। इससे स्नायुदुर्बलता तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव होता है। हार्डवुर्क कार्वन के वातावरण में उत्सर्जित होने से आस और गले में जलन तथा कैसर होने की सम्भावना रहती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति स खास सास लेने में दिक्कत और फेफड़ों के खराब होने का भय रहता है। इन गैसों से मिलकर बने फोटोकेमिकल स्मॉग से सास की बीमारी, आँखों में जलन और गले में छागी होती है। सल्फर डाई ऑक्साइड कई तत्वों में मिलकर जहरीले और कैसर कारक तत्वों को जन्म देते हैं। पेट्रोल की गाड़ियों से उत्सर्जित होने वाला सीमा फेफड़ों यकृत गुर्दे और वृक्कों के मस्तिष्क को हानि पहुँचाना है तथा महिलाओं की प्रजनन क्षमता को भी क्षीय करता है।

1987 के आकड़ों के अनुसार देश के 12 महानगरों में कुल मिलाकर लगभग 3 हजार टन प्रदूषणकारी तत्व वाहनों के धुएँ के रूप में वायुमण्डल में छूटते हैं। शायद यह माना जाता है कि सबसे अधिक प्रदूषण डीजल की गाड़ियों से होता है, लेकिन स्वास्थ्य को सबसे अधिक हानि दुपहिया व तिपहिया वाहनों की वजह से होती है। पेट्रोल से निकलने वाला सांसा भारत में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है जबकि यूरोपीय राष्ट्रों में ऐसे इन्जन वाहनों में लगाए जा रहे हैं जिन्हें सीमा मिले पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। हमारे देश में यह ब्रह्म वाहनों के इन्जनों की जरूरत के लिए मिलाना पड़ता है। मुम्बई में अनेक स्थानों पर तिपहिया वाहनों की चलाने की मनाही है पर दिल्ली में कोई स्थान उनसे अछूता नहीं है। दिल्ली के वाहनों की कुल संख्या में 70% में अधिक दुपहिया वाहन हैं। इनमें से 2 स्टोक इन्जन होने के कारण कार्वन मोनो ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन बहुत अधिक होता है। नई दिल्ली में निर्धारित किए गए प्रदूषणों के स्तर में यह स्मॉट रूप से पता चलता है कि यातायात नौराओं पर भुल एवं धुएँ का स्तर लगभग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीमाओं से भी अधिक बढ़ता जा रहा है। मुम्बई में समुद्र और बंगलौर की घनी हरियारी बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषणकारी मात्रा को माख लेती है इसलिए उनका अधिक प्रभाव दुस्मिगन्ध नहीं होता है। चलकन्ना और अहमदाबाद में न के हानिपला है और न ही बहुत अधिक खुल्ला स्थान है अतः मारी गैस मिमट कर रह जाते हैं और प्रदूषण बढ़ता जाता है। मरिंदो में वायु-प्रदूषण की समस्या अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि कम तापमान के कारण गैसें फैल नहीं पाती और नीचे ही रह जाती हैं।

ताप-विद्युत, गैस व अणु-शक्ति आदि शक्ति के साधनों का तीव्र गति में विकास हुआ है। शक्ति के माधनों से भी प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ी है। भव्यता-शक्ति के समय डिगबोई तेल शोधनशाला की स्थापना के साथ भारत में तेलशोधन उद्योग श्रम्भ हुआ। वर्तमान में अनेक तेलशोधन शालाएँ कार्यरत हैं। कच्चे तेल की शोधन-प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के तरल, गैसीय और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। ये पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। 'नवभारत टाइम्स-मोड सर्वेक्षण' से ज्ञात हुआ है कि दिल्ली के दो तापविजलीघरों का भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान है। इनसे 25 हजार टन से भी अधिक सल्फर डाई ऑक्साइड और राख प्रतिवर्ष वायुमण्डल में पहुँचती है। दिल्ली के बरारपुर तापविजलीघर में प्रदूषण को कम करने वाले बहुमूल्य उपकरण लगाये गए हैं, लेकिन इसकी चिमनियाँ से निरन्तर काला धुआँ निकलता रहता है। इससे आसपास के क्षेत्रों के घरों में कालिख जम जाती है। देश के प्रायः प्रत्येक बड़े शहर में अथवा उनके आसपास ताप विजलीघर होता है। अधिकांश प्रदूषण इसी से होता है। हमारे देश में तेल के साथ निकलने वाली शक्ति गैस की काफी बड़ी मात्रा जलकर गूँथ कर दी जाती है, क्योंकि उसका भंडारण सुभव नहीं है। वायुमण्डल में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर यह नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो बारिश के पानी को अम्लीय बना देता है। ऐसी बारिश से पेड़-पौधों, भूमि की उर्वरता और भवनों पर बुरा असर पड़ता है। मुम्बई के चेंबूर और कल्याण क्षेत्रों में वर्ष 1974 से लगातार अम्लीय बारिश की खबरें आती रही हैं। दिल्ली में इन्ड्रप्र तापविजलीघर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ वर्ष प अम्लीय वर्षा हुई थी।

भारत में समय-समय पर परमाणु ऊर्जा सयंत्रों में खराबी के कारण भी प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती रही है। 31 मार्च, 1993 को रायपुर परमाणु रिएक्टर के फूटित प्रथम के जेनेरेटर में आग लगने में एक बड़ी दुर्घटना होने-होते टल गयी थी, क्योंकि आग मुख्य सयंत्र से केवल दो सौ मीटर दूर लगी थी। उसके दो वर्ष पूर्व कारगरार रिएक्टर में भी आग लग चुकी थी। मकारी आकलन में परमाणु कार्यक्रम से भूमिगत प्राकृतिक जल भण्डारों को खतरे की चेतावनी दी गई है। यदि भूमिगत जल में रेडियोएक्टिव पदार्थ बढ़ते हैं तो यह बिना क वियत्र है, क्योंकि देश को आधी जनसंख्या के लिए भूमिगत जल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है।

4 शक्ति के साधन एवं प्रदूषण (Sources of Energy & Pollution) - भारत में पेट्रोलियम-शासन

5 खनिजों का विदोहन एवं प्रदूषण (Exploitation of Minerals & Pollution) - औद्योगिक विकास की

दृष्टि से खनिज पदार्थों का अधिक महत्व होता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में खनिज पदार्थों का तेजी से विदोहन किया जा रहा है अतः इससे पर्यावरण का सकट गहरा होता जा रहा है। खनिज प्राप्त करने हेतु वन काट दिए जाते हैं। इससे न केवल पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वरन् मिट्टी के कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। औद्योगीकरण के साथ-साथ खनिज पदार्थों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है अतः देश के प्रायः अनेक भागों में खनिजों के विदोहन का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। खनिज प्राप्ति हेतु वन काट दिए जाते हैं। अतः पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खान क्षेत्र में मलबे के बहुत बड़े क्षेत्र में ढेर लग जाते हैं। इससे न केवल वृष्टि विकास व वन विकास में बाधा उत्पन्न होती है, वरन् कुछ खनिजों के अत्यधिक वायु के माध्यम से उड़कर एक बहुत बड़े क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, उदाहरण के लिए, देश के जिन क्षेत्रों में कोयले की खानें हैं, वहां के आस-पास के क्षेत्रों में कोयले की गंध के छोटे-छोटे कण वातावरण में फैल जाते हैं। अतः आम लेंने में कठिनाई होती है और उन क्षेत्रों के अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के चर्म रोग व श्वास रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। खनिज प्राप्ति वाले क्षेत्रों में वन-विनाश के कारण मिट्टी का कटाव होना प्रारंभ हो जाता है। उन क्षेत्रों की भूमि वृष्टि के योग्य भी नहीं रह पाती है। अतः पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

मानव ने औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक ससाधनों जैसे भूमि खनिज पदार्थ, पशु-सम्पदा वन-सम्पदा एवं जल आदि का तेजी से उपयोग किया है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ भूमि का उपयोग आवासीय एवं औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। इससे न केवल कृषिभूमि के क्षेत्रफल में कमी हुई वरन् अतिरिक्त भूमि प्रायः वन हेतु वन काट दिए जाते हैं। अतः वनों के क्षेत्र में तेजी से कमी हो रही है।

● **शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि एवं प्रदूषण (Urbanisation Growth of Population & Pollution)** - विकास के साथ साथ शहरों के आकार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या शहरों का विकास बाधों का निर्माण एवं औद्योगीकरण के लिए वनों की अधाधुन कटाई का गवाकषण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगीकरण व कारण गन्नाकार के अवसरों में वृद्धि होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति राजगार प्राप्ति हेतु शहरों में जाकर बस जाते हैं। इससे शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। बढ़ती हुई

जनसंख्या से विविध होकर मानव ने बहुत तीव्रता से वन एवं पर्वत काटकर बहु-उपयोगी तथा आवासीय इमारतों का निर्माण किया है। इससे पिछले कुछ दशकों में ही पर्यावरण का सकट गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शहरीकरण में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मानव द्वारा विमर्जित मलमूत्र, धुआँ, गैस, धूल के कण और अशुद्ध जल के फलस्वरूप वायु जल एवं ध्वनि आदि प्रदूषणों में वृद्धि हुई है।

वाहनों व मशीनों की बढ़ती संख्या से वातावरण में अवांछनीय शोर भर गया है। जनसंख्या-वृद्धि में शहरीकरण मशीनीकरण औद्योगीकरण, भूमि की कमी, वैज्ञानिक आविष्कारों का परीक्षण एवं वनों का अधाधुन विनाश ही प्रदूषण के कारण हैं। प्राकृतिक साधनों के अत्यधिक उपयोग के फलस्वरूप ही पर्यावरण असंतुलन बिगड़ने से प्रदूषण बढ़ने लगा है। इस प्रकार बढ़ता हुआ प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक चुनौती बन गया है। इस समस्या का समाधान वनों के विकास में ही निहित है। वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि जिन इलाकों में वन क्षेत्र 6% से कम हो जाता है वहाँ सम्भाव्यताएँ नष्ट हो जाती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के वन-क्षेत्रों में तेजी से कमी हुई है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि वनों से आच्छादित क्षेत्र में तेजी से कमी हुई है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वन-क्षेत्रों का तेजी से विस्तार किया जाए।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के शहरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। शहरी जनसंख्या में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। एक अनुमान के अनुसार सन् 2000 तक भारत की शहरी जनसंख्या 35-40 करोड़ तक लगभग हो जाएगी। ग्रूमिमेंप के अनुसार बड़े मद्रास कलकत्ता व दिल्ली विश्व के 30 बड़े नगरों में गिन जाएंगे तथा इनमें प्रत्येक की जनसंख्या एक करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। अत्यधिक शहरीकरण के कारण भूमि की उपलब्धता आसाम में घटित हो गई है। विश्व में गंगा में अत्यधिक परतयन के कारण शहरी सुविधाओं में भी कमी आई है। विश्व वैश्व व एक शोध-पर्यटन आंतराष्ट्रिय पर्यटन प्रत्युत्पन्न इन्डिया एंड आशान्ति फार डेवसपिंग कट्टीज के अनुसार तीसरा दुनिया के देशों में तेजी से शहरीकरण के कारण प्रदूषण खतरनाक सीमा तक पहुँच रहा है। सन् 2000 तक इन देशों के 75 नगरों में प्रदूषण अत्यधिक हो जाएगा।

(स) राजस्थान की विशिष्ट समस्याएँ

SPECIAL PROBLEMS OF THE STATE

1 राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं प्रदूषण (Industrial Development in Rajasthan & Pollution) - स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राज्य के जयपुर, कोटा, अलवर, अजमेर, पाली भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर व ग्वालनगर आदि क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रही है। औद्योगिकरण के कारण इन क्षेत्रों का तटों से विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही साथ इन क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या ने भी गम्भीर रूप धारण कर लिया। राज्य के पाली क्षेत्रों में वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई का कार्य प्राचीनकाल से होता आ रहा है। विगत कुछ वर्षों में इस शहर में रंगाई एवं छपाई उद्योग का तेजी से प्रसार हुआ है। इन कारणों से लगभग 40 लाख गैलन अपशिष्ट जल प्रतिदिन विनिर्जित होता है। शहर के निकट वाडी नदी है जिसमें गाँव का तीन ओर से घेर रखा है। शहर के कारखानों का जल इस नदी में जाता है। इस जल में मीडियम मिनिक्वैलिटी हाइड्रोऑक्साइड क्लोराइड-नाइट्रोजेन कैंगसीन एवं बोरेट आदि तत्व होते हैं। घरे-घीरे विभिन्न प्रकार के रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। कुछ व्यक्ति इस अपशिष्ट जल से कैरोसीन निकालने का कार्य करते हैं। इस अपशिष्ट जल के कारण नदीक्षेत्र की भूमि की उर्वरशक्ति समाप्त हो गयी है और एक बहुत बड़े भू-भाग का भूगर्भीय जल भी रसायन तथा प्रदूषित हो गया है। इस जल के सेवन के कारण अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो चुके हैं। इन कारखानों में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक अशिक्षित एवं अग्रशिक्षित हैं। वे प्रायः अदाज से हो गये व रसायनों का मिश्रण तैयार करते हैं, अतः कुछ रंग व रसायन आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं जो प्रदूषण की समस्या को अधिक गम्भीर बनाते हैं। सरकार द्वारा जल प्रदूषण के निवारण हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं लेकिन इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इससे विपरीत राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेक कारखाने ही बंद कर दिए हैं लेकिन यह उपाय उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इससे राज्य के औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाएगी।

राजस्थान की राजधानी जयपुर का औद्योगिक विकास राज्य के प्रायः सभी औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में तीव्र गति से हुआ है। कोटा शहर राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहां कोयला कारखानों के कार्बन-स्टक और ईंट-पट्टों की प्रदूषित वायु ने शहर के पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर

दिया है। राज्य का उदयपुर शहर के निकट रसायन उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इन कारखानों के अपशिष्ट जल के कारण लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में भू-गर्भीय जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। इस क्षेत्र की भूमि की उर्वरशक्ति भी समाप्त हो चुकी है। गजस्थान में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के फलस्वरूप चम्पल, पार्वती, वातीसिंध, अलनिया, खडो और तुण्डी आदि नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं।

2 खनिज विदोहन एवं पर्यावरण अधिसूचना (Mining & Environmental Notification)¹ - राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य के अधिकांश खनिज क्षेत्र पहाड़ी व वन क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः खनिजों का विदोहन करने पर पर्यावरण को क्षति पहुँचती है और यदि खनिजों का विदोहन नहीं किया जाए तो विकास अवरोध होता है। अतः केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 1993 में जारी अधिसूचना का सर्वाधिक प्रभाव खनिज एवं उद्योग क्षेत्र पर पड़ेगा। केन्द्र द्वारा जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि वन्य-जीवों के लिए आरक्षित अभ्यारण्यों के 5 किलोमीटर क्षेत्र में खनन, भवन निर्माण व व्यवसाय को निषिद्ध क्षेत्र कर दिया है। राज्य में अधिकांश खनन कार्य अरावली पर्वत श्रृंखला में पट्टे-धारकों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। जहाँ इस पर्वत श्रृंखला में सोना, चादी, तांबा आदि बहुमूल्य धातुएँ पाई जाती हैं, वहाँ 30-35 अन्य किस्म के अप्रधान खनिज भी मिलते हैं, जिनमें दलहरी व पत्थर आदि भी शामिल हैं।

निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की ओर से जारी वार्षिक प्रतिवेदन में प्रधान खनिजों के पट्टों की संख्या 1413 है, वहीं अप्रधान खनिजों के पट्टों की संख्या 8809 है। पर्वतश्रृंखला में प्राप्त होने वाली धातुओं के जिलेवार आकड़ों की स्थिति से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि खनन कार्य प्रत्यक्ष तौर से प्रदेश के अभ्यारण्यों व अन्दर या नजदीक ही पट्टेधारकों द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में होने वाला खनन कार्य राष्ट्रीय परियोजना व अभ्यारण्यों से सीधे तौर पर जुड़ा है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य में दो राष्ट्रीय पार्क व 23 अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर रखे हैं। यह तथ्य अभ्यारण्य शत प्रतिशत तौर पर अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ते हैं जहाँ कि हरियाली का अभाव होता है। राष्ट्रीय पार्क में रजदमौर नेशनल पार्क व केन्द्रीय राष्ट्रीय उद्यान है। इनका क्षेत्रफल क्रमशः 392 व 2873 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य में अलवर स्थित मरिचक का 492 कोटा स्थित टर्न 265 धौलपुर स्थित वन विहार 5993 उदयपुर स्थित जयमन्द 52 मिर्गोही स्थित माऊण्ड

आबू 288 84, उदयपुर स्थित कुम्भलगढ 578 25, चूरु स्थित तालछापर 7 90 चित्तौड़गढ स्थित सीतापाता 422, कोटा स्थित राष्ट्रीय चमल 280, जयपुर स्थित नाहरगढ 50 रामगढ 300, कोटा स्थित जवाहर सागर 100, जैसलमेर स्थित डेजर्ट 3162, बूंदी स्थित रामगढ विष्णुगरी 307, चित्तौड़गढ स्थित पैमरोडगढ 229 14, सर्वाईमाधोपुर स्थित कैलदेवी 676 38, कोटा स्थित शेरगढ 98 71, अजमेर स्थित टाडागढ रावली 495 27, पाली एव उदयपुर स्थित फुलवती की नाल 511 41, सर्वाईमाधोपुर स्थित सर्वाई मानसिंह 403 25, भरतपुर स्थित बन्ध बराठा 192 76 तथा उदयपुर स्थित सज्जनागढ 5 19 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। वैसे विभाग ने बीकानेर स्थित गजनेर को भी गत कुछ वर्ष पूर्व अभ्यारण्य घोषित कर दिया है।

खनन कार्य व अभ्यारण्य की स्थिति का अवलोकन करने पर विदित होता है कि बहुत कम भू-भाग शेष रहता है, जहां कि खनन कार्य शुरू किया जा सकता है। वस्तुतः 5 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से भौगोलिक दृष्टि पर गौर करने पर ज्ञात होता है कि खनन कार्य हेतु कहीं भी भू-भाग शेष नहीं रहता है। खनन कार्य के भू-भाग का प्रश्न है, उसमें निदेशालय के आकड़ों के मुताबिक कच्चे तांबे की खदानें अलवर व नीम का धाना क्षेत्रों में सात की संख्या में कार्यरत हैं। इसके अलावा फास ही खेतड़ी तांबा परियोजना भी स्थित है। मार्बलजिन क्षेत्र में होने के बावजूद नये खननम्बोतों की मजूरी प्राप्त करने के लिए उसे भी अधिसूचना का पालन करना होगा।

पट्टेधारक खदानों के क्षेत्रों में स्पष्ट पता लग जाता है कि तमाम पट्टेधारकों को या तो अनापति प्रमाण-पत्र में गुजरना पड़ेगा या फिर उनके दावे खारिज हो जाएंगे। अगर उक्त खनन पट्टे पर्यावरण की ओट में खारिज होते हैं तो देश का विकास तो अवरोध होगा ही, साथ ही प्रदेश को दो अरब से भी ज्यादा आय से हाथ धोना पड़ेगा। इनमें मार्बलजिन क्षेत्र सबसे ज्यादा घाटे में रहेगा।

केन्द्र के वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना की गिरफ्त में राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (रीको) भी आ चुका है। निगम ने उद्योग विस्तार के उद्देश्य से खनिजप्रधान उद्योगों में प्रवर्तकों के सहयोग से करीब 92 करोड़ की पूंजी पंजा रखी है। लगता है कि इस राशि पर भी अधिसूचना का असर होगा। इनके अलावा अन्य खनिज आधारित उद्योगों पर कुल मिलाकर तीन-चार सौ करोड़ की पूंजी लगी हुई है। अब अधिसूचना के अक्रा ने इतनी बड़ी पूंजी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

रीको के सहयोग में स्थापित खनिजप्रधान उद्योगों की संख्या 59 है, जिसमें अवधि ऋण के अलावा रीको की भागीदारी भी है। रीको की भागीदारी वाले इन उद्योगों में ऋण की राशि 26 55 करोड़ है, वहीं हिस्सा राशि 152 25 लाख है। उद्योगों में 5556 व्यक्तियों को सीधा रोजगार भी मिला हुआ है।

खनिज तत्वों से भरपूर जिलों के आसपास स्थापित औद्योगिक इकाइयों के केन्द्रों में आबू रोड, उदयपुर, मकराना, राजममन्द, झालावाड़, अलवर, सिंगेही अजमेर, जयपुर बहरोड, सकोरोली, कुम्भलगढ, बेरावड नाथद्वार, चित्तौड़गढ, जोधपुर आदि प्रमुख हैं। ये तमाम औद्योगिक क्षेत्र न केवल इस अधिसूचना की चपेट में हैं वरन् प्रदेश में अभ्यारण्यों की महत्ता को देखते हुए कच्चे माल की खरीद के भी उद्योगपतियों को लासे पड़ सकते हैं। ऐसे खनिज-आधारित उद्योगों की संख्या 56 के आसपास है।

रीको के सहयोग से क्रियान्वित उक्त तमाम उद्योगों में अधिकतम प्रेनाइट - आधारित इकाइयों की है। प्रेनाइट उद्योग वर्तमान में शैशवकाल के दौर से गुजर रहा है। अप्रधान खनिज की इकाइयों की भरमार गत वर्ष से ही ज्यादा बढ़ी है, खासकर तय से जबकि सरकार ने प्रेनाइट के भण्डारों के बारे में बड़ चढ़कर प्रचार-प्रसार किया है। अब इस खनिज-आधारित इकाइयों की स्थिति यह है कि ये शल-प्रतिशत तौर पर टाइल्स का निर्यात कर रही हैं। इसके अलावा, रीको से सम्बन्धित कैमिकल व क्वार्ट्ज आधारित कई उद्योग भी 300-400 करोड़ की पूंजी से उत्पादन कार्य कर रहे हैं।

3 विकास एवं वन विनाश (Development & Deforestation) - वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक ससाधन है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन-संरक्षण के फलस्वरूप वातावरण में संतुलन बना रहता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के निरन्तर उत्पादन हेतु वन की समुचित सुरक्षा एवं प्रबंध की आवश्यकता होती है। यदि मानव औद्योगीकरण, शहरीकरण और आर्थिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए वनों का अत्यधिक प्रयोग करता है तो वनों का विनाश प्रारम्भ हो जाता है। इसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल केवल 9 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33 33 प्रतिशत में वन होने चाहिए। राज्य के कुल वनक्षेत्र का लगभग 1/3 भाग में सघन वन पाए जाते हैं और शेष भाग में झाड़ीदार वनों की प्रमुखता है। राज्य का लगभग 20 मिलियन हैक्टर क्षेत्र

शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में है। इसके लगभग 50 प्रतिशत भाग में बालू रेत के टीले विद्यमान हैं। यह क्षेत्र राज्य के मायाचिक-आर्थिक जीवन और पारिस्थिकी पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है, लेकिन इस क्षेत्र में मिट्टी के कटाव की समस्या एक बहुत बड़े भू-भाग में विद्यमान है। इन क्षेत्रों की लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि में चन्बल के गहरे गर्त विद्यमान है। इसका अलावा राज्य का विशाल भू-भाग अरावली, विन्ध्यचल पर्वतमालाओं के अंतर्गत आता है। विकास कार्यों के फलस्वरूप वनों का तेजी से विनाश हुआ है। इससे मिट्टी के कटाव की समस्या और भी गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। बिगला इस्टाड्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अध्ययन के अनुसार 1972-75 से 1982-84 के मध्य राज्य के 16 जिलों (अरावली पर्वतश्रृंखला व अर्नात आने वाले जिलों) में 41.5 प्रतिशत वनों की कमी आई। वनविनाश की यह गति राज्य के पर्यावरणीय समुलन के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकती है। राज्य में वनों का विनाश मुख्यतः वनों का तेजी से कटाई, अत्यधिक चराई वन उपजों का दोषपूर्ण तरीक़ों से एकत्रीकरण खनिजों का विदोहन, ईंधन हेतु लकड़ी की प्राप्ति तथा वनक्षेत्रों में सड़कों के निर्माण आदि के कारण है। राजस्थान में केवल ईंधन हेतु लकड़ी की प्राप्ति ही वन विनाश का एक बहुत बड़ा कारण है। राज्य के बड़े शहरों और बस्ती के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र तापमान वनविनाश हो चुके हैं। फलतः राज्य में पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या अत्यधिक गंभीर हो गई है। राज्य में घरेलू उपयोग हेतु ईंधन-लकड़ी की माग में निरंतर वृद्धि हो रही है और भविष्य में भी इसमें वृद्धि होने की सम्भावना है। राजस्थान में 1981, 1991 व 2001 के लिए लकड़ी की माग का पूर्वानुमान क्रमशः 51.21 लाख टन, 56.03 लाख टन और 67.62 लाख टन निर्धारित किया गया है। राज्य में वन विनाश के कारण ही विगत वर्षों में सामान्य तापक्रम में तेजी से वृद्धि हुई है।

4 शक्ति के साधनों का विकास एवं प्रदूषण (Sources of Energy ■ Pollution) - राजस्थान में स्वच्छता के पश्चात् शक्ति के साधनों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इन साधनों के विकास से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। लेकिन इसके साथ साथ इन साधनों ने प्रदूषण की समस्या को बहुत ही गम्भीर बना दिया है। राजस्थान में लगभग 55 हजार टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाता है जिसका उपयोग मुख्यतः ईंट के भट्टा, सामट व कारखाना रसायन उद्योगों, सूती मिलों, खाद सेवकों व घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कायना दार स मावाया जाता है। राज्य का व सभी उद्योग प्रदूषण समस्या का अधिक गम्भीर बना रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए शक्ति के साधनों का विकास करना आवश्यक होता है और यदि शक्ति के साधन विकसित नहीं किए जाते हैं तो औद्योगिक विकास का मार्ग भी अवरोध हो जाता है। उद्योगों के लिए, राजस्थान में लिम्नाइट कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। राज्य में लिम्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युतगृह का स्थापना में केवल इस कारण बाधा आई कि इसमें आधार स्थित ताजमहल को क्षति पहुंचने की सम्भावना थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार ने कोयलाधारा पॉवर प्रोजेक्ट मुक्तगढ़ धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट धौलपुर धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट चित्तौड़ धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट भाण्डला धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट कन्हा सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए। इनमें से केवल कोटा धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए बन्द सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई। राजस्थान में अणुशक्ति का भी प्रसार हुआ है। इस हेतु प्राकृतिक यूरेनियम तथा भारी पानी के उपयोग के लिए रणप्रताप मार अणुशक्ति गृह की स्थापना गवतभाटा नामक स्थान पर की गई। अणुशक्ति का विस्तार कच्चे शक्ति के साधनों की माग पूर्ण की जा सकता है। लेकिन समुचित प्रबंध का अभाव यह साधन भयंकर प्रदूषण एवं मानव विनाश का प्रमुख कारण भी बन सकता है। नगरीय अणुशक्ति गृह में आग लगने की दुर्घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Question)

1. "अर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय सुरक्षा में अंतर्गत संबंध" को विवेकपूर्वक चर्चिए।
"Economic growth and environment protection inextricably linked" Discuss
2. क्लाइमेट पर्यावरण अपक्रमण
Explain - Environment degradation
3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त विवरण लिखिए - राज्य में प्रदूषण का समस्या।
A short note on the following - Pollution Problem in Rajasthan
4. पर्यावरणीय संरक्षण का अर्थ क्या है?

Explain the concept of Ecological Balance

- 5 वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on air pollution
- 6 ध्वनि प्रदूषण से आर म्मा समझते हैं?
What do you mean by Noise Pollution?
- 7 भू प्रदूषण स आप क्या समझते हैं?
Define land pollution
- 8 राजस्थान में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति बताईए।
Mention the present position of Pollution in Rajasthan
- 9 राजस्थान के पर्यावरण विभाग पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the department of Environment in Rajasthan
- 10 राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों का उल्लेख कीजिए।
Write a note on the department in Rajasthan

B निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Question)

- 1 पर्यावरण प्रदूषण क्या है? इसके रूप, कारण और प्रभावों की विवेचना कीजिए।
What is Environment Pollution? Discuss its forms, causes and effects
- 2 राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Environment pollution in Rajasthan
- 3 राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी निम्न घटकों को समझाईए
(i) जल प्रदूषण (ii) औद्योगिक विकास एवं प्रदूषण
Explain the following factors of Environmental pollution in Rajasthan
(i) Water Pollution (ii) Industrial Development & Pollution
- 4 राजस्थान में पर्यावरणीय शान्ति के संतुलन की समस्या का वर्णन कीजिए।
Describe the Agencies for Ecological Balance in Rajasthan
- 5 पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण हेतु राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?
What steps have been taken to control Environment Pollution by you of Rajasthan

C विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Questions)

- 1 पर्यावरणीय संतुलन से क्या आशय है? पर्यावरणीय संतुलन का बनाए रखने के लिए कौन से पाय किए जा सकते हैं?
What is meant by ecological balance? What measures can be adopted to maintain ecological balance?
- 2 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवरण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दीजिए
(i) आकार (ii) वस्तुमान बना (iii) श्रम शक्ति का फैलाव
(iv) उद्योगों का राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान (v) उद्योगों का राज्य के क्षेत्र में अंतरांतर
Describe under the following heading the main features of industrial sector in Rajasthan
(i) Size (ii) Commodity structure (iii) Regional spread
(iv) Share of industries in total S D P (v) Share of industries in total employment
- 3 प्रदूषण स आप क्या समझते हैं? प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय बताईए।
What do you mean by pollution? Describe the measures of control on pollution. Discuss the effects of pollution in detail
- 4 पर्यावरण प्रदूषण विभिन्न रूप, कारण एवं परिणाम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Environment Pollution - its different forms, causes and effects"

अध्याय - 8

कृषि, भू-उपयोग, फसल प्रारूप एवं प्रमुख फसलें

AGRICULTURE, LAND UTILISATION, CROPPING PATTERN & MAJOR CROPS

“पुणने समय से ही खेती हमारे देश की ज़िंदगी रही है और अभी बहुत दिनों तक यही हमारी रंगो में दोड़ने वाला और हमें शक्ति देने वाला खून रहेगा।”

अध्याय एक दृष्टि में

- 1. राजस्थान में फसलों का प्रारूप
- 2. राजस्थान में कृषि जलवायु खंड
- 3. राजस्थान में कृषि का महत्व
- 4. राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएँ
- 5. राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि फसलें
- 6. राजस्थान में कृषि विकास की वर्तमान व्यवस्था/हंगित कृषि हेतु अपनाए गए कार्यक्रम
- 7. राजस्थान में योजनाबद्ध के अन्तर्गत कृषि विकास
- 8. राजस्थान की आठवीं योजना में कृषि विकास की व्यवस्था
- 9. राजस्थान की नवीन योजना में कृषि विकास की व्यवस्था
- 10. राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएँ एवं उनके समाधान
- 11. अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान में कृषि का महत्व

IMPORTANCE OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

डॉ. जॉर्ज हुसैन के अनुसार “पुणने समय से ही खेती हमारे देश की ज़िंदगी रही है और अभी बहुत दिनों तक यही हमारी रंगो में दोड़ने वाला और हमें शक्ति देने वाला खून रहेगा।” ये शब्द भारत के सदर्थ में कृषि के महत्व को स्पष्ट करते हैं। लगभग यही स्थिति राजस्थान के मदर्भ में है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। नवी योजना में राजस्थान का कृषि का निम्न प्रमुख विशेषताएँ बतलाई गई हैं। -

1. राजस्थान में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है।
2. अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में मानसून का समय लगभग 3 सप्ताह है। मानसून देर से आता है और जल्दी समाप्त हो जाता है।
3. राज्य की कुल वर्षा का लगभग 90% वर्षा मानसून से होती है।
4. राज्य की कुल खेती का लगभग 65% भाग सरफ की फसल के अर्थात् है और अधिकांश वर्षा पर निर्भर करता है।
5. राज्य के सिंचन क्षेत्र का 60% भाग कुओं और नलकूपों

नीतियां अपनाने का साहस नहीं करती। सामाजिक व राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण ही यह क्षेत्र राजस्थान में ही नहीं संपूर्ण भारत में भी आधुनिक जैसी व्यवस्था से मुक्त है।

9 परिवहन का विकास (Development of transportation) - यदि परिवहन की दृष्टि से राज्य का अध्ययन किया जावे तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि जो क्षेत्र कृषि की दृष्टि में अधिक विकसित है वे प्रायः परिवहन की दृष्टि में भी अधिक विकसित होंगे। औद्योगिक विकास के लिए परिवहन का विकास एक मूलभूत आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कृषि विकास का काफी महत्वपूर्ण योगदान है।

10 बीमा एवं बैंकिंग का विकास (Development of insurance & banking) - संपूर्ण देश की भांति राजस्थान में भी बीमा एवं बैंकिंग का विकास कृषि विकास से जुड़ा हुआ है। 1989 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार की नीति के अनुरूप कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान किये गये। कृषि के विकास के साथ-साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। कृषकों द्वारा इन वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बैंक की शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया गया। इस प्रकार कृषि विकास के साथ-साथ ग्रामीण बैंकों की शाखाएं बढ़ी हैं। इसी प्रकार धीरे-धीरे कृषि उपजों पर पशुधन आदि का ब्याज कमाने में भी लोग रुचि लेने लगे हैं। इससे रीमा के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं।

राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएं

MAIN CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राजस्थान में कृषि क्षेत्र का गहन अध्ययन व विश्लेषण करने पर राजस्थान की कृषि की कुछ विशेषताएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। इन विशेषताओं को इन विन्दुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है -

(1) कृषि जेत का बड़ा होना (Large Agncultural Land Holding) - 1985-86 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में 4 74 करोड़ जियाशत जेतों विद्यमान थीं और इनके अन्तर्गत 205 89 लाख हेक्टेयर भूमि थी। 1990-91 की कृषि गणना के अनुसार ये जेतें बढ़कर 5 10 करोड़ और क्षेत्र 209 71 लाख हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में 1980-81 में भू-जोत का औसत आकार 4 44 हेक्टेयर था जो 1985-86 में कुछ कम होकर 4 34 हेक्टेयर और 1990-91 में 4 11 हेक्टेयर रह गया। 1990-91 व उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में औसत कृषि जेत बड़ी है। कृषि जेतों

की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। औसत कृषि जेतों का अखिल भारतीय औसत 1 57 हेक्टेयर है। इस प्रकार राजस्थान में कृषि जेतों राष्ट्रीय औसत की लगभग दोगुनी है। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः पंजाब व गुजरात का है। 1990-91 में राजस्थान की सीमाना (1 हेक्टेयर से कम) व संप्र (1 से 2 हेक्टेयर के मध्य) जेतों के अंतर्गत कुल जेतों का लगभग 49 6% भाग आता है किन्तु उसके अंतर्गत कुल कृषि भूमि की केवल 10 5% भूमि ही आती है। बड़ी जेतों (10 हेक्टेयर एवं उससे अधिक) की मध्या कुल जेतों की लगभग 9 6% है किन्तु उनके अंतर्गत लगभग 45% भूमि आती है। शेष बची हुई लगभग 41% जेतों में लगभग 44% कृषि क्षेत्र में आता है।

(2) भू-उपयोग (Land Utilization) - राजस्थान में प्रथम योजना (औसत) में कुल फसल क्षेत्र 113 लाख हेक्टेयर था जो 1993-94 में 182 लाख हेक्टेयर रहा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी इस अवधि में 106 लाख हेक्टेयर से 162 लाख हेक्टेयर के मध्य रहा। स्थायी चारागाहों एवं चराई क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि की मात्रा में केवल कम है बल्कि गत 20 वर्षों से लगभग स्थिर बनी हुई है जबकि पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों की चराई भूमि पर गिरावट बोल बढता जा रहा है।

(3) वृहद् रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्र (Desert & Hilly Area) - राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग पहाड़ एवं रेगिस्तान के अंतर्गत है। राजस्थान का लगभग 10% भाग पहाड़ी एवं 60% रेगिस्तानी है। रेगिस्तानी क्षेत्र की मिट्टी में पर्याप्त उपजाऊपन विद्यमान है किन्तु जल के अभाव में यह क्षेत्र कृषियोग्य होते हुए भी बेकार पड़ा है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में वर्षों की कटाई के कारण भूमि लगभग बंजर होकर बेकार होती जा रही है। इस प्रकार राजस्थान के एक बहुत बड़े कृषि क्षेत्र का उपयोग नहीं हो पा रहा है। राजस्थान नहर परियोजना के पूरा होने पर रेगिस्तानी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग उपजाऊ भूमि में परिवर्तित होने की संभावना है।

(4) शुष्क कृषि एवं प्रकृति पर निर्भरता (Dependence on nature & dry farming) - जल संधारण के अभाव में राजस्थान के लिए शुष्क भूमि का महत्व बढ़ गया है। शुष्क कृषि के अन्तर्गत उपलब्ध जल संधारण का इस प्रकार से उपयोग किया जाना है कि कम में कम जल से अधिक से अधिक उर्ध्व पान की जा सके। इस हेतु अनुसंधान व शोध के माध्यम से राजस्थान की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये नये बीजों आदि का विकास किया जा रहा है, विशेषतः राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए शुष्क खेती अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है।

(5) उन्नत कृषि की स्थिति (Situation of improved Agriculture) - उन्नत कृषि के लिए कृषि के नवीन साधनों जैसे-उन्नत बीज, रासायनिक खाद, परिष्कृत औजार आदि का प्रयोग करना होता है। राजस्थान में इन चीजों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम रहा है क्योंकि उपलब्ध सभी नवीन तकनीक में प्रायः पर्याप्त जल की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि 1994-95 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर खाद का उपयोग 34.8 किलोग्राम था जो कि विभिन्न राज्यों की तुलना में अत्यधिक कम है। इसी अवधि में पंजाब में 174.7 किलोग्राम खाद प्रति हैक्टेयर उपयोग में ली जा रही थी। खाद के उपयोग का राष्ट्रीय औसत भी इस समय 75.7 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर था।¹ खाद के उपयोग की दृष्टि से देश में राजस्थान का 13 वा स्थान था।² अन्य नवीन साधनों की दृष्टि से भी लगभग वही स्थिति है।

(6) महत्वपूर्ण फसलें (Important Crops) - राजस्थान में लगभग सभी प्रकार की फसलें बोयी जाती हैं किन्तु समग्र दृष्टि से देखा जाये तो राजस्थान में खाद्यान्न फसलें सबसे अधिक बोयी जाती हैं। 1970-71 से 1990-91 तक खाद्यान्नों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र लगभग स्थिर बना हुआ था और यह कुल फसल क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग था। राजस्थान देश में एक मुख्य तिलहन उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। सरसों के उत्पादन में तो इसने देश में पहला स्थान भी प्राप्त किया है। राजस्थान में तिलहन उत्पादन की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये दलहन फसलों के सर्दार में भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान में व्यावसायिक फसलें सामान्यतः उन क्षेत्रों में ही सीमित हैं जहाँ पर्याप्त सिंचाई साधन उपलब्ध हैं। राजस्थान में घारे की फसला पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही केवल चारा उत्पादन के लिए दो जाने वाली कृषि भी अत्यन्त सीमित है।

(7) एक व दो फसलों के क्षेत्र (Areas of one or two crops) - राजस्थान में 1993-94 में 192.5 लाख हैक्टेयर भूमि फसलों के अंतर्गत थी। उम्मे से केवल 30.2 लाख हैक्टेयर भूमि में एक से अधिक फसलें ली जा रही थी।³ इस प्रकार राजस्थान में लगभग 85% कृषि क्षेत्र में केवल एक फसल ली जाती है।⁴ और लगभग 15% क्षेत्र में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं। इसका प्रमुख कारण राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं का कम होना है। राजस्थान में कुल बोये गये क्षेत्र का एक चौथाई के लगभग खिंचित क्षेत्रफल है। राज्य में सिंचाई के चार प्रमुख स्रोत अर्थात् नहरें, तालाब, कुएँ व नलकूप हैं। कुल खिंचित क्षेत्रफल का 62.76% क्षेत्रफल कुआँ तथा नलकूपों से और 33.24% नहरों से खिंचित होता है।⁵

(8) फसलों की उत्पादकता (Productivity of crops) - राजस्थान में अधिकतर फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता

राष्ट्रीय औसत से कम है। 1989-90 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में केवल मक्का, गन्ना, सरसों व राई तथा कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राजस्थान में राष्ट्रीय औसत से अधिक था।⁶ 1989-90 में ही चावल, ज्वार, बाजरा, चना, मूँगफली, गन्ना आदि का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम था। निम्न भविष्य में राजस्थान में तिलहन व दलहन की उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि होने की सम्भावना है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं कृषि में उन्नत आदानों के उपयोग के साथ साथ राजस्थान में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि की वृहद् सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

(9) पशुपालन प्रमुख सहायक उद्योग (Animal Husbandry - main Allied activity) - राजस्थान में कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में निरंतर पड़ते अकालों के कारण कृषकों की दृष्टि में पशुपालन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1992 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में 4.78 करोड़ पशु थे।⁷ इनमें से 60% से भी अधिक मछ्वा भेड़ व बकरियों की हैं। राजस्थान में प्रायः पड़ो वाले अकालों से पशु सम्पदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 1983 की पशुगणना की अपेक्षा 1988 में पशुओं की संख्या लगभग 87 लाख कम हुई। इसका प्रमुख कारण 1987-88 का भयंकर अकाल था जिसे इस शताब्दी का सबसे भीषण अकाल कहा गया है। इस अकाल व कारण गायों की संख्या में लगभग 19% भेड़ों की संख्या में लगभग 26% और बकरियों की संख्या में लगभग 18% की कमी हुई है। 1992 की पशुगणना से ज्ञात होता है कि राज्य में पशुओं की संख्या बढ़ी है। राजस्थान में कृषि के अंतर्गत आज भी मुख्यतः पशुशक्ति का उपयोग होता है और विज्ञान पौष्टिक पदार्थों के लिए सामान्यतः पशुओं पर ही निर्भर है। फसलें खराब हो जाने पर भी उसकी आजीविका का साधन भी पशु ही है।

(10) कृषि जलवायु क्षेत्र (Agricultural climate zone) - मपूर्ण देश की 14 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है और 14 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। इस वर्गीकरण व अनुरूप राजस्थान राज्य को 9 खण्डों व उपखण्डों में विभाजित किया गया है। भविष्य में कृषि के लिए बनाई जाने वाली योजनाएँ इसी वर्गीकरण का दृष्टिगत रखने हुये बनाई जायेंगी। राजस्थान में जैसलमेर पश्चिमी बाड़मेर पश्चिमी जापुर बीकानेर और पश्चिमी चुरू के शुष्क मैदानी क्षेत्र को खण्ड 1 एवं

केवल 2.51 लाख टन था जो 1989-90 में 18.45 लाख टन तक पहुँच गया। इस प्रकार 10 वर्षों की अवधि में तिलहन का उत्पादन 7 गुणा बढ़ा है। राजस्थान में तिलहन उत्पादन की प्रगति भारत के अन्य किसी भी राज्य से कहीं अधिक तीव्र है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कुल तिलहन उत्पादन की दृष्टि से भी भारत में इसका विशिष्ट स्थान है। राजस्थान में सूरजमुखी और होबा की फुली की भी लोकप्रिय बनाने का प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान में तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बन्धु सरदार ए सहयोग से विज्ञान प्रयास किये जाते रहे हैं। आरम्भ में राजस्थान में इससे सम्बन्धित वेन्द्र प्रवर्तित योजना विद्यमान थी। 1984-85 से 1985-86 तक शत प्रतिशत कन्द्रीय अंश के आधार पर आर 86-87 से 50-50 केन्द्रीय एवं राज्य अंशों के आधार पर राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरम्भ की गई। 1987-88 में तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय अंश के आधार पर एक अतिरिक्त योजना निम्नलिखित उत्पादन घट्ट कार्यक्रम के नाम से आरम्भ की गई थी। ये दोनों योजनाएँ 1989-90 तक लागू रहीं। इन योजनाओं को मिलाकर 1990-91 में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 75% व्यय बन्धु सरदार एवं 25% व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को वृद्ध प्रदर्शन मिनिमम उत्पन्न एवं पौध संरक्षण एवं ट्वाइल तथा जिप्सम के उपयोग पर अनुदान उपलब्ध है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने 24 जिलों का चयन किया जिनमें अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदेलखण्ड, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, जयपुर, झालावाड़, झुझु, जोधपुर, कोटा, नागौर, बागमवाड़ा, पाली, सिरोही, सीकर, मवाई, माधोपुर, टोंक और उदयपुर जिले सम्मिलित हैं। राज्य सरकार ने भी दो अतिरिक्त जिलों का चयन किया जिनमें झुझु और बूंदेलखण्ड जिलों में सायाहीन की खेती को लाकृषिय बनाने की चेष्टा की जा रही है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए नवी संरक्षण तकनीक जीवाणु खात का उपयोग सम्म पर बुवाई सम्भवता नियमन पौध संरक्षण आदि उपाय काम में लिए जा रहे हैं। सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप तिलहन की फसलों में जिप्सम का उपयोग बढ़ रहा है और इसके उपयोग से तिलहन फसलों का उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तिलहन के तेज प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणित बाजों के विपणन हेतु सुदूर बिंदी केन्द्रों की स्थापना की गई है। सभी प्रकार उपाय की

फल के लिए सोयाबीन तिल अरंडी सूरजमुखी भूगफली तथा रबी की फसलों के लिए रायडा एवं सरसों के मिश्रित वितरण किये जा रहे हैं। भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का वितरण किया जा रहा है। कृषकों को रिक्कलर सेंट उपलब्ध करवाने की चेष्टा की जा रही है तिलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत ही पौध संरक्षण का कार्य भी हम में किया गया है।

(3) शुष्क खेती (Dry Farming) राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का लगभग 3/4 भाग बरानी एवं अतिरिक्त है। 250 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाल क्षेत्रों में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। राजस्थान का अधिकांश भाग में 600 मिलीमीटर से कम ही वर्षा प्रतिवर्ष होती है। इस कारण इतनी कम अनिश्चित और अग्रामरिक्त वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की विभिन्न अवस्थाओं में पानी की कमी के कारण सूखे का सामना करना पड़ता है और इसका फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धन के अभाव और किसानों के रुढ़िवादी और परम्परागत विधियाँ अपनाने से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। राजस्थान का लगभग 1/4 भाग ही मिट्टि है। ऐसा अनुमान है कि यदि बहुत अधिक प्रयास किये जाय तो भी निकट भविष्य में 40% से अधिक क्षेत्र में मिट्टी सुविधायें उपलब्ध करना संभव नहीं हो पायेगा। अतः क्षेत्र विशेष के अनुसार शुष्क खेती की उन्नत व उपयुक्त तकनीक का आधार पर ही सुनिश्चित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में वर्षा का औसत कम ही है। इस तथा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान के लिए शुष्क खेती का महत्व बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने पानी का कमी का पश्चात् भी अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत कृषि विधियाँ विकसित की हैं। इन विधियों में स अधिक से अधिक विधियों को कृषकों द्वारा अपनाने पर रत दिया जाता है। इन विधियों में वर्षों में गहरी जुताई, ढलान का विपरीत बुवाई, बुवाई के पूर्व उर्वरक का प्रयोग, सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ाने, बीजोपचार, भूमि उपचार आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शुष्क खेती की विभिन्न विधियों का प्रसार प्रचार करने के लिए प्रचुर पाठ्यत समिति के चयनित गाँव में 10-10 फैमिली में एक एक प्रश्न का आयोजन किया जात है। एम गाँव का चयन किया जाता है जिनमें एक उन्नत शुष्क कृषि विधियाँ अपनाने में रूचि रखत हों तथा जिन क्षेत्रों में पहले एम प्रदर्शना का आयोजन नहीं किया गया हो। एक ही क्षेत्र में लघु सीमान्त अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषकों को प्रशिक्षित दी जाती है। क्षेत्र उर्वरक आदि पर कृषकों का अनुदान भी दिया जाता है। शुष्क खेती के लिए आगमन की व्यवस्था भी प्रचुर विपणन सहयोग समिति द्वारा की

महकरी समिति या किसी भी अधिकृत सहकारी समिति से की जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में उपयुक्त उन्नत विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इस हेतु कृषकों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण शिविरों में शुष्क खेतों की तकनीकी जानकारी दी जाती है।

(4) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (Special Foodgrain production programme) योजना आयोग की सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करते हुये यह अनुभव किया कि सातवीं यात्रा के अंत तक खाद्यान्नों का उत्पादन 17 ■ करोड़ टन होना चाहिये। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 राज्यों के 169 जिलों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम आरंभ किये गये। आरंभ में यह 1988-89 व 1989-90 के लिए तैयार किया गया था किन्तु यह कार्यक्रम 1990-91 में भी जारी रखा गया। 1990-91 में क्रियाशील कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 14 जिलों का चयन करके गेहूँ, चना, मक्का व बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। गेहूँ उत्पादन में विशेष वृद्धि के प्रयास के लिए अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोंक, कोटा व सर्वाधामाधपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, सीकर व पाली जिलों का चयन किया गया। चने के उत्पादन में विशेष वृद्धि के लिए अलवर, भरतपुर, चुरू, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोंक, कोटा व सर्वाधामाधपुर जिलों का चयन किया गया। मक्का के उत्पादन का बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बामवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ व अजमेर जिलों का चयन किया गया। बाजरे के उत्पादन में वृद्धि के लिये अलवर, जयपुर, झुझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर, चुरू और बाड़मेर जिला को उपयुक्त समझा गया। विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना के अंतर्गत फसलों से संबंधित विभिन्न आदानों पर अनुदान का भी प्रवधान रखा गया।

(5) चारा उत्पादन एवं कृषि वानिकी विकास (Fodder Production & Agricultural forestry development) - इस कार्यक्रम के अंतर्गत चारे की विभिन्न प्रभुत्वों की उन्नत किस्मों के मिनिस्ट्रिज का कृषकों में नि शुल्क वितरण किया जाता है जिसमें कृषक का इनके स्वयं में जानकारी मिले तथा साथ ही साथ क्षेत्र के पशुओं के लिए पोष्टिक चारा भी उपलब्ध हो सके। इस हेतु विभाग के विभिन्न ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र एवं किसानों के खेतों पर हरे चारा की नई किस्म के तुलनात्मक अध्ययन एवं प्रदर्शन हेतु परियोजना किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में हरे चारे की फसलों की उन्नत किस्मों का बीज कृषकों का अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में अधिकतर क्षेत्रों में

जानवरों की चारा कटकर खिलाने का प्रचलन नहीं है जिससे काफी मात्रा में चारा बेकार हो जाता है। चारा कटकर खिलाने के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए हथ से चलने वाली कुट्टी की मशीनों के लिए कृषकों को अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में कृषि वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को पौधे उपलब्ध करवाने के लिए पौलिट्रीन की शैलियों व बीज की नि शुल्क व्यवस्था की जा रही है। ऐसे तैयार पौधों का आम - पाम के क्षेत्र के कृषकों में वितरण किया जाता है। इन पौधेखालाओं की स्थापना में ग्रामीण कृषक महिलाओं की भी उचित प्रशिक्षण देकर सम्मिलित किया जाता है। घास व वानिकी के बीज समर्थित करने के उद्देश्य से स्थानीय बच्चों तथा बेरोजगार युवकों को बीज एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार एकत्रित किये गये बीजों का उचित मूल्य पर क्रय कर लिया जाता है। चारे की फसलों पर विभाग द्वारा आयोजित अन्य फसलों की तरह वृद्ध प्रदर्शन आयोजित किये जाने का प्रस्ताव भी है। इसके लिए आदानों का कृषि वानिकी के सदस्यों में मुख्यतः तीन प्रकार से प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। प्रथम, जलप्रवहण क्षेत्र एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर सामान्य फसल उगाये जाने वाले खेतों में उपयुक्त किस्म के पौधों का कटारों में रोपण किया जाता है। इसमें वृक्ष एवं फसलों का साथ-साथ लगाना होता है। एवं वृक्षों की जानियों का इस प्रकार चयन किया जाता है जिसमें फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। द्वितीय, जीवन बाड़ लगाना है जिसके अंतर्गत पर्यावरण में सुधार एवं खेतों में जीवित पाधा के बाड़ कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए कटेदार एवं अन्य उपयुक्त पौधे लगाये जाते हैं। इन पौधों के रोपण के बाद बाड़ के रूप में स्थायी विकास किये जाने हेतु वृक्षारोपण पर अनुदान प्राप्त होता है। तृतीय, वन एवं चरागाहों के सम्मिलित विकास की चेष्टा की जाती है। इस हेतु शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में कृषकों के खेतों पर चरागाहों में उन्नत घास के लिए एवं वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(6) जल वज्र योजना (Water Budget Plan) - जल की आपूर्ति एवं सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान बंसी वाला क्षेत्र है। राजस्थान में राष्ट्रीय जल संसाधनों का मात्र 1% ही उपलब्ध है जबकि देश के क्षेत्रफल का लगभग 10% भू-भाग यह है जिसमें लगभग 5% जनसंख्या निवास करता है। राजस्थान के जल संसाधनों का अधिनत उपयोग करने के बाद भी राजस्थान का लगभग 1/4 कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो पाई हैं। राजस्थान में किसी न किसी भाग में अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा के कारण निम्नतर अवस्था की भी स्थिति बनी रहती है।

(9) भू-सर्वेक्षण एवं मिट्टी परीक्षण (Land survey & soil testing) - भू-सर्वेक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। भूमि की क्षमता का पता लगाया जाता है। सिंचाई से संबंधित मिट्टी व पानी के विभिन्न प्रकार के गुणों की जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि भूमि की विशेषताओं के अनुरूप उचित फसलों की सिफारिश की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के सदस्यों में सिंचाई विभाग की भी नवीन सिंचाई योजना बनाने के सदस्यों में उपयोगी जानकारी प्रदान की जा सकती है। भूमि-सर्वेक्षण एवं परीक्षण का कार्य दुर्गापुर (जयपुर), कोटा, सीकर व जोधपुर के केंद्रों में संचालित किया जाता है, भू-सर्वेक्षण संगठन राजस्थान नहर व चमल नहर के क्षेत्रों में कार्यरत है। मिट्टी व पानी के नमूनों के परीक्षण हेतु 6 स्थायी प्रयोगशालायें हैं जो दुर्गापुर (जयपुर), जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, बागवाड़ा व अलवर में कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त छ प्रमणशील प्रयोगशालायें दुर्गापुर, पाली, सीकर, भरतपुर, भीलवाड़ा व मिराहो में कार्यरत हैं। 1989-90 में दो और स्थायी प्रयोगशालाओं झालावाड़ व झारपुर में तथा 4 और प्रमणशील प्रयोगशालाएं मवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर व चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गईं। 1990-91 में दो और प्रमणशील प्रयोगशालायें टोंक व उदयपुर जिलों में स्थापित की गईं।

(10) मिट्टी एवं जलवायु के अनुसार 9 खण्डों में विभाजन (Agnculutral Zone) - राजस्थान में सघन कृषि विकास व लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये जल एवं मिट्टी के आधार पर संपूर्ण राजस्थान को 9 खण्डों व उपखण्डों में इस प्रकार विभाजित किया गया है -

- (i) खण्ड 1 - ए शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र
- (ii) खण्ड 1. बी सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र
- (iii) खण्ड 2 - ए अन्न स्थानीय जलाशयों के अनन्तरी मैदानी क्षेत्र
- (iv) खण्ड 2. बी तृता नदी का अनन्तरी मैदानी क्षेत्र
- (v) खण्ड 3 - ए अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र
- (vi) खण्ड 3 - बी बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र
- (vii) खण्ड 4 - ए अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र
- (viii) खण्ड 4 - बी आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र
- (ix) खण्ड 5 - आर्द्र-दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र

(11) राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम एवं कृषक प्रशिक्षण (National Agriculture Extension Programme and Farmers Training) - कृषि में मर्यादित नवीनतम ज्ञान का समन्वित योजनामय व नियमित रूप से प्रसारण तक पहुंचाने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए

प्रशिक्षण एवं प्रमण यद्वाति पर आधारित कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना नवम्बर, 1977 में अक्टूबर 1982 तक विश्व बैंक की सहायता से आरंभ की गई थी। टी एन वी सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध यह प्रणाली कृषि विकास को गति देने में सहायक रही है। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों का ध्यान में रखते हुये ही 1984-85 से राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व के 18 जिलों के अतिरिक्त 6 और जिले सम्मिलित किये गये। इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में अधिक उपज देने वाले उर्वरकों बीजों तथा सरक्षण औषधियों आदि के उपयोग पर बल दिया गया और कृषि तकनीकों का भी प्रसार हुआ जिससे उत्पादकता बढ़ी। विस्तार कार्यक्रम के कारण राज्य में उर्वरकों की खपत दुगुनी से भी अधिक हो गई। पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग तेजी से बढ़ा। इनमें कृषि विधियों का प्रयोग होने लगा जिनमें बीज उपचार, उन्नत किस्मों का प्रयोग, उचित पौध संख्या बुवाई के पूर्व उर्वरकों का प्रयोग, खंडों फसल में उर्वरकों का प्रयोग, समयानुसार खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य में कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि विस्तार परियोजना एक शीर्ष एवं प्रमुख कार्यक्रम है जिनके माध्यम से विभिन्न कृषि विकास परियोजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित व क्रियान्वित किये जाते हैं। कृषि विस्तार कार्यक्रम की अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से कृषि में मर्यादित कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे नवीनतम ज्ञान के संपर्क में रहें और उसे किसानों तक पहुंचा सकें। दुर्गापुर एवं टोंक में कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त काजूर, कृषि विश्वविद्यालय, सिंचाई प्रबन्ध संस्थान आदि में भी प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। राज्य के बाहर सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

(12) प्रबंधन प्रशिक्षण (Managenal Training) - विश्व बैंक के मार्गदर्शन में राज्य में चल रहे कृषि विस्तार कार्यक्रम की प्रगति का समीक्षात्मक, वैचारिक नैपथ्य करने के लिए प्रबंधन एवं मूल्यांकन एक मराकत माध्यम है। इसके अन्तर्गत कृषकों द्वारा अपनाई गई उन्नत कृषि विधियों से संबंधित कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्राप्त निष्कर्षों से परियोजना प्रबन्धकों को आशा की फसल की बुवाई में पूर्व अवगत कर दिया जाता है ताकि विकास कार्य में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। इन निष्कर्षों को विस्तृत रिपोर्ट विश्व बैंक भारत सरकार राजस्थान के सम्मन्ध जिलों उपजिलों एवं उन सब स्थानों जहां विस्तार कार्य चल रहा है, पर प्रेषित जाती है ताकि प्राप्त सुझावों के

आधार पर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विस्तार कार्यक्रम में स्पष्ट जाना है कि ग्राम विस्तार कार्यक्रमों को संपर्क करने के लिए उनके खेतों का भ्रमण करने लगा है। कृषक भी उपयोगी जानकारी के लिए उससे संपर्क करने लगे हैं। प्रशोधन सर्वेक्षण के निष्कर्षों से विस्तार परियोजना प्रबंधकों का कार्यक्रम में निरंतर सुधार एवं उचित क्रियान्वयन में मदद मिली है जिसके कारण उन्नत कृषि विधियों के कुछ विन्दुओं का तो लगभग शत-प्रतिशत अनुसरण होने लगा है। जैसे - बीज की दर, समय पर निगड़-गुड़ाई आदि। राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम का अनर्गत मभा जिला में मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं। मूल्यांकन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक फसल मौसम में कृषि प्रसार कार्यक्रम के फलस्वरूप कृषकों द्वारा शोध उपज, आमद व रहन-सहन का प्रभाव आका जाता है। प्रशोधन एवं मूल्यांकन द्वारा सर्वेक्षण परम्परा सन्वित है एवं अलग-अलग तरीकों में प्रशोधन का लाभान्वित करत है। प्रशोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण के अतिरिक्त प्रशोधन एवं मूल्यांकन प्रबोद्ध द्वारा समय-समय पर कृषि में सन्वित आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन भी किए जाते हैं।

(13) बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं परीक्षण (Seed production, Standardization & Testing) - विभिन्न फसलों एवं किस्मों के बीज किस्मों का समय पर उपलब्ध करवाने का कार्य गजस्थान बीज निगम जयपुर करता है। यह निगम अपने स्वयं के पार्सल तथा कृषकों के खेतों पर बीज का उत्पादन करता है। आवश्यकता ज्ञान पर बीज निगम अन्य प्रान्तों एवं मस्थानों में भी बीज भण्डारता है। बीज प्रसारण की प्रक्रिया गजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण एजन्सी जयपुर के माध्यम से तथा बीज अद्विगण मशीनों द्वारा विमानों से बीज पाठान प्रसारणों में की जाता है। अन्तः क्षेत्र में उत्पादन का प्रत्याहित करने के लिए बीज उत्पादन करने वाले कृषकों को बीज के बीजक भाव में अधिकतर प्रदान करके प्रत्याहित किया जाता है। अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के अनाज बीजों का उपयोग गजस्थान में 1966-67 में आरम्भ हुआ। अन्य प्रसार की दृष्टि से निरन्तर प्रचार व प्रचार आदि फसलों के सुधार हुए बीजों का उपयोग 1978-79 में आरम्भ हुआ। राज्य में इन बीजों के बहन हुए उपयोग का पता इस तथ्य से लगता है कि प्रारम्भ में मात्र 2% क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले किस्मों की बुवाई की गई थी जबकि मातृबीज याचना अवधि में इन फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल के 31.94% क्षेत्र में बुवाई की गई। बीज उर्वरक व बीजनाशक औषधियों की मात्रा व दर में वृद्धि के कारण इनमें निरालाई की संभावना रहती जा रही है। इस संभावना का गहन तथा

दोषी मस्थानों व व्यवसायियों को दंडित करने हेतु भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985, अनावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और अधिनियम, 1966, बीज कानून, 1968, बीज नियंत्रण अधिनियम, 1983 व बीजनाशक अधिनियम 1968 पारित किए हैं। इन सभी का मुख्य उद्देश्य अमान्य कृषि आदतों को रोकना व गलत लगाना व दोषी व्यवस्था पर कानूनी कार्रवाई करके किसानों को उचित मूल्य व मानक स्तर के बीज प्राप्त व बीजनाशक औषधियाँ उपलब्ध कराना है। बीज विवरण हेतु गजस्थान में गजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय फार्म निगम, निरन्तर गज गजस्थान निजी मस्थान क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ जनजाति गज आदि कार्यरत हैं। उर्वरक व बीजनाशक औषधियों का वितरण हेतु राजपैड, मत्स्यी समितियाँ, गजस्थान जनजाति गज कृषि उद्योग निगम तथा निजी मस्थान एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं। उपरान्त अधिनियमों व नियमों का प्रभावी रूप में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने गुण नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से तीन इकाया - एनफोर्समेंट एजेंसीज बीज वितरण इकाया व उडन दम्मा कार्यरत हैं। बीज उर्वरक व बीजनाशक औषधियों का वितरण के लिए जयपुर व सीकर में प्रयोगशाला है जो राज्य मस्थान द्वारा विरलेके लिए अधिनियम है। उर्वरक वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला जयपुर व जयपुर में कार्यरत हैं। बीज वितरण हेतु तीन प्रयोगशाला जयपुर, श्रीगणेशपुर व फाटा में स्थित हैं। बीज गुण नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला दुर्गापुर में कार्यरत है।

(14) वर्षा की विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि विधियों का निर्धारण (Suitable Agricultural Strategy in Various Rain Conditions) वर्षा आधारित खेती हेतु विभागीय विचारों के अनुसार शुष्क खेती करने की विचारों की गई है। राज में हा नमी व भूमिगत के उपाय गुणाएं जाते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में तथा मस्थान के कम अनियमित व अनिश्चित ताप है तथा क्षेत्र जल्दी समाप्त हो जाता है। प्रयोग अवस्था में जलवायु व मिट्टी के अनुसार फसलों के पौधों की मस्थान विधि में व सुकारन समित मस्थान जाना निर्णय तथा उर्वरक का प्रयोग भी आवश्यकता में अधिनियमों द्वारा निर्धारित। ऐसा करने में फसल में फल आने व पाना बनने की अवस्था में रफ्तार वर्षा जल्दी भी समाप्त हो जाती है तो भी पौधा का उपयुक्त नमी मिल पायेगी। जिन क्षेत्रों में बहुत सा दोष व वृद्धि मिट्टी है वहां इस तथ्य का विचार करना है। यह विचारों का नहीं है कि वृद्धि व वृद्धि के कारण इनमें निरालाई की संभावना रहती जा रही है। इस संभावना का गहन तथा

प्रकार के जल का उपयोग वर्षा के अभाव में फसला की जावन-दायिता मिवाड के रूप में किया जा सकता है। प्रारंभ में मानसून ढग में प्रारंभ हो ता सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर भूमि को गमलत करक मक्का मूंगफली व सोयाबान का बुवाई समय पर करना चाहिये तथा आवश्यक हो ता फसल के दाना बनन का प्रारंभिक अवस्था पर भा सिंचाई करनी चाहिये। तथा की विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग-अलग कृषि विधिया का अपनाने की सिफारिश का गई है।

(15) जैविक एवं जीवाणु खाद रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा हुई समता की दृष्टिगत रखते हुये विभाग ने जैविक खाद के उपयोग का प्रोत्साहित करने का निश्चय किया है। जैविक खाद में अलग-अलग शहरा खाद, ग्रामीण खाद व हरा खाद का प्रयोग का बढ़ावा दिया जा रहा है। जावाणु खाद, दलहन एवं तिलहन फसल के साथ साथ अनाज वाला फसला में उत्पादन बढ़ान में भा सहायक रहगी। इनके उपयोग से उपज में 15-20% का वृद्धि हो जाता है तथा प्रति हेक्टेयर 25 कि ग्रा नाइट्रोजन खाद का बचत हो जाता है। इसके अतिरिक्त जावाणु खाद से पौधा का जड़ मजबूत होता है तथा इसका फेलात्र अधिक होता है। छोटे व सामान कृषक के लिए उत्पादन बढ़ान का यह एक सस्ता साधन है। जावाणु कल्चर का माग की पूर्ति विभागाय प्रयोगशालाओं द्वारा पूरी नहीं हो पाने के कारण विभाग ने यह निश्चय किया है कि गन्नास्थान राज्य कृषि उद्योग निगम इस काम को पूरा करने की चर्चा करेगा।

(16) भू संरक्षण कार्यक्रम (Land Conservation) राजस्थान में शुष्क छत का आधार प्रदान करने के उद्देश्य में भू संरक्षण कार्य का क्रियान्विति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भू एवं जल संरक्षण कार्यों का पूरे राज्य में विस्तार करत तथा उनके कार्यों में गति लान के लिये भू संरक्षण मण्डल को नया रूप दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में भू संरक्षण का कार्यक्रम मत्त विकास कार्यक्रम, सूखा संभव्यता कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहान संरक्षण कार्यक्रम, गन्नाय जल प्रयोग कार्यक्रम, मैसिव कार्यक्रम, बाह्य सुधार कार्यक्रम, अकाल संरक्षण एवं एकाकृत जल प्रयोग क्षेत्र परियोजना के माध्यम में किया जा रहा है।

(17) कृषि सूचना सेवा (Agricultural information service) अनुसंधान पर आधारित कृषि में सन्धित जानकारी के रूप में प्रसार कार्यक्रमों के तहत गन्नाय के उद्देश्य में कृषि सूचना सेवा मण्डल कार्यरत है। गन्नाय कृषि सूचना सेवा एक अलग जल विभिन्न जल सहाय संस्था जैम समार पत्रा कृषि पर परिचरिता अकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम में जानकारी देने का

प्रसार कर रहा है। वहां दूरगो और तकनीकी साहित्य का प्रकाशन तथा श्रव्य दृश्य माध्यम का प्रभाव उपयोग भा कर रहा है। राज्य कृषि सूचना सेवा 1986-87 में 1988-89 में मध्य राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की गई। इसे कृषि सूचना परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ बनाया गया है। राज्य में कृषि विस्तार कार्यक्रम के प्रशिक्षण पत्र का प्रभावी बनान के उद्देश्य से 1987-88 में वाडियों का उपयोग किया जान लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद एवं कृषि मण्डल का तकनीकी सहायता से वाडिया फिल्म का निमाण हो वाडियों इकाई स्थापित की गई है। इस विडियो इकाई द्वारा कृषि तकनीकी शोधक वाडिया फिल्म का निमाण किया जाता है। विभाग का वाडिया इकाई द्वारा दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रमों पर भा रचनात्मक योगदान किया जा रहा है। शारदेशिक समाचारों में कृषि समाचारों के वाडिया अंश व कृषि कार्यक्रमों में प्रभावशालीता लान हो लघु वाडिया कार्यक्रम तैयार कर प्रसारित किये जाते हैं।

(18) सहभागी कृषि विकास योजना (Participatory agricultural development plan) यह अनुभव किया गया कि वतमान में कृषि योजना बनान का प्रक्रिया में कृषि वर्ग का सहभागिता नगण्य है इसलिये 1990-91 में सहभागी कृषि विकास योजना बनान का एक नया प्रयास आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये दिसम्बर 1989 में 5 दिन का एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न जिला में आय अधिकारियों को सहभागी योजना बनान के लिए विचार-विमर्श करक प्रशिक्षण दिया गया। मातृशाला निर्देश प्रपत्र भा तैयार किया गया। इन योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर का योजनाएं ग्राम विस्तार कार्यकर्ता एवं सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्मित का जायगा। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत का बैठक में उपज दबा होगी। इस चर्चा में अग्रणी किसानों के विचार विमर्श कर योजना का अंतिम रूप दिया जायगा। इस प्रकार ग्राम स्तर पर निर्मित योजनाओं का सन्धित करक उपजिला स्तर पर पंचायत समिति स्तर का योजनाएं तैयार का जायगा। इन योजनाओं का पंचायत समिति का बैठक में रखा जायगा अथवा कृषि स्थायी समिति का महर्मा प्रण करक योजना का अंतिम रूप दिया जायगा। उपजिला स्तर पर बना योजनाओं का जिला स्तर पर सन्धित करक पंचायत समिति के परम्परीक मुद्रा की दृष्टिगत रखत हुये जिने की योजना तैयार का जायगा जिस पर जिला स्तर का बैठक में सहमति लान का जायगा। इन प्रकार निर्मित योजना में ग्राम स्तर पर कृषि निश्चय राज्य स्तर पर योजना तैयार करेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादन की सम्भावना का पहचान करक उपलब्ध ज्ञान में

अधिकतम उत्पादन लेने का प्रयास करता है। इस योजना में ग्राम विस्तार कार्यक्रमों द्वारा स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित किये आयेगे जिन्हें प्राप्त करने की उसकी अधिक प्रतिबद्धता रहेगी।

(19) राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं समन्वित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा उन जिलों में आरम्भ किया गया है जिनकी वार्षिक औसत वर्षा 500 मि.मी. से 1125 मि.मी. तक होती है। यह कार्यक्रम गजस्थान के अलावा अजमेर भरतपुर बांसवाड़ा झुणपुर झालावाड़ कोटा सवाई माधोपुर सिरोंही टोंक धौलपुर बूंदी भीलवाड़ा पाली जयपुर चित्तौड़गढ़ सीकर व उदयपुर जिलों में कृषि विभाग के साथ साथ वन पशुपालन उद्यान तथा अन्य विभागों के कार्यक्रमों को विमानों की भागीदारी के साथ समन्वित रूप में सम्पादित किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से भू एवं जल संरक्षण तथा इनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कृषि प्रदर्शन यागनी फसल उत्पादन तकनीक राग उत्पादन एवं कृषि वानिकी तथा कृषि विकास से सम्बंधित अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित है। समन्वित जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रमों की भांति कार्यक्रमों के सम्पादन के लिए अजमेर झालावाड़ा उदयपुर व जयपुर जिले चयनित किये गये हैं।

(20) राजस्थान की सर्वांगीण कृषि विकास योजना (Overall agricultural development plan of Rajasthan) कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 514.37 करोड़ रुपये की योजना बना कर भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक का सहायता हेतु प्रस्तुत की थी। इस योजना में फसल उत्पादन भूमि सुधार जल विभाग चरा विकास फल व सब्जी विकास भूजल उपयोग मिर्चाई व्यवस्था पशुपालन भंडारण मछलीपालन सहकारिता आदि के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए हैं। विश्व बैंक मिशन ने परियोजना के प्रारूप का अंतिम रूप देने में पूर्व कुछ अध्ययन प्रस्तावित किए थे। गजस्थान सरकार ने उन पर विचार विमर्श किया और यह योजना अर करार 300 करोड़ रुपये की होगी। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श किया गया। इस परियोजना के शोध लागू होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

(21) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर (Central Arid Zone Research Institute (CAZARI)) गजस्थान राज्य का अधिकारा भूभाग गिम्ताली है। इस क्षेत्र की कुछ विशिष्ट समस्याएँ हैं।

सखार ने स्वतंत्रता के पश्चात् रेगिस्तानी क्षेत्रों को समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट प्रयास किये हैं। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अक्टूबर 1952 के मरूस्थल वनीकरण शांघ केन्द्र जोधपुर की (Desert Afforestation Research Station Jodhpur) स्थापना की। 1957 में इसके अंतर्गत मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया और इस केन्द्र का नाम मरूस्थल वनीकरण एवं मिट्टी संरक्षण केन्द्र कर दिया गया। वस्तुतः रेगिस्तानी क्षेत्र में विभिन्न गंभीर समस्याओं के अनुसार एक एमो समस्या को आवश्यकता थी जो एक शोध संस्थान के रूप में कार्य कर सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये 1959 में मरूस्थल वनीकरण एवं मिट्टी संरक्षण केन्द्र का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के पश्चात् इस केन्द्र को 'केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर (काजरी)' का नाम मिला जाता है। 1966 के पूर्व इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता था लेकिन इसके पश्चात् इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किया जाता है। आस्ट्रेलिया सरकार एवं यू.एन. ने इस संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान किया है। यह संस्थान काजरी का नाम में सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वन मण्डल का विकास करने हेतु पड़ पाया मिट्टी जल व भूमि आदि के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना है। यह भूमिगत जल तथा वर्षा व बाढ़ के जल के उपयोग की व्यवस्था करता है। यह क्षेत्रीय पर्यावरण का अध्ययन करता है और उसमें सुधार के प्रयास करता है। उद्यानी पेड़ पाया एवं वनस्पतियों के उपयोग का प्रयास भी करता है। भूमि व जल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे वन व चरागाहों का विकास सिंचित फसलों का विकास व पशु सम्पदा विकास आदि की दृष्टि में किया जाता है। इस संस्थान के अंतर्गत पौध अध्ययन विभाग मूलभूत संस्थानों का अध्ययन करने वाला विभाग जलपुर्जों और जल उपयोग अध्ययन विभाग कृषि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग पशु अध्ययन विभाग कृषि अभियांत्रिकी विभाग मिट्टी पानी व पौध सम्बंधी अध्ययन विभाग मानवीय राज्य अध्ययन विभाग तथा प्रसार व प्रशिक्षण विभाग है। ये सभी विभाग संस्थान के विभिन्न कार्यों का सम्पन्न करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। यह संस्थान भारतीय दृष्टि अनुसंधान परिषद् की अनेक परियोजनाओं का संचालन करता है। इन परियोजनाओं में माट अनाज के विकास का अखिल भारतीय समन्वित परियोजना जल नियंत्रण व जल अखिल भारतीय समन्वित शांघ परियोजना का समन्वित केन्द्र हाटीर-रगत फसल पर शांघ परियोजना हाटीर-

एव पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक पर शोध परियोजना, शुष्क खेती भूमि खेती के लिए अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना, जल प्रबन्ध और मृदा लवणीयता के अनुसंधान पर एकीकृत परियोजना बुद-बुद सिंचाई और शुष्क भूमि प्रबन्ध पर ऑपरेशनल शोध परियोजना, पौधों की खोज तथा उपयोगिता के तहत अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना, एग्रो-फॉरमस्ट्री पर शोध परियोजना एवं ऊर्जा ससाधनों पर अनुसंधान व परियोजना प्रमुख है।

युनको एव देश की अनेक मस्याओं व समस्याओं व सहयोग म काजरी में अनेक शोध परियोजनाए संचालित की जा रही है। यहां के वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया है। यह संस्थान इन अनुसंधानों को कृषकों पशुपालकों और संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।

(22) भागीरथ योजना (Bhagirath Yojna) -

परिचय (Introduction) राजस्थान सरकार ने भागीरथ योजना का श्रीगणेश कृषि एवं सहकारिता विभागों में किया है। भागीरथ योजना का शुभारम्भ 24 मई, 1990 का कृषि प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में किया गया। राजस्थान सरकार की इस योजना में राजकीय कार्यों के लिए ऐसे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का आग्रह करने की चेष्टा की गई है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अदम्य साहस का कार्य कर सकें। वे व्यक्ति जो कुछ असामान्य कार्य का स्वप्न देखते हैं उनके स्वप्नों को कार्यरूप देने की यह योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामस्तर तक कोई अच्छी योजना बनाई जानी है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जला है। यह एक स्वेच्छिक प्रयास है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अमान्य और अभावपूर्ण कार्य करने का सफाया ले है जैसा कि प्राचीन युग में भागीरथ ने किया था। तभी व्यक्ति अकेला उस योजना का मूत्रधार होता है। इस अंतर्गत सरकार द्वारा विभाग के उन कर्मचारीयों का जो अपने क्षेत्र की परिस्थिति व स्वयं की क्षमता तथा विभागीय प्रवृत्तियों को देखते हुये स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं उनसे कहा गया है कि वे अपनी योजना के लिए असामान्य तथ्यों का निर्धारण करें और योजना को पूरा करने क्रियान्वित करें। संबंधित विकास विभाग ऐसे भागीरथों को उन असामान्य तथ्यों को प्राप्त करने के लिए साधन व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है।

मुख्य तथ्य (Main Elements) - इन असामान्य तथ्यों की प्राप्ति के लिए न तो कोई नया पद सृजित किया जाता है और न ही भवन निर्माण के लिए कोई गति उपलब्ध कराई जाता है। इस योजना में चयनित

व्यक्ति को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ भी प्रदान नहीं किया जाता है। यह कार्य तो चयनित व्यक्ति को केवल नि स्वार्थ और समर्पण भावना से करना होता है ताकि वह अपना असामान्य और असाधारण योजना को साकार रूप दे सके। भागीरथ योजना के अंतर्गत विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित प्रवृत्तियां सम्मिलित की जाती है। कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों, जिन्हें कृषि भागीरथ कहा जा सकता है, फसलों के लिए उन्नत बीज वितरण, बीजोपचार उर्वरक पौधों के वितरण, किमान नर्मिंग, जलोपयोग कार्यक्रम, शुष्क खेती कार्यक्रम भूमि सुधार कार्यक्रम आदि से जुड़े हुये रहेंगे।

भागीरथ योजना में चयनित व्यक्तियों को विभागीय प्रवृत्तियों में समुचित प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। भागीरथ विकेंद्रित रूप से कार्य करन, अपनी योजना स्वयं बनाने एवं उसकी क्रियान्वित भी स्वयं करने के लिए स्वतंत्र है। कार्यक्रम के लिए सुविधा सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व जिला स्तर पर, जिलामन्त्रीय विभागीय अधिकारी एवं विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष का है। राज्यस्तर पर विभागीय सचिव द्वारा कार्यक्रम की क्रियान्वित की वैमासिक समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार जिलामन्त्री पर जिलामन्त्रीय अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा का कार्य किया जाता है।

विभिन्न कार्यक्रम (Various Programmes)

- कृषि विभाग में भागीरथों द्वारा इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रवृत्तियां हय से ली गई हैं जिनमें से कुछ निम्नांकित से संघटित है

(1) जल ससाधन (Water Resources) - राजस्थान में जल ससाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश में उपलब्ध जल ससाधनों का केवल एक प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। वर्षा का अधिकांश जल भी बह चला जाता है। जल ससाधनों के लाभ 70% सतही जल तथा 50% भूजल का दोहन किया गया है जिसमें कुल कृषि क्षेत्र का लाभ 24% भाग में हो मिदाई सुविधाएं उपलब्ध है। सिंचित क्षेत्र की उत्पादकता 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है जबकि इस क्षेत्र की उत्पादकता 4 से 11 टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष होगी सहित। जल की आवश्यकता में अधिक उपयोग अपव्यय एवं जल की कमी का कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल का 50% भाग फसल तक पहुंचने-पहुंचत अपव्यय हो जाता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये जल के अनावश्यक उपयोग तथा अपव्यय को रोकने के लिए भागीरथ कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित शुष्क खेती की तकनीक का व्यापक उपयोग करवकर कृषि उत्पादन की

(8) खाद एवं बीज का वितरण (Distribution of Fertilizer & Seeds) - उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, दलहनो के बीजों, खुरीफ बीजों, रसी बीजों तथा कलचर पेक्टेस का वितरण किसानों में किया जाता है। इसी प्रकार प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए डी एचपी, यूरिया सुपर फास्फेट तथा त्रिप्सम उर्वरक का वितरण भी भागीरथी योजना के अंतर्गत किया जाता है।

राजस्थान में योजनाकाल के अंतर्गत

कृषि विकास

AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN UNDER FIVE - YEAR PLANS

राजस्थान की सभी योजनाओं में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि कृषि फसलों में अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र आ सकें। दूसरी योजना में कृषि के समुचित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसके अंतर्गत उपयुक्त कृषि आदाना का उपयोग का प्रोत्साहित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम के विचार को क्रियान्वित करने की चेष्टा की गई। इसका अंतर्गत कुछ चयनित क्षेत्रों और कुछ चयनित फसलों का कार्यक्रम के अंतर्गत लिखा गया। 1966 से 1969 के मध्य की वार्षिक योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि हरित क्रांति का आगम होना रहा है। इस काल में अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग आगम किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी इसी नीति को जारी रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समन्वित क्षेत्र की नीति को लागू किया गया। विभिन्न कृषि आदानों तथा उन्नत फसल प्रजनन के किसानों के छात्रों तक यह गान का विचार को कार्यरूप दिया गया। छठी योजना में इस रात पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि आदानों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि मौसम सम्बन्धी परिवर्तनों का कृषि उत्पादन पर अधिक प्रतिकूल असर न पड़ सके। यह भी रास्ता भी गई कि कृषि सबकी नई तकनीक को कमजोर वगैरह नष्ट न हो जाये। सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मिन्दा क्षेत्र में वृद्धि करने विद्यमान मिन्दा क्षेत्रों में कुशाकर मिन्दा प्रथम विस्तार करने उन्नत बीज खादों व बीजनाशक व उपयोग को बढ़ाने एवं शुष्क खेती को लाभप्रद बनाम तथा कृषि विन्दा मेकओ के कुशल उपयोग का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय जन अधिग्रहण विकास कार्यक्रम और बीहड मुधार कार्यक्रम का उद्देश्य पर हाथ में लिया गया। इस योजना में

कृषि आदानों को मिनिक्किट्स के रूप में तथु व सीमान्त कृषकों का उपलब्ध करना भी एक उल्लेखनीय तथ्य है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन विकास और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम भी हाथ में लिए गये जिनका अत्यधिक अनुकूल प्रभाव पड़ा। इस योजना के अंतर्गत ही कुछ चयनित फसलों के सर्ध में अच्छी सभावनाओं वाले जिलों में विशेष खोजान उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

(1) कृषि विकास दर (Agriculture Growth Rate)

1951 में 1990 तक लगभग 40 वर्षों में विभिन्न फसलों के क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता से संबंधित निम्नलिखित विकास दर प्राप्त की गई

प्रथम योजना से सातवी योजना के मध्य विकास दर (प्रतिशत में)			
विकास	प्रथम योजना से सातवी योजना के मध्य प्राप्त विकास दर		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
अनाज	3.6	11.4	7.5
दालें	3.4	8.0	4.6
हरी सब्जियाँ	3.6	10.9	8.9
तिलहन	11.2	22.0	13.7
गन्ना	5.4	20.2	14.0
कपास	10.2	24.4	12.1

स्रोत: Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan & Eighth Five Year Plan 1972-77 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से निम्नांकित तथ्यों का ज्ञान होता है -

- 1 उपरोक्त सभी फसलों में क्षेत्र की तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है।
- 2 खोजान फसलों की उत्पादकता तिलहन गन्ना व कपास में लगभग आधी रही है।
- 3 राजस्थान में तिलहन व कपास के अधिक उत्पादन का एक कारण तो इसका क्षेत्रफल में अधिक वृद्धि होना है तो दूसरी ओर इसकी उत्पादकता भी खोज फसलों की तुलना में लगभग दुगुनी होना है।
- 4 गन्ने के उत्पादक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के बावजूद भी इसका उत्पादन मुख्यतः इस कारण में बढ़ा है कि इसका उत्पादकता बढ़ गई है।

(2) महत्वपूर्ण कृषि फसलों का उत्पादन (Production of Important Agricultural Crops) - राजस्थान में खोजानों तिलहन, कपास गन्ना आदि का उत्पादन में हुई वृद्धि को योजनावार अग्र क्रमिक में प्रदर्शित किया जा सकता है -

महत्वपूर्ण कृषि फसलों का उत्पादन (उत्पादन लाख टन/गांठों में)

योजना अवधि के अंत में	फसले						
	अनाज	दाले	कुल खाद्यान्न	तिलहन	कपास	गन्ना	ग्वार
1950 51	28 88	4 98	33 86	1 34	1 03	4 14	
प्रथम योजना (1951 56)	32 37	7 61	39 98	2 09	1 31	4 48	
द्वितीय योजना (1956-61)	33 67	12 73	46 40	2 27	1 63	4 91	
तृतीय योजना (1961 66)	37 06	10 51	47 57	2 56	1 72	7 54	
3 वार्षिक योजनाएँ (1966 69)	28 76	6 73	35 49	1 52	1 72	5 24	
चतुर्थ योजना (1969 74)	50 56	12 94	63 50	3 72	2 62	12 82	
पाचवी योजना (1974 79)	52 42	17 94	70 36	4 43	4 31	21 49	5 79
छठी योजना (1980 85)	65 27	14 67	78 94	7 97	4 77	13 76	3 87
सातवी योजना (1985 90)	73 77	11 55	85 32	18 45	9 86	7 16	4 45
आठवी योजना (1992 97)	108 06	22 13	130 19	40 49	13 63	12 90	7 31
नवी योजना (1997 2002)	115 85	18 80	134 65	39 50	15 25	10 00	
समग्र							

स्रोत : Eighth Five Year Plan 1992-97 & D. A. R. N. II Five Year Plan 1997-2002 Govt. of Rajasthan

उपयुक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होना है कि

1 1950 51 से कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी वृद्धि होती रही है किन्तु आम तौर पर खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति बढ़ने की रही है

2 राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन 1994 95 में 117 लाख टन अंकित किया गया।

3 1980 90 के मध्य 1987 88 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन सबसे कम 47 81 लाख टन हुआ। इसका प्रमुख कारण 1987 88 के वर्ष का सर्वाधिक अकालग्रस्त वर्ष होना था।

4 राष्ट्रीय वर्ष की अवधि में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग तीन गुना हुआ है जबकि इसी अवधि में तिलहनो के उत्पादन में 17 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। 1986 87 से 1995 96 के मध्य ही तिलहन का उत्पादन लगभग सात गुना से अधिक हो गया है। तिलहनो में भी मरसों के

उत्पादन में विशेष वृद्धि अंकित की गई है।

5 दलहनो में अभी तक 1978 79 के उत्पादन 17 94 लाख टन को 1994 95 तक ही पुनः प्राप्त किया जा सका है।

6 कपास के उत्पादन में 1989 90 में विशेष उत्पादन वृद्धि देखने में आ रही है। इस वृद्धि का निरंतर बने रहने की संभावना है।

7 गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 1978 79 में 21 49 लाख टन हुआ था जबकि 1995 96 में उत्पादन उसका लगभग आधा है।

(3) कृषि आदानों का उपभोग (Consumption of Agricultural Inputs) कृषि विकास में कृषि आदानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें खाद उन्नत बीज काटनाशक आदि के संदर्भ में हुई प्रगति को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

राजस्थान में कृषि आदानों का उपभोग

योजना	रासायनिक खाद का उपयोग		उन्नत बीजों का विवरण (हजार किंवटन)	अन्य मुख्य कृषि कीटनाशक वाज़ (हजार किंवटन)	कीटनाशक (टन)
	हजार टन	किन्ग्रापम प्रति हेक्टेयर			
	द्वितीय योजना (1956-61)	1 30	0 09		
तृतीय योजना (1961-66)	7 28	0 48			229
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	30 20	2 12	25 1		
चौथी योजना (1969-74)	57 34	3 51	26 8		915
पाचवी योजना (1974-79)	96 36	5 72	48 1	8 1	1511

छठी योजना (1980-85)	170 96	9 44	125 9	31 8	2704
सातवीं योजना (1985-90)	285 59	15 95	130 9	52.7	2685
आठवीं योजना (1992-97)	701 15	33 81	264 75	137 36	2569
नवी योजना (1997-2002 लक्ष्य)	1138 50	56 08	446 5		5000

स्रोत - Eighth Five Year Plan 1992-97 & Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan

तालिका से ज्ञात होता है कि -

1- राजस्थान में अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण 1966-67 से आरंभ हुआ, उत्पन्न वित्तिन योजनाओं में इसका उपयोग बढ़ा है।

2- अन्य सुधरे हुए बीजों का उपयोग पाचवाँ पंचवर्षीय योजना से आरंभ हुआ और इसका उपयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।

3- रसायनिक खाद का उपयोग भी 1995-96 में वित्त 35 वर्षों की अपेक्षा लगभग 350 गुना हो गया है। प्रति हैक्टेयर रसायनिक खाद के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 1961 में 0.09 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1990-91 में 19.75 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया है। इस प्रकार इसमें लगभग 217 गुना वृद्धि हुई है।

4- 1968-69 की तुलना में 1995-96 में अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण लगभग 8 गुना हो गया है।

5- 1974-79 की तुलना में 1995-96 में अन्य सुधरे हुए बीजों का उपयोग 13 गुना बढ़ गया था। कीटनाशकों का प्रयोग 1961 की तुलना में 1990-91 तक लगभग 25 गुना हो गया था।

(4) राज्य की महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में वृद्धि (Increase in productivity of important crops) - राजस्थान में उन्नत एवं सुधरे हुए कृषि आदानों के उपयोग से महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

राजस्थान में महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)				
फसल	राज्य की उत्पादकता औसत			
	पाचवीं योजना 1974-79	छठी योजना 1980-85	सातवीं योजना 1985-90	आठवीं योजना 1992-97
चावल	1202	1066	1008	1073
आर	377	442	351	375
बाजरा	240	306	277	419
गेहूँ	1334	1642	22053	2340
फलिया	834	1007	900	958
जौ	1302	1362	1613	1773
चना	788	666	701	722
मूंगफली	640	649	751	801

मिट	140	127	125	174
सरसों व राई	541	759	875	890
अलसी	340	380	368	402
कपास	223	215	265	334
कुल	42137	40471	42273	47543

स्रोत - Eighth Five Year Plan 1992-97 & Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से फसलों की उत्पादकता के संदर्भ में इन तथ्यों का पता चलता है -

1- राज्य की महत्वपूर्ण फसलों में से अधिकांश फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत में अभी भी कम है।

2- विगत तीन योजनाओं में चावल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा है।

3- गेहूँ की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में विगत तीन योजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। लगभग यहाँ स्थिति सरसों व राई के उत्पादन में रही है।

(5) राजस्थान में कृषि पर व्यय (Expenditure on Agriculture in Rajasthan) - राजस्थान की विभिन्न योजनाओं में कृषि एवं उसकी सहायक सेवाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना से वर्तमान तक किये गये श्रावधान एवं वास्तविक व्यय को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है-

राजस्थान की योजनाओं में कृषि हेतु श्रावधान एवं व्यय				
योजना	श्रावधान (कोटि रुपये)	व्यय के कुल प्रवर्धन (कोटि रुपये)	व्यय के कुल प्रवर्धन (कोटि रुपये)	व्यय के कुल प्रवर्धन (कोटि रुपये)
प्रथम योजना	3.24	5.02	2.82	4.84
द्वितीय योजना	6.70	6.38	6.32	6.15
तृतीय योजना	16.30	6.91	12.40	5.83
चौथी योजना	11.01	8.20	10.02	7.33
पाचवीं योजना	10.95	3.85	10.28	3.33
षष्ठी योजना	32.83	3.88	31.44	3.67
सप्तम योजना (1979-80)	12.67	4.61	15.60	5.38
अष्टम योजना	82.33	4.07	96.55	4.55
नवम योजना	144.74	4.82	161.90	5.21
दशम योजना	1296.92	11.19		

स्रोत - Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि -

1 राजस्थान की विभिन्न योजनाओं में तो कृषि के लिए किया गया प्रावधान और न ही योजनाकाल में स्पष्ट किया गया वास्तविक व्यय निरंतर बढ़ा है, चतुर्थ योजना के पश्चात् यद्यपि इन दोनों में ही निरंतर वृद्धि अंशित की गई है।

2 योजना काल में कृषि पर किये गये प्रावधान एवं वास्तविक व्यय के प्रतिगत के संदर्भ में ही चतुर्थ योजना के पश्चात् ही निरंतर वृद्धि हुई है।

(6) राजस्थान में योजनाकाल में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय (Per Capita Expenditure on Agriculture under plans) - राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गए कुल प्रतिव्यक्ति व्यय एवं कृषि व सम्बंधित सेवाओं पर किया गया प्रतिव्यक्ति व्यय इस तालिका में स्पष्ट है।

राजस्थान में योजनाकाल में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय		
योजना	प्रतिव्यक्ति कुल व्यय (रुपये में)	प्रतिव्यक्ति कृषि पर व्यय (रुपये में)
प्रथम योजना	34	1 64
द्वितीय योजना	65	3 99
तृतीय योजना	97	5 65
चतुर्थ योजना	120	3 99
पाचवी योजना	332	12 18
छठी योजना	622	28 30
सातवी योजना	875	45 58

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्रतिव्यक्ति नगण्य राशि व्यय की गई। द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय बढ़ा किन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह पुनः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के स्तर पर आ गया। चौथी पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति व्यय तीन गुने से अधिक हो गया। पाचवी पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा छठी योजना में प्रतिव्यक्ति व्यय दुगुण से अधिक रहा किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह ह्रैद गुने से कुछ अधिक रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय राजस्थान में सातवी योजना की अपेक्षा पांच गुना अधिक होने की सम्भावना है।

राजस्थान की आठवी योजना में कृषि विकास की व्यूह-रचना

AGRICULTURAL DEVELOPMENT STRATEGY IN VIII PLAN

आठवी योजना में कृषि पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1 राजस्थान में शुष्क कृषि को अधिक लोकप्रिय बनाने की वृष्टि की गई। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 70-75% ऐसा क्षेत्र है जहाँ शुष्क खेती को अपनाया जा सकता है। अतः शुष्क कृषि का लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया।

2 योजना के अंतर्गत वज्र व पड़त भूमि का उपयोग करने के लिए कृषि संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया।

3 इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 17 94 लाख हेक्टेयर मरुस्थलीय भूमि को दृष्टिगत रखते हुये सुधार की चेष्टा की गई।

4 गमायनिक कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद के साथ साथ भूमि की उत्पादकता बनाये रखने के लिए जैविक और हरे खाद का प्रयोग किये जाने का प्रयास किये गये। राजस्थान में पानी की कमी को दृष्टिगत रखते हुये कृषि उपजों का विविधीकरण कर ऐसे फसलों लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती हो। भूमिगत जल के कुशल उपयोग के लिए बुद-बुद मिचाई पद्धति व फव्वारा मिचाई को प्रोत्साहित किया गया।

5 सातवी योजना के अंतर्गत कृषि नियोजन में कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किया गया। राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से 9 खण्डों तथा उपखण्डों में विभाजित किया गया। आठवी योजना में कृषि जलवायु क्षेत्र को दृष्टिगत रखत हुये ही कृषि विकास सत्रों निर्णय लिये गये।

6 कृषि एवं उसके माध्यम धर्मों के लिए एक विस्तृत कृषि विकास योजना बना कर विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई।

7 राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता व कमी को दृष्टिगत रखते हुये किसानों का जातिम में बचने व उन्नयन में फलम बोध का विस्तार किया गया।

राजस्थान में आठवी योजना के अंतर्गत खेती के उत्पादन का मूल्य 113 90 लाख टन निर्धारित किया

गया था जबकि वार्षिक उत्पादन 130 19 लाख टन हुआ। तिलहन का उत्पादन लक्ष्य 39 90 लाख टन, गन्ने का उत्पादन लक्ष्य 11 25 लाख टन एवं कपास का उत्पादन लक्ष्य 11 90 लाख गांठे निर्धारित किया गया। जई कि वार्षिक उत्पादन क्रमशः 40 49 लाख टन, 12 90 लाख टन व 13 63 लाख टन गांठे हुआ। आठवीं योजना में 38 54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उन्नत बोझों के अंतर्गत लाया गया। योजना की अवधि में 402 1 हजार क्विंटल उन्नत बीज वितरित किये गये। 'गन्नापनिक खाद' का उपयोग भी योजना अवधि में 701 1 हजार टन हुआ।

नवी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की व्यूह-रचना

राजस्थान में इस योजना में कृषि व संबंधित सेवाओं पर 1880 03 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं -

1 शक्तिगत समस्याओं के विकास तथा सामुदायिक ढांचागत आधार के निर्माण हेतु मार्गदर्शक एवं निजी निर्यातों को बढ़ावा देना। इस कार्य हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगे -

(i) सामान्य उगाओं टेक्नालॉजी पार्क उच्च तकनीकी प्रदर्शन एवं उत्पादक फलों की स्थापना हेतु निजी उद्यमियों को सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

(ii) कृषि विज्ञान को बढ़ावा देने वाली फर्मों को विशिष्ट महयोग प्रदा किया जायेगा।

(iii) वाहन एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली तथा दूर परम्परागत आगनों का उत्पादन करने वाली निजी फर्मों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(iv) फर्मों के ढांचागत विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं का महयोग प्राप्त किया जायेगा।

2 फर्मों के ढांचागत विकास हेतु विभिन्न प्रकार की माध्यम मुक्तिओं में रुचि की जादी और कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं का महयोग प्राप्त किया जायेगा।

3 छोटे मागान एवं स्को वक्कों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम मगाहित किया जायेगा।

4 कृषि उत्पादन एवं प्रक्रम में सुधार हेतु निम्न कार्य किये जायेंगे

(i) कृषि विज्ञान को सुदृढ़ करने तथा प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु स्थानीय व्यक्तियों एवं प्रै मरकती संस्थाओं का महयोग

प्राप्त किया जायेगा।

(ii) कृषि समुदाय के प्रशिक्षण व तकनीकी स्तर को उच्च करने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ किया जायेगा।

(iii) निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रैट किस्म के बीजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा।

(iv) कृषि आदानों को गुणवत्ता पर विशिष्ट ध्यान दिया जायेगा।

(v) कृषि क्षेत्र में तकनीकी खो एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(vi) कृषि विस्तार में मद्यार के माधनों का पूर्ण उपयोग किया जायेगा।

राजस्थान में भू-उपयोग

LAND UTILIZATION IN RAJASTHAN

शक्तिगत संसाधनों में भूमि अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः उसका उचित उपयोग होना चाहिये। भूमि को अनेक प्रयोगों में लिया जा सकता है इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चाहे जिस कार्य में भूमि का प्रयोग हो, वह उसका सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिये। इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिये कि सभी भूमि एक जैसी नहीं होती। इस कारण उनका महत्व भी अलग-अलग होता है। भूमि की स्थिति, उस की बनावट उसका ढाल आदि उसकी उपयोगिता को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। यह भूमि व मिट्टी के समाधानों का दुर्भयोग होता है तो इससे राज्य की समग्र उत्पादकता में ह्रास होता है। राज्य के भू-समाधानों के उपयोग को दृष्टि से जल प्रत्यु का भी विरोध मतत्व है। इस कारण भूमि के उपयोग का अनेक दृष्टिकोणों से पराखा जाना चाहिये। इनमें भू-संरक्षण, भूमि की उत्पादकता, पूर्वी-उत्पाद अनुदान तथा उत्पादक व अनुपादक उपयोग सम्मिता होने चाहिये। भूमि का कुछ उपयोग उसकी उत्पादकता को बढ़ाये रखना है व राज्य को लाभ पहुंचाना है। भूमि का कुछ उपयोग या दुर्भयोग भूमि का अन्वैी विशेषताओं को नष्ट कर राज्य का हानि पहुंचाना है। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में भूमि-उत्पादकता सर्वेक्षा किया जाये। राज्य में वर्तमान में समस्त भूमि-विन-विन कार्यों में प्रयोग में लाई जा रही है। इसका विस्तृत अध्ययन करते भूमि के प्रभावी उपयोग के लिए भावी नीति निर्धारण का जन्म चाहिये।

राजस्थान में भू-उपयोग में संरक्षित प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं -

(1) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (Total Geographical Area) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आशय उस क्षेत्र से है जिसके मध्य में भूमि उपयोग वर्गीकरण उपलब्ध है। भूमि उपयोग संबंध आकड़े ग्राम पटवारी द्वारा राजस्व के

उद्देश्य से निर्मित रिटर्न के आधार पर तैयार किये जाते हैं। राजस्थान का भू-उपयोग की दृष्टि से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल व उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग निम्न तालिका से स्पष्ट है।

राजस्थान में भू-उपयोग (हजार हेक्टेयर)					
विवरण	1970-71	1979-80	1989-90	1994-95	1995-96
1. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अन्तर्गत से	34109	34234	34248	34243	34243
2. गन्ना	1355	2068	2324	2450	2458
3. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि					
(अ) भूमि का अल्पि जलों से उपजाऊ	162	1509	1624	1667	1680
(ब) बरत ला अल्पि भूमि	4715	2931	2819	2670	2657
4. अन्य अल्पि भूमि					
(अ) अर्द्ध चरागाह तथा अन्य पशु भूमि	1807	1841	1802	1751	1745
(ब) विभिन्न कृषि फसलों और के अर्थात् भूमि	9	9	23	17	16
5. वन्य भूमि (संग्रह भूमि का)					
6. पशु भूमि (संग्रह)	6112	6406	5628	5165	5103
(अ) पशु भूमि (बाग पशु के अर्थात्)	2325	2275	2082	1832	1972
(ब) पशु भूमि	1443	2988	2340	1670	2036
7. गन्ना बाग हुआ विलस	15179	14207	15606	17021	16575
8. एक से अधिक बार बसाव गन्ना भूमि	1550	2164	2297	3359	3098
9. कुल बाग पशु भूमि	16729	16371	17903	20380	19673

Source Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt of Rajasthan A Broucher on some facts of Agriculture in Rajasthan five Year plan 1997-2002 Govt of Rajasthan & Statistical Abstract Rajasthan 1998

(2) वन (Forest) - वन का अतर्गत वह सम्पूर्ण भूमि सम्मिलित की जाती है जो किसी भी वैधानिक अधिनियम के द्वारा वन के रूप में वर्गीकृत की गयी हो चाहे वह सरकारी स्वामित्व में हो या निजी स्वामित्व का अतर्गत हो चाहे उस भूमि के कृषि हो या वह भूमि वनों की सहायता से युक्त हो। वनों के मध्य आने वाले कृषि क्षेत्र एवं चरागाह का भी वन क्षेत्र के अतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कृषि विभाग व वन विभाग द्वारा दिय गये वन क्षेत्र के आकड़े में सदैव अंतर बना रहता है। राजस्थान में द्वितीय योजना के अतर्गत औसतन 1067 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वन थे। सातवीं योजना के अतर्गत यह औसतन दुगुने से भी अधिक होकर 2276 हजार हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में है। राजस्थान में वनों की स्थिति एवं जिलेवार वन निम्न प्रकार है।

योजना काल में राजस्थान में वन क्षेत्र	
योजना	वन (हजार हेक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	1302
द्वितीय योजना का औसत	1067
तृतीय योजना का औसत	975
चौथी योजना का औसत (1966-69)	1182
पाँचवी योजना का औसत	1417
छहवी योजना का औसत	2069
सातवी योजना का औसत	2135
आठवी योजना का औसत	2276
1995-96	2458

Economic Review 1997-98 1998-99 Govt of Rajasthan
Source Trends in Land Use Statistics in Rajasthan and Agricultural Statistics 1994-95, Rajasthan A Broucher on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995

(3) भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग (Area Under Non Agricultural Use) - इस वर्गीकरण के अतर्गत वह सम्पूर्ण भूमि सम्मिलित है जो भवनों सड़कों रेलमार्गों नदियों नहरों तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो रही है। राजस्थान में अकृषि कार्यों में उपयोग की जाने वाली भूमि का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। द्वितीय योजना में यह औसतन 1164 हजार हेक्टेयर था जो सातवीं योजना में 1613 हजार हेक्टेयर हो गया है। राजस्थान में अकृषि कार्यों के अतर्गत सर्वाधिक भूमि उदयपुर जिले में और नयपुर गाँव श्रीगंगानगर जिले में प्रयुक्त की जा रही थी। राजस्थान में योजनावधि में तथा जिलेवार भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

योजना काल में राजस्थान भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग	
योजना	वन (हजार हेक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	NA
द्वितीय योजना का औसत	1164
तृतीय योजना का औसत	1137
चौथी योजना का औसत (1966-69)	1186
पाँचवी योजना का औसत	1289
छहवी योजना का औसत	1509
सातवी योजना का औसत	1509
आठवी योजना का औसत	1613
1995-96	1679

Economic Review 1997-98 1998-99 Govt of Rajasthan
Source Trends in Land Use Statistics in Rajasthan and Agricultural Statistics 1994-95, Rajasthan A Broucher on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995

(4) बजर एवं अकृषि भूमि (Barren & Uncultivable land) - इसके अंतर्गत वह समस्त बजर एवं अकृषि भूमि सम्मिलित है जो पहाड़ों, रेगिस्तान आदि के अंतर्गत आती है। यह वह भूमि है जो बहुत अधिक लागत लगाये बिना कृषि के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। ऐसी भूमि कृषि जेतों के बीच में हो या उनसे दूर हो सकती है। राजस्थान में 1995-96 में इस प्रकार की 2656 हजार हेक्टेयर भूमि थी जबकि द्वितीय योजना का औसत 4952 हजार हेक्टेयर का था। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि की मात्रा निरंतर कम हो रही है। इन प्रकार की सर्वाधिक भूमि राजस्थान के उदयपुर जिले में है। बत्सरवात जैमलमर जिले का स्थान है। राजस्थान में बजर भूमि एवं अकृषि भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है -

बजर एवं अकृषि भूमि	
योजना	वर्ग(हजार हेक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	NA
द्वितीय योजना का औसत	4953
तृतीय योजना का औसत	5087
चौथी योजना का औसत (1966-69)	4811
पाँचवी योजना का औसत	4684
छठी योजना का औसत	2931
सातवी योजना का औसत	2899
1995-96	2656

"Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan Vol. I Agricultural Statistics 1994-95, Raj. S.A. Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1993"

(5) कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र (Area Not Available For Cultivation) - कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र के अंतर्गत अकृषि कार्यों में उपयोग में लायी जा रहा भूमि बजर एवं अकृषि भूमि का सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र में गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। यह अच्छी स्थिति बरी हो सकता है। राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक अनुपलब्ध भूमि हमारा उदयपुर एवं जैमलमर जिलों में है। राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र को निम्न कतिपय में दर्शाया गया है

योजना काल में राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र	
योजना	वर्ग(हजार हेक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	7644
द्वितीय योजना का औसत	6117
तृतीय योजना का औसत	6225
चौथी योजना का औसत (1966-69)	5977
पाँचवी योजना का औसत	5972
छठी योजना का औसत	5440
सातवी योजना का औसत	4412
1994-95	4434
1994-95	4137

"Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan Vol. I Agricultural Statistics 1994-95, Raj. S.A. Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1993"

(6) स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि (Permanent Pastures and other Grazing land) - इस भूमि के अंतर्गत सभी चरागाह क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, चार वे स्थायी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। गवों का मानव्य चराई भूमि का भा इस वर्गीकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में इस भूमि का क्षेत्रफल धीरे धीरे घट रहा है। राजस्थान में इस प्रकार की सर्वाधिक भूमि बाड़मेर व बीकानेर जिलों में उपलब्ध है। राजस्थान में स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है

योजना काल में राजस्थान में स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि	
योजना	वर्ग(हजार हेक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	1528
तृतीय योजना का औसत	1771
चौथी योजना का औसत (1966-69)	1818
पाँचवी योजना का औसत	1811
छठी योजना का औसत	1841
सातवी योजना का औसत	1841
1995-96	1745

"Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan Vol. I Agricultural Statistics 1994-95, Raj. S.A. Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1993"

(7) विभिन्न वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि (Land Under Miscellaneous Tree Crops etc) - इनमें वह समस्त कृषि भूमि सम्मिलित है जो शुद्ध घरेलू गव क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है लेकिन वहाँ कुछ अन्य कृषि उपपान में ला जा रहे हैं। कृषि धाराओं बाम के बुधों एवं ईंधन इत्यादि के लिए प्रयुक्त भूमि, जो बगोचों व अवगव नहीं आती इस श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल चौथी योजना में औसत 9.2 हजार हेक्टेयर रह गया था। सातवी योजना में यह औसत बढ़कर 28.2 हजार हेक्टेयर हो गया था। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि का स्थिति निम्न गालिका से स्पष्ट है

योजना काल में भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग	
योजना	वर्ग(हजार हेक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	24
तृतीय योजना का औसत	14
चौथी योजना का औसत (1966-69)	13
पाँचवी योजना का औसत	9
छठी योजना का औसत	9
सातवी योजना का औसत	43
1995-96	28
1995-96	15.6

"Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan Vol. I Agricultural Statistics 1994-95, Raj. S.A. Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1993"

(8) बजर भूमि (Cultivable Waste) - इस वर्गीकरण के अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित है जिस पर कृषि होनी थी लेकिन बाद में किसी कारण से कृषि कार्य बंद करना पड़ा।

ये भूमि निश्चित तौर पर कृषि भूमि रही होती है। इन भूमियों को उचित लागत लगाकर एवं उचित प्रयास करके सुधारा जा सकता है। ऐसी भूमि पड़त भूमि हो सकती है या झाड़ियों और जंगल से भरी हो सकती है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार के प्रयासों के कारण इस प्रकार की भूमि का मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। द्वितीय योजना में इस प्रकार का क्षेत्र औसतन 7078 हजार हेक्टेयर था तो सातवीं योजना में घटकर औसतन 5815 हजार हेक्टेयर रह गया। गजस्थान में सर्वाधिक बजर भूमि क्रमशः जैसलमेर और बीकानेर जिलों में है। राजस्थान में बजर भूमि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है

योजना काल में राजस्थान में बजर भूमि	
योजना	बजर (हजार हेक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	7078
तृतीय योजना का औसत	6561
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	6316
चौथी योजना का औसत	5024
पाचवी योजना का औसत	8406
छठी योजना का औसत	6123
सातवी योजना का औसत	5815
1995-96	5103

Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
 Source: Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(9) अन्य अकृषि भूमि (पड़त भूमि को छोड़कर) (Other Uncultivated Land excluding Fallow Land) - इसके अंतर्गत स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि विभिन्न वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि एवं बजर भूमि का योग सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है तथा इसकी मात्रा जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक है। राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति निम्न प्रकार से है।

योजना काल में अन्य अकृषि भूमि (पड़त को छोड़कर)	
योजना	बजर (हजार हेक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	8924
तृतीय योजना का औसत	8628
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	8348
चौथी योजना का औसत	8148
पाचवी योजना का औसत	7844
छठी योजना का औसत	8258
सातवी योजना का औसत	8007
1995-96	7659
	6933

Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
 Source: Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(10) पड़त भूमि (चालू पड़त के अतिरिक्त) (Fallow Land other current fallows) - इसमें वह

समस्त भूमि सम्मिलित है जो कृषि में प्रयुक्त की जा रही थी लेकिन जिम पर अखाई तौर पर खेती नहीं की जा रही है। खेती न किये जाने की अवधि एक वर्ष से कम और पांच वर्ष से अधिक नहीं होती। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। द्वितीय योजना में यह क्षेत्र औसतन 3438 हजार हेक्टेयर था। सातवी योजना में यह क्षेत्र कम होने के बावजूद भी औसतन 2368 हजार हेक्टेयर था जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान के जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में इस प्रकार की भूमि बड़ी मात्रा में विद्यमान है। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि की स्थिति को निम्न तालिका की सहायता से समझा जा सकता है

योजना काल में पड़त भूमि (चालू पड़त के अतिरिक्त)	
योजना	बजर (हजार हेक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	3438
तृतीय योजना का औसत	2651
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	2146
चौथी योजना का औसत	2227
पाचवी योजना का औसत	2275
छठी योजना का औसत	1990
सातवी योजना का औसत	2356
1995-96	1972

**Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan*
 Source: Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(11) चालू पड़त भूमि (Current Fallow Land) - इसमें ऐसे फसल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जो चालू वर्ष के अंतर्गत पड़त रहा हो। राजस्थान में पड़त भूमि की मात्रा में सामान्यतः अधिक परिवर्तन नहीं आया है। तृतीय योजना में औसत चालू पड़त भूमि 1880 हजार हेक्टेयर थी। 1995-96 में भी यह क्षेत्र 2036 हजार हेक्टेयर था। राजस्थान में सर्वाधिक पड़त जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर जिलों में विद्यमान है। राजस्थान में चालू पड़त भूमि की स्थिति को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है -

योजना काल में चालू पड़त भूमि	
योजना	बजर (हजार हेक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	2078
तृतीय योजना का औसत	1880
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	2244
चौथी योजना का औसत	1878
पाचवी योजना का औसत	2988
छठी योजना का औसत	2059
सातवी योजना का औसत	2656
1995-96	2036

Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
 Source: Trends in Land use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(12) कुल पड़त भूमि (Total Fallow Land) - इस भूमि के अंतर्गत पड़त भूमि (चालू पड़त के अतिरिक्त) एवं चालू पड़त भूमि का योग सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में कुल पड़त भूमि निम्न प्रकार उपलब्ध है -

योगदान काल में कुल पड़त भूमि	
योगदान	वर्ग (हजार हेक्टेयर)
प्रधान योजना का औसत	5741
द्वितीय योजना का औसत	5517
तृतीय योजना का औसत	4531
वर्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	4390
चौथी योजना का औसत	4105
पाचवी योजना का औसत	5263
छठी योजना का औसत	4089
सातवी योजना का औसत	5024
1995-96	4008

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan.
Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan (Vol. Agricultural Statistics, 1994-95, Part 5 A) Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1995

(13) बोया गया शुद्ध क्षेत्र (Net Area Sown) - इसके अन्तर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें फसलें बोयी जाती हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें एक दो वर्ष में दो फसलें ली जा रही हों, उस क्षेत्र को एक ही बार जोड़ा जाता है। राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र निरन्तर बढ़ रहा है। द्वितीय योजना में यह औसत 12689 हजार हेक्टेयर था, जो 1995-96 में बढ़कर 16575 हजार हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र बाड़मेर, श्रीगंगानगर, व झुनझि में था। राजस्थान में शुद्ध बोये गये क्षेत्र को स्थिति निम्न प्रकार है -

बोयाना काल में बोया गया शुद्ध क्षेत्र	
योगदान	वर्ग (हजार हेक्टेयर)
प्रधान योजना का औसत	10619
द्वितीय योजना का औसत	12689
तृतीय योजना का औसत	13929
वर्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	14335
चौथी योजना का औसत	14873
पाचवी योजना का औसत	14207
छठी योजना का औसत	15591
सातवी योजना का औसत	14847
1995-96	18575

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan.
Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan (Vol. Agricultural Statistics, 1994-95, Part 5 A) Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1995

(14) कुल बोया गया क्षेत्र (Total Cropped Area) - इसके अन्तर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें फसलें बोयी गयी हैं और इसमें जम्माबन्द फसलों के क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाता है। ऐसी फसलें जो वर्ष में एक से अधिक बार ली जाती हैं, उस क्षेत्र को हर फसल के लिए अलग क्षेत्र मानकर जोड़ लिया जाता है। राजस्थान में कृषि विज्ञान के साथ साथ बोये गये क्षेत्रफल में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। द्वितीय योजनाकाल में राजस्थान में औसत 13772 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बोयी गयी। 1995-96 में यह क्षेत्रफल 19672 हजार हेक्टेयर हो गया। जिले की दृष्टि से कुल बोया गया क्षेत्रफल सबसे अधिक श्रीगंगानगर जिले में है।

इसका एक प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण एक से अधिक फसलें लिया जाना है। राजस्थान में कुल बोया गया क्षेत्र निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

बोयाना काल में कुल बोया गया क्षेत्र (सकल बोया गया क्षेत्र)	
योगदान	वर्ग (हजार हेक्टेयर)
प्रधान योजना का औसत	11322
द्वितीय योजना का औसत	13772
तृतीय योजना का औसत	14963
वर्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	15433
चौथी योजना का औसत	16350
पाचवी योजना का औसत	16371
छठी योजना का औसत	18101
सातवी योजना का औसत	17168
1995-96	19672

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan.
Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan (Vol. Agricultural Statistics, 1994-95, Part 5 A) Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1995

(15) एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र (Area sown more than once) इस क्षेत्रफल से इस बात का आभास होता है कि सिंचाई सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ है। राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण द्वितीय योजना में इस प्रकार का औसत क्षेत्र 1084 हजार हेक्टेयर था जबकि 1995-96 में राजस्थान में वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र लगभग विगुना होकर 3098 हजार हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सिंचाई सुविधाओं के कारण श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक है। राजस्थान में इस क्षेत्र की स्थिति निम्न तालिका से दर्शायी गई है -

बोयाना काल में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	
योगदान	वर्ग (हजार हेक्टेयर)
प्रधान योजना का औसत	703
द्वितीय योजना का औसत	1084
तृतीय योजना का औसत	1034
वर्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	1118
चौथी योजना का औसत	1478
पाचवी योजना का औसत	2164
छठी योजना का औसत	2510
सातवी योजना का औसत	2318
1995-96	3098

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan.
Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan (Vol. Agricultural Statistics, 1994-95, Part 5 A) Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1995

राजस्थान में फसलों का प्रारूप

CROPPING PATTERN IN RAJASTHAN

राज्य में फसलों का प्रारूप में प्रधान योजनाकाल में अब तक काफी परिवर्तन हुआ है। जिसका सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

फसलें	प्रथम योजना		छठी योजना		सातवीं योजना		आठवीं योजना	
	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनाज	65 64	56 04	91 03	50 29	87 14	50 91	90 74	-
माटा अनाज	55 74	47 58	70 81	39 12	69 45	40 58	-	-
गन्ना	9 22	7 88	18 70	10 33	16 50	9 64	-	-
धान	0 68	0 58	1 52	0 84	1 18	0 69	-	-
दलहन	24 60	21 00	35 09	19 39	29 39	17 17	37 96	-
तिलहन	7 23	6 16	14 85	8 20	25 28	14 72	38 77	-
जिरा	4 36	3 72	4 20	2 32	4 39	2 56	-	-
मुंगफली	0 38	0 32	1 99	1 10	2 76	1 61	-	-
रई व रागी	1 63	1 39	6 45	3 56	14 64	8 55	-	-
अन्य	19 67	16 80	40 04	22 12	29 43	17 20	-	-
कपास	1 93	1 65	3 77	2 08	4 34	2 54	6 54	-
ज्वार, चारा फल मन्डी व मसाले	17 74	15 15	36 27	20 04	25 09	14 66	-	-
योग	117 14	100 00	181 01	100 00	171 16	100 00	207 41	

1 राजस्थान के कृषि विकास इण्डेक्स 1991-92 & Economic Review 1997-98 Govt of Rajasthan

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि राज्य में अन्न फसलों के प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी आई है और यह कमी मुख्यतः मोटे अनाजों में हुई। प्रथम योजना अवधि में छठी योजना में करीब 8% की कमी आई जबकि गेहूँ व चावल का प्रतिशत क्षेत्रफल लगभग अपरिवर्तित है।

राज्य में दलहनो फसलों का प्रतिशत क्षेत्रफल में भी गिरावट का रुख रहा। मात्र पान्थवी योजना अवधि को छोड़कर सभी योजनाओं में प्रथम योजना की तुलना में क्षेत्रफल कम रहा। प्रथम योजना में 21 प्रतिशत क्षेत्रफल में दलहनो को खेती की गई थी, वह घटकर सातवी योजना के अंत में 17.17% हो रहा गई। दलहनो में कमी का मुख्य कारण इसका बागानी क्षेत्रों में बोया जाना है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। दलहनो का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होना भी इसके क्षेत्रफल में कमी का एक कारण है। दलहनो के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए ऐसी किस्मों के विकास की आवश्यकता है जो सूखे से प्रभावित हुये बिना भरपूर उत्पादन दे सकें।

राज्य में तिलहनो के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। छठी योजना से काफी तीव्र गति से वृद्धि हुई। राज्य में प्रथम योजना में मात्र 6.16 प्रतिशत क्षेत्र में इसकी खेती की जाती थी वह बढ़कर छठी योजना में 8.20 प्रतिशत हो गई। सातवी योजना में यह प्रतिशत 14.72 हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः गार्ड व सरसा के क्षेत्र में वृद्धि होने में हुई जो छठी योजना में 3.56 प्रतिशत से बढ़कर सातवी योजना में 8.55 प्रतिशत हो गई। रागी व राई में भी वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में जहां मात्र 8300 हेक्टेयर में रागी की खेती की गई थी वह

बढ़कर 1989-90 में 1.69 लाख हेक्टेयर के बराबर स्तर पर पहुंच गई।

मोटे अनाजों में दलहनो फसलों के क्षेत्रफल में हुई कमी को कृषक ने कपास, गन्ना, चारा, फल व सब्जिया तथा मसालों के क्षेत्रों में वृद्धि कर पूरा किया। प्रथम योजना अवधि में जहां 1.80 प्रतिशत क्षेत्र में इनकी खेती की गई वह बढ़कर छठी योजना में 22.12 प्रतिशत एवं सातवी योजना के 1989-90 वर्ष में 17.20 प्रतिशत रही। राज्य में कपास, ज्वार व मसालों के उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुछ फसलों के प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी हुई है। यह कमी मुख्यतः मोटे अनाजों, जैम-ज्वार, जौ, गन्ना, दालों व चना आदि में हुई है। गेहूँ के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। छठी योजना के पश्चात् चावल के क्षेत्रफल में भी गिरावट का रुख रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चावल की खेती 0.6% क्षेत्र में ही होनी थी जो बढ़कर पांचवी योजना में 1% हो गई। इसके पश्चात् चावल के प्रतिशत क्षेत्रफल में गिरावट हुई। गार्ड व प्रतिशत क्षेत्रफल में भी पांचवी योजना के पश्चात् कमी होना प्रारंभ हो गया। मुंगफली तथा रागी व राई के प्रतिशत क्षेत्रफल में छठी योजना के पश्चात् वृद्धि का रुख रहा।

राज्य में तिलहन व क्षेत्रफल में पक्ष में वृद्धि हुई है। छठी योजना के अन्तर्गत राज्य में ज्वार व तिलहनो के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई लेकिन सातवी योजना में कुछ तिलहन व क्षेत्रफल में गिरावट का रुख रहा।

मोटे अनाजों व दलहन फसलों के क्षेत्रफल में हुई कमी को कृषकों ने कपास, ज्वार, व चापा फलों व सब्जियों तथा मसालों के क्षेत्र में वृद्धि कर पूरा किया। राज्य में कपास, ज्वार व मसालों के उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं।

राजस्थान के कृषि जलवायु खण्ड

AGRICULTURAL CLIMATE ZONES OF RAJASTHAN

संपूर्ण भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों की दृष्टि से 14 भागों में बाटा गया है। इन क्षेत्रों में से क्षेत्र संख्या 6, 8, 9 और 14 के अंतर्गत राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय आधार पर राजस्थान के सर्दर में यह वर्गीकरण अत्र तालिका के रूप में प्रकट है -

राष्ट्रीय कृषि जलवायु क्षेत्र			
राजस्थान से संबंधित राष्ट्रीय कृषि जलवायु क्षेत्र	कृषि जलवायु क्षेत्रों में आने वाले राजस्थान के जिले		
जोन 6 दस-गण मैदान क्षेत्र	श्रीगंगानगर		
83 राजस्थान डिवीजन			
जोन 8 मध्य पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र			
85 पूर्वी राजस्थान मैदानी एवं पहाडी सभाग	जयपुर, अजमेर, पाली, टोंक, मयसूरगढ़, अलवर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, भातपुर, विवाडगढ़		
86 दक्षिणी राजस्थानी पठार एवं पहाडी सभाग	बंसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर		
जोन 94 राजस्थान मालवा पठार सभाग	झालावाड		
जोन 14 पश्चिमी शुष्क क्षेत्र			
14.1 राजस्थान शुष्क क्षेत्र	बीकानेर, जैसमेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, चुरू, डूंगरपुर, बड़मेर, जालौर		

राजस्थान में इस वर्गीकरण को दृष्टिगत रखते हुये, इन्हीं के अनुरूप राजस्थान को पांच प्रमुख खण्डों में विभक्त किया गया है। इन पांच प्रमुख खण्डों में से 4 खण्डों को पुनः 2-2 उपखण्डों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार राजस्थान का कृषि जलवायु की दृष्टि में कुल 9 खण्डों व उपखण्डों में विभक्त किया गया है और आठवीं योजना में इन खण्डों-उपखण्डों की कृषि जलवायु को दृष्टिगत रखते हुये ही कृषि में सर्वविध निर्णय लिये जायेंगे। राजस्थान के इन 9 खण्डों व उपखण्डों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

(1) शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र (खण्ड - 1ए) इस खण्ड में जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर और पश्चिमी चुरू शुष्क मैदानी क्षेत्र सम्मिलित है। इस खण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 124 37 लाख हैक्टेयर है। और इसका अधिकांश भाग मरुस्थली मिट्टी और रेतीली टीलों से युक्त है। यहां की मिट्टी बारीक बलुई दोमट से मोटी रेतीली तक है। इस खण्ड के पश्चिमी भाग में लगभग 100 मि.मी. और पूर्वी भाग में लगभग 300 मि.मी. वर्षा होती है। यहां पर खेती वर्षा ऋतु में निम्न से लेकर मध्यम ऊंचाई वाले टीलों के ढलान पर होती है। प्रायः बरानी स्थितियों में बाजरा तथा खरीफ दालें जैसे मोठ, मूंग आदि उगाई जाती है। जिन क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों से पानी उपलब्ध हो जाता है, वहां पर कुओं द्वारा सिचाई करके रबी अनाजों की ऐसी फसलें भी ली जाती है जो खपत को सहन करती है।

(2) सिंचित मैदानी उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र (खण्ड - बी 1)- लगभग 20 63 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल वाले इस खण्ड में श्रीगंगानगर जिले के नहर अधिकृत क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र की मिट्टी दोमट से चिकनी दोमट, पीले भूरे रंग की ओर चूना युक्त है। अनेक स्थानों पर इन मिट्टियों में रेतीली मिट्टिया भी मिली हुई है। सामान्यतः यहां की मिट्टियाँ में धुलनशील लवण एवं सोडियम की मात्रा काफी अधिक है। इस क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में लगभग 100 मि.मी. और पूर्वी भाग में लगभग 350 मि.मी. वर्षा होती है। श्रीगंगानगर में उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 20.5 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 42.1 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। इसी प्रकार निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 4.7 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 28 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। नहरी सिचाई सुविधाओं के कारण क्षेत्र में आवश्यक भूमि विकास के परचाहूँ येहूँ, चना सरसों कपास, गन्ना आदि अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती है।

(3) अर्ध-स्थलीय जलोत्सरण के अन्तर्गती मैदानी क्षेत्र (खण्ड- 2ए) इस क्षेत्र में नागौर, पूर्वी चुरू, डूंगरपुर, साकर और अलवर जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग है। अरावली पर्वत-श्रृंखलाओं के पश्चिम में स्थित इस खण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 36 लाख हैक्टेयर है। इस क्षेत्र की मिट्टिया बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक है। य मिट्टिया खराब जलोत्सरण और क्षारीयता की समस्याओं से ग्रसित है। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में 300 मि.मी. और पूर्वी भाग में 500 मि.मी. तक वर्षा होती है। साकर के उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 22 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 39.7 सेन्टीग्रेड तक है। इसी प्रकार निम्नतम औसत तापमान जनवरी में 5.3 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून 27.5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। इस क्षेत्र में कृषि की संभावनायें सीमित है

क्योंकि यहाँ की भूमि कम गहरी और चट्टानी घातल से युक्त है। यहाँ खरीफ में बाजरा, मोट चवला व भूगफली तथा रबी में गेहूँ व जौ प्रमुख फसलें हैं।

(4) लूनी नदी का अन्तरवर्ती मैदानी क्षेत्र (खण्ड-बी 2) - इस खण्ड में पश्चिमांग सितोले, पूर्वी जोधपुर, पानी एवं जालोर जिले और अरावली पर्वत-श्रृंखलाओं के पश्चिमी तलहटी वाले क्षेत्र आते हैं। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 29 42 लाख हेक्टेयर है। जोधपुर, जालौर और पाली क्षेत्र की मिट्टियाँ लाल मगस्थली हैं, जानोर क्षेत्र की मिट्टी क्षारीय है। इस क्षेत्र में वर्षा पश्चिम में 300 मि.मी. से पूर्व में 500 मि.मी. तक होती है। फुल फसली क्षेत्र के 27% क्षेत्र में कुआँ और नहर से सिचाई होती है इस खण्ड की मुख्य फसलें खरीफ में बाजरा, मक्का तिल व खरीफ फसल है। रबी में गेहूँ, जौ सरसों व चना को बुवाई प्रमुखता से की जाती है।

(5) आर्द्र-शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-ए3) इस क्षेत्र में अजमेर, जयपुर और टाक जिले आते हैं। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 29 48 लाख हेक्टेयर है। जयपुर जिले के पश्चिमी तथा उत्तरी-पश्चिमी भाग एवं अजमेर जिले की भूमि दोघट किस्म की है। टाक जिले के कुछ भागों में भी भूरी मिट्टी पाई जाती है। इस खण्ड का पश्चिमी व उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा 500 मि.मी. एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में 600 मि.मी. होती है। उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 22 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 40 6 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 8 3 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 27 3 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में कुल फसली क्षेत्रफल के 28% भाग में सिचाई सुविधा उपलब्ध है। खरीफ में बाजरा, मूग, नवला व भूगफली तथा रबी में गेहूँ, जौ व चना प्रमुख फसलें हैं। अजमेर जिले में ज्वार, मक्का तथा कपास की फसलें भी ली जाती हैं।

(6) बाढ़-सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-बी 3) इस खण्ड में दक्षिणी-पूर्वी अलवर, भरतपुर, भीलपुर और सवाई माधोपुर जिले के दक्षिणी भाग आते हैं। इस खण्ड का क्षेत्रफल लगभग 23 60 लाख हेक्टेयर है। इस क्षेत्र की मिट्टियाँ मुख्यतः शमट मिट्टियाँ हैं। कुछ स्थानों पर चूनायुक्त दोघट भी पाई जाती है। यहाँ उत्तरी-पश्चिमी भाग में 500 मि.मी. से दक्षिणी पूर्वी भाग में 650 मि.मी. तक वर्षा होती है। इस खण्ड का 14% फसली क्षेत्र सिंचित है। यहाँ बाजरा, गेहूँ, अरहर चना व सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है।

(7) अर्द्ध-आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (खण्ड - ए4) - इस खण्ड में पूर्वी सिंगेरी, उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 33 59 लाख

हेक्टेयर है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों की अगलगी पहाड़ियों की तलहटी वाले मिट्टी लिथोमोर्स किस्म की हैं। मैदानी क्षेत्र की मिट्टियाँ युगानी दोघट किस्म की हैं। इस खण्ड के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भागों में 500 मि.मी. दक्षिणी पूर्वी भागों में 700 मि.मी. और दक्षिणी पश्चिमी भागों में 900 मि.मी. तक वर्षा होती है। उदयपुर में उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 24 2 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 38 5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 7 8 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 25 3 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। इस खण्ड के कुल फसली क्षेत्रफल का लगभग 38% भाग सिंचित है। यहाँ की प्रमुख फसलों में खरीफ मक्का, ज्वार, भूगफली व कपास तथा रबी में गेहूँ, जौ चना व सरसों प्रमुख फसलें हैं। खरीफ में अधिकांश क्षेत्र में मक्का व रबी में अधिकांश क्षेत्र में गेहूँ व जौ की फसलें ली जाती हैं।

(8) आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-बी 4) - इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 17 21 लाख हेक्टेयर है। इसमें दुर्गपुर व बामवाड़ा जिलों के अतिरिक्त उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग व चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग भी सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश मिट्टियाँ मध्यम गठन व अच्छे जल निकास वाली और चूना युक्त हैं। पहाड़ी ढलाने वाले क्षेत्र की मिट्टियाँ कम गहरी और घाटियों वाले क्षेत्रों की मिट्टियाँ गहरी हैं। इस खण्ड के कुल फसली क्षेत्र का 16% क्षेत्र सिंचित है। धान, कपास व मक्का की खेती यहाँ प्रमुखता से की जाती है। खरीफ में मोटे अनाज व खरीफ दालों की फसलें ली जाती हैं। रबी में चने की खेती भी की जाती है।

(9) आर्द्र-दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-5) - इस खण्ड में झारखण्ड बोरा बूटी और सवाईमाधोपुर का पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 29 13 लाख हेक्टेयर है। इस खण्ड की मिट्टियाँ मूलतः दोघट मूल की हैं और कुछ स्थानों में भूमि क्षारीय है। कुछ क्षेत्रों में भूमि का जल क्षारीयता लिये दुर्ग है। वार्षिक उतर-पश्चिम में 650 मि.मी. से दक्षिण पूर्व में 1000 मि.मी. तक होती है। सारा उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 24 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 42 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 10 6 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 29 7 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य पाया जाता है। कुल फसली भाग का लगभग 26 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। यहाँ फसलें में प्रमुखतः ज्वार, मक्का, कपास, चावल व जौ की खेती की जाती है। रबी में गेहूँ, चना व अलसी की खेती प्रमुख है।

राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि फसलें

IMPORTANT AGRICULTURAL CROPS

राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान का स्थान (1995-96)

फसलें	स्थान
सरसों	प्रथम
ज्वार	"
ग्वार	"
धनिया	"
मोठ	"
बाजरा	द्वितीय
मक्का	"
जौ	"
खरीफ फसलें	तृतीय
चना	"
सोयाबीन	"
मिनाहन	"
तिल	चतुर्थ
मिर्च	पंचम
गेहूँ	षष्ठम्
कपास	"
तरबुज	"

स्रोत: निदेशालय कृषि एवं जलसंधन, राजस्थान, जयपुर

गेहूँ	राजपुर
जौ	जयपुर
चावल	बागवाडा
चना	गजपुर
तिल	नागौर
सरसों व खड़	सवाईमधोपुर
अजदी	जयपुर
मूंगफली	विर्ताडगढ़
अरुंडी	मिर्गोरी
गन्ना	बूंदी
कपास	गजपुर
तरबुज	अजमेर

स्रोत: Statistical Abstract, Raj., 1994

(अ) राजस्थान में रबी की प्रमुख फसलें - गेहूँ, जौ, चना, सरसों, गन्ना, चुकन्दर, तारपीरा, अलसी, तोरिया, कुसुम, जौर, धनिया, सीफ, मसूर, मटर, ईसबगोल, आलू, अफीम, आदि।

(ब) राजस्थान की प्रमुख खरीफ फसलें - बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरुंडी, सूरजमुखी, खरीफ दालें (अरुंड, मूंग, मोठ आदि), ग्वार, चावल, गन्ना आदि।

राजस्थान में विभिन्न फसलों के सर्वाधिक उत्पादक जिले (1993-94)

बाजरा	नागौर
ज्वार	बागवाडा
मक्का	विर्ताडगढ़
गेहूँ	गजपुर
जौ	जयपुर
चावल	गजपुर
चना	गजपुर
तिल	नागौर
सरसों व खड़	सवाईमधोपुर
अलसी	बाग
मूंगफली	विर्ताडगढ़
अरुंडी	मिर्गोरी
गन्ना	बूंदी
कपास	गजपुर
तरबुज	जयपुर

स्रोत: Statistical Abstract, Raj., 1994

राजस्थान में विभिन्न फसलों के अतिरिक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रमुख जिले (1993-94)

बाजरा	जयपुर
ज्वार	अजमेर
मक्का	जयपुर

राजस्थान की प्रमुख फसलें

MAIN CROPS OF RAJASTHAN

(1) गेहूँ (Wheat)

परिचय व महत्व (Introduction) - राजस्थान में गेहूँ की फसल अत्यधिक होती है। यह रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है। गेहूँ का प्रयोग मैदा, सूजी, डबलरोटी बिस्कुट आदि में किया जाता है। गेहूँ में विटामिन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होने के कारण भोजन संपुलित हो जाता है। गेहूँ के तने तथा भूसे का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। राजस्थान के विन्त क्षेत्र में गेहूँ की खेती की जाती है।

उपज की दशाएँ (Condition) गेहूँ के लिए 15 डिग्री से से 26 डिग्री में तक वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूँ खेते समय नमी की आवश्यकता होती है। अक्रूर के समय 3 डिग्री में तापक्रम उपयुक्त रहता है। गेहूँ पकाते समय शुष्क मौसम होना चाहिये लेकिन ऊंचे तापक्रम की अवधि अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे गेहूँ अतिशीघ्र पक जाता है। पकाते समय 21 डिग्री से से 26 डिग्री से तापक्रम ठीक रहता है। गेहूँ रबी

की फसल है। जिन क्षेत्रों में 50 सेमी से 100 सेमी तक वर्षा होती है, वे क्षेत्र गेहूँ उत्पादन के लिए उतम माने जाते हैं जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जनवरी तथा फरवरी में शीतकालीन वर्षा गेहूँ की खेती के लिए लाभप्रद होती है। गेहूँ अनेक प्रकार की मिट्टियों में पैदा हो सकता है किन्तु दोमट तथा हल्की चिकनी मिट्टी, जिसमें नाइट्रोजन तत्व अधिक होता है, सर्वोत्तम माने जाते हैं। गेहूँ उत्पादन हेतु राजस्थान के अधिकांश जिलों में उपयुक्त तापक्रम पाया जाता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों व गगनगर जिले में अधिकांश गेहूँ उत्पन्न होता है। गगनगर, अलवर, भरतपुर, सर्वाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली, सिरोंही, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में व्यापक क्षेत्र में गेहूँ की फसल बोई जाती है। 1995-96 में गगनगर जिले में गेहूँ की सर्वाधिक उपज ली जाती थी। राजस्थान में 1989-90 में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज 2060 किलोग्राम थी जो राष्ट्रीय औसत (1998 किग्रा) से अधिक थी। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज 2417 किग्रा थी और इसी वर्ष गेहूँ का उत्पादन क्षेत्र 23.2 लाख हेक्टेयर था। गेहूँ की उत्पादकता का 1992-97 का राज्य में औसत 2340 किग्रा प्रति हेक्टेयर रहा।

उत्पादन (Production) गेहूँ में मुख्यतः सोना कल्याण, मैक्सिकन, शारबती, कोहिनूर, आदि किस्में बोई जाती हैं। राजस्थान में गेहूँ का उत्पादन विभिन्न वर्षों में अग्रानुसार रहा -

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	39.1
1989-90	34.0
1995-96	54.9
1996-97	67.8
1997-98 (अनुमानित)	67.0
1998-99 (अनुमानित)	64.4

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1993 & Statistical Abstract Rajasthan 1986 & Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan

राजस्थान में गेहूँ का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) गेहूँ सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है -

- (1) गगनगर
- (2) हनुमानगढ़
- (3) जयपुर
- (4) अलवर

(B) सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन निम्न जिलों में होता है -

- (1) गगनगर
- (2) हनुमानगढ़
- (3) अलवर
- (4) जयपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1996

(2) चावल (Rice)

परिचय व महत्व (Introduction) - चावल दक्षिण भारतीयों का प्रमुख भोजन है। उत्तर भारत में चावल का प्रयोग प्रायः विशेष अवसरों तथा त्योहारों पर ही किया जाता है। चावल को साफ करने, इससे तेल निकालने आदि कार्यों में कुटीर व लघु उद्योग कार्यरत है। चावल के पौधे का तिनका काफी सखा होता है। अतः इसका प्रयोग छप्पर, बर्तन, कगज, झाड़ू आदि बनाने में किया जाता है। चावल के भूसे को सीमेन्ट में मिलाकर ध्वनिरोधक दीवारें बनाई जाती हैं।

उपज की दशाएँ (Conditions) - चावल उष्ण कटिबंध का पौधा है अतः इसे उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए वार्षिक तापक्रम 25° से 26° से तक होना आवश्यक है। पौधे के अंकुरित होने की दशा में 20° से मध्य में 24° से तथा चावल पकाने के समय 25° से तापक्रम आदर्श मानते हैं। चावल के पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका पौधा उमने के पश्चात् भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहना चाहिये। इसके लिए 124 सेमी से 200 सेमी तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है अन्यथा सिंचाई द्वारा पर्याप्त पानी देना पड़ता है। इसके लिए हल्की चिकनी, दलदली और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। चावल की खेती में अधिक सख्त में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) बासवाड़ा, गगनगर, कोटा, बूंदी, झुगपुर, उदयपुर आदि जिलों में प्रमुख रूप से चावल उत्पन्न किया जाता है। चित्तौड़गढ़, सर्वाई माधोपुर, भरतपुर, बार, झालावाड़ आदि जिलों में चावल की खेती होती है। राजस्थान में 1995-96 में 139 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चावल बोया गया था। 1992-97 में राजस्थान में चावल की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 1073 किग्रा थी जो राष्ट्रीय औसत से कम थी।

उत्पादन (Production) - राजस्थान में चावल का उत्पादन विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित प्रकार रहा है -

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	1.1
1989-90	1.5
1993-94	1.4
1994-95	1.7
1995-96	1.2
1996-97 (अनुमानित)	1.7
1997-98 (अनुमानित)	1.9

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1998 & 1994 Vital Agricultural Statistics 1994-95 Rajasthan & Indian Economic Survey 1998-99

राजस्थान में चावल का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) चावल सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) बासवाड़ा
- (2) झुगपुर

12 Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan
3 Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002 Govt. of Rajasthan

(3) हनुमानगढ़
(B) सर्वाधिक चावल का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) हनुमानगढ़
(2) बूंदी
(3) बासवाडा
Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(3) ज्वार (Jowar)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - यह ग्रीष्म की फसल है और वर्षा पर आधारित है। राजस्थान की शुष्क जलवायु में कम वर्षा के बावजूद ज्वार की अच्छी फसल ली जा सकती है। निर्धन व्यक्ति भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यह पशुओं के लिए चारे की मुख्य फसल है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - यह उष्ण कटिबंधीय खरीफ की फसल है। यह 30 से मी. से 100 से मी. तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न की जा सकती है। यह फसल कम वर्षा का सामना करने की भी क्षमता रखती है। लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी फसल ली जा सकती है किन्तु दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। 22° से 32° से तक का तापक्रम इस फसल हेतु उपयुक्त रहता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान के प्रमुख जिलों में ज्वार बोई जाती है किन्तु कोटा, बूंदी, झालावाड़, सर्वाईभावेपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर आदि जिलों में यह बहुतायत में बोई जाती है। राजस्थान में 1995-96 में 5.9 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की गई थी। 1992-97 में राजस्थान में ज्वार की औसत उत्पादकता 375 कि.ग्राम प्रति हेक्टेयर थी जो राष्ट्रीय औसत किमा से कम थी।

उत्पादन (Production) - निरन्तर अकाल के कारण ज्वार की फसलें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। विगत वर्षों में ज्वार का उत्पादन इस प्रकार रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	9.8	37
1989-90	8.2	32
1993-94	6.6	16
1994-95	6.7	27
1995-96	5.9	14

Source: Statistical Abstract Raj., 1993 Vital Agriculture

Statistics, 1994, Rajasthan

Index Economic Survey 1998-99

राजस्थान में ज्वार का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

- (A) ज्वार सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है
- (1) अजमेर
 - (2) पाली
 - (3) टोंक
- (B) सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
- (1) झालावाड़
 - (2) कोटा
 - (3) बाग

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1994

(4) बाजरा (Bajra)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - राजस्थान में पश्चिमी भाग में यह प्रमुख फसल खरीफ की फसल है। राजस्थान में खाद्यान्न के रूप में इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। इस पौधे को पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। मोटे अनाजों की इस फसल को अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - खरीफ की फसल को कम वर्षा वाले व कम उपजाऊ क्षेत्रों में भी आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इस फसल के लिए 40-50 से मी. वर्षा आदर्श रहती है लेकिन यह फसल थोड़े सूखे का भी सामना कर पाती है। राजस्थान में प्रायः यह समस्त फसल मानसून पर निर्भर करती है। इसके बोते समय भूमि में कुछ नमी व पक्के समय ऊंचा तापक्रम उपयुक्त रहता है। यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न किया जा सकता है किन्तु हल्की दोमट मिट्टी इसके लिये उपयुक्त रहती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - संपूर्ण राजस्थान बाजरे का उत्पादन क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान में यह विशेष रूप से बोया जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर, जोधपुर आदि के अतिरिक्त अलवर, जयपुर, भरतपुर, सर्वाईभावेपुर आदि जिलों में बहुतायत में उत्पन्न होता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ हैं वहाँ सिंचाई के माध्यम से भी बाजरा उत्पन्न किया जाने लगा है। 1995-96 में राजस्थान के 42.7 लाख हेक्टेयर भूमि में बाजरा बोया जाता था। 1992-97 में राजस्थान में बाजरे का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 419 कि.ग्राम था।

उत्पादन (Production) - फसल में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में ही होता है। विभिन्न वर्षों में राजस्थान में

बाजरे का उत्पादन इस प्रकार रहा

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	73
1989-90	182
1994-95	256
1995-96	116
1996-97	210
1997-98	2511
1998-99	1134

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1989-1991 & 1995 Year
Agricultural Statistics, 1994-95 Rajasthan Economic Review 1995-96, Raj

राजस्थान में बाजरे का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) बाजरा सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) बाड़मेर
- (2) जोधपुर
- (3) नागौर

(B) सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) नागौर
- (2) बूड़
- (4) सीकर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1996

(5) मक्का (Maize)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - यह राजस्थान में बोई जाने वाली खरीफ की फसलों में से एक महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल को भी बाजरा, ज्वार आदि की भांति प्रायः संपूर्ण राजस्थान में छोटा-बहुत अवश्य बोया जाता है। मक्का खाद्य के रूप में बहुतायत से प्रयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का का प्रयोग ग्लूकोज स्टार्च, एल्कोहल आदि निर्मित करने में भी किया जाता है। मक्का को पशुओं के चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - मक्का के उत्पादन के लिए 20° म से 27° से तक का तापक्रम उपयुक्त रहता है। 50 से भी से 100 से भी वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का आसानी से उत्पन्न की जा सकता है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। दोमट मिट्टी में मक्का की अच्छी उपज प्राप्त होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, पाली, जयपुर, दूरी, कोटा, अलवर, टोंक, सिरसही, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में बहुतायत से मक्का उत्पन्न की जाती है।

उत्पादन (Production) - 1995-96 में 9.11

लाख हेक्टेयर भूमि में मक्का बोई जा रहा था। राजस्थान में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1989-90 में 1393 किग्रा था जो राष्ट्रीय औसत 1270 किग्रा से अधिक था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में मक्का की उत्पादकता राजस्थान में 7.28 किग्रा प्रति हेक्टेयर थी। 1992-97 की अवधि में मक्का की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 958 किग्रा थी।

राजस्थान में मक्का का उत्पादन इस प्रकार रहा है-

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	64
1989-90	13
1994-95	67
1995-96	81
1996-97	101
1997-98	1217
1998-99	642

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988 & 1993 Year
Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan Economic Review 1995-96, Raj

राजस्थान में मक्का का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) मक्का सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) उदयपुर
- (2) भीलवाड़ा
- (3) चित्तौड़गढ़

(B) सर्वाधिक मक्का का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) चित्तौड़गढ़
- (2) भीलवाड़ा
- (3) उदयपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1996

(6) जौ (Barley)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - जौ राजस्थान की एक प्रमुख खाद्य फसल होने के साथ साथ पशुओं का भी एक प्रमुख पौष्टिक आहार है। राजस्थान में गेहूँ जौ बना आदि मिलाकर खाने के काम में लिया जाता है। जौ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इससे शराब भी बनाई जाती है। उन्नत किस्म के बीजों के कारण उच्च बोटि का जौ भी उत्पन्न किया जाने लगा है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - जौ रबी की एक प्रमुख फसल है और शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए नम ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। 15° से से 18° से तापमान आदर्श रहता है। गेहूँ के समान ही उत्पादन दशाएँ होने के कारण गेहूँ उत्पन्न न

करने की दशा में प्रायः जौ का उत्पादन किया जाता है इसके लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है किन्तु कुछ उपजाऊ भूमि में भी इसकी फसल ली जा सकती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - अलवर, भरतपुर, सर्वाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, झुजुनू, गगनगर, नागौर, सीकर, उदयपुर आदि जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी जौ उत्पन्न किया जाता है। 1995-96 में 1.96 लाख हेक्टेयर में जौ की खेती की गई। 1989-90 में जौ का उत्पादन 1587 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में जौ की प्रति हेक्टेयर उपज राजस्थान में 1850 कि.ग्रा. थी। 1992-97 की अवधि में राज्य में जौ की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 1773 कि.ग्रा. रही।

उत्पादन (Production) - जौ का शराब उत्पादन में प्रयोग बढ़ने के कारण इसकी उन्नत किस्मों का प्रयोग तथा उत्पादन निरन्तर बढ़ने रहने की संभावना है। विगत वर्षों में जौ का उत्पादन इस प्रकार रहा

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	57
1989-90	34
1994-95	44
1995-96	39
1996-97	51
1997-98	50
1998-99	59

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1999-2000 & 1996 Economic Review 1998-99, Raj.

राजस्थान में जौ का जिलेवार क्षेत्र एवं उत्पादन (1995-96)

(A) जौ सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) जयपुर
- (2) भीलवाड़ा
- (3) अजमेर

(B) सर्वाधिक जौ का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) जयपुर
- (2) भीलवाड़ा
- (3) अजमेर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(7) चना (Gram)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - यह रबी में उत्पन्न होने वाली दलहन की एक प्रमुख फसल है। यह राजस्थान के व्यापक धान में बोई जाती है और विभिन्न प्रकार से इसे खाने का काम में लिया जाता है। दाल के

अतिरिक्त नमकीन, मिठई, देसन आदि में प्रयोग किया जाता है। पशुओं के दाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - यह कम पानी में भी आसानी से उत्पन्न किया जाता है। उठे क्षेत्रों में, जहाँ तापक्रम प्रायः 20° से 25° से के मध्य रहता है, चने की अच्छी फसल ली जा सकती है। इसके लिए दोमट या बलुई मिश्रित दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल बोते समय जमीन में नमी होना आवश्यक होता है। इसमें खाद का प्रयोग बहुत ही कम होता है।

उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र (Production & Production Areas) - गगनगर, अलवर, जयपुर, चुरू, भरतपुर, सर्वाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बासवाड़ा, हनुमानगढ़, कोटा, अजमेर, झालावाड़, सीकर, झुजुनू आदि में चने की अच्छी फसल ली जाती है। शीत जिलों में अल्प मात्रा में चना बोया जाता है। 1989-90 में राजस्थान में चने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 622 कि.ग्रा. था जो राष्ट्रीय औसत 658 कि.ग्रा. से कम था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में चने की उत्पादकता 864 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर थी। विगत वर्षों में राजस्थान में चने का उत्पादन इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन में)
1983-84	17.9	10.8
1985-86	19.4	16.2
1987-88	6.8	5.1
1989-90	11.43	7.11
1991-92	11.0	8.1
1992-93	12.2	7.4
1994-95	15.9	13.7
1995-96	16.2	10.9
1997-98	19.3	-
1998-99	17.3	-

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1998-1999 & 1996-1997 Annual Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99, Raj.

राजस्थान में चने का जिलेवार क्षेत्र एवं उत्पादन (1995-96)

(A) चना सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) हनुमानगढ़
- (2) चुरू
- (3) श्री गंगानगर

(B) सर्वाधिक चने का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) हनुमानगढ़
- (2) चुरू
- (3) अजमेर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(8) कपास (Cotton)

परिचय व महत्व (Introduction) - रेशे वाली फसलों में कपास का महत्वपूर्ण स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास ही है। कपास के बीज (गिर्नाला) का प्रयोग पशुओं के पौष्टिक आहार के रूप में किया जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है। कपास के पौधे के तने का प्रयोग छप्पर बनाने व ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कपास के निर्यात से हमें महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।

उत्पन्न की दशाएँ (Conditions) - कपास के लिए 20° से 40° से के मध्य तापक्रम रहना चाहिये। ऊँचे तापक्रम व धूप से रेशों में अच्छी घनत्व आती है। इन पौधों के लिए पाला हानिकारक होता है। कपास खरीब की फसल है। इसके लिए 70 से 100 से तक की वर्षा ठीक रहती है। अधिक वर्षा से फसल खराब हो जाती है। कम वर्षा होने पर सिंचाई का सहाय लिया जा सकता है। इसके लिए उपजाऊ तथा नमी बनाये रखने की भी क्षमता वाली मिट्टी उपयोगी रहती है। मिट्टी में चूने की भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये। अतः कपास के लिए काली मिट्टी व नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी विशेष उपयोगी होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में गगनगर व हनुमानगढ़ जिले के अतिरिक्त अजमेर भीलवाड़ा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर पाली कोटा बूंदी बासवाड़ा आदि जिलों में कपास उत्पन्न की जाती है। सर्वाधिक फसल गगनगर जिले में होती है। 1998-99 में 63.38 लाख हेक्टेयर भूमि में कपास की खेती का अनुमान है। 1989-90 में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन 386 किलोग्राम था जो राष्ट्रीय औसत 169 किलोग्राम के दुगुने से भी अधिक था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन राजस्थान में 306 किलोग्राम था। 1992-97 की अवधि में राज्य में कपास की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 334 किलोग्राम रही जबकि 1952-53 में वार्षिक उत्पादकता मात्र 121 किलोग्राम थी।

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठें)
1985-86	47
1989-90	16
1994-95	14
1995-96	23
1996-97	136
1997-98	87
1998-99 (अनुमानित)	98

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988 & 1993; West Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99 Raj

राजस्थान में कपास का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) कपास सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) गगनगर
- (2) हनुमानगढ़
- (3) बीकानेर

(B) सर्वाधिक कपास का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) गगनगर
- (2) हनुमानगढ़
- (3) बीकानेर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1998

(9) तिलहन (Oilseeds)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - जिन फसलों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, उन्हें तिलहन में सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में तिल सरसो मूँगफली राई अलसी तारपीण अरुण्डी आदि मुख्य तिलहन फसलें हैं। तिलहन तेल व खली बनाने के प्रमुख साधन हैं। इनकी भाष खाद्य तेलों के अलावा वारिश साबुन दवाइयाँ वनस्पति घी सौन्दर्य प्रसाधन एग रोगन आदि के लिए भी की जाती है।

(क) मूँगफली (Groundnut) - मूँगफली के लिए 20° से 30° से तापक्रम तथा 50 से 75 सेमी वर्षा और हल्की दोपट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1989-90 में मूँगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 775 किलोग्राम था जो कि राष्ट्रीय औसत 847 किग्रा से कम था। 1994-95 वर्ष (अंतिम अनुमान) में राज्य में मूँगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 790 किग्रा था। 1992-97 की अवधि में राज्य में मूँगफली की औसत उत्पादकता 901 किग्रा रही। राजस्थान में मूँगफली का उत्पादन निम्न वर्षों में अप्रतिष्ठित प्रकार से रहा।

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1985-86	14
1989-90	21
1993-94	21
1994-95	19
1995-96	16

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1990, 1993 & West Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99 Raj

राजस्थान में मूंगफली का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) मूंगफली सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) विठोडगढ़
- (2) जयपुर
- (3) बीकानेर

(B) सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) विठोडगढ़
- (2) बीकानेर
- (3) जयपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(ख) सरसों व राई (Mustard & Rape seed) - सरसों तथा राई के लिए 100 सेमी तक की वार्षिक वर्षा और 15° से 26° से तक का तापक्रम तथा साव ही दोमट व हल्की मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1989-90 में सरसों व राई का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 872 किग्रा था जो राष्ट्रीय औसत 714 किग्रा से अधिक था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में सरसों व राई का प्रति हेक्टेयर उत्पादन राजस्थान में 887 किग्रा था। 1992-97 की अवधि में सरसों व राई की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 890 किग्रा रही। राजस्थान में विगत वर्षों में इसका उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठें)
1985-86	59
1989-90	127
1995-96	235
1996-97	310
1997-98	244
1998-99 (अनुमान)	243

राजस्थान में सरसों व राई का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) सरसों व राई सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) अलवर
- (2) गंगानगर
- (3) भरतपुर

(B) सर्वाधिक सरसों व राई का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) गंगानगर
- (2) अलवर
- (3) भरतपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

Economic Review Raj. 1998-1999

(ग) तिल (Sesame) तिल की फसल के लिए 20° से 22° से तापक्रम और 50 से 75 सेमी वर्षा व हल्की बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। 1989-90 में राजस्थान का प्रति हेक्टेयर तिल उत्पादन 287 किग्रा था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में तिल की प्रति हेक्टेयर उपज 227 किग्रा हुई। 1992-97 की अवधि में तिल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 174 किग्रा रहा। राजस्थान में विगत वर्षों में इसका उत्पादन इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठें)
1985-86	02
1989-90	129
1993-94	054
1994-95	092
1995-96	034

राजस्थान में तिल का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) तिल सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) पाली
- (2) नागौर
- (3) जोधपुर

(B) सर्वाधिक तिल का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) नागौर
- (2) बीकानेर
- (3) पाली

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(घ) अलसी (Linseed) - अलसी के लिए 75 से 100 सेमी वर्षा तथा काली व दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में अलसी का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1989-90 में 277 किग्रा था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में अलसी का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 364 किग्रा था। 1992-97 के अंतर्गत अलसी का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 402 किग्रा रहा। राजस्थान में विगत वर्षों में अलसी का उत्पादन इस प्रकार रहा।

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठें)
1985-86	03
1989-90	01
1993-94	01
1994-95	06
1995-96	007

राजस्थान में अलसी का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) अलसी सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) बाड़मेर

(2) रोहि

(3) कोरा

(B) सर्वाधिक अरली का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) बावा

(2) कोरा

(3) चित्तौड़गढ़

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1998

(द) अरली (Castor Seed) - अरली व नीए

20% से 25% से नाफ़स व 60 से 65 सेमी वर्षा व लोगट सिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1994-95 (अंतिम अनुमान) में अरली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 818 किग्रा रहा। निम्न वर्षों में अरली का उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा है -

वर्ष	उत्पादन (माछ टन)
1985-86	0.02
1989-90	0.23
1993-94	0.09
1994-95	0.20
1995-96	0.44

स्रोत : Statistical Abstract 1998 1999 & 1996, Plant Agriculture, 44 others, 1994-95, Raj

राजस्थान में अरली का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) अरली करने अधिक निम्न जिलों में पायी जाती है

(1) गिरी

(2) जालौर

(3) बाड़मेर

(B) सर्वाधिक अरली का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) गिरी

(2) जालौर

(3) बाड़मेर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1998

(10) गन्ना (Sugarcane)

गन्ना एक मूल्यपूर्ण व्यापारिक फसल है। प्रमुख रूप से गन्ने का उपयोग गूड, शर्करा, खाण्ड आदि बनाने में किया जाता है। इंग्रजों को शेष भाग बचना है वह शर्करा एष सिख बनाने के काम आता है। पशुओं को खिलाने, और जाना के लिए भी इस को हुने शेष भाग को काम में लिया जाता है। इस वने हुने भ्रम का उपयोग कागज, किलोना आदि बनाने में भी होता है। चीनी का निर्यात कच्चे विदेशी मुद्रा की अर्जित की जा सकती है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - गन्ने की पत्ती के लिए 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त रहता है। कटाई के समय उष्ण जलवायु ठीक रहती है। गन्ना व मर्दों इस फसल के लिए हर्षितरक है। 100 से 200 सेमी तक वार्षिक वर्षा अवधि पर्याप्त सिंचाई की

व्यवस्था लेनी चाहिये।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में लगभग सभी जिलों में कम या अधिक मात्रा में गन्ना बोया जाता है। इस दृष्टि से बूंदी, चुरू, गजानगर, उदयपुर आदि जिले विशेष महत्वपूर्ण हैं। 1996-97 में लगभग 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की गई। 1992-97 में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 47543 किग्रा/हेक्टेयर का जो राष्ट्रीय औसत से कम था।

उत्पादन (Production) - राजस्थान में विगत वर्षों में गन्ने का उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	उत्पादन (हजार टन में)
1993-94	33.6	14.8
1985-86	28.4	10.0
1987-88	26.0	9.4
1989-90	15.8	7.1
1991-92	31.2	13.6
1993-94	20.5	10.2
1994-95	21.9	9.8
1996-97	27.0	12.8
1967-68	23.0	11.8
1998-97	20.0	9.5

Source: Statistical Abstract 1998 & 1993, Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt of Rajasthan, Economic Survey 1998-99 Raj

राजस्थान में गन्ने का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) गन्ना सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

(1) बूंदी

(2) चित्तौड़गढ़

(3) गजानगर

(B) सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) बूंदी

(2) चित्तौड़गढ़

(3) गजानगर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1998

(11) तंबाकू (Tobacco)

तंबाकू एक मादक पदार्थ है। इसे विभिन्न प्रकार में खाने-पीने, सूम्स आदि के काम में लिया जाता है। तंबाकू के विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - तंबाकू के लिये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापक्रम होना चाहिये। इसकी उगाते समय 20 से 30 तापक्रम उपयुक्त रहता है। पछने समय मीमम शुष्क और तापक्रम उन्हा हो तो अच्छा रहता है। तंबाकू के लिए 50 से 100 सेमी की वर्षा उपयुक्त रहती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की जाती है। तंबाकू के पौधे प्रायः दानू जमीन पर बनाये गये हैं क्योंकि इसकी जड़ों में यदि पानी का जमाव

हो तो वह इसके लिए हानिकारक रहता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, गंगानगर, झुझुनू, सवाई माधोपुर, सोकर आदि जिलों में तबाकू की खेती की जाती है। 1995-96 में 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में तबाकू की खेती की गई थी और उस समय राज्य का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1610 किग्रा था।

उत्पादन (Production) - विगत वर्षों में राजस्थान में तबाकू का उत्पादन क्षेत्र निम्नांकित प्रकार से रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	उत्पादन (हजार टन में)
1983-84	2.5	2.5
1985-86	2.7	2.7
1987-88	1.8	2.2
1989-90	3.6	4.3
1991-92	1.8	2.2
1993-94	1.4	2.4
1994-95	1.7	2.7
1995-96	1.3	2.1

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988, 1994
1995, Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan

राजस्थान में तबाकू का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) तबाकू सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) अलवर
- (2) झुझुनू
- (3) दौसा

(B) सर्वाधिक तबाकू का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) झुझुनू
- (2) अलवर
- (3) जयपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(12) दलहन या दालें (Pulses)

राजस्थान के विभिन्न जिलों में दालों के अर्तगत मूग, मोठ, उड़द, चना, मसूर, मटर, तूर, अरहर आदि की खेती की जाती है।

(क) खरीफ की दालें (Kharif Pulses)

राजस्थान में खरीफ दालों में मूग, उड़द, मोठ तथा चवला की खेती सामान्यतः बारानी क्षेत्रों में की जाती है। दालों के ये पौधे अपनी जड़ों से भूमि में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता रक्खि में वृद्धि करते हैं। इन फसलों में सूखे की स्थिति को सहन करने की

क्षमता होती है। शारीर व लवणीय भूमि में भी दालों की खेती की जा सकती है अच्छे जल निकास वाली हल्की या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। नमी है। समव हो तो खेत में नमी की कमी होने पर सिंचाई करना उपयुक्त रहता है। 1995-96 में 3 22 लाख टन खरीफ की दालों का उत्पादन हुआ।

(व) रबी की दालें (Rabi Pulses) - राजस्थान में रबी के दाला में चना, मसूर, मटर, आदि की खेती की जाती है।

(i) **मटर (Pea)** - मटर एक दलहनी फसल है। इसमें फसल संरक्षण के उपाय आवश्यक हैं। मटर के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है भारी मिट्टी व ऐसे स्थान जहाँ पानी का निकास नहीं होता है, फसल अच्छी नहीं होती और सिंचाई के बाद पौधे पीले पड़कर नष्ट हो जाते हैं। मटर के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। फल के इसके फूलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचता है। बुवाई करते समय भूमि का तापक्रम 22 सेंटीग्रेड होना चाहिये।

(ii) **मसूर (Lentil)** - मसूर के लिए आरंभ में उष्ण एवं ठंड और पकते समय ठंडा लेकिन खुली धूप वाला वातावरण उपयुक्त रहता है। यह फसल फाले को सहन नहीं कर पाती। मसूर की अतिविधित फसल के लिए भूमि में उपलब्ध नमी एवं सर्दी के प्रसंग में ओस की बूंदें पर्याप्त होती हैं। भारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है किन्तु जल भण्डार वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है।

राजस्थान में 1995-96 में अरहर या तूर का सबसे ज्यादा उत्पादन अलवर जिले में हुआ था। तत्पश्चात् बांसवाड़ा और उदयपुर का स्थान रहा। इसी प्रकार, मूग का उत्पादन मुख्य रूप से नागौर, झुझुनू व अजमेर जिलों में होता है। मोठ उत्पादन की दृष्टि से बाड़मेर, बुरु और बीकानेर जिले प्रमुख हैं। सर्वाधिक उड़द चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। तत्पश्चात् बांसवाड़ा, झारपुर और उदयपुर का स्थान है। चवले का सर्वाधिक उत्पादन सीकर, जयपुर, नागौर व झुझुनू जिलों में होता है। सबसे अधिक मसूर भरतपुर जिले में होती है। तत्पश्चात् भीलवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ जिलों का स्थान आता है। सबसे ज्यादा मटर जयपुर जिले में पैदा होती है। तत्पश्चात् बाग व कोटा का स्थान है। 1995-96 में दालों का उत्पादन 14 56 लाख टन हुआ।

रबी की प्रमुख फसलें

(Other Rabi Crops)

(*) **तरापीर** - इस फसल को अनुपजाऊ एवं अनुपयोगी भूमि पर भी बोया जा सकता है। इसमें 35% तेल की मात्रा होती है। इससे संबंधित उपयुक्त किस्मों में टी 27 व आर

टी एम ए प्रमुख है। टी-27 किस्म की औसत उपज 6.5 किंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इस किस्म में 36% तेल की मात्रा पाई जाती है। बारानी क्षेत्रों में बुवाई के लिए उपयुक्त यह किस्म सूखे के प्रति सहनशील है। आर टी एस ए भी बारानी क्षेत्र की किस्म है और इसकी उपज भी 6 किंटल प्रति हेक्टेयर है। यह सूखे के प्रति भी सहनशील है किन्तु इसमें तेल की मात्रा 35% होती है। इस फसल से संबंधित रोगों में मोयला, जुसला, तुलासीदा एव सफेद रेली प्रमुख है।

(2) तोरिया - तिलहनी फसलों में यह सबसे कम समय में पकने वाली और सबसे पहले बोई जाने वाली फसल है। इसकी खेती फसल की कटाई एव रबी फसल की बुवाई के बीच के समय में की जाती है। इसमें 42% से 45% तक तेल होता है। यह फसल राजस्थान के सभी जिलों में होती है। किन्तु अलवर, भरतपुर, सर्वाईमाधोपुर एव गगनगर जिलों में इसकी फसल काफी क्षेत्र में की जाती है।

(3) कुसुम - यह एक नई तिलहनी फसल है। इसका तेल पौष्टिक एवं गुणकारी होता है। हृदय रोग के लिए इस तेल को उपयुक्त माना जाता है। कुसुम के बीजों में 30-35% तक तेल होता है। इसमें 3% खनिज लवण 18 से 20 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त विटामिन 'ए' और 'बी' प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके तेल का उपयोग वनस्पति तेल बनाने में किया जाता है। तेल निकालने के पश्चात् बची हुई कुसुम की खली में 30-35% प्रोटीन होता है अतः इसका उपयोग पौष्टिक आहार के रूप में भी किया जाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग बारानी है। और यहां पर सिंचाई के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में किसान एक से अधिक फसल नहीं ले पाते। इस कारण कुसुम की खेती का विशेष महत्व है। कुसुम की जड़ें जमीन में डेढ़ से दो मीटर तक गहरी जाती हैं। इस कारण सूखे की स्थिति आने पर यह भूमि की गहराई में नमी भी सकती है। इसके साथ ही इस फसल के पत्तों से बाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। रबी तिलहनी में यह एक ऐसी फसल है जिसे जल की कम आवश्यकता पड़ती है। बारानी क्षेत्रों में कुसुम को चने के साथ 4:6 (कुसुम चना) के अनुपात में कतारों में 30 सेन्टीमीटर की दूरी पर बुवाई करना लाभदायक रहता है।

(4) चुकन्दर - चुकन्दर की खेती के लिए राजस्थान उपयुक्त है। श्रीगंगानगर में चुकन्दर से चीनी बनाने का कारखाना भी है। चुकन्दर की अच्छी वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेन्टीग्रेड तक औसत तापमान होना चाहिये। चुकन्दर की खेती उन सभी क्षेत्रों में की जा सकती है जहां पर शीत ऋतु में कठिन तीन महीने रहती है। गन्ने की तुलना में यह फसल पाल को

सहन कर सकती है किन्तु गर्मी जल्दी आने और तापमान बढ़ने से इसके जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। चुकन्दर उन सभी मिट्टियों में पैदा हो सकता है जिनका जलनिकास अच्छा है तथा पानी सोखने की क्षमता अच्छी है। अच्छी वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। शारीर मिट्टियों में इसे उगाया जा सकता है। एक खेत में चुकन्दर 3 वर्ष में एक बार ही बोई जानी चाहिये।

(5) ईसबगोल - राजस्थान में ईसबगोल की खेती जालोर व सिरोही जिलों में प्रमुखता से की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ईसबगोल की भूमि, जिसकी मात्रा बीज के भार में 30 प्रतिशत होती है, सबसे कीमती व उपयोगी भाग है। बाकी भाग एव चारा पशुओं को छिलाने के काम आते हैं। साधारणतः ईसबगोल की फसल में कीट एव रोगों का प्रकोप नहीं होता है किन्तु कभी-कभी गूर्णी फफूंद रोग की रोकथाम करनी होती है।

(6) अफीम - राजस्थान के लिए अफीम की तैलिया, रमजराट एव चितौड़गढ़ सलेक्शन किस्में उपयुक्त पाई गई हैं। अफीम के लिए चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। यह फसल अक्टूबर के अंतिम मज्जाह में लेकर नवम्बर के पहले सप्ताह तक बोई जाती है। अफीम निकालने के समय सिंचाई बंद कर दी जाती है। अफीम के डोंडों पर चीस लगाना शुरू करने के बाद सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक हेक्टेयर में अफीम के लगभग 3 लाख पौधे होने चाहिए। अफीम निकालने के लिए डांडों पर कुल मिलाकर 3-4 बार चीस लगाना होता है। अफीम की उपज 35 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो जाती है। इसके अतिरिक्त 5 किंटल बीज एव 5 किंटल डोंडें भी प्राप्त हो जाते हैं।

अफीम के डोंडों में भूमिगत बीज, मृदु गेमिल, फफूंद, गूर्णी-फफूंद व छोड़ा लट आदि से बचाव किया जाना चाहिये।

(7) जीरा - जीरा एक प्रमुख नकदी फसल है। कम समय में पकने के साथ ही यह अधिक आमदनी भी प्रदान करती है। राजस्थान में जीरे की खेती मुख्य रूप से अजमेर, पाली, जालोर, मिरापुरी, बाडमेर, नागौर, टोंक व जयपुर जिलों में होती है।

(8) धनिया - राजस्थान में धनिया की खेती मुख्यतः नाटा झालावाड़, बूंदी, सर्वाईमाधोपुर और जयपुर जिलों में होती है। खनिज क्षेत्रों में जैविक खाद की दृष्टि में धनी सभी प्रकार की मिट्टियों में इसे बोया जा सकता है। बारानी फसल के लिए वाली व अन्य मिट्टी जिसमें पानी का गैर गहन की क्षमता हो, उपयुक्त है।

(9) सौफ - शरद एवं शुष्क वातावरण इसकी फसल के लिए उपयुक्त है। बसुई मिट्टी को छोड़कर ऐसी सभी मिट्टियाँ में जहाँ जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में हों, इसकी खेती की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए चुना-युक्त दोमट व कांसी मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में सौफ अधिकांशतः टोंक, सिरोंहा, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा कोटा एवं पाली जिलों में उगाई जाती है। राजस्थान में बुवाई के लिए सौफ की उन्नत किस्म यू एफ 32 उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को झुलसा, छाछिया व मोयला रोग से बचाया जाना चाहिये।

खरीफ की अन्य महत्वपूर्ण फसलें Other Kharif Crops

(1) सोयाबीन - सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहन एवं दलहन फसल है। इसमें 80% प्रोटीन एवं 20% तेल होता है। वनस्पति घी बनाने के अतिरिक्त इसका उपयोग पेन्ट, चारिंश, सानुन, स्याही, रबर, ग्लिसरिन आदि उद्योगों में भी किया जाता है। सोयाबीन से दूध, दही व मक्खन बनाये जाते हैं। इसका दूध रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से गाय के दूध के बराबर होता है। 750 से 1250 मि.मी. वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है।

(2) ग्वार की फसल - इस फसल को प्रमुख रूप से चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है किन्तु गौद के रूप में इसका विशेष औद्योगिक महत्व है। ग्वार की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है।

(3) सूरजमुखी - सूरजमुखी के लिए मध्यम किस्म की भूमि उपयुक्त रहती है। किन्तु पानी में भरे रहने वाले खेत इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त है। सूरजमुखी का तेल जैम जैम खाद्य तेल के रूप में लोकप्रिय होता आ रहा है। वैसे-वैसे सूरजमुखी की खेती लोकप्रिय होती जा रही है। राजस्थान में सूरजमुखी की उन्नत किस्मों में एम एस एफ एव 8, एम एम एफ एव 17, एम्सस त्रिकोर्ड व ई सी 68415 प्रमुख हैं। ये किस्में खरीफ ऋतु में 90 दिनों में पक कर तैयार हो जाते हैं। जायद (बसंत ऋतु) में 100 से 115 दिन व रबी में 125 से 135 दिन की अवधि लेती है। इस फसल के कटवर्ष, पत्ते कुतरने वाली लट, हलतेला, मण्डेद मकड़ी व पक्षियों से बचाना चाहिये।

(4) होहोवा - यह एक विदेशी पौधा है जो मैक्सिको, बेलिज, ग्रेनाडा और एरिजोना के रेगिस्तान में पाया जाता है। उस क्षेत्र को पथरीला और ककर वाली भूमि में यह अत्यधिक

रूप से उगता है। यह दीर्घायु (40 से 200 वर्ष), हमेशा हरा रहने व बहुत घनी गति से बढ़ने वाला पौधा है। इसकी ऊँचाई एक से तीन मीटर तक होती है।

यह पौधा एकलिंगी होता है अर्थात् नर व मादा फूल अलग-अलग पौधों पर लगते हैं। नर फूल हमेशा गुच्छों में लगते हैं जिनकी संख्या 7 से 36 तक होती है। मादा फूल शाखा के एक नोड से एक ही निकलता है। फूल प्रायः अक्टूबर या नवम्बर माह में आते हैं जिनमें अप्रैल-मई तक बीज बन जाते हैं। कभी-कभी अप्रैल-मई में भी फूल खिलते हैं, जिनसे अक्टूबर तक बीज प्राप्त हो जाता है परन्तु अप्रैल-मई के बीजों की पैदावार अधिक होती है। इसके बीज की संरचना, आकार, रंग तथा भार में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। बीज प्रायः सन्ना, गोलाईयुक्त व नुकीला होता है। इसके बीजों से करीब 45-55 प्रतिशत तक तेल प्राप्त किया जा सकता है। यह तेल उच्च तापक्रम व बहुत भारी दबाव वाली मशीनों के गियर्स आदि में प्रयुक्त होता है। इसके तेल के गुण 'स्पर्मवेल' से निकले तेल के समान हैं। प्रसाधन सामग्री उद्योग एवं विपकाने वाले पदार्थों के निर्माण में भी यह तेल प्रयुक्त होता है।

मूलतः रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा होने के फलस्वरूप इसकी खेती के लिए बहुत कम वार्षिक वर्षा वाले (100 से 300 मि.मी.) स्थान, वहाँ गर्मियों में 40 डिग्री सेन्टीग्रेड से भी अधिक व सर्दियों में 5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। खारे पानी को भी इसकी सिंचाई हेतु उपयुक्त पाया गया है। पथरीले, पल्लडी, ढलवा स्थान जहाँ वर्षा अधिक होती हो, वहाँ भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। इस विदेशी झाड़ी के फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं। अतः फल पकाव के समय पर सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिये। जलवायु की ऐसी परिस्थितियों को देखने से लगता है कि राजस्थान में इसकी खेती के लिए पर्याप्त सभावनाएँ हैं।

अन्य फसलों की तरह होहोवा के बीज की बुवाई सीधे जमीन में नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इससे अंकुरण बहुत कम होता है। साथ ही भूमि की ऊपरी सतह को हमेशा नम रखना पड़ता है। अतः पहले पौधशाला में इसकी पौध तैयार कर बाद में खेत में प्रतिरोपण किया जाना चाहिये।

राज्य में अभी होहोवा का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी मोटे तौर पर प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन से आमदनी का आकलन किया जा सकता है। खेत में 3x2 मीटर की दूरी पर पौधरोपण करने एवं अच्छे रख-रखाव से पाच वर्ष बाद प्रति पौधे में करीब 125 से 200 ग्राम बीज एवं दस वर्ष बाद प्रति पौधे से एक

किलोग्राम बीज प्राप्त होने लगता है। खेत में नर व मादा पौधों का अनुपात 1:4 रखने पर प्रति हेक्टेयर करीब (दस वर्ष बाद) 1080 किलोग्राम बीज की प्राप्ति हो सकती है। यदि न्यूनतम दर एक सौ रुपये प्रति किलोग्राम भी बेचा जाये तो प्रतिवर्ष एक हेक्टेयर में करीब 1,08,000 रुपये की आमदनी होती है जो अन्य फसलों की तुलना में ज्यादा लाभप्रद है। आठवीं योजना में इसकी खेती को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्य फसलें

Other Crops

(1) **मसाले (Spices)** राजस्थान में मसालों में संबंधित फसलों में मिर्च, अदरक, हल्दी धनिया, जीरा अजवाइन, सौंफ, मेथी आदि का उत्पादन किया जाता है।

राजस्थान में मिर्ची का सबसे ज्यादा (1994-95) जोधपुर जिले में होता है और तत्पश्चात् भीलवाड़ा व सर्वाई माधोपुर जिले आते हैं। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन (1994-95) उदयपुर में और तत्पश्चात् झुगरपुर जिले में होता है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन (1994-95) उदयपुर जिले में होता है। उसके पश्चात् क्रमशः भीलवाड़ा, बूंदी व झुगरपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे अधिक (1994-95) धनिया जालोर जिले में होता है। उसके पश्चात् झालावाड़ व कोटा जिलों का स्थान है। जीरे का सबसे अधिक उत्पादन (1994-95) जालोर जिले में और उसके पश्चात् नागौर जिले में होता है। लहसुन मुख्यतः चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा जिले में होता है। सौंफ का उत्पादन सिरोही व जोधपुर जिलों में होता है। मधी का उत्पादन 1994-95 में सर्वप्रथम सीकर और तत्पश्चात् चित्तौड़गढ़ झालावाड़ व जयपुर जिलों का स्थान है।

(2) **फल एवं सब्जियाँ (Fruits & Vegetables)** राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से केला और गगानगर जिले से अंगूर की खेती की जाती है। अमरूद की खेती अजमेर, बूंदी, गगानगर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में होती है। पपीते मुख्यतः अजमेर, बूंदी और उदयपुर जिलों में बोये जाते हैं। सब्जियाँ के अंतर्गत आलू मुख्यतः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, भीलपुर, गगानगर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, कोटा, पाली, सर्वाई माधोपुर, सिरोही आदि जिलों में होता है। आम मुख्यतः भरतपुर और गगानगर जिलों में होते हैं। इसका अतिरिक्त अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, बूंदी, जाधपुर जिलों में भी थोड़ा बहुत आम उत्पादित किया जाता है। मANGO राजस्थान में झालावाड़ जिले में उत्पन्न किये जाते हैं। इसी प्रकार, गौमभी व माल्टा गगानगर जिलों में होते हैं। नैजू क्रमशः भरतपुर, गगानगर और पाली जिलों में होता है। इसके अतिरिक्त,

अलवर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, झुगरपुर, जालोर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर, नागौर व सिरोही जिलों में भी नींबू का उत्पादन होता है।

(3) **मादक पदार्थ (Intoxicants)** - मादक पदार्थों में राजस्थान में मुख्यतः अफीम, सिंकोना, भाग-भाजा व तंबाकू का उत्पादन होता है। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले उनके महत्व के अनुसार क्रमशः चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा व भीलवाड़ा रहे हैं। सर्वाधिक तंबाकू अलवर जिले में उत्पादित की जाती है। तंबाकू का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। मादक द्रव्यों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जालोर और तत्पश्चात् बाड़मेर जिले का स्थान रहा है।

राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं MAJOR PROBLEMS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राज्य में कृषि की समस्याओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है।

(a) प्राकृतिक बाधाएँ (Natural constraints)

- 1 राजस्थान में वर्षा अत्यधिक अपर्याप्त और अनिश्चित प्रकृति की है।
- 2 राज्य का 61 प्रतिशत भाग मरुस्थलीय और अर्द्ध मरुस्थलीय है।
- 3 इस क्षेत्र की मिट्टी उत्पादकता की दृष्टि से कमजोर है। इस मिट्टी को जल ग्रहण क्षमता कम होती है और यह अपना स्थान बदलती रहती है।
- 4 वर्षा की कमी के कारण भूमिपर्व जल की उपलब्धता सीमित है।
- 5 उच्च तापमान और वायु की तीव्र गति फसलों को नुकसान पहुंचाती है।

(b) सामाजिक बाधाएँ (Social Constraints)

- 1 राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- 2 जोतों के उपविभाजन में वृद्धि हुई है। 1980-81 में जोतों की संख्या 44 87 लाख थी जो बढ़कर 1990-91 में 51 07 लाख हो गई।
- 3 माधुरता का स्तर (38%) विशेषतः महिला माधुरता (20%) कम है।
- 4 महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा कम है।
- 5 महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि कृषि कार्य

में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है।

■ जनसंख्या का अधिकांश भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (30%) से सम्बन्धित है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की जेबिंग उठाने की क्षमता कम होती है और ये लोग नवीन प्रौद्योगिकी को जल्दी नहीं समझ पाते हैं।

(c) शोध सम्बन्धी बाधाएँ (Research Constraints)

- 1 अकाल से लड़ने के उपयुक्त तरीकों का अभाव।
- 2 कृषि विधायन, बागवानी और चारा फ़सलों के विशेषज्ञ सीमित हैं।
- 3 फसल काटने के पर्याप्त कर्मियों की प्रबन्ध सम्बन्धी साहित्य और जानकारी सीमित मात्रा में उपलब्ध है।
- 4 बायो टेक्नोलॉजी और ट्रांशू कल्चर शोध सुविधाओं का अभाव है।
- 5 विभिन्न प्रकार की जलवायु में कृषि करने संबंधी जानकारी कम है।
- 6 ऑर्गेनिक फार्मिंग संबंधी शोध का निगान अभाव है।
- 7 अनेक फसलों के लिए समन्वित रोग प्रबन्ध का अभाव है।
- 8 जल की इकट्ठा करने वाले प्राचीन उपकरण जैसे - बूढ़-बूढ़ कृषि, फव्वारा सिंचई आदि के क्षेत्र में शोध का अभाव है।
- 9 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की व्यूह रचना का अभाव है।

(d) सरचनात्मक बाधाएँ (Research Constraints)

- 1 कृषि पर्याप्त संबंधी पुस्तक दुकानें अपर्याप्त (2450 व्यक्तियों पर एक) हैं।
- 2 वैज्ञानिक सुविधाओं (सितम्बर, 1993 तक एक लाख जनसंख्या पर 6.5 वैज्ञानिक) का अभाव है।
- 3 शक्ति की पूर्ति अपर्याप्त है।
- 4 कृषि विपणन और विधायन संरचना का अभाव है।
- 5 कृषि में यंत्रीकरण की गति धीमी है।
- 6 राजस्थान में सड़कों की लम्बाई प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध राष्ट्रीय औसत का 55 प्रतिशत है।
- 7 बागवानी और सब्जियों सम्बन्धी फसलों के विपणन की संरचना का अभाव है।
- 8 पशु चिकित्सकों की मांग और पूर्ति के मध्य अन्तर्गत बहुत अधिक है साथ ही पशु चिकित्सक अल्प हैं। इसमें पशु पालकों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(e) कृषक की अशिक्षा एवं अज्ञानता (Illiteracy & Lack of Knowledge) - यदि भारत के संदर्भ में राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान की कृषक अधिक

अशिक्षित प्रतीत होता है। इसी कारण राजस्थान में कृषि के अन्तर्गत नवीन विधियों का अधिक प्रयोग नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण कृषक साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। अशिक्षा के कारण ही राजस्थान में सहकारी आंदोलन अधिक गति प्राप्त नहीं कर पाया है। अशिक्षित कृषक अधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों के अशक्तों में शिकार हो जाते हैं। सामाजिक रीति-रिवाजों को निभाने के लिए उन्हें वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसमें कृषि विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस समस्या का समाधान कृषकों में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना है। इस क्रिया में ग्रौंड शिफ्ट का विरोध महत्व हो सकता है।

(f) अपर्याप्त वित्त एवं ऋणग्रस्तता (Lack of Finance & Indebtness) - राजस्थान का कृषक अशिक्षित होने के साथ-साथ निर्धन भी है। इस कारण वह अपने स्वयं के साधनों के कृषि विकास के लिए पर्याप्त वित्त नहीं जुटा पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समस्याओं का अभाव आज भी बना हुआ है। इस कारण उसे साहूकारों द्वारा ऊँची व्याज दरों पर ऋण पड़ता है। ये ऋण भी मुख्यतः अनुत्पादक ऋण होते हैं और इन अनुत्पादक ऋणों के कारण कृषक पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी इन ऋण का बोध बढ़ता चला जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढ़ता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अपना ऋण अनेक वाली पीढ़ी के लिए छेड़ जाता है। राजस्थान में कृषकों में असतोष का एक बड़ा कारण उनकी ऋणग्रस्तता है। डॉ. टॉमस ने ऋणग्रस्तता के संदर्भ में उपयुक्त ही कहा है, "ऋणग्रस्त समाज अनिवार्य रूप से एक सामाजिक ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के समाज में विभिन्न वर्गों में असंतोष उत्पन्न होना अनिवार्य है और भीतर हा भीतर बढ़ता हुआ असंतोष सदैव खतरनाक होता है।" विनाश साधनों की कमी के संदर्भ में सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख्त सर्वेक्षण समिति ने टोक ही कहा है कि "सहकारिता अमरुत है चूका है लेकिन सहकारिता मरुत हनी चाहिए।" ग्रामीण क्षेत्रों में देव शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा, आवश्यकता पड़ने पर अनुत्पादक ऋण भी प्रदान किए जाने चाहिए।

(g) सिंचाई साधनों की अपर्याप्तता (Lack of Irrigation Facilities) - राजस्थान में जल साधनों का अभाव है। नदियाँ कम हैं और लगभग सभी नदियाँ धानमूनी हैं। मानसून के अभाव में इनमें भी पानी नहीं रहता है। अनेक स्थानों पर भू-जल का स्तर बहुत नीचा होने के कारण भी कृषि कार्यों में उसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण जल के अभाव में राजस्थान में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत में कृषि

उत्पादन लगभग ॥ गुना बढ़ जाएगा। रेगिस्तानी भूमि में जल की और भी आवश्यकता होती है। अतः जल के अभाव में प्रायः ऐसे क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती है। सिंचाई साधनों के अभाव को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जल समझौते अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राजस्थान नहर ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास है।

(h) कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव (Lack of Cottage & Small Industries) - राजस्थान का कृषक सामान्यतः एक फसल लेता है और इस प्रकार वर्ष के लगभग 4 माह कार्य करता है। शेष अवधि में वह बेकार बैठ रहा है। ऐसा इसलिए है कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, "यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाए तो भारत ही नष्ट हो जाएगा। ग्रामीण उद्योगों का विनाश भारत के मात लाख ग्रामों को नष्ट कर देगा।" कुटीर व लघु उद्योग न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में श्रम-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि सरकारी एवं निजी प्रयासों से कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास हो। इस हेतु सरकार को आकर्षक औद्योगिक नीति बनाकर लोगों को इस ओर आकर्षित करना होगा।

(i) कृषि श्रमिकों की समस्याएँ (Problems of Agricultural Labour) - राजस्थान में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है। इनमें से भी बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। इस कारण वे दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। ये लोग कृषि कार्य में निपुण होते हुए भी अत्यन्त दीन-हीन स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं। इस कारण इनसे संबंधित समस्याओं के समाधान से ही कृषि का विकास संभव हो सकता है। कृषि सुधार समिति, 1950 ने कहा था "कृषि सुधार मन्त्री किसी योजना में में कृषि श्रमिकों की समस्या को छोड़ देना, देश की समस्या को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राजस्थान में दवार पड़ी भूमि की आर्थिक जोतों के अंतर्गत कृषि श्रमिकों में रात दिया जाना चाहिए।

(j) आदानों का बढ़ता मूल्य (Increasing Prices of Agricultural Inputs) - कृषि में काम आने वाले सभी साधनों का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले खाद, बीज और औजार आदि की कीमतें निरन्तर बढ़ी हैं। सरकारी प्रयासों के बावजूद भी यह प्रवृत्ति बनी हुई है। गमायनिक खाद के मूल्य में तेजा में वृद्धि होने के कारण उपागों की गति तीव्र नहीं हो पाई है। कृषि आदानों के बढ़ते मूल्यों के कारण एक ओर माधनों की लागत तो बढ़ गई है किन्तु दूसरी ओर उनकी दुर्लभा में कृषि उपजों का मूल्य नहीं

बढ़ पाया है। कृषि उपजों के मूल्यों में अनुपातिक वृद्धि न होने पाने के कारण कृषि को हानि बहन करनी पड़ती है। इस कारण कृषक प्रायः घाटे में रहते हैं। यह सरकार का दायित्व है कि वह साधनों की कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करे।

(k) अपर्याप्त भूमि सुधार (Lack of Sufficient Land Reforms) - राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक कानून बनाए हैं। इसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभी समस्याएँ हल हो गई हैं। वर्षों से खेती करते आ रहे किसान आज भी भूमिहीन किसानों की तरह खाते-दागे के अधिकारों से वंचित हैं। व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के कारण ही कृषकों में भूमि का वितरण अत्यन्त असमान है। भूमि का उप-विभाजन और उप-खण्डन अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ जेत का आकार छोटा छोटा चला जाता है और एक समय के बाद वह अनार्थिक जेत में बदल जाती है। ऐसी भूमि पर अनाद कृषि करना भी बंद कर दिया जाता है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि समस्याओं का व्यावहारिक हल निकाला जाना चाहिए और उन्हें वास्तव में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चकबन्दी के माध्यम में भी अनार्थिक जेतों को आर्थिक जेतों में बदला जा सकता है।

राजस्थान में कृषि की समस्याओं का समाधान

राजस्थान में कृषि की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं -

- 1 सतही एवं भूतलमयी जल स्तर में वृद्धि करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 2 क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- 3 भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।
- 4 कृषि जेतों के उप-विभाजन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून का निर्माण करके उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
- 5 कृषि कार्य में महिलाओं को योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए।
- 6 निर्धन, निष्पक्ष एवं पिछड़े वर्गों के कृषकों को कृषि की जीवनरक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रगण्य करना चाहिए।
- 7 कृषि विशेषज्ञों की सहायता में वृद्धि करने के लिए कृषि शिक्षा का तेजी से प्रसार किया जाना चाहिए।

- 8 कृषि सबभों माहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 9 कृषि शाख कर्कों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- 10 कृषि विकास के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 11 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 12 ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

- 13 कृषि कर्कों के लिए शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की जानी चाहिए।
- 14 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन एवं विधायन संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 15 ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
- 16 कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- 17 ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों का विस्तार किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 "राजस्थान में फसल प्रारूप" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Cropping Pattern in Rajasthan"
- 2 राजस्थान में भूमि उपयोग पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करें।
Give an analysis on the land use in Rajasthan
- 3 फसल प्रारूप से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by Cropping pattern
- 4 राजस्थान में फसल प्रारूप का वर्णन करें।
Explain the cropping pattern in Rajasthan
- 5 राजस्थान में भूमि उपयोग का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on the land utilisation in Rajasthan
- 6 राजस्थान में भूमि उपयोग की प्रवृत्तियाँ किन बातों की ओर संकेत करती हैं?
What are the indications from the land utilisation trends in Rajasthan
- 7 भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by land utilisation?
- 8 राजस्थान की प्रमुख राबी और खरीफ फसलें बताइए।
Name the principle Rabi and kharif crops of Rajasthan
- 9 राजस्थान किस फसल का मुख्य उत्पादक है?
Rajasthan is the chief producer of which crop?
- 10 राजस्थान की प्रमुख राबी और खरीफ फसलें बताइए।
Name the principle Rabi & Kharif crops of Rajasthan

निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में राजस्थान में कृषि विकास का समझा करें।
Review the agriculture development during plan period in Rajasthan
- 2 "राजस्थान में उन्नत की जान वाली प्रमुख राबी व अनाज फसलें" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Important Food and Non Food crops in Rajasthan"
- 3 राजस्थान में फसल चक्र प्रणाली का वर्णन करें और यह किस प्रकार फसलें की मात्रा एवं उत्पादन को बढ़ावा देती है।
What do you understand by cropping pattern in Rajasthan and discuss the production and area of major crops in Rajasthan

- 4 राजस्थान में भूमि उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the land utility in Rajasthan
- 5 राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याओं व बाधाओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान व सुझाव बताईए।
Discuss the problems and hindrance of agriculture development strategies in Rajasthan and suggest its remedies
- 6 राजस्थान में कृषि विकास छूट रचना की प्रमुख विशेषताएं बताईए तथा परम्परागत योजनाओं में राजस्थान के कृषि विकास का विवरण बताईए।
Describe the salient features of Agriculture development strategies in Rajasthan and discuss the agriculture development of Rajasthan in the Five years plans
- 7 "राजस्थान हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है।" समझाईए।
"Rajasthan is marching towards green revolution" Explain
- 8 राजस्थान में तिलहन पालेदारों में तिलहन विकास कार्यक्रम की प्रगति एवं उससे प्राप्त लाभ का मूल्यांकन कीजिए।
Assess the programme of oil seeds production and its impact on Rajasthan in last Five years

विश्वविद्यालय प्रश्न

(Questions of University Examinations)

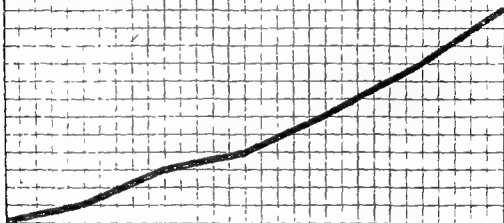
- 1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान स्पष्ट कीजिए। समझाईए कि राजस्थान हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है।
Describe the role of agriculture in the economy of Rajasthan Explain that Rajasthan is marching towards green revolution
- 2 राजस्थान में भूमि उपयोग, फसल पैटर्न (Cropping Pattern) एवं प्रमुख कृषि उपजों का उल्लेख करें।
Mention the land utilisation, cropping pattern and major agriculture products in Rajasthan
- 3 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान स्पष्ट कीजिए। समझाईए कि राजस्थान हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है।
Describe the role of agriculture in the economy of Rajasthan Explain the Rajasthan is marching towards green revolution
- 4 राज्य के कृषिगत विकास में बाधाएँ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Constraints in the agriculture development in the state"
- 5 राजस्थान में अपनायी गई कृषि छूट रचना की प्रगति एवं इससे उपलब्धियाँ का मूल्यांकन करें।
Discuss the Agriculture strategy as adopted in Rajasthan and evaluate its performance
- 6 राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याओं व बाधाओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान के सुझाव बताईए।
Discuss the problem and hindrances of agriculture development in Rajasthan and suggest its remedies
- 7 राजस्थान राज्य में कृषि की विशेषताएँ तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा उनसे हल करने के उपाय भी सुझाईए।
Discuss the salient features and problems of agricultural development in Rajasthan, also give some suggestions for agricultural development in Rajasthan



अध्याय - 9

राजस्थान में भूमि सुधार

LAND REFORMS IN RAJASTHAN



"राजस्थान का उल्लेख आधुनिक सभ्यता में मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहां की संस्कृति तिन्यु घाटी सभ्यता जैसे थी।"

अध्याय एक दृष्टि में

- भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य
- राजस्थान में भू-सुधारों की पृष्ठभूमि
- राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय के पूर्व प्रचलित भू-धारण प्रणालियाँ
- राजस्थान में भूमि सुधार के प्रयास एवं क्रियान्वयन
- भूमि सुधारों की प्रगति
- राजस्थान में भूमि सुधारों की संक्षेप, समस्याएँ व सुझाव
- राजस्थान सरकार की अधिनियम, 1955
- अभ्यास प्रश्न

भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य

MEANING & OBJECTS OF LAND REFORM

भूमि सुधार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भू-स्वामी कारखाने के अधिकार, कर्तव्यों एवं दायित्वों तथा राज्य व भू-स्वामी के संबंधों की विवेचना की जाती है। यह व्यवस्था भूमि के उपयोग एवं प्रबंध की वैज्ञानिक विधियों को जन्म देती है। इस प्रकार भूमि सुधारों का संबंध सत्तागत सुधारों में होता है। ये सुधार भू-स्वामी, कारखाने व सरकार के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। इन सुधारों से सामाजिक न्याय का बालावरण भी निर्मित होता है। भूमि सुधारों के द्वारा कृषि के ढांचे व संगठन में तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। भूमि सुधार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों एवं सुधारों के द्वारा एक नवोन भूमि व्यवस्था विकसित होती है जो पहले की तुलना में अधिक न्यायपूर्ण व कार्यकुशल होती है। अतः भूमि सुधारों में उत्पादन एवं आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। वह सामाजिक न्याय, समानता, एवं निर्धनता व शोषण के निवारण में भी सहयोग देते हैं। भूमि सुधारों के द्वारा कृषि विकास की वृद्धि तीव्र हो जाती है। राजस्थान में भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रहे हैं -

(1) उत्पादन वृद्धि (Increased Production) - कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कृषि के विकास में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि का विकास जुड़ा होता है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना हो तो कृषि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निवारण करना अत्यावश्यक होता है। भूमि सुधार व्यवस्था के अंतर्गत कृषि संबंधी विभिन्न समस्याओं एवं सरचनात्मक बाधाओं का निवारण करके कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सकती है। राजस्थान में कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भूमि सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(2) सामाजिक न्याय (Social Justice) स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में अनेक प्रकार की भू व्यवस्थाएँ एवं प्रणालियाँ प्रचलित थीं। इन व्यवस्थाओं के द्वारा कारतकार का सर्वाधिक शोषण किया जाता था। ये प्रणालियाँ मुख्यतः अंग्रेजी शासनकाल की देन रही हैं। राज्य में सामाजिक न्याय एवं समानता का वातावरण निर्मित करने के लिए इन दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करना आवश्यक था। स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य सरकार व भाग्य नरकर द्वारा दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करने हेतु अनेक नियम एवं अधिनियम लागू किये गये। इससे शोषण की समाप्ति एवं सामाजिक न्याय में वृद्धि हुई है।

(3) तकनीकी परिवर्तनों के आधार (Basis of Technical Changes) भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन नवीन तकनीकों को कुशलता पूर्वक लागू करने और इन तकनीकों में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि सुधारों के दौरान भूमि संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य में भूमि सुधारों को तेजी से लागू किया गया और उसके पश्चात् विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। अतः भूमि सुधारों को तकनीकी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण आधार कहा जाता है।

राजस्थान में भू- सुधारों की पृष्ठभूमि

BACK GROUND OF LAND REFORMS IN RAJASTHAN

सामान्य प्रथा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान में भूमि सुधारों को एक क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है। राजस्थान में शासन तंत्र बदलने पर भी इस प्रकार की

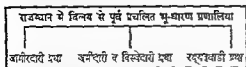
व्यवस्थाएँ जारी रहीं कि कृषक अपने भूमि का मालिक नहीं बन पाया। भूमि का स्वामित्व सदैव शासकों के पास ही रहा। और उन्होंने कृषकों को केवल जीवनयापन करने के उद्देश्य से भूमि प्रदान की ताकि वह अपने जीवनयापन के साथ अपने मालिकों को पर्याप्त लाभ प्रदान कर सकें। स्वतंत्रता के बाद भी यह स्थिति तुरन्त नहीं बदली। राजस्थान में जिन शासकों ने भूमि को अपने आधिपत्य में कर रखा था। उन्होंने अपने सहायकों को जागीरें प्रदान कीं। महायकों की सहायता करने वाले को भी भूमि प्रदान की गई ताकि वे अपने जीवनयापन के साथ अपने स्वामी की भी सेवा व रक्षा कर सकें। राजस्थान में भूमि सुधार लागू होने तक संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन्हीं शासकों, जागीरदारों आदि के द्वारा निर्देशित होती थी और उनके आदेश ही कानून बन चुके थे। राजस्थान में अनेक रियासतें थीं। इस कारण प्रत्येक रियासत के अपने नियम थे जिससे भूमि से संबंधित कानून एक रूप न होकर भिन्नता के कारण अत्यन्त जटिल हो चुके थे। सारी भूमि पर शासकों का स्वामित्व था, किसान का तो केवल पट्टे पर भूमि दी जाती थी और उसके बदले में उसकी उपज का अधिकांश भाग ले लिया जाता था। अनेक स्थानों पर किसानों को कुछ छातेदारी अधिकार भी मिले हुये थे। इनके अंतर्गत उन्हें वारिसाना अधिकार तो प्राप्त था किन्तु वे भूमि को दूसरों को हस्तारित नहीं कर सकते थे। भूमि का स्वामित्व संबंधित शासक का ही होता था। भू स्वामियों तथा कृषकों में मालिक व नौकर का संबंध होता था और मालिक कारतकार को जब चाहे, भूमि से बेदखल कर सकता था। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार की विचारधारा ने जन्म लिया कि भूमि जोतने वाले को भूमि का अधिकार मिलना ही चाहिये। साथ ही भूमि का वितरण समान हो और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित हो तथा विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रचलित कानूनों को बदलकर संपूर्ण राज्य में एकरूपता लाई जानी चाहिये।

राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय के पूर्व प्रचलित भू-धारण प्रणालियाँ

LAND TENURIAL SYSTEM OF RAJASTHAN BEFORE MERGER OF VARIOUS STATES

स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान राज्य में अनेक रियासतें थीं। वर्तमान राजस्थान में विलय से पूर्व इन रियासतों के

शासकों ने अपनी-अपनी रियासतों की भूमि को जमींदारों, जागीरदारों व बिस्वेदारों को दे रख था। ये व्यक्ति क़ाश्तकारों से लगान वसूल करने का कार्य करते थे उस समय राज्य में निम्नलिखित भू-धारण प्रणालियाँ प्रचलित थी -



(1) जागीरदारों द्वारा (Jagirdari system) - राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय से पूर्व जागीरदारों द्वारा राज्य के अधिकतर भागों में प्रचलित थी। जागीरदारों को भू-सूतों के अधिकार प्राप्त थे। वस्तुतः जागीरदार क़ाश्तकार व शसक के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा था। वह व्यक्ति क़ाश्तकार से उसकी उपज का एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में वसूल कर लेता था। इसके अतिरिक्त, बेगार आदि के रूप में क़ाश्तकारों का शोषण करता था। जागीरदार को बेदखली का अधिकार भी प्राप्त था। वह अपने क्षेत्र में क़ाश्तकारों को भूमि से बेदखल कर सकता था। जागीरदारों को भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन वे फौजदारी व दौवानी अधिकार तथा उम क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के कारण क़ाश्तकारों व कृषि-श्रमिकों पर अनेक अन्याय करते थे। जागीरदार, क़ाश्तकारों के सम्मुख अपने आपको भू-स्वामी के रूप में प्रकट करता था। जागीरदार द्वारा शासक को कुछ भेंट प्रदान की जाती थी लेकिन इस भेंट का भू-राजस्व से कोई संबंध नहीं था। भेंट की राशि का निर्धारण जागीरदारों प्राप्त होते समय किया जाता था। धीरे-धीरे जागीरों की आय में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती थी जबकि भेंट की राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था अतः लगान वसूली में जागीरदार प्रायः मनमानी किया करते थे। राज्य की अनेक रियासतों में उपज के अंश के रूप में लगान वसूल किया जाता था। जागीरदार प्रायः उपज का आधे से अधिक भाग लगान के रूप में प्राप्त कर लेता था। क़ाश्तकारों द्वारा इस व्यवस्था का समय-समय पर विरोध भी किया जाता था। लेकिन अधिकांश क़ाश्तकारों को तलाशनीय भूमि नियमों की जानकारी नहीं होती थी। क़ाश्तकारों में सैद्धिच क़ाश्तकारों की संख्या अधिक थी। भूमि का आवंटन प्रायः उन क़ाश्तकारों को कर दिया जाता था जो सबसे अधिक लगान देने के लिए तैयार थे।

(2) जमींदारी व बिस्वेदारों द्वारा (Jaminidan & Biswedari System) - राज्य के कुछ भागों में जमींदारों व बिस्वेदारों द्वारा प्रचलित थी। इन प्रणालियों के अन्तर्गत जमींदार अथवा बिस्वेदार क़ाश्तकारों से भू-सूत वसूल करने का कार्य करते थे। जमींदार अथवा बिस्वेदार शासकों को

प्रायः निर्धारित भू-राजस्व का भुगतान करते थे लेकिन क़ाश्तकारों से प्राप्त किये जाने वाले लगान की राशि का निर्धारण नहीं होता था। अतः ये व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार लगान वसूल करते थे। इस भू-व्यवस्था के कारण जमींदारों व बिस्वेदारों को क़ाश्तकारों के शोषण का अवसर मिल जाता था। ये व्यक्ति प्रायः कृषकों से उनकी उपज का लगभग आधे से अधिक भाग लगान के रूप में प्राप्त कर लेते थे। यदि कोई क़ाश्तकार इनका विरोध करता था तो उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। वह प्रथा राज्य के अलवर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, सौरा, कोटा व बग़लपुर जिलों में प्रचलित थी।

(3) रायतवाड़ी प्रथा (Raiyatwari System) - इस व्यवस्था के अन्तर्गत क़ाश्तकार अपने इच्छा के अनुसार लगान वसूल करता था। वह क़ाश्तकार को कभी भी भूमि से बेदखल कर सकता था।

राजस्थान में भूमि सुधार के प्रयास एवं क्रियान्वयन

STEPS FOR LAND REFORMS & THEIR IMPLEMENTATION IN RAJASTHAN

राजस्थान के निर्माण के समय अनेक दायपूर्य भू-व्यवस्थाएँ प्रचलित थी। राज्य में कृषि के विकास हेतु इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक था। अतः स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठये गये हैं। यह क्रम प्राथमिकताओं में परिवर्तन के साथ साथ आज भी जारी है। राजस्थान में भूमि सुधारों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं -

(1) भूमि पर किसानों की बेदखली को रोकना (Stoppage interfere of farmers on land) 1949 में जमींदारों द्वारा क़ाश्तकारों को भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया तोड़ दी गई थी। अतः सरकार द्वारा क़ाश्तकारों को बेदखली रोकने के लिए 'राजस्थान (क़ाश्तकार संरक्षण) अध्यादेश 1949' पारित किया गया। यह भूमि सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास था। इसका उद्देश्य किसानों को किन्हीं भी रूप में-मिली हुई भूमि से बेदखल होने से रोकना था। इसमें कहा गया कि जब तक यह अध्यादेश लागू रहेगा क़ाश्तकारों को उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इन अध्यादेश के अनुसार अवैधनिक ढंग से बेदखल किये गये किसानों को भू-स्वामी के अधिकार पुनः प्रदान कर दिये गये। राजस्थान क़ाश्तकारी अधिनियम 1955 में भी उक्त

अध्यादेश सबधी प्रमुख व्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित कर लिया गया।

(2) लगान का निर्धारण (Determination of Rent) पुरानी व्यवस्थाओं के अतर्गत मनमाने ढंग से बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता था। अतः काश्तकारों को शोषण में बचाने तथा राज्य के सभी क्षेत्रों में लगान वसूली में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम 1951' पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कृषकों से वसूल किया गया लगान उनकी कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक नहीं हो सकता था। 1952 में राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम 1952 पास किया गया। इस अधिनियम के अतर्गत एक जेत पर अधिकतम लगान की मात्रा भू राजस्व व दुगने तक निश्चित की गई। इस अधिनियम को रद्द करके 1954 में एक नया अधिनियम 'राजस्थान कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम, 1954' पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार मध्यम्यों द्वारा भातगुजारी के दुगने से अधिक की लगान वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्थान बज्रतकारी अधिनियम, 1955 में काश्तकारों को लगान की वसूली में होने वाले शोषण से मुक्त करवाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गईं।

(3) मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Mediators) राजस्थान सरकार ने मध्यस्थों की समाप्ति हेतु निम्नलिखित प्रयास किये -

(i) जागीदारी प्रथा का अंत (Abolition of Jagirdari System) - राजस्थान सरकार ने कृषकों और सरकार के मध्य से मध्यस्थों को हटाने के लिए 'राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन अधिनियम 1952' पारित किया। इस अधिकांश के अनुसार जमींदारों के पास भी केवल वही भूमि छोड़ी गई जो उनकी निजी काश्त के अतर्गत थी। बाकी भूमि इस अधिनियम के कारण सरकार की हो गई। राजस्थान में 'जागीरदारों को विलय के लिए पूर्ण तैयार करने का श्रेय तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल को जाता है। जागीरदारी समाप्त करने के लिए राजस्थान सरकार को जागीरों की आय निर्धारित करनी पड़ी तथा आय के कुल गुणा तक राशि मुआवजे के रूप में भी देनी पड़ी। उन्हें प्रत्येक प्रकार की गणशानि से बचाने की कोशिश की गई और खुदकाशत जमीन कम होने पर जागीरदारों को बर्बाद जमीन देकर उनका पुनर्वास करने की कोशिश की गई। समस्त कार्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए भू प्रश्न विभाग की स्थापना की गई। जागीरदारों के मुआवजे की राशि फिरतों में दी गई और

वकाया राशि पर ब्याज भी देना पड़ा। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को नकद ब्याज व बॉण्ड्स के रूप में लगभग 30 करोड़ रुपये देने पड़े। साथ ही उस समय के जागीरदारों के अतर्गत कार्य कर रहे लोगों की पैशन बांधी गई और उपयुक्त लोगों को सरकार की सेवा में लिया गया। इस अधिनियम के लागू हो जाने पर खुदकाशत के अतिरिक्त बची भूमि पर सरकार का कब्जा हो गया। इस अधिनियम के समय जो व्यक्ति भूमि पर खेती कर रहे थे उन्हें खानेदारी के अधिकार मिल गये।

(ii) जमींदारी व विस्वेदारी प्रथाओं का अंत (Abolition of Zamindari & Biswedari System) राजस्थान के लगभग 77 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में 299 लाख जागीरें और 383 लाख विस्वेदारियाँ विद्यमान थीं। इन व्यवस्थाओं के उन्मूलन हेतु 'राजस्थान जमींदारी व विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959' पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार व काश्तकारों के मध्य विगौलियों का क़त्त करने वाले जागीरदार व विस्वेदार अधिभारी विहीन हो गये और कृषकों व राज्य सरकार का सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया। जागीर समाप्त हो जाने के बाद भी राज्य में सामंती व्यवस्था एकदम समाप्त नहीं हुई थी। इन लोगों ने बड़ी बड़ी भूमि अपने अधिकार में ले ली थी और इस पर वे खुदकाशत नहीं करते थे वरन् छोटे किसानों से काश्त कराते थे तथा उनकी उपज में से अपना हिस्सा ले लेते थे। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मध्यम्यों से बची हुई कटौती को समाप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान भूमि सुधार एवं भू स्वामियों की सम्पदा अवधि अधिनियम 1963' पारित किया। इस कानून के अतर्गत ग़ज़ा महानगरों की भूमि पर आवास कर लिया गया एवं काश्तकार द्वारा जोती जाने वाली भूमि पर श्वेत सन्निहित काश्तकार को खानेदारी अधिकार मिल गये। इस प्रकार मध्यम्यों की अंतिम कड़ी भी समाप्त हो गई।

(4) खानेदारी अधिकार - 'राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन अधिनियम 1962' व अतर्गत अधिनियम के प्रभाव होने की तिथि में भूमि पर काश्त करने वाले लोगों को खानेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे किन्तु ऐसा सभी काश्तकारों के मध्य में नहीं हुआ क्योंकि कुछ श्रेणियों व काश्तकारों को यह अधिकार मिले थे। इस कारण राजस्थान के सभी काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने और राजस्थान में भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण करने के लिए 'राजस्थान काश्तकारों अधिनियम, 1955' व माध्यम से मूलभूत परिवर्तन किये गये। इसके अतर्गत सभी काश्तकारों

को खातेदारी अधिनियम प्राप्त हो गये। इस प्रकार इन्हें वारिसाना और मालिकाना हक तो मिला ही, भूमि के हस्तांतरण का अधिकार भी मिल गया। जो व्यक्ति भूमि का गैर खातेदार होता है उसे अपने जेत पर केवल पैतृक अधिकार प्राप्त होता है। 'राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970' के अंतर्गत कृषक को भूमि गैर कारशतकारी अधिकार देकर आरंभित की जाती है और जो कृषक आवंटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं करते उन्हें 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खातेदारी के अधिकार दे दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान कृषककारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत किराये पर भूमि जोतने में सहायित प्रतिबन्ध लगाये गए लेकिन सैनिकों, विधवाओं, अपाहिषों अल्प वयस्कों आदि को कुछ छूट दी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था भी की गई कि किसान अपनी भूमि के कुछ भाग पर कृषि के विकास के लिए व अपनी सुविधा हेतु कुछ निर्माण कार्य कर सके। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के व्यक्तियों को जमीनें अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित न हो पाए, इस बात की व्यवस्था की गई। अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार से भूमि हस्तान्तरित करने को अवैध बनाकर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। यदि इसके बाद भी भूमि हस्तान्तरित की जाती है तो खरीददारों को बेदखल किया जा सकता है। इसके संबंधित प्रावधानों में हाल में ही कुछ परिवर्तन किये गये। इसी प्रकार लोगों को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान कृषककारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके भूमि को रहन आदि रखने की अवधि 10 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दी है। अब कृषककारी की भूमि को 5 वर्ष से अधिक रहन नहीं रखा जा सकता। 5 वर्ष पूरे होने पर भूमि रहन से मुक्त माना जायेगी और यदि कोई ऐसी मुक्त भूमि को वापस नहीं लाया तो उसे दण्ड या कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं। यह भी व्यवस्था की गई कि जिस भूमि को रहन रखने की अवधि खत्म हो चुकी है उस भूमि को पुनः दो वर्ष तक रहन नहीं रखा जा सकता है। इस अधिनियम में कारशतकारी की भूमि की अदलाबदली और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु जोन में सुधार करने के अधिकार भी दिये गये। जमीन केवल जमीन जोतने वाले व्यक्तियों के पास ही रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुये खातेदार कारशतकारी को एक बार में अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए अपनी जमीन मब लोज पर देने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार गैर खातेदार कारशतकारी को अपनी जेत की भूमि को केवल एक वर्ष तक के लिए मब लोज पर देने का अधिकार दिया। इस बात को भी व्यवस्था की गई कि एक बार लोज देने के पश्चात् दो वर्ष तक वह भूमि पुनः लोज पर नहीं दी जा सकती।

(5) कृषि व अकृषि भूमि के अन्य उपयोगों की छूट - कृषकों, बेरोजगारों युवकों व कारीगरों को आवास सुविधा देने एवं छोटे उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से ही 'कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1971' एवं 'कृषि भूमि व अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग अधिनियम, 1961' बनाये गये। इन नियमों के अनुसार किसान अपनी भूमि आवास तथा छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए परिवर्तित कर सकता है। पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के लिए किसानों की जेतों पर लगाये गये पेड़ों को काटने पर 'राजस्थान कृषककारी अधिनियम, 1955' में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये। इन प्रतिबन्धों के अनुसार- कृषक एक कलेंडर वर्ष में उसकी भूमि पर लगे हुये वृक्षों के 10 प्रतिशत से अधिक वृक्ष नहीं काट सकता है। राजकीय नजर भूमि, अनुसूचाऊ व अकृषि भूमि पर वन विकास योजना के अंतर्गत निजी वन विकास हेतु वज्र भूमि का आवंटन नियम, 1986' बनाया गया। इन नियमों के अनुसार भूमि के आवंटन में ग्रामीण निर्धनों, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों, सहकारी समितियों व अर्द्ध-कारकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देने हेतु कारशतकारी अधिनियम में कुछ प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुसार, सड़क के किनारे लगाए गये पेड़ों व उनकी उपज पर किसानों को मालिकाना हक दिया जाता है।

(6) चकबंदी - कृषकों के खेतों की अनार्षिक जोत एवं उनकी जेतों का विखंडन, कृषि भूमि को एक महत्वपूर्ण बाधा थी। इस बाधा को चकबंदी अधिनियम लागू करके दूर करने की कोशिश की गई। इसके माध्यम से दूर-दूर विखरे हुये तथा छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों की समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया गया। इससे कृषि में नवीन विधियों को प्रोत्साहन मिला और कृषि विकास को गति तीव्र हुई। 1982-83 तक लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि चकबंदी के अंतर्गत आ चुकी थी।

(7) भूमि की अधिकतम सीमा - भूमि सुधार के अंतर्गत राजस्थान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कृषि भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है। इस अधिकतम सीमा के पश्चात् अधिग्रहण योग्य भूमि को भूमिहीनों में बांट दिया जाता है। इस हेतु 'राजस्थान कारशतकारी अधिनियम, 1955' के अंतर्गत 1963 में संशोधन किया गया। भूमि की उर्वर शक्ति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग सीमा निर्धारित की गई। इस प्रावधान को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1973 में एक नया संशोधन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार

परिवार की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। पुराने काश्तकारी अधिनियम में परिवार से आशय एक ऐसे परिवार से था जिसमें पति, पत्नी, उनके बच्चे और उन पर निर्भर पौत्र, पौत्रिया तथा पति की विधवा मा, जो उन पर अश्रित हो, को सम्मिलित किया जाता था। 1973 के अधिनियम के अनुसार अब 'परिवार' से आशय पति-पत्नी व अवयस्क सत्तारों (गदालिंग विवहित पुत्रों को सम्मिलित न करते हुये) में है। पिछले कानून की तुलना में अब परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई है, जिससे राज्य सरकार द्वारा सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत कृषिभूमि का अधिग्रहण करना संभव हो सका है। अधिग्रहण की गई भूमि को भूमिहीन कृषकों, भूतपूर्व सैनिकों, कमजोर वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों व ग्रामीणों में आवंटन हेतु 'राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970' बनाया गया।

राजस्थान में भूमि सुधार संबंधी महत्वपूर्ण नियम व अधिनियम

- 1 राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्स) अध्यादेश 1949
- 2 राजस्थान भूमि सुधार एवं जमीन पुनर्गठन अधिनियम 1952
- 3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
- 4 राजस्थान जमींदारी व बिस्वदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959
- 5 1963 का 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' में संशोधन
- 6 सीलिंग अधिनियम, 1973
- 7 राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि का आवंटन नियम, 1970
- 8 कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1971
- 9 कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नियम, 1961
- 10 निजी वन विकास हेतु नजर भूमि का आवंटन नियम, 1986

राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम' में 1966 में संशोधन करके राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में सीलिंग कानून क्रियान्वित कर दिया। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अर्थदण्ड व भूमि से बेदखली का प्रावधान किया गया। नये सीलिंग कानून के अंतर्गत व्यक्ति अपने वयस्क पुत्र के लिए भी अपनी भूमि में से निर्धारित सीमा तक भूमि का चुनाव कर सकता है। राजस्थान सीलिंग कानून के अंतर्गत जो भूमि अधिग्रहण की गई है वह अधिकारशत छटियाँ किस्म की है। अतः जिन लोगों को ऐसी भूमि आवंटित की जाती है, उन्हें भूमि के विकास के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। 30 सितम्बर, 1986 तक इस अधिनियम के अंतर्गत

86,156 मामले निपटारे किये और 5 95,874 एकड़ भूमि को अधिग्रहण योग्य माना गया। वस्में में 5,40,149 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके लगभग सवा चार लाख एकड़ भूमि को आवंटित भी कर दिया गया। इस आवंटन में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को प्राथमिकता दी गई।

(8) पास बुक अधिनियम खातेदारों द्वारा खुदकाशत की भूमि, भूमि सीमा तथा लगान के लिए 'राजस्थान पासबुक अधिनियम, 1983' पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसानों को उनकी भूमि के संबंध में मपूर्ण जानकारी के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। इससे कृषकों को अपनी भूमि का विकास करने हेतु वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से ऋण लेने में सुविधा हो गई है। इस प्रकार अब कृषकों को भूमि संबंधी रिकार्ड प्राप्त करने की एक लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई है। कृषकों के भूमि-अभिलेखों को सही रखने के लिए राजस्व अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन अभियानों में कृषकों द्वारा किये गये भूमि के हस्तांतरणों व विरासत आदि के परिवर्तनों को उसकी पास बुक में अंकित किया जाता है।

(9) राजस्व प्रबंध व्यवस्था का आधुनिकीकरण (Modernization of Revenue Administration) - रेवेन्यू बोर्ड जिला प्रशासन की प्रमुख संस्था होती है। राज्य में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में भगेत समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति ने क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को सिद्धान्त स्वीकार करके नवी योजना में राजस्व प्रबन्ध को सुदृढ़ करने के लिए 1294 78 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया है।

(10) राजस्थान राजस्व शोध प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (Rajasthan Revenue Research Training Institute, Ajmer - RRTI) - इस संस्था की स्थापना मार्च 1996 में प्रशिक्षण संस्थाओं की एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई। यह संस्था टोंक, गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर) डेवारी, उदयपुर, अलवर, कोटा और जोधपुर की राजस्व शोध प्रशिक्षण संस्थाओं को नियंत्रित करेगी। नवी योजना में इस संस्था के निर्माण हेतु 412 लाख रुपये कम करने का प्रावधान किया गया है। इससे राजस्व प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

भूमि सुधारों की प्रगति

भूमि सुधार कानूनों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य भूमि का समान वितरण करना है क्योंकि ग्रामीण

पूर्ति हेतु भूमि सुधारों में 30 जून, 1997 तक निम्न प्राप्ति हुई है -

भूमि के मूल्यों में वृद्धि तथा भूमि का अधिकतम

अधिक्य घोषित क्षेत्र	608163 एकड़
अधिशिष्ट क्षेत्र	565432 एकड़
विशेष क्षेत्र	454961 एकड़
सभी उद्योग वालों की संख्या	79009

उपयोग करने के लिए उपग्रह क्रियाओं का महत्व बढ़ा है। राज्य के प्रत्येक तहसील में 20 वर्ष पश्चात् उपग्रह क्रियाओं की आवश्यकता होती है लेकिन राज्य में उपग्रह संसाधनों का अभाव होने के कारण 107 तहसीलों का उपग्रह सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। वर्तमान में 14 उपग्रह दल क्रमशः जयपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, कोटा, भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा, सिरोंही और झुणपुर मुख्यालय से कार्यरत हैं। शेष उपग्रह कार्यों को पूर्ण करने के लिए 4 उपग्रह दल बनाये जायेंगे जिनके मुख्यालय बाड़मेर, नागौर, विनाडगढ़, और पाली होंगे। नवीं पंचवर्षीय योजना में उपग्रह कार्यों पर 988 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में भूमि सुधारों की समीक्षा, समस्याएं एवं सुझाव

EVALUATION OF LAND REFORMS IN RAJASTHAN, PROBLEMS & SUGGESTIONS

राजस्थान में भूमि सुधार हेतु राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय प्रयास किये हैं इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में जमींदारी, जागीरदारी एवं कस्बेदारी प्रथाओं का उन्मूलन हो चुका है। भू-धारण की सुलझ व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। लागत वसूली संबंधी दोषों एवं समस्याओं का निवारण हो चुका है लेकिन फिर भी बदती हुई परिस्थितियों के कारण अनेक नवीन समस्याएं एवं दोष उत्पन्न हो गये हैं। कृषि के समुचित विकास हेतु भूमि सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत इन दोषों एवं समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत राजस्थान में भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती है -

(1) काश्तकारों की स्थिति में सुधार Improvement in tenant's condition - स्वतंत्रता से पूर्व कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न प्रथाओं व रीतियों के कारण कृषक समुदाय का अत्यधिक शोषण होता था। राज्य सरकार ने विभिन्न

अधिनियम पारित करके कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया लेकिन इन अधिनियमों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण आज भी कृषक वर्ग के शोषण की प्रक्रिया जारी है। उपकाश्तकारों के सवध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, प्रमुख काश्तकार आज भी उपकाश्तकारों का जमींदारों व जागीरदारों के समान शोषण करते हैं। प्रमुख काश्तकार आज भी ऊँची लगान वसूल करता है और कभी भी उपकाश्तकार को भूमि में वेदखल कर सक्र है। अतः इस समस्या के निवारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये और काश्तकार को सही अर्थ में भूमि का स्वामी बनने का अवसर देना चाहिये। राज्य में फसल बटाई प्रथा आज भी प्रचलित है। राज्य सरकार के पास अनेक महत्वपूर्ण आकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उदाहरण के लिए, मध्यस्थों के पास कितनी भूमि है, कितनी भूमि पर काश्तकारों ने छातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं आदि। वस्तुतः भूमि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण इसी प्रक्रिया में निहित है। इस दृष्टि को ध्यान रखते हुये राज्य सरकार को चाहिये कि भूमि सुधार संबंधी विभिन्न समस्याओं का निवारण करे। ऐसा करके ही राज्य सरकार कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक न्याय में वृद्धि कर सकेगी

(2) राजस्व में वृद्धि Increase in Revenue - भूमि सुधार संबंधी प्राचीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भू-राजस्व का अधिकतम भाग मध्यस्थों को प्राप्त होता था अतः भूमि की इस आय का समुचित उपयोग नहीं हो सका। यह धन मध्यस्थों द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग कर लिया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् नवीन व्यवस्थाओं के अनुसार राजस्व की प्राप्ति, राज्य की आय का अंग है। भू-राजस्व से सरकार को पर्याप्त आय की प्राप्ति होती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों, विशेषतः छोटे कृषकों व छोटे-मझहूतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अतः सरकार भू-राजस्व संबंधी आय का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, विशेषतः कृषि विकास हेतु कर सकती है। विगत कुछ वर्षों के आर्थिक योजनाओं संबंधी कृत्यों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार भू-राजस्व का उपयोग कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कर रही है। राज्य सरकार को इस तथ्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भू-राजस्व की राशि को व्यय करने के कारण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में कितनी वृद्धि हुई है।

(3) जागीरदारों की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव Impact on Economic activities of Jagirdars - स्वतंत्रता के पूर्व भू-राजस्व जागीरदारों की आय का प्रमुख साधन था।

भूमि सुधार प्रक्रिया के अतर्गत जागीरदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया। इससे जागीरदारों का आर्थिक जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। अनेक जागीरदार पहले से ही ऋणी थे। अतः जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् वे और अधिक ऋणी हो गये। वे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं पर अत्यधिक व्यय करते थे। जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के पश्चात् भी उन्होंने अपने खर्चों में मितव्ययता नहीं बरती। अतः इनके ऋणों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रही। कुछ जागीरदारों ने कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया। अतः उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ जागीरदार व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सफल हो गये। उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में ठीक हो गई लेकिन कुछ जागीरदारों का ऋण प्रवृत्ति के कारण नैतिक व मानसिक दृष्टि से पतन हो गया। राज्य के कुछ क्षेत्रों में सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले जागीरदारों अथवा उनके वंशजों का आज भी प्रभुत्व बना हुआ है। कुछ जागीरदारों ने राजनीति में भाग लेना आरंभ कर दिया। अतः वे आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पहले की तुलना में अधिक सशक्त हो गये। ऐसे अनेक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कृषकों का अनेक तरीकों से शोषण करते हैं। व्यापक सर्वेक्षण करके इनकी दोषपूर्ण क्रियाओं पर प्रभावशाली दम से नियंत्रण स्थापित करना चाहिये। ऐसा करके ही कृषकों को पुरानी जागीरदारी व्यवस्था के चंगुल से पूर्णतः मुक्त किया जा सकता है।

(4) भूमि का असंतोषजनक वितरण Unsatisfactory Distribution of land स्वतंत्रता के पूर्व जमींदार एवं जागीरदार स्वयं को भूमि का मालिक मानते थे। भूमि सुधार कानूनों के अतर्गत क़ाशतकारों को ख़ातेदारी अधिकार मिल

गये। अतः वैधानिक दृष्टि से क़ाशतकार भूमि के मालिक बन गये। जागीरदारों एवं जमींदारों ने इस नवीन व्यवस्था का अत्यधिक विरोध किया और इसके विरुद्ध उन्होंने न्यायालय में शरण ली। अतः लंबे समय तक भूमि सुधारों को कानूनी बाधाओं के कारण लागू नहीं किया जा सका। इस अवधि में जमींदारों व जागीरदारों ने अपनी अधिकांश भूमि बेच दी उपहार में दे दी अथवा अन्य तरीकों से भूमि का हस्तान्तरण कर दिया। भूमि सुधार कानून लागू होने के पश्चात् भूमि उपजाऊ उन्होंने अपने पास रखी और शेष बचर एवं कृषि योग्य भूमि सरकार को प्राप्त हुई। इस प्रकार भूमि सुधारों के अतर्गत क़ायें गये भू वितरण से विभिन्न वर्गों में असंतोष बढ़ा। जमींदारों व जागीरदारों ने प्रत्येक स्थिति में लाभ उठाने का प्रयास किया। अतः भू वितरण से क़ाशतकारों में असंतोष की भावना बढ़ गई। वर्तमान कानूनों के अतर्गत अन्य वर्गों व्यपारियों अधिकारियों राजनीतिज्ञों आदि को भी खुदक़ाशत के लिए भूमि का अधिकार प्रदान करती है। यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये और भू स्वामित्व का अधिकार वास्तविक कृषकों को ही दिया जाना चाहिये। वास्तविक कृषक से आशय उस व्यक्ति से होता है जो स्वयं खेत जोता है और प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य करता है। भूमि सुधार कानूनों के अतर्गत वितरित की गई भूमि का पुनः एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और विभिन्न अनिवार्यताओं एवं समस्याओं का नियमों के अनुसार निवारण किया जाना चाहिये।

(5) क्रियाशील भूमि ज़ेत (Operational Holding)- राजस्थान में कार्यशील जेतों का वितरण अत्यधिक असमान है। इस तथ्य की जानकारी निम्नलिखित तालिका से होती है

क्रियाशील भूमि ज़ेत						
विवरण	सीमान्त (1.1 हेक्टेयर से कम)	लघु (1 से 2 हेक्टेयर)	अर्द्ध मध्यम (2 से 4 हेक्टेयर)	मध्यम (4 से 10 हेक्टेयर)	बृहत् (10 हेक्टेयर से ऊपर)	योग (हेक्टेयर)
1980-81						
जोतों की संख्या (हज़ार में)	1317	877	917	894	489	4487
क्रियाशील क्षेत्र (हज़ार हेक्टेयर में)	633	1270	2620	5524	5884	10932
औसत आकार (हेक्टेयर में)	0.48	1.45	2.86	6.24	20.18	4.44
1985-86						
जोतों की संख्या (हज़ार में)	1357	920	978	986	500	4742
क्रियाशील क्षेत्र (हज़ार हेक्टेयर में)	641	1325	2791	6152	6679	20589
औसत आकार (हेक्टेयर में)	0.47	1.44	2.85	6.24	19.34	4.34
1990-91						
जोतों की संख्या (हज़ार में)	1517	1019	1067	1017	493	5107
क्रियाशील क्षेत्र (हज़ार हेक्टेयर में)	725	1469	3021	6334	9422	20971
औसत आकार (हेक्टेयर में)	0.48	1.44	2.85	6.23	19.13	

* Eighth Five Year Plan 1983-87 Govt. of Rajasthan & Draft Ninth Five Year Plan 1991-2002, Govt. of Rajasthan
— Vital Agriculture Statistics, 1994 E1 Rajasthan

तात्त्विक के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि

- 1 राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण असमान है।
- 2 1980-81 में 1985-86 के मध्य 1 हेक्टेयर से कम की जोतों की संख्या में 3.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में कृषिशील क्षेत्र में 1.31 प्रतिशत की वृद्धि हो गई लेकिन जोतों के औसत आकार में 2.08 प्रतिशत की कमी हो गई। 1991 में कृषिशील क्षेत्र में वृद्धि हुई।
- 3 1-2, 2-4 व 4-10 हेक्टेयर तक की जोतों की संख्या व कार्यशील क्षेत्रफल में वृद्धि हुई लेकिन जोतों का औसत आकार नहीं बढ़ा।
- 4 10 हेक्टेयर से अधिक की जोतों की संख्या लगभग स्थिर रही लेकिन कृषिशील क्षेत्र तथा औसत आकार में कमी हुई।
- 5 1980-81 व 1990-91 के मध्य जोतों की संख्या व कृषिशील क्षेत्र में प्रायः वृद्धि हुई लेकिन जोतों का औसत आकार कम हो गया।
- 6 फसल बटाई प्रथा द्वारा शोषण (Exploitation by Crop Sharing System) - राजस्थान में पर्याप्त भूमि सुधारों की व्यापक व्यवस्था के पर्याप्त भी फसल बटाई प्रथा राज्य के प्रायः सभी भागों में आज भी जारी है। राज्य सरकार ने समय-समय पर इस संबंध में अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये हैं। इन स्पष्टीकरणों से ज्ञात होता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों (जैसे भू-स्वामियों का बीमार होना तथा कलशकार द्वारा अन्य कलशकार से भूमि संबंधी उपकरण व कच्चे माल प्राप्त करना आदि) के कारण फसल बटाई प्रथा पर रोक लगाना सदैव संभव नहीं है। सरकारी सर्वेक्षण से भी ज्ञात होता है कि राज्य में फसल बटाई प्रथा जारी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बटाईदार प्रायः कुल उपज का 50 प्रतिशत लगान के रूप में देता है अतः शोषण की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए फसल बटाई प्रथा को समाप्त किया जाना आवश्यक है। मगाने ढंग से लगान वसूली पर कड़ी मजबूती की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे भूमिहीन कृषकों की रक्षा की जा सकती है।
7. बेनामी हस्तांतरण (Fictitious Transfers) - भूमि के समुचित वितरण हेतु सीलिंग कानून लागू किया गया लेकिन इस कानून की राज्य में अत्यधिक अवहेलना हुई। सीलिंग व्यवस्था लागू होने के पूर्व ही जमींदारों, जागीरदारों व बड़े भू-स्वामियों ने अपनी भूमि का बेनामी हस्तांतरण कर दिया। यह कार्य व्यापक पैमाने पर किया गया था। अतः राज्य सरकार को तुलनात्मक रूप से कम भूमि प्राप्त हुई।

वास्तव में सरकार को बचर एव कृषि के अयोग्य भूमि हो अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। भू-स्वामियों द्वारा ऐसी भूमि का मुआवजा उपजाऊ भूमि के बराबर प्राप्त कर लिया गया था। इससे भू-स्वामी लाभ में रहते हैं सरकार पर इसका अनावश्यक भार बढ़ गया। 3 नवम्बर 1969 को अनुपगढ़ में भूमि की नीलामी के द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से वृद्धि करना चाहती थी लेकिन कृषकों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थितियों के कारण भूमि के वितरण में अनेक समस्या उत्पन्न हुई। इस कार्य में अनेक अनियमितताएँ भी करती गईं। इससे कलशकारों की अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त हुआ। इन्हीं समस्याओं, बाधाओं व अनियमितताओं के कारण राज्य की कार्यशील जोतों में आज भी अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। सीलिंग नियमों में आवश्यक सुधार एवं संशोधनों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

8 भूमि के नवीनतम रिकॉर्ड उपलब्ध न होना (Non-Availability of New Land Records) - राज्य में भूमि के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था अत्यधिक प्राचीन एवं दोषपूर्ण है। इस व्यवस्था में भूमि संबंधी नवीनतम तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार ने हर रिकॉर्ड की एक सख्त, नवीन एवं वैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ विधि को अपनाया चाहिये, ताकि आवश्यक तथ्यों की कमी भी जानकारी प्राप्त की जा सके।

9 प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव (Lack of Effective Implementation) - राजस्थान में भूमि सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहेगी। वास्तव में भूमि सुधार सम्बन्धी विभिन्न कानूनों को प्रभावशाली ढंग में लागू नहीं किया जा सकता है। इसका एक कारण सरकारी निर्णयों को न्यायालय में चुनौती देना भी रहा है। सरकारों कर्मचारियों की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण भी भूमि सुधार संबंधी विभिन्न कानूनों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सका है। कुछ अधिनियमों में अपूर्णता भी है। इन अपूर्णताओं का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया और कानून से बचने हेतु उपाय अन्तरे गये। भूमि सुधार कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए इन्हें अदालतों में चुनौती देने के अधिकार को पूर्वतः समाप्त किया जाना चाहिये। भूमि सुधार कानूनों को अखिलम्ब लागू किया जाना चाहिये। राज्य प्रशासन को अधिक कुशल बनाया जाना चाहिये। कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये तथा भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण लगाया चाहिये।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955

भारतीय किसान सदियों से अज्ञान व अर्धविश्वास से ग्रसित रहा है। उसका दृष्टिकोण भी सदैव भाग्यवादी रहा है। अपने मालिक के आदेश को उसने कानून के रूप में स्वीकार किया और शोषण का शिकार होता रहा। समय के परिवर्तन के साथ-साथ उसे अपने अधिकार का ज्ञान हुआ और 'जो बोये उसकी जमीन' का नारा लोकप्रिय होने लगा। इस कारण से कानून बदलने लगे। 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' उन्हीं में से एक है। इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि भूमि से संबंधित कानूनों को एक जगह एकत्रित करना तथा उनमें संशोधन करना रहा है। यह अधिनियम 15 अक्टूबर, 1955 से संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत भूमि सुधारों के सबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं -

प्रमुख परिभाषाएँ :

1 इस अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी गई हैं। 'कृषि' के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन और उद्यान कार्य को सम्मिलित किया गया। 'कृषि वर्ष' 1 जुलाई से 30 जून तक माना गया। 'कृषक' अथवा 'काश्तकार' से आशय ऐसे व्यक्ति से लिया गया जो मुख्यतः कृषि में अपना व आश्रितों का जीवन निर्वाह करता है। 'बिस्वेदार' ऐसे व्यक्ति को माना गया जिसे कोई गांव या उसका भाग बिस्वेदारी प्रथा के अनुसार दिया गया हो। भूमि के सदर्भ में 'सुधार' का अभिप्राय भूमि क्षेत्र में रहने के लिए बनाये गये मकान तथा पशुओं के बाड़ा, भण्डारगृह या कृषि कर्यों के लिए किये गये निर्माण से है। 'सुधार' से आशय ऐसे कार्य से भी लिया गया जिसे करने पर उसे भूमि के मूल्य में वृद्धि हो। इसमें बाघ तालाब व कुओं आदि का निर्माण, भूमि को समतल करना, बाढ़ बनाना आदि कार्य सम्मिलित हैं। 'जागीरदार' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जागीर कानून के अंतर्गत जागीरदार के रूप में मान्यता प्राप्त हो और 'जागीर भूमि' ऐसी भूमि कहलायगी जिसमें जागीरदार को भू-राजस्व या अन्य राजस्व के विषय में अधिकार प्राप्त हो। 'खुदकाश्त' से आशय भू मालिकों द्वारा स्वयं काश्त की गई भूमि से है।

2 इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में किसानों को खानेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

3 अधिनियम के अनुसार कृषकों को तीन भागों में विभक्त किया गया- खानेदार काश्तकार, खुदकाश्त के लिए काश्तकार एवं गैर खानेदार काश्तकार।

4 काश्तकारों को रियायती मकानों के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया।

5 भूस्वामियों से लीज पर भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था की गई।

6 बेगार व नजगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

7 खानेदार काश्तकार को अपनी भूमि को भूमि बंधक बैंक तथा सहकारी समिति के पास गिरवी रखने का अधिकार दिया गया।

8 काश्तकार को उसकी भूमि को भूमि बंधक बैंक तथा सहकारी समिति के पास गिरवी रखने का अधिकार दिया गया।

9 अधिनियम के अनुसार खानेदार काश्तकार पांच वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि को किराये पर दे सकते हैं।

10 लगान का भुगतान नकद रूप में करने की व्यवस्था की गई। लगान की राशि कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक नहीं लेनी चाहिये। लगान का भुगतान नहीं करने पर काश्तकार को भूमि से बेदखल करने की व्यवस्था की गई।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को संपूर्ण राजस्थान में 15 अक्टूबर, 1955 से लागू कर दिया गया। लेकिन उसके पश्चात् इस अधिनियम में तत्कालीन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये अनेक संशोधन भी किये गये।

अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

यह अधिनियम राजस्थान के काश्तकारी कानूनों में समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इसने राज्य के काश्तकारों के अधिकारों व दायित्वों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इस अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि संपूर्ण राज्य में एक साथ ही अनेक काश्तकारों को खानेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस व्यवस्था से राज्य के काश्तकार भूमि के मालिक बन गये। काश्तकारी अधिनियम, 1955 ने राज्य के काश्तकारों को अनेक अनूचित व्यवहारों से भी रखा की। अब भू-माली काश्तकार को भूमि से बेदखल नहीं कर सकता।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 आर्थिक होल्ट का अर्थ बताइए।
Define economic holding
- 2 भू-खेत की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different concept of land holding
- 3 भूमि-सुधार से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by land reforms?
- 4 राजस्थान में भू-दातों पर खेप निर्धारण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write short note on the fixation of land ceiling in Rajasthan
- 5 राज्य में भूमि सुधारों की धीमी प्रगति के कारण बताइए।
Explain the causes for the slow progress of land reforms in Rajasthan

B निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में भूमि सुधार के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। इस दिशा में राज्य को कहीं तक सफलता मिली है? समझाइए।
Explain various efforts made for Land Reforms in Rajasthan. How far the State succeeded in this direction? Discuss
- 2 'राजस्थान कृषकरी अधिनियम, 1955 राज्य में भूमि सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।' समीक्षा कीजिए।
'Rajasthan Tenancy Act, 1955 is the important step in the direction of land reforms in the state'. Comment.
- 3 भूमि सुधार उपायों से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में भूमि सुधार नीति की आलोचना कीजिए।
What do you mean by Land Reforms? Give a critical account of the land reforms programme in Rajasthan after independence

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

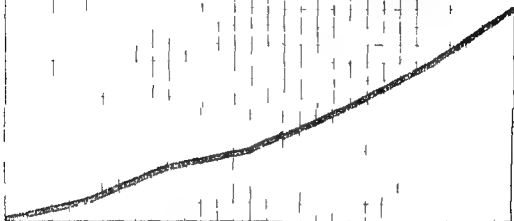
- 1 जागीरदारी उन्मूलन, राजस्थान कृषकरी अधिनियम तथा भू-खेपों पर सीमा निर्धारण पर टिप्पणी, लिखिए।
Write short notes on the following - Abolition of Jagirdary, Rajasthan Tenancy Act, Ceiling on land
- 2 स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में किए गए भूमि सुधारों उपायों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
Explain the critically the measures adopted for land reforms in Rajasthan after independence
- 3 निर्माण-बेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
(i) ग्राम आधार योजना (ii) गोपाल योजना
Write short note on the following
(i) Village base programme (ii) Gopal Yozana
- 4 कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति की विवेचना कीजिए।
Examine the position of Rajasthan in respect of agriculture holdings
- 5 राजस्थान में भूमि सुधारों की समस्या और उसके हल करने के लिए किए गए उपायों का वर्णन कीजिए।
Explain the problem of land reforms in Rajasthan and the measures adopted to solve these problems



अध्याय - 10

राजस्थान में पशु-पालन

ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN



“राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहाँ की संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसी थी।”

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में पशुओं की संख्या व पशु गणना 1997
- राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण
- राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु
- राजस्थान में पशुपालन के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएँ कार्यक्रम व सुविधाएँ
- योजनाकाल में पशु पालन का विकास
- राजस्थान में शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु संपदा का महत्व
- राजस्थान में कुक्कुट पालन
- राजस्थान में मत्स्य पालन
- अभ्यासार्थ प्रश्न

“भारत में बिना पशुओं के खेत जाते व बोय बिना पड़े रहते हैं खलिहान खाद्यान्न के अभाव में खाली पड़े रहते हैं तथा एक शाकाहारी देश में इससे अधिक दुखनामी बात क्या हो सकती है कि यहाँ पशुओं के अभाव में ची दूध आदि पौष्टिक पदार्थ भी मिलना कठिन हो जाता है। डार्लिंग की इन पंक्तियों से पशुपालन का महत्व स्पष्ट होता है। राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। पशुधन से तात्पर्य उन सभी पशुओं से लगाया जाता है जिनसे मनुष्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह हेतु कुछ न कुछ वस्तुएँ प्राप्त करता है। इस प्रकार इसमें सभी प्रकार के पशुओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। राजस्थान में पशुपालन एक जीवनशैली बन गया है अब पशुधन के सर्वांगीण विकास एवं विस्तार के लिए प्रयास करना एक अनिवार्यता हो गयी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी कहा गया है “पशुधन का विकास कृषि की सर्वांगीण प्रगति का एक आवश्यक अंग है। कृषि का पशुपालन के साथ उचित सामंजस्य अत्यन्त आवश्यक है।” रोजगार परिवहन अवसंरचना कृषि कार्य पौष्टिक पदार्थों की उपलब्धता आदि के मद्देन में पशुपालन राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राजस्थान में पशुओं की संख्या व पशुगणना, 1997 LIVESTOCK IN RAJASTHAN & LIVESTOCK CENSUS, 1997

राजस्थान में पशुओं की संख्या में 1951 से 1983 तक निरंतर वृद्धि हुई है। 1988 की पशुगणना

से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पशुओं की संख्या 87 लाख के लगभग कम हुई लेकिन 1992 में लगभग 69 लाख की वृद्धि हुई। 1997 में पशुओं की संख्या लगभग 66 लाख बढ़ी। निम्न तालिका से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है

राजस्थान में पशुओं की संख्या								
संख्या (लाख में) और कुल पशु संख्या का प्रतिशत (कोष्ठक में)								
पशु	1951	1961	1972	1977	1983	1988	1992	1997
गाय	107.87 (42.26)	131.36 (39.20)	124.70 (32.07)	128.96 (31.18)	135.04 (27.20)	109.16 (26.69)	115.95 (24.27)	121.58 (22.37)
भैंस	30.45 (11.93)	40.19 (11.99)	45.93 (11.81)	50.72 (12.26)	60.43 (12.17)	63.46 (15.50)	77.46 (16.21)	97.56 (17.95)
बैल	53.87 (21.11)	73.61 (21.97)	85.56 (22.01)	9.38 (24.03)	134.31 (27.05)	99.13 (24.24)	121.68 (25.47)	143.12 (26.33)
गर्दी	55.62 (21.80)	80.92 (24.03)	121.62 (31.28)	123.07 (29.76)	154.80 (31.18)	125.93 (30.78)	150.62 (33.52)	169.35 (31.16)
ऊट	3.41 (1.34)	5.70 (1.70)	7.45 (1.92)	7.52 (1.82)	7.56 (1.52)	7.21 (1.76)	7.30 (1.52)	8.68 (1.22)
अन्य	3.99 (1.58)	3.71 (1.11)	3.53 (0.90)	3.94 (0.95)	4.36 (0.88)	4.18 (1.02)	4.74 (1.01)	5.45 (0.97)
कुल	255.21 (100.00)	335.09 (100.00)	388.78 (100.00)	413.59 (100.00)	496.50 (100.00)	409.01 (100.00)	477.73 (100.00)	543.48 (100.00)

स्रोत: Board of Revenue for Rajasthan, Livestock Census, 1987 & various Statistical Abstracts of Raj.

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि -

(1) गाय व बैलों की संख्या में 1951 से निरंतर उतार-चढ़ाव होता रहा है किन्तु 1988 की पशुगणना के आधार पर इनकी संख्या 1983 की तुलना में 26 लाख कम हुई है। 1951 में कुल पशुओं में इनका अनुपात 42.26 प्रतिशत था जो 1988 में घटकर 26.69 और 1992 में 24.27 और 1997 में 22.37 प्रतिशत रह गया।

(2) भैंसों (नर व मादा) की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 1951 की तुलना में इनकी संख्या दुगुने से भी अधिक हो गई है जबकि इसी अवधि में गाय व बैलों की संख्या लगभग समान रही है। पशुओं का कुल संख्या में भैंसों का अनुपात 1951 में 11.93 प्रतिशत था जो 1988 में 15.50 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में इनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

(3) भेड़ों की संख्या में 1951 से 1983 तक निरंतर वृद्धि हुई है किन्तु 1988 की पशुगणना के आधार पर 1983 की अपेक्षा लगभग 35 लाख भेड़ें कम रहीं। कुल पशुओं में भेड़ों का अनुपात लगभग स्थिर रहा है। 1951 में यह 21.11 प्रतिशत था जो 1988 में बढ़कर 24.24 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में भी भेड़ों की संख्या में लगभग 22 लाख की वृद्धि हुई।

(4) भेड़ों की भांति बकरियों की संख्या भी 1951 से 1983 तक निरंतर बढ़ी किन्तु 1988 में इसमें लगभग 29 लाख की कमी अंकित की गई। पशु-सम्पदा में बकरियों की संख्या का अनुपात 1951 के 21.80 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 30.79 प्रतिशत हो गया। 1992 में बकरियों की संख्या में लगभग 25 लाख और 1997 में लगभग 19 लाख वृद्धि हुई।

(5) ऊटों की संख्या 1951 से 1972 तक निरंतर बढ़ी किन्तु उसके पश्चात् 1992 तक वह लगभग स्थिर बनी हुई है। कुल पशु-संख्या में इनका सादान 1951 में 1.34 प्रतिशत था जो 1988 में 1.76 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में घट कर यह क्रमशः 1.52% व 1.22% रह गया।

(6) राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या 1951 में 255.21 लाख थी जो निरंतर बढ़ते हुए 1983 तक 496.50 लाख हो गई। 1988 में यह फिर केवल 409.01 लाख रह गई। 1992 में पशुओं की संख्या बढ़कर 477.73 लाख हो गई। 1997 में यह संख्या 543.48 लाख थी।

(7) 1997 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या का 55.49 प्रतिशत में अधिक भेड़ व बकरियों का है।

राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण

DISTRICTWISE DISTRIBUTION OF LIVE STOCK IN RAJASTHAN

राजस्थान की पशु सम्पदा का जिलानुसार वितरण एक समान नहीं है और न ही सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के पशुओं का एकमात्र महत्व है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को अधिक महत्व देते हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पशुओं का जिलानुसार सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है

- 1997 का पशुगणना के आधार पर बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशु है। दूधरा व बीसरा स्थान क्रमशः नागौर व बीसवाड़ा जिलों का है। राजस्थान में सबसे कम पशु भीलपुर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक गाव-बैल उदयपुर जिले में है। दूधरा व बीसरा स्थान क्रमशः कोटा एवं बीसवाड़ा एवं किशनगढ़ जिलों का है। इनकी सबसे कम संख्या भीलपुर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक भैंसे जयपुर जिले में एवं सबसे कम जैसलमेर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक भेड़ जाधपुर जिले में तथा सबसे कम भीलपुर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक बकरियाँ बाड़मेर जिले में हैं एवं सबसे कम भीलपुर जिले में हैं।
- 1997 का पशुगणना के आधार पर राजस्थान के सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर जिले में एवं सबसे कम भीलपुर जिले में हैं।

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु

IMPORTANT ANIMALS IN RAJASTHAN

1 भैंस (Buffalo) - राजस्थान में दूध प्राप्ति के लिए भैंसे बहुतायत में पाली जाती हैं। राजस्थान में जो भैंस पाला जाता है उनकी मुख्यतः चार नस्लें हैं। मुरी, जाफरावादी, नागपुरी और बटावरी। इनमें से मुरी एक महत्वपूर्ण नस्ल है। यह नस्ल दूध की दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है और लगभग सार उत्तरी भारत में बहुतायत में देखी जा सकती है। जाफरावादी नस्ल, काठियावाड़ और जाफरावाड़ में सर्वाधिक होने के कारण जाफरावादी कहलाती है। इस भा दूध के लिए पाला जाता है। नागपुरी नस्ल और बटावरी नस्ल भी दूध के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

भैंसों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)

जिला	संख्या (लाख)
जयपुर	77
अलवर	76
भरतपुर	52

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

2. गाय (Cattle) - राजस्थान में गाय की मुख्य नस्लें सलीवाल, लालसिंधी, गिर, धारपरकर, मेवाणी, नागौरी, मालवी आदि हैं। राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों में धारपरकर नस्ल बहुतायत से पाई जाती है तो जोधपुर क्षेत्र की ओर नागौरी गाय अधिक मिलती है। मालवा के पठारी क्षेत्र में मालवी और राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र में मेवाणी नस्ल अधिक पाई जाती है। राजस्थान में गौ पालन का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन तो है ही साथ में कृषि कार्यों के लिए बैलों का प्रयोग करना भी है। राजस्थान में धीरे-धीरे देशी नस्लों के साथ-साथ विदेशी नस्लें भी पनपने लगी हैं। गौ-पालन की दृष्टि में भीरावाड़ा, उदयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, नागौर आदि प्रमुख हैं। विदेशी नस्लों में हॉलस्टीन व जर्सी प्रमुख हैं।

गायों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)

जिला	संख्या (लाख)
उदयपुर	97
भीलवाड़ा	69
किशनगढ़	75

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

राजस्थान में गौ वंश की प्रमुख नस्लें (Main Breeds of Cattles) निम्नलिखित हैं -

नागौरी (Nagauni) - मुख्यतः नागौर जिले में प्राप्त होने वाले गाय व बैल, इसी जिले में वंश उत्पत्ति के कारण 'नागौरी नस्ल' के नाम से प्रसिद्ध है। इनका रंग सफेद या भूरा होता है। ये लंबे मुँह तथा पतली लेकिन मजबूत टांगों वाले होते हैं। नागौरी बैल टोड़ने में तेज और कृषि कार्यों में उत्तम क्षमता एवं मजबूती वाला है। इसके अद्वितीय गुणों तथा कार्यक्षमता के कारण इनकी मांग संपूर्ण देश में सर्वाधिक है लेकिन इस नस्ल की गायें अपेक्षाकृत कम दूध देती हैं। नागौरी नस्ल जोधपुर जिले के पूर्वी भाग, बीकानेर जिले की मोछा तहसील तथा जयपुर के निकट रूपनगढ़ तक फैली हुई है।

काकरेज (Kankrej) - यह नस्ल भारवटन व मगर की दुग्ध-उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस नस्ल के बैल अधिक योद्धा होने, बठौर भूमि को जोतने तथा तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध हैं। गाय सामान्यतः 5 से 10 किलोग्राम दूध

बकरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)

जिला	संख्या (लाख)
बाड़मेर	188
जोधपुर	129
नगौर	108

स्रोत Board of Revenue, Livestock Census 1997

5 ऊँट (Camel) - राजस्थान में ऊँट मुख्यतः आवागमन में सुविधा की दृष्टि से पाला जाता है, साथ ही इसका प्रयाग कृषि कार्यों के लिए भी बहुतायत में किया जाता है। मण्डल दर्श में ऊँटों की गणना की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट हैं।

राजस्थान में जैसलमेर व निकट स्थित नाथना नामक स्थान का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस क्षेत्र का ऊँट मुख्यतः व लंबे समय तक तैज टौडन वाला होता है। यहाँ बाण है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में सवारी के लिए इस नस्ल के ऊँट का अधिक प्रयोग किया जाता है। फलोदी के पास गोमत नामक स्थान का ऊँट भी सवारी के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त कैमर, बाल व गुडा आदि स्थानों के ऊँट भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। जाधपुरी, बीकानेरी व जैमलमेरी ऊँट अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इन ऊँटों का प्रयाग मुख्यतः बोझा देने के लिए किया जाता है।

ऊँट की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)

जिला	संख्या (लाख)
बाड़मेर	11
जोधपुर	07
बीकानेर	06

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

6 कुक्कुट (Poultry) - राजस्थान में मुर्गीपालन का महत्व निरंतर उठता जा रहा है। कुक्कुटों का छाती समय में रोजगार प्रदान करने का यह एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। इस व्यवसाय में शहरी क्षेत्र व लोगों का भाग अपनी आरंभिक अवस्था में। मुर्गीपालन का मुख्य उद्देश्य अण्डा व मांस उत्पादन है। राजस्थान में अजमेर जिला अपनी जनसंख्या की उपयुक्तता के कारण मुर्गीपालन में प्रथम स्थान पर है।

कुक्कुट की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)

जिला	संख्या (लाख)
अजमेर	149
उदयपुर	43
बांसगढ़	42

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

राजस्थान में पशुपालन के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम व सुविधाएँ

VARIOUS PLANS, PROGRAMMES & FACILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN

1 एकीकृत पशुधन विकास योजना (Integrated Live Stock Development Project) - आठवीं पंचवर्षीय योजना से यह योजना जयपुर एवं बीकानेर समान में लागू की जा रही है। इस योजना का अंतर्गत गोपालन योजना की तरह पशुधन के स्वास्थ्य के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान, बेकार पशुओं का वसिवाकरण एवं अधिक चारा के लिए उन्ना चारा बीजों का वितरण सम्मिलित है। इस योजना में पशुओं का सुवर्तित आहार पर बल दिया जायेगा। अब तक जो विभिन्न योजनाएँ कार्यरत थीं वे साथ पशु स्वास्थ्य का ही अधिक महत्व देती थीं किन्तु यह योजना पशुओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

इस योजना का अंतर्गत प्रत्येक 2000 प्रजनन योग्य पशुओं पर सघन रूप से गन्त सुधार का कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण प्रदान किये जायेंगे। डेयरी एवं पशुपालन विभाग के सम्बन्धित प्रवासों में यह एकीकृत पशु विकास योजना निर्मित कर क्रियान्वित की जा रही है। डेयरी फैडरेशन इस योजना के अधीन अपनी मुगनी डेयरी महत्वपूर्ण समिति का गठन करेगा और कुछ नई डेयरी महत्वपूर्ण समितियों का गठन करेगा। डेयरी द्वारा गोपालन योजना की भाँति प्रजनन योग्य पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यतः डेयरी एवं पशुपालन विभाग की माइडवे में क्रियान्वित होगा।

2 देशी गौ नस्ल सुधार परियोजना (Indigenous Breed Development Project)

राजस्थान के प्रमुख गौ वंश व नाणों का रजिस्टर लागू कर, गार गटा ऑफ़ रजिस्ट्रेशन सक्त है। ये वंश मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रित हैं। यहाँ के पशुपालकों का जीवन सामान्यतः इन्हीं पर निर्भर है। इन्होंने पशुपालन विभाग में देशी गौ नस्ल सुधार परियोजना बनायी है। इस योजना का अंतर्गत श्रेष्ठ नस्ल व गाँडा के माध्यम से नस्ल सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम का जिस गाँव में अपनाया जायेगा उसी गाँव के शिक्षित प्राप्ताग सुवर्त का चयन करके, उसे कृत्रिम गर्भाधान एवं वसिवाकरण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। चयनित प्राप्ताग

युवक को 2000 प्रजनन योग्य पशुओं में यह श्रद्धा प्रदान करनी होगी। इस योजना के तहत बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर और अजमेर जिलों में गौ-वध का विकास कार्य हथ में लिया जायेगा।

3 ग्राम आधार योजना (Village Based Project)

ग्राम आधार योजना राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पशुपालन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाना है। ग्राम आधार योजना एक सघन योजना है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पांच बातों को सम्मिलित किया गया है -

a प्रजनन (Breeding) - उन्नत नस्ल के पशु विकसित करने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन को मुख्य आधार बनाया गया है। इससे नस्ल सुधारने के साथ-साथ उत्पादन भी सुधारा जा सकता है। इस प्रकार का प्रयास 1966-67 से हो किया जा रहा है। आरंभ में यह राज्य के कुछ क्षेत्रों में ही लागू किया गया था किंतु बाद में पूरे राजस्थान को इसके अन्तर्गत ले लिया गया। राजस्थान में प्रजनन कार्यक्रम को भलो-पाति चलाने के लिये 1984 में एक प्रजनन नीति अनुमोदित की गई। यदि कोई अन्य मसला इस प्रकार का प्रजनन कार्य करती है तो उसे भी इस नीति के अनुरूप कार्य करना होगा। राज्य में पशुओं की उन्नत नस्ल का विकास करने के लिए उन्नत नस्ल के नर पशु उपलब्ध कराये गये। दूधि गर्भाधान की सुविधा भी प्रदान की गई। 1956 में ही दूधि गर्भाधान कार्यक्रम आरंभ हो गया था। इसके अंतर्गत अनेक कठिनाइयाँ थीं। इनको दूर करने के लिए धीरे-धीरे प्रयास किये गये। इस प्रकार की चेष्टा की गई कि उन्नत नस्ल में किसी प्रकार की विकृति न आये अथवा वह बर्बाद न हो। 1979-80 से 1983-84 तक मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 11 जिलों में दूधि गर्भाधान के लिए 108 उपकेंद्रों की स्थापना की गई। तत्पश्चात् 1983-84 से भारत सरकार के अनुदान द्वारा केंद्र प्रवर्धित योजना आरंभ की गई। इसके अंतर्गत दासवाड़ा, झुणपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालाना, राजमहल, उदयपुर, नागौर आदि जिलों में दूधि गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयास के तत्पश्चात् एक लाख से भी ज्यादा दूधि गर्भाधान प्रतिवर्ष किये जा रहे हैं।

b सन्तुलित पशु आहार व्यवस्था एवं चारा उत्पादन (Balanced Diet & Fodder Production) - पशुओं में शारीरिक वृद्धि तथा उत्पादन में प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए सन्तुलित आहार अत्यन्त आवश्यक है। सन्तुलित आहार का अर्थ पशु का आवश्यकतानुसार

प्रोटीन, कसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल (खनिज) और विटामिन का नियमित रूप से व उचित मात्रा में मिलना है। सन् 1980-81 से ग्राम आधार योजना के अंतर्गत इसकी समस्त इकाइयों के माध्यम से बिना लाभ बिना हानि के आधार पर पशु आहार वितरित करने की व्यवस्था की गई। उन्नत किम्प का पौष्टिक चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारा उत्पादन एवं संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम हथ में लिये गये। अच्छे बीजों के उत्पादन के लिए राजस्थान में छ बीज गुणसङ्गठन लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं जिनसे 300 क्विंटल से भी अधिक बीज प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। ग्राम आधार योजना की इकाइयाँ इस बीज का वितरण करती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रबी व खरीफ की फसलों के अनुसार पशुपालकों की भूमि पर उन्नत किम्प के चारा प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु नि शुल्क बीज वितरित किये जाते हैं जिससे फसलों के उत्पादन और उसकी उपयोगिता को पशुपालक स्वयं परख सकें और श्रद्धा में उच्च उत्पादन के लिए प्रेरित हो सकें। चारा उत्पादन अधिक से अधिक हो और उसकी उन्नत किम्पें लगाई जायें। इस उद्देश्य से भारत सरकार भी 1979-80 से 1/4 एकड़ क्षेत्र में निजी पशुपालकों के यहाँ प्रदर्शन चगाने हेतु योगदान दे रही है। इसमें नि शुल्क बीज वितरण व तकनीकी जानकारी दी जाती है। प्रतिवर्ष इस प्रकार के लगभग 2500 मिनीकट लगाये जाते हैं। बीजों के परीक्षण एवं प्रमाणित होने के पश्चात् ही वितरित किया जाता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे वृक्ष लगाने पर भी बल दिया गया है जिससे पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध हो सके। इस कार्य के लिए वन विभाग के अधिकृत पशुपालन विभाग भी वृक्ष एवं बीज नि शुल्क उपलब्ध करवाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग एक लाख वृक्ष प्रतिवर्ष लगाये जाते हैं।

c उचित प्रबन्ध व्यवस्था (Management) - उन्नत प्रजाति के पशुओं को स्वस्थ रखना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस हेतु सक्कमक रोगों के प्रकोप से बचाने के लिये पशुओं को समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीका लगाया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग दो लाख टीके लगाये जाते हैं। ऐसे पशु जो बेकर हो गये हैं उनका कष्टकरण कर दिया जाता है ताकि दूसरे पशुओं की नस्ल खराब न हो। प्रजनन योग्य पशुओं में से अनेक पशु रोगग्रस्त होने के कारण समय पर प्रजनन नहीं कर पाते। इस हेतु उन्हें चिकित्सा प्रदान कर प्रजनन योग्य बनाया जाता है। इस आशय से प्रत्येक ग्राम आधार योजना के अंतर्गत समय-समय पर शिविर आयोजित किये जाते हैं ताकि ग्रामीण पशुपालकों को उनके निवास के समीप ही यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

पशुओं का दिन प्रतिदिन का खोना खोनी बीमारियों का भा पुरा ध्यान रखने का खेजा की जाता है। इन इकाइयों द्वारा लगभग एक लाख से अधिक पशुओं का उपचार शक्तिपूर्वक किया जाता है।

d समुचित विपणन व्यवस्था (Marketing) इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारना था है। यह तभी संभव है जबकि पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह चेष्टा की जाती है कि दूध के बिना मध्यमों के राधा उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सके। यह चेष्टा की जाती है कि दूध का विक्रय दुग्ध उत्पादक महकसे समितियों के माध्यम से हो पशुओं के विक्रय के लिए पशु मलों का आयोजन किया जाता है जिसमें क्रान्ति एवं विक्रेता मोधे मर्पक कर मर्के आर यह क्रय-विक्रय उचित मूल्य पर संभव हो सके अब अनेक ग्राम पचायत व पंचायत समितियाँ भी इस प्रकार के मर्के व आयोजन करने लगी हैं राज्य में 10 राज्यस्तरीय मेला में ढाई लाख पशु एकत्रित होते हैं। इन मेला में पशुपालकों को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए के क्रय विक्रय का लाभ मिलता है।

e शिक्षा एवं प्रसारण (Education & Extension)

पशुपालकों को आधुनिक वैज्ञानिक रीति से परिचित रखने के लिए समय समय पर प्रदर्शनी शिविर एवं गाण्डिया आयोजित की जाती हैं। इनके अतिरिक्त आकाशवाणी से वार्ता हेण्डलिंग आदि के माध्यम से जनवर्द्धन के प्रयास किये जाते हैं। दूरदर्शन में भी ग्राम आधार पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा प्रसारित की जाती है। विभिन्न राज्य स्तरीय पशु मलों के अवसर पर स्थानीय नस्लों की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जो पशुपालकों का शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखिल राजस्थान गौर एवं सकर पशु प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। इस प्रतिवर्ष पुष्कर मेले के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस प्रदर्शनी में गौर वंश की उत्पत्ति उत्पादन शक्ति एवं नस्ल के संरक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। इस प्रदर्शन के परिणामस्वरूप अग्रसर के गौर गौ वंश व वंश आर विदेश में निर्यातयोग्य प्राप्त का है। बहुत सी गौर पशुओं का विदेश में निर्यातकर बाजीन में भेजा गया जहाँ इसका सकारात्मक प्रभाव बाजीन के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। सकर प्रजनन के प्राप्ताभ्यन्त के लिए और अधिक प्रचार प्रसार के लिए सन् 1972 में अखिल राजस्थान स्तर की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताओं को गौर प्रदर्शनी के नाम से जोड़ा गया। इसका बहुत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुआ और लोगों में सकारात्मक के पशुओं के प्रति प्रेम दूर हुआ। सन् 19 4 65 से ही अखिल भारतीय प्रदर्शनीया में गौर वंश का प्रचार प्रसार व पशुओं का भजन का प्रचार गति

है। इससे पशुपालकों का अन्य राज्य में पशु विकास के प्रथम तत्त्वों की ज्ञान व अन्य राज्यों के पशुपालकों के विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलता है। राजस्थान में अखिल भारतीय पशु प्रतियोगिता 1957 में नागौर में 1973 में जयपुर में तथा 1981 में भरतपुर में आयोजित की गई थी। उन्नत निम्न के पशुओं का प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है एवं विभिन्न नस्लों के अनुसार अधिकतम दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं का पुरस्कार दिया जाता है। पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन संबंधी ज्ञान नवीनतम तकनीक की जानकारी उनके विचारों का ज्ञान व उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर शिविर एवं गाण्डिया का आयोजन किया जाता है। ग्राम आधार योजना इकाइयाँ आयोजित की जाती हैं। इस कार्यक्रम में सवार अधिकारियों व कर्मचारियों को आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान करने के लिए 1963-64 में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र पर पशु चिकित्सा को एक माह व पशुधन सहायक को 45 दिन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार ने पशुपालकों को विभिन्न गुणिगुणों से ज्ञान करने की चेष्टा की है। पशुओं की नस्ल एवं उत्पादन शक्ति में गुणों के साथ साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति का सुधारा हो रहा है। ग्रामीण विकास का भी बड़ा मिला है।

4 गोपाल योजना (Gopal Yojna) राज्य में श्वेत क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण और उपयोगी मानते हुए राज्य सरकार द्वारा यह योजना बनाई गई। उमर 17 वर्ष से अधिक आयु के पशुपालकों को स्वयंसेवा समूहों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य सरकार ने पशुधन के विकास एवं उन्नति के उद्देश्य के लिए 1989-90 में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 10 जिलों में यह योजना लागू की। इस योजना के तहत चयन समिति द्वारा स्थानीय जिलों के शिक्षित युवकों को जिनकी आयु 20 व 25 वर्ष मध्य है को प्रशिक्षित करने पशुधन विकास में भागीदार बनाया गया है। इनके अंतर्गत अनुभूति ज्ञान एवं अनुभवित ज्ञान ज्ञान युवकों का ज्ञान में योगदान देती गई है।

a उद्देश्य (Object) योजना का प्रमुख उद्देश्य पशुधन के सुधार द्वारा पशुपालकों के आर्थिक स्तर को उन्नत करना है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि इस योजना के माध्यम में किसान अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करके आर्थिक रूप में अधिक सम्पन्न बन सकें। इस

लोगों को नस्त सुधार के लिए पर्याप्त कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब पशुपालन विभाग इम रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेषतः जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले में पशुपालकों को नस्त सुधार के लिए उन्नत नस्त के साण्ड उपलब्ध कराता है।

6 सूअर विकास कार्यक्रम (Pig Development Project) - पशुपालन विभाग ने कमजोर आय वर्ग के परिवारों को उन्नत नस्त के विदेशी सूअर अनुदान पर उपलब्ध करने की योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से आरम्भ की है। अलवर एवं भरतपुर जिले में सूअर पालकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अलवर में एक सूअर विकास फार्म भी स्थापित किया गया है। इस फार्म में विदेशी नस्त के सफेद सूअरों का आधुनिक तरीके से पालन-पोषण करके उन्हे निजी सूअरपालकों को वितरित किया जाता है। राजस्थान में प्रयोग के तौर पर अलवर व भरतपुर में प्रारम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 924 निर्धन परिवारों को बैक से ऋण अनुदान दिलाकर विदेशी नस्त की सूअर इकाइया वितरित की गई।

7 बकरी विकास परियोजना (Goat Development Project) - बकरीपालन से आर्थिक स्रोतों का विकास करना और बकरीपालक परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने स्विट्जरलैण्ड सरकार के सहयोग से राज्य में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना आरम्भ की है। अजमेर जिले के रामसर गांव में इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। स्विट्जरलैण्ड से अल्पाईन एवं डोगन किस्म की उन्नत नस्त को राजस्थान की सिराही नस्त से मिलाकर उन्नत बकरे-बकरियों का उत्पादन कर बकरीपालकों को दिया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण में यह कार्यक्रम अजमेर भीलवाड़ा एवं मिर्साही जिलों में आरम्भ किया गया है।

8 अश्व विकास कार्यक्रम (Horse Development Project) - भारत में मालानी और काठियावाड़ी नस्त के घोड़े सर्वाधिक लाक्षणिक हैं। इनमें से मालानी नस्त के घोड़े बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील में पाये जाते हैं। ये शारीरिक दृष्टि से सुडील व ताकतवर होते हैं। राजस्थान का पशुपालन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ घोड़ों का आधिक्य है अच्छी नस्त के घोड़े उपलब्ध कराने की चप्टा कर रहा है ताकि उन्नत नस्त के ह्रम को रोक जा सका। विभाग द्वारा इस सदर्भ में विभिन्न पशु चिकित्सालयों में सुविधाय प्रदान की जा रही है अभी तक उदयपुर पॉलिक्लिनिक तथा झान्गनाड जालौर तथा पाली स्थित

पशु चिकित्सालयों को मालानी नस्त के घोड़े उपलब्ध कराये गये हैं। यहाँ सुविधाय गुडामालानी (बाड़मेर), जयपुर पॉलिक्लिनिक, बिलाड (जोधपुर) तथा बाली (पाली) पशु चिकित्सालय को उपलब्ध कराई गई है। इससे संबंधित रोगों के उन्मूलन और स्वस्थ के परीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

9 ऊँट विकास कार्यक्रम (Camel Development Project) - भारत के कुल ऊँटों का 70 प्रतिशत राजस्थान में है। वहाँ ऊँटों की दो मुख्य नस्लें हैं जैसलमेरी और बीकानेरी। बीकानेरी नस्त के ऊँट भार वहन करने की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं और जैसलमेरी ऊँट तेज रफ्तार के लिये विख्यात हैं। ऊँटों में आमतौर पर रोग कम होते हैं। इनमें मुख्य रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने सर्रा नियंत्रण इकाइया स्थापित की है। इस मदर्भ में पशुपालकों को भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। ऊँटों का प्रजनन कार्य शीत ऋतु में नवम्बर से फरवरी तक होता है। ऊँटों की उन्नत नस्त को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बीकानेर के समीप जोंहड बोड में ऊँट प्रजनन कार्य संचालित किया जा रहा है।

10 खाद्य एवं चारा विकास योजना (Food & Fodder Development Project) - नस्त सुधार के साथ साथ पौष्टिक आहार पर भी विशेष बल दिया जाना आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुये पशुपालन विभाग द्वारा 1959 से खाद्य एवं चारा विकास योजना चलायी जा रही है। इस योजना के द्वारा पशुओं के लिए पौष्टिक एवं सन्तुलित आहार और चारा उत्पादन की नवीनतम तथा उपयोगी जानकारी पशुपालकों को दी जाती है। माग के अनुसार उन्नत किस्म के प्रमाणित चारा बीज खरीद कर खरीद शुल्क पर ही उपलब्ध करने की व्यवस्था है। राजस्थान में उन्नत चारे के बीजों की कमी की पूर्ति के लिए 1990-91 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एक बृहद् चारा बीज उत्पादन फार्म की स्थापना ग्राम मोहनगढ़ (जैसलमेरी) में की गई है और 100 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करायी गई है। पशु प्रजनन केन्द्रों एवं गौशालाओं के माध्यम से उन्नत चारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। चारा प्रदर्शन योजना के अंतर्गत मिनिक्टिड्स भारत सरकार तथा क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र मूरतगढ़ से भी प्राप्त होते हैं। इनसे प्राप्त बीज पशुपालकों को नि शुल्क वितरित किये जाते हैं अच्छे उपलब्ध चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन उपचारित करने के प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं।

व्यवस्था की है। पशुपालन विभाग में कार्य कर रहे पशु चिकित्सकों को देश तथा विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अत्यंत जिला मुख्यालय पर एक कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों को आधुनिकतम उपकरणों में सुसज्जित मोबाइल वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजनाकाल में पशुपालन का विकास

DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN PLANS

1 पहली योजना से छठी योजना तक पशुधन का विकास (Development of Animal Husbandry from First to Sixth Plans) - पहली से छठी पंचवर्षीय योजनाओं तक राजस्थान में पशु विकास संबंधी अनेक आधारभूत एवं विकासात्मक कार्य सम्पन्न किये गये। इस अवधि में नस्ल सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। गाय व बैलों को नस्ल उन्नत करने हेतु राज्य के अनेक भागों में 'तै-शालाए' स्थापित की गईं। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में मेवार, हरियाणा और नागौर नस्लों के विकास हेतु नागौर बस्मी और अलवर में शाखाओं की स्थापना की गई। कुम्हेर सबर्डन फार्म में हरियाणा नस्ल विकास की जाती है। 1964 में जैसलमेर जिले के घादन ग्राम में बुलमटर फॉर्म की स्थापना की गई। इस फॉर्म में धारपाकर नस्ल के माड तैयार किये जाते हैं। नस्ल सुधार कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बुलमटर फॉर्म को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को सौंप दिया गया है। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत रामसर व चन्दनदेव (जैसलमेर) में शाखाओं की स्थापना की गई है। सांड विकास के लिए राज्य में गौदाम्य प्रोग्राम केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र द्वारा तैयार किये गए माड पचासों को वितरित कर दिये जाते हैं।

इस अवधि में पशुधन की वीमरियो में श्व एवं गोजराम के अनेक प्रयास किये गये। राज्य के विभिन्न भागों में चिकित्सालयों, दल चिकित्सालयों एवं चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की गई। मिडर पेस्ट के नियंत्रण हेतु बन्दा का स्थापना की गई। इसके अलावा पचासत रसमिया द्वारा भी पशु चिकित्सालयों का संचालन किया जाता है। द्वितीय योजना में जयपुर व बीकानेर में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। जोधपुर में ऊन व भेड़ प्रशिक्षण स्कूल प्रारंभ किया गया। मूरतगढ़ व बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भेड़ अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई। छठी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। इससे पशुओं के स्वास्थ्य

में सुधार हुआ। विदेशी नस्ल के माण्डों के उपयोग में वृद्धि हुई लेकिन भारतीय परिस्थितियों में इनका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुमेरुर, रायसिंह नगर, ब्यावर, किरानाख-बाम, झालावाड़ कंकड़ी, बस्सी, अलवर व नागौर आदि में कृषि गणधान केन्द्रों की स्थापना की गई। द्वितीय व तृतीय योजनाओं में भी कुछ केन्द्रों, उपकेन्द्रों व विशिष्ट इकाइयों की स्थापना की गई। चतुर्थ योजना से छठी योजना के मध्य पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। 1959 में चार विकास को एक विशिष्ट योजना निर्मित की गई जिसके अंतर्गत चारे की विशेष फ़मलें उत्पन्न करने पर जोर दिया गया। इसमें राज्य में चारे के उत्पादन में तेजी में वृद्धि हुई।

2 सातवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन का विकास (Animal Husbandry Development in Seventh Plan) - सातवीं योजना में विभिन्न पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा देशी पशुओं के सुधार पर बल दिया गया। इस योजना में पशुपालन विकास हेतु 31.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जबकि योजनाकाल में वास्तविक व्यय 37.62 करोड़ रुपये हुआ। लक्ष्य से अधिक व्यय का प्रमुख कारण केन्द्र सरकार द्वारा कुछ पशुपालन कार्यक्रमों का हस्तगतण था। मानवी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन पर किये गये वास्तविक व्यय में पशुपालन पर 2180.30 लाख रुपये, विरबीचालय पर 101.05 लाख रुपये, भेड़ व ऊन पर 234.64 लाख रुपये, मत्स्य पर 295.12 लाख रुपये व डेयरी विकास पर 915.00 लाख रुपये व्यय किये गये।

3 आठवीं पंचवर्षीय योजना (Animal Husbandry in Eighth plan) - आठवीं योजना में पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादकता में तेजी में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नस्ल सुधार कार्यक्रम मुख्य परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है। नस्ल सुधार पर अधिक बल दिया गया जहाँ चारे का प्रयोग उत्पादन के लिए किया जा रहा है। पशु स्वास्थ्य तथा कार्यक्रम के विकास में लक्ष्य के अन्तर्गत नस्ल सुधार के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। राज्य में पशुओं का स्वास्थ्य का विकास करना पशुओं की पशुपालन पद्धति शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आवश्यक अनुसार उसका विस्तार करने का निश्चय किया गया। पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम तथा पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के द्वारा पशुओं की श्रेष्ठ किस्में विकसित करने की चेष्टा की गई। चरगाहों का विकास करने, चारे के उन्नत बीजों का उत्पादन बढ़ाने तथा एकीकृत कृषि व्यवस्था का प्रचलन बढ़ाने तथा मुर्गा पालन की तेजी से विस्तार किया गया ताकि

लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके। योजनाकाल में पशु विकास हेतु 8500 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

4 नवी योजना में पशुपालन (Animal Husbandry in Ninth plan) - पशु मूल सुधार पशु आहार और पशु प्रबंध में आधुनिकतम वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुये पशुओं की किस्मों का सुधार कर पशु उत्पादकता में वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। नवी योजना में पशुपालन पर 12429 92 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु-सम्पदा का महत्व

IMPORTANCE OF ANIMAL HUSBANDRY IN ARID AND SEMI ARID REGIONS

राजस्थान में पशुओं का कृषि परिवहन व पशु उत्पाद की दृष्टि से विशेष महत्व है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। ऐसे स्थानों पर तो पशुपालन का महत्व और भी बढ़ गण है। इन क्षेत्रों में पशु पालन के महत्व का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

1 रोजगार (Employment) - राजस्थान में शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में लोग मृगीपालन दुग्ध व्यवसाय, चमड़ा उद्योग आदि में लगे हैं। परिवहन के साधन के रूप में भी पशुओं का प्रयोग कर रोजगार प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जहाँ कृषि के लिए अत्यन्त विषम परिस्थितियों तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि उपज लेना अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कठिन है उन क्षेत्रों में पशुपालन द्वारा लोगों को रोजगार मिला है।

2 परिवहन (Transport) - राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में ऊट परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका अतिरिक्त बैल भी बड़ी मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। मुख्यतः ऊँटों का प्रयोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में एवं स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने पर बहुतायत से होता है। ऊँटों का अकेले और उटगाडियों के अन्तर्गत परिवहन के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है।

3 अकाल एवं कम वर्षा (Famines & Draughts) - राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अकाल एवं सूख की स्थिति प्रायः बनी रहती है। वर्षा कम होने से अकाल व सूख की स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में अच्छी फसलें लेना सम्भव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में प्रायः पशु ही इनके जीवन का आधार बनते हैं। एग्रे क्षेत्र जहाँ पर अकाल एवं सूख की स्थिति होना है तथा वनस्पति प्रायः नहीं के बराबर पाई जाती है उन क्षेत्रों में भेड़ व

बकरियों का विशेष महत्व हो जाता है। भेड़ एवं बकरियाँ अत्यन्त बगैक घास तथा विम्बुत रेगिस्तानी क्षेत्र में भी मृन्मय रह सकती हैं और अपने पालकों को पर्याप्त सर्वोत्तम लाभ दे सकती हैं। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में उन की किस्म सर्वोत्तम होती है। ऐसे क्षेत्र जिनमें पर्याप्त वर्षा होती है और जो हरे-भरे होते हैं, वहाँ उन की किस्म निम्न कीटों की होती है। इस प्रकार शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशुओं ने मनुष्य को जीवित रहने का आधार प्रदान किया है। यही कारण है कि राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अन्य पशुओं की अपेक्षा भेड़ एवं बकरियाँ अधिक मात्रा में पाले जाते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा के उपलब्ध आकड़ों से स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में कृषि की अपेक्षा पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण है।

राजस्थान के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा प्रायः सामान्य से कम होती है। कम वर्षा के कारण फसलें प्रतिकूल रूप से कम होती हैं। कम वर्षा के कारण फसलें प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में पशुपालन एक महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है।

4 कृषि कार्य (Agricultural work) - राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण प्रदेश में पशु कृषि कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजस्थान में पशु भूमि को जोतने कुएँ में पानी निकालने फसलें पकने पर अनाज निकालने तथा कृषि फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में इनका बहुतायत में काम आता है। इन पशुओं के कारण ही किसानों को अधिक मशीनों एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती। ये पशु निरन्तर कार्य करते रहते हैं। इस कारण मशीनों के रखरखाव में आने वाली समस्याओं से किसान बचा रहता है। इन पशुओं का गोमूर कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आदान होता है इस खाद को अन्य रासायनिक खादों की अपेक्षा उत्तम माना जाता है। पशुओं के गोबर के अतिरिक्त उनकी हड्डियाँ व खून आदि भी खाद का कार्य करते हैं। इन पशुओं से प्राप्त खाद का प्रयोग करने में सिंचाई की आवश्यकता रासायनिक पदार्थों खादों की अपेक्षा कम होती है। यह खाद भूमि की उर्वरता को भी बनाये रखती है।

5 पौष्टिक पदार्थ (Nutrition) - राजस्थान के अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं। इस कारण पशुओं से प्राप्त होने वाले पौष्टिक पदार्थ जैसे - दूध, दही, घी आदि का महत्व बढ़ जाता है। शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ विषम हैं, वहाँ इन पौष्टिक पदार्थों का महत्व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। ये पौष्टिक पदार्थ मनुष्य को मनुष्यता आहार उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ अधिकांशतः मोटे अनाज का प्रयोग किया जाता है उन क्षेत्रों के लिये पशु उत्पाद प्रोटीन के अन्तर्

स्रोत सिद्ध हुए हैं। खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति में पशुओं में प्रायः अनेक पदार्थ जैसे दूध, मांस व अण्डे आदि खाद्यान्नों के विकल्प का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान के लोगों को स्वस्थ बनाये रखने में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

■ चमड़ा, खाल व ऊन आदि (Hides Skin & Wool) - राजस्थान में पशुओं की एक विशाल सख्खा विद्यमान है। साथ ही राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी सख्या में विभिन्न प्रकार के पशु पाये जाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पशुओं के आकड़ों पहले दिये जा चुके हैं। संपूर्ण राजस्थान में विभिन्न पशुओं की स्थिति के आधार पर ही इनसे प्राप्त पदार्थों का आभास मिल सकता है, उसकी समीक्षा की जा सकती है।

राजस्थान में लगभग 5.43 करोड़ पशु हैं। इन पशुओं से बड़ी मात्रा में चमड़ा, खाल एवं ऊन प्राप्त होते हैं जिनसे अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इस कार्य से जहाँ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है वहाँ विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इसके माध्यम से चमड़ा उद्योग पनपता है। चमड़े एवं खालों के चूते, पानी खींचने के घास, दस्ताने, रस्मे, दैले अटेची, कोट आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाना संभव है। उन से दुश्गाले, कबल स्वेटर गर्म कपड़े आदि बनाये जाते हैं। पशुओं से प्रायः सींग व दांतों का भी प्रयोग किया जाता है। इनके दांत बुझा आदि बनाने के काम आते हैं तो इनके सींग व हड्डियाँ बटन खाद, कपड़े धोने का सामान आदि बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार पशु जहाँ शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं वहीं स्थिति संपूर्ण राजस्थान के लिए भी है।

राजस्थान में पशु पालन की समस्याएं

तथा सुझाव

PROBLEMS & SUGGESTIONS ABOUT ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN

राजस्थान में यहाँ की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर ही पशुओं की संख्या है। यह स्थिति सरकार का पशुपालन के विकास के लिए प्रेरित करने के लिये पर्याप्त है। इस मर्म में सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं। किन्तु फिर भी राजस्थान में पशुओं की विभिन्न समस्याएँ विद्यमान हैं। इनमें से प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

1 अनर्थिक पशु (Uneconomic Live Stock) - राजस्थान के अधिकांश पशुओं की उत्पादकता इतनी कम है कि वे अपने मालिकों का बोझ बन जाते हैं। इस प्रकार के

अनर्थिक पशुओं के कारण पशुपालन व्यवसाय को भी धक्का पहुँचता है। राजस्थान सरकार ने सरकार नस्लों का विकास करके इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। राजस्थान में सरकार नस्लों के पशुओं की संख्या मुख्यतः गायों से बढ़ी है।

2 अपर्याप्त चरागाह (Lack of Grazing Lands) - राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग रेगिस्तानी है। इसके पश्चात्, काफी अधिक क्षेत्र में क्षुषि की जाती है। इस कारण ऐसे चरागाहों का अभाव है जो पूरे वर्ष भर चरागाह का काम दे सकें। पर्याप्त चरागाह न होने के कारण पशु अस्वस्थ रहते हैं। सरकार को चाहिये कि वह उन वन क्षेत्रों में, जहाँ वृक्ष पर्याप्त रूप से पनप चुके हैं तथा उन क्षेत्रों में जहाँ पशुओं से अधिक हानि होने की संभावना नहीं है, चरागाहों के लिए भूमि उपलब्ध कराये।

3 अपर्याप्त पोषाहार (Lack of Nutrient Food) - पशुओं को उचित पोषाहार उपलब्ध नहीं होता। उन्हें बहुत कम चारा उपलब्ध करवाया जाता है तथा चारे के साथ बाटा तथा पर्याप्त खनिज नहीं दिये जाते हैं। वर्षा काल को छोड़कर प्रायः उन्हें हरा चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इन सब कारणों से दूध का उत्पादन कम हो जाता है। इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार को पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना चाहिये तथा घास के अच्छे मैदान उपलब्ध कराये जाने चाहिये। हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए पशुपालकों को अपने चारे का उपचारित करने की विधि में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

4 मिश्रित फसले (Mixed Cropping) - क्षुषक अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये फसलों का चयन करता है। इस संदर्भ में वह पशुओं की आवश्यकताओं पर प्रायः ध्यान नहीं देता। उनके लिए कुछ चारा प्राप्त करने के लिए अपनी फसलों में ही कुछ और फसलों का मिश्रण कर लेता है। इस कारण उसे उत्पादन कम मिलता है और पशुओं के लिये चारा कम उपलब्ध होगा। इन फसलों के बहिर्द्वार में कुछ जहाँसे पौधे भी उग आते हैं जो कि फसल के साथ ही कट जाते हैं। इनको खाने से पशुओं का हानि पहुँचती है। अनेक बार अज्ञानवशात् कुछ ऐसे पौधे पशुओं को खिला दिये जाते हैं जो उन्हें फसल की प्रारम्भिक अवधि में नहीं खिलाने चाहिये। उदाहरण के लिये - छोट्टी अवस्था में ज्वार के पौधे खिलाना पशुओं के लिये फायदादाक सिद्ध हो सकता है और यहाँ तक कि उनको मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मजरा को सचेत कि वह मिश्रित फसलों को उचित रूप से चारा के मध्य सम्मिलित करे, जिससे एक ओर तो उनकी आवश्यकता पूरी हो सके और दूसरी ओर पशुओं को पर्याप्त

पौष्टिक तारा उपलब्ध हो सकेगा।

5 पशु स्वास्थ्य (Animal Health) राजस्थान में पशु सामान्यतः अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अधिकांश पशु अमृतुलित भोजन के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं। अमृतुलित पोषण के कारण कार्रोहाइडेट और प्रोटीन का संतुलन नहीं बना रह पाता। इस कारण पशुओं के खून में कीमती नामक पदार्थ की मात्रा घट जाती है और वह बीमारी में ग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार केवल सूजा चारा खाने रहने से भी वह स्वस्थ नहीं रह पाता। पशु को प्रायः चुला छोड़ दिया जाता है और वे अनेक प्रकार की अव्यक्ति वस्तुओं को खा कर रोगग्रस्त हो जाते हैं। इन सब समस्याओं का समाधान पशुपालकों में जागृति उत्पन्न करना एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है।

6 वैज्ञानिक प्रबंध का अभाव (Lack of Scientific Management) राजस्थान में पशुपालक पशुओं का पालने समय प्राथमिक दृष्टिकोण में न गाने वाले कारण है कि उन्हें पशुओं में संबंधित पूरा विज्ञान प्राप्त नहीं होता। पशुओं में आय प्राप्त करने के लिए कितनी लागत आ रही है इसका भी उन्हें पूरा आभास नहीं होता। वे अनुत्पादक पशुओं को भी निरन्तर अपने पास रखते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यावसायिक नहीं होता। वैज्ञानिक प्रबंध का अभाव में अप्रत्यक्ष अधिक हानि है और आय कम हो जाती है। पशुपालकों में इस सदर्थ में रति उत्पन्न करने के लिए पशुपालन विभाग का कर्मचारी व अधिकारियों को पशुपालकों से आविश्कार संपर्क करना चाहिये।

7 निर्धनता एवं अशिक्षा (Poverty & Illiteracy) राजस्थान में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत में पशुपालनक अप्रगति निर्धारण का कारण है। इस कारण वह इस क्षेत्र में हानि जान परिचरिता से भोजन बनाये नहीं रख पाता और तब हानि के कारण उसे पशुओं की पर्याप्त रक्षा के बारे में जानकारी नहीं मिलती। पशुओं का रख रखाव की वैज्ञानिक विधियों से उसका परिचय नहीं होता। वह शरीर की रक्षा के लिए जो आवश्यक है उसे नहीं करता। इस प्रकार की परिस्थितियाँ पशुपालन को नुकसान पहुँचाती हैं। सरकार को चाहिये कि वह पशुपालकों को पर्याप्त जितनी महत्त्वपूर्ण प्रदान करे साथ ही उचित पशुपालनका को अपने स्तर पर समुचित शिक्षा देकर स्वस्थ।

8 सरकार के कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ न मिलना (Lack of full use of Govt. Programme) सरकार पशुपालन व सदर्थ में जो शर्तें एवं अनुसंधान कार्य करवाता है वह बहुत कम समय तक पशुपालकों तक नहीं

पहुँच पाते। इसी प्रकार सरकार पशुपालकों के लिए पशुपालन विभाग हेतु जो योजनाएँ बनाती है उनकी जानकारी भी पशुपालकों को नहीं होती। कुछ प्राथमिक पशुपालक ही इन योजनाओं का लाभ उठाते रहते हैं जबकि एक बहुत बड़ी संख्या इन सुविधाओं से वंचित रहती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को अपने कार्यक्रमों का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना चाहिये।

9 सहकारिता का अपर्याप्त विकास (Under Development Co-operatives) राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका अत्यंत सीमित रही है। यदि दूध व चित्रण का छोड़ दिया जाये तो सहकारिता की भूमिका नगण्य भी हो जाती है। सामूहिक रूप में आर्थिक आधार पर एक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के नियम संचालित की नहीं आया गया। इस समस्या का समाधान पशुपालकों में सहकारिता का भाव और शक्ति का विकास करना है। यह कार्य संगठन और प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है।

10 कम उत्पादकता (Low Productivity) राजस्थान में पशुओं की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम है। यदि राजस्थान की तुलना विदेशों से की जाय तो उत्पादकता बहुत ही कम प्रतीत होगी है। इसका कारण पशु के स्वास्थ्य एवं पोषण पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना, नस्ल सुधार की विशेष प्रेरणा न देना तथा इस सदर्थ में शोध एवं अनुसंधान का अभाव होता है। कम उत्पादकता का प्रवृत्ति का बदलने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से पशुपालकों की मनोवृत्ति का बदलना होगा।

11 सूखा एवं अकाल (Drought and Famine) राजस्थान में आमतौर पर वर्षा होती है अतः राज्य के अधिकांश क्षेत्र में प्रायः सूखा एवं अकाल का स्थिति नहीं रहती है। सूखा एवं अकाल व क्षति के पशु तारक पालन की तलाश में राज्य के अन्य जिलों में चले जाते हैं। जल व चारे के अभाव में अनेक पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के कारण भी ओर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इस समस्या का समाधान पशुपालकों को यह शिक्षा देना है कि सूखापस्त क्षति में पर्याप्त जोर एवं चार का व्यवस्था की जाय।

12 उत्पादन एवं वितरण में समन्वय न होना (Lack of Co-ordination between Production & Distribution) पशुओं में मुख्यतः दूध प्राप्त होता है। इन वस्तुओं का संग्रहित विभाग का अभाव होता है। उत्पादन व वितरण शीघ्र से दूध सभ्य पर निर्भरता सम्बन्ध पर निर्भरता पाता अतः

दूध का खराब होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है जिससे पशुपालकों का हानि उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में पशुओं से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन व वितरण में समुचित समन्वय स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

13 पशु आधारित उद्योगों की कमी (Lack of Animal Based Industries) - राज्य में पशु आधारित उद्योगों का एक विकास नहीं हो पाया है। अनेक पशुओं से प्राप्त वस्तुओं की प्रायः कच्चे रूप में ही देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। इससे पशुपालकों को अपेक्षाकृत कम मूल्य प्राप्त होता है। राजस्थान सरकार का पशु आधारित उद्योगों के विकास पर पर्याप्त बल देना चाहिए ताकि पशुपालकों की आय व राज्य की आय में वृद्धि हो सके।

राजस्थान में कुक्कुट पालन

POULTRY IN RAJASTHAN

यह पशुपालन विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राजस्थान में कुक्कुट सम्पदा का सुनियोजित एवं आदर्श ढंग में विकास दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि 1983 की अन्वया 1988 में जब अधिकांश पशुओं की संख्या कम हुई तो उस समय भी कुक्कुट सम्पदा में वृद्धि अर्जित की गई। राजस्थान में कुक्कुट विज्ञान के लिए स्वतंत्रता व पर्याप्त भी निराश प्रयास किये गये। 1960 में जयपुर और अजमेर में राजकीय कुक्कुट शालाओं की स्थापना की गई। इस समय तक आधुनिक तरीकों में कुक्कुटपालन नहीं करके घरों में थोड़ी-बहुत मुर्गियाँ पाली जाती थीं इसी कारण अण्डों का उत्पादन सीमित था। 1960 के दशक में उन्नत किस्म की नस्लों का पालन शुरू किया गया और कुक्कुट सम्पदा निरन्तर बढ़ने लगी। राजस्थान में कुक्कुट सम्पदा का निराम निम्न तालिका में दृष्टिगोचर होता है।

राजस्थान की कुक्कुट सम्पदा (लाख में)			
वर्ष	मछली	वर्ष	मछली
1966	1.65	1983	22.12
1972	12.90	1988	25.85
1977	15.35	1992	29.86
		1997	43.80

स्रोत: Board of Revenue for Raj. Livestock Census 1997 & Statistical Abstract

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुक्कुट सम्पदा में निरन्तर वृद्धि हो रही है एवं उन्नत किस्म की मुर्गियाँ का पालन कर प्रचुर वट रही हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुक्कुट सम्पदा का स्तर निम्न दृष्टि से अजमेर जिले में माथेरा कुक्कुट सम्पदा विज्ञान है। सर्वोच्च

उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ अजमेर जिले में और सर्वाधिक देशी मुर्गियाँ बागवाड़ा जिले में हैं। देशी मुर्गियों की दृष्टि से उदयपुर का दूसरा श्रीगणेशपुर का तीसरा और झुगरपुर का चौथा स्थान है। उन्नत नस्ल की मुर्गियों की दृष्टि से उदयपुर का दूसरा, भीलवाड़ा का तीसरा, जयपुर का चौथा और अलवर का पाँचवा स्थान है। राजस्थान में 1983 की कुक्कुट सम्पदा 22.12 लाख में 25 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्राप्त हो रहा था। 1988 में 25.85 लाख मुर्गियों में 61.92 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्राप्त हुआ। यह आंकड़े कुक्कुट सम्पदा की नस्लों में अपेक्षित सुधार की ओर संकेत करते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में बाँयलर (मम के लिए मुर्गीपालन) के उत्पादन में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। बड़े-बड़े शहरों के आसपास बाँयलर पालन का महत्व बढ़ता जा रहा है। बाँयलर की निरन्तर बढ़ती हुई माँग की दृष्टिगत रखते हुये राज्य की चार कुक्कुट शालाओं में बाँयलर की उन्नत नस्ल के एक-दिवसीय चूड़ा का उत्पादन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में भी यह उत्पादन आरम्भ किया गया है।

राजस्थान निर्माण के समय राज्य में कवल एक ही कुक्कुटशाला जयपुर में कार्यरत थी। अजमेर राज्य के राजस्थान में वितरण के साथ 1956 में इसमें और एक कुक्कुट शाला जुड़ गई। राजस्थान में जयपुर और अजमेर का कुक्कुट शालाएँ राज्य स्तरीय हैं। अजमेर कुक्कुटशाला में उन्नत नस्ल का फॉट स्टॉक और जयपुर में बाँयलर के उन्नत नस्ल का फॉट स्टॉक रखा गया है। राज्य में 4 जिलास्तरीय कुक्कुटशालाएँ अलवर, जाधपुर, कोटा और टोंक जिलों में कार्यरत हैं। इनमें से अलवर, जाधपुर व टोंक में उन्नत नस्ल का बाँयलर फॉट करके रखा जा रहा है। राजस्थान कुक्कुटशालाएँ टोंक के एक-दिवसीय चूड़ों का पालन कर बड़ा करके निजा कुक्कुटपालकों को वितरित किया जाता है। जनजाति क्षेत्रों में निजी कुक्कुट पालकों को एक दिवसीय चूड़ा पालन एवं बड़ा करके वितरित करने की दृष्टि से दो चूड़ापालन केंद्र क्रमशः झुगरपुर और बागवाड़ा में कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र के कुक्कुटपालकों को तकनीकी सेवाएँ विभिन्न व्यवस्था का मार्गदर्शन वैकल्पिक की स्वीकृति में अपेक्षित सहयोग, प्रशिक्षण तथा कुक्कुट पालकों का पर्यायन करने के उद्देश्य से 1963 में वैश्व कार्यक्रम के अन्तर्गत कुक्कुट विकास खण्डों की स्थापना की गई। राज्य के जयपुर अलवर झुगरपुर टोंक सर्वाई माथेरा कोटा, जाधपुर पाली, उदयपुर अजमेर, भीलवाड़ा, बागवाड़ा, श्रीगणेशपुर आबू रोड (मिठाही) और बीकानेर में मम कुक्कुट किसान छांड कार्यरत हैं। व्यावर (अजमेर) में एक नया विकास छांड तथा झुझू में दो प्रयोग के रूप में

कुक्कुट पालन केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। विज्ञान खण्डों के माध्यम से कुक्कुटपालकों को चूजों के रख-रखाव उनके पालन-पोषण, टीकाकरण आदि की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर कुक्कुट सम्पदा के सर्वेक्षण एवं विवास के लिए गोष्ठियों का आयोजन करके कुक्कुटपालकों का नवीनतम जानकारी दी जाती है।

राजस्थान में अण्डों और कुक्कुट पक्षियों के विपणन का कार्य सम्पादित करने के लिए जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा एवं अजमेर में सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं। राजस्थान वर्तमान में 10 से 12 अण्डे प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष प्राप्त करता है। द्रवित राष्ट्रीय लक्ष्य 23 अण्डे प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। इससे राजस्थान में कुक्कुट विकास की भावी सम्भावनाओं का ज्ञान होता है। कुक्कुटपालन के माध्यम से लोगों को प्रोद्युक्त आहार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1965-66 में राज्य सरकार द्वारा पदायत समितियों के माध्यम से एवं ग्रामीणों के सहयोग से पोषाहार कार्यक्रम का अतगत् कुक्कुट शालाएँ स्थापित की थीं अब केवल ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डार (जोधपुर) में ही यह कार्यक्रम चल रहा है। इस केन्द्र से स्कुली बच्चों और गर्भवती माताओं को अण्डों का वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग के आधार पर सन् 1976 में राजस्थान के दो जिलों उदयपुर व अजमेर में विशिष्ट पशुधन उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से 200 मुर्गियों को इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य है। 1981 में जयपुर एवं टोक में फायलट राजेक्ट का स्वीकृति प्राप्त हुई जिस 1983 से क्रियान्वित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का चयन करके 200 मुर्गियों की कुक्कुटशाळा के लिए ऋण एवं अनुदान दिलवाया जाता है। इस योजना में लघु मोमान्त एवं भूमिहीन व्यक्ति को चयन करके प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्व-रोजगार के अतगत् भी 500 मुर्गियों की इकाई या 850 ब्रॉयलर चूजों से कुक्कुटशाला स्थापित करने का प्राक्धान है।

ग्रामीण कुक्कुट सम्पदा के मजबूत एवं विकास की विभिन्न योजनाएँ जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। सन् 1974 में एक मिलियन जाव ग्रामों के अन्तर्गत बेरोजगार स्नातकों को जावनयापन के लिए कुक्कुटपालन व्यवसाय प्रारम्भ करने के उद्देश्य में राज्य के जयपुर व कोटा में भूखंडों का आवंटन किया गया तथा देशों में ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर कुक्कुट शाळाएँ स्थापित की गईं। कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न

रोगों की रोकथाम के लिये जयपुर में एक राज्य स्तरीय रोग निदान केन्द्र है। कुक्कुटपालकों को सुविधा के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रोग-निदान, जाव आदि के लिए प्रयोगशाला विद्यमान है। कुक्कुटपालकों को प्रशिक्षण देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। नियमित कुक्कुट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से अजमेर में एक विज्ञानालय कार्यरत है।

कुक्कुट पालकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण 3 दिवसीय 10 दिवसीय तथा एक माह के होते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुट विकास एवं उससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं सुधार के लिए उत्पादन सर्वेक्षण की प्रक्रिया निरन्तर अपनाई जाती है। इस सर्वेक्षण के आधार पर भावी नीतियाँ एवं कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं।

वर्तमान में बतखपालन भी कुक्कुटपालन का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बतखपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सहयोग से बासवाड़ा में बतख चूजा उत्पादन केन्द्र की स्थापना का निश्चय किया है। इसके स्थापित हो जाने पर चूजा उत्पादन फार्म, हिसार गढ़वा (बगलौर) पर राजस्थान की निर्भरता लगभग सम्पन्न हो जावेगी। राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मत्स्य जलक्षेत्र उपलब्ध है। उन्हीं क्षेत्रों में बतख पालन व्यवसाय अच्छा पनप सकता है। इसके लिए कैम्पवैल नस्ल की खाकी बतखें अण्डों के उत्पादन की दृष्टि में लाभदायक मानी जा रही हैं जो कि एक वर्ष में 300 और इससे अधिक अण्डे देती हैं। राज्य के डुंगरपुर, बासवाड़ा, चित्तौड़गढ़, आनूगेड (मिरोर) एवं उदयपुर के जनजाति क्षेत्रों के निरर्थन परिवारों की पाच मादा एवं नर पक्षी बड़ा करके उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 1987-88 में चल रहा है।

राजस्थान में मत्स्य पालन

FISHERIES IN RAJASTHAN

प्राचीनकाल से ही मत्स्य उद्योग का प्रचलन रहा है। राजस्थान व महाभारत युगों में तो मत्स्यो अत्यधिक सम्पन्न थे। मत्स्यपालन व्यवसाय का समाज में एक विशिष्ट स्थान था। यह तथा मत्स्य उद्योग की उन्नति का परिचायक है। सम्राट अशोक के समय में शिलालेखों से भी स्पष्ट होता है कि भारत में मत्स्य उद्योग को विरोध मान्यता प्राप्त थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मत्स्यपालन व्यवसाय का

उत्पादक मिला है। दैनिक सामाजिक जीवन में मत्स्य की अत्यधिक माँग थी। भारत नदियों का देश है। अतः अनार स्थानीय जल संधन का आधार पर इस उद्योग का व्यापक प्रसार हुआ है। देश का लगभग 5000 किलोमीटर किन्तु समुद्र तट मत्स्य व्यवसाय में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। परिणाम बंगाल बिहार उड़ीसा आदि राज्यों में मत्स्य व्यवसाय का पर्याप्त विकास हो चुका है। राजस्थान में भी जहाँ जलसंध उपलब्ध है वहाँ मत्स्य व्यवसाय निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य में मछली उत्पादन में वृद्धि कर रहा है। इस उद्योग का पूर्ण विकास करने के उद्देश्य में 1982 में मत्स्य निगरालय का स्थापना की गई है।

राजस्थान में कृषि का अभाव है। अतः इस राज्य में मत्स्यपालन व्यवसाय अन्य राज्यों की तुलना में कम विकसित है। यहाँ का उपलब्ध जलक्षेत्रों का उपयोग कर इसका बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं। राज्य का आदिवासी क्षेत्र में मत्स्यपालन व्यवसाय का एक अदृश्य उद्योग का रूप में अपनाया जा चुका है। लेकिन अभी तक अभी तक इसका विकास करना बाकी है। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात् इस उद्योग के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना प्रारम्भ किया। राज्य में मत्स्यपालन सहाय विकसित तकनीक का अभाव रहा है। अतः मत्स्य वैज्ञानिकों का दायित्व है कि वे राज्य के निम्न कमजोर एवं जनजाति वर्गों के उत्थान के लिए मत्स्य उद्योगों का नवान तकनीक एवं ज्ञान प्रदान करके इसे एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करें। राजस्थान में वर्षापात रहने वाला नदियाँ एवं जलमाता का अभाव है लेकिन सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन तथा पर्याप्त दायित्व का अभाव निर्मित विभिन्न जलशयों में नदियों का बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न सिंचाई योजनाओं आ इतिहासों में नहर परियोजना तथा बाढ़ क्षेत्रों में उपलब्ध नहरों पानी का मत्स्यपालन के लिए उपयोग किया जा सकता है। राज्य में मत्स्यपालन व्यवसाय के क्रमिक विकास हेतु विभिन्न जिला में मत्स्यपालन विज्ञान अभिवर्गों का स्थापना की गई इन क्षेत्रों में राज्य में मत्स्य व्यवसाय के विकास की गति तेज करने का उद्देश्य है।

राजस्थान में मत्स्य उत्पादन Fish Production in Rajasthan

मत्स्य उत्पादन हेतु राजस्थान में कुल 725 जलशय हैं। इनमें 71 अश्वी, 12 अश्वी तथा 12 अश्वी के

जलाशयों का मुख्य क्रमशः 82 88 तथा 555 है। वर्षों के अभाव के कारण राज्य के अनेक जलाशय सूख जाते हैं। अतः मछली उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से कमी हो जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 1988 89 में पूर्व निरंतर 3-4 वर्षों तक अश्वी व सूख की स्थिति के कारण मई 1988 में राज्य के बड़े-बड़े जलाशय सूख गये थे। इनमें रामगढ़ व त्रवाई बांध जैसे जलाशय भी सम्मिलित थे। अश्वी व सूख की स्थिति के कारण 1988 में राज्य के मत्स्य उत्पादन में अत्यधिक कमी हो गई। मत्स्य द्वारा 1988 89 में मत्स्य विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये। अतः 1987 88 की तुलना में 1988 89 में मत्स्य उत्पादन में मछली तीन गुना वृद्धि हुई। 1990 91 में सरकार द्वारा लाज पद्धति में अनेक सुधार किये गये। केवल अश्वी के 63 जलाशयों का लाभ पर दान से ही सरकार को 1 89 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

राजस्थान में 1990 91 के अर्धवर्ष 6020 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। 1995-96 में दिसम्बर 1995 तक 6000 मेट्रिक टन का ही उत्पादन हुआ।

राजस्थान में मत्स्य उत्पादन हेतु जलाशय Reservoirs for Fish Production in Rajasthan

राजस्थान में वृहद् जलाशय चित्तौड़गढ़ जिला में रामगढ़ जलाशय, बसवाड़ा जिला में उदयपुर जिलों में पाये जाते हैं। मध्यम जलाशय मुख्यतः पाली, धौलपुर, भाजवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूढ़ा टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर व भरतपुर जिलों में हैं। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के कुछ प्रमुख जलाशय व उनके जल पैदाद क्षेत्रफल के अनुसार निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है।

- (1) अश्वी के सर्वाधिक जलाशय उदयपुर जिले में है। तत्पश्चात् क्रमशः सवाईमाधोपुर व चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं।
- (2) 'ब' श्रेणी के सर्वाधिक जलाशय बूढ़ा टोंक जिले में है तथा 'सा' श्रेणी के सर्वाधिक जलाशय टोंक जिले में है।
- (3) 'सा' श्रेणी के सर्वाधिक जलाशयों का मुख्य पाली जिले में है। तत्पश्चात् उदयपुर व राजसमन्द का स्थान है।
- (4) राजस्थान के प्रमुख नदी-बेसिन चवक, बानस और लूनी में सबह है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- राजस्थान में पशु पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Animal Husbandry in Rajasthan
- राजस्थान में पशु पालन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
Describe the salient features of live stock census in Rajasthan
- राजस्थान में पाई आन वत्ती, गौ वरा की चार महत्वपूर्ण नस्लें बताईए तथा वे कहाँ पाई जाती हैं।
Name four famous breeds of cattle in Rajasthan and area where they are found?
- राजस्थान के लिए पशुधन का महत्व पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
Write short note on economic importance of cattle wealth for Rajasthan
- राजस्थान में पशुधन की वर्तमान स्थिति बताईए।
Mention the present position of live stock in Rajasthan
- राजस्थान में पशुधन का जिलास्तरीय वितरण बताईए।
Explain the district wise distribution of live stock in Rajasthan
- राजस्थान में कुक्कुर पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Poultry in Rajasthan
- गोपाल योजना क्या है?
What is Gopal Yojna?
- राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क भागों में पशु सम्पदा का महत्व स्पष्ट कीजिए।
Explain the importance of Animal Husbandry in the special reference of arid and semi arid regions of Rajasthan
- राजस्थान में मत्स्य पालन पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on fisheries in Rajasthan

B निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान में पशु पालन के महत्व पर शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में प्रकाश डालिए।
Explain the importance of Animal Husbandry in the special reference of arid and semi arid regions of Rajasthan
- राजस्थान में शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क भागों में पशुधन क्यों महत्वपूर्ण है और भेड़ एवं बकरी पालन की क्या समस्याएँ हैं?
Why live stock is important in arid and semi arid regions of Rajasthan and what are the problems of sheep and goat Husbandry?
- ग्राम आधार योजना व गाँव आधारित विकास के विशेष संदर्भ में पशुधन विकास में राजस्थान सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए।
Discuss the efforts of Govt. of Rajasthan for the development of live-stock in the context of Gopal Yojna and village base programme
- राजस्थान में पशुधन के विकास की समस्याएँ क्या हैं? पशु पालन के विकास में सरकार ने क्या कदम प्रयत्न किए हैं? इनके समाधान के सुझाव दीजिए।
What are the problems of live-stock development in Rajasthan? What efforts are made for the development of livestock by the Govt. of Rajasthan? Give suggestions for the solution of the problem
- राजस्थान राज्य में पशुधन विकास के लिए अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
Describe the different programme adopted in state of Rajasthan to improve the live stocks
- पशुधन विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए।
Describe the programme adopted for the development of live stock in Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

- राजस्थान में शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन का महत्व स्पष्ट कीजिए। राज्य में पशुधन की समस्याएँ क्या हैं? इनके समाधान के सुझाव दीजिए।
Explain the importance of Animal Husbandry in arid and semi arid regions of Rajasthan. What are the reasons for inferior condition of cattle wealth in the state?

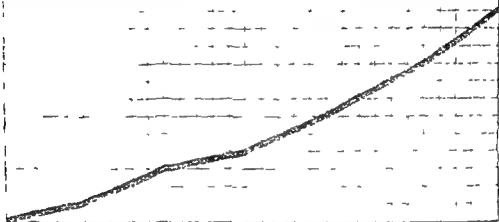
- 2 राजस्थान में पशुधन की वृद्धि की स्थिति को स्पष्ट कीजिए तथा यहां के शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पशुधन वृद्धि के क्या कारण हैं? स्पष्ट कीजिए।
Explain the position of Growth of live stock in Rajasthan. What are the reasons for the growth of live stock in the arid and semi-arid regions of Rajasthan?
- 3 राजस्थान में पशुपालन की समस्याओं पर भेड़-बकरी पालन की विशिष्ट समस्याओं सहित प्रबन्ध डालिए।
Give a focus on the problems of Animal Husbandry with special context of sheep and goat problems in Rajasthan
- 4 राजस्थान में पशुधन की संरचना पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on the structure of live stock in Rajasthan
- 5 राजस्थान में पशुपालन की संरचना पर एक निबन्ध लिखिए।
Critically analyse the steps of Govt. for the development of Animal Husbandry in Rajasthan
- 6 राजस्थान में पशुओं की हीन दशा का कारण को बताईए। राजस्थान सरकार द्वारा पशुवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत इनके लिए किए गए कार्यों का विवरण दीजिए।
Explain the reasons for the inferior conditions of cattle wealth in Rajasthan. Describe the programmes adopted by the government in various plans to improve their conditions



अध्याय - 11

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम

DIARY DEVELOPMENT PROGRAMME IN RAJASTHAN



“दूध सप्लाय और का एक कार्यक्रम 1971”

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में डेयरी विकास का पृष्ठभूमि
- राजस्थान के डेयरी मजदूर
- राजस्थान के पशु आटा मजदूर
- दूध दुध सप्लाय और राजस्थान सरकारों परियोजना
- डेयरी विकास में सहायक प्रमुख कार्यक्रम
- आठवीं व नवें दशक में डेयरी विकास
- राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएँ व समाधान के उपाय
- अन्तर्गत प्रश्न

उचित मूल्य दिलाना है। साथ ही उपभोक्ताओं तक अच्छे दूध का वितरण सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। ऑपरेशन फ्लड को आनन्द सहकारी सघ से प्रेरणा लेकर आरम्भ किया गया। यह सम्पूर्ण भारत में डेयरी के विकास हेतु एक समन्वित योजना है।

राजस्थान में डेयरी विकास अथवा श्वेत क्रांति की पृष्ठभूमि

BACKGROUND OF DAIRY DEVELOPMENT OR WHITE REVOLUTION IN RAJASTHAN

ऑपरेशन फ्लड ने सम्पूर्ण भारत में श्वेत क्रांति और डेयरी विकास की नींव रखी। भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 10 राज्यों में 117 करोड़ रुपये व्यय करके आरम्भ किया। इन दस राज्यों में राजस्थान भी एक है। अतः ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण से राजस्थान में भी श्वेत क्रांति और डेयरी विकास की नींव रखी गयी। 1978 में भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण आरम्भ किया जिसमें विश्व बैंक की सहयता से पशु व डेयरी विकास योजनाएँ चलाई गईं। इस समय ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण सफलतापूर्वक चर्याविष्ट किया जा चुका है। राजस्थान को दस परियोजना का पूरा लाभ मिला है क्योंकि इस राज्य में डेयरी विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पहले से ही विद्यमान था। राजस्थान में लगभग 5 करोड़ पशु हैं और पशुधन की दृष्टि से भारत में इसका तीसरा स्थान है। उत्पादक पशुओं की दृष्टि में देखा जाये तो राजस्थान का देश में छठा स्थान है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से राजस्थान को डेयरी विकास का पर्याप्त अवसर मिला। राजस्थान में डेयरी विकास को गति देने के लिए 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। राज्य में डेयरी विकास का कार्यक्रम गुजरात में आनन्द के अनुभवों के आधार पर चल रहा है। इस कारण राजस्थान में ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक महासंघी समिति है। ये समिति जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी परिमण्ड के सदस्य होती है। सभी जिला सहकारी सघ राज्य स्तर के राजस्थान सहकारी डेयरी परिमण्ड के सदस्य होते हैं। इस प्रकार राज्य में सभी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध होती हैं। राजस्थान में डेयरी विकास को गति देने में ऑपरेशन फ्लड के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय दुग्ध मिड को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण राजस्थान में उत्पादित अतिरिक्त दूध आसानी से देश के

अन्य क्षेत्रों में इस मिड के माध्यम से भेजा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा डेयरी विकास के लिए गठित टेक्नोलॉजी मिशन भी राजस्थान में डेयरी विकास को प्रोत्साहित करता है। इस मिशन का उद्देश्य डेयरी उद्योग की क्षमता का अधिक से अधिक दोहन करना है। इसलिए डेयरी उद्योग में प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की आवश्यकता को देखते हुए यह मिशन आरम्भ किया गया। इस मिशन के अन्तर्गत देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सहकारी दूध परिमण्डों आदि की गतिविधियों में समन्वय लाने की चेष्टा की जा रही है। इस प्रयास के बाद जो नई तकनीक विकसित होगी, उसका मानकीकरण किया जायेगा और इस तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी से सम्बन्धित लोगों तक पहुँचाया जायेगा। इस प्रयास से राजस्थान के डेयरी विकास को बल मिलेगा। राजस्थान में डेयरी विकास का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है

- (अ) राजस्थान के डेयरी बंदर
- (ब) राजस्थान में पशु अन्न सघ
- (ग) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ एवं राजस्थान सहकारी डेयरी परिमण्ड
- (द) डेयरी विकास में सहायक शुल्लक कारक
- (ए) अतृतीय क्षेत्र में डेयरी विकास के प्रयास
- (१) डेयरी विकास की समस्याएँ व समाधान के उपाय

राजस्थान के डेयरी संयंत्र

DAIRY PLANTS IN RAJASTHAN

दिसम्बर, 1997 तक राजस्थान में 10 डेयरी सयंत्र कार्य कर रहे थे। ये अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, गंगोबाड़ा व उदयपुर में स्थित थे। राजस्थान में दूध को सुखाने की सुविधा अजमेर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जालौर व जोधपुर में उपलब्ध थी। राजस्थान के डेयरी सयंत्रों की कुल विधायन क्षमता 9 लाख लीटर दूध प्रतिदिन विधायन करने की थी। इनकी कुल अवशोषण क्षमता 4.8 लाख लीटर दूध ठण्डा करने की थी। राजस्थान में दूध को सुखाने की कुल क्षमता 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की थी। राजस्थान में 25 अवशोषण केन्द्र थे। राजस्थान के डेयरी सयंत्रों के सदस्यों में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार राजस्थान में स्थानीय माग की अपेक्षा अधिक दूध एकत्र होता है। इस दूध का लगभग 1/4 भाग राष्ट्रीय दुग्ध मिड हेतु दिल्ली भेज दिया जाता है। राजस्थान

पास दौड़ा, मालपुरा, कोटपूतली और गणपुर सिटी में नार अवशीतन केन्द्र है। इस दूध में से अधिकतर दूध स्थानीय बाजार में ही विप्रेय कर दिया गया। राजस्थान में इस डेयरी सयत्र की स्थानीय माग सर्वाधिक है। इस सयत्र द्वारा लगभग सभी प्रकार के प्रचलित दूध उत्पाद निर्मित किए जाते हैं।

7 जोधपुर डेयरी सयत्र (Jodhpur Dairy Plant) : 'स डेयरी सयत्र की स्थापना 1975-76 के वित्तीय वर्ष में की गई। इसकी क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध प्राप्त करने की है। इसे जोधपुर सयत्र द्वारा दूध प्राप्त होता है। इसके पास पोल्कप, नागौर, मेड़ता सिटी बाडमेर, बालोतरा, और फलौद में 6 अवशीतन केन्द्र है। जिसमें से अधिकतर दूध का उपयोग स्थानीय माग का पूरा करने के लिए किया गया। इस सयत्र में विभिन्न प्रकार के दूध उत्पादन भी निर्मित होते हैं।

8 कोटा डेयरी सयत्र (Kota Dairy Plant) : इस सयत्र की स्थापना 1984 में हुई। इसकी दूध प्राप्ति की क्षमता ववल 0.25 लाख टन प्रतिदिन की है। यह कोटा दुध सयत्र में प्राप्त करता है। इसके पास कोई अवशीतन केन्द्र नहीं है। जिसका प्रयोग मुख्यतः स्थानीय माग के लिए किया गया। इसमें सभी प्रमुख प्रकार के दूध उत्पादन निर्मित किए जाते हैं।

9 रानीवाडा डेयरी सयत्र (Raniwara Dairy Plant) यह सयत्र 1986 में निजी व्यक्तियों से प्राप्त किया गया। इसकी क्षमता 0.5 लाख लीटर दूध प्राप्त करने की है। यह जालौर व पाला दुध सयत्रों में दूध प्राप्त करता है। इसके पास फाल्ता में एक अवशीतन केन्द्र है। यह अनेक प्रकार के दुध उत्पाद भी बनाता है।

10 उदयपुर डेयरी सयत्र (Udaipur Dairy Plant) इस सयत्र का स्थापना 1983 में की गई। इसकी क्षमता मात्र 0.25 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकर करने की है। यह उदयपुर और बामवाडा दुध सयत्रों से दूध प्राप्त करता है। इसके पास बामवाडा व झारपुर में दो अवशीतन केन्द्र हैं। इस सयत्र की स्थानीय माग इनके द्वारा एकर दूध की तुलना में अधिक है। यह अनेक प्रकार के दूध उत्पादों का निर्माण भी करता है।

राजस्थान में पशु आहार संयंत्र ANIMAL FEED PLANTS IN RAJASTHAN

राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक है कि पशुओं को पोषक तत्वों से युक्त आहार व चागा मिले। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में 4 पशु आहार सयत्र लाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी इस दृष्टिकोण में प्रयास किए हैं। वैज्ञानिक विधि से चारा उत्पादन को तकनीक विभिन्न ढंग के लिए देश के विभिन्न जलद्वय

वाले प्रदेशों में खात क्षेत्रीय केन्द्र खोले गये हैं, इनमें से एक राजस्थान के मूरतगढ़ में है। केंद्र सरकार चारे के अच्छी किस्म के प्रमाणित बीज विकसित करने के अतिरिक्त गावों में उनके प्रदर्शन का योजना भी बना रही है। इस प्रकार राजस्थान में केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रयास से उद्युक्त पशु आहार पर्याप्त मात्र में उपलब्ध हो सभाव्य है। राजस्थान में पशु आहार के क्षेत्र में य सयत्र कार्य कर रहे हैं।

1 झोटवाडा (जयपुर) पशु आहार सयत्र [Jhotwara (Jaipur) animal feed plant] यह सयत्र 1 अग्रेन, 1978 को लॉन्च पर लिया गया। नवंबर 1988 में इस सयत्र को राजफेड (RAJFED) को हस्तांतरित कर दिया गया। इस सयत्र की पशु आहार निर्मित करने की क्षमता 40 मेट्रिक टन प्रतिदिन है।

2 नदबई (भरतपुर) पशु आहार सयत्र [Nadba (Bharatpur) animal feed plant] इस सयत्र की स्थापना 1979-80 में हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेट्रिक टन प्रतिदिन है।

3 तबीजी (अजमेर) पशु आहार सयत्र [Tabji (Ajmer) Animal Feed Plant] इस सयत्र की स्थापना 1980-81 में की गई। इसकी पशु आहार उत्पादन क्षमता 100 मेट्रिक टन प्रतिदिन है। यह सयत्र U, A MOLASSES BRICK का भी उत्पादन करता है।

4 जोधपुर पशु आहार सयत्र [Jodhpur Animal Feed Plant] यह सयत्र 1982 में स्थापित हुआ। इसकी क्षमता 100 मेट्रिक टन पशु आहार प्रतिदिन निर्मित करने की है।

राजस्थान में इस प्रकार इन मनकों द्वारा पशु आहार का विविध एवं उत्पादन विभिन्न ढंगों में इस प्रकार रहा

वर्ष	पशु आहार का उत्पादन	पशु आहार का विक्रय
1987-88	83420 (मेट्रिक टन)	94695 (मेट्रिक टन)
1997-98	44795 (मेट्रिक टन)	44472 (मेट्रिक टन)

दिसंबर 97 तक)

सं. 98 Economics Review 1997-98 Rajasthan

जिला दुध उत्पादन सहकारी सघ
एवं राजस्थान सहकारी परिसंघ लि.
DISTRICT DIARY CO OPERATIVES &
RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY
FEDERATION LTD

राजस्थान में मान स्तर पर दुध सहकारी समितियाँ हैं। 31 दिसम्बर, 1997 का इनका संख्या 3797 की जितने

3 85 लाख सदस्य थे। सभी सहकारी समितियाँ राजस्थान में विद्यमान 16 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों की सदस्य हैं। ये संघ अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, गगनगर, जयपुर, जालौर - मिराही, जोधपुर, कोटा पाली भोवसर, टोंक, मवाईमाधोपुर और उदयपुर में स्थित हैं। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पशु आहार के वितरण के अतिरिक्त, पशु चिकित्सा पशु चिकित्सा हेतु चल चिकित्सालय कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, उन्नत चारे के बीजों का विक्रय, किमान व ग्राम वन आदि को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करते हैं। सभी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ राज्य स्तर के राजस्थान सहकारी डेयरी परिसर लिमिटेड के सदस्य हैं। राजस्थान में यह परिसर डेयरी विकास एवं दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष सन्स्था है। परिसर का मुख्य कार्यालय जयपुर में है।

डेयरी विकास में सहायक प्रमुख कार्यक्रम

MAIN PROGRAMMES OF DAIRY DEVELOPMENT

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों में ऑपरेशन फ्लड एवं पशु विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे हैं। इनका विवेचन इस प्रकार है

1 ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) - ऑपरेशन फ्लड विश्व में डेयरी विकास का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह आन्तरिक डेयरी सहकारी समितियों के स्वरूप का आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों एवम् शहरी उपभोक्ताओं में सम्यक् स्थापित करना है। भारत में श्वेत क्रांति का आगमन इसी कार्यक्रम के द्वारा हुआ है। इस कार्यक्रम के दो चरण पूर्ण हो चुके हैं और तीसरा चरण भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। दिसम्बर, 1990 में यह कार्यक्रम भारत के 22 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रहा था। 62800 डेयरी सहकारी समितियों के अन्तर्गत देश के 73 लाख कृषि परिवारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों में लगभग 14 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। ये समितियाँ प्रतिदिन औसतन 94.7 लाख विलोमान दूध एकत्रित करती हैं।

ऑपरेशन फ्लड I (Operation Flood I)

भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 में प्रारम्भ हुआ। भारत सरकार ने देश के 10 राज्यों में इस कार्यक्रम

हेतु 117 करोड़ रुपये व्यय किए। इन 10 राज्यों में राजस्थान भी एक है। अतः ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण से ही राजस्थान में श्वेत क्रांति और डेयरी विकास की नींव रखी गई। राजस्थान में पर्याप्त पशुधन है अतः ऑपरेशन फ्लड के द्वारा डेयरी विकास का पर्याप्त अवसर मिला है। डेयरी विकास को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान में 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना हुई। यह चरण 1981 में पूर्ण हुआ।

ऑपरेशन फ्लड II (Operation Flood II)

भारत सरकार ने 1978 में ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया। द्वितीय चरण के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से पशु व डेयरी विकास योजनाएं चालू की गईं। राज्य में यह कार्यक्रम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो जाने के पश्चात् 1980 में आरंभ किया गया। यह चरण 1985 में पूर्ण हो गया।

ऑपरेशन फ्लड-III (Operation Flood-III)

ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण राजस्थान में भी सतत योजनाकृत में क्रियान्वित किया गया। ऑपरेशन फ्लड तृतीय का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का विस्तार करना था। भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी विकास के लिए टेक्नोलॉजी मिशन प्रारम्भ किया। अतः आठवीं योजना में ऑपरेशन फ्लड III के कार्यक्रमों को टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया गया।

2 विश्व बैंक की सहायता से पशुपालन विकास (Development of Animal Husbandry with the Assistance of World Bank) राजस्थान में पशुपालन के विकास हेतु विश्व बैंक के सहयोग से एक योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के अधिकारियों ने सम्पूर्ण कृषि विकास की समीक्षा करते हुए यह अनुभव किया कि कृषि विकास के साथ साथ पशुपालन का विकास करना भी आवश्यक है अन्यथा कृषि विकास कार्य पूर्ण नहीं होगा। राजस्थान में 1983 की पशुगणना के अनुसार 496 लाख पशु उपलब्ध थे लेकिन 1985 व 1987 के अवर्षों के कारण पशुओं की संख्या घटकर 1988 में 409 लाख रह गई। 1983 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में देश का लगभग 7 प्रतिशत पशुधन उपलब्ध था। देश के दुग्ध उत्पादन में राज्य का हिस्सा 10.9 प्रतिशत था। देश के मांस उत्पादन का 40 प्रतिशत राजस्थान उपलब्ध करता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण विश्व बैंक ने राजस्थान को पशुपालन के विकास हेतु

लगभग 24 करोड़ रुपए की महायत्ता प्रदान की है। विश्व बैंक ने मुख्य पशु नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा एवं पशु कार्यकारियों के प्रशिक्षण, शिशु आदि के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने का प्रवधान किया है। यह राशि 4 वर्षों में उपलब्ध कराई जायेगी। बीकानेर पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय को 4.31 करोड़ रुपये की महायत्ता भी प्रदान की गई है। एक विशाल पशुपालन प्रशिक्षण सम्मान स्थापित करने के लिए एक करोड़ की महायत्ता भी प्रदान की गई है। पशुपालन विभाग के अन्तर्गत राज्य में 4 पशुपालन विद्यालय क्रमशः जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर में विद्यमान हैं। इन विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। अतः विश्व बैंक द्वारा पशुपालन विद्यालयों के सुदृढीकरण हेतु लगभग 1.30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। विश्व बैंक के अनुसार पशु चिकित्सा का भार मुख्यतः निजी क्षेत्र में रहना चाहिए। अतः विश्व बैंक की सहायता में निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा संस्थाएँ स्थापित करने के लिए पशु चिकित्सकों को 30 लाख रुपये उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। एक पशु चिकित्सा संस्था के लिए 50 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से "गोपाल योजना" को राज्य के प्रत्येक जिले में फैलाने की व्यवस्था की गई है। "गोपाल योजना" मधी कार्यक्रमों पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे। वृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से पशुपालन विभाग में एक योजना विश्व बैंक से स्वीकृत कराई है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर पशुपालन समिति स्तर से राज्यस्तरीय स्तर तक के स्थान पर पशुओं के क्रय विक्रय विपणन की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। विश्व बैंक ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की महायत्ता दी है। पशु चिकित्सकों की जागरूकता के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सकों को देश व विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा। इस योजना के लिए एक करोड़ रुपए का शक्यता किया गया है। विश्व बैंक ने विदेशीय स्तर से विज्ञान स्तर तक प्रचार प्रसार सामग्री व उपकरणों की व्यवस्था हेतु एक करोड़ रुपए की महायत्ता प्रदान की है।

आठवीं व नवी योजना में डेयरी विकास DAIRY DEVELOPEMENT IN EIGHTH & NINTH PLAN

आठवीं योजना में डेयरी विकास - इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्यों व व्यूह रचना का निर्धारण किया गया था।

उद्देश्य (Objects) अतः तत्पश्चात् प्रश्न किए गए लक्ष्यों को सुनिश्चित करना। अब तक विचारों की गई क्षमता का अधिवाधिक प्रसार करना। महत्त्वपूर्ण आधार को और अधिक

सुदृढ करने के लिए सहायगी मशीनियाँ, दूध मगटों और फेडरेशन को आर्थिक सहायता प्रदान करना। विभिन्न तकनीकों का आधुनिकीकरण करना। डेयरी पशुपालन और इनमें संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना लगातार में करी करना।

भारत सरकार ने डेयरी विकास हेतु टेक्नॉलॉजी मिशन प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। आधुनिक तकनीक को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करना तथा परिवर्तन लागतों में कमी करना और दूध व दूध उत्पादों की उपलब्धि में तेजी से वृद्धि करना भी इसका लक्ष्य है।

आठवीं योजना के लिए व्यूह रचना (Strategy for Eighth Plan) आठवीं योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का डेयरी व्यवस्था के साथ इस प्रकार समन्वय किया जा रहा है कि सरकारी मरवा के द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को उनका द्वारा किए गये विनियोजन का अधिकधिक प्रतिफल प्राप्त हो सके। डेयरी व्यवस्था छोटे एवं मीमांसा कृषकों को लाभदायक रोजगार प्रदान करती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्यम सहज 4.6 लाख से बढ़कर 5.60 लाख तक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डेयरी विकास के मध्य-स्थ रोजगार का प्रवर्धन एवं अत्यल्प अवसरों में भी वृद्धि हुई है। आठवीं योजना का अतः तक 50000 में अधिक जनसंख्या वाले जिला मुद्रालय पर विभिन्न डेयरी उत्पादों को वाजिब दामों पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जायेंगे। आठवीं योजना में पशु सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा। उन क्षेत्रों में जहाँ दुग्ध विधायन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई, वहाँ प्रोजेक्ट मोडल तकनीकों के द्वारा क्रॉस ब्रजन का विकास किया जायेगा। राठ, दामरका और नगीरा नस्लों की तेजी से विकास किया जायेगा। अनुसूचित जाति-बहुलता वाले दक्षिणी जिलों में पशुओं की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। डेयरी विकास कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए जनसहयोग प्राप्त किया जायेगा। विधायन सुविधाएँ अब तक फेडरेशन द्वारा सम्पन्न की जा रही हैं। इनके द्वारा उत्पादक सहकारी संघों का सम्मिलित कर दिया जायेगा। इसमें हजारों दुग्ध उत्पादक किसान सुविधाओं के स्वामी हो जायेंगे और वे दूध की प्रति उत्पादन पशु विकास और विपणन आदि के समन्वय में समुचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। चाा विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जायेगा। वर्तमान में दारुण उत्पादन आवश्यकता से कम है। अतः चाा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की जायेगी। कृषकों को निश्चित खेती की जानकारी दी जायेगी तथा बरकरार फसि में चाा की खेती पर बल दिया जायेगा। चाा के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रमोशन बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। टेक्नॉलॉजी मिशन कार्यक्रम को उन क्षेत्रों में तेजी से लागू किया जायेगा जहाँ ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम लागू नहीं

किए गये हैं। ये ये क्षेत्र हैं जहाँ परिवहन की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं अतः दूध को एकत्रित करना कठिन होता है। दूध शीघ्र नाशवान् वस्तु है अतः इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए ठण्डा रखना पड़ता है। अतः सहकारी समितियों को परिवहन एवम् शीत सुविधाओं का अभाव होने के कारण हानि उठानी पड़ती है। दुग्ध सघ एवं फैक्टरीयों भी पूँजीगत खर्चों, उँची ब्याज दरों एवं धमताओं के अपूर्ण उपयोग के कारण हानि की स्थिति में हैं। राज्य में किसी भी नये कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व ऐसी स्थितियों को समझा लिया जायेगा। अतः आठवीं योजना में डेयरी विकास के निम्न 26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

नवी योजना में डेयरी विकास (Dairy Development in 9th Plan) - नवी योजना में डेयरी प्रबन्ध को सुदृढ़ करने, तकनीकों का आधुनिकीकरण करने, दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने तथा डेयरी उद्योग को उद्यमियों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य निर्धारित किये गये। योजनाकाल में डेयरी विकास कार्यक्रमों पर 2000 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। योजनाकाल में दूध विपणन व्यवस्था पर 134 लाख रुपये, प्लांट व मशीनरी पर 350 लाख रुपये, प्रशिक्षण पर 90 लाख रुपये, पशु विकास पर 75 लाख रुपये और राजीव फार्म विकास पर 48 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

राज्य का लगभग 2/3 भाग शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में आता है। इन क्षेत्रों में श्रेष्ठ किस्म के पशुधन का विकास हुआ है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृषि की तुलना में पशुधन का विकास अधिक हुआ है। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में पशुधन का अंशदान 28% में अधिक है तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो यह और भी अधिक है। रेगिस्तानी अर्थव्यवस्था में पशु सम्पदा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अतः मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक धन के प्रावधान की आवश्यकता है।

राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएँ

व समाधान के उपाय

PROBLEMS & SOLUTIONS OF DAIRY DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

1 पशुओं से सम्बन्धित समस्याएँ (Problems Relating to Animals) राजस्थान में पशुओं की उत्पादकता कम है वही कि राज्य में अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव है। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित रहते हैं। उनकी देखभाल व आवास व्यवस्था भी निम्न स्तर की होती है। पशुओं की चिकित्सा के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सालय भी नहीं हैं। वही निर्मित वृष्टि गर्भाधान केन्द्रों के संदर्भ में भी है। इस समस्या का निवारण पशुपालकों में शिक्षा व पशुपालन के प्रति जागरूकता

उत्पन्न करके किया जा सकता है। पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था उचित मूल्यों पर की जा सकती है।

2. मूल्यों की समस्या (Problems of Prices) पशुपालन में प्रयुक्त चाय, पशु आहार निकाला व्यय आदि के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसकी तुलना में दूध के मूल्यों में उचित वृद्धि नहीं हो रही है। इस कारण पशुपालकों को पशु पालना अनार्थिक प्रतीत होता है। इस समस्या का समाधान दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्तकों की समितियाँ बनाने एवं दोनों पक्षों की राय का व्यापक मर्मबंधन कर किया जा सकता है।

3 दुग्ध उत्पादों की सीमित मांग (Limited demand of milk products) - दूध के अनेक उत्पादों की मांग केवल बड़े शहरों तक ही सीमित है। इस कारण दूध के विभिन्न उत्पादों को प्रोत्साहन नहीं मिला है। इस समस्या के लिए सम्बन्धित उत्पाद का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये तथा उनके मूल्य भी उचित होने चाहिये।

4 परिवहन की समस्या (Problem of transportation) - दूध उत्पाद केन्द्रों से दूध को डेयरी सयंत्र तक लाने में परिवहन सुविधाओं के अभाव में कठिनाई अनुभव होती है। इस कार्य के लिए जो वाहन प्रयोग में लिए जाते हैं उनके खराब होने या देरी से पहुँचने के कारण, दूध खराब हो सकता है। ऐसे वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जो अवशीतन कार्य भी कर सकें।

5 सहकारी समितियों के दर्शन को न समझना (Lack of understanding of co-operative philosophy) - राजस्थान में डेयरी विकास का आधार सहकारिता की मूल भावना के अनुरूप किया गया है। इन सहकारी समितियों की सदस्य संख्या बहुत कम है। साथ ही इसके सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों से परिचित नहीं होते। इस कारण इस व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हो गये हैं। दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों, कर्मचारियों व अधिकारियों को इससे सम्बद्ध होने से पूर्व एक अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये।

6 भ्रष्टाचार (Corruption) - इससे सम्बन्धित सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्य अनुचित तरीके अपना कर अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस कार्य में कुछ भ्रष्ट कर्मचारी भी उनका साथ देते हैं। भ्रष्टाचार, पशुपालन व राजनीति में प्रवेश में प्रबल अग्रणी हो जाता है और दोष पनपने लगते हैं। इस प्रक्रिया को तभी उल्टा जा सकता है जबकि सहकारी समितियों के सदस्य जागरूक और अपने हितों के लिए सघर्ष करने वाले हों।

7. अन्य (Others) - डेयरी सयंत्रों के अन्तर्गत अवशीतन केन्द्रों का अभाव है। इस दूर किया जाना चाहिये। जिला समी

के द्वारा दूध का उचित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये। जिला मग्न द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाये वास्तव में सभी सदस्यों तक पहुँचनी चाहिये। डेयरी से सम्बन्धित उपकरणों व

पशुओं से सम्बन्धित शोध व अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उनके लाभों को ग्रामीणों तक पहुँचाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राज्य का अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिए।
Determine the role of dairy industry in the Economy of Rajasthan
- 2 राजस्थान में श्वेत क्रांति पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on white revolution in Rajasthan
- 3 संक्षेप में राजस्थान के डेयरी मयनों का विवरण दायिए।
Describe the dairy plants in Rajasthan
- 4 ऑपरेशन फ्लड क्या है?
What is operation flood?
- 5 राजस्थान में डेयरी विकास की क्या समस्याएँ हैं?
What are the problems of dairy development in Rajasthan
- 6 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी विकास के उद्देश्य बताईए।
Explain the objectives of dairy development in Eighth Five Years Plan of Rajasthan
- 7 राजस्थान सहकारी परिसर लि. पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd

B निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 "राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Role of Dairy Industry in the Economy of Rajasthan"
- 2 "राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note "Dairy Development Programme in Rajasthan"
- 3 राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याओं तथा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
Describe the problems and achievement of Dairy Development in Rajasthan
- 4 राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए।
Explain the development, present position and problems of Dairy industry of Rajasthan
- 5 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
Describe the programmes of Dairy Development in Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

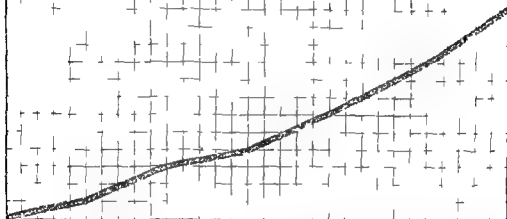
(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम पर एक लेख लिखिए। (अप्रैल 1992)
Write an essay on Dairy Development Programme in Rajasthan
- 2 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिए।
Determine the role of Dairy industry in the Economy of Rajasthan. Describe the efforts made by the State Govt. for Dairy Development.
- 3 टिप्पणी लिखिए
(i) राजस्थान में पशु आहार संयंत्र (ii) राजस्थान के डेयरी संयंत्र
Write note on (i) Animal feed plants in Rajasthan (ii) Dairy plants in Rajasthan

अध्याय - 12

राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन

SHEEP & GOAT HUSBANDRY IN RAJASTHAN



"राजस्थान में पाये जाने वाले पशुओं में आधे से अधिक भाग भेड़ व बकरियों का है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में भेड़ा व बकरियों का सटन
- भेड़ा व बकरीया का जितानुसार निरूपण
- राजस्थान में भेड़ा का प्रमुख मस्ते
- भेड़ व बकरी पालन में संबंधित विभिन्न याजनाएँ कायम व सुविधाएँ
- भेड़ व बकरी पालन का विशिष्ट समस्याएँ व मुद्दे
- अध्यात्मिक प्रश्न

राजस्थान के अधिकांश भाग में रेगिस्तान है अतः राजस्थान की शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति व जलवायु आदि भेड़ व बकरी पालन के लिए उपयुक्त है। भेड़ व बकरी पालन व्यवसाय से राज्य में अनेक व्यक्तियों का रोजगार की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह को अनेक वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं। भेड़ा में मुट्ठा उन की प्राप्ति होती है। भेड़ व बकरीया अत्यधिक बागक घास और विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में भी चराने रह सकती हैं और अपने पालकों को पर्याप्त लाभ दे सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भेड़ों से श्रेष्ठ विष्म की उन प्राप्त होता है। राजस्थान राज्य के अधिकांश भाग में ऐसा परिस्थिति पाई जाती है। यही कारण है कि राज्य के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अन्य पशुओं का अपेक्षा भेड़ एवं बकरीया अधिक मरूता में पाली जाती है। राज्य की भेड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऊत की प्राप्ति होती है। उन में केवल कपड़ा, गम कपड़े, दुग्धाले आदि वस्त्रों के लिए वस्त्र उन का निर्यात भी किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। भेड़ व बकरी पालन में राज्य के चमड़ा उद्योग का तत्त्व सविकसम हुआ है। चमड़ा व खान में वृत्त दमन रम्य धन को व अंतरिक्ष आदि अनेक प्रकार का वस्तु बनाई जाती है। राज्य में अनेक स्थान पर एका वस्तुओं बनाने के कारखाने

स्थापित किये गये हैं। राज्य से चमड़े का निर्यात भी किया जाता है। भेड़ व बकरियों से प्राण सींग, हड्डियों व बालों का प्रयोग भी किया जाता है। बालों से बुनाई बनाई जाते हैं और सींग व हड्डियों का प्रयोग मुख्यतः बटन, कपड़े व तेल का सामान तथा खाद आदि वस्तुएँ बनाने में किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि भेड़ व बकरियों न केवल राज्य के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के निवासियों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है वरन् राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास में भरतपूर्ण सहयोग भी दे रही है।

राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की संख्या

NUMBER OF SHEEP & GOATS

राज्य में 1951 के पश्चात् भेड़ व बकरीया दोनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही लेकिन 1983 के पश्चात् भेड़ व बकरियों की संख्या में अत्यधिक कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण राज्य में निरन्तर सूखे व अकाल की स्थिति का बने रहना है। भेड़ों व बकरियों की दृष्टि से 1987-88 का वर्ष इस शताब्दी का निकृष्टतम वर्ष रहा था। 1983 की तुलना में 1988 में भेड़ों की संख्या में 26.19 प्रतिशत तथा बकरियों की संख्या में 18.65 प्रतिशत की कमी हुई। अग्रे तालिका में भेड़ों व बकरियों की संख्या की दर्शाया गया है।

राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की संख्या				
वर्ष	भेड़ों की संख्या (लाखों में)	कुल परगुण का प्रतिशत	बकरियों की संख्या परगुण का प्रतिशत	कुल परगुण का प्रतिशत
1951	53.87	21.11	55.62	21.60
1961	73.61	21.97	80.52	24.03
1972	85.56	22.01	121.62	31.28
1977	99.38	24.03	123.07	29.76
1983	134.31	27.05	154.80	31.18
1988	99.13	24.24	125.93	30.79
1992	121.11	25.47	150.62	31.53
1997	143.12	26.33	169.36	31.16

स्रोत: Board of Revenue Rajasthan Livestock Census 1997

भेड़ों व बकरियों का जिलानुसार वितरण

DISTRICTWISE DISTRIBUTION OF SHEEP & GOAT

राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले में भेड़े पाली जाती हैं लेकिन राज्य के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भेड़पालन व्यवसाय अधिक उत्तम है। पश्चिमी राजस्थान में प्रतिवर्ष अकाल एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न रहती है अतः इन क्षेत्रों की भेड़े पालने व पानी की कलश में राज्य के अन्य जिलों में ले

जायी जाती है। भेड़ों व बकरियों के जिलानुसार वितरण की निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

भेड़ व बकरियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)		
जिला	संख्या (लाख)	
अ. भेड़		
1. जोधपुर	15.6	
2. बाड़मेर	15.1	
3. पाली	13.6	
ब. बकरी		
1. बाड़मेर	18.6	
2. जोधपुर	12.9	
3. नागौर	10.6	

स्रोत: Board of Revenue Rajasthan, Livestock Census 1997

राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लें

MAIN BREEDS OF SHEEP

1. चोकला (Chokla) अधिकतर यह नस्ल शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, अतः इस नस्ल को शेखावटी नस्ल भी कहते हैं। झुझुनू और सीका जिलों में यह काफी अधिक संख्या में विद्यमान है। इस नस्ल की भेड़ के चेहर पर गहरे भूरे व काले धब्बे होते हैं। इसके ऊन के रेशों की लम्बाई 5.5 सेटीमीटर होती है।

2. जैसलमेरी (Jaisalmeri) इस नस्ल की भेड़ मुख्यतः जैसलमेर तथा जोधपुर के पश्चिमी भागों में मिलती है। यह लम्बे कानों वाली व पुष्ट शरीर की होती है। देशी नस्लों में यह सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल है। इसका रेशा 5.7 सेटीमीटर लम्बा होता है।

3. पूगल (Pugal) - इसका मूल स्थान पूगल होने के कारण ही इसे वह नाम दिया गया है। पूगल, बीकानेर जिले की एक नस्ल है। यह भेड़े जैसलमेर व बीकानेर जिलों में पाई जाती है। जोधपुर व नागौर के कुछ क्षेत्रों में भी ये विद्यमान हैं। ये शारीरिक रूप से मजबूत होती है। इनसे प्राप्त ऊन का रेशा 5.9 सेटीमीटर लम्बा होता है।

4. मगरा (Magra) जैसलमेर, बीकानेर व नागौर जिलों में पाई जाने वाली यह नस्ल सुन्दर व मजबूत होती है। इसकी ऊन का रेशा 5.9 सेटीमीटर लम्बा होता है।

5. मारवाडी (Marwarai) राजस्थान की अधिकांश भेड़े इसी नस्ल से सम्बन्धित हैं। ये भेड़े जोधपुर, पाली, नागौर, जयपुर, बाड़मेर, झुझुनू, सीकर आदि जिलों में पाई जाती हैं। यह राजस्थान की अन्य नस्लों की अपेक्षा रोग प्रतिरोधी है। इस भेड़ के कान लम्बे तथा मुढ़ काला होता है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह पुष्ट होती है। इसकी की ऊन के रेशों की लम्बाई 2 सेंटीमीटर होती है।

■ **नाली (Nali)** श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में मुख्यतः यह नस्ल विद्यमान है। इस नस्ल की भेड़ों का चेहरा हल्का भूराभन लिए हुए होता है। इसके कान लम्बे होते हैं। इस नस्ल की ऊन के रेशों की लम्बाई 6.5 सेंटीमीटर होती है।

7 **मालपुरा (Malpura)** जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में यह नस्ल पाई जाती है। टाक और खवाईमाधोपुर जिलों में भी यह पाई जाती है। इसका भुल हल्के भूरे रंग का तथा कान छोटे होते हैं। इसके ऊन के रेशों की लम्बाई 6.2 सेंटीमीटर होती है।

8 **सोनाड़ी (Sonari)** अपेक्षाकृत लम्बी पूछ वाली यह नस्ल राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। बिलौडगढ़ बामवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर भोलवाड़ा आदि जिलों में यह पाई जाती है। इस नस्ल के ऊन के रेशों की लम्बाई 7.2 सेंटीमीटर होती है।

भेड़ व बकरी पालन के विकास से संबंधित

विभिन्न योजनाएँ, कार्यक्रम व सुविधायें
VARIOUS PLANS PROGRAMMES & FACILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SHEEP & GOAT HUSBANDRY IN RAJASTHAN

अ भेड़पालन

Sheep Husbandry

राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेड़पालन तबू से एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है क्योंकि यह व्यवसाय राज्य की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आय एवं राजस्व के अवसर प्रदान करता है। राज्य के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भागों में कमजोर वर्गों के लिए भेड़पालन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। वर्ष 1997 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 143.12 लाख भेड़ थीं जो कि देश में भेड़ों की कुल संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 170 लाख किं मा ऊन का उत्पादन होता है। भेड़ों में बीमारियाँ की रोकथाम हेतु दवाइयों की खुराक छिड़काव एवं टीकाकरण आदि कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। दवाइयों का रोकथाम के उपायों के अतिरिक्त अच्छी किस्म के ऊन उत्पादन के लिए उन्नत भेड़ उपलब्ध करने के उद्देश्य से चयनित एवं वर्षसर्वर नस्लों के प्रजनन एवं

प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी राज्य में तीव्रता से चलाए जा रहे हैं। पानी व चारे की कमी के कारण भेड़ें पश्चिमी राजस्थान से राज्य की सीमा में जुड़े गज्यों जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में चली जाती हैं। भेड़ों के ठहराव के दौरान उचित एवं तुरंत उपचार देने हेतु अनेक स्थाई निगरानी चौकियाँ स्थापित की गई हैं।

1 **स्वास्थ्य रक्षा (Health Protection)** भेड़ व ऊन विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भेड़पालकों को भेड़ा की उचित देखभाल हेतु जानकारी दी जाती है। इस जानकारी के अन्तर्गत भेड़पालकों को उन्नत एवं नवीन विधियों के बारे में बताया जाता है। भेड़ों को स्वस्थ रखने तथा गर्मियों में बरान के लिए नियमित रूप से दवा देने व टीके लगाने की जानकारी भी दी जाती है। औषधि वितरण एवं टीके लगाने का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है। भेड़ व ऊन विभाग के कर्मचारी भेड़पालकों के घरों पर ये सुविधायें उपलब्ध कराते हैं।

2 **भेड़पालक प्रशिक्षण (Training)** भेड़पालकों को प्रशिक्षित करने हेतु भेड़ व ऊन विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य भेड़पालकों को भेड़पालन सम्बंधी नवीनतम जानकारी से अवगत कराना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। भेड़ व ऊन विभाग के विभिन्न विभागों द्वारा भेड़ों की स्वास्थ्य रक्षा प्रजनन उत्पादन विपणन चरागाह विकास तथा कृषारापण एवं मत्कारिता आदि की जानकारी दी जाती है।

3 **घल रोग अनुसंधान कार्यशाला (Mobile Disease Research Workshop)** राज्य में भेड़ विकास का ध्यान में रखते हुए जयपुर काटा बीकानेर जोधपुर भागलपुर तथा उदयपुर में एक एक घल रोग-अनुसंधानशाला स्थापित की गई है। ये अनुसंधानशालाएँ टीके लगाने दवा पित्तन दवा छिड़कन तथा बंधिधारण आदि कार्य करती हैं। इनके द्वारा उन्नत प्रशिक्षण युक्त की जानकारी तथा फार्मास्यूटिकल आदि कार्य भी किये जाते हैं। ये नियमित भेड़ा की स्वास्थ्य रक्षा का भी कार्य करता है।

4 **संकर प्रजनन कार्यक्रम (Cross Breeding)** देशी नस्ल की भेड़ा में बहुत कम ऊन प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त ऊन घटिया किस्म की होती है। अतः श्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त करने के उद्देश्य से भेड़ नस्ल सुधार हेतु संकर प्रजनन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न नस्लों के भेड़ों में देशी नस्ल की भेड़ा में संकर प्रजनन कार्य किया जाता है। यह कार्य राज्य के 4 भेड़ प्रजनन फार्मों पर किया

जाता है। कार्यक्रम के अनुसार भेड़पालकों को सकर मेडे दिये जाते हैं। इन सकर मेडों से देशी नस्ल की भेड़ों के माध्यम से 25 प्रतिशत विदेशी नस्ल की सकर सतनि प्राप्त की जाती है। सकर नस्ल की भेड़ों से न केवल अधिक ऊन प्राप्त होती है वरन् उनसे प्राप्त ऊन श्रेष्ठ किस्म की भी होती है। भेड़ व ऊन विभाग द्वारा मकर प्रजनन का कार्यक्रम राज्य के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, पाली, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक तथा श्रीगंगानगर जिलों में चलाया जा रहा है।

■ चयनित प्रजनन (Selective Reproduction)

यह कार्यक्रम बाड़मेर, पाली, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम माधवी प्रमुख तथा निम्नलिखित हैं

- (i) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊन भेड़पालकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिनके पास 50 से 100 भेड़े हैं।
- (ii) भेड़ व ऊन विभाग द्वारा भेड़पालकों को मारवाड़ी जैसलमेरी तथा मगरा नस्ल के मेडे प्रजनन हेतु दिये जाते हैं।
- (iii) मेडों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी विभाग द्वारा निःशुल्क की जाती है। इन मेडों से उत्पन्न मेमनों को भी 18 माह तक पौष्टिक आहार निःशुल्क दिया जाता है।
- (iv) जब मेमने प्रजनन योग्य हो जाते हैं तो विभाग इन्हें 17 रुपये प्रति किलोग्राम के जीवित भार को दर से क्रय कर लेता है और इन्हें अन्य भेड़पालकों को वितरित कर देता है।
- (v) श्रेष्ठ किस्म के व अधिक ऊन वाले 20 प्रतिशत चयनित नर मेमनों का भेड़पालकों द्वारा बीमा करवाना आवश्यक होता है।

6 भेड़ प्रजनन केन्द्र (Sheep Reproduction Centre)

मकर प्रजनन कार्यक्रम को मफल बनाने के उद्देश्य से राज्य के चार स्थानों पर भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों पर विदेशी नस्ल की भेड़ एवं मेडे खरीदकर प्रजनन के उद्देश्य से पाले जाते हैं। राज्य के चार भेड़ प्रजनन केन्द्र निम्नलिखित हैं

- (i) भेड़ प्रजनन फार्म, फोहेपुर (सीकर)
- (ii) भेड़ प्रजनन फार्म, जयपुर
- (iii) भेड़ प्रजनन फार्म, चित्तौड़गढ़
- (iv) भेड़ प्रजनन फार्म, झरकिया (जाजर)

7 भेड़ इकाइयाँ (Sheep Units) : यह योजना परीची की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि हेतु लागू होती है। यह कार्यक्रम 1976-77 से प्रारंभ किया गया। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों को 30 भेड़ें और एक मेडे की इकाई उपलब्ध कराई जाती है। भेड़पालक को भेड़ों की कुल राशि में से तनु कृषकों को 25 प्रतिशत,

मीपान कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को 33 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह कार्यक्रम अनेक निर्धन व्यक्तियों की जीविका का प्रमुख साधन बन चुका है।

8 जनजाति हेतु भेड़ विकास सुविधाएँ (Facilities for Tribes) आदिवासी परिवारों को ऊन व भेड़पालन सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उदयपुर व बागवाड़ा में 2 जिला भेड़ व ऊन कार्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, तीन नये कृषि गन्धान प्रसार केन्द्रों की स्थापना भी की गयी है। अनेक स्थानों पर मकर प्रजनन के लिए विदेशी एवं मकर मेडों के पालन पोषण की व्यवस्था भी की गई है।

9 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला (Wool Analysis Laboratory) : ऊन की विभिन्न किस्मों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बीकानेर में एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यहाँ पर ऊन के नमूनों की वैज्ञानिक विधि से भौतिक एवं रासायनिक जाँच की जाती है। ऊन की किस्म की जाँच के आधार पर भेड़पालकों को श्रेष्ठ नस्ल के मेडे वितरित किये जाते हैं।

10. भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान (Sheep & Wool Training Institute) - भेड़ व ऊन सम्बन्धी तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिये एक भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। यह संस्थान भेड़ व ऊन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भेड़ व ऊन सम्बन्धी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य गण्यों से आने वाले कर्मचारियों एवं अधिवसियों को भी भेड़ व ऊन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ विदेशी से भी अनेक व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये आते हैं।

11 भेड़ों का निष्क्रमण एवं घरागाह कार्यक्रम (Outgoing Sheep & Pastures) राजस्थान में भेड़ों की संख्या अधिक है जबकि घरागाह सीमित है। अतः अकाल व सूखे की स्थिति में भेड़पालकों का निष्क्रमण होता है। राज्य की लगभग 30-35 लाख भेड़ें प्रतिवर्ष मन्थने से राज्य के अन्य जिलों व अन्य प्रदेशों को निष्क्रमण कर जाते हैं। भेड़ों को यह संख्या अकाल की स्थिति पर निर्भर करता है। भेड़ा के निष्क्रमण से वानर व व्यवस्था सम्बन्धी अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर चर्चा विकास के लिये एक योजना प्रस्तावित की गई है। यदि यह योजना समुचित रूप से पूर्ण हो जाये तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

12 सघन जलग्रहण परियोजना सघन जलग्रहण परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बनाई गई है। इस योजना में भंड व ऊन विकास कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अनुसार भेड़ विकास सबधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिये ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाना भी प्रस्तावित है।

13 इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम (Sheep & Wool Development Programme in Indira Gandhi Canal Project) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत बाकानेर व नैमलगर जिलों में लगभग 2.50 लाख भेड़ों के लिये भंड व ऊन विकास कार्यक्रम की एक योजना प्रस्तावित है।

14 मरु विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme) इस कार्यक्रम के अंतर्गत चरागाह विकास के लिये 160 हैक्टेयर क्षेत्र में चारा उत्पन्न किया जाता है। 1991-92 में भेड़ व ऊन विभाग के अधीन यह योजना बीकानेर, फतेहपुर तथा गुरू में चालू की गयी।

15 सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (Draught Prone Area Programme) इस कार्यक्रम के अंतर्गत डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में 1991-92 में चरागाह विकास कार्यक्रम चालू किया गया।

16 राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लिमिटेड इस संस्थान की स्थापना 1977 में की गई है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भेड़पालकों को सहकारिता के माध्यम से उनके ऊन व मेला का उचित मूल्य प्रदान करना था। फैडरेशन की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है अतः उचित विपणन व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था की जाना है।

17 भेड़ जिले (Sheep Districts) राजस्थान को 17 भेड़ जिलों में विभक्त किया गया है। ये भेड़ जिले हैं अजमेर, जयपुर, बंसवाड़ा, टोंक, झुंझर, भीलवाड़ा, बीकानेर, टोंक, चूरू, मृगतगढ़, जालौर, बुधनूर, जोधपुर, नागौर, पाली, उदयपुर व सीकर। भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना चित्तौड़गढ़, जयपुर व पटौदपुर में की गई है। जयपुर में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। जोधपुर में भेड़ व बकरियों की बीमारियों के लिये प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। व्यापार व बीकानेर में ऊन विश्लेषण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गयी हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, बंसवाड़ा, नागौर, उदयपुर, बडोली व कनैरी में चारा प्रयोगशालाएँ भी कार्यरत हैं।

अ बकरीपालन Goat Husbandry

राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में बकरियाँ पाली जाती हैं। अरावली पर्वतमालाओं के निकटस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तथा अलवर व गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में बकरीपालन एक प्रमुख व्यवसाय है। यह व्यवसाय प्रायः निर्धन एवं कमजोर वर्गों द्वारा अपनाया जाता है। यही कारण है कि बकरी को गरीब की भाँति ही समझा प्रदान की जाती है। बकरियों में दूध, मांस, चमड़ा, बाल आदि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। बकरी का दूध बच्चों के स्वास्थ्य हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। राज्य के शुष्क व अर्धशुष्क भागों में बकरियों की संख्या अधिक है। राज्य में पाये जाने वाली बकरियों को उन की नस्ल की दृष्टि से दो भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम दुधारू नस्ल की बकरियाँ और द्वितीय मांस वाली नस्ल की बकरियाँ। दुधारू नस्ल के अन्तर्गत जमनापारी, अलवारी, मिर्गोही, जखारना व बरबरी नस्लें अधिक लोकप्रिय हैं। मांस वाली नस्लों के अंतर्गत लोही और मारवाड़ी नस्लें प्रमुख हैं। स्थानीय नस्ल की बकरियों की उत्पादन क्षमता कम होने से पशुपालकों को पर्याप्त लाभ नहीं होता है अतः राज्य में उन्नत किस्म की बकरियाँ की नस्लें तैयार की जाना चाहियें। इससे लिये उन्नत किस्म के बकरे वितरित किए जाने चाहियें। नस्लाधुधार हेतु विदेशी नस्लों के द्वारा मकर प्रजनन से भी बकरियाँ की नस्ल में सुधार किया जा सकता है। बकरियों हेतु चारे की व्यवस्था हेतु सामाजिक बान्नी कार्यक्रम में ऐसे भेड़ पौधे व झाड़ियाँ लगाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये जहाँ बकरियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ हों। खेजड़ी, बोरडी, अरुड़ आदि पौधे बकरियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं। राजस्थान में मामाहारी कार्यक्रमों द्वारा मुख्यतः बकरों के मांस का सेवन किया जाता है। बकरों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। राज्य के प्रमुख शहरों में इसकी माण्डिया है। बकरियों के बालों से वस्त्र व दरिया आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं। इनके चमड़े में भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती हैं। राज्य सरकार ने बकरियों के विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है अतः इनसे सम्बंधित अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं।

बकरीपालन से आर्थिक स्रोतों का विनाश करने और बकरीपालन प्रणालियों की कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मियन्जरलैण्ड सरकार के सहयोग से राजस्थान में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना प्रारंभ की है। अजमेर जिले में रामनगर ग्राम में इस परियोजना पर कार्य करने के लिये एक फार्म का विकास किया गया है। आर्पाईन एवं टागम चारे के उन्नत नस्ल के बकरों एवं

राजस्थान की मिरोही नस्ल की बकरियों के माध्यम से उन्नत नस्ल के बकरे बकरियों का उत्पादन कर इन्हे राज्य के बकरी पालकों को वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में अजमेर, भीलवाड़ा एवं सिरोही जिलों को लिया गया है। इसके अंतर्गत उन्नत नस्ल के बकरे व बकरियों का वितरण करने के साथ ही चारा विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

भेड़ व बकरी पालन की विशिष्ट

समस्याएँ एवं सुझाव

SPECIAL PROBLEMS RELATING TO SHEEP & GOAT AND SUGGESTIONS

1 निष्क्रमण राजस्थान में भेड़ व बकरी पालक अपने पशुओं को लगभग प्रतिवर्ष 6-7 माह राज्य से बाहर तथा राज्य में ही उन स्थानों पर घूमाते रहते हैं जहाँ उन्हें पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाना है। चारा समाप्त होने पर पुनः वे अन्य स्थानों के लिये चल देते हैं। यह क्रिया लगातार दोहराई जाती है। इस स्थिति के कारण भेड़ एवं बकरी पालकों पर विशेष ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता। सरकार इस समस्या का समाधान पर्याप्त मात्रा में चारा एवं चरागाह उपलब्ध कराकर कर सकती है।

2 अपर्याप्त चरागाह (Inadequate Pastures) जो लोग बाहर निष्क्रमण नहीं करते, उन लोगों के लिये भी पर्याप्त चरागाह नहीं है। भेड़ एवं बकरी पालकों को काफी बड़े क्षेत्र में चरागाह की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण अभियान के कारण, जब तक पेड़ छोटे होंगे तब तक सम्यक् क्षेत्र भी जो उनके नियमित चरागाह रहे हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन पशुपालकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को चाहिए कि वह भेड़ एवं बकरी पालकों के लिये चरागाह निर्धारित कर दे और यदि इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाए तो वृक्षों की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

3 विकास कार्यक्रमों की अनुपालना न हो पाना (Lack of Implementation of Development Programmes) राजस्थान में भेड़ एवं बकरी पालन के विकास के लिये जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अन्तर्गते जाते हैं वे कार्यक्रम सरकारी प्रयोगों में एक बार आरम्भ तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें निरन्तर बनाए रखा जाता है या सफल क्योंकि भेड़ एवं बकरी पालक वर्ष में लगभग 6 माह तो

अपने स्थान पर रहते हैं नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, आरम्भ किये गये कार्यक्रम का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इस स्थिति को बदलने के लिये सरकार द्वारा पशुओं के निष्क्रमण को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

4 अच्छी नस्ल का अभाव (Lack of good Breeds). राजस्थान में भेड़ एवं बकरियों की अनेक नस्ले पाई जाती हैं किन्तु इनमें से जो सर्वोत्तम नस्ल है उसे नरों अपनाया गया है। भेड़ एवं बकरियों में उनकी नस्ल की अपेक्षा उनकी अधिक मात्रा पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इससे पशुपालक हानि में रहते हैं। विदेशी नस्लों को मिला कर जो मकर नस्ले तैयार की जाती हैं उन पर भी भेड़ एवं बकरी पालक अधिक ध्यान नहीं देते हैं इस कारण उनके पशुओं की नस्ल खराब बनी रहती है। इस समस्या का समाधान पशुपालकों से निरन्तर सम्पर्क करके उन्हें सकारात्मक नस्लों और उन्नत नस्लों की जानकारी देना है।

5 पर्याप्त देखभाल का अभाव एवं बीमारियाँ (Lack of Proper Maintenance and Diseases) भेड़ एवं बकरी पालकों का दृष्टिकोण व्यावसायिक नहीं है। इस कारण वे अपने पशुओं की देखभाल पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते और जो कुछ भी उन पशुओं से मिल जाता है, उसी में सन्तुष्ट रहते हैं। अपर्याप्त देखभाल की वजह से उनके पशु रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। ये रोग कई बार तो उनके समस्त पशुओं में फैल जाते हैं। समय पर दवाइयाँ और टीके आदि लगाने पर भी ये ध्यान नहीं देते। इसमें एवं बाधा उनका प्रतिवर्ष दूसरे स्थानों को निष्क्रमण भी है। इस समस्या का समाधान तो पशुपालकों में जागरूकता उत्पन्न करके ही किया जा सकता है।

6 निर्धनता एवं अशिक्षा (Poverty and Illiteracy) अन्य पशुपालकों की अपेक्षा भेड़ एवं बकरी पालक अधिक निर्धन हैं तथा वे अशिक्षित भी हैं। इन दोनों कारणों से उनके विकास के लगभग सभी मार्ग अवरोधित हो जाते हैं। भेड़ एवं बकरी पालकों के आवास की उचित व्यवस्था, उनकी पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, अच्छी नस्ल का विकास करना आदि कार्यों में कुछ धन की भी आवश्यकता होती है। ये पशुपालक ऐसे कार्यों को स्वीकार करते रहते हैं, जिनमें धन लगाना आवश्यक हो। सरकार को चाहिये कि वह पहले भेड़ एवं बकरी पालन के विकास के लिये पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करे। इससे पशुपालकों को पशु विकास में रुचि जागृत होगी तथा वे सश्रुता की ओर अग्रसर होंगे।

अध्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राज्य की अर्थव्यवस्था में भेड़ एवं ऊन का महत्व बताईए।
Explain the importance of Sheep and Wool in the economy of Rajasthan
- 2 "मूत्र योजना का अवधि में राजस्थान में भेड़पालन एवं ऊन उत्पादन के महत्व का उद्घाटन कीजिए।"
Highlight the importance of Sheep rearing and Wool production in Rajasthan during the current plan period
- 3 राजस्थान में भेड़ों व बकरीयों की वर्तमान स्थिति बताईए।
Mention the present position of Sheep and goats in Rajasthan
- 4 राजस्थान में भेड़ा का जिलानुसार वितरण बताईए।
Mention the districtwise distribution of Sheep
- 5 भेड़ों का प्रमुख चरम क्या है?
What are the main breeds of Sheep
- 6 राजस्थान के भेड़ प्रजनन केंद्रों का उल्लेख कीजिए।
Mention the Sheep reproduction centres of Rajasthan
- 7 राजस्थान में बकरी पालन पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on "Goat Husbandry in Rajasthan"
- 8 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन की विशेष समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the special problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan

II निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पशुधन क्यों महत्वपूर्ण है और भेड़ एवं बकरी पालन की क्या समस्याएँ हैं?
Why livestock is important in arid and semi arid regions of Rajasthan and what are the problems of Sheep and Goat Husbandry
- 2 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन का क्या महत्व है और उनके पालन में प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? विवरण कीजिए।
What is the importance of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan and what are the problems of Sheep and Goat Husbandry? Discuss
- 3 राज्य सरकार द्वारा भेड़ व ऊन विकास पर किए गए कार्यों की व्याख्या कीजिए।
Examine the efforts made by Govt. of Rajasthan for Sheep and Wool development
- 4 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on Sheep and goat Husbandry in Rajasthan
- 5 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन के विकास में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सुविधाओं का वर्णन कीजिए।
Explain the various plans, programmes & facilities for the development of Sheep-Goat Husbandry in Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

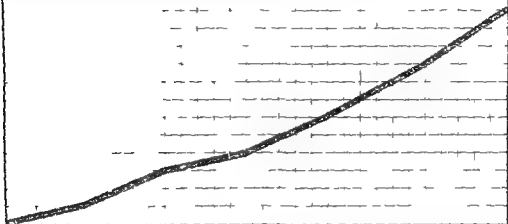
- 1 राजस्थान में भेड़ पर राज्य सरकार के विकास तथा उनकी समस्याओं के निवारण हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक विवरण कीजिए।
Critically analyse the Govt. efforts for the development and solution of problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan
- 2 "राजस्थान में भेड़ एवं उनके पालन की समस्याओं" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए विवरण कीजिए।
Write a short note on "Problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan"
- 3 "राज्य व शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भेड़ एवं बकरी पालन की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।"
Write a short note on "Role of Sheep and Goat Husbandry in arid and semi arid regions of the state"
- 4 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन के विभिन्न तथ्यों का वर्णन कीजिए
(i) भेड़ों व बकरीयों की संख्या (ii) भेड़ा का जिलानुसार वितरण
(iii) भेड़ा में प्रमुख चरम (iv) भेड़ व बकरी पालन की समस्याएँ
Describe the following factors of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan
(i) Number of Sheep & Goat (ii) Districtwise Distribution of Sheep
(iii) Breeds of Sheep (iv) Problems of Sheep and Goat Husbandry



अध्याय - 13

राजस्थान का संरचनात्मक विकास

INFRA STRUCTURAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN



"संरचनात्मक ढांचा विकास का आधार है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में सिंचाई
- राजस्थान नहर अध्याय इंदिरा गांधी नहर परियोजना
- राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ
- योजनाकाल में सिंचाई का विकास
- राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में सिंचाई सम्बंधी समस्याएँ व सुझाव
- राजस्थान में शक्ति
- राजस्थान में ऊर्जा विकास के सदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका
- ऊर्जा के साधनों की समस्याएँ और समाधान
- राजस्थान में सड़कों का विकास
- राजस्थान में रेल परिवहन
- अप्पासर्च प्रश्न

संरचनात्मक ढांचा विकास का आधार होता है। इसके सुदृढ़ होने पर ही बहुमुखी उन्नति संभव होती है। संरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत सिंचाई शक्ति परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा स्वास्थ्य आदि भी इसके महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं क्योंकि मानव-सम्पदा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होती है। राजस्थान में ढांचागत विकास जैसे ऊर्जा सड़क एवं पुल आदि क्षेत्रों में समतुल्यता एवं अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास किये गये हैं। प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान के संरचनात्मक ढांचे से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है -

(अ) राजस्थान में सिंचाई

(ब) राजस्थान में शक्ति

(स) राजस्थान में सड़कों व परिवहन के अन्य साधन

राजस्थान में सिंचाई

IRRIGATION IN RAJASTHAN

राजस्थान के विकास के लिए जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में स्थलीय व भूमिगत जल की कमी

(iii) पीठा पानी (Potable Water)- कुएँ प्रायः पीठे पानी वाले क्षेत्रों में खोदना उपयुक्त रहता है क्योंकि पीठे पानी से सभी प्रकार की फमलें उत्पन्न की जा सकती हैं। खारे पानी में कुछ हा फसले उत्पन्न की जा सकती हैं तथा खारे पानी से लगातार सिंचाई करने से कुछ समय पश्चात् भूमि कृषि के अयोग्य हो जाती है।

(iv) ऊँचा जल स्तर (High Water Level) कुएँ प्रायः ऊँचे जलस्तर वाले क्षेत्रों में खोदना उपयुक्त रहता है क्योंकि पानी भूमि को सतह से अधिक गहराई पर होने से कुएँ खोदने की लागत भी अधिक आती है और सिंचाई में भी कठिनाई होता है।

(अ) उपजाऊ मिट्टी (Fertile Soil) उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कुएँ खोदकर सिंचाई करने पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है जबकि अनुपजाऊ और बेकार भूमि वाले क्षेत्रों में कुएँ खोदना लाभदायक नहीं होता है।

क्षेत्र (Area)

कुओं से सिंचाई का दृष्टि से उत्तर प्रदेश आन्ध्र प्रदेश पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र और राजस्थान प्रमुख हैं।

नलकूपा का अधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश पंजाब गुजरात बिहार मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में होता है।

लाभ (Merits)-

- (1) कुओं स्वतंत्र व विश्वसनीय साधन हैं।
- (2) कम व्यय के कारण किसानों के लिए सिंचाई का सरल व सुगम साधन है।
- (3) खेतों में पानी भरने व लवणीकरण को समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती।
- (4) जल का उपयोग आवश्यकतानुसार हो जाता है।
- (5) कृषक फमला के चुनव के लिए स्वतंत्र होता है।
- (6) मत्स्य प्रतिकूल होने पर नहरों व तालाबों में पानी नहीं होगा उस समय कुओं से सिंचाई की जा सकती है।
- (7) नलकूपा के माध्यम से विस्तृत क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है।
- (8) कुओं के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती।

दोष (Demerits)

- (1) सिंचाई का क्षेत्र सीमित ही होता है।
- (2) वर्षा अपवाह होने पर सामान्यतः कुएँ भी सूख जाते हैं।
- (3) यदि कुएँ में खराब जल निकल आए तो सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं होता।

(4) अन्य साधनों की अपेक्षा इसमें अधिक परिश्रम व व्यय करना होता है।

(5) नलकूप में शक्ति के साधनों का प्रयोग होने के कारण संचालन व्यय अधिक आता है।

राजस्थान में नलकूपा द्वारा विभिन्न वर्षों में सिंचाई की प्रगति अग्रानुसार रही है

वर्ष	19०9-१०	1996-97
सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	9.85	4.66

राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की स्थिति 1995-96 में इस प्रकार रही है

कुओं से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले-1995-96	
(1) अजमेर	3.46 लाख हेक्टेयर
(2) जयपुर	3.23 लाख हेक्टेयर
(3) तालाब	2.91 लाख हेक्टेयर
(4) जालौर	2.14 लाख हेक्टेयर
(स्रोत: Statistical abstract Raj, 1998)	

(2) तालाब (Tanks) वे भू भाग नहीं जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है तालाब कहलाते हैं। यदि भू भाग काफी बड़ा हो तो वह झील के नाम से जाना जाता है। तालाब व झील कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकती हैं।

उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ या तत्व

(Favourable Geographical Conditions)-

तालाबों के निर्माण हेतु प्रायः निम्नलिखित अनुकूल भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है

(i) पथरीला जमीन (Rocky land)- पथरीली भूमि वाले क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण करना उपयुक्त रहता है क्योंकि पथरीली भूमि अधिक पानी नहीं सोख पाता है जिससे तालाबों में पानी अधिक समय तक भरा रहता है।

(ii) प्राकृतिक ढाल (Natural Slope) तालाबों का निर्माण भूमि के प्राकृतिक ढाल वाले स्थानों पर किया जाना चाहिए ताकि वर्षा होने पर पर्याप्त मात्रा में जल बहकर आ सके।

(iii) प्राकृतिक गड्ढे (Natural Depression) तालाबों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाना चाहिए जहाँ पहले से ही प्राकृतिक गड्ढे विद्यमान हों ताकि निर्माण-लागत कम हो जाये।

(iv) पर्याप्त वर्षा (Sufficient Rain) तालाबों का निर्माण करत समय वर्षा की पर्याप्तता का भी ध्यान रखना चाहिये। ऐसे स्थान जहाँ वर्षा कम समय कम मात्रा तथा मूसलाधार रूप में होती हो तालाबों के लिए उपयुक्त रहते हैं।

(v) सिंचाई के अन्य साधन न हो (Other Sources of Irrigation are not Available) तालाबों के निर्माण उन स्थानों पर भी उपयुक्त है जहाँ सिंचाई के अन्य साधनों का विकास न हुआ हो या वे अत्यन्त महंगे हों।

लाभ (Merits)

- (1) प्राकृतिक बनावट के कारण थोड़े से प्रयत्नों से भू-भाग का तालाब का रूप दिया जा सकता है।
- (2) खेती का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत नहीं हो तो सिंचाई के लिए तालाब पर्याप्त है।
- (3) चट्टानी भूमि के कारण जल संग्रह क्षमता अधिक होती है।
- (4) धरातल असमतल व चट्टानी होने के कारण वहाँ न तो कुआँ और न ही नहरा के लिए उपयुक्त धरातल विद्यमान होता है।
- (5) नदियाँ बरसाती होती हैं अतः वर्षा भर सिंचाई हेतु स्थान-स्थान पर जल संग्रह करना आवश्यक होता है जो तालाबों द्वारा ही संभव होता है।
- (6) तालाबों का निर्माण कम व्यय में संभव है।
- (7) वर्षा का पानी तालाबों में एकत्र होता है अतः सदैव माठा पानी उपलब्ध होता है।
- (8) तालाबों से वर्षा भर सिंचाई संभव है।
- (9) कम लागत वाले प्राकृतिक तालाबों से सिंचाई कार्य संभव है।
- (10) तालाबों में मछली पालन व्यवसाय भी संभव सकता है जो स्थानों की आवश्यकताओं का पूर्ति कर सकता है।
- (11) वर्षा का पानी जो वहकर समुद्र में चला जाता है उसका उपयोग संभव हो सकता है।
- (12) पानी के लिए माठा पानी उपलब्ध हो जाता है।
- (13) बेकार पठार और चट्टानी भूमि का भी उपयोग संभव हो पाता है।
- (14) जहाँ अन्य साधन संभव नहीं हैं तालाबों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाते हैं।

दाय (Demerits)

- (1) यदि तालाबों के पर नाच की आर एक क्रम में हो तो ऊपर का एक भी तालाब टूटने पर नाच के

अन्य तालाबों के टूटने का भय रहता है जिससे जन-धन की हानि संभव है।

- (2) ढालू भूमि पर से पानी वहकर आने से मिट्टी का कटाव होता रहता है और मिट्टी एकत्र होती रहती है जिससे तालाबों में जल जमा हो जाता है।
- (3) वर्षा कम होने पर तालाबों में पर्याप्त पानी एकत्र नहीं हो पाता और वर्षा भर सिंचाई नहीं हो पाती।
- (4) तालाबों खुल जाने के कारण सूर्य के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं अतः जल का एक बड़ा भाग वाष्प बनकर उड़ जाता है।
- (5) तालाबों का अनेक कार्यों में उपयोग करने से ब्यामारियों के फैलने का भय सदैव बना रहता है।
- (6) अधिक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई संभव नहीं है।
- (7) तालाबों से खेती तक पानी पहुँचाने में व्यय अधिक होता है।
- (8) तालाबों बहुत अधिक स्थान घाते हैं।

राजस्थान में तालाबों द्वारा विभिन्न वर्षों में सिंचाई का स्थिति अग्रानुसार रही है

वर्ष	1959-60	1996-97
सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	2.55	2.18

राजस्थान के विभिन्न जिलों में तालाबों द्वारा सिंचाई का स्थिति वर्ष 1995-96 में इस प्रकार रही

तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले 1995-96	
(1) गाल	0.55 लाख हेक्टेयर
(2) भीलवाड़ा	0.36 लाख हेक्टेयर
(3) उदयपुर	0.23 लाख हेक्टेयर
(4) टोंक	0.13 लाख हेक्टेयर

(स्रोत: Statistical Abstract, Raj. 1996)

(2) नहर (Canals) सिंचाई का कृत्रिम साधन में नहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नहर मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं

- (1) बरसाती नहर (Rainy Canals) ये केवल वर्षाकाल में सिंचाई करती हैं। नदियों के अतिरिक्त जल का निकासन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है।
- (2) नित्यवाही नहर (Perennial Canals)- इनमें नियमित रूप से वर्षा भर जल प्रवाह बना रहता है। ऐसा नहर वर्ष भर बहने वाला नदियाँ से निकाला जाता है।

(3) पोषक नहर (Feeder Canals)- ऐसी नहरों का निर्माण दूसरी नहरों को पानी उपलब्ध कराने हेतु किया जाता

1. Trends and Use Statistics & District Five Year Plan, 1977-2002, Govt. of Rajasthan Statistical Abstract, 1998, Raj.

है। इन नहरों से बोच में पानी लिया जाता है।

(4) बंद नहरें (Covered Canals)- वाष्पीकरण से होने वाली हानि से बचने के लिये नहरों को ऊपर से बंद भी कर दिया जाता है।

(5) लिफ्ट नहरें (Lift Canals)- इन नहरों में जलापूर्ति हेतु बाधों का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि नदी के पानी को मशीनों से ऊंचा उठाकर सिंचाई की जाती है।

उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ या तत्त्व (Favourable Geographical Conditions)-

(i) समतल भूमि (Plain Land)- नहरों का निर्माण समतल भूमि में किया जाना उपयुक्त रहता है क्योंकि असमतल भूमि होने पर ऊपरी भागों में सिंचाई नहीं की जा सकती है। अतः, सिंचाई के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये नहरों का निर्माण समतल भूमि में किया जाना आवश्यक है।

(ii) जमीन पथरीली न हो (Absence of Rocky Land)- नहरों के निर्माण वाले क्षेत्रों की भूमि पथरीली नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे नहरों की निर्माण लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। अतः नहरों के निर्माण के लिए नर्म धरातल होना उपयुक्त रहता है।

(iii) नित्यवाही नदियाँ (Perennial Rivers)- नहरों की जल की प्राप्ति मुख्यतः नदियों या बाधों से होती है। यदि नहरों या बाधों का निर्माण नित्यवाही नदियों पर नहीं किया गया तो नहरों को सदैव पानी नहीं प्राप्त हो पाता है। अतः नहरों से वर्ष पर्यन्त जल की प्राप्ति हेतु नहरों का निर्माण नित्यवाही नदियों पर ही किया जाना उपयुक्त रहता है।

(iv) उपजाऊ भूमि (Fertile Land)- नहरों का निर्माण उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिये ताकि भूमि निर्माण व्यय वहन कर सके।

(v) पर्याप्त श्रमशक्ति (Adequate Manpower)- नहरों के निर्माण क्षेत्रों में पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध होने से नहरों के निर्माण की लागत में कमी आ सकती है। नहर क्षेत्र में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध न होने पर अन्य स्थानों से श्रमिकों को बुलाया पड़ता है जिससे लागत में वृद्धि हो जाती है।

(vi) भूमि का ढाल (Gentle Slope of Land)- ढालू भूमि वाले क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई की सुविधा रहती है, अतः नहरों का निर्माण ढालू भूमि वाले क्षेत्रों में करना उपयुक्त रहता है।

लाभ (Merits)

(1) यह एक स्थायी व्यवस्था है जो वर्षों की

अनिश्चितता से बचाती है।

(2) बाधों के निर्माण से सिंचाई के अतिरिक्त जलविद्युत, मछलीपालन आदि लाभ भी प्राप्त होते हैं।

(3) नहरों के किनारे वृक्षारोपण व चरागाहों का निर्माण संभव है।

(4) इससे विस्तृत क्षेत्र सिंचा जा सकता है- अतः खेतों का आकार बढ़ाया जा सकता है।

(5) अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों की उगाया संभव हो सकता है।

(6) नहरों में मीठा पानी होने से पानी की समस्या भी हल हो जाती है।

(7) इनका उपयोग आंतरिक परिवहन में किया जा सकता है।

(8) बाढ़ का पानी नहरों से निकल कर जन-धन की हानि से बचा जा सकता है।

(9) रीगिस्टर में अन्य सिंचाई के साधन सफल नहीं हो पाते अतः नहर निर्माण आवश्यक हो जाता है।

(10) वर्ष भर में इच्छानुसार दो-तीन फसलें ली जा सकती हैं।

(11) हरित क्रांति को सफल बनाने में नहरों का योगदान सराहनीय रहा है।

(12) उपयुक्त परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई समीप सुगम होती है।

(13) क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय एवं सरकारी आय में वृद्धि होती है।

(14) इनके द्वारा अकालों का निवारण संभव है।

दोष (Demerits)-

(1) नहरों के स्थान-स्थान पर टूट जाने के कारण आस-पास के क्षेत्र में पानी भर जाता है और वहाँ कृषि संभव नहीं हो पाती।

(2) लवणीकरण की समस्या नहरों का मुख्य दोष है।

(3) नहरों से सिंचाई के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होता है और स्वतंत्रता नहीं रहती।

(4) जलप्रसार से बीमारियों का भय बना रहता है।

(5) कृषकों में आपसी झगड़ों और मुकदमों की संभावना बढ़ती है।

(6) नदियों के मार्ग-परिवर्तन पर विद्यमान नहरें बेकार हो जाती हैं।

(7) शुल्क निश्चित होने के कारण पानी के दुरुपयोग की संभावना रहती है।

राजस्थान में नहरों द्वारा विभिन्न वर्षों में सिंचाई की स्थिति निम्न प्रकार रही है।

वर्ष	1959-60	1996-97
सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	4.21	22.0

नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले 1995-96	
(1) गंगानगर	5.46 लाख हेक्टेयर
(2) हनुमानगढ़	3.09 लाख हेक्टेयर
(3) जोध	1.19 लाख हेक्टेयर
(4) चित्तौड़	1.09 लाख हेक्टेयर
(स्रोत: State of Rajasthan, Raj 1996)	

(4) अन्य साधन (Other Sources)- उपर्युक्त मुख्य साधनों के अतिरिक्त नदियों में बहते जल को खेतों में मोड़कर भी सिंचाई की जाती है। वर्षाकाल में नदियों का पाट बहुत चौड़ा हो जाता है लेकिन इस जल को समाप्त के पश्चात् पाट बहुत ही सूखकर हो जाता है। अतः पाट के शेष भाग में नमी के कारण कृषि की जाती है। छोटे-छोटे पहाड़ी झरनों और नदियों से पम्प द्वारा जल उठाकर भी सिंचाई होती है।

अन्य साधन से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले 1995-96	
(1) जयपुर	0 लाख हेक्टेयर
(2) नागौर	0.08 लाख हेक्टेयर
(3) कोटा	0.07 लाख हेक्टेयर
(4) भरतपुर	0.03 लाख हेक्टेयर
(स्रोत: State of Rajasthan, Raj 1996)	

राजस्थान की प्रमुख नहरें (Important canals of Rajasthan)

1 गंग नहर (Gang Canal) इस नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने करवाया था। इनके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना था। इसका निर्माण कार्य 1927 ई. में प्रारम्भ हुआ। यह नहर फिरोजपुर के निकट हुई हुसेनवाला से निकाली गई है। यह नहर पञ्जाब राज्य में बहने के पश्चात् राजस्थान के पास बीकानेर गंगानगर में प्रवेश करती है। इसके निर्माण पर 3 30 70,336 रूपए खर्च हुये। यह नहर शिवपुर गंगानगर जोरावरपुर पदमपुर रायसिंह नगर और सरूपसर के पास अनुपगढ तक जाती है। फिरोजपुर इंडवक से नहर को कुल लंबाई 292 किलोमीटर है यह 144 किलोमीटर तक पक्की है। इसकी अनेक शाखाएँ अग्राशाखाएँ हैं सन् 1980 में 91 किलोमीटर लम्बी एक लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया। इस गाँव नहर लिफ्ट चैनल कहते हैं। यह चैनल दूधिया गाँव में मुख्य नहर से जोड़ी जायगा। उद्घाटन के समय गंगानगर नहर की सबसे दक्षिणी पक्की नहर था। पाकिस्तान

के बहावलपुर प्रदेश से होती हुई यह नहर गंगानगर पहुँचती है। इस नहर से बीकानेर व गंगानगर क्षेत्र को लगभग 3.28 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अब यह नहर जर्जर हो चुकी है अतः इसका पुनः निर्माण कराया जाना चाहिये।

गंगानगर द्वारा सिंचित सकल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)			
जिला	1980-81	1990-91	1993-94
गंगानगर	331.42	328.99	320.14
(स्रोत: Rajasthan Water Resources & Vess 1994-95, Rajp. 1994)			

2 भरतपुर नहर (Bharatpur Canal)- इस नहर का निर्माण 1906 ई. में प्रारम्भ हुआ और यह 1963-64 ई. में बनकर तैयार हुई थी। यह नहर यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से निकाली गई थी। इस नहर की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है और इससे राज्य के पूर्वी भागों की लगभग 11000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

3 गुडगांव नहर (Gurgaon Canal)- यह नहर यमुना नदी से ओखला नामक स्थान के पास से निकाली गई है। यह राजस्थान व हरियाणा के समुक्त प्रयासों का परिणाम है। इससे राजस्थान की 500 क्यूसेक जल की प्राप्ति होगी। यह नहर भरतपुर जिले की कामा तहसील में जुरेस गाँव के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नहर में राज्य की लगभग 28.2 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होने का अनुमान है। गुडगांव नहर का प्रमुख उद्देश्य यमुना नदी के वर्षाकालीन जल का उपयोग करना है नहर का निर्माण 1985 में पूर्ण हो चुका है। राजस्थान में इस नहर की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है।

4 इंदिरा गांधी नहर परियोजना (Indira Gandhi Canal Project)- प्रारम्भ में इसे राजस्थान नहर परियोजना कहा जाता था। यह नहर पञ्जाब में सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरि के बाध से नियाली गई। इसका विस्तृत विवेचन अगले पृष्ठों में किया गया है।

राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएँ

MAIN RIVER VALLEY PROJECTS OF RAJASTHAN

राजस्थान नहर अथवा इंदिरा गांधी नहर RAJASTHAN CANAL OR INDIRA GANDHI CANAL

राजस्थान नहर परियोजना विश्व की विशालतम नहरों में से एक है। यह मानवीय श्रम के माध्यम से एक बड़े

भू-भाग में फैले थार मरुस्थल को पुनः हरे-भरे क्षेत्र में बदलने का एक प्रयास है। सदियों से वीरान पड़े इस रेगिस्तान के लिए मानव का यह प्रयास सफल होगा, इस बात की आशा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जागृत होती है। राजस्थान नहर परियोजना जिस भू-भाग पर बनी है वह मरुस्थलीय क्षेत्र वास्तव में उपजाऊ भूमि है। यह केवल जल के अभाव में बेकार पड़ी रहती है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होने से ही जल का अभाव बना हुआ है। एक समय था जबकि इस क्षेत्र में सरस्वती नदी बहा करती थी और यह क्षेत्र सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से काफ़ी उन्नत था। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी के इन्हीं किनारों पर वेदों की रचना की गई। इस क्षेत्र में कालीयगा की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, वे मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता के समकालीन हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक विकसित व समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र के विकास के लिए 1951 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा प्रथम सर्वेक्षण किया गया। 1954 और 1956 में राजस्थान सरकार ने स्वयं इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया। इन सर्वेक्षणों के आधार पर 1957 में प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार किया गया और 31 मार्च, 1958 को इस परियोजना पर औपचारिक रूप से कार्य आरम्भ हुआ। 31 मार्च, 1958 को इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत ने किया था।

हिमालय के पानी को थार रेगिस्तान में लाने का पहला प्रयास बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने 1920 में गानहर के निर्माण के द्वारा किया। 1948 में राजस्थान नहर परियोजना के जनक कवरसेन ने अपने पत्र 'बीकानेर राज्य के लिए जल आवश्यकता' में इस बात पर बल दिया कि इस क्षेत्र में अच्छी फसलें ली जा सकती हैं वरन् यहाँ पानी उपलब्ध हो। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के समय जब दोनों देशों की नदियों के पानी को बांटने के सम्बन्ध में विचार विमर्श चल रहा था उसी समय भारत में भाखड़ा नागल परियोजना पर कार्य हो रहा था जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है। यह पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों को सिंचाई की योजना थी। 1955 में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से रावी और व्यास के पानी में राजस्थान का हिस्सा तय किया गया और राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा तय किया गया। उसी के पश्चात् राजस्थान नहर परियोजना को सुदृढ़ आधार मिला। राजस्थान नहर परियोजना का नाम स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है।

परियोजना के उद्देश्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्य

OBJECTS & MAIN WORKS

इंदिरा गांधी परियोजना के मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है—

1 इंदिरा गांधी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के बहुत बड़े रेगिस्तान को पुनः पुरातन स्वरूप प्रदान करना है जिसके अंतर्गत यह क्षेत्र एक हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस परियोजना के माध्यम से पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

2 इस मरुभूमि में बहुत दूर-दूर तक पानी उपलब्ध नहीं है। कुआ में पानी का स्तर अत्यधिक गहरा है। लोगो को पीने के पानी की खोज में दूर-दूर तक जाना पड़ता है। इस कारण इस परियोजना के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है।

3 इस रेगिस्तानी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। कृषि और उद्योग पन्थे भी अधिक नहीं पनप पाये हैं। इस कारण इस परियोजना के माध्यम से कृषि एवं उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे जनसंख्या की विलता भी कम होगी।

4 इस परियोजना के अंतर्गत यथासंभव जल विद्युत उपलब्ध करने की चेष्टा भी की जायेगी। इस हेतु इस परियोजना में मुख्य रूप से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का प्रयोग किया जायगा और उन पर तनु जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

5 इस परियोजना के कमान्ड क्षेत्र में जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने का प्रयास किया जायेगा जिनमें मुख्य रूप से सड़क, विद्युत एवं सिंचाई तथा मचार व्यवस्था प्रमुख हैं।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस परियोजना में यह कदम उठाना प्रस्तावित है।

1 सर्वप्रथम राजस्थान फीडर का निर्माण किया जाना ताकि राजस्थान नहर को जल उपलब्ध हो सके।

2 राजस्थान नहर का निर्माण किया जाना ताकि एक बड़े भू-भाग को जल उपलब्ध कराया जा सके।

3 परियोजना के पूरे कमान्ड क्षेत्र तक पहुंचने के लिये राजस्थान नहर की शाखाओं और उपशाखाओं का जाल बिछाना।

4 ऐसे क्षेत्र जहाँ जल के सामान्य प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं

आ पाते उन क्षेत्रों तक पहुँचने तक लिफ्ट सिंचाई परियोजना का सहारा लिया जायेगा।

5. परियोजना के अंतर्गत लघु जल विद्युतगृहों का निर्माण भी किया जायेगा ताकि कुछ मोमी तक अन्य स्रोतों से विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता कम हो सके। इन लघु जल विद्युत गृहों का निर्माण लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के स्थान पर किया जा सकता है।

इंदिरा गांधी परियोजना की प्रमुख बातें

Important Features

1. उद्गम (Origin) - 1952-53 में जब हरिके बैराज बनकर तैयार हो गया तो केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा राजस्थान नहर परियोजना को व्यावहारिक रूप देने के लिये प्रयास किये गये। वैसे केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने 1951 में इस परियोजना हेतु सर्वेक्षण किया था। इस परियोजना का श्रेय बीकानेर रियासत के मुख्य अधिपति श्री वरसमन को भी दिया जाता है क्योंकि उन्हें इस परियोजना के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था। 1927 में निर्मित गगननहर के प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुये उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। राजस्थान सरकार ने भी इस परियोजना का सर्वेक्षण करवाया और अन्त में 31 मार्च 1958 को इस नहर का शिलान्यास तत्कालीन गृहमंत्री के हाथों हुआ। आरम्भ में जब यह योजना बनाई गई थी तो उस समय इस परियोजना के अंतर्गत पंजाब हरियाणा राजस्थान को बाँटता मदरगाह से जोड़ने का लक्ष्य था। अपर्याप्त साधनों और वित्तीय कठिनाइयाँ के कारण इस प्रयास को छोड़ दिया गया।

2. जल आवंटन (Water Allocation) - जनवरी 1955 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार राजस्थान को रावी और व्यास के उपलब्ध 19568 मिलियन क्यूबिक मीटर जल में से 9876 मिलियन क्यूबिक मीटर जल आवंटित किया गया। रावी और व्यास नदियों के प्रवाह के संदर्भ में 1921-22 से 1970-71 तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राजस्थान का भाग 10617 मिलियन क्यूबिक मीटर है। राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत 9383 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग होगा।

3. परियोजना के दो चरण (Two Stages) - इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्रियान्वयन चारु जैसलमेर, श्रीगंगानगर बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर जिलों में किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार राजस्थान को रावी और व्यास नदियों के जल से 8.6 मिलियन एकड़ फुट जल उपलब्ध होगा है। इसमें से इस परियोजना के

माध्यम से 7.59 मिलियन एकड़ फुट जल के उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पूर्ण होने पर इसका कमान्ड क्षेत्र 15.37 लाख हेक्टेयर का होगा जिसमें से प्रतिवर्ष 13.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

प्रथम चरण (First Stage)¹ - इंदिरा गांधी परियोजना के प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबी पीडर नहर का निर्माण किया गया है। यह पीडर नहर पंजाब के हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान में मसीतावाली तक बनाई गई है। प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान के मसीतावाली से लेकर छतरगढ़ तक 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। इसकी कमान्ड क्षेत्र 3075 किलोमीटर लंबी है। इसका कमान्ड क्षेत्र 5.25 लाख हेक्टेयर का है। इस चरण का कार्य 1991-92 में पूरा हो गया है। इस चरण के अंतर्गत तीन प्रमुख शाखाओं सूरतगढ़ शाखा अनुपगढ़ शाखा नौशंग शाखा एवं लूनकरनसर बीकानेर लिफ्ट नहर का निर्माण सम्मिलित है।

द्वितीय चरण (Second Stage)² - द्वितीय चरण में छतरगढ़ से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण प्रस्तावित था। दिसम्बर 1986 में इसका निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही इंदिरा गांधी परियोजना की 649 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर पूरी हो गई। इस मुख्य नहर को पूरी करने में लगभग 20 वर्ष लगे। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर की वितरण प्रणाली 3152 किलोमीटर लंबी है और इसका कमान्ड क्षेत्र 7 लाख हेक्टेयर है। इसी चरण में 6 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की वितरण प्रणाली 1960 किलोमीटर है और उनका कमान्ड क्षेत्र 3.21 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है व 5112 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली है और कुल कमान्ड क्षेत्र 10.12 लाख हेक्टेयर है। 80% सिंचाई गहनता पर इस चरण की सिंचाई क्षमता 8.10 लाख हेक्टेयर है। परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर दिसम्बर 1986 में पूरी हुई एवं 1 जनवरी 1987 को तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह द्वारा इसमें जल प्रवाहित किया गया।

आठवीं योजना में परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण पर 700 करोड़ (284 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सहित) उपलब्ध कराये गये। नवीं योजना में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।³ द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रथम चरण की 189 किलोमीटर लंबी नहर के अतिरिक्त शेष बची मुख्य नहर दत्तोत शाखा, विमिलपुर शाखा

1 & 2. Data from Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Raj.
3 & 4. Draft 11th Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Raj.

चारणवाली शाखा नाचना शाखा गडरा रोड उपशाखा लिफ्ट योजनाये व वितरण प्रणाली का कार्य सम्पलित था। मार्च 98 तक 6256 कि मी लम्बी शाखाओ तथा वितरिकाओ का निर्माण किया जा चुका है जबकि लक्ष्य 9180 कि मी तक का था इस कार्य पर 1746 करोड रु का (प्रथम चरण पर 343 करोड तथा द्वितीय चरण पर 1403 करोड रुपये) व्यय किये जा चुके हैं।

4 इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण की जलोत्थान सिंचाई याजना (Lift Irrigation Projects in First Stage) कवरसेन लिफ्ट सिंचाई योजना (लून्करणमर बीकानेर जलोत्थान नहर) (Kanwar Sen Lift Irrigation Project) यह प्रथम चरण की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्य से बीकानेर को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इस नहर में पानी को 60 मीटर ऊंचा उठाया गया है।

5 इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में लिफ्ट सिंचाई याजनाएँ (Lift Irrigation Projects in Second Stage)

(i) नोहर साहवा लिफ्ट सिंचाई योजना (Nohar Sahawa Lift Irrigation Project)- इस नहर से गगानगर व चुरू जिलों को लाभ पहुँचेगा। इस जलोत्थान नहर में पाच स्थाना पर पानी को पम्पों में उठाया जायेगा। साहवा नहर से 750 मीटर लंबी वितरण प्रणाली से प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई जायेगी। यह नहर 109 किलोमीटर लंबी है।

(ii) गजनेर लिफ्ट सिंचाई योजना (Gajner Lift Irrigation Project)- बीकानेर जिले के अंतगत 32 किलोमीटर लंबी इस नहर की वितरण प्रणाली 240 किलोमीटर होगी। इसमें 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जायेगी तथा इस योजना में पानी को छ स्थाना पर ऊंचा उठाया जायेगा।

(iii) कोलायत लिफ्ट सिंचाई योजना (Kolayat Lift Irrigation Project) बाकानेर जिले की यह नहर 31 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी वितरण प्रणाली की लंबाई 382 किलोमीटर होगी। इसमें 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई जा सकागी। इस नहर में भी जल को छ स्थाना पर ऊंचा उठाया जायेगा।

(iv) फलोदी लिफ्ट सिंचाई योजना (Phalodi Lift Irrigation Project) जोधपुर जिले की यह नहर 32 किलोमीटर लंबी होगी। इसका वितरण प्रणाली की लंबाई 400 किलोमीटर तथा इसकी सिंचाई क्षमता 1.4 लाख हेक्टेयर भूमि होगी। इस याजना में जल को 7 स्थाना पर ऊंचा उठाया जायेगा।

(v) पोकरण लिफ्ट सिंचाई योजना (Pokharan Lift Irrigation Project)- जैसलमेर जिले की यह

नहर 26 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी वितरण प्रणालिया 170 किलोमीटर लंबी होगी इसमें 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई जा सकेगा।

(vi) बांगसर लिफ्ट सिंचाई योजना (Bangarsar Lift Irrigation Project) यह परियोजना सन् 2004 में 2500 करोड की लागत से पूरी होने की संभावना है।

6 लागत (Cost)- 1957 में इस परियोजना के निर्माण की लागत 66.46 करोड रूपए आने की संभावना थी। परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन और कीमतों में वृद्धि के कारण 1970 में इस योजना के पूरा होने पर 207.70 करोड रुपये लगने की संभावना थी। 1975 में यह लागत बढ़कर 331.10 करोड रुपये तक आकी गई। 1978 में यह पुन 415 करोड रुपये हो गई। परियोजना के प्रथम चरण के कार्यों पर 31 मार्च 1992 तक 277 करोड रुपये व्यय हो चुके थे। राजस्थान नहर परियोजना का द्वितीय चरण सन् 2005 में लगभग 2267 करोड रुपये की लागत से पूरा होने की संभावना है।

7 राजस्थान फीडर (Rajasthan Feeder) सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर हरिके बाध बनाया गया है। वहां से राजस्थान फीडर निकाली गयी इस राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। इस फीडर का 150 किलोमीटर तक का भाग पंजाब में और उसके पश्चात् 19 किलोमीटर तक का भाग हरियाणा राज्य में है। राजस्थान फीडर का उद्देश्य राजस्थान नहर को पानी उपलब्ध कराना है। इस फीडर में पंजाब और हरियाणा में कहीं भी पानी नहा लिया जाता है। राजस्थान फीडर एक पक्का और पलस्तरपुक नहर है जो कि प्रथम श्रेणी चरण के अंतगत पूरी हो चुकी है।

8 राजस्थान नहर (Rajasthan Canal) जहाँ राजस्थान फीडर समाप्त होती है वहां से राजस्थान नहर का कार्य आरम्भ हो जाता है। राजस्थान नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। प्रथम चरण में राजस्थान नहर का 189 किलोमीटर का भाग और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर नहर का निर्माण कार्य पूरा करना था। राजस्थान की मुख्य नहर का कार्य अर्थात् सम्पूर्ण 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर पूर्ण हो चुकी है। राजस्थान नहर का पैदे की चौड़ाई 38 मीटर और नहर के ऊपरी भाग में इसकी चौड़ाई 67 मीटर है। राजस्थान नहर की गहराई 6.4 मीटर है। इस कारण इस नहर में 523 घन मीटर पानी प्रति सेकण्ड प्रवाहित हो सकता है।

9 प्रवाह एवं जलात्थान क्षेत्र (Flow and Lift Area)- राजस्थान नहर परियोजना के समस्त क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का कार्य दो प्रकार का प्रवाह क्षेत्र में बंटा हुआ है। सामान्य प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत पानी स्वतः अपने दल पर बहता है। राजस्थान

1. Economic Survey 1998-99 Ra

2. नक्शा नं 2 एम्स 5 मई 1993

3. Dist No III Five Year Plan 1997-2000 Govt of Ra

नहर परियोजना का पश्चिमी भाग स्वतः ढाल लिये हुये है। इस कारण उस क्षेत्र में शाखाओं और उपशाखाओं का जाल आसानी से सामान्य प्रवाह क्षेत्र के माध्यम से बिछाया जा सकता है। इस परियोजना में ऐसा भी किया जा है। राजस्थान नहर परियोजना का पूर्वी क्षेत्र सामान्य प्रवाह क्षेत्र में नहीं आता है। इस कारण जलोत्थान योजनाएँ बनाई गई हैं। जलोत्थान योजनाओं के अंतर्गत प्रथम चरण में लूणकरणसर चौकानेर लिफ्ट सिंचाई द्वारा पानी उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई। इसके अंतर्गत जल को चार पम्पिंग स्टेशनों के द्वारा 60 मीटर तक उठाया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत नोहर साहवा गजनेर कोलायत फलोदी पोकरण तथा बागडसर लिफ्ट नहरे मुख्य जलोत्थान परियोजनाएँ हैं।

10 वितरण प्रणाली (Distribution System)

राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत कुल 9 शाखाओं और 21 उपशाखाओं का निमाण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण के अंतर्गत प्रथम 3 शाखाओं अर्थात् सूरतगढ़ अनुपगढ़ आर नारोरा शाखा का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में शेष सभी शाखाओं पर कार्य करना था। राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत वितरण प्रणाली का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है।

विभाग	इकाई	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल योग
सामान्य				
ग्राम क्षेत्र	कि.मी.	2743	352	5895
जलोत्थान क्षेत्र	कि.मी.	332	1960	2292
योग	कि.मी.	3075	512	8187

11 कमाण्ड क्षेत्र विकास (Command Area Development)

विदेशी सहायता से प्रथम चरण के अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्यक्रम आरम्भ किया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से जून 1983 तक 1.87 लाख हेक्टेयर भूमि में पक्के जल प्रवाह मार्ग बनाये गये। द्वितीय कृषि विकास के अन्तर्राष्ट्रीय कोष की सहायता से दिसम्बर 1988 तक 1.73 लाख हेक्टेयर भूमि को पुनः इसी प्रकार के कार्य के अंतर्गत लाया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत 92911 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों प्रकार का कार्य पूरा किया गया। रेत क टीला का स्थिर करने और नहरों में रेत उड़कर एकत्रित होने जैसी स्थिति को समाप्त करने की चेष्टा की गई। वृक्षारोपण का कार्य हाथ में लिया गया। कमाण्ड विकास क्षेत्र में मड़का की स्थिति में सुधार किया गया। चरागाहों का विकास किया गया। उपलब्ध सिंचाई क्षमता को पूरा लाभ उठाने के लिये पर्वीय कृषि सहायक सेवाएँ प्रदान करने की वांछना की गई। वितरण नहरों को पक्का किया गया। पेयजल उपलब्ध करवाया

गया। भूमि को समतल बनाने की चेष्टा की गई। क्षारीय भूमि को सुधारने की चेष्टा की गई। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों और कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिये अनेक विकास योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

12 विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme)

1968 से विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत निशुल्क खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि इन पदार्थों को श्रमिकों व कम वेतन वाले कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बाजार मूल्य की आधी दरा से बेचा जा सके। इस विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी उस राशि से एक कोष निर्मित किया जाएगा। इस कोष पर ध्यान भी देय होगा। इस कोष की राशि श्रमिकों के कल्याण के विभिन्न कार्यों और कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक संरचना को सुधारने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकेगा।

1968 में विश्व खाद्य कार्यक्रम आरम्भ होने से लेकर मार्च 1990 तक खाद्य पदार्थों के विक्रय 24.14 करोड़ के कोष निर्मित किये गये। इस राशि में से विद्यालयी अस्पतालों पर्यु चिकित्सालयों बच्चा के उद्यान सामुदायिक केन्द्र विपणन केन्द्र शरण स्थली डिग्री खली सड़के नालिया वृक्षारोपण चरागाह विकास और चलती फिती चिकित्सा इकाइया आदि पर 19.62 करोड़ रूपए व्यय किये गये। दो करोड़ रूपए का एक ऐसा कोष भी बनाया गया है जिससे क्षेत्र में बसने वाले लोगों को बिना ब्याज के ऋण प्रदान किये जायेंगे जो कि उन्हें दो वर्षों की अवधि के पश्चात् चार किस्तों में चुकाने होंगे।

13 आवास (Housing) राजस्थान नहर परियोजना के अनेक उद्देश्यों में से एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि लोगों को उस क्षेत्र में बसने को प्रेरित करे। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये इस क्षेत्र में 112437 लोगों को 8.39 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। ऐसा किया जाने के पश्चात् भी इस दशा में इसकी प्रगति धीमी है। इसका कारण इस क्षेत्र में जलवायु की विषमताओं के साथ साथ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का विद्यमान न होना है। इन बाधाओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में लोग बड़ी मात्रा में बसने हेतु प्रेरित हो सकें।

14 पेयजल आपूर्ति (supply of Drinking Water) इस परियोजना के अंतर्गत जो जल उपलब्ध है उसका 11.5 प्रतिशत भाग पेयजन के लिए निर्धारित किया गया है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए

जन- स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लिफ्ट योजनाओं के माध्यम से 11 महसूलवाली जिलों का पेयजल उपलब्ध करने की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। कवर सैन लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से जोधपुर के 40 और जेसलमेर के 30 गावों सहित कुल 140 गावों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जोधपुर जल-आपूर्ति योजना के पूर्ण होने पर जोधपुर शहर और इसके आस-पास के 158 गावों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान में गगानगर, बीकानेर, जेसलमेर और जोधपुर जिलों को इंदिरा गांधी नहर से पानी मिल रहा है।

15 परियोजना अध्ययन (Project study) - राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण के संदर्भ में जल एवं विद्युत कन्सल्टेन्सी सेवा द्वारा सम्भाव्य सहायता के लिए सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ताकि इस प्रतिवेदन को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिये प्रस्तुत किया जा सके। इस परियोजना पर 15 और भी प्रतिवेदन हाथ में लिये जा चुके हैं ताकि इस परियोजना क्षेत्र की स्थिति एवं निवेदन को और प्रभावी बनाया जा सके। साथ ही उपलब्ध जल का अधिकतम प्रयोग इन सभी अध्ययनों को जल एवं विद्युत कन्सल्टेन्सी मॉनिटरिंग द्वारा बनाये गये प्रतिवेदन में स्थान दिया जायेगा।

16 लघु जल विद्युत गृह (Small Hydroelectricity Projects) - परियोजना के अंतर्गत आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में जल-विद्युत उत्पन्न का जा सकता है। वर्तमान में इस परियोजना के अन्तर्गत अनुपगंड व सूरतगंड शाखाओं पर जल विद्युतगृह निर्माण क्रिय में रहे हैं। इन विद्युतगृहों की कुल क्षमता 13 मेगावाट होगी। जल विद्युत उत्पादन की गति प्रदान करने के लिये चारणवाली और शहोद योरेवल शाखा को भी इस उद्देश्य में आचा परखा जा रहा है।

17 रोचक तथ्य (Interesting facts) - राजस्थान नहर परियोजना की विशालता का अनुमान इस बात से लगता है कि इसका निर्माण में की जाने वाली खुदाई व ढुलाई लगभग 1200 करोड़ घन फुट है। इस मिट्टी से विश्व के नार्न और चार फुट माटी और 20 फुट चाड़ी सड़क निर्मित की जा सकती है। इस नहर में जो इटे लगी ह, उन पर लगभग 72 पैसे प्रति इट की औसत रकम लगाने आई है। इस परियोजना के अन्तर्गत सूरतगंड में एक स्थान पर नीचे घग्घर नदी को डाइवजन चैनल की पानी प्रवाहित हो रहा है और उसके ऊपर राजस्थान नहर का पानी प्रवाहित हो रहा है। इस परियोजना में मुख्य नहर के ऊपर हर टाइम क्लोस मोटर को दूरी पर पुन है। हरपुल पर एक घाट भी बनाया गया है। परियोजना

के अंतर्गत हर 5000 फुट पर सीढ़िया बनाई गई हैं। नहर के साथ-साथ टेलीफोन सुविधा और पक्की सड़कें बनाई गई हैं। इस परियोजना पर यदि 15-20 करोड़ रुपये और व्यय किये जायें तो इस परियोजना को आंतरिक जल परिवहन के योग्य भी बनाया जा सकता है।

इंदिरा गांधी परियोजना की सफलताएं या इसके लाभ

ADVANTAGES

इंदिरा गांधी परियोजना मानवीय परिश्रम से प्राकृतिक प्रतिकूलताओं को अपने पक्ष में करने का अनुपम उदाहरण है। परियोजना के पूरा होने पर इस क्षेत्र की स्थिति क्या होगी इसका आभास वर्तमान में प्राप्त लाभों से हो सकता है। राजस्थान नहर परियोजना की सफलताएं और उनके लाभों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

1 सिंचाई (Irrigation) - राजस्थान नहर परियोजना के पूरा होने पर लगभग 14.77 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचा जा सकता है। सिंचाई के कारण अधिक फसल ली जा सकती है, साथ ही वनस्पति की मात्रा भी बढ़ेगी। फलस्वरूप रेगिस्तानी मिट्टी में जीवाणु का प्रतिशत बढ़ेगा। इस परियोजना के अंतर्गत अभी तक 10.38 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है और उसके माध्यम से 8.76 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा रही है। इस परियोजना के विद्यमान सिंचाई क्षमता और सिंचित क्षेत्र इस प्रकार हैं

(लाख हेक्टेयर में)				
विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल योग	
निश्चित सिंचाई क्षमता	5.76	1.50	7.26	
निश्चित क्षेत्र	5.53	0.17	5.70	
इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित सकल क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)				
जिले	1980-81	1985-86	1990-91	1993-94
गंगानगर	292.79	342.87	406.20	262.14
हनुमानगढ़	-	-	-	129.60
बीकानेर	33.70	64.16	124.00	141.47
जैसलमेर	-	0.002	1.52	6.20
योग	326.49	406.63	531.72	539.56

सं. Trends and Use Statistics 6/15 123-25 R

Source: Land Use Statistics 1993-94, p. 26

2 कृषि उत्पादन (Agricultural Production)

राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण गगनहर के माध्यम से हुये विकास को दृष्टिगत रखते हुये किया गया था। गगनहर ने यह सिद्ध कर दिया था कि रेगिस्तान प्राकृतिक नहीं बल्कि

कृत्रिम है। यहाँ की भूमि पहले काफी उपजाऊ रही है। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। इस प्रकार इस क्षेत्र में गेहूँ, जौ, गन्ना, कपास और अनेक प्रकार की व्यवसायिक और खाद्य फसलें लेना संभव हो सकेगा। जैसा अनुमान है कि परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 1200 करोड़ रूपए के कृषि सम्बन्धित वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि भूमि की लागत लगभग 5000 करोड़ रूपए आती गई है। इस परियोजना में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रथम चरण के अंतर्गत 14.5 लाख टन, द्वितीय चरण में 22.5 लाख टन और इस प्रकार संपूर्ण परियोजना के द्वारा 37 लाख टन खाद्य फसलें लेना संभव हो सकेगा।

3 सूखे व अकाल का सामना (Check on Draughts & Famines) - राजस्थान का यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सदैव ही अकाल व सूखे से ग्रस्त रहा है। राजस्थान के गठन के पश्चात् के 4-5 वर्षों को छोड़ दिया जाये तो शेष सभी वर्षों में यह क्षेत्र अकाल व सूखे से पीड़ित रहा है। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में फसल एवं वनस्पतियों के माध्यम से जीवारा की मात्रा बढ़ने की संभावना है। ऐसा होने पर क्षेत्र की मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन होगा। इस क्षेत्र की जलवायु भी धीरे-धीरे बदलने लगेगी। इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लग सकता है लेकिन अल्पावधि में मूष, एवं अकाल की समस्या का सामना करने की क्षमता इस परियोजना ने प्रदान कर दी है।

4 रेगिस्तान प्रसार पर रोक (Control over Desert) - इस परियोजना के अंतर्गत व्यापक रूप से किये जा रहे वृक्षारोपण के माध्यम से रेगिस्तान के प्रसार को रोका जा सकेगा। मिट्टी के टीलो को स्थिर बनाया जा सकेगा। वनों के माध्यम से वर्षा के आकर्षित होने से यह क्षेत्र धीरे-धीरे जलवायु की विषमता से मुक्त हो सकेगा। रेगिस्तान प्रसार को रोकने का सर्वाधिक ज्ञात एवं प्रभावी उपाय वृक्षारोपण ही है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये विश्व में पहली बार यहाँ एक वन रेगिस्तान की गई है जो समर्पित होकर वृक्षारोपण का कार्य कर रहा है। इस वृक्षारोपण का प्रभाव आगामी 15-20 वर्षों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा।

5 रोजगार (Employment) राजस्थान नहर परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है। इस परियोजना पर पिछले 30 से भी अधिक वर्षों से कार्य चल रहा है। आगामी 10 वर्षों तक तो इस पर कार्य चलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में यह परियोजना बहुत बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखती है। इस परियोजना के माध्यम से अन्य क्षेत्रों का भी विकास होगा। उन प्रभावों के कारण भी रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। इस परियोजना में बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, गार्थ आदि का मिट्टी ढलाई में प्रयोग किया

गया है और किया जा रहा है।

6 जलापूर्ति (Water supply) - जैसा की सभी को ज्ञात है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पेयजल की सदैव कठिनाई रहती है इसका कारण जलस्तर का बहुत नीचा होना है। इस प्रकार एक ओर तो इस क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध नहीं है तथा दूसरी ओर औद्योगिक कार्यों के लिये भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत 1200 घन मीटर जल पेयजल और औद्योगिक कार्यों के लिये निर्धारित किया गया है। परियोजना के प्रथम चरण में 300 और द्वितीय चरण में 900 घन मीटर जल उपरोक्त उद्देश्यों के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। कैंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर व पास के 99 गाँवों तथा गधेली महाबा लिफ्ट योजना चुरू जिले के 175 गाँवों तथा जोधपुर लिफ्ट योजना से जोधपुर शहर तथा गाँवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

7 कस्बों व मंडियों का विकास (Development of Towns & Mandis) - उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। इस कारण इस क्षेत्र में कस्बों व मंडियों का विकास नहीं हो पाया। मंडियों का विकास न होने का एक कारण इस क्षेत्र में कृषि और औद्योगिक विकास का भी अभाव रहा है। राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से कृषि एवं औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इस प्रकार इस परियोजना के अंतर्गत आवास को प्रोत्साहित करने के लिये नौ सुविधाएँ दी जा रही हैं। उससे लोग उस क्षेत्र में बसने को प्रेरित होंगे। इस प्रक्रिया में कस्बा व मंडियों का विकास होगा तथा जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा।

8 औद्योगिक विकास की संभावनाएँ (Possibilities of Industrial Development) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्तमान में कायला आलु, नमक दो प्रमुख खनिज विद्यमान हैं। तेल की खोज के लिये जो प्रयास किये गये हैं उनसे इस क्षेत्र में उर्जन तेल मिलने की संभावनाएँ और बढ़ी हैं। इस क्षेत्र में गन्धक तो मिली ही है भविष्य में बड़ी मात्रा में तेल भी मिल सकता है। इस तथ्य का दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावनाएँ बढ़ी हैं। साथ ही राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है उसका लाभ भी उद्योगों को प्राप्त होगा। कृषि के विकास के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्योग भी विकसित होंगे। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से भी आधुनिक विकास प्रोत्साहित होगा।

9 संचार साधना का विकास (Development of Communication) - राजस्थान नहर परियोजना की

प्राप्ति के साथ-साथ इस क्षेत्र में विशेषकर नहर के आस-पास के क्षेत्रों में टेलीफोन और मडकों की सुविधा का विकास किया जा रहा है। यह किसी भी विकास के लिये मूलभूत आवश्यकता नहीं जा सकती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवहन के माधनों के विकसित न होने का मूल कारण रेगिस्तानी क्षेत्र की प्रकृति है। इसे भी धीरे-धीरे परिवर्तित किया जा सकेगा और उसके साथ-साथ ही संचार के साधन विकसित हो पाएंगे।

10 सीमा सुरक्षा (Border Security) - राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र जैसे-जैसे विकसित होगा, वैसे-वैसे लोग यहां बसने के लिये आकर्षित होंगे। परियोजना के क्षेत्र में अवकाश प्राप्त सैनिकों व अन्य लोगों को भूमि आवंटित की जा रही है। इससे पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर वर्तमान में क्षेत्र के निर्जन होने के कारण जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान हो सकेगा। इस क्षेत्र में संचार माधनों का पर्याप्त विकास होने के पश्चात् सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुचारु बनाया जा सकेगा। साथ ही घनत्व में वृद्धि के साथ-साथ प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था विकसित होने से सीमा सुरक्षा उपायों को बल मिलेगा।

11 जल-विद्युत (Hydro-electricity) - जिस प्रकार समुद्र में लहरों से विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसी प्रकार नहर के बहने हुये पानी से आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल-विद्युत उत्पादित करना संभव है। राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत इस तकनीक का प्रयोग कर परियोजना को पूर्ण जल-विद्युत उत्पादन क्षमता न तो विकसित हो गई है, न उसमें संबंधित पूर्ण योजना बनाई गई है। वर्तमान में परियोजना के लिए आवश्यक जल-विद्युत प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। यदि सम्पूर्ण परियोजना में विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जाय तो इस परियोजना से कम से कम रेगिस्तानी क्षेत्र का तो जल-विद्युत उपलब्ध कराई ही जा सकती है।

12 पशुपालन व मत्स्यपालन (Animal Husbandry & Fisheries) - इस परियोजना के अंतर्गत पशुपालन को प्रेरित करने के लिये चरागाहों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। खेतियों का निर्माण किया गया, डिग्रीवा बनाई गई वृक्षारोपण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया घनत्व की विरलता को दूर करने की कोशिश की गई। इस सभी कारणों से पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्याप्त जल उपलब्ध होने से नहर के अतिरिक्त, डिग्रीवों व परियोजना के जल से निर्मित छोटे-छोटे तालाबों आदि में मत्स्यपालन भी संभव हो सकेगा।

13 पर्यटन विकास (Tourism Development) -

मरुभूमि हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। साथ ही जैसलमेर, जोधपुर आदि की स्थापत्य कला भी उनके आकर्षण का केंद्र है। यह परियोजना रेगिस्तान में उन्हें स्वर्ग का सा अहसास करावेगी। वैसे भी यह परियोजना अपने आप में एक आकर्षण का केन्द्र होगी क्योंकि यह मानव के मत्स्यत्म् प्रयासों में से एक है। इस कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

14 भूमि सुधार (Land Reforms) - इस परियोजना के अंतर्गत इसके कमाण्ड क्षेत्र में भूमि को समतल करने की चेष्टा की जा रही है। इस क्षेत्र की क्षारीय भूमि को ठीक करने की चेष्टा की गई है। कमाण्ड क्षेत्र में पक्की नालियों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों को जो भूमि आवंटित की गई है, उसका आकार, आर्थिक आकार रखा गया है। यह सभी प्रयास भूमि सुधार की ओर सराहनीय प्रयास कहे जा सकते हैं।

15 समग्र विकास (Overall Development) - इस परियोजना के पूर्ण होने पर सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास होने की संभावनाएं बनी हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि का विकास होगा। इसके फलस्वरूप सरकारी व राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। क्षेत्र के निवासियों का पिछड़ापन व गरीबी दूर हो सकेगी, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। संक्षेप में यह परियोजना उस क्षेत्र के निवासियों के लिये ही नहीं वरन् संपूर्ण देश के लिये वरदान सिद्ध होगी।

राजस्थान की अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

OTHER IMPORTANT IRRIGATION PROJECTS OF RAJASTHAN

1. चम्बल नदी - घाटी परियोजना

Chambal River - River Valley Project

पृष्ठभूमि व परिचय (Background & Introduction) - बल नदी मध्य प्रदेश राज्य में विन्ध्यचल पर्वत से निकलकर 1045 किलोमीटर बहने के पश्चात् यमुना नदी में मिल जाती है। वर्षा ऋतु के समय इस नदी में प्रायः बाढ़ें आती थीं। नदी के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण अक्ष-पास के क्षेत्रों में गहरे गलों का निर्माण हो गया था। अब चबल की विनाशालीला पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से चबल नदी घाटी परियोजना के निर्माण का निर्णय किया गया। 1943 व 1946 में इसके निर्माण का प्रयास किया गया लेकिन ये प्रयत्न सफल नहीं हुये। 1950 में केन्द्रीय

जल शक्ति व नाकायान आयोग ने इस परियोजना को अंतिम रूप प्रदान किया। वर्ष 1953-54 में चम्बल नदी घाटी परियोजना प्रारम्भ हुई। वह राजस्थान तथा मध्यप्रदेश राज्यों को समन्वित परियोजना है।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य (Main Object) :- चबल नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे

- (1) बाढ़ों पर नियंत्रण लगाकर जल धन की हानि को रोकना।
- (2) मिट्टी का कटाव की समस्या का समाधान करना।
- (3) बांधों व नहरों के निर्माण से राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना।
- (4) जल विद्युत की पूर्ति में वृद्धि करना ताकि राज्य को विद्युत सबंधी आवश्यकता पूर्ण की जा सके।
- (5) मलेरिया नियंत्रण व मच्छली पालन को बढ़ावा देना।
- (6) चबल क्षेत्र की जनजातियों के 'जावन स्त' को ऊँचा उठाना।
- (7) अकाल पर रोक लगाना तथा कृषि का स्थायी स्वरूप प्रदान करना।

परियोजना के प्रमुख कार्य (Main Works) :- उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए चबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

- (i) मध्यप्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में चबल नदी पर गांधीसागर बांध का निर्माण करना।
- (ii) चबल नदी पर काटा नगर में कोटा सिंचाई बांध का निर्माण करना।
- (iii) कोटा सिंचाई बांध के दोनों तरफ दो नहर बनाना।
- (iv) राणासागर बांध का निर्माण करना।
- (v) जवाहर सागर बांध बनाना।
- (vi) सभी बांधों (काटा सिंचाई बांध के अलावा) पर जल विद्युतगृहों का निर्माण करना।

चबल नदी घाटी परियोजना सबंधी प्रमुख तथ्य (Main Features of the Project) :-

(अ) **परियोजना का प्रथम चरण (First Stage of the Project) :-** परियोजना के प्रथम चरण में गांधीनगर बांध काटा सिंचाई बांध व काटा सिंचाई बांध के दोनों तरफ दो नहरों का निर्माण का कार्य पूरा किया गया। प्रथम चरण में निम्नलिखित कार्य पूरे किये गये

(i) **गांधीसागर बांध (Gandhi Sagar Dam) :-** चबल नदी पर मध्यप्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में राजस्थान राज्य की सीमा के निकट गांधी सागर नामक

बांध का निर्माण किया गया। इस बांध की लंबाई 513.5 मीटर व चौड़ाई 62 मीटर है। इस बांध के जलाशय का कुल क्षेत्रफल 380 वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण कार्य 1959 में पूर्ण हुआ था। इस बांध पर 5 मीटर चौड़ा एक सड़क भी बनाई गई। बांध से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु 10 फाटक बनाये गये हैं।

(ii) **कोटा सिंचाई बांध (Kota Barrage) :-** कोटा के पास चबल नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया जिसकी लंबाई व ऊँचाई क्रमशः 438 मीटर व 42 मीटर है। यह बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ। इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। दाईं मुख्य नहर की लंबाई 372 कि.मी. तथा बाईं मुख्य नहर की लंबाई 170 कि.मी. है।

(iii) **नहरों का निर्माण (Construction of Canals) :-** कोटा बांध के दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। बाय किनारे की नहर 95 किलोमीटर लंबी है और इस नहर की शाखाओं एवं उपशाखाओं सहित कुल लंबाई 182 किलोमीटर है। यह नहर बूंदी नगर के निकट मेजा नदी में मिल जाती है। दायें किनारे की नहर की लंबाई 425 कि.मी. है। शाखाओं व उपशाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। राजस्थान में यह 120 किलोमीटर दूरी तक पश्चात् मध्यप्रदेश में प्रवेश करता है।

(ब) **परियोजना का द्वितीय चरण (Second Stage of the Project) :-** इस चरण में राणाप्रताप सागर बांध तथा विद्युत गृह बनाने का निश्चय किया गया। यह कार्य पूर्ण हो चुका है। राणाप्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध के उत्तर में 33 किलोमीटर दूर चबल नदी पर बनाया गया। इस बांध की लंबाई व ऊँचाई क्रमशः 1100 मीटर व 41 मीटर है।

(स) **परियोजना का तीसरा चरण (Third Stage of the Project) :-** इस चरण में जवाहर सागर अथवा काटा बांध तथा इसके विद्युत गृह का निर्माण किया गया। जवाहर सागर बांध अथवा कोटा बांध काटा सिंचाई बांध से 16 किलोमीटर दक्षिण में बनाया गया है। इसकी लंबाई व ऊँचाई क्रमशः 440 मीटर व 45 मीटर है।

(द) **परियोजना से सिंचाई (Irrigation) :-** चबल नदी घाटी परियोजना के काटा सिंचाई बांध में निकासी गई बाय किनारे की नहर से राज्य की 170 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। दायें व बायें किनारे से नहरों से राजस्थान व मध्यप्रदेश की 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई है। इन नहरों की सम्बंधित सिंचाई भूमि 498 लाख हेक्टेयर है।

चबल नदी नहरों से बोनोर और पूना जिलों का सिंचित भूमि इस प्रकार है

चबल नहर से सिंचित सकल क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)				
वर्ष	1980-81	1985-86	1990-91	1993-94
कटा	121.14	145.73	152.70	131.49
बाघ	-	-	-	45.19
बूढ़ी	95.05	101.87	92.36	107.50
कुल बाघ	216.19	247.61	245.06	284.20

(य) परियोजना में जल-विद्युत का उत्पादन (Hydro-electricity) - गभीरसागर बाघ में 5 विद्युत जनन इकाइया है जिनसे विद्युत उत्पादन क्षमता 1,15,000 किलोवाट है। गंगाप्रताप सागर बाघ में 4 विद्युत जनन इकाइया है, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1,72,000 किलोवाट है। इसी प्रकार जवाहरसागर बाघ के 3 विद्युत जनन इकाइया है जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99,000 किलोवाट है। इस प्रकार चबल नदी घाटी परियोजना को कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,88,000 किलोवाट है।

(र) नवी योजना (1997-2002) में चबल परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों पर 67.8 करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे।

परियोजना के लाभ (Advantages) - प्रमुख लाभ निम्नलिखित है -

(i) सिंचाई एवं जलापूर्ति (Irrigation and Supply of water) - इस परियोजना के अंतर्गत कोटा सिंचाई बाघ से निकाली गई नहरों से लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अतः राज्य में खाद्यान्नों व व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। चबल क.पानी से कोटा बाघ, बूढ़ी व सवाई माधोपुर की जलापूर्ति होती है।

(ii) बाढ़ों पर नियंत्रण (Flood Control) - इस परियोजना से चबल नदी की बाढ़ों पर नियंत्रण कर लिया गया है। अतः क्षेत्र के जन धन व कृषि फसलों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। इससे वर्षा के जल का अधिकतम उपयोग संभव हुआ है।

(iii) कटाव पर रोक (Check on Soil Erosion) - चबल नदी ने लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि में कटाव की समस्या उत्पन्न कर दी थी। कटाव वाली भूमि के क्षेत्र में गहरे गड्ढों का निर्माण हो चुका है। इस भूमि को समतल करने में लगभग 3000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है लेकिन इस परियोजना के कारण भूमि के कटाव पर रोक लग चुकी है।

(iv) विद्युत उत्पादन (Electricity Generation) - यह परियोजना वृषि विकास के साथ साथ राज्य के औद्योगिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। इससे राजस्थान व मध्यप्रदेश को 3.86 लाख किलोवाट जल-विद्युत प्राप्त हुई

है तथा इसमें विद्युत सबंधी घरेलू आवश्यकताएं भी पूर्ण हो रही हैं।

(v) मण्डियों का विकास (Development of Mandies) - इस परियोजना से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होने के कारण राज्य में तेजी से कृषि का विकास हुआ है। अतः अनेक कृषि मण्डियों की स्थापना हो चुकी है। इससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने लगा है।

(vi) औद्योगिक विकास (Industrial Development) - इस परियोजना का क्षेत्र विद्युत साधनों को कमरे के कारप में पिछड़ा हुआ था लेकिन इस योजना से पर्याप्त जल विद्युत प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है। राज्य का कोटा शहर एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र बन चुका है।

(vii) वनों व चरागाह का विकास (Development of Forests & Pastures) - चबल नदी घाटी परियोजना से जल की पर्याप्त पूर्ति के कारण वनों व चरागाहों का तेजी से विकास हो रहा है। इससे पशुपालन व्यवसाय भी प्रगति कर रहा है। इस परियोजना क्षेत्र में फलों की बागवानी भी संभव हुई।

(viii) मछलीपालन (Fisheries) - चबल नदी घाटी परियोजना में प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ रुपये की मछलियां पकड़ना संभव हो सकेगा। इससे न केवल खाद्य पदार्थों की पूर्ति में वृद्धि होगी वरन् अनेक लोगों को राजस्वार की प्राप्ति भी होगी।

2 भांखड़ा-नांगल परियोजना

Bhakra Nangal Project

पृष्ठभूमि व परिचय (Background & Introduction) - यह राजस्थान पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह एक विशाल परियोजना है जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर भांखड़ा व नांगल नामक स्थानों पर दो बांध बनाये गये हैं। सर्वेक्षण सन् 1909 में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस डेन ने सतलज नदी पर एक बांध बनाने का विचार प्रस्तुत किया लेकिन इस परियोजना पर स्वतंत्रता के पश्चात् ही कार्य आरंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना के संघर्ष में कहा था 'भांखड़ा बांध का निर्माण एक चमत्कार, एक विराट वस्तु है इसे देख कर रामाचरण जाता है। इस योजना पर 236 करोड़ रुपए व्यय किये गये जिसका व्ययस्थापक राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा कर गई थी।

परियोजना के उद्देश्य (Objects) :- इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(i) सिचाई सुविधाओं के लिए नहरों का निर्माण आदि व सरहिंद नहर को जल की पर्याप्त पूर्ति करना।

(ii) बाढ़ों पर रोक लगाना।

(iii) राजस्थान पंजाब व हरियाणा के लिए पर्याप्त जल विद्युत का उत्पादन करना।

(iv) राजस्थान में सिचाई सुविधाओं का विस्तार करके रेंगमातन के प्रसार पर रोक लगाना।

(v) दलों व चरागाहों का विकास करना।

(vi) मछलीपालन व्यवसाय का विकास करना।

(vii) सतलज के मैदानी क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करके खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करना।

परियोजना के प्रमुख कार्य (Main Works) -

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाखड़ा-नागल परियोजना के अन्तर्गत ये कार्य करने का निश्चय किया गया-

(i) भाखड़ा नामक स्थान पर भाखड़ा बांध का निर्माण करना।

(ii) भाखड़ा बांध पर दो विद्युत गृहों का निर्माण करना।

(iii) नागल नामक स्थान पर नागल बांध का निर्माण करना।

(iv) नागल बांध पर जल-विद्युत उत्पादन के लिए नहर का निर्माण करना।

(v) नागल जल विद्युत नहर पर तीन विद्युत गृहों का निर्माण करना।

(vi) नागल बांध की मुख्य नहर शाखाओं व उपशाखाओं का निर्माण करना।

(vii) बिस्त दो-आब तथा सरहिन्द नहर का विकास करना।

परियोजना की प्रमुख बातें (Main Features of the Project)

(अ) बांधों का निर्माण (Construction of Dams)
इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बांधों का निर्माण किया गया -

(i) भाखड़ा बांध (Bhakra Dam) - यह बांध पंजाब राज्य के सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है। इस बांध की लंबाई 518 मीटर है और नदी तल से बांध की ऊँचाई 226 मीटर है। इसके जलाशय का नाम गोविन्दसागर है। इस जलाशय में जल एकत्र होने की क्षमता एक करोड़ घन मीटर है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है।

(ii) नागल बांध (Nangal Dam) - भाखला बांध से 12 किलोमीटर नीचे की ओर नागल नामक स्थान पर नागल बांध का निर्माण किया गया है। बांध की लंबाई व ऊँचाई क्रमशः 305 मीटर व 29 मीटर है। इस बांध के जलाशय

में 26000 एकड़ फुट पानी एकत्रित किया जा सकता है। इस बांध से 64 किलोमीटर लंबी जल विद्युत नहर निकाली गई है। यह नहर न केवल जल विद्युत उत्पन्न करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वरन् भाखड़ा बांध की मुख्य नहर व शाखाओं को जल की पूर्ति भी करती है।

(ब) परियोजना की नहरी व्यवस्था (Canal System of the Project) -

(i) भाखड़ा की मुख्य नहर (Main Bhakra Canal) - यह नहर रोपड़ नामक स्थान से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 175 किलोमीटर है। यह पंजाब राज्य में बहती हुई हरियाणा के हिसार जिले में दोहाना कस्बे तक जाती है। मुख्य नहर व शाखाओं की कुल लंबाई 1100 किलोमीटर है और उपशाखाओं की लंबाई लगभग 3400 किलोमीटर है। 565 किलोमीटर नहर पल्लस्तार युक्त है।

(ii) सरहिंद नहर (Sarhind Canal) - भाखला नागल परियोजना में सरहिंद नहर में लगभग 10 गुना पानी बढ़ गया है। इसमें पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में सिचाई की जाती है। अतः इस क्षेत्र में कृषि का तेजी से विकास हुआ है।

(iii) नरवाना शाखा नहर (Narwana Branch) - यह नहर भाखड़ा की मुख्य नहर के 50वें किलोमीटर में निकाली गई है यह नहर पल्लस्तारयुक्त है और इसकी लंबाई 104 किलोमीटर है। इसका प्रमुख उद्देश्य मिरसा नहर को जल प्रदान करना है लेकिन इससे हरियाणा राज्य के करनाल जिले में कुछ सिचाई भी की जाती है।

(iv) बिस्त-दो-आब नहर (Bist-do-Aab Canal) - यह नहर रोपड़ के दक्षिणी ओर से निकाली गई है। इसमें पंजाब राज्य के जालन्धर व होशियार पुर जिलों में सिचाई की जाती है।

(स) परियोजना से जल-विद्युत का उत्पादन (Generation of Hydro-Electricity) -

(i) भाखड़ा बांध के जल विद्युत केन्द्र (Hydro Electricity Power Station of Bhakra Dam) - भाखड़ा बांध के दोनों ओर दो विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। बाई ओर के विद्युतगृह में 4.5 लाख किलोवाट क्षमता की 5 इकाइयाँ हैं। दाई ओर के विद्युत गृह में 1.20 लाख किलोवाट क्षमता की 5 इकाइयाँ हैं।

(ii) नागल बांध के जल-विद्युत केन्द्र (Hydro-Electricity Stations of Nangal Dam) - नागल बांध में विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से एक नहर निकाली गई है। इस नहर की लंबाई 64 किलोमीटर है। इस पर विद्युत जनन केन्द्र स्थापित किया गया है। गगुवाल नागल बांध में

15 किलोमीटर दूर एक विद्युत जनन केन्द्र स्थापित किया गया है जिसका जनन क्षमता 77 000 किलोवाट है। कोटला बांध से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित विद्युत केन्द्र की क्षमता भी 77 000 किलोवाट है। भाखड़ा व भागल बांधों पर बनाये गये विद्युत जनन केन्द्रों की कुल क्षमता 12.04 लाख किलोवाट है।

(द) परियोजना के रोचक तथ्य (Interesting Facts of Project) भाखड़ा नागल परियोजना के कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं

(i) बांधों का नाव कहीं कहीं पर 67 मीटर तक गहरे हैं।

(ii) भाखड़ा बांध को ऊँचाई कुतुबमीनार से लगभग तीन गुना है।

(iii) भाखड़ा बांध के क्षेत्रफल में एक लाख कमठों वाले 60-मंजिला इमारत का निर्माण किया जा सकता है।

(iv) यदि भाखड़ा बांध में लगाई गई ईंटों को एक सीध में रख दिया जाये तो पृथ्वी का लगभग सात परिक्रमाएँ हो जायेगी।

(v) भाखड़ा की नहरों आदि के लिये छोटी गई मिट्टी में 18 मीटर चौड़ी व 1 मीटर ऊँची सड़क नई दिल्ली से न्यूयार्क तक बनाई जा सकती है।

(vi) भाखड़ा बांध में जितनी कंकरीय का प्रयोग किया गया है उससे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चारों तरफ आठ फुट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा सकता है।

(घ) परियोजना के लाभ (Advantage) भाखड़ा नागल परियोजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं

(i) कृषि विकास (Agricultural Development) सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि व जल विद्युत पूर्ति में वृद्धि के कारण विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन में वृद्धि हुई। खद्यान कृषि व तिलहन का उत्पादन में क्रमशः 1.14 लाख टन व 3.8 लाख टन तथा 4.1 लाख टन का वृद्धि हुई है।

(ii) सिंचाई (Irrigation) इस परियोजना से हरियाणा पञ्जाब राज्य के सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रहा है। परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता लगभग 28 लाख हेक्टेयर है।

(iii) सिंचाई लागत कम होना (Low Cost of Irrigation) - इस परियोजना की सिंचाई लागत अन्य परियोजनाओं की तुलना में बहुत कम है। इस परियोजना की प्रति एकड़ सिंचाई लागत केवल 287 रुपये है जबकि नागार्जुन व तुंगभद्रा परियोजनाओं की प्रति एकड़ सिंचाई लागत क्रमशः 798 रुपए व 717 रुपए है।

(iv) जल विद्युत (Hydro Electricity) भाखड़ा नागल परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 12.04 लाख किलोवाट है। इसका प्रयोग मुख्यतः उद्योगों में किया जाता है। विद्युत उपयोग अग्रलिखित प्रकार किया जाता है

भाखड़ा नागल परियोजना की विद्युत का उपयोग	
उपयोगकर्ता	विद्युत उपयोग (किलोवाट)
पावला-नागल डवल कारखाना	1 75 000
दिल्ली	80 000
रूपनगर	10 000
राजस्थान	68 680
हिमाचल प्रदेश	14 330
पञ्जाब	2 03 350
हरियाणा	1 47 380
बड़ानगर	13 070

(v) अकालों पर नियंत्रण (Control of Famines) भाखड़ा नागल परियोजना से जल का पर्याप्त पूर्ति के कारण इस क्षेत्र में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। इस क्षेत्र पर मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार अकालों पर नियंत्रण संभव हो गया है।

(vi) चरगाह (Pastures) इस परियोजना के कारण पञ्जाब हरियाणा आदि राज्यों के पशुओं को प्रतिदिन पर्याप्त घास में हरा चारा प्राप्त हो जाता है। इसी के कारण पञ्जाब में रवेत ब्रायि सफल हुई है।

(vii) औद्योगिक विकास (Industrial Development) कृषि विकास एवं जल विद्युत की पर्याप्त पूर्ति के कारण औद्योगिक विकास का बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पूर्ति के कारण लघु एवं मध्यम उद्योगों का तेजा से विकास हुआ है।

(viii) रोजगार में वृद्धि (Employment) इस परियोजना में अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी रोजगार का अवसर बढ़ है।

(ix) पण्डियों का विकास (Development of Mandies) इस योजना के कारण कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्रों में वृद्धि से व्यापारिक मण्डियों का भी तेजी से विस्तार

भाखड़ा नहर द्वारा राजस्थान का सिंचित सकल क्षेत्र (एक लाख में)				
वर्ष	1980-81	1985-85	1990-91	1993-94
राजस्थान	331.47	3.064	422.63	85.29
हजारा				328.69
कुल क्षेत्र	331.47	360.64	422.63	413.99

एन नेजी से निकल रहा।

(x) जीवन स्तर में वृद्धि (Rise in Standard of living)-परियोजना क्षेत्र के निवासियों की आय में वृद्धि हुई है। अतः लोगों के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ है।

3 माही बजाज सागर परियोजना

Mahi Baja Sagar Dam

माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्यों के सन्ध्याग रे निर्मित की गई है। यह एक सिंचन व जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का लाभ मुख्यतः राजस्थान के बासवाड़ा जिले को होगा। सर्वप्रथम 1958 में योजना आयोग ने इस परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना का शिलान्यास 1960 में एक मध्यम सिंचाई परियोजना के रूप में हुआ था लेकिन 1971 में योजना आयोग ने इसके वर्तमान स्वरूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके पश्चात् परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। परियोजना द्वारा सिंचाई का शुभारंभ नवम्बर 1983 में किया गया। सशोधित स्वरूप व अनुसार इस परियोजना से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

माही नदी मध्यप्रदेश राज्य के धार जिले में विन्ध्यारण्य पर्वत से निकलती है। 169 किलोमीटर चलने के पश्चात् यह नदी बासवाड़ा व निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह नदी लगभग 171 किलोमीटर बहती है। चनास सोम इराक इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी राजस्थान से होकर गुजरात में प्रवेश करती है। अतः यह खम्भत की खाड़ी में जाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। राज्य का बासवाड़ा जिला पथरीली मिट्टी भूमि वाला है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 80 सेंटीमीटर है। जिले की मिट्टी उपजाऊ है लेकिन पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में मुख्यतः खरीफ की फसल की जाती है। इस सिंचाई परियोजना का निर्माण के पश्चात् भू जल की सतह ऊँची होने एवं सिंचाई के साधनों में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है अतः बासवाड़ा क्षेत्र में कृषि एवं उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल होने की सम्भावना है। माही बजाज सागर परियोजना को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(i) प्रथम इकाई (First Unit) योजना की प्रथम इकाई के अंतर्गत बासवाड़ा क्षेत्र से लगभग 11 किलोमीटर दूर चोरछाड़ा नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की लंबाई 3109 मीटर है। बांध की जलग्रहण क्षमता 1840 लाख मी० मीटर है। इस बांध से लगभग 11 किलोमीटर दूर पर एक मिट्टी के बांध का निर्माण भी किया गया है।

(ii) द्वितीय इकाई (नहरे जल परिवहन और नालियों का कार्य आदि) (Second Unit)-सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से बांध से नहरे निकाली गई हैं। बासवाड़ा के पास कागदी पिकअप वियर से दो नहरे निकाली गई हैं-प्रथम-दोई मुख्य नहर जिसकी लंबाई 71.72 किलोमीटर है द्वितीय बाँई मुख्य नहर जिसकी लंबाई 36.12 किलोमीटर है। इन दोनों नहरों की वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है। इन नहरों से बासवाड़ा जिले की लगभग 90800 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने लगी है।

(iii) तृतीय इकाई (Third Unit)-माही परियोजना की तृतीय इकाई के अंतर्गत 2 विद्युत इकाइयों का निर्माण किया गया है। इन विद्युतगृहों की विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। इन विद्युतगृहों से विद्युत आरंभ हो चुका है। योजना आयोग ने माही बजाज सागर की स्वीकृति 12-11-1971 को दी थी। इसकी अनुमानित लागत 30.46 लाख रूपए निर्धारित की गयी जो प्रथम इकाई के कार्यों के लिए 2293 लाख रूपए द्वितीय इकाई के कार्यों के लिए 743 लाख रूपए तथा तृतीय इकाई के कार्यों के लिए 100 लाख रूपए में विभाक्त है। कच्चे माल व श्रम आदि की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण योजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हो गई। 1976 में योजना की नवीन लागत इस प्रकार निर्धारित की गई प्रथम इकाई 6735 लाख रूपए द्वितीय इकाई 3581 लाख रूपए व तृतीय इकाई-3823 लाख रूपए तथा कुल योग-14137 लाख रूपए।

श्रम व कच्चा माल आदि के मूल्यों में पुनः वृद्धि हो जाने के कारण योजना की लागत में वृद्धि हो गई। छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय परियोजना की प्रथम इकाई की लागत 80.02 करोड़ रूपए निर्धारित की गई। अग्र तालिका में योजना की अनुमानित लागत एवं व्ययों को दर्शाया गया है।

आठवीं योजना में माही बजाज सागर परियोजना पर 120 करोड़ रूपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। यह सम्पन्न धार्मिक निर्माणधीन कार्यों पर व्यय की जानी थी। आठवीं योजना में 20 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता का निर्माण प्रस्तावित था। 1997-98 के अंत में 98.8 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होने लगी हैं। नवी योजना में इस परियोजना पर 40 करोड़ रूपए व्यय करने का प्रावधान है। मार्च 1997 तक परियोजना के विभिन्न तार्यों पर 530.92 करोड़ रूपए व्यय किया जा चुका है।

माही खज्जाज सागर परियोजना								
अनुमानित लागत एवं सातवीं योजना तक व्यय (लाख रुपये में)								
	अनुमानित लागत			योग	सातवीं योजना तक व्यय			
	सिंचाई		विद्युत		सिंचाई		विद्युत	योग
	राजस्थान	गुजरात			राजस्थान	गुजरात		
प्रथम इकाई	4512	5812	244	10568	4354	5620	244	10218
द्वितीय इकाई	30350	-	3150	33500	12212	-	772	12984
तृतीय इकाई	-	-	7752	7752	(-)	-	6626	6603
चतुर्थ इकाई	200	-	-	200	292	-	-	292
पंचम इकाई	-	-	-	-	500	-	-	500
योग	35062	5812	11146	52020	17335	5620	7642	30597

संलग्न Eighth Five Year Plan, 1981-87, Govt. of Rajasthan

स्रोत Eighth Five Year Plan, 1981-87, Govt. of Rajasthan.

4 व्यास परियोजना

Beas Project

यह पंजाब राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सतलज, रावी एवं व्यास नदियों के जल का उपयोग करना है।

इस परियोजना को दो चरणों में पूर्ण किया गया है।

(i) प्रथम चरण (First Stage) - योजना के प्रथम चरण में व्यास-सतलज लिंक नहर का निर्माण किया गया है।

(ii) द्वितीय चरण (Second Stage) योजना के द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध का निर्माण हो चुका है। इस बांध की नहरों से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की भूमि पर सिंचाई की जाती है तथा जल विद्युत का उत्पादन भी किया जायेगा। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर को शीतकाल में जल की आपूर्ति नियमित बनाये रखना है। व्यास व सतलज पर दो बांधों के निर्माण की योजना भी है।

रावी-व्यास जल विवाद (Conflict over Ravi-Beas Water)

रावी-व्यास जल विवाद लंबे समय से चल रहा है। मूलप्रश्न इस विवाद को समाप्त करने के लिये 1955 में एक समझौता किया गया। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा राजस्थान, जम्मू व कश्मीर तथा दिल्ली के लिए जल का आवंटन किया गया। 1981 में पुनः एक समझौता हुआ बिना अनुसार विभिन्न राज्यों के हिस्से का मुन निर्धारण किया गया। जुलाई 1985 में यह विवाद पुनः उभरा। भारत सरकार ने 23 जनवरी 1986 का इस विवाद के मध्यम समझौता हेतु न्यायधिकरण का गठन किया। यह अद्योत न्यायमूर्ति इगडा का अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 1987 में प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब का हिस्सा 50 लाख एकड़ फुट जल निश्चित किया गया जबकि इस राज्य का पूर्व अंश 42.2 लाख एकड़ फुट था। हरियाणा राज्य के लिये 38 लाख 30 हजार एकड़ फुट जल का निर्धारण किया गया जबकि इसका पूर्व अंश 35 लाख एकड़ फुट था। राजस्थान के लिए 68 लाख एकड़ फुट जल का निर्धारण किया गया, पूर्व अंश भी 85 लाख एकड़ फुट था। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पंजाब व हरियाणा के हिस्से में वृद्धि हो रही है जबकि राजस्थान के जल हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें राज्य में असंतोष बढ़ा है। वास्तव में राज्य में सूख व अकाल की स्थिति को देखते हुये राजस्थान के जल हिस्से में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक था।

5. जाखम परियोजना

Jakham Project

प्रायःपण्ड तहसील में छोटी सादडी के निकट जाखम नदी का उद्गम-स्थल है। इस नदी के जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिये जाखम परियोजना बनाई गई। राज्य सरकार ने 1962 में जाखम परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना में चितौडागढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न केवल कृषि का विकास होगा बल्कि योजना में जल-विद्युत की शक्ति होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी तत्पश्चात् से हो सकेगा।

जाखम परियोजना के अंतर्गत चितौडागढ़ जिले के प्रायःपण्ड तहसील व अनुपपुत्र गांव के निकट एक मुख्य बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का लम्बाई 253 मीटर व चौड़ाई 81 मीटर है। फ्लिक-अप दिवा (छोटा बांध) का निर्माण

मुख्य बाध पानी का मिठाई जाने जाता जाने के लिए किया गया है। मुख्य बाध व पवन-अप विचार के मध्य लगभग 13 किलोमीटर की दूरी है। 1969-70 में मुख्य बाध एवं नहरों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। गेटे बाध की रूपरेखा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई है। इस बाध से दो नहरें निकली गई हैं। लगी व बायीं नहर की नर्मा क्रमशः 24 व 40 किलोमीटर है। परियोजना सुविधा में वृद्धि करने के उद्देश्य से सबवा का निर्माण किया गया है। उत्तरपूर्व से भूमिगत जल और प्रतापगढ़ से मुख्य बाध पर पानी गड़रो का निर्माण किया गया है। यह परियोजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इस योजना से मिठाई सुनिश्चित में वर्षापूर्व वृद्धि हुई है। मुख्य बाध पर 4 मीटर गेटे शक्ति का एक विद्युत् गृह बनाने का भी प्रस्ताव है। इस परियोजना पर 43 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

6 बीसलपुर परियोजना

Bisalpur Project

बीसलपुर परियोजना सिंहाई एन पीने योग्य जल की पूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई गई। राजस्थान सरकार ने 1302 में इस योजना का प्रोजेक्ट केन्द्रीय जल आयोग की भेजा। इस परियोजना से 60 हजार हेक्टेयर में सिंहाई तथा अजमेर किशनगढ़ व ब्यावर आदि नगरों में पीने योग्य पानी की उपलब्धि हो सकेगी। योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत बनाम नदी पर बीसलपुर नामक स्थान पर एक बाध का निर्माण किया जा रहा है। बनाम नदी पर बीसलपुर नामक स्थान पर एक बाध का निर्माण किया जा रहा है। इस चरण के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा एक पेयजल योजना का निर्माण भी किया गया। योजना की अनुमानित लागत 327.03 करोड़ रुपये है। योजना की प्रथम इकाई पर 202.03 करोड़ रुपये एवं द्वितीय इकाई पर 125 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। बीसलपुर योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पेयजल योजना को भी पूर्ण करने का प्रस्ताव है। इस पेयजल योजना के अंतर्गत अजमेर ब्यावर किशनगढ़ आदि शहरों को पेयजल की पूर्ति की जायेगी। पेयजल योजना का निर्माण कार्य शुरु किया जा चुका है। नसीराबाद से ब्यावर व किशनगढ़ तक पाइपलाइन बिछाने का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना पर बाध का निर्माण का कार्य भी चल रहा है। योजना का प्रथम चरण (इकाई प्रथम बाध का निर्माण एवं उससे संबंधित कार्य) आठवीं योजनाकाल में पूर्ण हो जायेगा। योजना का द्वितीय चरण (इकाई द्वितीय नहरों व्यवस्था का निर्माण) 1999-2000 तक पूर्ण होने की संभावना है। द्वितीय इकाई की अनुमानित लागत 125 करोड़ रुपये है जिसमें से 97.78 करोड़ रुपये

आठवीं योजना के अंतर्गत व्यय किये जाने का प्रावधान है। शेष 27.22 करोड़ रुपये नवीं योजना में व्यय किये जायेंगे। इस परियोजना से 69300 हेक्टेयर भू-क्षेत्र में सिंहाई सुविधाएँ होने का अनुमान है। आठवीं योजना के अंतर्गत लगभग 20000 हेक्टेयर में सिंहाई सुविधाएँ उपलब्ध हो जायेंगी। बीसलपुर योजना दो दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रथम इससे राज्य के एक विशाल भू-भाग में सिंहाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँगी जिससे परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योगों का तेजी से विकास हो सकेगा। द्वितीय योजना के अंतर्गत राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नगरों में पेयजल की पूर्ति की जायेगी। ये सभी नगर औद्योगिक दृष्टि से जननी पूर्ति में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप इन नगरों का तेजी से औद्योगीकरण होने की संभावना है। योजना के कारण राज्य के अनेक लोग व रोजगार मिल रहा है और संपूर्ण योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात् राज्य में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित होने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

7 नर्मदा परियोजना

Narmada Project

इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी के 5 लाख एकड़ फुट जल का उपयोग करने के लिये किया गया। इस जल का आवंटन नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया। इस परियोजना से 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंहाई सुविधाएँ उपलब्ध हो सकीं और इसका कमाण्ड सरिया सांचौर व गुडामलानी होगा। जननी शक्ति हेतु सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात राज्य में निर्मित) से 460 किलोमीटर नर्मदा मुख्य नहर के द्वारा की जायेगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र व राजस्थान का संयुक्त प्रयास है। राजस्थान इस परियोजना की प्रथम इकाई पर कुल लागत का 3.1 प्रतिशत तथा द्वितीय इकाई की कुल लागत का 1.1 प्रतिशत वहन करेगा। नर्मदा परियोजना के लिए 64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना से जालौर जिले के 76 एवं बाड़मेर जिले के 7 गांवों को सिंहाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

8 सिद्धमुख परियोजना

Siddhukh Project

इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य का व्यापक नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग हो सकेगा। यह जन राजस्थान के हिस्से में पञ्जाब हरियाणा व राजस्थान के राज 1981 में एक समझौते के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह जल बाण्डा नागल हैडवार्क में बाण्डा मुख्य नहर पञ्जाब राज्य में होने लगे पन्थवादा शाखा व किशनगढ़ उपशाखा हरियाणा के समान्तर नहर द्वारा रक्षित जायेंगे। इस परियोजना से

गगानगर जिले की भादरा व नोहर तहसीलों तथा चुरू जिले की तारनगर व राजगढ तहसीलों को जल की प्राप्ति हो सकेगी। इस जल का उपयोग मुख्यतः सिंचाई के लिए किया जायेगा। मिट्टीमुख परियोजना की अनुमानित लागत 103 करोड़ रूपए है। इस परियोजना से गगानगर व चुरू जिलों में कृषि का विकास होगा।

9. नोहर परियोजना

NOHAR PROJECT

यह परियोजना भी मिट्टीमुख परियोजना का एक अंग है। परियोजना के अंतर्गत श्रीगगानगर जिले में नोहर तहसील की जल की प्राप्ति होगी। यह जल भी रावी एवं व्यास नदियों से प्राप्त अतिरिक्त जल होगा। इस परियोजना की कुल लागत 40.60 लाख रूपए होने का अनुमान है।

10. इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना

INDIRA LIFT IRRIGATION PROJECT

यह राजस्थान के मवाई माधोपुर जिले की प्रस्तावित सिंचाई योजना है। इस योजना के अंतर्गत चबल नदी के जल को कसेड ग्राम के निकट 124 मीटर ऊंचा ठाकर हिण्डौन, करौली, गगानगर, टोडाभीम, नादौती, बामनवास, बयाना आदि स्थानों पर पहुंचाया जाना है। इस लिफ्ट योजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध करना है। इस लिफ्ट योजना का प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। इस क्षेत्र में अनेक पहाड़िया हैं। अतः जल को कृषि योग्य भूमि तक पहुंचाने के लिये लगभग 10 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना आवश्यक है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग पचास करोड़ रूपए है। जलोत्थान के लिये पर्याप्त विद्युत की भी आवश्यकता होगी। परियोजना से राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।

11. पीपल ला लिफ्ट सिंचाई परियोजना

PIPLA LA LIFT IRRIGATION PROJECT

यह सर्वाईमाधोपुर जिले की प्रस्तावित सिंचाई योजना है। इस योजना के अंतर्गत चबल नदी से गण्डावर गांव के निकट जल को 58 मीटर ऊंचा उठाया जायेगा। इस योजना से खण्डार तहसील (सर्वाईमाधोपुर जिला) के लगभग 34 गांवों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। खण्डार तहसील में लगभग 13,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इस सिंचाई योजना की अनुमानित लागत 5.29 करोड़ रूपए है।

12. सोम-कमला-अम्बा सिंचाई योजना

SOM KAMLA- AMBA IRRIGATION PROJECT

इस परियोजना का निर्माण राज्य के झुपरपुर जिले

में किया गया है। इससे झुपरपुर जिले की लगभग 18 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

13. पांचना परियोजना

PANCHNA PROJECT

यह सर्वाईमाधोपुर जिले की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। पांचना सिंचाई क्षेत्र गुडला गांव के निकट है। इस स्थान पर णच नदियों का संगम है। भदरावती, अटा, बरखेडा, भेसावट और भाचो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं।

14. बिलास सिंचाई योजना

BILLAS IRRIGATION PROJECT

यह कोटा जिले की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अंतर्गत मानगढ गांव के पास बिलास नदी पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। बिलास नदी पार्वती नदी की सहायक नदी है। इस बांध से एक नहर भी निकाली गई है। यह बांध मिट्टी से बनाया गया है। मुख्य नहर की लंबाई 20 किलोमीटर है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 25 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

15. छापी सिंचाई परियोजना

CHAPPI IRRIGATION PROJECT

यह झालावाड जिले की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। अकरला के पास एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध की प्रस्तावित लंबाई 344 फुट और ऊंचाई 120 फुट है। इस परियोजना से झालावाड जिले की लगभग 7000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

16. जवाई बांध परियोजना

JAWAI DAM PROJECT

1956 में पाली जिले में एरिनपुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जवाई बांध का निर्माण किया गया। इस बांध की लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 923 मीटर व 34 मीटर हैं। इस बांध से 24 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। वित्तिकार्ष 224 किलोमीटर लंबी हैं। इस बांध की जल की आवक बढ़ाने के लिए 1971 में सेई बांध बनाया गया। सेई बांध का पानी जवाई बांध में लाने हेतु, पहाड़ से 7 कि.मी. लम्बी सुरंग तैयार की गई है। इससे पाली व जलौर में क्रमशः 26,550 हेक्टेयर व 14,860 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इसकी नहरों का विस्तार और उन्हें पक्का करने का कार्य किया जा रहा है।

17. पार्वती परियोजना

Parwati Project

1959 में धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर 122 लाख रुपए की लागत से एक बांध बना निर्माण किया गया। इस बांध की लंबाई 7 किलोमीटर है तथा इसकी मुख्य नहर की कुल लंबाई 56 किलोमीटर है। इससे लगभग 12 100 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है।

18. ओरई परियोजना

Oral Project

चित्तौड़गढ़ जिले में ओरई नदी पर एक बांध बनाया जायेगा जिससे भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों की सिंचाई होगी।

19 अन्य परियोजनाएँ

Other Project

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य में अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। इनमें बाकली बांध (नागौर व पाली) मोरैल बांध (सवाई माधोपुर) गुढा बांध (बूंदी) खारी बांध (आसिन्द के पास) मेजा बांध (भीलवाड़ा) पश्चिमी बगस योजना (सिरोही) अडवान बांध (शाहपुरा) गम्भीरी योजना (चित्तौड़गढ़) इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना (सवाईमाधोपुर) विलाम सिंचाई योजना (कोटा) सोम कगदर सिंचाई योजना (उदयपुर) पीपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना (सवाई माधोपुर) बोलतपुर परियोजना (टोंक) सोम-कमला-अम्बा सिंचाई परियोजना (झगरपुर) व पाचना परियोजना (सवाई माधोपुर) आदि प्रमुख हैं।

प्रमुख नहरों से सकल सिंचित क्षेत्र								
नहरें	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1993-94
1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना	328 46	406 63	459 97	332 30	530 15	490 67	531 72	539 50
2 गंग नहर	275 97	299 92	336 06	262 88	319 96	322 44	328 99	320 14
3 चखल नहर	331 42	360 64	357 43	326 67	397 67	389 51	422 63	413 98
4 चम्बल की नहर	216 19	247 61	273 15	278 44	267 67	295 60	245 06	284 20
5 अन्य नहरें	107 72	197 04	207 98	176 74	217 64	172 53	239 74	277 43
योग	1257 81	1511 06	1634 61	1377 04	1733 01	1670 97	1768 18	1835 32

Source: Trends in Land Use Statistics & VAS 1984-95, Rajasthan.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि

1 राजस्थान की नहरों से सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1987-88 में सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक कमी हो गई लेकिन इसके पश्चात् वृद्धि का क्रम पुनः आरंभ हो गया।

2 गंग नहर से सिंचित क्षेत्र में 1987-88 तक उतार चढ़ाव होता रहा लेकिन इसके पश्चात् सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई।

3 चम्बल की नहरा में भी राज्य के पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई होती है। सिंचाई क्षेत्र में कमी वृद्धि होती रही है। सिंचाई की दृष्टि से इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्थान है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की प्रमुख नहरों के अतिरिक्त अन्य नहरों से भी सिंचाई की जाती है। अन्य नहरें राज्य के शायद सभी जिलों में विद्यमान हैं। अन्य नहरों से 1980-81 में सिंचित क्षेत्रफल 107 72 हजार

हेक्टेयर था जो 1990-91 में 239 74 हजार हेक्टेयर हो गया।

योजनाकाल में सिंचाई का विकास

DEVELOPMENT OF IRRIGATION IN PLAN PERIOD

प्रथम योजना (First Plan) इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 31 31 करोड़ रुपए व्यय किये गये। बाखड़ा नाथल चबल नदी घाटी परियोजना तथा अनेक छोटी योजनाओं का निर्माण प्रारंभ किया गया। 1950-51 में सिंचित क्षेत्र 11 74 लाख हेक्टेयर था जो बढ़कर 1955-56 में 13 6 लाख हेक्टेयर हो गया।

द्वितीय योजना (Second plan) इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 27 88 करोड़ रुपए व्यय किये गये। योजनाकाल में इंदिरागांधी नहर का निर्माण प्रारंभ किया गया तथा अपूर्वी योजनाओं को पूर्ण किया गया। योजना के अंत में कुल सिंचित क्षेत्र 17 6 लाख हेक्टेयर हो गया।

तृतीय योजना (Third plan) - इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 87.88 करोड़ रुपए व्यय किये गये। अधूरी योजनाओं को पूर्ण किया गया। योजना के अंत में कुल सिंचित क्षेत्र 22.6 लाख हेक्टेयर हो गया।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69) (Three One-Year Plans) - इस अवधि में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 46.59 करोड़ रुपए व्यय किये गये। इन योजनाओं के अंत में सिंचित क्षेत्र 23.5 लाख हेक्टेयर हो गया।

चतुर्थ योजना (Fourth plan) - इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण का 105.26 करोड़ रुपए व्यय किये गये। योजना के अंत में सिंचित क्षेत्र 26.24 लाख हेक्टेयर हो गया।

पाचवी योजना (Fifth plan) - योजनाकाल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 271.17 करोड़ रुपए व्यय किये गये। योजना के अंत में सिंचित क्षेत्र 30 लाख हेक्टेयर हो गया।

छठी योजना (Sixth plan) - छठी योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 547.08 करोड़ रुपए व्यय किये गये।

सातवी योजना (Seventh Plan) - इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 690.51 करोड़ रुपए व्यय किये गये। योजना के अंत में सिंचित क्षेत्र 44.61 लाख हेक्टेयर हो गया।

आठवी पंचवर्षीय योजना (Eighth Plan - 1992-97) - आठवी पंचवर्षीय योजना में 1,70,623 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का निश्चय किया गया। याम्यव्र में आठवी योजना के अंतर्गत 3.07 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई।

नवी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई विकास (1997-2002) - क्षति विकास के लिये सिंचाई का नियोजित ढंग से विकसन करना निश्चित आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति का ध्यान में रखते हुए सिंचाई के क्षेत्र में निम्न व्यूह रचना अपनाई गई।

- (i) सिंचाई की विद्यमान क्षमता में पर्याप्त मरम्मत के द्वारा वृद्धि करना।
- (ii) सिंचाई क्षमता का विस्तार करना।
- (iii) सिंचाई की चालू परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- (iv) छोटी मध्यम एवं बड़े आकार की चयनित सिंचाई परियोजना का कार्य आरम्भ करना।

(v) विदेशी सहयोग में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।

(vi) इस योजना में 1336.02 करोड़ रुपये कम करके 470.62 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति PRESENT POSITION OF IRRIGATION IN RAJASTHAN

(i) सिंचाई क्षमता (Irrigation Potential) - राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विकास - विस्तार का एक सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिये अनेक बहु-उद्देशीय, वृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं और कई परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। मार्च, 1992 तक 99 वृहद् और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएँ तथा 4307 लघु सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका था। इन वृहद् एवं मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं से अर्जित 20.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का 96.8 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका था। उपयोग का यह प्रतिशत देश में अधिकतम था। इसी प्रकार लघु सिंचाई परियोजनाओं में 3.34 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी थी। किन्तु 50% क्षमता का ही उपयोग किया जा सकता है। सृजित एवं उपयोग हुई क्षमता में अन्तर का मुख्य कारण सीमित वर्षा के कारण राज्य के बांधों में पानी की भारी क्षमता में अपेक्षाकृत कम जलसंग्रह होना रहा।

राज्य में पूरी हुई सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता अर्जित की चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व यही मात्र 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी।

(ii) चालू परियोजनाएँ (Ongoing Project) - प्रदेश के मिश्रित रकबे में और बढ़ोतरी हो सके, इनके लिये तेजी से प्रयास जारी है। वर्तमान में कई बहु-उद्देशीय, वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। इनके अतिरिक्त, विभिन्न सिंचाई परियोजनाएँ डिशाइट यांत्रिकी और पंचायतों द्वारा हथ में लिये गये विकास कार्यों के तहत क्रियान्वित की जा रही है।

वर्तमान में बहु-उद्देशीय परियोजनाओं के तहत माझ बजाज सागर, राजाधन सागर, जवाहर सागर और चंदल परियोजना के शेष कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

इनमें माही बजाज सागर का कार्य नवी पंचवर्षीय योजना तक पूरा होने का अनुमान है जब कि शेष परियोजनाओं का आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा होने के प्रयास हैं। इसी प्रकार वृहद् परियोजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के तहत 6 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। इनमें जाखम, गुडगाव, बीमलपुर, नर्मदा, नोहर व सिद्धमुख नहरें मुख्य हैं। जाखम व गुडगाव परियोजनाएँ आठवें पंचवर्षीय योजनाकाल में पूरा होगी जबकि नर्मदा, सिद्धमुख व नोहर परियोजनाओं के नवी पंचवर्षीय योजना में पूरा होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त, मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना के तहत जिन परियोजनाओं का काम प्रगति पर है उनमें भीमसागर, सोम कागदर, विलास, सोम-अम्बा-कमला, पाचना, सावन भादों, छापी, हरेशचन्द्र सागर और परवान लिफ्ट योजना मुख्य हैं। इन सभी परियोजनाओं को आठवें योजनाकाल में पूरा होने का प्रयास जारी है। राज्य में चल रही 88 लघु सिंचाई परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं को आठवीं योजना में पूरा करने के कार्यक्रम हैं।

(iii) सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम (Community Lifts Irrigation Programme) - राजस्थान में सीमित जलस्रोत हैं। राज्य के लघु व सीमान्त कृषक इन जलस्रोतों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में नदियों, नालों एवं नदी क्षेत्र आदि के रूप में पर्याप्त जलस्रोत विद्यमान हैं। सीमान्त व लघु कृषकों की सहायता के लिए इन जलस्रोतों का समुचित उपयोग करने के लिए राजस्थान सरकार ने 1980-81 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम आरंभ किया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु व सीमान्त कृषकों को सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना है ताकि वे गरीबी रेखा को पार कर सकें। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि सीमान्त व लघु कृषक किसी समिति अथवा समूह के अंतर्गत इस योजना को संचालित करेंगे। योजना की लागत का 10 प्रतिशत भाग कृषक द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा शेष राशि के लिये सरकार अनुदान प्रदान करेगी। इस कार्य के लिये वित्तीय सहायताओं से ऋण की व्यवस्था भी की गई है। यह योजना ग्रामीण जिला विकास सस्थाओं के तकनीकी विभाग द्वारा बनाई जाती है तथा इसका संचालन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यह योजना कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, झुपपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मिर्गोही, धौलपुर, टोंक आदि जिलों में आसानी से चालू की जा सकती है।

(iv) राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड - यह निगम 1984 में स्थापित किया गया। इसका प्रमुख कार्य भू-जल एवं सतही जल के विभिन्न कार्यों में उपयोगों को निर्धारित करना है। यह जल को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने के लिये ऊर्जा स्रोतों की भी व्यवस्था करता है। इस निगम को प्रभावी बनाने हेतु इसकी स्थिति एवं प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये।

राजस्थान में सिंचाई संबंधी समस्याएँ व सुझाव

PROBLEMS & SUGGESTIONS REGARDING IRRIGATION IN RAJASTHAN

(1) अपर्याप्त जल संसाधन (Inadequate Water Resources) - राज्य में वर्षा बहुत कम होती है अतः जल संसाधन अपर्याप्त हैं। इसलिये जल संसाधनों का कुशलता व मितव्ययिता से प्रयोग करना चाहिये।

(2) कुओं में पर्याप्त जल (Inadequate Water in Wells) - राज्य में कुओं में कम पानी की समस्या है। पानी बहुत अधिक गहराई पर मिलता है। अतः कुओं वाले क्षेत्रों में बांधों का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि जल स्तर ऊंचा हो सके।

(3) मरम्मत सुविधा का अभाव (Lack of Repair Facilities) - राज्य में तालाबों, नहरों व बांधों की मरम्मत की पर्याप्त सुविधा नहीं है अतः जल का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसके लिए तालाबों, नहरों व बांधों के निरीक्षण व सुधार संबंधी व्यवस्था की जानी चाहिये।

(4) वित्तीय साधनों का अभाव (Lack of Financial Resources) - राज्य में वित्तीय साधनों के अभाव के कारण सिंचाई योजनाओं के पूर्ण होने से बहुत अधिक समय लग जाता है अतः केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

(5) सामग्री का अभाव (Lack of Material) - राज्य में नदी-घाटी परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अभाव रहता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की धीमी प्रगति का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अतः ऐसी सामग्री का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये।

(6) भ्रष्टाचार (Corruption) - सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु स्थान के चयन, उसके निर्माण एवं जल के वितरण आदि के पक्षपात, भ्रष्टाचार व तालफतीशाही का

बोलबाला है। जन-जागरण ही इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है।

(7) जल ससाधनों का दुरुपयोग (Misuse of Water Resources) - किसानों द्वारा जल ससाधनों का दुरुपयोग किया जाता है। इसके जलमयिक व लवणीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः आवश्यकतानुसार ही जल का वितरण व प्रयोग किया जाना चाहिये।

(8) कृषकों के विवाद (Conflicts in Farmers) - जल ससाधनों के वितरण को लेकर कृषकों में ग्राम विवाद बना रहता है। कभी-कभी इसका कारण अधिकारियों की फसपात पूर्ण नीति भी होती है। निश्चित समय पर पर्याप्त जल का वितरण न करने पर भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इसके लिये निश्चित नियमों का निर्माण किया जाना चाहिये।

(9) रोगों का प्रकोप (Diseases) - तालाबों व नहरों के क्षेत्र में मच्छरों के कारण मलेरिया जैसी बीमारी तेजी से बढ़ती है। इस समस्या के समाधान हेतु कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिये तथा जल ससाधनों का सदुपयोग करना चाहिये।

(10) विद्युत प्रयोग का अभाव (Lack of Power Utilization) - डीजल पम्प की तुलना में विद्युत पम्प मिश्रव्ययी होते हैं अतः उपभोक्ताओं को विद्युत पम्प से अधिक प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये तथा विद्युत की पूर्ति लगातार बनाये रखनी चाहिये।

(11) अनुसंधान की दीर्घकालीन प्रक्रिया (Longrun Process of Research) - सिंचाई परियोजनाओं के अनुसंधान में काफ़ी लंबा समय लगता है। अतः पहले से जांचा हुआ योजनाओं को तैयार रखना चाहिये ताकि साधनों के अनुसार उनमें से किसी का भी चयन किया जा सके।

(12) भौगोलिक विकास (Geographical Disparities) - सिंचाई की आवश्यकता व सधन क्षेत्र विशेष की मिट्टी, जलवायु, वर्षा, कृषि, फसलों के प्रकार आदि द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों में नहरों आदि का निर्माण करते समय इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये, न कि सभी क्षेत्रों के लिये समान मानव निर्धारित किये जाने चाहिये।

(13) जनसहयोग का अभाव (Lack of Public Co-operation) - सिंचाई साधनों के विकास के अर्थानि विशेष रूप से बांधों व नहरों के निर्माण में जनसहयोग का अभाव स्पष्ट दृष्टिोपर होता है। कहीं-कहीं तो जन विरोध

का भी सामना करना पड़ता है। सिंचाई परियोजना सबधी सभी वास्तविक तथ्यों को अवगत करते हुये जन सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिये।

(14) जन-धन की हानि (Loss of Property & Lives) - बांधों, नहरों या तालाब आदि के टूट जाने पर जन-धन की हानि अत्यधिक क्षति होती है। इन साधनों के निर्माण में पर्याप्त सावधानी बरतकर व उचित देख-रेख से इस समस्या का समाधान सम्भव है।

(15) अन्तर्राष्ट्रीय विवाद (Inter State Disputes) - विभिन्न जलक्षेत्रों को लेकर विभिन्न राज्यों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं जिससे सिंचाई साधनों के विकास में बाधा पड़ती है। राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुये इसका कोई हल निकाला जाना चाहिये।

(16) अधिक सिंचाई लागतें (High Irrigation Cost) - मुद्रा प्रसार के कारण निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की लागतें में तेजी से वृद्धि हुई है। सिंचाई साधनों के दुरुपयोग से ये लागतें और भी बढ़ गई हैं। बढ़ी हुई लागतों को पूर्ति सिंचाई शुल्क वृद्धि करके की जानी चाहिये।

राजस्थान में शक्ति

POWER IN RAJASTHAN

सभी आर्थिक कार्यकलापों में ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होती है। ऊर्जा का उत्पादन एक बहुत ही खर्चीला कार्य है और ऊर्जा की मांग के अनुसार उसकी आपूर्ति के लिये भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इस कारण राज्य की योजना बट में ऊर्जा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना प्रावधान का लगभग 28.31 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के लिये निर्धारित था।

प्रतिस्पर्धात्मक एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित खुले बाजार की अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिये राज्य कंतिमाईट भंडारों को खोल दिया गया है। लगभग 18,000 करोड़ रुपये की लागत से निजी क्षेत्र में 4280 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु करवाई श्रम की जा चुकी है। विद्युत की कमी, जो राज्य की विकास गतिविधियों को प्रभावित कर रही थी, वह निकट भविष्य में हल कर ली जायेगी।

दिसम्बर, 1997 तक क्रमशः विद्युतीकरण कार्यक्रम

ने अन्तर्गत राज्य में 34528 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1997 तक 5.44 लाख कुओं को भी विद्युतीकृत किया गया है।

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (REDA) - राजस्थान में नैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के उद्देश्य से जनवरी 1995 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (REDA) की स्थापना की गई। यह संस्था राज्य में सौर-ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायो गैस के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। नौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के मूल्यव्यवस्था क्षेत्र विशेषतः जैमलमेर जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (मोज) की स्थापना कर रही है।

राजस्थान विद्युत मंडल (RSEB) - यह मंडल विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की स्थापना खोज एवं उनका क्रियन्वयन तथा विद्युत सवहन एवं वितरण व कार्यों में मग्न है। कोटा ताप विजलीघर मारी जल विद्युत परियोजना, व्यास, चबल एवं मनुषा परियोजनाएँ राज्य में विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के राजस्थान अपुरावित मिमरेली ताप विद्युत परियोजना, रिहन्द अन्ता औरैया नरीरा एवं दादरी गैस, ऊचातर ताप विद्युत एवं टनकपुर परियोजना राज्य का विद्युत आपूर्ति में योगदान करत हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण राजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 व अत तक राज्य में 33827 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। इनके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 188 ग्रामों का और विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार दिसम्बर 96 तक कुल 34015 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसी तरह वर्ष 1996-97 में दिसम्बर 96 तक 25535 कुओं का विद्युतीकृत किया गया। अब तक कुल 26 लाख कुओं का विद्युतीकृत किया जा चुका है।

वर्ष 1995-96 में 13079.73 मिलियन विद्युत उपभोग की तुलना में वर्ष 1996-97 में 14213.43 मिलियन यूनिट होने की सम्भवा है। इस प्रकार प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1995-96 में 265 यूनिट की तुलना में वर्ष 1996-97 में 281 यूनिट हान का अनुमान है।

1950-51 में विद्युत की स्थापित क्षमता 13 मेगावट थी जो सातवीं योजना के अंत तक बढ़कर 2711.42 मेगावट हो गई। 1995-96 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3049 मेगावट थी।

आठवीं योजना में शक्ति पर वार्षिक व्यय 3081.4 करोड़ रुपए हुआ है और नवीं योजना में 5510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सुधार

POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जिसे अपने राज्य विजली बोर्ड की क्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऑपरेशनल एवं फाइनेंसियल एकरान प्लान (ओएफ) अपनाया स्वीकार किया है। विश्व बैंक एवं ऊर्जा वित्त निगम को दिए गए आश्वासन की अनुपालना हेतु कृषि क्षेत्रों में वित्त खर्चों पर अनुदान में वृद्धि के सहित कुछ अन्य उपाय प्रारम्भ कर दिए हैं।

राजस्थान में शक्ति के साधन

POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

(1) कोयला (Coal) - राजस्थान में उतम किस्म के कोयले के अधिक भण्डार नहीं हैं। कोयला मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। लिग्नाइट, विटुमिनस और एन्थेसाइट। एन्थेसाइट वायव्य सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। इसमें कार्बन का अंश 80% से 95% तक होता है। इसका रंग चमकीला काला होता है तथा इसमें कम धुआँ तथा अधिक ताप प्राप्त होता है। विटुमिनस कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 75% से 80% के मध्य होता है। इसका रंग काला होता है। इसमें भी अधिक ताप व कम धुआँ प्राप्त होता है। लिग्नाइट निम्न किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 45% से 55% के मध्य होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें ताप व शक्ति अपेक्षाकृत कम व धुआँ अधिक होता है। राजस्थान में यही निम्न किस्म का कोयला अर्थात् लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। संपूर्ण भारत का कोयला उत्पादक क्षेत्र का ज़रा दो भागों में बाँटा जाता है तो हमारा गोंडवाना क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र हमारा सम्पन्न आते हैं। राजस्थान इसी दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है जिसके अन्तर्गत पलना, छाग आदि क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिले में गणसठेवर क्षेत्र प्रमुख है। राजस्थान में सबसे अधिक कोयला पलना की कोयला खानों में प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला यद्यपि निम्न श्रेणी का कोयला होता है किन्तु लिग्नाइट श्रेणी के कोयलों में तो राजस्थान में प्रायः

लिमाइट श्रेष्ठ किस्म का माना जाता है पलाना में औसतन 6 मीटर मोटी कोयले की परतें हैं। यहाँ पर लगभग 2 करोड़ टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान है। पलाना के अनिरिक्त गणसरोवर, चानेरी, खारी केसर, दसेर आदि स्थानों पर कोयले के भण्डार मिलते हैं किन्तु व्यापारिक स्तर पर उत्पादित नहीं किये जा रहे हैं। मेडाना में भी लिमाइट कोयला मिलने की संभावना है। इस क्षेत्र में धार्य किया जा रहा है।

उत्पादन (Production)

राजस्थान में लगभग 55,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जा रहा है। कोयले के निम्न श्रेणी के होने के बावजूद भी इन भण्डारों को यों ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस कारण इन क्षेत्रों के आस-पास विद्युत्‌गृहों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। शक्ति के साधनों की कमी के साथ-साथ राजस्थान के इन अविद्योहित कोयला भण्डारों का भी प्रयोग होने लगेगा, ऐसी संभावना है। राजस्थान में अभी भी विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बाहर से कोयला मगवाया जाता है। विगत कुछ वर्षों में ईंटों के भट्टों, सीमेंट के कारखानों, रसायन उद्योगों, सूती मिलों, खाद संकाओं, घोलू कार्यों आदि विभिन्न उपयोगों के लिये कोयला वितरित किया गया जा इस बात का द्योतक है राजस्थान में कोयले की पर्याप्त मात्रा है।

(2) खनिज तेल (Crude Oil) - खनिज तेल संपूर्ण विश्व में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। तेल राजनीति ने जिस प्रकार से विश्व की प्रभावित किया है वह इसके महत्व का परिचायक है। खनिज तेल ऐसा सुविभाजनक ऊर्जा साधन है जो विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होकर मानव को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान कर रहा है। करोड़ों वर्ष पूर्व जीव-जंतुओं और वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने के कारण शक्ति ने अपनी प्रक्रिया से उसे खनिज तेल में परिवर्तित कर अपनी परतदार बट्टियों में संचित करके रखा है। खनिज तेल की दृढ़ती कमियों के कारण राजस्थान में तेल मिलने की संभावनाओं का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में तेल एवं गैस के भण्डार होने का अनुमान है। हनुमंती में ऑयल इण्डिया लिमिटेड की राजस्थान परियोजना द्वारा बीकानेर-नागौर बेसिन में खोदे जा रहे पहले कुएँ में खनिज तेल मिलने के संकेत मिले हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 20 कुएँ खोदे जाने की योजना है। इस हेतु राजस्थान परियोजना को कुल 135 करोड़ रुपये का बजट

भी आवंटित किया गया है। बीकानेर - नागौर बेसिन के बागेवाला कुआँ न - 1 में चूने की छिद्रदार सरचना में खनिज तेल मिलने की पूरी आशा है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान की कयापलट हो सकती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजस्थान की इस प्रकार की सरचना अरब राष्ट्रों की तेल सरचना से मिलती जुलती है। इस कारण, इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना बढ़ गई है। बीकानेर के पश्चिम में 140 किमी दूर बागेवाला में 1 जुलाई, 1991 को खुदाई का कार्य आरम्भ हुआ है। खुदाई के मध्य किये गये परीक्षण से भारी मात्रा में खनिज तेल मिलने का संकेत मिला है। नागौर बेसिन के इस कुएँ में करीब 920 मीटर की गहराई पर काफी मात्रा में तेल के संकेत मिले हैं। लगभग 1095 मीटर गहराई में कुछ मात्रा में खनिज तेल भी प्रवाहित हुआ है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार इस खनिज तेल का रंग डामर जैसा है और यह अति उच्च लसोलापन किये हुये है। इस कुएँ की 1380 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है और आगे खुदाई का कार्य चल रहा है। जिन बट्टियों में यह तेल मिला है, वे सम्भवतः कैम्ब्रियन युग की हैं जो लगभग 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार ऐसी बट्टियाँ भारत में तटीय तलहटी बेसिन की होती हैं। बागेवाले सरचना का हवाई विस्तार लगभग 18 वर्ग कि.मी. है और 70 वर्ग किमी क्षेत्र में सरचनाओं के समूह बने हुये हैं। बागेवाला सरचना में, निगम के अनुसार 3 करोड़ टन खनिज तेल के भण्डार होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में खनिज तेल का भण्डार 18 करोड़ टन हो सकता है। निगम के अनुसार इस खनिज तेल का उत्पादन कार्य आसान नहीं है। उनके दृष्टिकोण में यह उत्तरी गुजरात में उत्पादित किये जा रहे खनिज तेल से मिलता-जुलता है। इस क्षेत्र में गाँडे खनिज तेल के उत्पादन तथा परिवहन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। बागेवाला में खनिज तेल मिलने से पूर्व जैसलमेर क्षेत्र के दो कुओं में भी खनिज तेल के भण्डार होने के संकेत मिले हैं। डाडेवाला के कुआँ न - 1 तथा 2 में खनिज तेल के संकेत प्राप्त हुए हैं। इन कुओं में प्राथमिक गैस के साथ ही थोड़ी मात्रा में हल्के किस्म का खनिज तेल भी मिला है। जैसलमेर बेसिन में अब तक 10 कुओं की खुदाई पूरी हो चुकी है। जैसलमेर बेसिन में तनोट तथा अन्य पूर्वी तनोट सरचना में कुएँ खोद गये हैं। छोटे गूँ कुओं में से 3 का विस्तृत परीक्षण भी किया जा चुका है। परीक्षण से पता चलता है कि इन कुओं में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस के भण्डार उपलब्ध हैं। तनोट क्षेत्र के चौथे कुएँ का परीक्षण जारी है किन्तु खुदाई के दौरान मिले संकेतों से ज्ञात होता है कि इस कुएँ में भी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। तनोट के दक्षिण में

ने अतर्गत राज्यों में 34528 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।¹ इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1997 तक 544 लाख कुओं को भी विद्युतीकृत किया गया है।²

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (REDA) - राजस्थान में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के उद्देश्य से जनवरी, 1995 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (REDA) की स्थापना की गई। यह संस्था राज्य में सौर-ऊर्जा, वायु-ऊर्जा और बायो गैस के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के मरूस्थलीय क्षेत्र विशेषतः जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (सीज) की स्थापना कर रही है।³

राजस्थान विद्युत मंडल (RSEB) - यह मंडल विभिन्न विजली परियोजनाओं की स्थापना, चोज एवं उनके क्रियान्वयन तथा विद्युत सवहन एवं वितरण के कार्यों में मलम है। कोटा ताप विजलीघर भारी जल विद्युत परियोजना, व्यास, चबल एवं सतपुड़ा परियोजनाएं राज्य में विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के राजस्थान अनुशक्ति, मिगरेली ताप विद्युत परियोजना, हिन्द अन्ता औरैया नदी एवं दादरी गैस, ऊँपाहार ताप विद्युत एवं टनवरपुर परियोजना राज्य की विद्युत आपूर्ति में योगदान करते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के अंत तक राज्य में 33827 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था।⁴ इनके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 188 ग्रामों का और विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार दिसम्बर 96 तक कुल 34015 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।⁵ इसी तरह वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 25535 कुओं को विद्युतीकृत किया गया। अब तक कुल 5 28 लाख कुओं का विद्युतीकृत किया जा चुका है।⁶

वर्ष 1995-96 में 13079 73 मिलियन विद्युत उपभोग की तुलना में वर्ष 1996-97 में 14213 43 मिलियन यूनिट होने की संभावना है।⁷ इस प्रकार प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1995-96 में 265 यूनिट की तुलना में वर्ष 1996-97 में 281 यूनिट होने का अनुमान है।⁸

1950-51 में विद्युत की स्थापित क्षमता 13 मेगावाट थी जो सातवी योजना के अंत तक बढ़कर 2711 42 मेगावाट हो गई। 1995-96 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3049 मेगावाट थी।⁹

आठवी योजना में शक्ति पर वार्षिक व्यय 3081. 4 करोड़ रुपए हुआ है और नवी योजना में 5510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।¹⁰

राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सुधार

POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जिन्होंने अपने राज्य विजली बोर्ड की क्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऑपरेशनल एवं फाइनेंसियल एक्शन प्लान (ओफेप) अपनाया स्वीकार किया है। विश्व बैंक एवं ऊर्जा पित निगम को दिए गए आवासन की अनुपालना हेतु वृषि कनेक्शनों के लिए छम्भों पर अनुदान में क्रमिक कमी सहित कुछ अन्य उपाय प्रारम्भ कर दिए हैं।

राजस्थान में शक्ति के साधन

POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

(1) कोयला (Coal) - राजस्थान में उत्तम किस्म के कोयले के अधिक भण्डार नहीं हैं। कोयला मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। लिग्नाइट, बिटुमिनस और एन्थेसाइट। एन्थेसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। इसमें कार्बन का अंश 80% से 95% तक होता है। इसका रंग चमकीला काता होता है तथा इसमें कम धुआं तथा अधिक ताप प्राप्त होता है। बिटुमिनस कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 75% से 80% के मध्य होता है। इसका रंग काता होता है। इसमें भी अधिक ताप व कम धुआं प्राप्त होता है। लिग्नाइट निम्न किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 45% से 55% के मध्य होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें वाष्प व शक्ति अपेक्षाकृत कम व धुआं अधिक होता है। राजस्थान में यही निम्न किस्म का कोयला अर्थात् लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों को जब दो भागों में बांटा जाता है तो क्रमशः गोंडवाना क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र हमारे समक्ष आते हैं। राजस्थान इसी दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है जिसके अन्तर्गत पलाना, राठी आदि क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिले में मणामरोवर क्षेत्र प्रमुख है। राजस्थान में सबसे अधिक कोयला पलाना की कोयला खानों में प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला यद्यपि निम्न श्रेणी का कोयला होता है किन्तु लिग्नाइट श्रेणी के कोयलों में तो राजस्थान में प्राप्त

लिग्नाइट ग्रेड किस्म का माना जाता है पलाना में औसतन 6 मीटर मोटी कोयले की परतें हैं। दहा पर लगभग 2 करोड़ टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान है। पलाना के अतिरिक्त गगामरोवर, चानेरी, खारे केसर, दसेर आदि स्थानों पर कोयले के भण्डार मिले हैं किन्तु व्यापारिक स्तर पर उत्पादित नहीं किये जा रहे हैं। मेडता में भी लिग्नाइट कोयला मिलने की संभावना है। इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

उत्पादन (Production)

राजस्थान में लगभग 55,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जा रहा है। कोयले के निम्न श्रेणी के होने के बावजूद भी इन भण्डारों को यों ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस कारण इन क्षेत्रों के आस-पास विद्युतघृहों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। शक्ति के साधनों की कमी के साथ-साथ राजस्थान के इन अविद्योहित कोयला भण्डारों का भी प्रयोग होने लगेगा, ऐसी संभावना है। राजस्थान में अभी भी विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बाहर से कोयला मगवाया जाता है। विगत कुछ वर्षों में ईटों के भट्टे, सीमेंट के कारखाने, रसायन उद्योगों, सूती मिलों, खाद संवर्धकों, घरेलू कपड़ों आदि विभिन्न उपकरणों के लिये कोयला विनिर्माण किया गया जो इस बात का द्योतक है राजस्थान में कोयले की पर्याप्त मांग है।

(2) खनिज तेल (Crude Oil) - खनिज तेल संपूर्ण विश्व में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। तेल राजनीति ने बिना प्रकार से विश्व को प्रभावित किया है वह इसके महत्व का परिचायक है। खनिज तेल ऐसा सुविधाजनक ऊर्जा साधन है जो विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होकर मानव को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। करोड़ों वर्ष पूर्व जीव-जंतुओं और वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने के कारण प्रकृति ने अपनी प्रक्रिया से उसे खनिज तेल में परिवर्तित कर अपनी पर्यावरण चट्टानों में संचित करके रखा है। खनिज तेल की बढ़ती कीमतों के कारण राजस्थान में तेल मिलने का संभावनाओं का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में तेल एवं गैस के भण्डार होने का अनुमान है। हाल ही में ऑयल इण्डिया लिमिटेड की राजस्थान परियोजना द्वारा बीकानेर भागीरथ बेसिन में खोदे जा रहे पहले कुएँ में खनिज तेल मिलने के संकेत मिले हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 20 कुएँ खोदे जाने की योजना है। इन हेतु राजस्थान परियोजना का कुल 135 करोड़ रुपये का बजट

भी आवंटित किया गया है। बीकानेर - नागौर बेसिन के बागेवाला कुआँ न - 1 में चूने की छिद्रदार सरचना में खनिज तेल मिलने की पूरी आशंका है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान को कयापलट हो सकती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजस्थान की इस प्रकार की सरचना अरब राष्ट्रों की तेल सरचना से मिलती जुलती है। इस कारण इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना बढ़ गई है। बीकानेर के पश्चिम में 140 किमी दूर बागेवाला में 1 जुलाई, 1991 को खुदाई का कार्य आरम्भ हुआ है। खुदाई के मध्य किये गये परीक्षण से भारी मात्रा में खनिज तेल मिलने का संकेत मिला है। नागौर बेसिन के इस कुएँ में करीब 920 मीटर की गहराई पर काफी मात्रा में तेल के संकेत मिले हैं। लगभग 1095 मीटर गहराई में कुछ मात्रा में खनिज तेल भी प्रवाहित हुआ है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार इस खनिज तेल का रंग डामर जैसा है और यह अति उच्च तलसोलापन किये हुये है। इस कुएँ की 1380 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है और आगे खुदाई का कार्य चल रहा है। जिन चट्टानों में यह तेल मिलता है, वे सम्भवतः कैम्ब्रियन युग की हैं जो लगभग 60 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार ऐसी चट्टानें भारत में तटीय तलहटी बेसिन की होती हैं। बागेवाले सरचना का हवाई विस्तार लगभग 18 वर्ग कि.मी. है और 70 वर्ग किमी. क्षेत्र में सरचनाओं के समूह बने हुये हैं। बागेवाला सरचना में, निगम के अनुसार 3 करोड़ टन खनिज तेल के भण्डार होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में खनिज तेल का भण्डार 18 करोड़ टन हो सकता है। निगम के अनुसार इस खनिज तेल का उत्पादन कार्य आरम्भ रही है। उनके दृष्टिकोण में यह उत्तरी गुजरात में उत्पादित किये जा रहे खनिज तेल से मिलता-जुलता है। इस क्षेत्र में गाढ़े खनिज तेल के उत्पादन तथा परिवहन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। बागेवाला में खनिज तेल मिलने से पूर्व जैसलमेर क्षेत्र के दो कुओं में भी खनिज तेल के भण्डार होने के संकेत मिले हैं। डाडेवाला के कुआँ न - 1 तथा 2 में खनिज तेल के संकेत प्राप्त हुए हैं। इन कुओं में प्राप्त प्राकृतिक गैस के साथ ही थोड़ी मात्रा में हल्के किस्म का खनिज तेल भी मिला है। जैसलमेर बेसिन में अब तक 10 कुओं की खुदाई पूर्ण हो चुकी है। जैसलमेर बेसिन में तनोट तथा अन्य पूर्वी तनोट सरचना में कुएँ खोद गये हैं। खोदे गए कुओं में से 3 का विस्तृत परीक्षण भी किया जा चुका है। परीक्षण से पता चलता है कि इन कुओं में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस के भण्डार उपलब्ध हैं। तनोट क्षेत्र के चौथे कुएँ का परीक्षण जारी है किन्तु खुदाई के दौरान मिले सफेते से ज्ञात होता है कि इस कुएँ में भी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। तनोट के दक्षिण में

करीब 4 किलोमीटर पर स्थित जलालवाला में खोद गया पहला कच्चा मफ़ल संचित होने की संभावना है। आयल इण्डिया लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेल और गैस की खान के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में एक और ग़म को गंभीरता से लिया है। यही ग़म बागेवाला कुआँ न 1 की खुदाई का कार्य कर रही है।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा मई 1991 में प्रस की भूकम्पी कंपनी 'फ़र्मेज़ाइन जनरल डी ब्रिआगिजक द्वारा भूकम्पी के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण का कार्य आरम्भ किया गया है। इस चरण में भूकम्पी सर्वेक्षण के लिये लगभग 2500 वर्ग किमी क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य करने की योजना है। इन सर्वेक्षणों से तनोट डाडेवाला एवं इसके आस पास के क्षेत्र में हाइड्रो-कार्बन गैस भण्डार का पता लगाया जा सकेगा। आयल इण्डिया लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के चार के भू गर्भ में तेल खोजने का कार्य 1982 ई में आरम्भ किया था। इस पर अब तक 125 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

उत्पादन (Production) आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अभी तक राजस्थान में दो जगह तेल मिलने की घोषणा की जा चुकी है। प्रथम डाडेवाला में और द्वितीय बागेवाला में। डाडेवाला में गैस के साथ तेल भी मिला है परन्तु इसकी मात्रा बहुत कम है। इस क्षेत्र में खोजे गये भारी खनिज तेल का उपयोग सदिग्ध है। ऐसा अनुमान है कि इसका उपयोग आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ेगा। बागेवाला में खनिज तेल उत्पादन होने की संभावना है। यद्यपि वह खनिज तेल पेट्रोल एवं मिस्ट्री का तेल उत्पादन करने योग्य नहीं है। आयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार बागेवाला में मिला तेल पेट्रो-केमिकल्स उद्योग के काम आ सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में खनिज तेल के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

जल विद्युत (Hydro-electricity) - राजस्थान में जल

विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्थान में कोयले का अधिक उत्पादन नहीं होता और इसी प्रकार अभी तक खनिज तेल का उत्पादन भी आरम्भ हो पाया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के पास जो विकल्प विद्यमान है उनमें जल विद्युत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में कोयले के अभाव के कारण तापीय विद्युत गृह निर्मित नहीं किये जा सकते थे और न ही खनिज तेल पर आधारित विद्युत गृह विकसित किये जा सकते थे। इस कारण राजस्थान सरकार ने अपने संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये अपने पड़ोसी राज्यों से इस प्रश्न पर सम्झौते किये कि उसे पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होती रहे। जल विद्युत कभी समाप्त न होने वाला साधन है। इससे वातावरण का प्रदूषण भी नहीं होता किन्तु दुर्भाग्य से राजस्थान में 12 महाने बहने वाली अधिक नदियाँ नहीं हैं। इस कारण राजस्थान की अपेक्षा के अनुसार जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाया है। जल विद्युत उत्पादन की कम लागत इसका कभी सम्पादन न होने वाला स्वरूप प्रदूषण रहित और कम पूँजी के कारण इतना महत्व बल गया है। राजस्थान में उद्योगों के विद्वेष्टीकरण लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास और रेगिस्तान में सिंचाई साधनों के विकास के लिये जल विद्युत उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना राजस्थान सरकार के लिये अनिवार्य हो गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) राजस्थान सरकार ने अपनी धूमताओं को ध्यान में रखते विभिन्न राज्यों से साझेदारी में जो योजनाएँ बनाई हैं उनमें राजस्थान को जल विद्युत उपलब्ध होती है। इनमें भाखड़ा नागल परियोजना, नवल परियोजना व्याग परियोजना और सतपुड़ा विद्युतगृहों की स्थापना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही विद्युत परियोजना अन्ना विद्युत परियोजना सगरोली विद्युतगृह एवं कई हाई गैम पर आधारित योजनाओं से ही विद्युत प्राप्त हो रही है अथवा होने की संभावना है।

राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं से 1995-1996 में प्राप्त विद्युत			
विद्युत गृह	विद्युत उत्पादन (किलोवाट)	कुल प्राप्त विद्युत विद्युत क्रय/प्राप्ति (किलोवाट)	उत्पादन व क्रय
1. भाखड़ा			4081.4
2. नवल			388.9
3. व्याग	329.7		4.8
4. सतपुड़ा	4.8		3.4
5. माही	1.3		10.1
6. अन्ना	11.5		8.1
(ग) जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन व क्रय			
1. पाश्चात्त		1024.2	1024.2

ऊर्जासम्पदा पाएँ वैज्ञानिक कर वहन ह कि मुख्य एव आणविक ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्रोतों पर ध्यान देना है। वह दिनपर जिनकी ऊर्जा ग्रहण करता है वह औसतन एक 100 वॉट की बिजली के कब के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक नहीं होगी। भोजन के रूप में पचाई गई इस ऊर्जा से ही वह सारे शारीरिक काम करता है। जहाँ तक मानसिक कार्यों का प्रश्न है, वे इससे लगभग नहीं कर सकेंगे। ऊर्जा खपती है किन्तु प्रश्न यह है कि मर्याद के अन्तर्गत औद्योगिक देश '100 वॉट की मानवीय दली' को बनाए रखने के विभिन्न ऊर्जा स्रोत कौन हैं?

वाल्मीकि प्रदेश है जहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्ति की विपुल सम्भावनाएँ हैं। जनवरी 1996 तक जोधपुर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में क्रमशः 200 मेगावाट 50 मेगावाट एव 50 मेगावाट क्षमता के 3 सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किये गये हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण सौर ऊर्जा के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य हुये हैं। इन सौर ऊर्जा वालित एम्पों, सामुदायिक टर्मिनल सैटों की स्थापना, एम पी बी लाइट आदि मुख्य हैं। राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एव सौर ऊर्जा सुलभ करने का कार्य राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण (रज) द्वारा किया जा रहा है। सौर शक्ति के क्षेत्र में 300 मेगावाट की शक्ति परियोजनाओं के लिए 3 कम्पनियों को आमन्त्रित किया गया है। ये सभी कम्पनियाँ सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (Solar Energy Enterprises Zone) बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में स्थापित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने म्यानिआ और तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए नवी योजना में 980 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

4 वायु शक्ति (Wind Power) - विश्व मोटोरिअरेलॉजी संगठन के अनुसार विश्व में अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में 20 बिलियन किलोवाट विद्युत, वायुशक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। हिन्दुस्तान एपेनोडिक्स लिमिटेड द्वारा किये गये अध्ययन में वायुशक्ति के मध्य में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये हैं

वायु की गति कि मी प्रति घंटा	वार्षिक विद्युत उत्पाद प्रति घंटा
13-17	10 200
9.5-12.5	8,000
6.5-9.6	4 500

यह ध्यान रखने योग्य है कि एक पवन चक्की उस समय कार्य करती है जबकि वायु की गति 8 कि मी प्रति घंटा हो। यमी और मानसून में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिला, पंजाब, असम, पञ्जाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों में वायु का शक्ति के रूप में प्रयोग सम्भव है। इन काल में मराठवाड़ा गुजरात व राजस्थान

के कुछ क्षेत्र तथा उड़ीसा व पंजाब के तटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गति 15 कि मी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र तथा राजस्थान में जैसलमेर-फलौदी क्षेत्रों में तो विद्युत उत्पादन भी सम्भव है। शीत ऋतु तथा मानसून के पश्चात् के समय में वायु में कम उत्पादन प्राप्त होगा। भारत में राजस्थान का शुष्क प्रदेश तथा दक्षिण भारत के तटीय प्रदेश वायुशक्ति प्रचुरता के लिये आदर्श है।

राजस्थान में ऊर्जा-विकास के संदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका

ROLE OF PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF POWER SECTOR IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने 4300 मेगावाट के अतिरिक्त विद्युत क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया है जो निम्न प्रकार हैं -

1 कपूरडी परियोजना - 1800 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की जायेगी। इसमें विद्यमान दो इकाइयों में से प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट होगी। यह परियोजना लिग्नाइट पर आधारित होगी।

2 बालीसा परियोजना - इस परियोजना में 3600 करोड़ रुपए की लागत से 1000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त की जायेगी। इस परियोजना में विद्यमान 4 इकाइयों में से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट होगी। यह परियोजना भी लिग्नाइट पर आधारित होगी।

3 भूरतगढ़ ताप बिजलीघर - कोयले पर आधारित इस परियोजना की प्रथम इकाई का कार्य राज्य विद्युत मंडल पूरा करेगा। जिसकी क्षमता 250 मेगावाट होगी। इसके दूसरे चरण के अंतर्गत विद्युत उत्पादन क्षमता की दो इकाइयाँ होगी - प्रथम से प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट होगी। - इस पर 1600 करोड़ रुपए की लागत आने की सम्भावना है। द्वितीय चरण के लिये निजी क्षेत्रों से संपर्क किया जा रहा है।

4 धौलपुर ताप बिजलीघर - ताजमहल की सुरक्षा की लेकर उत्पन्न हुये विवाद के कारण प्रसिद्ध धौलपुर ताप बिजलीघर की अब केन्द्र की स्वीकृति मिल गई है। 1300 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने वाली इस परियोजना की क्षमता 788 50 मेगावाट है। इसे निजी क्षेत्र के द्वारा पूरा किया जाएगा और तरल ईंधन (Liquid Fuel) से विद्युत उत्पन्न की जायेगी।

5 बीसलपुर बिजलीघर - 1800 करोड़ रुपए की लागत से 480 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जायेगी, इसमें दो विद्युत

इकाइया होगी जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 240 मेगावाट होगी। इसमें लिफ्टाइड के भंडारों का प्रयोग किया जायेगा।

6. नेथा आधारित विद्युत सयंत्र - राजस्थान सरकार ने हुये समझौते के अनुसार ब्रिटिश पावर इण्डस्ट्रीज कंपनी 40 मेगावाट क्षमता के 10 विद्युत सयंत्र लगायेगी। इनमें से प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार 1000 करोड़ रुपए की लागत से 400 मेगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।

7 सौर ऊर्जा - सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के मन्स्यलीय क्षेत्र विशेषतः जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र स्थापित कर रही है। इसके अंतर्गत 3 परियोजनाओं को हय में लिया गया है। बाड़मेर के आंगोरिया गांव के सन्मोर्म इंडिया लिमिटेड द्वारा 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा सयंत्र की स्थापना की जा रही है। जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। जैसलमेर में एनरान इटरनेशनल कंपनी 200 मेगावाट का एक सयंत्र लगायेगी। जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट होगी। जोधपुर में मखानिया गांव में एनको तथा एनरान कंपनी साझा रूप में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करेंगे।

8 राज्य विद्युत मंडल में निजीकरण की प्रवृत्ति - राजस्थान राज्य मंडल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए राज्य विद्युत निगम में बदला जा रहा है। मंडल में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम हय में लिये जा रहे हैं। बिजली का उत्पादन उसका वितरण तथा बिल वसूली आदि कार्य निजी क्षेत्र को ठेके पर देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ऊर्जा के साधनों की समस्याएं और उनका समाधान :-

ऊर्जा की पूर्ति एक राष्ट्रीय समस्या है। अतः ऐसी समस्याओं का समाधान जनसाधारण के सहयोग से ही किया जा सकता है। राज्य में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का निरंतर प्रयोग हो रहा है। लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। अतः अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाना चाहिये। शक्ति के साधनों की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं -

1 शक्ति के प्रमुख स्रोतों का अभाव - राज्य में शक्ति की मांग की तुलना में शक्ति स्रोतों की पूर्ति बहुत कम है। राज्य में कुछ मात्रा में कोयले पर निर्भर किया जाता है। वर्षा के वमी के कारण जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माण की

गति धीमी है। प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार भी सीमित हैं। अतः राज्य में अशक्ति के अभाव को दूर करने के लिये सूर्य शक्ति के स्रोत का पूर्णतः उपयोग किया जाना चाहिये।

2 परिवहन के साधनों का अभाव - राज्य में रेल एवं सड़क यातायात का धीमी गति से विकास हुआ है। अतः ऊर्जा स्रोतों विशेषतः कोयले के आवागमन में कठिनाई होती है। फलतः ऊर्जा संबंधी अनेक कार्य अवलंब हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान राज्य में परिवहन के साधनों का विकास करके से किया जा सकता है।

3 वर्षा का अभाव - राज्य के एक बहुत बड़े भू-भाग मरुस्थल में वर्षा का नितान्त अभाव रहता है। राज्य के पूर्वी भाग में वर्षा का सामान्य क्रम प्रायः जागे रहता है। अतः इस क्षेत्र में बांधों का निर्माण करके जल विद्युत की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। इस कार्य में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। राज्य में पूंजी साधनों का भी अभाव है। अतः केन्द्र सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय मन्माओं से ऋण प्राप्त करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

4 शक्ति सरचना का अभाव - राज्य में पूंजी के साधनों की अपर्याप्तता के कारण शक्ति के साधनों का आधारभूत ढांचा अत्यधिक कमजोर है। वही कारण है कि राज्य में शक्ति की पूर्ति की तुलना में मांग निरंतर बढ़ी रहती है। इस समस्या का समाधान करने के लिये निजी विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

5 अपव्यय एवं चोरी - राज्य में शक्ति के साधनों का वितरण मुख्यतः सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की सापराधाही के कारण शक्ति स्रोतों की चोरी होकर एक आम बात हो गई है। इस समस्या का समाधान के लिये शक्ति संबंधी संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिये तथा नियमन एवं निगरान प्रक्रिया सुदृढ़ किया जाना चाहिये। शक्ति के साधनों के मितव्ययतापूर्ण प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

6 शक्ति की बढ़ती हुई मांग की समस्या - राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विकास की तीव्र गति ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ते हुये यंत्रीकरण के फलस्वरूप राज्य में शक्ति की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। बड़े नगरों में विशेषतः औद्योगिक नगरों में आये दिन शक्ति कटौती के कारण न केवल उत्पादन कार्य अवलंब हो जाता है वरन् नगर में अंधेरा का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस समस्या का समाधान के लिये शक्ति आपूर्ति की एक दीर्घकालीन योजना निर्मित की

जानी चाहिये और उसी के अनुरूप शक्ति के माधनों का विकास किया जाना चाहिये।

7. अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास न हो पाना - राज्य में शक्ति के अपरम्परागत स्रोतों का सीमा सीमा से विकास हुआ है। राज्य में सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है लेकिन आधारभूत संरचना एवं पूंजी के अभाव के कारण इस शक्ति का उपयोग नगण्य रहा है। सौर ऊर्जा के विकास हेतु निजी विनियोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा सौर ऊर्जा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये केन्द्र सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये शक्ति के साधन राज्य अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले हैं। इनका विकास बरक ही राज्य अर्थव्यवस्था का चौमूली विकास किया जा सकता है। फलतः शक्ति के साधनों का विकास प्राथमिकताक्रम में किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान में सड़कों का विकास

DEVELOPMENT OF ROADS IN RAJASTHAN

1. सड़कों की लंबाई (Length of Roads) - राजस्थान भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है जहाँ सड़कों की लंबाई राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। वर्ष 1998-99 के अंत तक राज्य में सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किमी तक मात्र 42.68 किमी होने का अनुमान है जो कि राष्ट्रीय औसत 73 किमी प्रति 100 वर्ग किमी से बहुत कम था। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की कुल लंबाई वर्ष 1998-99 में बढ़कर 84958 किमी होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों व अभिकरणों द्वारा भी 64403 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है। गणपुर योजना के अनुसार प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 42 किलोमीटर लंबी सड़कें होनी चाहिये थीं और यह लक्ष्य 1961 तक प्राप्त किया जाना था किन्तु राजस्थान में यह लक्ष्य 1998-99 तक प्राप्त किया जा सका है। नवी योजना के अंतर्गत परिवहन पर 1353 करोड़ रुपये सड़क क्षेत्र में लिये रखे गये हैं। राजस्थान में श्रेणीवार सड़कों की लंबाई इस प्रकार है -

राज्य में विभिन्न प्रकार की सड़कों की लंबाई				
क्र.सं.	सड़कों के प्रकार	वर्ग मी.	किलोमी.	योग
1	राष्ट्रीय सड़कें	2464	-	2464
2	राज्य सड़कें	9956	34	9990
3	पुराना सड़कें	5660	129	5789
4	अपभ्रंश सड़कें	52345	11631	63976
5	रीमोन्स सड़कें	2229	-	2229
योग		73164	11794	84958
अपभ्रंश सड़कें द्वारा निर्मित सड़कें				64403
योग				149361

Source: Economic Review 1998-99 Rajasthan

2. जिले वार सड़क (Districtwise Roads) - राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर जिले में है। द्वितीय स्थान उदयपुर जिले का है और तृतीय स्थान पाली जिले का है। राजस्थान में विभिन्न जिलों में सबसे कम सड़कें भीतपुर व टोंक जिले में हैं।

3. सड़क मार्ग का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Routes) - राजस्थान में आद्वार 1964 में राजस्थान राज्य का परिवहन नियम का लागू किया गया था। राष्ट्रीय मार्गों पर नियम की है परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। निशान, माल परिवहन का कार्य मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर यात्री परिवहन का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालित किया जा रहा है।

4. मोटर परिवहन (Motor Transport) - वर्ष 1996 में कुल 19.29 लाख पंजीकृत मोटर वाहनों की तुलना में वर्ष 1997 में बढ़कर यह संख्या 21.27 लाख हो गई है जो कि 10.3 प्रतिशत की वृद्धि से दर्शाता है। विगत वर्षों में राज्य में परिवहन विभाग में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों की संख्या अलग-अलग है।

राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या			
क्र.सं.	परिवहन वाहनों के प्रकार	वर्ष 1997	वर्ष 1998
1	मोटर रिक्शा	90	90
2	ऑटो रिक्शा (साराई)	14.24	14.73
3	ऑटो रिक्शा	5346	5496
4	टैक्सी (साराई व अन्य)	2672	2192
5	साराई व अन्य (साराई, साराई)	0.98	1.2
6	ऑटो रिक्शा	0.82	0.85
7	टैक्सी	2.87	2.78
8	टैक्सी	0.47	0.48

Source: Economic Review 1998-99 Govt of Raj

की तुलना में कम है। अतः राज्य में सार्वजनिक परिवर्तनों के द्वारा अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगीकरण विकास आवश्यक है। राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन आधारभूत सुविधाओं (जल एवं शक्ति) के अभाव के कारण औद्योगिक उत्पादन पिछड़ा हुआ है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य का औद्योगिक विभाग, रीका, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी एवं ग्राम उद्योग भण्डाल निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। रीको औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यह निगम आधारभूत सुविधाओं जैसे भूमि का आवंटन आदि कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करता है। नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध की जा रही हैं। राज्य में औद्योगिक भूमि की मांग निरन्तर बढ़ रही है अतः रीको द्वारा अनेक नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापना और पूर्वस्थापित क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने भी धौलपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, झालवाड़ा व आबूरोड में विकास केन्द्रों की स्थापना की है। इन विकास केन्द्रों पर दो चरणों में लगभग 5800 एकड़ भूमि आवंटित करने की योजना है। प्रथम चरण में 85 करोड़ रुपये और द्वितीय चरण में 65 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत पिछड़ी चरण-3 परियोजना का प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस परियोजना के लिए 9.57 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। राजस्थान वित्त निगम लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह निगम कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सरल शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। निगम ने खनिज आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त निगम शिल्पियों महिला उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यशील पूँजी की व्यवस्था हेतु निगम सिंगल विण्डो स्कैम' का मंचालन करता है। निगम द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनः उत्पादन में लाने का भी प्रयास किया जाता है। निम्न तालिका में राज्य में उद्योगों का कुल राजस्व आय में भाग दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि -

1 प्रचलित कीमतों पर पंजीकृत कारखानों की आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राजस्वीय आय में इन कारखानों का प्रतिशत भाग कम हो रहा है।

2 प्रचलित कीमतों पर पंजीकृत विनिर्माण का राजस्वीय आय में योगदान कुल राशि की दृष्टि से निरन्तर बढ़ रहा है किन्तु प्रचलित कीमतों पर यह वृद्धि स्थिर कीमतों की अपेक्षा अधिक रही है।

3 गैर पंजीकृत विनिर्माण का कुल राशि की दृष्टि से राजस्वीय आय में योगदान निरन्तर बढ़ा है किन्तु प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर इन दोनों का ही राजस्वीय आय में प्रतिशत भाग कम हुआ है।

4 विनिर्माण (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) का 1990-91 में राज्य आय में भाग प्रचलित कीमतों पर 9.26 था जो 1998-99 में 7.78 रह गया। लगभग यही स्थिति स्थिर कीमतों पर इनके योगदान की रही है। इस दृष्टि से 1990-91 में इन दोनों का कुल राजस्वीय आय में योगदान 10.25 था जो 1998-99 में 11.01 हो गया।

2. उद्योगों का रोजगार में भाग अथवा रोजगार सृजन

Contribution of Industries in Employment or Employment Generation

बड़े उद्योगों की अपेक्षा लघु औद्योगिक इकाइयों की लगत कम होती है और इनमें अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। इस दृष्टि से औद्योगिक विकास में इनकी विशिष्ट स्थान है। औद्योगिक इकाइयों का तेजी से विकास करने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन, रियायतें और विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रही है। इन इकाइयों के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जिला उद्योग केंद्र 'सिंगल विण्डो' योजना का अंतर्गत इन इकाइयों को निरन्तर सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। नवार्ड पुरावित योजना तथा शिथिल बेटेजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पर्याप्त ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। पूँजी विनियोजन अनुदान योजना के अंतर्गत भी इन इकाइयों को ऋण दिया जाता है। अनेक इकाइयों का भारतीय मानक संस्थान में पंजीकरण हो चुका है। खादी व ग्रामोद्योग कम पूँजी विनियोजन से अपेक्षाकृत अधिक रोजगार सृजन करते हैं। इस बात की पुष्टि संस्कार द्वारा गठित व्यास समिति ने भी की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में

उद्योगों का कुल राजस्वीय आय में भाग

वर्ष	विनिर्माण प्रचलित कीमतों पर	पंजीकृत स्थिर कीमतों पर	विनिर्माण प्रचलित कीमतों पर	गैर पंजीकृत स्थिर कीमतों पर
1990-91	85908 (4.29)	42478 (4.93)	76804 (4.37)	43682 (5.32)
1995-96	25522 (5.12)	80769 (6.91)	138660 (2.86)	47542 (4.69)

खादी व ग्रामोद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे लाखों व्यक्तियों को खादी उद्योग में रोजगार उपलब्ध हुआ है और इसी प्रकार ग्रामोद्योगों में भी अनेक लोगों को रोजगार की शक्ति होती है।

कुल रोजगार में भीषण गति से निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1981 में पंजीकृत विनिर्माण में कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 1 66 लाख थी जो बढ़कर 1991 में 2 60 लाख हो गई। अतः रोजगार की दृष्टि से उद्योगों का महत्व निरन्तर बढ़ रहा है। दिसम्बर 1997 तक ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों में 7 39 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।

राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएँ

CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL SECTOR OF RAJASTHAN

1 आकार (Size) - स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान के औद्योगिक आकार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। बड़े उद्योगों के साथ साथ मध्यम व लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी की गई है।

पंजीकृत कारखाना की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का औद्योगिक आकार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1981 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1 608 थी जो बढ़कर 1996 में 13665 हो गई। राज्य में रोजगार की दृष्टि से ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। अतः इन इकाइयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1990-91 में ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1 53 लाख थी जो बढ़कर दिसम्बर 1997 में 1 90 लाख हो गई।

रोजगार की दृष्टि से भी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि का आभास होता है। 1981 में पंजीकृत निर्माण की कुल संख्या 6608 थी जिनमें 1 66 लाख व्यक्तियों का रोजगार प्राप्त हो रहा था। 1991 में पंजीकृत निर्माण की संख्या 10792 हो गई जिनमें 2 60 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इस प्रकार रोजगार में वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि का बतानी है। ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों में भी रोजगार के अभाव नेत्र से बढ़ रहा है। 1990-91 में ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों में 5 71 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था जो बढ़कर दिसम्बर 1997 में 7 39 लाख व्यक्ति हो गए।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि में भी राज्य के

औद्योगिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि का आभास होता है। 1971 में राज्य में चीनी का कुल उत्पादन 11 लाख टन था जो बढ़कर 1998 में 58 7 हजार टन हो गया। 1984 में राज्य का सीमेंट का उत्पादन 3 01 लाख मेट्रिक टन था जो बढ़कर 1998 में 6206 लाख मेट्रिक टन हो गया। इस प्रकार 1984 में राजस्थान में ममक का उत्पादन 8 20 लाख टन था जो बढ़कर 1998 में 11 00 लाख टन हो गया। इस प्रकार राज्य के प्रायः विभिन्न छेदे व बड़े उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह उत्पादन वृद्धि राज्य के औद्योगिक आकार में वृद्धि को दर्शाती है।

राज्य में पूँजी के विनियोजन सशर्त गतिविधियों से भी औद्योगिक आकार में वृद्धि का आभास होता है। राज्य के पंजीकृत उद्योगों के साथ लघु व ग्रामोद्योगिक इकाइयों में भी पूँजी विनियोजन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के विभिन्न औद्योगिक संस्थान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से पूँजी विनियोजन को बढ़ावा दे रहे हैं। दिसम्बर 1997 तक 1 90 704 ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन किया जा चुका था और इनमें 2184 43 करोड़ रुपये का पूँजीनिवेश हुआ था तथा 7 39 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

2 वस्तुगत ढाँचा (Commodity Structure)

राजस्थान में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये वस्तुएँ मुख्यतः फैक्ट्री क्षेत्र व गैर फैक्ट्री क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। फैक्ट्री क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी उद्योगों के वार्षिक संस्थान से हो जाती है। विभिन्न उद्योगों द्वारा भरे गए विवरणों के अनुसार राजस्थान में 1994 के अन्त में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 608 उद्योग सम्मिलित थे। इनमें सर्वाधिक खाद्य तेल में संलग्नित कारखाने थे। सूती वस्त्र के निर्माण में सम्मिलित 1250 कारखाने थे जिनमें से अधिकांश सूती वस्त्र की छपाई में संलग्नित थे। अन्धधु खनिजों में सम्मिलित 1045 कारखानों में लगभग 40 प्रतिशत पत्थर के सामान के निर्माण में संलग्नित थे। मशीन और मशीन उपकरण बनाने वाले 310 कारखाने थे जिनमें से एकतिरार्द्ध क्षति उपकरणों का उत्पादन कर रहे थे। विद्युत उपकरण से सम्बन्धित कार्यों में 151 कारखाने कार्यरत थे जिनमें से अधिकांश बिजली के तारों के उत्पादन में लगे हुए थे।

राज्य का फैक्ट्री क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। इनका द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है अतः राज्य के औद्योगिक उत्पादन

में विविधता दृष्टिगोचर होती है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने उद्योगों को पांच समूहों में विभक्त किया है। राज्य के उद्योगों को भी इसी समूहों के अनुसार बांटा जा सकता है। प्रथम समूह, गैर धात्विक खनिज पदार्थों से बनी वस्तुएँ इसके अंतर्गत ग्रेनाइट, मार्बल, सोपेस्ट, चीनी मिट्टी, अभ्रक से बनी वस्तुएँ तथा काच आदि को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय, बेसिक धातु व अर्धोद्योग इसके अंतर्गत तांबा, जस्ता, सोह, एल्युमिनियम व अन्य अल्पोद्योग धातु उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय, रेशम, ऊन तथा सिन्थेटिक रेशों के दस्त इसके अंतर्गत ऊन की बनाई तथा कटाई रेशम व सिन्थेटिक वस्त्रों से संबंधित क्रियाएँ आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ, सूती वस्त्र इसके अंतर्गत कटाई, बुनाई, रंगाई व छपाई आदि कार्यों का समावेश किया जाता है। पंचम, परिवहन उपकरण एवं कलपुर्जें इसके अंतर्गत रेल, सड़क के उपकरण तथा स्कूटर व माइक्रोकार्स आदि के कलपुर्जें सम्मिलित किए जाते हैं। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूध तथा खाद्यान्न से बनी वस्तुओं गुड-चीनी नमक-बेल आदि का उत्पादन किया जाता है। राज्य में विभिन्न प्रकार के रसायन व रासायनिक पदार्थों, प्लास्टिक एवं रबड़ आदि का उत्पादन किया जाता है। विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार की मशीनें एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन भी शुरु हो गया है। भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार उद्योगों के वस्तुगत ढांचे को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(i) खाद्य वस्तुओं का निर्माण (Manufacturing of Food Products) दूध पाउडर, आइसक्रीम, घी फलों का जूस, आटा दाल वैंड विस्कुट आदि गुड व खाण्डसारी शक्कर, नमक वनस्पति तेल एवं घी पशुओं के खाद्य पदार्थ पापड़ व खाद्य पदार्थों में संबंधित अन्य विधायन सम्बन्धित।

(ii) तम्बाकू (Manufacturing of Beverages, Tobacco & Tobacco Products) मिष्ट शराब, तम्बाकू और इनसे संबंधित अन्य वस्तुएँ।

(iii) सूने वस्त्र (Manufacturing of Cotton Textiles) चिन्नेल निक्कलना, कश्म की गूठे दाघना कश्म को माफ करना, कटाई-बुनाई धागा बनाना रंगाई-छपाई खाद्य के वस्त्र और वस्त्रों की अंतिम रूप देने संबंधी क्रियाएँ सम्मिलित करना।

(iv) ऊन रेशम व सिन्थेटिक धागे का निर्माण (Manufacturing of Wool Silk and Synthetic Fibre Textile) ऊन का माफ करना, धागे बनाना, बुनाई तथा

कटाई, केवल व शॉल बनाना, सिन्थेटिक धागे बनाना और उनमें संबंधित विधायन क्रियाएँ आदि रेशम और रेशम संबंधी चीजें।

(v) जूट (Manufacturing of Jute Hemp & Mesta Textile) जूट से संबंधित वस्तुओं का निर्माण एवं हेमप व मेस्ता संबंधी वस्तुएँ बनाना।

(vi) टेक्स्टाइल्स संबंधी वस्तुओं का निर्माण (Manufacturing of Textiles Products) कपास की कटाई, कपड़ा बनाना, धागा बनाना, जूट व हेमप से रस्सी आदि बनाना, दरिया बनाना, बस्त्र बनाना, छत्रिया बनाना आदि।

(vii) लकड़ी व लकड़ी में बनी वस्तुएँ (Manufacturing of Wood and Wood Products) प्लाईवुड बनाना और प्लाईवुड से विभिन्न निर्माण तथा अन्य प्रकार की लकड़ों में औद्योगिक वस्तुएँ बनाना।

(viii) कागज बनाना (Manufacturing of Paper & Paper Products, Printing, Publishing etc.) छपाई व प्रकाशन कागज व कागज से संबंधित वस्तुओं का निर्माण, छपाई व प्रकाशन अभ्यवन।

(ix) चमड़ा व चमड़े से बनी वस्तुएँ (Manufacturing of Leather & Fur Products) चमड़ा तैयार करना और चमड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाना।

(x) रबड़ प्लास्टिक, पेट्रोलियम व कोयला उत्पाद (Manufacturing of Rubber, Plastic, Petroleum & Coal Products) टायर-ट्यूब बनाना, रबड़ के जूते, प्लास्टिक और पी वी सी संबंधित वस्तुएँ। रबड़ व प्लास्टिक शॉटल पॉलिथिन बैग आदि वस्तुएँ बनाना।

(xi) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद (Manufacturing of Chemicals & Chemical Products) विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधियाँ, पेंट, वर्निश एन्थ्रेथिक, अयुर्वेदिक एवं सूतने औषधियाँ डिजेंट, विभिन्न प्रकार के तेल, फेरो रसायन आदि।

(xii) गैर धातु उत्पाद (Manufacturing of Non-metallic Mineral Products) ईंट, टाइल्स, कैंच व कैंच का विभिन्न प्रकार का माफान, सोपेस्ट, चूना, अभ्रक व अभ्रक से बनी वस्तुएँ, पत्थर व पत्थरों के विभिन्न उत्पाद, एम्बेस्तेज, सोपेस्ट एवं एम्बेस्तेज संबंधी विभिन्न उत्पाद, तोह एवं इम्पान एवं इनसे संबंधित वस्तुओं का निर्माण, धातुओं को शुद्ध करना, स्टेन बनाना, औद्योगिक बनाना, बरत बनाना, विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ, जैसे प्रेशर कुकर, रेजर ब्लेड, मशीनें ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, बॉयलर्स, विभिन्न उद्योगों संबंधी मशीनें।

(xiii) विद्युत मशीनें एवं सबधित उपकरण (Manufacturing of Electrical Apparatus & Appliances) ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पावर केबल्स एण्ड वायरिंग, ड्राई सेल, पम्पे, लैम्प्स, रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ सबधी उपकरण, कम्प्यूटर आदि।

(xiv) परिवहन सम्बन्धी उत्पाद (Manufacturing of Transport Equipments & Parts) रेलवे वाहन और रेलवे सबधी उपकरण साइकिल एवं सबधित उपकरण तथा परिवहन सबधी अन्य उपकरण।

3 विकास केन्द्र (Growth Centres) अक्टूबर, 1989 में भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 70 विकास केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी। राजस्थान में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य में 5 विकास केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है। इन चार विकास केन्द्रों के लिए कमरा भौतवाड़ा, बीकानेर व आबूरोड व धौलपुर का चयन किया गया है। भारत सरकार प्रत्येक विकास केन्द्र पर विद्युत, रेल, सड़क आदि परिवहन के साधन, संचार एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने हेतु 30-30 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इन औद्योगिक केन्द्रों पर सघनात्मक सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ न केवल इन केन्द्रों पर औद्योगिक गतिविधियाँ तीव्र हो जाएगी। वरन् इन केन्द्रों के आस-पास के क्षेत्रों का भी विकास हो सकेगा। इन औद्योगिक केन्द्रों का विकास दो चरणों में किया जाएगा। इसके लिए लगभग 5800 एकड़ भूमि प्राप्त करने की योजना है। योजना के प्रथम चरण पर 85 करोड़ रुपये एवं द्वितीय चरण पर भी 85 करोड़ रुपये विनियोजित किए जाने की संभावना है। वर्ष 1995-96 में केन्द्र प्रवर्तित योजनामार्गत चार औद्योगिक विकास केन्द्रों-बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़ एवं आबूरोड पर कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है तथा 1995-96 में माह दिसम्बर तक 11.78 करोड़ रुपये खर्च किये गये। जोधपुर में एक लघु विकास केन्द्र स्वीकृत किया गया तथा माह दिसम्बर 1995 तक 1.05 करोड़ रुपये व्यय किये गये। भीतवाड़ा में भी विकास केन्द्र की शीघ्र ही केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है।

4 औद्योगिक नीति (Industrial Policy) अर्थव्यवस्था के समुचित विकास के लिए उपयुक्त औद्योगिक नीति का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में केन्द्र के समान औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। राज्य में औद्योगिक नीति की घोषणा सन् 1977 में की गई लेकिन औद्योगिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हो जाने के कारण राजस्थान सरकार के नवीन औद्योगिक नीति, 1990 की घोषणा की। इस नीति

का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्षेत्रीय विपत्ता को समाप्त करना, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन एवं वित्तीय स्रोतों में वृद्धि करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नीति के प्रस्ताव के अंतर्गत खादी, ग्रामीण उद्योग, दस्तकारी व चमड़ा उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों पर सरचनात्मक सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा। मानवीय संसाधनों के विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भौतिक स्रोतों की जानकारी हेतु एक नवीन सर्वेक्षण किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के विनियोग के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त विभिन्न करों में रियायतें प्रदान की जाएंगी, विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, औद्योगिक उत्पादों के किस्म नियंत्रण पर विशेष बल दिया जाएगा तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

5 औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) राजस्थान सरकार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः उत्पादन योग्य बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रुग्ण इकाइयों को न्यूनतम शुल्क और पाँच वट से मुक्त कर दिया गया है। रुग्ण औद्योगिक इकाई को पाँच वट से छूट दी जाएगी। राज्य में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा और इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर रुग्ण इकाइयों के पुनर्गठन के प्रयास किए जाएंगे। 1990 की औद्योगिक नीति में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः उत्पादन योग्य बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

6 सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) राजस्थान में केन्द्र सरकार के कुछ उपक्रम कार्यरत हैं। इन उपक्रमों के अंतर्गत हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर, इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सागर माल्ट्स लिमिटेड तथा मॉडर्न बेकरीज इण्डिया लिमिटेड आदि सम्मिलित हैं। राजस्थान सरकार ने भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उपक्रमों की स्थापना की है। दो गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट वैंकिकल्स वर्क्स, डीडवाना, राजकोय लक्ष्मण सोत, डीडवाना, पंचपटल व जावदीनगर, राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड, स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड, बीकानेर, वरुण सिग्नलिंग मिल्स, चूना व लाडनू, पतोलपार इम्यान् वेनिफिशियेशन सयर्, मैन्सुल इंडिया मेन्सुफैक्चरिंग कम्पनी आदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए सार्वजनिक उपक्रम हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में राज्यस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड और राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड भी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख संस्थाएँ हैं।

7 औद्योगिक विकास में योगदान देने वाली संस्थाएँ (Organisations for Industrial Development) राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट समस्याओं की स्थापना की गई है। इनमें से राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (रिको) राजस्थान लघु उद्योग निगम उल्लेखनीय है। इन संस्थाओं द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। दक्ष व मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास में राजस्थान वित्त निगम व रिको तथा लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में राजस्थान लघु उद्योग निगम महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। इन संस्थाओं के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप ही राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई है।

8 राज्य के प्रमुख उद्योग (Major Industries of Rajasthan) राजस्थान में बड़े व मध्यम उद्योगों के साथ साथ लघु व ग्रामीण उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। बड़ उद्योगों में अंतर्गत प्रेनाइट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, नमक उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, काच उद्योग ऊन उद्योग सामरसर उद्योग, इजॉनिबरींग उद्योग गमामरिफिक उद्योग आदि उल्लेखनीय हैं। राज्य में खादी उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त तेल घाणी उद्योग, गुड व खड्डमारी उद्योग लोहे व ताकड़ी का कार्य, बेत व बाम उद्योग ताड़ व गुड उद्योग मादिस व आरकवाँ उद्योग, फलों व सब्जियों का संरक्षण चूना उद्योग अल्युमीनियम उद्योग, रेशम उद्योग धान कूटने का उद्योग, मधुमक्खी फालन, पॉट्रिज उद्योग, चमड़ा उद्योग अखाद्य तेल से बना साबुन उद्योग, हाथ में बना कागज रेशम उद्योग दाल बनाने का उद्योग, ग्वार गम उद्योग हथकरघा उद्योग हड्डी पीसना ऊनी वस्त्र उद्योग दरी व निवार उद्योग पीतल व ताँबे के वर्तन बनाना एवं पीतल को खटाई हथो दात का कार्य बीड़ी उद्योग स्वर्ण व चांदी के आभूषण व वर्तन बनाना चित्रकारी गीटा उद्योग हस्तशिल्प आदि लघु व ग्रामीण उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हुआ है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास

INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

(अ) स्वतंत्रता के पूर्व औद्योगिक विकास Industrial Development Before Independence

स्वतंत्रता के पूर्व राज्य के अनेक क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के अनेक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का

निर्माण किया जाता था। राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में 1889 का वर्ष औद्योगिक विकास के शुभारंभ का वर्ष रहा। इस वर्ष राज्य के ब्यावर शहर में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। यह राज्य में प्रथम संगठित औद्योगिक इकाई थी। यह 19वीं शताब्दी की एक मात्र पंजीकृत औद्योगिक संस्था थी। वर्तमान शताब्दी में राजस्थान के विभिन्न भागों में अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। 1908 में कृष्णा मिल्स, ब्यावर, 1915 में एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी ताखेरी तथा 1938 में महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर की स्थापना की गई। इसके पश्चात् वर्तमान राजस्थान निर्माण के पूर्व, स्टेट मल्लगजा मिल्स लिमिटेड पाली, जयपुर स्प्रिंग मिल्स, जयपुर, श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज, कोटा तथा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के समय राज्य के विभिन्न भागों में अनेक छोट-छोट कारखाने कार्यरत थे।

(व) स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगिक विकास

Industrial Development after Independence

स्वतंत्रता के पूर्व राज्य में अनेक उद्योगों का विकास हुआ लेकिन राज्य के औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह नगण्य था। राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था। अतः राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास की गति प्रदान करने व लोगों के जीवनस्तर में सुधार करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तथा राज्य में औद्योगिक संरचना का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गए।

1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Plan) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक संरचना के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। योजनाकाल में 46 लाख रुपये उद्योग व खनिज पर व्यय किए गए। राज्य में शक्ति के अभाव के कारण अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं हो सकी। 1951 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 207 थी जो बढ़कर योजना के अंत में 365 हो गई।

2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Plan) द्वितीय योजनाकाल में आधारभूत एवं प्राथमिक उद्योगों की तीव्र गति से विकास करने का निश्चय किया गया। इस योजना में झरपुर में बैंगन फैक्ट्री की स्थापना तथा सर्वईमाधपुर में

मॉनेट फैक्ट्री का विस्तार किया गया। योजनाकाल में औद्योगिक विक्रम एव नियम व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 51 नए लाइसेंस जारी किए गए। अतः राज्य में सामाजिक खाद कारखाना, कोटा, जिक मैल्टर प्लांट उदयपुर, नायलॉन फैक्ट्री, वेंलियम कार्बाइड फैक्ट्री पी.वी.सी तथा कास्टिक सोडा प्लांट कोटा सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ आदि की स्थापना की गई। 1960 के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या 885 हो गई। इस योजना में उद्योग व खनिज पर 3.37 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

3 तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Plan) तृतीय योजना में भाखड़ा-नागल व चम्पल परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया। 1955 में विद्युत की कुल प्राप्ति कबज 15 मेगावाट थी जो बढ़कर 1960 में 65 मेगावाट हो गई। राज्य में सड़क यातायात का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। इसी प्रकार विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के कारण जल की पूर्ति में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। अतः राज्य में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएँ दृष्टिगोचर हो रही थी। योजना के प्रारंभिक तीन वर्षों में देश का तेजी से विकास हुआ लेकिन इसके पश्चात् राज्य में मानसून का अभाव तथा खान व पवित्रस्थान में युद्धों के कारण औद्योगिक विकास कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। योजनाकाल में उद्योग व खनिज पर 3.31 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

4 वार्षिक योजनाएँ 1966-69 (Annual Plans 1966-69) इस अवधि में लघु एवं कुटार उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, जोधपुर कोटा अलवर एवं भीलवाड़ा के विकास हेतु अनेक सुविधाओं की घोषणा की गई। निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनेक रियायतों एवं प्रोत्साहनों की घोषणा की। अतः राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास प्रारंभ हो गया। 1986 के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1846 हो गई। वार्षिक योजनाओं में उद्योग व खनिज पर 2.06 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

5 चौथी पंचवर्षीय योजना (Fourth Plan) इस योजना में राज्य का तीव्र गति में विकास हुआ। योजनाकाल में वनस्पति तेल सीमेंट फॉस्फोरस कबज सुती धागे मशीन दूसरी चीन और नायलॉन के धागे आदि में सबूद उद्योगों की स्थापना की गई। इस अवधि में विद्युत का अभाव कम रहा लेकिन फिर भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। चतुर्थ योजनाकाल में राज्य की 1065 इकाइयों

को राजस्थान वित्त निगम द्वारा 15.37 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। राज्य सरकार ने इस योजना में भी आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने का क्रम जारी रखा अतः राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया। इन जिलों में रियायतों दरो पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इनमें से 6 जिलों में मन्निडी भी प्रदान की गई। चतुर्थ योजना के प्रारंभ में राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1846 थी जो बढ़कर योजना के अंत में लगभग 2800 हो गई।

6 पांचवी पंचवर्षीय योजना (Fifth Plan) पांचवी योजना काल में औद्योगिक विकास हेतु अनेक उपाय किए गए। मसौ साख-सुविधाएँ, कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति, तकनीकी महाविद्यालय तथा रियायतों दरो पर जल व शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की व्यवस्था की गई। योजनाकाल में उद्योग व खनिज पर 34.53 करोड़ रुपये व्यय किए गए। सांख्यिक क्षेत्र के अंतर्गत साइडिंग मशीन फब्री डोंडवान हाईटेक प्लांट फब्री धौलपुर राजस्थान वूलन मिल्स गोकर्ण बस्टेड वूलन मिल्स, चूर्ण तथा लाइन के विकास पर बल दिया गया। गगानगर शुगर मिल्स का विस्तार किया गया और टाक में नटर टर्न की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र में पांचवी योजना के अवसर्त अनेक विकासोन्मुख कार्य किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में राज्य में केवल 7 सूती वस्त्र निर्माता थे तथा 1967 के अंत तक 3 सीमेंट कारखाने व लैमिन चतुर्थ योजना के अंत में सीमेंट कारखानों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। 1967 तक राज्य में केवल एक वनस्पति मिल भातवाड़ा में था। पांचवी योजनावधि में जयपुर में 4 चिनोडगढ़ में 1 तथा उदयपुर में 1 वनस्पति धागे कारखाने स्थापित किए गए। योजना के अंत तक 1814 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया 13 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया और 252 औद्योगिक क्षेत्र निर्मित किए गए।

7 छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Plan) छठी योजना में उद्योग व खनिज पर 83.66 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय हुआ। योजनाकाल में औद्योगिक विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए जैसे कि इंधन मॉर्निंग मना पावर मसिनी टैस्तिंग इन्सुपुष्ट मसिनी कैपिटल इन्वैस्टमेंट मसिनी डीजल जेनरेटर सैटम खगेटन हेतु मसिनी। गोलू उद्योगों का विकास तथा सहकारी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल उद्योगों का विकास पर बल दिया गया। स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत 1983-84 में 15045 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ। 1984-85 में इस योजना के अंतर्गत 15382 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

इस दृष्टि से इस वर्ष देश में राजस्थान का द्वितीय स्थान रहा। 1984-85 के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1,12,241 हो गई। योजनाकाल में मगमगर व ग्रेनाइट उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इन उद्योगों के अंतर्गत 13 मध्यम श्रेणी की इकाइयों की स्थापना की गई। इस अवधि में उदयपुर, राजसमंद अन्तर किशनगढ़ और आवुरोड में मगमगर व ग्रेनाइट उद्योग का तेजी से विकास हुआ। योजनाकाल में 6 बड़ी इकाइयों की स्थापना की गई। भीलवाड़ा का कस उद्योग की दृष्टि से विकास हुआ और यह राज्य के कस उद्योग का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया।

8 सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Plan) सातवीं पंचवर्षीय योजना में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा पञ्चों पर आधारित औद्योगिक इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक सुविधाएं एवं रियायतों की घोषणा की गई। 1987-88 में दम्नराई की सहायता एक योजना रिफाईंस स्कीम प्राप्त की गई। 1985-90 की अवधि में 35112 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। अतः योजनाकाल के अंत में औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 1 48,353 हो गई जिनमें 5,39 487 व्यक्ति कार्यरत थे। इस समय इन पंजीकृत कारखानों में 761 53 करोड़ रुपये की पूंजी विनिपातित थी। योजनाकाल में वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इस अवधि में स्पिनिंग मिल्स व विधायन गृहों का पर्याप्त विकास हुआ। पावरलूम व्यवसाय किशनगढ़ के अतिरिक्त भीलवाड़ा, गुलाबपुरा अलवर, जयपुर उदयपुर तथा पाली आदि स्थानों पर विस्तृत हो गया। योजनाकाल में 97 बड़ी एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। इनमें से 23 औद्योगिक इकाइया फिवाडी में, 12 उदयपुर में 8 अजमेर में 8 भीलवाड़ा में तथा शेष राज्य के अन्य भागों में स्थापित की गई। उद्योग व खनिज पर इस योजना में 145 57 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

9 1990-92 की वार्षिक योजनाएं (Annual Plans 1990-92) 1990-91 के अंत में छोटे पैमाने की पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1 53,060 थी जिनमें 5 17 लाख व्यक्तियों का रोजगार प्राप्त था और इन इकाइयों में 85 993 लाख रुपये विनियोजित थे। 1990-91 तक 1 13 055 इकाइयों को खादी एवं सामान उद्योग कार्यक्रम व अंतर्गत सहायता प्रदान की गई। ये 2 85,000 व्यक्तियों का अंशित रोजगार उपलब्ध करा रहे थे। इस समय राज्य में 30 000 हेन्डलूम कार्यरत थे जिनमें लगभग 90 000 व्यक्तियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 3197 व्यक्तियों का राजस्थान लघु उद्योग द्वारा प्रायोजित तालीबा प्रशिक्षण

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 1991 तक राज्य में 181 औद्योगिक केंद्रों का विकास किया गया। राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का सबसे सीमेंट, सिंथेटिक यार्न, कागज, स्लाबोडसोल इलैक्ट्रॉनिक्स, ट्रक बेसिन, कॉपर फॉइल्स, टी वी अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स सामान, घड़िया और रसायन से था। राज्य-स्वामित्व की औद्योगिक इकाइयों में सोडियम सल्फेट, नमक व्यापार, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, मोटन स्पिनिंग व चीनी इकाइया प्रमुख हैं। उद्योग व खनिज पर इन योजनाओं में क्रमशः 88-72 व 62 22 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

10 आठवीं पंचवर्षीय योजना (Eighth Plan) आठवीं योजना में उपभोक्ता सामान का विस्तृत स्तर पर उत्पादन करने, राज्य में मरचनात्मक सुविधाओं का पर्याप्त विकास करने, पंजीगत माल की आवश्यकता को पूर्ण करने तथा निर्यातयोग्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने का निश्चय किया गया। राज्य के औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी उद्योग निदेशालय, खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, राजस्थान हथकरघा विकास निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम, ब्यूरो ऑफ स्टेट एन्ट्राइजेज, राजस्थान वित्त निगम तथा रोजो पर है।

राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में मरचनात्मक सुधारों और श्रेष्ठ विनियोग नीतियों के कारण राज्य की औद्योगिक स्थिति का स्वरूप बदल चुका है। वर्तमान में राजस्थान में 515 से अधिक बड़ी और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइया हैं जिनमें लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इसी प्रकार राज्य में 1 84 लाख लघु उद्योग इकाइया कार्यरत हैं जिनमें लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। 8 वीं पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 1032 16 करोड़ रुपये था इसी प्रकार बड़े व मध्यम आकार की इकाइयों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 8983 54 करोड़ रुपये था। इस प्रकार 223 बड़ी व मध्यम इकाइयों और 27468 छोटी इकाइयों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 9995 70 करोड़ रुपये हो गया। राज्य की मुद्रा औद्योगिक स्थिति को देखते हुए निजी उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश के लिये उत्सुक हैं। ऐसे निजी उद्योगपतियों की संख्या 1545 है। जिनमें से 344 ने 8 वीं पंचवर्षीय योजना में अपनी औद्योगिक गतिविधिया प्रारम्भ कर दी हैं। शेष 1201 उद्योगों को 9 वीं योजना में औद्योगिक गतिविधिया प्रारम्भ करने की सलाहना है। इनमें से 602 उद्योगों के औद्योगिक कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुके हैं जिनमें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का विनियोग होगा। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे उद्योगों की

गन्ना में प्रतिवर्ष लगभग 300 की वृद्धि होने की सम्भावना है।

11 नवी पंचवर्षीय योजना (Ninth Plan) नवी पंचवर्षीय योजना में राज्य व दंडे व मध्यम उद्योगों में लगभग 27000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्रों द्वारा विनियोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार नवी योजना में छोट उद्योगों में निजी क्षेत्र का विनियोग लगभग 3000 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार नवी योजना में राज्य की औद्योगिक क्षेत्र में कुल विनियोग 30000 करोड़ रुपये होगा जो 8 वी पंचवर्षीय योजना के विनियोग का 3 गुना से भी अधिक है।

नवी योजना में औद्योगिक विकास की व्यवस्था रचना

राज्य का नवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की निम्न व्यवस्था रचना अपनाने का निश्चय किया गया -

- 1 राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत भाग निर्माण भद्र में प्राप्त करना।
- 2 राजस्व व अतिरिक्त एवं पर्याप्त अवसर सृजित करना।
- 3 राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग का वातावरण निर्मित करना।
- 4 राज्य की आय एवं सम्पत्ति में वृद्धि करना।
- 5 राज्य के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।
- 6 राज्य के उद्योगों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि करना ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि में प्रतिस्पर्धी बन सकें।
- 7 राज्य की औद्योगिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिये समाज का सहयोग प्राप्त करना।
- 8 मानवीय सम्पत्ति का विकास पर बल देना।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं

POSSIBILITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान के उद्योगों में समस्त अनेक सम्भावनाएं विद्यमान हैं। हुए भी भविष्य में राजस्थान के औद्योगिक विकास की अच्छी सम्भावनाएं विद्यमान हैं। राजस्थान में औद्योगिकीकरण की दृष्टि में निर्माणित तथा महत्वपूर्ण है।

1 खनिज (Minerals) खनिज उत्पादन में राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान 8 धात्विक व 25 अधात्विक खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जस्ता, सोडा, टंगस्टन, चादी तांबा गैक फॉस्फेट, चूना, पत्थर, फेल्टगार, एस्बेस्टोस, कैल्साइट, गारनेट, जिप्सम, सोप स्टोन, ग्रेनाइट, गमगमर व अन्य इमारती पत्थर की दृष्टि से राजस्थान महत्वपूर्ण राज्य है। देश में उत्पादित जस्ता, सोडा, एमर्गल, गैक फॉस्फेट का लगभग शत प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में ही होता है। भारत के कुल सोपस्टोन व जिप्सम का 90 प्रतिशत एस्बेस्टोस का 83 प्रतिशत फेल्टगार का 76 प्रतिशत व चादी का 94.5 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में ही प्राप्त होता है।

2 पशुधन (Animal Wealth) पशु सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की आय का 15 प्रतिशत भाग पशु-सम्पदा से ही प्राप्त होता है। देश के दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी अधिक भाग राज्य के पशुओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। देश में मांस उत्पादन का 30 प्रतिशत और ऊन उत्पादन का 40 प्रतिशत राजस्थान के पशुओं द्वारा प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त, राज्य के पशुओं में चमड़ा व हड्डी आदि वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। पशुओं से प्राप्त वस्तुएं कच्चे रूप में देश के अन्य राज्यों का भेज दी जाती हैं। अब राज्य में पशुओं पर आधारित उद्योगों की स्थापना की पर्याप्त सम्भावना है।

3 कृषि फसले (Agricultural Crops) राजस्थान नहर और अन्य वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं व कुओं व व्यापक विद्युतीकरण से खाने की व व्यावसायिक फसलों का अधिक उत्पादन सम्भव हो सकेगा। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1950-51 में राजस्थान में 33.8 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था जो 1997-98 में बढ़कर अनुमानित 128.55 लाख टन हो गया।

4 वन-सम्पदा (Forests) वन सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। वनों से अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। राज्य में इन वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों का अभाव है। अब राज्य के विभिन्न भागों विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में वन आधारित उद्योगों की स्थापना की पर्याप्त सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

5 कुशल श्रमिक (Skilled Labour) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक परम्परागत रूप में उपलब्ध है, उदाहरणार्थ, जयपुर सागानर व बाडमेर में गार्ड उपाई मोहर, जयपुर, जोधपुर आदि में वस्त्र

9	टैक्स	15172	15593
10	बस एव निग बड	38764	40233
11	टैक एव अन्य मानन दोने कने वएन (लाउड)	1 13	1 66
12	अन्य	2945	2962
योग		2127494	2199799

Source: Economic Review 1998-99 Govt of Raj

उपलब्ध जिलेवार आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक वाहन जयपुर जिले में हैं। इसके पश्चात हमेशा जोधपुर, कोटा गणानगर, उदयपुर, अजमेर व अलवर का स्थान है।

5 सड़क दुर्घटना (Road Accidents) - राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या वाहनों की संख्या के साथ-साथ निरन्तर बढ़ती जा रही है। राजस्थान में सड़क दुर्घटना की स्थिति अग्र तालिका में स्पष्ट है¹

वर्ष	दुर्घटनाएँ	मृत व्यक्ति	घायल व्यक्ति
1993	12757	3893	15325
1994	13920	4129	16756
1995	16610	4863	20432
1996	18891	5430	24214

Source: Statistical Abstract 1996 Rajasthan

राजस्थान में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएँ जयपुर जिले में हुईं, इसके पश्चात अजमेर और कोटा का स्थान है।

6 सड़क नीति (Road Policy) - सड़कों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 1994 में सड़क नीति की घोषणा की गई है जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-

(i) 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 या इससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो टी सड़कों से जोड़ना।

(ii) 1981 एवं 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 या अधिक आबादी वाले ग्रामों को नवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सड़कों से जोड़ना।

(iii) नवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी पंचायत मुख्यालयों को दो टी सड़कों से जोड़ना।

(iv) ऐसे सभी जनजाति/मरुस्थल क्षेत्र के ग्राम जिनकी जनसंख्या 750 से अधिक है वो नवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो टी सड़कों से जोड़ना।

(v) मुख्य शहरी केन्द्रों का ढाई घाम निर्माण।

(vi) राज्य उच्च मार्ग (हाइवे) एवं जिला मार्गों को चौड़ा करना।

(vii) राज्य उच्च मार्गों पर अन्तर्राष्ट्रीय सड़कों, मिसिा लिक्म एव सी डी वर्क्स का निर्माण।

सड़क निर्माण के उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में क्रियान्वित विभिन्न विकास योजनाओं जैसे जवाहर रोडगार योजना, रोडगार ग्राम्पटी योजना, तीस त्रिले तीम काम आदि में उपलब्ध वित्तीय मसाधनों का उपयोग भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य पुलों, सुरगों एवं ढाई घाम आदि के निर्माण हेतु वित्तीय मसाधनों एवं निजी वित्तियोजकों का भी सहयोग लिखा जायेगा। इस कार्य में लगी पूँजी की वसूली टोल टैक्स के माध्यम से की जाएगी। विश्व बैंक सहयता कार्यक्रम के अन्तर्गत चार राज्य उच्च मार्गों को चौड़ा करने एवं उनका टर्जा बढाने का कार्य भी श्रुति पर है।

सड़क विकास का मास्टर प्लान (1981-2001)

सड़क विकास के मास्टर प्लान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं -

1 राज्य के पचास मुख्यस्थलों को सड़क मार्गों से जोड़ना।

2 दो मार्ग वाली सड़कों का निर्माण करना।

3 एक हजार और इससे अधिक बनमख्या (1971 की जनगणना के अनुसार) वाले ग्रामों को सड़क मार्गों से जोड़ना।

4 अन्तर्राष्ट्रीय सड़क के बनना।

5 जिला सड़कों पर पुल बनाना।

6 धार्मिक स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ना।

7 पर्यटन की दृष्टि से सड़कों का निर्माण करना।

8 रेलवे स्टेशनों को सड़क मार्ग से जोड़ना।

9 खनन-मंडलों का निर्माण करना।

10 मण्डियों को सड़क मार्गों से जोड़ना।

11 औद्योगिक केन्द्रों को सड़क मार्गों से जोड़ना।

राजस्थान में सड़क क्षेत्र के सुधार²

सड़क तन्त्र के श्रुत प्रवर्धन, अतिव्रम्भा रोकने एवं उच्च मार्ग के माध-साध पद्धिध विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान हाइवे अधिनियम, 1994 पुरति किया गया है। सड़कों के विकास हेतु घन चो अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया गे लुडशे एवं बैंक से मस्यागत वित्त प्राप्त करने की व्यवस्था की है। पुलों, सुरगों एवं ढाई घामों के लिए अतिरिक्त दृष्टि से उनयोगे परिपोरनाये बनाने उन्हे विनियम मन्त्रालो के सन्ध कर पुरति हेतु रखा गया है। सड़क परिपोरनाओं के निम्ना हेतु सड़क मनी उपलब्ध करने

के उद्देश्य में राज्य में एक स्टेट रोड इम्प्यूवमेंट फण्ड बनाया गया है। टोल टैक्स के रूप में प्राप्त धन राशि को इस बोध में जमा कर फिर इस राशि को इस बोध द्वारा मीड मनी के रूप में सड़क परियोजनाओं के निर्माण के काम में लिया जाएगा।

नवी योजना में सड़क विकास

राज्य की नवी योजना में सड़क विकास हेतु 1353 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। राज्य में 1996-97 में कुल सड़क मार्गों की लम्बाई 74229 किलोमीटर थी जो बढ़कर नवी योजना के अन्त में 94229 किलोमीटर हो जायेगी। अतः योजना काल में 20,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

इस निगम की स्थापना 1964 में की गई। निगम के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं - (i) राजस्थान में सड़क परिवहन का विकास करके राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करना। (ii) परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना। (iii) राज्य में सड़क परिवहन का विस्तार करना और सड़क परिवहन सेवा का कुरानता पूर्वक संचालित करना।

राजस्थान में रेल परिवहन

रेल की लाइनें मात्र लौह पट्टिका नहीं हैं अपितु विकास के वर्तमान मटर्गों में ये हमारे जीवन रेखाएँ हैं। जहाँ-जहाँ स जीवन रेखाएँ गुजरी, उन्हीं क्षण और अर्थराज्य के साथ-साथ निवासियों का भाग्य ही बदल गया। वहाँ के जन जीवन को जीने की सजीवनी मिली और इन भाग्य रेखाओं में जुड़े गाँव, कस्बे और शहर विकास की नई हलचल में आनन्दित हो उठे। इतिहास इस बात का गवाह है कि धरती के जिस हिस्से की हलचल पर स पीतलदा भाय रेखाएँ छाँगी गई, वहाँ के बेरोजगार हाथा का राजगार का दस्तक मिला विकास की धींगें रेखाएँ भी प्रकाश की प्रशन्न भाग्य बन गई और वह रोशनी विनाशकारी शक्तिविशियों का मगन बन गया। इन निर्जीव पट्टियों पर दल-आध्यात्म विनाश के पहिले टोड़ने लग और इनमें जुड़ा छोटा सा गाँव कस्बों के, कस्बा शहर के और राज्य महानगर के रूप में अगड़ाई लेने लगा।

राजस्थान में रेल परिवहन का इतिहास

राजस्थान में रेल विकास की प्रक्रिया 1842 ई में प्रारम्भ हुई। अंग्रेज सरकार एवं देशी रिगामतों के मध्य वानचित के कारण रेल विवरस का कार्य धीमा रहा। राज्य में प्रथम मीटर गेज रेलवे लाइन 14 फरवरी, 1873 को दिल्ली में रेवाड़ी एवं फारूकनगर के बीच राजपूत रेलवे के रूप में प्रारम्भ की गई। अजमेर में मीटर गेज लाइन मार्ग अगस्त, 1875 को, अजमेर, ब्यावर राजपूताना लाइन 15 मई, 1878 को एवं ब्यावर-हर्गपुर-सोजत रेलमार्ग पर कार्य शुरू किया गया। राजपूताना रेलवे के दक्षिणी भाग में अहमदाबाद - पलनपुर मार्ग 15 नवम्बर, 1879 को खोला गया। जोधपुर रेलवे के अन्धीन छत्रवी-यासी 20 मील रेल निर्माण का कार्य 16 फरवरी, 1881 को शुरू हुआ तथा 28 फरवरी, 1882 को पूरा कर लिया गया। 24 जून, 1982 को यह मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया।

जून, 1884 में 25 मील लम्बे फली लूनी मार्ग पर यातायात शुरू हो गया। 9 मार्च, 1885 को जोधपुर शहर रेल से जुड़ गया। जोधपुर-मेड़ता गेड रेलमार्ग को 8 अप्रैल, 1891 तथा नागौर-बीरमेर 72 मील रेलमार्ग को 9 दिसम्बर 1891 को प्रारम्भ कर दिया गया। जोधपुर दरवार में मेड़ता रोड से कुचामन रोड तक 73 मील लम्बी लाइन का निर्माण करवाया। इसे 13 मार्च, 1893 को यातायात के लिए खोल दिया गया। बीरमेर-दुनमेर 42 मील लम्बी रेलमार्ग 2 जून, 1896 को, दुनमेर-सुरतगढ़ 72 मील रेलमार्ग 1 जनवरी, 1901 को तथा सुरतगढ़ भटिण्डा 88 मील रेलमार्ग 9 सितम्बर, 1902 को यातायात के लिए प्रारम्भ कर दिया गया। जोधपुर दरवार तक बालोतग-बादमेर 60 मील रेलमार्ग 15 मई, 1899 को तथा बादमेर-साडीपल्ली 143 मार्ग को 2 दिसम्बर, 1900 को यातायात के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार स्वतन्त्रता के पूर्व राज्य में रेल परिवहन का पर्याप्त विस्तार हुआ। अप्रैल 1950 में जोधपुर रेलवे का प्रथम राजस्थान सरकार का हस्तान्तरित कर दिया गया। इसे 14 अप्रैल 1952 को उन्नी रेलवे में सम्मिलित कर दिया गया।

राजस्थान में रेल परिवहन की वर्तमान स्थिति

(1) रेलमार्ग - राज्य में रेलमार्ग का तेजो से विकास हुआ है राज्य के अनेक स्थानों पर छोटी रेलवे लाइनें की बड़ी लाइनें में बदलने का कार्य चल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की, मुम्बई, दिल्ली एवं कच्छतल से जोड़ दिया गया है तथा जापुर और बीरमेर भी बड़ी लाइन में जुड़ चुके हैं। अप्रैल 1952 में राज्य में रेलमार्गों का निर्मित का दर्शाया गया है -

राजस्थान में रेलमार्ग

ग्रेज	रेलमार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)	
	1990-91	1993-94
1 ग्रांड गेज	1235 37	1950 04
2 मीटर गेज	4505 52	3773 57
3 नैरव गेज	86 51	84 45

स्रोत: Statistical Abstract, Rajasthan 1994

(2) भारतपुर मिमको लिमिटेड - यह कम्पनी 31 जनवरी, 1957 को भारतपुर में प्रारम्भ की गई। यह कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 3000 मालवाहन डिब्बों का निर्माण करती है यह मालवाहक डिब्बों की लगभग एक-तिहाई भाग पूरी करती है।

(3) रेल बस - राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच 12 अक्तूबर, 1994 को देश की पहली डॉड गेज रेल-बस सेवा प्रारम्भ हुई। इस रेल बस में 71 यात्री बैठकर तथा 15 खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। इस रेल बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घण्टा है।

(4) जयपुर-मियालदाह एक्सप्रेस - 3 जुलाई, 1994 को जयपुर-मियालदाह एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया गया। यह प्रतिदिन दुर्गापुर, सवाईमाधोपुर, आगड़-किला, टुडला, बनपुर, इगहावाद गुलसराय और पटना होते हुई 36 घण्टों में अपना यात्रा पूरी करती है।

इसमें राजस्थान के प्रवासी उद्यमियों का राज्य में उद्योग लगान के प्रति विश्वास बढ़ेगा और परिवहन की सुविधा के विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास में भी भरोसा मिलेगा।

(5) आठवीं पंचवर्षीय योजना में परिवहन विकास - वार्दीकुई-आगरा तक बड़ी लाइन का कार्य आठवीं योजना में पूरा कर लिया जावेगा। वर्ष 1994-95 में मीटर गेज का बड़ी लाइन में बदलने के कार्यक्रम में जोधपुर-जैसलमेर के लिए 109 करोड़ रुपए, फुलेर-मारवाड-अहमदाबाद-मेहमाणा के लिए 92 करोड़ रुपए, लुनी-मारवाड के लिए 30 करोड़ रुपए, सवाई-माधोपुर-जयपुर फुलेरा के लिए 26 करोड़ रुपए, जोधपुर-कोशनगर-मेड़ता के लिए 8 करोड़ रुपए तथा मथुग-अलवर नई बड़ी रेल लाइन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

राजस्थान में मीटर रेल लाइन से

बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन

1991-92	1994-95
मुर्गाट-पट्टा 111 कि मी	फुलेरा अजमेर-81 कि मी
मुर्गाट-अजमेर 78 कि मी	रेकड़ी बरपुर 225 कि मी
मुर्गाट-बनपुर 178 कि मी	जोधपुर जैसलमेर 295 कि मी
1992-94	1995-96
लुनी-मारवाड रोड 177 कि मी	अजमेर मरवाड 140 कि मी
नाराज-गुलसराय 45 कि मी	मरवाड-मेड़ता 203 कि मी
नई बरपुर-जयपुर 125 कि मी	जयपुर-जोधपुर 113 कि मी

जयपुर फुलेरा-55 कि मी	नवी पंचवर्षीय योजना
फुलेरा-जोधपुर-254 कि मी	लुनी-मारवाड-297 कि मी
मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी-14 कि मी	सुखाद-दुर्गमनाद (विना-ल-लुनी) - 205 कि मी

स्रोत: राजस्थान नवस

(6) राजस्थान में नई रेल लाइनें - स्वतंत्रता के पश्चात, राजस्थान राज्य में नवीन रेलमार्गों के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रहा। राज्य में 1947 की अवधि में मात्र गी खेराटा (1947-48), खेराटा-कागोड (1948-49), सांगर-राणी (1949-50), कागोड-बड़ो सादडी (1949-50), पार्नाडिंग्गी (1950-51), डिग्गी-टोडा रायसिंह (1953-54), फनेहपुर-बुरू (1956-57), रानीवाडा-भीलडी (1957-58), उदयपुर-उदयपुर सिटी (1961-62) उदयपुर टिम्पनार (1965-66) प्रकरन-जैसलमेर (1966-67), फिन्टमलकोट-श्रीगंगानगर (1969-70), डाबला-सिधना (1974-75) कोटा-नन्दरिया (1988-89), चन्देरिया-चिन्ताडगड (1989-90), चित्तौडगढ़-नैमव (1990-91), मथुग-डाग (1992-93), तथा डोंग-अलवर (1993-94) नवीन रेलमार्ग बनाये गये।

(7) अजमेर का रेलवे वर्कशॉप - इस वर्कशॉप का निर्माण 1877 में प्रारम्भ हुआ जो सन् 1879 के अन्त तक पूरा हो गया। यहाँ इजनों, भास डिब्बों और सवारी डिब्बों की सभी प्रकार की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य किया जान लगा। 1881 में भण्डार विभाग तथा 1884 में माल डिब्बों और सवारी डिब्बों को अलग किया गया। 1885 में नुहगी कार्य, चक्का (Wheel) तथा दाबनर शाप की आग में कार्यशालाएँ स्थापित की गईं। यह भारत का एक मात्र रेलवे वर्कशॉप है जहाँ इजने बनते हैं। 1937 तक यहाँ 375 रेल इजनों का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी इस मरम्मत एवं नवीनीकरण की दृष्टि से रेलवे वर्कशॉप, अजमेर का महत्वपूर्ण स्थान है।

(8) रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर - इस स्कूल का शिफ्टनाम 25 मार्च 1955 को महामाणा भूपल सिंह ने दिया तथा 9 अक्तूबर 1956 का तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। यह स्कूल न केवला पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों का प्रशिक्षण देता है वन् अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों और विदेशी रेल कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। 1993-94 में 5713 देशों तथा 246 विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(9) बच्चों की रेल - यह रेल उदयपुर में है इसका संचालन गंगा चन्द्र उदयपुर द्वारा किया जाता है। इस रेल

का कार्य 5 मई, 1972 को प्रारम्भ हुआ और 8 अप्रैल, 1973 को भारत सरकार के तत्कालीन रेलमंत्री बाबू जगजीवन राम ने इसका उद्घाटन किया। इस रेलमार्ग की लम्बाई 179 कि.मी. है। यह रेल गुलार बाग में बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख माध्यम है।

(10) धौलपुर की नेरो गेज रेल - धौलपुर जिले में यह रेल लाइन धौलपुर से जाड़ी होते हुए आगरा जिले के तातपुर तक तथा इसदा धौलपुर में सरमयुता तक जाती है इस क्षेत्र क लोग इसे डी बी आर कहते है यह राजस्थान की एक मात्र नेरो गेज लाइन है। इस रेल लाइन का निर्माण 1908 (धौलपुर रियासत के महाराजा रामसिंह के शासनकाल में) प्रारम्भ हुआ और 1929 में पूर्ण हो गया। अभी तक इस रेल के मौलिक स्वरूप एवं संचालन में परिवर्तन नहीं आया है।

(11) कोटा-चित्तौड़-नीमच रेलमार्ग - कोटा चित्तौड़-नीमच बड़ी रेल लाइन के निर्माण से राजस्थान में प्रगति का एक और मार्ग खुल गया। इस रेलमार्ग पर 30 मार्च, 1968 से ही मालगाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया तथा अक्टूबर, 1989 में पहली बार सवारी गाड़ी चली। राजस्थान के कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में होकर यह लाइन मध्यप्रदेश में नीमच तक जाती है। इस रेल मार्ग में सोमेश्वर, कांयला, इमारती पत्थर और अन्य वस्तुओं की सप्लाई में सुविधा हो गई। यह रेल मार्ग चित्तौड़गढ़ जिले के पिछड़े इलाकों के लिए धरदान सिद्ध हुई है।

(12) पैलेस ऑन व्हील्स अथवा पहियों पर राजमहल - यह रेल 1982 में प्रारम्भ हुई। इसका निर्माण पुरानी रियासतों के शासकों द्वारा उपयोग में लाये गए विभिन्न रेलों के डिब्बों से किया गया। इसकी लोकप्रियता के कारण 1991 में नवीं पैलेस ऑन व्हील्स का निर्माण किया गया। इस रेल की लागत लगभग ॥ करोड़ रुपए आई। यह रेल प्रत्येक बुधवार को दिल्ली में रवाना होकर जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए पुन बुधवार की प्रात दिल्ली पहुँचती थी। लेकिन सितम्बर, 1994 में यह आगरा-भरतपुर के स्थान पर बीकानेर जाने लगी है और इसमें 13 डिब्बे हैं। इस रेल में प्रायः सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(13) प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग - राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग की लम्बाई 17.02 किलोमीटर है। इस दृष्टि से राजस्थान का भारत में 12 वा स्थान है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा राज्यों का है। प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्गों का अखिल भारतीय औसत 19.00 कि.मी. है। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान में रेलों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है।

(14) नया रेल क्षेत्र - 1996-97 के केन्द्रीय बजट में 6 नये रेल क्षेत्रों की स्थापना की गई, जिनमें उत्तर पश्चिम रेल्वे भी एक है। इसका मुख्यालय जयपुर को बनाया गया है।

राजस्थान के प्रमुख रेलमार्ग

राज्य के प्रमुख रेलमार्ग निम्नलिखित हैं -

(1) दिल्ली-अहमदाबाद रेलमार्ग यह रेलमार्ग राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर तथा आबू रोड आदि नगरीय से होकर गुजरता है। यह एक व्यस्त रेलमार्ग है। इस मार्ग का अरब बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जा रहा है।

(2) बीकानेर-दिल्ली रेलमार्ग यह रेलमार्ग बीकानेर में आरम्भ होकर चुरू, लोहावत होता हुआ दिल्ली पहुँचता है।

(3) जोधपुर-दिल्ली रेलमार्ग यह रेलमार्ग जोधपुर, फुलेरा, रिंगस होता हुआ दिल्ली जाता है।

(4) अजमेर-खण्डवा रेलमार्ग यह रेलमार्ग अजमेर से आरम्भ होकर नसीरवादा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेडा व इन्दौर होता हुआ खण्डवा पहुँचता है।

(5) जोधपुर-आगरा रेलमार्ग यह रेलमार्ग जोधपुर से फुलेरा, जयपुर, बादीकुई तथा भरतपुर होता हुआ आगरा पहुँचता है।

(6) कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच रेलमार्ग - यह रेलमार्ग कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों से होकर मध्य प्रदेश में नीमच तक जाता है।

राज्य में भीलवाड़ा-केकडी-टोडा रेलमार्ग का सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त (i) अजमेर कोटा रेलमार्ग (ii) वाडमेर-जैसलमेर रेलमार्ग (iii) फालन-बड़ी सादडी रेलमार्ग तथा (iv) रतलाम बासवाड़ा-डुंगरपुर रेलमार्ग के निर्माण की योजनाएँ विचाराधीन हैं।

राजस्थान में रेल परिवहन की समस्याएँ

गर्हण रेलों के माध्यम से राजस्थान देश के सभी प्रमुख नगरों से जुड़ चुका है किन्तु कुछ ऐसे जिले हैं जो इस सेवा से नती जुड़ पाय है। राज्य में रेलों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं

(i) राजस्थान का अधिकांश भू-भाग शीतमानी एवं पहाडी है। समतल क्षेत्र एवं मैदानों का अभाव। अतः रेलमार्गों का

निर्माण करना कठिन होता है। रेलमार्गों के निर्माण की लागत भी अधिक आती है।

(ii) राज्य के पूर्वी भाग में प्रायः वर्षा ऋतु में रेलमार्ग जल में डूब जाते हैं अतः रेल यातायात अवरोध हो जाता है। रंगितानी क्षेत्र में रेलमार्ग बालू मिट्टी के कारण अवरोध हो जाते हैं।

(iii) रेल दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की हानि होती है। इसका क्षणिक रेल व्यवस्था पर आर्थिक एवं प्रशासनिक

दोनों ही प्रकार से पड़ता है।

(iv) राज्य में रेलमार्गों की लम्बाई आवश्यकता से बहुत कम है। रेलमार्गों की लम्बाई की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 12 वा स्थान है।

(v) राज्य में रेलमार्गों के वितरण में असमानता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम रेलमार्ग है जबकि पूर्वी मैदानी भागों में रेलमार्गों का विस्तार अधिक हुआ है। पहाड़ी जिलों में भी रेलों का विकास नहीं हुआ है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A सक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 चम्बल घाट परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Chambal Valley Project
- 2 राजस्थान नहर या इन्दिरा गांधी नहर पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Rajasthan Canal or Indira Gandhi Canal
- 3 इन्दिरा गांधी नहर में मिलने वाले सम्भावित लाभ का वर्णन कीजिए।
Explain the possible gains out of Indira Gandhi Canal
- 4 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का सम्भावित कमान्ड क्षेत्र किन्तु है?
What is the expected command area of Indira Gandhi Canal Project?
- 5 "इन्दिरा गांधी नहर दलसना अधिदत्ताओं का समय पावन्द-कारक व मध्य सुपुर्द कर दा जानी चाहिए" क्या?
"Indira Gandhi Canal should be handed over to military engineers with a timebound programme" Why?
- 6 अणुशक्ति क्या है? तथा ऊर्जा में यह किस प्रकार भिन्न है?
What is Nuclear Power? How does it differ from Thermal Power?
- 7 राजस्थान में ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की व्याख्या कीजिए।
Explain Solar Energy as a good source of energy in Rajasthan
- 8 राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत के रूप में बायो गैस की व्याख्या कीजिए।
Explain Bio-Gas as a good source of energy in the rural areas of Rajasthan
- 9 राजस्थान में कहा-कहा बिजुत उत्पादन हो रहा है?
Where are the sources of power located in Rajasthan?
- 10 वर्तमानक ऊर्जा स्रोतों का आलोचनात्मक विवरण कीजिए।
Examine critically the alternative sources of energy

B निव्यासक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 चम्बल घाट परियोजना का एक विवरण दीजिए। इसमें राजस्थान को क्या आर्थिक लाभ है?
Give an account of the Chambal Valley Project. What are its economic benefits to Rajasthan?
- 2 राजस्थान नहर परियोजना का विवरण दीजिए। इसका क्या आर्थिक लाभ है? व्याख्या कीजिए।
Give details of Rajasthan (Indira Gandhi) Canal Project. What are its economic achievements? Explain
- 3 राजस्थान में आणविक, सौर तथा बायो गैस के विकास के लिए किए गए विभिन्न विकास परियोजनाओं की व्याख्या कीजिए।
Discuss the development of Atomic, Power and Road in the light of infrastructural development in Rajasthan

- 4 राजस्थान में आधारभूत आर्थिक संरचना के विकास के लिए बिजली बिदुत के विकास पर प्रकाश डालिए।
Discuss the development of Power in the light of Infrastructural Development in Rajasthan
- 5 राजस्थान राज्य के अर्थ संरचना विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on the structure facilities of the State of Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान नहर परियोजना के क्या उद्देश्य हैं? इसके प्रमुख बर्णन क्या हैं? राजस्थान का इससे क्या लाभ होगा?
What are the objects of Rajasthan (Indira Gandhi) Canal Project? What are the salient features? What will be its utility for the economic development of Rajasthan
- 2 योजनाकाल में राजस्थान में सिंचाई संभावना के विकास पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on the development of irrigation potential in the plan-era in Rajasthan
- 3 राजस्थान में ऊर्जा तथा सड़कों के विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Critically analyse the development of Roads and Power sectors in Rajasthan
- 4 इन्दिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान के लिए वादण्ड सिद्ध होगी।" समझाइए।
Indira Gandhi Nahr will be a blessing for Western Rajasthan " Discuss
- 5 "राजस्थान में अर्थ संरचना का विकास अभी शिशु अवस्था में है।" विवेचना कीजिए।
"Infra structural facilities in Rajasthan is in its infant stage," Discuss



राजस्थान में औद्योगिक विकास

एवं उद्योग

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INDUSTRIES IN RAJASTHAN

"प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही राजस्थान औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में प्रवेश कर गया।"

अध्याय एक दृष्टि में

- औद्योगीकरण का अर्थ
- राजस्थान में आय एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगीकरण का महत्व
- राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएं
- राजस्थान में औद्योगिक विकास
- राजस्थान में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं
- राजस्थान में उद्योगों का क्षेत्रीय वितरण/पैलाव/असमानताएं
- राजस्थान में औद्योगिक विकास की ज़रूरतें/क्षेत्रीय असमानताएं
- राजस्थान के वृहत् उद्योग
- राजस्थान में खनिज क्षेत्र के उद्योग
- अन्वयार्थ प्रश्न

औद्योगीकरण का अर्थ

MEANING OF INDUSTRIALIZATION

औद्योगीकरण का सम्बन्ध उद्योग से लगाया जाता है। उद्योग से आशय किसी वस्तु अथवा सेवा के निर्माण से होता है परन्तु मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण अथवा मृज्जन नहीं कर सकता है। मानव केवल किसी वस्तु को रूप उपयोगिता में वृद्धि करके उसे अधिक उपयोगी बना सकता है। मानव जब इस प्रक्रिया को व्यापक रूप प्रदान कर देता है तो औद्योगीकरण की सज्ञा प्रदान की जाती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से औद्योगीकरण की तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उदाहरण के लिए, चमड़ा राना गेहूँ पोसना सूत कलना आदि। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत कच्चे माल के रूप में परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है, उदाहरण के लिए जूते बनाना, भोजन तैयार करना कपड़ा व फर्नीचर बनाना आदि। तृतीय अवस्था के अन्तर्गत ऐसी मशीनों एवं प्लांटों यंत्रों के निर्माण को सम्मिलित किया जाता है या भावों उत्पादन किया जाये अधिक सुविधाजनक बनाने हैं। औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण उत्पादन कार्यों में परिवर्तन को एक श्रृंखला का जन्म होता है। औद्योगीकरण में

उन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी प्रतिष्ठान के यंत्रीकरण, किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी नवीन बाजार में प्रवेश एवं किसी नवीन क्षेत्र के विदोहन के कारण घटित होते हैं। हॉफमैन के अनुसार औद्योगीकरण की अवस्थाओं के क्रम में औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में उन-भोग वस्तु उद्योगों का सर्वाधिक महत्व रहता है और शुद्ध उत्पादन पूँजी वस्तु उद्योगों के उत्पादन में पाच गुना होता है। द्वितीय अवस्था में यह अनुपात 2.5:1 हो जाता है और तीसरी अवस्था में यह केवल 1:1 हो जाता है। इस प्रकार औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत पूँजी का महत्वमय उपयोग करके यंत्रीकरण एवं बड़े पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान अनेक छोटी-छोटी रियासतों में विभक्त था। उस समय यह राज्य औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य का पुनर्गठन हो गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही राजस्थान औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में प्रवेश कर गया। प्रथम योजना में तत्कालीन समस्याओं व परिस्थितियों के कारण राज्य का औद्योगीकरण तीव्र गति में नहीं हो पाया लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना से राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। राजस्थान में अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में राज्य का औद्योगिक विकास अधिक नहीं हो पाया है। यहाँ औद्योगिक विकास की पर्याप्त सभाजनाएँ विद्यमान हैं अतः राजस्थान में उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन, निर्यातों-मुखी इकाइयों का स्थापना और विशेष रूप से विद्युत शक्ति के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य में टेक्सटाइल चीनी मोनेन्ट, ग्लास सोडियम कीटनाशक कास्टिक सोडा और औद्योगिक रसायन, जैम उद्योग आदर्श रूप में स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों को पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उद्योगों की स्थापना का प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान में निर्यात सब्सिडी क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य में औद्योगीकरण का समुचित ढांचा विद्यमान है। यहाँ प्रायः सभी प्रकार की अनुकूलनाएँ भी विद्यमान हैं। अतः राज्य के अनेक क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। जयपुर हवाई अड्डा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं व निर्यात में सुविधा होगी। यह हवाई अड्डा दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद का सहकर्मक भी हो सकता है। राज्य में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करके तथा कार्योदिवसों में वृद्धि करके राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में आ सकता है। इसके लिए प्रबंधकों को अग्रशक्ति सहित ईश्वर शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार

दिया जाना चाहिए। इससे विदेशी निवेश को आकर्षित होने की सम्भावना भी बढ़ जाएगी। राज्य में जिस प्रकार के प्राकृतिक शोध विद्यमान हैं उन्हें देखते हुए यह देश के ही नहीं बल्कि विदेश के उद्योगपतियों को भी आकर्षित करने में सक्षम है।

व्यापार एवं उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आर्थिक नीति में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए श्रम कानूनों में भी सुधार किया जाना चाहिए। भारत सरकार की तरह राज्यस्तर पर भी औद्योगिक नीति में उदामंकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोकें राजस्थान वित्त निगम उद्योग निदेशालय तथा ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रयासों में राज्य में औद्योगिक निवेश के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पैट्रोकेमिकल क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी म्यिक ने राजस्थान में 70 करोड़ रुपये की लागत में फूड प्रेड फॉस्फोरिक एमिड संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य में रॉक फॉस्फेट के प्रचुर भण्डार उपलब्ध हैं। अतः इस कम्पनी के भावी विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इसी प्रकार कार्बोरण्डम यूनिवर्सल लिमिटेड ने राजस्थान में 100 करोड़ रुपये की लागत की रिफ़ेक्टरी इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रमुख कपड़ा उत्पादक विन्नी लिमिटेड ने भी सीमेन्ट क्षेत्र में प्रवेश की इच्छा प्रकट की है। यह कम्पनी राजस्थान में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक सीमेन्ट कारखाना स्थापित करना चाहती है। मद्रासी सीमेन्ट लिमिटेड ने भी राजस्थान में 350 करोड़ रुपये की लागत से पोर्टलैण्ड सीमेन्ट उत्पादन की एक परियोजना बनाई है। तृतीकोरन अल्कालिज भी राजस्थान में 500 करोड़ रुपये की लागत का एक सोडा-शेरा कारखाना स्थापित करना चाहती है। इसके अतिरिक्त अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी राज्य में अपने उद्योग स्थापित करना चाहती हैं। राजस्थान में औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं महत्व को अग्रलिखित बिन्दुओं के तहत स्पष्ट किया जा सकता है।

राजस्थान में आय एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगीकरण का महत्व

IMPORTANCE OF INDUSTRIALIZATION FROM INCOME & EMPLOYMENT POINT OF VIEW

1. उद्योगों का कुल राजस्थानीय आय में भाग Contribution of Industries in GDP of Rajasthan

राज्य की अधिकांश आय कृषि व उसमें मन्थित कार्यों में होती है। राजस्थानीय आय में उद्योगों का भाग क्षीण क्षेत्र

कैथून में कोटा डोरिया, नागौर में हाथ के औजार तथा बीगोट व डींग आदि में लुहारों उद्योग के कुशल दमनकार व श्रमिक उपलब्ध है।

6 अनुकूल औद्योगिक नीति (Favourable Industrial Policy): राज्य के औद्योगिक विकास के इतिहास में 1990 की नई औद्योगिक नीति निर्विरोध सिद्ध हो रही है। इस नीति में आर्थिक, गैर-आर्थिक के अवसर बढ़ाने, समुचित क्षेत्रीय विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार की औद्योगिक नीति, 1991 को ध्यान में रखकर कार्यप्रणाली को सरल एवं उदार बनाया है। 50 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने तथा वितरित करने के अधिकार त्रिस्रोत तक दिए गए हैं। इससे अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए राज्यस्तरीय समिति में अनुमति लेने की दायिबा समाप्त कर दी गई है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-आवरण हेतु एक लाज-डोड जारी करने के अधिकार जिला उद्योग केंद्र को दिए गए हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास की गतिविधियां तीव्र हुई हैं।

7 मानव-सम्पदा (Human Wealth) राजस्थान की जनसंख्या 4.4 करोड़ है। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय भी देश के अनेक राज्यों को तुलना में अधिक है। अतः औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य में पर्याप्त श्रमशक्ति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त राज्य की जनशक्ति विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के लिए पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करने में भी सक्षम है।

8 बृहद् क्षेत्रफल (Large Area) राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,214 वर्ग किलोमीटर है जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 11 प्रतिशत है और क्षेत्रफल का दृष्टि से मध्यप्रदेश के पश्चात् इसका द्वितीय स्थान है। अनुभव यह दर्शाता है कि विस्तृत क्षेत्रफल विस्तृत संभावनाओं का जनक है।

9 पर्याप्त पूंजी (Sufficient Capital) राजस्थान की पूंजी देश के अनेक राज्यों में विनिर्गोजित है। पर्याप्त सुविधाएँ व प्रेरणा देकर इस पूंजी के प्रवाह की दिशा राजस्थान का ओर भी मोड़ा जा सकती है। सर्वोप औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों देकर राज्य के औद्योगिकरण के लिए उद्यमियों को अकर्षित किया है। राज्य में अधिक विनिर्गोजन के लिए सरकार ने उद्योगों को उद्योग विनोद सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं।

10 विख्यात उद्यमी (Famous Industrialists) भारत के प्रसिद्ध औद्योगिक घराने, रथ, बिडला, पेंडार

गोलेठा साहू जैन आदि, राजस्थान के ही मूल निवासी हैं अतः यदि इन्हें प्रेरित किया जाए तो ये राजस्थान के प्रभावी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

11 प्राकृतिक गैस व तेल के बृहद् भण्डारों की संभावना (Possibilities of Large Deposits of Oil & Natural Gas) जैमलेश्वर से 180 किलोमीटर दूर धातार नामक स्थान पर 10 अप्रैल 1983 को 3554 मीटर की गहराई पर गैस के पर्याप्त भण्डार मिले थे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने जो खुदाई कार्य आरम्भ किए हैं उनसे भी अच्छे संकेत मिले हैं। गैस का प्रयोग शक्तिगृह स्थापित करने लघु उद्योगों के लिए व खाना पकाने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि में समृद्ध होते हुए भी कुछ बाधाओं के कारण औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। सरकार की वर्तमान औद्योगिक एवं खनिज नीति राजस्थान के औद्योगिकरण के उज्ज्वल भविष्य की ओर सकेत करती है।

राजस्थान में उद्योगों का क्षेत्रीय

वितरण / फैलाव / असमानताएँ

REGIONAL SPREAD OF INDUSTRIES

1 राजस्थान की औद्योगिक स्थिति

प्राप्त रिटर्न्स के आधार पर- 1993-94			
अ राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रमुख जिले 1993-94			
1 जयपुर	4 जयपुर		
2 जयपुर	5 उदयपुर		
3 जयपुर	6 जयपुर		
ब राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रमुख जिले 1993-94			
1 जयपुर	4 जयपुर		
2 जयपुर	5 जयपुर		
3 जयपुर			

संदर्भ: Statistical Abstract, Raj 1995

1993-94 उपलब्ध रिटर्न्स के विश्लेषण में ज्ञात होता है कि -

1 राज्य में कारखानों का वितरण समान नहीं है।

2 सर्वोच्च कारखानों जयपुर जिले में हैं। वनस्पति, कपड़ा, गन्ना, जल, उदयपुर, भोवडा, अजमेर, अजमेर व दीकनेर जिलों का स्थान है।

समीक्षा का औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति व विषयता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

1 अजमेर जिला (Ajmer District) 1993-94 में अजमेर में 8 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका क्षेत्रफल 732.87 एकड़ था। इसमें से 377.95 एकड़ का विकास किया जा चुका था। अजमेर जिले की औद्योगिक वस्तियों में मालुपुरा, बालुपुरा, फरवपुरा एच.एम.टी., व्यावर, किसानाट, केकड़ी और विजयनगर हैं। अजमेर जिले की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों में से कैमिज एण्ड वेगन वर्कशॉप, एच.एम.टी., एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स व कृष्ण मिल्स प्रमुख हैं।

2 टोंक जिला (Tonk District) 1993-94 में टोंक जिले में 4 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 328.30 एकड़ था जिसमें से 163.17 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जा चुका था। इस जिले में मालुपुरा टाक, निवाई आदि औद्योगिक क्षेत्र हैं। रीको द्वारा निवाई (टाक) में एकीकृत आधारभूत विकास केंद्र मिनी ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किया गया है।

3 उदयपुर जिला (Udaipur District) 1993-94 में उदयपुर जिले में 6 औद्योगिक वस्तियां थीं। इनका कुल क्षेत्रफल 1308.54 एकड़ था। जिसमें से 765.78 एकड़ का विकास किया जा चुका था। राजनगर, सुखर मेवाड़, पटनगर आदि जिले की औद्योगिक वस्तियां हैं। इस जिले में कपास कटाई मिल, शराब पेट्टों, जिक मेटटर, लकड़ी के छिलों के घना के कारखाने तथा रसायन व औषधियों के निर्माण के कारखाने हैं। उदयपुर सूती मिल व आयुर्वेद सेवकम प्राइवेट लिमिटेड यहाँ के प्रमुख संस्थान हैं। इसके अनिरक्त सोमेट व चूने में अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। लोहे व स्टील की टलाई के द्वारा बर्तनों का निर्माण भी किया जाता है। रीको द्वारा कालखन (उदयपुर) में एकीकृत आधारभूत विकास केंद्र स्वीकृत किया गया है।

4 जोधपुर जिला (Jodhpur District) 1993-94 में जोधपुर जिले में 12 औद्योगिक वस्तियां थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 2323.41 एकड़ था। इसमें से 2245.29 एकड़ क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका था। जिले में मयनिया फ्लोरीड मरुभू, डिबन, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, दोन्ट्या मांडौर भवन की बोर्ड आदि औद्योगिक वस्तियां थीं। उन्नत गलन कारखाना जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है। जिले में जोधपुर बलन मिल्स, होरा ब्रशिंग प्राइवेट लिमिटेड एल्का वैम मैरलन प्राइवेट लिमिटेड तथा पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक लिमिटेड आदि

प्रमुख संस्थान हैं। जिले में सूती वस्त्र, खाद्य तेल, रसायन निर्माण आदि के कारखाने भी कार्यरत हैं। लघु उद्योगों का विकास करने हेतु राज्य में इकोनियरिंग व प्लास्टिक उद्योगों का एक इकोनियरिंग कॉम्प्लेक्स निर्मित किया गया है। रीको द्वारा 5 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर में एकीकृत आधारभूत विकास केंद्र (मिनी ग्रोथ सेंटर) विकसित किया जा रहा है।

■ कोटा जिला (Kota District) 1993-94 में कोटा जिले में 12 औद्योगिक वस्तियां थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 2279.11 एकड़ था। इसमें से 2140.27 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में मुमराज मण्डी, गोविन्दपुर दाबडी इन्द्रप्रस्थ गेल्वे ब्रॉन्जा, रामाज मण्डी आदि औद्योगिक वस्तियां थीं। यह जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से उन्नत है। यहां श्रांगन रेपन्स जे के सिन्थेटिक लिमिटेड, ओरियन्ट पावर कंवेल्स, श्रांगन वायनिल एण्ड पैनिक्ल्स इण्डस्ट्रीज आदि प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। भारत सरकार द्वारा कोटा में सूक्ष्म यंत्र बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है। यहाँ दूध की बोतलों का निर्माण, चावल व दाल मिलें, खाद्यसारी व तेल का उत्पादन, वस्त्र निर्माण सम्बन्धी कारखाने, रंगों का निर्माण, कागज बोर्ड का निर्माण, प्लास्टिक के सम्बन्ध का निर्माण, रामायणिक खाद्य का निर्माण, सोमेट व चूना फर्नीचर भारी मशीनें, कृषि उपकरण आदि के कारखाने हैं।

6 नागौर जिला (Nagaur District) 1993-94 में नागौर जिले में 3 औद्योगिक वस्तियां थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 383.87 एकड़ था। इसमें से 383.87 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जा चुका था। मकरना नागौर व भड्डा मिठी जिले की औद्योगिक वस्तियां हैं। कारखाने मुख्यतः मर्दत चूना नमक प्रिंटिंग प्रेस अँदल मशीन, इकोनियरिंग वर्कशॉप व यंत्रों के निर्माण, पैमिकल्स वर्कशॉप, ऊनी मिल, व्याकरण तथा प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण में सम्बन्धित थे। रीको द्वारा 5 करोड़ रुपये की लागत में नागौर में एकीकृत आधारभूत विकास केंद्र (मिनी ग्रोथ सेंटर) विकसित किया जा रहा है।

7 जैसलमेर जिला (Jaisalmer District) 1993-94 में जैसलमेर जिले में 3 औद्योगिक वस्तियां थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 161.86 एकड़ था। इसमें से 52.66 एकड़ का विकास किया जा चुका था। इस जिले की प्रमुख औद्योगिक वस्तियां जमलमर ही हैं। कारखाने मुख्यतः पत्थर खोदों व दुग्ध उत्पादन में सम्बन्धित थे।

8 जालौर जिला (Jalore District) 1993-94 में

जालौर जिले में 4 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 393.40 एकड़ था। इसमें से 128.82 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में विशाखगढ़ सातौर व जालौर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। कारखाने मुख्यतः दुग्ध सेतल निर्माण सेतल मिले, सूती वस्त्रों की बुनाई, लकड़ी का काम, मुद्रण व प्रकाशन तथा उत्पादन के कार्यों में सम्मिलित थे।

9 झालावाड़ जिला (Jhalawar District)
1993-94 में झालावाड़ में 9 औद्योगिक इस्तिस्था थी जिनका कुल क्षेत्रफल 787.38 एकड़ था। इसमें से 4.20 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में ज्ञानरत्नपाटन भवानी मण्डो झालावाड़ आनरा आदि औद्योगिक इस्तिस्था थी। कागजान में मुख्यतः छोटे व नन उत्पादन काटन कलीनिंग काटन जिनिय व बनिंग मिटिंग गइलो वे निर्माण स्टीन टेमिंग एण्ड कशिग तथा स्टीव निर्माण में सम्मिलित थे। कन्द सरकार ने 22 अक्टूबर 1989 की विकास कन्दो की नार्ति के अनर्गी झालावाड़ का 30 करोड़ रूपय की लगन से विकास किया जा रहा है।

10 झुझुनू जिला (Jhunjhunu District) 1993-94 में झुझुनू जिला में 4 औद्योगिक इस्तिस्था थी जिनका कुल क्षेत्रफल 253.73 एकड़ था। इसमें से 173.67 एकड़ का विकास जा चुका था। जिले में पिनाली गिडाव झुझुनू व सिधाणा (खतडी) औद्योगिक इस्तिस्था थी। शैरीय खेतडी कापर कॉम्पलकस गदमारी ताम्र गियरज इस जिले के प्रमुख औद्योगिक सम्थान है। इस जिला में ल कोल्ड ड्रिक्स लकडों का क्कम बेसिव शैरी आर्गेनिक कैमिकल्स इन्सार्गेनिक फर्टिलाइजर आदि के पजीकृत कारखाने थे।

11 डूंगरपुर जिला (Dungarpur District)
1993-94 में डूंगरपुर जिला में 2 औद्योगिक इस्तिस्था थी जिनका कुल क्षेत्रफल 75.60 एकड़ था। इसमें से 54.93 एकड़ भक्कन का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में औद्योगिक इस्तिस्था गामवाडा व डूंगरपुर है। कारखाने शीमेन्ट फक्कट तथा रिपय आफ मोफ्फरीन एण्ड धातर सारविन में सम्मिलित थे।

12 गंगानगर जिला (Ganganagar District)
1993-94 में गंगानगर जिले में 15 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 1482.83 एकड़ था। इसमें से 779.17 एकड़ का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में शीगंगानगर हुमागढ़ मुख्यतः गन्ना मण्डो फक्कपुर फक्काना गीर अनुपगढ़ आदि औद्योगिक इस्तिस्था थी।

इस जिले में मार्टुल टैकराटाइल्स मिल्स गंगानगर शुगर मिल्स डिस्टिलरी गंगानगर पर्टिटोईजर्स सॉपोरेशन तथा गुप्ता इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन आदि प्रमुख औद्योगिक सम्थान हैं। कारखाने मुख्यतः दान, गैनी, मैटल आगमन फनार मिल्स तथा उत्पादन आदि में सम्मिलित थे।

13 जयपुर जिला (Jaipur District) 1993-94 में जयपुर जिले में 19 औद्योगिक इस्तिस्था थी जिनका कुल क्षेत्रफल 4131.72 एकड़ था। इसमें से 2893.22 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में रिश्मा शाटगाड़ा मालवीय मुद्रशोपुरा बक्क रनरान शाहपुरा टौगा रालमाट दूद्र पुनग बक्कपुरा जौपुरा आदि औद्योगिक इस्तिस्था थी। जिले में इजीनियरिंग उद्योग मान इण्डस्ट्रियल सारपोरेशन जयपुर ग्गनिंग एण्ड गैविय मिल्स निमिड गम्पर निमिडेड पोसर ग्गनिंग मिल्स निमिड गम्मान इजीनियरिंग कारपोरेशन तथा जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स आदि प्रमुख औद्योगिक सम्थान हैं। इस जिले में अनेक प्रका के छोटे एर बडे आकार के उद्योग का विकास हुआ है। देश का प्रथम निर्गत सबर्डी औद्योगिक पार्क (EPZ) की स्थापना जयपुर के सीतापुर में 47 एग्रेड रुपये की अनुमानित लागत में स्थापित किया जा चुका है। नियाँनानुग्रे इक्वईयो की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

14 चित्तौड़गढ़ जिला (Chittorgarh District)
1993-94 में चित्तौड़गढ़ जिले में 7 औद्योगिक इस्तिस्था थी जिनका कुल क्षेत्रफल 605.98 एकड़ था। इसमें 406.73 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ निम्नांशा वक्कसन आदि औद्योगिक इस्तिस्था थी। इस जिले में निम्ना सीमेन्ट वर्क चित्तौड़गढ़ जे के सीमेन्ट वर्क निम्नांशा मेवाड शुगर मिल्स भाषा न्यागर तथा मेवाड इंडस्ट्रियल ग्राइन्डर इस्तिस्था आदि प्रमुख औद्योगिक सम्थान हैं। कारखाने मुख्यतः ग्राइन्डरी इंडस्ट्रियल ग्राइन्डर गन्ना मिल्स कल्स ग्गनिंग सीमेन्ट काशीर एग्रेड पशीनग तथा पाइप निर्माण आदि में सम्मिलित थे।

15 चुरू जिला (Churu District) 1993-94 में चुरू जिले में 6 औद्योगिक इस्तिस्था थी जिनका कुल क्षेत्रफल 556.96 एकड़ था। इसमें से 259.68 एकड़ भक्कन का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। इस गम्मानग गन्ना व चुरू मुखानग गार्गापुर आदि औद्योगिक इस्तिस्था थी। ये कारखाने मुख्यतः दान (डिस्टिल) व खोप नेन गम्प गार्मट पाप्प रनि प्रशार रनर सड आदि वक्कन व उत्पादन में सम्मिलित थे।

16 धौलपुर जिला (Dholpur District) 1993 94 में धौलपुर जिले में 4 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 351 64 एकड़ था। इसमें से 98 42 एकड़ क्षेत्रफल को औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले के औद्योगिक क्षेत्र धौलपुर व राडो है। धौलपुर का कॉन उद्योग प्रसिद्ध है। यहां धौलपुर ग्लाम वर्कर्स हाईटैक ग्लास फैक्ट्री तथा गजस्थान एक्स्प्लाइव्स एंव कैमिकल लिमिटेड प्रमुख औद्योगिक मस्थान है। जिले में फाबरिक विद्युत उत्पादन दाल व तेल मिल प्रिटिंग प्रेम तथा बर्फ फैक्ट्री आदि औद्योगिक इकाइया कार्यरत है। धौलपुर को कन्द प्रवर्तित योजना व अनर्गल 30 बगड रूप्य की लात से औद्योगिक विकास कन्द के रूप में विकसित किया जा रहा है।

17 भीलवाड़ा जिला (Bhilwara District) 1993 94 में भीलवाड़ा में 6 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 619 24 एकड़ था। इसमें से 379 82 एकड़ क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका था। इस जिले में भीलवाड़ा उद्योग विद्यालय तथा अदि औद्योगिक दमिया थी। भीलवाड़ा राज्य का प्रमुख औद्योगिक कन्द बनता जा रहा है। यहां मूल वस्त्र मिले ऊनी मिल मिनिंग एवं वीरिंग मिल वनस्पति धी व कारखाने अभ्रक आरा मशीन ईटो का उद्योग दाल फैक्ट्री आदि औद्योगिक इकाइया है।

22 अक्टूबर 1989 की केंद्र सरकार की नीति (विकस केंद्रों की स्थापना) के अनुसार भीलवाड़ा का भी विकास कन्द के लिए चयन किया गया। इस क्षेत्र में 30 एकड़ रूप्य का लात से जल विद्युत परिवहन व सवार आदि मरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जाएगी और वस्त्र नारी के रूप में इसका विकास किया जायगा।

18 बीकानेर जिला (Bikaner District) 1993 94 में बीकानेर जिले में 7 औद्योगिक दमिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 1390 03 एकड़ था। इसमें से 512 95 एकड़ का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में जिल्लदान नगर नुनकण्णर आदि औद्योगिक बस्तिया थी। उनील डयंग तथा वक व क्लन मिल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक मस्थान है। इस जिले में विजली व उद्योग बैटरी का तज्जार पण्डित जल अणुवैद्युत फार्मसी तथा इन वन व रमादन अदि वन्य व कारखाने है।

22 अक्टूबर 1989 का विकास कन्दों की कन्द प्रवर्तित नीति व अनर्गल वन्य व भी वन्य किया गया है। इस विकास कन्द पर 30 बगड रूप्य का लात से

मरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जाएगी।

19 बूंदी जिला (Bundi District) 1993 94 में बूंदी जिले में 5 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 151 76 एकड़ था। इसमें से 71 22 एकड़ का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में बूंदी (वा सी आर) वूंदी (बी एन आर), बूंदी (बी पी आर) आदि औद्योगिक बस्तिया थी। इस जिले में सीमेंट के दो प्रमुख कारखाने साखरी में कार्यरत है। जिले में मुख्यतः तेल मिले चावल मिले पावरलुम आदि औद्योगिक मस्थान कार्यरत है।

20 अलवर जिला (Alwar District) 1993 94 में 10 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 6043 11 एकड़ था। इसमें से 4169 07 एकड़ का विकास किया जा चुका था। इस जिले की औद्योगिक बस्तियों में भिवाड़ी शाहजहापुर, सरली वरुण्ड मत्स्य गजगड व खेयतल है। राठी अलायव एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड त्रयपुर मिथ्येटिक, माडर मिथ्येटिक इण्डिया लिमिटेड, अरावली फॉर्म त्रिक्स लिमिटेड सुपर ट्रूल इण्डिया भारत एलम एण्ड कैमिकल लिमिटेड अलवर इजन प्लांट तथा इन्विर्मल मिलगडर लिमिटेड अदि जिले के प्रमुख औद्योगिक मस्थान है। दरा का दूसरा निर्यात मयदून औद्योगिक पाक पिजार्डी (अलवर) में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसका लागत लगभग 55 34 करोड़ रूप्य लागी।

21 बांसवाड़ा जिला (Banswara District) 1993 94 में बांसवाड़ा जिले में 4 औद्योगिक क्षेत्र थे। जिले का कुल औद्योगिक क्षेत्र 366 08 एकड़ था। इसमें से 207 13 एकड़ का विकास किया जा चुका था। कुशलगट यहां की प्रमुख औद्योगिक बस्ती है। इस जिले में कौटन जिनिंग एण्ड बलिंग खाने योग्य तेल व घा दिराई उद्योग मैमशक्ति आर्गुर्ति राइस मीलिंग स्टोन टमिंग एवं क्रिशिंग सिन्थेस फाइबर दवाइये का निर्माण अदि पञ्चकृत कारखाने थे।

22 बाडमेर जिला (Barmer District) 1993 94 में बाडमेर जिले में 5 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 733 80 एकड़ था। इसमें से 383 89 एकड़ का विकास किया जा चुका था। इस जिले में बाडमेर बालन्या समदडा अदि औद्योगिक क्षेत्र थे। काउर वंवि एण्ड बलिंग डडा एण्ड बलिंग आर काउर टैक्मजिल आयन मिल मिनिंग इस जिले में एल एल मिनिंग तथा वन्य हवी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पन्यू अदि पञ्चकृत कारखाने थे।

23 भरतपुर जिला (Bharatpur District) 1993
94 में भरतपुर जिले में 5 औद्योगिक बस्तिया थीं। जिनका कुल क्षेत्रफल 511 50 एकड़ था। इसमें से 398 44 एकड़ क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका है। भरतपुर डींग व बयाना आदि इस जिले की औद्योगिक बस्तिया हैं। परपैक्टम पाटीज लिमिटेड तथा सैन्टल इण्डिया मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (मिमको) इस जिले के प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। कारखाने मुख्यतः दूध व दूध में बना वस्तुएं दाल मिल साखर तेल रफ़ टायर ग्युब आयुर्वेदिक व युनानी रसायन आयन एण्ड मटीन आदि में सम्बन्धित थे

24 पाली जिला (Pali District) 1993 94 में पाली जिले में 9 औद्योगिक बस्तिया थी। इनका कुल क्षेत्रफल 829 18 एकड़ था। इसमें से 829 18 एकड़ का विकास किया जा चुका था जिले में मात्र मीठी मारवाड़ ज्वारान सुमेरपुर पाली मण्डिया राड तखाना आदि प्रमुख औद्योगिक बस्तिया हैं कारखाने मुख्यतः दुग्ध घेतलों का निर्माण ग्राह तेल शान निर्माण छाता व वस्त्र निर्माण लकड़ी का काम पत्रा का निर्माण पेपर बोर्ड गते का निर्माण रसायन व औषधियों का निर्माण विद्युत लैम्प का निर्माण पेन व बान पेन का निर्माण गडियो निर्माण आदि में सम्बन्धित हैं

25 सवाईमाधोपुर जिला (Sawai Madhopur District) 1993 94 में सवाईमाधोपुर जिले में 8 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 606 48 एकड़ था। इसमें से 468 75 एकड़ का विकास किया जा सका था। जिले में गगापुर सिटी रोड रोड हिण्डान गणधमौर आदि औद्योगिक बस्तिया थी जिले में गजल मिले दाल मिल साखर तेल मिले लकड़ी का काम प्रिटिंग प्रेस सीमेंट निर्माण सीमेंट की वस्तुओं का निर्माण आदि उद्योग कार्यरत थे।

26 सीकर जिला (Sikar District) 1993 94 में सीकर जिले में 6 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 431 56 एकड़ था। इसमें से 288 97 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में मोरार सण्डेला श्रीमाधोपुर गमगढ़ नामराधाना आदि औद्योगिक बस्तिया थी। ये कारखाने चर्बी उत्पादन साखर तेल का उत्पादन खादी उत्पादन सूना व पत्रा आदि वस्तुओं के निर्माण में सम्बन्धित हैं।

27 सिरोही जिला (Sirohi District) 1993 94 में

सिरोही जिले में 7 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 818 02 एकड़ था। इसमें से 724 80 एकड़ का विकास किया जा चुका था। शिवगज सिरोही रोड स्वरूपगज आबूरोड मण्डार सिरोही आदि इस जिले की प्रमुख औद्योगिक बस्तिया हैं। कारखाने तेल दाल व खाद्य पदार्थों का निर्माण कपास की सफाई व गांठ बनाने कपड़े व रेशम की रंगाई सूती वस्त्रों की बुनाई लकड़ी का काम मुद्रण व प्रकाशन प्लास्टिक का उत्पादन पत्थरों की कटाई व छायाई सीमेंट व स्क्वैट का उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन आदि में सम्बन्धित थे। भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 1989 की विराम केन्द्र की नीति के अन्तर्गत आबूरोड का चयन किया है। इस क्षेत्र में 30 करोड़ रुपये की लागत से मर्यादात्मक भुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

28 बारा जिला (Baran District) 1993 94 में बारा जिले में 2 औद्योगिक बस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 211 16 एकड़ था। इसमें से विकसित किये गये क्षेत्र के आठवें उपलब्ध नहीं हैं।

29 दौसा जिला (Dausa District) 1993 94 में दौसा जिले में 6 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 490 93 एकड़ था। इसमें से 291 38 एकड़ का विकास किया गया।

30 राजसमन्द जिला (Rajsamand District) 1993-94 में राजसमन्द जिले में 2 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 278 49 एकड़ था। इसमें से 191 73 एकड़ का विकास कार्य हाथ में लिया गया।

31 हनुमानगढ़ जिला (Hanumangarh District) हनुमानगढ़ जिले में 2 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 278 49 एकड़ था। इसमें से 191 73 एकड़ का विकास कार्य हाथ में लिया गया।

32 करौली जिला (Karauli District) हनुमानगढ़ जिले में 2 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 278 49 एकड़ था। इसमें से 191 73 एकड़ का विकास कार्य हाथ में लिया गया।

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन¹

राज्य में चयनित महत्वपूर्ण वस्तुओं के वर्ष 1997 एर 1998 के उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति निम्नांकित सारणी में दर्शाई गई है।

चयनित मर्दों का औद्योगिक उत्पादन

क्र.सं.	मर्द	इकाई	उत्पादन		1996 की तुलना में 1997 में परिवर्तन % / करोड़
			1997	1996 (प्रारंभिक)	
1	शक्कर	टन	26375	58695	+122.54
2	सिस्ट (सभी प्रकार)	000 टोन्स	24525	29278	+1.38
3	बनस्पति घी	टन	24995	24935	0.20
4	नमक	लाख टन	12	11	-8.33
5	गुरिया	000 टन	398	385	3.27
6	सुपर फॉस्फेट	000 टन	25	9	-6.70
7	सोनेट	000 टन	6493	6206	-4.17
8	अन्नक की ईंटें	000 सखा	472	202	57.20
9	बत्तों की ईंटें	000 टन	90	104	+15.56
10	कैडमियम अक्विन उत्पाद	टन	149	154	+3.36
11	शैल वैन	सखा	1754	1703	-2.57
12	बाल बिंदी	लाख सखा	228	214	-6.14
13	धानी के मोटर	सखा	40770	40883	+19.89
14	रेडिफ़ाई	सखा	4186	1839	-55.07
15	लेपित एवं पुनः लेपित पत्थर	000 स्क्वायर मीटर	167	165	-1.20
16	बिजली के मोटर	लाख सखा	4.80	1.95	59.36
17	गुब्बारेदार धागा	टन	2121	-	--
18	पैलिस्टर धागा	टन	4473	-	--
19	कैल्सिक सोडा	टन	38767	39735	+2.50
20	कैल्शियम कार्बाइड	टन	37951	35677	-5.99
21	पी.वी.सी. रेजिन	टन	29318	25458	13.17
22	पी.वी.सी. कम्पाउंड	टन	3199	5030	57.24
23	सल्फ्यूरिक एसिड	000 टन	213	249	16.90
24	कॉपर कैथोड	टन	26238	26232	-0.02
25	सूती कपड़ा	लाख मीटर	505	472	6.53
26	सूती धागा	000 टन	77	75	-2.60

Source: Economic Review, 1998-99, Govt. of Rajasthan

उपरोक्त सारणी से प्रकट होता है कि वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में चयनित वस्तुओं के उत्पादन में मिश्रित प्रवृत्ति रही।

राजस्थान के बृहद् उद्योग

LARGE SCALE INDUSTRIES IN RAJASTHAN

राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 11 बृहद् इकाइयाँ और 207 एजिस्टर्ड फैक्ट्रीयाँ थीं।¹ मार्च, 1998 में बृहद् एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या 531 थी जिनमें 13740 करोड़ रुपये विनियोजित थे और 1.70 लाख व्यक्ति कार्यरत थे।² राजस्थान के प्रमुख बृहद् उद्योग निम्न प्रकार हैं -

राजस्थान के बृहद् उद्योग मुख्यतः कृषि एवं खनिज सम्पदा पर आधारित हैं। राज्य के इन उद्योगों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है -

अ. कृषि पर आधारित उद्योग (Agriculture Based Industries)

1. सूती वस्त्र उद्योग
2. चीनी उद्योग
3. वनस्पति घी उद्योग

ब. खनिजों पर आधारित उद्योग (Mineral Based Industries)

1. सीमेंट उद्योग
2. लकड़ उद्योग
3. कोयला उद्योग
4. सोना उद्योग
5. ताम्र उद्योग

ग. अन्य उद्योग (Other Industries)

1. ऊन उद्योग
2. इस्पात उद्योग
3. रसायन उद्योग

1. Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Raj.
2. Economic Review, 1998-99, Govt. of Raj.

(अ) कृषि पर आधारित उद्योग

Agriculture-Based Industries

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industries)

1 इतिहास एवं विकास (History & Development)

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का अति प्राचीन उद्योग है। प्रारम्भ में यह उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था लेकिन राज्य में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना के पश्चात् यह दोनों ही रूपों में विद्यमान है। लघु उद्योग के रूप में यह मुख्तार दरियों, निवार आदि वस्तुओं के निर्माण तक ही सीमित रह गया है। राजस्थान राज्य के बड़े उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग काफी पिछड़ा हुआ है।

राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास 19 वीं शताब्दी के अंत में प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम ब्यावर नगर में सन् 1889 ई. में दी कृष्णा मिल्स लि. की स्थापना की गई। इसके पश्चात् ब्यावर नगर में ही सन् 1908 और 1925 में क्रमशः एडवर्ड मिल्स लिमिटेड तथा महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। सन् 1938 में मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाड़ा तथा 1942 में महाराज उम्रेद मिल्स लिमिटेड, पाली की स्थापना हुई। 1946 में सार्दूल टैक्सटाइल्स लिमिटेड गगानगर की स्थापना की गई। कृष्णा मिल्स व एडवर्ड मिल्स, ब्यावर रुग्ण इकाइया घोषित कर दी गई। अतः इनकी प्रबन्ध व्यवस्था को राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंप दिया गया। इस प्रकार ये मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित हो गई। इसके पश्चात् राज्य में बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा तथा भवानीगण्डी स्थानों पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। वर्ष 1956 में जब अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया राजस्थान में 11 सूती वस्त्र मिलें थीं।

2 इकाइयों की संख्या एवं इनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें गगानगर, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, पाली, जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, कोटा विजयनगर, बीकानेर, उदयपुर, किशनगढ़ तथा भवानीगण्डी आदि स्थानों पर स्थापित की गई हैं। राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें इस प्रकार हैं

राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें - 1

कृष्णा मिल्स, ब्यावर 2 एडवर्ड मिल्स, ब्यावर 3 महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर 4 कॉटन स्पिनिंग मिल्स, भवानीगण्डी 5 स्वदेशी कॉटन मिल्स, उदयपुर ॥ श्री गोयल इण्डस्ट्रीज, कोटा 7 जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग लिमिटेड, जयपुर 8 विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनगर 9 राजस्थान भीलवाड़ा मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा 10 मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा 11 राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा 12 महाराज उम्रेद मिल्स लिमिटेड, पाली 13 पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर 14 सार्दूल टैक्सटाइल्स मिल्स, श्रीगगानगर 1५ राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाड़ा 16 गगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गगानगर 17 गगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गगानगर 18 आदित्य मिल्स, किशनगढ़ 19 बासवाड़ा फैब्रिक्स, बासवाड़ा 20 बासवाड़ा सिन्टैक्स, बासवाड़ा 21 मॉडर्न सिन्टैक्स, अलवर 22 राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, खारीग्राम, भीलवाड़ा 23 सुदर्शन टैक्सटाइल्स, कोटा 24 मॉडर्न वेइस, रायला भीलवाड़ा 25 डबी टैक्सटाइल्स, जयपुर 26 भीलवाड़ा सिन्टैक्स, भीलवाड़ा 27 राजस्थान पॉलियेस्टर्स लिमिटेड, भिवाड़ी-अलवर 28 आधुनिक पॉलिटैक्स आबूरोड।

सार्दूल टैक्सटाइल्स लिमिटेड, गगानगर की स्थापना 1946 में की गई। कोटा टैक्सटाइल्स 1956 से श्री निवास कॉटन मिल्स मुम्बई की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य कर रही है। राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा की स्थापना 1960 में की गई थी। आदित्य मिल्स, किशनगढ़ की स्थापना 1960 में की गई थी। यह मुम्बई में स्थित पोद्दार मिल्स लिमिटेड की इकाई है। जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स भी इसकी सहायक मिल के रूप में कार्य कर रही है। उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर की स्थापना 1961 में की गई। यह स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर की इकाई के रूप में कार्य कर रही है। सन् 1968 में भवानी गण्डी में एक सूती मिल की स्थापना की गई। अतः स्पष्ट है कि राज्य का सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः ब्यावर, पाली, जयपुर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, श्रीगगानगर, विजयनगर, उदयपुर, भवानी गण्डी एवं कोटा में स्थित है।

निम्न तालिका में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के विकास को बताया गया है

राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों का विकास ¹						
वर्ष	स्पिनिंग मिल्स	कम्पोजिट मिल्स	कुल मिलें	स्थापित इकाइयों की संख्या	स्व-इकाइयों में	श्रमिकों की संख्या
1962	16	7	23	651	-	2939
1963	26	8	34	824286	-	3024
1994	32	6	38	905368	3080	2232
1995	34	7	41	906716	3944	2262
1996	38	7	45	1084980	8712	2145

Source: Statistical Abstract, 1988-1994 & 1995

उत्पुर्ण तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

1 राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। यह स्थिति राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के पर्याप्त विकास की ओर है।

2 राज्य में कम्पोजिट मिल्स की संख्या में कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण राज्य में पूँजी का अभाव होना है।

3 राजस्थान में स्पिनिंग मिल्स की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

4 राज्य की मिलों में अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। 1996 के अंत में राज्य की 38 मिलों में 56176 व्यक्ति कार्यरत थे।

5 राजस्थान में समस्त सूती व्यवसाय में लगभग दो तिहाई विनियोग राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रीके के माध्यम से किया गया है।

3 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है। राजस्थान में गगानगर के अतिरिक्त अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, पाली, कोटा, बुंदी, बांसवाड़ा आदि जिलों में कपास उत्पन्न की जाती है। सर्वाधिक फसल गगानगर जिले में होती है। गगानगर जिले में ब्रेण्ड किस्म की लम्बे रेशों वाली कपास भी उत्पन्न की जाती है।

राज्य के गगानगर जिले में सर्वाधिक कपास उत्पन्न होती है। इसके पश्चात् भीलवाड़ा, बीकानेर, बांसवाड़ा, नागौर, पाली व अजमेर जिले प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। राज्य की अधिकांश मिलें इन्हीं जिलों में स्थापित की गई हैं। इन जिलों में कपास के बढ़ते हुए उत्पादन की दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उद्योग का भावी विकास इन्हीं क्षेत्रों में होगा। 1996-97 में राजस्थान में कपास का उत्पादन 136 लाख गण्टे था। राजस्थान कपास उत्पादन की दृष्टि से निरन्तर विकास कर रहा है अतः यह सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।

राज्य की जनसंख्या में स्वतंत्रता के पश्चात् तालिका से वृद्धि हुई है। 1981 में राज्य की कुल जनसंख्या 3.42 करोड़ थी जो बढ़कर 1991 में 4.40 करोड़ हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति रोजगार की तलाश में प्रायः

शहरों में आते हैं अतः राज्य के सूती वस्त्र उद्योग की श्रम सम्बन्धी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। उद्योग को प्रायः सस्ता श्रम प्राप्त होता है।

4 राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले उत्त्व (Factors of Localisation) राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है अतः सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। उदाहरण के लिए, श्रीगगानगर में कपास की सर्वाधिक खेती होती है अतः सार्दूल टेक्सटाईल मिल्स, श्रीगगानगर को पर्याप्त मात्रा में कपास स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो जाता है। भीलवाड़ा अजमेर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि जिलों में भी कपास की पर्याप्त खेती की जाती है। अतः इन क्षेत्रों की मिलों को भी कच्चे माल की आवक आसानी से हो जाती है। माही सिचाई परियोजना के फलस्वरूप बांसवाड़ा जिले में सिचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। अतः इस जिले में भी कपास की खेती को प्रोत्साहन मिला है। बांसवाड़ा फेब्रिक्स को कच्चे माल की प्राप्ति स्थानीय एवं बाहरी दोनों स्रोतों में होती है। इसी प्रकार ब्यावर, विजयनगर व गुलाबपुरा की मिलों को भी स्थानीय स्तर पर ही कपास उपलब्ध हो जाती है।

राज्य की मिलों को सस्ता श्रम भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति प्रायः रोजगार की तलाश में आते हैं। राज्यों में मिलों की स्थापना प्रायः शहरी क्षेत्रों में की गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जल की पर्याप्त पूर्ति है और बैंकिंग सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये क्षेत्र परिवहन के साधनों की दृष्टि से भी धनी हैं। अतः निर्मित माल देश एवं विदेश की मण्डियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मिलों को कोयला बाहर से मगाना पड़ता है लेकिन राज्य में विद्युत शक्ति की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। राज्य में डीजल की पूर्ति भी पर्याप्त है। अतः राज्य की मिलों की शक्ति सम्पत्ती आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। राज्य के मिल क्षेत्र विशाल बाजारों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं अतः मिलों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं की बिक्री स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में हो जाती है।

5 राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन (Production) राज्य की मिलों द्वारा मुख्यतः धागे एवं सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान में सूती वस्त्र एवं धागे का उत्पादन

वर्ष	इकाई	वस्त्र उत्पादन (हजार मीटर)	धागे का उत्पादन (मैट्रिक टन)	पोलिस्टर धागे (हजार मैट्रिक टन)	नायलोन धागे (हजार मैट्रिक टन)
1985		43972	51308	5 46	-
1992		41100	54000	14 59	3 99
1997		50500	77000	4 47	2 12
1998 (अनुमानित)		47200	75000		

Source: Statistical Abstract 1998 Rajasthan & Economic Review 1998-99 Raj.

ह रूई एवं सूती वस्त्रों का आयात निर्यात (Import and Export) राजस्थान के श्रेष्ठ किस्म की कपास का उत्पादन सीमित मात्रा में होता है अतः श्रेष्ठ किस्म की कपास अन्य राज्यों से आयात करनी पड़ती है। देशी किस्म की रूई अन्य राज्यों को निर्यात की जाती है।

7 राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएँ व समाधान (Problems & Solutions)

(i) कच्चे माल का अभाव (Lack of Raw Material) राजस्थान में अच्छी किस्म की कपास मुख्यतः श्रीगंगानगर जिले में बोई जाती है। शेष क्षेत्रों में आज भी प्रायः अच्छी किस्म की कपास बोई जा रही है। देशी किस्म की कपास के रेशे छोटे जबकि विदेशी कपास के धागे प्रायः बड़े होते हैं। इसके साथ ही विदेशी किस्में उच्च स्तर की व मुलायम होती हैं। इस कारण ऐसी कपास से बने वस्त्र अच्छी किस्म के एवं अधिक मूल्य के होते हैं। इस कारण राजस्थान में अच्छी किस्म की कपास के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। राजस्थान के मिचित क्षेत्रों में अच्छी किस्म की कपास बोये जाने की पर्याप्त सम्भावनाएँ भी विद्यमान हैं। अच्छी किस्म की कपास का उत्पादन बढ़ जाने से इसके लिए विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी।

(ii) शक्ति के साधनों का अभाव (Lack of Power Resources) राजस्थान में शक्ति के साधनों का अभाव है अतः राज्य की कुल मिलें तो प्रायः बंद रहती हैं। राज्य की सभी मिलों को विद्युत शक्ति की सुविधा प्राप्त नहीं है। अनेक मिलें स्टीम प्लांट तथा डीजल जनरेटिंग सेट से विद्युत उत्पन्न करती हैं अतः उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाता है। इस समस्या के हल के लिये देशी व विदेशी विनियोजकों को राजस्थान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(iii) नवीनीकरण का अभाव (Lack of Modernisation) राज्य की अधिकांश मिलों की यशोर्त अत्यन्त पुरानी है जिनसे न केवल वस्त्रों का कम उत्पादन होता है वरन् ये बाजार खराब भी होती रहती हैं। अतः वस्त्र उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है। राज्य में पूँजी

के अभाव के कारण ही वस्त्र उद्योग सम्बन्धी नवीनीकरण कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है। नवीनीकरण के इस कार्य के लिए विशेषतः राजस्थान के प्रवासी उद्योगपतियों से सहायता ली जा सकती है।

(iv) शुष्क जलवायु (Dry Climate) राजस्थान की जलवायु प्रायः शुष्क है जबकि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए आर्द्र या नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग की कृत्रिम साधनों के द्वारा कृत्रिम वातावरण निर्मित करना पड़ता है जिससे वस्त्र उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में शोध अनुसंधान की आवश्यकता है।

(v) कम उत्पादकता (Low Productivity) राज्य की सूती वस्त्र मिलों में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादकता अन्य राज्यों के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम है। यहाँ 100 कुओं के पीछे 12-15 श्रमिक कार्य करते हैं जबकि अन्य राज्यों में इस कार्य हेतु केवल 8-9 श्रमिक ही रखने पड़ते हैं। इसी प्रकार वहाँ 100 कर्षों के लिये लगभग 80-85 श्रमिक रखने पड़ते हैं जबकि अन्य राज्यों में केवल 80-66 श्रमिक ही रखे जाते हैं। राज्य में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(vi) अन्य (Others) दोषपूर्ण प्रबंध के कारण अनेक सूती वस्त्र मिलें बंद पड़ी रहती हैं। राज्य की कुछ मिलें ही लाभान्ना की घोषणा कर पाती हैं। इसी प्रकार मिलों का छोटा आकार भी समस्या का एक कारण है। छोटे आकार के कारण ये मिलें बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त नहीं कर पाती, अतः सूती वस्त्र की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इन मिलों के समक्ष सदैव पूँजी की समस्या बनी रहती है अतः उपरोक्त सभी समस्याओं का उचित समाधान किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान में सहकारी मिलें (Co-operative Mills)

1 राजस्थान सहकारी कर्नाई मिल लिमिटेड, गुलानपुर
भीलवाड़ा 1985 में स्थापित यह मिल कपास का उत्पादन

करने वाले सदस्य-कृषकों व अन्य कृषकों से कपास खरीदने तथा कटाई-युनाई व रंगाई आदि कार्यों को सम्पन्न करती है। यह मिल धाने की बिंदी करके कृषकों को उनके द्वारा उत्पन्न कपास के लाभप्रद मूल्य दिलाने का कार्य करती है।

2. गगानगर सहकारी कटाई मिल लिमिटेड, श्रीगगानगर 1978 में स्थापित की गई इस मिल का कार्यालय हनुमानगढ़ जवशन नगर में है। यह मिल गगानगर जिले में उत्पन्न कपास का उपयोग करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इस मिल द्वारा पॉवरलूम व हथकरघों को भी कच्चे माल की पूर्ति की जाती है।

3. गगापुर सहकारी कटाई मिल लिमिटेड, गगापुर भीलवाड़ा जिले के गगापुर कस्बे में गगापुर सहकारी कटाई मिल लिमिटेड की स्थापना सन् 1981 में की गई है। इस मिल का प्रमुख उद्देश्य समिति के सदस्यों के लाभ के लिए महादक उद्योगों का संचालन करना है।

चीनी उद्योग

SUGAR INDUSTRY

1 इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान में सर्वप्रथम सन् 1932 में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना भोपालसागर चित्तौड़गढ़ में की गई है। इस मिल में उदयपुर सम्भा में उत्पन्न गन्ने का उपयोग किया जाता है। राज्य में चीनी का दूसरा कारखाना 1937 में श्रीगगानगर में स्थापित किया गया। इस कारखाने का नाम गगानगर शुगर मिल है। इस मिल में सन् 1946 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में बीकानेर के श्री लाल व्यास व श्री पोखरदाम ने गगानगर शुगर मिल्स में 3 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित की लेकिन 8 वर्षों तक इस मिल में उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। 1946 में इसे बीकानेर इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया। मिल में उत्पादन कार्य तो प्रारंभ हो गया लेकिन फिर भी इस मिल का संचालन असतोषजनक रहा। अतः 1953 के अंत में राजस्थान सरकार ने इस मिल को लीज पर ले लिया। इस प्रकार वर्तमान में यह मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस मिल में चुकन्दर से चीनी बनाने की योजना 1968 में प्रारंभ की गई। यह प्रयोग अत्यधिक सफल रहा है और चुकन्दर से चीनी बनाने का कार्य निरन्तर बढ़ रहा है। राज्य में चुकन्दर की खेती को बढ़ावा देने के नये ज्ञान जर्मनी तथा पुर्गोस्तलिया आदि राष्ट्रों से चुकन्दर के

उत्तर किस्म के दीज आयात किये जाते हैं। राज्य के बूंदी जिले के केशोरायपाटन में भी सन् 1932 में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना की गई।

2. इकाइयों की संख्या एवं उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में अग्रलिखित चीनी मिलें कार्यरत हैं

(i) **दी मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपालनसागर (चित्तौड़गढ़)-** इस मिल की स्थापना 1932 में की गई थी। यह राज्य की सबसे पुरानी चीनी मिल है। इसमें राज्य क उदयपुर सम्भा में उत्पन्न गन्ने से चीनी बनाई जाती है।

(ii) **दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड-** यह चीनी मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। इसके 97 प्रतिशत अंशों का राज्य सरकार का तथा शेष 3 प्रतिशत पर निजी व्यक्तियों का अधिकार है। इस मिल में गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है। मिल के अधीन एक शराब बनाने का कारखाना भी है जिसके केन्द्र अजमेर, अटारू, प्रतापगढ़ व जोधपुर में हैं। यह कारखाना मिश्र बनाने का कार्य भी करता है। राज्य की अन्य चीनी मिलें इनके द्वारा उत्पन्न शीरा शराब कारखानों को बेच देती हैं। मिल के अधीन धोलपुर में एक ग्लास फैक्ट्री भी कार्यरत है जिसमें काच का सामान व बोतलें आदि बनाई जाती हैं।

(iii) **श्री केशोरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड (बूंदी)-** सहकारी क्षेत्र की इस मिल की सहकारी स्थापना 1970 में की गई। यत्रा उत्पादक कृषक इसके सदस्य हैं। अतः इस मिल का एक उद्देश्य गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करना है।

3. "युक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material)" राज्य की अधिकतर चीनी मिलें चीनी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने का प्रयोग करती हैं लेकिन गगानगर शुगर मिल में चुकन्दर से भी चीनी बनाई जाती है। राजस्थान यत्रा उत्पादन की दृष्टि में देश व अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। यहां कुल कृषिक्षेत्र में 1 प्रतिशत से भी कम भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन सम्पूर्ण भारत का लगभग 1 प्रतिशत है लेकिन मानसून की अनिश्चितताओं के कारण राज्य के ज़रा उत्पादन में भी उठा-चटाव होता रहता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन मुख्यतः कोटा बूंदी भरतपुर, गगानगर, उदयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिलों में होता है। अग्रलिखित में विान् कुल वर्षों का यत्रा उत्पादन की दरशांका ज्ञात है

गन्ने का उत्पादन : लाख टन में			
वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1950-51	4.14	1980-85	13.76
1951-58	4.48	1985-88	10.10
1956-61	4.91	-	-
1961-66	7.54	-	-
1966-67	3.93	-	-
1967-68	3.12	1989-90	7.16
1968-69	5.24	1990-91	12.01
1969-74	12.82	-	-
1974-79	21.49	1996-97 अंतिम	12.00
1979-80	11.50	1997-98	11.59
		1998-99 (संभावित)	9.54

Source: Eighth Five year plan 1992-97 Govt. of Raj. & Economic Review 1997-98, Raj.

उपर्युक्त तालिका के विरलेषण से ज्ञात होता है कि-

(i) राज्य के गन्ना उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते रहे हैं। 1967-68 के पश्चात् गन्ना उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई और 1979 में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। इसके पश्चात् गन्ना उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते रहे हैं।

(ii) गन्ने का उत्पादन मुख्यतः वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस वर्ष राज्य में वर्षा अच्छी हो जाती है, गन्ने का उत्पादन भी अधिक होता है लेकिन वर्षा के अभाव में गन्ने का उत्पादन भी कम होता है।

(iii) गन्ने का उत्पादन इसके मूल्य से भी प्रभावित होता है। राज्य की मिलें अपनी क्षमता के अनुसार ही गन्ना खरीदती हैं अतः जिस वर्ष राज्य में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन होता है तो कृषकों को बाध्य होकर कम मूल्य पर गन्ना बेचना पड़ता है। 1979 में राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप कृषकों को बहुत कम मूल्यों पर गन्ना बेचना पड़ा। इस प्रवृत्ति के कारण भी गन्ने की खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(iv) राजस्थान में सिंचाई साधनों का विस्तार कटके गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। 1951, 1956 और 1961 की तुलना में विगत कुछ वर्षों में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन हुआ है। इसका प्रमुख कारण राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना है। राजस्थान नहर परियोजना के पूर्ण हो जाने पर गन्ने के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की सम्भावना है।

(4) राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) गन्ना चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। यह ऐसा पदार्थ है जो निर्माण

प्रक्रिया में अत्यधिक भाग खो देता है। लगभग 10 टन गन्ने से 1 टन चीनी का उत्पादन होता है। इसका भार अधिक होता है। अतः इसे अधिक दूरी तक लाना-ले जाना अनार्यक होता है। गन्ने को काटने के पश्चात् चीनी बसाने के लिये इसका प्रयोग भी शोध करना पड़ता है, क्योंकि काटने से एक दिन के पश्चात् ही इसमें उपलब्ध रस की मात्रा में कमी प्रारंभ हो जाती है। यही कारण है कि चीनी मिलें मुख्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आस-पास ही स्थापित की जाती हैं। राज्य की चीनी मिलें मुख्यतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई हैं। श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर आदि जिलों में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन होता है। चीनी मिलों को ईंधन घुना-पत्थर व सल्फर आदि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। राज्य के चीनी मिल क्षेत्रों में जनसंख्या भी पर्याप्त है अतः चीनी मिलों को सस्ते श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। गन्ने की खेती के कर्षकों में भी अनेक व्यक्ति सतम्न हैं। विगत कुछ वर्षों में राज्य में चुकन्दर की खेती भी होने लगी है। चीनी मिल क्षेत्रों में जल पूर्ति व बैकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं और ये क्षेत्र देश व विदेश के प्रायः सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों से तोतगायी परिवहन के साधनों के द्वारा जुड़े हुए हैं। अतः इन मिलों द्वारा उत्पन्न चीनी को देश एवं विदेश की मण्डियों तक पहुँचाया जा सकता है। स्वयं राजस्थान चीनी का बहुत बड़ा उपभोक्ता है। अतः चीनी मिलों द्वारा उत्पन्न चीनी का आसानी से विक्रय हो जाता है। राज्य में विद्युत शक्ति की पर्याप्त सुविधा है लेकिन कचला अन्य राज्यों में भगवाना पड़ता है।

4. चीनी उद्योग का उत्पादन (Production) राज्य की चीनी मिलों द्वारा मुख्यतः चीनी एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब तालिका में राज्य की चीनी मिलों के उत्पादन को दर्शाया गया है।

राजस्थान में चीनी का उत्पादन			
(हजार मीट्रिक टन)			
वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1985	19.6	1990	13.27
1986	-	1997	26.37
		1998	28.69

Source: Eighth Five year plan 1992-97 Govt. of Raj. & Economic Review 1997-98, Raj.

उपर्युक्त तालिका के विरलेषण से ज्ञात होता है कि

(i) 1984 के पश्चात् राजस्थान में चीनी के उत्पादन में कमी हुई। 1987 में चीनी का उत्पादन विगत कुछ वर्षों की तुलना में अधिक रहा लेकिन 1988 में चीनी के उत्पादन में अत्यधिक कमी हो गयी। इसके पश्चात् चीनी के उत्पादन में पुनः तीव्र गति से वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया। वस्तुतः चीनी का

उत्पादन वर्षा का प्रवृत्ति और बड़े के उत्पादन का मात्रा पर निर्भर करता है। गन्ने के उत्पादन में उतार चढ़ाव के साथ-साथ चाना के उत्पादन में भी कमी अथवा वृद्धि होता रहता है।

(ii) राजस्थान में चानी के उत्पादन के साथ-साथ शराब व मिश्रित का उत्पादन भी किया जाता है। यह कार्य मुख्यतः गंगानगर शराब मिल्स द्वारा किया जाता है। इस मिल्स के द्वारा शराब बनाने के अनेक कारखाने मंचालित किये जाते हैं।

6 गन्ना एवं चोनी का आयात व निर्यात (Import & Export) राज्य चाना मिलों द्वारा मुख्यतः अपने-अपने क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दूरी में गन्ने का परिवहन करना अनर्थिक होता है। राज्य का चाना मिन चानी की सम्पूर्ण आवश्यकता का पूर्ण नहीं कर पाता है अतः राज्य का चोनी का भाग का पूर्ति हेतु अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। विगत कुछ वर्षों से गंगानगर क्षेत्र कांठा व दूध क्षेत्र तथा बांसवाड़ा व उदयपुर क्षेत्रों में मिचाई का पर्याप्त सुवर्ण एरान के कारण गन्ना एवं चुकन्दर का पर्याप्त खेती हान लग है। भविष्य में राज्य का गन्ना एवं चुकन्दर उत्पादन में वृद्धि हान का सम्भावना है।

7 राजस्थान में चोनी उद्योग का समस्याये व समाधान (Problems & Solutions)

(i) गौण पदार्थों का उपयोग (Use of Minor Products) राज्य का चाना मिला में प्राप्त शराब का प्रयोग शराब व मिश्रित बनाने तथा खाई का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दमूत खाई का प्रयोग कागज स्टा बर्ड तथा खाद बनाने में किया जाना चाहिये। इन कार्यों के लिए पृथक् कारखाना का स्थापना की जा सकती है। लेकिन राज्य में पत्रों का अभाव का कारण है। यह कार्य अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। अतः राज्य का चाना उद्योग को सहस्रक कारखानों का स्थापना का पदार्थ सम्भावना विद्यमान है।

(ii) सरकार नियंत्रण एवं नीति (Govt Control & Policy) स्वतंत्रता के पश्चात् सन् 1947-1949-1954-58 तथा 1961-62 के वर्षों का छठका प्रथम 19 वर्षों में चाना पर प्रायः पूर्ण अथवा आंशिक नियंत्रण रहा है। चाना पर अन्तराष्ट्रीय नियंत्रण के फलस्वरूप चाना उत्पादन में कुछ समय के लिए रुकावट आता है। लेकिन इनमें अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाते हैं। वस्तुतः इस समस्या के समाधान हेतु एक निश्चित एवं तात्कालिक नीति का निर्माण किया जाना चाहिये। सरकार चाना के मूल्य पर नियंत्रण रखती है। जबकि गुड व खादमाल पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगा है। अतः इन दोनों उद्योगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती है। सरकारी नियंत्रण के कारण चाना के

मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पाती। वास्तव में इस समस्या का समाधान हेतु एक उचित नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।

(iii) गन्ना उत्पादन एवं मूल्य सम्बन्धी समस्या (Problems of Relation Between Sugarcane Production and Price) जिस वर्ष राज्य में गन्ना का उत्पादन होता है तो गन्ने का उत्पादन भी अधिक होता है। जिस वर्ष वर्षा कम रहती है तो राज्य में गन्ने का अभाव हो जाता है। राज्य में कम गन्ना उत्पन्न होने पर चोनी मिला को गन्ने का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। जबकि गन्ने का अधिक उत्पादन होने पर कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सन् 1977-78 में राज्य में गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप कृषकों का कम मूल्य प्राप्त करना पड़ा। वस्तुतः सरकार को गन्ने का नियंत्रण मूल्य निर्धारण कर देना चाहिये जिससे न तो कृषकों का और न चाना मिला का हानि उठाना पड़े।

(iv) कम उपभोग (Low Consumption) राज्य में चोनी का प्रतिव्यक्ति उपभोग लगभग 5.00 किलोग्राम है। यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसके लिए गुड व खादमाल के स्थान पर चाना के उपभोग का प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

8 भावी सम्भावनाएँ (Future Prospects) राज्य का सभा चाना मिलों द्वारा क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के पश्चात् भी राज्य का सम्पूर्ण गन्ने के उत्पादन का दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त चोनी मिला की स्थापना की जा सकती है। इससे न केवल चोनी के उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि हज़ारों व्यक्तियों का रोजगार भी प्रदान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य में चुकन्दर का खेती का सम्भावना पूर्वक प्रयोग किया जा चुका है। यहाँ का भूमि एवं जलवायु चुकन्दर का खेती के लिए लाभदायक है। अतः चुकन्दर के उत्पादन में होने वाला हान वृद्धि का सम्भवतः रूढ़न हुए राज्य में नई मिला का स्थापना का प्रस्ताव सम्भावना विद्यमान है। राज्य सरकार को चुकन्दर का खेती के लिए विशेष कार्यक्रम अधिधान चलाने चाहिये।

वनस्पति घी उद्योग

VEGETABLE GHEE INDUSTRY

1 इतिहास एवं विकास (History & Location) भारत में वनस्पति घी का उत्पादन सन् 1950 में ही प्रारम्भ हो गया था। लेकिन राजस्थान में उद्योग का प्रारम्भ तत्पश्चात् होने में ही हुआ है। सर्वप्रथम भालगढ़ में एक वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। इसके पश्चात् तत्पश्चात् दिल्ली

उदयपुर कोटा भरतपुर, गगानगर, अलवर आदि नगरों में इस उद्योग का विकास हुआ।

2 इकाइयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में वनस्पति धी के नौ कारखाने कार्यरत हैं जो राज्य के भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और गगानगर आदि स्थानों पर स्थित हैं।

3 प्रमुख औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) राजस्थान में तिलहन व कपास की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। तिलहनो के अतर्गत सरसों, तिल, मूँगफली आदि प्रमुख हैं। कपास से प्राप्त बिनौले में भी वनस्पति धी बनाया जाता है। तिल राज्य के अजमेर-भीलवाड़ा बूंदी चित्तौड़गढ़ जालोर झालावाड़, कोटा पाली आदि जिला में पर्याप्त मात्रा में बोया जाता है। मूँगफली व बिनौला राज्य के जयपुर, गगानगर भीलवाड़ा, टोंक चित्तौड़गढ़, पाली अजमेर कोटा बूंदी आदि क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होते हैं। विगत कुछ वर्षों में सम्मों के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हुई है। अभ्रतालिका में तिलहन उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में तिलहन का उत्पादन (ताम्र टन में)			
वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1950-51	1 34	1979-80	2 51
1951-52	2 09	1980-85	7 97
1955-56	2 27	1985-86	9 12
1956-57	2 55	1986-87	8 81
1957-58	2 01	1987-88	12 56
1958-59	3 29	1988-89	19 12
1959-60	1 52	1989-90	19 45
1960-61	3 72	1990-91	23 53
1974-75	4 43	1996-97	35 24
		1997-98	32 96
		1998-99 (अनुमानित)	35 58

Source: Eighth Five year plan 1992-97 Govt of Raj & Economic Review, 1998-99 Raj

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में तिलहन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। 1987-88 के पश्चात् तिलहन उत्पादन में नोब गति से वृद्धि हुई।

4 राजस्थान में वनस्पति धी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation)

राजस्थान का वनस्पति धी उद्योग मुख्यतः भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और गगानगर में केन्द्रित है। इन जिलों में तिलहन का पर्याप्त उत्पादन होता है। अतः वनस्पति धी

उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। राज्य में प्रायः विद्युत की पूर्ति बनी रहती है। लेकिन वनस्पति धी कारखानों में जेनरेटर सैटम की व्यवस्था भी की गई है। राज्य के विभिन्न कारखानों को सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी राज्य के अनेक जिलों की अपेक्षा अधिक है। यह सभी धेर परिवहन की दृष्टि से उन्नत है और राज्य व देश की प्रायः सभी मण्डियों एवं व्यावसायिक केंद्रों से जुड़े हुए है। अतः माल का आवागमन भी आसानी से हो जाता है। इन क्षेत्रों में बीघा व बैकिंग व्यवसाय भी उन्नत है अतः वनस्पति धी उत्पन्न करने वाली औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूँजी भी आसानी से प्राप्त हो जाती है।

5 राजस्थान में वनस्पति धी का उत्पादन (Production) राजस्थान में वनस्पति धी की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः राज्य में इसका उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के वनस्पति धी उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में वनस्पति धी उत्पादन (हजार टन में)									
वर्ष	1971	1973	1985	1988	1990	1991	1992	1993	1994
उत्पादन	198	267	657	620	503	3961	2488	1484	

Source: Statistical Abstract of India 1995; Economic Review, 1998-99 Raj

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में 1985 में वनस्पति धी का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, लेकिन उसके पश्चात् धी के उत्पादन में क्रमशः कमी होती चली गई। वनस्पति धी के उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण राज्य में वर्षा की अनिश्चितता व मूँगफली व बिनौले के उत्पादन में कमी होना रहा है।

6 वनस्पति धी का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान में वनस्पति धी की मांग की तुलना में इसका उत्पादन कम होता है, अतः वनस्पति धी देश के अन्य राज्यों से तथा विदेशों से आयात किया जाता है। राज्य में वनस्पति धी मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तथा उत्तरप्रदेश आदि राज्यों से मंगवाया जाता है।

7 राजस्थान में वनस्पति धी उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions)

1 कच्चे माल का अभाव (Lack of Raw Material) राज्य के वनस्पति धी कारखानों को मूँगफली व बिनौले तेल का देश के अन्य राज्यों से आयात करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में धी उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और वे देश के अन्य राज्यों के वनस्पति धी उत्पादक कारखानों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इस

समस्या के समाधान हेतु राज्य में मूंगफली व कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ii) रासायनिक पदार्थों का अभाव (Lack of Chemicals) तेलगांधन हेतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। भारत में रासायनिक उद्योग का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है अतः राजस्थान में भी रासायनिक पदार्थों की कमी दूनी रहती है। इसमें वनस्पति घी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का समाधान रासायनिक उद्योग के विकास में ही है।

(iii) कुशल श्रमिकों का अभाव (Lack of Efficient Labour) राजस्थान में कुशल श्रमिकों का अभाव है जिससे धा उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती रहती है। राज्य के धा उत्पादक कारखाने प्रायः देश के अन्य राज्यों से कुशल श्रमिक लाते हैं। उन्हें अधिक बतन देना पड़ता है अतः वनस्पति घी लागत में वृद्धि हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उन्हें समुचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये।

(iv) घी की किस्म (Quality of Ghee) वनस्पति घी उत्पादकों का मरकाट द्वारा निर्धारित मूल्य पर हो घी का विक्रय करना पड़ता है। इससे घी उत्पादकों के लाभ में कमी आ जाती है अतः व घा की किस्म गिर जाती है। इस समस्या का समाधान हेतु वनस्पति घी के उचित मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। घी के किस्म की ग्राहकों की पदावस्था की जानी चाहिए।

(v) सहायक उद्योगों का अभाव (Lack of Sub-Industries) राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग के सहायक उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है अतः वनस्पति घी उत्पादकों का तुलनात्मक रूप में हानि उठानी पड़ती है। वनस्पति घी के निर्माण के साथ-साथ यदि साबुन आदि का उत्पादन भी किया जाए तो लाभ में वृद्धि हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य में घी के निर्माण के साथ-साथ उभर उभरती हुई महत्वपूर्ण उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए।

(vi) पूंजी का अभाव (Lack of Capital) राजस्थान में पूंजी का अभाव है अतः धा उद्योग का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा पदावस्था एवं उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इस उद्योग में पूंजी विनिवेशन हेतु विशेष प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

३. भावी सम्भावनाएँ (Future Prospects) राजस्थान में धा की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः इसके भावी

विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। राजस्थान नहर के पूर्ण हो जाने पर राज्य में मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी। वर्तमान मूंगफली उत्पादन क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। कच्चे माल के अतिरिक्त राज्य में शक्ति के साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं अतः इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है।

व खनिजों पर आधारित उद्योग Industries based on Minerals

सीमेंट उद्योग (Cement Industry)

1. इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान में चूने का पत्थर व जिप्सम पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं अतः राज्य में सीमेंट उद्योग की पर्याप्त सम्भावना विद्यमान है। स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान में सीमेंट बनाने का कारखाना सन् 1915 में बूंदी के निकट लाछेरी में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में सीमेंट उद्योग व विकास पर विशेष जोर दिया गया। अतः राज्य में अनेक सीमेंट उत्पादक इकाइयों की स्थापना हुई। 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा सवाई माधोपुर में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई। सन् 1967-1970 तथा 1974 में क्रमशः चित्तौड़गढ़ उदयपुर तथा निम्बहेड़ा में सीमेंट कारखानों की स्थापना हुई। 1981 में मोडक (काटा) में एक सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त राज्य में मिर्जा सीमेंट प्लांट भी स्थापित किए गए हैं।

2. इकाइयों की संख्या एवं उनकी स्थिति (Units & Location) सीमेंट कारखानों में प्रयुक्त माल अत्यधिक भारयुक्त होता है अतः सीमेंट कारखानों की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति स्थलों के निकट करने का प्रयत्न किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट कारखाने लाछेरी, सवाईमाधोपुर, निम्बहेड़ा, मोडक, व्यावर तथा कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। इन क्षेत्रों के आसपास चूना पत्थर व जिप्सम के बंधन भण्डार विद्यमान हैं। जैसलमेर जिले में तुलनराम की दायीं खोया खिन्सर क्षेत्रों में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का दोहन किया जा रहा है और 261-33 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन संचित पाये गए हैं। अन्वयन व आधार पर जैसलमेर जिले के खोया खिन्सर क्षेत्र में 3 ग्रेड सीमेंट संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। राजस्थान में मुख्यतः निम्नलिखित सीमेंट कारखाने कार्यरत हैं।

1. ए. सी. सी. लिमिटेड, लाछेरी (बूंदी) - यह ए. सी. सी. ग्रुप का कारखाना है जो 1915 में स्थापित किया गया

है।

(ii) सवाईमाधोपुर सीमेंट कारखाना यह कारखाना 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। यह माचू जैन समूह का है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। यह कारखाना विशुन छाप सीमेंट का निर्माण करता है।

(iii) विडला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ यह कारखाना विडला समूह का है।

(iv) चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ यह कारखाना 'रतन' ग्रुप सीमेंट उत्पादन करता है।

(v) भगतमूरी सीमेंट योडक (कोटा) यह कारखाना विडला समूह द्वारा स्थापित किया गया।

(vi) श्री सीमेंट ब्यावर यह कारखाना बागड प्रतिष्ठान का है।

(vii) जे के सीमेंट निम्हाहेड़ा यह कारखाना जे के समूह का है। इसमें उत्पादन कार्य 1982 में प्रारम्भ हुआ।

(viii) स्टा प्राइव्डम बनारस (सिरोही जिला)

(ix) श्रीराम सीमेंट श्रीरामनगर कोटा

(x) डी एल एफ विनानी आदि और भी बड़े सीमेंट मयूर स्थापित हुए हैं।

(xi) मिनी सीमेंट प्लांट्स राज्य के मिरोही नीमकायाना (सीकर) तथा बगड (अलवर) में मिनी सीमेंट प्लांट भी स्थापित किए गए हैं।

3 औद्योगिक प्रयुक्त कच्चा माल (Industrial Raw Material) सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम व चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है जिप्सम व चूने पत्थर का 1350 डिग्री सेल्सियस (650 डिग्री फारेनहाइट) की क्षमता वाली भट्टिया में उतारकर सीमेंट बनाई जाती है। अतः सीमेंट बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायुने की आवश्यकता होती है। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और राज्य में उच्च किस्म का चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यही कारण है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। लाखों स्क्वैर फीटों के सैल मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इस क्षेत्र में पाया जाने वाला चूना पत्थर सैल मिट्टी की जगह काम में लाना जाता है। जिप्सम राजस्थान के बडमर वाकनेर गणनगर जैसलमेर जागौर जागौर व पाणी भूख में पाया जाता है। चूना पत्थर राज्य के

अजमेर बागवाड़ा वृदी गिरीडगढ़ चूना जयपुर जैसलमेर बुजुन, जोधपुर बाटा नागौर घाटी सवाईमाधोपुर मोकर सिरोही व उत्तरपुर जिलों में पाया जाता है। राज्य में सीमेंट कारखानों की स्थापना चूना पत्थर क्षेत्रों के आस पास ही की गई है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट उद्योग के लिए अधिक उपयुक्त है। यहां श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है तथा चूने के पत्थर की परतें भी मोटी हैं। यहां गम्बल की जल विद्युत शक्ति भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

राज्य में जिप्सम व चूना पत्थर का पर्याप्त विनिर्माण होता है। राज्य में सीमेंट कारखानों में जिप्सम व चूना पत्थर की आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण हो जाती हैं। मेरिन सीमेंट कारखाना को कोयले का आयात करना पड़ता है। कोयला मुख्यतः मिहिर की गंगा में मगवाया जाता है। राज्य के सीमेंट कारखानों चूना पत्थर प्राप्ति स्थलों के नजदीक ही स्थापित किए गए हैं और जिप्सम की प्राप्ति राज्य के विभिन्न जिलों से हो जाती है।

वितरितरण में ज्ञात होता है कि राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है जो पित्तौड़ में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण रहा है। राज्य के अन्य सीमेंट कारखानों भा चूना-उत्पादक जिलों में ही स्थापित किए गए हैं। जिप्सम भी राज्य के विभिन्न जिलों से आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। सर्वाधिक जिप्सम गणनगर जिले से प्राप्त की जाती है। चूना पत्थर का उत्पादन तथा जिप्सम व अन्य आवश्यक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में राजस्थान में सीमेंट उद्योग का तीव्र विकास होगा।

4 राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण के कारण स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राजस्थान में चूने का पत्थर व जिप्सम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चूने का पत्थर अत्यधिक भारयुक्त होता है अतः सीमेंट कारखानों की स्थापना प्रायः उसी स्थानों पर की जाती है जहां पर चूना पत्थर निकाला जाता है। राज्य में चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योग व स्थानीयकरण का प्रमुख कारण श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना है। राज्य के अन्य सीमेंट कारखानों के स्थापना भी चूना पत्थर उत्पादन क्षेत्रों में ही की गयी है। राज्य के प्रायः सभी जिलों परिवहन व संचारों का दृष्टि से देश का प्रमुख औद्योगिक बन्दरगाह एवं मण्डिया में जुड़ हुए हैं अतः सीमेंट का आसानी से आसानी से हो जाता है। चित्तौड़गढ़ व बागड में जुड़ जाने व कारण परिवहन सुविधा में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इसमें सीमेंट का आवागमन आसानी से अधिक हो पाया है। राज्य के सीमेंट कारखानों का कार्य करने के लिए अन्य राज्य पर निर्भर

रहना पड़ता है। कोयले का आयात मुख्यतः विहार से किया जाता है। कारखानों को विद्युत-शक्ति भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान में विद्युत की पूर्ति में होने वाले उच्चावचनों से बचने के लिए सीमेंट कारखानों ने अपने विद्युत उत्पादन सैन्ट्रस भी लगा रखे हैं। राजस्थान में पर्याप्त जनसंख्या होने के कारण यस्ता श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। राज्य के प्रायः सभी जिले बीमा व बैंकिंग समस्याओं की दृष्टि से भी विकसित हैं। राजस्थान में नगौर जिले में उच्च कोटि का चूना-पत्थर उपलब्ध होने के कारण सफेद सीमेंट का कारखाना इसी क्षेत्र में केंद्रित हो गया है।

5 राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन (Production)
सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रमुख स्थान है। अग्रे तालिका में विषय कुछ वर्षों के सीमेंट उत्पादन को दर्शाया गया है।

राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन में)					
वर्ष	1985	1990	1995	1997	1998
उत्पादन	3938.70	4263.40	8459.00	8493.00	8208.00

Source: Statistical Abstract, 1986, Pp. Budget Study, 1992
1992, Economic Review 1995-96, 1997-98 & 1998-99
Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राज्य में सीमेंट के उत्पादन में 1984 से 1988 के मध्य उबार चढ़ाव आता रहा है। 1985-88 के मध्य सीमेंट का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है, किन्तु 1990 के पश्चात् इसके उत्पादन में तेज गति आई है। 1998 में सीमेंट के उत्पादन में 1990 की अपेक्षा लगभग 20 लाख टन की वृद्धि हुई। राजस्थान में मिनी सीमेंट प्लांट की कई इकाइयाँ आरम्भ की गई हैं। इनके कारण घने के पत्थर के छोटे भण्डारों का भी उपयोग सम्भव हो सका। 1 अप्रैल, 1989 से सरकार द्वारा सभी निरक्षण हटा लिए गए हैं। 1994 की नई औद्योगिक नीति से भी इस उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी।

6 सीमेंट का आयात-निर्यात (Import & Export)
राजस्थान से सीमेंट पर्याप्त मात्रा में देश के अन्य राज्यों में भेजी जाती है। राज्य में कुछ मात्रा में सीमेंट अन्य राज्यों से भी मंगाया जाता है। मार्च 1995 से 26 लाख क्विंटल निर्यात देश के अन्य राज्यों में भेजी गई तथा 1.47 लाख क्विंटल सीमेंट देश के अन्य राज्यों से आयात की गई।

7 राजस्थान में सीमेंट उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions)

(i) पूँजी का अभाव (Lack of Capital) सीमेंट कारखाने

की स्थापना के लिए अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में अन्य उद्योगों की तुलना में लाभ भी कम होता है। अतः उद्योगपति सीमेंट उद्योग में पूँजी विनियोजित नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान में पूँजी का अभाव है अतः नए कारखानों की स्थापना करना कठिन होता है। अतः राज्य में सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग में पर्याप्त पूँजी विनियोजित की जानी चाहिए। राज्य में पूँजी के अभाव को देखते हुए मिनी सीमेंट प्लांट लगाना भी उपयुक्त रहेगा। इन कारखानों में अपेक्षाकृत कम पूँजी की आवश्यकता होती है और कच्चे माल के छोटे छोटे स्रोतों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अतः मिनी सीमेंट प्लांट्स की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ii) शक्ति का अभाव (Lack of Power) राजस्थान में कोयले का अभाव है, यहाँ कोयला मुख्यतः पश्चिम बंगाल बिहार व उड़ीसा आदि राज्यों से मंगाया जाता है। अतः कोयले पर अत्यधिक परिवहन व्यय आता है जिसके कारण सीमेंट की लागत में वृद्धि हो जाती है। परिवहन लागत में वृद्धि होने के साथ-साथ सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होती रही है। इसके अतिरिक्त, समय पर रेलवे वेगन नहीं मिलने के कारण भी राज्य में कोयले का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में सीमेंट निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। कभी-कभी कोयले के अभाव में सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो जाती है। इस समस्या के समाधान परिवहन व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करके ही किया जा सकता है।

(iii) दोषपूर्ण नीति (Defective Policy) सीमेंट के मूल्य एवं वितरण सम्बन्धी सरकारी नीति बार-बार बदलती रहती है। अतः सीमेंट उद्योग में अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। राज्य में प्रायः सीमेंट का अभाव बना रहता है। अतः उपभोक्ताओं को ऊँचे मूल्यों पर परीदनी पड़ती है। इस समस्या का समाधान एक निश्चित एवं उचित नीति के निर्माण में निहित है।

(iv) कुशल श्रमिकों का अभाव (Lack of Trained Labour) राज्य में अकुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है। अतः कुशल श्रमिकों के लिए भी अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे भी सीमेंट की लागत में वृद्धि हो जाती है। राज्य में कुशल श्रमिकों का अभाव दूर करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(v) कम उत्पादन क्षमता (Low Production Capacity) राजस्थान में अनेक सीमेंट कारखाने पुराने हैं। उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है अतः सीमेंट के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान

हनु पुराने भीमेट वारखानो का भीनीवरण बिगा जाना चाहिए एवं उसरी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

8 भावी सम्भावनाएँ (Future Prospects) याम्थान में सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि इसरी माध में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यहा पर नूने का पथर जिप्सम तथा जलशक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान में नील और मिनी सीमेंट प्लांट लगाये जाये वे प्रस्ताव आवे है। इनमे से दो प्रस्ताव इण्डियन बैमिन्ग्स इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली के है और एक अन्य मैसर्स जयन्तीलाल तातास्ट शाह का है। इण्डियन कैमिक्स ने अपने प्लाण्ट क्रमशः भिडाडी और आनूराड में लगाने का प्रस्ताव किया है। इन दोनों की क्षमता नौ नौ हजार टन वार्षिक रहने की योजना है। मैसर्स शाह अपना प्लाण्ट किवासी में लगाना चाहते है जिसकी वार्षिक क्षमता 50 हजार टन रहने का कार्यक्रम है। मैसर्स केसर सीमेंट का उदयपुर जिले का एक प्रस्ताव भी है जिसकी क्षमता 20 हजार टन वार्षिक रहने की योजना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा रूनिब विकास निगम के नाम 5 मिनी सीमेंट प्लाण्ट के लिए आशय पत्र जारी किये जा चुके है। यह प्लाण्ट क्रमशः जयपुर पाली जोधपुर सीकर तथा मिरौली जिलों में लगाये जायेगे। राजस्थान में छठा सीमेंट वारखाना भगलम् सीमेंट लिमिटेड के नाम से कटा रो 70 कि०मीटर दूर मोहक में स्थापित हो चुका है और इसमे 1 मार्च 1981 से उत्पादन भी आरम्भ हो गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। इसका निर्माण कार्य रिवाड समूह अर्थात् 24 महीनों में पूरा हुआ और इस पर 24 करोड़ रुपये लागत आई है। निम्न कुछ वर्षों में अनेक नई सीमेंट इकाइयों की स्थापना हुई है और विद्यमान उत्पादन क्षमता का भी विस्तार हुआ है।

नमक उद्योग

Salt Industry

1 इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान में यात्री रेनारा भरतपुर तथा लूणी और लूणकरण आदि स्थानों पर देशी तरीके से नमक उत्पन्न किया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा साभर पापदरा 7 डीडवाना में आधुनिक तरीके से नमक उत्पादन सन् 1887 में आरम्भ हुआ। नमक उद्योग राज्य के बड़े उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख स्थान है। यह देश का नमक उत्पादन का लगभग 10% नमक उत्पन्न किया जाता है। भारत में यह उद्योग एक प्रकार की धनी के समान है। यहाँ अजला खारे कओ व जल की कमीयों में एकरा रर किया जाता है।

पानी को भाप बनकर उड़ जाता है और पपडी के रूप में गढ़ा नमक रह जाता है जिसे नमक वारखाना में शुद्ध कर दिया जाता है। शुद्ध नमक का उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है जबकि अशुद्ध नमक का उपयोग पशुओं व अन्य कार्यों के लिए किया जाता है।

2 इकाइयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में छारे पानी की पीतें है जिनमे नमक बनाया जाता है। राज्य के नमक वारखाने सार्वजनिक व निजी दोनों ही में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वारखाना डीडवाना पापदरा व साभर में है। कुतामन 7 फलोदी सुजानगढ़ पोवरण आदि में छोटे आकार के वारखाने निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। राज्य के कुल नमक उत्पादन का लगभग 70% भाग सार्वजनिक क्षेत्र से व शेष निजी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी साभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है।

3 औद्योगिक वच्चा माल (Industrial Raw Material) राजस्थान में नमक प्राप्ति के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं।

(i) साभर झील (Sambhar Lake) यह राज्य का सबसे बड़ा नमक स्रोत है। यह राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत नमक उत्पन्न किया जाता है। यह नगर आधुनिक मशीनों से सहायता में चलाया जाता है। यह उद्योग जिसमें नमक का उत्पादन किया जाता है साभर नील जयपुर जोधपुर रेनमार्ग पर जयपुर में लगभग 60 कि०मीटर पश्चिम में स्थित है। इस झील में 65 मिलियन टन नमक लेने का अनुमान है। यह नगर उत्पादन का कार्य साभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में 1964 में की गई। इस प्रतिष्ठान के नियंत्रण में 4200 हेक्टेयर भूमि है।

(ii) पंचपदरा झील (Pachpadra Lake) जाधपुर से लगभग 128 कि०मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित इस झील का विस्तार लगभग 83 वर्ग कि०मी है। यह लगभग सम्पूर्ण पौसाजी आदि स्थान पर नमक का संचयन है। यह का नमक समुद्री नमक के समान होता है। यह उत्पन्न करने के लोग नमक बनाने का कार्य करते हैं।

(iii) डीडवाना झील (Didwana Lake) यह साभर साभर में लगभग 50 कि०मीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 10 वर्ग कि०मी है। यह नमक बनाए गए है। यह नमक उत्पादन का कार्य निम्न

संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें देवल के नाम से जाना जाता है। नमक उत्पादन का कार्य पुराने तरीकों से किया जाता है। यह क्षेत्र नमक उत्पादन की दृष्टि से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नमक उत्पादन की लागत अन्य क्षेत्रों से कम आती है।

(iv) पोकरण झील (Pokaran Lake) - यह उत्तम किस्म का नमक प्राप्त होता है जो कि देश के प्राय सभी भागों में भेजा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 6000 टन नमक तैयार किया जाता है।

(v) फत्तौदी झील (Phalodi Lake) इसी झील में प्रतिवर्ष में लगभग एक लाख टन नमक का उत्पादन होता है।

(vi) कुचामन झील (Kuchaman Lake) यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 12000 टन नमक का उत्पादन होता है।

(vii) सुजानगढ़ झील (Sujanagar Lake) इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 24000 टन नमक प्राप्त होता है।

4 राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के नमक कारखाने (Public Sector Salt Industries)

(i) राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री) इस कारखाने की स्थापना 1968 में की गई। यहाँ सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग चमड़े व रमाई उद्योग में किया जाता है।

(ii) राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) इस कारखाने की स्थापना सन् 1964 में की गई। यहाँ कूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है जिसका उपयोग सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री द्वारा किया जाता है।

(iii) राजस्थान सरकार साल्ट्स वर्क्स, डीडवाना - इस कारखाने की स्थापना सन् 1960 में विभागीय उपक्रम के रूप में की गई। यहाँ मुख्यतः चार प्रकार का नमक बनाया जाता है (1) खाद्य नमक (2) अखाद्य नमक (3) औद्योगिक नमक (4) आयोडिन-युक्त नमक

(iv) राजस्थान सरकार साल्ट्स वर्क्स, पंचपदरा - इस कारखाने की स्थापना 1960 में की गई। इस कारखाने में भी खाद्य-अखाद्य औद्योगिक तथा आयोडिन युक्त नमक तैयार किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में नमक का उत्पादन साभर झील, पंचपदरा व डीडवाना में किया जाता है। निम्न क्षेत्र में फत्तौदी, पोकरण, कुचामन सिटी और सुजानगढ़ इसके प्रमुख स्थान हैं। कुचामन, फत्तौदी और सुजानगढ़ में कुओं

से भी नमक प्राप्त किया जाता है।

(5) नमक उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राज्य की खारे पानी की झीलें राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में केन्द्रित हैं। अतः नमक उद्योग का विकास भी इस क्षेत्र में हुआ है। इस क्षेत्र में नमक उद्योग के अन्तर्गत कार्य करने वाले विशेष प्रकार के श्रमिक भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इन खारे पानी की झीलों में वर्षा का जल एकत्रित होता है, वह प्रतिवर्ष नमक के नए भण्डार अपने साथ बहाकर लाता है। अतः ये क्षेत्र नमक के अक्षय भण्डार कहे जा सकते हैं। फलस्वरूप नमक उद्योग का भावी विकास इन्हीं क्षेत्रों में केन्द्रित रहेगा।

6 राजस्थान में नमक का उत्पादन (Production) निम्न तालिका में राजस्थान के नमक उत्पादन को बताया गया है।

राजस्थान में नमक उत्पादन					
	(लाख टन)				
वर्ष	1985	1990	1993	1997	1998 (अंश)
उत्पादन	10.92	10.55	14.23	12.00	11.00
1 Statistical Abstract 1988 Ref. Budget Study 1992 2 Economic Review 1995-96 & 1998-99 Rajasthan					

राजस्थान का सर्वाधिक नमक साभर झील से प्राप्त होता है। साभर का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है।

7. नमक का आयात-निर्यात (Import & Export) मार्च, 1995 में 3.9 लाख क्विंटल नमक अन्य राज्यों को भेजा गया तथा देश के अन्य राज्यों में 0.14 लाख क्विंटल नमक आयात किया गया।

8 नमक उद्योग की समस्याएँ व सुझाव (Problems & Suggestions)

(i) वर्षा (Rain) नमक उद्योग के लिए कम व अधिक वर्षा, दोनों ही हानिकारक हैं। राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति रहती है। इस कारण नमक का उत्पादन भी सूखे की इस स्थिति से प्रभावित होता रहा है।

(ii) परिवहन (Transport) राजस्थान नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर उत्पादित नमक को विभिन्न राज्यों में भेजना होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में परिवहन सुविधाओं के अभाव से नमक को नियमित रूप से भेजे जाने में असुविधा अनुभव की जाती है। समस्या के समाधान के लिए नमक उत्पादन क्षेत्रों को रेल व सड़क मार्गों से जोड़ना चाहिये तथा पर्याप्त मात्रा में वैगन उपलब्ध कराए जाने चाहिये।

(iii) निश्चित नीति का अभाव (Lack of Firm Policy) राजस्थान सरकार ने नमक उद्योग के विकास के लिए कोई भी भू-संरचना निर्धारित नहीं की है। इस कारण नमक के स्रोतों का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस उद्योग में लगे कर्मचारियों में भी निरन्तर असंतोष की स्थिति बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि इस उद्योग के विकास के लिए कोई निश्चित कार्ययोजना निर्धारित करें।

(iv) लीज की प्रवृत्ति (Lease Tendency) नमक उत्पादन करने वाले मार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों को निजी क्षेत्र को लीज पर उपलब्ध कराया जाता है। निजी क्षेत्र द्वारा समय पर लीज का भुगतान नहीं करने से उद्योग के समक्ष वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है और उसे उत्पादन बंद करना होता है या उसे स्थगित करना पड़ता है। अब लीज पर दिये जाने की प्रवृत्ति की समीक्षा कर इसमें विद्यमान दोषों को दूर किया जाना चाहिये।

काँच उद्योग

Glass Industry

1. इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान में छोटे पैमाने पर काँच का सामान जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जोधपुर आदि स्थानों पर समय-समय में किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर काच का सामान धौलपुर के कारखानों में बनाया जाता है। राज्य में काँच बनाने में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न कच्चे पदार्थों का आहृत्य है। अतः राज्य में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

2. इकाइयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) काँच का सामान जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, पाली व बीकानेर आदि स्थानों पर बनाया जाता है। राज्य में काँच उद्योग की दो इकाइयाँ कार्यरत हैं।

(i) धौलपुर ग्लास वर्क्स यह कारखाना निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसमें 90 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित की गई है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष लगभग 1000 टन काच के सामान का उत्पादन किया जाता है। इसमें 800 से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है। यहाँ मुख्यतः काँच की बोतलें बनाई जाती हैं।

(ii) दी हाईटेक्नीकल प्रोसीजर ग्लास वर्क्स, धौलपुर यह कारखाना 50 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी से मार्जिनल क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपये है। कारखाने में काच के सामान का उत्पादन मार्च 1964 में किया जा रहा है। यहाँ

मुख्यतः बोतलें, बीकर्स, बॉयलर्स, कवर ग्लास व फ्लैस्क आदि का निर्माण किया जाता है। 1965-66 के औद्योगिक मर्ष के कारण कारखाने को 1967 में बन्द करना पड़ा, लेकिन 1968 में इसे पुनः चालू कर दिया गया। वर्तमान में यहाँ 750 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

3 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) काँच का सामान बनाने के लिए बालू मिट्टी, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ एवं शक्ति के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। बालू मिट्टी अत्यधिक भारी होती है। अतः काँच के कारखाने मुख्यतः बालू मिट्टी के प्राणस्थलों के नजदीक ही स्थापित किए जाते हैं। काच का सामान बनाने के लिए श्रेष्ठ किस्म की बालू की आवश्यकता होती है। राजस्थान बालू मिट्टी उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक धनी है। राज्य के जयपुर, बीकानेर, गूदी धौलपुर आदि जिलों में श्रेष्ठ किस्म की बालू मिट्टी पायी जाती है। काच का सामान बनाने के लिए बालू मिट्टी को 1600 सेटीग्रेड से 1650 सेटीग्रेड ताप पर पिघलना पड़ता है। अतः पर्याप्त विद्युत-शक्ति अथवा कोयले की आवश्यकता होती है। राज्य में कोयले का आयात मुख्यतः बिहार से किया जाता है। काच बनाने में सोडा मिट्टी, सोडा सल्फेट और शोरे की आवश्यकता होती है। ये वस्तुएँ मुख्यतः राज्य के रेगिस्तानी जिलों से प्राप्त हो जाती हैं। राज्य में चूने का पत्थर चित्तौड़गढ़, लाखेरी तथा सवाईमाधोपुर में बहुतायत से पाया जाता है।

4 राजस्थान में काच उद्योग के स्थानीयकरण के कारण स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राज्य का काच उद्योग मुख्यतः धौलपुर में केन्द्रित है। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में श्रेष्ठ किस्म की बालू मिट्टी पाया जाना है। यह शहर परिवहन की दृष्टि से भी उन्नत है और राज्य के प्रायः सभी प्रमुख केन्द्रों से जुड़ा हुआ है। धौलपुर के कारखानों का कुशल श्रमिक भी आगरा से प्राप्त हो जाते हैं। आगरा शहर की विभिन्न जातियाँ शानोनकाल से ही काँच का सामान बना रही हैं। वही लोग इस कार्य में प्रवीण हैं। काँच का सामान बनाने में काम आने वाली वस्तुएँ भी राज्य के विभिन्न भागों से आगामी से प्राप्त हो जाती हैं। कोयला मुख्यतः बिहार की खानों से मंगाया जाता है।

5 राजस्थान में काँच उद्योग का उत्पादन (Production) धौलपुर ग्लास वर्क्स में प्रतिवर्ष लगभग 1000 टन काँच का सामान तैयार किया जाता है। दी हाईटेक्नीकल प्रोसीजर ग्लास वर्क्स धौलपुर में 1968-69 में 65 लाख कोयले का उत्पादन किया।

6 कौच के सामान का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान से कौच का सामान देश के विभिन्न राज्यों को भेजा जाता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार कौच का सामान देश के विभिन्न राज्यों से आयात किया जाता है। सन् 1987 में 613 क्विंटल कौच का सामान देश के विभिन्न राज्यों में भेजा गया तथा देश के विभिन्न राज्यों में 524 क्विंटल कौच का सामान आयात किया गया।

7. राजस्थान में कौच उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions) राजस्थान में कौच का ज्ञान बनाने सम्बन्धी विभिन्न दस्तुनें पर्याप्त मात्रा में पायी जाती हैं फिर भी राज्य में इस उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। राज्य में पूँजी का अभाव इसका प्रमुख कारण है। अतः राज्य सरकार को इस उद्योग में पूँजी विनियोजित करनी चाहिए तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों को पूँजी विनियोजन हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस उद्योग में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। राज्य में कुशल श्रमिकों का निम्न अभाव है अतः कुशल श्रमिकों की उपलब्धि हेतु प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य के दोनों कौच उत्पादक कारखानों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है और इनकी प्लांट तथा मशीनरी भी अत्यधिक पुरानी है। अतः इन त्तराज्यों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए तथा इनकी क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

सगमरमर उद्योग (Marble Industry)

1 परिचय (Introduction) मकराना में उपलब्ध सगमरमर अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में इटली के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ का सगमरमर देश के हर हिस्से में जाने के साथ विदेशों को भी निर्यात किया जाता रहा है। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोमों खड़ी पहाड़ियों में सगमरमर के अथाह भण्डार मौजूद हैं। नवीं शताब्दी में निर्मित सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के अलावा अपनी वास्तुकला से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल व कलकत्ता का प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल में तथा मॉरिल इसी मकराना की ही टहन है। मकराना क्षेत्र में गुनावटी, धौली, डूंगरी, काली डूंगरी व कुमारी पहाड़ियों में प्रमुख मिलने वाले सगमरमर की लगभग सैकड़ों खानों में पाया जाने वाला यह सगमरमर तीव्र तरफ का होता है। इसमें 45 प्रतिशत स्फेट, इतना ही मुसानी व शेष 10 प्रतिशत सगमरमर बरतल होता है। मकराना कच्चे में लघु व मध्यम श्रेणियों के उद्योग स्थापित हैं। इनमें पच्चीस हजार श्रमिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत

हैं। इस उद्योग में 2 आब 13 करोड़ से अधिक की पूँजी विनियोजित है तथा इस उद्योग में मरारर की विक्री कर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व सॉपल्टी के रूप में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आय होती है। मकराना में सगमरमर की चिराई, पॉलिशिंग का काम बहुतायत से होता है जिससे ऐतिहासिक स्मारकों व मूर्तियों के निर्माण में सगमरमर का काम करी बढा है। सगमरमर के निर्यात सबर्द्धन की करी सभाबनाएँ मौजूद हैं और सरकार की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को विकास के लिए बनाई गई नीतियों से मकराना के इस खनिज उद्योग को बत मिलेगा। वहाँ के मार्बल उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए एक मार्बल मण्डी की परिकल्पना की गई है, जिसका प्रारूप बनकर तैयार है।

2 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) - सगमरमर ब्लॉक्स इस उद्योग का कच्चा माल है। ब्लॉक्स की शक्ति मुख्यतः मकराना, भैंसलाना व राजनगर में होती है। इस उद्योग में पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर उद्योग को मस्ते श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अन्न तालिका में सगमरमर ब्लॉक्स के उत्पादन की दर्शाया गया है

सगमरमर ब्लॉक्स का उत्पादन		
वर्ष	उत्पादन (इजा टन)	कैरेट (कैरेट)
1985	712.80	1130391.70
1990	949.00	557494.00
1993-94	1875.40	1923327.68
1994-95	2324.24	2407899.39
1995-96	2840.08	3099884.00

1. Statistical Abstract, 1988, Ray Budget Study, 1992-93.

3 सगमरमर उद्योग के स्थानीयकरण के कारण / स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) मकराना की खानों से सगमरमर प्राचीनकाल से प्राप्त किया जाता रहा है अतः इन खानों से सगमरमर सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन भैंसलाना व राजनगर में सगमरमर की खानों की खोज के परभाव कच्चे माल की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। यह उद्योग मुख्यतः मकराना व किरानाड में केन्द्रित है। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मकराना से इस उद्योग की किरानाड की ओर आने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। विगत कुछ वर्षों में भी किरानाड में अनेक डायमण्ड कटर-मशीनों की स्थापना की जा चुकी है। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण सगमरमर की एक बड़ी मण्डी के रूप में विकसित होता जा रहा है।

1. Statistical Abstract, 1988, Ray Budget Study,

4 सगमरमर का उत्पादन (Production) सगमरमर ब्लाक्स को चोरने व निर्यात करने के पश्चात् अनेक प्रकार की इमारती वस्तुओं (सामान) का निर्माण किया जाता है। सगमरमर से अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुएँ भी बनाई जाती हैं। सगमरमर उद्योग द्वारा सगमरमर ब्लाकम का उपयोग कच्चे उपयोग में लाये जाने वाला वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उनमें निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सगमरमर स्लैब प्रमुख है।

5 सगमरमर का आयात निर्यात (Import & Export) सगमरमर से बनी वस्तुओं का देश एवं विदेश के अनेक भागों को निर्यात भी किया जाता है।

6 सगमरमर उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions) राज्य में पूँजी का अभाव उद्योग के विकास में बाधक रहा है। पूँजी के अभाव के कारण उच्च तकनीकी मशीनों का प्रयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है इस उद्योग में शोध एवं अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है इस उद्योग द्वारा मुख्यतः मोटर परिवहन का उपयोग किया जाता है। समय पर माटर गाड़ियाँ की प्राप्ति न होने के कारण माल के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। टक यूनिट एवं मालिकों के मध्य भाड़े को लेकर प्रायः विवाद की स्थिति बनी रहती है इस उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षित श्रमिकों का भी अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। उद्योग के पर्याप्त विकास हेतु विदेशी पूँजी को आकर्षित किया जाना चाहिये परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये तथा सरकारी स्तर पर शोध एवं अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग्रेनाइट उद्योग Granite Industry

राजस्थान के बाहर जिलों में 1120 मिलियन घन मीटर ग्रेनाइट का भण्डार पाये गये हैं। इनके रंग आकार तथा गुण भिन्न भिन्न हैं। कुछ ग्रे व डिजाइन तो इतने आकर्षक हैं कि मन को मोहित कर देते हैं। जैसे माकलमर (वाडम) रायल ग्रे (अजमेर) पैपर पिंक हरमोरा (अलवर) लहरिया पिंक जेसरा ग्रे (भीलवाड़ा) ग्रीना पिंक-एरा ग्रे तथा गज्ज पिंक (जालौर) सरीना कनामिक-शेलावटी पिंक व इपीगियन रैड (भाऊर डुडुन) गाल्ड येलो एवं सनप्लावर (गान्धी) गिल्वर एवं प्यटिनम वाइट (पिप्लोहा) लकी मन्टी रेड व मानपुरा ग्रे (टाक) आदि प्रमुख हैं।

राजस्थान में ग्रेनाइट का विशाल भण्डार है लेकिन अभी तक मात्र 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक (कुल

ग्रेनाइट भण्डार का) ही खनन हेतु उपयोग हो रहा है। यह राजस्थान के लिए एक विकासशील उद्योग है। आशा है कि अगले 10 वर्षों में राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर का सर्वोत्तम बाजार तैयार हो जायेगा और ग्रेनाइट टाइलों के अलावा ग्रेनाइट से निर्मित अन्य सामान का भी निर्माण होने लगेगा।

राजस्थान में हाल ही में ग्रेनाइट खनन के पट्टों के आवंटन की नयी नीति तैयार की गयी है। इसके तहत पट्टे उन्हीं को दिये जाने का श्रवधान है जो खनन के साथ साथ चोरने एवं पॉलिशिंग करने के उद्योग भी स्थापित करेंगे। खान एवं भू विज्ञान निदेशालय ने निर्धारित नीति के तहत ही खनन पट्टों का आवंटन किया है और आशा की जाती है कि इस उद्योग में 350 करोड़ रुपये से भी अधिक पूँजी का विनियोजन होगा। इसमें निर्यातमुखी व्यवसाय को अधिक प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रेनाइट के खनन एवं पॉलिशिंग का काम करने की एकीकृत परियोजनाओं की स्थापना का काम राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (रेको) के माध्यम से किया जायेगा।

ग्रेनाइट प्रसस्करण (प्रोसेसिंग) उद्योग

राजस्थान में लगभग 215 करोड़ रुपये की लागत में दस ग्रेनाइट प्रसस्करण (प्रोसेसिंग) परियोजनाएँ लगाने के समझौते बड़े उद्योगपतियों से किये गये हैं। दूरा पर अभी तक ग्रेनाइट उद्योगों के जरिये 45 करोड़ रुपये के पूँजी विनियोजन का काम हुआ है। इनमें नौ ब्लाक काटने की नौ गोला आरी की तथा 3000 टाइल बनाने के कारखाने हैं।

राजस्थान में वर्तमान में ग्रेनाइट टाइल व ब्लाक काटने आदि के लगभग 1000 उद्योग कार्यरत हैं। ये उद्योग शाहपुरा (जयपुर) सीकर मदनगढ़ (किशनगढ़) एवं ध्यावर (अजमेर) उदयपुर डुडुन जालौर चित्तौड़ भीलवाड़ा बोरवड एवं मकराना (नागौर) जयपुर आदि स्थानों पर कार्यरत हैं। इनमें से अधिकतर उद्योग राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राजस्थान के राजमार्ग पर हैं तथा ये ग्रेनाइट के मुख्य बाजारों तथा देश के बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान वित्त निगम रोका तथा वाणिज्यिक बैंक इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं जिस पर ये नियमानुसार ब्याज लते हैं। इन उद्योगों का विद्युत पानी एवं कैल्सियम तेल की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

राजस्थान में पहली स्वदेशी ग्रेनाइट गैंगसा मशीन का 125 दिन तक सफल परीक्षण किया गया है। इससे देश को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इस भारतीय ग्रेनाइट गैंगसा मशीन का निर्माण भी प्रतिशत भारतीय पूँजी और माल

मे किया गया है। इस गैस का इकाई लगाने वाले उद्यमियों का काम और पैसा कभी भी आयोजित पुर्जों के इंतजार में बेकार नहीं होगा क्योंकि इस गैस के स्पेयर पार्ट्स और कम्पनिट्स भारतीय बाजार में ही उपलब्ध हैं। ग्रेनाइट के छोटी ब्लॉक या इम्प्लान्ट ब्लॉक पर परीक्षण करने पर औसत ग्रेनाइट का प्रयोग केवल 38 किलोग्राम स्टील शूट्स और केवल 1 किलोग्राम स्लैब का प्रयोग होगा। साथ ही इस गैस की कार्यक्षमता आयोजित विदेशी मशीन के समकक्ष 10 ह्वार में 12 ह्वार वर्गफीट प्रतिमाह होगी। इस मशीन की लागत लगभग 37 लाख रुपये आती है। अर्थात् कि भविष्य में इसका निर्यात किया जा सकता है।

विश्व में ग्रेनाइट पत्थरों की खपत 75 हजार करोड़ रुपये मालाना है जिसमें भारतीय निर्यात 1990-91 में 150 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1991-92 में 175 करोड़ रुपये हुआ। यह निर्यात प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रुपये का होना चाहिये।

राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का निम्नतर विकास तो हो रहा है लेकिन इस उद्योग से जुड़े हुए खनन कम्पाने दात ठेकेदार एवं उद्यमियों की अनेकानेक समस्याएँ एवं परेशानियाँ हैं।

राजस्थान में किसी केंद्र स्थान पर ग्रेनाइट उद्योग में सम्बन्धित मजदूर एवं मशीन ऑपरेटर्स तथा पत्थर की कटाई करने के मशीन ऑपरेटर्स पॉलिशिंग करने वाली मशीन के ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग को व्यवस्था साकार द्वारा की जानी चाहिये। एक प्रयोगशाला स्थापित की जाये जिसमें ग्रेनाइट पत्थर की गुणवत्ता का जांच की जा सके। इन उद्योगों की पानी बिजली और कैल्शियम तेल की समस्या का समाधान किया जाना चाहिये। कम ब्याज दर पर राजस्थान वित्त निगम तथा गरीबों द्वारा रूप उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। ग्रेनाइट में विविध प्रकार के आइटम (सामान) बनाने हेतु एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाये। वर्तमान समय में यदि सरकार द्वारा ये सुविधाएँ दिलवाई जायेंगी तो हम नान इंडोनेशिया समूह एवं अन्य अमीरत तथा गठनन समूह तथा में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इससे देश के अन्तर्गत निर्यात में हम अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि राज्य सरकार के अधिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

(स) अन्य उद्योग

OTHER INDUSTRY

ऊन उद्योग

Wool Industry

1. इतिहास एवं विकास (History & Develop-

ment) . राजस्थान में ऊन का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 48 प्रतिशत है। राज्य में लगभग 1 करोड़ भेड़ें हैं लेकिन फिर भी राजस्थान में ऊन उद्योग अधिक विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ का ऊन मोटा एवं अधिक खुरदुरा होता है। राजस्थान में ऊन की प्रमुख मण्डियाँ बीकानेर, पाली, केकड़ी, ओसियाँ और व्यावर में हैं। राज्य सरकार ने सन् 1963 में पूँचक रूप से भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना की है। जिसके अन्तर्गत 14 जिलों में भेड़ विकास कार्य चल रहा है। ये जिले हैं बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर, पाली उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, जालौर, झुंझार व जोधपुर। जोधपुर में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। जूँझपुर (जिला सीकर) में भी एक भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहा है। मानपुरा के निम्न अखिलमारा भेड़ प्रजनन केंद्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। विदेशों से उन्नत किस्म के भेड़ों भी यहाँ मगाये गये हैं। अन्तर्गत ब्रॉम-ब्रॉडिंग से देशी नस्ल को भेड़ों में सुधार हुआ है।

2. इकाइयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में ऊन उद्योग के अनेक संस्थान कार्यरत हैं। राज्य की प्रमुख इकाइयाँ निम्नलिखित हैं।

(i) स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर . यह मिल बीकानेर शहर में साकारी क्षेत्र में स्थापित की गई है। इस मिल में ऊनी धागा तैयार किया जाता है।

(ii) जोधपुर वूलन मिल्स, जोधपुर . इस मिल की स्थापना जोधपुर शहर में की गई। यहाँ ऊनी धागा, वास्तीन व कपड़न बनाए जाते हैं।

(iii) वर्स्टेड स्पिननिंग मिल्स, चूरू . यह मिल राजस्थान राज्य उद्योग निगम द्वारा चूरू में स्थापित की गई है।

(iv) वर्स्टेड स्पिननिंग मिल्स, लाडनू . यह मिल राजस्थान राज्य उद्योग निगम द्वारा लाडनू में स्थापित की गयी है।

(v) नागपाल कॉम्बिनिंग मिल्स, कोटा

(vi) राजस्थान वूलन मिल्स, बीकानेर

(vii) बीकानेर वूलन मिल्स, बीकानेर

(viii) फ्रेण्ड्स वूलन मिल्स, बीकानेर

(ix) भारत वूलन मिल्स, बीकानेर

(x) फॉरिन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट मिल्स, कोटा

राजस्थान में ऊनी कपड़ा बनाने के छः कारखाने कार्यरत हैं जिनमें से 3 कारखाने भीलवाड़ा में हैं जो कपड़न बनाने के धागे का उत्पादन करते हैं। इन कारखानों में शॉल, स्वेजर्स, ट्यूब्स आदि ऊनी वस्त्रों के लिए धागा तैयार किया जाता है। राजस्थान में उत्पादित कुल ऊनी धागे में

भीलवाड़ा की मिलों का भाग लगभग 50 प्रतिशत है। राज्य में ऊनी कपड़े के विधायन का एक भी कारखाना नहीं है अतः ऊनी कपड़े को विधायन हेतु लुधियाना व अमृतसर ले जाया जाता है। भीलवाड़ा में एक विधायन घर की स्थापना की गई है जिसकी विधायन क्षमता 6 लाख कम्बल प्रतिवर्ष है। जोधपुर में केन्द्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना की गई है अतः ऊन उद्योग का व्यवस्थित विकास हो सकेगा।

3. प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) ऊन इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है जो भेड़ों से प्राप्त की जाती है। राजस्थान में भेड़-पालन व्यवसाय अत्यधिक विकसित है। राज्य के कृषक खेती कार्य के साथ-साथ भेड़ें पालने का व्यवसाय भी करते हैं। राज्य की भेड़ों से मुख्यतः मोटे व खुरदरे ऊन की प्राप्ति होती है लेकिन ब्रेष्ठ किस्म की ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से नस्ल सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है।

राजस्थान में भेड़े मुख्यतः अवमेर, बाडमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, विरौडगढ़, गगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर व पाली जिलों में पाली जाती हैं। इन जिलों से राज्य के ऊन उद्योग को ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन का उपयोग करने हेतु बीकानेर, जोधपुर, नवलपद, कोटा, धूरु, लाडन, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर कारखानों की स्थापना की गयी है।

4. राजस्थान में ऊन उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राज्य में ऊन उद्योग का केन्द्रीयकरण मुख्यतः ऊन उत्पादक क्षेत्रों में ही हुआ है। बीकानेर, भीलवाड़ा व जोधपुर आदि स्थानों पर ऊन उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। कच्चे माल के अतिरिक्त इन स्थानों पर सस्ते श्रमिक, बीमा व बैंकिंग सुविधाएँ, परिवहन की सुविधा एवं शक्ति के साधनों की सुविधा होना है। इन क्षेत्रों में वस्त्र व्यवसाय पहले से ही उन्नत है। अतः ऊन उद्योग के लिए आवश्यक मशीनें व उपकरण तथा प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भीलवाड़ा में अन्य स्थानों की अपेक्षा ऊनी वस्त्र व्यवसाय का तेजी से स्थानीयकरण हुआ है। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से विशेषतः वस्त्र उद्योग की दृष्टि से विकसित होना है। शक्ति, जल, परिवहन तथा बीमा व बैंकिंग सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उद्योग को इस स्थान पर आन्तरिक व बाह्य दोनों ही प्रकार की बचत प्राप्त हो जाती है। भीलवाड़ा में ऊन उद्योग के विकास हेतु विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा यहाँ पर विधायन घरों की स्थापना की जानी चाहिये। वृत्तन कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी करना चाहिये ताकि ऊन उद्योग का तेजी से

विकास हो सके।

5. ऊन उद्योग का उत्पादन (Production) खादी उद्योग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ऊनी वस्त्रों का उत्पादन 1984-85 में 28.37 लाख स्क्वायर मीटर था। जिसका कुल मूल्य 17.78 करोड़ रुपये था। खादी उद्योग के ऊनी उत्पाद 1993-94 में 22.73 लाख वर्ग मीटर और इनका मूल्य 21.97 करोड़ रुपये हो रहा। इससे इस प्रवृत्ति का आभास मिलता है कि विगत वर्षों में ऊनी उत्पादों की कीमतों में कमी आयी है।

6. ऊन का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान में वस्त्रों का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। अतः कुछ ऊनी वस्त्र देश के अन्य राज्यों को भेजा गया तथा अधिक ऊनी उत्पाद देश के अन्य राज्यों से भगदाया गया।

7. राजस्थान में ऊन उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions) राजस्थान में अच्छी नस्ल की भेड़ों का अभाव है, इस कारण ऊन उद्योग को मोटी एवं खुरदरी ऊन प्राप्त होती है, जिसका विक्रय मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। सरकार को चाहिए कि विदेशी सरकारों की मदद से भेड़ की नस्ल सुधार कार्यक्रम को गति प्रदान करे ताकि अच्छी किस्म की मुलायम व लम्बे रेशे वाली ऊन प्राप्त हो सके। इस हेतु भेड़पालकों को भी विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भेड़ों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, विशेष रूप से अकाल के समय में, विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। ऊन उद्योग में ऊन के विधायन की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इंजीनियरिंग उद्योग Engineering Industry

1. परिचय (Introduction) राजस्थान में सर्वप्रथम 1943 में जयपुर मेटल की स्थापना हुई और इसके पश्चात् बॉलबियरिंग बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग का वास्तविक विकास स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया। अतः योजनाकाल में राज्य के विभिन्न भागों में इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी अनेक कारखानों की स्थापना की गई।

प्रमुख इकाइयाँ - इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ अप्रतिष्ठित हैं

(i) कैप्टन मोटर कम्पनी, जयपुर व पाली : यह कम्पनी

पानी के मोटर बनाती है।

(ii) जयपुर मैटल्स, जयपुर यह कम्पनी बिजली के मोटर बनाती है।

(iii) इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा - यह प्रशोषण एवं यंत्रों का उत्पादन करती है।

(iv) मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जयपुर यह लोहे का सामान तथा इमारती खिडकियाँ आदि वस्तुएँ बनाने का कार्य करती है।

(v) सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर इस कारखाने में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं।

(vi) नेशनल इजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर - यह कम्पनी बियरिंग बनाती है और बियरिंग बनाने की दृष्टि से यह एशिया की सबसे बड़ी कम्पनी है।

(vii) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जयपुर इस कम्पनी में टेलीविजन बनाये जाते हैं।

(viii) फ्लोर्सपार सयंत्र, झुगरपुर इस कारखाने में स्पाईक, एल्यूमीनियम व फ्लोराइड बनाने के लिए फ्लोर्सपार का निर्माण किया जाता है।

उपर्युक्त कारखानों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि उपकरणों का उत्पादन करने के उद्देश्य से आबूगड, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व सोबत आदि में कारखाने स्थापित किए गए हैं। राज्य का इन्जीनियरिंग उद्योग निरन्तर प्रगति कर रहा है। कारखानों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।

उत्पादन-अब हालिया में कुछ प्रमुख इन्जीनियरिंग उत्पादों का उत्पादन दर्शाया गया है।

राजस्थान में बिजली के मोटर, टेलीविजन व पम्पों के मोटर, टेलीविजन सेट्स व रेलवे वैगन का उत्पादन				
क्र.सं. क्र.सं.	इकाई	1990	1997	1998
1	विद्युत के मोटर (एचपी के)	1908.28	480.01	195.10
2	रेलवे के मोटर (एचपी के)	30115	40778	44883
3	रेलवे विद्युत (एचपी के)	157.13	228.00	214
4	टेलीविजन सेट्स (एचपी के)	654	एनए	-
5	रेलवे वैगन (एचपी के)	1954	1754	1709

Source: Statistical Abstract, 1988 Raj Budget Study 1997-98, Economic Review 1998-99 Raj

रासायनिक उद्योग (Chemical Industry)

योजनाकाल में रासायनिक उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ है। राज्य में सोडियम सल्फेट, रासायनिक खाद, सल्फ्यूरिक एसिड, पी वी सी कम्पाउण्ड, कास्टिक सोडा

आदि वस्तुओं के कारखाने स्थापित किए गए हैं। सोडियम सल्फेट का कारखाना राज्य सरकार द्वारा डीडवाना में स्थापित किया गया है। सोडियम सल्फेट का प्रयोग सूती, रेशमी व ऊनी कपड़ों तथा कैंब बनाने में किया जाता है। डीडवाना व सागर की झीलों से वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। पहले सोडियम सल्फेट निवाला जाता है और शेष बचे हुए जल से शुद्ध नमक बनाया जाता है। श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा के स्थापना निम्न क्षेत्र में की गई। इसमें रासायनिक खाद बनाई जाती है। उदयपुर के निकट देवागिरी जिक स्मेल्टर तथा खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। हाल ही में कोटा में चन्दल फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई है।

राजस्थान में प्रमुख रासायनिक पदार्थों का उत्पादन (मैट्रिक टन)				
क्र.सं. क्र.सं.	1987	1990	1997	1998
रासायनिक पदार्थ				
1 सोडियम सल्फेट	25257	39418	36787	39735
2 सोडियम कार्बोनेट	23445	39819	37951	39677
3 सोडियम क्लोराइड	6489	3494	3189	5000
4 एचपी के टैंग	17575	29963	29078	25438
5 सल्फ्यूरिक एसिड	128119	198120	208000	248000
6 एचपी के टैंग	291948	377980	398000	395000
7 सोडियम क्लोराइड	85084	76392	25000	6000
(हजार टन)				
1 Statistical Abstract, 1988 Raj Budget Study 1997-98				
2 Economic Review 1998-99 Rajasthan				

राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

Public Sector Undertakings of Rajasthan

राजस्थान में कार्यरत उपक्रमों को दोन भागों में विभक्त किया जा सकता है

(अ) राजस्थान में केन्द्र सरकार के उपक्रम

(ब) राजस्थान सरकार के उपक्रम

(स) सहकारी उपक्रम

(अ) राजस्थान में केन्द्र सरकार के उपक्रम

(Undertakings of Central Govt. in Rajasthan)

(अ) हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड (Hindustan Zinc Ltd) सीसा व जस्ता सार्वजनिक महत्व की धातुएँ हैं। इस तथ्य को ध्यान रखते हुए 10 जनवरी, 1966 को भारत सरकार ने मैटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अधिग्रहण

रू लिया और इस मशीन के स्थान पर हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड की स्थापना की गई वर्तमान में यह कम्पनी ज़ावर ग्रीवा आदि खानों से खनिज निचालकर देवारी स्थित परिशोधन संस्थान में इसका परिशोधन कर रही है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग एक हजार टन शुद्ध जस्ता तैयार किया जाता है। इसका प्रधान कार्यालय उदयपुर में है। देवारी का शासन सयरा पाण भाग फलूओरोलिट रेक्टर सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लीचिंग और प्यूरीफिकेशन प्लांट इलेक्ट्रोलाइसिस और मैलिंग प्लांट तथा सुपर फास्फेट प्लांट में विभक्त है। हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों की इराइयों को भी संचालित करता है। इसके अन्तर्गत पाण इराइया है (1) ज़ावर की खानें (गज) (2) जरा सयरा देवारी (गज) (3) बिहार का सीको सयरा (4) रायपुर देवारी खानें (5) रोहन सयरा विशाखापट्टनम् (भारतप्रदेश)। हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड ने एक स्वीन एकीकृत परियोजना के अन्तर्गत इन परिशोधन संयंत्र की स्थापना की है। (1) रामपुरा-आगुवा खनन परिगर यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है और इसकी दैनिक क्षमता 3 हजार टन है। (2) ग्नेरिया मीसा व जरा परिशोधन संयंत्र यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसकी प्रतिवर्षी शोधन क्षमता 70 हजार टन जस्ता व 35 हजार टन सीसे की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 670 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के पत्तररूप हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड की गणना विश्व की शीर्ष 7 जरा परिशोधन करन शानी बड़ी कम्पनियों में हो गई है।

(ii) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Ltd.) इसकी स्थापना 1967 में पुष्पु जिले की छेतडी नामक स्थान पर हुई। इसकी स्थापना रायक गज अमेरिका की वैस्टर्न मैप इंजीनियरिंग कम्पनी की मशरवा से की गई। यह उपक्रम राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी परियोजनाओं का सम्पादन करता है। छेतडी के दो तासा भण्डारों माधनराधन और कोनीरान में तासे का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड वलकण के अधीन निम्नलिखित परियोजनाएँ हैं

■ गजस्थान की योजनाएँ

छेतडी बाँपर रायनरमा रांडीनगर (जिला पुष्पु)

दरीसा नाम परियोजना अजमेर

गाम्गरी ताम परियोजना पुष्पु

छेतडी नाम परियोजना हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की सम्मो बड़ी इराई है।

■ बिहार में भाखडा नामक स्थान पर हिन्दुस्तान तासा सयरा

c आन्ध्रप्रदेश में अग्रिगुण्डान नाम सीसा परियोजना

■ मध्यप्रदेश में मदावरण्ड तासा सीसा परियोजना

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मुख्यतः ज़ावर वार च्तिस्तर वार बाग रोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड सेलेनियम स्वर्ण व तादी रिगल सुपर फॉस्फेट तथा निचल फॉस्फेट आदि वस्तुओं का निर्माण करती है। यह उपक्रम निरन्तर प्रगति कर रहा है।

(iii) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर (Hindustan Machine Tools, Ajmer) इस कारखाने की स्थापना 1967 में नेवोरलोकाक्रिया के सारयोग से की गई। इस कारखाने में विभिन्न प्रकार की मशीन डाइजिंग मशीनों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में यहाँ डाइजिंग मशीनों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के यंत्र व मशीन बनाई जाती हैं। इन मशीनों का उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग व आटोमोबाइल उद्योगों में किया जाता है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की सयरा भारत में छ इराइया है और यदि घड़ी व डेयरी मशीनों को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसकी सयरा भारत में 13 इराइया है।

(iv) इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा (Instrumentation Ltd Kota) इस उपक्रम की स्थापना मार्च 1964 में राज्य के कोटा नगर में की गई। राज्य में इस उपक्रम की स्थापना के साथ ही उद्योग की नींव पाने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास प्रारम्भ हो गया। इस कारखाने में शक्ति उत्पन्न करने वाले व रासायनिक संयंत्रों के लिए यंत्रों का निर्माण किया जाता है। मुख्यतः मैग्नेटिक वैरिफिक इन्स्ट्रुमेंट्स रिपेडिंग एण्ड बन्डोल इन्स्ट्रुमेंट्स इन्फ्रानिक् ऑटोमेटिक इन्डीवेटर्स ट्रांसमीटर तथा वर्मल पावर व वैरिफिकल प्लान्टो के वाप अनेक वाले यंत्रों का निर्माण किया जाता है। इस कम्पनी ने बड़ी रीइ इसका परियोजनाओं का प्रक्रिया निर्माण इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रणालियाँ उपलब्ध कराई हैं। राजस्थान इन्फ्रानिक् एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड जयपुर इसकी एक सहायक कम्पनी है। इस सहायक कम्पनी की स्थापना 1982-83 में की गई। इसकी एक इराई नेरन राज्य में भी वर्गीकृत है।

(v) सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर (Sambhar Salts Ltd Sambhar) 1964 में हिन्दुस्तान साल्ट्स की सहायक संस्था के रूप में सांभर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई। इसमें 40 प्रतिशत अंश राजस्थान सरकार के हैं। यह संस्थान विभिन्न प्रकार के नमक का उत्पादन करता

है। इस उपक्रम में नियंत्रण में 4200 हेक्टेयर भूमि है।

(vi) **मॉडर्न बेकरीज इण्डिया लिमिटेड, जयपुर (Modern Bakeries India Ltd, Jaipur)** इसकी स्थापना मॉडर्न फूड्स इण्डिया लिमिटेड के अधीन जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में की गई है। इस संस्था द्वारा भारत में अनेक इकाइयों का संचालन किया जाता है।

(व) राजस्थान सरकार के उपक्रम Undertakings of Rajasihan Govt

राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख उपक्रम निम्नलिखित हैं

(i) **दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगगानगर** इस संस्थान के अन्तर्गत राजस्थान में ये इकाइया कार्य कर रही है -

- दी गगानगर शुगर मिल्स इस मिल में चुकन्दर व गन्ने में चीनी का उत्पादन किया जाता है।

- श्रीगगानगर व अट्ठर में स्थापित कारखानों में मटिया व मिश्र का उत्पादन होता है। अट्ठर का कारखाना लम्बे समय में बंद है।

- कोटा व उदयपुर क्षेत्र के जनजाति क्षेत्रों में गगानगर शुगर मिल्स द्वारा शराब की दुकानों का संचालन किया जाता है।

- **हाईटैक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर** इस कारखाने में मुख्यतः बाल्टों काच के सामान रेलवे जार तथा प्रयोगशालाओं में काम आने वाले उपकरणों का उत्पादन किया जाता है।

(ii) **राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना** इस संस्थान के अन्तर्गत ये कारखाने कार्यरत हैं

- **सोडियम सल्फेट वर्क्स** इस कारखाने में क्रूड सोडियम सल्फेट में सल्फेट सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है।

- **सोडियम सल्फेट संयंत्र** इस कारखाने द्वारा शुद्ध नमक का निर्माण किया जाता है।

- **सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री** इस कारखाने में सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फाइड का मुख्य उपयोग राखई उद्योग व चमड़ा उद्योग में होता है।

(iii) **राजकीय लवणस्रोत - राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित लवणस्रोत हैं**

- **राजकीय लवणस्रोत डीडवाना** प्रारम्भ में यह लवणस्रोत केन्द्र सरकार के अधीन था लेकिन 1985 में इसे राजकीय उपक्रम विभाग को सौंप दिया गया है, यहाँ मुख्यतः अखाद्य नमक और सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फेट भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है।

- **राजकीय लवणस्रोत, जावदीनगर** यहाँ खाद्य नमक बनाया जाता है।

- **राजकीय लवणस्रोत, पचपदरा** यहाँ खाद्य नमक का उत्पादन किया जाता है।

(iv) **राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड** इस उपक्रम का प्रधान कार्यालय जयपुर में स्थित है तथा यह टोंक में स्थित कारखाने का संचालन करता है। कारखाने में मुख्यतः चमड़ा फॉम व खालें आदि का निर्माण किया जाता है। इन वस्तुओं के निर्माण में मुख्य रूप से भेड़ की खाल का उपयोग किया जाता है। इस कारखाने द्वारा उत्पादित अधिकांश माल निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ के चमड़े का उपयोग मुख्यतः बैग, दस्ताने व चमड़े के वस्त्र बनाने में किया जाता है। राज्य में पशुओं की पर्याप्तता के कारण कारखाने को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है।

(v) **स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर** इस मिल की स्थापना मुख्यतः ऊनी धागा बनाने के लिए की गई। यह इकाई घाटे में चल रही है अतः इसे रुग्ण औद्योगिक इकाई घोषित कर दिया गया है।

(vi) **वर्स्टेट स्पिनिंग मिल्स, चूरू व लाडनू** गन्नास्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चूरू व लाडनू में दा स्पिनिंग मिल्स की स्थापना की गई। इन मिलों में मुख्यतः ऊन की कताई की जाती है।

(vii) **फ्लोसंपार इस्पात वेनीफोर्सिएशन संयंत्र, डूंगरपुर** यह कारखाना मागडों की पाल डूंगरपुर में स्थापित किया गया। इस कारखाने में स्टील व फाउण्ड्री में काम आने वाला एसिड किम का फ्लोमॉनार इस्पात तैयार किया जाता है।

(viii) **राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड** इस निगम की स्थापना 1979 में कम्पने अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई। निगम का प्रमुख कार्य राज्यस्थान में खनिज सम्पदा का विवेचन एवं विनियमन करना है।

(ix) राजस्थान राज्य टगस्टन विकास निगम लिमिटेड इस निगम की स्थापना 1983 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की सहायक कम्पनी के रूप में की गई। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य डोगाना को टगस्टन खानों को आधुनिकतम तकनीक से विकसित करना है। यह टगस्टन एवं इसके साथ पाये जाने वाले सभी खनिज पदार्थों के नये भण्डारों को खोज करने का कार्य करता है।

(x) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड इस निगम की स्थापना भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई। निगम का प्रमुख कार्य उदयपुर जिले के झामर, कोटडा क्षेत्र से रॉक फास्फेट का विदोहन, परिशोधन एवं विपणन करना है। यह निगम चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर व पाली जिलों में जिप्सम एवं सैलेनाइट के विदोहन एवं विपणन का कार्य भी करता है। उच्च श्रेणी के फ्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति निगम द्वारा विदोहित सैलेनाइट से होती है।

(स) सहकारी उपक्रम Co-Operative Undertakings

राज्य के सहकारी क्षेत्र में निर्माहित गम्यान कार्यरत है

- केशोरायपाटन शुगर मिल्स, केशोरायपाटन (बूंदी)
- राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुर (भीलवाड़ा)
- पशु आहार कारखाना, जयपुर
- पावल मिल्स - चारा उदयपुर बूंदी, बामवाड़ा कोटा हनुमानगढ़
- शीत भण्डार-जयपुर अलवर
- कीटनाशक जयपुर

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान के औद्योगिक ढांचे का वर्णन कीजिए।
Explain the industrial structure of Rajasthan
- 2 एचत्रयीद सजनाओं में राजस्थान की औद्योगिक प्रगति को समीक्षा कीजिए।
Examine the progress made by industries of Rajasthan during the plan period
- 3 राज्य क औद्योगिक विकास की क्या सम्भावनाएँ हैं?
What are the potentials of industrial development in Rajasthan?
- 4 पात्रनाहाल में राजस्थान क औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों की जांच कीजिए।
Examine the main trends of industrial development of Rajasthan during plan period
- 5 राज्य के औद्योगिक विकास की प्रमुख कान्ठों का वर्णन कीजिए।
What are the main problems of industrialisation in Rajasthan?
- 6 राजस्थान सरकार के तीन औद्योगिक उपक्रमों के नाम बताईए।
Name the three industrial undertakings of Rajasthan Government
- 7 राजस्थान में कृषि पर आधारित कौन कौन से प्रमुख उद्योग धन्य स्थापित किए जा सकते हैं?
What are the important agro based industries which can be set up in Rajasthan?
- 8 राजस्थान में मित्त चार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों क नाम बताईए तथा उनके कार्य का उल्लेख कीजिए।
Name four Central Public Sector undertakings located in Rajasthan and describe their functions

(B) निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान क औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय भिन्नता विषय पर गठित एवं अल्लोचनात्मक निवन्ध लिखिए।
Write a brief and capital essay on Regional variation in industrial development of Rajasthan
- 2 राजस्थान में औद्योगिक धरा में सन्धस्थित प्रमुख विरासनाओं का विवेचन कीजिए।
Discuss the main features of industrial sector in Rajasthan
- 3 राजस्थान में कृषि आधारित और सखिज आधारित उद्योगों पर एक निवन्ध लिखिए।
Write a note on Agriculture based and mineral based industries
- 4 आजादी क बाद राजस्थान में हुए औद्योगिक विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राजस्थान में औद्योगिक विकास में कौनसा मुद्दा बाधा है।

Critically evaluate the industrial development of Rajasthan since independence. List out main obstacles in industrial development in Rajasthan.

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Examination's Questions)

1. राजस्थान के क्षेत्रीय विकास में अंतर (Regional Variation) विस्तृत विवरण में स्पष्ट एवं आलोचनात्मक निवेदन लिखिए।
Write a brief and critical essay on Regional Variation in Industrial Development of Rajasthan.
2. राजस्थान के औद्योगिक विकास में अंतर का अन्तर्भावक समझाइए।
Explain in detail the regional imbalance in industrial development of Rajasthan.
3. राजस्थान में औद्योगिक विकास के स्तर व राजस्थान में उद्योगों के हिस्से का विशाल में शिवांक दर्शाइए।
Discuss in detail the level of industrial development in the state and share of industries in employment generation.
4. राजस्थान में औद्योगिक विकास के स्तर व राजस्थान में उद्योगों के हिस्से का विशाल में शिवांक दर्शाइए।
Discuss in detail the level of industrial development in the state and share of industries in employment generation.
5. राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए।
Discuss the main features of industrial sector in Rajasthan.
6. राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख विशेषताओं का विवरण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत दीजिए।
(i) क्षेत्र (ii) वस्तु संरचना
(iii) क्षेत्रीय प्रसार (iv) उद्योगों का राज्य के कुल उत्पादन में योगदान
(v) उद्योगों का राज्य के कुल उत्पादन में योगदान
Describe under the following headings the main features of industrial sector in Rajasthan.
(i) Size (ii) Commodity structure
(iii) Regional spread (iv) Share of industries in total S D P
(v) Share of industries in total employment



राजस्थान में लघु व ग्रामीण उद्योग तथा हस्तकलाएं

SMALL SCALE & VILLAGE INDUSTRIES AND HANDICRAFTS IN RAJASTHAN

"कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णकालिक या अर्धकालिक व्यवसाय के रूप में पूर्ण या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- लघु व कुटीर उद्योग का अर्थ
- लघु व कुटीर उद्योग में अंतर
- लघु व कुटीर उद्योग का महत्व या भूमिका
- लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में गंभीर समस्याएँ
- राजस्थान के प्रमुख लघु व कुटीर उद्योग
- राजस्थान में रत्नशिल्प
- राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों का समस्याएँ
- अभ्यासार्थ प्रश्न

लघु व कुटीर उद्योग

SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRY

प्रशुल्क आयोग 1949-50 के अनुसार 'कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णकालिक या अर्धकालिक व्यवसाय के रूप में पूर्ण या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है।" दूसरी ओर "लघु उद्योग वह उद्योग है जो मुख्यतः भाड़े के मजदूरों सामान्यतः 10 से 53 मजदूरों के द्वारा चलाए जाते हैं। ये श्रमिक के घर पर नहीं चलाए जाते। इसमें वे सब इकाइयाँ शामिल हैं जिनमें 7.5 लाख रुपये से कम पूँजी लगी होगी।" इन परिभाषाओं में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। इन परिवर्तनों के अनुसार साढ़े सात लाख रुपये से कम पूँजी वाले सभी संस्थानों को उनमें कितने ही कम श्रमिक काम क्या न करते हों जो लघु उद्योग कहा गया है। 1975 से पूर्व की इस परिभाषा में साढ़े सात लाख से कम पूँजी विनियोजन को मापदंड बनाया गया तो 1975 में भारत सरकार ने 10 लाख रुपये तक पूँजी वाले औद्योगिक उपक्रमों को लघु उद्योग कहा। 1980 में घोषित औद्योगिक नीति में अति लघु क्षेत्र Tiny Sector में विनियोजन को सामान्य लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई। लघु इकाइयों में

विनियोग की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। सहायक उद्योगों (Ancillary Industries) में विनियोग की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। मार्च 1985 में भारत सरकार ने लघु उद्योगों का विनियोग सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की दी। सहायक उद्योगों में यह सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दी गई। 1990 में भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के अंतर्गत मयत्र एवं मशीनरी में विनियोग की सीमा 36 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए की दी गई। अति लघु क्षेत्र के लिए यह सीमा दो लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई।

जनवरी 1997 के अन्तिम सप्ताह में लघु उद्योगों के संबंध में गठित डा. आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योगों के लिये निवेश सीमा में वृद्धि करने से बाधा लघु उद्योगों के लिये निवेश सीमा समाप्त करने किंसा क्षेत्रीय बैंक के अन्तर्गत आने वाली समान प्रकृति का इकाइया को एक समूह मानते लघु उद्योगों के लिये बुनियादी सेवा ढांचे में मशीनरी, कच्चा को अपने प्राथमिकता वाले ऋण का 70% अति लघु उद्योगों के लिये सुरक्षित रखने एवं लघु उद्योग इकाइया की वर्ष में केवल एक बार जांच करने आदि के संबंध में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण सिफारिशों को है।

डा. आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के आधार पर 7 फरवरी 1997 को केन्द्रीय मंत्री मंडल को अधिक मामला की समिति ने लघु उद्योगों के अन्तर्गत मयत्र एवं मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी। इसी प्रकार सहायक उद्योगों में निवेश की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तथा अति लघु उद्योग में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। इसके अतिरिक्त लघु क्षेत्र के लिये निर्यात की दर 75% से घटाकर 50% कर दी। इसके अलावा सरकार लघु उद्योग में उत्पन्न के लिये वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने पर भी विचार कर रही है।

29 अप्रैल 1998 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को 3 करोड़ रुपए से घटाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि लघु

उद्योगों के लिये उत्पादों के आरक्षण की व्यवस्था आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के अनुसार समाप्त नहीं की जायेगी। इस घोषणा पर 5 अगस्त 1998 तक क्रियान्वयन नहीं हुआ था।

आठ उपक्षेत्र Eight Sub-Sectors

ग्रामीण और लघु उद्योग आठ उपक्षेत्रों में बंट हुए हैं जो क्रमशः खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, हस्तकला, जूता लघु उद्योग और विद्युत चालित करघा क्षेत्र हैं। इनमें से अंतिम दो आधुनिक लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि शेष छ उपक्षेत्र परम्परागत उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं। आधुनिक लघु उद्योगों का आरंभ करघा क्षेत्र आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ये सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में विद्यमान हैं और श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी ओर परम्परागत उद्योग मुख्यतः ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में विद्यमान हैं जो कि पूर्णकालिक अथवा अर्धकालिक रोजगार प्रदान करते हैं। ये भारतीय कलाओं को सुरक्षित रखते हैं और इन्हीं के माध्यम से आय भी प्राप्त करते हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों में अन्तर DIFFERENCE BETWEEN SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRY

कुटीर उद्योग प्रायः परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं जबकि लघु उद्योग मुख्य व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योगों में अधिकांश कार्य हाथ से किया जाता है लेकिन लघु उद्योगों में मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। कुटीर उद्योगों द्वारा मुख्यतः परम्परागत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और ये उद्योग मुख्यतः स्थानीय भाग की पूर्ति करते हैं। इसके विपरीत लघु उद्योगों द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और ये उद्योग विस्तृत क्षेत्र की मांग को पूरी करते हैं। कुटीर उद्योगों में बहुत कम मात्रा में पूरा विनिर्माण होता है जबकि लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत अधिक पूरा का विनिर्माण किया जाता है। कुटीर उद्योगों द्वारा प्रायः स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत लघु उद्योगों के लिए प्रायः अन्य स्थानों से कच्चा माल मांगा जाता है।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की भूमिका या महत्त्व

ROLE OR IMPORTANCE OF SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRIES IN RAJASTHAN

1. **रोजगार (Employment)** - राजस्थान में विद्यमान अत्यधिक बेरोजगारी का समाधान बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में निहित नहीं है। इनके विकास से कुछ ही क्षेत्रों में श्रमिकों का केन्द्रीयकरण होना सम्भव है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएँ जन्म लेगी। इस समस्या को लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस क्षेत्र द्वारा उपलब्ध रोजगार कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों से अधिक है। इस कारण इन उद्योगों का विकास राजस्थान की बेरोजगारी समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान में दिसम्बर 1997 तक कुल पंजीकृत लघु एवं दसकारी इकाइयाँ 1,90,704 हो गई हैं जिनमें 2184.3 करोड़ रुपये के विनियोजन से 7.39 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजित हुआ।¹

2. **उत्पादन (Production)** - राजस्थान में 1983-84 में ग्रामीण उद्योगों का कुल उत्पादन 59.18 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1995-1996 में 357.67 करोड़ रुपये हो गया।² इन उद्योगों द्वारा परम्परागत वस्तुओं के निर्माण के साथ नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण भी किया जा रहा है। उत्पादन में विभिन्न प्रकार के शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से निरन्तर विविधता दृष्टिगोचर हो रही है। उत्पाद की इस विविधता के कारण यह क्षेत्र राजस्थानवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण बन जाएगा, ऐसी सम्भावना है।

3. **निर्यात (Export)** राजस्थान ने लघु क्षेत्र में कुछ विशेष सफलताएँ प्राप्त की हैं। इस क्षेत्र द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इस क्षेत्र के द्वारा सिलेसिलाये वस्त्रों, रिज्जामन्, वस्त्रुओं, चमड़े का सामान, च, जामून्, आदि का निर्यात किया जा रहा है। इस उद्योग को विशेष श्रेय दिया जा सकता है कि यह परम्परागत निर्यातों के बदले गैर परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का एक बहुत बड़ा केन्द्र बन गया है। निर्यात सामान में पर्याप्त विविधता होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व निरन्तर बढ़ने की सम्भावना है।

4. **औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों का विकेन्द्रीयकरण (Decentralization of Industrial & Economic Activities)** - ग्रामीण लघु उद्योग क्षेत्र ने राज्य की औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को शहरी केन्द्र में केन्द्रित होने से बचाया है। राज्य की अधिकांश इकाइयाँ ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस विकेन्द्रीयकरण के कारण

राज्य आय के वितरण की विषमता में कमी आई है और राज्य बड़े उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की नुराइयों से नच सका है।

5. **स्थानीय ससाधनों व कुशलता का उपयोग (Use of Local Resources & Efficiency)** : लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस कारण यह उन क्षेत्रों में उपलब्ध मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों व उनकी कुशलता का उपयोग करने की स्थिति में है। राजस्थान में विद्यमान समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए लघु व कुटीर उद्योगों ने जहाँ सहसियों को राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया है, वहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक साधनों व मानवीय कलापूर्ण चातुर्य का भरपूर उपयोग भी किया है।

6. **ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में संतुलन (Balance between Rural & Urban Economies)** : योजनाकाल के प्रारम्भ से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के विकास का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के कुल साधनों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। इस प्रकार सरकार की नीति ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने की है। लघु व ग्रामीण उद्योग इस क्षेत्र में पहले से ही अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार की इस नीति के कारण उनका विकास प्रोत्साहित होगा।

7. **पिछड़े क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in Per Capita Income of Backward Regions)** राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाली जनसंख्या विभिन्न अनुमानों के अनुसार 1.25 करोड़ से 1.50 करोड़ के मध्य है। इसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार को ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल देना होगा। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का कार्यक्षेत्र भी मुख्यतः यही है। अतः सरकार की नीतियों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

8. **कृषिजनसंख्या का भारकम करना (Lessening the Load of Population on Agricultural Sector)** राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के अधिकांश व्यक्ति कृषि पर आश्रित हैं। कृषि क्षेत्र की मानसून पर निर्भरता व पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषक वर्ष भर खेती के काम में नहीं लगा रह सकता। वे प्रायः 4 से 6 माह तक बेकार रहते हैं। इस अवधि का उपयोग कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास से किया जा सकता है। इससे जहाँ उनके बेकार समय का उपयोग होगा वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। इन उद्योगों के विकास के

साथ-साथ लोगों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आया और धीरे-धीरे जनसंख्या कृषि क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित होगी। भारत में कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम लगा हुआ है। इस कारण कृषि पर से जनसंख्या के भार को इन क्षेत्रों के विकास से कम किया जा सकता है।

9 पूँजी उत्पादन अनुपात (Capital Output Ratio) बड़े उद्योगों का भाति कुटार उद्योगों में बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता नहीं होती। वे पूँजा प्रधान न होकर श्रम प्रधान होते हैं। भारत एक 'गोव' राष्ट्र है। इस कारण यहाँ मजदूर ही पूँजा का कमी रहा है। इस कारण राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र द्वारा राजस्थान में न केवल बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है वरन् साथ ही उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की चेष्टा की जाती है। यह कारण है कि बड़े उद्योगों में श्रम की कुशलता की तुलना में लघु एवं कुटीर उद्योगों की विकसित करना एक उचित कदम है।

10 आपातकाल में सहायक (Useful in Emergency) बड़े उद्योग केंद्रीयकरण का प्रवृत्ति का प्रोत्साहित करते हैं। इस कारण जहाँ अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ दूसरी ओर राष्ट्र की सुरक्षा हाथों में पड़ सकती है। युद्ध की स्थिति में शत्रु द्वारा ऐसे क्षेत्रों को निराना बनाकर अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। इस कारण उद्योगों के विकेंद्रायकरण के इस कार्य में लघु एवं कुटीर उद्योग सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार नहीं ये सुरक्षा के खतों को समझ करते हैं वहाँ दूसरी ओर आपातकाल में अधिक उत्पादन करके राष्ट्र की अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

11 श्रम एवं पूँजी में मधुर सम्बन्ध (Cordial Relations Between Capital & Labour) श्रम के अर्थशास्त्रिक गुण में श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुरता न होना औद्योगिक अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा कारण है। बड़े उद्योगों में मजदूरों एवं प्रबंधकों के मध्य साधा संबंध नहीं रह जाता। पूँजापतियों व मजदूरों के मध्य का संघर्ष की सभावना पनपन लगती है। इसी कारण हड़ताले व ताल्लुबदा होना है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर श्रम एवं पूँजा के मध्य लाभ को भेद हा नहीं है। स्वामी व मजदूर का भावना नहीं पनपती। इस कारण इस क्षेत्र में हड़ताल या ताल्लुबदा की चप नहीं चलती। बड़े उद्योगों में प्रबंधकों की व्यापक स्वतंत्रता एवं अस्तित्व हो मजदूरों में प्रयोज्य हो जाता है। इस कारण इनकी काम करते में जो विचार आता भी नहीं आता किन्तु लघु एवं कुटीर उद्योगों में उद्योग वाद में श्रम का अनुभव करने है। उद्योगों में उद्योगों में श्रम करने में ही जाना जा

ताता है। शोषण से मुक्त होने के कारण वे अधिक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।

12 अर्थव्यवस्था का समग्र विकास (Overall Economic Development) लघु एवं कुटीर उद्योग सभी विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी होते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो अथवा निर्यात का देश की आर्थिक गतिविधियों के विवेंद्रीयकरण का प्रश्न हो या राज्य का पूँजी का अधिक कुशलता से उपयोग करने का लघु एवं कुटीर उद्योग सभी में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए हैं। इस क्षेत्र में जहाँ नगरकरण की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है वहाँ कृषि जनसंख्या का भी कम हुआ है। लघु एवं कुटीर उद्योगों ने कुछ क्षेत्र में बड़े उद्योगों में कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा का है। इन क्षेत्रों में घाल व कायालय फावर सिले सिलाए वस्त्र गन्तु हवाई निस्कुट खाद्य तेल प्लास्टिक का सामान टेलाविस्त्र रेडियो असम्बली काब का सामान बड़े का वस्तु व बोल्ट आभूषण बनाया आदि प्रमुख हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक संस्थाएँ

INSTITUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL & COTTAGE INDUSTRIES

(अ) राष्ट्रीय संस्थाएँ National Institutions

1 लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग (Department of Small Industry and Agriculture & Village Industries) लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग का स्थापना उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करने में सहायक कार्यक्रमों एवं कार्यक्रमों का निष्पादन विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय और निरीक्षण करना है। यह अन्य मंत्रालयों से भी समन्वय बनाए रखता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में सहायक अनेक संस्थाएँ हैं। इनमें योजना विभाग राज्य सरकार के अन्तर्गत स्थापित स्वेचिक संस्थाएँ और अन्य सहायक संस्थाएँ प्रमुख हैं। विभाग द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यह विभाग नजीक के ताल्लुबदा विभागों के विकास के साथ-साथ राज्य सरकार के अन्तर्गत के उद्योगों के विकास में भी सहायक कार्य करता है। यह

सहायता 27 छोटे उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा 31 शराब कार्यालयों द्वारा 37 विस्तार केन्द्रों द्वारा एवं 4 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती है। इस विभाग के अंतर्गत एक उत्पाद विधायन विकास केन्द्र (एचवी) दो केन्द्रीय फुट-प्रिगर टेनिंग सेंटर 4 उत्पादन केन्द्र और 19 फील्ड टैस्टर स्टेशन कार्यरत हैं।

2 राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड और राष्ट्रीय उद्यमशीलता व लघु व्यापार विकास संस्थान [National Board for Entrepreneurial Development and National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)] 1983 में सरकार ने राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यापार विकास संस्थान का गठन किया। यह संति निर्धारित करने का कार्य करता है। यह इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करके उनमें सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता है। इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यह देश के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आदर्श षटयक्रमों का निर्माण करता है एवं परीक्षा आयोजित करता है। इस क्षेत्र से संबंधित आकड़े एकत्र करता है तथा अनुसंधान के माध्यम से लाभ पहुँचाने की चेष्टा करता है। संक्षेप में यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संस्थान विभिन्न एजेंसियों और उद्यमों के मध्य परस्पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है।

3 लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organisation) यह संगठन लघु उद्योगों को पक्की तकनीक व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। लघु उद्योगों की समस्याओं के सत्रध में परामर्श सेवा देने के साथ ही उनके उत्पादित माल के विपणन में भी मदद करता है। इस संगठन ने लघु उद्योगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य में नई तकनीकी संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। यह मुख्य रूप से लघु उद्यमों की उत्पादन प्रक्रिया प्रशिक्षण डिजाइन व अनुसंधान व संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्पाद विकास केन्द्र आज्ञा कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र आदि स्थापित कर सहायता कर रहा है।

4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corp.) इसका स्थापना 1955 में हुई। यह लघु उद्योग इकाइयों का क्रियाशील योजना के अंतर्गत मशीनों उपकरण कच्चा ह और मरक़ाज़ आर्डर प्राप्त करने में सहायता करता है। यह लघु उद्यमों का महत्वपूर्ण आयोजित सामग्री ख़ासदने और डाके उत्पादों को निदेशों से बेचने में भी मदद करता है। यह निगम के राष्ट्रीय में पूर्णतः तैयार परियोजना निर्यात करने का प्रयास भी करता है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इस संस्थान द्वारा लघु उद्यमों के

अंतर्गत काम आने वाली मशीनों और आज्ञासे के नमूने भी तैयार किए जाते हैं और उन्हें परिष्कृत करने के पश्चात् उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

5 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [Small Industries Development Bank of India (SIDBI)] भारतीय लघु उद्यमों (विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत भारतीय विकास बैंक की एक सहायक संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक का प्रमुख कार्य लघु व ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों को सहायता प्रदान करना उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना और लघु उद्यमों का विकास करना है। इस बैंक ने 2 अप्रैल 1990 से अपना कार्य प्रारंभ किया। बैंक द्वारा राज्य विनियमों व्यापारिक बैंकों और राज्यों के औद्योगिक निगमों के माध्यम से कुटीर एवं लघु उद्यमों को सहायता प्रदा की जाती है। बैंक की प्रदत्त पूंजी 125 करोड़ रुपये है जो पूर्णतः भारतीय औद्योगिक विकास द्वारा प्रदान की गई है।

(ब) राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्यमों के विकास में सहायक संस्थाएँ Institution for Development of Small & Cottage Industries in Rajasthan

1 उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) उद्योग निदेशालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निदेशालय द्वारा छोटे छोटे ग्रामीण उद्यमों व लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय दस्तकारी क्षेत्र के विकास हेतु सहायता प्रदान करता है। इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु निदेशालय द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्षिक योजनाएँ बनाई जाती हैं। यह लघु एवं शिल्पकार आर्थिक इकाइयों का पंजीकरण करता है। यह रोजगार में वृद्धि का प्रयास करता है और स्थानांतरण के उपयोग पर बरा देता है। इस प्रकार निदेशालय प्रादेशिक समुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक अभियान औद्योगिक सर्वेक्षण तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग प्रदान करता है। जनशक्ति व मरक़ाज़ व औद्योगिक विकास का प्रोत्साहन देता है। निर्यात सवर्द्धन के लिए प्रयास करता है। राज्य औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू कराने में सहयोग प्रदान करता है।

2 जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centers) यह एक जिला स्तरीय केन्द्र है जो उद्यमों की स्थापना व विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। राज्य के प्रायः सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की

स्थापना की गई है। राज्य के जिला उद्योग केन्द्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। (अ) स्पेशल श्रेणी-जयपुर (ब) 'ए' श्रेणी-अलवर अजमेर कोटा पाली उदयपुर जोधपुर भालवाड़ा (स) 'बी' श्रेणी-बासवाड़ा भरतपुर झुनार नागौर बाकवनेर चित्तौड़गढ़ टोंक गंगानगर सीकर और सवाईमाधोपुर (द) सा श्रेणी-चूरू सिरोंही धौलपुर झालावाड़ बूंदी बाड़मेर जागीर बंसलमेर और डूंगरपुर। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी ब्यावर आम्बोरोड हनुमानगढ़ फतलना बालोतरा तथा मकराना में उपकेन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई है लेकिन इनका संचालन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना में केन्द्र सरकार भी आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

3 लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institute) इस संस्थान की स्थापना राज्य के उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के लिए की गई। इस उद्देश्य का पूर्ति हेतु संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थान के पास विभिन्न उद्योगों सम्बन्धी परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध है। इन परियोजना रिपोर्टों के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि किसी उद्योग विशेष में कितनी पूँजी विनियोजित की जानी चाहिए किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होगी और वह कहा से प्राप्त किया जा सकेगा उत्पाद वस्तु का बाजार किन किन स्थानों पर उपलब्ध है। प्रशिक्षित श्रमिक कहा से प्राप्त किए जाएँ। आदि। इन तथ्यों की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भी अंतर्गत प्रदान की जाती है।

4 राजस्थान राज्य हथकरपा विकास निगम (Rajasthan State Handloom Development Corporation) निगम की स्थापना 1984 में की गई। इस निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हथकरपा उद्योग का विकास करना है। इसके निगम द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। निगम विपणन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करता है। निगम अपने विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से हथकरपा वस्त्रों के उत्पादन का राजस्व प्रदान करता है। निगम ने जयपुर के विश्वकामा औद्योगिक क्षेत्र में विधायन गृह की स्थापना की है। यह नवजाति श्रमण विकास निगम के सहयोग में अनुसूचित जाति व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। यह पंजीय निगम बासवाड़ा डूंगरपुर और उदयपुर केन्द्रों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

5 राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम (RAJSICO) राजस्थान में लघु उद्योगों व हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य में 1961 में राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई। इसके अन्तर्गत अन्य उद्योगों में किया गया है।

6 राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग वाड ' राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अपेक्षाकृत कम मूल्य की विनियोजन से अधिकधिक रोजगार अवसरों के सृजन में विशेष रूप से सहायक है। बोर्ड की देखरेख में इस प्रकार की इकाइयों के सर्वहन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान खादी उद्योग में 45.85 करोड़ रुपये कीमत का उत्पादन किया गया। इसी प्रकार ग्रामोद्योग के उत्पादन वर्ष 1996-97 में 324.60 करोड़ रुपये का था। खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों में वर्ष 1994-95 में 4.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। 1995-96 में 30,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 95 तक 12042 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 1996-1997 में 32631 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

7 राजस्थान वित्त निगम (RFC) इसका विस्तृत विवेचन अन्य अध्याय में किया गया है।

8 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RAICO) इसका विस्तृत विवेचन अन्य अध्याय में किया गया है।

राजस्थान के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग IMPORTANT SMALL & COTTAGE INDUSTRIES OF RAJASTHAN

- (अ) कृषि पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Agriculture Based)
- 1 खड़ा उद्योग (Khadi Industry)
- 2 तेल घण्टा उद्योग (Ghani Oil Industry)
- 3 गुड़ खांडसा उद्योग (Gur Khandsan Industry)
- 4 फल व सब्जियों का संरक्षण (Fruit & Vegetable Preservation)
- 5 रेशा उद्योग (Fibre Industry)
- 6 धान कुटने का उद्योग (Hand Pounding Rice Industry)
- 7 मधुमक्खन पालन (Bee Keeping)
- 8 अखड़ा तेल में बना मखन उद्योग (Non edible Oil Soap Industry)
- 9 दाल बनाने का उद्योग (Pulse Making)
- 10 पिसाड़ उद्योग (Grinding)
- 11 ग्वार गम उद्योग (Guar Gum Industry)
- 12 हथकरपा उद्योग (Handloom Industry)
- (ब) खनिज पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Mineral Based)
- 1 चूना उद्योग (Lime Industry)

- 2 एल्यूमीनियम उद्योग (Aluminium Industry)
- 3 पौल्ट्री उद्योग (Poultry Industry)
- (स) वनी पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Forest Based)
 - 1 लोहे व लकड़ी के कार्य (Black Smith & Carpentry)
 - 2 बेंत व बांस उद्योग (Cane & Bamboo Industry)
 - 3 ताल गूठ उद्योग (Palm Gurr Industry)
 - 4 माचिस व अगरबत्ती उद्योग (Cottage Match & Agarbatti Industry)
 - 5 हाथ से बना कागज उद्योग (Handmade Paper Industry)
 - 6 रेणु उद्योग (Sculpture)
 - 7 बीड़ी उद्योग (Bidi Industry)
- (द) पशुआ पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग
 - 1 चमड़ा उद्योग (Leather Industry)
 - 2 ऊनी वस्त्र उद्योग (Wool Garments Industry)
 - 3 हड्डी पीसना (Bone Crushing Industry)

(अ) कृषि पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग Agriculture Based Small & Cottage Industries

खादी उद्योग (Khadi Industry)

खादी के अन्तर्गत मुख्यतः सूती ऊनी व सिल्क आदि का कार्य किया जाता है। यह कार्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित होता है। हजारों व्यक्ति हाथ कढ़े पर कार्य करते हैं। हाथ कढ़े के द्वारा भोज्य कपड़ा साधारण व तैयारिये आदि अनेक प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जुलाहे खादी के रूपड़े अपने घरो पर ही तैयार करते हैं। खादी ग्रामोद्योग में अनेक व्यक्तियों को अतिरिक्त एवं पूर्णकालिक रोजगार की प्राप्ति होती है। यह कार्य स्त्रियों द्वारा भी किया जाता है। ऊनी खादी के अन्तर्गत जैसलमेर की बरडी व रेजी धोकरने के ऊनी कम्बल गुरु के रोस आदि प्रसिद्ध हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मेरिनी वस्त्र की धेड़ों से प्राप्त ऊन से खादी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं जिसकी संपूर्ण भारत में मांग रहती है। निम्न तालिका में राजस्थान के खादी उद्योग की दर्शाया गया है।

राजस्थान में खादी उद्योग उत्पादन व कीमत

वर्ष	इकाई	1984-85	1987-88	1992-93	1995-96
1 खादी उत्पाद	लाख वर्ग मीटर	63.71	74	18.94	92.19
	लाख रुपये	1696.34	217.34	1180.13	3441.64
1.1 सूती	लाख वर्ग मीटर	35.14	34	6.67	39.04
	लाख रुपये	507.96	675.01	250.17	1531.58
1.2 ऊनी	लाख वर्ग मीटर	28.37	40	10.17	48.12
	लाख रुपये	1778.38	1500.33	939.96	2133.63
2 खादी की बिक्री	लाख रुपये	3205.43	4023.17	1998.02	8905.83
2.1 धौक	लाख रुपये	2084.64	2472.64	1051.12	5132.19
2.2 कुटकर	लाख रुपये	1120.79	1550.53	946.53	3773.64

1984-85: State Abstract 1988-89: R & Economic Review 1995-96: R & N

तेल घानी उद्योग (Ghani Oil)

वनस्पति तेल उद्योग की भाँति यह उद्योग भी तिलहनो के उत्पादन पर निर्भर है। राजस्थान के जयपुर भरतपुर कोटा धौलपुर गगानगर पाली आदि में अलसी मूँगफली सरसों तिल आदि का उत्पादन होता है। अतः जयपुर बोटा गगानगर पाली आदि में ही तेल घानी उद्योग का विकास अधिक हुआ है। तेल मुख्यतः कोल्ड एन गणों के द्वारा निकाला जाता है। लघु एवं मध्यम उद्योग के रूप में यह राजस्थान में काफी विस्तृत है। इस व्यवसाय से राज्य के लगभग 37 हजार परिवारों को रोजगार की प्राप्ति होती है। निम्न तालिका में तेल घानी उद्योग के उत्पादन मूल्य एवं बिक्री मूल्य की दर्शाया गया है।

राजस्थान में तेल घानी उद्योग का उत्पादन व मूल्य

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	1559.55	1722.17
1994-95	2336.40	2571.45
1985-86	2780.74	3041.05
1986-87	3150.00	3360.00
1997-88	3501.18	3736.71
1991-92	2439.30	2666.93
1993-94	6523	2932.05
1994-95	7747.77	3352.79
1995-96	9124	472.64

1983-84: R & N 1985-86: R & N 1986-87: R & N 1987-88: R & N 1988-89: R & N 1989-90: R & N 1990-91: R & N 1991-92: R & N 1992-93: R & N 1993-94: R & N 1994-95: R & N 1995-96: R & N

विगत वर्षों में राज्य के तेल-घाणी उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण विपुन चालित तेल-घाणियों का प्रचलन होना है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत चालित तेल घाणियों की तेजी से स्थापना हुई।

गुड़-खाडसारी उद्योग (Gur-Khandsari)

राजस्थान में गन्ने से गुड़ व खाडसारी बनाने का कार्य प्राचीनकाल से हो रहा है। कुटीर उद्योग के रूप में यह कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन मुख्यतः बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झुगरपुर, गगानगर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर व उदयपुर में होता है। अतः इन जिलों में गुड़ व खाडसारी उद्योग भी विकसित है। इस उद्योग में राज्य के लगभग 55,000 व्यक्ति कार्यरत हैं। निम्न तालिका में राजस्थान में गुड़-खाडसारी उद्योग के उत्पादन एवं मूल्य को दर्शाया गया है।

राजस्थान का गुड़-खाडसारी उद्योग का उत्पादन तथा विक्री मूल्य (लाख रुपये में)			
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य	
1983-84	371.00	450.00	
1984-85	380.58	471.82	
1985-86	419.47	527.12	
1986-87	297.16	397.12	
1987-88	30.43	35.39	
1992-93	47.39	610.12	
1993-94	108.74	160.91	
1994-95	133.75	173.51	
1995-96	230.69	342.56	

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1993 & 1996

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गुड़ व खाडसारी के उत्पादन में अत्यधिक उतार-चढ़ाव हुए हैं। वास्तव में राजस्थान में वर्षों के अपर्याप्तता के कारण गन्ने का उत्पादन कम-ब्यादा होता रहता है। अतः इससे वीनी उद्योग के साथ गुड़ व खाडसारी उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं।

फलों व सब्जियों का संरक्षण (Fruit & Vegetable Preservation)

राजस्थान में सभी प्रकार की सब्जियाँ उत्पन्न की जाती हैं। उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में सब्जियों का अपेक्षाकृत कम उत्पादन होता है। राज्य में विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन भी होता है। विगत कुछ वर्षों से राजस्थान के विभिन्न भागों में अंगूर का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। राज्य में फलों का संरक्षण मुख्यतः कोटा, जयपुर व गगानगर में किया जाता है। अग्र तालिका में संरक्षित फल एवं उसके मूल्य को दर्शाया गया है।

रेशा उद्योग (Fibre)

राजस्थान में अनेक प्रकार की कृषि फसलों से रेशे की

फलों का संरक्षण : उत्पादन व विक्री मूल्य² (लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	1.23	1.62
1984-85	2.26	2.88
1985-86	4.20	5.08
1986-87	4.47	6.12
1987-88	2.12	2.95
1992-93	13.39	17.53
1993-94	19.67	25.96
1994-95	27.04	34.83
1995-96	16.71	25.20

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1993, 1994 & 1996

प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग मुख्यतः रसिया बनाने में किया जाता है। ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में यह कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्न तालिका में वित्त कुछ वर्षों के रेशा उत्पादन को दर्शाया गया है।

रेशा उद्योग : उत्पादन व विक्री मूल्य¹ (लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	169.66	225.69
1984-85	158.39	241.14
1985-86	244.39	237.92
1986-87	286.49	398.77
1987-88	440.53	547.81
1992-93	1667.59	2036.50
1993-94	1670.21	2041.41
1994-95	1774.13	2154.77
1995-96	1864.50	2353.25

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1993, 1994 & 1996

धान कूटने का उद्योग (Hand Pounding Rice)

यह उद्योग राजस्थान के मुख्यतः नासवाड़ा, झुगरपुर, गगानगर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर व झालावाड़ आदि जिलों में विकसित हुआ है। प्रदेश के विभिन्न भागों में यह उद्योग लघु इकाइयों द्वारा अस्थावित उद्योग के रूप में चलाया जाता है। धान उत्पादक क्षेत्रों में अनेक लघु इकाइयाँ कार्यरत हैं। गगानगर जिले में धान की भुसी से तेल निकालने का कार्य भी किया जाता है। अग्र तालिका में इस उद्योग के उत्पादन व मूल्य को दर्शाया गया है।

धान कूटने का उद्योग : उत्पादन व विक्री मूल्य² (लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	78.60	91.50
1984-85	171.57	122.53
1985-86	123.78	145.31
1986-87	132.66	164.88

1987-88	97.62	116.06
1990-91	207.11	274.30

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि धान के उत्पादन मूल्य में 1983-84 से 1986-87 तक निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन 1987-88 में उत्पादन में कमी आयी है। तत्पश्चात् उत्पादन बढ़ा है।

मधुमक्खी पालन (Bee Keeping Or Honey)

राजस्थान में मधुमक्खी पालन का कार्य प्राचीनकाल से किया जाता रहा है। मधुमक्खियों से मुख्यतः शहद एवं मोम की प्राप्ति होती है। शहद शक्तिवर्धक पदार्थ है। इसका उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों में भी किया जाता है, वर्तमान में कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन को उपयोगी माना जाता है। निम्न तालिका में शहद के उत्पादन एवं उसके मूल्य को दर्शाया गया है।

शहद का उत्पादन व बिक्री मूल्य ¹ (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	0.23	0.22
1984	0.17	0.37
1985-86	0.08	0.32
1986-87	0.09	0.34
1987-88	0.12	0.16
1989-90	0.54	0.38

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1992 1994

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शहद के उत्पादन मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव आया है। 1983-84 में शहद का उत्पादन 0.23 लाख रुपये का था जो बढ़कर 1989-90 में 0.54 लाख रुपये का हो गया।

अखाद्य तेल से बना साबुन उद्योग (Non-edible Oil Soap)

अखाद्य तेल का उपयोग मुख्यतः साबुन बनाने में किया जाता है। इस कार्य में राज्य के अनेक व्यक्ति सलग्न हैं। राज्य में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण इस उद्योग के विकास की अच्छी सम्भावनाएं विद्यमान हैं। निम्न तालिका में अखाद्य तेल से बने साबुन उत्पादन एवं उसके मूल्य को दर्शाया गया है।

साबुन का उत्पादन एवं बिक्री मूल्य ¹ (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	123.28	117.92
1984-85	155.72	138.15

1985-86	188.48	186.13
1986-87	256.31	259.00
1987-88	303.98	299.40
1992-93	236.73	230.43
1993-94	329.28	278.80
1994-95	400.01	459.02
1995-96	511.89	543.32

Source: S. R. S. of Abstract Rajasthan, 1988 1992 1994 & 1998

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में अखाद्य तेल से बने साबुन के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि को इस प्रवृत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि भविष्य में इस उद्देश्य का तेजी से विकास होगा।

पिसाई उद्योग (Grinding Industry)

राजस्थान में गगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कांटा सवाई माधोपुर, उदयपुर, बूंदी, पाली, टोक अजमेर भीलवाड़ा आदि जिला में पिसाई उद्योग विकसित है। राज्य में प्रत्येक नगर में गेहूँ पर आधारित आटा मिलें हैं जिनमें गेहूँ से आटा सूजी व मैदा तैयार किए जाते हैं। कुटीर, गृह उद्योग तथा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में प्रत्येक गांव में आटा चक्किया गेहूँ पीसने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार गेहूँ पीसने के उद्योग में करोड़ों रुपये की पूंजी लगी है जो हजारों लोगों का आजीविका उपलब्ध कराती है।

दाल बनाने का उद्योग (Pulses making Industry)

राजस्थान में अहरर, भूग, उडद व मोठ का दाल बनाने का कार्य काफी प्राचीन समय से होता चला आ रहा है। यह कार्य स्त्रियों द्वारा घरों पर किया जाता था, लेकिन अब इसने उद्योग का रूप ले लिया है। राजस्थान में दाल मिल उद्योग अजमेर, कोटा, उदयपुर, गगानगर, बीलीडागढ़, पाली, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर व टोक जिलों में बहुत विकसित हुआ है क्योंकि इस उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल दलहन इन जिलों के आसपास के कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है।

ग्वार गम उद्योग (Guar-Gum Industry)

राजस्थान में ग्वार गम उद्योग का विगत कुछ वर्षों से तेजी से विकास हुआ है। जयपुर व अजमेर आदि स्थानों पर इस उद्योग के कारखाने स्थापित किए गए हैं। राज्य में ग्वार का पर्याप्त उत्पादन होता है। अतः उद्योग के कच्चे माल संबंधी आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है।

हथकरघा उद्योग (Handloom)

राजस्थान हथकरघा उद्योग द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनमें चादर, छद्दी, साडिया, तौलिये, धोती व पगडिया आदि प्रमुख हैं। यह उद्योग मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जालौर व

कौली आदि स्थानों पर केंद्रित है। जयपुर व जोधपुर की चुनरिया और कोटा की समूरिया साड़ी प्रसिद्ध हैं। कौली, गोविन्दगढ़ व जालोर का बना हुआ कपड़ा भी प्रसिद्ध है। बालोदय, गुड्डा, सुमेरपुर और फाल्गु में धोती व खेसले बनाए जाते हैं। जयपुर व उदयपुर की पर्पाडिया व खेस प्रसिद्ध हैं। बधाई, छपाई व रंगाई राजस्थान को प्राचीन कलाएँ हैं। इस उद्योग ने राज्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। बधेज के लिए जयपुर, जोधपुर व कोटा तथा छपाई के लिए जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर व पाली आदि प्रमुख हैं। यह उद्योग राज्य के प्रायः सभी बड़े गांवों व नगरों तक विस्तृत है। बधाई का कार्य प्रायः स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रंगाई का कार्य प्रायः पुरुष करते हैं।

(ब) खनिजों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग

Minerals based Small Scale & Cottage Industries

चूना उद्योग (Lime Industry)

चूने का उपयोग मुख्यतः निर्माण कार्य में किया जाता है। राज्य में सीमेंट की तुलना में निर्माण कार्य हेतु चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पदार्थ सीमेंट की अपेक्षा अधिक सस्ता पड़ता है तथा इसकी प्राप्ति स्थानीय स्तर पर आसानी से हो जाती है। चूना पकाने के लिए चूना भट्टों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के चूना उत्पादन व उसके बिक्री को दर्शाया गया है।

चूना उद्योग का उत्पादन व बिक्री मूल्य ¹ (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	414.76	555.60
1984-85	301.76	419.00
1985-86	524.18	731.95
1986-87	753.72	940.75
1987-88	682.43	1053.09
1992-93	1237.61	1570.37
1993-94	1833.29	2295.18
1994-95	2026.84	2542.75
1995-96	2256.05	2712.11

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1992 1994, 1995

तालिका से स्पष्ट है कि चूने के उत्पादन व बिक्री मूल्य में 1983-84 से निरन्तर वृद्धि हो रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि चूना उद्योग प्रागति पथ पर चल रहा है।

एल्युमीनियम उद्योग (Aluminium)

राज्य में एल्युमीनियम से बर्तन व खिलौने आदि वस्तुएँ बनाने का कार्य भी किया जाता है। यह मुख्यतः जयपुर, उदयपुर व जोधपुर में तेजी से विकसित हुआ है। इससे अनेक व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है। अग्र तालिका में एल्युमीनियम उद्योग के उत्पादन व उसके बिक्री

को दर्शाया गया है :

एल्युमीनियम उद्योग का उत्पादन व बिक्री मूल्य ¹ (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	-	-
1984-85	0.45	0.28
1985-86	5.18	5.69
1986-87	6.53	7.05
1987-88	8.69	8.78
1992-93	1.72	1.82
1993-94	1.80	2.03
1994-95	2.82	3.30
1995-96	2.18	2.40

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1992 1994 1995

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एल्युमीनियम में बड़ी वस्तुओं के उत्पादन मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति विकास की संभावनाओं को भी व्यक्त करती है।

पाँटी उद्योग (Pottery)

राजस्थान में पाँटी बनाने का कार्य भी छोटे पैमाने पर किया जाता है। विगत वर्षों में इस उद्योग का तेजा से विकास हुआ है। शिक्षा प्रसार के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाँटी उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा है। अग्र तालिका में पाँटी के उत्पादन एवं उसके मूल्य दर्शाए गए हैं।

पाँटी उद्योग का उत्पादन व बिक्री मूल्य ² (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	295.43	295.07
1984-85	400.97	565.29
1985-86	476.34	609.24
1986-87	558.30	681.76
1987-88	652.67	724.46
1992-93	1104.09	1361.44
1993-94	1310.44	1793.72
1994-95	1426.3	1950.11
1995-96	1581.53	2111.83

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1992 1994 1995

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में पाँटी के उत्पादन मूल्य में निरन्तर वृद्धि हुई है। इस उद्योग में भी कच्चा सामान व आवश्यक सामग्री राजस्थान में उपलब्ध है। अतः इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं।

(स) वनों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग Small Scale & Cottage Industries Based on Forests

लोहे व लकड़ी का कार्य (Blacksmith & Carpentry)

राज्य के प्रायः प्रत्येक नगर व गाँव में लोहे का कार्य किया जाता है। चकू, कैची, उस्ताह आदि यन्त्रों का कार्य

अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। पाटिया लुहार यह कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। राज्य में लकड़ी व इससे बने उत्पादों के निर्माण में हजारों व्यक्ति कार्यरत हैं। यह उद्योग राहरी क्षेत्र के फर्नीचर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बेलगाड़ी तक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उदयपुर के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। मवाईमाधोपुर व जोधपुर में भी लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। अग्र तालिका में लोहे एवं लकड़ी में बनी वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री मूल्य का दर्शाया गया है।

लोहे व लकड़ी की वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री मूल्य ¹			
(लाख रुपये में)			
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	
1983-84	513.90	715.30	
1984-85	624.79	642.15	
1985-86	694.25	775.22	
1986-87	785.50	841.40	
1987-88	892.87	932.24	
1988-89	2121.54	2869.98	
1989-90	2430.97	2313.59	
1994-95	2809.97	3713.19	
1995-96	3104.41	3918.87	

Source: State of Rajasthan 1988-89, 1994-95 & 1996

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोहे एवं लकड़ी में बनी वस्तुओं का उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है।

बेत व बांस उद्योग (Cane & Bamboo)

बांस से मुख्यतः टाकरिया कुर्तियां मेजें तथा अनेक यंत्रात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। राज्य के जयपुर, जोधपुर व जयपुर जिला में यह कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बांस का सागन बनाने का कार्य किया जाता है। अग्र तालिका में उत्पादन व बिक्री के आंकड़े हैं।

बेत व बांस उद्योग का उत्पादन व बिक्री मूल्य ¹			
(लाख रुपये में)			
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	
1983-84	77.57	113.32	
1984-85	128.86	176.38	
1985-86	160.34	170.00	
1986-87	214.60	247.00	
1987-88	281.09	331.22	
1988-89	966.00	1597.79	
1989-90	1027.00	1686.00	
1994-95	1101.00	1774.35	
1995-96	1150.70	1763.90	

Source: State of Rajasthan 1988-89, 1994-95 & 1996

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में बेत व बांस के उत्पादन मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। बेत के फर्नीचर व यंत्रात्मक वस्तुएं अत्यधिक पसंद की जाती हैं। अतः इस उद्योग के विकास का पर्याप्त संभावना है।

ताड़-गुड़ उद्योग (Palm-Gur)

राजस्थान में ताड़ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ताड़ के वृक्षों से प्राप्त फलों से गुड़ का निर्माण किया जाता है। इस व्यवसाय से भी राज्य के अनेक लोगों का रोजगार की प्राप्ति होती है। निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के ताड़-गुड़ उत्पादन एवं उसके मूल्यों की दर्शाया गया है।

ताड़-गुड़ उद्योग का उत्पादन व बिक्री ¹			
(लाख रुपये में)			
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	
1983-84	3.37	7.60	
1984-85	5.92	9.74	
1985-86	6.31	10.78	
1986-87	9.54	17.59	
1987-88	12.33	18.70	
1988-89	79.34	106.03	
1989-90	103.39	154.73	
1994-95	128.44	189.78	
1995-96	188.97	258.20	

Source: State of Rajasthan 1988-89, 1994-95 & 1996

उपयुक्त तालिका में स्पष्ट है कि ताड़-गुड़ उद्योग निरंतर प्रगति कर रहा है क्योंकि ताड़ गुड़ के उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है।

माचिस व अगरबत्ती उद्योग (Cottage Match & Agarbatti)

अजमेर व अलवर में माचिस बनाने के छोटे-छोटे कारखाने हैं। अलवर जिले में माचिस बनाने हेतु 'मालर वुड' पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। राजस्थान में अगरबत्ती उद्योग का भी कुनौर उद्योग के रूप में तेजी से विकास हुआ है। इस उद्योग को दृष्टि से अजमेर व जयपुर आदि जिले अग्रणी रहे हैं। राज्य में अगरबत्तियों का निर्यात भी किया जाता है। निम्न तालिका में माचिस व अगरबत्तियों के उत्पादन व उनके मूल्यों की दर्शाया गया है।

राजस्थान का माचिस व अगरबत्ती उद्योग उत्पादन व बिक्री ¹			
(लाख रुपये में)			
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	
1983-84	1.11	0.98	
1984-85	0.01	0.02	
1985-86	7.06	1.00	
1986-87	0.52	1.14	
1987-88	0.73	0.56	
1988-89	14.71	17.26	
1989-90	4.85	6.65	
1994-95	6.20	9.90	
1995-96	9.14	12.91	

Source: State of Rajasthan 1988-89, 1994-95 & 1996

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि माचिस व अगरबत्ती के उत्पादन मूल्य में निरंतर उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही है।

हाथ से बना कागज (Hand made Paper)

राजस्थान में अनेक स्थानों पर हाथ से कागज बनाने का कार्य किया जाता है। जयपुर के सागनेर कस्बे में हाथ से कागज बनाने का कार्य लंबे समय से किया जा रहा है। वहाँ का कागज सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इस व्यवसाय से अनेक लोगों को रोजगार का प्राप्ति होती है। निम्न तालिका में हाथ से बना कागज का उत्पादन एवं उसके मूल्यों का दर्शाया गया है।

उत्पादन व बिक्री मूल्य ²		
(लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 III	39.91	46.42
9 4 85	38.31	45.31
95 5 86	41.70	47.49
1 96 87	44.49	45.15
98 7 88	44.82	49.51
99 2 93	105.13	120.50
1993 94	66.88	76.74
1994 95	94.39	117.30
199 96	95.02	125.30

Source: Statistics of the Rajasthan 1993, 1994, 1995 & 1996

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि हाथ से बने कागज का उत्पादन मूल्य में कुछ उतार-चढ़ाव होता रहा है। लेकिन कागज के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होता है।

रेशम उद्योग (Sericulture)

रेशम उद्योग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में अतः राज्य सरकार ने कौन और उदयपुर सभाग में रेशम उत्पादन की एक योजना प्रारम्भ की। राज्य के लगभग 6000 बुनकर कोट डोरिया व मसूरिया महिलाओं का नियुक्त करते हैं इनमें लगभग 16-20 मासिक टन धागा का प्रयोग किया जाता है। यह धागा दश के विभिन्न रंगों से आभूषित किया जाता है। राज्य में हा धागे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उद्योग विभाग जनजाति क्षेत्र विकास विभाग और केंद्रीय रेशम बोर्ड समुक्त रूप में प्रयत्न कर रहे हैं। रेशम के उत्पादन के अतः रेशम के काड़ा के लिए शहतूत का खेती रेशम के काड़ा को फलकरी कागज के उत्पादन तथा कोया से शराब बनाना और धागा से रेशम तैयार करना आदि सम्मिलित हैं। इस उद्योग से दयरा के परिवार के सभी सदस्यों का नियमित रूप से रोजगार की प्राप्ति होती है। इस उद्योग में अपेक्षाकृत कम पूँजी निवेश का आवश्यकता होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति इस व्यवसाय का आसानी से मवाजित कर सकते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वा क्षेत्र उदयपुर एवं कोट सभाग का भूमि और जलवायु रेशम उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इन स्थानों पर वर्ष में काया की तीन फसलें आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं।

बीडी उद्योग (Bidi Industry)

राजस्थान में बीडी उद्योग का तबो से विकास हुआ है। राज्य में तदु पत्तों का पर्याप्त उत्पादन होता है। लेकिन इन तदु पत्तों में सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी नही हो पाती है। अतः तदु पत्तों का देश के अन्य राज्यों से आयात भी किया जाता है। बीडी बनाने का कार्य मुख्यतः स्त्रियाँ द्वारा किया जाता है। नसीरगढ़ अजमेर ब्यावर चित्तौड़गढ़ भोलवाड़ा जोधपुर व कोटा आदि स्थानों पर बीडी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। बीडी बनाने के अनेक छोटे-छोटे कारखाने स्थापित किए गए हैं।

(द) पशुओं पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग

Small Scale & Cottage Industries based on Animals

चमड़ा उद्योग (Leather)

राजस्थान में पशुओं की सख्खा अधिक है अतः राज्य में चमड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। चमड़ा से जूते, आँटियाँ, थैलें, मशक व चरस आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं। यह उद्योग राज्य के जयपुर जोधपुर व बीकानेर आदि क्षेत्रों में पूर्ण विकसित है। चमड़ा पकाने के पदार्थ राज्य में उपलब्ध हैं। चमड़े को साफ करके मुख्यतः कानपुर आगरा व मद्रास भेजा जाता है। चमड़ा उद्योग में जूतियाँ का महत्वपूर्ण स्थान है। जयपुर व जोधपुर इसके प्रमुख केन्द्र हैं। निम्नलिखित तालिका में चमड़े के उत्पादन एवं उसके मूल्यों को दर्शाया गया है।

चमड़ा उद्योग का उत्पादन व बिक्री मूल्य		
(लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1981 85	2770 II	2422.83
9 9 9	7276.8	1034.73
1993 94	1 222.99	20670.33
1994 95	9349.33	14350.51
1995 96	10744.09	16120.44

Source: Statistics of the Rajasthan 1985, 1994 & 1996

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में चमड़े के उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई। वस्तुतः राज्य में पशुपालन व्यवसाय विकसित होने के कारण चमड़ा उद्योग का तबो में विकास हुआ है। राज्य के चमड़ा उद्योग से बना वस्तुओं की अन्य राज्यों के विभिन्न भागों में अत्यधिक मांग है अतः इस उद्योग के विकास की प्रवृत्ति सभावाएँ विद्यमान हैं।

ऊना वस्त्र उद्योग (Wool Garments Industry)

राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में भेड़ों की मख्खन अधिक है। अतः उनकी प्राप्ति आसानी से हो जाता है और इन क्षेत्रों की जलवायु भी ऊना उद्योग के अनुकूल है।

ऊन वे नमड़े कम्बल आसन घोड़े व ऊट का जीनें व मोटा कपड़ा बनाया जाता है। यह उद्योग मुख्य रूप से बीकानेर जोधपुर जैसलमेर व जयपुर में विकसित हुआ है।

हड्डी पीसना (Bone Crushing)

हड्डियों को पोसकर उनका विभिन्न कार्यों की दृष्टि से उपयोग किया जाता है। पशु अधिक होने के कारण राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में हड्डिया उपलब्ध हो जाती हैं। हड्डी पीसने से मुख्यतः चोन मि न प्राप्त होता है। जोधपुर जयपुर गंगल कोटा पलाना आदि में इसके कारखाने हैं।

हाथी दात का कार्य (Ivory Work)

हाथी दात से अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विगत वर्षों में हाथी दात पर चित्रकारी का कार्य भी किया जाता है। हाथी दात का काम मुख्यतः जयपुर नाली जोधपुर व अजमेर जिले में किया जाता है। हाथी दात से बनी वस्तुओं का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है।

राजस्थान में हस्तशिल्प

HANDICRAFTS IN RAJASTHAN

राज्य के कारीगरों व कलाकारों द्वारा अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। मिट्टी पत्थर पीतल हाथी दात सूती व रेगमी कपड़े लकड़ी व चमड़ आदि पदार्थों पर हाथ से काम करके अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। पाली बगरु व सागानेर में हाथ से वस्तुओं का रंगाई व छपाई का कार्य किया जाता है। नाथद्वारा की पिछवाड़ा और बाडमेर की अजरक प्रिट सम्पूर्ण राज्य एवं अनेक राज्यों में प्रसिद्ध है। जयपुर व जोधपुर की बन्धेज की चुनरिया ओढ़निया व लहरिये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। राज्य की राजधानी जयपुर में अनेक प्रकार की विश्व प्रसिद्ध वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। 250 ग्राम रुई से बनी रजाई स्वर्ण व चांदी के आभूषण विभिन्न प्रकार के रत्न पीतल के बर्तन पर पुतई व रंगाई लाख से बनी चुड़िया मीनकारी के बर्तन सलमा मितारों की कारीगरी से बनी जूतिया सगभरमर की मूर्तिया मिट्टी व लकड़ी के आकर्षक खिलौने ज्यू पाटी से बनी वस्तुएँ ऊनी गलीचे चन्दन व हाथी दाँत से बनी वस्तुएँ खम के पानदान ऊँट की छाल से बनी वस्तुएँ आदि राज्य के विभिन्न भागों में कलाकारों व कारीगरों द्वारा निर्मित की जाती हैं। राज्य के कोटा भरतपुर चित्तौड़गढ़ व बून्देली जिलों में रेशम उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। उदयपुर कोटा व बासवाड़ा जिलों में कृत्रिम रेशम (टसर) का भी विकास हो रहा है। कृत्रिम रेशम के उत्पादन हेतु अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। इसमें न केवल पर्यावरण सन्तुलित रहता है वरन्

रासायनिक विधि से कृत्रिम रेशम का निर्माण भी किया जाता है। राज्य से विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। अतः राज्य का हस्तशिल्प व्यवसाय विदेशी मुद्रा प्राप्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हस्तकलाएँ सभ्यता व संस्कृति को प्रभावित करती हैं। अनेक प्रकार की हस्तशिल्प कलाएँ प्राचीनकाल से लेकर अब तक प्रचलित हैं। अनेक कलात्मक कृतियाँ सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। राज्य सरकार ने हस्तशिल्प के उद्योग के लिए अनेक पथस किए हैं। प्रमुख प्राप्ति हैं

1 हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना (Handicrafts Board) हस्तशिल्प उद्योग रोजगार उत्पादन एवं निर्यात की दृष्टि से राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस उद्योग का तेजी से विकास करने के लिए 1990 की औद्योगिक नीति में विशेष बल दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गयी। 27 फरवरी 1991 को राज्य विधानसभा ने हस्तशिल्प बोर्ड विधेयक को पारित कर दिया।

2 आठवीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प (Handicrafts and Eighth Plan) हस्तशिल्प के क्षेत्र में कम पूँजी विनियोजित करके बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प का विकास किया जा रहा है। हस्तशिल्प की यह इकाई पूरे प्रदेश में फैली हुयी है और य अधिकारात ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित है। इन शिल्पकारों का अपनी उत्पाद का उचित बाजार उपलब्ध नहीं होता साथ ही उनमें बाजार में विपणन करने की योग्यता की कमी भी पाई जाती है। इन कर्मियों को दूर करने के उद्देश्य से एव शिल्पकारों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत चयनित वस्तुओं के बाजार का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनकी दक्षता में सुधार लाया जाएगा तथा प्रचार एवं प्रदर्शन के माध्यम से उनकी वस्तुओं के विपणन की चष्टा की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 10 हजार कारीगरों व शिल्पकारों को लाभ पहुँचाने की सम्भावना है। इस कार्य हेतु आठवीं योजना में 1.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आठवीं योजना में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए 1.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत कला विकास केन्द्र कार्यशालात्मक निवास शिल्प कुटीर एवं हस्तशिल्प की बिक्री पर छूट आदि योजनाएँ सम्मिलित हैं। शिल्पकारों को विपणन में महादत्त करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक विपणन समिति बनाने की भी योजना है। इस हेतु 3.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया

है। आठवीं योजना के अन्तर्गत हर वर्ष छ जिलों में और इस प्रकार योजना के पाँच वर्षों में सभी 30 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

3 हस्तनिर्मित कागज के लिए सागानेर में राष्ट्रीय संस्थान' (National Institute of Handmade Paper in Sanganer) यह राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान हस्तनिर्मित कागज के देश में उत्पादन के विकास में सहयोग देगा। इस संस्थान में हाथ से बने कागजों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह के कागज के निर्माण में प्रौद्योगिकी परामर्श व्यापारिक सहायता प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास का कार्य यह संस्थान करेगा। उल्लेखनीय है कि सागानेर देश भर में हाथ से बने कागज का प्रमुख उत्पादन कन्द्र है और इस संस्थान का स्थापना सागानेर में इसलिए कागजों के संस्थान को समुचित राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) की ओर से दो करोड़ रुपये और खादा तथा ग्रामोद्योग आयोग से 1.30 करोड़ रुपये की महायत्ना एशि प्राप्त हुई है। संस्थान के लिए इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड और अमेरिका से मशीन और उपकरण मंगाए गए हैं। सागानेर में निर्मित कागज की विदेशों में बड़ी मांग है और गत वर्ष जून में व्यापार में कागजों की एक प्रदर्शनी में सागानेर के कागज की श्रेष्ठ कागज का पुरस्कार भी मिल चुका है।

4 राजस्थान लघु उद्योग निगम एवं हस्तशिल्प (Handicrafts and Rajasthan Small Industries Corporation) राजस्थान में लघु उद्योग इन्डिया तथा हस्तशिल्पियों के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम विभिन्न सम्पत्तिकारी एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियाँ चला रहा है। भूतानी कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन 3 जून 1961 को स्थापित निगम को 1 फरवरी 1975 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया था। निगम को वर्तमान अधिभूत पूँजी सात करोड़ तथा प्रदत्त पूँजी 4.90 करोड़ रुपये हैं। निगम का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं 9 अन्य निदेशक हैं। प्रबंध निदेशक मुख्य अधिकारी हैं। इनके अधीन कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक, वित्त सहायक, उप महाप्रबंधक, वाणिज्य प्रबंधक एवं प्रबंधक कार्यरत हैं। निगम की एक दशक तक घाटे में रहने के बाद वर्ष 1991-92 में लाभान्वित कर सका।

राजस्थान में हस्तकलाओं का अपनी ही विशेषता है। इन परम्परागत कलाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखी और विकासमान बनाने में राजस्थान के हस्तशिल्पियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। परम्परागत हस्तशिल्प के समुचित विकास एवं प्रचार-प्रसार का निश्चय यह निगम समर्थन प्रयासरत है। हस्तशिल्प की वस्तुओं के विपणन हेतु

निगम द्वारा प्रदेश में व अन्य राज्यों में प्रमुख नगरों में राजस्थानी एम्पोरियम जयपुर आमेर (जयपुर) उदयपुर जैसलमेर माउंट आबू, नई दिल्ली मुंबई कलकत्ता गरियाहट (कलकत्ता) आगरा अशोक हट्टल नई दिल्ली प्रगति मैदान नई दिल्ली एवं होटल ओबेरॉय टावर्स मुंबई में संचालित हैं। प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में हस्तशिल्पियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा तथा उन्हें आवश्यक जानकारी डिजाइन विकास मार्गदर्शन तथा विपणन सहयोग प्रदान किया जाता है।

विपणन के आर्थिक निगम द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर देश के कोने-कोने में एच विदेशों में भी विविध एच प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता रहा है। इनमें स्वयं कलाकारों व उत्पादकों की सक्रिय भागीदारी रहती है। निगम हस्तशिल्पियों के साथ सीधा सम्पर्क रखता है तथा माल को पारदर्शिता के साथ सीधे सप्लायरों से सीधे का जाती है। निगम द्वारा कतिपय लघु प्रमुख हस्तशिल्पियों को पुनर्जीवित करने के भी विविध प्रयास किए गए हैं। जोधपुर बाडमेर उदयपुर एवं कोटा व भजमेर में हस्तशिल्प उपार्जन एवं प्रोत्साहन केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों द्वारा हस्तशिल्पियों को बाजार में लोगों की अभिरुचि और आवश्यकता के अनुरूप कार्य हेतु प्रेरणा मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाता है। निगम के जयपुर स्थित हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केन्द्र की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाते हुए इसके माध्यम से विशिष्ट कलाओं की समुचित आधार पर विकासमान बनाया जा रहा है।

हस्तशिल्प के प्रति मुख्यतः पर्यटकों में प्रमुख आकर्षण रहता है। इसी दृष्टि से हाल ही में दिल्ली तथा जयपुर स्थित राजस्थानी एम्पोरियम का नवनाकरण किया गया है। निगम के जयपुर स्थित राजस्थानी शोर्स की प्रथम मात्र प्रदर्शनी स्थल के रूप में उपयोग करत हुए वहाँ समय-समय पर विशिष्ट प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुओं की विविध प्रदर्शनीय समयबद्ध रूप में आयोजित करने की व्यवस्था है। विगत अवधि में देश-विदेश क्यूरी पेंटिंग हाथ का छपाई के कपड़े व साडियाँ कलात्मक फर्नीचर ग्लास व फर्श आदि की प्रदर्शनी किया गया।

राज्य स्तराव पुरस्कार उत्कृष्ट कलात्मक कार्य एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए अब तक राजस्थान की 53 हस्तशिल्प राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित हुए हैं। निगम द्वारा हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय पुरस्कार की तरफ राज्य स्तराव पुरस्कार तथा दक्षता प्रमाण पत्र देने की योजना वर्ष 1994 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के श्रेष्ठ शिल्पियों को ताम्रपत्र, अंग वस्त्र तथा 5 हजार रुपये का नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है तथा अन्य

हस्तशिल्पियों को दशता पुरस्कार स्वरूप एक हजार रुपये अंग वस्त्र तथा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

पैंशन योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पियों को वृद्धवस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के हस्तशिल्पियों में से अधिकांश व्यक्तियों को ये लाभ नहीं मिल पाता अतः भारत सरकार की योजना की भांति ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष में 10 राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पियों को वृद्धवस्था पैंशन देने की योजना प्रारंभ की गई है।

सामूहिक बीमा योजना राजस्थान में हस्तशिल्पों प्रदेशभर में सुदूर अंचलो में बसे हुए हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सतोषप्रद नहीं है। भारत सरकार की नीति के अनुसार ऐसे हस्तशिल्पियों के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ की गई जिसके अनुसार सामान्य मृत्यु होने पर रुपये तीन हजार तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर उह हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम द्वारा परिवार के सदस्य को देने का इस योजना में प्रावधान है।

डिजाइन विकास एवं शोध केन्द्र हस्तशिल्प में डिजाइन विकास तकनीक को ध्यान में रखते हुए निगम के डिजाइन विकास केन्द्र में पुराने डिजाइनों को नए रंगों के साथ तालमेल कर नए डिजाइनों का विकास किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर प्रसिद्ध जयपुरी रजाईयाँ बधेज का कार्य ब्लाक प्रिंटिंग आदि नये डिजाइनों में उत्पादन विकास पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प ब्ल्यू पाट्टा भाडना साड़ियों टेराकोटा कंकालात्मक सृजन में नए तकनीक से डिजाइन विकास एवं उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है। राज्य में कनी गलीचा उद्योग के विकास की निपुण सभावनओं को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा 28 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों को 250 रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता दिया जाता है। निगम द्वारा बीकानेर में उस्ता कमिता हाइड प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित चालू रखा गया जहाँ पात्र प्रशिक्षणार्थी ऊँट की छाल पर सोने की निपुणकारी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षण कन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जाजार्ज भवन में निगम द्वारा दरी बुनाई एवं फनीचर बनाने में प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाए जा रहे हैं।

निर्यात राज्य में निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने कायत् निगम द्वारा आयात निर्यात की प्रक्रिया विपणन तथा अन्य उपकरण सुविधा की जानकारी देने के साथ साथ वर्ष 1979 में सागानेर (जयपुर) में स्थापित एयर कारगो काम्पनरूम के माध्यम से सीधे ही निर्यात की गुंती भा प्रदान की जा रही है जिसका लाभ राजस्थान के हस्तशिल्पों की वस्तुओं मितो सिनाए वस्त्र गनीच मूल्यवान एवं

अर्द्धमूल्यवान जवाहरात आदि के निर्यातक प्राप्त कर रहे हैं।

5 प्रमुख राजस्थानी हस्तशिल्प (Important Handicrafts in Rajasthan) प्राचीन काल से ही राजस्थानी हस्तशिल्प का देश विदेश में महत्व रहा है। राजस्थान हस्तशिल्प की दृष्टि से एक धनी राज्य है। राजस्थान में हाथ से बनाई गई अनेक वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी हस्तशिल्प की प्रसिद्ध वस्तुओं में मृत्युवान रत्नों की कटाई जड़ाई सोने चांदी के कलात्मक आभूषण पीतल पर खुदाई भराई पत्थर व लकड़ों पर खुदाई ब्ल्यू पॉट्टी लारा व हाथीदात का सामान चन्दन की वस्तुएं सागानेरी प्रिंट के कपड़े पाली व मारवाड़ के रंगाई छपाई के वस्त्र चोटा की डारिया साड़िया बीकानेर के कात्तीन व कम्बरा जयपुर की मूर्तिया उदयपुर सवाईमाधोपुर व झगरपुर के लकड़ी के खिलौने शाहपुर की फड पैन्टिंग जैसलमेर व बाडमेर में जाटों के कपड़े पर हाथ की छपाई नाथद्वारा जेरागी जयपुर व जोधपुर की बधेज की साड़िया उदयपुर की हाथीदात की वस्तुएं सलमा सितारों व गोटे फिनारी के काम से युक्त परिधान तागौर के लोहे के औजार आदि प्रमुख हैं।

राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकराए निम्नलिखित हैं

(i) **हाथी दात का काम** हाथी दात से कई प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। राज्य में उदयपुर जयपुर तथा भरतपुर में हाथी दात पर खुदाई व कटाई करके कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जोधपुर में हाथीदात से कलात्मक बूडिया बनाई जाती हैं जिन पर लाल काली व हरी धारिया होती हैं। हाथी दात के छिन्नाने शतरंज की मोहर कपड़े मूर्तिया महिलाओं के चुड़ मणिमा पट्टीचिया अंगूठिया व कर्णाभूषण बनाए जाते हैं।

इनके अतिरिक्त गिलास हुपेदानी पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंगा पखिया पशु पक्षी पृष्ठ पत्तिया धातुक जाटोंद्वारा कटाई से युक्त कलात्मक वस्तुएं भी हाथी दात से बनाई जाती हैं।

(ii) **चमड़े का काम** पशुधन की दृष्टि से राजस्थान एक सम्पन्न राज्य है। हस्तशिल्पों पशुओं की छाल पर अनेक प्रकार की कलात्मक एवं उपयोगी वस्तुएं तैयार करती हैं। जयपुर में गम्डे की कलात्मक जूतिया तथा जूते बनाए जाते हैं। जयपुरी बुनिया (मोजनी) कलात्मक व सजावटी होने के साथ साथ हल्केपन के कारण लोकप्रिय हैं। पर्स बैल्ट गैम आसन आदि भी चमड़े से बनाए जाते हैं।

ऊट की छाल से तल व घी रखने की कपिया शेततन्मा मुगहिया कलात्मकतापूर्ण रौम्य रोड व आसन बनाए जाते हैं।

(iii) **रंगाई पर रंगाई छपाई का कार्य** जसा पर रंगाई

वस्तियों से मिले प्रमाण इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण है। राजस्थान में मूर्तिकला कालान्तर में भी फलती फूलती रही लेकिन उसका वह व्यापक स्वरूप नहीं रहा जो ईसा की चौथी शती तक था। आधुनिक राजस्थान में भी मूर्तियाँ बनाने का कार्य विशाल पैमाने पर किया जाता है। अधिकतर मूर्तियाँ पत्थर विशेषतः सगमरमर के पत्थर से निर्मित की जाती हैं। सगमरमर से सजावटी मूर्तियाँ कलात्मक निर्माण की वस्तुएँ महापुरुषों की प्रतिमाएँ फव्वारे आदि बनाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं महापुरुषों सत्तों महात्माओं आदि की सगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ की सगमरमर के पत्थर से बनी मूर्तियों को देश एवं विदेश में निर्यात किया जाता है। इस व्यवसाय में हजारों कारीगर कार्यरत हैं। वर्तमान में जयपुर मूर्तिकला का सबसे बड़ा केन्द्र बन चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न स्थानों पर धातुओं एवं लकड़ियों से भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ बनाने में अत्यधिक समय धन एवं शक्ति खर्च होता है जबकि कारीगर को उतनी मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। अतः कारीगर हतोत्साहित होता है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थों द्वारा कारीगरों का शोषण भी किया जाता है। इसलिए अनेक कारीगर इस उद्योग के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपना रहे हैं। सरकार को राज्य में इस उद्योग के विकास हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना चाहिये।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याएँ

1 कच्चे माल का अभाव - राज्य के लघु एवं कुटीर उद्योगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में वस्त्र माल नहीं मिल पाता है। अतः वांछित माल उत्पन्न करना कठिन होता है। इन उद्योगों को एक ही किस्म का कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण उत्पादित माल का किस्म में भिन्नता होती है।

2 शक्ति की कमी विद्युत की अपर्याप्त पूर्ति के कारण न केवल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बल्कि इससे श्रमिक भी प्रभावित होते हैं। अतः उद्यमियों को आर्थिक हानि होती है। नवीन इकाइयों को विद्युत कनेक्शन देरी में मिलने के कारण इन उद्योगों का तीव्र विकास नहीं हो पाता है।

3 वित्त का अभाव राज्य के बैंक लघु एवं कुटीर उद्योगों की कार्यशील पूँजी सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अतः वित्तीय अभाव के कारण इन उद्योगों के उत्पादन एवं विपणन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

4 नवीन तकनीक का समस्या लघु एवं कुटीर उद्योगों नवीनतम तकनीक अपनाना कठिन होता है क्योंकि नई तकनीक की लागत बहुत अधिक होती है। अतः पुरानी तकनीक से उत्पादित माल की कीमतें उनी लागतों के कारण अधिक रहती हैं। अतः उत्पादित माल का बिक्रय कठिन होता है।

5 बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा लघु व कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की उच्च एवं निर्मित माल में निम्नी में बड़े

उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में लघु व कुटीर उद्योग नहीं टिक पाते हैं फलतः उन्हें हानि होती है।

6 कुशल प्रबंध का अभाव इन उद्योगों में परिष्कृत प्रबंधकों के अभाव के कारण कुशल प्रबंध का अभाव बना रहता है। अतः साधनों का अप्रच्युत एवं अकारिण हानि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

7 निर्मित माल की बिक्री की समस्या इन उद्योगों का सदैव बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा बरनी पड़ती है अतः निर्मित माल को बेचना कठिन होता है।

8 औद्योगिक रूपरूपता वित्तीय संस्थाओं में प्राप्त धन का दुरुपयोग प्रचलित अकुशलता आदि कारणों से अनेक औद्योगिक इकाइयाँ बन्द हो जाती हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की मात्रा में कमी के कारण भी औद्योगिक रूपरूपता में वृद्धि हुई।

(VIII) **पीतल की कलात्मक वस्तुएँ** जयपुर एवं अलवर में पीतल पर फुटा पत्तियों व प्राकृतिक दृश्यों की खुदाई व जडाई का काम किया जाता है। राज्य में पीतल की भिसाई तथा पॉलिश करके अनेक प्रकार की सजावटी चीजें तैयार की जाती हैं। पीतल से देवी देवताओं के सिंहासन पशु पक्षी दीपदान फूलदान जालीदार झाड़ पानूस गुलदस्ते रोम्पस्टेण्ड तथा अन्य विविध प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं।

पीतल की बटाई करके मीठाकारी का कार्य भी किया जाता है। पीतल पर पेड़ पौधों बेल दूदों पशु पक्षी युक्त बाग तथा राजा की महफिल आदि को चित्रांकित किया जाता है।

(IX) **ब्ल्यू पाट्टी** राजस्थान में बीकानेर जयपुर तथा अलवर में काच गोद गुल्तारों में मिट्टी व चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नीले सफेद हरे व काले रंग में चित्रित बेलबटों से युक्त डिजाइनदार बर्तन फूलदान एंशट्र मुण्डरी व कलात्मक खिलौने भी बनाए जाते हैं। अलावर में बहुत पुराने परतदार कागजी बर्तन बनाए जाते हैं। बीकानेर में सुनहरी चैन्डि वाले 'रीपी मिट्टी' के कलात्मक व सजावटी बर्तन व अन्य वस्तुएँ बनाई जाती हैं। कलात्मक स्मृति चिह्न भी ब्ल्यू पाट्टी से बनाए जाते हैं।

(X) **वागज** सागनेर (जयपुर) में मजजू व टिराऊ कागज बनाया जाता है। यह कागज प्राचीनकाल से ही बहुतायत रूप से महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग किया जाता रहा है। सवाई माधोपुर में भी हाथ से वागज बनाया जाता है।

(XI) **लाछव का काग** राज्य में जयपुर व जापुर में लाछव का काग अधिक किया जाता है। लाछव से खिलौने चित्रिया लगाये जाते हैं। इसके पश्चात् गुलदस्ते ईयर रिंग गले का हार अंगूठी चूड़ियाँ मूर्तियाँ आदि बनाए जाते हैं। लाछव की चूड़ियाँ व चूड़ियाँ तथा पाटले महिमा आदि चित्रित

है। महिलाओं का रचित के अनुसार लाख से बचाए जाने वाली बहुरंगी चूड़ियाँ बचूड़ा पर कांच के गोल चाकोर तथा विविध आकार के दार चिपकाए जाते हैं। जिससे इनके स्वरूप में आकर्षक बदलाव आता है। लकड़ी पर लाख का लेपन करके उचित ही कलात्मक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। लाख के स्थान पर काच व प्लास्टिक की चूड़ियों के प्रतिबद्धते आकर्षण के कारण विभिन्न प्रकार की कलात्मक चूड़ियाँ भी बनाई जाने लगी हैं।

(XII) **आभूषण** सोने चांदी के आभूषण बनाने के लिए जयपुर जोधपुर अजमेर व उदयपुर राज्य में प्रसिद्ध हैं। जयपुर में रत्ना को कटाई व जड़ाई का काम बहुत सुन्दर होता है। वर्तमान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम रत्ना को कलात्मक कटाई व पॉलिश करने का काम बढ़ रहा है। सोने चांदी तथा प्लेटिनम के खूबसूरत आभूषण भी बनाए जाते हैं।

(XIII) **ओढ़निया एवं चूनडिया** महिलाओं के परिधान की चूनडिया ओढ़निया तथा लहरिये आदि भी सुन्दर ढंग से बनाए जाते हैं। राज्य में बंधन की ओढ़नियों का विशेष प्रचलन है जिन्हें चूनडिया का नाम से जाना जाता है। जोधपुर में उत्कृष्ट क्रिस्म की ओढ़निया व चूनडिया बनाई जाती हैं। राज्य में पाली बाकानेर बीकानेर जयपुर उदयपुर व नाथद्वारा में भी बंधन साँडियों का काम होता है। घुघट की डगरगाहा भाँडनिय का विशेष प्रचलन ग्रामीणों में है। मावत भाँडा व गजगौर पर्वों पर 'लहरिया' पहने जाते हैं।

राजस्थान में ही राजस्थान में हस्तकलाओं की विभिन्न पद्धतों की वस्तुएँ बनाई जाती हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम राज्य में हस्तकला वस्तुओं को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभा रहा है।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याएँ

1 कच्चे माल का अभाव राज्य के लघु एवं कुटीर उद्योगों का उचित मूल्य पर प्रशस्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः अचित्त माल उत्पन्न कराना उचित होता है। इन उद्योगों को एक ही क्रिस्म का कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण उत्पन्न माल का क्रिस्म में भिन्नता होती है।

2 **सर्वाधिकार** विद्युत का उत्पादन पतनिक, कारखाने के तेल उत्पादन पर निर्भर। प्रभाव पड़ता है वगैरह इससे श्रमिक भी प्रभावित होते हैं। अतः उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का उपाय। अधिकृत ऊर्जा स्रोतों से मिलने के कारण इन उद्योगों को लक्ष्य विकास नहीं हो पाता है।

3 **मूल्य का अभाव** राज्य के बैंक लघु एवं कुटीर उद्योगों को आवश्यक पूँजी प्रदान करने में आसक्ति को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अतः वित्तीय अभाव के कारण इन उद्योगों के उत्पादन एवं विपणन पर विपणन प्रभाव पड़ता है।

4 **नवीन तकनीक की समस्या** लघु एवं कुटीर उद्योगों में नवीनतम तकनीक अपनाया कठिन होता है। नई तकनीक की लागत बहुत अधिक होती है। अतः नवीन तकनीक से उत्पादित माल की कीमतें ऊँची लागती हैं के कारण अधिक रहता है। अतः उत्पादन करने वाले बेचना कठिन होता है।

5 **बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा** लघु व कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की खरीद एवं निमित्त माल को बिक्री में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में लघु व कुटीर उद्योग नहीं टिक पाते हैं। फलतः उन्हें हानि होता है।

6 **कुशल प्रबन्ध का अभाव** इन उद्योगों में प्रशिक्षित प्रबन्धकों के अभाव के कारण कुशल प्रबन्ध का अभाव बना रहता है। अतः साधनों का अपव्यय एवं अधिक हानि की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है।

7 **निर्मित माल की बिक्री की समस्या** इन उद्योगों को सदैव बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ती है। अतः निर्मित माल को बेचना कठिन होता है।

8 **औद्योगिक रणनीति** वित्तीय समस्याओं से ग्रस्त धन का दुर्लभता प्रबन्धकीय अकुशलता आदि कारणों से अनेक औद्योगिक इकाइयाँ बन्द हो जाती हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की भाग में कमी के कारण भी औद्योगिक रणनीति में वृद्धि हुई।

लघु व कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सुझाव

इन उद्योगों के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न हैं।

1 सरकार द्वारा कच्चे माल का आपूर्ति समय पर की जाना चाहिए।

2 इन उद्योगों के लिए कारखाने पुँजी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3 विद्युत का पर्याप्त पुरति हेतु राज्य का विद्युत क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

4 लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल को बिक्री हेतु दूर एवं विदेशों में बाजार का खोज को जाना चाहिए।

5 नवीन तकनीक अपनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिक सहायता प्रदान की जाना चाहिए।

6 एक विशिष्ट योजना के द्वारा औद्योगिक रणनीति की समस्या का हल किया जाना चाहिए।

7 इन उद्योगों में प्रशिक्षित प्रबन्धकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8 इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल को क्रिस्म में सुधार किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान व लघु उद्योगों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the Small Scale Industries in Rajasthan
- 2 SIDBI ने राजस्थान में लघु उद्योगों की इकट्ठाई का काम मदद का है? How SIDBI has helped SSI units in Rajasthan?
- 3 जनस्थान के गांवों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना क्यों हो सकती है? इनका विकास कैसे किया जा सकता है? What village industries may be set up in villages of Rajasthan? How they may be developed?
- 4 राजस्थान की हस्तकलाओं पर चर्चा करें।
Write about hand crafts of Rajasthan
- 5 लघु एवं कुटीर उद्योगों के उदाहरण बताइए।
Mention the sub-sectors of Small Scale and Cottage Industry
- 6 लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या अंतर है? What is the difference between Small Scale & Cottage Industry?
- 7 राजस्थान में लघु उद्योगों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the small industries in Rajasthan?
- 8 राजस्थान की पट्टी उद्योगों का वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए।
Mention the present position of Pottery industry in Rajasthan
- 9 "राजस्थान का बड़ी उद्योग राजगढ़ का मरुचूर्ण स्रोत है।" बतलावा कीजिए।
Bidi Industry of Rajasthan is an important source of employment "Discuss
- 10 राजस्थान के प्रमुख हस्तकलाओं का वर्णन कीजिए।
What are the main handicrafts of Rajasthan?

(B) निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में लघु उद्योग एवं हस्तकलाओं की महत्व का समझाइए। लघु उद्योगों का समस्याओं का विश्लेषण कीजिए तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताएं।
Explain the importance of Small Scale Industries and Hand crafts in Rajasthan. Analyse the problem of Small Scale Industries and also suggest the measures to improve them
- 2 लघु एवं कुटीर उद्योगों में आप क्या समझते हैं? लघु एवं कुटीर उद्योगों का अर्थव्यवस्था में महत्व बताइए।
What do you understand by cottage and small scale industries? Describe the importance of cottage & small scale industries in the economy
- 3 राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सम्बन्धित संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Discuss the different institutions involved in the development of small and cottage industries in Rajasthan
- 4 राजस्थान के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों का वर्णन कीजिए।
Explain the main small scale & cottage industries of Rajasthan
- 5 राजस्थान की हस्तकलाओं पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Hand crafts of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

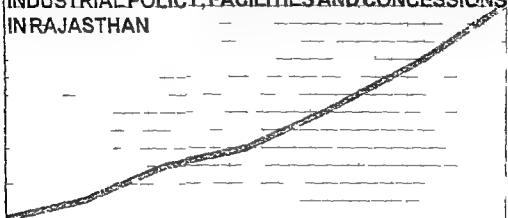
(University Examination Questions)

- 1 राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक शर्तों का विश्लेषण कीजिए।
Write a short note on Small Scale Industries and Hand crafts in Rajasthan
- 2 लघु एवं कुटीर उद्योगों में आप क्या समझते हैं? लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर बताइए।
What do you understand by cottage and small scale industries? Differentiate between cottage & small scale industries
- 3 राजस्थान के अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक शर्तों का विश्लेषण कीजिए।
Explain in brief the different cottage and small scale industries developing in the state economy
- 4 राजस्थान के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों का वर्णन कीजिए।
Explain the main cottage and small scale industries of Rajasthan
- 5 राजस्थान की हस्तकलाओं पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Hand crafts of Rajasthan

अध्याय - 16

राजस्थान की औद्योगिक नीति, सुविधाएं व रियायतें

INDUSTRIAL POLICY, FACILITIES AND CONCESSIONS
IN RAJASTHAN



"एक औद्योगिक नीति है किता राज के विकास के लिए"

औद्योगिक नीति का अर्थ व महत्व

NING &

अ राजस्थान राज्य नुसार सहाकारी साथ यह मध मरामी क्षेत्र से सम्बन्धित है।

ब राजस्थान हाथकरमा विवास निगम यह निगम व्यक्तिगत बुनकरों का है और राज्य में हैण्डलूम क्षेत्र का विकास करता है।

राजस्थान में हैण्डलूम क्षेत्र का विकास व्यवस्थापन एवं सहाय्य आधारों पर किया जायेगा। बुनकरों को उचित कीमत पर बच्चे माल तथा उपन्यास करने की सुविधा व्यवस्था की जायेगी। नवीन डिजाइनों की खोज तथा हैण्डलूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जायेगा। हैण्डलूम उत्पादों की बिक्री हेतु विपणन व्यवस्था से और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। बमजोर गाँव अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बुनकरों की आय में वृद्धि करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जायेंगे। आउटरी प्रमोशन योजना में इस एजेंसी नये हैण्डलूम स्थापित किए जायेंगे जिनसे लगभग 30 हजार व्यक्तिगतों को रोजगार की प्राप्ति होगी। उद्योग निदेशालय में हैण्डलूम प्रबोच को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।

7. हस्तकलाएं (Handicrafts) राजस्थान की हस्तकलाएं सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। यह क्षेत्र विभिन्न वस्तुओं व उत्पादन निर्गत एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के विकास हेतु अभी तक कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में हस्तकलाओं के विकास हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जायेंगे

(अ) हस्तकलाओं का वैज्ञानिक आधार पर विकास करने हेतु एक डिजाइन कवियाम केन्द्र की स्थापना की जाएगी। राज्य के कलाकारों को कला माल उपन्यास करने तथा हस्तकलाओं से सम्बन्धित वस्तुओं पर विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा विशेष प्रयास किए जायेंगे। हैण्डलूम विकास केन्द्रों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जायेगी जहाँ कलाकारों की अधिकता है। यह विकास केन्द्र कलाकारों को कला माल विपणन एवं मार्दर्शीय पूँजी अर्थात् की सुविधाएँ प्रदान करने के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम समन्वित करने के निर्धारित हेतु विशेष प्रयास रहेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम निर्वाहकों को आवश्यकता अनुसार व विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध करानेगा। राज्य में परम्परागत कलाओं व हस्तकलाओं का विकास करने के उद्देश्य में हस्तकला समन्वयन की स्थापना की जायेगी। शिल्पवाडी योजना (राजस्थान चित्त निगम द्वारा सहायता) के अन्तर्गत राज्य के

विभिन्न स्थानों पर नवीन शिल्पवाडियों की स्थापना की जायेगी। कलाकारों के लाभार्थी तलावे जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जायेगा और उनमें सुधार किया जायेगा। राजस्थान में हस्तकलाओं के विकास हेतु एक हस्तकला बोर्ड की स्थापना की जायेगी। यह एक कलाकारी संस्था होगी। वर्तमान में "मंड" व स्थानों विधायन हेतु देश के अन्य राज्यों को भेजी जात है। राज्य में ही "मंड" व स्थानों के विधायन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों के लिए वेन्डर द्वारा प्रशोजित योजनागत वृद्धिवादी पेशान स्वीकृत की जायेगी। उन क्षेत्रों में जहाँ कलाकारों की संख्या अधिक है समूह बीमा योजना व स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ करने की योजना विचारणीय है। राजस्थान में कलाओं एवं हस्तकलाओं का पूर्णतः संरक्षण किया जायेगा।

8 औद्योगिक क्षेत्रों का रख रखाव व संरचनात्मक सुविधाएँ (Infra Structure facilities and Maintenance of Industrial Areas) औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करने हेतु विशेष बल दिया जायेगा। विराम केन्द्रों के समन्वित विकास पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि आगामी दशक में इन केन्द्रों का तेजी से औद्योगिक विकास हो सके। जिन क्षेत्रों का पर्याप्त औद्योगिक विकास हो चुका है वहाँ सहाय्यकारी समितियों की स्थापना की जायेगी। इन समितियों में विभिन्न उद्यमियों के प्रतिनिधि भी होंगे। ये समितियाँ औद्योगिक क्षेत्रों के रख रखाव एवं विकास हेतु अपने सुझाव देंगी। राज्य सरकार मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्राड गेज रेलवे लाइन में परिवर्तित करने हेतु केन्द्र सरकार से बराबर अनुरोध करती रहेगी। रीलों विकास केन्द्रों पर सार्वजनिक व परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु एवं दीर्घकालीन योजना बनायेगी। राज्य सरकार औद्योगिक केन्द्रों के विकास हेतु विशेष स्कीमा का निर्माण करे केन्द्र सरकार को भेजेगी। भारत सरकार ने आनु रोड यातायात धौलपाडा रोडकैंन व धौलपुर का विराम केन्द्रों के लिए प्रयत्न किया है। आठवी योजना में प्रत्येक विराम केन्द्र पर संरचनात्मक सुविधाओं के विकास एवं विचार हेतु 30 करोड़ रुपये छुट्टी दिए जायेंगे। राज्य सरकार रूट और विकास केन्द्रों की रीतिरिक्त प्राप्त करने का प्रयास करेगी। मुख्य मंत्रि की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की जायेगी जो राज्य के विभिन्न विराम केन्द्रों का संरचनात्मक सुविधाओं का अध्ययन करेगी। यह समिति स्थानीय उद्योगमित्रों व उद्यमियों में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के मंत्रि और उद्योग मंत्रियों की स्थापना में आन सार में विभिन्न कठिनाइयों व समस्याओं का समाधान किया जा सके।

एमे उपभोक्ताओं को इस अवधि के लिए न्यूनतम निर्माण व्ययों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। औद्योगिक इकाइयों से गत तीन माह के अधिकतम उपभोक्ता पर आधारित 15 दिन के उपभोग के बराबर कैश सिक्कुरिटी वसूल की जायेगी। 'गैरल जनेरेशन सैटम' लगाने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को 2 फुट सॉबिडी दी जायेगी। यह सॉबिडी डीजल सैट्स की लागत के 25 प्रतिशत अथवा 50 000 रुपये जो भी कम होगा तक स्वीकृत की जायेगी।

14 भौतिक स्रोतों व मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण एवं विकास (Survey & Development of Human & Physical Resources)

(अ) भौतिक स्रोतों का सर्वेक्षण (Survey of physical Resources) राजस्थान में भौतिक स्रोतों का जिलावार सर्वेक्षण 1986 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया गया था। राज्य सरकार एक नया सर्वे करेगी जिसके अंतर्गत जिलाभार आधारित सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करके नवीन पार्य-योजना तैयार की जायेगी। प्रत्येक जिले के लिए उद्योग की स्थिति व अनुसार सूचनाएँ एकत्रित की जायेगी। राज्य के विभिन्न उद्यमों की समस्याएँ भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रोजेक्ट जिला उद्योग केन्द्रों में प्राप्त कर सकेगी। उद्यमियों को खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान वित्त निगम स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट, राजस्थान कन्सल्टेंसी और अन्य मस्थानों द्वारा प्रकाशित प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जायेगी। रीको के द्वारा भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जायेगी और विभिन्न उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ब) मानवीय संसाधनों का विकास (Development of Human Resources) औद्योगिक इकाई को ध्यान में रखते हुए इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट्स और पॉलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट्स के द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जायेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम, गलीचा निर्माण तथा यंत्रागत प्रविष्टि के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह निगम अन्य हस्तकलाओं के लिए भी नये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करेगा। राज्य के जनजाति क्षेत्रों में छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मर्यादा में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जायेगी और नये प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे। हैण्डलूम बुनकरों के लिए जयपुर में बुनकर सेवा सघ की स्थापना की गई है। यह सघ बुनकरों की समय-समय पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी

सलाह प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी फेडरेशन, राजस्थान राज्य हैण्डलूम विकास निगम द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। हाऊसहोल्ड इण्डस्ट्रीज प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न स्वेचिफ़ एजेंसियों द्वारा शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा निर्धन स्त्रियों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से 22 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार इनकी संख्या में वृद्धि की जायेगी। राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, राज्य के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केन्द्र चलाता है। यह बोर्ड अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार करेगा। राज्य सरकार उन कलाकारों एवं कारीगरों को सहायता प्रदान करेगी जो प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य में राज्य से बाहर भेजे जाते हैं। वर्तमान में कुछ बुनकर हैण्डलूम के प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजे जाते हैं। इन्हें स्टूडिपण्ड दिया जाता है। राज्य में उद्यमशीलता विकास करने हेतु एक उद्यमशीलता का विकास मस्थान की स्थापना की जायेगी। नागौर में परम्परागत तरीकों से हाथ के औजार तैयार किये जाते हैं। नागौर में हैण्डलूम डिजाइन डवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। यह एग्रा औद्योगिक अपना कार्य प्रारम्भ करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ऐसी ही अन्य संस्था की स्थापना के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। इसी प्रकार यह प्रस्ताव भी भेजा गया है कि ट्रेनिंग फॉर प्लास्टिक एण्ड इजीनियरिंग टूल्स, मद्रास का एक शाखा कार्यालय राजस्थान में खोला जायें। रीको ने भी एक टूलरूम स्थापित करने का प्रयास किया है। अजमेर में एक सैरेमिक ट्रेनिंग सेंटर तथा जयपुर में आयुषण डिजाइन सेंटर की स्थापना की जायेगी। राज्य में निर्मित परिधानों के निर्माण की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने परिधान डिजाइन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया है।

12. सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र (Public & Joint Sectors) राज्य सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि केन्द्र सरकार, राज्य में स्थित केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अधिक पूंजी का विनियोजन करे। राज्य सरकार उपलब्ध साधनों, के अनुसार राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पूंजी विनियोजित करेगी। रीको, अशपूजी के माध्यम से संयुक्त क्षेत्र में विनियोजन करता है। इसके अतिरिक्त, रीको, बड़े उद्योगों में अशपूजी के माध्यम से विनियोजन करने का प्रयास करेगा। विभागीय आधार पर राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जायेगी। घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लाभ की स्थिति लाने के प्रयास किए जायेंगे। यदि इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो

ऐसे मार्गजनिक उपग्रहों को बन्द करने पर विचार किया जायेगा।

13 एम्प्लीतरी इण्डस्ट्रीज़ (Ancillary Industries)

वर्तमान में राजस्थान राज्य में 69 एम्प्लीतरी इन्डस्ट्रिया फ़ैक्टरीयें हैं। इनमें से 42 इकाइया इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा 14 इकाइया हिन्दुस्मान मशीन टूल्स लिमिटेड, अबमेर, 8 इकाइया हिन्दुस्मान वॉर्ग लिमिटेड, खेतड़ी और 6 इकाइया हिन्दुस्मान पिक लिमिटेड उदयपुर पर आधारित हैं। एम्प्लीतरी उद्योगों के विकास हेतु राज्यस्तर पर एक मण्डल विद्यमान है। राज्य में एम्प्लीतरी उद्योगों का सर्वेक्षण किया जायेगा और इन उद्योगों के विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे। राज्य सरकार निम्न क्षेत्र व सर्वजनिक क्षेत्र में और अधिक एम्प्लीतरी इण्डस्ट्रीज़ की स्थापना का प्रयास करेगी।

14. प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सिंगल विण्डो सिस्टम (Simplification of Procedure and Single Window system)

प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रयास किए जायेंगे। जिलास्तर पर उद्यमियों को मिगल विण्डो सेवा प्रदान करने के उद्देश्य में चयनित क्षेत्रों पर नवीन योजना लागू की जायेगी। यदि यह योजना सफल रही तो इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया जायेगा। गैरों में राज्यस्तर पर सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करने का उद्देश्य से, व्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन नामक एक पृथक प्रकल्प की स्थापना की गई है। यह प्रकाश अपना वर्तमान स्थिति में सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। अतः राज्य स्तर पर एक पृथक व्यूरो और इण्डस्ट्रियल प्रमोशन स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा मध्यम बड़े उद्योगों के उद्यमियों को मिगल विण्डो सेवा का सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जायेंगे। विभिन्न मन्त्रिणाएँ एवं विभागों व्यूरो के अन्तर्गत बनाई गई मण्डल के मध्यम व उद्यमियों को प्रदान की जायेंगी ताकि उद्यमियों का विभिन्न विभाग विभागों व बोर्ड्स में नहीं जाना पड़े। इन व्यूरो में एक डाटा बैंक की स्थापना भी की जायेगी जहाँ विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स सम्बन्धित भूमि जल व शक्ति की उपलब्धता आदि की जानकारी हो सके। इस उद्देश्य को प्रति हेतु राज्य व जिला स्तर पर सलाहकार मण्डलों का पुनर्गठन किया जायेगा और उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये प्रयास किए जायेंगे।

15 ऋण सुविधाएँ (Loan Facilities)

अ) राजस्थान विन निगम 2 हजार रुपये में 90 लाख रुपये तक व ऋण स्वीकृत कर सकता है। इन ऋणों पर व्याज की दर 10 से 14 प्रतिशत के मध्य रहती है जबकि डोवल जेन्टिल मैन्स पर यह 17 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं

जनजाति के लोगों को एक लाख रुपये तक के ऋण पर व्याज दरों में 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है। उन्हें 5 प्रतिशत के मार्जिन पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान विन निगम ने ऋण स्वीकृत करने की शक्तियों को विकेंद्रित कर दिया है एवं ओर सग्न बना दिया है। 7 50 लाख रुपये तक के ऋण त्रिना एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 40 लाख रुपये तक के ऋण अन्तर्जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर वितरित किये जा सकते हैं। भूतपूर्व मैनिकों और विकलांगों को निगम द्वारा कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ब) रोकें भारत के औद्योगिक विकास बैंक की नीतियों के अनुरूप मध्यम स्तर के उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। निगम 150 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करता है। विशेष परिस्थितियों में राजस्थान विन निगम एवं रोकें समुक्त रूप से भी उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार राज्य में ही 24 करोड़ रुपये तक के ऋण उद्योगों को उपलब्ध करायें जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में बैंक भी 50 लाख रुपये तक के ऋण अतिरिक्त प्रदान कर सकता है। इस प्रकार उद्यमियों को लगभग 3 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध हो जाता है।

(ग) कभी-कभी नये उद्यमों के लिये मार्जिन मनी बुटलन मुश्किल हो जाता है। कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए भारत का औद्योगिक विकास बैंक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड और राजस्थान विन निगम के माध्यम से बीबीपूजी योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई को परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक बीबीपूजी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जिसकी उरि अधिकतम 15 लाख रुपये तक हो सकती है।

(द) रोकें के माध्यम से कुछ चुने हुए मध्यम व बड़े आवरणों के उद्योगों में राज्य सरकार भी पूँजी विनियोजित कर सकती है। कुछ मामलों में निगम अशो के अभिगोपन की भी सुविधा प्रदान करता है तथा वणिज्यिक बैंक से भी इन हेतु प्रार्थना की जा सकती है।

(इ) बैंक मुख्यतः कार्यशाला पूँजी के लिए ऋण प्रदान करते हैं। राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि उद्योगों को समय पर एवं पर्याप्त कार्यशाला पूँजी उपलब्ध हो सके। राजस्थान विन निगम ने कम्पोजिट लोन की योजना आरम्भ की है जिसमें 7 50 लाख रुपये तक ऋण स्वीकृत किये जा सकते हैं। उनमें से 5 लाख रुपये स्थायी पूँजी विनियोग और 2 5 लाख रुपये कार्यशाला पूँजी के लिये हो सकते हैं। इस योजना को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है परन्तु सरकार ने हाल ही में कम्पोजिट लोन

की राशि को 10 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है।

(ग) राजस्थान वित्त निगम द्वारा 50 हजार रुपये तक के ऋण अब जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किए जायेंगे।

16. पूँजी विनियोग अनुदान (Capital Investment Subsidy) :

(अ) राज्य में स्थापित किये जाने वाले नये मध्यम वृहद् आकार के उद्योगों को उनके स्थायी पूँजी विनियोग का 15 प्रतिशत भाग पूँजी विनियोग अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। जिसकी अधिकतम राशि 15 लाख रुपये होगी।

(ब) लघु एवं सहायक उद्योगों, राज्य के स्वतंत्र पर आधारित कुछ चयनित उद्योगों, अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा शत-प्रतिशत निर्यात वाले उद्योगों को नये उद्योग की स्थापना करने पर उनके स्थायी पूँजी विनियोग का 20 प्रतिशत पूँजी विनियोग अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम राशि 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(स) ऐसे उद्योगों को स्थायी पूँजी विनियोग का 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा जो 1948 के फेदरी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड एवं नये श्रमप्रधान उद्योग होंगे। इन उद्योगों का प्रति श्रमिक पूँजी विनियोजन 35 हजार रुपये से कम होना चाहिये। इनको उपलब्ध होने वाले अनुदान की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये हो सकती है।

(द) पूँजी विनियोग अनुदान राज्य में सभी जगह उपलब्ध होगा किन्तु जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा की शहरी सीमा में उपलब्ध नहीं होगा। कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि को पूँजी विनियोग अनुदान पूरे राज्य में उपलब्ध होगा।

(घ) अब भी केन्द्रीय विनियोग अनुदान योजना लागू होगी, उगा व अनुरूप राज्य पूँजी विनियोग अनुदान योजना को परिष्कृत किया जायेगा। जिस सीमा तक केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध हो रहा है, उस सीमा तक राज्य अनुदान उपलब्ध नहीं होगा।

17. छिन्नी कर की रियायतें (Sales Tax Concessions) : राजस्थान की बिक्री कर प्रोत्साहन और 'डेकरमेंट' योजनाएँ 1987 व 1989, जो नई इकाइयों और व्यापक विस्तार एवं विविधीकरण करने वाली इकाइयों के लिए लागू थी तथा 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली थी, उन्हें 31 मार्च, 1995 तक बढ़ा दिया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को

दूर करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार की योजनाएँ भी बनाई गई जिसमें शत-प्रतिशत विस्तार और विविधीकरण करने, अपने उत्पादन को शत-प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ाने पर भी बिक्री कर रियायतों की घोषणा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1986, 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो गई थी। अतः 1987 और 1989 की योजना में आवश्यक सुधार कर उसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर लागू किया गया। बीमार इकाई के पुनरुद्धार के लिए भी रियायत प्रदान की गई। आठवीं योजना के अंतर्गत सीमेन्ट, तन्वाकू, टैक्सटाइल्स, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य विधायन एवं छनिजों पर आधारित इकाइयों को मशीनरी क्रय करने पर बिक्री कर नहीं देना होगा। उद्योगों की एक अतिरिक्त 'वैरी प्रेस्टिजियम इण्डस्ट्रीज' को बिक्री कर में रियायत देने के लिए चुना गया है। ऐसे उद्योग जिसमें 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की स्थायी पूँजी लगी हो उन्हें 'अधिक सम्मानित उद्योग' श्रेणी में रखा गया है। छिरे एवं जवाहरात उद्योगों को भी करों में छूट प्रदान की गयी है। आठवीं योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए 'बिक्री के बदले में ब्याजमुक्त ऋण' की एक नई योजना आरम्भ की जा रही है इसमें इकाई द्वारा दिये गये बिक्री कर के बदले में उसे 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसका लाभ वे ही इकाइयाँ उठा सकेंगी जो अन्य बिक्री कर रियायतों का लाभ नहीं ले पा रही है।

18. चुगी से मुक्ति (Octroi Exemption) : आठवीं योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले नये उद्योगों को व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिये कच्चे माल पर चुगी नहीं देनी होगी। इन नई औद्योगिक इकाइयों को आयातित प्लाट एण्ड मशीनरी पर भी चुगी नहीं देनी होगी। पहले से ही विद्यमान उद्योगों द्वारा, आठवीं योजना के अंतर्गत विस्तार के उद्देश्य से, आपात की गई प्लाट एण्ड मशीनरी पर भी चुगी देय नहीं होगी।

19. मण्डी कर से मुक्ति (Exemption from Mandi Tax) : कृषि पर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मण्डी कर से मुक्ति देने का निश्चय किया गया बशर्त कि अपनी आवश्यकता का सामान सीधे कृषक से क्रय करें। यह सुविधा उन्हें व्यापारिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए उपलब्ध होगी।

20. अन्य वित्तीय रियायतें (Other Financial Concessions) : राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक

रेगा। यह सुविधा भी आठवीं पाठ्यपीय योजना के अन्तर्गत जारी रहेगी। राज्य में व्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बी आई एस) की कोई परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। इसमें उद्योगों विशेषकर लघु उद्योगों को अनेक उठानाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार व्यूरो में राज्य में परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना प्राथमिक है ता राज्य सरकार उस हस्तक्षेप सहयता प्रदान करेगी। इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट सेक्टर जयपुर में एव प्रयोगशाला चला रहा है। राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इंजीनियरिंग कॉलेज व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अधिकृत परीक्षण वेन्ट्रों में परिवर्तित करने में हम विचार जो बड़ी मात्रा में व्यय करते हैं उनके परीक्षण उपकरण बचाने जायेंगे। राज्य सरकार उन कॉलेजों और युनवर्स को प्रगतिशील अनुदान देने पर विचार करेगी जो किसी अधिकृत संगठन में अपनी उत्पादन के डिजाइन और डिम्स का सुधारने के लिए प्रगतिशील करेंगे।

24. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों का विशेष सहायता (Special Assistance to SC & ST Enterproneurs) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। उन उद्यमियों का वित्त और औद्योगिक क्षेत्र 4000 वर्ग मीटर भूखण्ड पर उन्हें के लिए 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। इन उद्यमियों का गजस्थान विशेष निगम द्वारा प्रत्येक एक लाख रुपये तक के प्रयोग पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इन 25 प्रतिशत का स्थान पर केवल 5 प्रतिशत मार्गिन मनी की ही आवश्यकता होती है। इन उद्यमियों के लिए गेलफ एम्प्लॉयमेंट टू एज्यूकेटेड युवक योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध है। इस प्रेमी व उद्यमियों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करायेगा। ट्रांसमिशन मार्गान क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को भी अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

25 महिला उद्यमी (Women Enterpreneurs)

महिला शक्ति एवं महिला उद्यमी कोष योजना एवं हाउसहोल्ड इण्डस्ट्री स्कीम का इस प्रकार से विचार किया जायेगा कि इसमें अधिक से अधिक महिला उद्यमी आ पायें। उद्यमी विकास कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए अलग से चलाया जाएगा और उन्हें ऋण एवं भूमि आदि में प्राथमिकता दी जायेगी। उद्यमी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को विशेष ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। यीको इन महिला उद्यमियों को भूमि आपूर्ति में

देने के प्रस्ताव पर विचार होगा।

26. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness)

राज सरकार रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए प्रेरित है। इस हेतु निम्नलिखित क़ाम उठाये जा रहे हैं।

(अ) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रुग्ण इकाइयों में न्यूनतम शुल्क और पावर कट में मुक्ति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार राजा राज्य विशेष निगम या एन आई एन आर द्वारा स्वीकृत योजना के आधार पर उद्योगों को सहायता प्रदान करने का विचार करता है। अतः यह सुविधा सैद्धांतिक और केन्द्रीय विभाग संगठनों द्वारा मनी (एन ई) के आधार पर व्यवस्था होगी। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार करेगी कि रुग्ण लघु उद्योग इकाई इस प्रकार का प्रमाण पर जितावस्तु पर भी प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त रुग्ण इकाई का पावर कट में 2 वर्ष के लिए छूट भी प्रदान की जायेगी।

(ब) राज्य में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का संशोधन कराना जायेगा और उसके परिणामों के आधार पर ही इकाइयों के पुनरुद्धार में प्रयास किए जायेंगे। रुग्णता के कारण ही रुग्णता से जायेगा और उनके दूर करने में प्रयास किए जायेंगे।

(ग) जिला स्तर पर एन सीसी बनवाई जायेंगी ता कि उद्योग इकाइयों के पुनरुद्धार में योजनाएं बनायेंगी ता उन विचारित होंगी। यतः सीसी विभागों में आगे के सहायता सीसी का उपसर्गित रूप में कार्य होगा ताकि निश्चितता में एक अलग प्रमाणित स्थापित किए जायेंगे ता रुग्ण इकाइयों की समस्याओं का समाधान और उन समस्याओं को दूर करने में सुझाव देगा।

(द) ऐसी रुग्ण इकाइया जिनके मामलों बी आई एफ आर के समान विचारणीय उनके मामलों की प्रकृति एवं पुनरुद्धार प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी।

(1) पुनरुद्धार व पावर कटों के लिए विद्युत इकाई को स्थान तथा राशित राशि पर यात्रा बर्तमान आदि में मुक्ति प्रदान की जायेगी।

(2) इसी तरह के रूप में विद्युत इकाई को ही राजा राशि की पुनः समय परीक्षा के लिए यात्रा बर्तमान आदि में मुक्ति प्रदान करना। पुनरुद्धार के समय में सीसी राशि के स्थान पर भुगतान में मुक्ति।

(3) रुग्ण इकाई का पुनरुद्धार पुनरुद्धार पैरिड के आधार पर व्यापकता से उपलब्ध कराई जायेगी। 4 वर्ष के लिए सीसी की अधिकतम भूमि का प्रत्येक रुग्ण उद्योग में उपलब्ध कराई जायेगी। यह विचार राज्य सरकार द्वारा

31 उद्यमियों से अपेक्षा (Expectation from Entrepreneurs) राज्य सरकार उद्यमियों से आशा करती है कि उद्यमी बिक्री कर आयकर एवं राज्य में उपलब्ध कच्चे मान का उपयोग कर राज्य के सहायकों में वृद्धि करेंगे। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे अधिार से अधिार कुशल एवं अकुशल श्रम राज्य से ही प्राप्त करेंगे। उद्यमियों से आशा की जाती है कि वे प्रदूषण नहीं फैलावें। उद्यमियों से यह भी आशा है कि वे अपने औद्योगिक श्रम चल रहे विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

राजस्थान की औद्योगिक नीति की समीक्षा EVALUATION OF INDUSTRIAL POLICY OF RAJASTHAN

राज्य के औद्योगिक इतिहास में 1990 की औद्योगिक नीति उल्लेखनीय महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार की औद्योगिक नीति 1991 को ध्यान में रखकर इस नीति को तैयार एवं उद्धार बनाया है। पचास लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने के अधिकार जिलास्तर पर दिये गये हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इकाई स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति से अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-आवरण व लिए लीज होटल जारी करने के अधिकार जिला उद्योग केंद्र को दिये गये हैं। राज्य एवं राज्य के बाहर के उद्यमियों को आकर्षित करने में राजस्थान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 1991-92 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। अनेक एवं वर्ष में सर्वाधिक सफल उद्यमियों एवं औद्योगिक घरानों ने राजस्थान आकार छात्र एवं मध्यम श्रेणी उद्योग लगाये हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न सुविधाएँ प्रियायतें देकर राज्य के औद्योगीकरण के लिए उद्यमियों को आकर्षित किया है। राज्य में अधिार विनियोजन के लिए सरकार ने उद्योगों को उद्धार वित्तीय सुविधाएँ सुनिश्चित की हैं। नये उद्योगों को पूँजी विनियोग अनुदान में 15 से 35 लाख रुपये की छूट दी है। बिक्री कर स्थगित करने की सुविधा डीजल जनरेटर सेट पर 50 हजार तक अनुदान तथा जल यंत्रों पर 20 हजार रुपये अनुदान जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। कलाश्रम व शिल्पश्रम योजना के तहत राज्य सरकार वर्षों के आधुनिकीकरण व लिए अनुदान देती है। यह अनुदान भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीकृत इकाइयों को सुलभ कराया जा रहा है। इसी प्रकार नई औद्योगिक इकाइयों को भी यह सुलभ कराया जा रहा है। इसी प्रकार नई औद्योगिक इकाइयों को भी नये मान की खरीद व नई परियोजना के लिए मशीनरी प्राप्त करने पर पात्र लोगों के पुँजी से मुक्ति देने जैसी सुविधाएँ राज्य में उपलब्ध कराई जा रही हैं। लघु उद्योगों में उत्पादित मान

पर सरकारी खरीद में 15 प्रतिशत की विपणन सहायता उपलब्ध कराया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने उद्योगविहीन जिलों एवं आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाली सभी वृद्ध, मध्यम एवं लघु इकाइयों को विनियोजन अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना में दिया जाने वाला अनुदान अन्य योजनाओं में मिलने वाले अनुदान से अधिार है।

वृद्ध एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा कुछ क्षेत्रों में 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये हो गई है। लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा भी 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। शेष पूरे राज्य में पूर्व घोषित 15 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। अप्रवासी भारतीयों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा राज्य में उद्योग लगाए जाने पर 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 35 लाख रुपये के अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शत प्रतिशत निर्यातानुमुख इकाइयों को विशेष मामलों में रियायतें एवं सुविधाएँ दी जा रही हैं। राज्य के बाहर के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए रीको रियल निगम तथा उद्योग विभाग की ओर से आयोजित दिये जाने वाले मधुकर अभियान विधायित्व रूप से जारी है। राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन व्यूटों की स्थापना की गई है जो मध्यम एवं वृद्ध श्रेणी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रवासी राजस्थानियों से निरन्तर सम्पर्क में है। उद्योग विभाग में रूपण इकाइयों को द्वारा शुरू करने के लिए प्रवृद्ध से प्रवृद्ध बनाया गया है। जिनास्तर पर भी ऐसे ही प्रवृद्ध बनाये गये हैं। रीको ने अग्रे 91 तक 36 रण इकाइयों का पंजीयन किया। इनमें से 16 औद्योगिक इकाइयों में पुनः उत्पादन शुरू हो गया है। इन इकाइयों में उत्पादन शुरू कराने के लिए 25 करोड़ के लगन के मुताबत में 36.8 करोड़ रुपये का ऋण सुलभ कराया गया है। ऋण के अलावा इन इकाइयों को अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। आठवीं पाँचवीय योजना में उद्योग एवं खनिज के लिए 536 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजनागत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली 50 औद्योगिक इकाइयों में 1 लाख 25 हजार लोगों को रोजगार सुलभ हो सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अनामछलों के लिये योजना में विशेष प्रावधान की गई है। इसका अतिरिक्त आठवीं योजना में 10 हजार परियोजनाएँ लागू जायेंगी जिनसे 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। तई बिक्री कर तथा व्याजमुक्त योजना शुरू की जा रही है। भारत सरकार ने अपनी विशाल वस्त्र योजना के अन्तर्गत आठवीं योजना के अन्तर्गत खाताशुद्ध एवं भीतराज का गन्त किया है। मौलाना में भी विकास उद्देश्य स्थापित करने की

स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। रीको व राजस्थान वित्त निगम राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रीको ने 185 औद्योगिक क्षेत्रों में 18679 औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये हैं। इसी प्रकार रीको ने वर्ष 1992-93 में 64 बड़े उद्योगों की स्थापना में प्रमुख निभाई। राजस्थान लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों का इकाई को समर्थन प्रोत्साहन देने में मग्न है। निगम ने ग्रामीण दस्तकारों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की एक योजना प्रारम्भ की है। मद्रास में 'रेडसर्पल' की स्थापना कर किये 15 लाख रुपये का आवधान किया गया है।

औद्योगिकरण की प्रगति को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने भी राजस्थान में अपने परियोजनाएँ लगाने में काफी रुचि दिखाई है। कुछ परियोजनाएँ विदेशी मदद से संचालित हो रही हैं। श्राप आकड़ों के अनुसार रीको की मदद से 16 नई परियोजनाएँ राज्य में लगाई जायेंगी। इनमें लगभग 1400 करोड़ रुपये का विनियोग होगा। इनमें से सात परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। राज्य की अधिकांश रेलवे लाइनें मॉडर-गैज हैं, जो अब बदली जा रही हैं। ब्रॉड-गैज हो जाने के बाद रेलवे लाइनों के समीपवर्ती शहरों व कस्बों में औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ जायेंगी। वर्ष 1995-96 के अन्त तक दो हजार मिलेनोटर रेलवे लाइन ब्रॉड गैज में बदली जानी थी। वर्ष 1991-92 में 1 58 252 लघु उद्योग राज्य में स्थापित हो चुके थे जिनमें 1,00 182 करोड़ रुपये का विनियोजन हो चुका है। ये लघु उद्योग 5,94 005 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ करा रहे हैं। बड़े व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की संख्या बढ़कर 287 हो गई है। जिनमें 1 31 110 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 72 औद्योगिक इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और पाली जिले औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित हो गये हैं जबकि भिवाड़ी क्षेत्र देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। जहाँ हर उद्योग उद्योग लगाना चाहता है क्योंकि यह दिल्ली के नजदीक है और यहाँ पर सभी आधारभूत सुविधाएँ मौजूद हैं। इस प्रकार राजस्थान जो पूर्व में मरुस्थलीय राज्य के रूप में जाना जाता था अब औद्योगिक परियोजनाओं का केन्द्र बन गया है। अब राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य में उद्योगों की भरमार हो जायगी।

राजस्थान सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योगधर्मन के संदेश का खण्ड

स्तार पर पहुँचाने का निश्चय किया है। तर्क औद्योगिक विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। राजस्थान सरकार ने 115 प्रकार की लघु व अलिलु स्तर की इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण के दायरे में बाहर निकालने का निश्चय किया है। इन इकाइयों को अब राज्य नियंत्रण अर्जेंट रियो से अनुपति प्रमाण पर प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने उन उद्योगों के लिये भी कुछ कदम उठाये हैं। जिनमें अधिक प्रदूषण होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के उद्योगों को वर्गीकरण किया जायेगा। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्वरित प्रतिवेदन निकालने के उद्देश्य से उद्योगों में उच्चस्तर पर पर्यावरण की स्थापना की गई है। वर्तमान प्रणाली को भी मग्न बनाया जा रहा है। जिलास्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों को उद्यमियों में प्रभावी सम्पर्क बनाने के लिये क्रियाशील बनाया जा रहा है। मजदूरों पर अन्तर-संस्थागत समिति (आई आई सी) जिसमें सभी सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधि होते हैं, अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जायेगा। भूमि रूपान्तरण के नियमों को प्राथमिक क्षेत्रों में और अधिक सरल बनाया जा रहा है। तर्क उद्यमियों को अधिक प्रेरणा दी देगी न हो। राजस्थान सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि स्थानीय समाजों पर आधारित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जायेंगे।

राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति- 1994*

नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 15 जून, 1994 को की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भाग्य मरता की नवीन औद्योगिक नीति 1991 के अनुरूप राज्य की नीति में परिवर्तन करना था। राजस्थान सरकार ने भी केन्द्र की औद्योगिक उद्योगकरण नीति का अनुसरण किया। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति, 1994 के प्रमुख मन्त्र निम्नलिखित हैं।

उद्देश्य

Objectives

राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1994 का मुख्य उद्देश्य कार्यविधि में मरताकरण, शीघ्रता से प्रकरणों का निम्नरण आर्थिक प्रोत्साहन एवं विभिन्न उपायों द्वारा राज्य में शीघ्र औद्योगिक विकास करना है। नवीन औद्योगिक नीति में राज्य के लघु एवं प्रामाण्य उद्योग, रोजगारोत्पन्न उद्योग एवं मरिता उद्यमियों हेतु पर्याप्त सहयोग दिये जाने की व्यवस्था की गई है। निर्यातवर्धन की राष्ट्रीय प्रामुखिता को ध्यान में रखते हुए निर्यात वृद्धि पर विशेष महत्व दिया गया है। इस औद्योगिक नीति से नये उद्योगों को प्रोत्साहन एवं रियायतें उपलब्ध होंगी।

- (i) राजस्थान का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना।
- (ii) राजस्थान के विभिन्न ससाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना।
- (iii) रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करना ताकि अतिरिक्त अवसरों का सृजन हो सके।
- (iv) प्रादेशिक असमन्तुलनों को समाप्त करना।
- (v) निर्यातों में वृद्धि करना।
- (vi) खादी, हथकरघा ग्रामीण उद्योग दस्तकारी लघु उद्योग तथा अतिलघु उद्योगों का विकास करने हेतु सहायता प्रदान करना।

व्यूह-रचना

Strategy

- (i) विनियोगों में वृद्धि के लिए प्रयास करना।
- (ii) औद्योगिक आदानों की तेजी से पूर्ति करना।
- (iii) स्वीकृतियों के मामलों को शीघ्र निपटाना।
- (iv) भौतिक एवं सामाजिक आधार-संरचना को सुदृढ़ करना एवं इसका विस्तार करना।
- (v) नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना।
- (vi) सरचनात्मक विकास में निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि करना।
- (vii) रोजगार वृद्धि की दृष्टि से विनियोग करना तथा श्रमीण एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना।
- (viii) दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार करना।
- (ix) अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।

व्यूह रचना एवं नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं

(अ) आधार-संरचना (Infra-structure)

- 1 सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी लेकिन ऐसा औद्योगिक क्षेत्र सैको के क्षेत्र से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए।
- 2 औद्योगिक कार्यों के लिए भूमि का रूपान्तरण किया जायेगा। 5 हैक्टेयर तक के भू-क्षेत्र का रूपान्तरण सम्बन्धित अधिकारी आवदन प्राप्त के 30 दिन की अवधि में कर देगा अन्यथा स्व। स्वीकृति मानी जायेगी। 5 म 20 हैक्टेयर भू-क्षेत्र के रूपान्तरण का अधिकार खण्ड कमिशनर को होगा नमक भण्डार के अन्तर्गत हेतु सरल नियम बनाय जायगा। सरकार नमक वाले भू-क्षेत्रों की लीज का अर्जा 10 वर्ष में बढ़ाकर 20 वर्ष कर रहा है।

3 शक्ति-क्षमता में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने के लिए एक पृथक समिति गठित की गई है। औद्योगिक इकाइयां अथवा शक्ति मयत्रों को स्थापना कर सकेंगे।

4 यमुना जल समीप के राज्य के पूर्वी भाग का 1119 करोड़ घनमीटर जल उपलब्ध होगा इन्दिरा गंधी नहर चम्पल एवं भारी परियोजनाओं से राज्य के अनेक क्षेत्रों को जल प्राप्त होगा।

5 1995-96 तक लगभग 2000 किलोमीटर लम्बे मीटरगज रेलमार्ग को बाड़गेज में बदल दिया जायेगा। इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। सड़क निर्माण कार्य में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

6 सैको ने मॉन्टे बैकिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया है अतः योजनाओं के लिये अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे। निजी उद्यमियां को इक्विटी के रूप में अधिक सहायता दी जायेगी।

7 सरकार आधार मराना व विकास हेतु निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन करेगी। सरकारी स्वामित्व के प्राचीन भवनों का छूटता का रूप देना हेतु सरकार निजी क्षेत्र को आमन्त्रित करेगी।

(ब) शीघ्र स्वीकृतियां एवं प्रणाली का सरलीकरण (Speedy clearances and simplified systems)

1 115 उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनारथन प्रमाण पत्र लेने में मुक्ति दिया गया 26 उद्योगों का लाल क्षेत्री (सर्वोच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग) में रखा गया तथा 32 उद्योगों को 'नारंगी क्षेत्र' (कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग) में रखा गया। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड 15 वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करेगा लेकिन लाल क्षेत्री व नारंगी क्षेत्रों के लिये यह अवधि क्रमशः 3 वर्ष व 5 वर्ष होगी स्वीकृति के नवीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा।

2 उद्योगों के निरीक्षणों का आवेदन पत्र सुधार किया गया वर्तमान में 14 श्रम जानूनों के अन्तर्गत उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है। अब पृथक-पृथक निरीक्षणों को 'नारंगी' का समाप्त करके एक सामान्य व्यवस्था लागू की जायेगी। 20 व्यक्तियों से कम श्रमिकों का सन्तार प्रदान करने वाले अति लघु आवासीय इकाइयों में में सैफ्टी आभार पर 11 प्रतिशत इकाइयां का निरीक्षण किया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों व सामान्य निरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारियों के लिखित में प्रमाणित किया गया होगा कि वे निरीक्षण हेतु योग्य हैं।

महिला उद्यमिका द्वारा रणगिरा इकाइयों को विक्रीकर म
शन प्रतिष्ठापना (13 वर्षों के लिए) दी जाएगी।

रत्न साइडिंग ग्रुप गॉलिंग स्टाक तथा गेन इन्वेंटोरी को
स्थिर परिसम्पत्तियों में सम्मिलित कर लिया गया।

गाफ्टरग्रुप इकाइया (10 करोड़ से अधिक निवेशों
वाली) को इस योजना का नकारात्मक मुद्दा से निम्नलिखित किया
गया।

आस्थागत योजना में विक्री कर को एक्जिस्टिंग गिरा
मुक्तिवादा तानु हान के 5 वर्ष बाद देय होगा।

धर्ममन्त्र इकाइया को स्थिर पूँजी निवेशों के अंतर्गत
20% तक लाभ दिया जाएगा।

आर्थिक अस्वीकृत तथा गिरा इकाइयों को यह
मुक्तिवादा प्रदान की जायगा।

गिरा निवेशों उद्योगों को जो म रणगिरा गॉलिंग स्टाक
100 करोड़ रुपयों में अधिक निवेशों (गॉलिंग स्टाक) को आस्थागत
योजना में लाभ 25 प्रतिशत में बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया
जायगा।

ईसरोपों पर कर को 25 प्रतिशत में कम करके 1
प्रतिशत किया जायगा।

कामान 3 प्रतिशत गिरावटों को कर को गिरा दिया
जायगा।

महिला को मुक्तिवादा को विक्री कर में छूट दी गई है।

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातों के उद्यमकारों
को विशेष सहायता प्रदान की गई है।

रीको-औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट (4000 मीटर टा) के
आवृत्ति पर 50 प्रतिशत को दी जायगी।

गोष्ठागत वित्त निगम द्वारा किए गए गिरा (5 लाख रुपये
तक) पर कर को 2 प्रतिशत में कम किया जायगा।

नवजात उद्योगों को क्षेत्र में गिरा में 1 प्रतिशत को अतिरिक्त
छूट देय होगा। इन क्षेत्रों पर गोष्ठागत मुक्तिवादा 25 प्रतिशत को
स्थान पर 5 प्रतिशत होगा।

गोष्ठागत वित्त निगम द्वारा कर को शायदगी फीस पर 50
प्रतिशत को छूट दी जाती है।

प्रधानमंत्री राजस्व योजना में 25 प्रतिशत आस्थागत को
प्रदान की है।

पूँजी उद्यमकारों विशेष सहायता को सहायता दिया
जायगा।

(v) महिला उद्यमियों को विशेष निम्नलिखित सहायता
को दी गई है।

2000 वर्षों में औद्योगिक मुक्ति पर 10 प्रतिशत को
प्रदान कर दी जायगी। सहायता को विशेष निम्नलिखित

(War widows) को 25 प्रतिशत छूट दी जायगी।

महिला उद्यमियों को योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाओं
(15 लाख रुपये की लागत तक) के लिए 1 प्रतिशत
वार्षिक व्याज की दर पर इक्विटी सहायता प्रदान की
जायगी।

शहरी निर्धन महिलाओं को घरों उद्योगों को प्रशिक्षण
दिया जायगा।

अति लघु उद्योगों को छोटी हुई गिरा में विक्री कर में छूट
दी जायगी।

उद्यमकारों विकास कार्यक्रमों को लाभ महिला उद्यमियों को
भी प्राप्त होगा।

6 विशेष उद्योगों को विकास हेतु निम्नलिखित उपाय किए
गए।

(i) लघु औद्योगिक उद्योगों को लघु श्रमिकों को
स्थान पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के
कार्यक्रम बनाये जायेंगे। इस उद्योगों की नवीन इकाइयों को
नियमित दर की देयताओं को सामान्य 75 प्रतिशत में 90
प्रतिशत तथा पुनर्निर्माण इकाइयों को विलम्ब हेतु 80 प्रतिशत
75 प्रतिशत को दी जायगी। बच्चे मान पर कर को 3
प्रतिशत में घटाकर 1 प्रतिशत किया जायगा।

(ii) लघु मिट्टी व कार उद्योगों वाली औद्योगिक इकाइयों
(5 से 25 करोड़ रुपये निवेशों वाली) को गिरा को
लाभ 7 वर्षों में बढ़ाकर 9 वर्षों किया जायगा। 25 से 100
करोड़ रुपये निवेशों वाली इकाइयों को गिरा को लाभ 9
वर्षों में बढ़ाकर 11 वर्षों को दिया जायगा। इन दोनों क्षेत्रों
को लघु कर देयता में छूट प्रदान की 75 प्रतिशत में बढ़ाकर
90 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत में बढ़ाकर 100 प्रतिशत को
दी जायगी।

(iii) उद्योगों को गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण उन को
प्रदान करने हेतु निम्नलिखित तथा कर को 2 प्रतिशत अतिरिक्त
गिरावट प्रदान की जायगी।

(iv) इनक्यूबेशन उद्योगों को कार उद्योगों को समान
सहायता प्रदान की जायगी। कर को 2 प्रतिशत देय होगा।
ब्राह्मणों को गिरा दी जायगी।

(v) लघु औद्योगिक उद्योगों को लघु पट्टा को विविध सहायता
को लघु निगमों द्वारा कर को प्रदान कर देंगे। इस नीति पर
2 वर्षों पश्चात् पुनः विचार किया जायगा। प्रारम्भिक इकाइयों
को लघु उद्यमियों को लघु गिरा को लघु निगमों द्वारा
दी जायगी।

(vi) लघु व लघु प्रमुख उद्योगों को कोटि करोड़ों तथा
मिलों तक के लघु निगमों को लघु सहायता प्रदान की जायगी। लघु
कर को लघु को लघु को लघु निगमों द्वारा दिया जायगा। इन

भूमि के लिये छोड़ दिये गये हैं। ऐसे औद्योगिक उपक्रम गज्जों के औद्योगिक दिग्गम में अनेक दावाएँ उठाने करते हैं अतः राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुये ऐसी इकाइयों के सम्बन्ध में अविलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिये।

निर्यात राजस्थान की औद्योगिक नीति एवं प्रयास उद्योगों को आकर्षित करने में सक्षम प्रतीत होते हैं। आवश्यकता इतनी इस बात की है कि औद्योगिक विकास को अवरोध करने वाले तत्वों यथा अनावश्यक देरी सालफ़ैताशाही व भ्रष्टाचार न मुक्ति पाई जाये।

नई औद्योगिक नीति, 1998

राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा 4 जून, 1998 में की गई। इस नीति के अन्तर्गत अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2003) में 20 हजार करोड़ रुपये का विनियोग किया जायेगा ताकि औद्योगिक उत्पादन की दर का 12 प्रतिशत किया जा सके।

उद्देश्य -

- 1 राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति वा त्वज करना इसका प्रमुख लक्ष्य है।
- 2 1994 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जो कमियाँ अनुभव की गईं उन्हें नई औद्योगिक नीति में दूर करने का प्रयास किया गया है।

विशेषताएँ -

- 1 आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- 2 निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- 3 बड़ा परियोजनाओं के लिये आधारभूत एवं विनियोजन मंडल का विकास किया जायेगा।
- 4 परियोजना विकास निगम की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि रूपान्तरण प्रक्रिया का सरल बनाना है।
- 5 निर्मित भूमि को उद्योगों के उपयोग में लेने के लिये आर्द्र भूमि की विम्वम में परिवर्तन किया जायेगा।
- 7 उर्जा की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये चालू विद्युत परियोजनाओं का समय पर पूर्ण किया जायेगा।
- 7 कैपिटल पावर प्लांट नीति की घोषणा की जायेगी।
- 8 निर्यातानुसूची इकाइयों का औद्योगिक विवाह अधिनियम की धारा 2 (एन) के अन्तर्गत 'पब्लिक यूटिलिटी स्टेटस' प्रदान किया जायेगा।

9 31 मार्च, 2003 तक लगाने वाले उद्योगों को 5 साल के लिये बिना कर मुक्ति दी जायेगी।

10 बिना कर सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

11 निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (365 एकड़) जयपुर (सीतागम) के समान एक पार्क की स्थापना भिवाड़ी में की जायेगी। इसके लिये केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

12 जयपुर जोधपुर कोटा और उदयपुर के समान भीलवाड़ा भिवाड़ी और श्रीगंगानगर में इन्वैस्ट कंटेनर डिपों का स्थापना की जा रही है।

13 गलतेचा एवं टस्करी की निर्यातक इकाइयों के लिए जयपुर में 'कम्प्यूटर एड्ड डिजाइन सेंटर' 'बुडनोर' सर्विस सेंटर स्थापित किये जायेंगे।

14 रायु उद्योगों का 70 प्रतिशत मूल सरकार खरीदगी।

15 150 उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण मंडल से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में छूट दी जायेगी।

16 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना राजमार्गों में 150 मीटर की दूरी पर रुकने का प्रावधान किया गया।

17 प्रशिक्षण एवं विशिष्ट पर चल देने के लिये नये संस्थानों की स्थापना की जा रही है।

18 पूँजी विनियोजन अनुदान योजना के अन्तर्गत पांच वर्षों की अवधि के लिये व्याज अनुदान योजना आरम्भ की गई। यह पर 2 प्रतिशत की दर में अनुदान दिया जायेगा।

19 नई इकाइयों को प्लाट एवं मशीनरी एवं कच्चे माल पर राहत दर में 5 वर्ष और प्रोत्साहन क्षेत्र में 7 वर्ष के लिये बुनियादी भूमि प्रदान की जायेगी।

20 रीवा द्वारा विकसित किया जा रहे धारा का मार्च 2003 तक नगर पालिका सीमा से बाहर रखा जायेगा।

21 डा. जी. गट खरीदने पर 25 प्रतिशत की दर में (अधिम्वम 2 5 लाख रुपये) अनुदान दिया जायेगा।

22 भूमि एवं भवन कर से उद्योगों की मुक्ति की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया।

23 कर्म मंडल पर स्टंप ड्यूटी 25 हजार रुपये में घटाकर एक हजार रुपये कर दी गई।

24 गल व पत्थर - गोरे एवं अधिनित परियोजनाओं का 100 प्रतिशत बिना कर व चुनौती मुक्ति टम वर्ष के लिये प्रदान का जायेगी।

25 बीमार औद्योगिक इकाइयों के लिये एक राजस्थानीय मण्डल की स्थापना की जायेगी।

अधिकतर उद्योग इसी जिले में विद्यमान है। इसी प्रकार राज्य के पञ्चकूट उद्योगों में विनियोजित पूँजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिले में विनियोजित है। क्षेत्रीय अमृतलन की ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) - राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकर की तुलना में रेलों का बहुत कम विकास हुआ है। बड़ी रेल लाईनों का विकास एक सीमित क्षेत्र में हो पाया है। राज्य के सभी भागों में पर्याप्त सड़कें भी नहीं हैं। अतः माल के आवागमन में न केवल अनेक कठिनाईयाँ आती हैं बल्कि परिवहन लागत भी ऊँची रहती है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों का विस्तार करने हेतु अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय मस्याओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य हो रहा है। अतः औद्योगिक विकास की गति प्रदान करने के लिए सड़क व परिवहन का विशेष रूप से विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) वर्षों के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। अतः राज्य में कृषि जन्य वच्चे माल का सदैव अभाव बना रहता है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति तेल आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त जल के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजी से विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इसमें औद्योगिक विकास की गति मन्द बढ़ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts) - राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति बना रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक है। राज्य में अकाल की स्थिति बने रहने का प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बड़े भाग में रेगिस्तान का होना

है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एवं बढ़ते हुए रेगिस्तान पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे की समस्या के समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओं का शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं के कारण कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी तेजी से विकास होता है।

10 प्रणाली संबंधी समस्याएँ (Problems relating to the System) - एक उद्योग को पंजीकरण अनुज्ञा पत्र भूमि जल बिजली वित्त कच्चा माल एवं विपणन इत्यादि सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागों का सम्पर्क करना पड़ता है। ये प्रणालियाँ अत्यन्त जटिल हैं जिनमें अनिवार्यक विलम्ब होता है। अतः विभिन्न रियासतों संबंधी व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) - राजस्थान में पर्याप्त शक्ति के साधन न होने के कारण ही औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। राज्य में कोयले व खनिज तेल का नितांत अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य में शक्ति के गैर पर्याप्त साधनों के विकास की पर्याप्त सभावनाएँ विद्यमान हैं लेकिन पूँजी के अभाव के कारण इन साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अतः पर्याप्त पूँजी विनियोजन के द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Capita Income) राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी कम है इसके अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि राज्य की प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है। अतः राजस्थान में पूँजीनिर्माण की गति भी धीमी बनी रहती है। जिसमें सदैव पूँजी का अभाव बना रहता है। पूँजी के अभाव के कारण राज्य का नेजी में औद्योगीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या का समाधान हेतु राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और लोगों में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की आदत विकसित की जानी चाहिए इसमें पूँजी निर्माण की गति में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाएगा।

13 उद्योगपतियों की उदासीनता (Indifferent Attitude of Industrialists) - राज्य का औद्योगीकरण के प्रति उद्योगपति प्रायः उदासीन बन रहे हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि राजः कम नतीज उद्योगों की स्थापना हेतु अनुसूचित जातों व वर्गों को लाभ देने के कारण व अपनी पूँजी को देश के अन्य भागों में विनियोजित करना अधिक लाभदायक मन्त्र है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों का आकर्षित करने के लिए

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत रियायतों व सुविधाओं की घोषणा करना चाहिए।

14. अन्य समस्याएँ (Other Problems) - उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। ग्राम समन्वयी समस्याओं के अन्तर्गत कुराल रमकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव हैं। इसमें उत्पादन कार्य में अवरोध बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णतः औद्योगिक सर्वोक्षण नहीं हो पाया। उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नहीं हो पाती है। अतः राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नहीं हो पाती है। अतः राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं का उत्पादन होता है। राज्य के अनेक उद्योग लक्ष्मणा की समस्या से ग्रस्त हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करके राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से आर्थिक विकास हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1 वित्तीय साधनों में वृद्धि राज्य की प्रथम मात योजनाओं का आकार बहुत छोटा था अतः राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत धीमी रही। राज्य की 18 वी व 9 वां योजना का आकार पहले की योजनाओं की तुलना में अधिक है लेकिन राज्य की समस्याओं और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जानी चाहिये।

2 आर्थिक सर्वेक्षण - राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षणों की गति धीमी है अतः राज्य की आर्थिक क्षमताओं का ज्ञान नहीं है अतः राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में की जानी चाहिये ताकि कृषि उद्योग परिवहन और खनिज विकास की भावी सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जा सके।

3 सिंचाई के साधनों का विकास - राजस्थान में शीघ्र अकाल एवं सूखे की स्थिति बन रही है। इस समस्या का

समाधान केवल सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त हैं अतः अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिये सिंचाई के साधनों में तेजी से विकास करना आवश्यक है।

4 राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग - राज्य का एक बड़ा क्षेत्र शुष्क प्रदेश का उपयोग करने में अभी तक अग्रणी स्थिति में नहीं है। राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग करने में नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भू-राशण को रोकने के लिये पेड़ों को लगाये जाने चाहिये और वर्षा को अवश्यता वाली फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिये।

5 अरावली क्षेत्र का विकास - राज्य का अरावली क्षेत्र रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षेत्र का पर्यावरण एवं परिस्थिति की अत्यधिक कमजोर हो गई है। अतः अरावली क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

6 पेयजल की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के पश्चात् भी राज्य में पेयजल का संकट विद्यमान है। यह विचार विमर्श है कि कुछ स्थानों पर पेयजल उपलब्ध ही नहीं है और अनेक स्थानों पर पेयजल का स्वाद क्षारीय और पीने योग्य नहीं है अतः राज्य में पेयजल की व्यवस्था के लिये कृत्रिम प्रयासों की आवश्यकता है।

7 लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगों का अभाव है अतः राज्य में खनिज आधारित उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निर्माण बैकिंग विकसित राजस्व वृद्धि आदि की विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः आर्थिक मसालों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। ताकि राज्य की विकास की दर बढ़ सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

1. औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by Industrial Policy?
2. औद्योगिक नीति का महत्व बताइए।
Explain the importance of Industrial Policy.
3. राजस्थान की 1990 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन कीजिए।
Evaluate the Industrial Policy 1990 of Rajasthan.

अधिकांश उद्योग इसी जिले में विद्यमान हैं। इसी प्रकार राज्य के पञ्चोत्तर उद्योगों में विनियोजित पूँजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिले में विनियोजित है। क्षेत्रीय असंतुलन की ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकार की तुलना में नदों का बहुत कम विकास हुआ है। यद्यपि रेल लाईनों का विकास एक योजना के अन्तर्गत हो रहा है। राज्य के सभी भागों में पर्याप्त सड़कें भी नहीं हैं। अतः माल व आवागमन में न केवल अनेक कठिनाईयाँ आती हैं बल्कि परिवहन लागत भी ऊँची रहती है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों का विस्तार करने हेतु अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य हो रहा है। अतः औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सड़क व परिवहन का विशेष रूप से विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) वर्षा के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। अतः राज्य में कृषि जन्म देने वाला एक सदैव अभाव बना रहता है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति तेल आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त जल के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजी से विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इसमें औद्योगिक विकास की गति स्वतः बढ़ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts) राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति पेश रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधा है। राज्य में अकाल की स्थिति में रहने का प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बड़ा भाग में गैरजलवायवीय है।

इसलिए गांधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एवं बढ़ते हुए रेगिस्तान पर नियंत्रण प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे की समस्या के समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओं का शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं व कारण कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी तेजी से विकास होता है।

10 प्रणाली संबंधी समस्याएँ (Problems relating to the System) एक उद्योग को पंजीकरण अनुज्ञा पर भूमि जल बिजली वित्त कच्चा माल एवं निष्पन्न इत्यादि सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागों या सस्थाओं से सम्पर्क करना पड़ता है। ये प्रणालियाँ अत्यन्त जटिल हैं जिससे अनिवार्यक विलम्ब होता है। अतः विभिन्न विभागों के मध्य जोड़कर व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) राजस्थान में पर्याप्त शक्ति के माध्यम से हान के कारण ही औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। राज्य में कायले व खनिज तेल का विनाश अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य में शक्ति के चार परम्परागत साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं लेकिन पूँजी के अभाव के कारण इन साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अतः पर्याप्त पूँजी विनियोजन के द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Capita Income) राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी कम है इसलिए अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों से तुलना करने पर पता चलता है कि राज्य की प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है अतः राजस्थान में पूँजीनिर्माण की गति भी धीमी बनी रहती है। जिसमें मुख्य पूँजी का अभाव बना रहता है। पूँजी के अभाव के कारण राज्य में तेजी से औद्योगीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या का समाधान हेतु राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए और लोगों में निवेश, ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिकी आदि विकसित की जानी चाहिए इसमें पूँजी निर्माण की गति में वृद्धि होने प्रारम्भ हो जाएगी।

13 उद्योगपतियों की उदासीनता (Indifferent Attitude of Industrialists) राज्य के औद्योगीकरण व प्रति उद्योगपति प्रायः उद्योगीय मन है। इसका प्रमुख कारण यह है कि राजस्व कम नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान व सब्सिडी के माध्यम से अपने पूँजी का देश में अन्य भागों में विनियोजन करना अधिक लाभदायक समझते हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों से आकर्षित करने के लिए

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत रियायतों व सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए।

14. अन्य समस्याएँ (Other Problems) - उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। प्रथम सम्बन्धी समस्याओं के अन्तर्गत कुशल रमकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव है। इसमें उत्पादन कार्य में अवरोध बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णतः औद्योगिक सर्वोत्थान नहीं हो पाया है। उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नहीं हो पाती है अतः 5 राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं की पर्याप्त रूप में जाच नहीं हो पाती है अतः राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं का उत्पादन होता है। राज्य के अनेक उद्योग लक्ष्मता की समस्या से ग्रस्त हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करके राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आर्थिक विकास हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1 वित्तीय साधनों में वृद्धि राज्य की प्रथम सात योजनाओं का आकार बहुत छोटा था अतः राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत धीमी रही। राज्य की 18 वी व 9 वी योजना का आकार पहले की योजनाओं की तुलना में अधिक है लेकिन राज्य की समस्याओं और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जानी चाहिये।

2 आर्थिक सर्वेक्षण - राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षणों की गति धीमी है अतः राज्य की आर्थिक क्षमताओं का ज्ञान नहीं है अतः राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में की जानी चाहिये ताकि कृषि उद्योग, परिवहन और खनिज विकास की सभी सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जा सके।

3 सिंचाई के साधनों का विकास - राजस्थान में प्रायः अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या का

समाधान केवल सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त हैं अतः अर्थव्यवस्था के तीव्रगामी आर्थिक विकास के लिये सिंचाई के साधनों में तेजी से प्रयास करना आवश्यक है।

4 राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग - राज्य का एक बड़ा हिस्सा शुष्क प्रदेश का उपयोग करने के नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भू-राशण को रोकने के लिये पौधे लगाये जाने चाहिये और वर्षा की आवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिये।

5 अरावली क्षेत्र का विकास - राज्य का अरावली क्षेत्र रेगिस्तान की पूर्णतः ओर बढ़ने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षेत्र का पर्यावरण एवं परिस्थिति की अत्यधिक कमजोर हो गई है। अतः अरावली क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

6 पेयजल की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के पश्चात् भी राज्य में पेयजल का संकट विद्यमान है। यह विविध विद्यमान है कि कुछ स्थानों पर पेयजल उपलब्ध हो नहीं है और अनेक स्थानों पर पेयजल का स्वाद क्षारीय और पाने योग्य नहीं है अतः राज्य में पेयजल की व्यवस्था के लिये क्रान्तिकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

7 लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगों का अभाव है अतः राज्य में खनिज आधारित उद्योग एवं इलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निर्माण बैकिंग विकास रोजगार वृद्धि आदि की विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। ताकि राज्य की विकास की दर बढ़ सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 औद्योगिक नीति से क्या क्या समझते हैं?
What do you mean by Industrial Policy?
- 2 औद्योगिक नीति का महत्व बताइए।
Explain the importance of Industrial Policy
- 3 राज्य की 1990 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन करें।
Evaluate the Industrial Policy 1990 of Rajasthan

- 4 राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति 1998 का उद्देश्य बताईए।
Mention the objectives of New Industrial Policy 1998 of Rajasthan
- 5 राजस्थान में औद्योगिक उदारीकरण की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए।
Mention the trend of industrial liberalisation in Rajasthan

(B) निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति 1994 का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the New Industrial Policy 1994 of Rajasthan
- 2 राजस्थान की 1998 की औद्योगिक नीति पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Industrial Policy 1998 of Rajasthan
- 3 औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं? 1994 का औद्योगिक नीति के प्रमुख विशेषताएँ बताईए।
What do you mean by Industrial Policy? Explain the main characteristics of Industrial Policy 1994
- 4 राजस्थान के औद्योगिक विकास में औद्योगिक नीति का भूमिका सिद्ध कीजिए।
Prove the Role of Industrial Policy in the industrial development of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Examination s Questions)

- 1 राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरवसिंह शेखावत की नवीन औद्योगिक नीति 1994 का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the New Industrial Policy 1994 of Chief Minister Shri Bharon Singh Shekhawat of Rajasthan
- 2 राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवं रियायतों का वर्णन कीजिए।
Describe the various incentives and facilities provided by the Government of Rajasthan for Industrial Development
- 3 औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक नीति का महत्व बताईए।
What do you mean by Industrial Policy? Describe the importance of Industrial Policy?



राजस्थान में औद्योगिक वित्त एवं विकास में संस्थागत योगदान

ROLE OF VARIOUS INSTITUTIONS IN INDUSTRIAL FINANCE AND DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

"वित्त उद्योगों का जीवन रक्त है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान राज्य वित्त निगम
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम
- राजस्थान लघु उद्योग निगम
- राजस्थान में औद्योगिक विकास का प्रास्तावित करने वाल अन्य विभाग/निगम
- भारत का औद्योगिक वित्त स मन्त्रालय राज्य सस्थाएं
- राजस्थान में आर्थिक वित्त व स मन्त्रालय व मुद्रा व
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है फिर भी प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। अतः एक विकासशील राज्य का आवश्यकताओं के अनुसार राजस्थान का भी आवश्यक औद्योगिक संस्थानों का तेजी से निर्माण करना होगा ताकि राजस्थानवासियों का जीवनस्तर ऊँचा उठ सके। राजस्थान की अवसरों में वृद्धि हो सके और सरकारी आय में वृद्धि हो सके। इस अतिरिक्त राज्य का आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विकास करना भी आवश्यक होगा। राज्य के सकल उत्पादन की दृष्टि में औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम सहयोग दे रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान का औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुआ। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनेक उद्योगों की स्थापना की गई। राज्य के तत्पश्चात् औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति का घोषणा की। नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है ताकि अधिक से अधिक उद्योगों राज्य में नये उद्योग स्थापित कर सकें। इस नीति के अन्तर्गत अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वित्त व प्रासाधनों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स वायोटैक्नालॉजी एण्ड प्रोसेसिंग तथा राज्य में उपलब्ध ससाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। विद्युत व जल का कम खपत वाले तथा राजस्थान की बहाक देने वाले उद्योगों की स्थापना

को प्राप्ताह्न दिया जायेगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है अतः इसे भी अन्य उद्योगों के समान सुविधाय एव रियायत प्रदान की जायेगी। राज्य में अनेक प्रभाग की वित्तीय संस्थाएँ कार्यरत हैं। औद्योगिक वित्त प्रदान करने में निम्नलिखित संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है

- (1) राजस्थान राज्य वित्त निगम (RFC)
- (2) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (RIICO)
- (3) राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO)
- (4) राज्य का उद्योग विभाग
- (5) अन्य (i) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (iii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (iv) केन्द्र व राज्य सरकारों एवं (v) व्यापारिक बैंक।

इनका विवेचन निम्नवत् है

राजस्थान राज्य वित्त निगम

RAJASTHAN STATE FINANCE CORPORATION

निगम की स्थापना Establishment

राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार 17 जनवरी 1955 को की गई। इस निगम ने 8 अप्रैल 1955 से कार्य प्रारम्भ किया। राजस्थान राज्य वित्त निगम का केन्द्रीय कार्यालय जयपुर में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, बीकानेर, जाधपुर, उदयपुर व कोटा में स्थित हैं। निगम के 37 शाखा कार्यालय भी हैं।

उद्देश्य

Objects

राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि राज्य का नागरिक विकास में औद्योगिक विकास हो सके। निगम न केवल कार्यरत उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है बल्कि नए उद्योगों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

पूँजी संरचना

Capital Structure

संसाधनों की गतिशीलता हेतु निगम ने अपने व्यापार विभाजन एवं समायोजन पूर्वानुमान के अनुसार प्रयत्न किए हैं।

निगम की अधिकृत पूँजी 100 करोड़ रुपये है जो 100 रुपये मूल्य के एक करोड़ अंशों में विभक्त है।

निगम का प्रबन्ध Management

निगम का प्रबन्ध संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। संचालक मण्डल में 13 सदस्य होते हैं। संचालक की सहायता के लिए 6-सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। यह समिति प्रबन्ध संचालक की अध्यक्षता में कार्य करती है। संचालक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं

एक अध्यक्ष	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक प्रबंध संचालक	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक जनरल मैनेजर	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक संचालक	रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत
दो संचालक	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मनोनीत
एक संचालक	अनुसूचित बैंकों द्वारा मनोनीत
एक संचालक	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मनोनीत
एक संचालक	सहकारी बैंकों द्वारा मनोनीत
एक संचालक	जनप्रतिनिधि

निगम के कार्य Functions

राजस्थान राज्य वित्त निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- (i) राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।
- (ii) विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा यदि अन्य संस्थाओं से ऋण लिये जाते हैं तो निगम से ऋणों की गारन्टी देने का कार्य करता है।
- (iii) निगम औद्योगिक इकाइयों के अंश व ऋणपत्रों में प्रत्यक्ष अभिदान भी करता है।
- (iv) यह केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता है।
- (v) निगम द्वारा अंश व ऋणपत्रों के अभिगोपन का कार्य भी किया जाता है।

राजस्थान वित्त निगम वर्तमान में इन योजनाओं के तहत सहायता प्रदान कर रहा है।

- (1) सिंगल विन्डा स्कीम - चल व अचल दाना प्रकार की सम्पत्तियों पर निगम ऋण उपलब्ध कराता है।
- (2) इन्क्यूपमेट रिफाईनेंस - वर्तमान में चार वर्ष से लाभ

में चल रही इकाइयों को यत्र व यत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(3) लघु उद्योग इकाइयों में निर्मित उत्पादों को विक्रय करने हेतु दुकानों एवं शोरूम पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(4) रिसेटेड होटल पवर्टन एवं मरिज हाल पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(5) छोटे अस्पताल एवं फार्मिंग होम पर ऋण दिया जाता है।

(6) खनन एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों पर ऋण दिया जाता है।

(7) महिला उद्यम निधि योजना में महिलाओं को ऋण दिया जाता है।

(8) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(9) व्यावसायिक गतिशीलता वाले व्यक्तियों को कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों पर ऋण दिया जाता है।

(10) फ्लोरो-क्लोर फिश कल्चर, पॉल्ट्री-फॉर्म आदि पर ऋण दिया जाता है।

(राशि करोड़ में)		
उपलब्ध वर्ष	ऋण स्वीकृति का ऋण वितरण	
1955-56 (प्रथम वर्ष)	0.97	0.02
1946-65 (दसवां वर्ष)	0.73	0.63
1974-75 (चौथा वर्ष)	7.06	2.83
1979-80 (पच्चीसवां वर्ष)	31.54	17.94
1984-85 (तीसवां वर्ष)	54.19	39.39
1989-90 (चौदहवां वर्ष)	110.25	64.96
1994-95 (चात्तासवां वर्ष)	177.55	120.72
1995-96 (इक्कीसवां वर्ष)	163.44	131.66
1996-97 (बत्तीसवां वर्ष)	167.45	122.09
1997-98 (अठारहवां वर्ष 1998 तक)	98.75	95.68
स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98		

निगम द्वारा उद्यमियों को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 1997-98 में क्रियान्वित किये गये प्रशासनिक निर्णयों का विवरण

1. वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृति को शक्तियों का और अधिक विकेंद्रीकरण किया गया है जिसका अन्तर्गत अब शाखा प्रबंधक द्वारा 5 लाख रुपये के ऋण एवं उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय) द्वारा 20 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसके साथ ही ये अधिकारी निगम की गुड चोरोस योजना के तहत इनकी ही राशि का ऋण अतिरिक्त में स्वीकृत कर सकेंगे। परियोजना को शीघ्र उत्पादन में लाने की दृष्टि से निगम ने स्वीकृत ऋण के 20 प्रतिशत तक उर्वरि कोस्ट ओवर रन के लिए अतिरिक्त ऋण देने के लिए भी शाखा प्रबंधकों को अधिकृत किया है।

2. निगम द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया का और अधिक सरलीकरण किया गया है। ऋण वितरण को सरलीकृत करने के लिए खनदी लखाकार के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत तक का वितरण निगम द्वारा किया जा सकेगा। परिवहन ऋण योजना के तहत बीडी बनाने के लिए ऋण वितरण चैसिस लाने के पश्चात् एडवांस में किया जा सकेगा।

3. वित्त निगम द्वारा सर्वेक्षण के दौरान चिह्नित उन ऋण इकाइयों जिनमें 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति ने जगार में हैं के पुनर्वास हेतु प्र प्रैक इकाई को फिजिविलिटी रिपोर्ट तैयार कर जाएगा। इकाई के उद्यमों से विचार विमर्श के पश्चात् पुनर्वास पैकेज बनाया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार की छूटें एवं भविष्य में दी जाने वाली वित्तीय सहायता आदि का समावेश होगा।

राजस्थान राज्य वित्त निगम की प्रगति Progress of R F C

राजस्थान राज्य वित्त निगम के कारण राज्य में औद्योगिक वित्त का सृजन हुआ है। राज्य में लघु एवं कुटीरा उद्योगों के साथ-साथ बड़े उद्योग भी विकसित हो चुके हैं। निगम ने अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय केन्द्र एवं राज्य की औद्योगिक नीतियों को ध्यान में रखा है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई है, जिनके अन्तर्गत उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। सरकार द्वारा इसमें अनेक सरोधन भी किये गए हैं। निगम इस नीति के अनुरूप एक नवीन दिशा अपना चुका है। निगम की प्रगति का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

कार्य व्यापार एवं प्रगति

निगम द्वारा अपनी स्थापना से माह जनवरी, 98 तक लगभग 65825 औद्योगिक इकाइयों का 2017.89 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं एवं 50251 औद्योगिक इकाइयों को 1361.98 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं। निगम ने अपने कार्य व्यापार में जो महत्वपूर्ण उपन्यासा अर्जित की हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है -

4 निगम द्वारा महिला उद्यमियों समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए दो योजनाएँ हाथ में ली जाएगी महिला उद्यमियों को शोध ऋण उपलब्ध करने के लिए निगम में अलग से महिला उद्यम निजी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसके द्वारा महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी है। निगम द्वारा महिला उद्यमियों को परियोजना लागत की जिसको अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है 15 प्रतिशत बीज पूँजी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

5 इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम के समुक्त तत्वाधान में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु 50 000 रु तक की ऋण सहायता दी जाएगी। इसमें 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 10 000 रु की राशि ॥ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी एवं अधिकतम 6 000 रु तक का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

6 निगम ने राज्य के दस्तकारों अतिमधु उद्यमियों तथा हैण्डलूम उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पर हैण्डलूम एवं हैण्डिक्राफ्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जिसके अन्तर्गत परियोजना के चयन परियोजना का प्रतिवेदन बनाने एवं ऋण सुविधा हेतु आवेदन पत्र संयोजी जानकारी प्रदान की जाएगी।

7 निगम द्वारा पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन उद्योग (उद्योग मोटल हैरीटेज होटल पैईंग गेस्ट आदि) लगाने वाले उद्यमियों को प्रचलित ब्याज दर में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार निगम द्वारा संचालित गुड बोरोअर्स योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले उद्यमियों से प्रचलित ब्याज दर से दो प्रतिशत कम ब्याज दर ली जाएगी।

8 निगम द्वारा नियमित भुगतान करने वाले उद्यमियों को वर्तमान में दी जा रही आधा प्रतिशत ब्याज में छूट को बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। यह छूट आरम्भ में एक वर्ष के लिए दी जाएगी।

9 शाखा स्तर पर ऋण प्रसक्तताओं को उनके खाना के विवरण देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा धीरे धीरे सभा शाखा कार्यालय पर कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा ऋण प्रामकर्ताओं अथवा अधिकृत व्यक्ति को रातो को विवरण की प्रति प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

वर्ष 1997-98 की उपलब्धियाँ

निगम द्वारा वर्ष 1997-98 में माह जनवरी 98 तक 98.75 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये एवं 95.68 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। वर्ष के दौरान राजिज

आधारित उद्योगों वस्त्र उद्योग एवं सूक्ष्म तकनीकी आधारित उद्योगों को विशेष बढ़ावा दिया गया। पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न भागों में होटल/हैरीटेज पैईंग गेस्ट आवास हेतु ऋण सहायता प्रदान की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग लगाने के लिए सामान्य से 2 प्रतिशत कम ब्याज पर 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

लघु उद्योगों का विस्तार

वर्ष 1996-97 की अन्तिम में छोटे पैमाने के उद्योगों को जो कि कुल ऋण स्वीकृतियों के मुख्य अंश थे सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई। कुल ऋण स्वीकृतियों का 96.36 प्रतिशत इस क्षेत्र के उद्यमियों को स्वीकृत किया गया। वर्ष 1997-98 में भी लघु उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है जो कि निम्न सारणी से परिलक्षित होती है।

(राशि करोड़ों में)					
		1996-97	1997-98		
(जनवरी, 98 तक)					
क्र.सं.	प्रकृति	राशि	सद्व्य.	राशि	
1	लघु परिवहन	138.3	149.38	79.1	91.11
2	अन्य	23	18.07	11	7.64
स्त्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98					

सहायता की परियोजनाएँ

निगम द्वारा दस्तकारों समाज के कमजोर वर्गों जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग भी शामिल हैं तथा बहुत कम पूँजी वाले उद्यमियों और इकाईयों को ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से विरोध योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। विभिन्न सहायता परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 में माह जनवरी 98 तक अर्जित की गई उपराशियों का विवरण निम्न प्रकार है।

(राशि करोड़ों में)			
क्र.सं.	योजना का नाम	मददा	राशि
1	कम्प्यूटरिज्ड ऋण योजना	53	11.99
2	अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए योजना	40	115.45
3	भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिकस योजना	13	44.42
4	महिला उद्यम निधि योजना	6	22.50
5	मिगल विण्डो स्कीम	37	223.76
6	होटल उद्योग	23	418.94
7	हॉटल उद्योग	4	42.50
8	परिवहन ऋण	27	99.98
9	मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों के तहत लघु उद्यमियों के ऋण	34	805.11
स्त्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 1997-98			

राज्य सरकार के अधिकर्ता की भूमिका

राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को व्यापक मुक्त ऋण एवं पूँजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत करने की दिशा में वित्त निगम राज्य सरकार के अधिकर्ता की भूमिका निर्वाहित करता है। राज्य सरकार द्वारा घोषित पूँजी विनियोजन अनुदान योजना के अंतर्गत निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों की वर्ष 1996-97 में 804 इकाइयों को 27.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये एवं 1130 इकाइयों को 23.91 करोड़ रुपये वितरित किये गये।

ऋण वसूली एवं अनुसरण प्रयास

वित्त निगम ने वित्तीय वर्ष 1996-97 में 194.78 करोड़ रुपये की वसूली कर एक नया कोर्तमान स्थापित किया है। यह उपलब्धिगत वर्ष की तुलना में 10.31 प्रतिशत अधिक रही।

वर्ष 1997-98 में वसूली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एच उद्यमियाँ से अधिक से अधिक वसूली के लिए निगम द्वारा विशेष नीतिगत नियम लेकर उद्यमियाँ द्वारा अपनी बकाया राशि एक मुक्त कराने पर विशेष प्रयास देने का नियम तैयार किया। अधिग्रहित इकाइयों के मामले में शोधप्रतिशीर्ष प्रबन्धन एवं अधिक से अधिक पुनर्जीवन हेतु नीतिगत नियम लेकर क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय स्तर पर और अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप निगम द्वारा आलोच्य वर्ष में माह जनवरी 98 तक 139.16 करोड़ रुपये की वसूली की गई है जो कि आलोच्य वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 61.85 प्रतिशत है एवं गत वर्ष का इसी अवधि में 7.65 प्रतिशत अधिक है।

ऋण इकाइयों का पुनर्जीवन

निगम द्वारा 1996-97 में ऋण इकाइयों को

पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। इन प्रयासों के अंतर्गत 44 इकाइयों के मामलों में किराने का पुनर्निर्धारण किया गया 173 इकाइयों को 6.51 करोड़ रुपये की दण्डनीय ब्याज में छूट दी गई 160 अधिग्रहित इकाइयों को बेचकर इकाई के प्रबन्ध में परिवर्तन कर पुनर्जीवित किया गया। इसके अलावा 10 ऋण इकाइयों की भारतीय बैंक के तहत कर पुनर्जीवित किया गया। इनको 0.57 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

वर्ष 1997-98 में माह जावित 1998 तक 155 अधिग्रहित इकाइयों का निगम ने निगम का 10.01 करोड़ रुपया बकाया था मूल ऋणों को लौटाकर, परिसम्पत्तियों का विक्रय कर प्रबन्ध में परिवर्तन कर पुनर्जीवित किया गया। इसी प्रकार पुनर्वास योजना के अंतर्गत जनवरी, 98 तक 9 इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया।

वित्तीय संसाधन एवं लेखा-जोखा

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अनुसार वर्तमान में वित्त निगम की अधिकृत पूँजी (अश पूँजी) 100 करोड़ रुपये है एवं प्रदत्त पूँजी 65.52 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जो पूँजीगत ऋण और अग्रिम दिये गये थे वे विभिन्न चरणों में पूँजी के रूप में परिवर्तित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अश पूँजी, ऋण एवं वित्तीय सहायता आदि के लिए वार्षिक योजना 1997-98 में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1997-98 में निगम द्वारा माह जनवरी 98 तक 10.50 करोड़ रुपये के बाण्ड्स निर्गमित किये गये हैं। वर्ष के दौरान 90.00 करोड़ रुपये का पुनर्धित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में प्राप्त किया जाएगा।

गत पांच वर्षों में निगम को उपलब्धियों का लेखा-

जोखा सलग तालिका में दर्शाया गया है।

गत पांच वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93
1	ऋण स्वीकृति	185.45 (1406)	163.44 (1770)	177.5 (1794)	165.77 (2169)	168.00 (2830)
2	ऋण वितरण	122.09 (1266)	131.66 (1411)	120.72 (1534)	106.32 (1804)	107.45 (2306)
3	वसूली	194.78	178.53	156.17	131.47	110.25
4	अश पूँजी					
	(क) (1) अधिकृत	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(2) प्रदत्त	67.52	67.52	67.52	63.02	60.17
	(ख) वर्षान्त में रिजर्व	40.76	34.26	27.26	25.41	24.62
	(ग) बाण्ड गैर	244.82	232.37	227.17	208.17	191.17
5	(घ) धातु नि बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	3.73	3.74	4.49	3.00	4.00
	(ङ) भा.स.ड.वि. बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	54.09	72.74	60.67	53.00	53.73

5	सरत लाभ	43 61	45 04	34 08	27 06	20 98
6	कार्य परिचालन व्यय	29 37	26 43	22 95	17 67	13 37
7	लाभ	13 54	15 70	1 90	0 81	0 79
■	शुद्ध लाभ	9 88	11 58	1 90	0 81	0 79

स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

व्यापार प्रोन्नति

निगम द्वारा राज्य में उद्योग राखने हेतु विभिन्न कदम उठाये गये हैं। निगम द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर व्यापार प्रोत्साहन शिवांगो का आस्तेजन किया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य के ग्रामीण एवं सभावित उन्नत क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अच्छा प्रदेश है। पर्यटकों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकें, इसके लिए वित्त निगम द्वारा होटल, मोटल, टैरेटेड होटल आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। निगम द्वारा मचेंन्ट बैंकिंग गतिविधियों के अंतर्गत निगम स वित्त पोषित इकाइयों के गुड वॉगर्स को कार्यशील पूँजी एवं अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु अल्पवर्षीय ऋण त्वरित गति से स्वीकृत किये जाते हैं। निगम ने अभी हाल ही में गोलड फाई योजना आरम्भ की है जिसके अंतर्गत निगम द्वारा ऋणों का नियमित भुगतान करने वाले उद्यमियों को 38 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता कार्यशील पूँजी अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु प्रदान की जाती है। निगम की सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

वर्ष 1998-99 के कार्यक्रम

वर्ष 1998-99 में वित्त निगम द्वारा 210 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने एवं 165 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऋण एवं ऋण इकाइयों के पुनर्जीवित हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

निगम द्वारा सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित उन ऋण इकाइयों जिनमें 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति राजगार में हैं के पुनर्वास हेतु प्रत्येक इकाई का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इकाई के उद्यमों से विचार निमार्श के पश्चात् पुनर्वास पैकज बनाया जाएगा। जिसमें विभिन्न प्रकार की छूट एवं भविष्य में दी जाने वाली वित्तीय सहायता आदि का समावेश होगा।

शाखा स्तर पर ऋण प्राप्तकर्ताओं को उनके खाता का

विवरण देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। धीरे धीरे सभी शाखा कार्यालयों पर कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं अथवा अधिकृत व्यक्ति को खातों के विवरण की प्रति प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

हैण्डलूम क्षेत्र में बुनकरों की रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से करीब 10 000 बुनकरों को हैण्डलूम कारपोरेशन के सहयोग से कार्यशील पूँजी के लिए ऋण प्रदान करने के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (रीको)

RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL & INVESTMENT CORPORATION

निगम की स्थापना Establishment

28 मार्च, 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग एवं राजनि विकास निगम की स्थापना की गई थी। 1979 में इस निगम के राजनि साधनों से सम्बन्धित कार्यों को एक नवगठित संस्था 'राजस्थान राज्य राजनि व्यापार निगम' को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा जनवरी 1980 से राजस्थान राज्य उद्योग एवं राजनि विकास निगम का नाम 'राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम' (रीको) कर दिया गया। अतः औद्योगिक ऋण उपलब्ध कराने में रीको की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई।

रीको राज्य सरकार व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ओर से एक विकास बैंक के रूप में कार्यरत है। इस रूप में यह संस्था अनेक योजनाओं को संचालित करती है और उन योजनाओं के अंतर्गत राज्य के उद्यमियों को पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। रीको द्वारा इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं।

(I) रीको उन योजनाओं में सहयोग करती है जिनकी निर्माण लागत 10 करोड़ रुपये तक होती है। इन योजनाओं में रीको असो के माध्यम से भूत का विनियोजन करती है।

(II) यह 150 लाख रुपये तक के अग्रिम ऋण स्वीकृत करती है। रीको राजस्थान में कहीं भी औद्योगिक परियोजनाओं को विस्तारित करने हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों के साथ मिलकर भी कार्य करती है।

(iii) रोकें उपकरण पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत प्रति औद्योगिक इकाई को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण स्वीकृत करता है। ऐसे ऋण की स्वीकृति में 7 दिन का समय लग जाता है।

(iv) रोकें द्वारा ब्याज मुक्त विक्री कर ऋण तथा अन्य पूँजी विनियोग अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

(v) रोकें द्वारा राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की अशुद्धियों में सहयोग प्रदान किया जाता है। रोकें प्रायः मरुभूमि क्षेत्र तथा निम्नोच्च क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहयोग प्रदान करते समय रोकें इस बात का पर्याप्त ध्यान रखती है कि कोई औद्योगिक इकाई वित्तीय समाधान के अभाव के कारण तो अपना उत्पादन बंद न कर पा रही हो।

(vi) रोकें द्वारा बीज पूँजी को भी व्यवस्था की जाती है। बीज पूँजी का व्यवस्थापन उन उद्योगिक एवं तकनीकी क्षमता वाले उद्योगियों के लिए की जाता है जो वित्तीय सहायता के अभाव में उद्योग की स्थापना करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

निगम के उद्देश्य

Objects

राज्य के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(i) **तांत्रिक आधुनिक विकास** निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना है। इस उद्देश्य को पूर्ति हेतु निगम उन संस्थाओं की स्थापना में सहायक करती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकें। निगम प्रायः औद्योगिक उपकरण व मशीनों का निर्माण करने वाला संस्थाओं का सहयोग प्रदान करता है।

(ii) **प्रवर्तन में योगदान** निगम का दूसरा प्रमुख उद्देश्य कम्पानियाँ जहाँ तक नवान्वास्थापित संस्थाओं के प्रवर्तन में योगदान देना है। इसमें राज्य के औद्योगिक वातावरण को सुजान का बड़ा योगदान है।

(iii) **वित्तीय सहायता** निगम द्वारा वित्त व सांख्यिक क्षेत्र को संस्थाओं का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह महत्त्व अशुद्धियों के अधिग्रहण व बीज पूँजी तथा राजस्वमुक्त ऋण के रूप में दी जाती है।

(iv) **नवान्वास्थापना का निर्माण व संचालन** निगम राज्य के तांत्रिक आधुनिक विकास के लिए नवान्वास्थापना का नया करण है और उनका संचालन करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त हेतु निगम विभिन्न योजनाओं में सहयोग प्रदान करता है और इन योजनाओं का विचार

तैयार करता है।

(v) **समुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करना** निगम का प्रमुख उद्देश्य समुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करना भी है। इस औद्योगिक क्षेत्र को नवीन प्रवृत्ति कहा जा सकता है। निगम समुक्त क्षेत्र के विकास एवं विस्तार में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

रोकें का प्रबन्ध एवं संगठन

Management & Organisation

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड जयपुर (रोकें) भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मर्यादित एवं सार्वजनिक संस्था है। राजस्थान सरकार इसकी मुख्य अशुद्धी है। रोकें के कार्य का नियंत्रण एवं निरीक्षण बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में निहित है जिसका वर्तमान संख्या सभापति एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्मिलित करते हुए 14 है। बोर्ड में निदेशक शासन सचिव की समता वाले वरिष्ठ प्रशासक एवं अनुभवा उद्योगपति हैं। निगम का उच्चतम दक्षता के साथ संचालन करने हेतु प्रबन्ध निदेशक को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये हैं।

वर्तमान युग में प्रजातन्त्र का युग है जिसमें सभी कार्यों को परम्परा परामर्श द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य को पूर्ति हेतु विशिष्ट गतिविधियों में सम्बन्धित निर्णयों को गति प्रदान करने के लिये निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों को सम्बन्धित मामलों में निर्णय लेने हेतु पर्याप्त अधिकार एवं दायित्व सौंपे जाते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह होता है जिन्हें इस शक्त पर कुछ कार्य सौंपे जाते हैं कि वे उन कार्यों को मिलाकर तथा सम्मिलित रूप से करें। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा तान समितियों का गठन किया जाता है। (1) कार्यकारणी समिति कार्यकारणी समिति जो कि स्थायी प्रकृति की होता है तथा निरन्तर उत्तरदायित्व का भार वहन करता है। इस प्रकार इस समिति को रोकें के सामान्य प्रशासन एवं वार्षिक मध्यम मामलों पर निर्णय लेने एवं उनके अनुसार कार्य कार्यान्वयन का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। (2) आधुनिक समिति आधुनिक समिति का कार्य क्षेत्र केवल उद्योगों को वित्तीय सहायता हेतु स्वाकृति प्रदान करना एवं विनियोग सम्बन्धी निर्णय लेने तक ही सीमित है। (3) आधारभूत विकास समिति आधुनिक क्षेत्र का विकास करना भूमि अधिग्रहण करना उद्योगों के सफल संचालन करने हेतु आधारभूत संविधान (नल विद्युत यंत्रणाएँ डाक एवं नगर) उपलब्ध करवाना इस समिति के कार्यक्षेत्र में आता है।

निगम के कार्य

Functions

निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये निगम निम्नांकित कार्य करता है

(1) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना फैक्ट्री सड़कों का निर्माण करना एवं इस हेतु आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना निगम के मुख्य कार्य हैं।

(2) राज्य में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित सम्भावित व्यवसायों का पता लगाना एवं उन पर शोध करना तथा साधनता धिवरण तैयार करना।

(3) संयुक्त एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना जिसमें तकनीकी योग्यता प्राप्त अनुभववी उद्योगपतियों को विशेष रूप से उत्साहित करना शामिल है।

(4) वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना निगम निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है

- (i) अरापूर्जी में हिस्सा एवं अंशों का अभिगोपन करना
- (ii) अर्वाधि ऋण
- (iii) बीज पूँजी
- (iv) व्याजमुक्त ऋण (राज्य सरकार की बिक्री कर योजना के अन्तर्गत)

रीको के वित्तीय स्रोत

Financial Resources

(अ) अशपूर्जी (Equity) 31 मार्च 1996 को निगम की प्रदत्त पूँजी 140 40 करोड़ रुपये तथा अधिकृत पूँजी 150 करोड़ रुपये थी।

(ब) बाण्ड (Bonds) निगम समय समय पर बाँड जारी करके भी आवश्यक धनराशि प्राप्त करती है।

(स) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं लघु भारतीय उद्योग विकास बैंक से पुनर्वित्त (Refinance) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक रीको के लिए वित्तीय सहायन प्रसिक्त प्रमुख

स्रोत हैं। रीको ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत राशि प्राप्त की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने रीको को अर्वाधि के द्वारा भी वित्तीय सहयोग प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। रीको द्वारा पुनर्वित्त सहायता के अतिरिक्त उपकरण पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत भी वित्तीय सहायता प्लान्ट व उपकरणों हेतु प्रदान की जाती है। यह सहायता सुदृढ आर्थिक स्थिति वाली औद्योगिक इकाइयों को ही प्रदान की जाती है। ऐसे ऋण प्रायः 7 दिन में स्वीकृत कर दिए जाते हैं।

निगम की प्रगति

Progress of RICO

राजस्थान में पूँजी का अपेक्षाकृत अभाव है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी संस्थाएँ ऐसी नीतियों का अनुसरण करें कि उद्योगों में पूँजी के विनियोजन को प्रेरणा मिल सके। इस दृष्टि से रीको महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। नवीन औद्योगिक नीति के पश्चात् राज्य सरकार की नीतियों में भी अनेक संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप पहले की तुलना में अधिक वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। रीको बीजपूँजी प्रदान करके प्रभावशाली व तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को उद्योगरूपी नृक्ष का बीज बाने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह औद्योगिक इकाइयों को अशपूर्जी में हिस्सा लेता है और उनके अंशों का अभिगोपन करता है। यह निगम औद्योगिक इकाइयों को आसान शर्तों पर ऋण भी प्रदान करता है।

1 आयोजना बजट - आवंटन एवं प्राप्ति

निगम की योजना मद में वर्ष 1996-97 में प्रावधानिक एवं स्वीकृत/प्राप्त राशि 3060 लाख रुपये रही जबकि वर्ष 97-98 में बजट प्रावधान 3500 लाख रुपये का रखा गया था जिसमें से जनवरी 98 तक 3300 लाख रुपये प्राप्त हुए। ग्रोथ सेंटर हेतु अशपूर्जी के 200 लाख रुपये प्राप्त होने शेष हैं। निम्न सूचना निम्न तालिका में उपलब्ध है।

1 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

राज्य सरकार द्वारा आवंटित एवं प्राप्त राशि				
				(रुपि लाख में)
वर्ष / विवरण योजना	1996-97	1997-98	1997-98	1997-98
	वर्षाविक प्राप्ति	बजट प्रावधान	जनवरी तक प्राप्ति	हनु शोधन राशिधित अनुमान
राज्य योजनावर्ष				
1 शहर पूँजी अंशदान योजना				
अ सा राशि	1427 00	1220 00	1220 00	1220 00
ब जनजीन उपयोजित	208 00	280 00	280 00	280 00

2	ग्राम सेंटर हेतु विकास अन्न पुरा	200 00			
3	जन रहित बिजली का अन्न	200 00	100 00	100 00	100 00
4	सांघाजिक आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रावधान	30 00	30 00	30 00	30 00
5	उद्योग श्रौ सेवता	100 00			
6	हाथद्वारा टेक्नोलॉजी पाक	65 00			
7	साफ़ावेपर टेक्नोलॉजी पाक	50 00			
8	अधरभूत सार्वजनिक विकास	975 00	975 00		315 00
9	बाल्य आधारभूत सुविधा विकास	100 00	100 00		
10	औद्योगिक क्षेत्र का वनस्पत सहायक विकास	125 00	125 00		25 00
11	स्थानांतरित औद्योगिक क्षेत्र का विकास हेतु अनुदान	200 00	150 00	150 00	150 00
12	शैक्षणिक क्षेत्रों का विद्युत्करण हेतु अनुदान	500 00			
13	औद्योगिक शोभाहन अनुदान	30 00	20 00	20 00	10 00
14	उद्योग गतिविधि जिला में आधारभूत सार्वजनिक विकास	50 00			
15	निर्माण सहायता औद्योगिक पार्क भिवाड़ी	200 00	100 00	100 00	100 00
16	भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण	100 00	100 00		100 00*
17	बाकहउम भिवाड़ी विकास गड				60 00
18	देलाकाम बी मट सुविधा विकास हेतु	50 00	50 00		10 00
19	अर्थ स्थान हेतु अनुदान				100 00
20	ममकित आधारभूत विकास (एन एम डी)	50 00	50 00		50 00
योग		3060 00	3500 00	3300 00	3300 00

* भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 100 लाख रु. लाभ हावी डी राजने में स्वागत करने

स्रोत: राजस्थान राज्य सरकार प्रतिवेदन 1997-98

विकास की आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने हेतु निर्माण वर्ष 1997-98 के लिए 3300 लाख रुपये की वार्षिक योजना के अन्तर्गत हा सशोधित वनस्पत प्रस्ताव भेज है। मुख्यतः धारुहेडा भिवाड़ी लिंक रोड एवं अर्थ स्थान के लिये हाल ही में स्थापित 860 लाख रुपये का अनुदान औद्योगिक सार्वजनिक विकास हेतु स्थापित सौर रान से परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमान किया गया है। इसका अतिरिक्त निगम के आन्तरिक स्रोतों में वर्ष 1997-98 की आयोजना सीमा में 3700 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल किए हुए हैं। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 के लिए 7200 लाख रुपये की वार्षिक योजना सामान्यतया जा गई है।

2. वार्षिक लक्ष्य एवं कार्य परिणाम

राजा के अच्छे कार्य परिणामों का फलस्वरूप लाभान्वित हुआ है तथा वर्ष 96-97 में कर पधन 1182 लाख रुपये का लाभ हुआ है। राज्य सरकार को 221.36 लाख रुपये का भाग वर्ष 1996-97 को लिये दिया गया।

3. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

राज्य में मार्च 97 तक स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 225 थी जो जनवरी 98 तक बढ़कर 245

हो गई। वर्ष 96-97 में औद्योगिक क्षेत्रों हेतु कुल 4827 एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी जबकि 97-98 में 4000 एकड़ भूमि के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 98 के अन्त तक 3214 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है जो कि लक्ष्यों के मुकाबले 80-85 प्रतिशत है। इस प्रकार इन औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक कुल 48260 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है।

वर्ष 96-97 को राजको द्वारा उत्तम आधारभूत सुविधा वषण रूप में मनाया गया तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं रखरखाव आदि कार्यों पर वर्ष 96-97 में निगम द्वारा 14212 लाख रुपये खर्च किये गए जराक चालू वर्ष में जनवरी 98 तक इस मद पर 9877 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। आलोच्य वर्ष 97-98 में लगभग 200 करोड़ रु. व्यय किये जाने की योजना है।

वर्ष 96-97 में 3140 एकड़ भूमि विकसित की गई तथा 1339 भूखण्ड आवंटित किए गए और उत्पादन से इन्कामों का मरका 688 रही जबकि चालू वर्ष में 2180 एकड़ भूमि विकसित की गई 693 भूखण्ड आवंटित किए गए तथा 359 और इन्काम उत्पादन में आई। विवरण निम्न तालिका में उपलब्ध है।

आधारभूत सुविधाएँ (सारांश)

(राशि लाख रु. में)

विवरण	वास्तविक प्रगति 1996-97	प्रस्तावित लक्ष्य 1997-98	वर्ष 1996-97 में प्रगति (जनवरी तक)
1 अवाप्त भूमि (एकड़)	4827.47	4000.00	3213.68
2 विकसित भूमि (एकड़)	3139.35	2000.00	2180.33
3 विकसित भूखण्ड (संख्या)	1338	-	3290
4 शुद्ध आवंटित भूखण्ड (मण्डल)	1339	3000	689
5 उत्पादन में इकाइयाँ (संख्या)	688	-	359

स्रोत: रीकी वार्षिक प्रतिवेदन 1997-98

मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में और उनके आसपास सामाजिक आधारभूत सुविधाओं तथा आवास विद्यालय, अस्पताल आदि का सुदृढीकरण किया जा रहा है। इससे औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियों के रित्ये आकर्षक एवं रहने योग्य हो सकेगें। रीकी का अनुभव रहा है कि अधिकाधिक विनियोजन एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उत्तम एवं एकीकृत आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। तदनुसार सभी सामाजिक आधारभूत सुविधाओं से युक्त समेकित औद्योगिक शहरो (इण्डस्ट्रियल टाउनशिप) को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें निजी क्षेत्र का भी सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है।

उद्योग विशेष समूह के विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रीकी द्वारा अनेकानेक विशिष्ट औद्योगिक पार्क्स एवं थीम पार्क्स के सृजन पर ध्यान दिया गया है। गन्ध में एक ओर राष्ट्रीय राजमार्ग मध्या 8 पर विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों (शहजहापुर, नीमगना बहरोड, सोतानाला, कोटपुतली, कूकस, बगरू, मिशनगढ व्यावर राजसमन्द उदयपुर) पर निगम द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भिवाडी औद्योगिक क्षेत्रों में सिरमौर के रूप में उभरा है जहाँ कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी अपने उद्योग स्थापित किए हैं। यातायात सुधार हेतु धारूहेडा-भिवाडी सड़क को चार लेन का बनाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ई पी आई पी, सीतापुर (जयपुर) में एक अर्थ स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

4 विकास केन्द्रों (ग्रोथ सेन्टर) की स्थापना

औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय अयम्यता को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा (केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत) स्वीकृत चार ग्रोथ सेन्टर (जोकारनेर, आनूरोड, ज्ञानावाड एवं भीतपुर) परियोजनाओं पर वर्ष 96-97 में कार्य

विभिन्न चरणों में प्रगति पर रहा और प्रारम्भ से मार्च, 97 तक कुल विनियोजन 2245 92 लाख रुपये का हुआ था। चालू वर्ष में अब तक ग्रोथ सेन्टरों के विकास पर 178 41 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। पाचवें ग्रोथ सेन्टर भीलवाडा की स्वीकृत भारत सरकार से प्राप्त हो गई है, जिस वस्त्र नगरी के रूप में विकसित किए जाने की योजना है।

5. मिनी ग्रोथ सेन्टर्स

ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को एकीकृत आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पाच-पाच करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर एवं नागौर में लघु विकास केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इसमें से जोधपुर मिनी ग्रोथ सेन्टर हेतु सागरिया में कुल 88.31 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है। मार्च, 97 तक इसके क्रियान्वयन पर 193 लाख रुपये व्यय किए गए तथा अप्रैल से जनवरी, 98 तक 150 लाख रुपये और व्यय किये जा चुके हैं। इसमें नियोजित 574 प्लाट्स में से 567 प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं।

नागौर जिले के गोरोलाव ग्राम में मिनी ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने का निर्णय दिनांक 18.3.97 को हुआ है। इस हेतु 78 8 एकड़ भूमि अवाप्त कर ली गई है एवं विकास कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। इस पर जनवरी 98 तक 83 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

राज्य में तीसरे एवं चौथे मिनी ग्रोथ सेन्टर निवाई (रोक), कलडवास (उदयपुर) की परियोजना पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अप्रेजल किया जा रहा है।

6 औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

सावधि ऋण एवं अरापूजी की स्वीकृति तथा निगरण निगम की महत्वपूर्ण विकास बैंकिंग गतिविधि हैं, परन्तु

विश्वव्यापी औद्योगिकमंदी के चलते हुए देश में औद्योगिक विकास की दरगत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष घटकर लगभग आधी रह गई है। निगम द्वारा वर्ष 96-97 में 86 औद्योगिक परियोजनाओं को 8924 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गए हैं। वर्ष 96-97 में उद्योगों को 5591 लाख रुपये के सावधि ऋण वितरण किए गए जबकि चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 3660 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार अशपूजी सहायता मद में वर्ष 96-97 में 451 लाख रुपये की स्वीकृति तथा 189 लाख रुपये का वितरण किया गया जबकि वर्ष 97-98 में माह जनवरी, 98 तक 85 लाख रुपये की स्वीकृति और 35 लाख रुपये का ही वितरण हुआ है।

ब्याज रहित विक्री कर ऋण के मद में वर्ष 96-97 में 85 लाख रुपये की स्वीकृति तथा 92 लाख रुपये का वितरण किया गया, जबकि चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 98 तक इस मद में 500 लाख रुपये की स्वीकृति एव 43 लाख रुपये का वितरण किया गया है। राज्य सरकार की ओर से उद्यमियों को वर्ष 96-97 में पूंजी विनियोजन अनुदान के रूप में 711 लाख रुपये की स्वीकृति एव 507 लाख रुपये का वितरण किया गया। इस मद में चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 189 लाख रुपये की स्वीकृति एव 289 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। विस्तृत विवरण निम्न तालिका में उपलब्ध है।

उद्योगों को वित्तीय सहायता			
(रुपि लाख में)			
विवरण	वार्षिक प्रगति	तक्ष्य 97-98	वर्ष 1997-98 में प्रगति (जनवरी, 98 तक)
1 सावधि ऋण / विन ऋण			
स्वीकृत	8924.18	6500.00	4175.62
वितरित	5591.12	5000.00	3659.96
2 अशपूजा			
स्वीकृत	451.15	400.00	85.00
वितरित	189.33	150.00	35.00
3 ब्याज रहित विक्रीकर ऋण			
स्वीकृत	85.04	550.00	500.19
वितरित	91.51	550.00	42.56
4 केन्द्रिय / राज्य अनुदान			
स्वीकृत	713.85	150.00	189.35
वितरित	507.00	50.00	288.82
संयुक्त टैक्स वित्तिय प्रगति, 1997-98			

वर्ष 96-97 में 5864 लाख रुपये के सावधि ऋण को वसूली का गई है। ब्याज मुक्त विक्री कर ऋण को वसूला भी वर्ष 96-97 में 46 लाख रुपये हुई जो एक कातिमान है। चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 4046 लाख रुपये के सावधि ऋण तथा 217 लाख रुपये के ब्याज रहित विक्री कर ऋण को वसूलिया का गई है।

निगम द्वारा वर्ष 1996-97 में 232 लाख रुपये अशपूजी के अप-विनियोजन के रूप में प्राप्त किए गए, जबकि वर्तमान बाजार स्थिति में भा चालू वर्ष में अब तक 66 लाख रुपये का अशपूजी का अप विनियोजन किया जा चुका है।

7. निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआई.पी.)

राज्य के निर्यातमुखी औद्योगिक विकास हेतु जयपुर के सातापुरा औद्योगिक क्षेत्र में नियत सवर्द्धन

पाक विकसित किया जा चुका है। इस पाक को कुल लागत 47.17 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस पाक के लिये 10 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार तथा 3.33 करोड़ रुपये राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।

इस पाक हेतु 365 एकड़ भूमि विक्रयित की गई जिसमें 385 भूखण्ड प्लान क्रिय गए हैं। अब तक 122 उद्यमियों को 154 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं जिनमें 12 यूनिट्स में निमाण कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा 3 यूनिट्स में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। जनवरी, 1998 तक पाक पर लगभग 36.23 करोड़ रुपये का विनियोजन हो चुका है।

इसकी प्रगति से प्रभावित होकर केन्द्र सरकार ने राज्य में भिवाडों के समीप दूसरा निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान

की है जिसका लागत लगभग 55-34 करोड़ रुपये होगी तथा इसमें 11547 एकड़ भूमि को अवाधि की कार्यवाही काग रही है। इसका विस्तार करने हेतु एन सी आर पा बा स 24 लाख रुपये ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं।

8 गार्ड छपाई उद्योग-सागानेर

गार्ड छपाई उद्योग के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से सागानेर के निकट ही एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये लगभग 800 एकड़ भूमि का जमा किया गया है। इस भूमि की अवाधि हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत विज्ञापित करा जा चुका है। भूमि पत्राधिकार बाद इस क्षेत्र के विकास की कार्यवाही को जायगी आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकास करने की विस्तृत तकनीकी/वित्तीय परियोजना बनाने के लिये आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ की सेवाओं के रूप में मंजूर व्यय व कन्सल्टेंट्स से विस्तृत प्रतिनित्तन तथा कार्यवाही जा रहा है ताकि प्रदूषण निवारण हेतु संपत्त उपचार संयंत्र की स्थापना में नवीनतम उपलब्ध तकनीकी का उपयोग किया जा सके।

9 मार्बल मण्डी किशनगढ़

किशनगढ़ में राज्य का प्रथम मार्बल मण्डी विकसित की गई है। यह मण्डी 16 चौकी भूमि पर स्थापित की गई है तथा इसमें 109 मार्बल गादाम 34 दुकानें एक शॉटल पट्टाल पम्प बैंक भवन आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

10 इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी पार्क

नयपुर के निकट सागानेर में इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी पार्क हेतु 41 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है। इस पार्क में फ्लैट फेक्टो काम्प्लेक्स व उच्च गति की डेटा संचार सुविधाओं द्वारा स्थापित का जायगी जिस पर कुल 396 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इस हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराय जान की आशा है। इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी पार्क में अभा तंत्राचार उद्योगपतियों का अपनी इकाईयां लगान हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रयोजना में 64 के पी पा एम इंटर्नट लीड लाइन उद्योग भवन के सामन निम्न भवन में लगा दी गई है तथा कार्यगत है। उक्त योजना पर अभा तक लगभग रुये 15 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। भवन निर्माण का योजना पर कार्य चल रहा है। इस दिशा में आर्सेटिक्ल से नमूना बनवाकर भवन निर्माण स्वीकृति दी जा गई है।

उक्त पार्क में अर्थ स्टेशन स्थापित करने के लिये साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया में एम ओ यू (Memorandum of Understanding) किया जा रहा है।

11 भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण - (बीडी)

औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 11.3.97 का अधिभूषित का अध्यादेश की दिनांक 21.3.97 को नियुक्ति की गई। राज्य सरकार ने जून 97 में इसके पांडी खाते में एक करोड़ रुपये की राशि हस्तान्तरित कर दी है। प्राधिकरण के कार्यकलाप को मूर्त रूप देने के लिए प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनांक 14.5.97 को तथा द्वितीय बैठक 18.11.97 का सम्पन्न हुई बैठक के लिए गए निर्णयों की अनुपालना में भिवाडी की मुख्य सड़क की सफाई व्यवस्था एवं भिवाडी क्षेत्र में अग्नि शमन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भिवाडी क्षेत्र में राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी की नियमित सफाई व्यवस्था नालियों की मरम्मत का कार्य मलवा इत्यादि हटाने के कार्य कलापा की व्यवस्था हेतु निविदाएं प्राल कर स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। भिवाडी क्षेत्र में नगराय परिवहन सेवा उपलब्ध करान हेतु नगरीय मार्ग का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मार्ग पर वाहन चलाने हेतु एन अनुज्ञापत्र भी स्वीकृत हो गया है। भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन कार्यों पर जनवरी 98 तक 9.27 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

12 औद्योगिक प्रोत्साहन गतिविधियां

निगम द्वारा वित्त निगम औद्योगिक प्रोत्साहन व्यय एवं उद्योग विभाग व सहायक राज्य में औद्योगिकरण के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन शिखर लगाए जाते हैं। वर्ष 1996-97 में 13 एम ओ यू हस्ताक्षरित हुए। चालू वर्ष में जनवरी 98 तक एम ओ यू हस्ताक्षरित किया गया है। इस वर्ष अगस्त 4 वृद्ध एवं मध्यम उद्योगों का टारट अप किया गया है जिसमें राज्य में 1939 करोड़ रुपये विनिर्माण में सहायताएं और बनी हैं।

13 नियोजन (रोजगार)

निगम में 31 मार्च 1997 का कुल 1508 अधिकारियां एवं कर्मचारियों के स्थापित पत्र पर 1366 कार्यरत थे। निगम में सहायक प्राप्त इकाईयां में 19

96-97 में 814.27 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनियोजन के फलस्वरूप 4372 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 87.55 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनियोजन से 1361 व्यक्तियों को और रोजगार उपलब्ध करने के अवसर सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त रीको के औद्योगिक प्रोत्साहन से टाई-अप उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में सृजित रोजगार के अन्तर्गत वर्ष 96-97 में क्रमशः 5948 तथा 14800 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा अगस्त वर्ष में जनवरी, 98 तक औद्योगिक प्रोत्साहन से टाई-अप उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में करीब 6000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये।

14 जनजाति उपयोजना क्षेत्र

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निगम द्वारा 96-97 में सावधि ऋण पर मार्जिन राशि के रूप में 8.20 लाख रुपये की अंश पूंजी का भुगतान किया गया। चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 25.76 लाख रुपये सावधि ऋण मार्जिन के रूप में वितरण किये गये।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आधुनिक विकास केन्द्र के विकास पर वर्ष 96-97 में 85.27 लाख रुपये व्यय किए गए, जबकि चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक इस मद पर 98.75 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

15. अनुसूचित जाति संगठक योजना

इस योजनान्तर्गत निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किए जाते हैं। वर्ष 96-97 में 260 व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित किए गए जबकि चालू वर्ष में संशोधित लक्ष्य 100 उद्यमियों में से जनवरी 98 तक 93 उद्यमियों का भूखण्ड आवंटित कर 10460 लाख रुपये की रियायत दी गई है।

16 वॉच फैक्ट्री की गतिविधियाँ

रीको की अजमेर स्थित वाच फैक्ट्री में वर्ष 96-97 में 149260 घड़ियाँ असेम्बल की गई थी जबकि चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 56870 घड़ियाँ असेम्बल की गई हैं। कमी का कारण एच एम टी की घड़ों के कम्पोनेन्ट (कलपुर्जों) की आपूर्ति कम होना रहा है।

17. रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार

औद्योगीकरण के बढ़ते हुए दौर पर कुछ उद्योग रुग्ण होते ही हैं। रीको द्वारा अब तक कुल 708 इकाइयों को सावधि ऋण/अंशपूजी सहायता स्वीकृत की गई है, इनमें से वर्तमान में 58 इकाइयाँ रुग्ण हैं जिनके सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना इस प्रकार है -

अ. रुग्ण इकाइयों का वर्गवार विवरण :

रुग्ण इकाइयों का वर्गवार विवरण	इकाइयों की संख्या
बी आई एफ आर में पंजीकृत इकाइयाँ	8
ए ए आई एफ आर में पंजीकृत इकाइयाँ	3
रीको एन एफ सी द्वारा संस्तान 29 के अन्तर्गत अधिग्रहित इकाइयाँ	35
समापन हेतु निर्णित/डो अर.आई के अधीन इकाइयों की संख्या	12
कुल	58

इसके वाचिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

बी आई एफ आर सम्बन्धी इकाइयों में से एक की ड्राफ्ट पुनर्जीवन योजना तैयार कर ली गई है तथा 7 कम्पनियों के प्रस्ताव ओपरेटिंग एजन्सी/बी आई एफ आर के पास विचारार्थीन हैं।

ब. अधिगृहीत इकाइयाँ :

एस एफ सी एक्ट की धारा 29/30 के अन्तर्गत कुल 35 इकाइयाँ अधिगृहीत की गई हैं, इनमें से 7 इकाइयाँ इसी वर्ष 1997-98 में अधिगृहीत की गई हैं। इन इकाइयों का परिमर्पणितियों के अंशान के सम्बन्ध में रीको प्रयत्नशील है।

वर्ष 96-97 में रीको ने 4 इकाइयों का पूर्ण बेचान एक इकाई की पश्चिमी एव दो इकाइयों की भूमि व भवन का बेचान कर दिया है तथा कुछ अन्य इकाइयों का बेचान वर्ष 1997-98 में होने की संभावना है।

एस एफ सी एक्ट की धारा 29/30 के अन्तर्गत अधिगृहीत इकाइयों को परिसम्पत्ति का भी सुरक्षा के सम्बन्ध में रीको पूणित सजग है। सुरक्षा व्यवस्था के लिये रीको द्वारा चौकीदार नियुक्त किए जाते हैं यदा कदा आवश्यकतानुसार प्राइवेट एजन्सियों की मदद भी ली जाती है।

दो अन्य सहायता प्राप्त इकाइयाँ - सजावनी फोर्ड्स प्रा. लि. की परिमर्पणितियों का डाइरेक्टर रवेन्डू इण्टेलीजन्स, भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया गया

है। इनमें रीको की बकाया राशि 856 50 लाख रुपये हैं। इन इकाईयों के सम्बन्ध में मामला चैजर्ड उच्च न्यायालय में लम्बित है।

स वसूली के लिये एक बारीय समझौते के प्रयास

कुछ ऐसी इकाइयाँ जो रूग्णता की स्थिति में हैं व जिनमें बकाया ऋण एवं व्याज की वसूली करने में कठिनाई हो रही हैं, वे भी एक त्रयीय समझौता करके पसला के प्रयास किए जाते हैं। यह समझौता करते समय यह प्रयास किया जाता है कि ऋण की मूल राशि के साथ-साथ अधिकतम व्याज की राशि भी वसूल कर ली जाए एवं कुछ ही छूट दी जाए जिससे प्रलोभित होकर प्रवर्तक एक बारीय समझौता कर ले व जिनमें को अधिग्रहण एवं बेचान में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

वर्ष 95-96 में 10 व 96-97 में 8 इकाइयों से इस प्रकार से वसूली के प्रयास सफल भी हुए हैं तथा कुछ अन्य इकाइयों के प्रस्ताव विचारधीन हैं।

द उद्योगों में रूग्णता रोकने के प्रयास

उद्योगों में रूग्णता विभिन्न कारणवश नैसर्गिक रूप से होती है। जहाँ तक रीको द्वारा महायत्ना प्रदत्त इकाइयाँ में रूग्णता के ग्रन्थ हैं उसका एक प्रमुख कारण यह है कि रीको द्वारा वित्त पोषित इकाइयाँ अधिकतर फ्लू जेनरेशन के उद्यमियों द्वारा लगाई गई हैं। इन उद्यमियों का ससाधन सामान्यतया सामित ही होते हैं एवं कार्यशाल पूजा के लिए भी वे पूरी तरह से बैंका पर ही निर्भर होते हैं और समय पर यदि कार्यशाल पूजा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो इस कारण से भी ये उद्योग रूग्ण हो जाते हैं। रीको प्रयासरत है कि कार्यशाल पूजा के लिए परियोजना अप्रजल करते समय बैंक से विचार-विमर्श कर लिया जाए तथा पर्याप्त कार्यशाल पूजा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाए जिससे इस कारणवश होने वाला रूग्णता का यथाशक्ति गैर हो जा सके।

सुधार के विशेष प्रयास एवं अभिनव योजनाएँ

1 राज्य में पथर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका आकर्षण बढ़ाने हेतु सी डास (मन्टर फार डेवलपमन्ट आफ स्टान्स) के नाम से एक विशिष्ट संस्था बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका स्वरूप तैयार हो चुका है। इस पर कुल 20 करोड़ रु की लागत आने की सम्भावना है। रीको ने इसके लिए 30 एकड़ भूमि सतपुरा जयपुर में आरक्षित कर दी है।

2 राजस्थान में पहली बार राजस्थान पञ्जाब हरियाणा तथा दिल्ली सरकार ने मिलकर काडला में बन्दरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है तथा इस बन्दरगाह की स्थापना से राजस्थान के निर्यातकों को सामान आयात निर्यात करने में बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

3 राज्य में प्रथम बार ग्रामीण सुविधा विकास कोष एवं कोशल विकास कोष की स्थापना की गई है। कोशल विकास कोष की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि उद्योगों हेतु भूमि अधिगृहित करने के उपरान्त बचा क बेरोजगार युवकों का ट्रेनिंग देकर रोजगार हेतु तैयार किया जाए। ग्रामीण विकास कोष के माध्यम से जिन ग्रामों को भूमि अधिगृहित की जाती है उनके विकास कार्य को करवाया जाता है। इन दोनों बोधों में अधिगृहित भूमि की कीमत की एक एक प्रतिशत राशि जमा करवाई जाती है। रीको द्वारा भिवाडी एवं जयपुर के आस-पास कई ग्रामों में विकास योजना को हाथों में लिया जा चुका है।

4 भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र को रेल से जोड़ने हेतु रेवाडी में भिवाडी रेल लिंक का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया है। इस पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति भी दी जा चुकी है तथा आश्वासन दिया गया है कि इसे शीघ्र लागू किया जाएगा। इस पर 40 करोड़ रु की लागत आने की सम्भावना है।

5 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात की प्रबल सभावनाओं को देखते हुए रीको द्वारा सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना की गई है। पार्क में भारत सरकार की मदद से एक अर्थ स्टेशन लागू करने की योजना भी स्वीकृत की गई है जिसकी लागत करीब साढ़े पार करोड़ रु होगी। इसके लगने से सॉफ्टवेयर के निर्यात की अत्यन्त बढ़ावा मिलेगा।

6 प्रथम बार राज्य में प्रदूषण सलाहकार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को प्रदूषण सम्बन्धी सलाह देना तथा इससे रोकथाम हेतु मदद करना है।

7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योगों की सभावना को दूर करने हेतु एक योजनाबद्ध तरीके से योजना का विकास किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 70 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की गई है तथा निर्धारित राशि के प्रस्ताव उन पराम भिजवाए जा चुके हैं। इस पर करीब 100 करोड़ रु का महायत्ना केन्द्र से प्राप्त हो सकेगा जब कि किसी अन्य प्रदेश के मुकाबले औद्योगिक विकास हेतु प्राप्त की गई सार्वाधिक राशि है।

8 औद्योगिक क्षेत्रों के समीप सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं तथा आवासीय एवं अन्य सुविधाओं को विकसित किया गया है।

9 उद्यमियों को सहायताार्थ रीको के विभिन्न नियमों का सरलीकरण किया गया है। जैसे कि -

- 40000 वर्ग मीटर भूमि तक के नवरो स्वीकृत करने की अनिवार्यता समाप्त।

भूखण्ड के ट्रांसफर को सरल बनाना।

आवटन समितियों में उद्यमियों की भागीदारी।

- प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य चार्ज को वहाँ खर्च करना।

राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको)

RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION

स्थापना एवं उद्देश्य

Establishment & Objects

भारतीय कम्पनी अधिनियम 1965 के अनुसार राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून 1961 को की गई। इसे फरवरी 1975 में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का रूप प्रदान कर दिया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य का लघु इकाइयों एवं छोटे छोटे कारीगरों को पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन देना है ताकि राघु उद्योगों की दृष्टि में राज्य का नाम गति से औद्योगिक विकास हो सके।

कार्य

Functions

राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

- (1) राज्य में निगम के पास कई कच्चे माल के भंडार हैं। इन भंडारों से लघु उद्योगों को कच्चा माल वितरित किया जाता है।
- (2) निगम हस्तशिल्प की बिक्री अपने एम्पोरियमों के द्वारा करता है।
- (3) निगम चूरु व लाडनू की ऊन मिलों तथा जयपुर स्थित फर्नीचर उत्पादन केन्द्र का संचालन करता है।
- (4) निगम द्वारा गलीबा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। उ० की छाल पर मनोवृत्ति के काम की विशिष्ट कला को जातिव रखने के लिये बीकानेर में एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है।
- (5) जयपुर स्थित हातशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध

केन्द्र का संचालन निगम द्वारा ही किया जाता है।

(6) सागनर एयरपोर्ट पर स्थापित एयर कारगो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यातकों को सुविधायें सुलभ कराई जाती हैं।

(7) हाथकरघा उद्योग के विकास हेतु निगम अनेक कार्य करता है।

(8) निगम मयूर नामक बाड़ी का उत्पादन करता है। यह बीडी फैक्ट्री टाक में स्थित है।

(9) निगम राज्य की हस्तकला का प्रचार करता है।

निगम की पूंजी

Capital

राजस्थान लघु उद्योग निगम की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपये है जो 100 रुपये के अंशों में विभक्त है। 31 मार्च 1992 को निगम की प्रदत्त पूंजी 4 69 करोड़ रुपये के बराबर था।

निगम की वित्तीय स्थिति

Financial Position

राजस्थान लघु उद्योग निगम की वित्तीय स्थिति का ज्ञान निम्नलिखित तालिका से प्राप्त किया जा सकता है।

(राशि 5 लाख ₹ में)		
क्र. वर्ष	व्यापारावर्त	लाभ हानि
1 1993-94	2688 52	(-)14 00
2 1994 95	3803 40	(-)22 73
3 1995-96	5001 11	(+)219 49
4 1996-97	7130 43	(+)349 65
5 1997 98	4473 87	(+)347 31
दिसम्बर 97 तक		
स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98		

प्रगति 1997-98

हस्त शिल्प हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें कच्चे माल, प्रशिक्षण सुविधा एवं विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में सन्दिग्ध अवधि में अनेक कदम उठाये गये हैं। हस्तशिल्पियों से साधे माल खरीदन का प्रणाली भी प्रारम्भ की गयी है।

1 **हस्तशिल्प** - हस्तशिल्प वस्तुओं का उचित बाजार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से गत वर्ष शिल्पग्राम मजबूत मेचे व अन्य प्रदर्शनिया देश के प्रमुख शहरों में आयोजित की गयी हैं जो हस्तशिल्पियों के लिये सार्थक सिद्ध हुई हैं।

हस्त शिल्प वस्तुओं के विक्रय को बढ़ाने में प्रदर्शनियों के साथ ही एम्पोरियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हस्तशिल्प की कलात्मक वस्तुओं की अभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त एवं उचित स्थान के साथ ही सुरक्षित एवं सुविधा सम्पन्न स्थान होना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से राजस्थालियों के नवीनीकरण की योजनाएँ बनायी जा रही हैं तथा इस हेतु प्रशिक्षित आर्कोजेक्ट का पैन्ल भी अपनाया गया है। इन नवीनीकरण प्रोजेक्ट में राजस्थली, नई दिल्ली, आमेर व उदयपुर स्थित एम्पोरियम का नवीनीकरण सम्मिलित हैं।

उत्तरोत्तर बढ़ती हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के क्रम में 1996-97 में रुपये 749.54 लाख की बिक्री की गयी जबकि चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 की जनवरी, 1998 तक रुपये 613.12 लाख की बिक्री हुई है।

बिक्री की भांति ही निगम द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं के क्रय में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1996-97 में रुपये 165.30 लाख की वस्तुओं का क्रय किया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनवरी, 1998 तक रुपये 192.95 लाख की हस्तशिल्प वस्तुओं का क्रय किया गया है।

एम्पोरियम के माध्यम से निगम द्वारा क्रय किये समान का विक्रय करने के साथ ही न्यूनतम विक्रय गारन्टी के साथ कन्साइनमेन्ट सेल के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में रुपये 433.45 लाख की न्यूनतम गारन्टी प्राप्त की है। इस स्रोत से निगम की आय में वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में दिल्ली, आगरा उदयपुर के एम्पोरियमों के नवीनीकरण के कारण कन्साइनमेन्ट सेल के अन्तर्गत रुपये 172.43 लाख की न्यूनतम गारन्टी जनवरी, 98 तक प्राप्त हुई है।

हस्तशिल्प का विपणन (रुपये लाख में)		
वर्ष	क्रय	विक्रय
1992-93	187.69	540.06
1993-94	140.45	661.22
1995-96	223.02	662.87
1995-96	213.56	781.14
1996-97	165.30	749.54
1997-98	192.25	613.12
(जनवरी 98 तक)		

स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

राजस्थान में हस्तशिल्प विकास की दिशा में राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन निर्यात-निर्याती गतिविधियों को सबल देने व समृद्ध आधारभूत सारचना

उपलब्ध कराकर निर्यात-संवर्द्धन की गतिविधि में प्रमुख भूमिका निभाई है।

जयपुर में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स व आई सी डी को स्थापना व जोधपुर में आई सी डी की स्थापना से हस्तशिल्प निर्यात को काफी प्रोत्साहन मिला है।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात, गलीचो सहित (राशि लाख रूपयें)			
वर्ष	एयर कारगो जॉयलैक्स	आई सी डी जयपुर	जोधपुर
1993-94	557.58	2281.42	-
1994-95	671.58	3307.72	-
1995-96	956.58	5719.98	2691.40
1996-97	1002.36	5715.41	10149.83

स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 1997-98

2. कच्चे माल का उपार्जन एवं वितरण -

राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के लिये विभिन्न प्रकार का कच्चा माल जैसे लोहा-इस्पात, पिग आइरन, कोक/कोल, मोम आदि का उपार्जन व वितरण, निगम की स्थापना से ही एक प्रमुख गतिविधि रही है।

जनवरी, 1992 से विनियत्रण एवं भारत-सरकार की उदारीकरण नीति के कारण लोहा-इस्पात के व्यापार में काफी मन्दो का दौर आ गया था। वर्ष 1993-94 व 1994-95 में तो ठहराव-सा आ गया था। परन्तु निगम द्वारा अथवा प्रयास कर इस व्यवसाय को पुनर्जीवन प्रदान किया गया। वर्तमान में लोहा-इस्पात के व्यवसाय में वृद्धि करने एवं अधिक से अधिक मात्रा का उपार्जन एवं वितरण करने वांछित निगम के समस्त कच्चा माल आगारों पर माल की वितरण नीति के अनुसार राज्य में सभी लघु औद्योगिक इकाइयों को लाभान्वित करने की मशा है। इसके तहत इकाइयों राज्य में सम्बद्ध आगारों पर सिक्कूरिटी राशि जमा करवाकर इच्छुक मात्रा की बुकिंग करवा सकती हैं ताकि अधिकतम अवधि एक माह में माल की पूरी राशि जमा करवाकर माल प्राप्त कर सकती हैं। इससे निगम के व्यवसाय में अधिक से अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

पिछले वर्षों में कच्चे माल का व्यापारावर्त निम्न प्रकार रहा -

उत्पादन

वर्ष	लौहा-इस्पात	पिय-शेयरन	पैराफिन वैक्स	बॉच/कोक मै टन म	कुल ध्वसागर्वन रु लाखों म
1993-94	474	2308	600	16827	1050 68
1994-95	2116	7833	547	8490	3547 10
1995-96	8912	4246	610	8863	2526 04
1996-97	12252	1454	588	12830	3164.22
1997-98	12469	-	427 5	6258	2695 95

स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

3 निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाएँ- राज्य में निर्यातमुखी गतिविधि को सफल देने व समृद्ध आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने में राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि. महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहा है। निगम द्वारा जयपुर व जोधपुर में संचालित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, (शुष्क बन्दरगाह) एवं जयपुर स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की राज्य में निर्यात संवर्द्धन की

गतिविधि में प्रमुख भूमिका रही है। जयपुर व जोधपुर में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना के पश्चात राज्य से किये जा रहे निर्यात में निरन्तर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी है। पिछले वर्षों में आई सी डी व जोधपुर एव एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की परिलब्धियाँ तालिका में दर्शायी गयी हैं।

एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर (AIR CARGO COMPLEX JAIPUR)

(Qty in MT/Value Rs in Lacs)

Year	Export Quantity	Value	Import Quantity	Value	Total Quantity	Value
1980-81		700				700
1981-82		1132.05				1132.1
1982-83		593.47	-	524	-	1517.5
1983-84		1421	-	1054	-	2475
1984-85		1634		1588		3202
1985-86		2107		2044		4151
1986-87	-	2986	-	3026	-	6012
1987-88		4742	-	3369		8111
1988-89	518.2	11685.1	-	4615	518.2	16300
1989-90	844	16874		-	844	16874
1990-91	818	16520.5			818	16521
1991-92	821.6	15175.1	151.1	7656	772.7	22831
1992-93	321.2	15058.3	120	7646.59	441.2	22705
1993-94	410.8	16803.5	92.6	6357.04	503.5	23161
1994-95	361.8	27122.2	152.8	8852.3	514.6	35975
1995-96	441.2	35368.5	210.6	13996.65	651.8	49363
1996-97	368.2	41725	269	16301.21	638.2	58028
1997-98	582.5	36919.4	216.9	15363.71	899.4	50288

(Jan 98)

इनलैण्ड कन्टेनर डिपो (INLAND CONTAINER DEPOTS)

Year	Jaipur Export Teus	Value	Import Teus	Value	Total Teus	Value	Jodhpur Export Teus	Value	Import Teus	Value	Total Teus	Value
1989-90	88	222.42	-		88	222.42						
1990-91	295		11		306							
1991-92	589	2628.65	87	124.22	676	2752.87	-	-	-	-	-	-
1992-93	743	4015.79	32	186.44	775	4202.23						
1993-94	820	8666.85	69	443.07	889	9109.92	-	-	-	-	-	-
1994-95	1714	11430.73	80	361.01	1794	11691.74	-	-	-	-	-	-
1995-96	3077	19572.81	197	1079.36	3274	20651.17	815	2788.02	24	340.0	939	3129.82
1996-97	3672	22581.64	313	2005.2	3985	24586.84	3014	10407.05	31	233.3	3045	10640.3
1997-98	3263	21627.75	177	1150.69	3440	22978.44	4035	15033	28	214	4063	15248

(Jan 98)

स्रोत: राजस्थान, वार्षिक प्रगतिवेदन, 1997-98

कमियाँ एवं इन्हें दूर करने की दिशा में प्रयास

1 सागानर हवाई अड्डे पर स्थित निगम के एयर कारगो काम्पलैक्स की गतिविधियाँ सुचारु रूप से चलाने व सुविधा विस्तार की प्रक्रिया में यथेष्ट स्थान की कमी दृष्टिगत हुई है। हवाई अड्डे पर एयर कारगो की काम्पलैक्स केलिये अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के विषय में माह मितम्बर 1997 में जबपुर में आयोजित स्कोप एयर' की बैठक के दौरान समस्या से अवगत करवाने पर अतिरिक्त वाणिज्य सचिव, भारत- सरकार एवं निदेशक केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा स्थानीय हवाई अड्डा अधिकारियों के साथ एयर कारगो कॉम्प्लैक्स का समुक्त निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के पश्चात यह सुनिश्चित किया गया है कि केन्द्रीय विमानपत्तन अधिकरण द्वारा अतिरिक्त स्थान का आवंटन करने पर स्थानाभाव की समस्या का निदान हो सकता है। निगम ने भावी आवश्यकताओं का दृष्टिगत रखकर अतिरिक्त स्थान हेतु एक भागित्र भी तैयार करवाया है जिसे केन्द्रीय विमानपत्तन अधिकरण को भिजवाया जा चुका है।

2 इण्डियन एयर लाईन्स के विमानों की सीमित भार क्षमता के परिणामस्वरूप जबपुर के इन्दिग गांधी अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली तक बोण्डेड ट्रक के जरिये निर्यातित सामान भेजने की सुविधा प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में समस्त प्रकार की वस्तुएं बोण्डेड ट्रकिंग सेवा के माध्यम से भिजवाया जाना संभव नहीं है परन्तु निगम समस्त वस्तुओं को बोण्डेड ट्रकिंग सेवा के माध्यम से भेजे जाने हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये वाणिज्य मंत्रालय व सीमा शुल्क विभाग से सम्पर्कित है तथा शीघ्र निर्णय की आशा है।

3 सुरक्षात्मक प्रावधान के अन्तर्गत एयर कारगो कॉम्पलैक्स के निर्यात किये जा रहे सामान का विमान में लदान से पूर्व 24 घण्टे का 'कूलिंग पेरियड' निर्धारित है। इस कारण निर्यात में विलम्ब एवं निर्यातकों की परेशानी को दृष्टिगत रखकर क्रिटिकल इन्फ्राम्प्टवर स्क्रीम के तहत एयर कारगो कॉम्पलैक्स में एकसरे मशीन स्थापित करने हेतु एक योजना निगम ने तैयार की है, जिसे राज्य-सरकार स्तर से भारत सरकार को भिजवायी गयी है। एकसरे मशीन स्थापित होने पर कूलिंग पेरियड के कारण हो रही समस्या से निर्यातकों को राहत मिलेगी।

4 आई सी डी. से चन्द्रगढ़ तक कन्टेनर्स का परिवहन

सड़क यातायात के माध्यम से हो रहा है। प्राकृतिक विपदा, वाहन में खराबी व कतिपय अन्य कारणों से मार्गीय विलम्ब के फलस्वरूप वाहन की मार्गीय स्थिति का पता करना अभी संभव नहीं है। इस समस्या के निदान के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक अपनाये जाने की औचित्यता की संभावना पर निगम ने मालवीय रीजनल इजीनियरिंग कॉलेज से कम्प्यूटराइज्ड ऑटोमोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम की योजना पर प्राथमिक अध्ययन भी करवाया है। इस योजना का क्रियान्वयन निगम के विचारधीन है।

5 आयात-निर्यात नीति में आई सी डी, जबपुर व जोधपुर का नाम 'पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन' के रूप में उल्लेखित न होने के कारण डी ई ई सी स्क्रीम के प्रावधानों के अन्तर्गत आयात/निर्यात में व्यवसायियों को अनावश्यक कार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप असुविधा होती है क्योंकि ऐसे मामलों में पृथक से सीमा शुल्क विभाग से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। निगम द्वारा यह प्रकरण हाल ही 'स्कोप शीपिंग' की बैठक में उठाया गया है तथा आयात-निर्यात नीति में आई सी डी, जबपुर व जोधपुर सहित नये आई सी डी खुलने पर स्वमेव उनका नाम अधिसूचित हो इसकी मांग की गयी है। इस मांग पर शीघ्र निर्णय की आशा है।

अन्य प्रमुख प्रयास

1 निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से निगम ने आई सी डी, जबपुर व जोधपुर के माध्यम से निर्यात पर निर्यातकों हेतु वोल्यूम बेस्ड इन्सेन्टिव स्क्रीम लागू की है।

2 आई सी डी के संचालन में सुझाव एवं समस्याओं पर विचार एवं समुचित निदान के उद्देश्य से एक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत निर्यातक एवं कस्टम हाउस एजेंट के प्रतिनिधि भी सदस्य मनोनीत किए गए हैं।

3 जोधपुर में एयर कारगो की स्थापना की संभावना पर अध्ययन करवाया जा रहा है। निगम ने राजस्थान कन्सलटेन्सी ऑर्गनाइजेशन को इसकी सम्भाव्यता पर अध्ययन का कार्य सौंपा है। अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।

इन्टरनेट पर ऑन लाईन ट्रेडिंग सुविधा

निगम ने 2 फरवरी 1998 को इन्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 'इण्डियाजार् कम' से ऑन लाईन ट्रेडिंग जान का शुभारम्भ किया है, जिससे भारतीय

निर्यातकों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रेताओं को भारतीय उत्पादों के बारे में विस्तृत सूचना व जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। यही नहीं, इन्स्टेन पर ही विचार-विमर्श की सुविधा तथा अन्य व्यापारिक जानकारीयों तथा सहायता, सुविधाएँ, शिपिंग, होटल, हवाई यात्रा सम्बन्धी जानकारी भी इस पर उपलब्ध हो सकेगी। भारत में यह सुविधा सर्वप्रथम उपलब्ध करने का श्रेय निगम को प्राप्त हुआ है।

नवीन योजनाएँ

1. आई सी डी भीलवाड़ा - भीलवाड़ा में आई सी डी की स्थापना हेतु निगम द्वारा नगर विकास न्यास से आजाद नगर योजना में 25,000 वर्ग गज भूमि क्रय की जा चुकी है। उक्त भूमि पर भवन, शेड, चार-दीवारी व अन्य आवश्यक निर्माण कार्य राजस्थान राज्य प्लान निर्माण निगम को आवंटित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है।

2. आई सी डी भिवानी - भिवानी में आई सी डी की स्थापना हेतु निगम द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर से 15,000 वर्ग मीटर भूमि क्रय की जा चुकी है तथा दिनांक 6 नवम्बर, 97 को इसका शिलान्यास कर आवश्यक निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाये जाने के प्रयास जारी हैं।

3. रेल मार्ग से कन्टेनर परिवहन - निगम ने आई सी डी, जयपुर से मुम्बई स्थित बन्दरगाह तक रेल मार्ग से कन्टेनर परिवहन की योजना का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र की सहभागिता में करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से निगम द्वारा आमन्त्रित निविदाएँ विचारणीय हैं। इस कार्य में रेलवे का भी अपेक्षित सहयोग आवश्यक है, अतः निगम ने रेलवे से भी अधिमूचिन दस्त पर रेल आवटन की मांग की है।

अन्य राज्यों से तुलनात्मक स्थिति देश के विभिन्न स्थानों पर आई सी डी का संचालन पृथक पृथक संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अतः आकड़ों के अभाव में तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। देश में राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य कोई लघु उद्योग निगम आई सी डी संचालन की गतिविधि में सलग्न नहीं है। एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स के बारे में वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त देश के विभिन्न 9 एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स के आकड़ों की तुलनात्मक स्थिति की विवेचना करने पर यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1995 में नियातित वस्तुओं के मूल्य की दृष्टि से एयर कार्गो

कॉम्प्लैक्स जयपुर का स्थान बैंगलोर के पश्चात् दूसरा था। मात्रा की दृष्टि से इसका स्थान चौथा था।

3. विपणन सहायता - राज्य की विभिन्न लघु औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के संवध में वर्ष 1996-97 में दो मेले 'कन्जुमैक्स-96' एवं 'सजावट मेला-96' प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-96' का आयोजन भी प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-96 में राजस्थान मण्डप को रजत पदक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह उपलब्धि 17 वर्षों पश्चात् अर्जित की गयी है। माह जनवरी, 1997 व मार्च 1997, में राजस्थान हैंडलक्राफ्ट्स फेयर, 1997 प्रगति मैदान, नई दिल्ली एवं आई एस ओ 9000 तथा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कार्यशाला आयोजित की गई। वर्ष 1997-98 के अगस्त माह में पैकेजिंग पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला को जयपुर में आयोजित किया गया।

राज्य सरकार ने निगम को अपने विभिन्न विभागों को कांटेनर तार पौलिथीन थैलिया, टेन्ट्स-ट्रिपाल, चिप्स, टाईल्स, पी वी सी वायर्स और कंबल, अपर सी सी पाइप्स, डेजर्ट कूलर्स, उन्नत किस्म के औजारों के किट आदि की पूर्ति करने के लिए एक मात्र स्त्रोत माना है।

वर्ष 1996-97 में रु 804 करोड़ का व्यापारावर्त किया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष की माह जनवरी, 98 तक रु 5.06 करोड़ का व्यापारावर्त किया गया है।

विपणन सहायता अन्तर्गत विगत 5 वर्षों का व्यापारावर्त निम्न प्रकार है -

राशि - लाख रु में							
वर्ष	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	Jan 98 तक	
व्यापारावर्त	635.58	854.82	941.57	803.81	506.00		
स्त्रोत: राजकीय, प्रगति प्रतिवेदन 1997-98							

प्रोत्साहन गतिविधियाँ

1. गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र - राजस्थान में ऊनी गलीचों के विकास की संभावना को मध्यनजर रखते हुए इस उद्योग को कुशल कारीगर उपलब्ध करवाने की दिशा में वर्ष 1976-77 में निगम द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1996-97 में आयोजना मद से

10 केन्द्र चलाए गए जिसमें 224 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। वर्ष 1997-98 में 180 प्रशिक्षणार्थियों के राज्य के विरूद्ध जनवरी 98 तक 156 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा 112 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में इस मद में 13.00 लाख का प्रावधान किया गया था जबकि चारू वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 15.00 लाख ही स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध माह जनवरी 98 तक ₹ 21.86 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

वर्ष 1996-97 में केन्द्रीय वृत्त विकास बोर्ड जाधपुर की वित्तीय सहायता से 8 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किये गए जिनमें कुल 165 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुए। इन केन्द्रों पर माह मार्च 97 तक 131 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया।

अनुसूचित जाति विकास महकारी निगम की वित्तीय सहायता से वर्ष 1996-97 में 8 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किए गए जिनमें 240 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया जिनमें 190 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 1997-98 के लिए दोनों ही योजनाओं में किसी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

2 हैण्ड ब्लॉक प्रिंटिंग कार्यक्रम हाथ छपाई उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम द्वारा 10 माह का हाथ छपाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में तीन प्रशिक्षण केन्द्र 25 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाले ग्राम रूपनगढ़ मसूदा एवं श्रीनगर (अजमेर) में चलाए गए।

3 ऊट की खाल पर सुनहरी पेंटिंग ऊट की खाल पर सुनहरी पेंटिंग को कला के विकास हेतु वर्ष 1976 से बीकानेर में एक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में 8 बच्चे प्रशिक्षण हेतु चयन किए गए तथा इस मद हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 1.00 लाख का लगभग पूरा उपयोग का लिया गया है। चारू वित्तीय वर्ष 1997-98 हेतु इस मद में ₹ 100 लाख स्वीकृत किए गए हैं जिसके विरूद्ध माह जनवरी 98 तक ₹ 0.76 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

4 हस्तशिल्पियों को पुरस्कार हस्तशिल्पियों को पुरस्कार व सम्मानित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 1983 से जिला एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से राज्य स्तरीय विजेताओं को दो जाने वाला राशि

₹ 5000.00 व दशता पुरस्कार विजेताओं को ₹ 1000.00 से बढ़ाकर ₹ 3000.00 कर दी गयी है।

वर्ष 1995-96 में 1991-92 व 1992-93 के 17 राज्य स्तरीय व 28 दशता पुरस्कार इस प्रकार कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 1996-97 में 1993-94 के लिए 30 हस्तशिल्पियों का चयन किया गया है। वर्ष 1997-98 में इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 8.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

5 डिजाइन विकास समय के अनुसार प्रत्येक कला को परिवर्तन की आवश्यकता रहती है जिसके अनुरूप ही कला को आगे विकसित कर जन साधारण में प्रचार प्रसार किया जा सकता है। हस्तशिल्प क्षेत्र में डिजाइन विकास तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है एवं इसी लक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए डिजाइन विकास केन्द्र द्वारा पुराने डिजाइनों को नए रंगों एवं तकनीक के साथ मेल कर नए डिजाइनों का विकास किया जा रहा है। केन्द्र पर पसिद्ध रजाईयाँ बन्धेज का कार्य ब्लॉक प्रिंटिंग आदि का उत्पादन के साथ साथ नये प्रिंटिंग डिजाइन भी तैयार किये जाते हैं। हैण्ड ब्लॉक प्रिंटेड सिल्क की रजाईयाँ तैयार की जा रही हैं तथा जयपुर रजाईयों को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में एक सफल प्रयास है। वर्ष 1996-97 में टेरा कोटा एवं पेपरमशी हेतु 20 तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। वर्ष 1997-98 के लिए इस मद में ₹ 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध जनवरी 98 तक ₹ 4.16 लाख व्यय हुआ।

6 हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम हस्तशिल्पियों के समुचित विकास हेतु 1991-92 में हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के नाम से एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम में हस्तशिल्पियों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर कला को संरक्षण प्रदान करना कला के क्षेत्र में नवीनतम जानकारीयों से हस्तशिल्पियों को अवगत करवाना हस्तशिल्पियों को कच्चा माल उपलब्ध करवा कर उन्हें आर्थिक संरक्षण देना एवं उन्हें विपणन सुविधा देने के लिए प्रदर्शनियाँ मेले व हाट बाजारों का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 1996-97 में टेराकोटा एवं चित्रकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का माध्यम से 23 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। इन समस्त सुविधाओं के साथ हस्तशिल्पियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके सीमित ससाधनों की पूर्ति हेतु उन्हें कच्चा माल भी उपलब्ध करवाया जात है। निगम द्वारा वर्ष 1996-97 में हस्तशिल्पियों को छपाई हेतु ₹ 15.46 लाख का मलमल कोटा

डोरिया, ग्रे-क्लाथ आदि का कपड़ा उपलब्ध करवाया गया तथा तैयार माल पुनः उनके उनकी मेहनत की उचित कीमत प्रदान करते हुए प्राप्त किया गया। चालू वर्ष 1997-98 के जनवरी, 98 तक हस्तशिल्पियों को छपाई हेतु रु 6.36 लाख का मलम व कोटा डोरिया आदि कपड़ा उपलब्ध करवाया गया।

हस्तशिल्पियों को सामाजिक सुरक्षा

1 **बुद्धावस्था पेन्शन** - वर्ष 1991-92 में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को बुद्धावस्था पेन्शन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 तक 24 व्यक्तियों को बुद्धावस्था पेन्शन दी गयी। वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम हेतु रु 1.50 लाख की राशि स्वीकृत की गयी, इसके विरुद्ध रु 1.44 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 1997-98 के लिए इस मद में रु 2.00 लाख का प्रावधान किया गया है तथा 26 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित किया गया है।

2 **सामूहिक बीमा योजना** - निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के अतिरिक्त सामूहिक बीमा कार्यक्रम के तहत दस्तकारों को लाभान्वित किया जा रहा है जिससे आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह योजना वर्ष 1991-92 से चलायी जा रही है। इसके तहत वर्ष 1996-97 तक 10687 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। इस हेतु चालू वर्ष में भी रु 2.00 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। इस वर्ष 10683 दस्तकारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 1997-98 के कार्यक्रम

1 **हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स** - जयपुर में हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने हेतु राजस्थानी जयपुर के पीछे स्थित भूमि नगर निगम जयपुर से रु 3.00 करोड़ में क्रय की गयी है। अब तक इस हेतु रु 2.50 करोड़ का भुगतान नगर निगम जयपुर को कर दिया गया है। प्रस्तावित हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार करवाने का कार्य प्रगति पर है।

2 **बुडसिजनिंग प्लान्ट की स्थापना** - बुडन फर्नीचर को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से यह आवश्यकता है कि लकड़ियों की पहले सिजनिंग की जाये अन्यथा यह तो वह क्रेक हो जाती है या सिकुड़ जाती है जिससे फर्नीचर की साख बाजार में कम हो जाती है। इस हेतु जाधपुर में बुड सिजनिंग प्लान्ट व कॉमन फेसिलिटी सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस प्लान्ट

की ऊंची लागत होने के कारण निजी इकाईयाँ इसको स्थापित करने में असमर्थ होती हैं।

उक्त प्लान्ट की स्थापित करने हेतु नेशनल इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है, जिसके अनुसार इस प्लान्ट की स्थापना पर पूँजीगत व्यय रु 85.81 लाख व्यय होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में इस हेतु रु 20.00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है।

3 **भीलवाड़ा व भिवाड़ी में आई सी डी की स्थापना** - जयपुर एवं जोधपुर स्थित आई सी डी की सफलता को देखते हुए वर्ष 1997-98 में भीलवाड़ा व भिवाड़ी में आई सी डी की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु भीलवाड़ा में आई सी डी की स्थापना के लिए निगम द्वारा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा से 25,000 वर्ग गज भूमि क्रय की जा चुकी है। उक्त भूमि पर भवन, रोड, चार दीवारी व अन्य आवश्यक निर्माण हेतु राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम को कार्य आवंटित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है।

आई सी डी भिवाड़ी की स्थापना हेतु भी निगम ने नगर विकास न्यास, अलवर से 15,000 वर्गमीटर भूमि क्रय की जा चुकी है तथा दिनांक 6 नवम्बर, 97 को शिलान्यास कर आवश्यक निर्माण कार्य राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम को आवंटित कर दिया गया है। निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की आशा है।

विशिष्ट गतिविधियाँ

1 निगम ने पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड लाभ कमाया। वर्ष 1995-96 में रु 219.49 लाख का लाभ अर्जित किया था वहीं 1996-97 में यह बढ़कर रु 349.65 लाख हो गया।

2 निगम ने वर्ष 1996-97 के लिए राज्य सरकार को रु 25.72 लाख का लाभान्तर प्रदान किया।

3 सरकार के आर्थिक उदारीकरण व विनियत्रण नीति के फलस्वरूप कच्चे माल के उपार्जन व वितरण में जो ठहराव आ गया था वह वर्ष 1996-97 से पुनः इस गतिविधि को तीव्रता से सम्पादित किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में 14067 मै टन लाहा-इस्पात व 12830 मै टन कोयले का विक्रय किया गया। इस वर्ष अब तक (जनवरी 98 तक) 14237 मै टन लाहा-इस्पात

व 6258 में टन कोयले का विक्रय किया गया।

4 रेल द्वारा कन्टेनर्स का बन्दरगाह तक परिवहन की योजना का कार्य प्रगति पर है।

5 आई सी डी नवाडो व भोलवाडा हेतु कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 1997-98 में ही प्रारम्भ होने की आशा है।

6 जयपुर में अजमेरी गेट स्थित राजस्थली के पीछे की भूमि का अधिग्रहण कर उस पर आधुनिक हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दा गयी है।

7 दिल्ली स्थित राजस्थली एम्पोरियम का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है।

8 देश के महानगरो में राजस्थली प्रदर्शनियों के अतिरिक्त फ्रेन्चाईस स्कीम के माध्यम से हस्तशिल्प वस्तुओं की धिक्की के प्रयास जारी हैं। प्रयोग के रूप में जैसलमेर में इसे प्रारम्भ किया गया है। अन्य प्रमुख नगरो में इस संबंध में प्रस्ताव विचारधीन है।

9 कार्य की सरलता व तीव्र गति लाने की दृष्टि से निगम मुख्यालय व अन्य इकाइयों को कंप्यूटराइजेशन किए जाने का कार्य वर्ष 1997-98 में ही पूर्ण कर लिया जावेगा।

10 इन्टरनेट पर आन लाइन ट्रेडिंग सुविधा निगम ने 2 फरवरी 1998 को इन्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक मॉडिया पर इण्डोबाजार काम से आन लाइन ट्रेडिंग जोन का शुभारम्भ किया है जिसमें भारतीय निर्यातकों से अन्तराष्ट्रीय बाजार में क्रेताओं का भारताय उत्पादों के बारे में विस्तृत सूचना व जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा यही नहीं इन्टरनेट पर ही विचार विमर्श की सुविधा तथा अन्य व्यापारिक जानकारीयों तथा सहायता सुविधाएँ शिपिंग हाटल हवाई यात्रा संबंधी जानकारी भी इस पर उपलब्ध हो सकेगी। भारत में यह सुविधा सर्वप्रथम उपलब्ध कराने का श्रेय निगम को प्राप्त हुआ है।

राजस्थान में आद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले अन्य विभाग/संगठन/निगम

1 उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) राज्य में उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न रियायत व सुविधायें प्रदान करने वाली यह प्रमुख संस्था है। यह लघु उद्योगों नम्र क्षेत्रों हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास व प्रोत्साहन के लिए भी उत्तरदायी है।

2 औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो (Bureau of Industrial Promotion Policy) 1991 से घरेलू विनियोग बहुगुणीय निगमों अप्रवासी भारतीया के विनियोगों को राज्य में आकर्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। यह राज्य की विनियोग प्रोत्साहन एजेंसी बनी जा सकती है। यह सूचना प्रदान करके व्यापार व मेलों में भाग लेकर औद्योगिक संगठनों तथा दूतावासा से सम्पर्क करके अपना लक्ष्य प्राप्त करने को चेष्टा करती है। यह निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए भी उत्तरदायी है।

3 जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centre) जिला स्तर पर केन्द्र संचालित यह जिला उद्योग केन्द्र लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। ये वित्तीय संस्थाओं औद्योगिक विकास में सहाय विभिन्न निगमों/संगठन आदि में समन्वय व सम्पर्क कड़ी का कार्य भी करती है।

4 सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो (Bureau of Public Enterprises) यह ब्यूरो सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा कर सहाय देता है। विभिन्न उपक्रमों की नीतियों में समरूपता लाने का प्रयास करना है। प्रशिक्षण और कल्याणकारी सुविधाओं की व्यवस्था करता है तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सदर्थ में सूचनायें एकत्र कर प्रसारित करता है। मुख्य सचिव इस ब्यूरो का अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में वित्त सचिव उद्योग सचिव राजकीय उपक्रमों के दो अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ होते हैं।

5 राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड (Khadai & Village Industries) 1955 में स्थापित यह बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी व ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहाय है। इस हेतु यह वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

6 राजस्थान हथकरघा विकास निगम (Rajasthan Handloom Development Corporation) 1984 में स्थापित यह निगम विशेषतः मजदूर के कमजोर वर्ग में संबंधित हथकरघा बुनकरों को रोजगार प्रदान करता है। यह बुनकरों को प्रशिक्षण आधुनिकीकरण उत्पादन व विपणन में भी सहायता करता है।

7 क्राफ्ट संस्थान (Institute of Craft) 20 अप्रैल 1995 को स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। संस्था का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के प्रोफेशनल का विकास करना है जो अपनी कुशलता ज्ञान व व्यवहार से क्राफ्टमैन और समाज का इस

क्षेत्र के विकास के माध्यम से लाभ पहुंचायेगा।

8 ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी (Rural Non-Farm Development Agency RUDA) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि सभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने जून, 1995 में ग्रामीण गैर-कृषि विकास क्षेत्र के लिए नई नीति का घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस प्रकार की नीति देश में प्रथम बार बनाई गई। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नवम्बर, 1995 को राज्य सरकार ने RUDA की स्थापना की। इस नीति के अनुसार, चयनित 10 क्षेत्रों के विकास के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करने हेतु RUDA द्वारा विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, प्रशिक्षण व विपणन को व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा।

भारत की औद्योगिक वित्त से संबंधित राष्ट्रीय संस्थाएं

National Institutes for Industrial Development

(1) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) देश के औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति हेतु 30 जून, 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। निगम 25 वर्ष की अवधि तक के निचे ऋण दे सकता है। यह ऋणों की गारंटी भी देता है और अभिगोपन का कार्य भी करता है। निगम का प्रबंध संचालक मण्डल द्वारा किया जा सकता है। निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके द्वारा प्रदत्त सहायता को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

(अ) परियोजना वित्त (ब) वित्तीय सेवा (म) विकासमूलक सेवाएं।

(2) भारतीय औद्योगिक साख व वित्तियोग निगम (ICICI) इसकी स्थापना 1955 ई. में एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य भारतीय औद्योगिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। यह भारतीय एवं विदेशी मुद्राओं में अधिऋण प्रदान करता है, अनेक ऋण-पत्रों का अभिगोपन करता है अशा व ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष रूप से विनियोजन करता है।

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) इस बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अंतर्गत की गई थी। बैंक का प्रमुख कार्य भारतीय उद्योगों को साख उपलब्ध करना और अन्य सेवाएं प्रदान

करना है। यह बैंक वित्तीय कार्यों में सलग विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है। यह देश के बड़े एवं मध्यम उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है और कुटार व लघु उद्योगों को बैंकों तथा राज्य-स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करता है।

(4) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) छोटी-छोटी वचनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1964 का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य छोटी छोटी वचनों को एकत्रित करके उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाना है। ट्रस्ट के द्वारा 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की यूनिट्स बेची जाती हैं। यूनिटों के माध्यम से एकत्रित धन का प्रयोग मुख्यतः देश के औद्योगिक विकास हेतु किया जाता है।

(5) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 के द्वारा जीवन बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। जीवन बीमा निगम देश के नागरिकों के जीवन पर पोलिसिया जारी करके धन एकत्रित करता है। निगम द्वारा इस धन का विनियोग देश के औद्योगिक विकास हेतु किया जाता है। निगम देश के विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत की वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता (करोड़ रुपये में)

संस्था	स्वीकृत सहायता 1990-91 1997-98	वितरित सहायता 1980-81 1997-98
1 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	206.6 10882.6	108.9 5650.1
2 भारतीय औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड	314.1 25532.0	185.3 15806.9
3 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1277.0 84198.5	121.1 15165.3
4 भारतीय औद्योगिक वित्तियोग निगम	19.4 2051.0	76.9 1149.6
5 राज्य विद्युत निगम	370.5 3324.6	248.0 2678.4
6 भारतीय यूनिट ट्रस्ट	40.4 422.91	51.0 3449.7
7 भारतीय जीवन बीमा निगम	70.0 3563.1	65.6 3971.4
8 भारतीय साख निगम	30.3 634.6	44.0 587.9
9 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	742.6	5239.4
10 भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि	370.1	186.3

Source: Economic Survey 1998-99

(6) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना एक वैधानिक निगम के रूप में मार्च 1985 में की गई। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करके उन्हें उत्पादन योग्य बनाना था।

(7) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) इस बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास की सहायक संस्था के रूप में की गई। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास एवं उन्हें सहायता प्रदान करना है। बैंक ने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से प्रारंभ किया। बैंक मुख्यतः राज्य वित्त निगमों, व्यापारिक बैंकों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी प्रदत्त पूंजी पूर्णतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई है।

(8) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (TFCI) इस निगम की स्थापना एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में 1989 में की गई। इस निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं को आर्थिक सहायता एवं समुचित कोषों की व्यवस्था करना है। इसकी प्रदत्त पूंजी देश की वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई है।

(9) राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) राज्य वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अन्तर्गत की गई। यह देश की विभिन्न औद्योगिक वित्त प्रदान करती वित्तीय संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। वर्तमान में 18 राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं जो अर्थात् ऋणों के माध्यम से छोटे व मध्यम उद्यमकर्तृओं को सहायता प्रदान करते हैं। निगम विशिष्ट पूंजी एवं बीज पूंजी की व्यवस्था में सहायता प्रदान करता है।

(10) सामान्य बीमा निगम (GIC) भारत में 1971 में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। केन्द्र सरकार ने 1972 में सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए एक सरकारी कम्पनी की स्थापना की। यह कम्पनी भारतीय सामान्य बीमा निगम के नाम से जाना जाती है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व देश में अनेक देशी एवं विदेशी बीमा कम्पनियाँ थीं जिन्हें वर्तमान में क्रियाशील 4 कम्पनियाँ में सम्मिलित कर लिया गया। (i) नेशनल इश्योरस कम्पनी लिमिटेड (ii) न्यू इंडिया इश्योरस कम्पनी लिमिटेड (iii) आर्यन इश्योरस कम्पनी लिमिटेड (iv) यूनाइटेड इंडिया इश्योरस कम्पनी लिमिटेड। ये चार कम्पनियाँ भारतीय सामान्य बीमा

निगम की सहायक कम्पनियाँ हैं।

(11) केन्द्र व राज्य सरकारें (Centre & State Governments) केन्द्र व राज्य सरकारें औद्योगिक विकास हेतु प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती हैं। सरकारी प्रोत्साहन के कारण राज्य का संतुलित औद्योगिक विकास सम्भव हुआ है। राज्य व केन्द्र सरकारें मुख्यतः ऋण व अनुदान प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती हैं।

अग्र तालिका में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिये स्वीकृत किये गये ऋण व अनुदान को दर्शाया गया है।

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा प्राप्ति प्राप्त उद्योगों की सहायता (हजार रु में)		
	वर्ष 1995-96	
	ऋण	अनुदान
1 खाद्य तेल	333	
2 गुरु खाइमार	130	
3 राय स बना कागज	50	
4 चबल अन्न व दालें (श्री 4 में साफ करना)		
5 चपड़ा	588	
6 अछाछ तेल	700	
7 मिट्टी के बर्तन	1235	21
8 धागे	1109	
9 एल्यूमिनियम के बर्तन		
10 चुन	130	
11 फल संरक्षण		
12 माथिम व जपरगरी (जूनै)	30	
13 पाप मुड़	123	
14 बेंद बास	265	
15 लुगा सबंधी बाय	865	
योग अन्य सहित	6490	177
स्रोत: State of Rajasthan 1996-97		

राज्य व केन्द्र सरकारों द्वारा लघु उद्योगों को भी सहायता प्रदान की जाती है। अग्र तालिका में विगत कुछ वर्षों की वित्तीय सहायता को दर्शाया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्योगों का सहायता (लाख रु में)		
विवरण	1993-94	1995-96
(अ) ऋण		
वित्त उद्योग केन्द्र द्वारा	54.13	
(i) योजनात्मक व्यापार दर ऋण	94.17	25.05
(ii) व्यापार धुक् ऋण	12.91	7.60
(ब) अनुदान		
(i) मानव संसाधन सट		201.87
(ii) केन्द्रीय शिक्षण	387.20	
अनुदान		

(iii) राज्य विनियोग		
अनुदान	97.25	4809.60
जीव उपकरा	5.25	19.10
आई एस आई पाक		
अनुदान	0.15	1.25

Source: Statistical Abstract 1996, Ray

राजस्थान में औद्योगिक वित्त की समस्याएँ व सुझाव

- (1) पूँजी का अभाव राज्य में औद्योगिक वित्त की माँग अधिक है जबकि राज्य की वित्तीय सस्याओं का चुकता पूँजी बहुत कम है। अतः ये सस्याएँ सभी उद्यमियों को माँग को पूर्ण करने में असमर्थ रहती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि विनियोग सस्याओं की पूँजी में आवश्यक वृद्धि की जाये।
- (2) विशेषज्ञों का अभाव राज्य की वित्तीय सस्याओं में तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव है अतः ऋणों का उचित रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। अनेक परियोजनाएँ केवल इसी कारण चालू नहीं हो पाती हैं। अतः राज्य में तकनीकी ज्ञान का विस्तार किया जाना चाहिए तथा इसके लिये समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था की जाना चाहिये।
- (3) परम्परागत उद्योगों को अधिक सहायता राज्य की वित्तीय सस्याओं द्वारा प्राप्त परम्परागत उद्योगों जैसे चानी चकपडा मिलों को ही अधिक ऋण प्रदान किये जाते हैं। अतः आधुनिक उद्योगों को भी पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिये ताकि राज्य में सभी प्रकार के उद्योगों का तेजी से विकास हो सके।
- (4) उदार दृष्टिकोण का अभाव वित्तीय सस्याओं की ऋण नीतियाँ व जमानत आदि के नियम अत्यधिक कठोर हैं

अतः अनेक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः यह आवश्यक है कि ऋण देने में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाये।

(5) लाच का अभाव राज्य की वित्तीय सस्याओं में लोच का अभाव है। अनेक आवश्यक क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इसके लिये यह आवश्यक है कि वित्तीय सस्याओं की नीतियों व कार्यविधि का पुनः निर्धारण किया जाये।

(6) खर्चा प्राप्त सस्याओं का अधिक ऋण राज्य की वित्तीय सस्याओं द्वारा प्राप्त खर्चा प्राप्त व्यक्तियों सस्याओं को अधिक ऋण प्रदान किया जाता है। अतः अन्य उद्यमों सहायता में वित्तित रह जाते हैं। वित्तीय सस्याओं व ऋणों का वितरण समान रूप से करना चाहिए।

(7) पिछड़े जिलों को कम सहायता वित्तीय सस्याओं द्वारा राज्य के पिछड़े जिलों में बहुत कम सहायता वितरित की जाती है जिससे अन्य जिलों की तुलना में वे पिछड़े हुए रहने रहते हैं। अतः सभी जिलों में समान रूप से सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

(8) स्वीकृति की तुलना में कम वितरण राज्य की वित्तीय सस्याओं द्वारा ऋणों की स्वीकृति तो पर्याप्त मात्रा में कर दी जाती है लेकिन ऋणों का वास्तविक वितरण कम होता है। अतः ऋणों की स्वीकृति एवं वितरण में समानता लाई जाना चाहिए।

(9) लालफीतशाही राज्य की वित्तीय सस्याओं में अफसरशाही भाई भ्रान्तावाद घूसखोरो व लालफीतशाह का बोलबाला है अतः ऋणों की शीघ्र स्वीकृति नहीं हो पाती है। इसके लिये प्रशासनिक कुशलता व वृद्धि की जानी चाहिए।

(10) कर्मचारियों में असंतोष राज्य की वित्तीय सस्याओं के कर्मचारियों में असंतोष पाया जाता है अतः इनके कार्यक्षमता कम होता है। कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को समाप्त किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short type Questions)

1. राजको (Rajico) की चार प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
Name four of the outstanding achievements of the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (Rajico)
2. RDC, Rajico व उद्योग विभाग के कार्यालय अब तहसील स्तर पर स्थानान्तरित कर दिये जाने चाहिये। क्यों?
RDC, Rajico and Industries Development Offices Should now be shifted to Tehsil Level. Why?
3. राजस्थान की वित्त विभाग तथा राजस्थान वित्त निगम के अंतर स्पष्ट काजिए।
What is the difference between the Finance Department of Govt. of Rajasthan and Rajasthan Finance Corporation?
4. निम्नलिखित सस्याओं के मुद्दान्तर्गत क्या स्थिति है।
(i) काजिरी (ii) वीर एफ मा

Where are the headquarters of following institutions located -

(i) CAZRI

(ii) R F C

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान के औद्योगिक विकास में आर एफ सी तथा रीको का योगदान समझाईए।
Discuss the role of R F C and RIICO in the Industrial Development in Rajasthan
- 2 राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different financial institutions involved in the Industrial development of Rajasthan
- 3 राका क्या अपने उद्देश्य में सफल रहा है? इस संदर्भ में उसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
Is RIICO successful in its operations? Describe the working performance of RIICO in this context.
- 4 राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Describe in brief the different type of loans granted by Rajasthan Financial Corporation
- 5 राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के कार्यालयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
State briefly the function of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

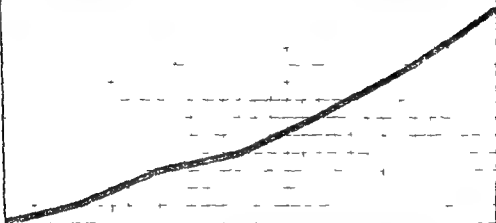
- 1 राजस्थान का औद्योगिक विकास में R F C RIICO एवं RAJSICO की भूमिका की विवेचना करें।
Discuss the role of R F C RIICO and RAJSICO in the industrial development in Rajasthan
- 2 राजस्थान का औद्योगिक विकास में राजस्थान राज्य वित्त निगम तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
Explain the role of Rajasthan State finance Corporation and Rajasthan State Industrial and Investment Corporation in the Industrial Development of Rajasthan
- 3 राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different financial institutions involved in the Industrial Development of Rajasthan



अध्याय - 18

राजस्थान में पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN RAJASTHAN



“पर्यटन विश्व का महत्वपूर्ण उद्योग है।”

अध्याय एक दृष्टि में

- ▶ पर्यटन का महत्व
- ▶ राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति
- ▶ राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास
- ▶ आठवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास
- ▶ नवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास
- ▶ राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ
- ▶ राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएँ व समाधान
- ▶ राजस्थान की पर्यटन नीति
- ▶ राजस्थान पर्यटन विकास निगम
- ▶ राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल
- ▶ अध्यासार्थ प्रश्न

पर्यटन का महत्व

IMPORTANCE OF TOURISM

विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में धीरे-धीरे पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग का रूप लेता जा रहा है। इसका प्रभाव मात्र आर्थिक ही नहीं वरन् सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों पर भी देखा जा सकता है। स्विट्जरलैण्ड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान से भी किसी अन्य अथवा राष्ट्र के विकास की सम्भावना का पता चलता है। राजस्थान में पर्यटन की भूमिका का अध्ययन निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है -

(1) पर्यटकों से आय (Income From Tourists)

राजस्थान अपनी विभिन्नताओं, प्राकृतिक ससाधनों, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों व वन्य जीवों के लिये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे और उत्पत्तियों में भाग लेने भी लोग राजस्थान में आते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख पर्यटक राज्य में आते हैं, उनमें से लगभग 9 प्रतिशत विदेशी पर्यटक होते हैं। एक विदेशी पर्यटक औसतन 800 रुपये और देशी पर्यटक 400 रुपये प्रतिदिन व्यय करते हैं। 1996-97 में 62.87 लाख लोग राजस्थान आये जिनमें से 5.61 लाख विदेशी पर्यटक थे। 1973-74 में केवल 20 लाख पर्यटक ही राज्य में आये

थे।¹ नई दिल्ली के टाटा सलाहकार सेवा के सहयोग से राज्य सरकार ने 2005 तक पर्यटन विकास हेतु 1999-8 करोड़ रुपये का एक मास्टर प्लान भी निर्मित किया है।² मास्टर प्लान के अनुसार 2002 में राजस्थान में 86 लाख पर्यटक आने की संभावना है जिसमें से 11 लाख विदेशी पर्यटक होंगे।³ वर्तमान में राजस्थान में घरेलू व विदेशी पर्यटकों की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 7 व 5 प्रतिशत है।⁴ पर्यटन के महत्व व संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने नवीं योजना (1997-2002) में 303-10 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया है।⁵ राजस्थान के विभिन्न जिलों में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, तटस्थालू, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजपुर, भरतपुर, जैमलमेर, माउंट आबू, पुष्कर, झुझु, बीकानेर, सवाई माधोपुर व अजमेर में आते हैं। अन्य पर्यटक स्थलों पर आनेवाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कम रहा।

(2) व्यापारिक केन्द्रों के रूप में विकास (Development as Trade Centre) राजस्थान में जैसे-जैसे पर्यटन स्थलों का विकास होना जा रहा है वैसे-वैसे उन स्थलों पर व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। धीरे-धीरे ये क्षेत्र आस-पास के क्षेत्रों के आकर्षण का केन्द्र भी बनते जा रहे हैं। इससे इनकी व्यापारिक गतिविधियाँ पुनः बढ़ी हैं। कालान्तर में इन पर्यटन स्थलों के अच्छे व्यापारिक केन्द्रों के रूप में विकसित होने की संभावनाएँ हैं।

(3) निर्यात की संभावनाएँ (Export Possibilities) विदेशों से आने वाले पर्यटक पर्यटन के साथ-साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों में भी जुड़े होते हैं। राजस्थान के उद्योगपति व व्यापारियों को उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिलता है। इस कारण विदेशों में राजस्थान की वस्तुओं की मांग बढ़ने की संभावना से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही अनेक उद्योग विदेशों की नवीनतम तकनीक प्राप्त करने के लिये भी इन पर्यटकों से संपर्क का उपयोग करते हैं।

(4) परिवहन का विकास (Development of Transportation) राजस्थान में लाजपत पटेल प्रतिवर्ष आते हैं। इतने लोगों का परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को कार्य करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में परिवहन व्यवसाय का विकास होता है। राजस्थान में इसी कारण पर्यटन क्षेत्रों में विशेषतः निजी क्षेत्र में परिवहन व्यवसाय नवीनतम रूप में बढ़ रहा है।

(5) रोजगार (Employment) पर्यटन उद्योग के विकास के साथ-साथ राजस्थान में एक-नए क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ बनी हैं। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों व

व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होने, परिवहन सुविधाओं के विस्तार आदि के कारण नये रोजगार के अवसर बनने लगे हैं। पर्यटन उद्योग में नये कर्मचारियों की आवश्यकता के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है।

(6) राज्य के प्रति आकर्षण (Attraction Towards State) पर्यटन के विकास के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है और पूर्व में फैली अनेक प्रविष्टियाँ दूर हुई हैं। इस प्रवृत्ति के कारण राज्य के बाहर के लोग भी अपने व्यवसाय और सगठना की स्थापना राजस्थान में करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इससे राज्य के विकास के अवसर और बढ़ेंगे।

(7) निर्माण कार्योद्घाग सम्पत्ति में अभिवृद्धि (Increase in Assets by Construction Activities) विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार करना होगा। इस हेतु मुख्य रूप से आवास सुविधाएँ जुटानी होंगी और परिवहन के माध्यमों के विकास के लिए सड़क, रेलमार्गों आदि का विकास करना होगा। इस प्रकार के निर्माण कार्यों द्वारा राज्य की सम्पत्ति में भी वृद्धि होगी। ये निर्माण कार्य आस-पास के क्षेत्रों के विकास को भी गति प्रदान करेंगे।

(8) पर्यटन—एक उद्योग (Tourism—An Industry) राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटन को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए 1988-89 के अंत में (मार्च 1989 में) पर्यटन को उद्योग घोषित किया। सरकार का इस निर्णय से पर्यटन के क्षेत्र में सलग सभी इकाइयों व व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा। एक उद्योग के रूप में व्यापक सुविधाएँ जुटाना सम्भव हो सकेगा। इस कारण पर्यटन उद्योग का विकास तेजी से होगा। यह विकास राज्य के अन्य क्षेत्रों पर भी व्यापक अनुकूल प्रभाव डालेगा। ऐसा अनुमान है कि यदि पर्यटन उद्योग का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाये तो राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से प्राप्त हो सकता है।

राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयास

RAJASTHAN GOVERNMENT'S EFFORTS FOR TOURISM DEVELOPMENT

राजस्थान में पर्यटन विभाग मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। प्रथम—पर्यटन स्थलों का विकास नये पर्यटन स्थलों की खोज प्रचार-प्रसार के माध्यम से पर्यटकों को राजस्थान की ओर आकर्षित करना राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में मेलों एवं त्यौहारों के माध्यम से लोकमगी।

और लोककला को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य, पर्यटन कला एवं सस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। द्वितीय-पर्यटकों को आवास एवं परिवहन सुविधाएं उपलब्ध काने का कार्य राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है :

(1) पर्यटन प्रचार-प्रसार साहित्य (Tounism Publicity Literature) राज्य के पर्यटन आकर्षण केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को राज्य की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष आकर्षक एवं रंगीन पर्यटन साहित्य प्रकाशित करता है जिससे पर्यटकों को राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यह साहित्य पर्यटन स्थलों, राज्य के मेला व त्यौहारों, राज्य की लोक एवं हस्तकलाओं तथा वन्य-जीवों के सम्बन्ध में होता है।

(2) विज्ञापन द्वारा प्रचार (Publicity by Advertisements) - पर्यटन साहित्य के अतिरिक्त पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष आकर्षक विज्ञापन देकर लोगों को राज्य की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इन विज्ञापनों में विभिन्न पर्यटक स्थलों, सुविधाओं, पैकेज टूरों आदि की जानकारी दी जाती है। विज्ञापनों के माध्यम से पर्यटकों को विभाग से सम्पर्क काने हेतु भी प्रेरित किया जाता है।

(3) फिल्म प्रदर्शन (Film Show) - पर्यटन विभाग विशेष अवसरों पर तथा विभिन्न होटलों या अन्य स्थानों पर, भाग किये जाने पर अपने द्वारा राज्य के पर्यटन पर बनाई गई फिल्में उपलब्ध काने है। राज्य पर्यटन विभाग ने इस सम्बन्ध मे 24 फिल्मों का निर्माण किया है जो राज्य के पर्यटन स्थलों रीति-रिवाजों, वन्य-जीवों एवं मेले-त्यौहारों आदि से सम्बन्धित हैं।

(4) पर्यटन स्थलों का विकास (Development of Tounst Places) ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं अथवा जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं वहाँ पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधा के लिये आवास एवं परिवहन सुविधाओं के अलावा उस स्थान के पर्यावरण विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देता है। यद्यपि पर्यावरण विकास का कार्य अन्य विभाग भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्य पर्यटन विभाग द्वारा विशेष रूप से किये जाते हैं। राज्य के अविच्छिन्न पर्यटन स्थलों के विकास, उनके सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार ऐतिहासिक स्मृतियों को मरम्मत आदि की योजनाएँ भी

पर्यटन विभाग तैयार करता है।

पर्यटन स्थलों के विकास के अन्तर्गत ये कार्य हाथ में लिये गये-पुष्कर घाटों का विकास, आनासागर, अजमेर हेतु चार सीट एवं दो सीट की एक-एक पैडल नाकाओं का क्रय, जिला कारागार, बून्दी के समीप कुण्ड का विकास, आमेर टाउन का सौन्दर्यीकरण व विद्युतीकरण, केसर क्यारी, अजमेर का विकास, अजमेर दुर्ग की चारदीवारी को मरम्मत, जयपुर एवं आमेर के विभिन्न पर्यटन स्थानों का सौन्दर्यीकरण, भीम मंदिर, जैतारण (पाली) का सुधार, गणेश एवं बालेश्वर (जिला सीकर) का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास एवं सौन्दर्यीकरण, दूधतलाई, उदयपुर का विकास, गुलाब बाग, उदयपुर का विकास, रक्ततलाई बादशाही बाग, चेतक समाधि, चावण्ड, गोगुन्दा व कुम्भलगढ में विकास कार्य। केन्द्र सरकार ने अनेक योजनाओं को स्वीकृत किया, जैसे कैमल सफ़र, गोगुन्दा (जिला उदयपुर) में कैफेटेरिया का निर्माण, बरौली (जिला चित्तौडगढ) में कियोस्क का निर्माण, शालाबाड में एक पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण, ओसिया (जिला जोधपुर) में कैफेटेरिया का निर्माण, मैनाल (जिला चित्तौडगढ) में पर्यटक कॉम्प्लेक्स का निर्माण।

(5) सांस्कृतिक गतिविधियाँ व कार्यक्रम (Cultural Activities & Programmes) - राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से पर्यटकों को राज्य में आकर्षित करने हेतु तथा उन्हें कला एवं सस्कृति का दिग्दर्शन काने के लिये पर्यटन विभाग मेले एवं त्यौहारों का आयोजन करता है। पर्यटन विभाग द्वारा 'राजस्थान आमंत्रित कर रहा है' समारोह का भी आयोजन किया जाता है। पर्यटकों के लिये मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं। इनमें परम्परागत लोकसंगीत एवं लोक नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इन मेलों व त्यौहारों में ख्यातिप्राप्त पत्रकारों, छायाकार, लेखकों एवं यात्रा अभिकर्ताओं को विभागीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इन मेलों व त्यौहारों में जयपुर का गणगीर उत्सव, तीज मेला एवं हाथी समारोह, पुष्कर मेला तथा जैसलमेर का भर मेला काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मेवाड समारोह (उदयपुर) ग्रीष्म समारोह (भाउण्ट आबू), कजरी मेला (बून्दी), मारवाड समारोह (जोधपुर), चन्द्रभागा मेला (शालाबाड), बोकानेर समारोह (बोकानेर), नागीर मेला (नागीर) बेणेश्वर मेला (बेणेश्वर, डूंगरपुर), ब्रज समारोह (भारतपुर) भी धीरे-धीरे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। देश के अन्य प्रदेशों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये 'राजस्थान आमंत्रित कर रहा है' नामक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है।

इस प्रकार पर्यटन आकर्षण के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदर्शनियों के अन्तर्गत राज्य के स्मारक मेले एवं त्यौहार लोककला एवं संस्कृति लोक जीवन एवं रीति रिवाजों से सम्बन्धित चित्र मॉडल आदि का प्रदर्शन किया जाता है।

(6) परिचयात्मक भ्रमण (Introductory Travelling)

राज्य के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन प्रचार प्रसार को अधिक सशक्त बनाने के लिये विभाग देश विदेश के रज्जातिप्राप्त पर्यटन लेखकों छायाकारों दूरदर्शन दल यात्रा अभिकर्ताओं छायातिप्राप्त कलाकारों एवं पर्यटन से सम्बन्धित अन्य लोगों को परिचयार्थक भ्रमण हेतु आमंत्रित करता है तथा इन्हें विभागीय आतिथ्य प्रदान कर अपने व्यय पर राज्य के पर्यटन स्थलों एवं मेले त्यौहारों का भ्रमण करवाता है ताकि इन्हें राज्य के पर्यटन आकर्षण की विस्तृत जानकारी हो सके और इनके लेखों चित्रों एवं प्रपण अनुभवों के माध्यम से राज्य के पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार से अधिकाधिक लोगों को राज्य के बारे में जानकारी मिल सके और इसके माध्यम से अधिकाधिक पर्यटकों राज्य के प्रति आकर्षित हो सकें।

(7) हाथी रोटेशन (Elephant Rotation) जयपुर आने वाला प्रायः प्रत्येक विदेशी पर्यटक आमेर में हाथी की सवारी को आनन्द लेना चाहता है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हाथी रोटेशन की व्यवस्था की गई है। पहले यह व्यवस्था पुणतत्व विभाग द्वारा संचालित की जाती थी किन्तु इसका संचालन पर्यटन विभाग ही कर रहा है। इस कार्य के सम्पादन हेतु आमेर में पर्यटन रचना केन्द्र कार्यरत है जहाँ पर्यटन अधिकारी इस व्यवस्था का संचालन करते हैं।

(8) होटलों का वर्गीकरण व दुकानों का पंजीयन (Classification of Hotels and Registration of Shops) राजस्थान में होटलों को एक व दो सितारा होटलों में वर्गीकृत करने का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इस कार्य के लिये पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय वर्गीकरण समिति बनी हुई है जो इस कार्य को सम्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग से सम्बन्धित दुकानों का पंजीकरण भी पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है ताकि पर्यटकों में इन सहायकों की विश्वसनीयता बनी रहे गये और उन्हें उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।

(9) होटल निर्माण को प्रोत्साहन (Promotion to Hotel Construction) पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में मार्गजनिक क्षेत्र में आवास सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही हैं। इस हेतु निजी क्षेत्र द्वारा होटल निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। परिणामस्वरूप

निजी क्षेत्र में काफी होटलों का निर्माण भी हुआ है। पर्यटन विभाग निजी क्षेत्र में होटल निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें भूमि चयन एवं नक्शों की स्वीकृति आदि में सहयोग देने के अलावा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके लिये विभाग इन्हें अनुपत्ति प्रमाण पत्र देता है।

(10) आवास सुविधाएं (Housing Facilities)

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए आवास सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। 1989-90 में निगम के अधीन 36 इकाइयां कार्यरत थीं। इस वर्ष दो इकाइयां-मिडवे देवगढ़ तथा पर्यटन ग्राम पुष्कर में पर्यटकों के लिए आवास शुरू किए गए। इस वर्ष रतनगढ़ पौकरण सिलीमेड जैसलमेर जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ स्थित पर्यटकों के विश्राम गृहों में नये कमरों के निर्माण करवाए जाने एवं दो नई इकाइयों के प्रारम्भ होने से वर्ष के अन्त में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इकाइयों में कुल क्षमता जो 1988-89 के अन्त में 1861 थी बढ़कर 1989-90 में 1983 तक पहुँच गई।

(11) परिवहन सुविधाएं एवं पैकेज टूर (Transport Facilities and Package Tours)

पर्यटन विभाग इस बात की चेष्टा करता है कि पर्यटकों को सस्ती दर पर आरामदेय परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हों। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पर्यटन विकास निगम न जयपुर उदयपुर मारुण्ड आबू, सरिस्का चित्तौड़गढ़ जैसलमेर जोधपुर व सर्वाई माधोपुर में दूरयावलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन जयपुर में पृथक से एक यातायात इकाई संचालित की जा रही है। दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा भी परिवहन व्यवस्था संचालित की जाती है। पर्यटन मौसम (अक्टूबर से मार्च) के दौरान दिल्ली से विभिन्न पैकेज टूर प्रारम्भ किए जाते हैं। निगम द्वारा जयपुर दिल्ली जोधपुर एवं उदयपुर से अवकाश यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा संचालित निम्न पैकेज टूर काफी लोकप्रिय हो गए हैं

दिल्ली से संचालित

गोल्डन ट्राईएंगल (3 दिवसीय)

हवापहल टूर (3 दिवसीय)

मेवाड़ पैकेज टूर (6 दिवसीय)

डेजर्ट पैकेज टूर (6 दिवसीय)

राजस्थान पैकेज टूर (15 दिवसीय)

यन्त्र जीव अभयारण्य टूर (4 दिवसीय)

उदयपुर से संचालित .

उदयपुर माऊट आबू-उदयपुर

उदयपुर हल्दीघाटी-कुम्भलगढ-रणकपुर-उदयपुर

(12) पर्यटक सूचना केन्द्र (Tourists Information Centre) राजस्थान और राजस्थान से बाहर पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने में कठिनाई न हो। वर्तमान में राज्य के बाहर आगरा, अहमदाबाद, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में ये पर्यटक सूचना केन्द्र स्थित हैं। राजस्थान में ये जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माऊंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा-बूंदी, सर्वाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, आमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा और झुझुनू में कार्यरत हैं।

(13) हाऊस बोट (House Boat) - राजस्थान की झीलों में कर्मियों का भाति हाऊस बोट को सुविधा उपलब्ध करने की चेष्टा की जायेगी। यह हाऊस बोट राजस्थान को अपनी शैली और शिल्प से तैयार कराये जायेंगे। झीलों में हाऊस बोट पर्यटकों के लिये अच्छे व आरामदायक सिद्ध होने की संभावना है। झीलों में ही 'वाटर-स्पोर्ट्स' की गतिविधियाँ आरम्भ करने की चेष्टा की जा रही है।

(14) स्वागत केन्द्र (Reception Centre) - राजस्थान में पर्यटक स्वागत केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करने की योजना है। इन पर्यटक स्वागत केन्द्रों की स्थापना के पीछे मुख्य अवधारणा यह है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जायें, जैसे पर्यटन स्थलों की जानकारी, होटलों का आरक्षण यात्रा के लिये आरक्षण, टूरिस्ट टैक्स गाइड, विदेशी मुद्रा आदि। इन केन्द्रों पर आरक्षण की व्यवस्था कम्प्यूटर से की गयी है और टेलीक्स फैक्स, एस टी डी, आई एस डी आदि की सुविधाएँ भी इन केन्द्रों पर उपलब्ध रहनी। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली सहित राजस्थान के 9 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। दिल्ली के बीकानेर हाऊस के अतिरिक्त जयपुर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, माऊंट आबू, कोटा, चित्तौड़गढ़ व जैसलमेर में यह केन्द्र खोले जा रहे हैं।

(15) पेईंग गैस्ट योजना (Paying Guest Project) - पर्यटक स्थानीय लोगों की जीवन शैली एवं उनके जीवनस्तर के बारे में जानने हेतु उत्साह रखते हैं। साथ ही, कुछ पर्यटक घरेलू वातावरण में रहना पसन्द करते हैं। इन उद्देश्यों को पूर्ण हेतु राजस्थान में पेईंग गैस्ट योजना जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में प्रारंभ की गई है। अब यह योजना

अजमेर, पुष्कर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर एवं भरतपुर में भी आरम्भ की गई है। राजस्थान की पेईंग गैस्ट योजना को भारत सरकार ने भी सहायता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पेईंग गैस्ट निर्देशिका को पूरे देश के पर्यटन कार्यालयों और विदेशों में स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों में भिजवाया गया है।

(16) निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन (Incentives to Private Entrepreneur) - राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के किलों, हवेलियों आदि को, जो पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र रहे हैं, होटलों में परिवर्तित करने हेतु एक नई श्रेणी 'हेरिटेज होटल' का नाम दिया गया है। इससे इन किलों, दुर्गों एवं हवेलियों का रख-रखाव होने के साथ-साथ राज्य की धरोहर को सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके लिये निजी उद्यमियों को इनमें निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(17) हॉर्स सफारी (Horse Safari) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त पुष्कर मेला हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहां के लोकजीवन की जीवंत-जागती झांकी पर्यटकों को मोह लेती है। प्रतिवर्ष कार्तिक में हजारों लाहों की सख्या में दूर-दूर से लोग पवित्र सरोवर में स्नान करने हेतु आते हैं। पुष्कर मेले के इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के मनोरंजन एवं आकर्षण हेतु घुड़सवारी (हॉर्स सफारी) आयोजित की जाती है। 17 दिन एवं 6 रात्रियों की यह घुड़सवारी प्रतिदिन औसतन 35 कि.मी. सफर तय करती है।

(18) शाही रेलगाड़ी (Royal Train-Shahi Rail) - पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये शाही रेलगाड़ी का भी संचालन किया जाता है। पर्यटन विकास निगम की ओर से चलायी जा रही शाही रेल 'पैलेस ऑन व्हील' ने विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की है। लन्दन से प्रकाशित समाचार पत्र सण्डे टाइम्स ने पैलेस ऑन व्हील को समार की 10 सर्वश्रेष्ठ रेलगाड़ियों में से एक माना है।

(19) कैनाल बोटिंग (Canal Boating) - राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य के 5 जलाशयों-जमवा रामगढ़, आमेर, फतेहसागर, जयसमंद व सिलिसेड-में पर्यटकों के मनोरंजन के लिये नौकायन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। मरुस्थली क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर में कैनाल बोटिंग को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके अंतर्गत छोटी नहरों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है जिससे राजस्थान नहर के किनारे को नुकसान न हो।

(20) डैजर्ट ट्राइएंगिल या मरु त्रिकोण (Desert Triangle) राजस्थान में पर्यटकों के लिए मरु त्रिकोण विशेष आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। इस त्रिकोण के अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के पर्यटन स्थलों को सम्मिलित किया गया है। जैसलमेर में फरवरी महीने में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मरु मेले में बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। विश्व पर्यटन संगठन के सलाहकार रॉड हेगिल्टन के अनुसार मरु त्रिकोण की पर्यटन योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पर्यटन विकास की वृहद् सभावनाएँ विद्यमान हैं। राजस्थान सरकार ने मरु त्रिकोण योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भिजवाई है। केन्द्र सरकार ने इस योजना को विश्व पर्यटन संगठन को भेजा है। बीकानेर डैजर्ट ट्राइएंगिल योजना का प्रवेशद्वार होगा। ओ.ई.सी.एफ. की सहायता से मरु त्रिकोण परियोजना 1996-97 में क्रियान्वित करना प्रस्तावित था।

(21) राजस्थान पर्यटन कानून (Rajasthan Tourism Regulation of Travel Trade Act) राजस्थान ट्यूरिज्म एक्ट के प्रारूप को राज्य के विधि विभाग द्वारा निर्मित कर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के पास भिजवा दिया गया है। वहा से पारित होने के बाद गृह व विधि विभागों से पारित होकर 6 माह के भीतर इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस अधिनियम का पूरा नाम राजस्थान ट्यूरिज्म रेग्यूलेशन ऑफ ट्रेवल ट्रेड एक्ट है। इसके प्रभाव में आने से देशी व विदेशी पर्यटकों के मध्यस्था के चगुल में फसन का डर समाप्त हो जायेगा। नियमों को तोड़ने वाले ट्रेवल एजेंट्स टैक्सी चालक, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर कानून के प्रावधानों के अंतर्गत अकुश्रत लगेगा। इससे राजस्थान पर्यटन व्यवसाय में युद्ध के साथ साथ गुणवत्ता भी आयेगी।

(22) भूमि बैंक (Land Bank) पर्यटन इकाइयों/परियोजनाओं के संचालन में विकास हेतु एक भूमि बैंक की स्थापना की गई है जो नवीय योजना में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) को 450 लाख रुपये का ऋण प्रदान करेगा।

(23) खाद्य कला संस्थान (Food Craft Industry) पर्यटन में खाद्य कला में प्रशिक्षित व्यक्तियों की भाग निरन्तर बढ़ने के कारण अजमेर और जोधपुर में दो नये खाद्य कला संस्थान आरम्भ किये गये हैं। उदयपुर और जयपुर में इस प्रकार के संस्थान आरम्भ किये गये हैं। बीकानेर और माउन्ट आबू में एक एक होटल खोलने का प्रस्ताव है। पर्यटन प्रबन्ध हेतु जाधपुर में एक केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

इन कार्यों के लिये नवीय पंचवर्षीय योजना में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(24) जयपुर हवाई अड्डे का विकास जयपुर हवाई अड्डे का विकास एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में किया गया है। इस हवाई अड्डे के रन वे (Runway) का विस्तार 7000 फीट से बढ़ाकर 9000 फीट किया जायेगा।

राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं एवं समाधान

MAJOR PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TOURISM INDUSTRY IN RAJASTHAN

राजस्थान में पर्यटन उद्योग अभी परिपक्व अवस्था में नहीं आ पाया है। यह विकास के प्रारम्भिक चरणों में है। इस कारण इस उद्योग को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

(1) अपर्याप्त प्रचार-प्रसार (Lack of Sufficient Publicity) पर्यटन स्थलों की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए उन क्षेत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इस ओर अनेक प्रयास किए हैं किन्तु फिर भी पूरे देश में राजस्थान के सम्बन्ध में बहुत अधिक उत्सुकता पैदा नहीं की जा सकी है। विदेशों में तो अधिकांश लोगों को राजस्थान के सदर्भ में जानकारी ही नहीं है। राजस्थान का पर्यटन विभाग को पर्याप्त वित्तीय साधन और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(2) नये पर्यटन स्थलों का विकास (Development of New Tourist Places) राजस्थान के गौरवमयी इतिहास और प्राकृतिक भिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए सारा जाये तो यहाँ पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकतानुसार इस बात की है कि विभाग को इन स्थलों के सदर्भ में पूर्ण जानकारी जुटानी होगी तथा ऐसे स्थल जिन पर देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है उन पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष बल देना होगा। नये पर्यटन स्थलों के विकास के लिये पुनर्तत्त्व विभाग को तथा इस क्षेत्र में शोधकार्य कर रहे लोगों की सहायता सी जानी चाहिये। विभाग को स्वयं ही व्यापक सर्वेक्षण कर इन स्थानों का पता लगाना चाहिये।

(3) पर्यटन स्थलों की देख रेख व विकास कार्य (Maintenance & Development of Tourist

Places) पर्यटकों को प्रेरित करने के लिये यह भी आवश्यक है कि पर्यटन स्थल आकर्षक लगे। इस हेतु उनको पर्याप्त देखभाल किया जाना आवश्यक है। ऐसे स्थलों पर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए विकास कार्य भी करने होंगे। नये पर्यटन स्थलों के सर्दर्भ में जहाँ देख रेख की सुविधाओं का अभाव है तथा अधिक विकास कार्य भी नहीं हो पाए हैं वहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(4) भोजन व आवास सुविधाओं का अभाव (Lack of Lodging & Boarding Facilities) राजस्थान में सभी पर्यटन स्थलों पर भोजन व आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है। आवास सुविधाएँ प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। निजी उद्यमी भी अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं। अतः विभिन्न सुविधाएँ प्रदान कर निजी क्षेत्र को आवास सुविधाओं के विस्तार के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए। विदेशी पर्यटकों को उनकी इच्छा के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने के लिये भी निजी उद्यमियों को प्रेरित किया जाना चाहिये।

(5) अपर्याप्त परिवहन सुविधाएँ (Lack of Sufficient Transport Facilities) राजस्थान में पर्यटन के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा वायु परिवहन के विकास का न होना भी है। विदेशी पर्यटक समय अभाव के कारण उन क्षेत्रों में नहीं जा पाते जहाँ उन्हें परिवहन के साधनों के कारण अधिक समय लगता हो। इस स्थिति को सुधारने के लिये राज्य के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों की वायुसेवाओं तथा अन्य उपयुक्त तीर्थगमों पर परिवहन सुविधाओं से युक्त किया जाना चाहिए। इस हेतु सड़क मार्गों का निर्माण भी किया जा सकता है।

(6) आकर्षक पैकेज टूर का अभाव (Lack of Attractive Package Tours) राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पैकेज टूर का संचालन मुख्य रूप से दिल्ली से किया जाता है। ये पैकेज टूर राज्य के सभी जिलों से आरम्भ किये जाने चाहिए साथ ही ये पैकेज टूर इस प्रकार के हाने चाहिए ताकि वे राजस्थान के निवासियों को भी आकर्षक प्रतीत हों। ऐसा तभी सम्भव है जबकि एक उपयुक्त अवधि में राज्य के लगभग सभी प्रमुख व गौण पर्यटन स्थलों को इस पैकेज टूर में सम्मिलित किया जाए।

(7) अधिक लागत (High Cost) वित्तीय बाधाओं के कारण भी पर्यटन के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रदान की जाने वाली आवास व भोजन सुविधाओं की लागतें इतनी कम होनी चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति भी पर्यटन पर जाने की सौच सके। पर्यटन विभाग द्वारा पैकेज टूरों की ओर लोगों को आकर्षित करने

के लिए भा अपनी लागतों को कम करना होगा। ये पैकेज टूर विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थिति के लोगों को दृष्टिगत रखते हुए भी बनाए जा सकते हैं।

(8) पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र का कम योगदान (Low Contribution of Private Sector) पर्यटन उद्योग पर मुख्यतः सरकार प्रभुत्व ही प्रतीत होता है। निजी उद्यमी अनेक कारणों से पूरे तरह इस क्षेत्र में नहीं आ पाये हैं। सास्थान में पर्यटन में उद्योग घोषित कर दिए जाने के पश्चात् इस क्षेत्र को मिलने वाला सुविधाओं से प्रेरित होकर निजी क्षेत्र के उद्यमी अब इस व्यवसाय की ओर आने लगे हैं। लेकिन उनका योगदान अभी भी अपर्याप्त है। निजी क्षेत्र को उन योजनाओं का भी हाथ में लेना चाहिए जिनमें अधिक पूँजी विनियोजन आवश्यक है।

(9) भूमि का व्यवस्थापन (Arrangement of Land) पर्यटन क्षेत्रों में होटल व अन्य पर्यटन सुविधाएँ जुटाने के लिए भूमि मिलना कठिन हो गया है। नगर पालिकाओं व स्थानीय निकायों के कारण भी भूमि के विकास में अनेक बाधाएँ आती हैं। सरकार को इस समस्या के हल के लिए पर्यटन स्थलों व सम्भावित पर्यटन स्थलों में इन सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि उस क्षेत्र के मास्टर प्लान में पहले से ही निर्धारित कर देनी चाहिए व इस क्षेत्र में आने वाले उद्यमियों को कम लागत पर विकसित भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(10) वित्तीय सहायता (Financial Assistance) वित्तीय समस्याओं द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋण अन्य उद्योगों की भाँति ही हैं। इस सर्दर्भ में विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं। उद्यमियों में ली जाने वाली मार्जिन रशि भी अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र में आने वाले उद्यमियों के लिए वित्तीय समस्याओं की अज्ञापूर्व में भागीदारी भी निश्चित का जानी चाहिये ताकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण पर्यटन का विकास नहीं रहे। पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए अनुदान व सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है और कम व्याजदर पर पूँजी उपलब्ध कराई जा सकती है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि को लम्बा किया जा सकता है।

(11) विपणन की व्यवस्था (Marketing Arrangements) बाहर से आने वाले पर्यटक स्थानाय वस्तुओं को खरीदने में प्रायः रुचि रखते हैं किन्तु उनको अच्छे बिक्री केन्द्रों का ज्ञान नहीं होता अथवा अच्छे बिक्री केन्द्र उपलब्ध ही नहीं होते। ऐसी स्थिति में सरकार का यह दायित्व है कि वह पर्यटकों की रुचि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे वस्तुओं को जुटाए और उचित माध्यम से उचित मूल्य पर पर्यटकों को उपलब्ध कराए। समुचित विपणन व्यवस्था

होने पर पर्यटक सतुष्ट रहते हैं व पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना रहती है।

राजस्थान की पर्यटन नीति¹

TOURISM POLICY OF RAJASTHAN

'पर्यटन' आधुनिक विश्व में तेजी से बढ़ता उद्योग है। विश्व के पर्यटकों की कुल संख्या लगभग 520 बिलियन प्रतिवर्ष है जो लगभग 321 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। विश्व का प्रत्येक नया व्यक्ति पात्र एव पर्यटन में व्यस्त है। इस उद्योग से विश्व के लगभग 112 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। भारत सरकार ने मई 1992 में पर्यटन नीति की घोषणा की थी। इस नीति में निर्धारित किया गया कि सन् 2000 तक भारत विश्व पर्यटन में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि कर लेगा। पर्यटन उद्योग विदेशी विनिमय प्राप्ति का प्रमुख साधन है। 1994-95 में पर्यटन उद्योग से भारत को लगभग 7400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इस शताब्दी के अन्त तक पर्यटन उद्योग 10 000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत में भी पर्यटन की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। यहाँ प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या लगभग 63 मिलियन है।

पर्यटन नीति के उद्देश्य

राजस्थान की पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों का अनुकूलतम उपयोग करना।
- (2) रोजगार के अवसरो में वृद्धि करने के लिए राज्य के पर्यटन उद्योग का विकास करना।
- (3) दस्तकारी एव कुटीर उद्योग के लिए एक विकसित बाजार का विकास करना।
- (4) राजस्थान की प्राकृतिक ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना।
- (5) निजी क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन उद्योग का विकास करना।
- (6) धार्मिक पर्यटन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना।
- (7) पर्यटक को सतुष्ट करना।
- (8) पर्यटन उद्योग को 'जनसाधारण का उद्योग' का रूप देना।
- (9) पर्यटन उद्योग की समस्याओं को समाप्त करना।

(10) पर्यटन उत्पादों में विविधता लाना।

पर्यटन नीति की विशेषताएँ

(1) पर्यटन संरचना—राजस्थान भारत का दूसरा बड़ा राज्य है और यहाँ पर्यटन उद्योग के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु आवास, यातायात सुविधाएँ, संचार के साधन तथा अन्य सुविधाओं का होना आवश्यक है। अतः राज्य में सरचनात्मक विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार और विदेशी स्रोतों से वित्तीय साधन प्राप्त किए जायेंगे। राज्य में पर्यटन उद्योग के लिए सरचनात्मक विकास हेतु सरकार ने एक 'मास्टर प्लान' तैयार किया है। सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त प्रशासनिक तन्त्र का विकास किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटकों के आवास की समस्या है। राज्य के 772 होटलों में लगभग 15,280 कमरे हैं। राज्य के पर्यटन विभाग ने 20 000 कमरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। शताब्दी के अन्त तक लगभग 45 000 कमरों की आवश्यकता होगी। सरकार होटल उद्योग के विकास हेतु निजी विनियोग को प्रोत्साहन देगी। राज्य के महलो एवं हवेलियों को होटल का रूप देने के लिए भारतीय पर्यटन विस निगम 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकारें होटल उद्योग के विकास हेतु सस्मिडी, करों में कमी आदि सुविधाएँ प्रदान करती हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए कैम्पो की व्यवस्था की जाती है। राज्य के पर्यटन विभाग ने 27 सितम्बर, 1991 से "पेयिंग गैस्ट स्कीम" (Paying Guest Scheme) चालू की है। यह योजना राज्य के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, अजमेर, पुष्कर, माउण्ट आबू, अलवर तथा भरतपुर में प्रारम्भ की गई है। राज्य में रास्ते की सुविधाएँ (Mid way Hotels) कम हैं अतः इनमें वृद्धि की जाएगी। सरकारी स्वामित्व वाले प्राचीन म्थारकों, हवेलियों आदि को पर्यटन होटल अथवा पर्यटन कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जाएगा। होटलों के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा उचित दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) पर्यटन संरचना में विनियोग—राजस्थान में होटल उद्योग के विकास हेतु संस्थागत वित्त प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। होटलों के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक 'प्रभावी तन्त्र' (Effective Mechanism) विकसित

¹ Tourism Policy of Rajasthan Deptt. of Tourism, Art & Culture, Rajasthan

किया जाएगा। अनेक सरकारी इमारतों का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। इन इमारतों का होटल के रूप में उपयोग संयुक्त उपक्रमों (सरकार एवं निजी क्षेत्र) के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है। सरकार ने 1993 में नवीन पर्यटन इकाइयों के लिए अनेक सुविधाओं एवं रियायतों की घोषणा की थी। सरकार ने इस उद्योग के विकास हेतु समय-समय पर अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करने का निश्चय किया। राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग के विकास हेतु 1993-94 में 6 करोड़ रुपये तथा 1994-95 में 12 करोड़ रुपये व्यय किए थे। वर्ष 1995-96 में 15 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त पर्यटन उद्योग की संरचना में सुधार हेतु केन्द्र सरकार से भी सहायता प्राप्त की जाती है।

(3) पर्यटन परिवहन-राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण नगर रेल परिवहन से जुड़े हुए हैं। 'शताब्दी' और अन्य रेलों के माध्यम से जयपुर, जोधपुर और अजमेर नगरे को दिल्ली से जोड़ दिया गया है। बड़ी लाइन पर "Palace on Wheels" 1995 में चालू की गई। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य से गुजरने वाले राजमार्गों का सुधार किया जाएगा तथा तिक रोड बनाने हेतु बाह्य सहायता प्राप्त की जाएगी। अच्छे मार्ग बनाने की वर्तमान व्यवस्था को चालू रखा जाएगा। उत्तम किस्म की बसों की प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा मार्गों के राष्ट्रीयकरण की नीति का अनुसरण किया जाएगा। घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों से समुचित किराया वसूल किया जाएगा। स्थानीय परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा ताकि पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सके। एयर टैक्सी और हेलीकॉप्टर सेवाओं की प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि कम से कम समय में पर्यटक अधिक पर्यटन स्थलों में भ्रमण कर सकें। राज्य के अनेक स्थानों पर हेलीपैड और हवाई पट्टियाँ विद्यमान हैं। इनका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। राज्य में हवाई अड्डों के निर्माण हेतु निम्न क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए अनेक रियायतों की घोषणा की गई है।

(4) पर्यटन सूचना एवं प्रचार-पर्यटन उद्योग के विकास में सूचना एवं प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए राज्य के सभी प्रवेश बिन्दुओं पर पर्यटक स्वागत केन्द्रों का होना आवश्यक है। जोधपुर और बीकानेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा राज्य के जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झुझु, माऊण्ड आबू, सर्वाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर में पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा

है। पर्यटकों के आगमन काल में दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और माऊण्ड आबू के पर्यटक स्वागत केन्द्र 24 घण्टे सेवाएँ प्रदान करेंगे। साहित्य, फिल्म, वीडियो तथा अन्य साधनों के माध्यम से पर्यटन उद्योग का प्रचार किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन पर जवाहर कला केन्द्र द्वारा एक फिल्म बनाई जाएगी। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार माध्यमों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। पर्यटन साहित्य फ्रेन्च, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, इटैलियन, ओरिजिक तथा अंग्रेजी भाषाओं में सभी पर्यटन स्वागत केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रकाशन विभाग के प्रकाशन 'अतिथि' को अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जाएगा।

(5) राजस्थान के पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा-राजस्थान में दस्तकारी, हैंडलूम तथा विभिन्न कारीगरों द्वारा अनेक प्रकार की आकर्षक और सुन्दर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इन वस्तुओं के विपणन को प्रभावशाली बनाने के प्रयास किए जाएंगे। कारीगरों को अपनी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए बाजार में स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पर्यटन केन्द्रों पर विभिन्न सभ्यताओं के महयोग से शिल्पग्राम बनाने के प्रयास किए जाएंगे। एक दस्तकारी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। किलों, महलों तथा प्राचीन इमारतों को सुधार जाएगा और निजी क्षेत्र के सहयोग से इनमें होटल बनाए जाएंगे। राजस्थान के मेले और उत्सव पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। पुष्कर मेला और रेगिस्तानी उत्सव, जोधपुर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अतः राज्य के विभिन्न मेलों एवं उत्सवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। जिलाधीशों को ऐसे मेलों एवं उत्सवों की व्यवस्था हेतु विशेष धनराशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान में सरिस्का, घना और रणथम्भौर जैसे स्थानों को नियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा तथा वन्य जीव स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। राजस्थान के रेगिस्तानी फ्लोरा (वनस्पति) और घना (जीव-जन्तु) पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। अतः राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में पर्यटक म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे। कुशल एवं प्रतिष्ठित गाड़ों की सख्या में वृद्धि की जाएगी। घरेलू पर्यटकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बगाली और गुजराती पर्यटकों में राजस्थान अत्यधिक लोकप्रिय है। अतः पर्यटन साहित्य बगाली एवं गुजराती भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर खेल कूद, घुड़सवारी, ऊट सवारी, तैराकी, चोटिंग आदि की

व्यवस्था की जाएगी। चम्पल और इन्दिरा गांधी नहर में जल परिचहन की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन स्थलों की पहचान बनाए रखने एवं उनको सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे। राज्य में पर्यटन का विकास करने हेतु राज्य सरकार पड़ोसी राज्य में भी सहयोग प्राप्त करेगी। पर्यटन स्थलों पर सायकल मनोरंजन की व्यवस्था भी की जाएगी। पर्यटन सम्बन्धी सहायकारी सेवाओं में सुधार तथा विस्तार किया जाएगा।

(6) पर्यटन में सहायक सेवाओं का विकास करना—पर्यटन में मनुष्यीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस क्षेत्र में वृद्धिमान एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भारत में होटल प्रबन्ध की 18 संस्थाएँ और भोजन व्यवस्था सम्बन्धी 16 संस्थाएँ कार्यरत हैं जिनमें से केवल दो संस्थाएँ (Institute of Hotel Management Jaipur Food Crafts Institute Udaipur) ही राज्य में हैं। अतः सरकार निजी क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं की स्थापना का प्रयास कर रही है। World Tourism Organisation (W.T.O.) के सहयोग से उदयपुर में होटल प्रबन्ध की एक संस्था स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। राज्य में फैला जोधपुर विश्वविद्यालय पर्यटन एवं होटल प्रबन्ध में डिप्लोमा प्रदान करता है। सरकार ने पर्यटन विभाग के निदेशकों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो राज्य में पर्यटन शिक्षा के विस्तार पर सुझाव देगी। आमेर और जैसलमेर में एक पृथक पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गई है। अन्य स्थलों पर भी पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। जल, गैस और विद्युत की आवश्यकताओं में पर्यटन इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। होटलों में शराब की व्यवस्था हेतु आयकारी नीति को सरल बनाया गया है। पर्यटन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में पर्यटन त्रिप भी पढ़ाया जाएगा।

(7) प्रशासनिक सहयोग—प्रशासनिक सहयोग के उद्देश्य से राज्य पर्यटन मन्त्रालय बोर्ड की स्थापना की गई है। मुख्यमन्त्री इसके अध्यक्ष हैं। राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास हेतु एक अधिकृत समिति (Empowered Committee) का गठन किया गया है। प्रत्येक डिविजनल कमिश्नर के अधीन ऐसी समिति का गठन किया गया है जो पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। प्रत्येक जिलाधीश की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली समिति कार्य करती है।

(8) पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटना—पर्यटन विभाग द्वारा मारुट आनू, पुष्कर, जैसलमेर तथा आमेर जैसे स्थलों की पर्यटन क्षमता की विशेष जाँच की जाएगी। इन

क्षेत्रों में पर्यटन ट्रैफिक को नियमित किया जाएगा तथा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उद्योग के अनियन्त्रित विकास के कारण इन स्थानों पर सांस्कृतिक प्रदूषण न बढ़ पाए।

राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति

PRESENT POSITION OF TOURISM IN RAJASTHAN

इस शताब्दी के अंत तक अनुमान है कि राजस्थान में हर वर्ष लगभग एक करोड़ पर्यटक आने लगेगे। एक अध्ययन के अनुसार राज्य में आने वाला एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन 800 रुपये तथा भारतीय पर्यटक औसतन 400 रुपये व्यय करता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सन् 2000 तक हर वर्ष राजस्थान में आने वाले एक करोड़ पर्यटक अनुमानित प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय करेंगे। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने की संभावना है। आज विश्व में तेल उद्योग के पश्चात् पर्यटन दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व का हर सोलहवा व्यक्ति किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा हुआ है। भारत को 1992-93 में पर्यटन से लगभग 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई जो इस शताब्दी के अंत तक 10 000 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। वर्तमान में विश्व पर्यटन बाजार के अन्तर्गत भारत का भाग केवल 0.9% है। राजस्थान में पर्यटन के भारी विकास में दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन के आधारभूत ढांचे तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान इस्टीमेट ऑफ ट्रेवल मैनेजमेन्ट की स्थापना की है और इसके तहत 1993-94 में 5 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई। पर्यटन से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु राजस्थान पर्यटन अधिनियम में परिवर्तन भी किया जा रहा है। राजस्थान में पर्यटन से जुड़े राजस्थान पर्यटन विकास निगम का वार्षिक व्ययसाय बढ़ा है और इसने लाभ अर्जित किया। राजस्थान की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए राजस्थान पर्यटन विकास का यह दृष्टसंभावनाएँ विद्यमान हैं।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम RAJASTHAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD

1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को आवास, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से की गई। निगम राजस्थान में पर्यटन को

विकसित करने के उद्देश्य से योजनाएँ निमित्त करता है व उन्हें प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की चेष्टा करता है। निगम द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु निगम द्वारा टूरिस्ट बगले, होटल, युवा होस्टल आदि चलाये जाते हैं। सड़कों के किनारे यह मिडवे आदि की व्यवस्था भी करता है। पर्यटन स्थलों मे भ्रमण के लिए यह परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराता है तथा पैकेज टूर भी आयोजित करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नौकायन सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शाही रेलगाड़ी का मचालन भी यह भारतीय रेलवे से मिलकर करता है। पर्यटकों के मनोरंजन व उनके लिये वस्तुओं के क्रय की व्यवस्था करता है। पर्यटन स्थलों को सुन्दर बनाए रखने के लिए उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार-सामग्री प्रकाशित कर उसे वितरित करता है।

आठवीं योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN EIGHTH PLAN . 1992-97

राजस्थान अपनी भूमि एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं, ऐतिहासिक गौरव एवं दुर्लभ वन्य-पशुओं के कारण पर्यटन के विरह मानचित्र में अपना स्थान बनाता जा रहा है। राजस्थान सरकार ने पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। साथ ही पर्यटन को उद्योगों का दर्जा भी प्रदान कर दिया है। राजस्थान में पर्यटन की विशाल संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान की आठवीं योजना के अंतर्गत 38.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस योजना में पर्यटन के बढ़ते हुए भार को दृष्टिगत रखते हुए सम्मान्य मुख्यालयों पर पर्यटक सूचना ब्यूरो को सुदृढ़ किया गया। बीकानेर जैसलमेर, जोधपुर व उदयपुर में स्थित पर्यटक सूचना ब्यूरो को भी और सुदृढ़ किया गया। आठवीं योजना के अंतर्गत पर्यटकों को अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राजसमन्द तथा जोधपुर के रेतवे स्टेजनों और जयपुर के हवाई अड्डे पर नये पर्यटक कार्यालय खोले गये। राजस्थान का पर्यटन विभाग ने आठवीं योजना - अर्न्तगत मेंलों एवं उत्सवों में भाग लेकर राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहित किया। राजस्थान में पर्यटकों की रुचि का दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन स्थलों के विकास के लिये 'सर्किट एप्रोच' अपनाई गई। राज्य को निम्नलिखित 9 पर्यटक सर्किटों में बाँटा गया .

राजस्थान के पर्यटक सर्किट	
पर्यटक सर्किट	जिले/पर्यटक स्थल
1 शोखावाटी सर्किट	सीकर, झुझरू व चूरू
2 हाडीनी सर्किट	बूंदी, कोटा झालावाड
3 मेरगड सर्किट	हल्दीवाडी, गारुणा, चावण्ड, कुम्भलगड एवं समीर के क्षेत्र
4 रेगिस्तानी सर्किट	जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर
5 अमवर, भरतपुर, धौनपुर सर्किट	अलवर, भरतपुर, धौलपुर
6 जयपुर टोंक, सवाई-माधोपुर सर्किट	जयपुर टोंक, सवाईमाधोपुर
7 मारुण्ड आबू सर्किट	मारुण्ड आबू
8 जयपुर, अजमेर सर्किट	जयपुर, अजमेर
9 जयपुर जैसलमेर, बीकानेर सर्किट	जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Raj.

राजस्थान के पर्यटन स्थलों में 'मार्तंडकोण' (जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर) विशेष आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन योजनाओं के लिए स्वाकृति प्राप्त होने की संभावना थी। ये विभिन्न योजनाये मेवाड सर्किट, शोखावाटी सर्किट, अलवर, भरतपुर सर्किट जयपुर-टोंक सवाईमाधोपुर सर्किट जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर सर्किट, मारुण्ड आबू सर्किट तथा जयपुर-अजमेर सर्किट से सम्बन्धित हैं। आठवीं योजना में भी एक करोड़ रुपये की अंशपूर्वी से राजस्थान होटल निगम बनाने की योजना थी जो कि होटल आनन्द भवन, उदयपुर का पर्यटकों की भाग के अनुरूप विस्तार करेगा।

नवीं योजना (1997-2002)के अंतर्गत पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN NINTH PLAN 1997-2002

पर्यटन विभाग नई दिल्ली की डाटा सलाहकार सेवा के माध्यम से एक मास्टर प्लान 2005 की अवधि तक का निर्मित किया है। मास्टर प्लान के अनुसार अन्य में पर्यटन के प्रस्ताविन विनियोग 1991.8 करोड़ रुपये का है। प्लान के अनुमार नवीं योजना के अंत तक राज्य में 86 लाख पर्यटक आँवेंगे जिनमें 11 लाख विदेशी पर्यटक होंगे। नवीं योजना (1997-2002) में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु 303 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाएं

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान का इतिहास अत्यन्त शास्वमयी है। इस इतिहास से जुड़े हुए राजस्थान के ऐतिहासिक किले, विद्यमान प्राचीन हवेलियों एवं मंदिरों के वास्तुशिल्प, राजस्थान के इतिहास से सम्बन्धित शौर्य एवं वीरता की गाथाओं के केन्द्र, कला एवं संस्कृति की उच्च परम्पराएँ राजस्थान के रंग-बिरंगे मेले व त्यौहार तथा राजस्थान की हस्त तथा लोककलाएँ, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस अथाह सम्पदा का पूरा लाभ उठाने में ही राजस्थान के पर्यटन विकास या पर्यटन का भविष्य छिपा हुआ है। राजस्थान में एक बड़ा भू-भाग परम्परागत क्षेत्र है तो एक ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ अपना आकर्षण समेटे हुए हैं। राजस्थान में प्राकृतिक संरचना की विविधता भी पर्यटन के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पशु एवं पक्षियों की अथाह सम्पदा और विविधताओं के कारण भी राज्य में पर्यटन की विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। राजस्थान का इतिहास उमकी संस्कृति एवं कला, विदेशी पर्यटकों को निरन्तर आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में पर्यटन विकास की विपुल सम्भावनाओं का प्रयोग करने के लिए पर्यटकों को पर्याप्त आवास एवं यातायात सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इस हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र को भी सामने आना होगा। इसके साथ ही ऐसे पर्यटन स्थल जो अब तक देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए अज्ञात रहे हैं, उन्हें उपयुक्त प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से लोगों के समक्ष लाना होगा। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने से भी राजस्थान में पर्यटन की सम्भावनाओं को बल मिला है।

भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों का आकर्षित करने के लिए राजस्थान भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र बनना जा रहा है। राज्य में अगले पांच वर्षों में पर्यटन विकास हेतु 1700 करोड़ रुपये के विनियोजन की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में पर्यटन विकास का मूल ढाँचा तैयार करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा राज्य के सभी बड़े पर्यटक स्थलों सहित सात बड़े पर्यटन केन्द्रों का विकास करना आदि हैं। इन सभी पर्यटन केन्द्रों का विकास जयपुर आगरा और दिल्ली के 'त्रिभुज पर्यटन त्रिकोण' के समान हो होगा।

निष्कर्ष रूप में, वर्तमान परिस्थितियों का दृष्टिगत

रखते हुए राजस्थान में सांस्कृतिक पर्यटन, सभा या सम्मेलन पर्यटन, खेलकूद से सम्बन्धित पर्यटन तथा वन्य-जीव पर्यटन की वृहद् संभावनाएँ विद्यमान हैं। सांस्कृतिक पर्यटन के विकास की तो यह अथाह सम्भावनाएँ विद्यमान हैं क्योंकि राजस्थान ऐतिहासिक वास्तुशिल्प, कला एवं संस्कृति की उच्च परम्पराओं के लिए विख्यात है। इस अथाह सम्पदा को उजागर करके देशी व विदेशी पर्यटकों को राजस्थान में आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आजकल अच्छे स्थानों पर सभा व सम्मेलन करने की परम्परा-सी आरम्भ हो गयी है। इस प्रवृत्ति का लाभ उठाया जा सकता है। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि को इन सभा व सम्मेलन पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। राजस्थान में खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यों से सम्बन्धित पर्यटन के विकास की भी अच्छी संभावनाएँ विद्यमान हैं। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग अरावली पर्वत-श्रृंखला से जुड़ा है। इस क्षेत्र में पर्वतारोहण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। राजस्थान का एक बड़ा भू-भाग रेगिस्तान है। इसके किसी क्षेत्र को मर्यादा के लिए विकसित किया जा सकता है। हाथी व कैंट आदि की सवारी भी इन सांस्कृतिक अभियानों में सम्मिलित की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हूण्ड ग्लाइडिंग आदि के विकास की संभावनाओं का भी पता लगाया जाना चाहिए। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के वन्य-जीव उपलब्ध हैं। अतः इन क्षेत्रों में वन्य-जीव पर्यटन विकास की संभावनाएँ हैं। संक्षेप में, राजस्थान में विद्यमान विभिन्न अध्यापण्य इस दृष्टि से उपयुक्त कहे जा सकते हैं। अतः राजस्थान में विद्यमान पर्यटन विकास की संभावनाओं का विवेकपूर्ण करने की आवश्यकता है।

राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थल IMPORTANT TOURIST CENTRES OF RAJASTHAN

जयपुर-आमेर (Jaipur-Amer) • जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है। यह एक नियोजित नगर है। यह नगर कथियों शिल्पियों तथा अपने गौरवमयी इतिहास के कारण सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सी वी रमण ने इसे 'आयलैण्ड ऑफ ग्लोरी' की सज़ा प्रदान की है। यहां के पर्यटन स्थलों में हथामहल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, गलता का पवित्र कुण्ड, नाहरगढ़ का विशाल दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग, आमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय, बिरला मंदिर, सागानेर के प्राचीन जैन मंदिर, सिसोदिया रानी का महल आदि प्रमुख हैं। ये

पर्यटन स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि नगर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सदैव भीड़ दृष्टिगोचर होती है।

अजमेरा-पुष्कर (Ajmer-Pushkar) अजमेरा शहर को हिन्दू-मुस्लिम तीर्थों का संगम कहा जा सकता है। यह शहर राज्य की राजधानी से 135 किलोमीटर दूर है। यह आबली पर्वत की घाटी में स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर का हिन्दू तीर्थस्थान, तारागढ़ का किला, ढाई दिन का झोंपड़ा, आनामगर झील, सोनोजी की चसिया आदि प्रमुख हैं। पुष्कर में कांतिक पूर्णिमा पर एब अजमेरा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगने वाले मेले देशी व विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन मेलों में अत्यधिक सख्या में व्यक्ति भाग लेते हैं।

जोधपुर (Jodhpur) - यह शहर राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित है। जोधपुर का निर्माण 1469 में राव जोधाजी ने करवाया था। यह नगर अपने गौरवपूर्ण इतिहास, भव्य महलों की वास्तुकला के कारण प्रसिद्ध है। यहां जसवत मेमोरियल उम्मेद भवन महल, मण्डौर के उद्यान, जसवत घड़ा, बालसमंद झील जैन मंदिर हरिहर के मंदिर तथा सूर्य मंदिर आदि पर्यटन स्थल हैं। यहां के पर्यटन स्थल वास्तुकला व शिल्पकला, दोनों ही दृष्टियों से प्रसिद्ध हैं।

उदयपुर (Udaipur) इस शहर की स्थापना 1589 में मेवाड़ के महाराज उदयसिंह द्वारा की गई थी। यह नगर झीलों की नगरी पर्यटकों का स्वर्ण, प्राकृतिक सौन्दर्य का प्रतीक झीलों का जादू, वेनिस ऑफ द ईस्ट और राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से जाना जाता है। यह नगर पिछोला झील के किनारे बसा हुआ है। यहां के पर्यटन स्थलों में लेक पैलेस, पिछोला झील, फतहसागर झील, लेक गार्डन पैलेस उदयपुर का मिठी पैलेस, सहेलिया की बाड़ी, जगदीशजी का मंदिर महाराजा प्रतापका स्मारक, गुलाबबाग, मार्गनगरा नेहरू पार्क, सुजान निवास आदि प्रमुख हैं। उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर बनास नदी पर श्रान्धजी का मंदिर एकालगजी का मंदिर प्रसिद्ध हैं। उदयपुर व नाथद्वार के मध्य अनेक मंदिर हैं। नाथद्वार से 11 किमी दूर रणपुर का जैन मंदिर, इन्दोघटी और वेतक घोड़े की समाधि है। कुम्भलगढ़ का किला भी दर्शनीय स्थल है।

बीकानेर (Bikaner) बीकानेर शहर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहां एक विशाल दुर्ग है जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। आधुनिक बीकानेर की स्थापना महाराजा गंगासिंह द्वारा की गई।

उन्होंने गगनहर का भी निर्माण करवाया। यहां के दर्शनीय स्थलों में बीकानेर का किला, प्राचीन महल, मंदिर, मस्जिद, शम्भुगृह चन्द्रमहल, शूर महल, कर्ण महल, शीश महल, छनर महल, तालगढ़, करणीमाना का मंदिर, कोलायन तालाब तथा कपिलमुनि का आश्रम प्रमुख हैं।

अलवर (Alwar) - अलवर शहर की स्थापना 1775 में राव प्रतापसिंह द्वारा की गई। यह शहर दिल्ली के दक्षिण में तथा जयपुर के उत्तर-पूर्व में पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यहां के पर्यटन स्थलों में विजयसागर झील, निजुम्हमहल, सलीमसागर, मयुराधीश का मंदिर, सुरजमहल, सुरजकुण्ड, अलवर का विशाल किला, महाराज की छतरी तथा विनयविलास महल में स्थित अजायबघर आदि प्रमुख हैं। पिलोसेड झील, सरिस्का अभयारण्य, पाण्डुपौल, राजा भुनहरी का समाधि स्थल तथा नीलकण्ठ महादेव भी दर्शनीय स्थल हैं।

भारतपुर (Bharatpur) - यह नगर राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित है। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। यहां का किला मिट्टी से बना हुआ है। यहां के पर्यटन स्थलों में, घना पक्षी विहार प्रमुख है। भारतपुर से 35 किलोमीटर दूर डींग शहर है। डींग मुख्यतः उद्यानों, महलों, ऐतिहासिक दुर्ग व रणनी फव्वारे के लिये प्रसिद्ध है। भारतपुर के दक्षिण में बयाना भी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है।

बूंदी (Bundi) इस शहर की स्थापना राव देव द्वारा की गई। यहां का महल एक पहाड़ी पर स्थित है। यह महल अपनी सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है। यह शहर प्रसिद्ध कवि सूरजमल की जन्मस्थली है। यहां के दर्शनीय स्थलों में दीवाने-आम, छत्र महल, नवलसागर, फूलसागर, सुखमहल तथा चौपसी स्तम्भों की छतरी आदि प्रमुख हैं।

माऊण्ट आबू (Mount Abu) यह नगर अबली बृखला की लगभग 1200 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित है। यह राज्य का एकमात्र 'हिल स्टेशन' है। इसे राजस्थान का शिमला कहा जा सकता है। यहां के दर्शनीय स्थलों में नन्की झील, दिनवाड़ा के जैन मंदिर, बुलरक टॉडरॉक, ननरॉक कैम्प, सनसेट पॉइंट, गौपुछ, हर्नामून पॉइंट तथा अचलगढ़ के जैन मंदिर आदि प्रमुख हैं।

चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) : यह एक ऐतिहासिक नगर है। यह राजपूतों के शौर्य और मोरा को भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहां एक विशाल दुर्ग है जो भारत के विभिन्न किलों में अत्यधिक प्राचीन एवं भव्य है। यहां के दर्शनीय स्थलों में कौर्ति स्तम्भ, विजय स्तम्भ, महाराज पद्मिनी का जलमहल, महाराजा कुम्भा के महल, जौहर

कुण्ड गौ मुख नौखड़ा खजाना तोपखाना काली का मंदिर बनवीर की दीवार भीमताल भीरा मंदिर तथा जैन मंदिर प्रमुख हैं।

जैसलमेर (Jaisalmer) यह नगर राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1156 में जैसलसिंह द्वारा की गई। यहां का किला पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। यह किला 85 मीटर ऊँची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यहां के पर्यटन स्थलों में

भोतोगहल विलासगहल, रंगगहल षटुओ की हवेली, राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख हैं।

कोटा (Kota) यह नगर चम्बल नदी के किनारे पर स्थित है। यह राज्य का प्रमुख औद्योगिक नगर है। पर्यटन स्थलों में छतर निवास बाग मंदिर आधारशिला अमर निवास भित्तिरिया कुण्ड छत्र निवास बाग चम्बल गार्डन आदि प्रमुख हैं। कोटा से लगभग 80 किलोमीटर दूर दश गेम्स सैन्युरी है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

1. शॉर्ट नोट्स लिखिए (i) पैलेस ऑन व्हील्स (ii) लो-कोस्ट होटल तथा घरेलू पर्यटन
Write short notes on (i) Palace on Wheels (ii) Low Cost Hotels and Domestic Tourism
2. पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन का भविष्य उज्ज्वल है। समझाईए।
Tourism in Western Rajasthan has a bright future. Explain.
3. निम्नलिखित के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसलमेर एक पर्यटन स्थल।
What do you know about the following? Jaisalmer as a tourist place.
4. निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखिए।
राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल।
Write explanatory notes on important tourist places in Rajasthan.

B निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

1. राजस्थान में पर्यटन विकास पर एक निव्या लिखिए।
Write an essay on the Development of tourism in Rajasthan.
2. राज में अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका, सम्भावनाएँ व समस्याएँ का वर्णन कीजिए।
Discuss the role, prospects and problems of Tourism Industry in the economy of the State.
3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग के महत्व को बतलाईए। इस उद्योग के विकास की भारी सम्भावनाएँ एवं समस्याएँ क्या हैं?
Discuss the importance of Tourism Industry in the economy of Rajasthan. What are the prospects and problems of this industry?
4. राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? विवेचना कीजिए।
Rajasthan has immense potentials for tourism development. Do you agree or not? Analyse.

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

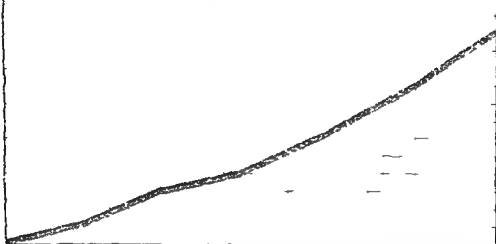
(Questions of University Examinations)

1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग के महत्व को बतलाईए। इस उद्योग के विकास की भारी सम्भावनाएँ एवं समस्याएँ क्या हैं?
Discuss the importance of Tourism Industry in the economy of Rajasthan. What are the prospects and problems of this industry?
2. राजस्थान में पर्यटन उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Tourism Industry in Rajasthan.
3. राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका, सम्भावनाएँ व समस्याएँ का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित में इस उद्योग के विकास के लिए सुझाव भी दीजिए।
Describe the Tourism development under plan in Rajasthan.
4. राजस्थान में पर्यटन उद्योग में पर्यटन विकास का स्थापना।
Describe the Tourism development under plan in Rajasthan.
5. राज में पर्यटन के विकास में राज में पर्यटन के विकास की भारी सम्भावनाएँ हैं। इन सम्भावनाओं के विकास के लिए उपाय सुझा दीजिए।
Mention the problems of tourism in Rajasthan and also make suggestions for its development in near future.

अध्याय - 19

विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम

SPECIAL AREA PROGRAMMES



“क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से ही सम्भव है।”

अध्याय एक दृष्टि में

- मन्त्रि श्रम विभाग कार्यक्रम IRDP
- मूल सम्पत्ति क्षेत्र कार्यक्रम DPAP
- मूल विकास कार्यक्रम DDP
- जनशक्ति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम TADP
- अरावली विकास कार्यक्रम ADP
- अन्य कार्यक्रम
- सम्पन्न

स राज्यस्थान में निर्धनता उन्मूलन योजना के अन्तर्गत में वृद्धि व विकास के उद्देश्य से संचालित प्रमुख कार्यक्रम अग्रानुसार हैं

- (1) सम्पत्ति ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
- (2) ग्रामीण युवाओं को स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षण (TRYSEM)
- (3) ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA)
- (4) जवाहर रोजगार योजना (JRY)
- (5) जनशक्ति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (TADP)
- (6) मूल विकास कार्यक्रम (DDP)
- (7) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)
- (8) अन्वेषण योजना
- (9) बास सूची कार्यक्रम
- (10) अरावली विकास कार्यक्रम (Aravalli Development Programme)
- (11) मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना (Mewar Regional Development Project)
- (12) कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Command Area Development Programme)
- (13) न्यूनतम विकास कार्यक्रम (Minimum Needs Programme)

- (14) महिला विकास कार्यक्रम (Women Development Programme)
 (15) दम्पत्युत्त क्षेत्रों में खेराड सुधार कार्यक्रम (Decolt Prone Revine Improvement Programme)
 (16) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(I R D P)

INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978-79 में देश के चुने हुए 2300 विकास खण्डों में आरम्भ किया गया था। वर्तमान में इसको सम्पूर्ण भारत में विस्तृत कर दिया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है ताकि वे परिवार बेरोजगारी एवं निर्धनता के अभिशाप से मुक्त हो सकें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार की योजना है जिसमें केन्द्र एवं राज्य दोनों आधी आधी धनराशि प्रदान करते हैं।

उद्देश्य

Objects

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उपनिर्णित परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत उन्हें आय प्रदान करने वाली परिसम्पत्तियाँ जुटाने का अवसर दिया जाता है। जिसमें कार्यशील पूँजी भी सम्मिलित है। वयनित परिवारों को एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सस्यागत ऋण अथवा अनुदान के रूप में होती है।

मुख्य अवधारणाएँ

Main Concepts

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अन्तर्गत अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः कार्यक्रम को स्पष्ट समझने के लिए इससे सम्बन्धित शब्दावली को भी समझना होगा।

गरीबी की रेखा (Poverty Line) गरीबी की रेखा को परिवार की वार्षिक आय के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 11060

रुपये या इससे कम है उसे गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक चयनित परिवार को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह 11060 रुपये वार्षिक आय के स्तर तक पहुँच जाए। इसमें भी सबसे पहले कम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है। जब ऐसे परिवारों को सहायता दी जा चुकी होती है और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए सफल चेष्टा हो चुकी होती है तो उसके पश्चात् उससे अधिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है।

लक्ष्य समूह (Aimed Group) इस कार्यक्रम का लक्ष्य लघु कृषक सीमा कृषक कृषि श्रमिकों ग्रामीण करीबी एवं अन्य व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। लघु कृषक से आशय उस कृषक से है जिसके सम्पत्ति के बेटेयर उससे कम भूमि है। यदि किसान के पास प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि है तो यह सीमा एक हैक्टियर या उससे कम होती है। जहाँ पर भूमि सिंचित हो किन्तु वह प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि न हो तो राज्य सरकार यह सीमा निर्धारित करती है लेकिन यह दो हैक्टियर से अधिक नहीं हो सकती। कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमा कृषक उस व्यक्ति को माना गया है जिसके पास एक हैक्टियर या उससे कम भूमि हो। जिस कृषक के पास प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि है वही सीमा कृषक की भूमि सीमा अलग से निर्धारित की जाती है। कृषि श्रमिकों से आशय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों से है जिनके पास कोई भूमि नहीं है और जो अपनी आय का 50 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि मजदूरी से कृषि श्रमिक के रूप में प्राप्त कर रहे हो।

विशेष लक्ष्य समूह (Specially Aimed Group) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति महिलाओं आदि पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कहा गया है कि अधिकतर गरीबी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समूहों में विद्यमान है। अतः यह निर्धारित किया गया है कि सहायता प्राप्त परिवारों में से कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति और जनजाति से हों। यह न्यूनतम प्रतिशत किसी जिले अथवा राज्य में औसत रूप से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएँ होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अपने परिवारों को मुखिया हैं।

भौतिक लक्ष्य (Physical Targets) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य 1995 तक गरीबी रेखा के नीचे रह रहे ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का प्रतिशत 10

प्रतिष्ठित तक लाना है। भारत में गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे लोगों के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। इस कारण सातवीं योजना में गरीबी के आधार पर परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इस सन्दर्भ में अधिक गरीब राज्यों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सख्या में वृद्धि के कारण कार्यक्रम की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया Process of Implementation of Programme

आय के समूह के आधार पर चयनित परिवारों को एक सूची विकास खण्ड अथवा ग्रामीण स्तर पर बनाई जाती है। यह सूची विकास खण्ड अधिकारों द्वारा बुलाई गई ग्राम सभा में रखी जाती है। इस ग्राम सभा में स्थानीय प्रतिनिधि, गैर सरकारी व्यक्ति, विकास अधिकारी एवं बैंक अधिकारी उपस्थित होते हैं। यदि कोई स्वीकृत सक्रिय समूह हो तो उसे भी इस बैठक में बुलाया जाता है। ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। यदि किसी नाम पर कोई विवाद होता है तो इस विवाद को ग्रामीण विकास अधिकरण का परियोजना अधिकारी विकास खण्ड अधिकारी से विचार-विमर्श कर निर्णय लेता है। ग्रामसभा का उपयोग इस हेतु भी किया जाता है जिससे लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता का स्वरूप भी लाभार्थी की प्राथमिकता, उसकी इच्छा और योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जा सके। अन्य बातों को समान रखते हुए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनको भू-समा से अधिक अधिग्रहण की हुई भूमि आवंटित की गई हो, साथ ही मुक्त कपड़ा एवं बन्धुआ मजदूर और आर्थिक क्रियाओं को करने योग्य विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा महिला लाभार्थियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

योजना का चयन

Selection of Scheme

चयनित परिवार को, उस परिवार की मानसिकता, आवश्यकता और स्थानीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए योजना प्रदान की जाती है। इसमें, परिवार में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान अथवा प्राप्त किए जा सकने वाले तकनीकी ज्ञान तथा जिस आर्थिक योजना व क्रिया को हाथ में लिया जा रहा है, उसको स्थापना के पूर्व एवं पश्चात् की सुविधाओं एवं स्थितियों को भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी सम्पत्ति परिवार को एक इकाई मानते हुए प्रदान की जाती है। इसका

आशय यह है कि परिवार के एक से अधिक सदस्यों का सहायता दी जा सकती है लेकिन इसमें यह देखना पड़ता है कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्या यह आवश्यक और अनिवार्य है। जहाँ तक अनुदान को अधिकतम सीमा का प्रश्न है, यह परिवार पर एक इकाई की भांति तय की जाती है। इसी प्रकार आय के अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए चयनित परिवारों को एक या एक से अधिक योजनाएँ या आर्थिक क्रियाएँ प्रदान की जा सकती हैं। यदि गरीबी की रेखा से उस परिवार को ऊपर लाने का लक्ष्य एक से अधिक योजनाओं से पूरा होता है तो कम लागत की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके।

कार्यक्रम की मुख्य आर्थिक क्रियाएँ व योजनाएँ

Main Economic Activities & Schemes of the Programme

सम्पन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र से सम्बंधित कोई भी आर्थिक क्रिया हाथ में ली जा सकती है जो आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त हो और जिसमें पूँजी-उत्पाद अनुपात अनुकूल हो। कृषि क्षेत्र पर जो अत्यधिक भार आ गया है, उसे दृष्टिगत रखते हुए इस बात के प्रयास किए जाते हैं कि चुनी हुई आर्थिक क्रियाएँ कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त उद्योगों, सेवाओं व व्यावसायिक क्रियाओं की ओर विवेकित हों किन्तु ऐसा करने से पूर्व स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। योजना का चयन करते समय उपलब्ध संसाधनों का ध्यान रखा जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक क्रिया के लिए जो आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए सहायता दी जाती है वह इस क्षेत्र में बहुत थोड़े से विद्यमान अन्तर को पाटने के लिए होती है न कि पूरा का पूरा आधारभूत ढांचा निर्मित करने के लिए होती है। दम कारण यदि किसी आर्थिक क्रिया के संबंध में आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी आर्थिक क्रिया को हाथ में नहीं लिया जाता है। आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए समूह की क्रियाओं की नीति को प्राथमिकता दी जाती है। समूह की क्रियाओं की सफलता के अधिक अवसर होते हैं क्योंकि समूह के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ जुटाना अधिक सरल होता है। साथ ही समूह को सौदेबाजी करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। सम्पन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक सूची प्रदान की गई है जो कि लाभार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है। इस सूची में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र से सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं की

दर्शाया गया है

प्राथमिक क्षेत्र की सूची (List of Primary Sector) इस क्षेत्र के अंतर्गत जिन क्रियाओं का उल्लेख किया गया है उनमें बीज उत्पादन एवं विपणन फल नर्सरी व उत्पादन बागवानी एवं फूलों की रोनी खुम्बों का उत्पादन मत्स्य पालन गहलियों के बीज का उत्पादन शहद उत्पादन जड़ी बूटियों की रोती मुरगी पालन सूअर पालन भेड़ व बकरी पालन कृषि सिंचाई योजनाएँ आदि प्रमुख हैं।

द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) इस क्षेत्र के अंतर्गत जो गतिविधियाँ आती हैं उनमें निम्न प्रमुख हैं माचिस का निर्माण पटाखों आदि का निर्माण अणुबिजली का निर्माण अखण्ड पदार्थों और साबुन उद्योग चमड़े से सज्जित उद्योग तैल घण्टी उद्योग हाथ से बने कागज से सम्बन्धित उद्योग गुड़ और छाण्डमारा निर्माण छात्रागृह और नालों का विधायन फलों एवं मत्स्यजों का विधायन एवं संरक्षण बेकरी हैण्डलूम हस्तकला खादी जूट के सामान रेशम की तुनाई चूना उद्योग एल्यूमीनियम के वर्तन का निर्माण नकदों और लोहे से बने घरेलू सामान बास से सम्बन्धित उद्योग आदि।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) इस क्षेत्र में कृषि पशुपालन आदि से सम्बन्धित सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे कृषि के अंतर्गत बीज उत्पादन और जल व कीटनाशकों की पूर्ति कृषि उपकरणों की पूर्ति एवं मरम्मत कुआँ की खुदाई और ट्यूबवेल खोदना जल प्रपंच एवं कृषिगत उत्पादनों का संग्रहण भण्डारण एवं विपणन आदि। इसी प्रकार पशु सम्पदा के लिए चारा एवं बाटे की पूर्ति उन्नत नस्ल के पशुओं की पूर्ति रेशम के कोठों के अडों की पूर्ति रेशम से सम्बन्धित उत्पाद का संग्रहण भण्डारण और विपणन। दूध एवं दूध के सामान की बिक्री अण्डे मांस चमड़े हड्डियों आदि का संग्रहण भण्डारण और विपणन ग्रामीण उद्योगों में प्रमुख आर्थिक क्रियाएँ निम्न से सम्बन्धित हो सकती हैं - ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक आदारा की पूर्ति उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संग्रहण भण्डारण एवं विपणन इनमें संबंधित रखरखाव एवं मरम्मत के कार्य घरेलू उपकरणों की मरम्मत और रक्षा रखवा जैसे टीवी रेडियो घड़ियाँ बिजली के उपकरण सार्वजनिक वाहन स्टोव सिलाई मशीन आदि। बायो गैस संयंत्रों की स्थापना मरम्मत व रक्षा रखवा बायो गैस संयंत्रों के लिए गोबर एवं अन्य कच्चा माल एकत्रित करना आदि। इसी प्रकार निर्माण कार्यों के अंतर्गत भवनों का निर्माण मरम्मत और रख रखाव यातायात के अंतर्गत पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहन सार्वजनिक रिक्षा हाथ के ठेके आँटो रिक्षा राहमति के आधार पर मेटाडोर टेम्पो आदि

वाहन ट्राईविंग का कार्य आदि। फुटकर व्यापार के अंतर्गत कोई भी फुटकर व्यापार जिसकी वार्षिक बिक्री 50 000 रुपये से अधिक न हो कोई भी लघु व्यवसाय जिसमें 10 000 रुपये से अधिक का निवेश न हो राशन की दुकान आदि बैंकिंग एवं बीमा के क्षेत्र में बैंक के कनेक्शन एजेंट जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा के प्रमोशन एजेंट आदि। अन्य के अंतर्गत चलता फिरता पुस्तकालय लाउंड्री स्पीकर किराए पर देना गैस बत्ती उपलब्ध करना आदि कार्य सम्मिलित हैं। उपरोक्त सूची केवल मार्गदर्शन के लिए है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कार्य हाथ में लिए जा सकते हैं।

कार्यक्रम का नियोजन एवं परियोजना का निर्माण

Programme Planning & Project Preparation

उपरोक्त नियोजन से स्पष्ट है कि कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर उसे पूरा करने तक अनेक कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है। इस कारण स्थानीय संसाधनों के विनियोजन एवं नियोजन के लिए गहन कार्य किया जाता है। जिरा, एवं विकास खण्ड स्तर पर दो तरह की योजनाएँ बनाई जाती हैं ताकि कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सम्भव हो सके। प्रथम योजना मार्गदर्शक योजना होती है एवं द्वितीय योजना वार्षिक योजना कहलाती है। मार्गदर्शक योजना स्थानीय संसाधनों से परिचित कराती है। इसके आधार पर वार्षिक कार्य हाथ में लिए जाते हैं।

मार्गदर्शक योजना (Pilot Projects) सर्वप्रथम विचार खण्ड स्तर पर यह योजना बनाई जाती है और इसके पश्चात् इसे समन्वित करके जिला योजना का निर्माण होता है। मार्गदर्शक योजना में स्थानीय संसाधनों का लेखा जोखा होता है जिससे विशेष रूप से जनसंख्या का प्रवृत्ति या संसाधनों का क्षेत्र एवं स्थिति इस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं की आर्थिक क्रियाएँ क्षेत्र में उपलब्ध सामाजिक और संस्थागत ढांचे का उल्लेख होता है। इसमें योजना और गैर योजना मदों में चल रही योजनाओं व कार्यक्रमों का भी उल्लेख होता है। साथ ही आगामी पांच वर्षों में विकास विभाग द्वारा हाथ में ली जाने वाली सम्भावित क्रियाओं की भी परीक्षा होती है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार उत्पन्न करने वाले अग्रसरों का विशेष उल्लेख होता है। इस मार्गदर्शक योजना को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा समीक्षा व स्वीकृत कर अपनाया जाता है।

वार्षिक योजना (Annual Plan) मार्गदर्शक योजना के पश्चात् वार्षिक योजना अपनाई जाती है। यह वार्षिक योजना संसाधनों की स्थिति और लाभार्थियों की

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाती है। वार्षिक योजना में विकास खण्ड च जिले में अपनाए जाने वाले क्षेत्रों का आर्थिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार लाभार्थी परिवारों का उनकी आवश्यकताओं व मानसिकताओं आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और उनके लिए चयनित योजनाओं का उल्लेख होता है। इसमें यह भी उल्लेख किया जाता है कि अन्य विभागों के साथ कैसे व किस सीमा तक समन्वय किया जायेगा। साथ ही कच्चे माल प्राप्त करने के स्रोत एवं तरीके तथा निर्मित माल के विपणन सम्बन्धी जानकारी भी होती है। इस वार्षिक योजना में प्रस्तावित गतिविधियों के लाभार्थी परिवारों की आय पर तथा क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी समीक्षा की जाती है। वार्षिक योजना में माडल प्रोजेक्ट का भी उल्लेख होता है, साथ ही निर्धारित वर्ष में किन लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है उसको भी एक सूची दी जाती है। खण्डोंय जिला स्तर पर बनाई गई वार्षिक योजना को जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा मंजूर किया जाता है तथाकथित हो इसका क्रियान्वयन आरम्भ होता है। स्वीकृत की गई जिला योजना को राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाता है जहाँ वह इसको समीक्षा करती है।

वार्षिक कार्य योजना (Annual Work Schedule) राज्य सरकार और जिला ग्रामीण विकास अधिकरण मिलकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए एक वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करते हैं। यह एक विस्तृत कार्य योजना होती है। जिसमें एक पखवाड़े अथवा माह के आधार पर ली जाने वाली क्रियाओं एवं वन्दे पूर्ण किए जाने का उल्लेख होता है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के आधार पर ही अधिकरण के अतर्गत कार्यरत संगठनों को कुशलता को मापा जाता है।

योजनाओं की स्वीकृति (Acceptance of Projects) लाभार्थियों का ऋण के लिए प्रार्थना पत्र एक कैम्प में पूरा किया जाता है। इस कैम्प में विकास खण्ड के अधिकाधिक एवं अन्य सम्बन्धित विभाग जैसे रा.प.व. विभाग और बैंक आदि भाग लेते हैं। कैम्प के आयोजन को इस कारण उपयुक्त माना जाता है कि इससे लाभार्थी के समय एवं शक्ति का बचत होता है और उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आवेदन पत्र पूर्ण होने के पश्चात् उन्हें बैंक को भेजा जाता है। बैंक को भेजने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सार आवेदन पत्र एक साथ न भेज जाए बल्कि वे कुछ समान अंतर पर निरन्तर भेजे जाते रहें। खण्ड स्तर के कार्यालय में इन आवेदन पत्रों का पूरा विवरण रखा जाता

है। इस विवरण में योजना की प्रकृति के अतिरिक्त वह धनराशि भी उल्लेखित होती है जिसके लिए आवेदन किया गया है एवं बैंक से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् इसका विवरण भी रखा जाता है। बैंक को भेजे जाने वाले प्रार्थना-पत्र वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप होते हैं। लाभार्थियों को वर्तमान में आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र लगाने होते हैं प्रथम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋण का आवेदन एवं समीक्षा पत्र। द्वितीय, परिसम्पत्ति की गिरवी रखने एवं सम्पत्ति पत्र। तृतीय धनराशि की टिकट लगी रसीद। चतुर्थ, प्रोमोट। पाचवा, समूह जीवन बीमा योजना का प्रपत्र। बैंक मैनेजर का यह दायित्व है कि वह खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भेजे गए ऋण आवेदन पत्रों को बिना किसी देरी के देखे एवं निर्णय लें। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्रों का निपटारा एक पखवाड़े के भीतर कर दिया जाना चाहिए। इस ऋण से जो परिसम्पत्ति क्रय की जाती है वह एक अच्छे स्तर की और उचित कीमतों पर दी जानी चाहिए। यह जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का दायित्व है कि वह लाभार्थी को इन आधारों पर परिसम्पत्ति उपलब्ध करवाए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए एक क्रय समिति का गठन किया जा सकता है। जिसमें लाभार्थी, विहीन सदस्य सम्बन्धित विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक प्रतिनिधि हो सकता है। जहाँ तक सम्भव हो इस समिति द्वारा ही सभी परिसम्पत्ति क्रय की जानी चाहिए। इन परिसम्पत्तियों को भलीभाँति चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि उस सम्पत्ति का दुरुपयोग न हो सके और न ही उसे हस्तान्तरित किया जा सके। यह बीमा के उद्देश्य के लिए भी उचित रहता है।

वित्त

Finance

छठी पंचवर्षीय योजना के अतर्गत राज्य में विद्यमान विकास खण्डों की संख्या के अनुसार ऋण आवंटित किए गए थे किन्तु चलती पंचवर्षीय योजना में ये ऋण राज्य में गरीबी की स्थिति के अनुसार आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम के अतर्गत आर्थिक क्रियाओं को साठ एवं अनुदान के द्वारा सहस्रता प्रदान की जाती है। यह धनराशि आधी आधी केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। 1986 से भारत सरकार द्वारा नैमासिक बजट बनाना आरम्भ किया गया है। नैमासिक बजट के अनुसार आवंटित राशि का 15 प्रतिशत वर्ष को प्रथम तिमाही में प्रमुक्त हो जाना चाहिए तथा द्वितीय तिमाही में आवंटित राशि का 20 प्रतिशत काम में ले लिया जाना चाहिए। इस प्रकार 6 माह में 35 प्रतिशत राशि का प्रयोग हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो अनुपतिक रूप में आवंटित राशि को कम कर दिया

जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आवंटित धनराशि का 15 प्रतिशत जिला ग्रामीण विकास अधिकारियों में प्रशासकीय सरचना बनाने पर व्यय किया जा सकता है। यदि अधिकरण में 5 से 7 विकास खण्ड हैं तो साढ़े 12 प्रतिशत और यदि 8 या 8 से अधिक खण्ड होने पर आवंटित राशि का 10 प्रतिशत तक लाभ में लिया जा सकता है। लाभार्थी को जो अनुदान दिया जाता है उसके दुरुपयोग को रोकने और सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभार्थी से एक बॉण्ड अपना प्रोमोट लिखाया जाता है। यदि दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट होती है तो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

खाते रखना

Accounts

यह ज्ञात करने के लिए कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप धनराशि व्यय की जाती है अथवा नहीं, खाते रखना आवश्यक है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, रजिस्टर्ड सोसायटीज होने के कारण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार खाते रखती है। अधिकरण का परियोजना अधिकारी 30 जून तक खाते तैयार कर लेता है। इन खातों को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अकेक्षक से इनका अंकेक्षण कराया जाता है। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति भारत सरकार को और राज्य सरकार को 30 सितम्बर तक भेज दी जाती है। भारत सरकार का कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल अधिकरण के खातों की जांच करने का पूरा अधिकार रखता है।

प्रशासकीय व्यवस्था

Administrative System

इस कार्यक्रम में नीति निर्धारण निपटण और मूल्यांकन का कार्य भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग करता है। केन्द्रीय स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके सहायक कार्यक्रम (ट्राईसप एव मरिला एव जाल विकास कार्यक्रम) के लिए एक केन्द्रीय समिति गठित की गई है। इस समिति का अध्यक्ष, ग्रामीण विकास विभाग का सचिव होता है। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग या अन्य कोई विभाग जिसे ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है, वह इस कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का कार्य करता है। इस हेतु राज्य स्तरीय एक समन्वय समिति बनाई गई है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव अथवा कृषि उत्पादन कमिश्नर या विवास कमिश्नर होता है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा किया जाता है। यह अधिकरण सोसायटीज एक्ट के

अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसायटीज होती हैं। इनका अध्यक्ष प्रायः जिले का कलेक्टर होता है। जिला समिति का सदस्य सचिव, अधिकरण का परियोजना अधिकारी अथवा निदेशक होता है। विकास खण्ड स्तर पर मार्गदर्शी और वार्षिक कार्य योजना बनाई जाती है। साथ ही स्वोक्म योजना के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। साथ ही कार्यक्रम के प्रभावों की जानकारी भी इसी स्तर से प्राप्त होती है। खण्ड स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी (बी डी ओ) मुख्य समन्वयक का कार्य करता है और यह देखता है कि योजना समय पर बनाई जाए और समय पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जाए।

निरीक्षण एवं मूल्यांकन

Monitoring & Evaluation

इस हेतु एक प्रपत्र (विकास पत्रिका) भरा जाता है। इसको दो प्रतियां होती हैं। एक प्रति लाभार्थी के परिवार को दी जाती है तथा दूसरी विकास खण्ड मुख्यालय पर रखी जाती है। इस प्रति को पूर्णतः पूर्ण रखने का प्रयास किया जाता है ताकि परियोजना की पूर्ण जानकारी सदैव उपलब्ध रह सके। राज्य सरकार अपने स्तर पर इस हेतु कोई नयी विधि भी अपना सकती है। प्रतिवर्ष परिसम्पत्ति का निरीक्षण होता है और इस निरीक्षण के परिणाम आगामी वार्षिक योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति को मासिक मुख्य सूचकों मासिक एवं त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों से परखा जाता है। कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थानों और समूहों द्वारा कराया जाता है। ये मूल्यांकन केन्द्र और राज्य दोनों के द्वारा कराए जा सकते हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण इस प्रकार की मूल्यांकन अध्ययन के लिए 40 हजार रुपये प्रति वर्ष तक व्यय कर सकता है किन्तु इस प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है।

कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त

Institutional Finance for the Programme

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्थात् लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता ऋण व अनुदान के रूप में होती है। इसमें ऋण का भाग बड़ा होता है। यह राशि साख-संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। यह ऋण लाभार्थी की किसी परियोजना पर प्रदान किया जा सकता है। परियोजना के लिए ऋण, स्थाई पूँजी या कार्यशील पूँजी के रूप में अथवा समुक्त रूप में हो सकता है। कार्यशील पूँजी परियोजना की प्रकृति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

यदि कोई परिवारजना केवल कार्यशील पूँजी के आधार पर ही बनाई जाती है तो ऐसी दशा में अनुदान को सम्मिलित करते हुए यह राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सहायता लाभार्थियों को रियायती व्यापक दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। जो वित्तीय सस्याएँ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त प्रदान करती हैं उन्हें नाबाई से अपने आप पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त होती है। लाभार्थी से कृषि एवं उससे सम्बंधित क्षेत्र में 10,000 रुपये तक के विनियोजित ऋण पर कोई सहायक प्रतिभूति नहीं मांगी जाती है। केवल उन्हें ऋण से प्राप्त की गई परिसम्पत्ति को रखना होता है। उद्योग, सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में 25,000 रुपये की सीमा तक कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती। ऋण के लिए आवेदन-पत्रों का प्रारूप लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक जैसा बना दिया गया है। ऋण के वितरण के लिए बैंक में एक विशिष्ट दिन भी निर्धारित कर दिया जाता है।

पुनर्भुगतान Repayment

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए ऋणों की मध्यकालीन ऋण माना जाता है। इन ऋणों का पुनर्भुगतान तीन वर्ष से पाँच वर्ष के मध्य सामान्यतः हो जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऋणों का पुनर्भुगतान निर्धारित समयवधि में हो जाए। इस हेतु राज्य सरकार, बैंक अधिकारियों को कार्यक्रम के लाभार्थियों से पुनर्भुगतान के लिए यथासम्भव सहायता प्रदान करती है। इस हेतु समय समय पर कैम्प भी आयोजित किए जाते हैं। बैंक मैनेजर, रिटर्न बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकास खण्ड अधिकारी को प्रतिमाह इस बात की सूचना प्रदान करते हैं कि कार्यक्रम में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए कितने स्वीकृत किए और कितने अस्वीकृत हुए। साथ ही सम्बंधित सलाह देने के लिए केन्द्रीय, राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों का निर्माण किया गया है।

पूरक सहायता Supplementary Assistance

कार्यक्रम के अन्तर्गत जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उन्हें पूरक सहायता देने का प्रावधान भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है, बशर्ते वे अपने पूर्ण प्रयासों के बाद भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हों। बैंक प्रकोप अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से जिनमें सम्बन्धित परिवारों का कोई दोष नहीं है, के कारण यदि वह परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाया है तो उसे पूरक सहायता देकर इस रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है।

प्रगति'

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना एवं चिन्हित लक्षित समूहों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाना है। वर्ष 1996-97 तक 27 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। 1997-2002 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 184.5 करोड़ रुपये खर्च द्वारा व्यय किया जायेगा। इतनी ही राशि केन्द्र से भी प्राप्त होगी।

ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसम) TRAINING OF RURAL YOUTH FOR SELF EMPLOYMENT

यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 15 अगस्त, 1979 में आरम्भ की गई थी। ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसम) योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक घटक है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कुरालता प्रदान करना है ताकि वे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के व्यापक क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापार कार्यकलापों में स्व-रोजगार अथवा मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व-रोजगार/मजदूरी/रोजगार उपलब्ध कराना है। केवल प्रशिक्षण दिया जाना ही कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है।

उद्देश्य Objects

जैसा कि अभि बताया गया है कि ट्राईसम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवकों को तकनीकी योग्यता प्रदान करना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। ये रोजगार कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं अथवा व्यापारिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना में 18 से 35 वर्ष के मध्य के ग्रामीण युवकों को लिया जाता है। कार्पेट बुनने की गतिविधियों में यह आयु 14 से 35 वर्ष तक रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत प्रशिक्षित युवक अनुसूचित जाति और जनजातों से सम्बन्धित होने चाहिए। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं का एक-तिहाई भाग महिलाओं का होना चाहिए। ट्राईसम के उद्देश्यों को मजदूरी रोजगार तक विस्तृत कर दिया गया है। मजदूरी रोजगार की

परियोजनाओं को राज्य स्तरीय समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। इस योजना में चयनित युवकों को एक अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थी को अनुदान और सहायता साख समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

चयन Selection

ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन के मापदण्डों में वे युवा ही चयन के पात्र होते हैं जो समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों के सदस्य हैं। सामान्यतः 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं का चयन किया जाता है। इस आयु में मलीचा बनाई डायमण्ड कटिंग एव पॉलिशिंग के लिए आयु सीमा 14 से 35 वर्ष रखी गई है। विद्यार्थियों अधिक श्रमिकों विस्थापितों उपचारित कोड के बीमारों के लिए आयु की ऊपरी सीमा 45 वर्ष तक है। अनाथों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष है। चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम विकास अधिकारी क्षेत्र के ग्राम सेवकों अथवा ग्रुप सचिवों को जिले के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कौन कौनसे व्यवसायों में प्रशिक्षण चल रहे हैं इस बात की जानकारी दी जाती है। इसके पश्चात् ग्राम सेवक अथवा ग्रुप सचिवों के माध्यम से प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं के प्रार्थना पत्र विकास अधिकारियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तदुपरान्त निर्दिष्ट मापदण्डों के अनुसार पत्रों की जाच की जाती है। इसके बाद एक प्राथमिक सूची ब्लॉक स्तरीय समिति के विचारार्थ रखी जाती है। ब्लॉक स्तरीय ट्राईसम कमेटी में पचायत समिति का प्रधान अध्यक्ष तथा विकास अधिकारी सदस्य सचिव होता है। इसके अतिरिक्त लोड बैंक अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत बैंक का प्रतिनिधि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रतिनिधि जिला उद्योग केन्द्र का प्रतिनिधि पचायत समिति में कार्यरत उद्योग प्रसार अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रतिनिधि तथा जिला नियोजन अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं। प्राथमिक सूची में जिन युवाओं के नाम होते हैं उन्हें साक्षात्कार हेतु इस समिति के सम्मेलन बुलाया जाता है। प्रशिक्षण के योग्य युवाओं का चयन तथा किस व्यवसाय अथवा किस प्रशिक्षण संस्थान में किस किस युवा को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना है इसका निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है। व्यवसाय के निर्धारण में क्षेत्र की आवश्यकता युवा की अभिन्नि प्रशिक्षण संस्थान में स्थान की उपलब्धता और प्रशिक्षण के पश्चात् स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार की

सुनिश्चिता का ध्यान समिति द्वारा रखा जाता है। समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम सूची बनाई जाती है।

प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थी Trainees in Training Institutions

1 अप्रैल 1990 के पूर्व मास्टर क्राफ्ट्स मैन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना बंद कर दिया गया है। इस कारण अब चयनित युवाओं को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ही प्रशिक्षण दिलाया जाता है। एक व्यवसाय में 15 से 20 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाता है। जिला उद्योग या राज्य के बाहर के प्रशिक्षण संस्थान में कौन कौनसे व्यवसाय में प्रशिक्षण सत्र कब कब से आरम्भ हो रहे हैं इस बात की जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पचायत समितियों को दी जाती है। प्रशिक्षण हेतु भेजे गए प्रशिक्षणार्थियों का विवरण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं पचायत समिति स्तर पर रखे जाने वाले रजिस्ट्रो में किया जाता है। ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्यतः प्रशिक्षण अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती। यदि यह अवधि 6 माह से अधिक होना आवश्यक हो तो इसकी स्वीकृति राज्य स्तरीय समन्वय समिति से ली जानी आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 6 माह तक का निर्धारण ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिकरण स्तर पर किया जाता है। काष्ठ सिल्क व्यवसाय की प्रशिक्षण अवधि 9 माह की निर्धारित की जाती है।

प्रशिक्षण हेतु देय वृत्तिका एवं मानदेय Stupend in Training

यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के गांव में ही दिया जाता है तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रति माह 100 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के गांव के अलावा अन्य स्थान पर दिया जाता है और मुफ्त आवास की व्यवस्था की जाती है तो प्रतिमाह 200 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण अवधि एक माह से कम हो तो 8 रुपये दैनिक या अधिक से अधिक 125 रुपये तक देय होते हैं। यदि प्रशिक्षणार्थियों को गांव के अलावा अन्य स्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है और मुफ्त आवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो प्रतिमाह 250 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण की अवधि ऐसी स्थिति में एक माह से कम हो तो 9 रुपये दैनिक या अधिकतम 125 रुपये तक देय होते हैं।

प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रशिक्षण देने वाली संस्था

को प्रशिक्षण देने हेतु मानदेय के रूप में 75 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी, प्रति माह की दर से देय होते हैं। इसके अतिरिक्त कच्चा माल, बिजली, पानी, भवन, किराया, कार्यालय व्यय आदि के लिए 50 रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रशिक्षण संस्थान को राशि दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के मध्य अधिक से अधिक 500 रुपये की सीमा तक मुफ्त औजार किट दिया जाता है। यह किट प्रशिक्षार्थियों द्वारा कुछ निपुणता प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण में रुचि दिखाने पर दिया जाता है। प्रशिक्षण देने हेतु अनुदेशक की तथा कच्चे मांस आदि की व्यवस्था करने का दायित्व प्रशिक्षण संस्था का ही होता है।

टूल किट Tool Kit

विभिन्न व्यवसायों के लिए 500 रुपये तक की सीमा का औजार किट प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करने का प्रावधान है। किस व्यवसाय हेतु औजार किट के अन्तर्गत क्या-क्या सामान दिया जाना है, इसका निर्धारण ट्राईसम कार्यक्रम हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। उक्त सामान को अनुमानित कीमत के आधार पर, प्रत्येक व्यवसाय के लिए औजार किट के राशि, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ व्यवसायों के लिए औजार किट की आवश्यकता नहीं होती। वहा औजार किट नहीं दिए जाते। औजार किट प्रशिक्षण संस्था द्वारा क्रय किए जाते हैं। इस हेतु राशि अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। क्रय करते समय संस्था के समिति में एक सदस्य अभिकरण या पंचायत समिति का अधिकारी होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों को औजार किट का वितरण अधिकारियों या कम से कम एक अधिकारी को उपस्थिति में किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण Implementation & Supervision

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संस्था को सौंपे हो अथवा पंचायत समिति के माध्यम से प्रशिक्षण आरम्भ होने से पूर्व के उपस्थिति पत्रक उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस उपस्थिति पत्रक में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति नियमित रूप से अंकित की जाती है। इस उपस्थिति पत्रक के आधार पर ही भुगतान किया जाता है। यदि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में अवकाश के दिनों के अतिरिक्त अनुपस्थित रहते हैं तो अनुपस्थित दिनों की वृत्तिका ॥ रुपये प्रतिदिन की दर से काट ली जाती है। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी माह में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसे उस माह की वृत्तिका नहीं दी जाती है। अवकाश के दिनों के

अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षणार्थियों को एक माह में अधिकतम दो आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं। ऐसे अवकाशों पर भुगतान भी किया जाता है।

मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण Training for Wage Employment

मजदूरी रोजगार के लिए भी ट्राईसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इसे सीमित रखा गया है। ट्राईसम योजना के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों में से 50 प्रतिशत से कम को, केवल द्वितीय एवं तृतीय कार्यकलापों में ही मजदूरी रोजगार दिलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि पहले उन औद्योगिक इकाइयों या परियोजनाओं का पता लगाया जाए जहां मजदूरी रोजगार उपलब्ध होना सुनिश्चित है। इसके पश्चात ही औद्योगिक इकाइयों या परियोजनाओं को मांग के अनुसार व्यवसाय में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। बिना औद्योगिक इकाइयों अथवा परियोजनाओं से जुड़े जो युवा प्रशिक्षण के पश्चात् स्वयं के स्तर पर मजदूरी रोजगार प्राप्त करते हैं, उन्हें रोजगार से लाभान्वित नहीं माना जाता है। इस कारण जहां पहले से ही मजदूरी रोजगार मिलना सुनिश्चित होता है, तभी मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है अन्यथा नहीं।

अन्य बातें (Other Things)

सामान्यतः एक परिवार के एक सदस्य को ट्राईसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि परिवार के एक सदस्य को इस योजना में लाभान्वित करने के बाद भी वह परिवार गरीबी को रखा से नीचे रहता है तो एक और सदस्य को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार द्वारा लाभान्वित किया जा सकता है। इस योजना में प्रशिक्षण समाप्त करने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। किन्तु ये प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार अभिकरण द्वारा छपवाए जाते हैं। ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरोक्षण एवं अवलोकन समय-समय पर पंचायत समिति अथवा अभिकरण अथवा एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रशिक्षण के दौरान ही ऋण आवेदन पत्र तैयार कर लिए जाते हैं तथा सम्बन्धित बैंकों से ऋण स्वीकृति की कार्यवाही पूरी कर दी जाती है। ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के तुरन्त पश्चात् प्रशिक्षणार्थी को स्वरोजगार हेतु ऋण मिल सके तथा वह अपना कार्य आरम्भ कर सके। ऋण

आवेदन पर तैयार करवाने व ऋण वितरण कराने का दायित्व अभिकरण व पंचायत समिति के अधिकारियों का होता है। योजना के अन्तर्गत ऋण व अनुदान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुसार हो देय होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर जिन जिलों में सहायक परियोजना अधिकारी (उद्योग) का पद है, वहां वही ट्राईसम कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी होते हैं। जहां यह पद नहीं है वहां अभिकरणों में जिला आयोजना अधिकारी को ट्राईसम कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाता है। ये अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक के अधीन एवं मार्गदर्शन में कार्यों का निष्पादन एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

प्रगति¹

ट्राईसम योजना के अन्तर्गत, जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ही एक अंग है, बेरोजगार ग्रामीण युवकों को मजदूरी एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1997-98 में दिसम्बर 1997 तक 2397 युवकों को प्रशिक्षित किया गया तथा 3536 युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 1988-99 में ट्राईसम के अन्तर्गत लाभान्वितों को सख्या 10500 होने का अनुमान है।²

ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (द्वाकरा)

DEVELOPMENT OF WOMEN & CHILDREN IN RURAL AREAS

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने पर यह तथ्य सामने आया कि सहायता का प्रवाह महिलाओं की ओर लगभग नगण्य है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों की दशा को सुधारने के लिए महिलाओं पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया। इस कारण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायक योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया गया। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि महिलाओं की आय का परिवार के पोषाहार और शिक्षा की स्थिति में सुधार से सीधा सम्बन्ध है। इस कारण महिला की आय में वृद्धि होने से परिवार की स्थिति में सुधार होने के अधिक अवसर होते हैं। इस कारण महिलाओं को अधिक आय प्राप्त करने के अवसर देने का निर्णय लिया गया।

उद्देश्य

Objects

ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का प्रमुख ध्येय जिला स्तर पर महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उनकी आय बढ़ाने वाले कार्यों के अवसर उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य समूह वही है जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत है अर्थात् वे परिवार जिनकी वास्तविक आय 4,800 रुपये प्रति वर्ष से कम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तियों को सहायता एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तारीके से एवं उसी के बजट में से की जाती है। इस कार्यक्रम को 1982-83 में भारत के 50 चुने हुए जिलों में पायलेट परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया था। 31 मार्च, 1992 तक यह 241 जिलों में विस्तृत हो चुका था।

समूह का निर्माण

Formation of Group

इस कार्यक्रम में 15 से 20 ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाने की चेष्टा की जाती है जो कि पारस्परिक हित की क्रियाओं में सलग्न होती हैं। आरम्भ में हो सकता है कि यह समूह की आय प्राप्त करने से सम्बन्धित क्रियाओं में न लगें। हो किन्तु यह इसका एक आवश्यक तत्व है। ऐसे समूह के निर्माण में काफी समय लग सकता है। इस हेतु लोगों से सम्पर्क करना होता है। उन्हें इसका महत्व समझाना होता है। इस समूह का निर्माण ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भर होता है। ऐसे समूह को 15,000 रुपये की सहायता भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ के द्वारा बराबर-बराबर भाग में दी जाती है। केन्द्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और शेष यूनिसेफ प्रदान करता है। इस धनराशि को एक कार्यशील कोष के रूप में कच्चा माल खरीदने और विपणन आदि में काम में लिया जा सकता है। समूह के संगठक को अधिकतम 50 रुपये प्रति माह एक वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है। इसी प्रकार यह धनराशि आय प्राप्त करने के गतिविधियों के सार्वजनिक ढांचे को विकसित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। इस राशि का उपयोग बच्चों की देखभाल से सम्बन्धित सुविधाओं पर एक बार किए जाने वाले व्यय के रूप में भी किया जा सकता है। 15,000 रुपये के अतिरिक्त समूह के संगठक को 200 रुपये प्रति वर्ष का यात्रा भत्ता दिया जाता है।

आय प्रदान करने वाली क्रियाएं Income Generating Activities

सभी सम्बन्धित आर्थिक गतिविधियों को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत गतिविधियों को चिन्हित करने का कार्य समूह द्वारा किया जाता है और इस कार्य में ग्राम सेविका आदि उसकी सहायता कर सकते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आर्थिक क्रिया के पूर्व और उसके पश्चात् की गतिविधियों में सम्बन्धित तात्त्विक उस क्षेत्र में उपलब्ध हो ताकि उन क्रियाओं को आरम्भ करने से पूर्व तथा आरम्भ करने के पश्चात् सभी प्रकार की सहायता और सहयोग मिल सकें। भारत सरकार द्वारा प्रति ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ब्लॉक में प्रति ब्लॉक को दर से सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने की योजना है। यह केन्द्र अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्रशिक्षण व उत्पादन आदि में भी सहयोग करेगा। इसके अन्तर्गत ग्राम सेविका के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कटने की भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार के सामुदायिक विकास केन्द्र को उपयुक्त तकनीकों के विकास हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सामुदायिक केन्द्रों पर 1.90 लाख रुपये से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। पहाड़ी और काली कपास की मिट्टी वाले क्षेत्रों में यह धनराशि 2.30 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रशिक्षण Training

इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाता है ताकि मानसिक दृष्टिकोण में तथा जागरूकता में परिवर्तन लाया जा सके और प्रेरणा प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम उन समस्याओं या निकायों का उत्तरदायित्व है जो इस कार्यक्रम के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारें ऐसे व्यक्तियों को एक सूची बना सकती हैं जो एक निर्धारित समय एवं स्थान पर प्रशिक्षण दे सकें। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इस कार्यक्रम के प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारियों के स्तर तक के व्यक्ति साल में एक बार अवश्य प्रशिक्षण प्राप्त करें।

कर्मचारी

Employees

राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व उप सचिव स्तर के एक अधिकारी के पास होता है जो यदि महिला हो तो अधिक उपयुक्त रहेगा। जिला स्तर पर एक महिला अधिकारी को सहायक परियोजना अधिकारी,

महिला विकास नियुक्त किया जा सकता है जो कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी की सहायता कर सके और कार्यक्रम के क्रियान्वयन को निकट से देख व समझ सके। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्य, फिल्म आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि मामले पर वह धनराशि यूनिसेफ द्वारा प्रदान की जाती है।

वित्त

Finance

यदि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बना समूह सोसायटीज एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है तो यह आर्थिक क्रियाओं के लिए बैंक से एक समूह के रूप में ऋण प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत महिला सदस्य समूह, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यदि समूह अनौपचारिक है और यह बैंक से एक समूह के रूप में ऋण लेने की स्थिति में नहीं है तो एक सामूहिक ऋण को व्यक्तिगत ऋण एवं अनुदान में बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में समूह को ऋण की समस्त राशि को गारंटी देनी होगी। आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों, बच्चों में सम्बन्धित सुविधाओं आदि के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ सहाय अनुपात में धनराशि प्रदान करते हैं। केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में भारत सरकार और यूनिसेफ के वित्त प्रदान करने का अनुपात 2:1 का होता है। समूह के संगठक को जो यात्रा भत्ता दिया जाता है वह भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अर्धा-अर्धा प्रदान किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों में यात्रा भत्ते की समस्त राशि केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारी की लागत हेतु यूनिसेफ कोष उपलब्ध होता है। बहुउद्देशीय केन्द्रों के उपकरण एवं अन्य पूर्ति के लिए पचास हजार रुपये प्रति केन्द्र तक की राशि यूनिसेफ प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण वर्कशॉप और सेमिनार आदि के लिए यूनिसेफ के कोष उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस प्रशिक्षण या योग्यता की आवश्यकता है उसे ट्राइसम द्वारा उपलब्ध कटने की चेष्टा की जाती है। इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि और प्रशिक्षण देने वालों से, प्रशिक्षणाधियों को भुगतान की दर, ट्राइसम योजना के मानदण्डों के अनुसार हो होती है।

नियंत्रण एवं मूल्यांकन

Monitoring & Evaluation

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहायक सेवाओं के लिए सरकार के अन्य कार्यक्रमों का भी

सहयोग लिया जा सकता है जो कि दूसरे सगठनों और दूसरे विभागों द्वारा चलाए जा रहे हैं जैसे प्रौढ शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रम, बालवाडी, बच्चों का टीकाकरण आदि। इस हेतु प्रशासकीय अधिकारियों का परस्पर सम्पर्क में रहना होगा। इस ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का परस्पर सहयोग से मूल्यांकन करने के लिए ग्राम सेविका, मुख्य सेविका और समूह के सदस्यों का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। अर्द्ध वार्षिक अवधि में यह कार्य किया जा सकता है। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि वे अपने लक्ष्यों को कहा तक प्राप्त कर रहे हैं और उनके समक्ष कौनसी समस्याएँ आ रही हैं। इन सब का लेखा-जोखा ग्राम सेविका द्वारा रखा जाना चाहिए जिसे समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को इस कार्यक्रम पर व्यय से सम्बन्धित विवरण भेजा जाता है।

1997-98 में दिसम्बर 1997 तक द्वारका योजना के अन्तर्गत 51 महिला समूहों का गठन किया गया।

अपना गांव-अपना काम' योजना 'APNA GAON-APNA KAM' YOJNA

परिचय

Introduction

राजस्थान सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ 1 जनवरी 1991 से किया है। विशिष्ट योजना सगठन व एकिकृत ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य करवाते हैं। राज्य के ग्रामों में बसे गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 'अपना गांव-अपना काम' योजना आरम्भ की है।

अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के रूप में जवाहर रोजगार या अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत होते रहे हैं। वित्तीय साधनों की कमी के कारण गांवों में सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण कार्य तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए यह अनुभव किया गया कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ ग्रामीण जनता को भी विकास कार्य में सहभागिता बनाया जाए। यह तभी सम्भव है जबकि जनता की इच्छा से विकास की प्राथमिकताओं

का चयन हो तथा उसके द्वारा भी विकास कार्यों में आर्थिक योगदान दिया जाए। पूर्व अनुभवों से भी यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण जनता के योगदान से कई स्थानों पर स्थानीय जनता द्वारा धनराशि एकत्रित कर विद्यालयों, औषधालयों, पंचायत घरों, पुस्तिकाओं, नालियों, वाचनालयों के भवनों, पेयजल कुूपों, खेलियों, आदि का निर्माण किया गया। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने जनसहयोग को इस योजना को आरम्भ किया।

कार्यक्रम

Programme

राज्य सरकार को इस योजना के अन्तर्गत जनसमुदाय की सहायता से किए जाने वाले कार्यों से बेरोजगारी को समस्या का कुछ हल निकालना तथा नियोजन के नये अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजना में जलसमुदाय की सुविधा के लिए सड़क निर्माण, शाला भवन निर्माण, औषधालय, पुस्तिका, पक्की नालियों का निर्माण, बालबाचन भवन, आगनवाडी भवन का निर्माण, महिला मंडल भवन, पंचायत भवन, वाचनालय भवन, सामुदायिक केन्द्र भवन, पीने के पानी के कुएँ, टकी, खेलों, गांव का तालाब, एनीकट सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, शौचालय, बस स्टैण्ड आदि निर्माण कार्यों के लिए तत्परता से सरकार द्वारा वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कार्य के चयन में उन गांवों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ पहले राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अथवा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण नहीं हुआ हो तथा सम्बन्धित ग्रामवासी अपने स्तर पर निर्धारित राशि का योगदान उपलब्ध कराने को तैयार हो।

माध्यम

Medium

इस योजना के निर्माण कार्यों के लिए 30 प्रतिशत राशि स्थानीय समुदाय, ग्रामीण पंचायत या पंचायत समिति उपलब्ध कराएंगी तथा शेष 70 प्रतिशत राशि राज्य सरकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत समिति को उपलब्ध कराएंगी। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति तथा सरकार द्वारा उपलब्ध राशि का समुचित उपयोग हो, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक चयनित कार्य ग्राम पंचायत द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। यदि पंचायत समिति स्वयं किसी कार्य को करना चाहे और उसके लिए निर्धारित योगदान राशि उपलब्ध कराए तो पंचायत समिति को भी चयनित करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

योजना-अन्तर्गत यह भी प्रावधान रखा गया है कि यदि ग्राम पंचायत प्रस्ताव करती है कि उसके द्वारा पारित प्रस्ताव

को मनोनीत 5 सदस्यों की भवन निर्माण समिति द्वारा करवाया जाए तो निर्माण कार्य इस प्रकार गठित पाच सदस्यीय भवन निर्माण समिति से भी करवाया जा सकेगा। भवन निर्माण समिति को व्यय का लेखा-जोखा पचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राजकीय वित्तीय अनुदान की राशि पचायत के माध्यम से भवन निर्माण समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

योजनान्तर्गत प्रावधानानुसार सर्वप्रथम ग्राम पचायत द्वारा जिला ग्रामीण विकास अधिकरण में अपने हिस्से की 10 प्रतिशत योगदान राशि जमा करानी होगी और लिखित में देना होगा कि शेष 20 प्रतिशत राशि उसके द्वारा सामग्री या नकद द्वितीय या तृतीय किस्त लेने से पूर्व जमा करा दी जाएगी। सामुदायिक निर्माण में व्यय होने वाली कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण में जमा होने पर ही जिला ग्रामीण विकास अधिकरण कार्य के लिए स्वीकृति जारी करेगा और ग्राम पचायत द्वारा निक्षेपित 10 प्रतिशत राशि सहित कुल लागत की 30 प्रतिशत राशि स्वीकृति के साथ ही कार्य सम्पन्न करने वाली ग्राम पचायत या पचायत समिति को सुलभ करा दी जाएगी। द्वितीय व तृतीय किस्त लेने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पचायत या पचायत समिति को 10 प्रतिशत राशि दो किस्तों में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण में जमा करानी होगी और उसी के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अधिकरण कुल लागत की 30 प्रतिशत राशि द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में उन्हें उपलब्ध करेगा तथा शेष 10 प्रतिशत राशि निमाण कार्य की समाप्ति पर उपयोगिता पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि कोई धर्मार्थ ट्रस्ट या पञ्जीकृत समिति किसी निर्माण कार्य को करना चाहे तो 30 प्रतिशत वांछित राशि का योगदान उसे देना होगा। ऐसी संस्था या ट्रस्ट को निमाण की लागत पुनर्भरण के आधार पर जैसे-जैसे काम सम्पादित होगा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी पञ्जीकृत समिति या धर्मार्थ ट्रस्ट को नियमानुसार कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि स्वीकृति कार्य के पूर्व जिला ग्रामीण विकास अधिकरण में जमा करानी होगी। अन्तिम किस्त को अनुदान राशि देते समय संस्था द्वारा जमा कराई गई 10 प्रतिशत राशि लौटा दी जाएगी। किसी भी स्थिति में धर्मार्थ ट्रस्ट या पञ्जीकृत समिति को रकम अग्रिम रूप से नहीं दी जाएगी। उभे राज्य के हिस्से की राशि उसके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य के आधार पर 3 किस्तों में दी जाएगी।

स्वीकृति

Acceptance

कार्य के स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा दी जाएगी। यदि किसी कारण से 15 दिन की अवधि

में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण वांछित कार्य की स्वीकृति जारी नहीं कर पाता है तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर निजी तौर पर सतुष्ट होकर ग्रामीण विकास अधिकरण, ग्राम पचायत, पचायत समिति, धर्मार्थ ट्रस्ट, पञ्जीकृत समिति अथवा सगठन को सीधे ही कार्य की स्वीकृति जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

प्रगति'

ग्रामीण क्षेत्रों में जनोपयोगी सम्पदा के निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के सृजन हेतु एक जनवरी, 1991 से 'अपना गांव अपना काम योजना' लागू की गई थी। वर्ष 1997-98 के दौरान दिसम्बर, 1997 तक 1350 आधारभूत जनोपयोगी कार्य पूर्ण किए गए। इनके अतिरिक्त 2728 कार्य प्रगति पर थे।

जवाहर रोजगार योजना

JAWAHAR ROZGAR YOJNA

भारत में रोजगार से सम्बन्धित दो कार्यक्रम क्रमशः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) पूर्व में ही चल रहे थे। इन दोनों कार्यक्रमों को समाप्त करके भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1989 से जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की। इस योजना के मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।

उद्देश्य

Objects

जवाहर रोजगार योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- (1) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं को रोजगार के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध करना है।
- (2) कार्यक्रम में रोजगार जुटाने के साथ-साथ ऐसी परिसम्पत्तियाँ बनाने की चला की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जीवन स्तर में सुधार लाए और उससे निर्धन लोगों को छुड़ाए।

(3) योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के लोगो जो रोजगार चाहते हैं, प्राथमिकता दी जाती है। योजना में रोजगार देते समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगो को पहले अवसर दिए जाने की चेष्टा की जाती है। यह चेष्टा होती है कि योजना में जो रोजगार उपलब्ध कराया जाए उसमें 100 में से कम से कम 30 महिलाएं होनी चाहिए।

(4) योजना के अन्तर्गत जब भी आवश्यकता हो उस समय लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इस कारण योजना के अन्तर्गत कभी भी काम शुरू किए जा सकते हैं लेकिन उन दिनों में कार्यो को प्राथमिकता दी जाती है जब खेतों में काम कम होता है। ये कार्य खेतों के दिनों के पश्चात् पुन जारी रखे जा सकते हैं।

योजना में किए जाने वाले कार्य

Works in the Plan

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, किसी भी ऐसे काम को चुन सकती है जो ग्राम सभा से सलाह करके निर्धारित किया गया हो और गांव के हित में हो। सामान्यतः ऐसे कार्य पहले आरम्भ किए जाते हैं जिससे टिकाऊ आर्थिक स्वरूप की उत्पादक परिसम्पत्तियां बन सकें। इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यो में निम्न कार्य प्रमुख हैं।

(1) भूमि विकास (Land Development) इसके अन्तर्गत ऐसे छोटे तथा सीमान्त कृषक, जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और जिनके नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रजिस्टर में दर्ज हैं, उनकी अपनी भूमि का विकास जवाहर रोजगार योजना की धनराशि से किया जा सकता है। भूमि विकास के कार्यो में भूमि को समतल करना, जल निकासी हेतु नालो का निर्माण करना, खेत की नालियां बनाना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। भूमि विकास पर किए जाने वाले व्यय, जिसमें भूमि सुधार की लागत (जैसे जिप्सम और सिबाई के साधन आदि) जवाहर रोजगार योजना की धनराशि में से दी जा सकेगी बशर्ते भूमि विकास के खर्च का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के रूप में दिया जाए। भूमि विकास पर यदि सामान का खर्च 60 प्रतिशत से ज्यादा है तो इसके लिए अन्य साधनों से पैसा जुटाया जा सकता है। भूमि विकास परियोजना में बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, जैसी भट्टों पर भार-बार आने वाली लागत पर व्यय की अनुमति नहीं दी जाती चाहे यह उस परियोजना का हिस्सा ही क्यों न हो। जवाहर रोजगार योजना में केवल वही भूखण्ड आने चाहिए जिनमें कम से कम 10 किसान हों या कम से कम 50 प्रतिशत भूमि-धारक छोटे तथा सीमान्त कृषक हों या कम से कम 25 प्रतिशत भूमि छोटे तथा सीमान्त कृषको से हो। इस प्रकार ऐसी कोई भी

परियोजना भूमि विकास परियोजना कही जा सकती है जिसमें जल विभाजक अथवा आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि हो। छोटे तथा सीमान्त कृषकों से भूमि विकास की लागत वसूल नहीं की जाती। ग्राम पंचायत बड़े किसानों से उस दर पर वसूली करती है जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है।

(2) सामाजिक वानिकी (Social Forestry) इस योजना के अन्तर्गत वानिकी के केवल वही कार्य हाथ में लिए जाते हैं जिनसे ग्रामीण लोगो और खास तौर पर गांव के निर्धन लोगो को लाभ मिले। भूमि तथा जल संरक्षण उपायो में ऐसे कार्य जिनसे पौधों की सुरक्षा हो सके, सामाजिक वानिकी के कार्य माने जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना में सामाजिक वानिकी कार्य सरकारी और सामुदायिक भूमि, सड़कों, नहरों तथा रेलवे लाइनों के दोनों ओर किए जा सकते हैं बशर्ते कि अच्छी सामुदायिक भूमि उपलब्ध न हो तथा गांव के लोगो को उन पेड़ों के लाभ उठाने का अधिकार हो। ग्राम पंचायतें क्षेत्र विशेष की आवश्यकता तथा भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए पौधों का चुनाव करती हैं। ईधन-बारा, छोटी इमारती लकड़ी के तेजी से बढ़ने वाले पौधे तथा दूसरे पेड़ों की तुलना में स्थानीय किस्म के फलों के पेड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक वानिकी में, पौधा लगाने से तीन वर्ष की अवधि तक सामुदायिक भूमि पर और सामुदायिक लाभ के लिए लगाए गए वृक्षों के रख-रखाव की लागत का जवाहर रोजगार योजना के पैसे से पूरा किया जा सकता है।

(3) फार्म वानिकी (Farm Forestry) फार्म वानिकी के कार्य केवल उप-ग्रामीण निर्धनों की भूमि पर ही किए जा सकते हैं जिनके नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सर्वे रजिस्टर में लिखे हुए हों। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर तथा अधिकतम सीमा से अतिरिक्त भूमि, भूदान की भूमि, बजर भूमि, सरकारी भूमि के वे सभी भू-स्वामी सम्मिलित हैं जिनकी भूमि जाति छोटे किसानों से अधिक न हो तथा उस भूमि पर जिसके लिए वृक्ष-पट्टा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार निम्नलिखित श्रेणियों के सभी चुने हुए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगो को लाभ पहुंचाने के कार्य किए जा सकते हैं-

- अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग

- एक बन्धुआ मजदूर

- अधिकतम सीमा से फलतृ भूमि, भूदान भूमि, बजर भूमि, सरकारी भूमि के सभी आवंटियों को चाहे वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हों अथवा न हों।

फार्म वानिकी के अन्तर्गत बुनियादी चीजों की

सुविधाओं के विकास के साथ साथ अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए मकान बनाना उन्हें दी गई भूमि पर विकास निजी भूमि पर इधन की लकड़ा तथा चार उगाने जैसे सामाजिक वित्तीय कार्यक्रम तत्पु सिचाई कुए तथा सामुदायिक कुए पाने के पानी के कुए यदि कार्य भी सम्मिलित हैं।

(4) इन्दिरा आवास योजना (Indira Housing Plan) इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को आवास उपलब्ध कराए जाएं जो गरीबों की रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य इन वर्गों के सदस्यों को नि शुल्क मकान देना है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान के निर्माण पर 8000 रुपये स्वच्छ शौचालय और धुआ रहित बूले के निर्माण पर 1400 रुपये और आधारभूत ढाचा तथा सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करने को लागत 3300 रुपये तक हो सकती है। पहाड़ों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की लागत 8000 रुपये के स्थान पर 9800 रुपये तक हो सकती है। इन्दिरा आवास योजना में मकानों का कोई डिजाइन निर्धारित नहीं किया है। किन्तु यह निर्धारित किया गया है कि इन्दिरा आवास योजना में मकानों का कुर्सी क्षेत्र 17 20 वर्ग मीटर होना चाहिए। मकान का डिजाइन जलवायु की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है। बने हुए मकानों के डिजाइन में लोगों को सहमति से सुधार किए जा सकते हैं। मकानों में रसोई धुआ रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। इन्दिरा आवास योजना में जहां तक सम्भव हो उठे उठे बसंतों अथवा समूहों में मकान बनाने का नीति अपनाई जाती है जिसमें बस्तियों को सामुदायिक सुविधाएं दी जा सकें। यदि भूमि के न मिल पाने अथवा लाभार्थियों के भूखण्ड पूरे गांव में बिखरे हैं अथवा किसी कारण से समूहों की नीति का पालन न हो पाए तो भी इस योजना के अन्तर्गत मकान बनाए जा सकते हैं।

(5) दस लाख कुआ की योजना (Project of Ten Lakh Wells) इस योजना की 1988 89 अनुसूचित जाति/जनजाति क गरीब छोटे तथा सीमांत कृषक तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को नि शुल्क खुले सिचाई कुए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। दस लाख कुओं का योजना के वित्त से केवल खुले कुए बनाए जा सकते हैं और ट्यूबवेल और बोर वाले कुए इस योजना में नहीं आते। जहां जमान की बनावट के कारण कुए नहीं खोदे जा सकते हैं वहां इस योजना के अन्तर्गत दिया गया वित्त सिचाई तालाबों जल चकट्टा करने के ढाचों जैसे तत्पु सिचाई कार्य को अन्य योजनाओं पर व्यय किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति और मुक्त बन्धुआ

मजदूरों की भूमि जिनमें अधिकतम सीमा से फालतू भूमि और भूदान की भूमि आदि सम्मिलित हैं के विकास की योजनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। इस धनराशि को अन्य योजनाओं अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और मुक्त बन्धुआ मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के कार्यों पर व्यय नहीं किया जा सकता। योजना का लाभ उठाने वालों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे तथा सीमांत कृषक व मुक्त बन्धुआ मजदूर होने हैं जा गरीबों की रेखा से नीचे जावनयापन कर रहे हैं और जिनके नाम गांव के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रजिस्टर में दर्ज हैं।

इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य राजगार के अवसर जुटाना है और उसके परचाय योजना के लाभार्थियों के लिए नि शुल्क खुले सिचाई कुए बनाना है। जवाहर राजगार योजना के अन्तर्गत राज्य/सम शासित क्षेत्र की दी गई धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि इस योजना के लिए रखा गई है। जवाहर राजगार योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्यों पर व्यय किए जाने के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत धनराशि की भी इस योजना के काम में लाया जा सकता है। योजना में बनाया गया प्रत्येक कुआ या सिचाई का साधन लाभार्थी के हित में होना चाहिए और इसका ब्यौर गजम्ब रिवाइड में दर्ज किया जाना चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों को तत्पु सिचाई के लिए पहले ही सहायता प्राप्त हो चुकी है उन्हें इस कार्यक्रम में सहायता नहीं दी जाती है। लाभार्थियों को स्वयं अपने श्रम और स्थानीय श्रम से कुए खोदने को प्रेरित किया जाता है। इसके लिए उन्हें मजदूरों भी दी जाती है। इस कार्य में ठेकेदारों को सम्मिलित नही किया जाता है। पानी कम निक्कलने के कारण अथवा घटिया किसम के पानी के कारण अथवा कुओं को बनावट सम्बन्धी खराबों के कारण यदि कुआ असफल रहता है तो उसका गनकारी डा और टी ए या जिला परिषद् को दी जाना है अर्थात् यदि यह एग्रेसिव इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कुआ असफल हो गया है तो कृषक द्वारा कुआ खोदने के लिए जो खर्च किया गया है उसका शत प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य ठीकाण होने चाहिए और सरकार द्वारा निर्दिष्ट उचित तकनीकी मानकों के अनुसार होने चाहिए।

जवाहर राजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी Wages

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किसी वर्ष में किए गए व्यय का कम से कम 60 प्रतिशत भाग अकुशल मजदूर का मजदूरी पर खर्च किया जाना चाहिए। अकुशल

मजदूरी के अतिरिक्त दूसरे मजदूरी को दी गई मजदूरी को मजदूरी के मद में नहीं गिना जाता है उसे गैर मजदूरी (सामान) मद में गिना जाता है। रोजगार की प्रत्येक श्रेणी के लिए वही मजदूरी दी जाती है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। मजदूरी का कुछ भाग नफ़द और कुछ भाग अनाज के रूप में दिया जा सकता है। अनाज के वितरण की दर 1.5 किलोग्राम प्रति मानव दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए। जवाहर रोजगार योजना में श्रमियों को जो 1.5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है उसकी वितरण दर गेहूँ के लिए 2.09 रुपये खाद्यान्न चावल के लिए 2.64 रुपये अच्छी किस्म के चावल के लिए 3.24 रुपये और सबसे अच्छी किस्म के चावल के लिए 3.45 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। जवाहर रोजगार योजना में मजदूरी में अनाज का हिस्सा यथासंभव काम के स्थान पर ही उपभोग्य कराया जाता है।

निर्माणकार्यकी योजना और क्रियान्वयन Planning & Implementation

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्य हाथ में लिए जाते हैं तथा उनका आकार लागत तथा स्वरूप ऐसा निर्धारित किया जाता है कि उनको स्थानीय स्तर पर पूर्ण किया जा सके और उनमें उच्च स्तर की तकनीक वी आवश्यकता न पड़े। इसमें घड़े और अधिक लागत वाले कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिनमें बड़ी मात्रा में कुशल मजदूर तथा सामग्री की आवश्यकता हो। नये कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व ऐसे कार्यों को पूर्ण करने की चेष्टा की जाती है जो अधूरे पड़े हों। इस योजना में प्रायः ऐसे कोई कार्य आरम्भ नहीं किए जाते जिन्हें दो वर्ष में पूरा न किया जा सके। शुरू किए जाने वाले कार्यों पर ग्राम पंचायत की बैठक में गहराई से विचार विमर्श होता है तथा उसके आधार पर कार्य की योजना बनाई जाती है। योजना निर्मित करते समय गांव के कमजोर वर्ग के हितों का ध्यान में रखा जाता है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा ग्रामीण समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लाभ के कार्यों को सबसे पहले आरम्भ किया जाता है। कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्यों के सदर्थ में ग्राम सभा में कम से कम दो बार कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। ग्राम सभा से ऊपर स्थित जिला परिषद् आदि द्वारा ग्रामीण कार्य योजना की तकनीकी जांच की जाती है। तकनीकी आधार पर सरल कार्यों को ग्राम पंचायत स्वयं आसानी से पूरा कर सकती है। तकनीकी स्टाफ को कभी तथा अन्य स्थिति में ग्राम अधिकारियों को यह अनुमति होती है कि वे परियोजनाओं को तकनीकी मूल्यांकन निजी व्यक्तियों से भी करा सकें।

ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार की निर्धारित शर्तों के अनुसार होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर योजनाएँ बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तकनीकी देख रेख का उत्तरदायित्व ब्लॉक एजेन्सियों और जिला स्तर के निकायों पर होता है। इस कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्यों के निरीक्षण देख रेख तथा निगरानी के लिए ग्राम पंचायतें हर गांव के लिए एक समिति बनाती हैं। इस समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य रखा जाता है।

जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित अन्य तथ्य

Other Facts

जवाहर रोजगार योजना की भौतिक तथा वित्तीय लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से होती है। यह कार्य राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होता है। पंचायत द्वारा इस कार्यक्रम में बनाई गई परिसम्पत्तियों को राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को सौंप दिया जाता है और उनकी देख रेख उसी विभाग द्वारा की जाती है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ परिसम्पत्तियों की देख रेख का कार्य राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा नहीं किया जाता हो वहाँ पंचायतों को उसकी देख रेख के लिए योजना में से खर्च करने की अनुमति दी जाती है। योजना पर मामाजिक नियंत्रण रखने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक हर माह एक निर्धारित दिन समय तथा स्थान पर होती है जिसमें योजना का मूल्यांकन किया जाता है। इन बैठकों में गांव का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और अपने विचार रख सकता है। ग्राम सभा में भी जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए, को भी जवाहर रोजगार योजना के कार्यों की प्रगति के बारे में बताया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यक्रम में बनाई गई परिसम्पत्तियों का पूरा विवरण रखती है। ग्राम पंचायतें योजना के विस्तार अथवा परिसम्पत्तियों के टिकाऊपन के लिए एवं गैर मजदूरी व्यर्च के लिए धन की आवश्यकता होने पर दान स्वीकार कर सकती हैं। ऐसे कार्यों में ग्राम समुदाय से सहायता ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त बाजार समिति सहकारी समितियों, यन्त्रा समितियों अथवा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं व व्यक्तियों जैसे अन्य माध्यमों से मिलने वाली धनराशि को भी जवाहर रोजगार योजना के कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें उन्हें दिए गए पैसे और उनके द्वारा चुने हुए कार्यों के बारे में स्वयं निर्णय लेती हैं। पंचायत द्वारा लिया गया निर्णय किसी वरिष्ठ प्राधिकारी के निर्देश पर बदला नहीं जाता। ग्राम पंचायतों को नियमावली में दी गई कार्य की स्वतंत्रता में भी किसी

अधिकारी का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। योजना में श्रमिकों के होने के पानी, आगम करने के सड़ और काम पर आने वाली महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए शिशु गृह जैसी सुविधाएँ देने की चेष्टा भी की जाती है। इन सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय योजना के गर-मन्त्रद्वारे मद में से पूरा किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना में चल रहे कार्यों में पचायत क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों को पहले काम दिया जाता है। यदि उम गांव में श्रमिक नहीं मिलते हैं तब साथ वाले दूसरे गांवों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार में अनुमूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन एवं महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक प्रमुख दोवार चुनकर उस पर ग्रामवासियों के लिए यह सब बाने लिखवा दे जो गांव के निवासी जवाहर रोजगार योजना के बारे में जानना चाहते हैं। इससे योजना को ठीक प्रकार से चलाने में मदद तो मिलती ही है, ग्रामीणों के मन में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी भी उत्पन्न नहीं होती।

प्रगति

जवाहर योजना का मूल उद्देश्य ग्रामाण क्षेत्र में बेरोजगार एवं अर्द्ध-बेरोजगार पुरुष एवं महिलाओं हेतु रोजगार के आतिरिक्त अवसर सृजित करना है। वर्ष 1997-98 के दौरान माह दिसम्बर, 1997 तक 109 77 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजित किया गया।

जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम

TRIBAL AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

जनजाति विकास के लिए भारतीय सविधान में विशेष प्रावधान रखा गया है। इसी संदर्भ में पाचवी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय क्षेत्र एकीकृत विकास के लिए एक नवीन मापदण्ड अपनाया गया जिससे जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किए जा सकें। इस उद्देश्य को पूरित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जनजाति क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। ये क्षेत्र निम्न प्रकार हैं

- (1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र
- (2) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपग्रामन (माडा)
- (3) माडा कलस्टर योजना
- (4) बिछरी हुई जनजाति जनसंख्या

(5) सहारा आदिम जाति क्षेत्र

जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए निम्न संस्थाएँ भी कार्यरत हैं

- (1) जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी सघ
- (2) माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था
- (3) स्वच्छ परियोजना (सम्बन्धित नारु रोग उन्मूलन परियोजना)
- (4) विभागीय प्रशासन

(अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र

Tribal Subplan Area

राज्य के दक्षिण-पूर्व में स्थित पांच जिलों में जनजातियों का सघन आवास है। इस क्षेत्र में कुल 4409 गांवों का 19770 14 वर्ग किमी क्षेत्र सम्मिलित है। 1981 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 27 57 लाख थी जिसमें जनजाति संख्या 18 30 लाख थी जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 66 39 प्रतिशत थी। उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित पांच जिलों में से इसमें बांसवाड़ा व डूंगरपुर संपूर्ण जिले सम्मिलित थे। उदयपुर की 6 पूर्ण तहसीलें व उसकी एक तहसील गिरवा के 91 गांव सम्मिलित थे। चित्तौड़गढ़ जिले की अमोद व प्रतापगढ़ तहसील इसके अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार निगोही जिले का आवू गडखण्ड इस में सम्मिलित है। इस प्रकार इस क्षेत्र में पांच जिलों की 19 तहसील व 23 पंचायत समितियाँ सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील, मीणा, गारसिया व डामेर प्रमुख हैं। यह योजना राजस्थान में 1974 75 से क्रियान्वित की जा रही है।

कार्यक्रम (Programmes) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्न कार्य किए जा रहे हैं -

- (1) कृषि (Agriculture) कृषि विस्तार कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्रीय तिलहन एवं दलहन योजनाओं में नवीनतम तकनीकी एवं प्रति यूनिट अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम पर व्यापक प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत फल विकास सन्धी की उन्नत किस्म के बीजों का वितरण, बेर बडिंग, किभिन्न फसलों के प्रदर्शन, शुष्क खेती प्रदर्शन, कल्चर वितरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आदिवासी कृषकों के यहाँ फल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फलदार पौधों का बगीचे लगाए गए। इस हेतु नि शुल्क पौधे वितरित किए गए तथा उन्नत बीज के पैकेट्स का वितरण किया गया।
- (2) पशुपालन तथा दुग्ध विकास (Animal Husbandry) - इन कार्यक्रमों में भेड़ विकास एवं प्रजनन,

जा रहा है। बासवाड़ा में एक नर्स प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। आयुर्वेद पद्धति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कम्पाउंड प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर में आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आयुर्वेद डिस्पेंसरियों के विस्तार का लक्ष्य है और समय-समय पर आयुर्वेद कैम्पो का आयोजन किया जाता है। जनजाति उपयोगिता क्षेत्र में गांव पेयजल की समस्या से ग्रसित थे। इन क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई है। जनजाति उपयोगिता क्षेत्र के लोगों का नियोजन कार्यालयों में प्रजीवन किया गया है। जनजाति उपयोगिता क्षेत्र ने कार्यरत विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में आदिवासियों को भर्ती करने की चेष्टा की गई है। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर, पशु धन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र व एक पहिला निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र बामवाड़ा तथा उदयपुर (गढ़ी) बासवाड़ा मारुण्ट आबू व डूंगरपुर में एस टा यो केन्द्र तथा बा एड प्रशिक्षण केन्द्र उडको उदयपुर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त उपयोगिता क्षेत्र के पांचे जिलों में छ आई टी आई केन्द्र भी कार्यरत हैं। इस क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न प्रकार का शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है तथा उन्हें नियोजन उपलब्ध कराने की चेष्टा की जाती है।

(12) वित्त आयोग (Finance Commission) आठव वित्त आयोग के अन्तर्गत 1985-86 से 1988-89 तक की चार वर्षों की अवधि में आभ्रगभूत सुविधाएँ जुटो। इस क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों हेतु गृह निर्माण आदि का चेष्टा की गई। आभ्रगभूत सुविधाएँ जुटाने के लिए इस अवधि में स्वास्थ्य शिक्षा संचार एवं अन्य कार्य करवाए गए। जनजाति उपयोगिता क्षेत्र में राजकीय कर्मचारियों को राजकीय आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास गृह निर्माण कराए जाने का प्रावधान किया गया। आवास गृह निर्माण कार्य को अकाल रहित कार्यों से जोड़कर रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत अन्य कर्मचारियों का क्षतिपूर्ति भत्ते का भी प्रावधान रखा गया।

1997-98 के कार्यक्रम जनजाति उपयोगिता क्षेत्र

1997-98 में जनजाति उपयोगिता क्षेत्र का विकास करने के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं

1 1997-98 में जनजाति क्षेत्रों के विकास पर 283.9 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में स जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना पर 38.6 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

2 इस अवधि में जनजाति उपयोगिता क्षेत्र में 14 नये आभ्रग

छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा।

3 15 छात्रावासों की क्षमता को दुगुना किया जायेगा।

4 छात्रावासों में छात्रों (कक्षा 11 से 12) को पोशाक पुस्तकें एवं स्टेशनरी आदि पर प्रत्येक के लिये 1000 रुपये वार्षिक व्यय किये जायेंगे। विज्ञान सभा के छात्र के लिये यह राशि 1200 रुपये होगी।

5 1997-98 में जनजाति उपयोगिता क्षेत्र में 13 जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण 1456 कुआ को गहरा कराने 250 डाजल पम्प सेटों का वितरण 25 एनीकट और 30 जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

6 अनुसूचित जनजाति के होशियार छात्रों के लिये औद्योगिक व प्रबन्धशास्त्र में उच्च शिक्षा के लिये योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने पर प्रति छात्र 5000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

7 पहल परियोजना (डूंगरपुर जिला) पर 8.9 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) कार्यक्रम

Modified Area Development Approach

इस योजना के अंतर्गत 16 जिलों अलवर धालपुर भालागाड़ा बूंदी चितौड़गढ़ जयपुर झालावाड़ कोटा पाली सवाई माधोपुर सिंगेरी टोंक तथा उदयपुर आदि में 44 माडा खण्डों का गठन किया गया है। यह योजना 1978-79 में क्रियान्वित की जा रही है। इस क्षेत्र में मोणा जनजाति का बाहुल्य है। माडा कार्यक्रमों हेतु नवीं योजना में 30.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस कार्यक्रम के लिए जो धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है वह सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य माडा क्षेत्र में विद्यमान जनजाति परिवारों के आर्थिक स्तर को इस क्षेत्र में विकास करने वाले गैर जनजाति परिवारों के समकक्ष स्थान देना है। आदिवासियों के विकास के लिए अपनाई गई रणनीति में व्यक्ति से सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना में निम्न कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जा रहा है।

(1) शिक्षा (Education) शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माता योजना में उपयोगिता के साथ साथ मुफ्त पोशाकें पुस्तकें व स्टेशनरी। वितरण एवं बुक बैंक कार्यक्रम चल रहा है। माडा क्षेत्र में अब तक कुल 24 आभ्रग स्कूल

या छात्रावास भी स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से 30 पूरे भी हो चुके हैं। माडा क्षेत्र के जिन गावों में प्राथमिक शालाओं के भवन नहीं थे उनमें प्राथमिक शाला भवन बनवाए गए हैं।

(2) पेयजल एवं सिंचाई (Drinking Water & Irrigation) माडा कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नए कुआँ या निपाण किया गया है। अनेक हैण्डपम्प इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जा चुके हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत 308 एनीकटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष अनेक स्थानों पर कार्य चल रहा है। जलोत्थान मिर्चाई योजनाएँ और सिंचाई कुओं को गहरा करके भी प्रयास किए गए हैं।

(3) चिकित्सा (Medical) जनजाति के लोग को लाभान्वित करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। य शिविर एलापेथिक एवं आयुर्वेदिक दोनों प्रकार की चिकित्सा से सम्बन्धित हैं।

(4) फलदार पौधे (Fruit Trees) माडा योजना के अंतर्गत आदिवासीया की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जनजाति के कृषकों को 25 पौधों की इकाई पर 5 रुपये प्रति जोधित पौधे तीन वर्ष तक अनुदान दिया जाता है। इन फलदार पौधों के माध्यम से ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति बहतर बना सकते हैं।

(5) सामुदायिक पम्प सैट (Community Pump Set) माडा योजना के अंतर्गत वृषकों के समूह को मिर्चाई कार्य के लिए डीजल पम्प सैट दो वर्ष के लिए नि शुल्क प्रदान किया जाता है। दो वर्ष बाद समूह द्वारा उसको सफलतापूर्वक चलाए जाने के पश्चात् सदस्य के लिए यह पम्प सैट उक्त समूह को दे दिया जाता है। इस कार्य के लिए योजना में अलग से व्यय का प्रावधान रखा गया है।

(6) व्यक्तिगत लाभ योजनाएँ (Individual Benefit Schemes) माडा क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों की निर्धनता को दूर करने के लिए व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में पुराने कुआँ को गहरा करना सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाने के लिए हिस्सा पूंजी अनुदान आदि कार्यक्रमों में अनुदान किया जा रहा है। माडा क्षेत्र में ग्रामीण गृह निर्माण योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इन क्षेत्रों में जो आदिवासियों छोटी छोटी परचूनी की दुकान लगाना चाहते हैं उन्हें 2000 रुपये तक का सामान दिलाना हेतु अनुदान देने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। जनजाति के लोगों को लाभपहुँचाने के उद्देश्य से 10 मिनी आई टी आई अलग-अलग जिलों में स्थापित की गई है जिनके अंतर्गत 1200 युवाओं को प्रतिवर्ष 6 माह की अवधि में परीक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें स्वयंसेवा के लिए प्रेरित किया जाता है।

(7) माडा क्लस्टर (MADA Cluster) ऐसे क्लस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जाजाति की है उनमें माडा क्लस्टर याचना लागू की गई है। राज्य के नौ जिलों में 11 माडा क्लस्टर स्वीकृत हैं। नवी योजना में क्लस्टर कार्यक्रमों हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(8) बिखरी जनजाति (Scattered Tribal Population) जाजाति उपयोजना माडा खण्डों एवं माडा क्लस्टरों के अतिरिक्त जनजाति 30 जिला में बिखरी हुई है।

(स) सहरिया आदिम जनजाति क्षेत्र Sahariya-The Most Primitive Tribal Area

राज्य की एकमात्र आदिम जाति सहरिया है जो कोटा जिले की किरानगज एवं शहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित करके सहरिया वर्ग का विकास के लिए सहरिया विकास समिति का गठन किया गया। इस क्षेत्र की जनजाति संख्या सहरिया वर्ग को सम्मिलित करते हुए 1981 की जनगणना के अनुसार 40 000 है जो वहाँ की कुल जनसंख्या का 32.84 प्रतिशत है। सहरिया जनजाति की जनसंख्या 31 000 है जो परियोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 23.52 प्रतिशत है। सहरिया विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में योजना निर्माण क्रियान्वयन दिशा-निर्देश व समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए सहरिया विकास समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष कंठा के जिलाधीश हैं और क्षेत्र के विधानसभा सदस्य लोकसभा सदस्य, सहरिया जाति के प्रतिनिधि एवं अन्य सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारों इसके सदस्य हैं। सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि लघु सिंचाई पशुपालन, वानिकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रामीण गृह निर्माण, पेयजल राजस्व रिकार्ड में सुधार कार्यक्रम पुनर्वास सहायता मुक्त कानूनी सहायता आदि सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में कृषि प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सहरिया कृषकों को कृषि आदान हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई। एनीकट के निर्माण और जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समूह डीजल पम्प सैट द्वारा कृषकों को लाभान्वित किया गया है। कृषि कुओं को गहरा कराया गया है। गुर्गापालन को प्रोत्साहित किया गया है। आश्रम छात्रावास की व्यवस्था की गई है। सहरिया विद्यार्थियों को नि शुल्क पोशाक वितरित की जाती है। समय-समय पर सहरिया संगियों को लाभान्वित करने के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता

है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गृह निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। गर्मी के मौसम में समस्याग्रस्त ग्रामों में डीप वैंल हैण्डपम्प स्विकृत किए गए। अनेक गावों में राजस्व रिकार्ड में सुधार का कार्य पूरा किया जा चुका है। सहरीया विकास क्षेत्र पर 1997 से 2002 तक 5.62 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

(द) जनजाति क्षेत्र में रेशम कीटपालन कार्यक्रम Sericulture

जनजाति क्षेत्र में लाभ के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं के साथ साथ रेशम कीटपालन कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसका महत्व निरन्तर बढ़ रहा है। क्षेत्र के आदिवासी कृषकजिनके पास भूमि है एवं सिंचाई के साधन भी सौमि हैं तो ऐसी स्थिति में उपलब्ध साधनों द्वारा पर्याप्त आम प्राप्त नहीं होती। ऐसे आदिवासी कृषक रेशम कीटपालन कार्यक्रम को अपनाकर अपने खाली समय में अतिरिक्त स्थाई आय प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण महिलाएँ जिनके पास काफी समय रहता है घर पर रहते हुए भी इस कार्यक्रम को अपना सकती हैं। राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर द्वारा कई वर्षों तक परीक्षण के बाद इस कृषि आधारित उद्योग के लिए उदयपुर बासवाड़ा डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ के जिलों की मिट्टी और जलवायु को उपयुक्त पाया गया और इन क्षेत्रों के यहाँ व्यापक रूप से आरम्भ करवाने की सिफारिश की। उपरोक्त सफल प्रशिक्षणों के आधार पर राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा समुचित महिला कल्याण कोष एवं विशेष क्षेत्रीय सहायता के आर्थिक सहयोग द्वारा रेशम कीटपालन कार्यक्रम को लघु अवधि 3 वर्षीय परियोजना के रूप में अगस्त 1983 में आरम्भ किया था और इसका कार्यक्षेत्र उदयपुर जिले की गिरवा एवं झाड़ोल पंचायत समितियों को रखा गया था। शहतूत की फसल रेशम के कीड़े को पालने के लिए आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों का शहतूत की उन्नत किस्म उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें नर्सरी लगाने में सहायता दिया जाता है। आदिवासियों को तकनीकी स्टाफ की देख रेख में 10-12 दिन तक शिशु रेशम कीटपालन का व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

उसके पश्चात् कृषकों को उनके खेतों में उपलब्ध शहतूत की पत्तियों के अनुसार इन शिशु कीटों का विवरण कर दिया जाता है। इनका पालन कर कृषक रेशम के कोये प्राप्त करते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इनके रेशम के कोयों को उचित दर पर खरीद लेता है। कृषकों की स्वच्छ वातावरण में रेशम कीटपालन करने के लिए व्यक्तिगत रेशम

कीटपालन गृह बनाने हेतु 1500 रुपये का अनुदान भी विभाग द्वारा दिया जाता है। विभाग द्वारा सिसारागा में एक रीलींग केन्द्र भी स्थापित किया गया है जो रेशम के कोये से धागा तैयार करता है। गिरवा पंचायत समिति में स्थापित यह केन्द्र गावों की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा धागा तैयार करवाता है। प्रत्येक महिला को उसके कार्य के आधार पर धागे का मूल्य दिया जाता है। रेशम कीटपालन के कार्य में बास के उपकरणों का प्रयोग होता है। इनमें टूट फूट भी बहुत होती है। इनको बाजार से क्रय करने और ठीक करवाने में काफी धन व्यय होता है। इस कारण इस मामले में आदिवासी कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपकरण निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन्हीं लोगों की सहकारी समिति बनाकर इन उपकरणों का निर्माण करवाया जाता है और इसे विभाग क्रय कर लेता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक कृषक को शहतूत की खेती रेशम कीटपालन ककून (कोपा) उत्पादन एवं बास उपकरण निर्माण आदि कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण एक माह का अवधि का होता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक कृषक को 200 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

(य) स्वच्छ परियोजना (समन्वित नारु रोग उन्मूलन परियोजना)

Clean Project

स्वच्छ परियोजना राजस्थान सरकार व यूनिसेफ का एक सम्मिलित प्रयास है। इस परियोजना हेतु स्वीडन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा आर्थिक सहायता यूनिसेफ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना हेतु राजस्थान सरकार व यूनिसेफ के सहयोग से 30 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है। यह परियोजना उपपोजना क्षेत्र के 3 जिला उदयपुर बासवाड़ा और डूंगरपुर में चल रही है। इस परियोजना का मुख्यालय उदयपुर में है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त इस परियोजना के समन्वयक हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्राविन क्षेत्र डूंगरपुर व बासवाड़ा जिलों के लिए 12 करोड़ रुपये की एक पंचवर्षीय योजना 1986 से अरम्भ की गई। उदयपुर जिले की 18 करोड़ रुपये की परियोजना को भी परियोजना क्षेत्र में 5 वर्ष की अवधि के लिए 1987 से सम्मिलित कर लिया गया। इस स्वाकृत राशि का 60 प्रतिशत भाग यूनिसेफ के माध्यम से स्वीडन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा एवं शेष 40 प्रतिशत भाग राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं एवं बालकों के स्तर में सुधार पेयजल के सम्पादन के विकास में सामुदायिक भागीदारी का विकास स्वच्छता

का नाम सशोधित कर वर्तमान में राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विवरण एवं विवास सचकारी निगम रख गया है। निगम द्वारा इस समय मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण के रूप में दो तरह की योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति

सविधान क अनुच्छेद 46 में राज्य सरकार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को उत्थान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्र के विकास एवं जनजाति परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु आधारभूत रूपरेखा तय की गई थी। क्षेत्रीय आधार पर जनजाति स्वास्थ्य क्षेत्रों का मूल आधारभूत रूपरेखा वर्ष 1974-75 में जनजाति क्षेत्रीय उपयोगिता बनाने समय निर्धारित की गई थी। जनजातियों में मुख्य रूप से भूल भण्डा गणसिपा डानार एवं कपोडों राजस्थान में निवास करने हैं। घोंघिन उपर्योजना क्षेत्र में वासवाडा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर एवं सिरोही की कुल 23 पंचायत हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनजातियों की संख्या 54.75 लाख है जिसमें से 24.01 लाख व्यक्ति जनजाति उपयोगिता क्षेत्र में निवास करते हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा जनजातियों के विकास आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान से सम्बन्धित विभिन्न विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों हेतु नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में 167.92 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है।

जनजाति उपयोगिता क्षेत्र में स्थानांतरित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घण्टी श्रेणी कर्मचारी वनपाल सिपाही कनिष्ठ लिपिक अध्यापक एवं वाहन चालक के पदों पर भर्ती हेतु 45% पदों का आक्षण किया गया है। 'नाम' उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत दामवाडा जिले को पूरा रूप से नाम रोगमुक्त घोषित किया जा चुका है तथा यह आशा की जाती है कि डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले को भी इस रोग से शीघ्र मुक्ति मिल सकेगी।

मरु विकास कार्यक्रम

DESERT DEVELOPMENT PROGRAMME

पृष्ठभूमि व उद्देश्य

Background & Objects

राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में आरम्भ किया गया। यह वन्द्य प्रवर्तिन योजना के रूप में

श्री एनिसन केन्द्रीय महायन्त्रों के आधार पर आरम्भ हुआ। 1979-80 में इस वित्तीय सहायता का आधार बदलकर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर की राशि देने का प्रवधान रखा गया। 1985-86 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनः इस शत प्रतिशत सहायता दी जाने लगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण का सुधारना उपलब्ध ससाधनों को आर्थिक विकास के लिए अधिकतम उपयोग कराना तथा रोजगार के मुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। यह कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान के 16 रेगिस्तानी जिले अजमेर जयपुर सिरोही राजसमंद उदयपुर जोधपुर जैसलमेर जालौर सुन्तलु बीकानेर बाडमेर चुरू पानी साकर नागौर तथा गणानगर जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है।

राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग मरुस्थल है। मरु में ऐसा कोई दुर्गम मरुस्थल नहीं है जहाँ राजस्थान के थार मरुस्थल जिला सख्य में मनुष्य व पशु रहते हैं। एस मरुस्थल के विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना बनाई गई है। 1974-75 में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के नाम से राज्य के 9 जिलों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। ये 9 जिले थे—जोधपुर नागौर पाला जालौर बाडमेर जैसलमेर बीकानेर चुरू व सुन्तलु। 1977-78 में इस क्षेत्र में विनामों की गति को ध्यान में रखकर आवश्यक समझा गया। अंत 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ जिसमें उपरोक्त 9 जिलों के अतिरिक्त गणानगर व सीकर जिलों को भी सम्मिलित कर लिया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रामाण विकास अधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मरु जिला पर व्यय			
[आरम्भ 1974-75 से 1996-97 तक]			
(करोड़ रुपये में)			
(अ)	प्राथमिक पंचवर्षीय योजना		
(1)	सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	1974-75 से 1979-80	37.27
(11)	मरु विकास कार्यक्रम	1978-79 से 1979-80	17.31
(ब)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना		
(1)	सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	1980-81 से 1984-82	15.97
(11)	मरु विकास कार्यक्रम	1980-81 से 1984-85	55.33
(स)	सातवें योजना		
	मरु विकास कार्यक्रम	1985-86 से 1999-90	145.45
(द)	वाष्पिक योजनाएँ		
	मरु विकास कार्यक्रम	1990-91 से 1991-92	46.80
	मरु विकास कार्यक्रम	1991-92	36.58

(घ) आठवीं योजना			
मरू विकास कार्यक्रम	1992-93	36.47	
मरू विकास कार्यक्रम	1996-97	14.46	
(दिसम्बर 1996)			
(र) नवीं योजना			
सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम	1997-2002	46.50	
(प्रावधान)			
मरू विकास कार्यक्रम	1997-2002	669.75	
(प्रावधान)			
स्रोत: Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Raj			

मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में तक हुई भौतिक उपलब्धियों का मदवार विवरण			
क्र.सं.	मद	इकाई	प्राप्ति
1	भू. संरक्षण	हैक्टेयर	12283
2	जल सन्निधान-(अ) मिर्चाई	हैक्टेयर	1597
3	वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास-(अ) वृक्षारोपण	हैक्टेयर	10666
4	अन्य कार्य-(अ) खली-कोठे/पौण्ड/टैंक निर्माण सज्या		752+1032
स्रोत: Desert Development Programme Annual Plan 1993-94 & 1994-95			

विभिन्न कार्यक्रम

Various Programmes

मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण, भू-गर्भ जलदोहन विद्युतीकरण, सिंचाई भेड एवं चरागाह विकास, मरू क्षेत्र में वृक्षारोपण, पशु एवं दुग्ध मार्गों का सुधार, पशु स्वास्थ्य आदि कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इन कार्यक्रमों का सक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है -

(1) कृषि (Agriculture) इस मरूस्थलीय क्षेत्र में 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसे हुए हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। इस मरूप्रदेश में सामान्यतः एक फसल ली जाती है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा कम होने के कारण यह आवश्यक है कि उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग किया जाए। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये भू. संरक्षण का कार्य तथा भू-सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया। पानी का सदुपयोग करने के लिए फव्वारे मेंट वितरित किए गए। मिट्टी को जाच करने के लिए परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए जो कृषकों को उनकी कृषि भूमि में उपयोग में आने वाले उर्वरकों का ज्ञान कराते हैं और लवणीय तथा क्षारीय भूमि के दोषों को दूर करने का उपाय बताते हैं।

(2) भू जल दोहन (Use of Ground Water) इस

मरू प्रदेश में जल की समस्या एक प्रमुख समस्या है। यदि इस क्षेत्र में जल उपलब्ध हो जाए तो अधिकांश समस्याओं का निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, पेयजल और कृषि के लिए भू-गर्भ में छिपी जल सम्पदा का पता लगाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया। इस हेतु आवश्यकतानुसार नलकूपों का निर्माण भी किया गया। ये नलकूप सिंचाई के साथ-साथ पेयजल भी उपलब्ध कराते हैं। भू-गर्भ में छिपी जल का विम्वृत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। मरूप्रदेश की एकमात्र नदी लूनी के सहारे-सहारे परीक्षण और सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिए गए हैं।

(3) वन सम्पदा का विकास (Development of Forest) मरू प्रदेश के खेतों पर खेजड़ी, जाल, बबूल, रोहिडा, बेर आदि के वृक्ष लगाने की परम्परा रही है। दुर्भाग्य से उनको के 15 प्रतिशत भाग पर ही वन रह गए हैं। अतः बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए वन विभाग क्रियाशील है। इन जिलों में स्थान-स्थान पर वन व चरागाह विकास के कार्य हाथ में लिए गए हैं। मुख्य रूप से गांवों के जंगल, जलाऊ लकड़ी, वन पौधशालाएँ, टीलो का स्थिरीकरण, सहकों के किनारे वृक्ष लगाना आदि कार्य हाथ में लिए गए हैं। कृषकों को उनकी निजी भूमि पर छायादार एवं फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(4) दुग्ध विकास (Dairy Development) राजस्थान के मरू क्षेत्र में पशुधन के रख-रखाव को वैज्ञानिक रूप देने और व्यावसायिक दृष्टि से दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करने के लिए दुग्ध विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इसके अन्तर्गत अच्छी नस्ल के पशु खरीदना, सन्तुलित पशु आहार उपलब्ध करवाना, दुग्ध संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध सहकारी संघों को प्रोत्साहित करना, आदि प्रमुख कार्य हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में दुग्ध विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(5) भेड़ विकास (Sheep Development) भेड़ व चरागाह विकास, इस कार्यक्रम को एक प्रमुख योजना है। इस मरू क्षेत्र में भेड़ें काफी अधिक मात्रा में हैं जो कि कुल पशुओं का लगभग 30 प्रतिशत हैं। इसलिए भेड़ विकास कार्यक्रम को समुचित महत्व दिया गया। इस कार्यक्रम में भेड़ों के रख-रखाव, चारे की व्यवस्था, नस्ल सुधार आदि कार्य हाथ में लिए गए हैं। भेड़ व चरागाह विकास खण्ड स्थापित किए गए हैं। सहकारी समिति इन खण्डों की देखभाल करती है। इन खण्डों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भेड़ों का रख-रखाव किया जा रहा है। भेड़-पालकों को यह प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि वे भेड़ों को किस प्रकार से रखें तथा इसी की व्यवस्था के रूप में अपनाएं।

(6) पशु स्वास्थ्य (Animal Health) मरू क्षेत्र में

पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। प्रत्येक परिवार में जितने सदस्य हैं प्रायः उतनी ही मछली में पशुधन भी है। इस पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल को आवश्यक मानते हुए इसे कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि प्रति 20,000 पशुओं पर एक स्वास्थ्य केन्द्र हो। इस हेतु नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। पशु चिकित्सालय इकाइया आरम्भ की गई हैं। रेगिस्तान में ऊट का विशेष महत्व है। अतः इसकी देखभाल एवं रोग नियन्त्रण के लिए इकाइया स्थापित की गई हैं। गौ-शुल्लों को पशु क्रय करने, चारे व पानी की उत्तम व्यवस्था करने, आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

(7) सिंचाई (Irrigation) रेगिस्तान में सिंचाई की कल्पना करना एक अद्भुत बात है। इस कार्यक्रम में तालाबों और जल संधियों के अभाव के कारण वर्षा के जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए छोटे-छोटे तालाब बांध व एनीकट बनाकर जल का पूरा उपयोग करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटी एवं मध्यम श्रेणी की योजनाएँ पूरी की गई।

(8) विद्युतीकरण (Electrification) जब भूगर्भ के जल का पता लगा लिया जाता है तो उस जल को प्राप्त करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। सामान्यतः एक नलकूप की गहराई 200 मीटर होती है। परम्परागत कुएँ भी 100 से 200 मीटर गहरे होते हैं। इन कुओं से पानी निकालना अत्यन्त कठिन कार्य है किन्तु मनुष्य को इसे सुलभ करना भी निरन्तर आवश्यक है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मह विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण का योजना को हाथ में लिया गया। इस क्षेत्र में विद्युत की स्थिति दयनीय थी। इसलिए अब गाँवों में बिजली पहुँचाई जा रही है ताकि विकास की गति तीव्र हो सके। घरेलू उद्योग धन्धों को बिजली मिल सके और साथ ही पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

(9) ग्रामीण जलप्रदाय योजना (Rural Water Supply Projects) मरु जिलों में बहुत कम गाँवों में पेयजल उपलब्ध था। शायद गाँव समस्याग्रस्त गाँव थे। इन क्षेत्रों में वर्षा आने पर ही पेयजल उपलब्ध हो जाता था और वर्षा न आने पर नलकूप खोदें जाते थे तथा टैंकरो से पानी भिजवाया जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण पेयजल योजना आरम्भ की गई है।

(10) दूध मार्गों का सुधार (Improvement of Dairy Routes) - ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने का एकमात्र साधन सड़क है किन्तु इस मरुप्रदेश में सड़कें भी बहुत कम हैं। दूध को एकत्रित करके अवशीतन केन्द्रों तक पहुँचाने के लिए सड़क के छोटे-छोटे टुकड़े बनाए गए हैं ताकि दूध बिना छराव हुए अवशीतन केन्द्र तक पहुँच जाए। यह कार्यक्रम अभी भी जारी है।

(11) राष्ट्रीय मरु उद्यान (National Desert Garden) राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करने की योजना है। इसमें नैसर्गिक वनस्पति को सुरक्षित रखना, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना और करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के भूगर्भ में दबे हुये जीवाणु अवशेषों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2.47 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए योजना बनाई गई है।

कार्यक्रम की प्रगति

PROGRESS

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से वन विकास, भू-जल विकास तथा सिंचाई पशु स्वास्थ्य, भेड़ विकास, जल प्रदाय एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जाता था। लेकिन सातवीं योजनावधि के वर्ष 1987-88 से केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विकास एवं आर्द्रता संरक्षण, जल संधियों का विकास वन व चरागाह विकास एवं पशु जल प्रदाय योजनाएँ भी स्वीकृत की हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का 15 प्रतिशत भू-संरक्षण कार्यों पर व्यय किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राशि सम्पूर्ण व्यय हेतु दी जाती है। कार्यक्रम के आरम्भ से छठी योजना तक, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 125.90 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 147.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 148.48 करोड़ रुपये व्यय किए गए। सातवीं योजनावधि में 42.637 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण का कार्य 10,367 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सूजन, 68,443 हैक्टेयर क्षेत्र में वन एवं चरागाह विकास आदि तथा 4926 अन्य कार्य कराए गए। मरु विकास कार्यक्रम जो शत-प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है, के अन्तर्गत नवी योजना 1997-2002 के लिए 66975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

DROUGHT PRONE AREA PROGRAMME

राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 से आरम्भ किया गया। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान व आठ जिलों जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, दूधर तथा दक्षिणी राजस्थान के झुंझारु तथा ताम्बाड़ा क्षेत्रों में आरम्भ किया गया। इस

कार्यक्रम को धीरे धीरे 13 जिलों के 79 विकास खण्डों में विस्तृत कर दिया गया। जिन तीन जिलों को इस कार्यक्रम में ओर सम्मिलित किया गया वे हैं - अजमेर, बुझमु व जयपुर। 1982-83 में भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिश के आधार पर रेगिस्तानी क्षेत्र में 9 जिला के 11 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के 4 जिलों - नासवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा अजमेर के 18 विकास खण्डों में ही यह कार्यक्रम जारी है। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 1985-86 से राजस्थान के चार नये जिलों के 12 विकास खण्डों में इस कार्यक्रम को आरंभ करने की केन्द्रीय स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1985-86 से यह कार्यक्रम राजस्थान के आठ जिलों क्रमशः अजमेर नासवाडा उदयपुर कोटा, डूंगरपुर, टोंक, सवाई माधोपुर व झालावाड में 30 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा था। 1995-96 में यह कार्यक्रम 10 जिलों के 32 विकास खण्डों में चल रहा है।

सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से विकास कार्य करना है जिसमें सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य रूप से कृषि वन विकास भू जल विकास, लघु सिंचाई, पशुस्वास्थ्य भेड विकास पशु जलप्रदाय एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को क्रियान्वित किया जाता था। 1987-88 के केन्द्र सरकार ने भूमि विकास तथा आर्द्रता संरक्षण, जल संसाधनों का दिवाम वन एवं चरागाह विकास तथा पशु जलप्रदाय कार्यों को क्रियान्वयन की ही स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं -

1 भू-संरक्षण कार्य (Land Conservation Work)- सातवीं योजना में 21471 हेक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण का कार्य किया गया।

1991-92 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 4755 हेक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वास्तव में दिसम्बर 1991 तक 3104 हेक्टेयर क्षेत्र में ही भू-संरक्षण कार्य सम्पन्न किये गये। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका।

2 सिंचाई क्षमता सृजन (Generating Irrigation)- सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2398 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई क्षमता सृजन की गई।

1991-92 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 1681 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन वास्तव में दिसम्बर 1991 तक 465 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई कार्य सम्पन्न किये गये।

3 वृक्षारोपण (Plantation) - सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 10918 हेक्टेयर क्षेत्र में वन एवं चरागाह विकास का कार्य किया गया।

1991-92 में राज्य के विभिन्न जिलों में 4196 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया लेकिन वास्तव में दिसम्बर, 1991 तक 3466 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किये गये।

4 अन्य कार्यक्रम (Other Programmes) - सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 1516 अन्य कार्य भी सम्पन्न किये गये जिनमें गांवों का विद्युतीकरण, छेतियों का निर्माण, कुओं का विद्युतीकरण आदि कार्य सम्मिलित हैं।

1997-98 में सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया

- भूमि के मानगिर बनाने की योजनाएं और मिट्टी के संरक्षण की योजनाएं
- जल स्रोतों का विकास
- वनीकरण
- पशुओं के लिये जल की व्यवस्था मत्स्य एवं चारा विकास

प्रोफेसर हनुमन् राण की अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार जलसंयोजन विकास के लिये अप्रैल 1995 में प्रत्येक ग्राम की लगभग 500 हेक्टेयर भूमि के लिये चरणबद्ध रूप में क्षेत्रों की व्यवस्था की जायेगी।

5 वित्तीय प्रावधान (Financial Provisions) - सातवीं योजनावधि में सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिये 2288 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे किन्तु वास्तव में 2378 करोड़ रुपये व्यय हुये। सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना में दिसम्बर, 1996 तक नये कार्य पर 135 करोड़ रुपये व्यय किये गये। यह कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जो 50 प्रतिशत केन्द्र एवं 50 प्रतिशत राज्य की सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। 1997 से 2002 तक के लिये राज्य द्वारा 465 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है।

अन्त्योदय योजना

ANTYODAYA YOJNA

राज्य के साधन और स्रोतों का लाभ निर्धनता के अधिकारे छोर पर बैठे व्यक्तियों को देने के लिये 'अन्त्योदय' योजना का शुभारम्भ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती 2 अक्टूबर 1990 से राज्य भर में पुनः शुरू किया गया है।

अन्त्योदय योजना राजस्थान में पूर्व में वर्ष 1977 से 1980 में भी क्रियान्वित की गई थी। पूर्व में योजना के आशतीत परिणामों को ध्यान में रखते हुये इस बार पुन सरकार ने इस योजना को परिष्कृत और परिमार्जित रूप से लागू किया है।

उद्देश्य

Objects

अन्त्योदय कार्यक्रम का मुख्य ध्येय निर्धनों में भी निर्धनतम व्यक्ति को रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध करवा कर उसे अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाना है। इस योजना की सफल क्रियान्विति के लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि वे सभी सरकारी विभाग जिसकी योजनाओं का लाभ ग्रामीण परिवारों को मिलना है, वे यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनकी योजनाओं का लाभ अन्त्योदयी परिवारों को प्रथम प्राथमिकता में मिले। अन्त्योदय कार्यक्रम का लाभ चयनित अन्त्योदयी परिवारों को ही मिल रहा है यह देखने के लिए सभी विभाग नोडल अधिकारी भी मनोनीत करते हैं।

चयन के मानदण्ड

Standards of Selection

अन्त्योदय परिवारों का चयन पांच श्रेणियों में किया जायेगा

प्रथम श्रेणी

- भूमिहीन परिवार जिनके पास पशु व अन्य आय के कोई साधन न हों।
- परिवार में 15 से 59 वर्ष की आयु का कमाने वाला कोई व्यक्ति न हो एवं
- अशक्त, अपंग अथवा वृद्धावस्था के कारण जो परिवार जीवनयापन की स्थिति में नहीं है।

द्वितीय श्रेणी

- भूमिहीन परिवार जिनके पास पशु व अन्य आय के कोई साधन न हों, एवं
- परिवार में एक या अधिक कमाने योग्य व्यक्ति है किन्तु वार्षिक आय सभी भोजों से 2 250 रूपय में कम है।

तृतीय श्रेणी

- ऐसे परिवार जो लघु कृषक के लिए निर्धारित जोत कर सीमा तक भूमिधारक है किन्तु उनकी कुल वार्षिक आय 3 500 रूपय से कम है।

चतुर्थ श्रेणी

- ऐसे परिवार जिन्हें पूर्व में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के तहत लाभान्वित किया

जा चुका है एवं जो ससाधन इन्हें दिलाये गये हैं, से सुदृढ़-दुर्द उल्लेख किये गये हैं व परिवार की कुल वार्षिक आय 3 500 रूपय से कम है।

पंचम श्रेणी.

- ऐसे परिवार जो लघु कृषक के लिए निर्धारित जोत की सीमा तक भूमिधारक है किन्तु उनकी कुल वार्षिक आय 3 500 से 4,800 रूपय के बीच है।

चयन की प्राथमिकता व संख्या

Preference in Selection & Number

परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। प्रथम श्रेणी के परिवार चयनित होंगे एवं स्थान उपलब्ध होने पर ही क्रमशः द्वितीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के परिवार चुने जायेंगे। साधारणतया पाचवी श्रेणी के परिवार चुनने से पहले यह विशेष रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रथम चार श्रेणियों का कोई परिवार नहीं बचा है।

ऊपर बताई गई श्रेणियों में विधवा परिवार एवं वेशहारा लोगों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित एवं लाभान्वित किया जायगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के हितों का विशेष ध्यान रखा जाये।

चयनित परिवारों की संख्या ग्राम की जनसंख्या पर आधारित होगी।

जनसंख्या	चयनित परिवारों आरक्षित सूची में परिवार की संख्या	की संख्या
500 से कम	3	2
501 से 1000	5	2
1001 से 2000	7	3
2001 से ऊपर	10	5

प्रथम चयन में केवल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से चयनित परिवार लाभान्वित नहीं हो सक तो अर्हकित सूची के परिवार को चयनित परिवार के स्थान पर लाभान्वित किया जायेगा।

परिवारों का प्राथमिक चयन

Primary Selection of Families

सबसे पहले सर्वोच्च एटर्नरी राजस्व रिकार्ड के आधार पर गांव के लाल में जम्बकारी प्रत्येक घर चयनित होने योग्य परिवारों की श्रेणीवार नामांकित सूची बनायेंगे। इन प्राथमिक सूची में सम्मिलित परिवारों का संख्या चयनित आरक्षित सूची के परिवारों से तुलना होगा। उदाहरणार्थ, 100 को जनसंख्या

वाले ग्राम के लिये प्राथमिक सूची दस परिवारों की होगी। किन्तु दस परिवार यदि उपलब्ध न हों तो सूची कम मख्या की होगी। प्राथमिक सूची ग्राम सभा की बैठक के दस दिन पहले पटवारी द्वारा विकास अधिकारी एवं मरपव को उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम सभा की बैठक

Meetings of Gram Sabha

ग्राम सभा की बैठक जिला कलेक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुलाई जायेगी। निश्चित तिथि की सूचना 15 दिन पूर्व गांव में डोंडी पिटवाकर करा दी जायेगी एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड व मुख्य स्थानों पर भी नोटिस लगवाये जायेंगे। ग्राम सभा में सबंधित सासद, विधायक, प्रमुख व मरपव भी आमंत्रित किये जायेंगे। इन्हें भी 15 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।

बैठक बुलाने के समय से दो घंटे पहले भी गांव में डोंडी पिटवाकर गांव वालों को बैठक में भाग लेने के लिये निमंत्रण दिया जायेगा।

ग्राम सभा की बैठक में ग्रामवासियों व जन-प्रतिनिधियों के अलावा विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, तहसीलदार नायब तहसीलदार आदि अधिकारियों में से कम से कम एक अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सबंधित उपखण्ड अधिकारी इस व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होंगे।

ग्राम सभा द्वारा चयन

Selection by Gram Sabha

ग्राम सभा की बैठक में गांव के पटवारी चयन के लिये निर्धारित मापदण्डों को पढ़कर सुनायेंगे। पटवारी द्वारा तैयार की गई प्राथमिक सूची की पूर्ण जानकारी भी ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई जायेगी। ग्राम सभा में प्राथमिक सूचना पर चर्चा के बाद निर्धारित संख्या में अन्त्योदय परिवारों व आरक्षित सूची का चयन किया जायेगा।

यदि ग्राम सभा का यह मत है कि कोई परिवार चयन के लिए पूर्ण रूप से योग्य है किन्तु प्राथमिक सूची में उसका नाम छूट गया है तो ऐसे परिवार का चयन भी किया जा सकेगा। इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को अंतिम माना जायेगा।

अन्त्योदय परिवारों के विकल्प

Alternatives

अन्त्योदय परिवारों के चयन के पश्चात् ग्राम सभा की बैठक में पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा अन्त्योदय योजना में दिये जाने वाली सहायता का विवरण दिया जायेगा। चयनित

परिवारों के मुखियाओं से सलाह करने के बाद उनके विकल्प प्राप्त कर लिये जायेंगे एवं इसी आधार पर अग्रिम योजना बनाई जायेगी। बाद में यदि विकल्प के अनुसार परिवार को लाभान्वित करना संभव न हो तो परिवार की राय से विकास अधिकारी द्वारा विकल्प में उपयुक्त परिवर्तन किया जायेगा।

ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण

Minutes of Gram Sabha

ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण सबंधित पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा मौक पर मौजूद सभी लोगों के सामने लिखा जायेगा और ग्राम सभा में मौजूद सभी ग्रामवासियों, जन प्रतिनिधियों व प्रभारी अधिकारियों के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। ग्राम सभा की कार्यवाही के विवरण को विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जायेगा और उसकी सही प्रति को गांव रसीद लेकर उसे ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जायेगा। पटवारी द्वारा ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के साथ गांव के सबंध में परिशिष्ट-2 में वर्णित सूचनाएं और चयनित परिवारों की परिशिष्ट-3 में वर्णित सूचनाएं तैयार कर विनाम अधिकारियों को बैठक की तारीख से 7 दिन में भेजी जायेगी।

विकास अधिकारी द्वारा सूचना का सकलन

Collection of information by B.D.O

चयनित परिवारों की सूचना के आधार पर परिशिष्ट-4 (क) व (ख) के अनुसार रजिस्टर पंचायत समिति द्वारा संचालित किया जायेगा और उसके पूरा रखने की जिम्मेदारी सबंधित विकास अधिकारी की होगी। इस रजिस्टर में चयनित परिवारों के सबंध में दी गई आर्थिक सहायता और उसके बाद प्रगति के सबंध में जानकारी होगी। परिवारों की सहायता के लिये जो विकल्प प्राप्त हुये हैं उनके आधार पर परिशिष्ट-5 (क) व (ख) के अनुसार योजना तैयार की जायेगी और चयन की तारीख के एक माह के भीतर जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को भेजना होगा। विकास अधिकारी द्वारा चयनित परिवारों की सूचना (परिशिष्ट-6) के अनुसार तैयार कर सबंधित दैवों, विभागों एवं जि.प्र.वि. अधिकरण को भेजी जायेंगी।

परिचय-पत्र

Identity Card

सभी चयनित परिवारों को एक परिचय-पत्र दिया जायेगा। यह परिचय-पत्र ग्राम सभा में चयन का कार्य पूर्ण होने के दो माह के अंदर वितरित करने की जिम्मेदारी सबंधित विकास अधिकारी की होगी। इस कार्य के लिये ग्राम सेवक और

पटवारी को सहायता ली जायेगी।

चयन की जिम्मेदारी

Responsibility of Selection

अन्त्योदय परिवारों के चयन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की होगी। सभी गावों में चयन के लिए विस्तृत कार्यक्रम कलेक्टर बनायेंगे एवं उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रसार अधिकारी, गिन्दावर, पटवारी व ग्राम जेबक इस कार्यक्रम को सम्पादित करावेंगे। यह सम्मेलन व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

साथ ही जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं अन्य समकक्ष अधिकारीगण ग्राम सभा की कम से कम 5 प्रतिशत बैठकों में स्वयं भाग लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन सही रूप से हो रहा है। जिला कलेक्टर एवं उपरोक्त प्रत्येक अधिकारी कम से कम 10 ग्राम सभा की बैठकों में इस प्रकार भाग लेंगे।

प्रत्येक अधिकारी के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 7 पर उपलब्ध है।

उपसंहार

Conclusion

अन्त्योदय योजना के मुख्य बिन्दुओं का ऊपर उल्लेख किया गया है। जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसकी क्रियाविति निश्चित तिथि तक हो, यह दायित्व शीवे से लेकर ऊपर तक उन सबका है, जो इस योजना का लाभ निर्धन वर्गों तक पहुंचाने के लिए इनसे जुड़े हैं। यह कार्यक्रम सामाजिक प्रतिबद्धता का कार्यक्रम है। इसकी सफल क्रियाविति प्रशासन की सवेदनशीलता का प्रदिबिम्ब होगी। इसकी प्रगति हर स्तर पर गंभीरता से होनी चाहिये।

अन्त्योदय चयन प्रक्रिया के अतर्गत विभिन्न

स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के कर्तव्य

Duties of Officials

1 कलेक्टर (Collector)

1 चयन प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित निर्देशानुसार अपने जिले में यह कार्य समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करने हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना।

2 चयन दौर के प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजस्व / विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर क्षेत्रों का विभाजन करना।

3 क्षेत्रीय पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के सम्मेलन पटवारी/ग्राम सेवकों की चयन तिथि से 10 दिन पूर्व बुलाई जाने वाली बैठकों का पर्यवेक्षण करना।

4 चयन प्रक्रिया के दौरान समस्त जिले में कार्यरत अधिकारियों द्वारा पूर्व निश्चित कार्यक्रमानुसार सभी सभाओं की बैठकों की चयन कार्य सम्पन्न कराये जाने की पूर्णरूपेण देख-रेख करना।

5 चयनोपरान्त सम्मेलन संधिगत क्षेत्रीय अधिकारियों/ विकास अधिकारियों से चयनित परिवारों की पूर्ण सूची मय खण्ड-स्तरीय प्रयोजनवार योजनाओं के लिए एकत्रित करना।

6 एकत्रित सूचियों व खण्डस्तरीय प्रयोजनवार योजनाओं के आधार पर जिलामुखीय योजना बनाकर जिला प्रांतीय विकास अधिकरण में अनुमोदित करवाना एवं विशिष्ट योजना संगठन को समय पर प्रेषित करना।

II उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer)

1 अपने क्षेत्र के समस्त ग्रामों के निर्धारित कार्यक्रमानुसार ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित करवाने एवं अधीनस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जिलाधीश के निर्देशानुसार विकास प्रसार अधिकारियों के बीच एवं ग्राम सभाओं की बैठकें भी भाग लेने हेतु उपक्षेत्र आवंटित करना।

2 ग्राम सभाओं की बैठकों की तिथियां तय करवाकर संधिगत विकास अधिकारी से विधिबद्ध नोटिस जारी करवाना।

3 ग्राम सभाओं के निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजन का पूर्ण पर्यवेक्षण करना एवं सभी बैठकें निश्चित समय पर सम्पन्न कराना।

4 ग्राम सभाओं की बैठकों का स्वयं भी मौके पर निरीक्षण करना।

5 बैठकों में चयनित व्यक्तियों की सूचियां, मय निर्धारित प्रपत्रों में रूचनाएँ एकत्रित करवाकर विकास अधिकारियों को निर्धारित समय में भेजने के लिए अधीनस्थ स्टाफ के पाबंद लगाना।

III विकास अधिकारी (B D O)

1 जिलाधीश के निर्देशानुसार आवंटित क्षेत्र के चयन का पर्यवेक्षण/संचालन करवाना एवं अधीनस्थ प्रसार अधिकारियों को उन्हें आवंटित क्षेत्र में चयन कार्य सम्पन्न करने हेतु पाबंद करना।

2 उप खण्ड अधिकारी/ तहसीलदार के परामर्श से नोटिस जारी कर अपने अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त ग्रामों की ग्राम सभाएं आयोजित करना।

3 ग्राम सभाओं में चयनित परिवारों की सूचियां एवं वक्तव्यों

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान ने उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की है और राजस्थान का स्थान देश के अग्रणी देशों में रहा है।

अरावली विकास

ARAVALI DEVELOPMENT

भारत की पाचवीं पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्र के विकास को एक योजना केन्द्रीय क्षेत्र के अतर्गत आरम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण का विकास, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना था। यह कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

वर्तमान में यह योजना 3 क्षेत्रों में सम्मिलित करती है-

- (1) हिमालय व अन्य पहाड़ी क्षेत्र (2) पश्चिमी घाट (3) नीलगिरी

राजस्थान सरकार, अरावली पहाड़ी क्षेत्र को भी इस योजना में सम्मिलित करने का आग्रह करती रही। 1986 में योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। इस दल के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान में अरावली पर्वत क्षेत्र के कुछ भागों को पहाड़ी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित करने योग्य माना गया। अरावली पर्वत श्रृंखला का राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं उड़ीसा के लिए विशेष महत्व है। यह जल के वितरण व रेगिस्तान के प्रसार को रोकने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृंखला में पहले काफी घने जंगल थे। उसमें बड़े-बड़े पेड़ों के साथ वन्य जीवन भी बहुतायत में पाये जाते थे। इस क्षेत्र में वनों के विनाश ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पिछले कुछ दशकों में मानव एवं पशुओं के बढ़त दबाव, वन विनाश, खनन कार्य, जलवहन की लागत पर कटौती आदि विभिन्न निर्माण कार्य के प्रसार से पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हानि, अरावली क्षेत्र में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार धार के रेगिस्तान को उत्तर-पूर्व में गंगा के मैदान की ओर बढ़ने से रोकने, राष्ट्रीय वन नीति के अतर्गत पहाड़ियों पर पुनर्स्थापना राजस्थान के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वन विनाश और भूमि के क्षय को रोककर अरावली क्षेत्र में पहाड़ियों के चट्टानी क्षेत्र को बाहर निकालने से रोकने, पहाड़ी क्षेत्र में परिस्थितिकी स्थिरता को बरकरार रखने एवं दक्षिणी अरावली जनजाति क्षेत्र में रह रहे जनजातियों को संरक्षण देने हेतु अरावली क्षेत्र का विकास

आवश्यक हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र के राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अतर्गत अरावली पर्वत क्षेत्र के 41447 वर्ग किलोमीटर भाग को सम्मिलित किया गया है। यह क्षेत्र 16 जिलों के 120 खण्डों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 1178 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, उन अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है, जिनका ढाल 30% से कम है। इस प्रकार अरावली पर्वत का मुख्य क्षेत्र तो लगभग 29661 वर्ग किलोमीटर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिये निम्नांकित सुझावों के आधार पर कदम उठाये गये -

1. ममस्त परिस्थितिकी क्षेत्र के समन्वित विकास के प्रयास करना। इसमें स्थानीय स्रोत और विकसित सभावनाओं को भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

2. यह विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के सदर्भ को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना चाहिये।

3. इस क्षेत्र के विकास के लिए वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

4. भू एवं जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

5. ईंधन व चारे की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे पेड़ लगाने चाहिये जो इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दें।

6. वनों पर बढ़ते हुए दबाव को दृष्टिगत रखते हुये ईंधन के वैकल्पिक साधनों का विकास किया जाना चाहिये।

7. उद्यान के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

8. क्षेत्र में चारे की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुये पशु पालन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9. अरावली पर्वत क्षेत्र में विद्यमान कम ऊँचे क्षेत्रों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे रेगिस्तान को रोका जाना चाहिये।

10. बजर एवं बेकार भूमि विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिये।

11. जिन समुदायों के लाभ के लिये यह कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, उनका सक्रिय सहयोग इस कार्यक्रम में प्राप्त किया जाना चाहिये। अरावली पर्वत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, भिन्न-भिन्न जलवायु दशाओं, आधारभूत सुविधाएँ जुटाने की ऊँची लागत एवं इस क्षेत्र में निवास कर रहे विभिन्न समुदायों के भिन्न-भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुरूप अरावली विकास के कार्यक्रमों का सुझाव दिया है। योजना-आयोग के कार्यालयी दल ने राज्य सरकार का यह सुझाव

मान लिया है कि अगवली क्षेत्र को राष्ट्रीय पहाड़ी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाये। दल ने यह सिफारिश भी की है कि वृक्षारोपण, भूमि एवं जलमयोजन आदि कार्यक्रमों पर अरावली क्षेत्र में जो भी व्यय होगा उसे राज्य एवं केंद्र सरकारों 1:3 में वहन करेंगी। जय के इस भार के लिए योजना आयोग और राजस्थान सरकार विचार कर रही हैं। अखिल भारतीय किसान हार्दिक के ब्रिजान्वयन एवं समन्वय के लिए वन विभाग मुख्य भूमिका निभायेगा। आठवीं योजना में राजस्थान सरकार ने अगवली क्षेत्र विकास हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था किंतु राज्य सरकार का व्यय का अंश लिया जा सके। परियोजना को दशोचित कर इसकी समयावधि 1999 तक बढ़ा दी गई है। 1998-99 में 26600 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना

MEWAT REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT

राजस्थान सरकार ने फरवरी 1987 में अलवर और भरतपुर जिला के मेवात क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य से मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की। इन मेवात क्षेत्रों में अलवर जिले की सात पंचायत समितियाँ, तिलाग रामगढ़, किसानगढ़, लखनगढ़, मंडावर, उमरैन, कदमर और भरतपुर जिले की तीन पंचायत समितियाँ कामा नगर डोम सम्मिलित हैं। यह कार्यक्रम जिला प्रामाण विकास एजेंसियाँ द्वारा प्रियन्वित किया जा रहा है। इन मेवात क्षेत्रों में मेवा समुदाय के लोगों के विकास हेतु आठवीं योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना का आठवीं योजना के व्यय	
प्रकार	प्रावधान (लाख रुपये में)
सड़क निर्माण	188.70
ग्रामार्ड	87.10
पेयजल	66.75
शिक्षा	14.00
पर्यावरण	12.70
निजित्वा एवं स्वास्थ्य	32.00
विशेष	11.90
सह-सहायता	17.45
दल व विभाग	4.40
प्रशासन	35.00
कुल	400.00

स्रोत: Eighth Five Year Plan 1982-87 Raj

इस योजना में मिनीकूट का वितरण उद्यान का निजाम दवाईये आदि का वितरण लक्ष्य में लिया गया। पशुपालन हेतु निजिनों का आयोजन किया गया। सार्वजनिक निजित्वा केंद्रों में आर्थिक कमरे का निर्माण किया गया। विद्यार्थियों को पुस्तकें व वर्दी नि शुल्क वितरित की गई। स्व-मेजदार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान था। साथ ही एक लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित थी। मेवात विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मत बहुल क्षेत्रों पर दिसम्बर 1997 तक 2.59 करोड़ रुपये का राशि व्यय की गई।

कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

COMMAND AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सृजित क्षमता और उसके उपयोग के अंतर को कम करना है। ऐसा सिंचित क्षेत्रों में समन्वित विकास के माध्यम से ही संभव है। इसके अंतर्गत मिट्टी, भू-उपयोग, जल प्रबंध आदि को नियोजित कर उत्पादकता में वृद्धि करता है। राजस्थान में 1974 में 'गुमल एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना' के कमान्ड क्षेत्र के विवास के लिये कार्य आरंभ किया गया था। उसके पश्चात् गगनहर और भाउडा के कमान्ड क्षेत्रों को भी विकसित करने की गृह्य की गई लेकिन पर्याप्त धन का अभाव में यह जारी नहीं रह पाई। 1983-84 में जारी परियोजना के कमान्ड क्षेत्र को 'नम' कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है। कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रबंध, राइक निर्माण, वृक्षारोपण, कृषि विस्तार कार्यक्रम, आसुदी का नियोजन, मत्स्य पालन, पशुपालन, सहकारिता आदि के कार्य लक्ष्य में लिए जाते हैं। कमान्ड क्षेत्र में गंगा साधनों का विकास, नियोजन के विभिन्न विन्दुओं का अध्ययन, सूचि रोत, नृपकों का प्रशिक्षण, मंडिया का विकास एवं राजस्थान कोलानाईजेशन एक्ट 1954 के अंतर्गत कोलानाईजेशन का महत्वपूर्ण कार्य भी निज जाय है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में कमान्ड क्षेत्र विकास में सार्वजनिक विभिन्न व्ययों पर 580.55 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

MINIMUM NEEDS PROGRAMME

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारम्भ मार्च 1980 में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समित गणना में विराम के लिये आवश्यक

विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम

आधारभूत सुविधाएँ जुगुने का चेष्टा की गई। इस कार्यक्रम में वदनन में निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है समानक वनिकी ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण सड़कें समान्य शिक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य ग्रामीण जलापूर्ति ग्रामीण सराई ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को आवास सहायता शहरी वन्य वनिकी में पर्यावरण सुधार पोषाहार एवं खाद्य एवं नारिकर्त पौष्टिक। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये 1217 17 करोड़ रुपए का अंश देव किया गया था इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रम पर निम्न प्रकार के व्यय किये जाने का प्रवधान था।

आठवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय (करोड़ रुपए में)	
क्षेत्र/कार्यक्रम	प्रस्तावित प्रावधान
सामाजिक सुविधा	15 00
ग्रामीण विद्युतीकरण	93 50
ग्रामीण सड़कें	182 00
सामान्य शिक्षा	386 63
स्वास्थ्य शिक्षा	12 00
ग्रामीण स्वास्थ्य	134 62
ग्रामीण जलापूर्ति	296 50
ग्रामीण सड़कें	2 00
आवास सुधार	20 16
पर्यावरण सुधार	20 40
पोषाहार	47 21
ग्रामीण वनिकी	7 15
योग	1217 17

स्रोत: Eighth Five Year Plan, 1991-97 Raj

आधारभूत न्यूनतम सेवाएँ कार्यक्रम BASIC MINIMUM SERVICES PROGRAMME

के कार्यक्रम प्रचलन की प्रेरणा पर आरंभ किये गये हैं और सात आधारभूत न्यूनतम सेवाओं को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। य सहाय है

- 1 सभी निवासियों को राष्ट्रीय मानक क अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना।
- 2 5000 तक क समूह को कुशल प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करना।
- 3 बेकार गरीब व्यक्तियों को सार्वजनिक आवास सहायता उपलब्ध करना।
- 4 हर गांव को बाजार अथवा बाजार से जोड़ने वाली और वषः पर्यन्त आवागमन वाला सड़क से जोड़ना।
- 5 विद्यालय से पूर्व और प्राथमिक शिक्षा स्तर पर निर्धन

परिवारों के बच्चों को पोषाहार सहायता देना।

6 प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु सार्वजनिक वितरण की दुकान खोलना।

7 सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में विशेषकर महिलाओं व लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना।

सन् 1996-97 में इस कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार से 87 63 करोड़ रुपये राज्य सरकार का प्राप्त हुय। इस कार्यक्रम पर जून 1997 तक 95 24 करोड़ रुपए कम किये गये।

महिला विकास कार्यक्रम WOMEN DEVELOPMENT PROGRAMMES

1984 में राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया इसके अंतर्गत मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार का ध्येय रखा गया यह अनुभव किया गया कि विकास कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका होनी चाहिये। ऐसा उनकी शिक्षा प्रशिक्षण और मूचनाओं के सहन एवं सामूहिक प्रयासों से हा संभव है। महिला विकास परियोजना राजस्थान के 10 जिलों जयपुर जयपुर अजमेर उदयपुर बामवाडा भालवाडा काटा झारपुर साकर बीकानेर में क्रियान्वित की जा रहा है। विभिन्न चरण के अंतर्गत इस परियोजना का विकास राजस्थान के सभी जिलों में किये जाने का योजना है। आठवीं योजना में इसक अंतर्गत चार और जिला को सम्मिलित किया जाना था आठवीं योजना में महिला विकास परियोजना के लिए 11 33 करोड़ रुपए का प्रवधान किया गया।

दस्यु ग्रस्त क्षेत्रों में बीहड सुधार कार्यक्रम

DACOT PRONE REVINE IMPROVE MENTO PROGRAMME

राजधान में केन्द्र सुधार कार्यक्रम 1987-88 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि डाकूमन इन क्षेत्रों में य केन्द्राये अपने आस-पास का उपजाऊ कृषि भूम में विस्तृत नहीं हो पाय साथ ही इन केन्द्रा क्षेत्रों को पुन सुधार कर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना था इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। राजस्थान में य कार्यक्रम 5 डाकूमन जिला कोटा दूदी स्वाइमधपुर भरतपुर एवं धौलपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राशि दो जा रहे है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 54 07 करोड़ रुपए व्यय करके

24100 हेक्टेयर क्षेत्र में वन लगाने एवं अन्य विकास कार्यक्रम हाथ में लिये जाने की योजना थी।

वंजर भूमि विकास कार्यक्रम

BARREN LAND DEVELOPMENT PROGRAMME

पर्यावरण सुधार तथा ईंधन चारा फल एवं इमारती लकड़ी की उपलब्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर बजड़ भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान में बजड़ भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल राष्ट्रीय बजड़ भूमि विकास बोर्ड के अनुसार 1.8 बजड़ हेक्टेयर है। अतः राजस्थान में भी बजड़ भूमि विकास कार्यक्रम के माध्यम से विशाल क्षेत्र में विस्तृत बजड़ भूमि पर वृक्षारोपण व घास के उत्पादन द्वारा पर्यावरण सुधार के साथ आर्थिक आय बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित भूमियों का वृक्षारोपण द्वारा विकास किया जा सकता है -

- 1 कृषि के अयोग्य भूमि जो पहले से ही पचावती राज सस्याओं में निहित है जैसे चरागाह भूमि व गवंई भूमि
- 2 राजकीय विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं के पास कृषि के अयोग्य भूमि
- 3 कृषि के अयोग्य पड़त भूमि जिसका वृक्षारोपण हेतु व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को आवंटन हो सके तथा
- 4 खादेदारी भूमि जो कृषि के अयोग्य या कम योग्य हो और जिस पर वृक्षारोपण द्वारा अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

राजस्थान में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये ग्रामीण विकास एवं पचावती राज विभाग 'कर्ता विभाग' बनाया गया है जो वन, राजस्व, विशिष्ट योजना संगठन कृषि सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण आदि विभागों के समन्वय एवं सहयोग से कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन पचावती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है तथा कार्यक्रम के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता राज्य जिला खण्ड एवं ग्राम स्तरों पर वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

इस कार्यक्रम के लिये वितीय सहायता राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मरुस्थल विकास कार्यक्रम सूखा प्रदूषण क्षेत्र कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति विकास, सामाजिक वित्तिका अनुसूचित जाति संपत्तिक यात्रा आदि परतों से चली आ रही योजनाओं से आर्जन तथा बैंक व वितीय संस्थाओं से ऋण द्वारा प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत वंजर भूमि विकास के लिये 1986-87 से एक कार्यकारी योजना

बनाई गई, जिसके अनुसार प्रत्येक गांव पचावत समिति द्वारा कम से कम 25 से 40 हेक्टेयर बजड़ भूमि को ग्राम्य वन के रूप में विकसित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक पचावत समिति में कम से कम दस ग्राम पचावत 10-10 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम्य वनों के विकास की योजना हाथ में लेगा। पचावत समिति स्तर पर कम से कम एक पौधशाला की स्थापना की जायेगी जिसमें एक लाख पौध तैयार किए जायेंगे इसके अलावा क्षेत्र की ग्राम पचावतों विज्ञानियों आदि में कम से कम 20 पौधशालाएं तैयार की जायेंगी।

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

BORDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

सातवां पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिये पूर्णतः केन्द्र की सहायता में एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिमी सीमान्त क्षेत्रों के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करके स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान पंजाब, गुजरात को सम्मिलित किया गया है। बाट में जम्मू कश्मीर को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। सातवां पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस पर 200.00 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया था। इस कार्यक्रम का वार्षिक क्रियान्वयन 1986-87 में आरंभ हुआ। प्रारंभ में इस कार्यक्रम की देखभाल गृह मंत्रालय की करनी थी, बाद में इसे मूल्य समायोजन विकास मंत्रालय को दे दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वरूप के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 मुख्य बिन्दु सम्मिलित हैं। प्रथम इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को फाटा परिचय-पर निर्गमित करना द्वितीय शिक्षा तृतीय सिंचाई एवं चतुर्थ सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना। 1990-91 एवं 1991-92 में सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए बजट 86 एवं 85 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यह कार्यक्रम आठवीं सातवां में भी जारी रहा और इसके अंतर्गत पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया। आठवीं योजना में इन समस्त बाधों पर केन्द्र ने 640 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।

1993-94 में यह कार्यक्रम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चार जिलों (बांसागर, जैसलमेर, बांसागर एवं जयपुर) में चलाया जा रहा है। 1997-98 में दिसम्बर 1997 तक इस कार्यक्रम पर 16.79 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए मरु-विकास कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए।
Explain the Desert Development Programme adopted in Seventh Five-Year Plan of Rajasthan
- 2 राजस्थान में मरु-विकास कार्यक्रम के क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं?
What are the specific objective of the Desert Development Programme in Rajasthan
- 3 जवाहर राजरंग योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Explain the main features of Jawahar Roggar Yojna
- 4 राजस्थान के विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।
Point out the Special Schemes and Programmes for development of Special Areas in Rajasthan
- 5 ट्राइसेम क्या है?
What is TRYSEM?
- 6 'DWCRA' पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on DWCR
- 7 'मंदा' क्या है?
What is MADA?
- 8 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Minimum Need Programme

B. निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विवेचना करें। यह कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुए हैं?
Point out the special schemes and programmes for development of special areas in Rajasthan. To what extent these have been proved beneficial?
- 2 राज्य में मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम का साठवाँ समझाइए। इस कार्यक्रम की उल्लिखितों पर प्रकाश डालिए।
Mention the government's efforts to develop the tribes in Rajasthan. Specify the role of sub-plan in the context.
- 3 अरावली विकास का क्या महत्व है? इसके सम्पन्नित लाभों पर प्रकाश डालिए।
What is the importance of Aravalli Development? Analyse the possible gains of this programme
- 4 राजस्थान में जनजाति क्षत्रीय विकास कार्यक्रम की रूपरेखा में व्याख्या कीजिए।
Analyse in brief the Tribal Area Development Programme (TADP) in Rajasthan
- 5 जवाहर राजरंग योजना पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on Jawahar Roggar Yojna (JRY)
- 6 निम्नलिखित पर 100 शब्दों (प्रत्येक) में टिप्पणी कीजिए।
(i) राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका (ii) मरु-विकास कार्यक्रम
Write short notes on the following in 100 words for each -
(i) Role of National Development Council (ii) Desert Development Programme

C. विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

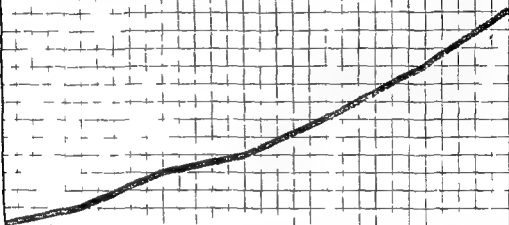
- 1 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।
(i) सूखा सम्पन्नित क्षेत्र कार्यक्रम (ii) मरु-विकास कार्यक्रम
(ii) जनजाति क्षेत्र तथा अरावली विकास (iii) सम्पन्नित क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(iv) जवाहर राजरंग योजना
Write short notes on the following
(i) Drought Prone Area Programme (ii) Desert Development Programme
(iii) Tribal Area and Aravalli Development (iv) Integrated Rural Development Programme
(v) Jawahar Roggar Yojna

- 2 राजस्थान में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन वांछित शब्दों में इसको कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है?
Describe the Drought Prone Area Programme (DPAP) in Rajasthan. How it can be more effective in future?
- 3 मक्षिन्द टिप्पणी लिखिए -
(i) राज्य में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (ii) अरावली विकास कार्यक्रम
(iii) राज्य में मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम
Write short notes on -
(i) Drought Prone Area Programme in the State (ii) Aravalli Development Programme
(iii) Desert Development Programme in the State
- 4 राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित ग्रामाण विकास कार्यक्रम का समीक्षा कीजिए।
Review the Integrated Rural Development Programme as a specific programme to eradicate the poverty in Rajasthan



राजस्थान में आर्थिक नियोजन

ECONOMIC PLANNING IN RAJASTHAN



* राजस्थान में जिला नियोजन 1988-89 से आरम्भ हुआ। *

अध्याय एक दृष्टि में

- ❖ राजस्थान का नियोजन तंत्र
- ❖ विकेंद्रित नियोजन
- ❖ राजस्थान में आर्थिक नियोजन
- ❖ राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना
- ❖ अन्त्यसर्च प्रश्न

राजस्थान का नियोजन तंत्र

PLANNING MACHINERY IN RAJASTHAN

राजस्थान में प्रभावपूर्ण नियोजन के लिए जो तंत्र विकसित किया गया है उसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाएँ और विभाग महत्वपूर्ण हैं

1 योजना आयोग (Planning Commission) - योजना आयोग भारत में योजना के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। इसका गठन सन् 1950 में किया गया था। आयोग संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विकास की रूपरेखा बनाता है। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है।

2 राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) - राज्य स्तर पर सभी राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया गया है। इस परिषद् में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं व कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री इस परिषद् का अध्यक्ष होता है।

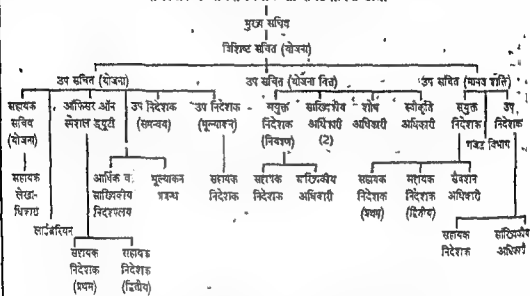
3 राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) योजना के सदर्भ में निर्णय लेने के लिए यह एक उच्चस्तरीय

अनुभव वाला बोर्ड है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन के लिए सलाह देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विद्यमान होते हैं।

4 योजना विभाग (Planning Department) - राजस्थान में योजना विभाग राजस्थान की योजना के निर्माण

एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अन्तर्गत योजनागत वित्त, जनशक्ति आदि के नियोजन, समन्वय, निरीक्षण और मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। इसके प्रभावी संचालन से राजस्थान में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है। राजस्थान में योजना विभाग का संगठन आक्रांत चित्र में समझा जा सकता है -

राजस्थान में योजना विभाग का संगठनात्मक ढांचा



5 जिला योजना प्रकोष्ठ (District Planning Cells)- प्रत्येक जिले में जिला विकास अधिकारी को सहयोग देने के लिए जिला प्रकोष्ठ बनाए गए हैं ताकि योजना के क्रियान्वयन के वास्तविक स्तर पर नियोजन को सुदृढ़ बनाया जा सके। यह 'नीचे से नियोजन' प्रेरित करता है। जिला योजनाओं का माध्यम से राज्य के लिए प्रभावी और वास्तविक योजना का निर्माण संभव है।

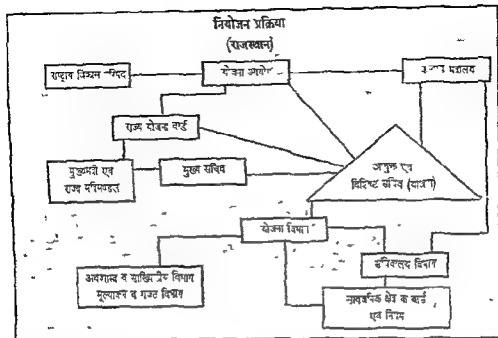
6 निरीक्षण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) - राज्य योजना विभाग के अन्तर्गत निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है ताकि समय रहते योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हो सके और आगामी योजनाओं में सुधार किया जा सके। योजना के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त कुशलता लाने की चेष्टा की गई है। योजनाओं को लागत लाभ की दृष्टि से भी देखा जाता है ताकि विभिन्न परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सुविधा हो सके।

7 विशिष्ट योजना संगठन (Special Scheme Organisation) - राजस्थान सरकार ने इस संगठन की

स्थापना लघु सिंचाई, भूमि विकास और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में सत्यागत वित्त को आवंटित करने के लिए की थी क्योंकि इसकी स्थापना से पूर्व ऐसा कोई संगठन नहीं था जो विभिन्न वित्तीय राशियों की आवश्यकता के अनुसार परियोजनाओं का निर्माण कर सके। इस संगठन ने डेयरी, पशुपालन, विपणन आदि में विशेषज्ञता प्राप्त की है। इस संगठन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर, उन क्षेत्रों का समन्वित विकास करना है। इस संगठन के अन्तर्गत अनेक विराट् योजनाओं का निर्माण किया गया है।

8 निर्व्यय जिला योजना (Untied District Plan Fund) - राजस्थान सरकार ने सभी जिलों को निर्व्यय जिला योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध करवाई है। यह जिलास्तर पर योजना निर्माण की ओर एक कदम है। इनके अन्तर्गत निर्धारित राशि को जिले द्वारा भेजी गई योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात् उनके क्रियान्वयन पर खर्च किया जाता है।

इस प्रकार राजस्थान में समग्र रूप से देखा जाए तो नियोजन की प्रक्रिया को इस चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है



विकेन्द्रित नियोजन

DECENTRALISED PLANNING

राजस्थान में नियोजन के अंतर्गत राज्य की केंद्रीय भूमिका रही है। जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से स्थानीय भाषनों एवं प्रतिष्ठानों को उपयोग करने के लिए जिला स्तर एवं उसमें नीचे नियोजन अपरिहार्य हो जाता है। इससे लोगों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं का गरी आकलन किया जा सकता है एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। निर्धनता निवारण और रोजगार के कार्यक्रमों को गत कुछ वर्षों से जिला स्तर पर क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इससे ऐसा अनुभव हुआ कि नियोजन के कुछ कार्यों को राज्य स्तर से जिला स्तर पर हस्तान्तरित किया जा सकता है ताकि नियोजन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता एवं सक्रिय सहयोग मिल सके। राज्य सरकार ने दायवेल मदनमलान, कमाण्ड ग्रिया डवलपमेन्ट, सूखा सम्भावित कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से क्षेत्रीय नियोजन से सम्बन्धित कुछ कदम भी उठाये। जिला स्तर पर जिला प्रायोगिक विकास अभिकरण कार्य कर रहे हैं। इन अभिकरणों का यह दायित्व है कि वे सम्बन्धित प्रायोगिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार योजना मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित कार्यक्रम आदि प्रायोगिक रोजगार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें। इन अभिकरणों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाती है। और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। जिले में जिला नियोजन समिति का गठन

प्राचीन पंचदशवर्ष योजना के अंतर्गत उस समय किया गया था जब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। उस समय इन समितियों का केवल सलाह और समीक्षा का कार्य दिया गया था किन्तु इन्हें कोई क्रियात्मक एवं वित्तीय शक्ति प्रदान नहीं की गई है। मरकरी क्रियाओं में जिले का विशाल प्रभाव है। इसके भविष्य में भी बन रहने की संभावना है। इसमें एक सुसंगठित एवं समन्वित प्रशासनिक तंत्र विद्यमान होता है जिसमें जिलाधीश के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ जिला परिषद प्रमुनिमित्त कौंसिल एवं बोर्ड आदि चयनित संस्थाएँ होती हैं। विधानमण्डल की सभी संसदें भी जिले की सीमा के भीतर होती हैं। ऐसा स्थिति में जिला विकेन्द्रित नियोजन के लिए एक उचित माध्यम व आधार है।

राजस्थान में जिला नियोजन का आरम्भ 1988-89 से हुआ जबकि झालावाड़ जिले की व्यापक जिला योजना निर्मित की गई। ऐसे प्रोजेक्ट्स फली भोलवाडा, मवाई माधोपुर आदि में भी निर्मित हो रहे हैं। इन सबका मुख्य उद्देश्य नियोजन की क्रियविधि को कुशल बनाने से है। राजस्थान में राज्य स्तर पर नियोजन विभाग के अंतर्गत एक अलग जिला नियोजन प्रकोष्ठ बनाया गया है जो राजस्थान में जिला नियोजन से सम्बन्धित है। जिला स्तर पर भी नियोजन प्रकोष्ठ बनाये गए हैं। ये प्रकोष्ठ जिला नियोजन में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेंगे। जदपुर के राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जिला नियोजन के विभिन्न पक्षों से

परिचित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन प्रकोष्ठों को जिले की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाओं के दोषावधि एवं अत्यावधि योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों द्वारा निर्मित योजनाओं को राज्य योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। ये प्रकोष्ठ जिलाधीश के अन्तर्गत कार्य करेंगे। ये प्रकोष्ठ जिला नियोजन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भी सहयोग देंगे। इन प्रकोष्ठों का कार्य मुख्य नियोजन अधिकारी के नाम से निर्मित पद के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। राज्य का नियोजन विभाग राज्य स्तर पर, जिला नियोजन का मुख्य विभाग होगा। जिला नियोजन प्रकोष्ठों को ग्राम स्तर के आकड़े इकट्ठे करने का कार्य भी सौंपा जायेगा। इन आकड़ों का प्रयोग जिला नियोजन के अंतर्गत किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के आकड़े इकट्ठा करने का कार्य एवं उम्र सूचना को कम्प्यूटर में भरने का कार्य प्रगति पर है। ये प्रकोष्ठ प्रत्येक जिले के समाधनों का विवरण भी निर्मित करेंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही जिलों को निर्बन्ध कोष (United Funds) भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को उचित महत्व दिया जा सके। इन कोषों का उपयोग पेयजल, विद्यालय भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लड बैंक, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ही जा सकता है बशर्ते इन कार्यों के कारण भविष्य में राज्य का दायित्व उत्पन्न न हो। आठवी योजना के अंतर्गत इन कोषों के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1991-92 के वर्ष से 30 जिले 30 काम नाम की एक नई योजना प्रारम्भ की गई। इसके अंतर्गत 20 करोड़ रुपये जिलों को निर्बन्ध कोषों की भाँति एवं उसी आधार पर आवंटित 30 जिले 30 काम का उद्देश्य यही है कि जिले द्वारा अल्प अवधि में स्थानीय समस्याओं का कुशलता उपयोग कर सके। साथ ही यह राशि इस प्रकार से विनियोजित की जाये कि स्थानीय समाधनों के उपयोग के साथ साथ जिले का विकास भी संभव हो सके। इस हेतु जिले को इस गतिविधियों में से एक को चुनना होता है लिफ्ट सिंचाई, स्विक्लर, एनोकट, लघु सिंचाई, पर्यटन विकास, पशुपालन विकास, विद्यालय भवन का निर्माण, अस्पताल के भवन का निर्माण, चरागाह एवं वन विकास, क्षारीय भूमि विकास, विद्युत पंपजल, सड़क हमकला, परिवार कल्याण सक्षरता, कमजोर वर्ग का कल्याण। उपरोक्त में से किसी एक किया जा चयन जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा किया जाता है जिसमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय नियोजन की प्रक्रिया एवं विकास में जनता से जनता लोगों की सक्रिय

भाग्यदार हो सके। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण मुख्य नियोजन अधिकारी द्वारा जिलाधीश के अधीन किया जाता है। 30 जिला 30 काम के लिए आठवी योजना में 190 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्यस्तरीय नियोजन विभाग ने अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, हनुमन्त राव समिति की सिफारिशों एवं झालावाड जिला योजना के निर्माण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर राज्य में विकेंद्रित नियोजन की क्रियाविधि निर्धारित कर ली है।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन

ECONOMIC PLANNING IN RAJASTHAN

राजस्थान में योजनाबद्ध विकास 1951 में आरम्भ हुआ। सन् 1950 में देश में योजना आयोग की स्थापना की गई। राज्य स्तर पर सभी राज्यों के अन्तर्गत समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राजस्थान में अब तक पूरे देश की भाँति सात पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। 1990 में सातवी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के पश्चात् 1990-91 और 1991-92 के लिए दो वार्षिक योजनाएँ बनाई गई हैं क्योंकि आठवी योजना 1 अप्रैल, 1992 से आरम्भ हुई। राजस्थान में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार है

प्रथम पंचवर्षीय योजना

(First Five-Year Plan (1951-56))

राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक क्रियान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मदों पर 6450 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु योजना के अन्त तक केवल 54 14 करोड़ रुपये ही व्यय हो पाए।

योजना के उद्देश्य

Objectives

इस योजना के अंतर्गत सबसे कठिन कार्य राजस्थान के जनमानस का नियोजन के लिए तैयार करना था क्योंकि इस प्रकार के आयोजन के लिए जनता में आवश्यक जनकारी का वित्कुल अभाव था। इसी प्रकार न तो अलग-अलग टुकड़ों में बटे हुए राजवादों की सभावाओं और समस्याओं की पूरी जानकारी उपलब्ध थी तथा न ही राज्यों की अर्थव्यवस्था का सांख्यिकीय विश्लेषण उपलब्ध था। इस

कारण साधन जुटाने के साथ-साथ साधनों की गणना करना भी कठिन था। इसलिए विभिन्न रियासतों से सम्बन्धित जानकारी अनुमान के रूप में ही तैयार की गई। इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल वे ही कार्यक्रम लागू में लिए गए जो तत्कालीन प्रशासनिक स्तर पर अनुभवों के आधार पर उचित समझे गए। जब यह योजना आरम्भ हुई तो राजस्थान में वर्षा के अभाव के कारण सूखे एवं अकाल की स्थिति बनी हुई थी। कृषक की हालत दयनीय थी और कृषि जोतों का आकार छोटा और बिट्ठा हुआ था। किमान को खातेदारों अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस कारण वह अपनी पैदावार से भी वंचित था। सिंचाई के साधन लगभग नहीं के बराबर थे। इस कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस हेतु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, का विशेष प्रयास किया गया। इसके पश्चात् सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया।

उपलब्धियाँ Achievements

राजस्थान में विकासशील अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना इसी योजनाकाल में आरम्भ की गई। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भाखड़ा एवं अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से कार्य आरम्भ किया गया। कृषि विस्तार के कार्यक्रमों पर सम्पूर्ण योजना व्यय का 65 प्रतिशत व्यय किया गया। सिंचाई साधनों में वृद्धि एवं सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 3.35 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकी। योजना के अन्त में खाद्यान्न का उत्पादन 42.42 लाख टन हुआ। इसी प्रकार 1950-51 में जो सिंचित क्षेत्र 11.71 लाख हैक्टेयर था, योजना के अन्त में बढ़कर 15.93 लाख हैक्टेयर हो गया। इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा राजस्थान में भविष्य की योजना के लिये सुदृढ़ आधार बना। यहाँ के आर्थिकों ने राजस्थान की छिपी हुई सम्भावनाओं का पता लगाया। विद्युत के विकास के लिए प्रयास आरम्भ किए गए। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय राज्य में केवल मामूली शासकीय की राजधानियों में ही विद्युत थी। उद्योग-धंधे कम होने के कारण राज्य में विद्युत की मांग कम थी। प्रथम योजना के आरम्भ में 42 बस्तियों में विद्युत उपलब्ध थी। विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या 1955-56 के अन्त में 1242 हो गई। इसी प्रकार विद्युत की क्षमता इसी मध्य 8 मेगावाट में बढ़कर

96 मेगावाट हो गई। प्रथम योजनाकाल तक कुओं पर विद्युतचालित पम्पसेट लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से यह संभव हो सका। इस योजना में शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया जिससे 1951 में साक्षरता की दर बढ़ी। प्रथम योजनाकाल में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रयत्न किए गए और इस हेतु एक करोड़ रुपये से अधिक का राशि व्यय की गई। चम्बल नदी से सिंचाई के लिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप में चम्बल नदी पर एक बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजना क्रियान्वित की गई जो कि आगे चलकर तीन चरणों में पूरी हुई। भाखड़ा-नागल तथा चम्बल की दो बहु-उद्देशीय योजनाओं के अतिरिक्त, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 111 वृहद् एवं मध्यम परियोजना और 244 लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्य भी आरम्भ किए गए। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजनाकाल में राजस्थान में दो चीनी मिलें, दो सीमेंट फैक्ट्रियाँ, एक काच फैक्ट्री 10 मृत्ती कपड़ा मिलें, एक बॉल बियरिंग फैक्ट्री और एक इलेक्ट्रिकल एवं एक मैटल फैक्ट्री मुख्य रूप से क्रियाशील थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

SECOND FIVE-YEAR PLAN - 1956-61

राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1956 में आरम्भ हुई और 31 मार्च 1961 का पूरी हुई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर 105.27 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वास्तव में 102.74 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए।

योजना के उद्देश्य

Objectives

राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत का सामूहिक एवं पृथक् विकास इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को भी पर्याप्त महत्व दिया गया। इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों के द्वारा विकास का वातावरण बनाने का प्रयास भी किया गया। एक प्रकार से यह योजना पुनः कृषिप्रधान योजना थी।

उपलब्धियाँ

Achievements

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में जमींदारी, जागीरदारी एवं बिस्वेदारी व्यवस्थाओं का उन्मूलन हुआ। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य था जिससे कृषकों को विशेष सहित मिला। जागीरदारी उन्मूलन से एक सामाजिक द्रवित का भी सूरपात हुआ। भूमि जोतने वालों को खातेदारों के अधिकार प्राप्त हो गए और लम्बे समय से चला आ रहा भूमिपतियों का अधिकार समाप्त हो गया। इन व्यवस्था में कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। योजनाकाल में 48 प्रतिशत भाग, कृषि एवं मिर्चाई कार्यक्रम पर व्यय हुआ। इसमें मुख्यतः राजस्थान नहर पर केन्द्र द्वारा किया गया 13 करोड़ रुपये का व्यय भी सम्मिलित है। इस योजना में 10.30 लाख टन खाद्यान्न की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का विकास हुआ। प्रथम योजना में यह क्षमता केवल 3.35 लाख टन ही थी। इस योजना में पर्याप्त वर्षों के अभाव में भी 3.11 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। इस योजना से सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया। कृषि में उनका विधियों के बारे में सोचा जाने लगा। विधित क्षेत्र का विस्तार हुआ। विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ और उद्योग एवं व्यवसाय को नये अवसर उपलब्ध हुए। इन योजनाकाल में समस्त परिवोजना के अंतर्गत कोटा बैराज का निर्माण-कार्य किया गया। इससे कोटा के विकास के लिए महत्वपूर्ण मदद मिली। कोटा का औद्योगिक विकास राजस्थान से दूरकर जाने वाली इमो-एकनाइ नदी के कारण संभव हो सका। इस योजनाकाल में भारत सरकार ने कोटा में नाथलाइन पैक्ट्री, उदयपुर, भवानीमण्डी, किशनाठ तथा भीलकाड़ा में सूती मिलें और देवारी में जिक स्पेन्डर सयर आदि अनेक महत्वपूर्ण उद्यमों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान किए। कुटीर एवं लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। इनमें अन्ध में राजस्थान खादी एवं ग्रामोबांग मण्डल, राजस्थान कर्मा मण्डल, राजस्थान हस्तकला मण्डल, राजस्थान लघु उद्योग मण्डल, राजस्थान वित्त निगम आदि की स्थापना की गई। इन योजना के अन्त तक विद्युत उत्पादन क्षमता 109 हजार किन्वाट तक पहुँच गई जबकि पहली योजना के अंत में यह केवल 35 हजार किन्वाट तक ही थी। खेतड़ी में ताड़ा और जावर खानों के जम्मे का व्यवस्थित रूप से खनन, इसी योजना में अरम्भ हुआ। मरुस्थल क्षेत्र में बदलाव लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण कार्य भी इसी योजना में अरम्भ हुआ। इनके अतिरिक्त मोटा दूध, माहें दूजवा सागर, जाखम दैडच, बगस, पत्नी आदि परिवोजनाओं पर भी कार्य किया गया। 2 अक्टूबर

1959 को राज्य की संपूर्ण ग्रामीण जनता को 232 विकास खण्डों में बाँटा गया। पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीण विकास को गति मिली।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

THIRD FIVE-YEAR PLAN - 1961-66

राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966 के मध्य क्रियान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रों पर 236 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वास्तविक रूप में 212.70 करोड़ रुपये का रहा।

योजना के उद्देश्य

Objectives

इस योजना में विगत योजनाओं की भांति सर्वाधिक महत्व कृषि को ही प्रदान किया गया। साधन कृषि के अन्तर्गत उन्नत बीज, पान्थिक छेती और मिर्चाई पर विशेष धन दिया गया। कृषि, मिर्चाई तथा विद्युत व्यवस्था पर समस्त योजना व्यय के 66 प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया गया।

उपलब्धियाँ

Achievements

इस योजना में 1962 में चीन के आक्रमण के बाद कृषि के उत्पादन कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। कृषि का एक महत्वपूर्ण पहलू कुछ चुने हुए कृषि क्षेत्रों में अधिक निवास पर ध्यान दिया गया ताकि उठने से व्यय से सर्वाधिक कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सके। जिला स्तर पर साधन कृषि कार्यक्रम जैसे कार्य आरम्भ किए गए। चीन के आक्रमण के पश्चात् देश की विभागधारा में परिवर्तन हुआ और सभी राज्य अधिक से अधिक वित्तीय साधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। लेकिन चीनी आक्रमण के साथ-साथ ही प्रकृति की प्रतिकूलता भी दनी रही। राजस्थान में सूखे और अकाल के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस योजना-वर्ष में अधिकांश अकाल व सूखे से स्थिति रही। इन कारणों से वित्तीय साधन इन प्राकृतिक प्रकोप पर कठू पन के लिए प्रयुक्त किए गए। विकास कार्यों को जहाँ-जहाँ कार्यो को प्राथमिकता दी गई। योजना के अन्त में खाद्यान्न का उत्पादन 38.39 लाख टन हो रहा गया। तृतीय योजना के अन्त में विद्युत क्षमता 65 मेगावाट से बढ़कर 96 मेगावाट हो गई। इस योजना में सामाजिक

सेवाओं में काफी कार्य किया गया। इसी योजना में दो नये विश्वद्यालय राज्य में खोले गए। शिक्षा के प्रसार, तकनीकी शिक्षा में गति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की नई सुविधाएँ और नये उद्योगों के विकास से राज्य में आर्थिक विकास का वातावरण बना।

वार्षिक योजनाएं

ANNUAL PLANS - 1966-69

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् चौथी योजना वर्ष 1966 में आरम्भ नहीं हो पाई। इस कारण 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के लिए वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया। इन वार्षिक योजनाओं में कुल 132.72 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वास्तविक व्यय 136.78 करोड़ रुपये हो गया।

योजना के उद्देश्य

Objectives

तीन वार्षिक योजनाओं ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यप्रभूमि का निर्माण किया। इस योजना में सर्वाधिक महत्व पुनः कृषि एवं सिंचाई को ही प्रदान किया गया। शक्ति के साधनों के विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। राजस्थान के अधिकांश भागों में तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल से ही सूखे की ही स्थिति बनी हुई थी। अतः इन योजनाओं में चेष्टा की गई कि अपूर्व पड़े कार्यों को पहले पूरा किया जाए।

उपलब्धियां

Achievements

वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत सूती धागा, सीमेन्ट आदि औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि हुई। कल्याणकारी कार्यों के फलस्वरूप समाज में नई चेतना का आगमन हुआ। औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप पञ्जीकृत इकाइयों की संख्या 1509 में बढ़कर 1968 में 1753 हो गई। इस योजनाकाल में कई प्रमुख कारखाने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए, जैसे जम्ना परिश्रवक (जिक समेन्टर), उदयपुर कॉपर स्मेल्टर, खेतड़ी, इस्ट्रुमेंटेशन लि., कोटा, फर्टीलाइजर एण्ड फाइबर प्लांट कोटा, वुलन स्पिनिंग मिल बीकानेर, बस्टेड वुलन मिल, चूरू बस्टेड वुलन मिल, लाडन, फ्ल्योगाइट बेनिपिकेशन प्लांट माण्डो की पाल, हिटेची प्रीमोजन स्लास फैक्ट्री भीलपुर सोडियम सल्फेट प्लांट डीडवाना सोमेट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़, कॉपर

एलाय टयूब्स फैक्ट्री, कोटा, कोका-कोला फैक्ट्री, जयपुर, ट्रान्समिशन हाईट्रान्ज़िस्मिटेड आइल्स फैक्ट्री, भीलवाड़ा आदि। इस योजना के अन्त में विद्युत उत्पादन क्षमता 96 मेगावाट से बढ़कर 174 मेगावाट हो गई। राज्य में छाछान की विषम स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन का मधन कार्यक्रम भी इसी वार्षिक योजनाओं में आरम्भ किया गया। इस योजनाकाल में 300 या इससे अधिक जनसंख्या के सभी गांवों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी थी। कुछ पर्वतीय या मरुस्थली क्षेत्रों को छोड़कर राज्यभर में हर ढाई किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध थी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

FOURTH FIVE-YEAR PLAN - 1969-74

राजस्थान की चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1974 तक क्रियान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत 306.21 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था किन्तु वास्तविक व्यय 308.79 करोड़ रुपये का हुआ।

योजना के उद्देश्य

Objectives

इस योजना में विगत योजनाओं की भांति कृषि व सिंचाई पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, शक्ति के साधनों के विकास के लिए विशेष प्रयास करने का उद्देश्य रखा गया। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करने की योजना भी बनाई गई।

उपलब्धियां

Achievements

इस योजना में तीन बड़ी एवं मध्यम परियोजनाएँ पूरी की गईं। राश हो 1.63 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की गई। चतुर्थ योजना में राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में विशेष प्रगति हुई। विद्युत उत्पादन क्षेत्र में उत्तेजनीय वृद्धि होने में विद्युत उत्पादन 174 मेगावाट से बढ़कर 400 मेगावाट हो गया। अनेक ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया और अधिक कुओं को बिजली प्रदान की गई। उन्नत कृषि प्रणाली के कारण छाछान के उत्पादन में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में वनस्पति तेल, सोमेट पावर वेंटिल, उन्नत सूती धागे, मशीन टूल, चीनी एवं नायलोन के धागे आदि के उत्पादन में

सम्बन्धित महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए। तिलहन एवं उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा। सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं में वृद्धि की दृष्टि से लगभग 2500 किलोमीटर लम्बी सड़कें, 2100 से अधिक प्राथमिक शालाएँ आदि स्थापित किए गए।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

FIFTH FIVE-YEAR PLAN - 1974-79

राजस्थान में पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च 1979 तक लागू की गई। इस योजना में 847.18 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वास्तविक व्यय इससे कुछ अधिक 857.62 करोड़ रुपये हुआ।

उद्देश्य

Objectives

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरचनात्मक ढांचे को विकसित एवं सुदृढ़ करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसी कारण योजना में सर्वाधिक व्यय मिचई और शक्ति के क्षेत्रों में किया गया। इससे कृषि एवं अन्य सम्बन्धित व्यवसाय भी स्वयं ही प्राथमिकता की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को पुनः महत्व प्रदान किया गया। शालायात, उद्योग एवं खनिज को विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

उपलब्धियाँ

Achievements

इस योजनावधि में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन 67.21 लाख टन से बढ़कर 77.80 लाख टन पर पहुँच गया। इसी प्रकार तिलहन का उत्पादन 3.39 लाख टन से बढ़कर 5.5 लाख टन तक पहुँच गया। इस योजनावधि में उन्नत कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई। सिंचाई के क्षेत्र में 4.54 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता निर्मित की गई। इस योजना में लघु उद्योगों, हस्तकला तथा छोटी एवं मायोड्यो को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कारण ग्रामोद्योगों का उत्पादन 14 करोड़ रुपये से बढ़कर 10.00 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों का स्थापन कर दी गई।

वार्षिक योजना

ANNUAL PLAN - 1979-80

पांचवीं योजना के पश्चात् छठी योजना समय पर आगम्य नहीं हो पाई। इस कारण वार्षिक योजना बनाई गई। इस योजना में 275 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वास्तव में व्यय 290.19 करोड़ रुपये हुआ।

योजना के उद्देश्य

Objectives

इस वार्षिक योजना का उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि तैयार करना था व इन हेतु सरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने की चेष्टा की गई। इसी कारण इस योजना में सबसे अधिक व्यय सिंचाई और शक्ति के माध्यमों पर किया गया जो कि राज्य के योजनागत व्यय का 54.76 प्रतिशत था। इसके साथ ही कृषि को भी महत्व दिया गया तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ और अधिक विकसित की गईं।

उपलब्धियाँ

Achievements

इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का उत्पादन 1978-79 की अपेक्षा अकाल की स्थिति के कारण कम हुआ। यहाँ स्थिति तिलहन और अन्य कृषि उत्पादनों की रही। ऐसा होने पर भी उन्नत कृषि के अन्तर्गत भूमि 15.77 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.63 हेक्टेयर हो गई। सिंचित क्षेत्र में अकाल के कारण कुछ कमी आई। ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन बढ़ा और वह 1978-79 में 10 करोड़ रुपये की अपेक्षा 1979-80 में 12 करोड़ रुपये हो गया। राजस्थान में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों, प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल, पोषाहार अन्दि, पर भी ध्यान दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना

SIXTH FIVE-YEAR PLAN - 1980-85

छठी पंचवर्षीय योजना राजस्थान में 1 अप्रैल, 1980 से आगम्य हुई और 31 मार्च, 1985 तक पूरी हुई। इस योजना में विभिन्न मलों पर 2025 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वास्तविक व्यय 2120.45 करोड़ रुपये हुआ।

उद्देश्य

Objectives

छठी योजना में तीव्र ग्रामीण विकास के माध्यम से निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया। निर्धनता निवारण के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रम आरम्भ किए गए। इस योजना के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए साधनों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने की चेष्टा की गई। शक्ति के साधनों के विकास एवं संरक्षण पर दल दिया गया। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का चेष्टा भी की गई।

उपलब्धिया

Achievements

मूलभूत संरचना, उत्पादन और सामाजिक सेवाओं से सम्बन्धित नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। गरीबी में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा लघु एवं सीमांत क्षेत्रों की उन्नति के विशेष प्रयास किए गए। सिंचाई के क्षेत्र में भाखड़ा व चम्बल घ्यवस्था तथा इन्दिग गांधी नहर व मारी परियोजनाओं का विकास किया गया। शक्ति के साधन के दृष्टिबोध से भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं में अधिक विद्युत के लिए जल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। छठी योजना के अन्तर्गत 2120 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि इससे पूर्व की प्रथम योजना से पाचवी योजना तक राजस्थान में केवल 1963 करोड़ रुपए विनियोजित किए गए थे। इस प्रकार छठी योजना में जो विनियोग किया गया वह विगत 30 वर्षों के विनियोग में अधिक था। इस पंचवर्षीय योजना में 2 24 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की गई। खाद्यान्नों में वृद्धि हुई। विभिन्न फसलों के प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ी। मध्यकालक दाय्य अधिक सुदृढ़ हुआ। मछली की लम्बाई योजना के अन्त में 48811 किलोमीटर हो गई। विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ी। ताप से उत्पन्न विद्युत उत्पादन 1105.1 मिलियन किलोवाट हो गया। विद्युत का उपभोग भी बढ़ा। योजना के अन्तर्गत में रा. 4386.5 मिलियन किलोवाट तक पहुंच गया। योजना के अन्त तक 201 बस्से और 20287 गांव विद्युतीकृत हो चुके थे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

SEVENTH FIVE-YEAR PLAN - 1985-90

सह योजना 1 अप्रैल 1985 में 31 मार्च 1990 तक विस्तारित की गई। इस योजना में 3000 00 करोड़

रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक व्यय 3106 18 करोड़ रुपये हुआ।

योजना के उद्देश्य

Objectives

सातवीं योजना में भोजन, कार्य व उत्पादकता को विशेष प्राथमिकता दी गई। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन को अधिकतम करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। गरीबी दूर करने के उद्देश्य में रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इस प्रकार सातवीं योजना में राजस्थान के विकास के लिए नई प्राथमिकताएं निर्धारित की गईं। विद्युत, जल, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण, अकाल की समस्या का निवारण, पिछड़े वर्गों का उत्थान एवं क्षेत्रगत में औद्योगिकीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया। इस प्रकार से योजना बनाई गई कि सन्तुलित विकास को बल मिले।

उपलब्धियां

Achievements

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मरुस्थल की श्रेष्ठताम के लिए सघन प्रयास किया गया तथा 182 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास और उनमें सिंचाई, पैयजल, निजली, लघु उद्योग शिक्षा आदि के कार्यक्रम भी सक्रमतापूर्वक संचालित किए गए। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वनों की कमी और भूमि के कटाव को देखते हुए अरावली पर्वतीय क्षेत्र को पुन विकसित करने का निश्चय किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की भी चेष्टा की गई। 20-सूत्री कार्यक्रम का अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन एवं सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किए गए। २०-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रहा। इस योजनाकाल में कृषि उत्पादन का गूचकाक 1984-85 में 127 27 से बढ़कर योजना के अंत में 165 87 हो गया। इसी प्रकार मिचित क्षेत्रफल जो 1984-85 में 3204 हजार हैक्टेयर था, बढ़कर 3481 हजार हैक्टेयर हो गया। म्बी एवं खुरफ, दोनों फसलों में अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 27 27 लाख हैक्टेयर हो गया। इस योजनाकाल के अन्त में विद्यु का उत्पादन 6102 मिलियन युनिट तक पहुंच गया। मछली की लम्बाई भी 56956 किलोमीटर हो गई।

वार्षिक योजनाएं

ANNUAL PLANS - 1990-91 & 1991-92

31 मार्च 1990 को सातवीं योजना अवधि पूर्ण

हुई। इसके पश्चात् आठवीं योजना तुरन्त आरम्भ नहीं की जा सकी। आठवीं योजना को 1 अप्रैल '92 से आरम्भ किया गया। इस कारण राजस्थान में 1990-91 व 1991-92 की दो वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं। 1990-91 की योजना में 951 53 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था जबकि वास्तविक व्यय 975 57 करोड़ रुपये हुआ। 1991-92 की योजना में 1166 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था। इस योजना में सम्भावित वार्षिक व्यय 1184 41 करोड़ रुपये था।

वार्षिक योजनाओं के उद्देश्य

Objectives

ये वार्षिक योजनाएँ आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई थीं। इन योजनाओं में शक्ति के साधनों को विकसित करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसी के साथ कृषि एवं सिंचाई के साधनों को विकसित करने की चेष्टा की गई। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर एक बड़ी राशि खर्च करके उनका विस्तार करने का लक्ष्य भी रखा गया। उद्योग एवं खनिजों के विकास के लिए सरचनात्मक ढांचे के विस्तार हेतु योजनागत, शक्ति एवं निचाई पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

उपलब्धियाँ

Achievements

1990-91 में खाद्यान्नों का उत्पादन 109 लाख टन तक पहुँच गया। 1991-92 में तिलहन का उत्पादन 27 लाख टन हो गया। विद्युत की स्थापित क्षमता 1991-92 में 2775 30 मेगावट तक पहुँच गई व विद्युत्बल गृहों की संख्या 28564 हो गई। सड़कों की लम्बाई 1991-92 में बढ़कर 59913 किमी हो गई और 11536 गाँवों का सड़कों के माध्यम से सम्पर्क सम्भव हो गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना - 1992-97

EIGHTH FIVE-YEAR PLAN - 1992-97

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1990 से आरम्भ होनी थी किन्तु विभिन्न कारणों से यह 1 अप्रैल, 1992 से आरम्भ हो गई।

उद्देश्य

Objectives

(i) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए शक्ति के संधियों के विकास एवं प्राणीय विद्युतीकरण पर विशेष बल दिया गया। इस उद्देश्य से परिवहन एवं

संचार साधनों को विकसित किया गया। आर्थिक विकास के लिए खानगान दालों आदि के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे कि न केवल राज्य की आवश्यकताएँ पूरी हो पाएँ वरन् उनका निर्यात भी किया जाये।

(ii) मानवीय ससाधन के विकास के लिए रोजगार के सृजन के विशेष प्रयास किए गये। जम्माछा को प्रभावी तरीकों में नियंत्रित करने की चेष्टा की गई। महारता का प्रयास किया गया। न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएँ एवं प्रत्येक गाँव को पेयजल उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई।

(iii) कृषि के विकास के लिए सिंचाई साधनों पर विशेष बल दिया गया। अकाल एवं सुखाग्रस्त तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवन्ध को विशेष महत्व दिया गया, कृषि विविधिकरण की चेष्टा की गई तथा जल प्रवन्ध के साथ ही बज्र धूमि के विकास का कार्य भी किया गया।

व्यूहरचना

Strategy

अधुनक उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये गये

(i) प्रतिव्यक्ति आय के गृहीय औसत और राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय में विद्यमान अंतर को कम करने का प्रयास किया गया। इस हेतु ऊँची विकास दर अपनानी थी। ऊँची विकास दर प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन, जल प्रवन्ध और विद्यमान क्षमता का पूरा प्रयोग किया गया। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे पर्यटन, हस्तकला, हस्तकराधा आदि पर विशेष बल दिया गया। इसके साथ ही खनिज एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया गया।

(ii) सामाजिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। इस सदर्भ में श्रापीय क्षेत्रों का विशेष ध्यान दिया गया।

(iii) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिनमें अधिच रोजगार की सम्भावना विद्यमान है, जैसे कृषि एवं प्राणीय कार्यक्रम, छोटी निचाई योजनाएँ, वा विकास, पर्युपालन का विकास, हस्तकला, त्रास्यन एवं लघु उद्योग आदि।

(iv) जनसंख्या की विकास दर को कम करने की चेष्टा की गई।

(v) विभिन्न परियोजनाओं में निरधारित समयावधि से ज्यादा समय लगने पर परियोजना लागत बढ़ जानी है। इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर सिंचाई के क्षेत्र में क्षमता के पूरे उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

(iv) कृषि में विविधकरण तान की चेष्टा की गई। इस हेतु पशुपालन, मत्स्यपालन, कृषि विधायन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार ही विभिन्न योजनाएँ बनाई गईं।

(vii) राजस्थान में जल की कमी है अतः इस सीमित साधन के सर्वाधिक कुशल उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

(viii) सूखा एवं अकाल राजस्थान की प्रमुख समस्या रहे हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्हें सामान्य योजना कार्यक्रमों में स्थान दिया गया।

(ix) शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान की स्थिति में सुधार के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया जिसमें वे राज्य के विकास में अधिक योगदान कर सकें।

(x) समाज के एक पिछड़ा वर्ग-अनुसूचित जाति एवं जनजाति को निर्धनता निवारण और रोजगार कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी गई।

(xi) आधारभूत सुविधाएँ जुटाने के उद्देश्य से प्रत्येक गाँव का पेयजल उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई। रूत की बीमारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया ताकि 'सन् 2000 में सबके स्वास्थ्य' का लक्ष्य पूरा किया जा सके। मानव एवं पशु की निरन्तर घटती जनसंख्या के कारण वातावरण पर पड़ने वाले प्रतिभूत प्रभावों को रोकने तथा अनेक क्षेत्रों में मरुस्थल प्रसार की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किये गये।

(xii) विज्ञान एवं औद्योगिकी को राज्य की आवश्यकताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ध्यान वृद्धि किया गया।

(xiii) सड़क की गैर विकास मंदों पर किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करने की चेष्टा की गई।

(xiv) आठवीं योजना में जिला नियोजन पर विशेष बल दिया गया।

योजना का आकार

Size of the Plan

राजस्थान की आठवीं योजना के अंतर्गत 11500 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। विभिन्न मंदों पर निरा जाने वाला व्यय के आधार पर ज्ञात होता है कि -

(1) योजनाकाल में शक्ति के विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई

(2) व्यय के प्राथमिकताक्रम के अंतर्गत द्वितीय व तृतीय स्थान सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण को दिया गया। कृषि एवं सहायक सेवाओं और ग्रामीण विकास हेतु भी पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार अन्य पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में अधिक है।

(4) राज्य की अन्य पंचवर्षीय योजनाओं के समान आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी उद्योग एवं खनिज विकास हेतु अन्य मंदों की अपेक्षा कर्म धन का निर्धारण किया गया।

(5) परिचय्य के आवंटन से ज्ञात होता है कि राज्य में सरचनात्मक ढाँचे के निर्माण हेतु सर्वाधिक धन व्यय किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन Review of 8th five Year Plan

आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण, चालू परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने और कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुधन, मत्स्यपालन, व कृषि विधायन (Agro-processing) आदि में प्राथमिकता प्रदान की गई। राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) का परिचय्य 11500.00 करोड़ रुपये था। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 283 प्रतिशत अधिक था। आठवीं योजना का वास्तविक व्यय 11865.06 करोड़ रुपये रहा। ऐसा करना राज्य के तुलनात्मक पिछड़ेपन की दृष्टि से भी उपयुक्त था। क्षेत्रानुसार सर्वाधिक प्राथमिकता शक्ति क्षेत्र को प्रदान की गई जिसके लिये योजना के कुल परिचय्य का 28.31 प्रतिशत भाग निश्चित किया गया। सामाजिक व सेवाओं के लिये 21.41 प्रतिशत, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये 16.70 प्रतिशत, कृषि और सहायक गतिविधियों के लिये 11.19 प्रतिशत, यातायात के लिये 6.82 प्रतिशत, उद्योग एवं खनिज के लिये 4.66 प्रतिशत, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये 0.73 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं व वैज्ञानिक सेवाओं के लिये 1.30 प्रतिशत भाग निश्चित किया गया था।

आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम

Basic Minimum Services programme

आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, आधार सुविधा, सड़क का निर्माण पोषाहार,

अधिक मूल्य की दुकानें, शैक्षिक शिक्षा की अनिवार्यता तथा सस्तरता में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर व्यय करेंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ एवं असफलताएँ निम्न हैं।

(1) कृषि और सम्बन्धित सेवाएँ (Agriculture & Allied Services) - राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। 1996-97 तक खाद्यान्न का कुल उत्पादन 130 19 लाख टन के स्तर तक पहुँच चुका है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन मानचुन की स्थिति पर निर्भर करता है। राजस्थान देश एक बड़े तेल उत्पादक के रूप में उभरा है। 1991-92 में तेल का कुल उत्पादन 27 08 लाख टन था जो बढ़कर 1996-97 में 40 49 लाख टन हो गया। कृषि विकास परियोजनाएँ (Agriculture Development Project) विश्व बैंक की सहायता से 1992-93 में प्रारम्भ की गईं। यह परियोजना कृषि और सम्बन्धित सेवाओं में क्रियान्वित की जा रही है। 1996-97 में 7 01 लाख टन रसायनिक खाद का वितरण किया गया जो 25 लाख टन वितरण लक्ष्य से अधिक है। इसलिये वितरण लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। आठवीं योजना में 'गोपाल' योजना को सुदृढ़ किया गया। यह राज्य के 12 जिलों की 40 पंचायत समितियों में चल रही है। आठवीं योजना में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) द्वारा 72 2 लाख लीटर दूध का संग्रह किया गया जब दूध संग्रह का लक्ष्य 12476 लाख लीटर था। इसका प्रमुख कारण दुग्ध व्यवसाय में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा है। योजना काल में अल्प-कालीन, मध्यम-कालीन तथा दीर्घ-कालीन साख वितरण के लक्ष्य क्रमशः 250 करोड़ रु., 10 करोड़ रुपये तथा 50 करोड़ रु. थे जबकि साख वितरण की वास्तविक रकम क्रमशः 508 करोड़ रुपये, 151 करोड़ रुपये तथा 185 90 करोड़ रुपये रही। राज्य के 10 जिलों में जापान के सहयोग से 1992-93 में अरावली वनीकरण परियोजना (Aravalli Afforestation Project) प्रारम्भ की गई। इसी प्रकार राज्य के 14 जिलों में जापान के सहयोग से ही वन विकास परियोजना (Forestry Development Project) 1994-95 में प्रारम्भ की गई।

(2) ग्रामीण विकास (Rural Development) - गरीबी निवारण कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाकाल में 4 89 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया जबकि लक्ष्य 7 45 लाख परिवारों को लाभान्वित करना था। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना काल में 1819.20 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना राज्य के 237 ब्लॉक्स में अप्रैल 1997 में प्रारम्भ की गई। 1996-97 में यह योजना

204 ब्लॉक्स में लागू थी। योजनाकाल में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 148871 आवासों तथा जीवन धारा योजना के अन्तर्गत 22734 कुओं का निर्माण किया।

(3) सिंचाई (Irrigation) - 1992-93 में कुल सिंचित क्षेत्र 52 64 लाख हेक्टेयर था जो बढ़कर 1995-96 में 63 61 लाख हेक्टेयर हो गया। योजनाकाल में 3 05 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया जबकि लक्ष्य 4 35 लाख हेक्टेयर था।

(4) शक्ति (Power) - योजना के अन्त में शक्ति सृजन क्षमता 3049 56 मेगावाट तक पहुँच गई। योजनावर्ष में 3703 गावों को विद्युतीकृत किया गया जबकि लक्ष्य 3750 गावों को विद्युतीकृत करना था। योजना में 125278 कुओं/पम्पसेटों को विद्युतीकृत किया गया जबकि लक्ष्य 1,25,000 कुओं को विद्युतीकृत करना था। राज्य के निचले क्षेत्र में 7230 मेघावाट विद्युत का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

(5) उद्योग एवं खनिज (Industries & Mineral) - योजनाकाल में 13594 लघु उद्योग इकाइयाँ तथा 13874 दस्तकारी इकाइयों का पञ्जीकरण किया गया जबकि दोनों का लक्ष्य 10,000 इकाइयों का पञ्जीकरण करना था। राज्य वित्त निगम ने योजनाकाल में 10005 इकाइयों को 842.27 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। राज्य सरकार द्वारा 1994 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास करना है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना की गई है। खनिज आधारीत उद्योगों का विकास करने के लिये नवीन खनिज नीति का घोषणा की गई है।

(6) यातायात (Transport) - योजनाकाल में 4022 गावों को सड़क से जोड़ा गया जबकि योजनाकाल में 6600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 1089 गावों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य था।

(7) सामाजिक एवं समुदाय सेवाएँ (Social & Community Services) - योजनाकाल में 5730 प्राथमिक स्कूलें, 2649 उच्च प्राथमिक स्कूलें, 442 सेकण्डरी स्कूलें, 340 सीनियर सेकण्डरी स्कूलें खोली गईं जबकि लक्ष्य क्रमशः 3498, 1400, 300 और 200 स्कूलें खोलने का था। योजनाकाल में 15 नवीन महाविद्यालय खोले गये जबकि लक्ष्य केवल 3 महाविद्यालय खोलने का था। राज्य के सभी जिलों को खसरा अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। योजनाकाल में 505 स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य था जबकि वास्तव में 288 स्वास्थ्य 'केन्द्र' खोले गये। राज्य में एक महत्वपूर्ण

विकास यह है कि 1995-96 से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना 'विकल्प' (Vikalp) के नाम से आरम्भ की गई। सरकार विकल्पालयों के निर्माण में निजी विनियोग को बढ़ावा दे रही है। योजनाकाल में 143068 ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिये आवासों की व्यवस्था की है जबकि लक्ष्य 1,34,000 आवासों का निर्माण था। योजना काल में 88 8 हजार अनुसूचित जाति के छात्रों, 68 7 हजार अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा 5 6 पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 1990-91 तक 34818 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई थी जो बढ़कर मार्च, 1997 में 37414 हो गई। इस प्रकार आठवी योजना में 3668 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई। 1995 तक राज्य में 52 49 लाख घरेलू और 5 35 लाख विदेशी पर्यटक आना प्रारम्भ हो गए। सितम्बर 1995 में 'परित्या पर राजमहल' नामक रेलगाड़ी प्रारम्भ की गई।

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य

GENERAL OBJECTIVES OF FIVE-YEAR PLANS IN RAJASTHAN

राजस्थान में भी भारत के समान पंचवर्षीय योजनाएँ संचालित की जाती हैं। वस्तुतः राज्य सरकारें केन्द्र सरकार का अनुसरण करती हैं। अतः राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्यों में समानता दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। अतः राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यह उद्देश्य राज्य की प्रायः सभी योजनाओं पर अपनाया गया है। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्यों का विवेचन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(1) शक्ति के साधनों का तीव्र गति से विकास (Development of Power Resources) - राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव था। इस तथ्य का ध्यान में रखते हुए राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सख्यनात्मक ढांचे के निर्माण पर विशेष धन दिया जाता रहा है। राज्य की प्रायः सभी पंचवर्षीय योजनाओं में शक्ति के साधनों, विशेष रूप से विद्युत शक्ति के विकास एवं विस्तार का उद्देश्य रहा है। राज्य में शक्ति के साधनों का अभाव दूर करने के लिए दीर्घकालीन नीति का अनुसरण किया गया है। फलतः

शक्ति के साधनों का समुचित विकास हुआ है।

(2) औद्योगिक विकास (Industrial Development)

- राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगिकीकरण पर भी विशेष धन दिया गया है। इस क्षेत्र के विकास हेतु खनिज उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य निर्धारित किए गए। यही कारण है कि राज्य में सीमेंट, सगमरमर, इमारती पत्थर, तांबा, सोमा व जस्ता आदि खनिज आधारित उद्योगों पर तेजी से विकास हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य के औद्योगिकीकरण का स्तर भी पहले की तुलना में ऊँचा हुआ है। राज्य में रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और अन्य उपभोग्य उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का उद्देश्य भी निश्चित किया जाता है। फलतः इन उद्योगों का भी तेजी से विस्तार हुआ है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

(3) कृषि विकास (Agricultural Development)

राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र का विकास क्रांति के रूप में किया गया और इस क्रांति को भाग्य के सम्राज में हरित क्रांति के नाम से ही संबोधित किया जाता है। हरित क्रांति के अन्तर्गत राज्य में कृषि संबंधी विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु नवीनतम कृषि तकनीक के प्रयोग पर विशेष धन दिया गया। इसके अतिरिक्त, सिंचाई के साधनों में तीव्र गति से विस्तार करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। फलतः राज्य में सिंचाई के साधन विशेष रूप से नहरों व बहु-उद्देशीय परियोजनाओं का तेजी से विकास एवं विस्तार हुआ। इंदिरा गांधी नहर जैसी विशाल नहर परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लक्ष्य का ही परिणाम है कि राज्य के इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में अनेक सिंचाई परियोजनाओं के लक्ष्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं।

(4) पशु सम्पदा का विकास (Development of Animal Wealth)

- राज्य में पशुधन को रोजगार एवं दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। अतः विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पशु सम्पदा का विकास एवं डेयरी व्यवसाय को भी उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इन क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार हेतु महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। डेयरी उद्योग का विकास एवं विस्तार हेतु

ऑपरेशन फ्लट प्रथम व द्वितीय सभी उद्देश्य पूर्ण कर लिए गए हैं और ऑपरेशन फ्लट तृतीय चालू है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में टेक्नोलॉजी मिशन कार्यक्रम के द्वारा डेपेंडें विकास किया जा रहा है।

(5) परिवहन व संचार के साधनों का विकास (Development of Transport & Communication) - सार्वजनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से परिवहन व संचार के साधनों का भी विकास करना आवश्यक होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता रहा है। इसके साथ-साथ संचार के साधनों पर भी तेजी से विकास हुआ है। इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में परिवहन व संचार सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। संचार के साधनों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। राज्य के पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं का विस्तार एवं जनकल्याण कार्यों में वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के द्वारा सामाजिक सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

(6) क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करने के प्रयास (Efforts to Lessen the Regional Disparities) - राज्य में अत्यधिक क्षेत्रीय असमानताएँ विद्यमान हैं, इन असमानताओं में कमी करके ही आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करने के उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करने हेतु सरकार ने योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रयास किए हैं। फलतः राज्य के प्रायः सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से प्रारम्भ हो रही हैं।

(7) अकाल एवं सूखे की समस्या का समाधान (Solution of Famine & Draught) - राजस्थान में प्रायः अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी रहती है अतः राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस समस्या के समाधान सम्बन्धी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता रहा है। योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रयासों के फलस्वरूप इस समस्या की गम्भीरता में कमी आयी है। राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया है और पेयजल की व्यवस्था हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

(8) बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण (Eradication of Poverty & Unemployment) - राज्य की प्रायः

सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके विपरीत, आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत कम है। फलतः निर्धनों व बेरोजगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार ने बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं प्रयोजनाओं का संचालन किया। समय-समय पर इन कार्यक्रमों सम्बन्धी लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। राज्य की छठी, सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता एवं बेरोजगारी सभी विभिन्न कार्यक्रमों का विशेष स्थान प्रदान किया है। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन के प्रावधान सर्वोच्च लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आठवीं योजना की व्यूह-रचना इस प्रकार निर्धारित की गई है कि सन् 2000 तक लगभग सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

योजनाओं का आकार

SIZE OF PLANS

व्यय की दृष्टि से राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के आकार में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अधिक विकास का क्रम प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में एकीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। योजनाओं के अंतर्गत कृषि के साथ-साथ उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। अतः उत्तरोत्तर अधिक धनराशि की आवश्यकता अनुभव की गई। दक्षिण भारत के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के परिचय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। पाचवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् ये योजना परिव्यय में भारी वृद्धि हुई है। निम्न तालिका में राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के परिव्यय एवं वास्तविक व्यय की दृष्टियाँ गयी हैं -

राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का परिचय व वास्तविक व्यय (क्रोड रुपये)			
योजना-योजना	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय व वास्तविक व्यय में अंतर
प्रथम पंचवर्षीय (1951-56)	64.50	54.15	63.2
द्वितीय पंचवर्षीय (1956-61)	105.27	102.74	63.2
तृतीय पंचवर्षीय (1961-66)	236.00	212.70	124.1
चतुर्थ पंचवर्षीय (1966-69)	132.72	135.75	-
पंचम पंचवर्षीय (1969-74)	305.21	308.79	29.7

प्रथम पंचवर्षीय (1974-79)	849.16	857.62	176.6
द्वितीय पंचवर्षीय (1979-80)	275.00	290.19	-
तृतीय पंचवर्षीय (1980-85)	2025.00	2120.45	139.0
चतुर्थ पंचवर्षीय (1985-90)	3000.00	3108.18	48.1
पंचम पंचवर्षीय (1990-95)	961.53	975.57	-
छठम पंचवर्षीय (1995-2000)	1166.00	1178.46	-
सातम पंचवर्षीय (2000-05)	11500.00	11965.06	283.3

Source: Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt of Rajasthan
 Data: Ninth Five Year Plan 2000-05 Govt of Rajasthan

उपरोक्त तालिका 3 पराक्षेप से ज्ञात होता है कि-

- (1) राज्य की विभिन्न योजनाओं के आकार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।
- (2) प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक व्यय केवल 54.15 करोड़ रुपये था जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11865.06 करोड़ रुपये व्यय किए गए।
- (3) राष्ट्रीय योजनाओं के आकार में वृद्धि का आभास इस तथ्य से भी होता है कि प्राथमिक पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में वार्षिक योजनाओं में भी तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय किया गया।
- (4) राष्ट्रीय योजनाओं के आकार में वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि के साथ-साथ उद्योग परिवहन एवं व्यापार आदि क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना है।

योजनाओं के आकार में वृद्धि से यह भी ज्ञात होता है कि राज्य के आर्थिक विकास की दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

योजनाकाल में क्षेत्रवार वास्तविक व्यय

SECTOR WISE EXPENDITURE IN PLANNING PERIOD

राज्य की विभिन्न योजनाओं में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु धनराशि का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकताक्रम का निर्धारण किया जाता है। प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य की नवजाती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उदाहरण के लिए राज्य में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। इन समस्याओं के निवारण हेतु लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इसी प्रकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए मरचनात्मक ढांचे का निर्माण करने हेतु मिचाई शक्ति एवं परिवहन के साधनों के विकास पर विशेष बल दिया जाता है। इस तथ्य का ज्ञान राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजना में किए गए क्षेत्रवार वास्तविक व्यय से किया जा सकता है। क्षेत्रवार वास्तविक व्यय को अग्रजित तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रवार वास्तविक व्यय (प्रतिशत में)									
क्षेत्र	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	छठम	सातवीं	आठवीं	नववीं
कृषि एवं सहकार क्षेत्र	4.84	6.15	5.83	3.33	3.67	4.53	5.21	11.24	11.24
सामाजिक विकास	5.61	12.19	6.81	0.97	2.24	5.87	6.74	8.71	8.71
सहकारिता	0.48	1.89	1.14	1.72	1.80	1.25	1.34	0.38	0.38
विशाल एवं बहु निदेश	57.82	27.12	41.31	34.09	31.62	25.80	22.23	18.40	18.40
शक्ति	2.29	14.75	18.50	30.43	29.03	26.70	29.68	30.99	30.99
उद्योग एवं उद्योग	0.85	3.28	1.56	2.77	4.03	3.95	4.69	8.49	8.49
परिवहन	10.25	9.90	4.33	3.24	9.82	11.50	4.59	8.70	8.70
वैज्ञानिक सेवाएँ एवं उद्योग	-	-	-	-	-	0.01	0.07	0.18	0.18
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	16.84	24.38	20.15	23.34	17.35	19.61	23.70	30.93	30.93
आर्थिक सेवाएँ	-	0.11	0.11	0.11	0.10	0.07	0.43	0.72	0.72
सामान्य सेवाएँ	-	0.24	-	-	0.32	0.48	1.20	1.85	1.85
कुल वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	54.15	102.74	212.70	308.79	857.62	2120.45	3108.18	11865.06	11865.06
कुल प्रतिशत	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Source: Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt of Rajasthan Data: Ninth Five Year Plan 2000-05 Govt of Rajasthan

तालिका 3 पराक्षेप से स्पष्ट है कि -

- (1) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इन मद पर

योजना के कुल व्यय का 57.82 प्रतिशत व्यय किया गया। सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं एवं परिवहन पर व्यय क्रमशः 16.84 प्रतिशत एवं 10.25 प्रतिशत रहा।

योजनाकाल में वैज्ञानिक शोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उद्योग एवं खनिज विकास सहकारिता व आर्थिक सेवाओं पर बहुत कम धनराशि व्यय की गई।

(2) द्वितीय योजना में पुनः सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान क्रमशः सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, शक्ति एवं ग्रामीण विकास का रहा। परिवहन के विकास हेतु भी पर्याप्त धन व्यय किया गया। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के विकास हेतु सरचनात्मक ढांचे के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा शक्ति का रहा। शक्ति के विकास हेतु प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं की तुलना में अधिक धनराशि का निर्धारण किया गया सहकारिता, उद्योग एवं खनिज पर अपेक्षाकृत बहुत कम धन व्यय किया गया।

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना में भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः शक्ति और सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का रहा। योजनाकाल में अन्य योजना की तुलना में ग्रामीण विकास पर बहुत कम धन व्यय किया गया। इसी प्रकार कृषि और सहायक क्रियाओं तथा परिवहन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया।

(5) पांचवी पंचवर्षीय योजना पर भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान शक्ति एवं सामाजिक सेवाओं का रहा। शक्ति के साधनों पर तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा अधिक व्यय किया गया। उद्योग एवं खनिज विकास पर विगत योजनाओं की तुलना में अधिक धन व्यय किया गया।

(6) छठी पंचवर्षीय योजना में शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का रहा। कृषि एवं सहायक सेवाओं तथा ग्रामीण विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस योजना में सर्वप्रथम वैज्ञानिक मेकअप एवं शोध कार्यों के लिए कुछ धन व्यय किया गया।

(7) सातवी पंचवर्षीय योजनाओं में भी सर्वोच्च प्राथमिकता शक्ति को प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के रहे। कृषि, ग्रामीण विकास तथा उद्योगों के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया।

(8) राजस्थान की आठवी योजना का व्यय सातवी योजना के व्यय से लगभग 4 गुना है। निम्न 7 क्षेत्रों में यह व्यय किया गया कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण, शक्ति, उद्योग एवं खनन, यातायात तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं। कुल व्यय का मात्र 2.65 प्रतिशत विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम, वैज्ञानिक शोधन मेकअप, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय किया गया। आठवी योजना में सर्वाधिक व्यय 26.12 प्रतिशत शक्ति के क्षेत्र में किया गया। यह व्यय सातवी योजना में किए गए व्यय का लगभग नौ गुना है लेकिन प्रतिशत-व्यय की दृष्टि से इसका भाग लगभग 3.2 प्रतिशत कम हुआ है। आठवी योजना में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय (26.08 प्रतिशत) सातवी योजना की तुलना में शक्ति की दृष्टि से 'पराह' गुना से अधिक हो गया। सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण पर सातवी योजना की तुलना में लगभग नौ गुना राशि व्यय की गई है लेकिन कुल व्यय के प्रतिशत में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। आठवी योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सातवी योजना की तुलना में इस पर आठ गुना से अधिक राशि व्यय की गई है।

(9) राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक धन सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण शक्ति तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय किया गया। योजनाकाल में उद्योग एवं खनिजों के विकास हेतु व्यय किए गए धन में उतार-चढ़ाव रहा। पांचवी और सातवी योजनाओं में अन्य योजनाओं की तुलना में उद्योग एवं खनिज पर अधिक ध्यान दिया गया।

योजनाओं में प्रतिव्यक्ति व्यय

PER CAPITA EXPENDITURE IN PLANS

भारत व राजस्थान का विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति व्यय की स्थिति को भी अग्रणीक तालिका से समझा जा सकता है -

प्रतिव्यक्ति योजना व्यय			
व्यय	भारत (रुपये)	राजस्थान (रुपये)	राष्ट्रीय औसत की तुलना (रुपये)
प्रथम योजना	38	34	4 से कम
द्वितीय योजना	51	65	14 से अधिक
तृतीय योजना	92	97	5 से अधिक
चतुर्थ योजना	142	120	22 से कम
पांचवी योजना	362	332	30 से कम
छठी योजना	718	622	96 से कम

सातवी योजना	1157	875	282 से कम
आठवी योजना*	5129	2614**	2516 से कम

*आठवी योजना में परिव्यय में 1991 की जनगणना का भाग दिया गया है। अप्रैल, 1992 को अनुमानित जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति व्यय कम हो जायेगा।

* Economic Review 1995-96 Rajasthan

Source: Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजस्थान की प्रथम योजना से लेकर अब तक आठवी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत (283.3%) की वृद्धि हुई है। द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय अधिक रहा है किन्तु इसके पश्चात् अर्थात् चतुर्थ योजना से लेकर सातवी योजना तक यह निम्नतर राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। साथ ही राष्ट्रीय औसत की तुलना राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय तेजी से पिछड़ता जा रहा है। यह चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय औसत से 22 रुपये कम था किन्तु सातवी योजना में यह इस औसत से 282 रुपये कम था। राजस्थान की आठवी योजना का प्रतिव्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से 2516 रुपये कम प्रतीत होता है।

राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का भाग SHARE OF RAJASTHAN IN NATIONAL PLAN EXPENDITURE

राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का भाग भी परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन का आभास इस तालिका से होता है -

योजना	राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का प्रतिशत भाग
प्रथम योजना	3.29
द्वितीय योजना	2.25
तृतीय योजना	2.75
चतुर्थ योजना	1.94
पांचवी योजना	2.15
छठी योजना	2.07
सातवी योजना	1.67
आठवी योजना	2.65

Source: Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या के आकार की दृष्टि से नवा व क्षेत्रफल के आकार की दृष्टि से दूसरा स्थान है किन्तु राष्ट्रीय योजना परिव्यय में इसका भाग अभी भी 3% (प्रथम योजना को छोड़कर) से अधिक नहीं रहा। राजस्थान की सातवी योजना के परिव्यय (1.67%) की तुलना में आठवी योजना के

अन्तर्गत (2.65%) लगभग 1% की वृद्धि अंकित की गई है।

प्रमुख विकास कार्य¹

IMPORTANT DEVELOPMENT WORK

योजनाकाल के आरम्भ से अब तक किए गए विकास कार्यों की सक्षिप्त समीक्षा निम्न प्रकार है-

(1) राजस्थान ने खाद्यान्नों में लगभग आत्मनिर्भरता का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। 1950-51 में 33.8 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता था जो 1998-99 में बढ़कर 112.25 लाख टन हो गया। कृषि क्षेत्र में विशेष प्रयास के बावजूद भी कृषि उत्पादन में मानसून की अनुकूलता का गहरा प्रभाव पड़ता है। कृषि क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता विलहन उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में तो राजस्थान अग्रणी राज्य हो गया है। राजस्थान में सिंचित क्षेत्र 1951-52 में 11.7 लाख हेक्टेयर था जो 1996-97 में 67.43 लाख हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में आज भी आधे से अधिक भाग कुओं से सींचा जाता है यद्यपि नहरों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। बोई गई कृषि भूमि का लगभग एक-तिहाई (32.6%)² भाग ही सिंचित है जो कि चित्त का विषय है।

(2) शक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की गई है। 1951-52 में विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 13 मेगावाट थी जिसमें असाधारण वृद्धि हो चुकी है। यह क्षमता आठवी योजना के अंत में 258.65 मेगावाट हो गई।

(3) राजस्थान के औद्योगीकरण के परिवेश में परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिक उत्पादों का विविधीकरण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान में 1949 में 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थी जो 1994 में बढ़कर 13395 तथा 1996 में बढ़कर 13665 हो गईं³।

(4) योजनाकाल में राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज की गई है और उनके विशाल भण्डार खोजे गए हैं। इस संदर्भ में रॉक फॉस्फेट, इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला चूना-पत्थर, लिग्नाइट, मार्बल, ग्रेनाइट, जस्ता-सीसा, सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होने वाला चूना-पत्थर, जिप्सम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

(5) परिवहन की दृष्टि से सड़कों की लम्बाई 1951-52 में 17339 किलोमीटर थी। 1998-99 में बढ़कर 84958 किलोमीटर हो गई है⁴।

(6) शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। 1950-51

¹ Data from Eighth Five Year Plan 1992-97, Govt. of Rajasthan
² Ibid
³ Ibid
⁴ Ibid

में 4436 श्राईमगे विद्यालय थे ये आठवी योजना के अंत में बढ़कर 33829 तथा 1998-99 में 34098 हो गये हैं। सरकार के प्रयासों से आठवी योजना के अंतर्गत 37889 गावों में से 37540 गावों को पंचवत्स सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी।

(7) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सबसे अधिक ध्यान सुदृढ़ सरचनात्मक आधार बनाने पर दिया गया। इसीलिए सिंचाई एवं शक्ति के साथ सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं शक्ति पर धन केन्द्रित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं शक्ति पर कुल योजना परिव्यय का 60% से भी अधिक व्यय करने का प्रावधान किया गया था। आठवी योजना में यह प्रतिशत कम होकर 41.6 रह गया है। दूसरी ओर, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का 16.84% था जो कि आठवी पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 26.08 प्रतिशत हो गया। दूसरे क्षेत्रों पर प्रतिशत व्यय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मूलभूत संरचना के विकास के लिए सिंचाई, शक्ति यातायात पर किया जाने वाला व्यय प्रथम योजना के परिव्यय का 70.63% था जो आठवी योजना में कम होकर 48.97% रह गया।

(8) योजनाकाल के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रयासों के बाद भी राज्य का घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत से नीचे है। 1980-81 की सीमांत पर 1980-81 में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय (1222 रुपये) राष्ट्रीय औसत (1630 रुपये) से लगभग 400 रुपये से कम थी। 1995-96 में भी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय (2051 रुपये) राष्ट्रीय औसत (2573 रुपये) में लगभग 500 रुपये कम थी। 1998-99 में भी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2275 रुपये थी। संक्षेप में, राजस्थान ने विगत चार दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन फिर भी राज्य के विकास की अथाह विकास की सम्भावनाएं अभी विद्यमान हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए।

राजस्थान की नवी पंचवर्षीय

योजना (1997-2002)

NINTH FIVE YEAR PLAN OF RAJASTHAN

आजादी की 50वीं जयजयन्ती के सुनहरे अवसर पर राजस्थान में नवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 में प्रारम्भ की गई जो 31 मार्च सन् 2002 में पूर्ण होगी। इस योजना के लिये 27,443.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो आठवी पंचवर्षीय योजना में व्यय की

गई राशि के दुगुने से भी अधिक है। अतः योजनाकाल में राज्य की आर्थिक विकास की दर में तेजी से वृद्धि होने की सम्भावना है। नवी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख तत्वों का विवेचन निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा रहा है।

A. नवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

Objects of Ninth Five Year Plan

नवी योजना के लिये निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये -

1. राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय औसत के अन्तर को कम करने के लिये उच्च विकास दर को प्राप्त करना।
2. सेवा क्षेत्र (ग्रामीण) तथा जन समाधनों के प्रबन्ध में जनसहभागिता को बढ़ावा देना।
3. सरचनात्मक विकास की चालू योजनाओं को पूर्ण करना तथा जल व शक्ति के लिये आधारभूत संरचना का निर्माण करना।
4. कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन तथा कृषि-विध्वन को प्राथमिकता प्रदान करना।
5. जल के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जल उपयोग नीति का निर्माण करना।
6. सिंचाई संरचना को सुदृढ़ करने के लिये एक नीति का निर्माण करना।
7. किन्हीं परियोजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही उसके विस्तार पर विचार करना ताकि समय व लागत में बचत हो सके।
8. औद्योगिक विकास पर विशेष बल देना।
9. पर्यटन, हेन्डलूम और दस्तकारों का तीव्र विकास करना।
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु प्रभावी प्रयास करना।
11. राज्य की जनसंख्या यदि वर्तमान दर से बढ़ती रही तो यह 2045 ई में स्थिर होकर लगभग 11 करोड़ हो जायेगा। अतः जनसंख्या नियोजन के ऐसे प्रयास किये जायेंगे ताकि जनसंख्या 2021 ई में ही स्थिर हो जाये।
12. सामाजिक न्याय की दृष्टि से निर्धनता निवारण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा।
13. रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिये कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम, छोटी सिंचाई योजनाओं, वन, पशुधन, दस्तकारों तथा ग्रामीण उद्योगों का तेजी में विकास करना।
14. समय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
15. महिला विकास कार्यक्रमों को प्रभाव दान से लागू करना।

- 16 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।
- 17 मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाने के प्रभावपूर्ण प्रयास करनी।
- 18 ग्रामीण विकास के लिये राज्य में विज्ञान एवं तकनीकी विकास को सुदृढ़ किया जायेगा।
- 19 सजुलित विकास को ध्यान में रखते हुए कमी वाले क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जायेगा।
- 20 कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जायेगा।

योजना का आकार

Size of Ninth Plan

यह योजना 27 44380 रुपये की है। इस राशि का आवन्तन निम्न प्रकार किया गया है -

नवी पंचवर्षीय योजना में व्यय (कोड़ रुपये)		
क्र. सं.	क्षेत्र	व्यय
1	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाएं	1880 04
2	ग्रामीण विकास	1979 68
3	विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	140 60
4	सिंचाई	2876 67
5	शक्ति	6534 88
6	उद्योग एवं परिवहन	2127 59
7	परिवहन (वातायता)	2689 18
8	पैदाइय सेवाएं	38 40
9	सांसायनिक एवं सामुदायिक सेवाएं	7452 31
10	आर्थिक सेवाएं	349 72
11	सांसायनिक सेवाएं	674 73
12	कमर प्रयोजित योजनाएं	700 00
योग		27443 80
		100 00

स्रोत Ninth Five Year Plan 1997-2002 Govt. of Raj

कृषि

Agriculture

योजनाकाल में कृषि उत्पादन की दर में वृद्धि करने, अधिक स्थिर एवं समान विकास को बढ़ावा देने, कृषि तकनीक का विकास करना तथा कृषि विधायन के द्वारा योजना के अवसरों में वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। योजना में निम्न परम्परा के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये -

नवी योजना में कृषि उत्पादन (लक्ष्य)		
फलन	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन)
खाद्यान्न	124.25	134.65
फलितहन	39.00	39.50

जन्य	0.20	10.00
विकास (लाख गाँवों)	6.00	15.25

स्रोत Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Raj

इस योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाओं के लिये 1880 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशुधन

Animal Husbandry

नवी योजना में पशुधन के विकास हेतु उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी। पशु आधारित उद्योगों का विकास किया जायेगा। दुग्ध व्यवसाय में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा। पशुओं के लिये घास उत्पादन में वृद्धि की जायेगी। योजनाकाल में पशुओं से प्राप्त वस्तुओं के निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये-

नवी योजना में पशु आधारित उत्पादों के उत्पादन लक्ष्य	
उत्पाद	लक्ष्य (2001-2002)
ऊन (ताप किलोग्राम)	200
अण्डे (मिलियन)	600
दूध ('000 टन)	6200
घास ('000 टन)	60

स्रोत Ninth Five Year Plan, 1997-2002 Govt. of Raj

योजनाकाल में पशु विकास पर 12429 92 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य पालन

Fisheries

राजस्थान में मत्स्य पालन की पर्याप्त सम्भावनाएँ उपलब्ध हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नवी योजना में 3 30 लाख हेक्टेयर में मत्स्य पालन का कार्य किया जायेगा। 1 2 लाख हेक्टेयर में बांधों से 1 लाख हेक्टेयर में ताताबो से तथा 0 30 लाख हेक्टेयर में नदियों से मछलियाँ पकड़ी जायेगी। योजनाकाल में मत्स्य पालन पर 944 40 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

वन

Forests

नवी योजना में वन विकास हेतु निम्न कार्य पर बल दिया जायेगा -

- (i) वन प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जायेगा।
- (ii) वन सुरक्षा के विभिन्न प्रकार के कार्य जायेंगे।
- (iii) पारिस्थितिकी सन्तुलन बनाये रखने के लिये विभिन्न

प्रबन्ध किये जायेंगे।

(iv) परम्परागत तरीकों एवं नवीन तकनीक के आधार पर वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी।

(v) वन विस्तार की योजना बनाई जायेगी।

जल संसाधन

Water Resources

नवी योजना में भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार का कार्य जारी रखा जायेगा। अकालग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई साधन का विस्तार किया जायेगा। जल प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जायेगा। राज्य की 29.13 लाख हेक्टेयर मम्भविध सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जायेगा। भूगर्भीय जल के अत्यधिक विदोहन को नियंत्रित करने के लिये कानून बनाया जायेगा। बाढ़ के पानी को रोकने लिये छोटे तालाबों का निर्माण किया जायेगा। जल विकास कार्यक्रमों में विनियोजित के लिये निजी-क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

शक्ति

Energy

राज्य में शक्ति की मांग एवं पूर्ति में अन्तर बना हुआ है। सन् 2001-02 तक राज्य में शक्ति की मांग लगभग 5606 मेगावाट होगी। इस भाग को पूर्ण करने के लिये 8000 मेगावाट शक्ति विकसित करनी होगी। राज्य की वर्तमान शक्ति क्षमता 3050 मेगावाट है। अतः 4900 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सूरतगढ़ व रायदा-गैस आधारित शक्ति परियोजनायें निर्माणधन हैं जिनकी शक्ति क्षमता लगभग 600 मेगावाट हो गी। शेष 4300 मेगावाट शक्ति क्षमता का सृजन करने के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में 6184.50 मेगावाट शक्ति क्षमता के लिये प्रयास प्रारम्भ किये जा चुके हैं। इस कार्य की वर्तमान मूल्य पर लागत लगभग 18845 करोड़ रुपये होगी। नवी योजनाकाल में निजी क्षेत्र में 2265 मेगावाट शक्ति क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाकाल में राज्य के ग्रामीणों को विद्युतीकृत करने का कार्य किया जायेगा। नवी योजना में 300 मेगावाट क्षमता की सौर-ऊर्जा विकसित की जायेगी। योजनाकाल में शक्ति के विकास पर 6534.88 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

उद्योग एवं खनिज विकास

Industry & Mineral Development

आय एवं आर्थिक सामाजिक मूचकों के राज्य-एवं राष्ट्रीय स्तरों में विद्यमान अन्तरों को समाप्त करने के लिये नवी योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान

की गई है। नवीन औद्योगिक नीति का शीघ्र निर्माण किया जायेगा। निर्धनता निवारण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर बल दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी। इसके लिये प्रशिक्षित श्रम शक्ति विकसित की जायेगी। ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिये नवीन प्रौद्योगिकी विकसित की जायेगी।

नवी योजना में उन खनिजों के विदोहन पर विशेष बल दिया जायेगा जिनका देश में अभाव है और जिनका निर्यात बढ़ाया जा सकता है। योजना में आधारभूत धातुओं, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट सीमेन्ट बनाने का पत्थर, मार्बल ग्रेनाइट, फायर क्ले, फ्लोराइट, पोटाश, रॉक फॉस्फेट स्वर्ण, टंगस्टन आदि की खोज एवं विदोहन पर बल दिया जायेगा। इस योजना में उद्योग एवं खनिजों के विकास हेतु 2127.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

परिवहन के साधनों का विकास

Development of Communication Network

राज्य के ग्रामों को ग्रामीण सड़कों के द्वारा जोड़ा जायेगा। सड़क नीति 1994 के अनुसार राज्य में सड़कों का तेजी से विकास किया जायेगा। सड़क भरवना के विकास में निजी विनियोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। रेल-विकास में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य में परिवहन प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जायेगा। योजनाकाल में परिवहन के साधनों के विकास में 2689.18 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

अन्य क्षेत्र

- (1) नवी योजना में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।
- (2) शिक्षा-संस्थानों (तकनीकी शिक्षा सहित) का तेजी में विस्तार किया जायेगा।
- (3) योजना में 'ममी के लिये स्वास्थ्य' के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।
- (4) सम्पूर्ण राज्य में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
- (5) शहरी क्षेत्र के विकास पर बल दिया जायेगा।

प्रस्तावित नवी पंचवर्षीय योजना राजस्थान की आर्थिक प्रगति में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी क्योंकि (i) यह योजना विगत पंचवर्षीय योजना की तुलना में बड़े आकार की है। (ii) योजना कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया है। (iii) राज्य के मूचकों की राष्ट्रीय स्तरों से तुलना करके विकास का प्रयास किया गया है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A सक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान की छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताएँ बताईए।
Print out the main priorities of the Sixth and Seventh Five-Year Plans of Rajasthan
- 2 राजस्थान की विकास योजनाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on development plans of Rajasthan
- 3 आठवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा कीजिए।
Evaluate the 8th Five Year Plan of Rajasthan
- 4 राजस्थान की नवी योजना के क्या उद्देश्य हैं?
What are the objects of 9th Five Year Plan of Rajasthan?
- 5 राजस्थान की वर्तमान नियोजन तंत्र क्या है?
What is the present Planning Machinery in Rajasthan?
- 6 विकेंद्रित नियोजन क्या है?
What is Decentralised Planning?

B निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
What are the objectives of Economic Planning in Rajasthan? Review the economic progress made during the planning period
- 2 राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य क्या रहे हैं? उनको व्यवहार में कहीं तक प्राप्त किया जा सका है? विवेचना कीजिए।
What are the main objectives of Economic Planning in Rajasthan? How far have these been achieved in practice? Analyse
- 3 राजस्थान राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Critically examine the objectives and targets of Eighth Five Year Plan of Rajasthan State
- 4 राजस्थान में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये और नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
Discuss the main achievements of Planning in Rajasthan and review the economic progress under the planning period
- 5 '45 वर्ष के नियोजित नियोजन के बाद राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है।' व्याख्या कीजिए।
'Rajasthan is a backward state despite of its regular planning of 45 years' Discuss

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
What are the objectives of Economic Planning in Rajasthan? Review the economic progress under the planning period
- 2 राजस्थान में नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
Review the economic progress during the planning period in Rajasthan
- 3 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरुआत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
Critically explaining the Draft of Eighth Five Year Plan of Rajasthan
- 4 आर्थिक नियोजन किसे क्या है? आधुनिक युग में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।
What is Economic Planning? Explain its importance in present age
- 5 नियोजन काल में राजस्थान में विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिये।
Analyse the main trends in economic development during plan period in Rajasthan
- 6 राजस्थान में नियोजन तंत्र का वर्णन कीजिए।
Discuss the Planning Machinery in Rajasthan

राजस्थान का आर्थिक विकास : विशेषताएं एवं बाधाएं

ECONOMIC DEVELOPMENT IN RAJASTHAN CHARACTERISTICS & CONSTRAINTS

'बचने का इन, उनके निराकरण हेतु आवश्यक है।'

अध्याय एक दृष्टि में

- ☐ राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं
- ☐ राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान
- ☐ राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान
- ☐ राजस्थान के होत विकास हेतु सुझाव
- ☐ अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं

MAIN CHARACTERISTICS OF ECONOMY OF RAJASTHAN

राजस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भौगोलिक दृष्टि से इस राज्य की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है। यही कारण है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अपेक्षाकृत धीमी गति से विकास हुआ। वस्तुतः राजस्थान निर्माण का कार्य 1956 में पूर्ण हुआ। अतः विकास प्रक्रिया में विलम्ब होना स्वाभाविक था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों, पशु सम्पदा और मानवीय श्रम की विशेष भूमिका रही है। राज्य व केंद्र सरकारों के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भी नियोजित ढंग से विकास किया जा रहा है। भारत के समान राजस्थान में भी नियोजन प्रक्रिया का प्रभाव निरन्तर बना हुआ है। राज्य सरकार वर्तमान में नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 का संचालन व निर्देशन कर रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(1) कृषि की प्रधानता एवं कृषि का आधुनिकीकरण (Dominance of Agriculture & Modernisation of Agriculture) - राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यह राज्य-आय का प्रमुख स्रोत है और राज्य की अधिकांश जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करती है। कृषि के अंतर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन पशुपालन व डेयरी विकास, वन विकास तथा मत्स्य व्यवसाय आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रारम्भ में राजस्थान में कृषि मुख्यतः परम्परागत तरीके से की जाती थी लेकिन हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं पीली क्रांति के फलस्वरूप राज्य की कृषि में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। इन श्रमिकारी उपायों के माध्यम से उत्पादन विधियों में सुधार किया गया, वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ उठाया गया और कृषि क्षेत्र में पहले की तुलना में अधिक धन व्यय किया गया। राज्य में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण का क्रम आज भी जारी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कृषि में संबंधित विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कृषि क्षेत्र का विकास अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है लेकिन कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में सिंचाई एवं शक्ति के साधनों के विकास पर विशेष धन दिया गया है। राजस्थान नहर जैसी सिंचाई परियोजनाओं को राज्य की ही नहीं बरन सम्पूर्ण भारत के लिए एक उत्तेजनीय उपलब्धि कहा जा सकता है।

2 अपर्याप्त औद्योगिकीकरण एवं खनिज विकास (Insufficient Industrialisation & Mineral Development) - किन्ती भी क्षेत्र, राज्य अथवा देश के औद्योगिक विकास हेतु एक आधारभूत ढांचे के निर्माण की पूर्व शर्त होती है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान की अर्थव्यवस्था अत्यधिक छिन्न-छिन्न अवस्था में थी। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव था। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राज्य योजनाओं में सार्वनात्मक ढांचे के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। यह क्रम वर्तमान में भी जारी है। अब तो भारत सरकार ने भी राजस्थान की इस समस्या को अनुभव करते हुए राज्य के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वनात्मक सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। राज्य में सार्वनात्मक ढांचे सम्बन्धी समस्या के विद्यमान होते हुए भी योजनाकाल में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ। राज्य के जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, गानगार बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसमें राज्य में औद्योगिक एवं आर्थिक विपन्नताओं में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार राज्य में औद्योगिकीकरण की गति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम रही।

राज्य में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी एवं आर्थिक विपन्नताओं के आधार पर भी कहा जा सकता है कि राज्य में औद्योगिक विकास अपर्याप्त है।

(3) जनसंख्या वृद्धि एवं पर्याप्त श्रमशक्ति (Growth of Population & Sufficient Labour Force) - राजस्थान में भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या विश्व के अनेक छोटे राष्ट्रों की तुलना में अधिक है। राज्य की जनसंख्या का एक उत्तेजनीय बिन्दु यह है कि यह का जनसंख्या घनत्व केवल 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत के जनसंख्या घनत्व के औसत से बहुत कम है। राज्य की जनसंख्या पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध करने में सक्षम है लेकिन राज्य की संपूर्ण जनशक्ति का नियोजित ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। मानवीय श्रमशक्ति का पर्याप्त उपयोग न हो पाने का एक प्रमुख कारण यह है कि राज्य में पूँजी का अभाव है। राज्य के जनसंख्या घनत्व का वितरण अत्यधिक असमान है। रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं अरावली पर्वत-श्रृंखलाओं वाले क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। अतः इससे राज्य के आर्थिक विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। राज्य में जनसंख्या बढ़ने की गति तीव्र है, जबकि आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत कम है।

(4) कम वर्षा व सीमित जल ससाधन (Less Rain & Scarce Water Resources) - राजस्थान में भी मानसून के ढांग वर्षा होती है। राज्य में वन अत्यधिक सीमित क्षेत्र में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, राज्य में ऊँचे पहाड़ों का भी अभाव है। अतः मानसून में राज्य में बहुत कम वर्षा होती है। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो वर्षा का प्रायः अभाव ही बना रहता है। इस स्थिति में राज्य के कृषि क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु सिंचाई के साधनों का विस्तार करने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी इसे राज्य की संपूर्ण आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पा रही है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। राज्य में वर्षा पर्यन्त बढ़ने वाली नदियों का अभाव है। राजस्थान के आन्तरिक सतही जलस्रोतों से उपलब्ध जल देश के सतही जलस्रोतों का 1/16 प्रतिशत ही है। वर्षा की कमी और मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण यहां लगभग 75 लाख एकड़ फीट भूगर्भीय जल और 158 60 लाख एकड़ फीट भूतटील जल की क्षमता है। इस स्थिति में राज्य में सिंचाई के लिए खिने पानी और माध्यमों की जरूरत है उसमें हम काफी पीछे हैं।

(5) सामाजिक संरचना (Social Structure) राज्य में सामाजिक सुविधाओं का स्तर निम्न है अतः योजनाकाल में आधारभूत सामाजिक सुविधाओं की वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। आधारभूत सामाजिक सुविधाओं के विस्तार हेतु राज्य की पाचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवारों को समाज के अन्य वर्गों के समान आगे लेने के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की रचनात्मक योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। इसी प्रकार बाल कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण कार्यक्रम, वृद्धों एवं अशक्त व्यक्तियों की सेवा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन और शोषण को समाप्त करने के लिए व्यापक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं धुमकड़ जातियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है। इसी प्रकार अदिवासी माताओं के बच्चों की देख रेख हेतु जयपुर और जोधपुर में शिशु गृहों की स्थापना की गई है। पिछड़े वर्गों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने एवं सामाजिक न्याय दिलाने सम्बन्धी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को 30 जनवरी, 1990 से लागू कर दिया गया है। निर्धनता निवारण के लिए एक विशिष्ट योजना लागू की गई है। अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम अनुसूचित जाति के परिवारों के व्यक्तिगत लाभ व आय वृद्धि की योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इसी प्रकार, विकलांगों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु राज्य में अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है।

(6) राजनैतिक विचारधाराओं का प्रभाव (Effect of Political Ideologies) राज्य अर्थव्यवस्था विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं में भी प्रभावित होती रही है। राजनैतिक विचारधारा के साथ-साथ योजनाओं के निर्माण और उनकी प्रथमिकताओं में परिवर्तन हो जाता है। सरकारें बदलने पर कभी आवर्ती योजनाएँ अपनाई जाती हैं तो कभी पंचवर्षीय योजनाएँ। राजनीति के कारण ही प्रायः राज्य और केंद्र में विवाद उत्पन्न होते हैं। राजनैतिक विचारधाराओं में भिन्नता के कारण आर्थिक विकास के कार्य में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब केंद्र एवं राज्य में विभिन्न विचारधारा वाली सरकारें होती हैं तो प्रायः राज्य में आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। मत विभिन्नता के कारण अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन नहीं हो पाता है। अतः राज्य अर्थव्यवस्था भी राजनीति के प्रभावों से मुक्त नहीं है।

(7) प्रदूषण के प्रति निश्चेत अर्थव्यवस्था (Irresponsible Economy Towards Pollution) - योजनाकाल के पश्चात् राजस्थान में पर्याप्त औद्योगिक एवं वृष्टि विकास हुआ है किन्तु आर्थिक विकास के साथ-साथ प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं किए गए। यह मान लिया गया कि आर्थिक विकास और प्रदूषण साथ-साथ चलते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए हैं किन्तु वे किसी प्रकार से पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। इस कारण आर्थिक विकास एवं प्रदूषण के साथ-साथ चलने की संभावना है। विगत कुछ वर्षों से राज्य के पाली, जोधपुर, कोटा, जयपुर आदि शहरों में प्रदूषण की समस्या गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। पानी में तो प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने न केवल अनेक कारखानों को बंद कर दिया वरन् नवीन कारखानों की स्थापना पर रोक लगा दी है। यह प्रवृत्ति राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकती है।

(8) भ्रष्टाचार व लालचीताशाही (Corruption & Red Tapsism) - राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गई है। भ्रष्टाचार व लालचीताशाही इस हद तक बढ़ गई है कि इसके मानवीकरण की मांग की जाने लगी है। गुनार मिडल ने भी इस संदर्भ में कहा कि भारत में भ्रष्टाचार की अनदेखी की जाती रही है। राजस्थान में किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। दुर्भाग्य से, इसमें मलमल विभाग, अधिकारी व कर्मचारी पूर्ण कर्मठता व लगन से कार्य नहीं करते।

(9) व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी व क्षेत्रीय विषमता (Poverty, Unemployment & Regional Disparities) - राजस्थान की अर्थव्यवस्था इन तीनों ही समस्याओं से ग्रस्त है। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में कम है। बेरोजगारी एक आम समस्या है और राजस्थान के रंगिस्तानी क्षेत्रों का विकास अत्यन्त ही धीमा है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग रंगिस्तानी होने के कारण यहाँ का विकास आरम्भ से ही अवलूट सा रहा है। इस क्षेत्र में राजस्थान नहर के कारण स्थिति के बदलने की संभावना है। साथ ही रंगिस्तानी क्षेत्र में खनिज तेल की संभावना के कारण सम्पूर्ण राजस्थान का आर्थिक विकास तीव्र हो सकता है।

(10) परिवहन व संचार (Transport Communication) - राजस्थान में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए परिवहन व संचार के माधनों का विकास

करना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं में परिवहन व सड़क के साधनों के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाती रही है अतः राज्य के अधिकांश भागों में परिवहन व संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ है। लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र अभी भी इन सुविधाओं में बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हो पाये हैं। इन सुविधाओं के अभाव के कारण पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्र का औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत नाण्य रहा है। यह स्थिति राज्य के पिछड़ेपन की ओर संकेत करती है।

(11) निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका (Increasing Role of Private Sector) स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था का विकास भी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्रारम्भ हुआ। जुलाई 1991 के पूर्व तक इसी नीति का अनुसरण किया गया लेकिन जुलाई 1991 की नवीन औद्योगिक नीति में शार्वरीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी पुनरी एवं उदार अर्थव्यवस्था के विचार को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया। भारत सरकार की इस नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार राजस्थान में भी सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आठवीं पञ्चवर्षीय योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन इसी तथ्य का ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में तत्काल गति से विकास की सम्भावना है।

(12) पर्यटन का बढ़ता महत्व (Increasing role of tourism) राजस्थान में भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। यह उद्योग राज्य-आय में वृद्धि कर प्रमुख स्रोत बन सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के ऐतिहासिक स्थलों और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जैसलमेर दुर्ग और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए जयपुर के समाचार आयुक्त की अध्यक्षता में एक बारह सदस्यी समिति गठित की गई। अजमेर में दरगाह क्षेत्र के विकास के लिए योजना स्वीकृत की गई। भारत सरकार के माध्यम से जयपुर साठमेर जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पर्यटन विपणन व लिए विवरणित संस्थाओं से सहयता प्राप्त करने तथा अजमेर को वायुसेवा से जोड़ने के प्रयास जारी हैं।

(13) अकाल एवं सूखा (Famines & Droughts) राजस्थान में वर्षा के अभाव के कारण अकाल एवं सूखा की स्थिति बनी रहती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव राज्य का निर्धन जनता पर पड़ता है। राज्य सरकार ने इस समस्या को समाधान हेतु निर्माई सामान्य के विकास पर पर्याप्त ध्यान

दिया है। लेकिन यह व्यवस्था राज्य की आवश्यकताओं से बहुत कम है। अकाल एवं सूखे के कारण राज्य के अनेक भागों में पयजल का अभाव उत्पन्न हो जाता है। राज्य में ग्रोष्मकाल में पयजल आपूर्ति की स्थिति ठीक रहे तथा लोगों को मकट का सामना न करना पड़े। इस दृष्टि से समुचित प्रबन्ध विये जाते हैं। पयजल आपूर्ति में सुधार के लिए सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध किया जाता है। जर्मन सरकार के सहयोग से राज्य के गगानगर चुरू और धुल्लू जिलों के खारे पानी वाले क्षेत्रों में गांवों को पयजल मुलभ बनाने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को 75 लीटर पयजल मुलभ करवाया जायेगा। योजना अन्तर्गत पयजल के लिए पानी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से उपलब्ध करवाया जायेगा। वर्तमान में साहवा व पाण्डूर में जल शोधन संयंत्र लगे हुए हैं। तीन और जल शोधन संयंत्र चरणान्तर करमसाणा और तारापुर में बनाए जायेंगे। यूनिसेफ के सहयोग से भूमिगत जल विकास के लिए योजना बनाई जा रही है। बीसलपुर जयपुर परियोजना के लिए सहयता जुटाने की एक योजना विश्व बैंक को भेजी गई है।

(14) सम्पन्नता में दरिद्रता (Poverty in Plenty) राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एवं धनी प्रदेश है। लेकिन फिर भी वल्ल के निवासियों की प्रतिष्ठाक्ति आय बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। राज्य में अनेक प्रकार की विषमताएं विद्यमान हैं। राज्य के कुछ व्यक्तियों की आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत राज्य की अधिकांश जनसंख्या प्रायः निर्धन है। राज्य के शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्र विकास का इंतजार कर रहे हैं। ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं और भव्य इमारतों की तुलना में झोपड़ियों की बाहुल्यता राज्य में सम्पन्नता के मध्य दरिद्रता को दर्शाती है। राज्य सरकार इस समस्या के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है लेकिन राज्य की तेज गति से बढ़ती जनसंख्या इन सरकारी प्रयासों को असफल कर देती है।

(15) राजस्थान में बढ़ता विदेशी पूंजी निवेश (Increasing Foreign Capital Investment in Rajasthan) आर्थिक विपन्नताओं के चलते राजस्थान का विकास अर केवल वल्ल सहायता पर निर्भर है। इसके लिए राज्य सरकार की उम्मीदें विदेशी आर्थिक सहयोग पर टिकी हैं। सरकार ने अभी विदेश बैंक सहित विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थाओं से जो वाराम्य बिठाया है उसके मुताबिक

करीब सवा छह हजार करोड़ रुपए की विदेशी सहायता और ऋण मिलने की सभावना है। अगले पाच वर्षों में यह सहायता कृषि, भूमि सधारण, वनीकरण, ग्रामीण विकास सिंचाई, ऊर्जा, सड़क, शिक्षा तथा समाज कल्याण के कार्यों के लिए मिलेगी। इनमें से कुछ के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं से समझौते कर लिए गए हैं तथा अन्य के लिए बातचीत अंतिम दौर में है। उच्च सरकारी सूत्रों के अनुसार 1992-97 के 1055 करोड़ रुपए विश्व बैंक और अन्य वित्तीय एजेंसियों से लिए गए हैं। विदेश से आने वाला यह ऋण भारत सरकार के जरिए आता है, जिसमें 70 प्रतिशत ऋण और तीस प्रतिशत अनुदान होता है। ऋण की अदायगी की अवधि बीस वर्ष है। राजस्थान को आम तौर पर विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, जापान की ओडोराईफ, जर्मनी के के डब्ल्यू एफ, स्वीडन की सोडा और कनाडा की सीआईडीए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त हो रहा है। इनमें कुछ वित्तीय संस्थाओं की परियोजनाएँ इस वर्ष पूर्ण होने वाली हैं आन्ध्र प्रदेश के पश्चात राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ इन वित्तीय संस्थाओं ने अपना रुपया लगाना स्वीकार किया है। उधर गैर सरकारी सूत्रों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में प्राप्त ऋण से हालाँकि सुधरने की बजाय बिगड़े। राज्य सरकार पर फिलहाल जितने ऋण हैं उन पर 1865 करोड़ रुपये इनका ब्याज चुकाने में ही चले जाते हैं, जबकि राज्य की बिजली से आमदनी ही 2050 करोड़ है। यानी जितनी राजस्व प्राप्तियाँ हैं उसका तीर-चौथाई ब्याज के चुकाने में ही जा रहा है। कर्ज इस तरह बढ़ते रहे तो भावी स्वरूप क्या होगा यह सोचा जा सकता है। राजस्थान ने अभी तक कर्ज चुकाने के लिए पूरे साधन तलाश नहीं किए हैं। सरकार जुटी अवश्य है, पर रास्ते सूझे नहीं हैं। राज्य सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में बाह्य सहायता की जो परियोजनाएँ तैयार की हैं उनसे उसे 6327 करोड़ रुपए मिलने की सभावना है। इसमें सर्वाधिक 16965 करोड़ रुपये ऊर्जा के क्षेत्र में हैं, जिसमें 660 करोड़ रुपये बिजली सुधार, पारेषण और वितरण पर और 980 करोड़ रुपये मर्यादित सौर ऊर्जा परियोजना के भी शामिल हैं। इसी तरह कृषि विकास परियोजनाओं के लिए 203 करोड़, भूमि एवं जल सधारण के लिए 145 करोड़ 88 लाख की परियोजनाएँ हैं। वनीकरण के लिए 547 करोड़, 91 लाख की योजना में अरावली पौधरोपण परियोजना के लिए 367 करोड़ और ओसीएफ की 180 करोड़ की वन विवास परियोजना है। इसी तरह ग्रामीण विकास की 401 करोड़ की तथा सिंचाई की 402 करोड़ की परियोजनाएँ हैं। इसमें 198 करोड़ का राजस्थान वाटर कमोन्टिडेशन प्रोजेक्ट है। कमांड एरिया डवलपमेंट की 76 करोड़ की परियोजनाएँ हैं। मड़कों के लिए 353

करोड़ का राजस्थान स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट है, जबकि शिक्षा के लिए डीपीसी परियोजना भी 880 करोड़ की है। पाच सालाना इस परियोजना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की 211 करोड़ की परियोजना है, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 601 करोड़ की परियोजनाएँ हैं। इनमें बीसलपुर से जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने की 243 करोड़ की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पहुँचा करने की 164 करोड़ की परियोजनाएँ भी शामिल हैं।

(16) विकास के लिये विदेशी सहायता पर बढ़ती निर्भरता (Increasing dependence on foreign Assistance for development) - राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी कंपनियों एवं अनिवासी भारतीयों द्वारा पूँजी विनियोजन में 10 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 तक राज्य में सीधे व अनिवासी भारतीयों में 10 इकाइयों में कुल 15 करोड़ 18 लाख रुपये की विदेशी पूँजी निवेशित थी। वर्ष 1990-97 की अवधि में 54 इकाइयों में सीधे अनिवासी भारतीयों के माध्यम से कुल 159 करोड़ 85 लाख रुपये की विदेशी पूँजी का विनियोजन हुआ जो 1990 तक हुए विदेशी पूँजी निवेश की तुलना में 10 गुना से भी अधिक है। राज्य में वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए भारत सरकार की अगस्त, 1991 से जुलाई, 97 तक 1638 औद्योगिक उद्यमिता संपन प्रस्तुत किए गए जिनमें 25 हजार 700 करोड़ रुपये का पूँजी विनियोजन प्रस्तावित है तथा जिनसे 3 लाख 3 हजार 698 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हो सकेगा।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में वर्ष 1990-97 की अवधि में 35 हजार 764 लघु एवं कुटीर उद्योग इकाइयाँ स्थापित हुईं। इनमें 13 अरब 81 करोड़ रुपये से अधिक का पूँजी विनियोजन हुआ। इसके विपरीत वर्ष 1985-90 के मध्य 35 हजार 112 लघु एवं कुटीर उद्योग इकाइयों की स्थापना हुई जिनमें 3 अरब 29 करोड़ 71 लाख रुपये का पूँजी विनियोजन हुआ।

राज्य में इस वर्ष सितंबर तक एक लाख 89 हजार लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित हो चुके हैं जिनमें 21 अरब 42 करोड़ 61 लाख रुपये का पूँजी विनियोजन हुआ है।

वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में भी राजस्थान में पिछले वर्षों में सरहदनीय प्रगति हुई है। मार्च, 1990 तक राज्य में वृहद एवं मध्यम स्तर की इकाइयों की संख्या 225 थी तथा उनमें 22 अरब 23 करोड़ 37 लाख रुपये का पूँजी विनियोजन हुआ था। आर्थिक उदारीकरण एवं राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषण के उपरान्त वर्ष

1990 में 1997 के मध्य 290 वृद्ध एवं मध्यम स्थापित हुए। जिनमें 99 अर्ब 84 करोड़ 38 लाख रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ।

राज्य में वर्ष 1985-90 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख 33 हजार 968 व्यक्तियों को रोजगार मुलभ हुआ जबकि 1990-97 की अवधि में इस क्षेत्र में 2 लाख 33 हजार 930 व्यक्तियों को रोजगार मुलभ हुआ है।

राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं MAJOR PROBLEMS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राज्य में कृषि की समस्याओं का अध्ययन निम्न शार्थकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(a) प्राकृतिक बाधाएं (Natural constraints)

1 राजस्थान में वर्षा अत्यधिक अर्पाज और अनिश्चित प्रकृति की है।

2 राज्य का 61 प्रतिशत भाग मरुस्थलीय आर अर्द्ध मरुस्थलीय है।

3 इस क्षेत्र की मिट्टी उत्पादकता की दृष्टि से कमजोर है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता कम होती है और यह अपना स्थान बदलता रहता है।

4 वर्षा की कमी के कारण भूगर्भीय जल की उपलब्धता मामूली है।

■ उच्च तापमान और वायु की तीव्र गति फसलों को नुकसान पहुंचाता है।

(b) सामाजिक बाधाएं (Social Constraints)

1 राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

2 ज्ञात के उपविभाजन में वृद्धि हुई है। 1980-81 में जोनों का संख्या 44-87 लाख था जो बढ़कर 1990-91 में 51-07 लाख हो गई।

3 मर्यादा का स्तर (38%) क्रिपेण्ड मंडिला साक्षरता (20%) कम है।

4 महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा कम है।

5 महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि कृषि कार्य में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होता है।

6 जनसंख्या का अधिकांश भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (30%) से सम्बन्धित है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। एम. व्यक्तियों की जेखिम उठाते की क्षमता कम होती है और ये लोग नवीन प्रौद्योगिकी को जल्दी नहीं समझ पाते हैं।

(c) शोध सम्बन्धी बाधाएं (Research Constraints)

1 अकाल से लड़ने के उपयुक्त तरीकों का अभाव।

2 कृषि विधायन, बागवानी और चारा फसलों के विशेषज्ञ सीमित है।

3 फसल काटने के पश्चात की क्रियाओं के प्रबन्ध सम्बन्धी साहित्य और जानकारी सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

4 वायो टेक्नोलोजी और टीशू कल्चर शोध सुविधाओं का अभाव है।

5 विभिन्न प्रकार की जलवायु में कृषि करने मन्त्री जानकारी कम है।

6 ओरगेनिक फार्मिंग सम्बन्धी शोध का निरन्तर अभाव है।

7 अनेक फसलों के लिए सम्बन्धित रोग प्रबन्ध का अभाव है।

8 जल की बचत करने वाले प्राचीन उपारों जैसे - बूढ़ बूढ़ कृषि फव्वारा मिचाई आदि के क्षेत्र में शोध का अभाव है।

9 समस्या ग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की व्यूह रचना का अभाव है।

(d) सरचनात्मक बाधाएं (Research Constraints)

1 कृषि पदार्थों सम्बन्धी फुटकर दुकानें अपर्याप्त (2450 व्यक्तियों पर एक) है।

2 बैंकिंग सुविधाओं (सितम्बर, 1993 तक एक लाख जनसंख्या पर 6-5 बैंक) का अभाव है।

3 शक्ति की पूर्ति अपर्याप्त है।

4 कृषि विपणन और विधायन संरचना का अभाव है।

5 कृषि में यंत्रोपकरण की गति धीमी है।

6 राजस्थान में सड़कों की लम्बाई प्रति चौ. वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध राष्ट्रीय औसत का 55 प्रतिशत है।

7 बागवानी और सब्जियों सम्बन्धी फसलों के विपणन की संरचना का अभाव है।

8 पशु चिकित्सा की मांग और पूर्ति के मध्य अन्तराल बहुत अधिक है साथ ही पशु बाजार असंगठित है। इसमें पशु पालकों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(e) कृषक की अशिक्षा एवं अज्ञानता (Illiteracy & Lack of Knowledge)

- यदि भारत के सद्भ में राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान का कृषक अधिक अशिक्षित प्रतीत होता है। इसी कारण राजस्थान में कृषि के अन्तर्गत नवीन विधियों का अधिक प्रयोग नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण कृषक साह्कारों के घगुल में फंसे हुए हैं। अशिक्षा के कारण ही राजस्थान में महकारी आंदोलन अधिक गति प्राप्त नहीं कर पाया है। अशिक्षित कृषक अधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों के आगामी से शिकार हो जाते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसमें कृषि विकास

अवरूद्ध हो जाता है। इस समस्या का समाधान कृषकों में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना है। इस प्रक्रिया में श्रेष्ठ शिक्षा का विशेष महत्व हो सकता है।

(f) **अपर्याप्त वित्त एवं ऋणग्रस्तता (Lack of Finance & Indebtness)** - राजस्थान का कृषक अशिक्षित होने के साथ-साथ निर्धन भी है। इस कारण वह अपने स्वयं के साधनों के कृषि विकास के लिए पर्याप्त वित्त नहीं जुटा पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सस्वाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। इस कारण उसे साहूकारों द्वारा ऊँची व्याज दरों पर ऋण पड़ता है। ये ऋण भी मुख्यतः अनुत्पादक ऋण होते हैं और इन अनुत्पादक ऋणों के कारण कृषक पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस ऋण का बोझ बढ़ता चला जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढ़ता है और ऋण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वह अपना ऋण आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ जाता है। राजस्थान में कृषकों में असंतोष का एक बड़ा कारण उनकी ऋणग्रस्तता है। डॉ. टॉमस ने ऋणग्रस्तता के संदर्भ में उपयुक्त ही कहा है, "ऋणग्रस्त समाज अनिवार्य रूप से एक सामाजिक ज्वाला-मुखी होता है। इस प्रकार के समाज में विभिन्न वर्गों में असंतोष उत्पन्न होना अनिवार्य है और भीतर ही भीतर बढ़ता हुआ असंतोष सदैव खतरनाक होता है।" वित्तीय साधनों की कमी के संदर्भ में सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ठीक ही कहा है कि "सहकारिता असफल हो चुके हैं लेकिन सहकारिता सफल होनी चाहिए।" ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अनुत्पादक ऋण भी प्रदान किए जाने चाहिए।

(g) **सिंचाई साधनों की अपर्याप्तता (Lack of Irrigation Facilities)** - राजस्थान में जल ससाधनों का अभाव है। नदियाँ कम हैं और लगभग सभी नदियाँ मानसूनी हैं। मानसून के अभाव में इनमें भी पानी नहीं रहता है। अनेक स्थानों पर भूजल का स्तर बहुत नीचा होने के कारण भी कृषि कर्मों में उसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण जल के अभाव में राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में कृषि उत्पादन लगभग 6 गुना बढ़ जाएगा। रेगिस्तानी भूमि में जल की और भी आवश्यकता होती है। अतः जल के अभाव में प्रायः ऐसे क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती है। सिंचाई साधनों के अभाव को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जल समझौते अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राजस्थान नहर ऐंसा ही एक उपरितीय प्रदान है।

(h) **कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव (Lack of Cottage & Small Industries)** - राजस्थान का कृषक

सामान्यतः एक फसल लेता है और इस प्रकार वर्ष के लगभग 4 माह कार्य करता है। शेष अवधि में वह बेकार बैठा रहता है। ऐसा इस कारण से है कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, "यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होती है तो भारत ही नष्ट हो जाएगा। ग्रामीण उद्योगों का विनाश भारत के सात लाख ग्रामों को नष्ट कर देगा।" कुटीर व लघु उद्योग न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में श्रम-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि भरकरी एवं निजी प्रयासों से कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास हो। इस हेतु सरकार को आकर्षक औद्योगिक नीति बनाकर लोगों को इस ओर आकर्षित करना होगा।

(i) **कृषि श्रमिकों की समस्याएँ (Problems of Agricultural Labour)** - राजस्थान में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है। इनमें से भी बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। इस कारण वे दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। ये लोग कृषि कार्य में निपुण होते हुए भी अत्यन्त दैन-हीन स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं। इस कारण इनसे संबंधित समस्याओं के समाधान से ही कृषि का विकास सम्भव हो सकता है। कृषि सुधार समिति 1950 ने कहा था, "कृषि सुधार सन्धी किन्नी योजना में से कृषि श्रमिकों की समस्या को छोड़ देना देश की समस्या को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राजस्थान में बेकार पड़ी भूमि को आर्थिक जोतों के अंतर्गत कृषि श्रमिकों में बाँट दिया जाना चाहिए।

(j) **आदानों का बढ़ता मूल्य (Increasing Prices of Agricultural Inputs)** - कृषि में काम आने वाले सभी साधनों का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले खाद, बीज, औजार आदि की कीमतें निरन्तर बढ़ी हैं। सरकारी प्रयासों के बावजूद यह प्रवृत्ति बनी हुई है। रासायनिक खाद के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने के कारण उपभोग की गति तीव्र नहीं हो पाई है। कृषि आदानों के बढ़त मूल्यों के कारण एक ओर साधनों की लागत ता बढ़ गई है किन्तु दूसरी ओर उसकी तुलना में कृषि उपजों का मूल्य नहीं बढ़ पाया है। कृषि उपजों के मूल्यों में अनुपातिक वृद्धि न हो पान के कारण कृषि को हानि वहन करनी पड़ती है। इस कारण कृषक प्रायः घाटे में रहते हैं। यह सरकार का दायित्व है कि वह साधनों की कीमत को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करे।

(k) **अपर्याप्त भूमि सुधार (Lack of Sufficient Land Reforms)** - राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक कानून बनाए हैं। इसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा

सकता कि सभी समस्याएँ हल हो गई हैं। वर्षों से खेती करते आ रहे किसान आज भी भूमिहीन किसानों की तरह खेतदेगी के अधिकारों में दचित है। व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के कारण ही कृषकों में भूमि का वितरण अत्यन्त असमान है। भूमि का उप विभाजन और उप खण्डन अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जोत का आकार छोटा होता चला जाता है और एक समय के बाद वह अनार्थिक जोत में बदल जाती है। ऐसी भूमि पर अन्ततः कृषि करना भी बन्द कर दिया जाता है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि समस्याओं का व्यावहारिक हल निकाला जाना चाहिए और उन्हें वास्तव में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। 'उत्कृष्टता' के माध्यम में भी अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदला जा सकता है।

राजस्थान में कृषि की समस्याओं का समाधान

राजस्थान में कृषि की विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं।

- 1 सतहा एवं भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने के लिए बाधा का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 2 शारीरिक भूमि का कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- 3 भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।
- 4 कृषि जोतों के उपरिभाजन का प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून का निर्माण करके उस प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
- 5 कृषि कार्य में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए।
- 6 निर्धन निर्गम एवं पिछड़े वर्गों के कृषकों का कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत कराना चाहिए।
- 7 कृषि विशारदों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कृषि शिक्षा का तजी से प्रसार किया जाना चाहिए।
- 8 कृषि मशीन सहाय्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 9 कृषि शोध कार्यों का प्रसार किया जाना चाहिए।
- 10 कृषि विवास के लिए मिटाई के साधनों को पर्याप्त व्यवस्था की जाना चाहिए।
- 11 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रभाव प्रत्यक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 12 ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक मुक्तिधियों का निर्माण किया जाना चाहिए।

13 कृषि कार्यों के लिए शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की जानी चाहिए।

14 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन एवं विधायन संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।

15 ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए।

16 कृषि क्षेत्र में यंत्रोपकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

17 ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार किया जाना चाहिए।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की बाधाएँ व इनके निराकरण हेतु सुझाव

CONSTRAINTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN & SUGGESTIONS TO OVERCOME THEM

राजस्थान में विभिन्न उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं फिर भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि में देश के ओक राज्यों की तुलना में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। राज्य के कुछ ही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ है एवं राज्य के अधिकांश क्षेत्र औद्योगिकरण की दृष्टि में पिछड़े हुए हैं। 1969 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पांडे समिति ने राजस्थान राज्य के औद्योगिक दृष्टि में पिछड़ा घोषित किया था आज भी पिछड़ापन की स्थिति तनी हुई है। इसका प्रमुख कारण औद्योगिकरण में विभिन्न बाधाएँ अथवा समस्याएँ का उपस्थित होना है। राजस्थान के औद्योगिकरण की विभिन्न बाधाओं का विवरण अग्र विस्तार के अंतर्गत किया जा सकता है।

1 आधारभूत सुविधाओं का अभाव (Lack of Infrastructure) विविध औद्योगिक भूमि रिजर्व पाना सड़क, रेल इत्यादि में संरक्षित आधारभूत समस्याएँ उद्योगों के समक्ष हैं। राजस्थान के 38 जिलों में से केवल 10 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं। कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने में बाधाएँ पाना व संरक्षित जलने व टांगमार्गों लपान में अत्यधिक असुविधाएँ हैं। रेलवे की अधिशेष जमीन सीमांत क्षेत्रों में है। राजस्थान में प्रति एक वर्ग किलोमीटर पर सड़क का लम्बाई राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी प्रकार 1000 किलोमीटर में मात्र 17.02 किलोमीटर सड़क है। इसी प्रकार वन प्रति वर्ग किलोमीटर की खपत राष्ट्रीय औसत से कम है।

2 कच्चे माल की कमी (Lack of Raw Material) राजस्थान में कुछ विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल की

अभाव है। लोहा, कोयला, अलौह धातु, रसायन, पी वी सी आदि वस्तुएँ राज्य के उद्यमियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं। अतः इन वस्तुओं से संबंधित उद्योगों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। इन कच्चे पदार्थों का राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र में अभाव है। ऐसी स्थिति में आयातों के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

3 वित्तीय कठिनाईयाँ (Financial Difficulties) - राजस्थान में वित्त संबंधी अनेक कठिनाईयाँ विद्यमान हैं। अतः अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का औद्योगिक विकास कम हुआ है। वैक्यों ने इन औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं कराया है। वित्त संबंधी दूसरी समस्या अरा पुरी जुटाने की है। देश की विनियोजन समस्याओं का इस क्षेत्र में बहुत कम योगदान है। उन्होंने विनियोजित पूँजी का 23 प्रतिशत भाग ही राजस्थान में विनियोजित किया है। छोटे उद्योगों के लिए विद्युत संधियों द्वारा जो ऋण मार्ग निर्धारित किया जाता है, वह भी उद्यमी कई बार नहीं जुटा पाते हैं। केन्द्र सरकार ने भी अपने कुल विनियोगों का अल्पभाग ही राजस्थान में विनियोजित किया है।

4 विपणन समस्या (Marketing Problem) - राजस्थान स्वयं में एक बहुत बड़ा विपणन क्षेत्र नहीं है। यहाँ विशाल बाजारों व विकसित मण्डियों का अभाव है। इसके अतिरिक्त यह बंदरगाह व अन्य केंद्रों, जैसे कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कानपुर इत्यादि से बहुत दूर है। अतः कच्चा माल मगाना व निर्मित माल भेजना महंगा पड़ता है। राज्य की विभिन्न समस्याओं द्वारा भी स्थानीय उद्योगों से अपेक्षित खरीद नहीं होती। विप्रेषण की भी समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य के कुछ स्थानों पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करके मण्डियों की स्थापना की जा सकती है।

5 सुविधाओं में अंतर (Difference in Facilities) - नवीन उद्योगों की स्थापना मुख्यतः अधिक सुविधा वाले क्षेत्रों में की जाती है। सरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त जिन स्थानों पर बिमा, बैंकिंग व तकनीक संबंधी सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, उन क्षेत्रों की ओर नए उद्योगपति सहज आकर्षित होते हैं। कच्चे माल का अभाव व विपणन समस्या उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित करती है। यही कारण है कि अन्य राज्यों में राजस्थान की अपेक्षा अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने अपनी विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुछ स्थानों पर सरचनात्मक सुविधाएँ विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य के आबू रोड, बीकानेर, झालावाड़, भीलवाड़ा और धौलपुर का चयन विकास केंद्र योजना के अंतर्गत किया गया है। राज्य सरकार भी इसी तरह की अन्य

योजनाओं के माध्यम से राज्य में सुविधाओं का विस्तार कर सकती है।

6 क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance) - सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक कारणों से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में संतुलन नहीं रहा है। कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान दिया गया है जबकि अधिकांश क्षेत्रों को अद्वैतता की गई है। फलतः क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। राज्य के अन्य सभी जिलों की अपेक्षा जयपुर जिले का सर्वाधिक विकास हुआ है। राज्य के अधिकांश उद्योग इमी जिले में विद्यमान हैं। इसी प्रकार राज्य के पड़ोसी उद्योगों में विनियोजित पूँजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिले में विनियोजित है। क्षेत्रीय असंतुलन की ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध सधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) - राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकार की तुलना में रेलों का बहुत कम विकास हुआ है। बड़ी रेल लाइनों का विकास एक सीमित क्षेत्र में हो पाया है। राज्य के सभी भागों में पर्याप्त सड़कों की नहीं हैं। अतः माल का आवागमन में न केवल अनेक कठिनाईयाँ आती हैं वरन् परिवहन लागत भी ऊँची रहती है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों का विस्तार करने हेतु अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य हो रहा है। अतः औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सड़क व परिवहन का विशेष रूप से विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) - वर्षों के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। अतः राज्य में कृषि जन्य कच्चे माल का सदैव अभाव बना रहता है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों, जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति धातु आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए 'हरित क्रांति' का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त बत के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण

राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजा से विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इससे औद्योगिक विकास की गति स्वतः बढ़ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts)

राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति बनी रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक है। राज्य में अकाल की स्थिति बने रहने का प्रमुख कारण मासूम की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बड़े भाग में रेगिस्तान का होना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एवं बढ़ते हुए रेगिस्तान पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे की समस्या व समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओं का शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। एपी परियोजनाओं के कारण कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी तेजी से विकास होता है।

10 प्रणाली संबंधी समस्याएँ (Problems relating to the System) एक उद्यमी को पंजीकरण, अनुज्ञापत्र, भूमि, जल, बिजली, वित्त का ऋण प्राप्त करना एवं विपणन इत्यादि सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागों या मंत्रालयों से सम्पर्क करना पड़ता है। ये प्रणालियाँ अत्यन्त जटिल हैं जिन्हें अनावश्यक क्लिष्ट होता है। अतः विभिन्न रियायतों, सम्पत्ति व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) राजस्थान में पर्याप्त शक्ति के साधन न होने का कारण है औद्योगिक विकास की गति धीमा रही। राज्य में कोयला व खनिज तेल का निम्न अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य में शक्ति के परम्परागत साधन व विद्युत की पर्याप्त सहायता विद्यमान है। किन्तु पूँजा व अभाव के कारण इन साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अतः पर्याप्त पूर्ण विनियोजन व द्वाग शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Capita Income) राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी कम है। इसके अतिरिक्त देश व अन्य राज्यों से तन्त्रा वस्त्रों का आयात होता है कि राज्य का प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है। अतः राजस्थान में पूँजानिर्माण की गति भी धीमी नहीं रहती है। निम्न गृहय पूँजी का अभाव बना रहता है। पूँजी का अभाव के कारण राज्य का तेजी से औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या व समाधान हेतु राज्य में वैज्ञानिक एवं न्याय सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और न्याय में

विशेषण, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की आदत विकसित की जानी चाहिए। इससे पूँजी निर्माण की गति में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाएगा।

13 उद्योगपतियों की उदासीनता (Indifferent Attitude of Industrialists) राज्य के औद्योगिकरण के प्रति उद्योगपति प्रायः उदासीन बन रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि खजूर, यम, नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण न होने के कारण वे अपनी पूँजी को देश के अन्य भागों में विनियोजित करना अधिक लाभदायक समझते हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत न्यायता व सुविधाओं की प्राप्ति करनी चाहिए।

14 अन्य समस्याएँ (Other Problems) - उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। धर्म सम्बन्धी समस्याओं के अन्तर्गत कुशल श्रमिकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव है। इसमें उत्पादन कार्य में अवरोध बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णतः औद्योगिक सर्वेक्षण ही नहीं हो पाया। उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाँच नहीं हो पाती है। अतः 5 राज्य में अप्रसूत घटिया वस्तुओं का मार्गण रूप से जाना नहीं जा पाता है। अतः राज्य में अप्रसूत घटिया वस्तुओं का उत्पादन होता है। राज्य के अनेक उद्योग रणनीति की समस्या से ग्रस्त हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करके राज्य में औद्योगिकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवस्था के तत्त्व गति से आर्थिक विकास हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं।

1 वित्तीय साधनों में वृद्धि राज्य की प्रथम सात योजनाओं का आकार बहुत छोटा था अतः राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत धीमी रही। राज्य की 8वीं व 19वीं योजना का आकार परन्तु की योजनाओं का तुलना में अधिक है। किन्तु राज्य की समस्याओं और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय साधनों में वृद्धि का जोर दिया गया है।

2 आर्थिक सर्वेक्षण राजस्थान में विभिन्न सर्वेक्षणों का गति धीमी है। अतः राज्य के आर्थिक क्षमताओं का ज्ञान नहीं है। अतः राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में हो जाना चाहिए ताकि दृष्टि उद्योग परिवर्तन और खनिज विकास की

भावी सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जा सके।

3 सिंचाई के साधनों का विकास - राजस्थान में प्रायः अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या का समाधान केवल सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त हैं। अतः अर्धव्यवस्था के तीव्रगामी आर्थिक विकास के लिये सिंचाई के साधनों में तेजी से विकास करना आवश्यक है।

4 राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग - राज्य का एक बहुत बड़ा भू-भाग मरुस्थल है अन्तर्गत आता है। प्रदेश में वर्षा का अभाव रहता है और भू-क्षरण की प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसी स्थिति में शुष्क प्रदेश का उपयोग करने के लिये कृषि की नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भू-क्षरण को रोकने के लिये पेड़-पौधे लगाये जाने चाहिये और वर्षा की आवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिये।

5 अरावली क्षेत्र का विकास - राज्य का अरावली क्षेत्र रेगिस्तान को पूर्व का ओर बढ़ने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षेत्र का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अत्यधिक कमजोर हो गई है। अतः अरावली क्षेत्र के विकास पर विरोध

बल दिया जाना चाहिये।

6 पेयजल की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के पश्चात् भी राज्य में पेयजल का संकट विद्यमान है। यह विचित्र विडम्बना है कि कुछ स्थानों पर पेयजल उपलब्ध हो नहीं है और अनेक स्थानों पर पेयजल का स्वाद क्षारीय और पीने योग्य नहीं है अतः राज्य में पेयजल की व्यवस्था के लिये क्रान्तिकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

7 लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगों का अभाव है अतः राज्य में खनिज आधारित उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निर्माण बैंकिंग विकास राजस्व वृद्धि आदि का विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। ताकि राज्य की विकास की दर बढ़ सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- राजस्थान राज्य के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? उनको दूर करने के साक्ष्य में क्या उपाय किए हैं। स्पष्ट कीजिए।
What are the constraints in the Economic development of Rajasthan State? Explain the steps which have been taken by the Govt. of Rajasthan to remove the constraints.
- राजस्थान के आर्थिक पिछड़पन का स्थापित करने के लिए आर्थिक सूचकों का उल्लेख कीजिए।
Identify the important economic indicators to establish the economic backwardness of Rajasthan.
- राजस्थान के विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?
What are the main constraints in the economic development of Rajasthan?
- उन पाँच प्रमुख विषयों/क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनसे राजस्थान के विकास में अति महत्वपूर्ण होगा।
Mention five major sectors/areas which would be crucial in the development of Rajasthan in 21st Century. Explain why?
- राजस्थान अब भी आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। इसके पिछड़ेपन के क्या कारण हैं?
Rajasthan continues to be an economically backward state. What are the reasons for it?
- स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में हुए विकास का मूल्यांकन करें हुए पाँच प्रमुख सकारात्मक एवं सकारात्मक बिंदु उल्लेखित करें।
Write five main positive and negative points in assessing the development of Rajasthan after independence.

B. निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान राज्य के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? उनको दूर करने के साक्ष्य में क्या उपाय किए हैं? स्पष्ट कीजिए।
What are the constraints in the economic development of Rajasthan state? Explain the steps which have been taken by the Govt. of Rajasthan to remove the constraints.

- 2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
Critically describe the economic development of Economy of Rajasthan after Independence
- 3 पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान के आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए।
Describe economic development of Rajasthan during five year plans

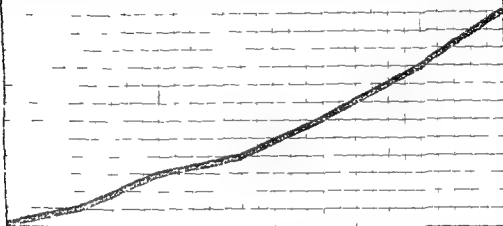
C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान में अर्थव्यवस्था की धीमी गति के क्या कारण हैं? भविष्य में राज्य में तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव दीजिए।
What are the causes of slow growth of the Economy of Rajasthan? Give Suggestions for rapid economic growth in future in the State
- 2 "राजस्थान के आर्थिक विकास में अवरोध" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Constraints in the Economic Development of Rajasthan"
- 3 राजस्थान के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? इन बाधाओं का कैसे दूर किया जा सकता है?
What are the main constraints in the economic development of Rajasthan. How can these constraints be removed?
- 4 स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था व आर्थिक विकास का आलोचनात्मक विवेचन दीजिए।
Critically explain the economic development of Economy of Rajasthan prior to Independence and post Independence



राजस्थान में अकाल एवं सूखा

FAMINE & DRAUGHT IN RAJASTHAN



अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में अकाल व सूखे के अध्ययन का महत्व
- राजस्थान में अकाल व सूखे का इतिहास
- अकाल व सूखा प्रदम्य को अल्पकालीन व दीर्घकालीन व्यूह मचना
- राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के कारण व निवारण के उपाय
- अन्तर्सर्प्य प्रश्न

राजस्थान सदियों से अकाल एवं सूखे की समस्या से जूझता चला आ रहा है। मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण करने के हर सम्भव प्रयास किए हैं किन्तु वह इसमें पूर्ण रूप से अभी तक सफल नहीं हो पाया है। अकाल एवं सूखे की समस्या वैसे तो सम्पूर्ण राजस्थान की समस्या है किन्तु विशेषकर उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र इस समस्या से अधिक ग्रसित है। यह क्षेत्र आरम्भ से ही रेगिस्तानी नहीं है। इस क्षेत्र में हजारों वर्ष पूर्व दैविस महासागर हुआ करता था, जो धीरे धीरे लुप्त हो गया। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में आज जो खारे पानी की झीलें विद्यमान हैं वे उसी सागर का अवशेष मानी जाती हैं। अति प्राचीनकाल में यह क्षेत्र काफी हरा भरा और समृद्ध था। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में मिले वनों के अवशेषों से भी इस बात की पुष्टि होती है। मानव जैसे जैसे इस क्षेत्र के वनों को नष्ट करता गया, वैसे वैसे इस क्षेत्र में समृद्धि लुप्त होने लगी। इस क्षेत्र में पारले सरस्वती नदी बहा करती थी। वह भी भौगोलिक उथल पुथल के कारण लुप्त हो गई। इस कारण यह क्षेत्र धीरे धीरे हरियाली खोता चला गया और कालान्तर में रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। रेगिस्तान के दुष्प्रभावों के कारण सम्पूर्ण राजस्थान की जलवायु अत्यधिक विषम हो गई व वर्षा की मात्रा भी कम होती चली गई। फलस्वरूप अकाल एवं सूखे की समस्या अपने जडे जमाती चली गई। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि

अकाल एवं सूखे की समस्या राजस्थान में सदैव से विद्यमान है।

राजस्थान में अकाल एवं सूखे के अध्ययन का महत्व

IMPORTANCE OF THE STUDY OF DRAUGHTS & FAMINES IN RAJASTHAN

राजस्थान में प्रायः अकाल एवं सूखे की स्थिति, स्वरूप व विस्तार आदि का अध्ययन करना विभिन्न प्रभावों एवं निम्न कारणों से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है -

1 रेगिस्तानी क्षेत्र (Desert Area) - राजस्थान के समस्त क्षेत्र को मोट तौर पर अरावली पर्वत श्रृंखला ने दो भागों में बांट दिया है। उत्तरी पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है और यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में जलवायु अत्यन्त विषम है तथा वर्षा की मात्रा बहुत कम है। साथ ही जनसंख्या का घनत्व राज्य के औसत से कम है। जनसंख्या काफी घिरी हुई है। ऐसी स्थिति में जब यह प्रायः अकाल एवं सूखे से जूझता रहता है तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के लगभग 60 प्रतिशत भाग का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति की गति रुक रूप में प्रभावित होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र का इस समस्या से मुक्त कराने के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में अकाल एवं सूखे की समस्या का प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से पूर्ण अध्ययन किया जाए और अध्ययन में निम्नलिखित बिन्दुओं को क्रियान्वित करके इस समस्या की सम्मोचना तथा यथासम्भव दम किया जाए।

2 कृषि प्रधान राज्य (Agriculturally dominated State) - राजस्थान में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि का विशेष महत्व है। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। कृषि क्षेत्र में अधिकांश भूमि अगिचित है तथा जो भूमि गिचित है उसमें भी मुख्यतः कुएँ की सिंचाई व प्रमुख मानस ऋतु की स्थिति में राजस्थान में रबी और खरीफ की दो फसल ली जाती है उनमें से खरीफ की फसल तो प्रायः पूर्णतः वर्षा पर आश्रित रहती है। रबी की फसल में बहुत कम क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। रबी की फसल की सिंचाई भी मुख्यतः कुओं के माध्यम से की जाती है। जब अकाल एवं सूखे की स्थिति होती है तो इन कुओं का जल स्तर भी बहुत नीचा चला जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह स्तर तीन मी फीट से पांच मी फीट तक गहरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुओं में

भी पर्याप्त जल नहीं मिल पाता। इस प्रकार राज्य के कृषि प्रधान होने के कारण एवं सूखे का प्रभाव राज्य के बहुत बड़े हिस्से और जनसंख्या पर पड़ता है। इस कारण इस समस्या का अध्ययन अनिवार्य प्रतीत होता है।

3 पशुपालन (Animal Husbandry) - राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। साथ ही पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय वन नुषा है। विशेषकर उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में पशुपालन काफी महत्वपूर्ण है। 1983 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 4 करोड़ पशु हैं जो कि एक बड़ी संख्या माने जा सकते हैं। इन पशुओं को अकाल एवं सूखे के कारण पर्याप्त चरागाह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस कारण राजस्थान से पशुओं का अन्य राज्यों व क्षेत्रों की ओर भारी मात्रा में पलायन होता है। इस पलायन के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि अकाल एवं सूखे के स्वरूप को समझा जा सके तो पशुओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

4 ग्रामीण जनसंख्या (Rural Population) - राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं। गावों में प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। अकाल एवं सूखे का सर्वाधिक प्रभाव कृषि एवं पशुपालन पर ही होता है। इस कारण राज्य की बहुत बड़ी जनसंख्या ग्राम एवं अकाल से प्रभावित हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र पहले ही विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत एवं राज्य की अधिकांश निर्धन जनसंख्या गावों में निवास करती है। अतः ये निर्धन ग्रामीण लोग ही अकाल एवं सूखे में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। शहरी जनसंख्या पर इसका अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य केंद्र मानते हुए अकाल एवं सूखे की समस्या का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

5 आर्थिक भार (Economic Burden) - राजस्थान में अकाल एवं सूखे की समस्या प्रायः रबी रहती है। राजस्थान के लोगों को किसी भी किसी रूप में इस समस्या का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात् 1995-96 तक केवल 7 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी वर्षों में राजस्थान इस समस्या में पीड़ित रहा है। जिन वर्षों में इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा वे वर्ष हैं 1959-60 1973-74, 1975-76 1976-77, 1983-84, 1990-91 और 1994-95। इस प्रकार सदैव

इन समस्या के निवारण एवं राहत कार्यों पर व्यय करना होता है। 1987-88 में तो इस शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल रहा है। इस कारण विकास के लिए उपलब्ध धन-राशि ऐसे कार्यों में भी व्यय हो जाती है जो अपेक्षाकृत कम उत्पादक या अनुत्पादक होते हैं। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति धीमी होती है। स्वतंत्रता के बाद अब तक 2200 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी राज्य के एक भी जिले को अकाल से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकी है।

6 रोजगार (Employment) - सूखे एवं अकाल के कारण राज्य में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कि यह तो स्पष्ट ही है कि अधिकांश लोग कृषि में लगे हैं लेकिन साथ ही राज्य के विभिन्न रोजगार अवसरों का विग्लेषण किया जाए तो वे सभी प्रत्यक्ष रूप में कृषि से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, बीमा, बैंकिंग आदि सभी क्रियाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पन्नता से शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। अकाल एवं सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो रोजगार के अवसर प्रायः समाप्त हो जाते हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है। सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने मानवीय माधनों का कुशलतम उपयोग करे किन्तु सूखे एवं अकाल के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाता। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सूखे एवं अकाल की समस्या पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7 पेयजल (Drinking Water) - राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफी वर्षों बीत जाने के बाद भी पेयजल की समस्या का निदान नहीं हो पाया है। पेयजल मनुष्य को जीवित रखने के लिए एक अनिवार्यता है। यह पेयजल शुद्ध होना भी आवश्यक है क्योंकि इसका अभाव में मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। यह पूर्णतः सत्य है कि जितने लोग शराब पीने से नहीं भरते, उससे भी अधिक लोग दूषित जल के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कुएँ व तालाबों पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं। गन्नाबों में तो पशु और मनुष्य सभी उसका उपयोग करते हैं। सूखे एवं अकाल के कारण कुओं का पानी सूख जाता है। इसमें लोगों को पेयजल के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। शहरी क्षेत्रों में जो पानी उपलब्ध कराया जाता है वह भी वर्षों से ही प्राप्त होगा है चाहे वह बाध बनाकर रोका गया पानी हो या भूमिगत जल। दोनों ही दशाओं में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य की इस मूलभूत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अकाल एवं सूखे की समस्या का

अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है।

8 मूल्यवृद्धि (Inflation) - अकाल एवं सूखे के समय प्रायः मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ता है क्योंकि कृषिगत उत्पादन कम हो जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल महंगा हो जाता है, व्यापारियों व उत्पादकों में जमाखोरी की प्रवृत्ति पनपने लगती है तथा ऐसे ही विभिन्न कारणों से लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मूल्य सूचकांक से इस प्रवृत्ति की पुष्टि की जा सकती है। मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव राज्य में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भी पड़ता है क्योंकि उन विकास परियोजनाओं को लागत बढ़ जाती है। इसमें और अधिक वित्तीय प्रावधान करने होते हैं जो कि राज्य के आर्थिक भार में वृद्धि कर देते हैं। मूल्य वृद्धि से जनता भी पीड़ित रहती है। इसके राजनैतिक दुष्परिणाम भी सरकार को भुगटने पड़ते हैं। इस कारण अकाल एवं सूखे की समस्या का उचित अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

राजस्थान में अकाल व सूखे का

इतिहास

HISTORY OF FAMINES & DRAUGHTS IN RAJASTHAN

राजस्थान के पर्यावरण पर अकाल एवं सूखे की समस्या का गहरा प्रभाव रहा है। राजस्थान में जलवायु की विषमता, वर्षा की स्थिति, वनों का स्वरूप, धरातल की स्थिति, पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा आदि का अकाल एवं सूखे की समस्या से आदिकाल से सम्बन्ध रहा है। राजस्थान में अकाल एवं सूखे की स्थिति अन्न का अभाव, चारे का अभाव या जल का अभाव होने के कारण या अन्न, जल व चारे के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। जिस अकाल में अन्न, जल व चारे तीनों का अभाव रहता है वह अकाल अत्यन्त भीषण माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के सन्दर्भ में लिखते हुए 11वीं शताब्दी के एक अकाल का वर्णन किया है जो लगभग 12 वर्ष तक चला। इसी प्रकार मन् 1291 (वि.स. 1348) में राजस्थान में भयंकर अकाल का उल्लेख मिलता है। 1309 से 1313 के मध्य भारतभर भयंकर अकालों से ग्रस्त था। इन्होंने 1899 (वि.स. 1956) को कि "छप्पेनाकाल" के नाम से

1335 1485 1570 1577 1578 1694, 1695
1696, 1755 1796 1811 1843 1844
1848, 1851 1860 1868 1877, 1891
1895, 1899 1917 1939 आदि वर्षों में राजस्थान
भयंकर अकालों से ग्रस्त था। इन्होंने 1899 (वि.
स. 1956) को कि "छप्पेनाकाल" के नाम से

विलुप्त हो अपनी भयंकर विभीषिका के लिए आत्र भा याद जिगा जाता है। लगभग एसी ही स्थिति 1939 (वि म 1998) के छिनवेकाल क मन्दर्भ में रही है। राजस्थान के निर्माण क पश्चात केवल 5 वर्षों को छोड़कर यदा हमेशा अजल एव सूखे की स्थिति देखने में आई है। इस स्थिति का मयम बड़ा कारण वर्षा का कम होना है। गन्धर्व में पिछले दो दशका में अकाल एव सूखे में प्रभावित जिला की मख्या राज की अधिकांश जनसंख्या पर पड़न बाल प्रभाव व राज्य की आर्थिक क्षति को निम्न तर्जिका में दर्शाने की चष्टा की गई है।

राजस्थान में अकाल की स्थिति

अ प्रभावित प्रान्त की संख्या की दृष्टि से भयंकर प्रभाव के वर्ष

1 1987 88	36252 गाव
2 1986 87	31936 "
3 19 9 80	31095 "
4 1991 92	30041 "

ब अकालों से प्रभावित सर्वाधिक जनसंख्या वाले वर्ष

1 1987 88	3 17 बगड
2 1991 92	2 89 बगड
3 19 05 96	2 73 बगड
4 1986 87	2 52 बगड

स राजस्थान के निर्माण के पश्चात् 1996 97 के वे वर्ष निर्माण अक्षल व सूखा नहीं रहा

1 1950 60
2 1973 74
3 1975 76
4 1976 77
5 1983 84
6 1990 91
7 1994 95

द शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल का वर्ष 1987 88

*The Economic Review 1987-88 1988-89 2nd
Ann. Reports of the Department*

ज्या कि पहल उताया गया है कि राजस्थान में अकाल का प्रमुख कारण वर्षा का कम होना है। वर्षा का अध्ययन व लिए गन्धर्व में 1901 से 1950 तक का वर्षों हुई उगा को आधार पर राजस्थान के विभिन्न जिलों व क्षेत्रों व लिए औसत सामान्य वर्षा निर्धारण का गई है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में औसत वर्षा आग विगत वर्षों में हुई वर्षा का स्थिति से अकाल एव सूखे का समग्र अध्ययन में सुविधा हागा।

राजस्थान में वर्षा का वितरण

अ राजस्थान के औसत (57 51 से मी) से अधिक सामान्य वार्षिक वर्षा वाले प्रमुख जिले

1 बागलपा	95 03 से मी
2 बग	87 38 से मी
3 बगलपापौर	87 34 से मी
4 झालावाड	84 43 से मी
5 जयपुर	84 15 से मी

ब राजस्थान के औसत (57 51 से मी) के लगभग बराबर सामान्य वार्षिक वर्षा वाले जिले

1 अजमेर	60 18 से मी
2 गिरवा	59 12 से मी
3 राजस्थान	56 78 से मी
4 जयपुर	56 38 से मी
5 जयपुर	56 10 से मी

स राजस्थान के औसत (57-51 से मी) से कम सामान्य वार्षिक वर्षा वाले प्रमुख जिले

1 जयपुर	18 55 से मी
2 गजमेर	22 64 से मी
3 बीकानेर	24 30 से मी
4 जयपुर	26 57 से मी
5 जयपुर	31 17 से मी
6 जयपुर	31 37 से मी

स्रोत (Statistical Abstract Raj 1996)

अकाल के प्रमुख क्षेत्र अथवा जिले -

राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रायः अकाल की स्थिति बना रहती है। इस क्षेत्र में राज्य के जिला सम्मिलित हैं जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है और इसमें राज्य की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। राज्य में अकाल से प्रभावित जिला के नाम इस प्रकार हैं बाडमेर जयसलमेर जावपुर जालौर नागौर चूरू पारली श्रीगंगानगर बीकानेर गीर और झुण्डु। इन जिला में वर्षा बहुत कम होती है तथा तब अधिकांश व कारण मिट्टी की कटाव होता रहता है।

अकाल एव सूखे के राज्य अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव -

1 अकाल एव सूखे से राज्य अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित होती है। आय एव राजस्व का मर निम्न है और राज्य में उकाश भुखमरी एव निर्धनता की स्थिति बना रहती है। अर्थव्यवस्था में दार्शनिक तर्क अभाव की स्थिति बना

राजस्थान में रेलमार्ग		
वेब	रेलमार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)	
	1990-91	1995-96
1 ग्रह पत्र	1235.37	2288.03
2 मीटर	4505.52	3551.22
3 गेज	86.51	84.45

स्रोत: Statistical Abstract, Rajasthan 1996

(2) भरतपुर सिमेंट लिमिटेड - यह कम्पनी 31 जनवरी, 1957 को भरतपुर में प्रारम्भ की गई। यह कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 3000 माल वाहन डिब्बों का निर्माण करती है। यह मालवाहक डिब्बों की तमाम एक-दिशाई याग पूरी करती है।

(3) रेल बस - राजस्थान के जगमो जिले के मेड़ना शहर से मेड़ना रोड के बीच 12 अक्टूबर, 1994 को देश की पहली बस रेल-बस सेवा प्रारम्भ हुई। इस रेल बस में 71 यात्री बैठकर तथा 15 खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। इस रेल बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घण्टा है।

(4) जयपुर-सियालदाह एक्सप्रेस - 3 जुलाई, 1994 को जयपुर-सियालदाह एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया गया। यह प्रतिदिन दुर्गापुर, सवाईमाधोपुर, आगरा-किला, टुडला, कानपुर, इलाहाबाद, मुलनायक और पटना होते हुए 38 प्लेसों में अपनी यात्रा पूरी करती है।

इससे राजस्थान के श्रवणी उद्योगों का राज्य में उद्योग लगाने के प्रति रुझान बढ़ेगा और परिवहन की सुविधा के विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी।

(5) आठवीं पंचवर्षीय योजना में परिवहन विकास - बायोडिज़ल-आधारित एक बड़ी लाईन का कार्य आठवीं योजना में पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 1994-95 में मीटर गेज की बड़ी लाईन में बदलने के कार्यक्रम में जोधपुर-जैसलमेर के लिए 108 करोड़ रुपये, फुलेर-भारवाड-अहमदाबाद-मेहसाणा के लिए 92 करोड़ रुपये, लूनी-भारवाड के लिए 30 करोड़ रुपये, सवाईमाधोपुर-जयपुर-कुलेय के लिए 26 करोड़ रुपये,

जयपुर-जयपुर 55 किमी	जयपुर-जयपुर 254 किमी
मेड़ना रोड, 14 किमी	मेड़ना रोड-जयपुर 205 किमी
मेड़ना सिटी	

जोधपुर-जोकोर-मेड़ना के लिए 8 करोड़ रुपये तथा जयपुर-अलवर नई बड़ी रेल लाइन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

(6) राजस्थान में नई रेल लाइनें - स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान राज्य में नवीन रेलमार्गों के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रहा। राज्य में 1947 की अवधि में मात्र दो खेरादा (1947-48) खेरादा-कानोड (1948-49), साभान-झागी (1949-50), कानोड-बडो सादही (1949-50), झागी-डिगाँव (1950-51), डिगाँव-साँडा गणेश (1953-54), पतेहपुर-बुरु (1956-57), रातोवाडा-भोलडी (1957-58), उदयपुर-उदयपुर सिटी (1961-62), उदयपुर-हिमनगर (1965-66), पोरन-वैमलमेर (1966-67) हिन्दमकोट-झागाना (1969-70), डादसा-सियाल (1974-75), कोटा-बन्देरिया (1988-89), बन्देरिया-बिलौडगढ़ (1989-90), बिलौडगढ़-नीमव (1990-91), जयपुर-झींग (1992-93), तथा झींग-अलवर (1993-94) नवीन रेलमार्ग बनाये गये।

(7) अजमेर का रेलवे वर्कशॉप - इस वर्कशॉप का निर्माण 1877 में प्रारम्भ हुआ जो सन् 1878 के अन्त तक पूरा हो गया। यह हथके, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की सभी प्रकार की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य किया जाने लगा। 1881 में धन्डार विभाग तथा 1884 में माल डिब्बों और सवारी डिब्बों को अलग किया गया। 1885 में लुहरी वर्क, चक्का (Wheel) तथा बॉयलर शाप को अलग से कार्यशालाएँ स्थापित की गईं। यह भारत का एक मात्र रेलवे वर्कशॉप है जहाँ इज्जत बनते हैं। 1937 तक यहाँ 375 रेल इज्जतों का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी रेल मरम्मत एवं नवीनीकरण की दृष्टि से रेलवे वर्कशॉप, अजमेर का महत्वपूर्ण स्थान है।

(8) रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर - इस स्कूल का शिलान्यास 25 मार्च, 1955 को महाराणा प्रताप सिंह ने किया तथा 9 अक्टूबर, 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति जवाहर लाल नेहरू उद्घाटन किया। यह स्कूल न केवल पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है बल्कि आखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों और विदेशी रेल कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल क्लब है। 1993-94 में 5713 देशी तथा 246 विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(9) बच्चों की रेल - यह रेल उदयपुर में है। इसका संचालन नगर प्रसिद्ध, उदयपुर द्वारा किया जाता है। इस रेल

राजस्थान में मीटर रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन	
1991-92	1994-95
सूनाई-पटोडा 81 किमी	सूनाई-जयपुर 225 किमी
सूनाई-अजमेर 78 किमी	जयपुर-जैसलमेर 295 किमी
सूनाई-जैसलमेर 178 किमी	
1992-94	1995-96
सूनाई-मेड़ना रोड 177 किमी	अजमेर-सूनाई 140 किमी
सूनाई-कोटा 145 किमी	जयपुर-जैसलमेर 203 किमी
सूनाई-जयपुर 125 किमी	जयपुर-मेड़ना 113 किमी

का पूर्ण विकास हुआ व नये पट सृजित करके व्यापक स्तर पर राहत कार्य की व्यवस्था की गई।

सहायता विभाग राजस्थान प्रशासन का एक स्थायी विभाग है जो सहायता आयुक्त एवं शासन सचिव के अन्तर्गत कार्य करता है। इस विभाग का मुख्यालय राज्य स्तरीय है तथा इसके अधीन कोई कार्यालय या शाखा नहीं है। प्रारम्भ में राहत कार्य राजस्व अधिकरण के माध्यम से सम्पन्न कराए जाते थे। अब यह कार्य विभिन्न अधिकरण जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग वन विभाग भू सन्तान विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पंचायत राजस्व आदि के माध्यम से सम्पन्न कराए जाते हैं। जिलाधीन एवं तहसीलदार तथा जिला स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारी अपने-अपने जिलों में सहायता विभाग के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों का नियंत्रण प्रतिपादन एवं समन्वय अधिकारों के रूप में कार्य करते हैं।

विभाग ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के आकड़ों को यथाशीघ्र आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से संचालित करने एवं सूचनाओं को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करने के उद्देश्य में मार्च 1987 में एक कम्प्यूटर यूनिट का स्थापना की वर्तमान राजगार की व्यवस्था सिंचाई व्यवस्था पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था इत्यादि अनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण सम्पादन एवं विश्लेषण कर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। पूर्व में यह सब कार्य मानव श्रम शक्ति द्वारा किया जाता था जिसमें अधिक श्रम व समय लगने के उपरान्त भी अपेक्षित कार्य नहीं हो पाते थे। भविष्य में इस यूनिट के द्वारा अन्वेषण अभिप्रेत गहन कार्यात्मक विभिन्न शिकायतों एवं कर्मचारियों के वृत्त भुगतान व सेवा मरम्मत विभिन्न सूचनाओं का कम्प्यूटीकरण करने की योजना है।

4 प्राकृतिक आपदा सहायता निधि कोष (Fund for Natural Calamity) वर्ष 1990-91 में दौरी विपत्तियों में राहत प्रदान करने के मकसद में केन्द्रीय सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु नव वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य में एक प्राकृतिक आपदा सहायता निधि की स्थापना की गई। इस निधि में हर वर्ष 93 करोड़ रुपये भागत सरकार द्वारा एवं 31 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा। यह व्यवस्था 5 वर्षों तक जारी रहेगा। राज्य में इस व्यवस्था के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले गम्भीर नुकसान को दूर करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। यदि एक वर्ष में कम बार कम वर्षा अधिक राशि का व्यय किया जाता है तो उसका सामग्रिक बाढ़ व वर्षों में किया जाएगा।

5 रोजगार व्यवस्था (Employment Generation)

राज्य सरकार द्वारा 25 जिलों के अभावग्रस्त लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य विभागों की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया। रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विशिष्ट योजना संगठन को प्राकृतिक आपदा सहायता निधि से उपलब्ध करवाई गई।

6 पेयजल व्यवस्था (Arrangement of Drinking Water) अभाव स्थिति में पेयजल की समस्या से निपटने हेतु समस्त जिला कमेटीयों को पेयजल परिवहन एवं सिंचाई व्यवस्था करने हेतु अधिकृत किया गया। प्राकृतिक आपदा सहायता निधि पेयजल परिवहन व्यवस्था हेतु सिंचाई व्यवस्था हेतु तथा टैंकरों की मरम्मत हेतु प्रभावित जिलों को उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल समस्या से निपटने हेतु राशि आवंटित की गई।

7 सिंचाई व्यवस्था (Irrigation Facility) राज्य के पश्चिमी जिलों में क्रमशः बाढ़ों में नैसर्गिक जलौर घटती जा रही गगानगर नागौर एवं जोधपुर में सिंचाई द्वारा पेयजल व्यवस्था करने हेतु राशि का आवंटन किया गया।

सिंचाई हेतु अनुदान की 150 फीट से 200 फीट जल स्तर वाले कुओं के लिए 50 रुपये प्रति कुआ प्रतिदिन तथा 200 फीट से अधिक गहरे जल स्तर वाले कुओं के लिए राशि 75 रुपये प्रति कुआ प्रतिदिन रखी गई।

8 पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था (Animal Protection & Fodder Arrangement) राज्य के विभिन्न जिलों में मानसून पूर्व की वर्षा होने के कारण चारे की स्थिति सामान्य रहने एवं पशुपालकों को कठिनाई नहीं होने पर वन विभाग का घास सुरक्षित रखने एवं हरे चारे का उत्पादन करने की कार्य योजना शुरू करने की आवश्यकता महसूस नहीं होता है। इसके अलावा पशु शिविर योजना पशु पापण कन्द्र गठना तथा गाड़ा का अनुदान देने सहित कोई योजना भी आरम्भ नहीं की जाती है। अन्यथा यह कार्य किए जाते हैं।

राजस्थान में अकाल एवं सूखे की स्थिति के कारण

FACTORS RESPONSIBLE FOR DRAUGHT & FAMINES IN RAJASTHAN

राजस्थान में अकाल व सूखे का स्थिति व निम्न मुख्य रूप से प्राकृतिक कारण उत्पत्तीय है। साथ ही मानसून प्रत्याशा में भी कमी रहती है। राजस्थान में अकाल व सूखे के लिए उत्पत्तीय कारण इस प्रकार हैं।

1 अरावली पर्वत की स्थिति (Situation of Aravali Range) - अरावली पर्वत राजस्थान को लगभग दो भागों में विभक्त करता है। इसके एक ओर मरुस्थलीय क्षेत्र है तथा दूसरी ओर मैदानों और पठारी क्षेत्र है। अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता हुआ है और यहाँ दिशा दक्षिणी पश्चिम मानसून की है। इस कारण मानसूनी हवाएँ इस पर्वत के सहारे सहारे बिना कोई विशेष वर्षा किए आगे की ओर निकल जाती हैं। दूसरी ओर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बगाल की खाड़ी की शाखा जब तक राजस्थान में पहुँचती है तो उसमें विशेष पानी नहीं रह जाता। इस समय अरावली पर्वत इन हवाओं को रोकता है। इस प्रकार कम वर्षा के कारण प्रायः राजस्थान को अकाल व सूखे का सामना करना पड़ता है।

2 रेगिस्तानी क्षेत्र (Desert Area) - राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र की जलवायु अत्यन्त विषम है। इस क्षेत्र में वन लगभग नहीं के बराबर हैं। इस कारण यह क्षेत्र मानसून को आकर्षित नहीं कर पाता। इस क्षेत्र में गर्मी के कारण जो निम्न वायु भार की स्थिति बन जाती है, उसमें आकर्षित होकर जो मानसून यहाँ पहुँचता है, उसका मार्ग में कोई ऐसी अवरोध नहीं है जो इस क्षेत्र में वर्षा बनाने में सक्षम हो सके। इस कारण राजस्थान में सबसे कम वर्षा रेगिस्तानी क्षेत्र में होती है। साथ ही अकाल एवं सूखे की स्थिति का सर्वाधिक सामना भी हम रेगिस्तानी क्षेत्र को ही करना पड़ता है।

3 वनों का अभाव (Lack of Forest) - सम्पूर्ण राजस्थान में वनों की मात्रा बहुत कम है। यह भारत के औसत वनों की मात्रा की भी लाभा आधी है। विभिन्न अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि वन वर्षा को आकर्षित करत है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में वना के अभाव के कारण एक ओर तो वर्षा कम होती है दूसरी ओर वन कम होने के कारण जलवायु विषम होती चली जाती है।

4 फसलों में रोग (Crop Diseases) - वैसे तो सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रों में निम्नरता का साम्राज्य है किन्तु राजस्थान में यह अपेक्षाकृत अधिक ही है। आज भी कृषक प्राचीन विधियों को ही अपनाता है। वह फसल को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक औषधियों के प्रयोग का बहुत आदर नहीं है। इस कारण अनेक बार फसलें रोगों से नष्ट हो जाती हैं। राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र के कारण टिड्डियों का प्रकोप भी होता रहता है। इस कारण फसलों के नष्ट होने से भी अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

5 अतिवृष्टि व अनावृष्टि (Deluge & Drought) - राजस्थान मुख्यतः अनावृष्टि से पीड़ित रहता है किन्तु

अनेक बार अच्छी वर्षा बाढ़ का कारण बन जाती है। इस कारण फसलें उगाना सम्भव नहीं हो पाता और कई बार खाड़ी फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुँचता है। इस प्रकार अतिवृष्टि व अनावृष्टि दोनों ही अकाल की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं।

6 जल का समुचित उपयोग न होना (Lack of Full utilisation of Water) - अनावृष्टि की स्थिति में फसलें मिचाई द्वारा ही ली जा सकती हैं। राजस्थान में जल का समुचित उपयोग न हो पाने के कारण मिचाई का पर्याप्त जन उपलब्ध नहीं हो पाता। राजस्थान में नदियों पर तो बांध आदि बनाने के प्रयास किए गए हैं किन्तु छोटे छोटे नालों और मिचाई साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अधिकांश जल बह जाता है और जो जल भूमिगत जल में परिवर्तित होता है वह भी अनावृष्टि के कारण सूख जाता है।

7 मिट्टी का कटाव (Soil Erosion) - राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हवा द्वारा मिट्टी का कटाव एक आम बात है। इस कटाव के कारण उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदल जाती है। रेगिस्तान के प्रसार के साथ साथ यह स्थिति अनुभव की जाने लगी है। वर्षा के कारण भी कटाव उत्पन्न होता है। चम्बल के बीहड़ इसका एक उदाहरण है। मिट्टी के कटाव के कारण फसलों का क्षेत्र कम होता है वन नष्ट होते हैं। तथा वर्षा कम होती है और फलस्वरूप अकाल एवं सूखे की सम्भावना बढ़ जाती है।

8 कुटीर व लघु उद्योगों की कमी (Lack of Cottage & Small Scale Industries) - कुटीर व लघु उद्योग वैकल्पिक रोजगार व आय के स्रोत माने जाते हैं। कृषि काय मौसमी प्रवृत्ति का होता है। अतः कृषक वर्ग कुटीर व लघु उद्योगों के द्वारा अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात् बड़े उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया अतः राज्य के लघु व कुटीर उद्योगों का लगभग पतन हो चुका है। रोजगार के इस वैकल्पिक स्रोत के समाप्त हो जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की आय में कमी हुई है। यह स्थिति अकाल व सूखे की समस्या को अधिक गंभीर बनाएगी।

9 विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याएँ (Various Social & Economic Problems) - राजस्थान में निर्धनता की समस्या अत्यधिक व्यापक है। निर्धन वर्ग अकाल व सूखे से उत्पन्न आर्थिक भार को वहन नहीं कर सकता है। बेरोजगारी की समस्या ने भी लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। अतः वे अकाल का सामना नहीं कर पाते हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वित्तीय स्रोतों के

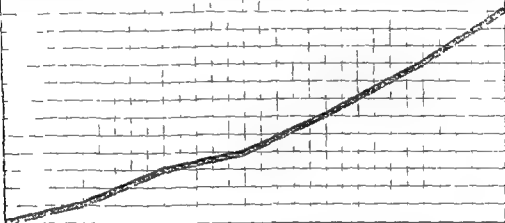
Describe the main causes for famine and drought in Rajasthan. Discuss the short term and long term famine & drought management strategies of Govt. of Rajasthan.

- 4 राजस्थान में अकाल व मण्डास पर एक संक्षिप्त व आलोचनात्मक लेख लिखिए।
Write a short critical essay on the famines in Rajasthan "Causes and Remedies "
- 5 अकाल के कारण राज्य को होने वाला क्षति का वर्णन हुए इन अकालों के कारण का भी समझाइए।
While giving an account of losses due to famine and explain the reasons for droughts/famines in Rajasthan



राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ

STATE BUDGETARY TRENDS



"राज्य बजट से राज्य का स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- बजट का अर्थ
- राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ
- राजस्व की विरासत में सुधार के मुद्दे
- वन्द राज्य विनियमन
- राज्य योजना का वित्तिय व्यवस्था
- परिवर्तित ७५५५५५ १९९३ ९९
- अनुमान प्रश्न

बजट का अर्थ

MEANING OF BUDGET

भारत के मविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय व व्यय का विवरण राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करे। आय-व्यय के इन विवरण को ह बजट अथवा आय-व्यय कहा जाता है। राज्य द्वारा बजट प्रस्तुत करने पर यह "राज्य सरकार का बजट" व कन्द सरकार द्वारा प्रस्तुत करने पर "कन्द सरकार का बजट" कहलाता है। बजट का सम्बन्ध एक वित्तीय वर्ष से होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और राज्य का वित्तमन्त्री हा प्राय इस राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। बजट का बजट विवरण का नाम भी दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट आकड 'बजट अनुमान' (Budget Estimates) होते हैं। तब वर्ष के बजट के अकड 'संशोधित अनुमान' (Revised Estimates) और इसके पूर्व के वर्ष के आकड 'वास्तविक' (Actual) होते हैं। लोक सभा नियम के विनियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि मविधान में अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण त्रिम वजट के रूप में जमा जाता है समद में एम दिन पेश किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दे। कन्द सरकार हा बजट दा भागे रल और सामान्य बजटों के रूप में पेश किया जाता है मन्त्र्य बजट में

राज्यभर एक सप्ताह पूर्व रेल बजट पेश किया जाता है। सामान्य बजट सामान्यतया फरवरी के महीने के अंतिम कार्य दिवस का रखा जाता है। जो राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है उन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। यह भा उत्प्लेखनीय है कि बजट लोकसभा में उस समय पेश किया जाता है जब गेन तथा वित्तिय कार्यकारी मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तिय विवरण सामान्यतः लोकसभा में मंत्रियों के भाषणों का समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है। तब रासदा म सभ्यकी कार्य क आयोजन क अश के मध म ससनाय कार्य मसलय सामान्य बजट दणि काई राज्य बजट हा ता उम मसित उन पर सामान्य रचा अनुमान की मागे पर चर्चा अंग मनदान तथा वित्त विधेयक पर विचार और पारित वान क लिए अस्थाई रागेख नियत करता है। सामान्य बजट का प्रगुति के बाद समदोय बाय मत्रा द्वारा उन मसनाय का वयन करणे के लिए जिनका अनुमान मागे पर चर्चा कर जानी है नाचमभा म विभिन्न दला/मुषा के नेताओं की बैठक दुलाई जागी है।

राजस्व तथा पूँजीगत कुल प्राप्तियाँ एवं व्यय का अंतर बजट घाटा (Budget Deficit) कहलाता है। राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय का अंतर राजस्व घाटा (Revenue Deficit) दर्शाता है। मौद्रिक घाटा (Monetary Deficit) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट मरकाज का लिए गए क्रेडिट म मरकल वृद्धि का प्रतीक है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मरकाज विलो तथा मरकाज के मरकाज उधार म इसके याफदान का जोड़ है। उमर द गई गरी सहित कुल व्यय राजस्व प्राप्तियाँ अनुदान और गैर क्रेडिट पूँजी प्राप्तियाँ के याग स जितना अधिक होता है वह राजि गजरापीय घाटा (Fiscal deficit) कहलाता है। इस गजरापीय घाटे म स व्याज का अदायगी क बात वचा गणि मूल घाटा है।

राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ

STATE BUDGETARY TRENDS

राज्य बजट का विश्लेषण करन फ राज्य बजट की अनेक प्रवृत्तियाँ दर्शित कर लाता है। राजस्थान का बजट विश्लेषण म निम्न प्रवृत्तियाँ का जान लाता है

1. राजस्व खाते में आय की प्रवृत्ति

Trend in Revenue Receipts in Revenue Account

राजस्व प्राप्तियाँ म राज्य मरकाज का कर राजस्व अवर राजस्व एवं मसनायाना अनुदान म प्रन हान वाना

आय का दर्शाया जाता है। राजस्थान के बजट में विगत वर्षों म राजस्व प्राप्तिओं की स्थिति निम्न प्रकार रही है

राजस्व प्राप्तियाँ	
(कोड़ रु)	
वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ
1994-95	6321 7
1995-96	7629 6
1996-97	7559 7
1997-98 (मरगाहित अनुमान)	8713 7
1998-99 (बजट अनुमान)	10189 4
स्रोत: वार्षिक वित्तिय विवरण 1998-99 राजस्थान सरकार, जून 1999	

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्तियाँ म निरन्तर वृद्धि होती रही है। राजस्व प्राप्तियाँ 3 खानों में हाता है। इनका विवेका निम्नानुसार है

(i) **कर राजस्व (Tax Revenue)** - राजस्व प्राप्तिओं के समान राज्य के कर राजस्व स प्राप्तियाँ भी विगत वर्षों से निरन्तर बढ़ रही हैं। कर राजस्व का दो भागों में विभाजित किया जा सकता है केन्द्रीय करों का अंश एवं राज्य कर राजस्व। केन्द्रीय करों के अंशों में सार्वधिक यागदान मधीय आदकारी करों का रहता है। तत्पश्चात दूसरा स्तर आयकर का है। राज्य के कर राजस्वों में भू राजस्व मुद्राक एवं पजीयन शुल्क राज्य सरकारों द्वारा कर वानों पर कर सामान और यात्रियों पर कर मितली पर कर और शुल्क आदि सम्मिलित हैं।

निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों में कर राजस्व का दर्शाया गया है।

कर राजस्व		
वर्ष	कर राजस्व (कोड़ रु)	कुल राजस्व प्राप्तियाँ म कर राजस्व का प्रतिशत भाग
1994-95	3598 85	56 93
1995-96	4213 81	55 23
1996-97	4889 60	64 68
1997-98	5794 51	66 50
(मरगाहित अनुमान)		
1998-99	7212 80	70 79
(बजट अनुमान)		
स्रोत: वार्षिक वित्तिय विवरण 1998-99 राजस्थान सरकार, जून 1999		

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कर राजस्व में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का भाग आधे से अधिक रहा। निम्नलिखित तालिका में राजस्व प्राप्ति के राज्य के कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों के अंश के रूप में दर्शाया गया है।

वर्ष	कुल कर राजस्व	राज्य कर राजस्व	केन्द्रीय कर का अंश
1994-95	3598.85	2307.16	1291.68
1995-96	4266.78	2783.56	1483.22
1996-97	4983.35	3276.56	1706.79
1997-98	5794.51	3768.78	2025.73
(संशोधित अनु.)			
1998-99	7212.80	4440.87	2771.93
(घट्ट अनु.)			

स्रोत: परिवर्तित आय व्ययक अभ्युपगम 1998-99 राजस्व वारिकर
जुलाई 1998

तालिका स निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होगा है

- (1) कुल कर राजस्व में केन्द्रीय करों का अंश राज्य कर राजस्व से कम है।
- (2) केन्द्रीय करों के अंश में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (3) राज्य कर राजस्व भी निरन्तर बढ़ रहा है और कुल कर राजस्व में राज्य कर राजस्व का भाग केन्द्रीय करों के अंश की तुलना में अधिक है।
- (4) केन्द्रीय करों के अंश के अतिरिक्त आयकर, भू-सम्पत्ति कर तथा मध्यम आवकाश कर से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है।
- (5) राज्य कर राजस्व में मुख्यतः भू-राजस्व, मुद्राक एवं पञ्जीन शुल्क राज्य आवकाश विधायक कर वाहनों पर कर सामान व यात्रियों पर कर, पिबती पर कर व शुल्क तथा अन्य करों व महसूल आदि में प्राप्त होता है।
- (6) राज्य के कर राजस्व को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों की दृष्टि से बांटा जा सकता है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय की दृष्टि से बांटा होता है कि

- (1) राज्य को प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों में अधिक आय प्राप्त होती है।
- (2) प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (i) अकर राजस्व (Non Tax Revenue) राज्य

सरकार के अकर राजस्वों में व्याज का प्राप्ति लाभ आश एवं लाभ सामान्य सेवाओं, समाजिक सेवाओं (शिक्षा, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास आदि) आर्थिक सेवाएँ (लघु सिंचाई, वनिकी और वन्य जीव उद्योग, ग्रामोद्योग व लघु उद्योग, वृहत एवं मध्यम सिंचाई, परियोजनाएँ, खनन आदि) व सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक राजस्व सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। तत्पश्चात् सामान्य सेवाओं, आर्थिक सेवाओं व व्याज की प्राप्ति लाभ आश तथा आदि का स्थान है। इस प्रकार कुल अकर राजस्व एवं सहायता अनुदान मिलकर अकर राजस्व के रूप में कुल राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा भाग बन जाता है। अतः तालिका में विगत कुछ वर्षों के अकर राजस्व एवं कुल राजस्व में अकर राजस्व के प्रतिशत भाग को दर्शाया गया है।

अ कर राजस्व		
(करोड़ रुपये में)		
वर्ष	अकर राजस्व	कुल राजस्व में अकर राजस्व का प्रतिशत भाग
1994-95	1295.58	20.49
1995-96	2250.74	29.08
1996-97	1361.11	18.00
1997-98	1437.92	18.50
(संशोधित अनु.)		
1998-99	1444.84	14.18
(घट्ट अनु.)		

स्रोत: परिवर्तित आय व्ययक अभ्युपगम 1998-99 राजस्व वारिकर
जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल राजस्व प्राप्ति में अकर राजस्व से भी एक बड़ा अंश प्राप्त होता है।

अकर राजस्व के सम्बन्ध में निम्न तथ्य विचारणीय हैं।

- (1) व्याज की प्राप्ति लाभ आश एवं लाभ से प्राप्त आय में उचित वृद्धि हो रहा है।
- (2) सामाजिक सेवाओं में प्राप्त आय का मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है।
- (i) शिक्षा, कला एवं संस्कृति: इससे प्राप्त आय विगत कुछ वर्षों से बढ़ रही है। (ii) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्राप्ति से आय भी बढ़ रहा है। (iii) जनसंख्या

सर्वाई आवास और शहरी विवास इनसे प्राप्त आय भा विगत वर्षों में निरन्तर बढ़ रही है (iv) अन्य इस शीर्षक व अंतर्गत प्राप्त आय के खाते में कमी हुई है।

(3) आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत निम्न का समावेश किया जाता है।

- (i) लघु सिंचाई (ii) वानिकी एवं वन्य जीवन (iii) उद्योग प्रमोदोग एवं लघु उद्योग (iv) वृद्ध एवं सिंचाई परियोजना
(v) अनाह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग (vi) अन्य।

सहायता अनुदान (करोड़ ₹)		
वर्ष	सहायता अनुदान	कुल राजस्व प्रतिशत में % भाग
1991-92	1427.30	22.58
1992-93	1257.54	16.22
1996-97	1337.05	17.79
1997-98	1481.28	17.00
(संशोधन अनुदान)		
1998-99	1531.81	15.03
(बजट अनुदान)		
स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्थान सरकार, जूलाई 1998		

तालिका से स्पष्ट है कि सहायता अनुदान की राशि में 1994 में के परभाव कमी हुई लेकिन इसके परभाव इस राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1992-93 में कुल राजस्व प्रप्तियों में सहायता अनुदान का भाग 21.99 प्रतिशत था जो धटकर 1995-96 में 16.22 प्रतिशत हो गया।

2 राजस्व खाते में व्यय की प्रवृत्ति

Trends in Revenue Expenditure in Revenue Account

सरकार द्वारा राजस्व व्यय भी निरन्तर बढ़ रहा है कुल राजस्व व्यय को राज्य के बजट में 3 भागों के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ये शीर्षक हैं (i) सामान्य सेवाओं पर व्यय (ii) सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा (iii) आर्थिक सेवाओं पर व्यय। राजस्थान व बजट में विगत वर्षों में कुल राजस्व व्यय की स्थिति निम्न प्रकार रही है।

कुल राजस्व व्यय (करोड़ रुपये)	
वर्ष	कुल राजस्व व्यय
1994-95	6746.47
1995-96	8331.55
1996-97	8425.67
1997-98 (संशोधन अनुदान)	9209.72
1998-99 (बजट अनुदान)	11521.56
स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्थान सरकार, जूलाई 1998	

तालिका से स्पष्ट है कि कुल राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुक्तक की प्रवृत्ति भी राजस्व व्यय में वृद्धि को दर्शाती है राजस्व व्यय का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है।

(i) सामान्य सेवाओं पर व्यय (Expenditure on General Services) सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा कुल राजस्व में सामान्य सेवाओं पर व्यय व प्रतिशत भाग का निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सामान्य सेवाओं पर व्यय (करोड़ रुपये)		
वर्ष	व्यय	प्रतिशत
1994-95	2502.57	37.09
1995-96	3465.82	41.60
1996-97	3064.09	36.37
1997-98 (संशोधन अनुदान)	4558.93	36.37
1998-99 (बजट अनुदान)		
स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्थान सरकार, जूलाई 1998		

तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। सामान्य सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय का छ भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) राज्य के अर्थ इसमें अंतर्गत विधानसभा सत्री परिषद न्यायिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय में उतार-चढ़ाव होता रहा है। (ब) राजकोषीय सेवाएं राजकोषीय सेवाओं का मुख्यतः सम्पत्ति एवं प्रजीवित लेन-देनों और वस्तुओं एवं सेवाओं पर किये के समष्टि अन्य शीर्षक में दर्शाया जाता है। राजकोषीय सेवाओं के व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। (स) व्याज का भुगतान और ऋण परिशोधन इस शीर्षक के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय भागों में वृद्धि हो रहा है। (द) प्रशासनिक सेवाएं प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत एक महाभाग मंत्रालय जिला प्रशासन कानून पुलिस जल मुद्रण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय भी विगत वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। (इ) वैश्वीय विधि सामान्य सातए इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय भी तेजी से बढ़े हैं। (उ) सहायता अनुदान और अश्वान इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय में विगत कुछ वर्षों में प्रायः स्थिर रहने लगे हैं।

(ii) सामाजिक सेवाओं पर व्यय (Expenditure on Social Services) सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा खाने-पीने एवं सम्पत्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परापूर्व भण्डार आवास व शहरी विवास श्रमिक और श्रमिक कल्याण अनुमृति जातिगत अनुमृति जनजातिगत और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा मानविक

कल्याण व पोषाहार आदि को सम्मिलित किया गया।

सामाजिक सेवाओं पर विगत वर्षों में किए गए व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

सामाजिक सेवाओं पर व्यय		
वर्ष	सामाजिक सेवाओं पर व्यय	सामाजिक सेवाओं के कुल व्यय का प्रतिशत
1994-95	2525.84	37.44
1995-96	3024.38	36.30
1996-97	3467.73	41.15
1997-98 (संशोधित बजट)	3840.25	41.70
1998-99 (बजट अनुमान)	4372.74	42.29

स्रोत - वित्तिक और विकास व्यय 1994-99, राजस्व बजट, गुवाहाटी, 1998

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि

- (1) सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि होती रही है।
- (2) सामाजिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत 1994-95 में 37.44 प्रतिशत था जो बढकर 1998-99 में 42.29 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- (3) शिक्षा कला व संस्कृति पर किया गया राजस्व व्यय चार भागों में विभक्त किया जा सकता है - (अ) सामान्य शिक्षा पर किया गया व्यय विगत वर्षों में तेजी से बढा है। (ब) तकनीकी शिक्षा पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। (ग) खेल और युवा सेवाओं पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। (द) कला एवं संस्कृति पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (4) चिकित्सा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए व्यय को निम्न भागों में बांटा जा सकता है - (अ) ऐलोपैथी इसके अन्तर्गत निर्देशन एवं प्रशासन और चिकित्सा सक्षमता, जनजाति क्षेत्र उपयोजना चिकित्सा, शिक्षा व प्रशिक्षण कर्मचारों राज्य बोमा योजना चिकित्सा भण्डार डिपो और विभागीय भौत निर्माण आदि को सम्मिलित किया जाता है। ऐलोपैथी पर विगत वर्षों में किया गया व्यय निरन्तर बढ रहा है। (ब) अन्य चिकित्सा प्रणालियों के अन्तर्गत आयुर्वेदिक जनजाति क्षेत्र उपयोजना होम्योपैथी, यूनानी और अन्य पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है। विगत वर्षों में इन चिकित्सा पद्धतियों पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन चिकित्सा प्रणालियों में सर्वाधिक व्यय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर किया गया है। (ग) जन स्वास्थ्य पर किया गया व्यय भी निरन्तर बढ रहा है। परिवार कल्याण पर किया गया व्यय प्रारम्भ में तेजी से बढा लेकिन विगत वर्षों में इसमें स्थिरता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है।

(iii) आर्थिक सेवाओं पर व्यय (Expenditure on

Economic Services) - आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप शर्माण विकास एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, उद्योग एवं खनिज मिर्चाई एवं बाड नियन्त्रण, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है।

निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है।

वर्ष	आर्थिक सेवाओं पर व्यय (कोटि रुपये)	आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत
1994-95	1718.06	25.47
1995-96	1841.34	22.10
1996-97	1893.83	22.48
1997-98 (संशोधित बजट)	1813.63	19.69
1998-99 (बजट अनुमान)	2083.88	18.14

स्रोत - वित्तिक और विकास व्यय 1994-99, राजस्व बजट, गुवाहाटी, 1998

तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि -

- (1) विगत वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय लगभग स्थिर बढा हुआ है।
- (2) आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत घटा है।
- (3) कृषि और सम्बद्ध कार्यों में कृषि काय भू-जल संरक्षण, पर्याप्तन, मत्स्य उद्योग वनिका और वन्य जीवन, खाद्य व भण्डारण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा महत्त्वपूर्ण तथा अन्य कृषि कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है।
- (4) उद्योग पर राज्य व्यय का दो भागों में बांटा जा सकता है - प्रथम सामान्य व्यय - इसके अन्तर्गत निर्देशन व प्रशासन औद्योगिक उत्पादनक औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण जनजाति क्षेत्र उपयोजना तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित किया जाता है द्वितीय उद्योगिक उद्योग - इसके अन्तर्गत नमक का व्यापार का योजना, मीडियम मन्फैकचर का व्यापार की योजना, राज्यीय ऊर्जा मिल, डीजल तथा नदीन सेवा आदि को सम्मिलित किया जाता है।
- (iv) विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय (Development & Non-Development Expenditure) - राज्य व्यय को विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय में भी विभक्त किया जा सकता है। निम्न तालिका में विकास व्यय एवं अविास व्यय को दर्शाया गया है।

लेख का शीर्षक	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
कुल राजस्व व्यय	6746.47	8331.55	8425.67	9209.72	11521.56
(1) विकास व्यय	4243.90	4865.73	5361.57	5653.88	6962.63
(2) गैर विकास व्यय	2502.57	3465.82	3064.09	3555.83	4558.93
कुल व्यय से वित्त					
व्यय का प्रतिशत	62.91	58.40	63.63	61.39	60.43
सूचकांक (अधार 1980-81=100)					
(क) विकास व्यय	883	1012	1115	1176	1448
(ख) गैर विकास व्यय	1210	1676	1482	1720	2206

स्रोत - वित्तविवरण और व्ययक अभ्यन्तर 1998-99, राजस्थान सरकार नुमाई, 1998

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

- (1) विकास व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (2) गैर विकास व्यय नीच गति से बढ़ रहा है।
- (3) कुल व्यय से विकास व्यय का प्रतिशत जो 1994-95 में 62.91% था जो 1997-98 में 61.39 प्रतिशत रहा।
- (4) गैर विकास व्यय के सूचकांक गैर-विकास व्यय में वृद्धि को दर्शाते हैं। इसी प्रकार विकास व्यय के सूचकांक विकास व्यय में वृद्धि को बताते हैं।

(v) राजस्व व्यय का उद्देश्यानुसार वर्गीकरण (Objective wise Revenue Expenditure) -

राजस्व व्यय को उद्देश्य के अनुसार ही वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत राजस्व व्यय को मजदूरी एवं वेतन, यात्रा एवं चिकित्सा व्यय, किराया रेंटपट्टी, प्रकाशन, विज्ञापन, कार्यालय व्यय, सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति एवं निर्वाह भत्ता वृहद एवं लघु निर्माण कार्य, मशीन एवं सयंत्र मोटर गाड़िया एवं ह्रास विनियोग/ऋण/व्याज साभारा, पेंशन और ग्रेज्युटी आदि भागों में विभक्त किया जा सकता है। विगत वर्षों में मजदूरी एवं वेतन सम्बन्धी व्ययों में तेजी से वृद्धि हुई है इसी प्रकार यात्रा एवं चिकित्सा व्यय किराया व रेंटपट्टी, छात्रवृत्ति एवं निर्वाह भत्ता, वृहद एवं लघु निर्माण कार्य मशीन एवं सयंत्र और पेंशन व ग्रेज्युटी सम्बन्धी व्ययों में निरन्तर वृद्धि हुई।

3 राजस्व खाते में बचत(+) अथवा घाटा (-) निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के राजस्व खाते में बचत अथवा घाटा दर्शाया गया है -

(करोड़ रुपये)	
वर्ष	बचत (+) अथवा घाटा (-)
1994-95	(-)109.49
1995-96	(-)300.68
1996-97	(-)424.75
1997-98	(-)546.90
(संशोधित अनुमान)	
1998-99	(-)462.41
(बजट अनुमान)	

स्रोत - वित्तविवरण और व्ययक अभ्यन्तर 1998-99 राजस्थान सरकार नुमाई 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व खाते में सभी वर्षों में घाटे की प्रवृत्ति रही है।

4. राजस्व खाते के अतिरिक्त लेनदेन

Transaction outside the Revenue Account

(i) प्राप्तियां (Receipts) : राजस्व खाते के अतिरिक्त प्राप्तियों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश किया जा सकता है। (1) स्थाई ऋण निम्न तालिका में प्राप्त स्थाई ऋण, स्थाई ऋणों का भुगतान एवं शुद्ध प्राप्तियों को दर्शाया गया है -

(करोड़ रुपये)	
वर्ष	स्थायी ऋण
1994-95	314.27
1995-96	394.27
1996-97	433.69
1997-98	522.18
(संशोधित अनुमान)	
1998-99	649.02
(बजट अनुमान)	

स्रोत - वित्तविवरण और व्ययक अभ्यन्तर 1998-99 राजस्थान सरकार नुमाई 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1994-95 में स्थायी ऋण 314.27 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1997-98 में 522.18 करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार द्वारा स्थायी ऋणों का भुगतान भी किया जाता रहा है। भुगतान किए गए ऋणों की राशि में कमी वृद्धि होती रही है।

(ii) अल्पकालीन ऋण (Floating debt) : राज्य सरकार प्रायः अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती है निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों में अल्पकालीन ऋण की स्थिति को दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपये)	
वर्ष	अल्पकालीन ऋण
1994-95	1343 00
1995-96	2478 90
1996-97	4657 81
1997-98 (संशोधित अनुमान)	3335 83
1998-99 (बजट अनुमान)	1200 00
स्रोत : वित्तिकृत अर्थ व्यवस्था 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998	

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्राप्त की गई अल्पकालीन ऋणों की मात्रा में कमी-वृद्धि होती रहा है। सरकार अल्पकालीन ऋणों का भुगतान भी करती रही है। भविष्य में भी यह प्रवृत्ति बनी रहने की सम्भावना है।

(iii) केन्द्र सरकार का ऋण (Loans From Central Government) राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से भी ऋण प्राप्त करती है। अग्र तालिका में विगत कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण को दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपये)	
वर्ष	प्राप्त ऋण
1994-95	887 46
1995-96	1140 22
1996-97	1489 88
1997-98 (संशोधित अनुमान)	2033 58
1998-99 (बजट अनुमान)	1866 91
स्रोत : वित्तिकृत अर्थ व्यवस्था 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998	

तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार से प्राप्त किए गए ऋण की मात्रा में वृद्धि होती रहा है। राज्य सरकार द्वारा समुचित मात्रा में केन्द्र से धन प्राप्त किया जाता है। ऋणों के भुगतान में भी निरन्तर वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।

(iv) सार्वजनिक लेखा (Public Account) इस शापक क अंतर्गत प्राप्त की गई राशि को अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपये)	
वर्ष	सार्वजनिक लेखा
1994-95	13942 14
1995-96	16179 96
1996-97	15632 49
1997-98	19765 19
(संशोधित अनुमान)	
1998-99	20817 61
(बजट अनुमान)	
स्रोत : वित्तिकृत अर्थ व्यवस्था 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998	

तालिका से स्पष्ट है कि सार्वजनिक लेखों के अंतर्गत प्राप्ति का वृद्धि रही है।

(v) ऋण एवं अग्रिम (Loan & Advances) इस शीर्षक से प्राप्त आय में कमी वृद्धि होती रही है। सरकार द्वारा भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प-वक्त समग्र एवं एमो हो अन्य जमाओं की प्राप्ति को ला- खाते में दिखाया जाता है और सम्बन्धित खर्च इसी खा- में से रकम निकाल कर किया जाता है। सरकार इन लेन- देनो के सम्बन्ध में मोटे तौर पर एक बैक के रूप में कार्य करती है। यदि देखा जाए तो लोक खाते में दिखाई जाने वाली रकम सरकार की आय नहीं होती क्योंकि इस धनराशि का किसी न किन्हीं समय उन लोगों को लौटाना होता है जो -म जमा करते हैं। कभी कभी ऐसे अवसर भी आ जाते हैं ज-म सरकार को विधानसभा की स्वयं-कुवि मिला से पूर्व भी कुछ ऐसा व्यय करना पड़ जाता है जिसका पहले से पूर्वानुमान नहीं होता। इस तरह का व्यय आकस्मिकता निधि में किया जाता है। इस निधि में से जो राशि व्यय की जाती है उसके बारे में विधानसभा से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। स्वा-कुवि मिलन पर उतनी ही राशि पुन- आकस्मिकता नि-म में डाल दी जाती है। पू-जी गत व्ययों में स्थापना मशीन-ग सयन व अन्य उपकरण निर्माण विनियोग प्रतिष्ठितियों ए- ऋण प-यों का ऋय अदि को सम्मिलित किया जाता है। पु-नीत व्यय का सबसे अधिक भाग निर्माण कार्यों पर व्यय होता है। इसके पश्चात् राज्य सरकार निगमों और अन्य संस्था-ग को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम पर व्यय करती है।

राजस्व खाने के अतिरिक्त बचत (+) अथवा घाटा (-) को अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्व खाते के अतिरिक्त बचत (+) अथवा घाटा (-) करोड़ रुपये में			
विवरण	(संशोधित अनुमान)	1996-97	1995-96
राजस्व खाते के अतिरिक्त	(+)	987 33	976 34
बचत (+) या घाटा (-)	(+)	560 29	
स्रोत : वित्तिकृत अर्थ व्यवस्था 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998			

5. बचत अथवा घाटा Surplus or Deficit

राज्य सरकार की अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों और व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान के बजट का घाटा अथवा बचत ज्ञात की जा सकती है। इस मा-म में विगत

कुछ वर्षों की स्थिति इस प्रकार रही है।

मेरे का पीरिड	(घरोपित अनुमानों) (बचत का अनुमान)		
	1996-97	1997-98	1998-99
(i) राजस्व लेख की			
- प्रतिष्ठा एवं व्यय -865 94	-495 93	-1332 09	
बचत(+) या घाटा(-)			
(ii) गवर्नर खाते के अनिश्चित			
सेवन +987 33	+976 34	+1560 29	
बचत(+) या घाटा(-)			
(iii) घरोपित शुद्ध +121 38	+480 41	+228 20	

स्त्रोत : वित्तीय आर्थिक व्यवस्था 1995-98 राजस्थान सरकार
दुम्गाई, 1998

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस शीर्षक के अंतर्गत शुद्ध बचत व शुद्ध घाटे का प्रभाव विभिन्न वर्षों में अलग-अलग रहा है।

राजस्थान की वित्तीय स्थिति में

सुधार के लिए सुझाव

SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT IN FINANCIAL POSITION OF RAJASTHAN

राजस्थान की वित्तीय स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कमजोर है। राज्य अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान बनी हुई है। राज्य आय का लगभग आधा हिस्सा कृषि एवं कृषि संबंधी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। मानसून अनिश्चित प्रवृत्ति के है। अतः मानसून की प्रवृत्ति के अनुसार ही राज्य की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। राज्यों में औद्योगिक विकास के स्तर में परिवर्तन हो रहा है लेकिन विकास स्तर बहुत धीमा है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य में अनेक प्रकार की विषमताएँ विद्यमान हैं। राज्य में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1990-91 में 183 यूनिट था जो वर्ष 1991-92 में लगभग 215 यूनिट प्रतिव्यक्ति हो गया। लेकिन यह देश की विरसित राज्यों की तुलना में बहुत कम है। अतः राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की विद्युत शक्ति के अभाव के कारण भारी क्षति उठानी पड़ती है। राजस्थान में विभिन्न वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों की समस्या लम्बे समय से बनी हुई है। अतः राज्य के उपभोक्ता बढ़ती हुई महागाई के कारण परेशान है। 1989-90 तथा 1990-91 के मध्य प्रति व्यक्ति राजस्वीय आय (1990-81 की स्थिर कीमतों के अनुसार) में 12.72% की वृद्धि हुई लेकिन 1991-92 में प्रतिव्यक्ति आय में 1990-91 की तुलना में 7.09% की कमी हो गई। 1991-92 के लिए बालू

कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय 3983 रुपए थी।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन राज्य की आर्थिक स्थिति मापने का एक प्रमुख पैमाना है। स्थिर कीमतों (1980-81) पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1989-90 के 7104 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1990-91 में 8213 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया। इस प्रकार इसमें 11.61 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई, जो कि मुख्यतः कुल राज्य आय के कृषि अनुभाग में तीव्र वृद्धि के कारण है। कृषि में वृद्धि वर्ष 1990-91 में अनुकूल मौसम तथा समय पर वर्षा के कारण हुई है। वर्ष 1991-92 के त्वरित अनुमान इंगित करते हैं कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 7825 करोड़ रुपए होगा जो कि गत वर्ष की तुलना में 4.73 प्रतिशत कम है। वर्ष 1991-92 के राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों में 1990-91 वर्ष के विपरीत कमी का कारण कृषि उत्पादन में गिरावट रही है अधिकांश जिलों में विलम्ब से पव औरत से कम वर्षा होने के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट हुई। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1989-90 में 13848 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था जो 1990-91 में 28.94 प्रतिशत से बढ़कर 17578 करोड़ रुपए हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसमें 18.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 के त्वरित अनुमानों के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 19151 करोड़ रुपए था जो 1990-91 की अपेक्षा 8.95 प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान प्राकृतिक समाधनों, औद्योगिक क्षमताओं और श्रमशक्ति आदि की दृष्टि से एक धनी राज्य है। अतः कुछ सक्रिय प्रयासों के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं -

(1) कृषि क्षेत्र का विकास (Development of Agriculture) - राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार एवं विकास करके राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। विगत कुछ वर्षों में राज्य में भू-राजस्व का महत्व निम्नतर कम हो रहा है। सरकार भू-जोत कर अथवा कृषि पर आयकर और मिर्चाई की दरों में वृद्धि करके राज्य की आय में वृद्धि कर सकती है। इस कार्य में सरकार का जन विरोध का सामना करना पड़ सकता है लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार का यह एक अच्छा माध्यम हो सकता है क्योंकि राज्य का कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है।

(2) कर वसुली में सुधार (Improvement in tax Collection) - राज्य की कर वसुली व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण है। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं कर चोरी का बढ़ावा मिला। समय पर कर वसूल नहीं किया जाता है। अतः बकाया

वर्षों की राशि में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। अतः विक्री कर एवं अन्य करों की वसूली व्यवस्था में सुधार करके राज्य की आय में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को समझने के निवारण हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस कार्य हेतु निरीक्षण व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। कर वसूली में सुधार करके राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। इस तथ्य का संकेत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न बजट प्रस्तावों से भी होता है। विक्री कर की दरों में वृद्धि करके भी राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। विक्री करों में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक उपयुक्त प्रणाली लागू की जा सकती है।

(3) उद्योगों का तीव्र गति से विकास (Rapid Development of Industries) - राज्य सरकार उद्योगों का तीव्र गति से विकास करके राज्य आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकती है। राज्य में खजिन सम्पदा एवं पशु सम्पदा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अतः खनिज आधारित उद्योग, पशु सम्पदा पर आधारित उद्योगों एवं कृषि पर आधारित उद्योगों का तेजी से विकास किया जाना चाहिए। इन उद्योगों के विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर इन उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और चयनित स्थानों पर सरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अतः औद्योगिक विकास के साथ-साथ राज्य आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया।

(4) राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों में सुधार (Improvement in Govt Undertaking) - राजस्थान में परिवहन, विद्युत एवं सिंचाई संबंधी समस्याओं/राजकीय उपक्रमों को प्रबंध व्यवस्था में सुधार करके भी राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में इन उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में अनेक दोष दिखते हैं। इनमें विपणन का अभाव है। इनकी दरों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः राज्य में महंगाई की समस्या बढ़ रही है। इसके विपरीत ये उपक्रम प्रायः घाटे की स्थिति दर्शाते रहे हैं। इसका प्रमुख कारण प्रशासनिक अनुशासिता एवं भ्रष्टाचार है। अतः राज्य सरकार के इन उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में किन्हीं विशिष्ट योजना के अंतर्गत सुधार करके राज्य की वित्तीय स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है। इन उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना भी आवश्यक है।

(5) ऋण भार में कमी (To lessen the burden of Loans) - राज्य सरकार अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय-समय पर केन्द्र

सरकार से ऋण प्राप्त करती है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त किए हैं। अतः राज्य सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए केन्द्र सरकार से ऋण माफी का अनुरोध कर सकती है लेकिन यह राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करने का केवल सामयिक उपाय है।

(6) अल्प बचत कार्यक्रमों का विस्तार (Extension of Small Saving Programmes) राज्य सरकार अल्प बचतों को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक स्थिति का सुधार कर सकती है। विभिन्न आकर्षक योजनाओं के माध्यम से राज्यों में बचत की जाती है। अल्प बचत में जमा राशि का 3 चौथाई भाग राज्य को वापस लम्बी अवधि के ऋण के रूप में प्राप्त होता है। अतः अल्प बचत कार्यक्रमों से राज्य की आय में वृद्धि होगी।

केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध

CENTRE-STATE FINANCIAL RELATIONS

संघीय प्रकृति द्वि-स्तरीय सरकार की प्रतीक है। इस प्रकार के राष्ट्र में सत्ता केन्द्र व राज्यों में बटी हुई होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र राज्यों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। वस्तुतः किसी भी संघीय सरकार में केन्द्र व राज्यों के कार्य, करारोपण के अधिकार तथा व्यय करने के अधिकार देश के मन्त्रिपरिषद् में स्पष्ट रूप से दिए हुये होते हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैण्ड आदि में यह प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र व राज्यों में सौहार्दपूर्ण तथा सुदृढ़ सम्बन्ध होने पर देश का आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है। इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य सहयोग को बढ़ाया जाए। प्रो वी एन गुप्ता के अनुसार "संघ को एक समुक्त परिवार की भाँति कार्य करना चाहिए व केन्द्र को परिवार के मुखिया की भाँति कार्य करना चाहिए जिसका कार्य अपने सदस्यों का आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।" इसी प्रकार प्रो आर एन भार्गव के अनुसार "संघीय वित्तीय सम्बन्धों का आशय देश व राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों तथा उन दोनों के मध्य समन्वय से लगाया जाता है।"

संघीय वित्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -
केन्द्र व राज्य सरकारों के सविधान के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में कर लगाकर आय प्राप्त कर सकते हैं।

- केन्द्र सरकार द्वारा वसूल किए गए कुछ करों में राज्यों के हिस्से का भी निर्धारण किया जाता है।

- केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को विकास कार्य हेतु अनुदान देती है।

भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों की विशेषताएँ

CHARACTERISTICS OF CENTRE & STATE FINANCIAL RELATIONS IN INDIA

भारतीय संविधान (26 नवम्बर 1949) में केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों का वर्णन किया गया है इसके अतिरिक्त प्रत्येक पांच वर्ष पर गत वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जाती है जो केन्द्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के बारे में सुझाव देता है। भारतीय मध्य व राज्यों के पारम्परिक मन्थनों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 245 से 300 के अन्तर्गत समाविष्ट है। अनुसूचा 7 में केन्द्र राज्य तथा दोनों के सम्मिलित अधिकारों से सम्बन्धित तीन तालिकाएँ दी गई हैं। केन्द्र व राज्यों के बीच भा वित्तीय सम्बन्धों में विवाद का विषय रहे हैं। अधुनिक समय में कल्याणकारी राज्यों के दायित्वों में निरन्तर होने वाली वृद्धि की पूर्ति वित्त के बिना संभव नहीं लगती। संविधान निर्माताओं को भी भविष्य में उठने वाले विवादों का आभास था। अतः संविधान के अनु 280 के तहत गठन की गई पांच वर्ष पर चलने वाला एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(अ) आय के साधनों का वितरण

Distribution of Sources of Income

भारतीय संविधान के अन्तर्गत आय के विभिन्न साधनों का वितरण की व्यवस्था इस प्रकार की गई है

(i) केन्द्र के आय स्रोत (Centre's Sources of Income) आय के प्रमुख संप्रदाय मध्य इस प्रकार है

(1) निगम कर (2) मुद्रा सिक्के और वैधानिक मुद्रा विदेशी विनिमय (3) चुगी निर्यात कर संहिता (4) तम्बाकू एवं अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर (5) सम्पत्तियों पर लगन वाला कर (कृषि भूमि को छोड़कर) (6) फीस (कन्द्रीय भूभाग व अनुभाग) (7) विदेशी ऋण (8) लाटरी (9) डाक घर बाजार बैंक (10) डाक तार टेलिफोन व मसार व अन्य साधन (11) केन्द्र सरकार की सम्पत्तियाँ (12) केन्द्र सरकार व कर्मचारीजनिक ऋण (13) रेलवे (14) विनिमय विन केन्द्र तथा प्रांतिक प्रांत पर मुद्राक कर (15) भारतीय ग्रिडवर्क मध्य आय (16) आयकर (कृषि आय व अतिरिक्त) (17) सम्पत्ति कर (18) विनिमय बाजार कर (19) समाचार पत्रों व कृषि विक्रय एवं उद्यम दिए गए विज्ञापनों पर कर (20) जल स्थल एवं वायु मार्ग द्वारा ढाए गए माल व यात्रियों पर कर।

(ii) राज्यों के आय स्रोत (State's Sources of Income) राज्य सरकारों का आय स्रोत इस प्रकार है

(1) भूमि पर लगन (2) कृषि भूमि व उन्नतधिकार पर कर (3) भूमि तथा मकानों पर कर (4) राज्यों में निर्मित मालक द्रव्यों पर उत्पादन कर (5) माल के क्रय विक्रय पर कर (6) स्थानीय क्षेत्र वस्तुओं का आन पर कर (7) गड्डियों पर कर (8) आन्तरिक जल तथा स्थल मार्गों के यात्रियों तथा माल पर कर (9) स्टाम्प शुल्क (मुद्राक कर) (10) कृषि आय पर कर (11) कृषि भूमि पर सम्पदा कर (12) रजिस्ट्रार पर कर (13) विद्युत उत्पादन एवं उपयोग पर कर (14) विज्ञापन पर कर (समाचार पत्रों व अतिरिक्त) (15) मनोरंजन कर शर्त एवं जुए पर कर (16) जानवरों पर कर तथा नौसेना पर कर (17) व्यापार व व्यवसाय पर कर (18) कोर्ट शुल्क के अतिरिक्त राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय पर शुल्क आदि।

(iii) केन्द्र द्वारा लगाए गए तथा एकत्र किए गए कर जो राज्य सरकारों के मध्य वितरित किए जाते हैं (Taxes levied & collected by the centre and distributed among state) (1) कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार का सम्पत्ति पर लगन वाला उन्नतधिकार कर (2) रत फ्रिगए तथा भाड़े पर कर (3) समाचार पत्र तथा विज्ञापन पर लगन वाला कर (4) यात्रियों व मकान पर लगन वाला टर्मिनल टैक्स (5) मट्टा वस्त्रों पर किए गए सौदों पर कर (6) अन्तर्गन्धीय व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं पर बिंदी कर।

(iv) केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र व उपयोग किए जाने वाले कर (Taxes levied by the centre but collected & used by States) स्टाम्प शुल्क टवाइयों व मौन्दर्य प्रमाथनों की वस्तुओं पर केन्द्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है लेकिन ऐम कर राज्य सरकारें वसूल करती हैं और इन का स प्राण आय का वितरण उन्हीं के मध्य कर दिया जाता है।

(v) केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए एवं एकत्रित किए गए कर जिनसे प्राप्त आय का वितरण केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य किया जाता है (Taxes levied and collected by the centre but income is distributed among centre by states) ऐम करों में दो कर प्रमुख हैं प्रथम कृषि आय व अतिरिक्त अन्य आय पर कर तथा द्वितीय कुछ वस्तुओं पर लगाए गए उत्पादन कर। वे दोनों पर केन्द्र द्वारा लगाए गए कर किए जाते हैं। इन करों में प्राप्त आय का वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है।

(व) अनुदान

Grants-in Aid

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी करो व ऋणों की राशि एक भारतीय सचिव निधि में तथा राज्यों द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण करो व ऋणों की राशि सचिव निधि में जमा होती है। आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र राज्यों को प्रतिवर्ष कुछ राशि अनुदान के रूप में देता है क्योंकि उनके विकास के लिए वांछित वित्त कर्षों द्वारा समूल नहीं हो पाता है। केन्द्र अपनी आय के लिए अधिभार द्वारा राज्यों में विभाजित होने वाले करो में वृद्धि कर सकता है क्योंकि अधिभार की आय पर केन्द्र का अधिकार होता है। धारा 282 के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकारें अनुदान दे सकती हैं। ऐसे अनुदान उन कार्यों के लिए दिए जाते हैं जो केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

(स) ऋण

Loan

सविधा के अनु 293 (2) के अनुसार केन्द्र किसी भी राज्य सरकार को ऋण अथवा उनके द्वारा लिए गए ऋणों की गारन्टी दे सकता है। केन्द्र से ऋण लेने वाली राज्य सरकार पर यह नियंत्रण होता है कि केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना वह अन्यत्र ऋण का उपयोग नहीं कर सकती तथा केन्द्र यह अनुमति कुछ शर्तों के अधीन देता है। राज्यों को प्रायः योजनाओं को पूर्ण करने के लिए ऋण दिए जाते हैं।

(द) वित्तीय समायोजन

Financial Adjustment

केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आय व आवश्यकताओं में अनुकूलन बनाए रखने के लिए सविधान में "वित्तीय समायोजन" का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार कर लगती है और उनको वसूली भी करती है लेकिन करो से प्राप्त आय का राज्य सरकारों में वितरण कर दिया जाता है।

(य) संचित निधि

Reserve Fund

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त करो व ऋणों की राशि भारतीय सचिव निधि में जमा करा दी जाती है तथा राज्यों द्वारा प्राप्त करो व ऋणों की राशि राज्य सचिव निधि में जमा करा दी जाती है। इन निधियों की राशि को लोकसभा अथवा विधानसभा की स्वीकृति के पश्चात् ही खर्च किया जा

सकता है।

(र) वित्तीय आपातकाल का प्रावधान

Provision of Financial Emergency

सविधान के अनु 360 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में वित्तीय कारणों से संकट उपस्थित हो सकता है तो वह देश में वित्तीय आपात काल की घोषणा कर सकता है।

(ल) सम्पत्ति कर

Property Tax

सविधान के अनु 285 व 289 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें उनके राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार की किसी भी सम्पत्ति पर कर नहीं लगाएगी। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों की सम्पत्ति पर कर नहीं लगाएगी।

(व) अन्य प्रावधान

Other Provisions

कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत राज्य सरकारों के कर से मुक्त रहती है। 2 केन्द्र सरकार द्वारा उत्पन्न जल एवं विद्युत (नदी घाटी योजनाओं द्वारा अथवा अन्य योजनाओं द्वारा) पर कोई भी राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है।

(श) वित्त आयोग

Finance Commission

सविधान के अनु 280 व 281 के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इससे अतिरिक्त राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कभी भी वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं - (1) केन्द्र व राज्य सरकारों में विभाजित करो से प्राप्त आयक के सम्बन्ध में सुझाव देना कि उस आय का विभाजन किस अनुपात में किया जाए (2) देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देना (3) भारत सरकार की सचिव निधि में से राज्य सरकारों को अनुदान देने की नीति का सुझाव देना (4) राष्ट्रपति द्वारा चाहे गये विषयों पर सुझाव देना। वित्त आयोग के सदस्य प्रायः अर्द्धशास्त्री, न्याय शास्त्री,

प्रणामक तथा राजनैतिक होते हैं। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति उसका ससद द्वारा अनुमोदन करवाता है।

राज्य योजना की वित्तीय व्यवस्था

STATE PLAN FINANCING

राज्य की योजनाओं के लिए वित्त दो माध्यमों से प्राप्त होता है

(अ) राज्य को केन्द्र से प्राप्त ससाधन या राज्य को केन्द्रीय हस्तान्तरण द्वारा

1 वैधानिक हस्तान्तरण (वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा)

■ योजना हस्तान्तरण (गैडगिल फार्मूले के आधार पर योजना आयोग द्वारा)

3 ऐच्छिक हस्तान्तरण द्वारा

(ब) राज्य के मन्त्र के अंतर्गत अथवा राजस्थान का योजना ससाधन में भाग।

(अ) राज्य को केन्द्र से प्राप्त ससाधन या राज्य को केन्द्रीय हस्तान्तरण

Central Resources to States or Central Transfers to State

वे राज्य जो वित्तीय दृष्टि में कमजोर होते हैं उनके लिए केन्द्र द्वारा राज्य को हस्तान्तरित वित्तीय ससाधनों का विशेष महत्व होता है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति भी बहुत सुदृढ़ नहीं है। अतः केन्द्र से प्राप्त अधिक ससाधन राज्य के आर्थिक विकास का गति द सकत है। केन्द्र द्वारा राज्य वित्तीय साधन का हस्तान्तरण तीन प्रकार में किया है

1 वैधानिक हस्तान्तरण (वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा) (Statutory Transfers By Central Govt. on the recommendation of Finance commission) वित्त आयोग द्वारा राज्या का आरक्षण किए गए हस्तान्तरण का वैधानिक हस्तान्तरण का नाम दिया जाता है। इनके अन्तर्गत केन्द्रीय करा में राज्य का भाग तथा उसे दिए जाने वाले सहाय्यार्थ अनुदान सम्मिलित हैं। वैधानिक हस्तान्तरण वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा किए जाते हैं।

विभिन्न वित्त आयोग एवं राजस्थान को किए गए वैधानिक हस्तान्तरण

गणना द्वारा प्रति पात्र वर्ष प्राप्त या आवश्यकता

पड़ने पर इससे पूर्व वित्त आयोग का गठन किया जाता है यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अब तक दस वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। वित्त आयोग केन्द्रीय करा का किन्ना अंश केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य वितरित है यह निर्धारित करता है साथ ही यह भी देखता है कि विभिन्न राज्यों में इस अंश या राशि का वितरण किम प्रकार हो। यह राज्यों को दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदानों के सिद्धान्त निर्धारित करता है इसके अतिरिक्त वित्त आयोग उन मामलों में भी सिफारिश करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंप जाते हैं।

इस प्रकार वित्त आयोग राज्य को वित्तीय ससाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के आय स्रोत सीमित होते हैं अतः वे वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर अधिक से अधिक धन राशि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसी कारण विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशें प्रायः अलग-अलग होती हैं क्योंकि परिस्थितियों में भी निरन्तर बदलाव आता रहता है। भारत में अब तक 10 वित्तीय आयोगों की स्थापना की जा चुकी है। इनमें सम्बन्धित प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं

1 प्रथम वित्त आयोग नवम्बर 1951 (First Finance Commission November 1951)

इस आयोग की स्थापना श्री क. सी. नियागी की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने दिसम्बर 1952 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

आयकर का वितरण (Distribution of Income tax) आयकर से प्राप्त राशि में राज्य सरकार को हिस्से का 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया। आयकर की विभाज्य राशि में से 20 प्रतिशत राज्यों की वसुली के आधार पर और 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। वित्त आयोग ने "क" वर्ग के राज्यों के लिए 3.25 प्रतिशत से 17.50 प्रतिशत तथा "ख" वर्ग के राज्यों के लिए 0.75 प्रतिशत से 4.50 प्रतिशत और "ग" वर्ग के राज्यों के लिए 2.75 प्रतिशत भाग निश्चित किया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) इस आयोग ने तथ्यांक वनस्पति तेल और दियामुई 5% लगाए गए उत्पादन कर से प्राप्त रकम के 40 प्रतिशत भाग का राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की।

राज बजट की प्रवृत्ति

अनुदान (Grants-in-Aid) आयोग ने बजट आवश्यकताओं व समाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए मात राज्यों को सामान्य अनुदान देने का सुझाव दिया। आठ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा तीन राज्यों को उनकी आय में कमी को पूर्ण करने के लिए अनुदान दिए जाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त जूट उत्पन्न करने वाले राज्यों के अनुदान में वृद्धि करने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1950-51 से 1955-56 के अन्तर्गत राजस्थान को 18.6 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तांतरित कुल राशि का 2.1 प्रतिशत था।

2 द्वितीय वित्त आयोग - जून 1956 (Second Finance Commission June, 1956) - इस आयोग की स्थापना श्री के. मन्थानम की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1957 में प्रस्तुत की। आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नानुसार हैं -

आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) - इस आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में से राज्य सरकारों को 55 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या और 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। आयकर से प्राप्त एक प्रतिशत भाग केन्द्रशासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने उत्पादन कर से प्राप्त रकम के 25 प्रतिशत भाग को राज्य सरकारों के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। उत्पादन कर में और अधिक वस्तुओं को सम्मिलित किया गया।

अनुदान (Grants-in-Aid) - द्वितीय वित्त आयोग ने 11 राज्य सरकारों को उनकी विकासशील आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1957-58 से 1960-61 के मध्य राजस्थान को 55 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तांतरित की गई कुल राशि का 4.57 प्रतिशत था।

3 तृतीय वित्त आयोग - दिसम्बर, 1960 (Third Finance Commission Dec, 1960) - तृतीय वित्त आयोग की स्थापना श्री ए. के. चट्टाजी की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने दिसम्बर, 1961 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार हैं -

आयकर का विभाजन (Distribution of Income tax) - तृतीय वित्त आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में राज्यों के हिस्से को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 66.67 प्रतिशत कर दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में से 2.5 प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों को देने की सिफारिश की।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन करों से प्राप्त रकम में राज्य सरकारों का हिस्सा 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया लेकिन उत्पादन कर वाले वस्तुओं की मर्यादा बढ़ाकर 35 कर दी गई।

अनुदान (Grants-in-Aid) - इस आयोग ने दस राज्यों को 110.25 करोड़ रुपये का अनुदान देने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, दस राज्यों को मड़क परिवहन के विकास के लिए 9 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने का सुझाव दिया गया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1961-62 में 1965-66 के मध्य राजस्थान को 123 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया।

4 चतुर्थ वित्त आयोग - मई, 1964 (Fourth Finance Commission May, 1964) - इस आयोग की स्थापना श्री पी. वी. रावमन्ना की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1965 में प्रस्तुत कर दी। इस आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नांकित थे -

आय कर का विभाजन (Distribution of Income Tax) - इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में राज्यों का हिस्सा 66.67 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। आयकर की विभाज्य रकम में से 80 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या और 20 प्रतिशत राज्यों में आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की। आयकर की विभाज्य राशि में से 2.5 प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया गया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) इस आयोग ने उत्पादन करों से प्राप्त रकम में राज्य सरकारों का हिस्सा 20 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया। अतिरिक्त उत्पादन कर की राशि में से एक प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों, 0.05 प्रतिशत नगालैण्ड, 1.5 प्रतिशत जम्मू एवं कश्मीर तथा शेष 32.54 लाख रुपये विभिन्न राज्य सरकारों को वितरित करने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grant InAid) - आयोग ने दस राज्यों को 121 89 करोड़ रुपए अनुदान देने का सुझाव दिया। इस आयोग ने अन्य पूर्व आयोगों की तुलना में राज्यों को अधिक अनुदान देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1966-67 में 1970-71 के मध्य राजस्थान को 130 4 करोड़ रुपए का हस्तान्तरण हुआ जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4 52 प्रतिशत था।

5 पाचवा वित्त आयोग - अक्टूबर, 1968(Fifth Finance Commission Oct 1968) - इस आयोग की स्थापना श्री महावीर की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, 1969 में प्रस्तुत कर दिया। पाचवें वित्त आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं -

आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) इस आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में राज्यों के हिस्से को 75 प्रतिशत के पूर्व स्तर पर ही रखा लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों के हिस्से को बढ़ाकर 2 60 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद करों से प्राप्त राशि में राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया। इस राशि को राज्यों की जनसंख्या आर्थिक विकास के स्तर तथा प्राप्त व्यक्ति आय के अनुसार वितरित करने का सुझाव दिया गया।

अनुदान (Grants-in-Aid) इस आयोग ने दस राज्यों को 637 85 करोड़ रुपए की रकम अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1969 70 में 1973 74 के मध्य राजस्थान को 265 करोड़ रुपए की राशि हस्तान्तरित की गई जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4 99 प्रतिशत थी।

6 छठा वित्त आयोग जून, 1972 (Sixth Finance Commission June, 1972) - इस आयोग की स्थापना श्री क. व्रतानंद रेडडी की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 1973 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे -

आयकर का वितरण (Distribution of

Income Tax) - आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में राज्यों के हिस्से को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की रकम में से 1 79 प्रतिशत केन्द्र शासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया तथा आयकर की विभाज्य राशि में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत राज्यों की आयकर वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of central Excise Duty) इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद करों से प्राप्त रकम में राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत निर्धारित किया और इसका 75 प्रतिशत भाग जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। उत्पादन कर से प्राप्त शुद्ध आय में से 1 41 प्रतिशत केन्द्र शासित प्रदेशों व शेष राशि को राज्यों के मध्य वितरित करने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grants-in-Aid) - इस आयोग ने कुछ राज्यों को 2509 61 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - 1974-75 से 1978-79 के मध्य राजस्थान को 536 9 करोड़ रुपए की राशि का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 5 87 प्रतिशत था।

7 सातवा वित्त आयोग जून, 1977 (Seventh Finance Commission June, 1977) - इस आयोग की स्थापना श्री जे. एम. शैलट की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, 1978 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे -

आयकर का विभाजन (Distribution of Income Tax) - इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में से राज्यों के हिस्से को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की रकम में से केन्द्रशासित प्रदेशों को 1 19 प्रतिशत देने की सिफारिश की। आयकर की विभाज्य रकम में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या और 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - केन्द्रीय उत्पाद करों से प्राप्त राशि में से राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने 1 मार्च

1979 से बिजली के उत्पादन पर लगाए गये कर्गों की राशि राज्यों को देने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grants In Aid) - इस आयोग ने 2156 करोड़ रुपए ऋणों में राहत एवं 437 करोड़ रुपए फिंडे हुए राज्यों के विकास के लिए अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - 1974-75 से 1983-84 के मध्य राजस्थान को 902 करोड़ रुपए का हस्तान्तरण हुआ जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4.33 प्रतिशत था।

8-आठवा वित्त आयोग : जून, 1982 (Eighth Finance Commission June, 1982) - इस आयोग की स्थापना श्री लार्ड वे चह्यान की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अप्रैल, 1984 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख निम्नलिखित हैं

आयकर का वितरण (Distribution of Income) - इस आयोग ने राज्यों के लिए आयकर के हिस्से को 85 प्रतिशत ही रखा। केन्द्र शासित प्रदेशों का हिस्सा 1.79 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 10 प्रतिशत आयकर बसुली के आधार पर तथा शेष 90 प्रतिशत एक नवीन प्रावधान के अनुसार वितरित करने का सुझाव दिया। इस नवीन प्रावधान के अनुसार 25 प्रतिशत राशि का आवंटन जनसंख्या के आधार पर और 25 प्रतिशत का आवंटन प्रति व्यक्ति के व्युत्क्रम का जनसंख्या के गुणनफल (प्रतिव्यक्ति x जनसंख्या) के आधार पर तथा 50 प्रतिशत का आवंटन अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों व सम्बन्धित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अवर के गुणनफल के आधार पर करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद करों में राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। एक अक्टूबर, 1984 से बिजली पर लगाए गए उत्पादन कर का 5 प्रतिशत भाग घाटे वाले राज्यों को देने का सुझाव दिया गया।

अनुदान (Grants in Aids) - इस आयोग ने गैर योजनात्मक राज्य छूट की पूर्ति के लिए सन 1985 से 1989 तक की अवधि के लिए 1555.83 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया। राज्यों की विशेष समस्याओं का समाधान करने व प्रशासनिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य में 17 राज्य सरकारों का 800 करोड़ रुपए का अनुदान देने का सुझाव दिया गया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - 1984-85 से 1988-89 के मध्य राजस्थान को 1676.2 करोड़ रुपए का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4.25 प्रतिशत था।

9 नवा वित्त आयोग - जून, 1987 (Ninth Finance Commission June, 1987) - इस आयोग की स्थापना 17 जून 1987 का समद श्रीएन के पी साहू के अध्यक्षता में की गई। व्यापमूर्ति श्री अब्दुल सत्तार कुरैशी डॉ राजा जे चैलया, लातुनहावला व महेश प्रसाद इसके अन्य 4 सदस्य थे। आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन मितम्बर, 1988 में प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन 1989-90 के लिए था। इस समिति ने अपना दूसरा प्रतिवेदन मिति ने अपना दूसरा प्रतिवेदन 1990-95 की अवधि के लिए प्रस्तुत किया। प्रथम प्रतिवेदन, सितम्बर, 1988 (First Report) Sept, 1988)

(अ) आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत ही रखा गया और राज्यों को जो अधिक रकम मिलेगी वह अधिक करारोपण अथवा कर बसुली के कारण होगी। आयकर की रकम में से केन्द्रशासित प्रदेशों को 1.004 प्रतिशत देने का सुझाव दिया। आयकर की राशि में से राज्यों का कुल हिस्सा 2990.38 करोड़ रुपए होगा।

(ब) केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - राज्यों को केन्द्रीय उत्पाद कर का 40 प्रतिशत तथा उत्पाद कर की कुल राशि का 5 प्रतिशत घाटे वाले राज्यों को देने का सुझाव दिया गया है। इस आयोग ने राज्यों को रेल यात्री भाडों में कुल 95 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया गया। अतः केन्द्रीय उत्पाद करों में राज्य सरकारों को 11785.64 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया गया।

(स) अनुदान (Grants-in Aid) इस आयोग ने राज्य व्यव में घाटे की पूर्ति के लिए 13 राज्यों को 984.06 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया। 1986-87 व 1987-88 के लिए देय मूलधन व व्याज की राशि को माफ करने का सुझाव दिया गया। राहत कर्यों की राशि 240.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 330 करोड़ कर दी गई। इस आयोग ने राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के लिए 551.55 करोड़ रुपए अनुदान देने का सुझाव दिया।

(द) राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) नव वित्त आयोग ने देश के सभी राज्यों को 13662 करोड़

रुपए स्थानान्तरित किए। इसमें से राजस्थान 651.3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यह राशि सभी राज्यों को हस्तांतरित होने वाली राशि का 4.77 प्रतिशत रही। इस राशि में से 143 करोड़ रुपए आयकर के हिस्से के रूप में, 326 करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क के भाग के रूप में, 32 करोड़ रुपए घाटे में चल रहे राज्यों को उत्पाद शुल्क की राशि में से दिए जाने वाले हिस्से के रूप में, 69 करोड़ रुपए बिबी कर के बदले में उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त राशि में से प्राप्त हुए। शेष राशि रेल यात्री किंगेये के निरस्त की गई राशि के बदले, राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु रहत व्यय की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

द्वितीय प्रतिवेदन, दिसम्बर, 1989 (Second Report, Dec 1989)

नवे वित्त आयोग ने 1990-95 के लिए द्वितीय प्रतिवेदन दिसम्बर, 1989 में प्रस्तुत किया।

(अ) आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) - इस प्रतिवेदन में भी आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत ही रखा गया किन्तु राज्यों के मध्य उनके वितरण का आधार परिवर्तित कर दिया गया। अब यह आधार निम्न प्रकार निर्धारित किया गया।

- 10 प्रतिशत 1985-86 से 1987-88 की अवधियों में आयकर निर्धारण द्वारा तय अग्रदान के आधार पर

11 25 प्रतिशत पिउडेफन क मिश्रित निर्देशांक के आधार पर

- 11 25 प्रतिशत राज्य की 1971 में जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय व प्रतिव्यय में गुणा करने के आधार पर

- 22 5 प्रतिशत - 1971 में राज्य की जनसंख्या की आधार पर

- 45 प्रतिशत - प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाले राज्य और राज्य विंग्रेप की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर की तुलना के आधार पर

(ब) केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) राज्यों में केन्द्रीय उत्पाद कर की शुद्ध प्राप्तियों का 45 प्रतिशत वितरित करने का सुझाव दिया गया। इस वितरण का निम्नलिखित आधार निश्चित किया गया

- 12 5 प्रतिशत आय समायोजित कुल जनसंख्या के आधार पर

- 12 57 प्रतिशत पिउडेफन क निर्देशांक के आधार पर

- 16 5 प्रतिशत घाटे वाले राज्यों के अन्तर्गत

- 25 0 प्रतिशत राज्य की 1971 की जनसंख्या के आधार पर

- 33 5 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय (1982-83 में 1984-85 तक प्रति व्यक्ति आय की नई श्रृंखला के आधार पर) एवं प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाले राज्य से उसके अन्तर को ज्ञात करके उससे राज्य की 1971 की जनसंख्या को गुणा करने के आधार पर।

(स) अनुदान (Grants in-Aid) आयोग ने मक्खान के अनु 275(1) के अन्तर्गत सहायता अनुदान की सिफारिश की है। भोपाल गैस रिसाव कांड के पीड़ितों को रहत पहुंचाने के लिए भी अनुदान देने की सिफारिश की है।

(द) राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) नवे वित्त आयोग ने राज्यों को 106036.4 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करने का सुझाव दिया। इसमें से राजस्थान सरकार को 6525.6 करोड़ देने की सिफारिश की गई। यह राशि राज्यों को हस्तांतरित होने वाली कुल राशि का 6.11 प्रतिशत है। नवे वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान को केन्द्र से प्रतिवर्ष लगभग 1300 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।

नवे वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा

EVALUATION OF RECOMMENDATIONS OF IX FINANCE COMMISSION

केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध पिछले दो दशकों से गहन विवाद के विषय रहे हैं। इस विवाद को सतोषजनक रूप में हल करने में सरकारिया आयोग भी विफल रहा है। वर्तमान दावे के अन्दर केन्द्र आर्थिक रूप से अत्यन्त शक्तिशाली है जबकि राज्यों के पास समाधान प्राप्त करने के साधन सीमित हैं। अतः केन्द्र पर उनकी निर्भरता अपरिहार्य है। वित्त आयोग इसी निर्भरता को परिभाषित करने का संवैधानिक प्रयास है लेकिन आयोग की भी अपनी सीमा है। वह अपनी इच्छानुसार सभी कर्तों से राज्य को हिस्सा नहीं दिला सकता। आयकर ही एक ऐसी मद है जो अनिवार्यतः राज्यों तथा केन्द्र में बांटी जा सकती है। भारत तेजी से विकसित कर रहा है परन्तु आयकर उभर उभरता नहीं बढ़ रहा है। विकास को हथकौड़ी या निग्रह उन्मुख विकास कह सकते हैं। कर्मियों की आमदनी में बेहतर वृद्धि हो रही है। अतः उनके शेरों तथा ऋण पत्रों में निवेशों की आस्था भी बढ़ रही है। परन्तु उनकी बढ़ती आमदनी में दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों के खजाने को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। वाष्ण, कर्मियों की आमदनी पर जो कर लगाया जाता है वह आयकर नहीं कहलाता,

“लिक कार्पोरेशन टैक्स, (निगम कर) कहलाता है और वित्त आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह निगम कर को भी राज्यों तथा केन्द्र के बीच बाँटे। केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय मन्त्रियों के सदर्भ में जब भी वित्त आयोग की चर्चा होती है तो मिथ्यान्त यह माना जाता है कि आयोग का मूल उद्देश्य राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा करना है लेकिन व्यवहारतः इसका ठीक उल्टा होता है। वित्त आयोग पहले केन्द्र के खर्चों में अनेक खर्च अनुत्पादक है लेकिन उन पर अकुश लगाने की मलाह वित्त आयोग नहीं दे सकता। दूसरी ओर वित्त आयोग राज्यों के खर्चों की प्रत्येक मद की गहरी छानबीन करता है। आयोग को यह शक्ति दी जानी चाहिए कि वह केन्द्र के खर्चों पर भी ऐसी ही निगाह रखे क्योंकि राज्यों को अधिक से अधिक वित्तीय मसाधन जुटाने के लिए केन्द्र के अनावश्यक खर्चों में कटौती आवश्यक है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने से वित्त आयोग की राज्यों के हितों की रक्षा करने वाले एक निकाय के रूप में विश्वसनीयता बढ़ जायेगी।

10 दसवा वित्त आयोग : जून, 1992 (Tenth Finance Commission June, 1992) - पूर्व रक्षा मंत्री के सी एत की अध्यक्षता में दसवें वित्त आयोग का गठन 15 जून, 1992 में किया गया। आयोग के अन्य चार सदस्य हैं - डॉ. देवीप्रसाद पाल, श्री पी. आर. विठ्ठल, डॉ. भी. रमणजन और एम. सी. गुप्ता। आयोग केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के बटवारे का निर्धारण करने और विभिन्न राज्यों के बीच राजस्व बटवारे के मापदण्ड तय करेगा। दसवा वित्त आयोग विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदानों के बारे में भी नीति निर्देश तय करेगा। आयोग अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के आवंटन समूहों में परिवर्तन को सुझाव दे सकता है। 1957 के रेल्वे यात्री भाड़ा कानून का रद्द किए जाने के एवज में राज्यों को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी यह सुझाव देगा। जिन राज्यों के बारे में अनुदान और आवंटन खसमसला के आधार पर तय किया जात है उनके मामले में 1971 की जनसंख्या का आधार माना जाएगा। वित्त आयोग प्राकृतिक आपदा निधि योजना में परिवर्तन और 31 मार्च 1994 को राज्यों के ऋणों के सदर्भ में निदान सुझा सकता है। अधिसूचना के मुताबिक राजस्व मन्त्री मिश्ररिशो करते हुए आयोग राजस्व प्रतिष्ठ और खर्चों के बीच समुलन पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जन तथा वित्त में कमी करने की आवश्यकता ध्यान में रखेगा। मिश्ररिशो का आधार यह भी होगा कि किसी राज्य ने अपना राजस्व बढ़ाने को कितनी कोशिश की है तथा निचाई ऊँची परिवहन एवं मरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक उपक्रमों में पूंजी निवेश व राजस्व अर्जन का क्या अनुपात है। अयोग बहुर विम प्रमथ अनवचयक मरकारि खर्चों में कटौती राजस्व बढ़ाने

के उपार्यों और बजट घाटे पर नियंत्रण के बारे में भी सुझाव देगा। दसवें वित्त आयोग ने सन् 1995 से 2000 तक के लिए अपना प्रतिवेदन 26 नवम्बर, 1994 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया था। इस प्रतिवेदन को 14 मार्च 1995 को मसद के दोनो सदनों में रखा गया।

दसवें वित्त आयोग की मुख्य बातें निम्न हैं -

- 1 राजकोषीय समुलन स्थापित करने के लिये पूंजीगत विनियोगों में वृद्धि तथा राजस्व खर्चों में समुलन स्थापित करना होगा।
- 2 उत्पादन शुल्क का 47.5% तथा आय कर का 77.5% भाग राज्यों में बाँटा जायेगा।
- 3 कर नीति को एकीकृत रूप में लागू करने के लिये समस्त केन्द्रीय करों का एक निश्चित अनुपात राज्यों में वितरित करना उचित होगा।
- 4 भविष्य में चालू परिसम्पदियों के रख रखाव व्यय को भी महत्व देना होगा।
- 5 पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के लिये अनुदान की व्यवस्था करनी होगी।
- 6 सर्वाजनिक उपक्रमों के अशों की विक्री से प्राप्त धन का उपयोग पुराने ऋणों का भुगतान करने में करना उचित होगा।
- 7 वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय का राजस्व साधनों में समायोजन करना होगा।
- 8 राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये अनुत्पादक व्ययों में कमी करनी होगी।
- 9 ग्रै योजना राजस्व व्यय के साथ-साथ योजना राजस्व व्यय पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा।
- 10 खाद्यान्नों एवं उर्वरकों के अनुदान की राशियों को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कम करना होगा। राज्यों को निर्यात समस्याओं के लिये अनुदान दिये जायेंगे।

राष्ट्रपति के अंगरक्षकन में श्री ए. एम. खुमरो की अध्यक्षता में 11 वा वित्त आयोग गठित कर दिया है। श्री टी. एन. श्रीवांगतव इसके सदस्य स्नचिव होंगे। वित्तमन्त्री यशवन्त सिन्हा ने आज लोकसभा में यह घोषणा कन हए वतदा कि आयोग के अन्य सदस्यों में सर्व श्री एन. सी. जैन, जे. सा. जे. नन्ना और डॉ. अनुरेश बाराधे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दसवें वित्त आयोग द्वारा नवम्बर 1994 में प्रस्तुत की गई मिश्ररिशो मार्च 2000 तक वैध है। ग्यारहवें वित्त आयोग को 31 दिसम्बर 1999 तक अपनी रिपोर्ट दे देने के लिए कहा गया है ताकि उसकी मिश्ररिशो पर मरकार के निर्णय को पहले ही अप्रैल 2000 में लागू किया जा सके। श्री सिन्हा

ने कहा कि सविधान के अनुच्छेद 280 के अनुरूप आयोग के विभागों विषयों में कन्द्रीय वगे की प्राप्ति को भी भागीदारी और राज्यो को अनुदान सहायता शामिल है विन आयोग को पहली बार सविधान के 73वे और 74 वे संशोधन के संदर्भों में राज्यो में पचासवाँ और नगरपालिकाओं के संसाधनों को अनुपूर्ति के लिए राज्य की सम्पत्ति निधि का बढाने हेतु आवश्यक उपायों को सुझाने का भी दायित्व सौंपा गया है। इसमें उल्लेख करने के लिए प्रस्ताव आपन करते मानसों के उत्पन्न का आवश्यकताओं और राज्य सरकार के कर्मचारियों के पैन सम्पादन अर्दि जैसे राज्यो के वित्त में मर्यादित अर्थिक सु-1 को चार करने व लिए आयोग को चला गया है।

प्रो खुमरो देश के जाने मान कृषि अर्थशास्त्री है और ग्रामीण भाग में विशेष रूप में परिचित है। व देश के स्थानाव निकाया का आर्थिक रूप में सुदृढ बनाने में विशेष योगदान दे सकते है। यहा इस तथ्य को उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सविधान के नवें खण्ड के प्रावधान पांच वर्ष से अस्तित्व में आये है और इन पांच वर्षों में लगभग सभी राज्यों में निर्वाचित स्थानिय निकाय बन गये है।

इस कारण पहले जहा नेवल 5000 रासद और निधावक सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते थे वहा अब निकायों के चुनावों के कारण जनप्रतिनिधियों की संख्या 30 लाख हो गई है जिनमें 10 लाख महिलाएं है।

योजना हस्तान्तरण (गाडगिल फार्मूले के आधार पर योजना आयोग द्वारा) PLAN TRANSFERS (BY PLANNING COMMISSION ON THE BASIS OF GADGIL FORMULA)

योजना हस्तान्तरण योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर तब तक उसको द्वारा निर्धारित परियोजनाओं के लिए होता है। योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले हस्तान्तरण का वर्तमान आधार गाडगिल फार्मूला है। आ इस स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

गाडगिल फार्मूला (Gadgil Formula) - केंद्र द्वारा राज्यों को दो जात वाले सहायता समूह पंचवर्षीय योजना तक योजना आयोग के नियंत्रण पर आधारित होती थी और इस निर्णय का वर्तमान आधार बना हुआ करता था। चौथी पंचवर्षीय योजना में केंद्राध्य महायन्त्र के अंतर्गत राज्यों का वितरित किए जाने वाले वित्तीय समर्थन का गाडगिल फार्मूले के माध्यम से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा

की गई। इस फार्मूले के अंतर्गत केंद्र के संसाधनों का 60 प्रतिशत राज्य की जासखता 10 प्रतिशत राज्य के पिछड़ेपन को स्थिति (जिसका ज्ञान राज्य की प्रति व्यक्ति आय में हो जाता है) 10 प्रतिशत राज्य के लोगों द्वारा दिए गए प्रति व्यक्ति कर, 10 प्रतिशत चालू सिचाई व विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और शेष 10 प्रतिशत राज्य की विभिन्न सामाजिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य का महत्व प्रदान की गई। इस फार्मूले में भी धीरे-धीरे अनेक दोष दृष्टिगोचर होने लगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि यह मूल संसाधनों के वितरण की बात ना करता है किन्तु उम्मा आधार के बारे में कुछ नहीं करता। इस सूत्र में दोष होने पर भी केंद्रीय सरकारों उपलब्ध करने का अभी भी यह महत्वपूर्ण आधार है। यद्यपि छठी योजना से केन्द्रीय सरकारों उद्योग बनने का नया आधार विनियमित किया गया। इसे अन्य समायोजित कुल जनसंख्या (Income Adjusted Total Population) सूत्र कहा गया। इसके अंतर्गत 10 प्रतिशत के स्थान पर राज्य के पिछड़ेपन के आधार पर 20 प्रतिशत सहायता दी गई। यह अतिरिक्त 10 प्रतिशत भाग विद्यमान सिचाई व विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए दती जाने वाली सहायता को बढ़ कर प्राप्त किया गया। फिर राज्यों को प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत में कम थी उन्हें 1000 वगेड रुपए मार्जिनल इकाई में स प्रतिरित करने का निर्णय किया गया। निष्कर्ष यह जाता सफता है कि राज्यों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए और विशेषतः राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों के विकास के लिए अधिक धन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1969 का मूल गाडगिल सूत्र (Original Gadgil Formula of 1969) योजना आयोग व वित्तीय उपाध्य प्रो बी आर गाडगिल के नाम में यह सूत्र प्रसिद्ध है यह सूत्र 1969 में लागू किया गया। इस सूत्र का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य समुत्पन्न तान का बाँटो जाना था। इस सूत्र के आधार पर योजना आयोग के निर्णय व कचवा योजनाओं में राज्यों को राशि का हस्तान्तरण किया था। मूल गाडगिल सूत्र के अंतर्गत राज्यों की 1971 में जनसंख्या को 60 प्रतिशत भार प्रदान किया गया प्रायः व्यक्ति आय चालू सिचाई व शक्ति परियोजनाओं पर प्रथम तथा विशेष समस्याओं के सभी आधारों को 10 10 प्रतिशत भार प्रदान किया गया।

1980 का संशोधित गाडगिल सूत्र (Revised Gadgil Formula of 1980) इस सूत्र को 1971 की जनगणना का ही आधार बना रखा गया और उम्मा भार भी 60 प्रतिशत का बना रखा। प्रायः व्यक्ति आय का मूल सूत्र के आधार पर अधिक भार प्रदान किया गया। इसमें

भार पूर्व के 10 प्रतिशत को अपक्षा 20 प्रतिशत कर दिया गया वर प्रथमा व विशेष समस्याओं का भाग 10 10 प्रतिशत पहले का ह्रा भात बने रहन दिया गया। चालू सिचाइ व शाक्त परियाजनाओं को संशोधन सूत्र में कोई भार प्रदान नही किया गया।

1990 का परिवर्तित गाडगिन सूत्र (Modified Gadgil Formula of 1990) इस सूत्र के अंतर्गत भा 1971 का जनगणना को ह्रा आधार बनाए रखा गया। इस आधार बनाए रखे जाने का प्रमुख कारण यह रह्य है कि जिन गन्ना में जनसंख्या तेजी में बढ़ रही है वे इसका अनुचित लाभ उठाया। यदि यह आधार बनाए रखा गया तो राज्यों का जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास करने का प्रोत्साहन प्राप्त होगा। परिवर्तित सूत्र अनुसार 1971 का जनसंख्या को पहले के 60 प्रतिशत का अपक्षा केवल 55 प्रतिशत भार प्रदान किया गया। प्रति व्यक्ति आय को 1980 के 20 प्रतिशत का अपक्षा 25 प्रतिशत भार प्रदान किया गया। इसमें कर प्रयास का कोई भार नहीं दिया गया। विशेष समस्याओं का भाग 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। 1990 में कर प्रथमा के स्थान पर राजकायाय प्रबंध का विचार लागू किया गया। इसमें अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाएगा कि राज्य विशेष में याजना आयात में स्वाकृत कराए गए सधन समूह के लब्ध का सटपट में वास्तव में कितना सधन समूह किया है। इस सूत्र में तृतीय क्षेत्रा विशेष पर्यवराय प्रश्नों वाढ व सूछा समावत क्षेत्रा विशेष रूप में कम या अधिक जनसंख्या घनत्व वाल क्षेत्रा मत्स्यलाय समस्याओं शाहुर की गदा बमिया व न्यूनतम वाछत यंत्रना आकर प्रान करने में अने वाला विशेष वित्ताय समस्याओं का आर ध्यान आकृत किया गया।

राजस्थान व गाडगिल सूत्र (Rajasthan & Gadgil Formula) भारत के राज्य को विशिष्ट व गैर विशिष्ट राज्य में बाकृत किया गया है। विशिष्ट श्रेण के राज्या में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश अरुम मणालय मणिपुर नागालैण्ड त्रिपुरा व मिाकम का यम्मिलन किया गया है। राजस्थान गैर विशिष्ट श्रेण के राज्या में से एक है। अतः राजस्थान का अन्य गैर विशिष्ट श्रेण के राज्या का भाति याजना हस्तान्तरण का गरी का 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 70 प्रतिशत रूप के रूप में प्राप्त होगा है। विशिष्ट श्रेण के राज्य में यह अंश क्रमशः 90 व 10 प्रतिशत है। 1990 के सूत्र में प्रति व्यक्ति आय को जा 25 प्रतिशत भार प्रदान किया गया है। उम्मे में 20 प्रतिशत गरी गरीय प्रति व्यक्ति आय व राज्य का प्रति व्यक्ति आय के अंतर (वचन विधि Deviation method) के आधार पर व 5 प्रतिशत राजा में मध्यम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्या में प्रति व्यक्ति आय के अंतर (दू विधि

D stance method) के आधार पर वितान होगा। गाडगिल सूत्र में यदि राज्य के क्षेत्रफल का भा उचित भार प्रदान किया जाता है तो राजस्थान लाभ का स्थिति में रहेगा।

(ब) राज्य के स्वयं के स्रोत अथवा राजस्थान का योजना ससाधनों में भाग State's Own Resources or Rajasthan's contribution in Plan Resources

राज्य को तज्ज में विकास करने के लिए स्वयं के वित्तीय माधन का विकास करना हाता है। राज्य के वित्ताय समाधन का अनर्गत वजन में वचन व सार्वजनिक उपक्रम द्वारा वधन प्रमुख है। बजट में वचन की दृष्टि से दो बात महत्वपूर्ण है। प्रथम विद्यमान राजस्व का शेष कितना है? राज्य सरकार के कर व अ-कर राजस्व तथा सरकार के गैर याजना राजस्व व्यय का अंतर विद्यमान राजस्व का शेष हाता है। द्वितीय वजन उपाया से अतिरिक्त समाधन का निमाग भा महत्वपूर्ण है। नये वजन उपाया से अनर्गत नये कर लगाना विद्यमान करों में शुद्धि करना प्रमुख है। अतिरिक्त समाधन जुगान में राज्य विद्यत मंडल राज्य परिवहन निगम आदि वड निगमा का भागित गगटन है। य निगम विद्यमान दरों या क्रियाय आद में हा। र समाधन जुटाते है। इसका विशेष महत्व है। ये विगम समाधन न्दाम के लिए अपना दरा या क्रियाय आद में शुद्धि कर सकते है।

पूजा वचता को भा मवजानक ह्रा भविष्य निधिया में अशदा ला वचा और अन्य शुद्ध पूजागत प्रनिय के मध्यम में फिर जात है। नय उपाय अपनकर इन राशय में भा का व सकता है।

राज्य सरकार में राजस्व मुद्रा एवं पूजायन शुतक राज्य अन्तरका वचनकर वहां पर कर समन और पात्रदा पर कर निरुध पर कर और शुल्क आकृत रूप में व राजस्व प्राप्त करता है। इनमें दिवा कर एक महत्वपूर्ण भाग है। राजस्व राजा हाता है कि राज्य सरकार को राजस्व का भा एक भाग है और वह समान लाभ आता है। अतः विभिन्न करों का वचन अन्ध अन्धता से कर के लिए निव्याय न्दाम अवश्यक है। इस हेतु प्रशासन का शुद्ध करना भा मवजानक क्षेत्र का अथवा उलटन धमा वचनकर एवं राजा का वचन कर के अधिक यन्त्रण देना हाता। दाम कमता के मदर्थ में वचन धाग सत्ते वचन के स्थान पर अपन उपादा व मवजानक का मुद्रा वचन ला। राज्य सरकार का प्रशासनिक व्यय का निधि कना हाता। मवजानक का अतिरिक्त अन्धक दाम अर्थिक घन सन्निव करने हाता। राजा का समन पर पुग वचन हाता कि उपादा लाता वचन

राज्य सरकार का मात्र निधि विकास के लिए

अधिर विभिन्न समामन नुटपा आवरण है। इस सदर्थ म राज्य सरकार का कर गहरा निगनर बढ रहा है। रात्र सरकार ने अल्प बरत व मध्यम स भी अधिक मे अधिक धनराशि एकत्रित करन का प्रयाम किया है। राज्य सरकार ने अत्र बरत योजना 100 रुपए की राशि विनियोजन पर एक नि शुल्क उपहार कून नाटरी द्वारा डा नूनो पर पुनर्भार दिए है। इस योजना से जनता की भयता के आर्षित किया जा सका और गहरा हो आय म मुक्ति हुई बना माना कम करने का दूरगम मरुचपूर्ण उपहार ज्यो म कटौती किया जाना है। राजस्थान सरकार ने रात्र व कपुनगी पर हेतु एक डा म ति का गटा भी किया है। समिति उन शत्रों का निर्धारण करती जा मित राशिया मभर जा। य मिर्जागिता इस प्रकार जाना होगा कि राज्य क विकास म चाई राधा उत्पन्न न हा। राज्य के विनाय साधना के बढान के लिए रात्र पैक व अन्य मस्थाना मे अतिरिक्त म्हायता प्राप्न वग्न को चट्टा की

जा रही है। कई परियोजनाय केन्द्र सरकार के माध्यम मे मिनि सस्थाओं को भजी गई है। नयी प्रसार अधिक साधन प्राप्न वग्न के लिए कुछ परियोजनाए केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है। इन मत्र प्रयासों म हमरा गता है कि राज्य व आगामी रात्र विकास की गति हो और तीव्र कर पाएगा।

परिवर्तित आय-व्ययक 1998 99

MODIFIED BUDGET 1998 99

राजस्थान व उपमुख्यमंत्रि हरिश्चर भाभडा म 9 जुलाई 1998 म विधानसभा म राजस्थान का 1998 99 का मशाधिया य परिवर्तित रात्र प्रस्तुत किया। इस रात्र की प्रमुख गां 3 प्राधान निम्न प्रकार हैं

(A) राजस्थान आय व्ययक 1998 99

स रा म राजस्थान का रात्र निम्न प्रकार है

राजस्थान आय व्ययक का सहावलोकन

विवरण	लेखे 1994 95	लेखे 1995 96	लेखे 1996 97	समाधित अनुमान 1997 98	आय व्ययक अनुमान 1998 99
1	2	3	4	5	6
(अ) राजस्व लेखे की प्राप्तिरा एवं खय					
(i) राजस्व प्राप्तिरा	632172 57	762968 94	755972 16	871379 26	1018046 87
(ii) राजस्व खय	674647 91	833155 62	842567 02	920972 44	1152156 28
() वरत () अपरा प्राप्ति ()	() 42475 34	() 70186 68	() 86594 86	() 49593 18	() 133209 41
(ब) राजस्व खय के अतिरिक्त सनदेन					
1 प्राप्तिरा					
() स्वायत्त कण	31427 09	39427 00	43369 11	52218 00	64902 00
() अन्तरात्मीन कण	134300 54	247890 23	465781 22	333593 00	120000 00
() केन्द्रिय सरकार म विना गवा कण	88746 81	114022 31	148988 12	202358 40	186691 95
(iv) अन्य कण	5927 07	8866 60	11365 95	17149 79	17535 85
(v) गार्वनिक नुजा	1394214 04	1617996 18	1563249 62	1976510 50	2081761 62
(vi) कण एवं अभिम	12843 97	40212 84	31513 15	87477 42	7403 12
(v) आरम्भिता निधि					
2 विवरण					
() पुनर्गत खय(शुद्ध)	106065 05	175746 60	165788 21	260134 99	212480 35
(i) स्वायत्त कण	12 56	9 80		4511 51	11383 66
(ii) अन्तरात्मीन कण	134300 54	232414 18	431386 82	333593 00	120000 00
(v) केन्द्रिय सरकार म विना गवा कण	19326 40	28408 10	56358 84	69713 85	31671 40
(vi) अन्य कण	1506 13	1738 93	1929 14	3213 91	4276 79
(v) गार्वनिक नुजा	1317590 55	1428496 65	1486000 01	1065044 01	19024 3 18
(vi) कण एवं अभिम	40576 81	51707 83	29777 47	35470 55	35993 60
(v) आरम्भिता निधि निनिधाय					
(x) आरम्भिता निधि		15 97			
कुल विवरण	1619378 04	2018516 46	2165333 50	2571681 87	2322264 87
3 राजस्व खय व अतिरिक्त वरत (+)					
अपरा प्राप्ति ()	48091 48	45898 70	98733 67	97634 8	150020 86
4 गार्वनिक शुद्ध	5000 14	20287 88	12138 81	4004 20	22820 15

(B) विभिन्न क्षेत्रों हेतु प्रावधान (Provisions in Different Sectors)

1998-99 के इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के मसूदा में प्रमुख दावे व प्रावधान निम्न हैं -

1 शिक्षा (Education) - इसी वर्ष प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिककरण हेतु भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत में आरम्भ किया जा रहा है। 5 वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में लगभग 35 में 40 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 1998-99 में 11 नवीन जिलों में उच्च माधुरता कार्यक्रम व एक जिले में मूल शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ होगा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोटा व दोहानेर में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में दो नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। करोली नाथद्वारा व जैसलमेर में महाविद्यालय आरम्भ किये जायेंगे। तकनीकी शिक्षा के विस्तार का दृष्टिकोण रखते हुए बीकानेर में एक अभियंत्रिकी महाविद्यालय आरम्भ करने का निश्चय किया गया। अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण मस्थान (ITI) भी खोलने का विचार व्यक्त किया गया है।

2 कृषि (Agriculture) - 750 कृषि उत्पादन वितरण कन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है ताकि किसान का अपनी उपज बेचने के लिये अधिक दूर न जाना पड़े। कमजोर मण्डियों के विकास हेतु 'मण्डी विकास निधि' का गठन होगा। दस जह्रा हैक्टयर समस्या ग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन हेतु क्रमशः 120 व 35 लाख टन का लक्ष्य रखा गया।

3 पशुपालन (Animal Husbandry) इस वर्ष पशुपालन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। नये पशु चिकित्सा कन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। कम में कम 2 डायरी संघों को 150 9002 के अन्तर्गत पञ्जीकृत करने का प्रस्ताव है।

4 सहकारिता (Co-operation) जयपुर शहर की दूरस्थ कालोनियों में डेपरी वृक्ष व्यवस्था को भाति सहकारी फल व सब्जों वितरण व्यवस्था आरम्भ की जा रही है।

■ विद्युत (Electricity) 550 गांवों के विद्युतीकरण व 25 हजार कुओं के ऊर्जाकरण का प्रस्ताव है।

■ सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण (Irrigation & Flood Control) इस वर्ष 21200 हैक्टयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित करने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 50 हजार हैक्टयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जायेगी। पानी के उच्च उपयोग और नहरों के रखरखाव हेतु किसानों की जन-सहभागिता

प्रबन्ध हेतु 194 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
7 सहायता - केन्द्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा राहत कोष से केवल लघु एवं मध्यम किसानों का राहत देने का प्रावधान था। सरकार ने इसे संशोधित कर सभी प्रभावित किसानों को सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

8 सड़क निर्माण (Road Construction) 1998-99 में 257 करोड़ रुपए के प्रावधान में 3400 किमी नवीन सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इनके निर्माण में 1050 गांव सड़कों में जुड़ जायेंगे। कृषक को सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का शाध भुगतान किया जायेगा।

9 विशिष्ट योजनाएँ व ग्रामीण विकास (Special schemes & Rural Development) ग्राम स्वराज की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विशिष्ट योजनाओं हेतु राज्य सरकार ने जन सामान्य को विकास कार्यों में व्यय के निर्देशन का अधिकार दिया है।

10 आवास (Housing) - इस वर्ष एक लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के भूमिहीन परिवारों व ग्रामीण कारीगरों व दलितों की आवास समस्या के हल हेतु 11 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है।

11 वन (Forest) - इस वर्ष 63500 हैक्टयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। मन्सूर के विस्तार की ऐक्यता हेतु एक नवीन परियोजना आरम्भ करने हेतु 11 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

12 पेयजल (Drinking water) - पश्चिमी राजस्थान के 24 ब्लॉकों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना इस वर्ष की गई है। भूतल स्तर पर विमाऊ रूपा तथा चुरू जिलों के 168 छात्र पन्ना में निवास करने वाले पयजल उपलब्ध करने हेतु व्यय का प्रावधान किया गया है।

13 चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा परिवार कल्याण (Medical & Health Services and family welfare) - मौसमी बीमारियों व शारीरिक अपातों को लिय विशेष प्रावधान किया गया है। कोटा शहर में एक 'सेटेलाइट अस्पताल' सहित राज्य में 10 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 67 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है। कटोरा दल-डूडन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अम्भता निवारण के प्रयास किये जायेंगे। इस वर्ष प्रजनन व बाल स्वास्थ्य परियोजना के नाम में परिवार कल्याण व बाल स्वास्थ्य की एक योजना 18 जिलों में आरम्भ करने का निश्चय किया गया है।

14 महिला एवं बाल विकास (Women & child Development) - किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य, सफाई, पोषण और व्यक्ति विकास का योजना 'ताइली' का राज्य के

भी जिलों में विस्तार किया जायेगा। सरकार ने सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहित करनेके उद्देश्य में दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान प्राप्त करने हेतु 25 जोड़ों की सीमा को घटाकर 10 जोड़े कर दिया है।

15 जनजाति क्षेत्रीय विकास (Tribal Area Development) इन क्षेत्रों में स्थानीय आशार्थियों को अधिक शक्तिनिधित्व व राजस्व देने के उद्देश्य से सभी विभागों के 1 से 6 तक की वतन श्रृंखला के पट्टा तथा ग्राम सेवकों के पट्टा में आरक्षण बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है।

16 उद्योग (Industry) राज्य में निर्यात की दीर्घकालीन वृद्धि के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्यागत वित्त के माध्यम से 35 करोड़ रुपये लागत के कन्टेनरों के शीप परिवहन हेतु गेड रेल परियोजना आरम्भ करने का लक्ष्य है। भिवाड़ी में निर्माण मसूदा में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माहला उद्यमियों को शांति कृष्ण सुविधा उपलब्ध कराने व परियोजना मंजूरी देने हेतु राजस्थान वित्त निगम में महिला उद्यम निधि प्रकाश की स्थापना की गई है। महिलाओं के गृह उद्योग योजना का प्रारम्भ की गई है।

17 खनिज (Minerals) राज्य में प्राकृतिक गैस एवं तेल का खोज का प्रगति दन हेतु एक कृषक पेट्रोलियम निदेशालय का स्थापना की गई है। 'दक्कन नागौर' और 'गुरु जिला' में खोज का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जलविद्युत में एन सायोर क्षेत्र में यह कार्य पूर्व में ही चल रहा है।

18 पर्यटन (Tourism) पर्यटन उद्योग व विकास हेतु इस वर्ष में नई पर्यटन गाँवों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

19 नगरीय विकास (Urban Development) 1998-99 में राज्य का आठ शहरों का चिन्ति कर इनक

निर्वाजित वित्तों के प्रयास हेतु।

20 चुंगी (Octroi) राज्य में 1 अगस्त 1998 से प्रदर्श में चुंगी समाप्त करने की घोषणा की है।

21 786 वाउर्स (Urs 786) उर्स के सुचारु आयोजन हेतु सरकार ने विभिन्न वर्गों हेतु 16 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं।

22 राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) प्राथमिक जनता की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु 20 अगस्त से 20 सितम्बर 1998 की अवधि में अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। राज्य में विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोग हुआ। इस संदर्भ में दीर्घकालीन से पूर्व मरल भूमि रूपान्तरण नियम बनाये जायेंगे।

23 कानून व्यवस्था (Law & Order) पुलिस बल को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने एवं पुलिस स्टेशनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने आवास एवं नगर विकास लिमिटेड के सहयोग में 600 करोड़ रुपये की परियोजना बनाया है जिसका प्रथम चरण इसी वर्ष आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

24 अन्य (Other) सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमास कर दिया है। बोध प्रशासन के विकेंद्रीकरण व आधुनिकीकरण के प्रयास किये गये हैं। कर्मचारी पल्याण के अनेक कदम उठाये गये हैं और वित्त विभागों के प्रकल्पों के संबंध में राज्य सरकार एक आयोग के गठन का निर्णय रखी है।

(C) कर प्रस्ताव (Tax Proposals)

निम्न तालिका में बजट 1998-99 का स्पष्ट विवरण दिया गया है।

क्र.सं.	वस्तु	विवरण
1	2	3
I — कृषि		
1	राज्य के सभी क्षेत्रों में शांति कृष्ण सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत
2	10 अग्रजों के लिए शांति कृष्ण सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत
3	कृषि	4 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत
4	कृषि	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत
II — उद्योग		
1	राज्य के सभी क्षेत्रों में शांति कृष्ण सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत
2	10 अग्रजों के लिए शांति कृष्ण सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत
3	कृषि	4 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत
4	कृषि	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत
5	कृषि	4 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत
6	कृषि	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत
7	कृषि	4 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत

1	2	3
II नूतन धारा को नई इकाई को कर मुक्त कक्षों को करने की सुविधा	यूना लिक्वा सीमा 50 करोड़ से घटकर दस करोड़ पाया है। अक्टूबर 1991 एक वर्ष बढकर 31 मार्च 1999 को बढ़े	
9 नई शत प्रतिशत निर्माण शुल्क गारंटी को कल्पित करने का मुक्त	लाभ हनु उलाहने की विधि 31 मार्च 1999 को गई	
10 एल.सि.न. सीमा	4 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत	
11 एल.सि.न. सीमा	12 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत	
12 कर प्रदान गारंटी से निर्मित गारंटी रिफंड का	कर मुक्त	
13 औद्योगिक गैस	रियायत कर दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)	
14 बॉन्डिंग इलक्वेन्ट व राइट	8 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)	
15 एच.डी.पी.ई. फंडिंग	विराही कर दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)	
16 स्पेसिफिक सीमा शीट व पट्टा को इकाई	कर मुक्त बन्ना मात्र अन्य धन का सुविधा 31 मार्च 2000 तक बढ़ाई गई	
17 बॉन्ड निर्माण हनु स्पेसिफिक सीमा शीट का सीमा शीट के रूप में खरीद	रियायती कर दर 1 प्रतिशत 31 मार्च 2000 तक बढ़ाई गई	
18 एल.सि.न. सीमा	अन्यथाक विधि कर की 1 प्रतिशत की दर 31 मार्च 1999 तक	
III — व्यापार	4 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत	
1 सभा प्रकर के विवरित	6 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)	
2 सभा प्रदान व एल.सि.न.	12 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)	
3 नई या लाइसेंस व एल.सि.न.	8 जुलाई 1998 तक कर मुक्त	
4 लि.सि.न. सीमा शीट सभा प्रदान अदि	अथ 12 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत कर दर	
5 पुनर्निर्माण	रियायती कर दर 12 प्रतिशत (31 मार्च 1999)	
IV — जनसामान्य	अन्यथाक विधि कर की 1 प्रतिशत की दर 31 मार्च 1999 तक	
1 नई सभा प्रदान व एल.सि.न.	12 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत	
2 चक्र का पैदा	12 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत	
3 सेंट इलाखी लौह टाट काई इकाई तथा औद्योगिक के काम आने का	12 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)	
4 निर्माण सीमा शीट सभा प्रदान अदि	6 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)	
5 सभा प्रदान व एल.सि.न.	रियायती कर दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)	
6 सभा प्रदान व एल.सि.न.	12 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत	
7 नई एस.आई. मकान की प्रकर के बंधन सीमा	कर मुक्त	
8 नई एस.आई. मकान की प्रकर के बंधन सीमा	10 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत	
9 सभा प्रदान व एल.सि.न.	4 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत	
10 सभा प्रदान व एल.सि.न.	कर मुक्त (31 मार्च 1999 तक)	
11 सभा प्रदान व एल.सि.न.	कर मुक्त	
12 सभा प्रदान व एल.सि.न.	अन्यथाक विधि कर की 1 प्रतिशत की दर 31 मार्च 1999 तक	
13 सभा प्रदान व एल.सि.न.	12 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत	
V — जनस्वास्थ्य		
1 अद्युक्त सभा प्रदान व एल.सि.न.	8 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)	
2 सभा प्रदान व एल.सि.न.	कर मुक्त	
3 सभा प्रदान व एल.सि.न.	12 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत	
4 सभा प्रदान व एल.सि.न.	कर मुक्त	
5 सभा प्रदान व एल.सि.न.	कर मुक्त	
VI — कर में बदोतरी	यदी हुई दो	
1 सभा प्रदान व एल.सि.न.	12 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत	
2 सभा प्रदान व एल.सि.न.	16 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत	
3 सभा प्रदान व एल.सि.न.	4 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत	
4 सभा प्रदान व एल.सि.न.	4 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत	
5 सभा प्रदान व एल.सि.न.	36 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत	
6 सभा प्रदान व एल.सि.न.	36 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत	

(D) समग्र वजटीय स्थिति (Overall Budgetary Position)

गज्य वजट की राशि किन स्रोतों में प्राप्त होगी इसका अनुमान निम्न तालिका - 1 से होता है -

तालिका - 1

मद	प्रतिशत राशि
आन्तरिक उधार व शुद्ध सार्वजनिक ऋण	24
कन्द्रीय कर्जों में निम्ना	17
वित्तिका	14
केन्द्रीय ऋण	12
सहायता अनुदान	10
कर भिन्न राजस्व	9
राज्य आवकारी शुल्क	7
बाल्ना पर कर	3
अन्य कर	4
कुल योग	100
स्रोत राजस्थान प्रविका	

राज्य वजट की राशि किन मदों पर व्यय होगी इसका अनुमान निम्न तालिका - 2 से होता है

तालिका - 2

मद	प्रतिशत राशि
आयोजना भिन्न व्यय (ऋण लाक कर्जों)	50
आर काज क अतिरिक्त)	18
आयोजना व्यय	14
व्यय नुदान	13
आन्तरिक व कन्द्रीय ऋण	5
कन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ	
कुल योग	100
स्रोत राजस्थान प्रविका	

बजट की समीक्षा

APPRAISAL OF BUDGET

चुगी हटाने की घोषणा एक माहसिक कदम है। व्यापारी वर्ग और जनता को इससे राहत मिलेगी। चुगी हटाने से जो राजस्व हानि होगी उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा इस बात के निर्णय के पश्चात ही वस्तविक प्रभावों की समीक्षा संभव है। बजट के किये गये प्रावधानों से राज्य में नियात की संभावनाएँ बढ़ेंगी। महिला उद्यमियों को भी राहत मिलेगी। प्राकृतिक गैस तेल की खोज के दूरगामी परिणाम संभव है। यदि खोज सफल होती है तो गजस्थान आर्थिक दृष्टि में सक्षम हो सकेगा। शक्ति के साधनों का नया स्रोत भी उपलब्ध होगा। नई पर्यटन नीति की घोषणा का प्रस्ताव सराहनीय है लेकिन इस नीति का मूल्यांकन इसकी घोषणा के पश्चात ही संभव है। नगरीय क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके विकास का प्रयास करना सराहनीय कदम है। राजस्व नियमों में ढीलमोजनता को राहत मिलेगी। मण्डी विकास निधि का गठन किसानों को राहत देने वाला सिद्ध होगा। डेयरी मयशों के आधुनिकीकरण में डेयरी उत्पादों के निर्यात की संभवना बढ़ेगी। सड़क निर्माण व कुओं के विद्युतीकरण की योजना में ग्रामीण क्षेत्र को राहत मिलेगी। एक लाख आवासीय इकाइयों को निर्माण लक्ष्य कमजोर वर्ग के लिये लाभदायी होगा। वन विकास व पेयजल सुविधा का विस्तार सराहनीय प्रयास है। प्रजनन व बाल स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ एक अच्छा कदम है।

जिला शैक्षिक शिक्षा कार्य का आरंभ और उत्तर माहसुरत व सतत शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार समय की आवश्यकता थी अतः सराहनीय है। बजट के प्रावधानों में बजट को विकाससन्मुखी कहा जा सकता है। लेकिन बजट अवधि की समाप्ति तक इन प्रावधानों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है। इसी पर बजट की सफलता व असफलता निर्भर करेगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- राजस्थान में कुल व्यय में से विकास व्यय का प्रतिशत क्या है?
What is the percentage of development expenditure to total expenditure in Rajasthan?
- यह कहा जाता है कि नव वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र में पिछले आयोग की तुलना में दृष्टिकोण का परिवर्तन विद्यमान है। स्पष्ट कीजिए।
It is said that the terms of reference given to the Ninth Finance Commission involve some changes in approach compared to those of the previous Commissions. Explain.
- कन्द तथा राज्य सरकारों के परस्पर वित्तीय संबंधों के बारे में संवैधानिक व्यवस्थाएँ क्या हैं? इस संबंध में दाने किन आयोग का क्या सिफारिशें हैं?
What are the constitutional provisions for financial relations between the Central and State Governments? What are the recommendations of the Tenth Finance Commission in this respect?
- बजट से आप क्या समझते हैं?

What do you mean by Budget.

- राजस्थान के वर्तमान बजट की नवीन प्रवृत्तियों का उन्मुख बर्णन।
Explain the recent trends of present Budget of Rajasthan
- ग्यारहवीं वित्त आयोग का गठन कब व किस उद्देश्य से किया गया है?
Why & when the Eleventh Finance Commission was constituted?

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान की राज्य-आय के प्रमुख स्रोतों का विवेकान बर्णन। राज्य व केंद्रों की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का है।
Discuss the various sources of revenue receipt in Rajasthan. Analyse the two major taxes of Rajasthan
- राजस्थान की राजस्व स्थिति का हिस्सा कैसे निर्धारित होता है? नव वित्त आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में विचार करें।
How the Share of Rajasthan in plan resources is finalized? Explain it in the context of 9th Finance Commission
- राज्य और केंद्रों के बीच संपत्ति का वितरण कैसे होता है? समझाएं।
How resources are distributed between centre and state? Explain
- वित्त आयोग की मुख्य कार्य क्या है? यह राज्य को हस्तांतरण किन आधार पर करता है?
What are the main functions of Finance Commission? How resources are transferred to the State?
- राजस्थान में बजटगत प्रवृत्तियाँ बताईए। तथा राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के सुझाव दें।
Mention the budgetary trends in Rajasthan and also suggest the measures for the improvement in the financial conditions of the state
- राज्य के राजस्व व्यय की प्रमुख मदें बताईए। किन मदों पर सरकारी व्यय अधिक है?
Mention the main heads of revenue expenditure in Rajasthan. On what items state government spends the most?
- राज्य राजस्व व व्यय का वित्त बजट-आधारित केंद्रीय सहायता का वितरण की व्याख्या करें। इस राजस्थान का पक्ष में क्या करके लाभ प्राप्त कर सकता है।
Discuss the distribution of formula-based central assistance for state plans. Suggest modifications to any to make it favourable to Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

- राजस्थान राज्य के बजट का कुछ प्रवृत्तियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "State Budgetary Trends in Rajasthan"
- राजस्थान के बजट में राजस्व आय एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। तथा राजस्व व्यय को दूर करने के लिए सुझाव दें।
Analyse the trend of revenue receipts and revenue expenditure in the Budget of Rajasthan and also suggest the measures to bridge the revenue deficit.
- राज्य योजना के वित्त व्यवस्था कैसे होता है? वित्त आयोग का इसमें क्या भूमिका है?
How the state plan finance resources are decided? Explain the role of Finance commission in this field
- गैडगल सूत्र क्या है? राजस्थान का इस सूत्र से प्राप्त राजस्व हस्तांतरण की दृष्टि से क्या लाभ मिले है? क्या अप्रैल 1990 का संशोधित गैडगल सूत्र राज्य को हित की अवधारणा करता है? इस संबंध में अपने सुझाव दें।
What is Gadgil formula? What gains have been derived by this formula through plan transfer to the state of Rajasthan till today? Does the modified form of Gadgil Formula of Oct. 1990 ignores the state interests? Comment on it.
- वित्त वित्त आयोगों ने राजस्थान को कितने व शुद्ध लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राजस्व हस्तांतरण का है। उनमें मुख्य व नाग्य का उल्लेख करें। क्या इनमें से निम्न बूझा जा सकता है? निम्न बर्णन करें।
Show the nature and quantum of the amount transferred to Rajasthan in the form of taxes, fees and grants-in-aid by the different finance commissions. Is it increasing regularly? Analyse
- राज्य योजना द्वारा राज्य को वित्त सहायता किन सिद्धान्तों पर आधारित है।
On what basis the financial aid is made available to states by planning Commission?
- निम्नलिखित लिखिए (i) राजस्थान का प्रमुख कर (ii) राज्य के व्यय का प्रमुख मद
(iii) राज्य के राजस्व में राज्य व्यय (iv) राज्य के राजस्व में राज्य व्यय
Write short notes on (i) Main Taxes of Rajasthan (ii) Main items of expenditure of Rajasthan Govt.
(iii) Revenue deficit in state budget (iv) Overall budget deficit in state budget

अध्याय - 24

राजस्थान में पंचायती राज

PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

पंचायती राज से समा में लोग का भागीदार बन है *

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान पंचायत राज आन्दोलन 1994 का विचार-ए आर का प्रवर्धन
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पंचायत राज का वर्तमान स्थिति

“राजस्थान में पंचायती राज का स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाया और उनका ऐसा शक्ति और अधिकार प्रदान किया जो उनका स्वयं शासन का स्वरूप के रूप में कार्य करने में सक्षम बनने के लिए आवश्यक है। भारत के संवधान का धारा 40 में राज्य प्रति निर्देशक मन्त्र में पंचायती राज का इसा धारणा के अनुसार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगौर जिले में प्रथम पंचायती राज के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रवर्धन पंचायती राज का कार्यक्रम किया वर्ष 1960 में पंचायती के प्रथम चुनाव हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायती अधिनियम के जिला परिषद अधिनियम 1959 तथा 73 व संवधान संशोधन के प्रावधानों का ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानमंडल ने नए पंचायती राज अधिनियम 1994 का निर्माण किया जो पंचायती राज के अनुदान के पत्रों पर 23 अप्रैल 1994 को संसदीय कार्य में लाया गया।

वित्तिय सहायता एवं प्रशासनिक सहायता के कारण पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का क्रियान्वयन हो सका है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज के लिए अनुदान राशि निर्धारित की गई है।

1996 जाय किया गये है। ये नियम 30 दिसम्बर, 1996 में सम्पूर्ण राज्य में विधिवत लागू कर दिये गये। नये नियम व अनुसार आवश्यक व्ययों की गई। वर्ष 1997 को जन अभियोजन निष्करण वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसरण में जिलाधीश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं। राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजना समितियों का गठन किया जा चुका है जो जिले में नव निर्माण कार्य विभागों में मयन्वय ग्रामीण स्वास्थ्य विकास, पर्यावरण व्यवस्था एवं उपलब्ध संसाधनों का सुचित उपयोग कर विभागों का कार्य मंचालित करेंगी।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की विशेषतायें अथवा प्रावधान CHARACTERISTICS OR PROVISIONS OF PANCHAYAT RAJ ACT 1994 IN RAJASTHAN

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की विशेषतायें अथवा प्रावधान निम्न हैं -

(1) **क्रिस्तीय पद्धति** - राज्य में पूर्व की भूमि पंचायती राज की क्रिस्तीय पद्धति कायम रहेगी - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत वॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषदें रहेंगी। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों की भूमि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी प्रत्येक पांच वर्ष में होगी।

(2) **महिलाओं की सहभागिता** - राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में साक्षरता के कम प्रतिशतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरपंच के पद के लिये साक्षरता देने की जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की हुई थी उससे निम्नतर कर दिया है, जिससे कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति या स्त्री चाहे वे निम्नतर हों, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ सकें।

(3) **ग्राम सभा** - पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार सरपंच/उप सरपंच को वर्ष में दो बार ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से बुलानी होगी। ग्राम सभा की पहली बार सैद्धांतिक दर्जा दिया गया है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अर्थात् से जून और वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही जनवरी में मार्च के लिए यदि ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई तो सरपंच का पद स्वतः ही रिक्त घोषित माना जाएगा। ग्राम सभा में 1/10 मतदाता उपस्थिति होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक में आवश्यक व्यय का लेखा,

बजट, आगामी वर्ष में प्रस्तावित विकास कार्य ऑडिट एतराज एवं उनके उत्तर तथा गांव की अन्य सार्वजनिक समस्याओं पर विचार विमर्श होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन भी ग्राम सभा द्वारा ही किया जायेगा। ग्राम सभा के द्वारा विचार - विमर्श एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं की क्रियान्विति होगी। बजट के अनुसार व्यय किये जाने का प्रावधान है। यदि बजट अथवा योजना में किसी प्रकार सुशोधन आवश्यक है तो दूसरे ग्राम सभा की बैठक में उसको पारित करना होगा। विकास अधिकारी या उसके द्वारा नामांकित प्रसार अधिकारी ग्रामसभा की बैठक में भाग लेंगे और उसकी सहाय्य कार्यवाही बैठक रजिस्टर में अंकित कर जिम्मेदार होंगे।

(4) **उम्मीदवारों की आयु** - नये अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाला कोई भी पुरुष या महिला पंचायत चुनावों में किसी पद के लिए उम्मीदवार बन सकता/सकती है। जबकि पूर्व में आयु की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष थी।

(5) **सतर्कता समिति** - पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा सतर्कता समिति का गठन करेगी, जिसमें ऐसे चुने हुए व्यक्ति होंगे जिनमें जनता का विश्वास हो। उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि ग्राम सभा के निर्देशों के अनुसार देखें कि ग्राम पंचायत योजनाओं की एवं नये कार्यक्रमों की क्रियान्विति ठीक प्रकार के करती है अथवा नहीं। इसकी समीक्षा रिपोर्ट अग्रणी ग्राम सभा के सन्तुष्ट पेश की जायेगी। इस प्रकार सतर्कता समितियाँ ग्राम पंचायत के कार्यों पर ग्राम सभा के माध्यम से नियंत्रण रख सकेंगी।

(6) **पंचायत चुनाव** - लोकसभा एवं विधानसभा की तरह धारा 17 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद के भी चुनाव हुआ करेंगे। जिस प्रकार लोकसभा एवं विधान सभा के चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग है इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के भी हर 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग स्थापित होगा। इस संदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का श्री अमरगिरि राठौड़ की अध्यक्षता में गठन किया है। तदनुसार आयोग ने अपना कार्य मुबालू रूप से शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग को यह जिम्मेदारी होगी कि 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दे ताकि निर्धारित समय पर नई

पचायती राज संस्थाएँ गठित हो सकें। यदि किसी कारणवश पचायत भंग हो तो अधिकतम ३ माह की अवधि में नई पचायत आवश्यक रूप से चुनाव धारा 17(3) के अनुसार गठित करनी होगी।

(7) **प्रत्यक्ष चुनाव** - राज्य में अब तक केवल पंच और सरपंचों के ही सीधे चुनाव होते थे। लेकिन पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 एवं 14 के अनुसार पचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य भी विधायक की तरह सीधे मतदाताओं के द्वारा चुने जायेंगे। नई व्यवस्था में पचायती राज के प्रत्येक जन प्रतिनिधि को सीधे रूप से जनता से निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। ग्राम पचायत के सरपंच और पंच का चुनाव पूर्व की भांति सीधी मतदान प्रणाली से होगा। पचायत समितियों के सदस्यों का चुनाव भी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा तथा पचायत समिति के लिए सीधे रूप से निर्वाचित सदस्यों में ही प्रधान और उपप्रधान का चुनाव किया जायेगा। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव भी मतदाताओं द्वारा सीधा मतदान प्रणाली से होगा और इन सीधे रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही जिला परिषद के प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव किया जायेगा। धारा 19 के अनुसार पचायती राज संस्थाओं में 25 वर्ष की वृद्धावस्था 21 वर्ष की आयु वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। नई पचायती राज व्यवस्था में अब सरपंच पचायत समिति के सदस्य नहीं होंगे। पचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य नहीं होंगे। विधायक भी पचायत समिति के निर्णयों में तो हिस्सा लेंगे परन्तु वे प्रधान व उप प्रधान के चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। विधायक एवं समस्त सदस्य जिला परिषद की बैठकों में भाग लेंगे, लेकिन जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख या अविश्राम प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे।

(8) **ग्राम पचायत की संरचना** - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 12 के अनुसार सरपंच के अलावा 3000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पचायत में कम से कम 9 वार्ड में प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। 3000 से अधिक जनसंख्या वाली पचायतों में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या उसके किसी भाग पर 2-2 अतिरिक्त सदस्य चुन जायेंगे। यदि किसी पचायत की जनसंख्या 4200 है तो प्रथम 3000 पर ३ दूसरे 1000 पर अतिरिक्त 2 तथा शेष 200 पर भी अतिरिक्त 2 पंच अर्थात् कुल 13 वार्ड पंच व एक सरपंच उस पचायत में चुने जायेंगे।

(9) **पचायत समिति की संरचना** - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार एक लाख की जनसंख्या वाली पचायत समिति में कम से कम 15 सदस्य चुने जायेंगे। प्रत्येक 15 हजार या उससे कम किसी भाग पर 2-

2 अतिरिक्त सदस्य निर्वाचित होंगे। यदि किसी पचायत समिति की जनसंख्या 1,35,000 है तो प्रथम एक लाख पर 15 सदस्य, दूसरे और तीसरे 15-15 हजार पर 2-2 सदस्य तथा शेष 4 हजार पर भी 2 सदस्य कुल ३१ सदस्य उस पचायत समिति में होंगे। एक या दो उसके क्षेत्र के विधायक भी उस पचायत समिति के एक-एक ऑफिशियल के सदस्य होंगे। सरपंच न तो पचायत समिति के सदस्य होंगे और न ही प्रधान/उपप्रधान के चुनाव में भाग लेंगे।

(10) **जिला परिषद की संरचना** - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख तक मामूली जनसंख्या हेतु 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख या उससे किसी भाग पर 2-2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। यदि किसी जिला परिषद के क्षेत्र की जनसंख्या 5,20,000 है तो प्रथम 4 लाख पर 17 सदस्य होंगे दूसरी एक लाख पर 2 सदस्य और शेष 20,000 पर भी दो सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल 21 सदस्य उस जिला परिषद के होंगे। प्रमुख एवं उप प्रमुख इनकी निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुने जायेंगे। जिले के विधायक एवं मसद सदस्य तथा राज्यसभा सदस्य, जिन जिले के मतदाता हों, संबंधित जिला परिषद के सदस्य तो होंगे लेकिन प्रमुख एवं उप प्रमुख के चुनाव या होने वाली बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। धारा 20 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दो पचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकेगा। दो पचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होने पर पूर्व की सीट रिक्त समझी जायगी। धारा 21 के अनुसार विधानसभा सदस्य अथवा मसद सदस्य यदि सरपंच, प्रधान या प्रमुख निर्वाचित हों तो 14 दिन में विधानसभा / लोकसभा आदि से त्याग पत्र देना होगा अन्यथा, प्रधान या प्रमुख का स्थान रिक्त माना जायेगा।

(11) **आरक्षण** - (अ) महिलाओं के लिए पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अनुसार राज्य की पचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित किये गये हैं। एक तिहाई पंच प्रत्येक गांव पचायत में एक तिहाई सरपंच पचायत समिति में एक तिहाई प्रधान प्रत्येक जिले में तथा एक तिहाई जिना प्रमुख पूरे राज्य में महिलाएँ होंगी। राज्य सरकार द्वारा लाठी पद्धति में महिला वार्ड/महिलाएँ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कर दिये गये हैं। महिला वार्ड या महिला निर्वाचन क्षेत्र से केवल महिलाएँ चुनाव लड़ सकेंगी। परन्तु पुरुष वार्ड में भी महिलाएँ चाहें तो चुनाव लड़ सकती हैं। इस प्रकार राज्य में 3058 महिला सरपंच 79 महिला प्रधान, 1३ महिला प्रमुख एवं लगभग 1150 पचायत समिति एवं जिला परिषद की सदस्य महिलाएँ होंगी। लगभग 3000 से अधिक महिला

राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति, सफलतायें अथवा उपलब्धियाँ

PRESENT POSITION & ACHIEVEMENT OF PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य मता का विवेकीकरण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 30 दिसम्बर 1996 में पंचायती राज विधिवत रूप से लागू किया गया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है -

(1) राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएँ - राजस्थान राज्य

पंचायती राज का जिलेवार स्वरूप								
क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत संख्या	ग्राम पंचायत (गणगणित) 1991	ग्राम पंचायत 1991	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	भूतत्वगत आर्थिक संसाधन	भूतत्वगत संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	8	276	1001	8156.33	1034536	174950	31378
2	अनूप	14	478	1991	8220.66	1999569	364936	177913
3	बाण	7	215	1599	612.55	700740	130631	168446
4	बाणगढ़	8	325	1462	5011.41	1065883	52029	841820
5	बांसगढ़	8	380	1634	28327.71	1319485	208417	81290
6	भारपुर	9	372	1454	4935.44	1331981	279971	34916
7	भारपुर	11	378	1620	10101.91	1308134	229342	134076
8	भारपुर	4	189	650	27059.16	745602	171561	1384
9	भारपुर	4	181	841	5384.95	635744	121847	151139
10	बिलासपुर	14	391	2379	10703.43	1281463	190302	294424
11	बूंदेलखंड	7	279	965	16638.77	1097172	254774	5277
12	बूंदेलखंड	5	225	1052	3345.08	900098	197754	258797
13	बूंदेलखंड	4	153	569	2909.70	620654	129185	33923
14	बूंदेलखंड	5	237	850	3742.73	815628	35811	567122
15	बूंदेलखंड	7	320	2998	12643.02	1046579	394047	2115
16	बूंदेलखंड	3	251	1992	8953.02	1002256	273205	1486
17	बूंदेलखंड	13	488	2187	10404.79	2053393	353653	240236
18	बूंदेलखंड	3	123	578	38266.73	290917	44784	14854
19	बूंदेलखंड	7	264	676	10592.31	1059355	187691	91704
20	झालावाड़	■	251	1585	6136.62	841409	148223	105532
21	झुंझुनार	■	288	827	5786.30	1280842	199093	29006
22	झुंझुनार	9	333	853	22041.40	1386933	235670	43292
23	झुंझुनार	■	224	729	4981.64	800262	168816	208709
24	झुंझुनार	5	161	502	4923.23	630816	151852	98595
25	झुंझुनार	11	461	1396	17448.72	1816239	382472	4244
26	झुंझुनार	10	320	919	12074.47	1187375	225516	73544
27	झुंझुनार	7	205	904	4256.48	704790	90524	94215
28	झुंझुनार	5	197	858	5378.57	729176	49604	187487
29	झुंझुनार	■	329	946	7540.31	1455393	213948	44919
30	झुंझुनार	5	151	461	5056.63	535466	103739	143480
31	झुंझुनार	6	231	1099	7027.98	784586	163721	113972
32	झुंझुनार	11	408	2333	11527.43	1699429	98335	941456
योग		237	8184	39910	329349.53	34162205	6142702	5224751

में 32 जिले, 32 जिला परिषदें, 229 तहसीले, 100 उपखण्ड, 237 पंचायत समितियाँ, 9184 ग्राम पंचायतें, कार्यरत हैं। राज्य में पंचायती राज के 3 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 250 व्यक्ति है।

(2) राजस्थान में पंचायती राज का जिले वार स्वरूप - राजस्थान में 237 पंचायत समितियाँ कार्यरत हैं। सर्वाधिक पंचायत समितियाँ अलवर (14) और बिलोडगढ़ (14) में हैं। सबसे कम पंचायत समितियाँ हनुमानगढ़ (3) और जैसलमेर (3) में हैं। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें उदयपुर जिले में हैं और जैसलमेर में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। राज्य में पंचायती राज का वर्तमान जिलेवार स्वरूप निम्न तालिका में दिशा गया है -

है। नवीन व्यवस्था में संगठन एवं प्रबन्ध व्यवस्था को मजबूत बनने का प्रयास किया गया है। राजस्थान में वर्तमान प्रशासनिक संगठन को निम्न तालिका में बताया गया है

राजस्थान में पचासवीं राज का नवीन स्वरूप सुदृढ

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रशासनिक सगठन

मन्त्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रमुख शासन सचिव एवं विकास आयुक्त प्राचीण विकास एवं पचायती राज विभाग

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

ग्रामाण विकास एव पचायती राज विभाग

उप हाथम सचिव श्व पदेन ड
विश्व अपुला (३) विधि
शिक्षण शहसन उप विष
पुनर्गति विधि सम्बन्ध

उप विभाग अटुल (2)
प्रशासन-३ जीव

विशेष सचिव
सेलुसिस्ट (२)
सदर सचिव

उपनिवेश (प्रति) (1)
उपनिवेश (प्रति)

सुखिदह अचरस्यै (१)

साम्यांक (1)
साल साम्यांक (1)

वसिष्ठ वरद विष्णोर्ब्रह्म
 अधिराज्य अभिराज्य (१)
 इति च विदितम् ()
 ब्रह्मवर्ष अभिराज्य (१)

जिला परिषद स्तर

प्रमुख/उप प्रमुख/निर्वाचित सदस्य/स्वयं समिति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एदन सचिव जिला परिषद

सम्पद अपिदन्त
(सुन्दरिच विक्रम)

लक्ष्मिदेव
सर्वज्ञ लक्ष्मिदेव

ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਅਧਿਕਾਰਤ

सम्यक् सुविधा

पचायत समिति स्तर

प्रधान/उप प्रधान निर्वाचित सदस्य/स्वाई समितियों
विद्वान् अधिकारी

प्रसार अधिकारी (सहकारिता शिक्षा प्रगति खादी एवं कनिष्ठ अधिव्यंता)

ग्राम पंचायत स्तर

सरपंच/उप सरपंच/निर्वाहक मंडल

ग्राह्य सेवक एवं अन्य भविष्य प्राप्त बचावन

(4) विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से सर्वांगीत कार्यक्रमों में आवासीय भूखण्ड आवंटन आवासीय अनुदान सहायता ग्रामीण शौचालय एवं स्वच्छता कार्यक्रम प्रमुख सदस्यों पर सेवा

सुविधाओं का कार्यक्रम उपग्रह गाँवों का विकास कार्यक्रम एन हेण्ड थम्प संचारण कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। पचासवाँ राज अधिनियम 1994 की धारा 50 के अनुसार ग्राम पंचायतें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का 150

वर्ष 1997 क्षेत्रगत का आवासीय भू-खण्ड आवक्यन करने के लिए अधिकृत है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्ति के लिए अनुमति जति अनुमति जन जति के भूमिदान परिवार ग्रामाण वाउर लु एव मान्य कृषक गाडिया लुहार भुषकड जति के परिवार तथा विकरगण जा ग्राम म स्याड निवास कर रहे हो तथा ऐसे परिवार जा गराबी रेखा स नाथ जीवन यापन कर रहे हो ऐसे व्यक्ति भू-खण्ड प्राप्त करने के पात्र है। वर्ष 1996-97 तक आवासीय भू-खण्ड नि शुल्क न्ये जात है। तथा वर्ष 1997 98 म अन्तर्गत भूखण्ड गजस्थान पचायती गज नियम 158 (1) व 158(2) के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्री दगों पर अन्तिम किये जा रहे है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974 75 म भाग 97 तक 16 90 863 परिवारों का भू-खण्ड आवक्यन कर लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1997 98 के दौरान 30 000 रियायत दर पर आवासीय भू-खण्डों के सन्धों के विरुद्ध जनवरी 1998 तक 22 986 परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवक्यन कर लाभान्वित किया जा चुका है जिसमें अनुमति जति के 9270 परिवारों को व अनुमति जन जति के 4202 परिवारों का लाभान्वित किया जा चुका है।

(5) पंचायती राज संस्थाओं को भवन व्यवस्था पन्थी राज संस्थाओं के जिला परिषद / पंचायत समितियाँ के भवन की व्यवस्था एवं दुम्मा हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997 98 में 50 00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 3 जिला पन्थी एवं 7 पंचायत समितियाँ को उनके कार्यालय भवन निर्माण/ परिवहन/ परिवहन एवं मरम्मत हेतु 15 00 लाख रुपये का राशि का स्वाकृति जरा का जा चुकी है तथा नव गठित जिला हुमानगढ़ म जिला परिषद कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु 25 00 लाख व अन्य जिला परिषद व पंचायत समितियाँ का 10 00 लाख रुपये की राशि की स्वाकृति इसी वित्तिय वर्ष म जारी कर दा जावगा।

(6) चौपाल (पंचायत विज्ञानि ग्रह) पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के जयपुर प्रवास के दौरान उनके ठहरने के लिए चौपाल (पंचायत विज्ञानि ग्रह) का निर्माण कराया गया है। इस भवन में 24 कमरे 5 डारमेटो कमरस हल एवं आन्तुक के ठहरने के लिए फेसल व चाय नारता एवं भोजन हेतु कुन्टीन की व्यवस्था इस वर्ष स कर गई है। चौपाल भवन के लिए 9 0 लाख रुपये का बजट म प्राधान्य इस वर्ष किया गया है। माह दिसम्बर तक 5 42 लाख रुपये की राशि स्टाफ के वेतन आदि एवं अन्य कार्यों म खर्च

किये जा चुके है तथा राशि राशि का उपयोग इसी वित्तिय वर्ष में कर लिया जावगा। इस वर्ष चौपाल में आगन्तुकों के ठहरने पर दिसम्बर 97 तक 0 90 लाख की आय हुई है।

(7) जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण - पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पंचायत राज का कार्य प्रणाली नियमों अधिनियमों एवं राज्य सरकार द्वारा पन्थी जा रहे ग्रामाण विकास म सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के जानकारी राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा दा जाता है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इन्दिरा गंधी परागती राज संस्थान हरिश्चन्द्र मायुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर एवं उदयपुर ग्राम सवक प्रशिक्षण कन्द्र मण्डा पंचायत प्रशिक्षण कन्द्र अजमेर एवं डूंगरपुर म आयोजित किये जाते है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक संस्था में पंचायत प्रशिक्षण कन्द्र हेतु राशि सम्भागों (जयपुर राग व बाकार) में प्रशिक्षण कन्द्र खाले जाते के प्रस्ताव कन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

इस वर्ष 307 पदाधिकारियों एवं 407 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त नव चयनित ग्राम सवक पन्थ पंचायत सचिवों में से 643 ग्राम सवक पन्थ पंचायत सचिवों को उनके कार्य स सम्बन्धित निदेशित प्रशिक्षण 3 माह का अवधि का आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया है।

विभाग के अधीनस्थ प्रशिक्षण कन्द्रों के लिए 74 62 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

(8) संस्थाओं का निरीक्षण एवं जांच विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के समय-समय पर निरीक्षण एवं जांच का कार्य सम्पानित किया जाता है जिसमें पंचायत राज संस्थाओं का गतिविधियों पर समुचित निरीक्षण रखा जाता है एवं किमा भा प्रकार की अनियमितता पर अहुरा रहता है।

(9) वित्तीय प्रबन्ध ग्रामाण विज्ञान एवं पंचायत राज के अन्तर्गत विकास कार्यों के क्रियन्वयन प्रार्थमिक रिक्त के प्रमाण पैण्ड पन्थों के रसम्भाव परिवार कल्याण तथा फमल कृषि आदि हेतु वित्तीय प्रबन्ध आयोजना आयोजना धिन् तथा कन्दाय प्रवर्तित योजना के तहत किया जाता है। वर्ष 1997 98 म विभाग के वित्तिय प्थिति निम्नानुसार है।

(करोड़ रुपये में)				
वर्ष	वर्ष 1997-98			
	बजट प्राप्ति	अपेक्षा	पिन	योग
	आयोजना	अपेक्षा	पिन	योग
1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पंचायती राज एवं नवनीकरण ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान उन्नत कृषि ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासीय योजनाएं राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्त आयोग	148.52	56.35	3.39	208.06
2. शिक्षा (सामान्य कम्प्लेक्स व उच्चमध्यम शिक्षा) स्कूल बोर्ड योजनाएं एवं औद्योगिक शिक्षा	31.86	430.80	48.96	511.61
3. हेल्थ प्रयोग के रख रखव हेतु जिना परिषद व पंचायत समितियों को सहायता		8.83		8.83
4. परिवार कल्याण प्रकृत वृद्धि हेतु		0.15	0.27	0.42
कुल	180.18	496.13	52.61	728.92

स्रोत: प्रति विभाग 1997-98, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान

10 विकेन्द्रीकृत वित्तीय नियोजन राज्य मुख्यालय जिला परिषद व पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आवश्यकतानुसार एवं वित्तीय उपलब्धता के आधार पर बजट अनुमान बनाये जाते हैं।

वित्तीय उपलब्धता जिला परिषद व पंचायत समिति स्तर पर केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के आयोजना व आयोजना पिन मद के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि तथा इन सहायताओं की निजी आय से होती है। मुख्यालय स्तर पर सभी अनुमानों का इकजाई कर राज्य सरकार के आयोजना एवं वित्त विभाग के साथ बजट अन्तिमिकरण बैठक में तय की जाती है जिसे राज्य विधानसभा में प्रस्तुत होने के पश्चात् राज्य सरकार के बजट में दर्शाया जाता है। पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज नियमों व समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों, परिपत्रों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा धनराशि के संचरण, सहायता के समुचित उपयोग लेखों के सही संचरण और विलाय शतवेदन सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थाएँ की गई हैं।

(11) राज्य वित्त आयोग राज्य के नवीन पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के अनुसार राज्यपाल महोदय द्वारा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेसी विधायक श्री चन्दनमल वैद्य एवं पूर्व निर्देशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री देवेन्द्र सिंह शर्मावत का सदस्य मननित किये गये हैं। श्री टी. श्रीनिवासन इस आयोग के सदस्य सचिव के रूप में मननित किये गये हैं।

राज्य वित्त आयोग राज्य की सभी स्तरों की पंचायतों

की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार को अग्रलिखित बिन्दुओं पर सिफारिश करेगा

1 पंचायत पंचायत समिति व जिला परिषद के बीच राज्य सरकार के करोड़ों रुपये अन्य करोड़ों एवं फंड्स शुद्ध प्रप्तियों का वितरण करना एवं उनके मध्य अंतरों का आवंटन।

2 ऐसे कर शुल्क एवं कर फंड जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समनुदेशित अथवा विनियोजित किये जा सकेंगे।

3 राज्य सचिव निधि में से पंचायत पंचायत समिति व जिला परिषद को सहायता अनुदान।

4 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारन के आवश्यक उपाय।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित राज्य वित्त आयोग ने राज्य की जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था स्थापन की स्थिति व कार्य प्रणाली आदि के सभी आयामों की विस्तृत विवेचना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिन्हें राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 से मान लिया है। चारू वित्तीय मद में राज्य सरकार के विरुद्ध मद 3604 में ग्राम पंचायतों को 5.00 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान एवं राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत सामान्य अनुदान रुपये 7.20 प्रति व्यक्ति पंचायत समितियों को 0.25 रुपये मद 3604 से एवं राज्य वित्त आयोग मद से रुपये 1.00 प्रति व्यक्ति अनुदान देव हैं। (यह राशि एम. एफ. सी. के अवार्ड के अनुसार पिछले वर्ष 1995-96 से देव अनुदान में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर तय हुई है) व प्रत्येक जिला परिषद को 30,000 रुपये दिया जा रहा है।

आयोग की सम्पादन अनुदान सम्बन्धी अभिशपथ को मानते हुये वर्ष 1997-98 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पद ग्राम सेवक करने हेतु शेष 3992 पदों में से इस वर्ष 800 पद सृजित किये गये हैं। नये पद सृजित किये गये हैं तथा 237 कनिष्ठ अभियन्ता व 237 कनिष्ठ लिपिकों के भी पद स्वीकृत कर दिये गये हैं वर्ष 1997-98 के लिये इस मद में राशि रु 5950 00 लाख का प्रावधान है।

(12) विभागीय प्रकाशन (Department of Publication) - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा "राजस्थान विकास" पत्रिका का प्रकाशन माह अगस्त 1993 से निरमित रूप से किया जा रहा है यह पत्रिका द्वै मासिक है। इस पत्रिका में राज्य सरकार के आदेश परिपत्रों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा ग्रामीण जनता के उत्थान की विविध योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

राजस्थान विकास पत्रिका की प्रतिष्ठ राज्य की समस्त पंचायती राज सस्थाओं को नियमित रूप से प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका के अन्य भी ग्राहक हैं, जिन्हें सशुल्क यह पत्रिका भिजवाई जाती है।

"राजस्थान विकास" पत्रिका के अलावा विभाग के अन्य प्रकारान भी प्रकाशन शाखा द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

(13) पंचायती राज एवं शिक्षा (Panchayati Raj & Education) - ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व पंचायती राज सस्थाओं का है। नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उच्च प्राथमिक शालाएँ भी पंचायती राज को सुपुर्द हो सकती हैं। शाला व्यवस्था हेतु ग्राम स्तर पर शिक्षा

समिति का कठिन होना चाहिए। सन् 2000 तक "सबके लिए शिक्षा" का लक्ष्य रखा गया है। गांव, पंचायत, पंचायत समिति व जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें होती हैं। समस्याएँ दूर की जाती हैं। नव माशरों की परीक्षा लेकर यदि 80 प्रतिशत निरक्षर साक्षर हो जाते हैं तो जिले को सम्पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है।

(14) पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Women Representation In Panchayati Raj) - पंचायती राज का पहला पंचायत सस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। मविधन संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुसार पंचायत समितियों के तीनों स्तरों में कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के एक-तिहाई पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

पंचायतों को मुख्य रूप से विकास कर्मों का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेती, लघु उद्योग, आर्थिक आधार को मजबूत बनाएँगे और राजस्व प्रशासन, न्याय व्यवस्था, नागरिक आपूर्ति और अपराध नियंत्रण विषयों से स्थानीय लोगों के सामाजिक परिवेश को सुधारने में मदद मिलेगी। महिलाएँ स्वभावतः इसमें सशक्त भूमिका निभाएँगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।

(15) राजस्थान की पंचायत समितियाँ (Panchayat Samitis of Rajasthan) - राजस्थान राज्य में 237 पंचायत समितियाँ हैं इन समितियों का जिलेदार वितरण निम्न है -

राज्य की पंचायत समितियाँ

1 अजमेर (Ajmer)

श्री नगर (Snnagar)	पीसागन (Pisangan)
केकडी (Kekn)	भिनार (Bhinai)

जवाजा (Jawaja)	मसूदा (Masuda)
सिलोरा (Silora)	अगई (Arai)

2 अलवर (Alwar)

किशनगढ़ वाम (Kishangarh Bas)	लक्ष्मणगढ़ (Laxmangarh)
उमरैन (Umrain)	रामगढ़ (Ramgarh)
मुण्डावर (Mandawar)	थानागाजी (Thana Gazi)
बानसुर (Bansur)	

कोट कासीम (Cot Qasim)	राजगढ़ (Rajgarh)
तिजारा (Tijara)	कटूमर (Kathumar)
बहरोड (Bahror)	नीमराना (Nimrana)
रेणी (Reni)	

3 बारा (Baran)

बरना (Baran)	अन्ता (Anta)	अटरू (Atru)	शाहबाद (Shahbad)
छीपाबडोद (Chhipa Barod)	छबड़ा (Chhabra)	किशंगढ़ (Kushangarh)	

4 बान्सवाड़ा (Banswara)

गढ़ी (Garhi)	कुशलगढ़ (Kushalgarh)	सज्जगढ़ (Sajjangarh)	बागीडोर (Bagidora)
भूखिया (Bhukha)	घाटोल (Ghatol)	पिपलखूंट (Peepal Khoont)	आनन्दपुरी (Anandpun)

5 बाडमेर (Barmer)

सिवाना (Siwana)	शिव (Shiv)	बालोत्रा (Balotra)	चौहान (Chohtan)
धौरामना (Dhonmanna)	बायलू (Baylu)	बाडमेर (Barmer)	सिणघरी (Sindan)

■ भरतपुर (Bharatpur)

डीग (Deeg)	नगरपहाड़ी (Nagarphan)	कमान (Kaman)	बैर (Wer)	बयाना (Bayana)
रूपवास (Rupvas)	नदबाई (Nadbai)	सेवर (Sewar)	कुम्हेर (Kumher)	

7 भीलवाड़ा (Bhilwara)

माण्डलगढ़ (Mandalgarh)	शाहपुरा (Shahapura)	सुवाना (Suwana)	माण्डल (Mandal)
आसीन्द (Asind)	हुरडा (Hurda)	बनेडा (Banera)	जहजपुरा (Jahazpur)
रायपुर (Raipur)	कोटडी (Kotn)	सहारा (Sahara)	

8 बीकानेर (Bikaner)

नोखा (Nokha)	लूणकरणसर (Lunkaransar)	कोलायात (Kolayat)	बीकानेर (Bikaner)
--------------	------------------------	-------------------	-------------------

9 बूंदी (Bundi)

तालेडा (Taler)	हिण्डोली (Hindoli)	नैनवा (Naenwa)	केशोरिपटान (Keshori patan)
----------------	--------------------	----------------	----------------------------

10 चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh)

बेगू (Begun)	चित्तौड़गढ़ Chittaurgarh)	रशमी (Rashmi)	कपासन (Kapasani)
प्रतापगढ़ (Pratap garh)	निम्बाहेड़ा (Nimbahera)	भदेसर (Bhadesar)	डुंगला (Dungla)
छोटी सादडी (Chhoti Sadn)	अमोद (Amaud)	भैमरोडगढ़ (Bhainsrogarh)	
बडी सदरी (Ban Sadn)	भोपालसागर (Bhopal sagar)	गंगरार (Gangrar)	

11 चुरू (Churu)

चुरू (Churu)	रतनगढ़ (Ratangarh)	सरदारशाहर (Sardarshahar)	
राजगढ़ (Rajgarh)	तारानगर (Taranagar)	सुजानगढ़ (Sujangarh)	डूंगरगढ़ (Dungargarh)

12 दौसा (Dausa)

महुवा (Mahuva)	बान्दीकुई (Bandikui)	लालसोट (Lalsot)	दौसा (Dausa)	सिकराय (Sikrai)
----------------	----------------------	-----------------	--------------	-----------------

13 धौलपुर (Dhaulpur)

धौलपुर (Dhaulpur)	बसेडी (Basen)	बाडी (Ban)	राजखेड़ा (Rajakhara)
-------------------	---------------	------------	----------------------

14 डूंगरपुर (Dungarpur)

सागवाड़ा (Sagwara)	सिमलवाड़ा (Simlawa)	बिछीवाड़ा (Bichhiwara)	डूंगरपुर (Dungarpur)
आसपुर (Aspur)			

15 हनुमाननग (Hanumangarh)

हनुमानगढ़ (Hanumangarh)

नोहर (Nohar)

भादरा (Bhadra)

16 गंगानगर (Ganganagar)

रायसिंह नगर (Raisingh nagar)

करणपुर (Karanpur)

सादुलशहर (Sadulshahar)

श्रीगंगानगर (Shri Ganganagar)

सूरतगढ़ (Suratgarh) पदमपुर (Padampur)

अनुपगढ़ (Anupgarh)

17 जयपुर (Jaipur)

बस्सी (Bassi)

सांगानेर (Sanganer)

झोतवाड़ा (Jhotwara)

फागी (Phagi)

सामर (Sambhar)

दूदू (Dudu)

गोविन्दगढ़ (Govindgarh) ओमेर (Amer)

जमवा रामगढ़ (Jamwa Ramgarh)

विराटनगर (Viratnagar) कोटपुतली (KotPutli)

चाकसू (Chaksu)

शाहपुरा (Shahpura)

-

18 जैसलमेर (Jaisalmer)

साकड़ा (Sankra)

जैसलमेर (Jaisalmer)

सम (Sam)

19 जालौर (Jalore)

आहोर (Ahore)

जालौर (Jalore)

सायला (Saila)

भीनमाल (Bhinmal)

जसवंतपुरा (Jaswantpura)

साचौर (Sanchor)

रानीवाड़ा (Raniwara)

20 झालावाड़ (Jhalawar)

झालरापाटन (Jhalrapatan) खानपुर (Khanpur)

डग (Dag)

पिडावा (Pirawa)

बकानी (Bakani)

मनोहरथाना (Manohar Thana)

21 झुझुनू (Jhunjhunu)

झुझुनू (Jhunjhunu)

अलसीसर (Alsisar)

बुहाना (Buhana)

खेतड़ी (Khetri)

उदयपुरवाटी (Udaipurwati) नवलगढ़ (Nawalgarh)

चिहवा (Chirawa)

सूरजगढ़ (Surajgarh)

22 जोधपुर (Jodhpur)

ओसिया (Osian)

विलाडा (Bilara)

भोपालगढ़ (Bhopalgarh) मण्डोर (Mandore)

लूनी (Luni)

शेरगढ़ (Shergarh)

बालेसर (Balesar)

फलोदी (Phalodi) बाप (Bap)

23 करौली (Karauli)

हिण्डोन (Hindaun) करौली (Karauli) सपोटरा (Sapotra) टोडाभीम (Todabhim) नादोती (Nadoti)

24 कोटा (Kota)

लाडपुरा (Ladpura) चेचर (खैराबाद) (Chechar) सांगोद (Sangod) सुल्तानपुर (Sultanpur) इटावा (Itawa)

25 नागौर (Nagaur)

डीडवाना (Didwana)

लाडनू (Ladnun)

कुचामन सिटी (Kuchaman City)

नागौर (Nagaur)

मुण्डवा (Mundwa)

जायल (Jayal)

मकराना (Makrana)

परवतसर (Parvatsar)

डेगाना (Degana)

मेडवा (Merta)

रिया (Riyan)

26 पाली (Pali)

बाली (Bali)

सुमेरपुर (Sumerpur)

खारची (Kharchi)

रानी स्टेशन (Rani)

देमूरी (Desun)

जैतरण (Jaitaran) रायपुर (Raipur)

सोजत (Sojat City)

पाली (Pali)

रोहट (Rohit)

27 राजसमन्द (Rajsamand)

राजसमन्द (Rajsamand) कुम्भलगढ (Kumbhalgarh) रेलमगण (Railmagra) आमेट (Amet)
देगढ (Deogarh) खमनौर (Khamnor) भीम (Bhim)

28 सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur)

गंगापुर (Gangapur) स माधोपुर (Sawai Madhopur) खण्डार (Khandar)
बौली (Bouli) बामनवास (Bamanwas)

29 सीकर (Sikar)

लक्ष्मणगढ (Lachmangarh) फतेहपुर (Fatehpur) पिपराली (Piprali)
घोद (Dhaod) दाता रामगढ (Danta Ramgarh) श्री माधोपुर (Shri Madhopur)
खण्डेला (Khandaela) नीम का थान (Neem ka Thana)

30 सिरोही (Sirohi)

पिण्डवाडा (Pindwara) शिवगंज (Shivganj) रेवदर (Revdar) अबूरोड (Abu Road) सिरोही (Sirohi)

31. टोंक (Tonk)

टोंक (Tonk) मालपुरा (Malpura) निवाई (Niwai) देवली (Devali)
उनियारा (Uniarar) तोडारसिंह (Toda Rai Singh)

32. उदयपुर (Udaipur)

गिरा (Girwa) बडगाव (Bargaon) कोटडा (Kotra) धरियावद (Dhanawad)
सलुम्बर (Salumber) सरडा (Sarada) मावली (Mavli) खैरावाडा (Khairwara)
भीण्डर (Bhinder) गोगुन्दा (Gogunda) झाडोल (Jhadol)

राजस्थान में पंचायती राज की कमियाँ अथवा असफलतायें

SHORTCOMINGS/FAILURES OF PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

आज स्थिति यह है कि गोवर तथा ओरण भूमि पर अधिकरण के मामले बढ़ रहे हैं, वन क्षेत्रों से जंगली लकड़ी की अवैध कटाई तथा निकासी हो रही है, ग्राम जलाशयों के जल-मिसाधन का मनमाना उपयोग हो रहा है और पटवारे, फॉरेस्ट गार्ड तथा मिर्बाई विभाग के स्थानीय कर्मचारी या तो मूक दर्शक और असहाय हैं या फिर स्वयं भी इन संसाधनों के दुरुपयोग में लिप्त हैं। इन भगठनों को पंचायत के प्रबंधधीन किए जाने से न केवल इनका बेहतर प्रबंध होगा बरन पंचायत की आय में वृद्धि भी होगी।

राजस्थान में पंचायती राज की प्रमुख कमियाँ निम्न हैं-

- 1 नवीन पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों की संगठनात्मक संरचना में परम्पारिक सम्बन्ध एवं सम्बन्ध का अभाव है। अतः पंचायती राज संस्थाओं को कुशलतापूर्वक अपने दायित्व को पूर्ण नहीं कर पाती हैं।

- 2 गांव के माधनों पर पंचायत के स्नामित का अभाव होने के कारण गांव के संसाधनों का दुरुपयोग होता है।

- 3 योजना प्रबंधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव होने के कारण पंचायती राज सम्बन्धी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन नहीं हो पाता है।

- 4 पर्याप्त धन के अभाव के कारण विकास कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं।

- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण राज्य की ग्रामीण जनता को पंचायती राज का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है।

- 6 पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षा-विज्ञान की अनियमिततायें विद्यमान हैं और इन संस्थाओं पर नौकरशाही का दबाव है।

- 7 प्रशिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्त के कारण पंचायती राज संस्थाओं में अनेक स्थान रिक्त हैं।

पंचायती राज की कमियों को दूर करने के उपाय SUGGESTIONS

- 1 विकास योजना पर पर्याप्त धन उपलब्ध करने के लिए बजट में प्रावधान तथा उचित आवंटन करना,
- 2 पंचायतों को स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए लगान

वसूलने एवं कर लगाने का अधिकार

3. संबंधित स्तर की पंचायतों में संबंधित अधिकारियों और बर्मचारियों को बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश देना जिससे समस्याओं का निराकरण प्रभावी ढंग से किया जा सके

4. समय समय पर चुने हुए पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

5. हिसाब किताब का अंशेक्षण करना एवं निरीक्षण व्यवस्था को सशक्त बनाने की वास्तविक कार्यवाही करना

6. वर्गभेद तथा भ्रष्टाचार की शिवायती की जांच करके सम्बन्धित विभाग के विरुद्ध कार्यवाही करना।

राजस्थान में पंचायती राज का मूल्यांकन EVALUATION

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण के नये युग का सुप्रसन्न हुआ है।

राज्य में पंचायती राज के प्रारम्भिक दौर में प्रबंध संगठन तथा कुछ आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का उपस्थित होना स्वाभाविक है। इन समस्याओं का शीघ्र समाधान सम्भव है। पंचायती राज संस्थाओं में, विशेष रूप से दलित पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवस्था महत्वा गांधी की कल्पना भारत की आभा गावों में बसती है। जब तक गांव स्वतंत्र नहीं होते देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। का वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करती है इस सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत ने ठीक ही कहा है कि "राजस्थान में एक नई सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की रचना हो रही है। तीव्र गति से आर्थिक विकास के साथ विकेंद्रीकृत सत्ता की संस्थाओं की सहायता से गरीबी उन्मूलन तथा वृहद सामाजिक बल्याण का महाअनुष्ठान चल रहा है। इसे देखकर मेरा दृढ़ विश्वास है कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है।"

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- निम्नलिखित पर 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए। राजस्थान में नया पंचायती राज अधिनियम।
Write short notes on the following in 100 words. New Panchayat Raj Act in Rajasthan
- राजस्थान में पंचायती समितियों की संरचना बताइए।
Explain the structure Panchayat Samitis in Rajasthan
- पंचायत समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं?
What are the main functions of Panchayat Samiti?
- पंचायत समिति में सरपंच की क्या भूमिका है?
What is the role of Sarpanch in Panchayat Samiti?
- राजस्थान में पंचायती राज पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Panchayat Raj in Rajasthan
- राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए।
Mention the present position of Panchayat Raj in Rajasthan

B. निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की उपलब्धियों तथा कमियों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe in detail the achievements and shortcomings of Panchayat Raj System in Rajasthan
- राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the main characteristics of Panchayat Raj Act, 1994 in Rajasthan
- राजस्थान में पंचायती राज पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Panchayat Raj in Rajasthan
- पंचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।
Explain the functions and powers of Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad
- राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
Explain the present position and achievements of Panchayat Raj in Rajasthan



प्रतियोगा परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(OBJECTIVE TYPE QUESTIONS OF COMPETITIVE EXAMS)

1 Energy-Crisis is a major problem of Rajasthan. Which one of the following sources would be of great help in Rural Rajasthan -

- a Wind energy ii Bio-Gas
c Solar energy iii Thermal energy

ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा?

- a पवन ऊर्जा ii बायो-गैस
c सौर ऊर्जा d तापीय ऊर्जा

2 The second highest Peak of Aravalli Range is

- a Kumbhalgarh b Nag Pahar
c Ser d Achargarh

अरावली श्रेणियों की दूसरी सबसे ऊँची चोटी का नाम है

- ii कुम्भलगढ़ b नाग पहाड़
c सेर d अक्षलगढ़

3 Which of the following pairs is correct -

- a Banganga-Banas b Kolhan-Luni
c Sukri-Chambal d Jakhom-Mahu

निम्नलिखित में से सही सा युग्म मिलाई

- a बाणगा-बनास b कोलहान-लूनी
c सूक्री-चम्बल d जाखम-माहु

4 The soil of Hadoti Plateau is

- a Alluvial ii Red
c Brown d Medium black

हाड़ोती पठार की मिट्टी है

- a बजरा b लाल
c भूरा d मध्यम काली

5 The Long term solution to the problem of soil salinity and alkalinity is the use of -

- ii Rock Phosphate b Gypsum
c Manure d Urea

जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है

- a रॉक फॉस्फेट ii जिप्सम
c खाद d यूरिया

6 The District with the highest growth of population during 1981-1991 is

- a Jaipur b Bikaner
c Ajmer d Banswara

1981-91 के दशक में जिस जिले में जनसंख्या का विकास सर्वाधिक हुआ है वह है

- a जयपुर b बीकानेर
c अजमेर d बंसवाड़ा

7 According to the Census [1991] the percentage of the population of scheduled castes and scheduled tribes in Rajasthan is -

- a 17.29 & 12.44 ii 13.82 & 6.77
c 17.29 & 13.82 iii 12.44 & 6.77

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है

- a 17.29 एवं 12.44 ii 13.82 एवं 6.77
c 17.29 एवं 13.82 d 12.44 एवं 6.77

8 The main cause for the occurrence of frequent drought and famines in Rajasthan is -

- a Degradation of forests c Erratic rainfall
b Irrational use of water d Soil erosion

राजस्थान में बारबार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है

- a वनों का अपक्रमण b जल का अविद्वेषपूर्ण उपयोग
c अनियमित वर्षा d धूमि का कटाव

9 The chief aim of Integrated Rural Development Programme (I R D P)

- a To provide training to village youth
b To give employment to landless labourers
c To check desertification
d To give employment to families living below poverty line in rural areas

संयुक्त ग्रामीण विकास योजना (I R D P) का मुख्य लक्ष्य है

- a ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना
b भूमिहीन कृषिों को रोजगार प्रदान करना
c मरुस्थलीकरण का नियंत्रण
d ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रद्द करने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना

10 The famous cow-breeds for the production of milk are -

- a Tharparkar - Raithi ii Raithi Nagon
c Malwa Tharparkar d Mewar Malwa

दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध गायों की प्रजातियाँ हैं

- a थारपारकर एवं राठी ii राठी एवं नागौर
c मालवी एवं थारपारकर d मेवारी एवं मलवी

11 Match the following -

Mineral	Region
A. Gypsum	I Jhama Kotra
B Copper	II Rampura Aguncha
C Phosphate Rock	III Kho Danba
D Lead and Zinc	IV Jamsar

	A	B	C	D
(1)	III	II	IV	I
(2)	II	III	IV	I
(3)	IV	III	I	I
(4)	I	IV		

निम्नलिखित को सुनेल कीजिए

खानि	क्षेत्र
A जिप्सम	I झारखण्ड
B ताबा	II रामपुर-आरुण
C फॉस्फेट रॉक	III छोट्टीया
D सीसा एवं जस्ता	IV जामपुर
(1)	A III B IV C I D II
(2)	A II B III C IV D I
(3)	A IV B III C I D II
(4)	A I B IV C II D III

- 12 Som Kamlia Amba Irrigation Project is situated in the District of -

a Dungarpur b Banswara
c Udaipur d Chittor

सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है

a डूंगरपुर b बांसवाड़ा
c उदयपुर d चित्तौड़

- 13 The two districts of Rajasthan where there is no river

a Jaisalmer & Barmer b Jaisalmer & Jalore
c Bikaner & Churu d Jodhpur & Jaisalmer

राजस्थान के दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है

a जैसलमेर एवं बाड़मेर b जैसलमेर एवं जालोर
c बीकानेर एवं चुरू d जोधपुर एवं जैसलमेर

- 14 Per capita income in Rajasthan for the year 1996-97 at current prices is estimated at -

a Rs 8000 b Rs 7500
c Rs 7800 d Rs 7000

राजस्थान में 1996-97 वर्ष के लिए प्रतिव्यक्ति आय का अनुमान वर्तमान कीमतों पर आरंभ है

a 8000 रुपये b 7500 रुपये
c 7800 रुपये d 7000 रुपये

- 15 Two cities of Rajasthan which are included for determining of General Consumer Price Index Number for Industrial workers are -

a Kota & Jaipur b Kota & Beawar
c Jaipur & Ajmer d Jaipur & Jodhpur

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के दो शहर हैं

a कोटा एवं जयपुर b कोटा एवं बीकानेर
c जयपुर एवं अजमेर d जयपुर एवं जोधपुर

- 16 Out of total inhabited villages in Rajasthan the percentage of electrified villages is about -

a 90% b 80%
c 75% d 70%

राजस्थान के कुल आबाद गाँवों में विद्युतीकृत प्रतिशत है करीब

a 90% b 80%
c 75% d 70%

- 17 The Net SDP from agriculture for the Year 1996-97 (at constant prices) in Rajasthan is estimated at about -

a 40% b 42%
c 44% d 48%

राजस्थान में खेती क्षेत्रों पर सन् 1996-97 के अनुमानित शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है -

a 40% b 42%
c 44% d 48%

- 18 Out of Rs 11500 Crores Plan outlay for the Eighth Plan of Rajasthan the provision for maximum amount has been made for -

a Agriculture and allied sector
b Power sector
c Social and community services
d Rural development

राजस्थान में आठवी योजना में योजना उद्घरण 11500 करोड़ रुपये में से अधिकतम राशि का प्रयोजन किया गया है

a कृषि एवं संबन्धित सेवाओं के लिए
b ऊर्जा क्षेत्र के लिए
c सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए
d ग्रामीण विकास के लिए

- 19 From the tourism point of view there is a plan to divide Rajasthan into -

a 10 regions b 3 regions
c 6 regions d 4 regions

पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बाँटने की योजना है -

a 10 क्षेत्रों में b 3 क्षेत्रों में
c 6 क्षेत्रों में d 4 क्षेत्रों में

- 20 The search for gold in Rajasthan is under progress in the District of -

a Udaipur b Kota
c Jhalawar d Banswara

राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में शक्ति पर है वह है

a उदयपुर b कोटा
c झालावाड़ d बांसवाड़ा

- 21 The district in Rajasthan which is now famous for production of Isabgol Jeera (cumin seed) and Tomato is -

a Ganganagar b Bundi
c Jalore d Kota

राजस्थान का वह जिला जो अब इसमूल जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है

a गंगानगर b बुंदी
c जालोर d कोटा

- 22 Jeevan Dhara Yojna in Rajasthan is concerned with -

a Insurance scheme for the poor
b Construction of irrigation wells

- b. Providing electricity to rural poor
d. Providing medical facilities

राजस्थान में जीवन धारा योजना का सम्बन्ध है

- घरों के लिए सीमा योजना
■ सिंचाई कुओं का निर्माण
c. ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध करवाना
d. चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना

23. The district in Rajasthan which has the world's unique habitat for birds and which is also a paradise for water birds -

- a. Alwar b. Bharatpur
c. Udaipur d. Jodhpur

राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जलपक्षियों का स्वर्ग है -

- a. अलवर b. भरतपुर
c. उदयपुर d. जोधपुर

24. Central sheep and wool research institute is located at -

- Bikaner b. Jasol
c. Avikanagar d. Jaisalmer

केन्द्रिय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है

- a. बीकानेर b. जसोल
c. अजमेर d. जैसलमेर

25. The district in Rajasthan located adjacent to the International Boundary are -

- (1) Ganganagar, Bikaner, Jaisalmer & Barmer
(2) Ganganagar, Jodhpur, Jaisalmer & Jalore
(3) Ganganagar, Bikaner, Jodhpur & Jalore
(4) Jalore, Jaisalmer, Barmer and Bikaner

राजस्थान के वे जिले जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं -

- (1) गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर
(2) गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालौर
(3) गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालौर
(4) जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर

26. What is the percentage of female literacy in Rajasthan as per censuses of year 1991 -

- a. 20.84% b. 39.42%
c. 38.41% d. 52.11%

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है -

- a. 20.84% b. 39.42%
c. 38.41% d. 52.11%

27. Assertion Rule (A) The western desert district of Rajasthan have abundant food crops today Reason rule (R) The Indira Gandhi Canal has provided means of irrigation in most parts of Jaisalmer and Barmer districts Use it -

- Assertion is right and reason is also right
■ Assertion is wrong and Reason is also wrong

- c. Assertion is right but reason is wrong
d. Assertion is wrong but reason is right

कथन (अ) राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली जिलों में अबकल भापुर छाछान फसलें उत्पन्न होती हैं।

कारण (क) इन्दिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई को सुविधा प्रदान कर दी है।

उपरोक्त कौनसे सही -

- a. कथन सही है और कारण भी सही है
■ कथन सही है और कारण भी गलत है
c. कथन सही है परन्तु कारण गलत है
d. कथन गलत है परन्तु कारण सही है

28. Rajasthan has abundance of rock phosphate and gypsum but is poor in coal resources. In order to have chemical fertilizers it would be profitable to -

- a. Import coal from other states of India
b. Import electricity from other states of India
c. Export rock phosphate and gypsum to other states of India
d. Establish beneficiation plants of rock phosphate and gypsum in Rajasthan

राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम खनिजों की बहुतायत है परन्तु कोयला संसाधनों की कमी है। रासायनिक खाद तैयार करने के लिये यह लाभदायक होगा -

- a. भारत के अन्य राज्यों से बिजली आयात किया जाए
b. भारत के अन्य राज्यों से कोयला आयात किया जाए
c. भारत के अन्य राज्यों से रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का निर्यात कर दिया जाए
d. राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के परिशोधन कारखाने लगाए जाए

29. The longest river which flows entirely in Rajasthan state is -

- a. Chambal b. Luni
c. Banas d. Mahi

राजस्थान में ही पूरब बहने वाली सबसे लम्बी नदी का नाम है

- a. चम्बल b. लूनी
c. बानस d. माही

30. The Most important cause of forest degradation in Rajasthan for timber -

- a. Climatic changes
b. Felling of Trees for timber
c. Felling of trees for fuel wood
d. Cattle grazing

राजस्थान में वनों की कटौत का प्रमुख कारण है -

- a. जलवायु परिवर्तन
b. ईंधन के लिये वनों की कटौत
c. जलाने के लिये वनों की कटौत
d. पशु चारा

- 31 The most important resources of lignite in Rajasthan are located at -
 a Palana Agucha and Merta
 b Palana Kapurdi and Sonu
 c Kapurdi Merta and Sonu
 d Lapurdi Merta and Palana

राजस्थान के प्रमुख वहुत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन हैं

- a पलाना अगुचा और मड़ना b पलाना कपूरडी और सोनू
 c कपूरडी मड़ना और सोनू d कपूरडी मड़ना और पलाना

- 32 The highest percentage of livestock animals in Rajasthan is that of

- a Goat b Sheep
 c Cattle d Camels

राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो पशु है

- a बकरियाँ b भेड़ें
 c दूधारा पशु d ऊँट

- 33 In 1991 census the lowest population growth rate in Rajasthan remained in the district of Faliymer and Chittorgarh. The main reason for this low growth rate is

- a Low birth rates
 b High death-rates
 c Poor employment opportunities
 d Lack of Transport system

सन् 1991 की जनगणना में राजस्थान के फालीयमर और चित्तौड़गढ़ जिलों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही। कम वृद्धि दर का मुख्य कारण है

- a कम जन्म दर b अधिक मृत्यु दर
 c रोजगार के कम अवसर d वाणिज्य संस्था की कमी

- 34 What is the percentage of outlay on power sector in the Rajasthan Annual Plan of 1991-92?

- a 18.6% b 27.2%
 c 30.0% d 38.6%

वर्ष 1991-92 की राजस्थान की वार्षिक योजना में शक्ति (ऊर्जा) क्षेत्र के लिए निर्धारित सट्यब का प्रतिशत प्रतिशत तब क्या गया है?

- a 18.6% b 27.2%
 c 30.0% d 38.6%

- 35 Which is the most crucial issue that affects the level of economic activity in all the major sectors of economy in Rajasthan namely agriculture industries and quality of life of people?

- a Scarcity of water b Lack of capital
 c Scarcity of power d Wide spread illiteracy

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों (कृषि उद्योग एवं जनसंसार के जीवन के गुणवत्ता में सम्बंधित) सर्वाधिक निर्धारक मुद्दा योजना है जो आर्थिक क्रियाओं के स्तर को प्रभावित करने है

- a जल का अभाव b पूँजी की कमी
 c ऊर्जा की कमी d व्यापक निरक्षरता

- 36 The Organisation which participates in large and medium scale industries through term loans and equity participation for industrial development in Rajasthan is -

- a Rajasthan Agro-Industries Corporation
 b RAJSICO
 c RFC
 d RIICO

राजस्थान में औद्योगिक विकास के निम्ने वृहद एवं मध्य आकार के उद्योगों को अर्थव्यवस्था एवं अंश पूँजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है

- a राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन
 b राजसीको
 c अर एफ सी
 d रिफो

- 37 Which is the mineral stone that fetches maximum total sale value in Rajasthan?

- a Masonary stone b Lime stone
 c Sand stone d Marble

वह खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है

- a चुनई का पत्थर b चूने का पत्थर
 c बालू पत्थर d संगमरमर

- 38 What has been the percentage share of agriculture state income of Rajasthan (At current prices) by industrial output in 1989-90?

- a 40.8% b 52.6%
 c 56.4% d 61.5%

राजस्थान राज्य में आर्थिक गतिविधि (वर्तमान कीमतों पर) के आधार पर वर्ष 1989-90 में कृषि का हिस्सा प्रतिशत था?

- a 40.8% b 52.6%
 c 56.4% d 61.4%

- 39 The annual per capita income at current prices in Rajasthan in 1990-91 was estimated to be

- a Rs 1841 b Rs 2327
 c Rs 3595 d Rs 4214

राजस्थान में वर्ष 1990-91 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (वर्तमान कीमतों पर) का अनुमान निर्धारित है

- a रुपये 1841 b रुपये 2327
 c रुपये 3595 d रुपये 4214

- 40 Number of registered factories in Rajasthan in the year 1990 is approximately

- a 5400 b 9900
 c 16500 d 28300

राजस्थान में पंजीकृत कारखानों की संख्या वर्ष 1990 में लगभग कितनी है

- a 5400 b 9900
 c 16500 d 28300

- 41 The female-male ratio in Rajasthan in 1991, when compared with 1981 -
 ■ is the same
 b has increased slightly
 c has decreased slightly
 d has increased substantially

1991 में राजस्थान में स्त्री-पुरुष 1981 की तुलना -

- a बराबरी है b कुछ मात्र में बढ़ा है
 c कुछ मात्र में घटा है d काफी मात्रा में बढ़ा है

- 42 The most important basis of Bhagirathi Yojna initiated by the Government of Rajasthan is -
 a Economic motivation
 b Self motivation
 c Co-operative spirit
 d Centralized direction

राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई 'भागीरथ योजना' का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है -

- a आर्थिक अभिवृद्धि b स्व-अभिवृद्धि
 c सहकारिता से भावना d केन्द्रीय निर्देशन

- 43 Mahi Bajaj Sagar Project covers the following areas -

- a Only Rajasthan
 b Rajasthan and Gujarat
 c Rajasthan, Gujarat and Maharashtra
 d Rajasthan and P

महा बाजा सागर परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है -

- a केवल राजस्थान
 b राजस्थान एवं गुजरात
 c राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र
 d राजस्थान एवं पच्छिम प्रदेश

- 44 Gopal Yojana has been implemented by the Government of Rajasthan in ten districts of -

- a South East Rajasthan
 b South-West Rajasthan
 c North-East Rajasthan
 d Western Rajasthan

गोपाल योजना सरकार ने राजस्थान के किन्ति क्षेत्र के 10 जिलों में 'गोपाल योजना' को लागू किया है

- a दक्षिण-पूर्वी राजस्थान b दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान
 c उत्तर-पूर्वी राजस्थान d पश्चिमी राजस्थान

- 45 The Share of Rajasthan in net irrigated area of India is -

- a 7.7% b 8.8%
 c 9.9% d 11.0%

भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का किन्ति हिस्सा है -

- a 7.7% b 8.8%
 c 9.9% d 11.0%

- 46 Assertion (A) The second Zinc smelting plant of Rajasthan ■ now being established at Chandana (Chittorgarh)
 Reason (R) Chittorgarh district has abundant

resources of Zinc ore

Use If -

- a Assertion is right and reason is also right
 b Assertion is wrong and Reason is also wrong
 c Assertion is right but reason is wrong
 d Assertion is wrong but reason is right

कथन (अ) राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन मन्दिर अब चन्देरीया (चित्तौड़गढ़) में स्थापित किया जा रहा है।

कारण (ख) चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता अपरिष्कृत पण्डार प्रचुर मात्रा में मौजूद है।

उपयोग कीजिए यदि -

- a कथन सही है और कारण भी सही है
 b कथन गलत है और कारण भी गलत है
 c कथन सही है परन्तु कारण गलत है
 d कथन गलत है परन्तु कारण सही है

- 47 The Indira Gandhi Canal Project (Stage-I) has been able to create upto 1991 91 an irrigation potential of -

- a 20.3 Lakh ha ■ 15.6 Lakh ha
 c 5.7 Lakh ha d 1.5 Lakh ha

वर्ष 1990-91 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना (प्रथम चरण)

द्वारा सिंचाई क्षमता का अनुमान हुआ -

- a 20.3 लाख हेक्टेयर b 15.6 लाख हेक्टेयर
 c 5.7 लाख हेक्टेयर d 1.5 लाख हेक्टेयर

- 48 During the Earth summit held at Rio-de-Janero in 1992 the problems discussed related to -

- a Only environment
 b Only development
 c Only global warming and ozone hole
 d Different aspects of environment and development

सन् 1992 में रियो डे-जानेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान चर्चा मुख्यतः पर विचार किया गया थे की -

- a केवल पर्यावरण से सम्बंधित
 b केवल विकास से सम्बंधित
 c केवल वैश्वीकरण और ओजोन छिद्र से सम्बंधित
 d पर्यावरण और विकास के विभिन्न पक्षों से सम्बंधित

- 49 The highest increase in growth of population in the various districts of Rajasthan from 1901 to 1991 has been in the district -

- a Bikaner b Jaisalmer
 c Dungarpur d Jaipur

राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1901 से 1991 तक जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि जिस जिले में हुई है वह बिजना है

- a बीकानेर b जैसलमेर
 c डुंगरपुर d जयपुर

- 50 The effective media of self-dependence of village of Rajasthan is -

- a Formulation of village sponsored economic plans

- b Extension of cities
- c Extension of village education
- d Services to village unemployees in cities

राजस्थान के गाँवों को स्वावलम्बी बनाने का प्रभावी माध्यम है -

- a ग्रामीणमुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण
- b शहरीकरण का विस्तार
- c ग्रामीण शिक्षा प्रसार
- d ग्रामीण बेरोजगारों को गाँवों में नौकरी

110661

51 The highest literacy district of Rajasthan is -

- a Ajmer
- b Bikaner
- c Jaipur
- d Pali

राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है

- a अजमेर
- b बीकानेर
- c जयपुर
- d पाली

52 The city of Rajasthan where there is no air base is -

- a उदयपुर
- b कोटा
- c जोधपुर
- d अजमेर

राजस्थान का वह नगर जहाँ हवाई अड्डा नहीं है

- a अजमेर
- b कोटा
- c जोधपुर
- d उदयपुर

53 The present formation of the State of Rajasthan exists from the date -

- a 17-3-1948
- b 15-5-1949
- c 26-1-1950
- d 1-11-1956

राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है

- a 17-3-1948
- b 15-5-1949
- c 26-1-1950
- d 1-11-1956

54 The oldest organised industry of Rajasthan is

- a Cement Industry
- b Cotton Textile Industry
- c Sugar Industry
- d Vegetable Oil Industry

राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है

- a सीमेन्ट उद्योग
- b सूतीयम उद्योग
- c चीनी उद्योग
- d वनस्पति तेल उद्योग

55 Rich deposits of Copper lie in Rajasthan at -

- a Deedwana area
- b Bikaner area
- c Udaipur area
- d Khetri area

राजस्थान में ताम्र के विशाल भण्डार स्थित हैं

- a डीडवाना क्षेत्र में
- b बीकानेर क्षेत्र में
- c उदयपुर क्षेत्र में
- d खेतड़ी क्षेत्र में

56 The factory which is run by Central Government in Rajasthan is

- a Hindustan Zinc Limited Udaipur
- b Salt works, Deedwana
- c Ganganagar Sugar Mills, Ganganagar
- d Aravali Automatic vehicle Limited Alwar

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है

- a हिन्दुस्तान जिंक लि
- b साल्ट वर्क्स डीडवाना
- c गंगानगर शुगर मिल्स
- d अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड अलवर

57 The total area of Rajasthan is about -

- a 16% of India
- b 13% of India
- c 15% of India
- d 11% of India

राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है

- a भारत का 16%
- b भारत का 13%
- c भारत का 15%
- d भारत का 11%

58 The river of Rajasthan which carries water to Bay of Bengal is -

- a Mahi
- b Banas
- c Looni
- d Sabarmati

राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है वह है -

- a माही
- b बनास
- c लूनी
- d साबरमती

59 The river which originates from Rajasthan and drops its water into the Gulf of Kambhat is -

- a The Luni
- b The Mahi
- c The Jawai
- d The Parwati

नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खम्भात की खाड़ी में डालती है -

- a लूनी
- b माही
- c जवाई
- d पार्वती

60 The District having the highest percentage of variability in the annual rainfall is -

- a Barmer
- b Jaipur
- c Jaisalmer
- d Banswara

जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है -

- a बाड़मेर
- b जयपुर
- c जैसलमेर
- d बान्सवाड़ा

61 The district of Rajasthan having a good potentially of both oil and natural gas is -

- a Barmer
- b Jalore
- c Jaisalmer
- d Ganganagar

राजस्थान के जिस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की सम्भावनाएँ अच्छी हैं वह है

- a बाड़मेर
- b जालोर
- c जैसलमेर
- d गंगानगर

62 Which one of the following pairs is correct Census, 1991

- | District | Sex Ratio |
|------------|-----------|
| a Dholpur | 796 |
| b Durgapur | 942 |

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- c. Jaisalmer 997
d. Jalore 810

निम्नांकित में से सही एक चुनिए

जुलाई 1991

- | जिला | रिज अनुपात |
|------------|------------|
| a. जोधपुर | 796 |
| b. झुजपुर | 942 |
| c. जैसलमेर | 997 |
| d. जालोर | 810 |

- 63 The basic cause for frequent drought and famines in Rajasthan is

- a Extension of Aravalli's from S W to N E
b Irregular Insufficient and erratic rainfall
c Degradation of soil and forest
d Irrational and unscientific use of water

राजस्थान में बारूक सूखा एवं अकाल पड़ने का अकारण क्या है

- a अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार
b अनियमित अल्पमान एवं अविरत वर्षा
c मिट्टी एवं वनों का अवनश्य
d विवेहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग

- 64 The main objective of Aravalli Development Project is to

- a Control soil-degradation
b Check the expansion of Thar-desert
c Arrest deforestation
d Restore ecological stability

अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है

- a मिट्टी अवक्रमण को नियंत्रित करना
b थार-मरुभूमि के प्रसार को रोकना
c वनों को नष्ट होने से रोकना
d पारिस्थितिकी सिस्टम को बचाये रखना

- 65 Which one of the following sectors have been provided the highest percentage of allocation in the 8th Five Year Plan of Rajasthan

- a Agriculture
b Irrigation and flood control
c Power
d Social and community service

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस खण्ड (सेक्टर) में सबसे अधिक प्रतिशत धन निवेश किया जा रहा है

- a कृषि
b सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
c ऊर्जा
d सामाजिक सामुदायिक सेवार्थ

- 66 Rajasthan ranks first in India in the production of -

- a Rock Phosphate Turgsten & Gypsum
b Granite Marble and Sandstone
c Lead Zinc and Copper
d Mica Soapstone and Fluorite

बिनाके उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान प्रथम है ये है

- a रॉक फॉस्फेट एवं जिप्सम
b ग्रेनाइट संगमरमर एवं बलुआ-पत्थर
c सोडा जल एवं लौहा
d भस्म विनायक एवं फ्लुओराइट

- 67 Most significant programme in the alleviation of poverty in the rural area of Rajasthan is -

- a NREP
b SGV
c IRDP
d RLEGP

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मुलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है

- a राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम
b समय आधारित विकास
c समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
d ग्रामीण परिवर्तन हेतु राजस्थान राष्ट्रीय कार्यक्रम

- 68 Match the following -

- | Dams | Places |
|-------------------------|-------------|
| a Jawahar Sagar Dam | Chittorgarh |
| b Rana Pratap Sagar Dam | Kota |
| c Unmed Sagar Dam | Banswara |
| d Bajaj Sagar Dam | Bhilwara |

निम्नांकित को मिलाएँ -

- | | |
|----------------------|-------------|
| a जवाहर सागर | चित्तौड़गढ़ |
| b रणप्रताप सागर बांध | कोटा |
| c उन्मद सागर बांध | बांसवाड़ा |
| d बाजा सागर बांध | भोसवाड़ा |

- 69 Assertion Rule (A) The western desert district of Rajasthan have abundant food crops today
Reason rule (R) The Indira Gandhi Canal has provided means of irrigation in most parts of Jaisalmer and Barmer districts

use If

- a Assertion is right and reason is also right
b Assertion is wrong and Reason is also wrong
c Assertion is right but reason is wrong
d Assertion is wrong but reason is right

कथन (अ) राजस्थान के पश्चिमी मरुभूमि जिलों में आसन्न पशु पशुधन प्रमुख उपज है।

कारण (ब) इन्दिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बारमेर जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की है।

उत्तर का चयन करें

- a कथन सही है और कारण भी सही है
b कथन गलत है और कारण भी गलत है
c कथन सही है परन्तु कारण गलत है
d कथन गलत है परन्तु कारण सही है

- 70 On the basis of the nature and availability of natural resources the maximum potential in Rajasthan exist for the development of industries based on -

- a Livestock b Agriculture
c Minerals d Forests

बहुविध संपादन की बहुविध उपकरणों के आधार पर संचालन
में उन उपकरणों के
आधार पर

- a पशुधन
c खनिज

GOVT. GOBBERS LIBRARY

KOT

- 71 Which one of the follow

District	50
a Sirohi	952
b Jaisalmer	910
c Alwar	889
d Banswara	969

निम्न में से सही उत्तर चुनिए

जिला	जनसंख्या
a सिरोही	952
b जैसलमेर	910
c अलवर	889
d बान्सवाड़ा	969

- 72 Which one among the following pairs is correct

% desert Area (Raj)	% population (Raj)
a 60	40
b 55	45
c 50	50
d 40	60

निम्न में से सही युग्म चुनिए

शुष्क भूमि क्षेत्र (राज)	जनसंख्या (राज)
a 60	40
b 55	45
c 50	50
d 40	60

- 73 "Brown Revolution" in Rajasthan is concerned with

- a Food processing
b Buffalo milk production
c Wool production
d Goat hair production

राजस्थान में ब्राउन क्रांति का सम्बन्ध है

- a खाद्य प्रसंस्करण b गेहूँ दुग्ध उत्पादन
c ऊन उत्पादन d बकरी के बालों से उत्पादन

- 74 Relatively speaking which one of the following physiographic parts of Rajasthan is an area of ill drained inferior drainage

- a South eastern
b North - North Western
c South - South Western
d North Eastern

सापेक्ष रूप से राजस्थान के निम्न भू-आकृतिक भागों में से कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अल्प निकास क्षेत्र है

- a दक्षिणी पूर्वी b उत्तर-उत्तर पश्चिमी

- 75 Indira Gandhi Canal Project includes "Lift Canal" Schemes numberings -

DUE DATE SLIP

की संख्या है

- b The proposed Export Promotion Industrial Park in Rajasthan will be established with the assistance of

- a Japan
b World Bank
c Government of India

- d International Development Agency

राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात प्रमोशन औद्योगिक उद्यान में निम्न में सहायता से स्थापित किया जाएगा

- a जपान b विश्व बैंक
c भारत सरकार d अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था

- 77 Which one of the following has the natural gas based power project -

- a Dholpur b Jallpa
c Bhiwadi d Ramgarh

कौनसा गैस आधारित उद्योग प्राकृतिक गैस के आधार पर है

- a धौलपुर b जलपा
c बिहवाड़ी d रामगढ़

- 78 White cement in Rajasthan is produced at

- a Bawar b Colan
c Nimbahera d Chittorgarh

राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है

- a बावर b कोलन
c निम्बाहेरा d चित्तौड़गढ़

- 79 The Second highest peak of Aravalli range is

- a Jarga b Scr
c Taragarh d Achalgarh

अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक उचाई की चोटी है

- a जर्गा b स्क्र
c तारगढ़ d अचलगढ़

- 80 Which one of the following pairs is correct?

- a Kothari Luni b Sukdi Banars
c Jakhm Mahi d Banganga Chambal

निम्न में से सही युग्म चुनिए

- a कोठारी-लूनी b सुकदी-बनारस
c जखम माही d बंगंगा-चम्बल

TA (Haj.)

Student
two weeks at the m

ain library books only for

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE
17.1.12 